

अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें

भारत की विदेश नीति नए आख्यम

प्रमुख देशों की विदेश नीतियाँ

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

(द्वितीय विश्वयुद्ध से अद्यतन)

डा० सुष्पेश पंत

एसोसिएट प्रोफेसर

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

श्रीपाल जैन

मुख्य उपसम्पादक

दैनिक 'हिन्दुस्तान', नई दिल्ली

मीनाक्षी प्रकाशन

मेरठ

मीनाक्षी प्रकाशन
वेगम बिज, मेरठ।

तीसरा संशोधित एवं परिवर्द्धित संस्करण

अंक्य 60 00

© पत एव जैन, 1992-93

एवेरेडिबल प्रेस मरठ मे मुद्रित।

प्रस्तावना

अन्तर्राष्ट्रीय संबन्धों के अध्ययन का महत्व आज स्वयं सिद्ध है। जिस प्रकार समाज में रहने वाला व्यक्ति अपने बृहत्तर परिवेश से उदासीन नहीं रह सकता, उसी तरह कोई भी सम्प्रभु-स्वतन्त्र राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर उपस्थित क्रियाशील अन्य पात्रों की उपेक्षा या अवहेलना नहीं कर सकता। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में इस विषय का महत्व तेजी से बढ़ा है और इसका शोध व अध्ययन काफी लोकप्रिय हुआ है। राजनीति विज्ञान और इतिहास के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अन्य प्रश्न-पत्र के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय संबन्ध का विषय अच्छी तरह प्रतिष्ठित हो चुका है।

यह कम क्लेशदायक नहीं कि अन्तर्राष्ट्रीय संबन्ध विषय पर छात्रोपयोगी पठन की आवश्यकता एवं रुचि के अनुरूप हिन्दी में पाठ्य सामग्री का नितान्त अभाव है। प्रस्तुत पुस्तक इस कमी को दूर करने का एक प्रयास है। हमारी मान्यता रही है कि पाठ्य पुस्तक तब तक उपयोगी नहीं हो सकती, जब तक वह रोचक न हो। इसके अतिरिक्त तथ्यों का अम्बार भर जमा करना सार्थक नहीं हो सकता। पुस्तक का आकार बढ़ाने के लिए अनावश्यक दुहराव व विस्तार, गैर-जरूरी पाठ्य-प्रदर्शन के लिए उद्धरणों की भरमार, फुटनोट आदि भी छात्र को भ्रमित ही कर सकते हैं। हमने निरन्तर यह प्रयत्न किया है कि विषय-वस्तु को सरस व पठनीय ढंग से विश्लेषण के रूप में प्रस्तुत किया जाये। पुस्तक के विभिन्न अध्यायों का क्रम ऐसा रखा गया है कि उनके अन्तर-संबन्ध सहज ही स्पष्ट हो सकें और कोई मुख्य मुद्दा छूटने न पाये, परन्तु किसी चीज का पिच्छपेयण भी न हो। हम इस बात के लिए विशेष रूप से सतर्क रहे हैं कि विश्लेषण वस्तुनिष्ठ होने के साथ-साथ उसका नजरिया भारत-केन्द्रित हो।

पुस्तक की विषय सामग्री हिन्दी भाषी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों के छात्रों के पाठ्यक्रम की जरूरत अच्छी तरह पूरा करने वाली है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए भी प्रस्तुत पुस्तक काफी उपयोगी है। पुस्तक का जिस प्रकार स्वागत किया गया है उससे हमारा उत्साह बढ़ा है। इस नवीन संस्करण में सारी सामग्री को दोहराकर अद्यतन कर दिया गया है। इस रूप में पुस्तक पाठकों को और अधिक प्राप्ति होगी। पुस्तक को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए प्रेषित सुझावों का हम सहर्ष स्वागत करेंगे।

विषय-सूची

1	द्वितीय विश्व युद्ध पृष्ठभूमि, कारण और प्रभाव (Second World War Background Causes and Consequences)	1
2	अफ्रो-एशियाई एवं लातीनी अमरीकी देशों का उदय (Rise and Resurgence of Afro-Asian and Latin American Countries)	17
3	शीत युद्ध और उसका प्रभाव (Cold War and its Impact)	44
4	क्षेत्रवाद क्षेत्रीय तथा सैनिक संगठन (Regionalism Regional and Military Organizations)	71
5	गुटनिरपेक्ष नीति बदलते आयाम (Non-alignment Changing Dimensions)	120
6	देतान (तनाव शैथिल्य) एवं इसका विश्व राजनीति पर प्रभाव (Detente and its Impact on World Politics)	152
7	नया शीत युद्ध (The New Cold War)	175
8	संयुक्त राष्ट्र तथा व उसकी विशिष्ट एजेंसियाँ (United Nations and its Specialized Agencies)	193
9	निास्त्रीकरण समस्या व सम्भावनाएँ (Disarmament Problem and Prospects)	254
10	पश्चिमी एशिया की राजनीति (Politics of West Asia)	280
11	विदेश नीति सैद्धान्तिक विश्लेषण (Foreign Policy A Theoretical Analysis)	314
12	अमरीका की विदेश नीति (Foreign Policy of the United States)	325
13	सोवियत संघ की विदेश नीति (Foreign Policy of the Soviet Union)	340
14	साम्यवादी चीन की विदेश नीति (Foreign Policy of Communist China)	355

15. भारतीय विदेश नीति
(Indian Foreign Policy) 383
16. विश्व राजनीति के अन्य प्रमुख मामले
(Other Important Matters) 517
- सोवियत-चीन संबंध
(Sino-Soviet Relations)
- कम्बोडिया विवाद और हिन्द-चीन संकट
(Cambodia Issue and the Crisis in Indo-China)
- विश्व तेल संकट और भारत
(World Oil Crisis and India)
- आतंकवाद की समस्या
(Problem of Terrorism)
- हिन्द महासागर में महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा
(Super Power Rivalry in Indian Ocean)
- पाकिस्तान की परमाणु तैयारियाँ
(Pakistan's Efforts for Nuclear Bomb)
- रगभेद की समस्या : दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया
(Problem of Apartheid : South Africa & Namibia)
- नामीबिया की आजादी एवं नई चुनौतियाँ
(Independence of Namibia and New Challenges)
- नई विश्व अर्थव्यवस्था की तलाश
(Search for New World Economic Order)
- तीसरी दुनिया की एकता का सवाल
(Question of Third World Unity)
- अफगान संकट एवं जेनेवा समझौता
(Afghan Crisis and Geneva Agreement)
- पूर्वी यूरोप में परिवर्तन व विश्व राजनीति पर प्रभाव
(Changes in East Europe and their Impact on World Politics)
- जर्मनी के एकीकरण की समस्या
(Issue of German Unification)
- सुपर-301 पर भारत व अमेरिका में मतभेद
(Indo-U.S. Relations : Super 301)
- सोवियत संघ का विघटन
(Dissolution of U.S.S.R.)
- समाहित इस्लामी महासंघ और भारत
(Islamic Federation and India)

मानचित्र तालिका

1	दक्षिण-पूर्व एशिया (आसियान देश)	98
2	अरब-इजराईल संघर्ष	287
3	लेबनान संकट से सम्बन्धित स्थान	296
4	ईरान-इराक संघर्ष सम्बन्धित मुद्दे	303
5	विवादग्रस्त कश्मीर	444
6	चीन के अधिकार में भारतीय भूमि	452
7	सोवियत-चीन सीमा विवाद के प्रमुख बिंदु	522
8	हिंद-चीन के मदमं में कम्बुचिया का संकट	527
9	हिंद महासागर महासक्तियाँ और डिप्लोमासिया	542
10	दक्षिणी अफ्रीका समस्या स्थल	555
11	अफगानिस्तान और उसके पड़ोसी देश	567
12	रूस का नया राष्ट्रकुल	584
13.	संभावित इस्लामी महासंघ	588

द्वितीय विश्व युद्ध : पृष्ठभूमि, कारण व प्रभाव

इस शताब्दी के इतिहास में ही नहीं, बल्कि मानव जाति के इतिहास में भी द्वितीय विश्व युद्ध का विस्फोट एक निष्पत्तिक घटना है। अनेक इतिहासकारों का मानना है कि वास्तव में यह त्रासदी इस अहसास के लिए जरूरी है कि समस्त भूमण्डल के देशों की नियति एक-दूसरे के साथ अनिवार्यतः जुड़ी हुई है। मानव जाति की सांस्कृतिक विरासत के सभी मनुष्य समान रूप से उत्तराधिकारी हैं और इसे बनाये रखने की जिम्मेदारी उन सभी की है। इस युद्ध के बाद न केवल अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप बदल गया, बल्कि विश्व भर में रहन-सहन और सोचने-समझने के तौर-तरीकों में आमूल धूल परिवर्तन हुए।

द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि

(Background of the Second World War)

आज का अन्तर्राष्ट्रीय विश्व द्वितीय विश्व युद्ध की अग्नि परीक्षा से गुजरा है। मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय नैतिक व्यवस्था इस युद्ध के परिणामों से ही निर्धारित हुई है। फिर भी, इस बात की ध्यान में रखना उपयोगी है कि प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद के 'तनावपूर्ण शान्ति के सबट का अन्तराल' (1919-1939) आज भी अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के उत्थार-वढ़ाव को प्रभावित करता रहा है। अतः समसामयिक अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का अध्ययन-विश्लेषण करने के पहले प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर दृष्टिपात करना समीचीन होगा। जैसा कि यूरोपीय इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान् डेविड थॉमसन का मानना है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के घषाघं को समझने के लिए 'सिर्फ द्वितीय विश्व युद्ध के तात्कालिक कारणों को जानना दृष्टेष्ट नहीं बल्कि प्रथम विश्व युद्धजनित परिस्थितियों एवं उसके बाद के काल पर दृष्टिपात करना आवश्यक है।'¹ इनमें से घटनाक्रम को प्रभावित करते वालों में मुख्य शक्ति और मुख्य परिस्थितियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। परन्तु ऐसा नहीं सोचा जा सकता कि जो कुछ घटा, वह नियति द्वारा तय था। हाँ, इतना जरूर सब है कि भविष्य के संघर्ष और संकट के बीज 1919 में बोये जा चुके थे।

विभिन्न शान्ति समझौते (Various Peace Settlements)

सबसे पहली बात 1919 से 1922 तक सम्पन्न शान्ति समझौतों से सम्बन्धित है। यह प्रक्रिया पेरिस शान्ति सम्मेलन (1919) से आरम्भ हो चुकी थी और वही इसकी मूल प्रवृत्ति सामने आने लगी थी। अतः इन सन्धियों पर अलग-अलग

¹ David Thompson, *Europe Since Napoleon* (London, 1976), 651

टिप्पणी करने की अपेक्षा यह बेहतर है कि हम इनके प्रभावों का मूल्यांकन एक साथ करें। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सम्पन्न प्रमुख शान्ति समझौते व सन्धियाँ इस प्रकार हैं—वर्साय सन्धि (1919), आस्ट्रेलिया के साथ सेंट जर्मेन की सन्धि (1919), वल्गारिया के साथ निऊली की सन्धि (1919), हंगरी के साथ त्रिआनो की सन्धि (1920), तुर्की के साथ सेवर्स की सन्धि (1920) आदि। वर्साय सन्धि का एक आधारभूत सिद्धान्त यह था कि विजेता मित्र राष्ट्र (अमरीका, ब्रिटेन और फ्रांस) पराजित जर्मनी की कीमत पर अपने को पुरस्कृत करें और पराजित राष्ट्र को अपराधी के रूप में दण्डित किया जाये। बोल्शेविक क्रान्ति के बाद जारशाही रुम, सोवियत संघ में बदल चुका था और उसकी स्थिति अनूठी थी। वह विश्व युद्ध में न तो विजेता था और न ही पराजित। उसको लड़ाई की हानि तो उठानी पड़ी थी, किन्तु उसे हर्जाना-मुआवजा कुछ नहीं मिल सकता था। इतना ही नहीं, समस्त पूँजीवादी और उपनिवेशवादी व्यवस्था समाजवादी सोवियत संघ को एकाएक अपना शत्रु समझने लगी थी। एक छोटे से निर्णायक दौर में रूसी युद्ध में विदेशी शक्तियों ने सफ़ेद सेना के माध्यम से हस्तक्षेप का प्रयत्न भी किया था।

इस घटनाक्रम के कारण जिम पारम्परिक शक्ति-मन्तुलन ने लगभग दो सौ वर्षों तक (फ्रांसीसी क्रान्ति के व्यवधान को छोड़कर) यूरोपीय अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अनुशासित किया, वह बेकार कर दिया गया। जर्मन एकीकरण के बाद पाँच बड़ी शक्तियों में एक आस्ट्रिया कम हो चुकी थी। इसका स्थान भले ही अमरीका ने एक हद तक ले लिया, तथापि कैसरशाही जर्मनी के ध्वस्त हो जाने और सोवियत संघ की धराबन्दी के बाद सहमति के आधार पर, राष्ट्रीय हितों की सामूहिक व्यापक व्याख्या करने की कोई गुज़ाईश नहीं बची रही। इसका सबसे बुरा प्रभाव यह पड़ा कि जहाँ विजेता राष्ट्रों द्वारा शान्ति सन्धि पर हस्ताक्षर तो करवाये जा सके पर वही आपसी मतभेद की स्थिति में किसी बहुमत के आधार पर इन्हें लागू करने की कोई गुज़ाईश नहीं बची।

इन सन्धियों का एक दूसरा दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष यह था कि विजेताओं ने पराजित राष्ट्रों पर कमरतोड़ मुआवजे का ऐसा बोझ डाला, जिसने अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बुरी तरह चरमरा दिया। इस बात का विश्लेषण अपेक्षाकृत विस्तार से किया जाना जरूरी है। विजेता राष्ट्रों ने जर्मनी के कोयला-उत्पादन इलाक़े रुम और साइलेसिया वाला क्षेत्र अपने आधिपत्य में ले लिया। तब यह था कि ऐसा करने से भविष्य में जर्मनी की युद्ध क्षमता कम हो जायेगी। परन्तु इसका एक परिणाम यह भी हुआ कि जर्मनी के लिए युद्ध क्षतिपूर्ति का दण्ड-योगदान देना असम्भव हो गया। यह बात राष्ट्रीय आत्म सम्मान के साथ जुड़ गयी। जब तक पराजित राष्ट्र अपना पुनर्निर्माण नहीं कर सके, तब तक किसी भी व्यवस्था में अमनोप-आक्रांश बड़ी मात्रा में बचा रहता है। इसका उपचार निदान किये बिना स्थायी समाधान, शान्ति या स्थिरता ढूँढी नहीं जा सकती। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जॉन मेनहें कीन्स ने इस विषय का विस्तृत अध्ययन किया और अपनी एक पुस्तक का शीर्षक ही 'दि इकोनोमिक कोमेन्सेस ऑफ पीस' रखा।¹

जैसा कि प्रसिद्ध इतिहासकार ई० एच० कार ने लिखा है—'जर्मनी को जो

¹ John Maynard Keynes *The Economic Consequences of Peace* (London, 1920)

हर्जाना विजेताओं को देना था, वह अत्यन्त अयथार्थवादी ढंग से तय किया गया था। युद्ध क्षतिपूर्ति आयोग ने यह रकम साठे छह अरब पौंड आकी थी। बाद में एक अरब पौंड का पहला भुगतान तय किया गया। अन्ततः जर्मनी ने पचास करोड़ पौंड की एक किश्त ही दी।¹ कार आये कहते हैं कि—'कब्जापरी (विजेताओं) ने जर्मनी के पूरे आर्थिक जीवन को जड़ कर दिया। जहाँ एक ओर फासीसी पक्ष रुर से कोयले और लोहे का आयात कर अपना लूटें तक निकालने में असमर्थ था वहीं जर्मनी का दिवाल्ला निकल गया। इस बारे में कोई सन्देह नहीं किया जा सकता कि युद्धजनित आर्थिक घबराहट और राज्य-तन्त्र के अप्यवस्थित होने (disorganization of state machinery) पर जर्मन सरकार स्थिति पर नियन्त्रण नहीं पा सकती थी। मुद्रास्फीति जर्मनी के लिए बर्बाद मन्थि से भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुई।²

विजेताओं ने इन शान्ति सन्धियों के वहाने जर्मनी और इटली को उनके उपनिवेशों से भी वंचित कर दिया और स्वयं न्यासधारी (Trustee) के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की। इन सब निर्णयों का मिला-जुला प्रभाव यह हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और इटली में बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, तंगी, मन्दी तेजी से फैले। ये घातें कुछ ही वर्षों में जनतन्त्र के लिए जानलेवा सिद्ध हुईं और इन्होंने इटली में फासीवाद और जर्मनी में नाजीवाद को खतरनाक ढंग से बढ़ावा दिया।

इन शान्ति सन्धियों की एक ओर बड़ी असफलता रही। प्रथम विश्व युद्ध के विस्फोट ने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा की तलाश में सम्पन्न गुप्त समझौतों और सन्धियों ने ही बाह्य का वह बड़ा अम्बार जुटाया था जिसके विस्फोट में आर्च ह्यूक फर्डिनेंड की हत्या ने चिंगारी का काम किया। वार्षिक सम्मेलन में सभी प्रतिनिधियों के सामने यही समस्या सामूहिक सुरक्षा की थी। विडम्बना यह है कि लोगों ने आसानी से इसे राष्ट्र सघ (League of Nations) पर थोप दिया।

जहाँ एक ओर फ्रांस, जर्मनी से आसक्ति-आतंकित था और प्रतिरक्षा की प्राथमिकताओं को देखते हुए इसे (राष्ट्र सघ) अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का सामूहिक सुरक्षा का प्रबन्ध करना ही था, वहीं इस यथार्थ को अनदेखा नहीं किया जा सकता था कि ऐसा प्रबन्ध तभी कारगर हो सकता है, जब वह मूलतः अन्यायपूर्ण या विषम न हो। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि जिस अन्तर्राष्ट्रीय संगठन को सामूहिक सुरक्षा को यह जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, वह इसके निर्वाह में समर्थ एवं सक्षम हो। राष्ट्र सघ कोई यथार्थवादी रचनात्मक पहल नहीं थी, बल्कि एक आदर्शवादी प्रयोग था। इस विश्व संगठन की सीमाएँ इसके जन्म के साथ ही स्पष्ट हो चुकी थी। इसके प्रमुख प्रस्तावक अमरीकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन अपने देश को राष्ट्र सघ की सदस्यता के लिए तैयार नहीं कर सका। अमरीकी सदस्यता और समर्थन के अभाव में राष्ट्र सघ भी नपुंसक ही रह सकता था। जब भी कोई छोटा-बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय सङ्कट उभरा, तो राष्ट्र सघ उसका मामला करने में असफल रहा। अबोसीनिया हो या मन्नूरिया या फिर जर्मनी द्वारा क्षतिपूर्ति-मुआवजा भुगतान करने में इकार, राष्ट्र सघ हमेशा अकर्मण्य ही गिना गया। फ्रेडरिक एल० ड्यूमाँ का कहना है—'राष्ट्र सघ के लिए यह जरूरी था कि सदस्य राष्ट्रों में उसके सिद्धान्तों के प्रति

¹ E. H. Carr, *International Relations Between the Two World Wars* (London, 1961), 54-55

² देव, ६० एच० एच० बी पुस्तक पुस्तक के पृ० 57-58।

निष्ठा, बुद्धिमत्ता और साहस होता किन्तु उनमें इनका सर्वथा अभाव था। इसलिए जेनेवा की झील के तट पर एरियाना पार्क में निर्मित उसका मय्य प्रासाद शीघ्र ही उसका मुन्दर समाधि-स्थल बन गया।¹

इसके अतिरिक्त एक अप्रत्याशित-अनेपक्षित दिशा से भी अन्तर्राष्ट्रीय सन्तुष्टि पैदा हुआ। सुदूर पूर्व में जापानी सैन्यवाद के उफान ने 1923 में वाशिंगटन नौतंत्रिक सम्मेलन की घड़ी से ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर नये दबाव डालने आरम्भ कर दिये। विस्तारवादी सैनिक शक्ति द्वारा बल प्रयोग के निषेध के राष्ट्र सभ के प्रयत्न मदाशयी भले ही रहे हों, किन्तु वे नितान्त व्यावहारिक और 'सैद्धान्तिक' थे। युद्ध के उन्मूलन के लिए केनोग-त्रिया पैक्ट (1927) और लोबार्नो सन्धियाँ इसी धेनी में रखे जा सकते हैं।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद सम्पन्न शान्ति सन्धियों-मन्त्रोक्तों और राष्ट्र सभ की असफलता ने अगले 20-30 वर्षों में यूरोपीय रंगमंच पर ही नहीं, बल्कि अन्यत्र भी बैर-वैमनस्य और अवसरवादी मित्रता की दिशा-दशा तय की।

कुछ विद्वानों का मानना है कि पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बीच के अंतराल को शान्ति युग नहीं बल्कि अधिक से अधिक युद्ध विराम माना जाना चाहिए। दोनों युद्धों में इतनी समानता थी कि आरम्भ से ही इनका मामकरण दूसरा विश्व युद्ध कर दिया गया। दोनों बार विस्फोट पूर्वी यूरोप में हुआ, दोनों ही बार जर्मनी का मुकाबला फ्रान्स, ब्रिटेन आदि के सन्धि-संगठन से हुआ और सैनिक सघर्ष के विस्फोट के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि व्यवस्था की असफलता जिम्मेदार रही। दोनों ही विश्व युद्धों के बारे में यह बात भी महत्वपूर्ण है कि दुनिया पर युद्धरत राष्ट्रों की सुनियोजित रणनीति से कहीं अधिक दूरगामी प्रभाव आकस्मिक घटनाक्रम के पड़े। दोनों विश्व युद्धों के बाद युद्धोत्तर पुनर्निर्माण और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की स्थायी बनाने के प्रयत्न चरम महत्वपूर्ण बन गये। तथापि, जैसाकि डेविड थॉमसन का मानना है कि 'सुस्पष्ट समानताओं की देखते हुए भी इन दो विश्व युद्धों के बीच महत्वपूर्ण अन्तरों को हमें नजरअन्दाज नहीं करना चाहिये। दूसरा महायुद्ध पहले युद्ध की तुलना में कहीं अधिक वास्तविक युद्ध था। अफ्रीका और एशिया में निर्णायक रणक्षेत्र थे। विजयना यह थी विजिता होने के बाद भास का हाम रोका नहीं जा सका और द्वितीय विश्व युद्धोत्तर वर्षों में विभाजित-पराजित जर्मनी के राष्ट्रीय हित विजिता अमरीका व फ्रान्स के साथ जुड़ गये। मित्र राष्ट्रों में एक होने के बावजूद युद्ध समाप्त होने ही सोवियत सभ का बायावल्प शत्रु के रूप में हो गया। चीन में शान्ति, जापान की पराजय और आणविक अस्त्रों के प्रयोग ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को शान्तिकारी ढंग से बदल डाला।

¹ The government of Democratic Great Powers upon which the future of the League depended fell into the hands of those who were utterly lacking in the loyalty, wisdom and courage through which alone the League could survive by fulfilling the dreams of its founders. The League's white palace in Ariana Park, by shores of Geneva's Lake Lemman, therefore became, in the end, a sepulchre. Frederick L. Schuman, *International Politics* (New York, 1969), 313

द्वितीय विश्व युद्ध का विस्फोट : प्रमुख घटनाएँ (Outbreak of Second World War : Major Events)

द्वितीय विश्व युद्ध का आरम्भ एक सितम्बर, 1939 को हुआ, जब हिटलर ने पोलैण्ड पर आक्रमण किया। यह युद्ध लगभग छह वर्ष तक चला। जापान कि हिरोशिमा व नागासाकी नगरों पर अणु बम गिराये जाने (छह व नौ अगस्त, 1945) के बाद उसकी पराजय और आत्मसमर्पण (14 अगस्त, 1945) के साथ इसका अन्त आम तौर पर माना जाता है। यदि सूक्ष्म रूप से देखा जाय तो अलग-अलग राष्ट्र अपने हितों को देखते हुए संघर्ष में शामिल हुए और विभिन्न शत्रुओं की पराजय के साथ अलग-अलग रणक्षेत्रों में इसकी समाप्ति एक मोटे काल खंड के भीतर अलग-अलग क्षणों में हुई। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार हैं—7 दिसम्बर, 1941 को पर्ल हार्बर पर जापानी हमले के बाद अमरीका युद्ध में शामिल हुआ, जबकि जून, 1941 में सोवियत संघ पर जर्मन हमले के बाद सोवियत संघ रणक्षेत्र में कूद चुका था। जून 1940 में फ्रांस ने जर्मनी के सामने समर्पण किया और पासा पलटने के बाद जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने 8 मई, 1945 को समर्पण किया। इस तरह दिसम्बर, 1941 से मई, 1945 तक युद्ध पूरे उफान पर था। मित्र राष्ट्रों (Allied Nations) में अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और राष्ट्रवादी चीन थे। ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश अपने महाप्रभुओं की जरूरत के अनुसार युद्धरत रहे। जर्मनी द्वारा पराजित यूरोपीय राष्ट्र पोलैण्ड, चेकोस्लोवाकिया, हालैंड, आदि राष्ट्र मित्र राष्ट्रों का संरक्षण ग्रहण करने के बाद एक तरह से इसके सन्धि-मित्र और सहयोगी बन गये। धुरी राष्ट्रों (Axis Powers) में नाज़ी जर्मनी, फासीवादी इटली, जापान मुख्य थे। इनके अनुचर के रूप में तुर्की आदि या उनके द्वारा अधिग्रहित प्रदेश थे। मसलन जर्मनी ने फ्रांस में विचि नामक कठपुतली सरकार स्थापित की थी। इसी तरह जापान ने दक्षिण पूर्व एशिया में इण्डोनेशिया, हिन्द चीन आदि में अपने अनुकूल प्रशासन संगठित किये और अपनी इच्छानुसार उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवादी तत्वों को समर्थन-प्रोत्साहन देकर विश्व युद्ध में अपने पक्ष में भाग लेने के लिए विवश किया। आजाद हिन्द फौज, मुकाफ़ों, हट्टा आदि की जोड़ी इसी का उदाहरण है।

द्वितीय विश्व युद्ध के कारण (Causes of Second World War)

द्वितीय विश्व युद्ध के विस्फोट के अनेक कारण थे। प्रथम विश्व युद्ध की तरह इन्हे बहुत आसानी से तात्कालिक और बुनियादी कारणों (ऐतिहासिक, सामाजिक एवं आर्थिक) में नहीं बाँटा जा सकता। कई विद्वानों ने यह सुझाने का प्रयत्न किया है कि यूरोप में अल्पसंख्यकों का असंतोष और जर्मनी का पोलैण्ड पर आक्रमण युद्ध की लपटें भड़काने वाला सिद्ध हुआ। परन्तु इनका सम्बन्ध युद्ध के विस्फोट के लिए सिराजीवो थे आर्नो ड्यूक फ्रांज़ फर्डिनेंड की हत्या से भी कम महत्व का है। वस्तुतः पोलैण्ड का अतिक्रमण और चेकोस्लोवाकिया में जर्मन सेनाओं को भेजा जाना ऐसी घटनाएँ थी, जिनका वास्ता पहले विश्व युद्ध के बाद सम्पन्न सन्धि-समझौतों से है। नाज़ीवाद और फासीवाद का उदय किसी खास जातीय या नस्लीय

मानसिकता से नहीं हुआ, बल्कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद तनाव पर नियन्त्रण न पा सकने से सम्भव हुआ। इन सभी प्रसंगों पर अपेक्षाकृत विस्तृत टिप्पणी की आवश्यकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के विस्फोट के प्रमुख कारण निम्नावित हैं—

1. तुष्टीकरण की नीति (Policy of Appeasement)—अविश्वास जनता आज इस गलतफहमी की शिकार है कि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए मिर्फा हिटलर और मुसोलिनी जैम सरफिरे तानाशाह जिम्मेदार हैं। एक हद तक इस धारणा का पोषण विजय के बाद विजता के गुणमान करने वाले इतिहास लेखन ने किया है। यह प्रश्न पूछा जाना चाहिये कि क्यों समय रहते हिटलर और मुसोलिनी जैसे 'राक्षसों' का उन्मूलन करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया? ब्रिटेन और कुछ हद तक उसके सहयोगी मित्र राष्ट्र फ्रांस और बाद में रूस भी तुष्टीकरण की नीति के पक्षधर रहे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण म्यूनिख सम्मेलन है। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधान मंत्री नेविल चेंबरलेन बेहूद दबू किसिम के आदमी थे। जब वह 1936 में हिटलर से मिलने म्यूनिख पहुँचे तो उन्होंने अपनी वापसी पर बहाने के साथ यह घोषणा की कि 'मैं सम्मान के साथ ज्ञानि की व्यवस्था कर आया हूँ।' कुछ ही समय बाद इस दमपूर्ण घोषणा का खोललापन अगजाहिर हो गया तथा न सम्मान बचा और न ही ज्ञानि। म्यूनिख में चेंबरलेन के राजनयिक आचरण को आज तक अवसरवादी व समझौतापसन्दी का सबसे घटिया स्वरूप समझा जाता है। उन्हीं दबू समझा गया और ऐसे व्यक्ति को प्रधानमन्त्री बनाये रखने वाले राष्ट्र की छवि अनिवार्यन कमजोर हो हो सकती थी। म्यूनिख समझौते के बारे में फ्रेडरिक एन० शूमा ने लिखा है—'म्यूनिख समझौता तुष्टीकरण की नीति की चरम सीमा तथा पश्चिमी लोकतन्त्रों का मृशु-पत्र था। यह हिटलर की आत्मरक्षा नीति की अन्त तक की सबसे बड़ी विजय थी।'¹

जब आरम्भ में जर्मनी ने युद्ध का मुआवजा देना बन्द किया तो ब्रिटेन की तरह फ्रांस ने भी कोई जवाबी कदम नहीं उठाया। इनसे जर्मनी ने यही समझा कि धीमे-धीमे से फ्रांस को छुट रखा जा सकता है। मोक्षिपत सप का आचरण भी भिन्न नहीं था। तानाशाह स्टालिन उस समय अपने विराधियों के सपाये में व्यस्त थे। न केवल नाजी जर्मनी, बल्कि तमाम पश्चिमी पूँजीवादी देशों को वह अपना शत्रु समझते थे। कम से कम फासीवादी इटली और नाजीवादी जर्मनी शब्दादम्भर के स्तर पर समाजवाद को प्रतिष्ठित कर रहे थे। उनके साथ 'सहकार' में स्टालिन को कोई हिचक नहीं थी। स्टालिन का कुटिल प्रयत्न यह था कि पश्चिमी देशों को एकता सहित हो रहे। फ्रांस और जर्मनी का पारस्परिक वैर मोक्षिपत सप के लिए फायदेमंद था। जर्मनी के बहाने वह स्वयं पौरुष में मनमानी कर सकता था। स्टालिन रिवेन्शोप समझौता इस विद्वेषण को पुष्ट करता है। वास्तव में तुष्टीकरण की नीति मिर्फा कमजोरी या आत्मरक्षा का कारण नहीं बल्कि अवसरवादी नीतुपता के कारण अपनायी गयी। आज भले ही मिर्फा चेंबरलेन की बदनामी याद आती है, लेकिन अन्य लोगों की हिम्मेदारी भी दमम थी।

2. नैजीवाद व फासीवाद का उदय (Rise of Nazism and Fascism)—

¹ 'The Peace of Munich was the greatest triumph in date of Hitler's strategy of terror. It was the culmination of appeasement and warrant of death for Western Powers'—Schuman, *op cit*, 695

नाजीवाद व फासीवाद के आविर्भाव के लिए सिर्फ तुष्टीकरण की नीति ही जिम्मेदार नहीं थी, और न सिर्फ इतना कहने से काम चल सकता है कि जर्मनी का मूल सम्कार ही खड़ाकू व विस्तारवादी है, जिसके साथ अन्य देशों का टकराव अवश्यभावी है। जर्मनी की ऐसी हिंसक छवि के लिए नाजियों का नृशंस, अमानुषिक आचरण एक सीमा तक ही उत्तरदायी है। नीत्से और बिस्मार्क से लेकर विलियम कैसर के जरिये एडोल्फ हिटलर तक पहुँचना सहज अवश्य है, परन्तु सही नहीं। वास्तव में फासीवाद और नाजीवाद दोनों ही उग्र राष्ट्रवाद और भीड़तन्त्र के सन्निपात से जन्मे थे। इस तरह की प्रवृत्तियाँ यूरोप में अनेक देशों में तर उठा रही थी। इस महाभूमी के आरम्भ में 'थोअर बार' के दौरान उग्र राष्ट्रवाद के लिए अंग्रेजी में एक शब्द तक गढ़ा गया—'जिओइज्म'। ओस्वल्ड स्पेंगलर तथा औरतेगा इगासे जैसे विद्वानों को भीड़तन्त्र का खोफ द्वितीय विश्व युद्ध के वर्षों पहले सताने लगा था। इस प्रकार नाजीवाद व फासीवाद द्वितीय विश्व युद्ध के विस्फोट का कारण बना।

3. वर्साय सन्धि के प्रति असन्तोष (Resentment with the Treaty of Versailles)—वर्साय सन्धि मूलतः अन्यायपूर्ण थी और उसने जर्मनी जैसे पराजित राष्ट्रों पर कमरतोड़ आर्थिक मुआवजों का बोझ लादा था। परिणामस्वरूप 'वाइमार' गणतन्त्र (Weimar Republic) की असफलता पूर्व निश्चित हो गयी। हिटलर जैसे कुटिल राजनीतिज्ञ के लिए राष्ट्रीय सम्मान की दुहाई वे शकना न केवल सम्भव बल्कि विरसनीय बन सका। जब हिटलर अपने देशवासियों को कुर्बानी के लिए ललकारता तो वे न केवल आत्म-सम्मान एवं राष्ट्रीय गौरव के लिए, बल्कि रोजमर्रा की जिन्दगी चैन से बसर करने के लिए कमर कस रहे होते। राष्ट्र संघ ने जर्मनी पर तो तरह-तरह के प्रतिबंध लगाये परन्तु इसकी कोई व्यवस्था नहीं की कि जन-आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आर्थिक संसाधन उसे कैसे प्राप्त होंगे। शहरों में घोर अभाव और दरिद्रता ने लपट अमानुषिक तत्वों की हितक टीलियों को बढ़ावा दिया और इन्हे संगठित कर अपने विरोधियों के सफाये का अवसर हिटलर को दिया। अतः द्वितीय विश्व युद्ध के लिए वर्साय सन्धि भी जिम्मेदार रही है।

4. राष्ट्र संघ की असफलता (Failure of the League of Nations)—राष्ट्र संघ की असफलता ने जर्मनी में ही नहीं, बल्कि फ्रांस में भी घटनाक्रम को प्रभावित किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शान्ति की पुनर्स्थापना इस आदर्शवाद के साथ हुई थी कि राष्ट्र संघ सामूहिक सुरक्षा का प्रवर्धन करेगा, युद्ध का उन्मूलन करेगा और निःशस्त्रीकरण के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहेगा। इनमें से कोई भी आशा पूरी नहीं हुई। निराश एवं खिन्न फ्रांस ने स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्रीकरण का रास्ता चुना, जिसने हिटलर द्वारा सत्ता ग्रहण करने के बाद शस्त्रीकरण की होड़ और तेज की। यहाँ राष्ट्र संघ की असफलता के कारणों का विस्तृत विश्लेषण करने की कोई आवश्यकता नहीं, तथापि एक महत्वपूर्ण पक्ष की ओर ध्यान दिलाया जाना जरूरी है। राष्ट्र संघ की स्थापना अमरीकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन की प्रेरणा और सद्प्रयत्नों से हुई थी। बाद में स्वयं अमरीका इस संगठन का सदस्य नहीं बना। प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम अमरीका की सैनिक भागीदारी से निर्णायक ढंग से प्रभावित हुआ था। अमरीकी शक्ति तथा साधनों के अभाव में राष्ट्र संघ एक आदर्शवादी सपना भर रह गया। इथियोपिया में इतालवी हस्तक्षेप,

मनूरिया और चीन पर जापानी आक्रमण आदि संकटों के समाधान में राष्ट्र संधि बुरी तरह अमफल रहा। इसने नाजीवादी जर्मनी और फासीवादी इटली को यह सोचने का मौका दिया कि उन्हें अनुशासित करने वाली कोई सस्था नहीं और सैनिक बल ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का एकमात्र अर्थार्थ है। इस तरह राष्ट्र संधि अमफल होने पर द्वितीय विश्व युद्ध भड़का।

4 अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट (International Economic Crisis)—प्रथम विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में यूरोप भर में सामाजिक उच्छ्वस्तता तथा राजनीतिक अस्थिरता बढ़ने के लिए आर्थिक संकट जिम्मेदार रहा। तेजी या मंदी आर्थिक जीवन के साथ जुड़ी रहती है परन्तु इसके इतने नाटकीय परिणाम विश्व इतिहास में इससे पहले कभी नहीं देखे गये। आर्थिक संकट का आरम्भ अमरीका से हुआ और शीघ्र ही पूरा विश्व इसकी चपेट में आ गया। प्रथम विश्व-युद्ध के बाद जब शांति स्थापित हुई तो अनेक औद्योगिक इकाइयों का उत्पादन 'मरप्लस' हो गया। दूसरी तरफ पराजित राष्ट्र युद्ध के ध्वम के कारण माल खरीदने की स्थिति में नहीं थे। ऐसी स्थिति में महँगाई, मुद्रा स्फीति, कालाबाजारी, तस्करी, बैंकों की ऋणों की अदायगी में कष्ट स्वाभाविक थे। अनेक उद्योगपतियों ने अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए घातकीकरण, संन्याकरण और विस्तारवादी विदेश नीति को रामबाण आपधि के रूप में ग्रहण किया। जर्मनी तथा जापान के औद्योगिक संगठन तानाशाही व साम्राज्यवादी शक्तियों के पापक बने।

एक दान और। इस समय तक औपनिवेशिक शक्तियाँ अपने उपनिवेशों से सम्पत्ति का दोहन कर अपनी समृद्धि को अक्षत रखती रही थी। प्रथम विश्व-युद्ध ने इससे व्यवधान डाल दिया था। इसने अतिरिक्त इन उपनिवेशों में स्वदेशी पूँजीवाद के विकास का संयोग, उपनिवेशवाद विरोधी स्वाधीनता सश्रम के साथ ही चुका था। नेहरू और गांधी जैसे नेता फासीवाद के विरोधी तो थे परन्तु औपनिवेशिक शक्तियों के संन्याकरण का बटुआ विरोध भी करते थे। इसी कारण औपनिवेशिक सत्ताधना का पूर्ववत् मनमाना उपयोग न कर पाने से भी इन शक्तियों की आर्थिक स्थिति दुर्बल हुई थी।

6. जापान में सैन्यवाद का विकास (Development of Militarism in Japan)—द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों को जितना संकट नाजी जर्मनी और फासीवादी इटली से था, उतना ही पूर्वी प्रशान्त भोर्चे पर जापान से। यह गलत भी नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध को विश्व युद्ध में परिवर्तित पलें हाब्सबर्ग नामक अमरीकी नौसैनिक अड्डे पर जापानी हमले ने ही किया। तब तक अमरीका तटस्थ था और सोवियत संधि के युद्ध क्षेत्र में उतर आने के बाद भी यह सश्रम यूरोपीय ही था। जापानी सैनिक अभियानों ने ही दक्षिण-पूर्व एशिया में फासीवादी व डच साम्राज्य का सफाया किया और भारत में अंग्रेजी आधिपत्य को विपदा में डाला। द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों में जापानी सैन्यवाद को नाजीवाद और फासीवाद से कम महत्वपूर्ण नहीं समझा जा सकता।

जापानी सैन्यवाद एक तरह की तानाशाही था। परन्तु उसका जन्म नाजीवाद और फासीवाद से बिल्कुल भिन्न कारणों से हुआ था। इसने मूल में राष्ट्रीय अपमान, युद्ध में हार और आर्थिक परेशानियाँ नहीं, बल्कि सैनिक व सामन्ती महत्कार वाली परम्परा का आक्रमण तथा पूँजीवाद का प्रत्यारोपण था।

19वीं शताब्दी में जापान का आपुनिकीकरण तेजी से हुआ। जापान की आर्थिक व औद्योगिक सफलता ने साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को जन्म दिया। 1905 में रूस को हारने के बाद से जापान में नस्ली अहंकार निरन्तर बढ़ता गया। वाशिंगटन नौसैनिक सम्मेलन जैसे अवसरों पर पश्चिमी राष्ट्रों ने जापान की इन ध्रान्तिपूर्ण महत्वाकांक्षाओं को तुष्ट किया। इसके बाद जापान का यह सोचना तर्कसंगत था कि समानधर्मी नाजी व फासी ताकतों के साथ गठजोड़ कर वह अपने मसूवे पूरा कर सकता है। इस प्रकार, जापानी सैन्यवाद ने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया।

7. साम्यवाद का संकट (Crisis of Communism)—जापानी सैन्यवाद की तरह सोवियत संघ में साम्यवाद की स्थापना ने भी अप्रत्याशित ढंग से द्वितीय विश्व युद्ध के विस्फोट के लिए जमीन तैयार की। 1917 के बाद तमाम पूँजीवादी राष्ट्र रूस से क्रान्ति के निर्घात के प्रति आशंकित थे। उनके द्वारा समर्थित समूह मैनाभो ने सोवियत संघ में सैनिक हस्तक्षेप का प्रयत्न भी किया। उसके बाद रूस 'शत्रु' के रूप में पारिभाषित किया जाता रहा और उसकी चेखवन्दी के प्रयत्न किये जाते रहे। इंग्लैंड तथा फ्रांस में अनेक लोगों का सोचना था कि यदि नाजी जर्मनी अपनी विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं का सक्षम रूप को बनाता है तो इसमें उनका साम ही है। जर्मनी में हिटलर ने जिस हिंसक तरीके से अपने साम्यवादी विरोधियों का सफाया किया, उससे भी यह आभा प्रकट हुई। हिटलर की उपपथिता को सहन करना और उसके तुष्टीकरण के प्रयत्न इसी सम्बन्ध में समझ में आते हैं।

दूसरी ओर स्वयं रूस का राजनयिक आचरण सिद्धान्तहीन और दुर्लभलपंथी रहा। सोवियत संघ ने अवसरवादी ढंग से नाजी जर्मनी के साथ गुप्त समझौता किया और जब तक स्वयं उस पर हमला नहीं किया गया, तब तक उसने नाजियों और फासीवादियों को शत्रु नहीं समझा। रूस पर हमले के बाद ही राष्ट्रवादी युद्ध में कूद पड़ने के लिए विश्व भर के क्रान्तिकारियों का आह्वान किया गया। निश्चय ही, इस आचरण ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की अस्थिरता को बढ़ाया और विश्व युद्ध को सम्भव बनाया।¹

**युद्धकालीन राजनयिक सम्मेलन, शान्ति सन्धियाँ,
उनका महत्व एवं संयुक्त राष्ट्र संघ**

द्वितीय विश्व युद्ध के विस्फोट के साथ अन्तर्राष्ट्रीय राजनय की प्रक्रिया अस्त-व्यस्त हो गयी। परन्तु इससे यह समझना गलत होगा कि राजनयिक परामर्श पूर्णतः समाप्त हो गया। युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के बीच महत्वपूर्ण परामर्श निरन्तर चलता रहा और अनेक ऐतिहासिक राजनयिक सम्मेलनों का आयोजन किया जा सका। इनमें कुछ सम्मेलन ऐतिहासिक महत्व के सिद्ध हुए और युद्ध संचालन के अतिरिक्त युद्धोत्तर अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के स्वरूप पर भी इनका प्रभाव देखा जा सकता है। इनमें से प्रमुख सम्मेलन निम्नलिखित हैं :

1. लन्दन सम्मेलन घोषणा (London Declaration, 1941)—जून, 1941 में जब विश्व युद्ध अपने पहले चरण में था, लन्दन में तब ब्रिटेन, कनाडा,

¹ द्वितीय विश्व युद्ध के विस्फोट के तात्कालिक और बुनियादी कारणों का सबसे मारप्रभित वर्णन ई० एच० कार ने किया है।

न्यूजीलैण्ड, आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका आदि राष्ट्रमण्डलीय देशों ने अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की स्थापना के साथ-साथ एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का सुझाव दिया। भले ही यह अपने आप में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं थी, फिर भी इसने अटलांटिक चार्टर की अगुवाई की।

2. अटलांटिक चार्टर (Atlantic Charter, 1941)—यह सम्मेलन अटलांटिक महासागर में एक युद्धपोत पर सम्पन्न हुआ। इसी कारण इसका ऐसा विचित्र नामकरण है। इसमें भाग लिया—ब्रिटिश प्रधानमंत्री विसटन चर्चिल और अमरीकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने। इस बैठक की प्रस्तावना मित्र राष्ट्रों द्वारा महायुद्ध में अपने उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए की गयी थी। इस परामर्श के बाद जो घोषणा की गयी, वही अटलांटिक चार्टर के नाम से विख्यात है। इससे प्रमुख प्रावधान इस प्रकार थे—नाज़ी जर्मनी द्वारा अब तक पराजित देशों, पोलैण्ड, फ्रांस और नाज़ी आक्रमण के शिकार नाबॉ, मोवियन सभ जैसे देशों की प्रतिरोध क्षमता बढ़ाना, युद्ध के बाद हिटलर द्वारा स्थापित व्यवस्था को विस्थापित कर उनके स्थान पर अधिक मानवीय व्यवस्था की स्थापना तथा मध्य समाज में सर्वत्र अनुमोदित कुछ सामान्य मिद्दान्तों के आधार पर नई अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए प्रयत्न करना। इनमें से अन्तिम प्रावधान ने समुक्त राष्ट्र सभ की आधारशिला रखी। इस अटलांटिक चार्टर में कुछ महत्वपूर्ण बातें अन्तर्निहित थीं। अमरीका और ब्रिटेन दोनों ने यह बात स्पष्ट की कि युद्ध में उनकी अपनी कोई क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा नहीं है और न ही वे किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई व्यवस्था लादना चाहते हैं। अमानवीय अत्याचार व शोषण के विरोध के साथ-साथ रचनात्मक सहकार और शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की जरूरत पर भी बल दिया गया। यह घोषणा 14 अगस्त, 1941 को की गयी।

3 'समुक्त राष्ट्र' की घोषणा (Declaration of United Nations, 1942)—एक जनवरी, 1942 को वाशिंगटन में यह घोषणा की गयी। अब तक पक्ष हार्वर के हमले के बाद अमरीका भी युद्ध में सम्मिलित हो चुका था। फौजों की समुचित तैनाती और मोर्चों पर सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए 'मित्र राष्ट्र' 'समुक्त राष्ट्र' में परिवर्तित हो गये। इस घोषणा में अटलांटिक चार्टर की भावना और स्थापनाओं की स्वीकार किया गया और यह सबलप किया गया कि इनमें से कोई भी शत्रु ने अलग सन्धि नहीं करेगा। युद्ध संचालन के इस समुक्त प्रयास ने आगे चलकर इन सहयोगी देशों को एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में बदलने का सहज अवसर दिया। इस सामरिक राजनय के बाद ब्रिटेन-यू.एस. तथा डबल्टन ओकम सम्मेलन बुलाये गये, जिनका प्रमुख विषय अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में महामति बनाना था। आर्थिक विचार विनिमय के साथ-साथ डबल्टन ओकम सम्मेलन में समुक्त राष्ट्र सभ की सदस्यता, सुरक्षा परिषद के स्वरूप और इसकी सदस्यता के विषय में भी महत्वपूर्ण निष्कर्षों तक पहुँचा जा सका। ब्रिटेन-यू.एस. समझौते के तहत अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की जा सकी।

4 तेहरान सम्मेलन (Tehran Conference, 1943)—इस सम्मेलन (28 नवम्बर से एक दिसम्बर, 1943 तक) की विशेषता यह थी कि पहली बार तीनों बड़े नेताओं—चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन ने किसी युद्धकालीन सम्मेलन में एक साथ भाग लिया। सम्मेलन के समापन पर यह घोषणा की गयी कि तीनों यहाँ

से मित्र बनकर लौट रहे थे। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य सोवियत नेता स्टालिन को इस बारे में आश्वस्त करना था कि अमरीका तथा अन्य पश्चिमी राष्ट्र दूसरे मोर्चे पर कोई कोताही नहीं कर रहे थे और मोवियत रणनीति के साथ अपने पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों के क्रिया-कलापों का समुचित समायोजन चाहते थे। पश्चिमी राष्ट्र यह सोचकर सन्तुष्ट हुए कि स्टालिन से वे ईरान की स्वतन्त्रता, अखण्डता और सम्प्रभुता के बारे में आश्वासन पाने में सफल रहे। इसके पहले किसी सरकार को अप्यक्ष ने मोवियत क्रान्तिकारी नेता से इस प्रकार सीधे बातचीत नहीं की थी। इस अनुभव ने उन्हें अपने इस वैरी मित्र को पहचानने का अच्छा अवसर दिया। तेहरान समझौते में कुछ बातें गुप्त रखी गयीं, जिनका प्रकाशन मार्च, 1947 में जाकर हुआ। इन सभी बातों का सम्बन्ध युद्धकालीन समर नीति से था।

5. **याल्टा सम्मेलन (Yalta Conference, 1945)**—जब युद्ध अपने अन्तिम चरण में था तो फरवरी, 1945 में एक बार फिर तीन बड़े नेताओं की बैठक याल्टा (क्रीमिया, अब रूस में) में हुई। इनमें अटलांटिक चार्टर और तेहरान समझौते में कही गयीं कई बातों का विस्तार किया गया—जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना पर बल। परन्तु हमारे जो सबसे महत्वपूर्ण फैसले लिये गये वे जर्मनी से सम्बन्धित थे। यह तय किया गया कि जर्मनी चार क्षेत्रों में बाँट दिया जायेगा, युद्ध अपराधियों पर भुक्तमा चलेगा, जर्मनी का निःशस्त्रीकरण किया जायेगा और जर्मन अर्थव्यवस्था पर मित्र राष्ट्रों का नियन्त्रण रखा जायेगा। यूरोप के सन्दर्भ में पोलैण्ड की पूर्वी सीमा का निरूपण किया गया और युगोस्लाविया में मार्शल टीटो की सरकार को समर्थन देना तय किया गया। सोवियत संघ ने मुद्रूर पूर्व के सम्बन्ध में जापान पर आक्रमण का आग्रहामन दिया और बदले में मंगोलिया पर अपने आधिपत्य की स्वीकृति प्राप्त की। निम्न ही याल्टा सम्मेलन अब तक आयोजित ऐसे सभी सम्मेलनों में सबसे महत्वपूर्ण था। एक तो हमने युद्धोपरान्त राज्यों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करने का प्रयत्न किया था। इससे बाद में मनोमालिन्य और ईर्ष्या फैलना स्वाभाविक था। कुल मिलाकर, याल्टा सम्मेलन का स्वर विजेताओं द्वारा युद्ध में प्राप्त पुरस्कार के बँटवारे का था। जाहिर था कि विभिन्न राष्ट्र अपनी निजी युद्धशक्ति को ध्यान में रखकर अपने परिधम की कीमत आँक रहे थे। ऐसी स्थिति में मित्र राष्ट्रों की मैत्री ज्यादा समय तक अक्षुण्ण नहीं रह सकती थी।

माघ ही, इस वातावरण में अटलांटिक चार्टर की आदर्शवादिता, ध्यार्यवाद का पुट पाकर नितान्त व्यावसायिक बन गयी। समुक्त राष्ट्र संघ की प्रस्तावना, विश्व सरकार का बीज न रहकर विजेता मित्र राष्ट्रों की पचासत में बदलने लगी। उन्ग्रेन और वाइलो एशिया की सदस्यता, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों का प्रावधान, वीटो प्रणाली आदि ने शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। ऐसे अनेक विषय थे, जिन्हें विशेष कारणों से याल्टा में अछूता छोड़ दिया गया और उन्होंने आगे चलकर बड़ी अड़चने पैदा कीं। इनमें सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली, स्थायी न्यायालय तथा प्रारम्भिक सदस्यता विषयक मुद्दे प्रमुख थे।

6. **सान फ्रांसिस्को सम्मेलन (San Francisco Conference, 1945)**—इसका आयोजन द्वितीय महायुद्ध की अवसान वेला (25 अप्रैल से 26 जून, 1945) में हुआ। सम्मेलन की आरम्भ में ही चार आयोजकों में बाँटा गया और मुल 12

समितियाँ बनायी गयी। एक तरह से यह सम्मेलन म० रा० मघ का जनक था। समन्वय, संचालन एवं प्रक्रिया विषयक जो निर्णय यहाँ लिये गये, वे निर्णायक रहे। इस सम्मेलन के दार में एक रोचक तथ्य यह है कि इसमें भारत के दो प्रतिनिधि-मण्डलो ने भाग लिया। एक का नेतृत्व तत्कालीन विदेश सचिव गिरजा शंकर वाजपेयी कर रहे थे तो दूसरे का थीमती विजय लक्ष्मी पण्डित। भारत के योगदान ने यह बान उजागर की कि नया अन्तर्राष्ट्रीय संगठन उपनिवेशवाद का विरोधी है और इसकी अस्वाच्छलगायी नियति को समझता है। इस सम्मेलन में ऐसी अनेक अवधारणाएँ परिष्कृत-स्वीकृत हुईं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के धोपणा पत्र का अभिन्न अंग हैं, जैसे वीटो प्रणाली, क्षेत्रीय व्यवस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका, व्यक्तिगत तथा सामूहिक सुरक्षा का अधिकार एवं आर्थिक व सामाजिक परिपद का महत्व। इस सम्मेलन में लिये गये निर्णय के अनुसार प्रस्तावना को चार्टर से जोड़ा गया तथा राष्ट्रीय सम्प्रभुता को प्रतिष्ठा दी गयी। निश्चय ही सान-फ्रान्सिस्को सम्मेलन की उपलब्धियाँ उल्लेखनीय हैं, परन्तु यह बात भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि यही संयुक्त राष्ट्र मघ के मौलिन एवं निर्वाचित सदस्यों के बीच भेदभाव किया गया। आत्मरक्षा के व्यक्तिगत एवं सामूहिक अधिकार ने संस्था के क्षेत्राधिकार को बुरी तरह सीमित किया और विवादों के निपटारे के लिए बल प्रयोग के निषेध वाले प्रावधानों को लगभग निबंध बना दिया। इसी तरह क्षेत्रीय संगठन-व्यवस्थाओं के महत्व को स्वीकृत कर 'आदर्श विद्व' की परिवर्तना को दुर्बल किया गया।

7. पोद्सडेम सम्मेलन (Potsdam Conference, 1945)—पोद्सडेम सम्मेलन का आयोजन जर्मनी के बिना शर्त समर्पण के बाद जुलाई-अगस्त, 1945 में हुआ। इस वक्त तक अमरीकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट का निधन हो चुका था। इस सम्मेलन में अमरीकी राष्ट्रपति ट्रूमेन के अतिरिक्त, एटली, स्टालिन तथा चियांग काई शेक ने भाग लिया। इस सम्मेलन की प्रमुख उपलब्धि युद्ध के बाद शान्ति समझौतों के लिए जमीन तैयार करना था। युद्ध के बाद जर्मनी से आर्थिक क्षतिपूर्ति, जर्मनी के विभाजन, जर्मनी तथा पोलैण्ड में जनतान्त्रिक शासन की पुन स्थापना तथा आस्ट्रिया के तटस्थीकरण के बारे में प्रमुख निर्णय इस सम्मेलन में लिये गये। सम्मेलन में यह बात भी स्पष्ट हुई कि 'विजेता मित्र राष्ट्रों' के बीच आपसी मतभेद इन समय तक काफी उग्र हो गये हैं। इसी कारण पराजित राष्ट्रों के साथ अलग-अलग शान्ति संधियाँ करनी पड़ी। सन्दन, मास्को, पेरिस तथा न्यूयार्क में अनेक बैठकों के बाद इटली, बुल्गारिया, फिनलैण्ड तथा रूमानिया से अलग-अलग सन्धियाँ की गयी। इनके बाद भी जापान और आस्ट्रिया के साथ शान्ति समझौतों की समस्या बची रही।

द्वितीय विश्वयुद्ध . प्रभाव

(Effects of the Second World War)

द्वितीय विश्व युद्ध मानव जाति के इतिहास में पिछले लगभग दो हजार वर्षों में सबसे अधिक निर्णायक महत्व की घटना थी, जिसने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में ग्राह्यकारी परिवर्तनों का सूत्रपात किया। समसामयिक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति आज तक इस युद्ध के परिणामों और प्रभावों से अनुगमिन हो रही है। डेविड थॉमसन ने ठीक ही कहा है—द्वितीय विश्व

युद्ध का सबसे भजेदार परिणाम यह रहा कि युद्ध और शान्ति का अन्तर समाप्त हो गया। युद्ध के बाद शान्ति नहीं लौटी। उसकी जगह से ली शीत युद्ध ने। अन्य परिणाम कहीं न कहीं इसी बुनियादी परिवर्तन से जुड़े थे। विश्व राजनीति पर द्वितीय विश्व युद्ध के निम्नांकित प्रमुख प्रभाव पड़े।

1. यूरोपीय प्रभुत्व का अन्त (End of European Domination)—द्वितीय विश्वयुद्ध का सबसे पहला परिणाम यह रहा कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में यूरोप की बड़ी शक्तियों का वर्चस्व समाप्त हो गया। नेपोलियन युग के अन्त से प्रथम विश्व युद्ध के विस्फोट तक यूरोप की पाँच बड़ी शक्तियों के बीच शक्ति सन्तुलन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा यथार्थ था। कोलम्बरा द्वारा अमरीका की खोज और दास्कोडिगामा के भारत पहुँचने के साथ उपनिवेशवाद के जिस युग का आरम्भ हुआ, उसका अन्त 1945 में हुआ। इन पारम्परिक बड़ी शक्तियों का स्थान रूस और अमरीका दो महाशक्तियों ने ले लिया, जिनके हित और सामर्थ्य विश्व-व्यापी थे। इनकी आपसी प्रतिस्पर्धा में न केवल सैनिक शक्ति, बल्कि सैद्धान्तिक-वैचारिक आयाम भी महत्वपूर्ण था। यह भी उल्लेखनीय है कि अमरीका और सोवियत संघ दोनों में कोई भी शोषक औपनिवेशिक शक्ति नहीं रहा था। इसी कारण अफ्रो-एशियाई देशों में एक या दूसरी महाशक्ति द्वारा प्रस्तुत विकास का विकल्प सहज ग्राह्य था। स्वयं यूरोप की बड़ी औपनिवेशिक शक्तियाँ महायुद्ध के पर्वत के बाद राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए अमरीका या रूस पर निर्भर थीं। यह सुझाना तर्कसंगत होगा कि महाशक्तियों को छोड़कर बाकी सभी यूरोपीय शक्तियाँ 1945 के बाद दूसरे दर्जे की शक्तियाँ बनकर रह गयीं। यह स्थिति कमोबेश आज तक बरकरार है।

2. परमाणु युग का आविर्भाव (Advent of Nuclear Age)—द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पहले ही जापानी नगरी, हिरोशिमा तथा नागासाकी पर परमाणु अस्त्रों का प्रयोग किया जा चुका था। इसने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को क्रान्तिकारी ढंग से परिवर्तित किया। सर्वनाशक परमाणु अस्त्रों के आविष्कार ने रेडियो-धर्मिता-जनित प्रदूषण के कारण स्वयं विजेता के अस्तित्व को संकट में डाल दिया और मनुष्य जाति के अस्तित्व पर प्रश्न चिह्न खड़ा दिया। इस घटनाक्रम ने शक्ति-सन्तुलन की अवधारणा को निरर्थक सिद्ध कर दिया और इस परिकल्पना का विस्थापन आतंक के सन्तुलन से किया। रणनीति, राजनय, परमाणु शक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोग की सम्भावना, निषेधोपकरण आदि मुद्दों को इस घटनाक्रम ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का केन्द्रीय विषय बना दिया।

3. अफ्रो-एशियाई देशों में आभरण (Resurgence in Afro-Asian Countries)—यूरोपीय प्रभुत्व के हास तथा शक्ति गन्तुलन के क्षय ने उपनिवेशवाद की सभाप्ति की गति को तेज किया। अनेक अफ्रो-एशियाई देशों के उदय को द्वितीय महायुद्ध ने प्रेरणाहित किया। भारत, इण्डोनेशिया, मिस्र आदि इसी श्रेणी में आते हैं। चीन में साम्यवादी सरकार का गठन भी इस पर आधारित था।

अफ्रो-एशियाई देशों के पुनर्जागरण ने दो महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा के कारण प्रकट द्विध्रुवीय विश्व में सैनिक संघर्षों के गठन तथा युट निरपेक्षता के महत्व को उजागर किया। जहाँ एक ओर छोटे असमर्थ राष्ट्रों को सामूहिक सुरक्षा के नाम पर ओर आर्थिक सुरक्षा का सालप देकर महाशक्तियाँ अपनी ओर व अपने

सेमा में आकृष्ट कर सकी, वही अपेक्षाकृत बड़े सम्पन्न राष्ट्र अपनी राजनीतिक स्वाधीनता की रक्षा के लिए गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के संयोजक बने।

गुट-निरपेक्षता की अवधारणा के साथ दो और महत्वपूर्ण परिवर्तनाएँ जुड़ी थीं। इनमें से एक आर्थिक आत्म-निर्भरता की थी तो दूसरी सांस्कृतिक स्वाभिमान के साथ साथ शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की। आत्म के सन्तुलन ने हिंसक मुठभेड़ के स्थान पर पड़ोसपड़ोसी घुमपैठ और कलुषित प्रचार वाले शीत युद्ध का उद्घाटन किया। इस परिस्थिति ने प्रमुख अफ्रो-एशियाई देशों के लिए दो महाशक्तियों के बीच मध्यस्थता की भूमिका उजागर की तथा स० रा० सघ में उनकी रचनात्मक पहल के लिए जमीन तैयार की।

4. क्षेत्रीयता तथा जातीय संस्कार की पुष्टि (Assertion of Regionalism and Racial Affinities)—द्वितीय विश्व युद्ध ने जहाँ एक ओर समस्त भू-मण्डल की एकता व अन्तर-निर्भरता को रेखांकित किया, वही उमने विभिन्न मोर्चों में बंटवारे के साथ क्षेत्रीय विरोधता और जातीय संस्कार को भी पुष्टि किया। युद्धोत्तर काल में शीत युद्ध के पहले उध चरण में ये उदोद्यमान प्रवृत्तियाँ महत्वपूर्ण साबित हुईं। यह सिर्फ सयोग नहीं कि यूरोपीय आर्थिक पुनर्निर्माण की मार्गाल परियोजना और दक्षिण पूर्व एशिया में 'इकाफे' (ECAFE) का ग्राह्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सहजता से स्वीकार किये गये।

5. तकनीकी व वैज्ञानिक प्रगति (Technological and Scientific Progress)—द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सामरिक प्राथमिकताओं में वैज्ञानिक व तकनीकी शोध को तीव्रतर बनाया। राडार, जेट विमान, रेडियो तथा टेलीविजन प्रसारण जैसे क्षेत्रों पर जितने बड़े पैमाने पर पूँजी निवेश किया गया, वह शान्ति-काल में सम्भव नहीं था। यह बान परमाणु विज्ञान में भी लागू होती है। मित्र और घुरी राष्ट्रों को इस बात का अच्छी तरह अहसास था कि जो सेमा वैज्ञानिक व तकनीकी आविष्कारों की इस दौड़ में पिछड़ेगा, वही अन्ततः पराजित होगा। इतना ही नहीं युद्ध के मोर्चों की व्यापक जटिलता के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन की वैज्ञानिक प्रणालियाँ ईजाद की गयीं। 'एसेम्बली लाइन' का परिवार 'टी माइल' की कार के निर्माण के लिए हेनरी फोर्ड ने पहले ही मुद्रा दिया था। परन्तु ओपरेशन्स रिसर्च और सीनियर प्रोग्रैमिंग के साथ इसके सयोग से इसका असर वही चमत्कारिक ढंग से बढ़ गया। इसी तरह युद्धकालीन प्रचार, तंगी व रागमिग बानी अर्थव्यवस्था ने युद्धोत्तर काल में वैज्ञानिक व तकनीकी विकास को बाकी समस्त आर्थिक क्रियाकलापों के साथ केन्द्रीकृत और नियोजित करना सहज बनाया। प्रचार एवं बड़े पैमाने पर सैनिक भर्ती न विज्ञापन और माध्यमिकीय अध्ययन पर आधारित नीति निर्धारण को पुष्टि किया। इसी तरह युद्ध के दबाव ने रबड़, लीज आदि कच्चे माल को घाटे या अधिक समय के लिए अनुपलब्ध बनाकर इनके कृत्रिम विकल्पों के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त किया। प्लास्टिक, रपन, हल्की मिश्र धातु (Alloys), चमत्कारिक औषधियाँ आदि बहुत बड़ी सीमा तक द्वितीय विश्व युद्ध की ही देन हैं। सामरिक जटिलता के अनुसार जर्मन वैज्ञानिकों ने बी-2 प्रक्षेपास्त्र का आविष्कार किया। यही उन राकेटों के पूर्वज थे, जो आज हमें अन्तरिक्ष में विरप्य दिवा रह हैं। यदि एनरिको फर्मी आइस्टीन और ओपनहाइमर जैसे वैज्ञानिक नाबो अत्याचारों में प्रसन्न होकर अमरीका में शरण नहीं लेत तो शायद परमाणु बम के

साथ-साथ परमाणु शक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोग की बात आज तक सोची भी नहीं जा सकती थी। यदि फॉबड जैसे लोग अमरीका न पहुँचते तो उनके अपेक्षाकृत अमूर्त दार्शनिक रुझान वाले वैज्ञानिक चिन्तन का इतना प्रसार न हो पाता। यह सच है द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान का ध्वंस हुआ, परन्तु इससे इन देशों के वैज्ञानिक उत्तराधिकार का अन्त नहीं हुआ। विजेता राष्ट्रों को इसका लाभ हुआ। कई विद्वानों का मानना है कि जर्मनी और जापान के आविष्कारों के आधार पर ही सोवियत संघ और अमरीका ने शेष राष्ट्रों से बाजी मारी है। इस अतिशयोक्तिपूर्ण सरलीकरण से पूरी तरह गहमत्व हुए बिना यह कहा जा सकता है कि बिना वैज्ञानिक व तकनीकी प्रगति के इन राष्ट्रों का युद्धोत्तर पुनर्निर्माण सम्भव न होता।

6. सांस्कृतिक प्रभाव (Cultural Impact)—द्वितीय विश्व युद्ध का विस्लेषण करते समय अधिकांश विद्वान अपनी दृष्टि को राजनीतिक घटनाक्रम तक ही केन्द्रित रखते हैं। हमारी समझ से यह गलत है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध ने जिस सांस्कृतिक प्चार को उभारा उसके दूरगामी सामाजिक व राजनीतिक परिणाम अवश्यभावी थे। वस्तुतः ऐसा हर बड़े निर्णायक युद्ध के साथ होता है। जिस तरह भारतीय इतिहास के मिथकीय महात्मर महाभारत ने एक अन्वेष्य युग का सूत्रपात किया था, उसी तरह द्वितीय विश्व महायुद्ध के बाद के वर्ष निराशा-हताशा एवं विश्वव्यापी कुठा का युग था। सोरेम किर्कगार्ड जैसे अपेक्षाकृत गीण, व दुरुह दार्शनिक का अस्तित्ववादी चिन्तन यूरोप तथा अमरीका में लोकप्रिय बना। ब्रह्माण्ड में मनुष्य के अस्तित्व की नगण्यता और अर्थहीनता की अनुभूति ने धार्मिक व नैतिक मूल्यों का तेजी से ह्रास किया और सामाजिक उच्छृङ्खलता को पतपाया। उसने जहाँ एक ओर पश्चिमी पूंजीवादी समाज में टेडी बोएज, बीट निको और आगे चलकर हिप्पियों को प्रलिच्छा दिलायी, तो दूसरी ओर साहित्य और कला के क्षेत्र में अमूर्तता (abstractions), स्वातः सुसाय तथा गिरंकुश उद्गारों की अभिव्यक्ति वाली नलाकृतियों के सृजन को प्रोत्साहन दिया। पॉप आर्ट, रॉक म्यूजिक आदि इसी के उदाहरण हैं।

दूसरी ओर इन प्रवृत्तियों के प्रतिक्रियास्वरूप समाजवादी देशों में सबल देने के लिए सर्वोच्च नेता की भक्ति पूजा आम बात हुई। सोवियत संघ में स्टालिन, चीन में माओ और यूगोस्लाविया में टिटो का करिश्माती व्यक्तित्व इसी बुनियाद पर वर्षों तक टिका रहा। समाजवादी खेमे के बाहर भी प्रतिवद्ध या उदासीन, परन्तु गुस्से और आक्रोश में भरे युवा लेखकों, कवियों एवं कलाकारों ने हिंसा, ध्वंस और सरकार की शक्ति में प्रसार के विरुद्ध आवाज उठायी। पिकासो की प्रसिद्ध कलाकृति, गोंयरदिकन और सौरभ की कविताएँ स्थानीय युद्ध से प्रेरित थीं। कामू का उपन्यास 'प्लेग', हेरल्ड विटर और जॉन ओसबोर्न के नाटक भी इसी परम्परा में आते हैं। युद्ध की विभीषिका, महानगरीय संक्रास, अलगाव आदि अनुभूतियाँ, जो आधुनिक साहित्यिक व कला जगत का अभिन्न अंग बन चुकी हैं द्वितीय विश्व युद्ध की ही देन हैं।

इनका ही नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध के घटनाक्रम ने यूरोपीय औपनिवेशिक वर्चस्व को समाप्त कर अफ्रो-एशियाई देशों के पुनर्जागरण को सम्भव बनाया और उपनिवेशवाद की स्थापना के पहले के जातीय व सांस्कृतिक उत्तराधिकार का पुनरोद्धार गहन बनाया। इन सांस्कृतिक उथल-पुथल ने शीत युद्ध के दौर में महत्व-

पूण आयाम ग्रहण किया, क्योंकि बिना शस्त्रों से सड़ी जाने वाली यह लड़ाई लोगों का दिल और दिमाग जीतने के लिए थी। आज तक गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के जमघट में सांस्कृतिक साम्राज्यवाद बनाम सांस्कृतिक स्वाधीनता की यह स महत्वपूर्ण घंटी हुई है। फ्रांस फेनोन जैसे न्रान्तिकारियों ने नव उपनिवेशवाद के विरुद्ध जन सघर्ष में सांस्कृतिक मोर्चे को सबसे महत्वपूर्ण समझा है। नाजियों के आविर्भाव और जापान में सैन्यीकरण के प्रसार ने इस स्रकट को उजागर किया कि कैसे लोक सत्कार—एक खास तरह की मानसिकता, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को निर्णायक ढंग से प्रभावित कर सकती है।

7 सयुक्त राष्ट्र सघ का उदय (Rise of the U N O)—द्वितीय विश्व युद्ध ने विभिन्न देशों को उनकी अन्तर-निभरता का अहसास कराया। इससे परिणामस्वरूप मित्र राष्ट्रों के प्रयत्ना में सयुक्त राष्ट्र सघ की स्थापना की घोषणा की गयी, जो एक तरह से विश्व सरकार का बोजारोपण था। भले ही आगे चलकर स० स० सघ से जुड़ी अनेक आदर्शवादी आशाएँ घूमिल हुईं, परन्तु इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्रकट निवारण, उपनिवेशवाद उन्मूलन और आर्थिक व सामाजिक सहयोग बढ़ाने में इस सस्था ने तब से आज तक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। निशस्त्रीकरण हो, या सांस्कृतिक आदान प्रदान, युद्ध विराम हो या तत्तापलट, महामारी नियन्त्रण हो या नई विश्व अर्थव्यवस्था की तलाश या फिर किसी नवोदित राष्ट्र या सरकार को मान्यता देने का प्रश्न, आज स० स० सघ का राजनय सभी छोटी-बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं से अनिवार्यत जुड़ा रहता है। इस स्थिति के लिए भी द्वितीय विश्व युद्धकालीन घटनाक्रम निर्णायक रहा है।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध ने न केवल अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप बदला, बल्कि विश्व के तमाम देशों की सामाजिक व आर्थिक स्रचनाओं का भी न्रान्तिकारी ढंग से आमूल मूल बदल डाला। यह स्वाभाविक था कि इन परिवर्तनों के सांस्कृतिक परिणाम सामने आते और ये सांस्कृतिक आयाम आज तक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते रहे हैं। मूल रूप में वैज्ञानिक व तकनीकी आविष्कार ज्यादा आसानी से दृष्टिगोचर होते हैं, परन्तु वास्तव में सूक्ष्म-अमूर्त हयान्तरण इनसे कम महत्वपूर्ण नहीं समझे जा सकते। परमाणु अस्त्रों का उत्पादन व प्रयोग और द्विभुवीय विश्व का आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के उतने ही महत्वपूर्ण नतीज हैं, जितना सयुक्त राष्ट्र सघ का गठन, उपनिवेशवाद का अन्त, जन-मुक्ति सयामों का प्रसार या इन वैज्ञानिक व राजनीतिक परिवर्तनों का साहित्य, दर्शन व कला पर प्रभाव। निष्पर्यंत कहा जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध ने एक ऐसी दुनिया को जन्म दिया, जो 1939 से पहले के जगन से बिल्कुल भिन्न है।

दूसरा अध्याय

अफ्रो-एशियाई एवं लातीनी अमरीकी देशों का उदय

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अफ्रीका और एशिया का महत्व साबित करने के लिए किसी भी तरह की अतिशयोक्ति या अतिरजना का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं। सभार की लगभग दो-तिहाई जनसंख्या अफ्रो-एशियाई देशों में रहती है और दुनिया की चार प्राचीनतम सभ्यताओं में तीन का जन्म एशिया में हुआ है। सामरिक महत्व की दृष्टि से अफ्रीका तथा एशिया का अपना अलग महत्व है। ऐतिहासिक काल में भारत की सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था और चीन तथा जापान की ओर भी पश्चिमी शक्तियाँ सोलुप दृष्टि से देखती रहती थी। चीन, भारत, इंडोनेशिया और अफ्रीकी महाद्वीप के उत्तरी छोर के मिल में हजारों वर्ष पुराने साम्राज्यों की परम्परा आज भी जीवित है।

उपनिवेशवाद (Colonialism) का घातक प्रभाव सबभग सभी अफ्रो-एशियाई देशों में देखने को मिलता है। साम्राज्यवादियों ने सर्वत्र 'फूट डालो और राज करो' की नीति का अनुसरण किया तथा निमंत्रण दम से अफ्रो-एशियाई जनता का आर्थिक शोषण एवं सामाजिक उत्पीड़न किया। उपनिवेशवादियों ने सामन्ती विषमता को और भी गहरा किया। उन्होंने साम्प्रदायिक व कबायली पक्षपात की नीति अपनाकर अफ्रो-एशियाई समाज का विभाजन किया।

विघटनकारी घटनाक्रम के कारण सदियों तक अफ्रीका और एशिया के देश अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में समुचित भूमिका नहीं निभा सके। उपनिवेशवाद के उन्मूलन के बाद एक बार फिर उनका महत्व उजागर हुआ है। शीत युद्ध के पहले चरण में द्विष्टनीय विद्व में हर महाशक्ति के लिए अपने शिविरानुचर बढ़ाने की उपयोगिता थी और गुट निरपेक्षता के प्रसार ने इन देशों की सामूहिक शक्ति के कारण इनकी एकता को कई गुना बढ़ा दिया था। आज भी इनके बीच सैद्धांतिक और मध्य मतभेदों के बावजूद इनको थनदेखा करना सम्भव नहीं।

उपनिवेशवाद को समाप्त और अफ्रो-एशियाई देशों के उदय के समुचित विश्लेषण के लिए ऐतिहासिक गुनरीक्षण आवश्यक है। एशिया में यह प्रक्रिया सबसे पहले जापान और उसके बाद चीन में शुरू हुई। यो एक तरह से चीन और जापान पश्चिमी शक्तियों द्वारा कभी पूर्णतः गुलाम तो नहीं बनाये गये, परन्तु शोषण-उत्पीड़न का पूरा अपमानजनक बोझ उन्हें सहन करना पड़ा। सामुराई व सामन्ती परम्परा के धारिण जापानियों को यह बात बनई सहनीय नहीं थी कि किसी और का आधिपत्य प्रच्छन्न रूप में भी उन्हें स्वीकार करना पड़े। अमरीकी नौसैनिक अधिकारी कोमोडोर पेरी द्वारा जापान का प्रवेश द्वार खोल दिये जाने के बाद से इन जापानी नेताओं का यही प्रयत्न रहा कि अतिप्रगल्भकारी विदेशी आततायी के नीर तरीके अपनाकर ही नहीं, उनका मुकाबला किया जाये और अपने देश को आगे बढ़ाया

जाय। परिवर्तन के साथ-साथ सामाजिक सुधार एवं प्रगतिशील अधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया जापान में आरम्भ की वह 'मजी पुनर्स्थापना' के नाम से विख्यात है।

इस रणनीति की सफलता 1905 में प्रमाणित हुई जब जापान ने रूस को पराजित किया। यह किसी भी एशियाई देश द्वारा किसी यूरोपीय देश को पराजित करने की पहली घटना थी। इसने निश्चय ही पराधीन एशियाई जनता के मनोबल को अश्र्वत्थित ढंग से बढ़ाया। जापानी प्रगति मित्र सैनिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रही। द्वितीय विश्व युद्ध के विस्फोट तक अपने सस्त औद्योगिक उत्पादन के लिए भी जापान विश्वविख्यात हो चुका था। वॉशिंग्टन निर्गन्धीकरण सम्मेलन (1922) में जापान को यूरोपीय शक्तियाँ के समकक्ष मान लिया गया और उनका बाद के वर्षों में जापान के सैन्यीकरण की निरन्तर वृद्धि हुई। यहाँ यह जोड़ने की जरूरत है कि जहाँ इस सैन्यीकरण में जापानियों में नस्लवादी अहंकार और निजी साम्राज्यवाद की बटावा दिया वहीं यूरोपीय ताकतों के मुकाबले एशियाई आत्म-सम्मान की पुनर्स्थापना में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया में फ्रान्सीसी, बर्नार्डी तथा डच औपनिवेशिकों को मार भगाने का काम जापानियों ने सम्पन्न किया और अनेक जगह राष्ट्रवादियों का कार्य सहज बनाया। जापानियों के सम्बाधन में आयोजित सह-मनृष्टि का क्षेत्र (Co-prosperity sphere) तथा आचार हिंद फौज का यत्न इसी के उदाहरण हैं। हिरोशिमा तथा नागासाकी में परमाणु बम गिराये जाने के बाद जापान को आत्म-समर्पण करना पड़ा और एक पराजित राष्ट्र के रूप में अपमान का घूँट पीना पड़ा। परन्तु इसके बाद तत्काल एक दशक में ही जिस चमत्कारी ढंग से जापान ने अपना आर्थिक पुनर्निर्माण कर दिखाया, उसने अगुडे ढंग से एशियाई मौलिकता, बमडना और क्षमता को उजागर किया है।

जापान की तरह चीन भी गुलामी की बन्धनों में तो मुक्त रहा परन्तु इस स्वतन्त्रता का कोई लाभ उसे नहीं मिला। जून, 1839 में अफीम युद्ध (Opium War) के बाद स चीनी साम्राज्य ने पश्चिमी ताकतों के सामने अपनी अमनस्यता स्वीकार अपने दावाविषय को घुग्ने टक्के के लिए विवश किया था। यूरोपीय ताकतों ने चीन का विभाजन संरक्ष की फौकी की तरह आरम्भ में कर लिया और मिल बाँटकर चीनी सम्पदा का उपयोग करने लगे। बेकमर विद्रोह तक 'गार्ड जैस महानगरी में चीनी स्वदेश में अनुबन नगरवीय जीवन स्थान करने को विवश थे। पश्चिमी गिप्पा प्राण सन यान सेन जैमे चीनी नेताओं ने इससे विरुद्ध अपने देशवासियों की संगठित किया और 1911 में एक सफल क्रांति का सूत्रपात हुआ। साम्यवादी क्रांति की सफलता (1949) के बाद यान ही, चीनी राष्ट्रनीति के सन्दर्भ में इस घटना का महत्व कम माना जाता रहा ही भयर इसमें दो राय नहीं कि एशियाई राष्ट्रवाद का घुट करन में कुदिरताय पागों यान चीनी राष्ट्रवादियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सन यान सन और चांग बाइ शक के घनिष्ठ सम्बन्ध पर नरक और टंगार जैस प्रभावशाली राष्ट्रवादियों से रहे और एशियाई मानव के बार में साबना तथा दक्षिण की मापेशरी की बाय बनना सम्भव हुआ। 1949 के बाद के वर्षों में यान ही साम्राज्य युग के साम्यवादी चीन के बारे में और उनका द्वारा क्रांति के शिखर निर्वाह के शिष्ट में अनेक अजी-एशियाई देश आश्रित रहे परन्तु नरक शक्ति मिडान के आधार पर चीन की उपनिधियों का अनदया किया जाना अनम्भव

है। जिन तरह माओ ने यूरोपीय विचारों तथा मार्क्स और एंगेल्स की स्थापनाओं को अफ्रो-एशियाई परिवेश के लिए परिष्कृत व रूपान्तरित किया, उसका उल्लेख भी आवश्यक है। माओज्म तब की छापाखाना स्थितियों पर आधारित जनमुक्ति संग्राम की परिस्थितियों ने अनेक अपीकियाँ और एशियावासियों को यह मिथ्या विकारने का मौका दिया कि चीनिक शक्ति का अभाव दुर्बलता नहीं। विप्लवाधी जनमुक्ति संग्राम इसका अच्छा उदाहरण है। चीनी नेताओं की स्थापनाओं ने महान ह्रास बिना यह कहा जा सकता है कि अफ्रो-एशियाई नवजागरण में प्रेरणा-स्रोत के रूप में चीनी जापानियों ने कम महत्वपूर्ण नहीं रहे। इसी तरह की भूमिका भारत की भी रही है।

भारत की भूमिका

पश्चिमी उपनिवेशवाद के प्रतिक्रियात्मक रूप भारत का राष्ट्रीय नवजागरण 19वीं शती के मध्य तक जारी गतिशील हो चुका था। भारत, चीन और जापान में कई बातों में भिन्न था। भारत की सांस्कृतिक परम्परा गङ्गिष्णु और समन्वयवादी रही है, हर विदेशी को अनु समझने वाली रही और न ही हर विदेशी धनू का कुशाग्रपूर्ण निरन्धर करने वाली। राजा राम मोहन राय शरीर लोगों ने किसी हवाय में नहीं, बल्कि स्वेच्छा से पश्चिमी शिक्षा ग्रहण की और अपने समाज में व्याप्त कुुरीतियों के उन्मूलन के लिए जुट गये। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के बाद औपनिवेशिक शासन के औपण-स्वरूप के प्रति भारतीय अधिक गहरे हुए और प्रजा का जिन उदात्त करने वाले प्रशासन की प्रवृत्ति: शक्ति: मांग ने धीरे-धीरे राजनीतिक गमाओं, परिषदों और दलों के गठन की जन्म दिया। एशियाई जागरण का विश्वकोश बनने का भारत ही एक ऐसा श्रुती मिताय है, जहाँ यह प्रक्रिया बलाग काम्निवारी रूप से सम्पन्न या उपर में चोपी नहीं गयी। दुर्वा जहाँ (grass-roots) में उभरने वाले लोगों ने इसे बल दिया।

भारत का सांस्कृतिक नव जागरण किसे पश्चिमीकरण पर आधारित नहीं था, बल्कि यह देश के गौरवपूर्ण अर्थात् की किर में पहचानने के प्रयत्न के साथ जुड़ा था। जापान ने प्रगति के लिए अपने की पूरी तरह पश्चिमी ढाँचे में क्षमता जल्दी समझा तो चीन में सदियों पुरानी जड़ता, पुरानी व्यवस्था की जड़ में उपाड़ की बिना नहीं समाप्त की जा सकी। भारत में राष्ट्रवाद की महत्त्व ने राजनीति के साथ-साथ आर्थिक एवं सामाजिक क्रिया-कलाप को अग्रसर नहीं छोड़ा। सभी परिस्थितियों की प्रकृति विकासवादी-सृष्टावादी रही। इस बात को जोर देकर स्पष्ट करना इसलिए जरूरी है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर अफ्रीका और एशिया के अनेक देशों ने चीन, जापान तथा भारत को अपने अनुसूच और उद्घाटन के लिए निम्न-निम्न विचारों के रूप में देखा।

भारत के राष्ट्रीय जागरण के दो और उल्लेखनीय बात है—उपनिवेशवाद के खिलाफ अग्रिम सफाई तथा संवदीय प्रशासकीय बाले परामर्श द्वारा समाज का उन्मादन। ये दोनों बाले समाज और राजनीति के क्षेत्र में विकासवादी शक्ति: को बिना महत्व नहीं हो सकती थी। यदि जापान में वखाट के प्रतीक में आयुर्वि-करण की वैधानिकता का जमा पहचानकर व्यापक जन-महमदि क्रियाशील और चीन में जारी-जारी में एक बात सेन और माओज्म तब ने दिखाए जन समूह की गतिशील

बनाया तो भारत में राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक महत्व के अनेक नेताओं ने यह काम सहयोगी दम से पूरा किया। शीपेंस्य स्तर पर गांधी जी और नेहरू जी की जोड़ी इस बात का बहुत अच्छा प्रमाण है। एशियाई नव-जागरण में जापान, चीन और भारत तीनों ही जगह परम्परा और आधुनिकता का द्वन्द्व या अन्तर्विरोध नहीं, बल्कि समन्वय देखने को मिलता है। इस उपलब्धि में अफ्रीका और एशिया के अन्य देशों के लिए भी इस स्थिति को आदर्श लक्ष्य बनाया है। यह काम हमेशा सहज नहीं रहा। इस बात से आज तक कठिनाई होती है कि अनेक नये अफ्रो-एशियाई राष्ट्र इन देशों जैसी अनवरत समृद्ध परम्परा के उत्तराधिकारी नहीं हैं।

अफ्रो-एशियाई देशों के उदय के कारण (Rise of Afro-Asian Countries)

चीन, जापान और भारत तीनों के अनुभव से यह बात साफ बलवती है कि इन कृत्रिम सम्राज्यों के नव जागरण के कुछ बुनियादी कारण थे। इन तीनों जगह कुछेक बन्धुनिष्ठ कारणों के प्रभाव ममान रहे हैं। अन्य अफ्रो-एशियाई देशों के अम्पुदय में भी ये प्रभाव साफ देख जा सकते हैं। अफ्रो-एशियाई देशों के उदय के प्रमुख कारण निम्नांकित हैं।

1. पश्चिमी शिक्षा का प्रसार (Spread of Western Education)—इस बार में दो बातें नहीं कि उपनिवेशवाद की समाप्ति और अफ्रो-एशियाई देशों के उदय में सबसे प्रमुख योगदान पश्चिमी शिक्षा के प्रसार का रहा है। मले ही कहें यह शिक्षा किसी श्रेष्ठ वर्ग (Elite) ने विशेषाधिकार या सुविधा के रूप में प्राप्त की और कहीं औपनिवेशिक प्रशासकों ने इसे अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए घोषा। परिणाम देर मकर एक जैसा देखने को मिला। पश्चिमी यूरोपीय इतिहास एवं राजनीति से परिचित होने के बाद इन लोगों का प्रबुद्ध होना स्वाभाविक था। यूरोपीय पुनर्जागरण, औद्योगिक क्रांति तथा वैज्ञानिक प्रगति, फ्रांसीसी क्रांति के बाद शोषण के अन्त आदि के व्यापक रूप से प्रेरणादायक प्रभाव पड़े। चीन, जापान और भारत के अलावा इण्डोनेशिया, हिन्द चीन तथा अफ्रीका में भी जगह-बे-ही राजनेता सफल हुए। बाह्य उन्होंने हिंसा का मार्ग अपनाया जो या अहिंसा का, जो अपने उत्पीड़कों से उनकी भाषा मुहावरों में बात करने में समर्थ थे।

2. आधुनिक टेक्नोलोजी एवं नई संचार माताप्रात व्यवस्था (Modern Technology & New Communication and Transportation System)—पश्चिमी शिक्षा की ही तरह उपनिवेशवादी अपनी हित साधक यादनाओं की पूर्ति के लिए आधुनिकतम टेक्नोलोजी अपनाएँ का विवश थे। डाक, तार, रेल गाड़ियाँ आदि सामान जनता को अप्रत्याशित रूप में जाह्नन वाले मिष्ट हुए। एक ओर इन्होंने जनता का गतिशील बनाया तो दूसरी ओर वर्ग के वर्णमय भेदभाव का निर्जीव बना दिया। तार के बिना प्रेम और प्रेम के बिना आन्दोलन की बात साधना कठिन है। बिना रेलगाड़ियों के राष्ट्रवादियों के आन्दोलन, महासभाएँ आदि आयोजित नहीं किए जा सकते थे। बिना बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों और कच्चे कारखानों के नगरीकरण एक मपना ही बना रहता। हम सबके बिना अफ्रीका एक जल-कारण महाद्वीप ही बना रहता और एशिया एक अनवृक्ष पट्टी। वैज्ञानिक-तकनीकी साधना के उपकरणों के अभाव में अफ्रो-एशियाई देश एक-दूसरे में अपरिचित ही बन रहते।

3. प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव (Impact of First World War)—

पहला विश्व युद्ध यूरोप की प्रमुख औपनिवेशिक शक्तियों के संकीर्ण स्वार्थों के टकराव से उत्पन्न था। परन्तु इसमें मरने-खपने वाले सैनिकों की बहुत बड़ी संख्या अफ्रीका और एशिया से जुटायी गयी थी। ये 'सैनिक' बुनियादी तौर पर अशिक्षित किसान और मजदूर थे और उन्हें पहली बार गाँव-देहात की जमीन से अलग दुनिया देखने का मौका मिला। अपनी हानत (बुद्धि) की तुलना दूसरों की पृष्ठभूमि से कर वे कार्य-कारण सम्बन्ध सोचने के लिए विवश हुए। स्वदेश में औपनिवेशिक महाप्रभु और देशी जनता के बीच विचौलियों (जमींदारी) आदि के कारण औपनिवेशिक शासन का नवायव्ह उत्पीड़क चेहरा दिखाये रखना सम्भव था।

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान साम्राज्यवादी ताकत और उपनिवेश के बीच सम्पर्क हमेशा नहीं बनाये रखे जा सके और कच्चे माल, उत्पादन केन्द्र तथा मण्डी के बीच जो ताना-बाना बुना गया था, वह कमजोर पड़ गया। भारत जैसे देशों में स्थानीय आप्रान्त उद्यमियों ने स्वदेशी उत्पादन आरम्भ किया और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति तक यह बिरादरी महत्वपूर्ण स्वरूप स्वार्थ धन चुगी थी। इसका राष्ट्रवादी होना समझ में आने वाली बात है।

युद्ध की सामरिक जरूरतों ने औपनिवेशिक शक्तियों को इस बात के लिए विवश किया कि वे उपलब्ध समाधनों और प्रशासनिक प्रतिभा को उपनिवेशों से हटाकर मातृभूमि या पितृभूमि के लिए लगावें। युद्ध के बाद बहुत लम्बे समय तक आप्रान्त पुनर्निर्माण तथा छागित और मुख्यस्थानी की पुनर्स्थापना फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी आदि को व्याप्त रहे रही।

जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध के अनेक इतिहासकारों ने लिखा है—यह युद्ध मुख्यतः यूरोप में लड़ा गया और इसके दौरान औपनिवेशिक प्रतिद्वन्द्विता उपेक्षित ही रही। परिणामस्वरूप उपनिवेशों में वह चीज, हिन्द चीज हो या भारत, राष्ट्रवादी आन्दोलन व उपनिवेशवाद का विरोध, मजरी अपेक्षाहीन हो गये। कई जगह राष्ट्रवादी आन्दोलन का नेतृत्व इस अन्तराल में बदल गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गांधी जी का आधिपत्य इसका सबसे अच्छा उदाहरण है।

4. सोवियत क्रान्ति का प्रभाव (Impact of Soviet Communist Revolution)—सारे ही कुछ विद्वानों का मानना है कि रूसी बोल्शेविक क्रान्ति को प्रथम विश्व युद्ध ने निर्णायक ढंग से प्रभावित किया, लेकिन यह बात निर्विवाद है कि उपनिवेशवाद की समाप्ति और अफ्रो-एशियाई देशों के अन्तर्गत में सोवियत क्रान्ति ने अलग से महत्वपूर्ण योगदान दिया।

रूसी क्रान्ति के नेता लेनिन, त्रोत्स्की आदि सर्वप्रथम वर्गों की अन्तर्राष्ट्रीय एकता में आस्था रखते थे और साम्राज्यवाद को पूँजीवाद की सबसे ऊँची सीढ़ी मानते थे। उन्होंने पूँजीवाद के उन्मूलन के लिए वर्ग संघर्ष का रास्ता मुझाया था। इसी कारण सैदान्तिक रूप से उपनिवेशवाद से उनका जन्मजात वैर था। मता ग्रहण करने के साथ ही बोमिनतर्ग की स्थापना की गयी, जिसका एक प्रमुख उद्देश्य अफ्रीका तथा एशिया में क्रान्ति का निर्माण था। रूसी के उत्थापधान में वीरेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय जैसे लोगों ने साम्राज्यवाद-विरोधी लीज ना मठन किया। 1927 में मुम्बई में सोवियत-उत्प्रेक्षित जनता-राष्ट्रों का सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस मशहूर सम्मेलन में नेहरू जी ने भाग लिया और

तानमलाका तथा हट्टा आदि अन्य एशियाई राष्ट्रवादियों के साथ घनिष्ठ व उपयोगी सम्पर्क स्थापित किये।

बोमिननन के सचिवालय के साथ मानवेन्द्र नाथ राय तथा वीरोदिन जैसे प्रतिभाशाली लोग सम्बद्ध थे, जिन्होंने मैक्सिको, चीन और हिन्द चीन में राष्ट्रवादी और उपनिवेशवाद-विरोधी आन्दोलन को निर्णायक ढंग से प्रभावित किया।

5 सामाजिक व धार्मिक सुधारवादी आन्दोलन (Social and Religious Reformist Movements)—अफ्रीका तथा एशिया में राष्ट्रीय नवजागरण के साथ सामाजिक व धार्मिक सुधारवादी आन्दोलन अभिन्न रूप में जुड़े रहे। धार्मिक चेतन्य का आह्वान इसलिए जरूरी था कि औरनिवेशिक धार्मिक इसे घातक पड़ोयत्र न समझें और पारम्परिक सूत्रों व अवधारणाओं की दुहाई देकर जनता के वड़े स बड़े हिस्से को गतिमोल बनाया जा सके। इसके अनिरिक्त सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन, शिक्षा के प्रसार आदि के आधार पर राष्ट्रवादी एकता को अनायास विभिन्न दोरों में जैसे बोकमर बगावन, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार सम्बन्धी कई आन्दोलन तथा कुमियतांग पार्टी के गठन से ये भिन्न चरण तय किये गये। इसी तरह जापान में मामुराई व मामन्नी सत्कार की पुनर्प्रतिष्ठा तथा बाम्पोंआ सैनिक अकादमी की स्थापना उल्लेखनीय हैं। भारत में राजा राममोहन राय ने जिस काम का बीड़ा उठाया था, उसे ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, दयानन्द मरस्वरनी, विवेकानन्द, रानाडे और रवीन्द्र ठाकुर जैसे लोगों ने आगे बढ़ाया। इण्डोनेशिया भी इसका अपवाद नहीं रहा। बोक्रोमिनानो के तमाम विमुआ विद्यालय एक तरह में गुम्कुल और विश्व भारती के बीच की चीज थे। इन्होंने जनजागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। यह उल्लेखनीय है कि जहाँ-जहाँ चीन और भारत जैसे सामाजिक परिवेश में भाओ या गाँधी जैसे प्रतिभाशाली भूमि-मुक्तों की प्रेरणा में देसी सत्कार बचा रहा, वहाँ ध्यारण जन-आन्दोलन मजबूत हुए और उपनिवेशवाद-विरोधी स्वर-मस्कार स्वचीनता प्राप्ति के कई दशक बाद भी रोपे रह सके हैं। भित्रियों की दशा में सुधार, हरिजन और अन्य दलित वर्गों का उत्थान इमर अर्धे उदाहरण है।

6 शोषण-उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिक्षिया (Reaction Against: Exploitation and Repression)—पश्चिमी शिक्षा के प्रसार, राजनीतिक चेतना व आविर्भाव तथा आधुनिक टैक्नोलॉजी के प्रसार के समानान्तर चल रहे सुधारवादी आन्दोलनों ने इस बात के लिए जमीन तैयार कर ली कि उपनिवेशों में सामित-उत्पीड़ित जनता शोषण व अत्याचार के विरुद्ध मुखर हो सके। चीन में भाओ के नेतृत्व में गधार्ड के औद्योगिक श्रमिकों तथा मेनान के किसानों को पहली बार यह अहसास होने लगा कि वे ही राजनीति के केन्द्रीय विषय हैं। भारत में गाँधी जी ने किसी भी राजनीतिक अभियान की सफलता की मिकं एक जमीनी मानी थी—‘दरिद्र नारायण’ को खुशहाली और मुक्ति। बाद के वर्षों में इण्डोनेशिया में मुसलमानों ने इसी तरह औपन इण्डोनेशियाई किसान का रम्बाचित निरूपण करत हुए ‘मरहान’ का उल्लेख किया था। इन सभी परिकल्पनाओं में दो बाने माफ पना चलनी हैं। उपनिवेशों में सामाजिक व आर्थिक दुर्दशा के लिए साम्राज्यवाद का हो उत्तरदायी ठहराया गया (जैसे भारत में यह प्रक्रिया दाशमार्ड नौराजी जैसे विद्वानों ने बहुत पहले आरम्भ कर दी थी)—भारत की सम्पदा के दोहन के मिदालन (अर्थान् Drain Theory) के प्रतिपादन द्वारा। इसके साथ उही बात यह भी कि स्वधीनता प्राप्ति के बाद

देशी सरकार विपमता का अन्त करने के लिए कटिबद्ध रहेगी और नव-उपनिवेशवाद का भी विरोध करेगी। इन दोनों बातों ने अफ्रीकी व एशियाई जगत के राष्ट्रवादी खेमे को अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी आन्दोलन के निकट ला दिया। 1919 के बाद सोवियत संघ अन्तर्राष्ट्रीय समाजवाद का गढ़ माना जाने लगा और कोमिनतर्न के माध्यम से प्रतीकात्मक ढंग से ही सही, अफ्रीकी और एशियाई स्वतन्त्रता सेनानियों को प्रशिक्षित करने और सोवियत सहायता देने का काम शुरू किया गया। इस सैद्धान्तिक प्रेरणा के आधार पर कई जगह उपनिवेशवाद विरोधी संयुक्त मोर्चों का गठन किया गया और श्रमिकों, किसानों आदि को एक दूसरे की समस्याएँ-सामर्थ्य समझने का अवसर मिला। यही कारण है कि अक्सर वामपंथी छद्मन वाले आजादी की लड़ाई के नारे व मुहान्वरे अफ्रीका और एशिया में क्रमशः और उभरते होते रहे।

परन्तु यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि शोषण-उत्पीड़न के खिलाफ यह प्रतिक्रिया मित्र अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर निर्भर रही। नम्पारण में नील खेती-हरो के पारंपरिक शोषण के प्रत्यक्षदर्शी बनने के बाद ही गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन से जुड़े। माओ के मन में औपनिवेशिक शक्तियों से लोहा लेने की प्रेरणा तभी बसवती हुई जब उसने दुर्भिक्ष में लाखों चीनियों को मरते देखा और मर पर मज पक्षार्थ देने के लिए विवश पशुपत जीने वाले अपने बन्धुओं की स्थिति में मुधार का संकल्प किया। वास्तविकता यह है कि औपनिवेशिक शासन और साम्राज्यवादी व्यवस्था के परिणाम शोषक और उत्पीड़क ही हो सकते थे तथा सर्वैधानिक सुधार व प्रशासकीय परिष्काररूपी सौन्दर्य प्रसाधन कुरूपता और रोग की वेदना को छुपा नहीं सकते थे। जब तक राजनीतिक चेतना का प्रसार नहीं हुआ था और जन साधारण की शक्ति को सम्पूर्णित नहीं किया जा सकता था, तब तक अत्याचारों के प्रतिरोध की बात सोची नहीं जा सकती थी और जनक्रीश का छिटपुट विस्फोट किसी निश्चित आन्दोलन की शक्त नहीं ले सकता था। यह बात चीन, भारत, इण्डोनेशिया, हिन्द-चीन, मिस्र तथा अफ्रीका के अनेक देशों में समान रूप से देखी जा सकती है। राजनीतिक चेतना के एक निश्चित बिन्दु तक पहुँच जाने के बाद अत्याचारों के प्रतिरोध के लिए लोग अपने प्राणों की आहुति तक देने के लिए प्रस्तुत होने लगे। समझने में सुविधा की दृष्टि से यहाँ इन सारे कारणों को अलग-अलग गिनाया गया है। यथार्थ में ये सब एक-दूसरे से जुड़े हुए और एक-दूसरे को परस्पर पुष्ट करने वाले रहे हैं। अनेक बार पहले और बाद का अन्तर करना कठिन बन जाता है। मिसाल के तौर पर यातायात, संचार और प्रकाशन के तकनीकी साधनों के विकास ने आधुनिक पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का प्रसार तथा शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ नई तकनीक की माँग बढ़ी। इस प्रकार इस नई तकनीक की अपनाता सम्भव हुआ। यही बात सामाजिक व धार्मिक सुधार आन्दोलनों और शोषण उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध पर भी लागू होती है।

7. पारम्परिक उपनिवेशवादी ताकतों का क्षय (Decline of Traditional Colonial Powers)—कल-क्रम में इन विविध कारणों के सहिष्णु ने लगभग सभी औपनिवेशिक ताकतों को प्रतिपक्ष के साथ परामर्श के लिए विवश किया। भारतीय परिवेश में जन साधारण की दृष्टि में एक नंगे फकीर महात्मा गांधी का ब्रिटेन के शहसाह के साथ बैठकर बतियाना ही उसकी शक्ति-करिश्मे का प्रमाण था।

इसके बाद प्रादेशिक या जिला प्रशासन में औपनिवेशिक हुक्मानों के लिए अपने आतंककारी प्रमामण्डल को बचाये रखना बठिन हो गया। हिन्द चीन और इण्डोनेशिया में जहाँ औपनिवेशिक दमन अधिक क्रूर और बर्बर था, वहाँ सैनिक व पुलिस उपकरणों द्वारा नियन्त्रण बनाये रखना बेहद खर्चीला होता गया और औपनिवेशिक सम्पदा का दोहन ताम्रप्रद पूँजी निवेश में नहीं बदला जा सका। परिणामस्वरूप साम्राज्यवादी शक्तियाँ धीरे-धीरे खोखली और प्रभावहीन होती गयीं।

किन्तु पारम्परिक औपनिवेशिक शक्तियों के साथ वा सबसे बड़ा कारण द्वितीय विश्व युद्ध में उनका थक जाना रहा। हॉलैंड, फ्रांस तथा इटली को कभी न कभी पराजय का मुँह देखना पड़ा। ब्रिटेन जैसी ताकत विजयी होने के बाद भी इस स्थिति में नहीं रही कि अपने प्रभुत्व को बचाये रख सके। पूर्वी एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के उदय ने यूरोपीय साम्राज्यवाद का सफाया कर दिया। भारत में 1942 की उषल-पुषल, आज़ाद हिन्द फौज के गठन और नौसैनिक क्रान्ति ने उपनिवेशवाद के उन्मूलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ही यह घटनाक्रम सामरिक महत्व का बन सका। चीन में जापान के हस्तक्षेप का सामना करने के लिए साम्यवादियों और बुद्धिमानों के बीच साझेदारी हो सकी और अमरीकी पूँजीवादियों तक ने उन्हें सहायता दी। हिन्द चीन में जनरल जिप्सो के नेतृत्व में वियत-मिन्ह की छापाकारी और इण्डोनेशिया में जनरल नमुनियोन के नेतृत्व में हनी रणनीति का अपनाया जाना विश्व युद्ध के कारण सम्भव हुआ। मलाया में साम्यवादियों का उदय तथा बर्मा में जातीय बगावत, पश्चिम एशिया में शस्त्रों के प्रसार से पैदा हुई राजनैतिक अस्थिरता के लिए भी द्वितीय विश्वयुद्ध उत्तरदायी रहा।

अतः ही द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की बेला पर अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्व में कई उपनिवेश बचे थे, परन्तु यह स्पष्ट हो गया कि इनकी स्वतन्त्रता अब अधिक दिनों तक रोकी नहीं जा सकती। फ्रांस और हॉलैंड इस हालत में नहीं थे कि घर से दूर अपनी सैनिक शक्ति का निक्षेप कर सकें। ब्रिटेन भी अफ्रीका में बने रहने के लिए पहले जितना समर्थ नहीं था। 1945 के बाद भारत, चीन, इण्डोनेशिया और मिस्र जैसे अनेक बड़े अपने एशियाई देशों के राष्ट्र राज्य के रूप में उदय ने उनके पड़ोसियों को उपनिवेशवाद के विरुद्ध सघर्ष करने के लिए निरन्तर प्रेरित किया।

अफ्रो-एशियाई नवजागरण के विभिन्न चरण (Resurgence of Afro-Asian Countries)

अफ्रो एशियाई राष्ट्रों में राष्ट्रवाद के उत्थान तथा इसी के अनुसार अन्तराष्ट्रीय मंच पर इनकी सक्रियता का अध्ययन आसानी से विभिन्न चरणों में विभाजित किया जा सकता है। यह कालखण्ड विभाजन न सिर्फ आधारभूत कारणों बल्कि प्रवृत्तियों और परिणामों के सम्दर्भ में भी तर्कसंगत है। इसके प्रमुख चरण इस प्रकार हैं

प्रथम चरण 1905 से 1945 तक

स्वतन्त्रताभिनापी अनौपचारिक राजनय

दामवी नदी के आविर्भाव तक यह बात अध्धी तरह स्पष्ट हो चुकी थी कि

अफ्रीका और एशिया को अनिश्चित काल तक गुलाम नही बनाये रखा जा सकता। आर्थिक शोषण और सामाजिक उत्पीड़न की स्थिति लगभग वसह्य बन चुकी थी। पश्चिमी शिक्षा तथा आधुनिक टेक्नोलॉजी के प्रभाव से राजनीतिक चेतना तेजी से बढ़ी। सामाजिक व आर्थिक सुधारवादी आन्दोलनों ने राजनीतिक संगठन के लिए अभीष्ट अनुभव जुटा दिया था। प्रथम विश्व युद्ध और रोबियत संघ में बोल्लेविक क्रान्ति ने अपने-अपने ढंग से इस जागरण में हिस्सा बँटाया। आज लगभग 85 वर्ष बाद रूस पर जापान की विजय की याद धुपली पड़ गई है। इस बात को अनदेखा करना पठिन है कि यह घटना विश्व इतिहास में कितनी महत्वपूर्ण रही है। न केवल भारत में, बल्कि हिन्द चीन और इण्डोनेशिया में भी सर्वभारिक सुधारवादी सुगमुताहट आरम्भ हो चुकी थी।

इस दौर में राष्ट्रवादी आन्दोलनों का नेतृत्व पश्चिमी शिक्षा-सम्पन्न श्रेष्ठ वर्ग के हाथ में ही रहा, परन्तु उनके तौर तरीकों के प्रति असन्तोष भी भूखर होने लगा। प्रथम विश्व युद्ध में वफादारी के पुस्कार स्वरूप भारत में सुधारों की घोषणा कर साम्राज्यवादियों ने अपनी उदारता का परिचय देना चाहा। इसके साथ ही अमरीकी राष्ट्रपति विल्सन की आदर्शवादिता तथा राष्ट्र सभ की स्थापना में उपनिवेशवाद के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय जनमत तैयार करवाया। राष्ट्र सभ व्यवस्था में मंडेट (Mandate) प्रणाली अस्तनिहित थी, जिसके अनुसार कालक्रम में उपनिवेशवाद का शान्तिपूर्ण उन्मूलन करने का प्रयत्न किया गया। यह ध्यान दिलाने की जरूरत है कि रोबियत क्रान्ति और राष्ट्र सभ की स्थापना के पहले भी अनेक अफ्रो-एशियाई नेता अन्तर्राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए सक्रिय रहे। न केवल भारत से लाला हरबचान, राजा महेन्द्र प्रसाद, रास बिहारी बोस और मानवेन्द्र नाथ राय जैसे लोग मैक्सिको, कनाडा, जापान आदि तक पहुँचे बल्कि इसी दौर में हो ची मिङ्ग, चाऊ एन लाई, मोहम्मद हुसैन और सुलतान साहरिर सरीसे स्वतन्त्रता सेनानी फ्रांस और हॉलैण्ड में तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी आजादी की लड़ाई चालू रखने की कोशिश करते रहे। विदेश में ये अफ्रो-एशियाई नेता आपस में मिलते-जुलते रहे। वाकू व कुसेलम के सम्मेलनों में या स्पेनिय गृह युद्ध, चीनी घटनाक्रम, रोबियन प्रयोग को लेकर इनका मर्तक्य बार-बार झलकता रहा। इस चाँईथारे के आधार पर आगे चलकर अफ्रो-एशियाई एकता का चिन्तन्यास हुआ। यहाँ यह याद रखना चाहिये कि 1905 से 1939 तक के वर्षों में एशियाई राष्ट्रवादी ही मुखर रहे। अफ्रीका का प्रतिनिधित्व नाममात्र का और नगण्य रहा। यह पूरा दौर ऐतिहासिक पुनरीक्षण, सैद्धान्तिक तर्क-परामर्श तथा अपने मार्ग की चुनौतियों व अवचत्तों का, औरों के अनुभवों के साथ तुलनात्मक अध्ययन कर समुचित रणनीति के विकास का था। इस सिलसिले में नेहरू जी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। उनकी आत्मकथा का प्रकाशन अफ्रो-एशियाई देशों के समाम पढ़े लिखे लोगों में हृवचल मचाने वाला सिद्ध हुआ।

द्वितीय विश्व युद्ध के विस्फोट के साथ इस स्वतन्त्रताभिलाषी अतोपचारिक राजनय में वकायक व्यवधान पड़ गया और 1939 से 1945 तक के वर्ष एक तरह से बंजर रहे। भारत में नेहरू जी और उनके सहयोगी जेल में डाल दिये गये एवं चीन तथा हिन्द चीन में जापानी आक्रमण ने गृह युद्ध को प्रायमिकता दी। फिर भी जापानियों ने लगभग इन सभी जगहों में ब्रिटिश, फासीसी और डच औपनिवेशिक

व्यवस्था को ध्वस्त कर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए एशियाई राष्ट्रवादियों को अपना सहयोगी बनाया और युद्ध के बाद गुरुतर जिम्मेदारियाँ ग्रहण करने के लिए प्रशिक्षित किया।

दूसरा चरण 1945 से 1955 तक आजावादी स्वर

इस चरण की दो विशेषताएँ हैं। भारत की स्वतन्त्रता (1947) तथा चीन में साम्यवादी दल के सत्ता ग्रहण (1949) करने से एशिया का बहुत बड़ा हिस्सा गुलामी के जुए में मुक्त हो गया। इण्डोनेशिया और भियम भी स्वाधीन हुए। इस दशक में इन सभी देशों के आपसी सम्बन्ध मधुर रहे। उन्होंने मिलकर अफ्रीका तथा एशिया में उपनिवेशवाद को बचाव की मुद्रा ग्रहण करने के लिए विवश किया। 1945 के बाद हिन्द चीन में जन मुक्ति संग्राम छिड़ गया तथा मलाया में चीनी विप्लव के कारण अत्यातकाल की घोषणा करनी पड़ी। पूर्वी अफ्रीका में वह प्रदेश जो आज युगांडा, तंजानिया तथा कन्या की भूमि है, 'माऊ माऊ विद्रोह' की चपेट में आया। हिन्द चीन से लेकर अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्र तक मुक्ति सैनिकों ने शस्त्र उठा लिये। 1919 से 1939 तक के दो दशक यदि सर्वधानिक मुधारों, सिविल नाफरमानी और अहिंसक सत्याग्रह बाले थे तो युद्ध के बाद का दशक हिंसक सत्ता-समर्पण का था। इस दौर में अफ्रो-एशियाई एकता के साथ-साथ क्षेत्रीय विरादरी का स्वर भी उठाया जाने लगा।

इसके अलावा दो और मील के पथर आज भी स्पष्ट दखे जा सकते हैं। इनमें एक भारत और चीन के बीच पचवीस समझौते पर हस्ताक्षर (1954) है तो दूसरा बाङ्गुम सम्मेलन (1955)। आपस में सम्बद्ध इन दोनों घटनाओं का आधार शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की अवधारणा थी। अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति, निरास्त्रीकरण और गुट निरपेक्षता इन दस वर्षों में अफ्रो-एशियाई राजनय के सबल रहे। नवोदित राष्ट्र 'राजनीतिक स्वतन्त्रता ही नहीं, आर्थिक आत्म निर्भरता भी चाहते थे जिसके बिना राजनीतिक स्वाधीनता अक्षत नहीं रह सकती थी। व यह बात मली भाँति समझते थे कि यदि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति नहीं बनी रहो तो उन्हें अपना आर्थिक विकास करने का अवसर नहीं मिल सकता। इस पूरे दौर में नेहरू जी ने निर्णायक भूमिका निमायी और मुक्तियों तथा नामिर की सहायता से राष्ट्र संध तथा राष्ट्रमण्डल के मंचों का सफल राजनीतिक प्रयोग किया।

इस प्रकार, इन वर्षों का मूल स्वर आजावादी रहा और अफ्रो-एशियाई राष्ट्रों में आपसी तनाव सनड तक नहीं आये। मावियत संध में स्टालिन की मृत्यु के बाद कम ने अफ्रो-एशियाई आन्दोलन के साथ अपनी महानुभूति बिना शर्त प्रकट की और कोरिया युद्ध में मध्यस्थता के बाद गुट निरपेक्षता मनी भाँति प्रतिष्ठित हो सकी।

तीसरा चरण 1956 से 1960 तक दुर्भाग्यपूर्ण टकराव

तीसरे चरण की विशेषता यह है कि अनेक एम अफ्रो एशियाई देश, जो आजादी के लिए लड़ते नहीं सक्ते जाते थे, महत्वपूर्ण आन्तरिक परिवर्तनों और अन्तर्राष्ट्रीय दबाव के कारण आजाद हुए। 1954 में जेनेवा सम्मेलन के बाद हिन्द चीन के राज्या का मविष्य एक तरह से तय किया गया था। 1956 में ब्रिटेन और फ्रांस के स्वतंत्र सम्बन्धी दुस्मादमिक अभियान के बाद पश्चिम एशिया में नई व्यवस्था

के बारे में सोचना आवश्यक हो गया। पूर्वी अफ्रीका के अनेक देश इस बीच स्वतन्त्र हुए। परिणामस्वरूप सपनिवेशवाद-विरोधी संघर्ष का एक प्रमुख मुद्दा रंगभेद तथा नस्लवाद का विरोध बन गया। इन सब बातों ने अफ्रो-एशियाई देशों को काफी प्रभावित किया। एक तो जिन राष्ट्रों ने अपने बाहुबल से स्वतन्त्रता अर्जित की थी, उन्होंने सुधार की अपेक्षा क्रान्ति पर बल दिया और अपने तेवर निरन्तर जुझारू रखे। नेहरू जी जैसे नेताओं का नई पीढ़ी के लोगों के साथ सवाद बनाने रखना कठिन होता गया। साथ ही अफ्रो-एशियाई देशों के आपसी तनाव और हितों के टकराव धीरे-धीरे सामने आने लगे। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद, मामन्ती-राजसी अरब राज्यों तथा समाजवादी सैनिक अरब सरकारों के बीच टकराव, हिन्द चीन में जेनेवा व्यवस्था की असफलता आदि अनेक घटनाएँ इस बीच घटी, जिन्होंने अब तक चली आ रही आशावादिता को घूमिल कर दिया। अब तक यह भी स्पष्ट हो चुका था कि अधिक आत्मनिर्भरता का सपना कितना ही सार्थक एवं आकर्षक क्यों न हो, लेकिन कष्टमाध्य है। अफ्रीकी व एशियाई देशों की विदेशी महायत्ना पर निर्भरता बढ़ती ही चली जा रही थी। इसके रहते दूसरों को उपदेश देते रहना हास्यास्पद बन गया था। 1960 में कांगो संकट के साथ यह बात प्रबल हो गयी कि समुक्त राष्ट्र सच बड़ी शक्तियों के सत्ता-संघर्ष के कारण कितना कमजोर हो चुका है। कुल मिलाकर मध्य-उपनिवेशवाद की चुनौती तथा शीत युद्धजनित स्थानीय संकटों के कारण अफ्रो-एशियाई एकता खण्डित होने लगी। सोवियत-चीन विग्रह के बाद चीन का माओवादी नेतृत्व अपने को एक स्वतन्त्र शक्ति-केन्द्र के रूप में स्थापित करने के लिए उद्यत हुआ। चीन ने अफ्रीका तथा एशिया के तथाकथित प्रगतिशील देशों को अपने 'खेम' में लाने का प्रयत्न आरम्भ किया। इन सब परिघटनों का प्रभाव बेलग्रेड में आयोजित पहले गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन (1961) में देखने को मिला, जहाँ 'नव उपनिवेशवाद बनाम अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति' को लेकर एक बड़ी बहग और बुर्नाम्यपूर्ण मुठभेड़ नेहरू जी और मुकारों के बीच हुई। मित्र मुकारों ने अफ्रो-एशियाई एकता व भाई-चारे को टुकटाते हुए नये उदयमान राष्ट्रों को समठित करने वाला आह्वान किया और उप-पक्षियों के इस जमघट से नेहरू जी के पुराने प्रशस्तक एन्क्रूसा जैसे लोग भी चले गये।

दिसम्बर, 1960 में समुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने उपनिवेशवाद के उन्मूलन सम्बन्धी अपना प्रतिष्ठित प्रस्ताव भारी बहुमत से पारित किया। वास्तव में यह यथार्थ-स्थिति की औपचारिक स्वीकृति थी। परन्तु इससे यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि उपनिवेशवाद की चुनौती समाप्त हो गयी और अफ्रो-एशियाई देशों का अभ्युदय सर्व स्वीकृत हुआ। हाँ, इतना अवश्य है कि इस आन्दोलन की दिशा और स्वर दोनों महत्वपूर्ण ढंग से बदल गये।

चौथा चरण 1961 से 1975 तक :
हताशा के बाद नये उत्साह का संचार

1961 में ऐसी दो घटनाएँ हुई, जिन्होंने अफ्रो-एशियाई एकता को मुकसान पहुँचाया और यह प्रकट निषा कि अफ्रो-एशियाई राष्ट्रों का अभ्युदय एक छलावा सा था। भारत-चीन सीमा संघर्ष ने दो प्रमुख एशियाई राष्ट्रों की प्रतिद्वन्द्वी ही नहीं, शत्रु के रूप में पेश किया। मले ही अधिकांश गुट निरपेक्ष राष्ट्र इस मुठभेड़ में तटस्थ रहे,

किन्तु व्यक्तिगत पक्षधरता के आधार पर वे अलग-अलग घटो में बँट गये। साथ ही, क्यूबाई मिसाइल मकट (1962) ने यह तथ्य रेखांकित किया कि मानव जाति का भविष्य गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के अभ्युदय के साथ नहीं, बल्कि महाशक्तियों के बीच आतंक के सन्तुलन के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ा है। 1962 के बाद अमरीका-रूस सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख वेन्द्र बन गये। उनके बीच 'होट लाइन' के माध्यम से सीधा राजनयिक सवाद आरम्भ होने बाद सदाशायी भध्यस्थों की आवश्यकता नहीं रही और न ही उनके विकास की समस्याओं के बारे में सोचने की कुर्मत किसी को रही।

1950 के दशक के मध्य से अफ्रो-एशियाई राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सच में सक्रिय रहे। उन्होंने इस संगठन में अपनी क्षमता का परिचय दिया। 1960 में कांगो सफ्ट के बिसफोट के बाद संयुक्त राष्ट्र सच स्वयं महाशक्तियों के बीच संघर्ष का अखाड़ा बन गया और कांगो सैनिक अभियान के खर्च ने इस पर कमरतोड़ बाझ डाल दिया। इस घटनाक्रम ने अफ्रो-एशियाई देशों के प्रभाव को कम किया।

यहाँ दो महत्वपूर्ण बातों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। अनेक छोटे-छोटे अफ्रो-एशियाई देशों में जनतन्त्र का जन्म हुआ और सैनिक तानाशाही एवं पारिवारिक अधिनायकवाद ने अपनी जड़ें जमाना आरम्भ किया। घाना में एन्क्रूमा का क्रायली भ्रष्टाचार, इण्डोनेशिया में सुकार्णो की तुनुक्रमिजाजी व खर्चनशीनी और नेपाल में जनतान्त्रिक प्रयोग की विफलता सब इसी के लक्षण थे। कही निर्देशित जनतन्त्र (Guided Democracy) तो कही बुनियादी जनतन्त्र (Basic Democracy) को सुझाया गया कही सेना ने 'मुपती' पहन ली तो कही निरंकुश शासन ने कृपापूर्वक जनता को 'राष्ट्रीय पचायत' का उपहार दिया। राजनीतिक अस्थिरता के इस सत्रमण काल में बाहरी शक्तियों के लिए हस्तक्षेप सहज हुआ। साथ ही, नवोदित राष्ट्रों की स्वाधीनता में कटीनी हुई। इस प्रकार विनी भी तानाशाह की गद्दी को सफ्टपलत करना और उस पर दबाव डालना अपेक्षाकृत आसान हुआ।

इसके साथ-साथ अफ्रो-एशियाई देशों में विकास कार्यक्रम गड़बड़ हो गये और विदेशी सहायता पर इन देशों की निर्भरता बहुत तेजी से बढ़ी। 1964-65 तक स्वयं भारत बहुत बड़ी सीमा तक विदेशी सायात्र के आयात पर निर्भर था। इण्डोनेशिया का दिवालियापन जग जाहिर हो चुका था। मिस्र में नासिर की दरिद्रता और पूर्वी अफ्रीकी देशों की विपन्नता किसी से छिपी नहीं रही। इसके विपरीत अनेक देश ऐसे थे जो सौभाग्यवश सामरिक महत्व के प्राकृतिक ससाधनों के स्वामित्व के कारण यथायक समृद्ध हो गये और अपनी खुशहाली और मकलता के नदों में अपने अभागों विरादरों के साथ उठने-ढँठने से नतराने लगे। मऊरी अरब, ईरान, मलेशिया व सिंगापुर हमी खेणों में रखे जा सकते हैं। इनमें से अनेक जैसे फिनीपीन्स, दक्षिण कोरिया आदि बेहिचक पश्चिमी पूँजीवादी व्यवस्था को अपना चुके थे। राजनीतिक जनतन्त्र के जमाव में इन देशों के राष्ट्रीय हित न्यस्त स्वार्थों के लिए ही परिमाणित किये जाने रहे और अक्सर अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर अफ्रो-एशियाई देशों का आपसी टकराव देखने का मिला। विडम्बना तो यह है कि नई अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की तलाश में भी इस अन्तर-विरोध को तूल दिया और अफ्रो-एशियाई देशों की जमान को विकासशील, अर्द्ध-विकसित, अल्प-विकसित और पिछड़े-श्री में बाँटा।

इसके अतिरिक्त अल्जीरिया में सदास्थ-शान्ति की सफलता, ब्यूटा में उग्र भावसंवादियों द्वारा सत्ता ग्रहण करने और वियतनाम युद्ध में निरन्तर तेजी से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में दो स्पष्ट, परस्पर-विरोधी अभिगम—सुघातवादी और शान्तिकारी—अफ्रो-एशियाई देशों के सामने प्रकट हुए। यह उल्लेखनीय है कि यह मिर्फ़ देलप्रेड सम्मेलन में नेहरू-सुकार्णो मुठभेड़ की परिणति नहीं थी, बल्कि परवर्ती वर्षों में नवोदित राष्ट्रों में राजनीतिक विकास की जटिलता से उपजे तमाम तनावों का ज़ासद सन्निपात था। इसको महाशक्तियों के बीच बड़े तनाव ने विस्फोटक रूप दिया। इससे अफ्रो-एशियाई अस्मिता की पहचान धुँधली हुई। इतने एक बड़ी सीमा तक अफ्रो-एशियाई अम्युदय को झुठला दिया। यह स्थिति कमोवेश 1961 से 1968-69 तक चली। अनेक महत्वपूर्ण अफ्रो-एशियाई देशों में इस बीच महत्वपूर्ण सत्ता परिवर्तन हुए। भारत और इण्डोनेशिया में नेहरू तथा सुकार्णो का स्थान ऐसे उत्तराधिकारियों ने लिया, जिनके लिए अफ्रो-एशियाई विरासदी, उसका नाईबारा व उसकी एकता विदेश नीति निर्धारण में प्राथमिकता-प्राप्त विषय नहीं थे।

जिस समय अफ्रो-एशियाई तन्दर्भ में हताशा-निराशा का स्वर प्रमुख था, उस समय घटनाक्रम एक बार फिर तेजी से बदला। अफ्रो-एशियाई अम्युदय में पुनर्जीवन का संचार हुआ। 1967 में अरब देशों और इजरायल के बीच तीसरा युद्ध हुआ। इसमें इजरायल ने मिस्र को चुरी तरह पराजित किया और बहुत बड़े अरब भू-भाग पर कब्ज़ा कर लिया। इसमें न केवल मिस्र, बल्कि अनेक अफ्रो-एशियाई देशों को अपनी सैनिक दुर्बलता और आर्थिक असमता का महसूस हुआ। इन युद्ध से बहुत बड़ी सस्या में फिलस्तीनी बिस्थापित हुए और वे अन्य अरब राष्ट्रों में शरणार्थी बन गये। फिलस्तीनी हर जगह उत्पीड़ित-गोपित होते रहे। उन्होंने यह बात आत्ममान कर ली कि रास्त्रों का सहारा लिये बिना न तो वे अपने राष्ट्र को वापस कर सकेंगे और न ही खोया हुआ आत्म-सम्मान। सैनिक और आर्थिक साधनों के अभाव में उनके सामने सिर्फ़ छापाकारी का रास्ता उपलब्ध था। 1967 के बाद फिलस्तीनी मुक्ति संगठन के 'अल फतह' नामक जुझारू गुट ने लोकप्रियता प्राप्त की और हवाईरण-अपहरण तथा 'शत्रुओं' की आतंकवादी हत्याओं की बाढ़ ली आ गयी। यानिर अराफ़ात, जाज़ हवास, लैला खाविद आदि के नाम विद्वद्विख्यात हो गये। म्यूनिख ओलम्पिक में यह बात सामने आयी कि अफ्रो-एशियाई जगत में राष्ट्रवाद और शान्ति की प्रेरणा अब भी सशक्त है और इसको दबाने के प्रयत्न विफल देशों को भी अपनी लपटों में झुलमा सकते हैं।

फिलस्तीनियों की गतिविधियों ने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरोध की भावना के प्रसार को प्रोत्साहित किया। फिलस्तीनी मुक्ति संगठन मूलतः धर्म निरपेक्ष और समाजवादी रूढ़ान बना है। जिन देशों ने फिलस्तीनियों का समर्थन किया, उनके प्रति तो यात्तिर अराफ़ात और उनके अनुयायी आभार मानते ही रहे, अन्यथा भी जन-मुक्ति मञ्चन में उनकी सक्रिय हिस्सेदारी रही। फिलस्तीनी पक्ष का समर्थन करने-करने अफ्रो-एशियाई एकता रूढ़ हुई।

1969 तक चीन में मार्क्सवादी शान्ति का ज्वार पूरे उफ़ान पर आ चुका था। इन परिवर्तन ने जहाँ एश और माओवादी नेतृत्व का ध्यान अन्तर्राष्ट्रीय राजनय में हटारकर आन्तरिक समस्या के समाधान की ओर लौटाया, वही इस बात को भी रेखांकित किया कि एशिया में इतने बड़े पैमाने पर होने वाला कोई भी

घटनाक्रम पूरे विश्व के सन्दर्भ में भी ऐतिहासिक हो सकता है। इस दौर में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के सन्दर्भ में तमाम पश्चिमी अवधारणाओं को नकारा गया और निरन्तर क्रान्ति की परम्परा के साथ-साथ नए माओवादी क्रान्तिकारी मानव की आदर्श कल्पना प्रस्तुत की गयी। इन्हीं दिनों सोवियत-चीन विग्रह खुलकर सामने आया और अफो-एशियाई देश सोवियत या चीनी पक्षधर के रूप में बँटने लगे। परन्तु इसमें अफो-एशियाई देशों की एकता खण्डित नहीं हुई। उनमें आपसी वाद-विवाद कितना बढ़े कथो न हुआ हो, पश्चिमी साम्राज्यवादी तबके के विरुद्ध असन्तोष और आक्रोश पूर्ववत् बना रहा। बल्कि चीन की 'महान सांस्कृतिक क्रान्ति' ने एक खास तरह से सरकार से अलग जनता के स्तर पर अफो-एशियाई एकता को पुष्ट किया। इसका एक उदाहरण भारत में नक्सलवादी उपल-पुल है, जिसके दौरान इस तरह के नारे लगाये गये—'चेअरमेन माओ, हमारे चेअरमेन'। दूसरी मिसाल इण्डोनेशिया और फिलीपींस की है, जहाँ साम्यवादी दल और प्रतिवधित साम्यवादी गुट चीन का समर्थन करते थे और अपना विश्व-दर्शन चीनी नेताओं की घोषणा के अनुसार ढालते थे। इन्हीं वर्षों में चीन ने सामरिक उपयोग की दृष्टि से बड़े पैमाने पर अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहायता कार्यक्रम आरम्भ किया। तजानिया में रेलमार्ग विद्यमान, नेपाल में मोटर मार्ग बनाना, और श्रीलंका को दी गयी खाद्यान्न सहायता इसी श्रेणी में रखे जा सकते हैं।

उप क्रान्तिवादिता के स्तर को प्रोत्साहित करने वाली एक और प्रमुख घटना वियतनाम संघर्ष थी। यो यह जनमुक्ति संग्राम तीन दशक तक चला और इसमें क्रमशः कई उत्तर-पड़ोस आये, फिर भी युद्ध में नुससता 1968 के बाद ही आयी। अमरीका द्वारा नागरिक ठिकानों पर बमबारी, वनस्पति नाशक रासायनिक अस्त्रों का प्रयोग तथा 1968 से 1973 के बीच हिन्द चीन में बड़े पैमाने पर अत्याचार देखने को मिले। माइ लाई बाइ जैसी अमानुषिकता इसमें पट्टे अवलम्बनीय थी। अमरीकियों का वादादम्बर यह बात छिपाने में असफल रहा कि अहकारी गोरों लोग अस्त्र वियतनामियों को दूरसे दर्ज का प्राणी समझते हैं। इनके विरुद्ध तमाम एशिया और अफ्रीका में व्यापक जन-आक्रोश फैला, उन देशों में भी जिनकी कठपुतली सरकारें वियतनाम में अमरीकी हस्तक्षेप का समर्थन कर रही थी।

जिम जीवट और जुझारु रणनीति से नग्रा मा वियतनाम एक महाशक्ति को हलदल में फँसाने में सफल हुआ, वह अन्य सभी उत्पीड़ित शोषित जनता के लिए प्रेरणा की चीज थी। 1969-70 तक हो ची मिन्ह तीसरी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों में से एक थे। वियतनाम में सामन में सोवियत संघ और चीन तक आपसी बैर भुला बैठे। ब्रिटेन जैसे पूँजीवादी देश और स्पष्ट अमरीका में भी बटोड़ रसेल, चोमस्की व मेरी मेकार्थी जैसे लोग अमरीकी नीतियों का खुलकर विरोध करने लगे। पश्चिमी देशों की सरकारों ने वियतनाम के बहाने ही मही, एशिया के बारे में महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय शोध की जड़न ममझी। वियतनाम युद्ध और चीन की सांस्कृतिक क्रान्ति को वृहत्तर एशियाई सन्दर्भ में रखकर व्याख्यायित किया गया। यह ठीक भी था। प्रकाशान्तर में ही मही, हमने भी अफो-एशियाई एकता और माई-चारे का अहमाम बढ़ाया।

इन्हीं वर्षों में अफो-एशिया के सामर्थ्य, इसकी रचनात्मक सम्भावना, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में इन दो महाद्वीपों के महत्व को हलकाने वाले युद्ध और

परिवर्तन हुए। 1960 के दशक के अन्त तक जापान का आर्थिक पुनर्निर्माण लगभग पुनः सम्पन्न हो चुका था। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, ऑप्टिकल सामग्री, कारों, इस्पात आदि के उत्पादन में जापान अमरीका का प्रतिद्वन्द्वी बन चुका था। यह स्वाभाविक था कि दक्षिण पूर्व एशिया में जापान का आर्थिक प्रभुत्व आसानी से फैल गया। यूरोप और अमरीका में जापान का निर्यात तेजी से बढ़ा और उनके साथ उसका विदेश व्यापार सन्तुलन बिगड़ गया। एक ओर पश्चिमी देशों के मन में यह भय सताने लगा कि दोनों पीले मंगोल वंशज राष्ट्र चीन और जापान मिलकर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में गोरो का वर्चस्व सत्तम कर देंगे तो दूसरी ओर उन्हें यह चिन्ता सताने लगी कि भविष्यतः सध तथा जापान के बीच सहकारी समझौता (साइबेरिया के विकास सम्बन्धी) हो सकता है। हर्मन कान जैसे अनेक प्रतिष्ठित अमरीकी विद्वानों ने उस समय जापान की चर्चा एक उदीयमान राष्ट्र के रूप में करना आरम्भ कर दिया था। जिस तरह चीन में माओ के आविर्भाव ने एशिया की गरिमा बढ़ायी, उसी तरह जापान की आर्थिक सफलता ने एशियाई जनता का मान बढ़ाया।

ईरान के शाह की महत्वाकांक्षी साम्राज्यवादी योजनाओं ने एक विशिष्ट तरीके से अफ्री-एशियाई अभ्युदय को बिडम्बनापूर्ण तरीके से प्रमाणित किया। शाह तानाशाह थे, परन्तु अपनी अपार सम्पदा का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा पश्चिम के विकसित राष्ट्रों से शस्त्रास्त्रों के आयात पर खर्च करते थे। अनेकानेक बड़े-बड़े पश्चिमी शस्त्र विन्रेता ईरानी सरोप पर निर्भर रहने लगे। शाह ने पेन एम जैसी प्रख्यात वायु सेवाओं तथा न्यूयार्क में अनेक महँगी जागीरों को भी खरीदा। उप-निवेशवाद के उन्मूलन के बाद ऐसा पहली बार हुआ, जब कोई समृद्ध अर्धवैत गोरो का उपयोग परिचारकों-सेवकों के रूप में अपने बसबूते पर कर रहा था। मजेदार बात यह है कि ईरान जैसे 'प्रतिक्रियावादी' तत्त्व को माओ जैसे प्रगतिशील व्यक्ति का समर्थन भी प्राप्त था। चीन की सैनिक शक्ति और जापान की आर्थिक क्षमता दोनों का संयोग (कम से कम सम्भावना के रूप में) कई विद्वानों को तत्कालीन ईरान में दिखायी देता था। इस सदर्न में यह आशा करना असंभव नहीं था कि ईरानी पक्ष का भ्रमण कर अन्य समाज भी परम्परा का आधुनिकीकरण कर सकते हैं। ईरान के बाद तेल संकट के दौरान अन्य अरब राष्ट्रों ने भी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में खम ठोकना शुरू किया। अब तक चीन, भारत, जापान, ईरान, मिस्र और इण्डोनेशिया जैसे प्राचीन देश ही राजनय में सक्रिय थे, किन्तु अब सही मायनों में नवोदित राष्ट्र मंच पर आये।

1950 के दशक के उत्तरार्द्ध तक यह बात सामने आ गयी कि अन्धकार महाद्वीप के रूप में प्रख्यात अफ्रीका को अब रोशनी में आने से अधिक समय तक रोका नहीं जा सकता। 1950 से 1953 तक पूर्वी अफ्रीका में केन्या, युगांडा, टांगानिका वाले प्रदेश में माऊ-माऊ विप्लव तेज होता रहा। जोमो केन्याटा, जूलियस न्यरेरे और मिल्टन ओबोटे ऐसे नेता थे, जिन्हें मोटे तौर पर छोटे पैमाने पर गांधी और नेहरू के नमूने का समझा जाता है। इनकी शिक्षा-दीक्षा अंग्रेजी माध्यम से हुई थी। घाना ने क्यामे एन्क्रूमा भले ही अफ्रीका के पश्चिमी तट पर रहने वाले थे, किन्तु इसी परम्परा में आते हैं। ये पेशेवर लोग डाक्टर, वकील व अध्यापक थे और इनकी आग्या गणसत्त कांति में नहीं, शान्तिपूर्ण ससदीय परिवर्तनों में थी। तामरर पूर्वी अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों के उत्तम में मध्यम वर्ग उदीयमान था

और आर्थिक क्रियाकलाप की जड़ें गहरी जमी थी। इन सभी राष्ट्रों ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रमण्डल का सदस्य बने रहना स्वीकार किया। इन अखिल राष्ट्रों में औपनिवेशिकता के विरुद्ध सबसे अधिक आशोधन नस्लवाद (Racialism) को लेकर था। इन्हीं के राजनयिक दबाव से राष्ट्रमण्डल से दक्षिण अफ्रीका को निकाला गया और गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का एक बड़ा मुद्दा रणभेद नीति का विरोध बना।

मले ही एन्क्रूमा, न्येरेरे आदि भारत का अनुकरण कर स्वावलम्बी आर्थिक विकास और गुट-निरपेक्ष नीति का अनुसरण करना चाहते थे, किन्तु उनकी क्षमता और सामर्थ्य भारत जैसी नहीं थी। लगभग ऐसे सभी देशों की कमाई किसी एक ग्लोबल फर्मल या खनिज पर निर्भर थी, जिसके निर्यात, उत्खनन व शोधन का काम किसी बहुराष्ट्रीय निगम द्वारा किया जाता था। कालक्रम में ये राष्ट्र अपनी स्वाधीनता का स्वर स्पष्ट नहीं रख सके। फिर भी यह अनदेखी करनी बठिन है कि अफ्रीका का उदय युद्धोत्तर वर्षों की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसके पहले अफ्रीकी महाद्वीप का प्रतिनिधित्व सिर्फ मिस्र करता था, जो मूलतः एक अरब राष्ट्र था।

नीग्रो शक्ति का अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर प्रवेश दो तरह से महत्वपूर्ण था। एक तो इसके द्वारा यह घोषणा हुई कि अफ्रीकी जनता अपने यहाँ यूरोपीय देशों की बन्दरगाह अब नहीं चलने दगी। दूसरी बात, इसका अफ्रीका की आन्तरिक राजनीति में भारी प्रभाव पड़ा। यहाँ ये वर्षों से जब अमरीका में नागरिक अधिकारों वाला आन्दोलन चला था, जिसका नेतृत्व मार्टिन लूथर किंग कर रहे थे। मले ही अमरीका में यह युद्ध के बाद दाम प्रथा का उन्मूलन हो गया था, परन्तु व्यवहार में अखिलों को अपमानजनक विषमता का सामना करना पड़ रहा था। अफ्रीकी देशों की स्वतन्त्रता-प्राप्ति ने अमरीका के नीग्रो-व्यथा में नये उत्साह का संचार किया और उन्हें अनहमति व विरोध का स्वर मुलर करने की प्रेरित किया। अलाबामा जैसे राज्यों में स्मूली वसो में नस्ली भेदभाव समाप्ति का मुद्दा राष्ट्रपति चुनाव में महत्वपूर्ण बन गया। आगे चलकर हिन्द चीन के युद्ध में नीग्रो सैनिकों के भेज जाने एवं उनकी सहायता ने भी अमरीका में जातीय तनाव बढ़ाया।

अफ्रीका के दूसरे हिस्सों जैसे अल्जीरिया में भावगंवादी जनमुक्ति आन्दोलन और सरकार के गठन के बाद पश्चिम का विरोध स्पष्ट हुआ था। अफ्रीका में नवोदित राष्ट्र के महत्व को अनदेखा करना बठिन होना गया। अफ्रीका का उदय एकदम निपटव नहीं रहा। सभी अफ्रीकी समाज कवायली थे और एशियाई देशों की तुलना में आदिम। कवायली प्रतिस्पर्धाओं ने पश्चिमी जनतान्त्रिक व्यवस्था को आरोपित करना बठिन बनाया। कई जगह राजनीतिक दलों की अमफलता और नेताओं के भ्रष्टाचार न सैनिक तानाशाही को बढ़ावा दिया। इनके कारण सर्वनाशक युद्ध युद्ध भट्ट उठा। वागो दुम्का सबसे अच्छा उदाहरण है। वागो न इस बात को भी उजागर किया कि कम चीन-युद्धजनित दबावों के कारण बाहरी हस्तक्षेप नये देशों की स्वाधीनता को निरर्थक मिट कर सकता है और मधुत राष्ट्र मंच को अक्षम बना सकता है। वागो प्रसंग अधिक चर्चित रहा है परन्तु अमल में यह आगामी वर्षों में नाइजीरिया में घटने वाली त्रासदी का पूर्वान्गम्य भर था। लगभग इसी की पुनरावृत्ति अंगोला और मोजाम्बिक में भी हुई। यथास्थिति और परिवर्तन के

एकधरो का समर्थन पश्चिमी और साम्यवादी शक्तियों ने किया और अन्ततः सत्ता-परिवर्तन सत्तवीय प्रणाली के शान्तिपूर्ण ढंग से नहीं, बल्कि सशस्त्र क्रांति द्वारा ही हुआ। इसी सिलसिले में रोडे़शिया-ज़िम्बाब्वे का प्रकरण उत्तेजनीय है। इयान स्मिथ की हठीली मोरी सरकार ने ब्रिटेन की सलाह न मानकर एकपक्षीय स्वाधीनता की घोषणा की और बरसों तक एक हिंसक रस्साकशी को जारी रखा।

दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की स्थिति हमेशा अलग रही है—भू-राजनीतिक (geo-political) और ऐतिहासिक कारणों से दक्षिण अफ्रीका को 'क्वासिकी' नमूने का उपनिवेश नहीं समझा जा सकता। वहाँ रहने वाले गोरे अल्पसंख्यक हैं, किन्तु दुर्बल नहीं। यह भी ग़लत है कि गोरे अफ्रीकी लोगों के पाम लौटकर जाने के लिए कोई मातृभूमि नहीं। कहने का अभिप्राय यह कतई नहीं कि नामीबिया का शोषण-उत्पीड़न बाजिब है। हमारा अभिप्राय सिर्फ यह स्पष्ट करना है कि अफ्रीका का घुर दक्षिणी छोर शेष महाद्वीप से बुनियादी तौर पर फर्क होने के कारण अफ्रीकी नवजागरण का प्रमुख तत्त्व या। पाम-अफ्रीकी भावना का प्रसार—इसे मुक्त करने वालों में एन्क्रूमा पहले नेता थे। पेद्रिस लुमुम्बा, न्यरेरे आदि ने इसे पुष्ट किया। यद्यपि यहाँ तक कहा जा सकता है कि युगांडा के दादा इंदी अमीन जैसे कचकी-मगकी नेताओं तक ने इसका लाभ उठाते हुए पश्चिमी दुनिया के साथ मिडने के लिए सीसारी बुनिया के विपन्न देशों का मनोबल बढ़ाया। संक्रमण काल में इथियोपिया जैसे देशों की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं रही। सम्राट हेले सलासी का वंश चाहे कितना ही अकुशल मनो न रहा हो, नम्बो परम्परा के कारण उसकी अपनी एक गरिमा थी, जिसका लाभ पूरे महाद्वीप को मिलता रहा। इसी तरह व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के बावजूद एन्क्रूमा के रचनात्मक कृतित्व को नकारा नहीं जा सकता। अन्तर्राष्ट्रीय परामर्श में विकास की बुनियादी समस्याओं को सामरिक महत्व देना और नई अन्तर्राष्ट्रीय अव्यवस्था की तलाश में सक्रिय होना, अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर अफ्रीकी देशों के उदय के साथ ही यथोचित हुआ।

इसी सन्दर्भ में एक और बात महत्वपूर्ण है। अफ्रीका में उपनिवेशवाद के उन्मूलन की प्रक्रिया को अल्जीरियाई और क्यूबाई क्रांति की सफलता ने तनयन और प्रोत्साहन दिया। इस तरह अफ्रीका के नवजागरण ने एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमरीका को साथ लाकर तीसरी दुनिया के रूप में वास्तव में साकार किया। भारत जैसे देशों ने राष्ट्रमण्डल और संयुक्त राष्ट्र संघ में मस्त्ववाद और उपनिवेशवाद के विरोध में मुहिम जारी रखी तो अल्जीरिया ने हिंसक मुक्ति सैनिकों को शरण दी। क्यूबाई सैनिक अंगोला तथा मोजाम्बिक में छापामारों के साथ कंधे से कंधा मिड़ाकर लड़ते रहे, तो चीन ने स्वयं आर्थिक अभाव झेलते हुए भी तंजानिया जैसे देशों को बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता दी और उनकी क्रांतिकारिता की धार को कुद नहीं होने दिया।

अफ्रीका के सन्दर्भ में एक और टिप्पणी जरूरी है। अल्जीरिया, नाइजीरिया और सीरिया में तेल की खोज के बाद सभी अफ्रीकी देशों को दरिद्र याचकों के रूप में देखना असम्भव बन गया। तेल उत्पादक व निर्यातक राष्ट्रों के जमघट में एक बार फिर तीसरी दुनिया के सामूहिक हित और सामूहिक समस्याएँ रेखांकित हुईं। 1960 के दशक के अन्त तक अफ्रीका के अनेक नवोदित राष्ट्र भू-राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गये। अन्तर-महाद्वीपीय प्रयोगशाला के युद्ध मंचालन के लिए जिस

तरह की संचार-सम्पर्क प्रणाली की जरूरत थी, उसमें सोमालिया और इथियोपिया के सैनिक अङ्ग्रे अफ्रिका में डग से 'परमावश्यक' प्रतीत होने लगे। अंगोला में स्वाधीन सरकार का गठन पुर्तगाल में आन्तरिक राजनीतिक घटनाक्रम को निर्णायक ढंग से प्रभावित करने वाला सिद्ध हुआ। इसे एक तरह से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अफ्रीका के उदय का चरमोत्कर्ष समझा जा सकता है। इसके बाद राजनीतिक उथल-पुथल का केन्द्र एशिया और अफ्रीका से हटकर मध्य अमरीका में स्थानान्तरित हो गया।

भले ही तब से अब तक अफ्रीकी देशों के राजनीतिक-आर्थिक विकास में तीसरी दुनिया में अनेक लोगों को निराश किया है, परन्तु इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि जब एशिया के पुराने देश स्थिर-मुधारवादी दृष्टिकोण होने लगे थे, तब अफ्रीकी उल्लाह ने ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में तीसरी दुनिया का बोलबाला बनाये रखा था।

अफ्रीकी राष्ट्रों का भाईचारा और उनकी एकता एशियाई या अरब राष्ट्रों की अपेक्षा काफी ज्यादा मजबूत रही है। इसे क्वाइली नाते की मजबूती कहें या और कुछ, अफ्रीकी राष्ट्रों के संगठन का मतलब, उनकी सहकारिता, 'आसियान' (ASEAN) और 'लाफटा' (LAFTA) से कहीं अधिक स्पष्ट रहित है। इसी तरह मयुक्त राष्ट्र मध्य, राष्ट्रमण्डल और गुटनिरपेक्ष आन्दोलन में अफ्रीकी प्रतिनिधियों की अपनी साफ अलग पहचान है।

अफ्रीकी व एशियाई राष्ट्रों के अभ्युदय में 1973 अत्यन्त महत्वपूर्ण वर्ष रहा। अचानक इस तेल संकट के माय जोड़कर देखा जाता है और यह काफी हद तक सही भी है। परन्तु इसका वास्तविक महत्व 'यमकीपर युद्ध' के कारण है। अरब देशों और इजरायल के बीच इस चौथी सैनिक भिड़न में पहले तो इजरायल ने मित्र की सेनाओं का लगभग सफाया कर डाला, परन्तु जबकी हमले में एक बड़ी सीमा तक अपना खोया हुआ आत्म-सम्मान वापस पाने में सफल हुआ। इस युद्ध की एक बड़ी उपलब्धि यह रही कि अरब राष्ट्र पहले से कहीं अधिक एकता का अनुभव करने लगे। अब तक यही लगता था कि इजरायल से लड़ने-भिड़ने की जिम्मेदारी मित्र के नेतृत्व में सिर्फ सीमान्ती (frontline) राष्ट्रों की है। किन्तु अब तब सीरिया, जोर्डन और लीबिया ने भी रणक्षेत्र में बूढ़ पड़ने की तत्परता दर्शाना आरम्भ कर दिया। फिलिस्तीनी छापामारों की तेज गतिविधियों में भी अरब देशों के तेवर आश्रमणकारी बने। इसी युद्ध के बाद 'तेज' का प्रयोग एक राजनयिक अर्थ के रूप में करने की बात सोची जा सकी।

अन्तर्राष्ट्रीय तेल संकट का विस्तृत अध्ययन इस पुस्तक में अन्यत्र किया गया है, परन्तु यहाँ इतना जोड़ना जरूरी है कि इस परिवर्तन ने पहली बार पूँजीवादी देशों की तीसरी दुनिया की तानन का अहसास कराया। स्पष्ट था कि 'तेल शस्त्र' इजरायल से कहीं ज्यादा मुक्तमान अमरीका और पश्चिमी यूरोप के देशों और जापान को पहुँचाने वाला था। स्वयं अमरीका तेल का बड़ा उत्पादक है परन्तु पश्चिम एशियाई देशों में आन वार्न मरने तेल के अभाव में विलासितापूर्ण उपभोग की जीवन शैली यथावत नहीं रखी जा सकती थी। इसके अनिश्चित अपने मध्य मित्रों और निविरानुचरों को उनकी जरूरत के अनुसार तेल पहुँचाना अमरीका अपनी जिम्मेदारी समझता रहा। इसके अभाव में महानजि के रूप में अमरीका की छवि निश्चय ही

भूमित होती। हालांकि तेल सपत में थोड़ी कटौती कर अमरीका पर-निर्भरता से मुक्त हो सकता था परन्तु यूरोप और जापान के लिए ऐसा करना सम्भव नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार यूरोप और अमरीका यह सोचने को विवश हुए कि अरब राष्ट्र जाहिल, मूर्ख और विलासी ही नहीं, बल्कि उनको ताराज करने या रखने की भीमत उन्हें चुनौती पड सकती है।

इसके अलावा अमरीकी तेल शोधक कम्पनियों की खरबों डालर की सम्पत्ति-पूँजी मध्य पूर्व में लगी हुई है। पहली बार अमरीका को यह अहसास हुआ कि इस निवेश को निरापद नहीं समझा जा सकता। यह उल्लेखनीय है कि पहले पहल इन्हीं की हिफाजत के लिए 'तुरन्त तैनाती दस्ते' (Rapid Deployment Force) का प्रस्ताव किया गया। इसके अतिरिक्त अमरीका को यह चिन्ता सताने लगी कि कहीं बदले परिप्रेक्ष्य में पश्चिम एशिया का तेल सोवियत संघ के हाथ में लग जाये (यों सोवियत संघ भी अमरीका को तरह अपनी और अपने सन्धि मित्रों की जरूरतें पूरी करने में सलम है)।

यह सोचना गलत होगा कि तेल संकट के सामरिक और राजनयिक आयाम सिर्फ महाशक्तियों के सम्बन्ध में ही महत्वपूर्ण थे। तीसरी दुनिया के अनेक देशों में यह आशा जगी कि अब अपने विकास की जरूरतें पूरी करने के लिए वे सस्ते तामों में तेल जुटा सकेंगे। तेल की बड़ी कीमतों से जो पैट्रो-डालर अरब राष्ट्र कमायेंगे, उनका पुनः निवेश तीसरी दुनिया के देशों में किया जायेगा, विशेषकर इस्लामी देशों में धार्मिक भाईचारे के आधार पर यह आशा और भी बलवती रही। लीबिया, सऊदी अरब आदि ने पाकिस्तान, बंगलादेश इत्यादि को इसी आधार पर अमर्यादित सहायता दी।

पैट्रो-डालर की रकम इतनी बड़ी थी कि उसको अपने यहाँ लाने व जमा कराने के लिए यूरोपीय बैंको और पूँजीपतियों में होड़ सी लग गयी। इन प्रभावशाली निजी उद्यमियों-उद्योगपतियों ने अपनी सरकारों पर पश्चिम एशियाई नीति में परिवर्तन पर दबाव डालना शुरू किया। इस अनुभव से अफ्रो-एशियाई जमात के अनेक राष्ट्रों को यह सोचने की प्रेरणा मिली कि अपने प्राकृतिक संसाधनों के न्यायोचित वाम पाने के लिए वे भी जुझारू दंग से प्रयत्नशील हो सकते हैं। आगामी वर्षों में ऐसे सद्प्रयत्नों की जो भी नियति रही हो, किन्तु इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि 1973 के बाद तेल-संकट ने पान-अरब (Pan-Arab) भाई-चारा पुष्ट करने के साथ-साथ कई अर्थव्यवस्था की खोज को उत्साहवर्धक दंग से आगे बढ़ाया।

पाँचवाँ चरण 1975 से अब तक :

अफ्रो-एशियाई देशों की एकता का ह्रास

दुर्भाग्यवश अरब राष्ट्रों के आविर्भाव से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अफ्रो-एशियाई योगदान की जो आशा जगी, वह जवादा समय तक नहीं बनी रही। आज इस विस्मरण से कुछ लाभ होने वाला नहीं कि इसके लिए अरबों का जातीय अहंकार और धार्मिक कट्टरता जिम्मेदार रहे या राजनयिक अनुभवहीनता या पश्चिमी देशों के कुटिल पद्धत्यन्त्र। कटु गणार्थ यही है कि 1975 से आज तक अफ्रो-एशियाई एकता प्रमथाः मण्डित होनी रही है और इन राष्ट्रों की राजनयिक समता का ह्रास हुआ

है। इसके लिए व्यक्तिगत और सांस्कृतिक नहीं, बल्कि ऐतिहासिक (सामाजिक व आर्थिक प्रवृत्तियों से अनुकूलित) कारण जिम्मेदार रहे हैं। ये कारण इस प्रकार हैं।

1. हेल्सिंकी समझौता (Helsinki Agreement)—इस समझौते ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनय का केन्द्र-बिन्दु एक बार फिर यूरोप को बना दिया और एक तरह से सन्तान-मौलिकता की प्रक्रिया को औपचारिक मान्यता दी। सॉल्ट-एक (SALT-I) समझौते के बाद महाशक्तियों के बीच परमाणु सामरिक सवाद सबसे महत्वपूर्ण राजनयिक चुनौती समझा गया और यह स्वामाजिक था कि इसकी तुलना में अफ्रीका व एशिया के स्थानीय संकटों का अवमूल्यन हुआ।

2. अमरीका-चीन सम्बन्धों में सुधार (Normalisation of Relations between the U S and China)—जैसे यह प्रक्रिया 1972 में निकसन की चीन यात्रा से शुरू हुई, किन्तु इसके परिणाम 1975 के आस-पास ही प्रकट हुए। माओ की मृत्यु के बाद दैंग लियाओ पिंग ने सत्ता-सूत्र सँभाले और पथ-परिवर्तन की घोषणा करने में उन्होंने देर नहीं लगायी। उनकी चार महान आधुनिकीकरणों की घोषणा चलतुन सुधारवादी-मशीनवादी कार्यक्रम ही है। सबसे बड़ा और नाटकीय अन्तर यह पड़ा कि चीन एकाएक तीसरी दुनिया की बिरादरी से हटकर महाशक्तियों के साथ जा बैठा। चीन समार की सबसे ज्यादा आवादी वाला देश भर नहीं, बल्कि सैद्धान्तिक धुड़ और हठ के कारण ही अफ्री-एशियाई घटना-क्रम में बेहद प्रभावशाली रहा है।

3. जापान के विरुद्ध बग (Riots Against Japan)—इन्हीं वर्षों में जापान की आर्थिक सफलता का उल्टोडव बोझ अन्य एशियाई देश महसूस करते रहे। इण्डोनेशिया, थाईलैण्ड, मलेशिया आदि में जापानी व्यापारियों के शोषक आचरण के विरुद्ध आक्रोश का विस्फोट जातीय दंगों में हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध-काल की कटु स्मृतियाँ झुंझी गयीं। जापानी उद्यमियों का भ्रष्टाचार, उनका नस्ली अहंकार, पश्चिमी-अमरीकी सामरिक परिप्रेक्ष्य में उनकी घत-प्रतिघात साम्राज्यवादी तथा एशियाई पड़ोसियों के विकास-कार्यक्रमों की उपेक्षा आदि वास्तव में अखरने वाली बातें थीं। जापान के विकसित राष्ट्रों के 'ट्राई कोटिनेंटल' समूह में सम्मिलित हो जाने में भी अफ्री-एशियाई सेम को दुर्बल किया।

4. भारत में राजनीतिक अस्थिरता (Political instability in India)—1973 से 1975 के दौरान भारत में राजनीतिक उथल-पुथल चलती रही। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की। आपातकाल का अन्तराल समाप्त होने के बाद भी चित्र स्पष्ट नहीं हुआ। जनता सरकार का जीवन केवल दो वर्ष का रहा। चीन और जापान यदि अपनी विदेश-नीति और आर्थिक जरूरतों के दबाव में अफ्री-एशियाई बिरादरी से अलग हुए थे तो भारत आन्तरिक राजनीतिक घटना-क्रम के कारण एकांतवासी हुआ। इण्डोनेशिया और मिस्र (अफ्री-एशियाई समूह के अन्य दो प्रमुख राष्ट्र) ऐसे ही कारणों से अफ्री-एशियाई बिरादरी का नेतृत्व सम्मानन में असमर्थ थे। भारत के अतिरिक्त पड़ोसी पाकिस्तान के लिए भी ये वर्ष दुःखद रहे। वहाँ जनतान्त्रिक प्रयोग की असफलता के बाद मैनिफ तानाशाही ने अपनी जड़ें फिर से जमा लीं। 1975 में वंगनादेश में मुजीब की हत्या के बाद लगभग पूरा दक्षिण एशिया अग्रगण्यित ढंग में संकटग्रस्त हो गया। इस तरह न केवल दो सबसे बड़ी आवादी वाले देश (भारत व चीन), बल्कि प्रमुख

आर्थिक शक्ति (जापान) भी अफ्रो-एशियाई घटनाक्रम को दिशा देने में असमर्थ थी।

5. ओपेक की असफलता (Failure of the OPEC)—तेल-उत्पादक अरब राष्ट्र विपमता वाली अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बदलने की बातें तो करते रहे परन्तु स्वयं उन्होंने अपने यहाँ किसी भी रचनात्मक पहल की जरूरत महसूस नहीं की। विभिन्न शासक या सरकारें अपनी स्थिति निरापद रखने के लिए पश्चिमी हितों से समझौते करने को विवश हुए। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा विनिमय की जटिलता को समझने में असमर्थ होने के कारण ईरान के शाह जैसे चतुर लोग भी पश्चिमी बैंकों के शिकरे में फँस गये। पेट्रो डालर की पूंजी का लाभ पश्चिमी उद्योगपतियों को ही मिला। इस तरह तेल की बढ़ी कीमतों का जमा-खर्च बराबर ही रहा। पहले एशियाई, फिर अफ्रीकी राष्ट्रों के उदय ने अफ्रो-एशियाई एकता को बल दिया था। जब तक यह वेग धीमा पड़ा, अरब राष्ट्रों का आविर्भाव हुआ। इनकी राजनयिक सक्रियता शिथिल होने का संयोग अन्तर्राष्ट्रीय संकटों में वृद्धि के लिए हुआ।

6. अन्तर्राष्ट्रीय संकटों में वृद्धि (Increase in International Crises)—1975 के बाद अन्तर्राष्ट्रीय संकटों में निरन्तर वृद्धि हुई है। कम्प्यूटिवा में वियतनामी हस्तक्षेप और अफगानिस्तान में सोवियत सैनिक हस्तक्षेप ऐसी घटनाएँ हैं, जिन्होंने अफ्रो-एशियाई देशों को बुरी तरह विभाजित किया। यहाँ स्थिति ईरान-ईराक संघर्ष (1980) और कुवैत पर इराकी चरजे के मसले (1990) तथा अमरीका एवं अन्य राष्ट्रों द्वारा 1991 में उसके सामने के हस्तक्षेप पर भी लागू होती है। जिस तरह एकता में ध्वान्ति है, उसी तरह विभाजन दुर्बल बनाने वाला ही हो सकता है। इस प्रकार पिछले दशक के घटनाक्रम ने अफ्रो-एशियाई राष्ट्रों के अभ्युदय को एक बड़ी सीमा तक बेअसर किया है।

उपरोक्त सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि पिछले चार दशक में अफ्रो-एशियाई देशों की अनेक संयुक्त सफलताएँ रही हैं। परन्तु वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन इसी निष्कर्ष तक पहुँचाता है कि सभी सम्भावनाओं को सिद्ध नहीं किया जा सका। आज बदली परिस्थितियों में इनमें अनेक सम्भावनाएँ शेष भी नहीं रही। औपनिवेशिक काल में जिस तरह का संघर्षशील अफ्रो-एशियाई माईचारा सहज था, आज उसकी कल्पना करना कठिन है। स्वतन्त्र राष्ट्रों में हितों का टकराव और मतभेद स्वाभाविक भी हैं। आज अफ्रो-एशियाई राष्ट्रों का अभ्युदय एक सुसद स्मृति व आदर्श अवधारणा ही है। फिर भी, यदि यह हमें घातक फूट से बचाती है तो इसे उपयोगी समझा जाना चाहिए।

लातीनी अमरीकी देशों का अभ्युदय (Rise of Latin American Countries)

जिस महाद्वीप को लातीनी अमरीकी महाद्वीप कहा जाता है, वह मोटे तौर पर विस्तृत दक्षिण अमरीकी भू-भाग ही है। इस विवेक नामकरण (लातीनी अमरीका) का अभिप्राय उन देशों को अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण बतलाना है, जो औपनिवेशिक काल में लातीनी यूरोपीय देशों (स्पेन और पुर्तगाल) के प्रभाव में रहे। एक हद तक यह सही भी है। इस प्रदेश में इन देशों का नाता उसी वक्त से घनिष्ठ रूप में जुड़ा रहा, जब यूरोप के देश अणुकार के युग से उबर रहे थे और मसुद्दी, जहाजरानी तथा अन्य वैज्ञानिक आविष्कारों की सहायता में औपनिवेशिक विस्तार व साम्राज्यवादी

अभिप्राय पूरे उत्साह के साथ माये जा रहे थे। भू-मण्डल की गोलाई इस दौर में प्रमाणित हुई और पृथ्वी की परित्रमा भी तभी सम्पन्न हुई। मेगलन, कोलम्बस, वास्कोडिगामा के नाम आज विसर्ग के लिए अपरिचित रह गये हैं? दुर्लभ मसालों और सोन की खोज में दुस्साहसिक अन्वेषकों और नौसैनिकों की कहानी बड़ी रोमांचक है। इतिहास का यह चरण 'कनक्वास्टीडोर' (औपनिवेशिक विजेता) प्रकरण के नाम से जाना जाता है। इसके विस्तार में जाने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं, तथापि उन विशेषताओं की ओर ध्यान दिलाया जाना जरूरी है, जिनका प्रभाव समसामयिक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर स्पष्ट देखा जा सकता है।

लातीनी अमरीकी क्षेत्र में दोम देश हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं—ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे, मैक्सिका (सेंट्रल अमरीका), ग्वातेमाला, होन्डुरास, अटलांटिक, निकारागुआ, कोस्टा रीका, पनामा, चिली, बोलीविया, पेरू, इक्वेडोर, कोलम्बिया, वेनेजुएला, डोमिनिकन रिपब्लिक, हैती और क्यूबा। दक्षिण अमरीका के इन देशों में मूल ही चीन, भारत और मिस्र जैसी महत्त्वपूर्ण पुरानी सांस्कृतिक परम्परा के चिन्ह नहीं मिलते, तथापि इनकी स्थिति अफ्रीका और एशिया के अनेक अन्य देशों से काफी भिन्न है। मैक्सिको, चिली, पेरू, अर्जेंटीना, और ब्राजील में 'माया', 'इका', 'अज़टेक' आदि 'इण्डियन' जनजातियों ने सम्पत्ता के उत्कृष्ट भिन्न रूप लिए थे। इसका प्रमाण दैत्याकार पिरामिडों और माचू-पिचू जैसे विस्मृत भग्नावशेषों में मिलता है। इतिहासकारों का मानना है कि कृषि, पशु-पालन, खगोल विद्या, धातु विज्ञान, औषधि और भवन-निर्माण कला का बहुत अच्छा ज्ञान इन जनजातियों को था।

यूरोपीय शक्तियों के हाथों पराजित होने के बाद इन आदिवासियों की 'जीवनी शक्ति' (Vitality) का लगभग पूरी तरह ह्रास हो गया था और वे क्रमशः अपने अतीत के गौरव से पूरी तरह कट गये। औपनिवेशिक काल में यूरोपीय आक्रासियों, अफ्रीकी दासों तथा अरब-एशियाई व्यापारियों के जातीय अन्तर्-मिश्रण से आज लातीनी अमरीकी जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा वर्ण सफ़ेद (मैस्तीज़ो) का है। इनमें से अधिकांश लातीनी देशों के अनुमरण में, रामन बॅयोनिस सम्प्रदाय के अनुयायी हैं। इतनी आसानी से इस सम्प्रदाय का अमरीकी भूमि पर प्रत्यारोपण शायद इमीलिए हो सका कि आदिवासियों की मानसिकता, मर्यादित धर्ममत्ता के लिए तैयार थी और मूलतः अनुष्ठान प्रेमी थी। धर्म और राज्य का नाता इनके लिए अपरिचित नहीं था। इसी तरह औपनिवेशिक काल के पहले राजनीतिक समझौतों के समाधान के लिए हिंसा का प्रयोग और समाज का सामाजिक आधार पर वर्णभेद इन देशों के परिवेश के अभिन्न अंग रहे।

एक बहुत बड़ी सीमा तक लातीनी अमरीका की भौगोलिक स्थिति उच्च ऐतिहासिक और राजनीतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशान्त महासागर इसे यूरोप और एशिया से अलग करने के हैं। इससे भी दूर पश्चिमी यह ज़ररानि एक ऐसी बाधा प्रस्तुत करती है, जिसे आसानी से नापा नहीं जा सकता। इससे रहते इस प्रदेश की विपुल प्राकृतिक सम्पदा का दोहन और इसके माध्यम से व्यापार औरों के लिए आसानी से सम्भव नहीं। इतना ही नहीं स्वयं अमाज़ोन के घने जंगल, एण्डीज़ पर्वत शृंखला, दलदल, बेगवती नदियाँ और ब्रून की दुर्गमता इस महाद्वीप के देशों को

एक-दूसरे से अलग-अलग करते हैं। कुछ मिलाकर लातीनी अमरीका चाहे-अनचाहे अपने उत्तरी पड़ोसी के साथ ही घनिष्ठ सम्बन्ध बनाये रख सकता है।

ये तो अनेक लातीनी अमरीकी देशों ने ऐतिहासिक 'कान्तियो' द्वारा औपनिवेशिक प्रभुत्व से मुक्ति 19वीं शताब्दी से प्रारम्भ में ही प्राप्त कर ली थी। परन्तु उनकी स्वाधीनता उत्तरी अमरीका में किसी बड़ी शक्ति के संघर्ष और उदय तक ही निरापद रह सकती थी। 19वीं सदी के पहले चरण में मुनरो सिद्धान्त (Doctrine) का प्रतिपादन इस बात को प्रमाणित करता है। तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति मुनरो का मानना था कि यह सारा प्रदेश संयुक्त राज्य अमरीका की विशेष शक्ति (प्रभाव) का क्षेत्र है और वह इसमें किसी यूरोपीय शक्ति का हस्तक्षेप वर्जित नहीं कर सकता। संसार और आतायात के तत्कालीन साधनों को देखते हुए कोई भी यूरोपीय शक्ति इस खुलीता को तब करने की स्थिति में नहीं थी। जब कभी अङ्ग्रेजों ने महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने ऐसा करने की चेष्टा की भी तो उसे असफलता का चरण करना पड़ा (जैसे मैक्सिको में राजकुमार मैक्सिमिलियन को समर्पण देने की नेपोलियन तृतीय की चेष्टा)। कांस्रम में अधिक हिंसा के संयोग तथा संयुक्त राज्य अमरीका की राजनीतिक व सैनिक छत्रछाया के आकर्षण व प्रभाव के कारण ये सभी दक्षिण अमरीकी देश शीघ्र समार से कट-छट गये और उनके सम्बंध में स्वेच्छा से एकान्तवासी (Isolationist) बनते गये। यह स्थिति कभीबेश दूसरे विश्व युद्ध तक बनी रही। कहने को बाजीरा, मैक्सिको, बांसीबिया, अर्जेंटीना आदि में कान्तियो होनी रहीं, परन्तु इन्हें सैनिक बग़ावत कहना कहीं अधिक सटीक होगा। इसमें अधिकांश सरकारें कुलीनतन्त्र द्वारा समर्थित सैनिक तानाशाही थी, जिनके लिए एक विशेष शब्द जुटा (Junta) गड़ा गया है। संयुक्त राज्य अमरीका के सामरिक और व्यावसायिक हितों को पुष्ट करने का आश्वासन देकर ये शासक और ग्यस्त स्वार्थ स्वदेश में अपने को दशकों तक निरापद रख सके। इन वर्षों में लातीनी अमरीकी देशों के शिक्षित प्रचुर वर्ग का सांस्कृतिक इज्ञान अपने भूतपूर्व औपनिवेशिक महाप्रभुओं की ओर ही लगा रहा। इस स्थिति में अफ्रो-एशियाई घटनाक्रम से उनका अपरिचित और अलग रहना स्वाभाविक था। द्वितीय विश्व युद्ध एवं उसके अवसान के बाद शीघ्र युद्ध के आरम्भ में इस स्थिति को नाटकीय ढंग से बदला।

सबसे पहला महत्वपूर्ण परिवर्तन क्यूबा में हुआ। वहाँ बातीस्ता की सरकार छत्रछाया के कारण कुम्भगत थी। क्यूबा की राजधानी हवाना समूह अमरीकियों की ऐतजगह था। यूनाइटेड फ्रूट कम्पनी के साथ क्यूबाई बागान मालिकों के सम्झौते थे। इन कुलीन भूस्वामियों के अतिरिक्त क्यूबाई जनभाधारण की दशा बहुत अर्जर थी। क्यूबा द्वीप अमरीकी राज्य फ्लोरिडा के इतना निकट था कि इसे अमरीका का ही उपनिवेश समझा जाता था।

उत्पीड़क शासकों के विरुद्ध मध्यम वर्ग में वृद्ध रहा अगन्तोष निरन्तर फैलता गया। मध्यमवर्गीय जनता ने मार्क्सवाद के प्रभाव में तानाशाही से मुक्त होने का संकल्प लिया। इनमें युवा फिदेल् कास्त्रो और अर्नेस्टो चे गेवेरा प्रमुख थे। ये लोग जानते थे कि पारम्परिक मध्य शक्ति में वे कभी भी अपने विपक्षियों का मुकाबला नहीं कर सकते। अतएव उन्होंने छापामार (Guerrilla) रणनीति अपनायी। बहुत कम महयोगियों की साथ लेकर फिदेल् कास्त्रो ने इस रण का संचालन किया और 1959 में बातीस्ता को अपदस्थ किया। यह घटना नाटकीय ही नहीं, बल्कि

ऐतिहासिक भी थी।

भले ही इस समय अमरीका में 'युवा आदर्शवादी' राष्ट्रपति कनेडी, शासनाख्य थे, परन्तु उनका प्रशासन भी सीत युद्ध की डलेस वाली मानसिकता से मुक्त न था। उन्हे लगता था कि आज क्यूबा में तो बस दोष लातीनी अमरीकी देशों में 'लाल सहर' फैल जायेगी। फिदेल कास्त्रो की सरकार को बमजोर करने और गिराने का हर सम्भव प्रयत्न किया गया। विद्वानों का यहाँ तब मानना है कि यदि अमरीका ने क्यूबा की आर्थिक नाने जन्दी नहीं की होती तो शायद फिदेल कास्त्रो को सोवियत सभ की कारण में जाने की विवशता नहीं होती। अमरीकी असमर्थता आगामी महीनों में और भी कोशदायक ढंग से उजागर हुई। सी० आई० ए० (C I A) की पड़मण्डवारी नादानी और अदूरदर्शी सलाह के कारण कनेडी को 'वे ऑफ पिज' में प्रवागी क्यूबाई भाटे के सैनिकों के माध्यम से हस्तक्षेप के प्रयत्न में मूँह की छानी पड़ी और यह स्वीकार करना पड़ा कि क्यूबा अन्तर्राष्ट्रीय विधि में ही नहीं, वास्तव में सम्प्रभु स्वतन्त्र राष्ट्र है। इस घटना का बहुत प्रेरणादायक असर अन्य लातीनी अमरीकी देशों पर भी हुआ, जो अब तब अपने को संयुक्त राज्य अमरीका के अधीन और उसका अनुषर समझते थे। इस समय तब जब भी लातीनी अमरीकी प्रान्ति के नाक्यों की विरुदायली का गायन न होना था तो 'सीमोन डी बुलीयार' तब सदिपो पीछे लौटना पड़ता था या चीगधी गदी के पूवार्ध के मिथर गडने पड़ते थे। युद्धोत्तर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थ में उनकी विषयगनीयता बहुत कम थी। क्यूबा अरी फिदेल कास्त्रो के उदाहरण से न केवल अन्य लातीनी अमरीकी देशों को अपनी पराजितता-पराधीनता का बोध हुआ, बल्कि यह प्रेरणाहल भी मिला कि यथार्थपति को बदल जा सकता है। क्यूबा में प्रान्ति की सफलता के बाद औपनिवेशिक तत्वार बमजोर पड़ा और समाजवादी देशों के साथ 'नवोदिन' राष्ट्रों के सम्बन्ध अपेक्षाकृत घनिष्ठ हुए। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में समाजवादी रहान वाले गुट-निरपेक्ष क्यूबा के अभ्युदय के पड़ते बिनी में भी लगभग 150 वर्षों से प्रतिपादित मूनरो सिद्धान्त (Munroe Doctrine) को चुनौती नहीं दी। इसका महत्व अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। ये मारी बातें सिर्फ सैद्धान्तिक नहीं थी। फिदेल कास्त्रो के सहयोगी थे मेवेरा की प्रान्ति के निर्माण में पूरी आस्था थी और उन्होंने क्यूबा के बाद बोलीविया में दग प्रयोग को दोहराने का प्रयत्न किया। छह-मास वर्ष के सम्बन्ध में बाद उन्हें अपनी बलि देनी पड़ी। परन्तु इस बात को नहीं भगारा जा सकता कि पूरे दक्षिण अमरीकी महाद्वीप को अपनी प्रतर प्रान्तिवारिता से थे मेवेरा ने गरमा दिया। 1960 का दशक अमरीका के लिए बहुविध चिन्ता पैदा करने वाला रहा।

जिन देशों में क्यूबाई-बोलीवियाई नमूने की छापाभार रणनीति नहीं भी अपनायी गयी, यहाँ अमरीका और पश्चिमी पूँजीवादी व्यवस्था के प्रति असन्तोष व अग्रहमति का स्वर सुनर हुआ। पनामा में पनामा नहर के स्वामित्व एवं नियन्त्रण को लेकर 'राजनीति' सरगमियाँ बढ़ी तो मैक्सिको में दग भगवना ने सर उठाया कि घटे गमूढ़ पड़ोगी अमरीका से हर बत्त हर विषय पर सहमत होना आवश्यक नहीं। वेनेजुएला अब तब अपनी तेन सम्पदा का आधार पर अपेक्षाकृत स्वतन्त्र होने लगा था और उन्हे में नागरिक छापाभारी गरदद बनन लगी। पूरे दक्षिण अमरीकी महाद्वीप में कास्त्रो और वे मेवेरा सम्मानित प्रतीक पुष्प बन गये।

लातीनी अमरीकी देशों में राजनीतिक चेतना के आविर्भाव और उसके प्रसार में रोमन कैथोलिक पादरियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें अधिकांश युवा पादरी वामपंथी रुझान वाले थे और उनके अनुसार ईशू मसीह का धर्म किसी भी प्रकार की विपत्ति का समर्पण नहीं कर सकता। उन्होंने अपने चर्च में अत्यन्त तत्त्वों को महर्षि धारण दी। इसने अमरीका को और भी पेचीदगी में डाल दिया क्योंकि अब तक वह साम्यवाद के विरुद्ध ईश्वर को खड़ा कर अपने पक्ष में एक खास तरह का अन्वेषिवादी फैलाता रहा था। चर्च के साथ-साथ लातीनी अमरीकी विद्वानों की नई पीढ़ी ने इन देशों के सांस्कृतिक पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण रचनात्मक योगदान दिया। पाउलो फेरे जैसे विद्वानों ने 'Pedagogy of the Oppressed' (उत्पीड़ितों की दीक्षा) जैसी जन-चेतना को जगाने वाली पैनी राजनीतिक धार वाली पुस्तकें लिखीं। इवान इलिच जैसा ने सघटन व जन-गंचालन के नए तरीके गुंथाये। आर्द्र गुदर फ्राक और राउल प्रेबेरिण जैसे विद्वानों ने 'निर्भरता सिद्धान्त' का प्रतिपादन किया। यह गारा शोध एवं प्रसार न केवल लातीनी अमरीकी यथार्थ को प्रभावशाली ढंग से विश्लेषित करने वाला था, बल्कि छीसरी दुनिया के अन्य विकासशील देशों के साथ उनकी आत्मीयता को भी उद्घाटित करने वाला था। इस दृष्टि से 1960 वाले दशक को ही वास्तव में लातीनी अमरीकी अभ्युदय का काल माना जाना चाहिये क्योंकि पहली बार अमरीकी महाद्वीप से उत्तर क्षेत्र विश्व के सम्पर्क में उसकी अस्मिता प्रकट हुई।

चिली जैसे देशों में आई० टी० टी० और अंगकोडा कार्पोरेशन जैसे अमरीकी बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रति व्यापक जन-आक्रोश फैला। आचामी वर्षों में इसके महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम सामने आये। 1970 के दशक में जब सत्तवीय प्रणाली से इस देश में राष्ट्रपति अम्बादे ने सरकार बनायी तो यह बात भलीभाँति प्रमाणित हुई कि लातीनी अमरीकी देशों में परिवर्तन की दशा अमरीका द्वारा पोषित श्रेष्ठ वर्ग (Elite) से हटकर जन-साधारण के हाथों में आने लगी है।

इसी वर्षों में बनेक लातीनी अमरीकी साहित्यकार अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुए। चिली में पाबलो नरुदा, अर्जेन्टीना में होर्जे लुई बोर्जे, कोलम्बिया में प्रायियल मार्क्वेज तथा क्यूबा में ओक्टोबिया पाब इस सिलसिले में उल्लेखनीय नाम हैं। इन लोगों ने यह मिश्र कर दिया कि विचारों की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए लातीनी अमरीका को उत्तर अमरीकी महाद्वीप की कोई नजरत नहीं।

1950 के दशक में जब भी समुक्त राज्य अमरीका लातीनी अमरीकी देशों को अनुशासित करना चाहता, या उनके प्रति अपनी नाराजगी दिखाना चाहता तो वह सत्ता के नाम प्रयोग से नहीं हिचकता था। ग्वातेमाला तथा डोमिनिकन गणराज्य में बारम्बार पनडुब्बी सैनिकों की टुकड़ियों द्वारा हस्तक्षेप किया गया। 1960 के दशक में जब अमरीका भियतनाम में फँसा था, तब ऐसा आचरण कम हुआ और इसने लातीनी अमरीकी देशों को स्वाधीन बनने में निमग्न हो सहायता दी।

परन्तु इससे यह समझना शक्य होता है कि अमरीका ने इस प्रवृत्ति का विरोध नहीं किया। दार्जील और अर्जेन्टीना जैसे विनाशकारी देशों में अमरीकी बहुराष्ट्रीय निगमों का वर्चस्व बना रहा और अमरीकी पक्षधर दक्षिणपंथी सैनिक सरकारें भी

निरापद रही। इन राज्यों में अमरीका के प्रति अनन्तोप दूसरे चरण में और अगले दशक में प्रस्तुति हुई।

जब अमरीका को यह महसूस होने लगा कि सारे अमरीकी राज्य और मूडबंद उनका अनुसरण करने को तैयार नहीं हैं तो उनमें बड़ पैमाने पर समथन तरीक़ा शुरू किया। साथ सैनिक हस्तक्षेप की अपेक्षा आर्थिक पुनर्निर्माण के नाम पर नज़र रख सलाहकारों का घुमपैंगु का काम शुरू किया। अमरीकी विकास एजेंसी सांख्यिकी, वैज्ञानिक और प्राध्यापक सफल राजनयिक माध्यम बने। अपनी उपमोक्षा जीवन यापन पैली को ललचान बाले ढंग से प्रस्तुत कर अमरीका ने अपना हित साधन आरम्भ किया। नाटो दिखान का स्थान कोको बोला साम्राज्यवाद और 'हालत राजनय' में से लिया। थियोडोर रूजवेल्ट की मुद्रा चौधरी-बोनवाल जैसे पौ तो प्रेरित रूजवेल्ट ने अपने को अच्छे पड़ोसी के रूप में पण किया। आइज़नहायर ने सापनारी का मुनाब माग्न रखा तो राष्ट्रपति कैंनेडी ने प्रगति के लिए मैत्री का स्वर उठाया। अमरीकी विदेश नीति के ये विविध चरण विंग लिंक, 'हालत डिप्लोमेसी' गुड नगर पालिमी 'गुड पाठन और एनापन्स फार पाठनरणिप के नाम में प्रसिद्ध हैं। या अमरीकी राज्या का मथन द्वितीय विश्वयुद्ध के तत्काल बाद बना मिला गया परन्तु उनकी सक्रियता 1960 के दशक के मध्य में ही इतने की मिली।

महावरे में नये ही निरन्तर परिवर्तन होना रहा ही किन्तु वस्तुस्थिति में कोई फरकबदल नहीं हुआ। सानीनी अमरीकी देशों में राजनीतिक घेनना के विकास के साथ इस बात का अहमाम जमना बढना ही गया है कि उत्तरी पड़ोसी (अमरीका) एक विनालकाय देश है जिसके साथ समानता का व्यवहार कठिन है। उसके सामने बाकी देश होते ही रह सकते हैं। अमरीकी विदेश विभाग में उदारवादी तत्व सानीनी अमरीकी देशों के प्रति नीति परिवर्तन मुपाते रहे परन्तु इसमें उन्हें साम सफलता नहीं मिली। जान कैंनेय मेलब्रय और एडवर्ड कैंनेडी जैसे लोग अमरीकी नीतियों की बड़ी आलाचना करते रहे परन्तु इनकी अपेक्षा सीनेट और जन-संचार माधन में हेनरी किमिजर और जोन बर्क प्रैन्स जैसे कट्टरपथी तत्व ही हावी रहे हैं। इनकी पड़नकारी गतिविधियां ने बहुत बड़ी सीमा तक सानीनी अमरीका के आक्रामक का निरन्त किया है।

विषी में राष्ट्रपति अयादे का ज्ञान दिन तक सलाहकार नहीं रहन दिया गया। जब यह स्पष्ट हो गया कि जनताधिक समदीय प्रणाली में उह अवस्थ नहीं किया जा सकता तो अमरीकी खुफिया मण्डल (सी आई ए) द्वारा प्ररित प्रालाहित हडनाला के बाद तन्नापन द्वारा सरकार विरायी गयी। तब से उन्पीठक सैनिक तानाशाह पीना वहाँ गहीनगीन है। मानव अधिकारों के हनन के लिए बिनी मात्र दुनिया के सबन बढनाम दगा में एक है। इसी तरह फाईनेण्ड युद्ध के बाद अमरीका में सैनिक सरकार घिनन के पटन कभीना महा म्यिनि भी। जब राष्ट्रपति वाटर न अपन कायका में पूर्व पश्चिम सवाद में मानकाधिकार का समता उठाया तो उनमें पुछा गया कि वे इस मन्त्रन में सानीनी अमरीका के विषय में अपनी अति क्या मूली रखन हैं?

फाईनेण्ड युद्ध के दौरान अमरीका और सानीनी अमरीकी देशों के बीच विदेश सम्बन्धों का भ्रम टूट गया। अमरीका के लिए मुद्रा विनन के साथ घनिष्ठ सम्बन्धों

को अक्षत रखना कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था। न केवल अर्जेंटीना बल्कि अन्य देश भी यह मोचने को विवश हुए कि अपने सामरिक हितों की बेदी पर अमरीका उनमें से किसी भी देश के राष्ट्रीय हित कुर्बान कर सकता है। इस अनुभव के बाद अमरीकी राज्यों का संगठन और भी दुर्बल हुआ। 1980 के दशक में ब्राजील, अर्जेंटीना और मैक्सिको जैसे बड़े देशों को अमरीकी विशेषज्ञों और बैंकों की मलाह के अनुसार आर्थिक विकास का मार्ग चुनने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। आज यह सब देश अन्तर्राष्ट्रीय अर्थजगत में सबसे बड़े नर्जदार हैं और इनका भविष्य एक तरह से गिरवी रखा जा चुका है। इस स्थिति ने राजनीतिक स्वाधीनता के भाव को बड़ावा दिया है। बढ़ते अमनोप का मुकाबला करने के लिए अमरीका को अच्छे पड़ोसी का नाटक छोड़कर फिर बल प्रयोग के लिए निर्लज्ज ढंग से तैयार होना पड़ा है। छोटे से देश ग्रेनेडा में अमहमति न सह सकने के कारण उसे बल प्रयोग करना पड़ा। इसमें मले ही अमरीका को तात्कालिक सामरिक सफलता मिली, किन्तु वर्षों की उसकी राजनयिक कमाई मिट्टी में मिल गयी।

लातीनी अमरीका के अम्युदय का एक और आयाम पिछले कुछ वर्षों में मध्य अमरीकी देशों (Central American Countries) में उद्घाटित हुआ है। निकारागुआ और अल सल्वाडोर में द्वापामारी के बाद व्यापक जन-समर्थन प्राप्त मार्क्सवादी-वामपन्थी रक्तान वाली सरकारों का गठन हुआ है। इन दोनों जगहों में विपत्तनामी अनुभव के बाद बड़े पैमाने पर सैनिक हस्तक्षेप के लिए अमरीका तैयार नहीं, और न ही वह परिवर्तन स्वीकार कराने की स्थिति में है। अमरीका का रीयन प्रशामन तमाम प्रतिक्रियावादी तत्त्वों (जैसे कोंतरा समूह) को हर सम्भव सहायता और प्रोत्साहन देता रहा। इस काम के लिए उसने सर्वैधानिक प्रायधानों और सारी सतदीय परम्पराओं को ताक में रखा। सीनेट के वीटो के बावजूद रीयन ने अवैध ढंग से इन प्रतिरोधियों को अमरीकी सैनिक सहायता देने की अनुमति दी। इन तक हथियार और पैसा पहुँचाने के लिए उन्होंने जिन साधनों को अपनाया, उसमें सीमावर्ती राज्यों में मादक द्रव्यों की तस्करी और अपराधपूर्ण गतिविधियों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देना शामिल है। इस अदूरदर्शिता के खतरनाक परिणाम सामने आने लगे हैं।

(NATO North Atlantic Treaty Organisation) और वारमा पैक्ट, राज्य दे—समुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ, तथा व्यक्ति थे—जोसेफ स्टालिन और जॉन फास्टर डलेम ।’

मेहन की उपरांत धारणा की पुष्टि इवान लुआर्ड ने भी अपनी पुस्तक में की है। इवान लुआर्ड ने अपने द्वारा सम्पादित पुस्तक ‘The Cold War’ की भूमिका में कहा है—‘शीत युद्ध वास्तविक इतनी सुनिश्चित परिभाषा के अभाव में विलक्षण है। मगर यह तीव्र राजनीतिक, आर्थिक तथा वैचारिक प्रतियोगिता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो राज्यों के बीच मैनिफेस्ट संघर्ष के दायरे के नीचे आता है। यह राज्य सम्भवतः अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में ऐसे किसी भी तीव्र संघर्ष के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है किन्तु साधारण प्रचलन की पूर्वधारणा के अनुसार दो पक्ष माने गये हैं—पश्चिमी शक्तियाँ तथा राजनीतिक दल एक तरफ और साम्यवादी शक्तियाँ तथा राजनीतिक दल दूसरी तरफ ।’

शीत युद्ध की परिभाषा एक उद्भव के बारे में फ्रेड हेन्रीडे ने अपनी पुस्तक ‘The Making of the Second Cold War’ में एक महत्वपूर्ण विचारोत्तेजक टिप्पणी की है। लेखक का मानना है कि ‘शीत युद्ध’ शब्द का प्रयोग 1946 से 1953 के दौर में तथा 1979 के बाद में अनिवार्यतः दो अर्थों में एक साथ किया जा रहा है—(अ) दो महाशक्तियों या दो सेमों के बीच परस्पर सम्बन्ध जमे हुए दृष्टान्त हैं तथा (ब) संघर्ष ने विस्फोटक—अर्थ रूप नहीं लिया। असल में दोनों स्थितियाँ एक साथ चलती हैं और शीत युद्ध का अन्तर 1940 के दशक के मित्र राष्ट्रों के समुक्त मोर्चे तथा 1970 के दशक के तनाव-संमिलित के युग से किया जा सकता है।

फ्रेड हेन्रीडे के अनुसार ‘पहले शीत युद्ध’ की यह प्रमुख पहचानें (प्रवृत्तियाँ) दृष्टिगोचर होती हैं, जिनके आधार पर किसी और शीत युद्धवालीन स्थिति को कमीटी पर रखा जा सकता है। ये छह प्रवृत्तियाँ निम्नांकित हैं—

(1) सैनिक शस्त्रोत्करण में वृद्धि—विधोपकरण महाशक्तियों के पास परमाणु अस्त्रों के संचार में,

(2) एक-दूसरे के बिना प्रचार-अभियान में तेजी (यह ध्यान में रखने लायक है कि यह प्रचार (एक दूसरे की निन्दा-मर्त्यना आदि) सिर्फ नेतृत्व तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरी व्यवस्था के दोषों को अपना लक्ष्य बनाना है),

(3) महाशक्तियों के बीच सफल व सार्थक बातचीत-निराशा का अभाव,

(4) पूँजीवाद एक साम्यवाद के बीच संघर्ष के कारण तीसरी दुनिया के अनेक देशों में जातिवादी घटनाक्रमों का सूत्रपात,

(5) इन सबके परिणामस्वरूप दोनों सेमों में एक-दूसरे के मणि मित्रों पर बड़ा अनुशासन, और

(6) पूर्व और पश्चिम के बीच घने आ रहे तनावो-बिबादों का बहो अधिक जोतिमय बन हो जाना।

फ्रेड हेन्रीडे काय कहते हैं—शीत युद्ध की सबसे बड़ी पहचान पर्यवेक्षकों को बड़े हुए अन्तर्राष्ट्रीय मंच की प्रतीति है। दूसरे छन्दों में, शीत युद्ध की सबसे बड़ी विशेषता एक गाम तरह की मानविक दगा है। नए शीत युद्ध के सन्दर्भ में भी यह बात मटीक बैठती है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार ‘शीत युद्ध’ की परिभाषा यही है कि बिना प्रकट हिंसा के धमकी, अवरोध और प्रचार के माध्यम से

बैर का निर्वाह ।'

उपरोक्त परिभाषाओं में से किसी एक को भी शीत युद्ध का अर्थ एवं प्रकृति को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने वाली नहीं माना जा सकता । इस कारण शीत युद्ध के अन्तिमार्थ को स्पष्ट करने के लिए उसकी प्रमुख विशेषताओं वा सशिष्ट उल्लेख अत्यन्त समीचीन होगा ।

शीत युद्ध की प्रमुख विशेषताएँ (Salient Features of Cold War)

शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति है जिसे मूलतः 'ठण्डा शान्ति' कहा जाता चाहिए । ऐसी स्थिति में न तो 'पूर्ण रूप से शान्ति' रहती है और न ही 'वास्तविक युद्ध' होता है, बल्कि शान्ति एवं युद्ध के बीच की अस्थिर स्थिति बनी रहती है । हालांकि वास्तविक युद्ध नहीं होता, किन्तु यह स्थिति युद्ध की प्रथम सीढ़ी है जिसमें युद्ध के वातावरण का निर्माण किया जाता है या होना रहता है । इन दोषण महा-शक्तियाँ एक-दूसरे से नज़रबंद रहती हैं, जिनके अस्त्र-शस्त्रों का निर्माण ही नहीं, मानव-समाज की कुछ सगुणों में समाप्त कर देने वाले घातक परमाणु प्रक्षेपास्त्रों के निर्माण की होड़ भी करती हैं । वे समाचार-पत्रों, रेडियो, टेलीविजन आदि जन प्रचार के साधनों के जरिए एक-दूसरे की आलोचना-प्रत्यालोचना करती रहती हैं । यह ऐसी स्थिति है, जिनमें दोनों पक्ष परस्पर शान्तिकालीन कूटनीतिक सम्बन्ध बाधन रखते हुए भी परस्पर गन्धुनाब रखते हैं और महात्तम युद्ध को छोड़कर अन्य समस्त उपायों का सहारा लेकर एक-दूसरे की स्थिति दुर्बल बनाने का प्रयत्न करते हैं । यह कूटनीतिक दाव-पेचों में लड़ा जाने वाला युद्ध है जो कभी भी 'वास्तविक युद्ध' (Real War) का विनाशकारी मार्ग प्रशस्त कर सकता है ।

शीत युद्ध का उद्भव (Origin of Cold War)

शीत युद्ध का उद्भव कैसे हुआ, और यह कब शुरू हुआ ? कुछ लोग इसका उद्भव द्वितीय विश्व युद्ध के तत्काल बाद मानते हैं तो कुछ अन्य विशेषज्ञ इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विन्स्टन चर्चिल के 5 मार्च, 1946 को दिये गये पुण्डित जायन से, जिनमें उन्होंने कहा था कि 'हमें ठानाशाही के एक स्वरूप के स्थापन पर उनके दूसरे स्वरूप की स्थापना रोकनी चाहिए । स्वतन्त्रता की दारुशिक्षा प्रज्ज्वलित रखने एवं ईसाई नम्बना की सुरक्षा के लिए आग्न-धनरीकी सङ्घबन्धन स्थापित किया जाना चाहिए । साम्यवाद के प्रचार को नीनित रखने के लिए हर नम्बय नैतिक-अनैतिक उपायों का अवलम्बन किया जाना चाहिए ।' अमल में शीत युद्ध के उद्भव के बारे में किसी निश्चित दिन अमरा खनन की बनाना अनुभव है, क्योंकि यह युद्ध एक सम्वी प्रक्रिया थी, जिनके अन्तर्गत दो महानशक्तियों में आपसी हितों के टकराव से विभिन्न संकट भिन्न-भिन्न समय पर लगातार पैदा हुए, जयान् दोनों के बीच तनाव धीरे-धीरे बढ़ता गया और इन्हीं ही शीत युद्ध बहा गया ।

अनरीकी विद्वान हॉव तथा फ्रान्सीसी विद्वान आन्ड्रे फोनेन मानते हैं कि वम्बुनः अन्तराष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध का आरम्भ 1945 में नहीं बरन् 1917

¹ Fred Halliday, *The Making of the Second Cold War* (London 1933).

में बौद्धोद्विग्न शान्ति के साथ हुआ जिससे राज्य शक्ति का नया स्वरूप और सामाजिक व आर्थिक विकास का वैकल्पिक कार्यक्रम सामने आया, जबकि शीत युद्ध के आविर्भाव के बारे में सोवियन विदेश नीति विषयक पुस्तकों—सन्दर्भ ग्रन्थों में एक मिश्र दृष्टिकोण देखने को मिलता है। प्रोग्रेम प्रकाशन, मास्को द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'The Road to Communism' में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बढ़ते अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का वैकल्पिक परिदृश्य प्रस्तुत किया गया है। 'आर्थिक, राजनीतिक एवं सैनिक साम्राज्यवाद का केन्द्र यूरोप से हटकर अमरीका चला गया। अमरीका का इजारेदार पूँजीवाद युद्ध में अजिब मुनाफे के कारण पुष्ट हुआ। उसने शत्रुओं की होड़ को बढ़ावा दिया तथा पूँजी निवेश के अवसर, बच्चे माल और बाजार की तलाश में अमरीका ने एक नये तरह के औपनिवेशिक साम्राज्य का गठन किया और उसका उदय सबसे प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय शोषक के रूप में हुआ। इस पुस्तक में उन कारणों का विश्लेषण भी है, जिनमें सोवियन मघ और अमरीका का टकराव अनिवार्य हो गया। 'अमेरन फामीवाद और जापानी संग्घवाद की दूसरे विश्व युद्ध में पराजय हुई। इसमें सोवियन मघ ने निर्णायक भूमिका निभायी और उन परिस्थितियों को जन्म दिया, जिनसे पूँजीवाद और यूरोप तथा एशिया के अनेक देशों में जमींदारों के आधिपत्य का उन्मूलन सम्भव बना।'

शीत युद्ध के कारण

(Causes of Cold War)

शीत युद्ध अनेक घटनाओं, कारणों, व मिश्र विचारधाराओं व राष्ट्र हितों का परिणाम था। वैसे इसका इतिहास 1920 और 1930 के दशक से शुरू हो सकता है, किन्तु उसका विद्वद राजनीति में इतना प्रभाव नहीं पड़ा, जितना 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद अन्तर्राष्ट्रीय समाज का दो नेमों में विभाजित होना आरम्भ हो गया। इस बात को कोई भी नहीं नकार सकता कि दो विश्व युद्धों के बीच के अन्तराल में यूरोप का ह्रास ही शीत युद्ध का प्रमुख कारण रहा। इस बारे में निरापद नहीं बैठे रहा जा सकता था कि यदि यूरोप की राजनीतिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो शीत युद्ध का विस्फोट और भी सनराख ढग से ही मरता है। जैसाकि बेयरून महान के शासनकाल में घेनरिक घीन ने भविष्यवाणी की थी कि दो विन्तारवादी साम्राज्य सारी दुनिया को आपस में बाँट लेंगे। महाशक्तियों के उदय के बाद यह घात और भी सटीक साबित होनी है। अतएव पूर्व तथा पश्चिमी नेमों के बीच इस टकराव अर्थात् शीत युद्ध के लिए अनेक कारण जिम्मेदार रहे। ये कारण निम्नांकित तीन माथों में विभाजित किये जा सकते हैं—

- (अ) सामान्य कारण अर्थात् जो दोनों में पाये जाते हैं,
- (ब) अमरीका के विरुद्ध सोवियन मघ की शिकायतें, और
- (स) सोवियन मघ के विरुद्ध अमरीका की शिकायतें। इनके बारे में विभूत विद्वेषण वादनीय है।

(अ) सामान्य कारण

1. विचारधाराओं का टकराव—द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमरीका और

सोवियत संघ के बीच वैचारिक मतभेद से तनाव पैदा हुआ। जहाँ एक तरफ पूँजीवादी अमरीका ने सोवियत साम्यवाद को स्वतन्त्रता और विश्व शान्ति का शत्रु बताते हुए रूसी प्रभाव का विस्तार रोकने का प्रयास किया और हंगरी जैसे पूर्व-यूरोपीय देश में राष्ट्रीय विद्रोह के आधार पर रूस को 'साम्राज्यवादी शक्ति' की संज्ञा दी, वहीं दूसरी तरफ सोवियत संघ ने अमरीका तथा पश्चिम यूरोपीय राष्ट्रों को उपनिवेशवादी एवं उसका समर्थक घोषित करते हुए साम्यवाद को एशिया, अफ्रीका एवं लातीनी अमरीका के विकासशील देशों की गरीब जनता की भलाई के लिए रामबाण औपधि के रूप में प्रस्तुत किया। असल में दोनों पक्ष सत्कार में अपनी-अपनी विचारधारा का प्रचार एवं प्रसार कार्य कर रहे थे। इन्हीं दो विरोधी विचारधाराओं के टकराव में शीत युद्ध नष्ट हुआ।

2. विजित प्रदेशों पर प्रभुत्व—इच्छा—जैसाकि अक्सर होता है, कुछ राष्ट्र अपने किसी सामान्य हित के कारण प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्रों से लड़ते हैं। जब वे जीत जाते हैं, तो विजित प्रदेशों पर 'प्रभुत्व' को लेकर उनमें मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की यही स्थिति हुई। विजित जर्मनी तथा इटली पर आधिपत्य को लेकर अमरीका तथा सोवियत संघ के बीच लीचताम आरम्भ हो गयी। एक तरफ अमरीका तथा उसके पश्चिमी साथी राष्ट्रों ने जर्मनी तथा इटली में उन्हीं तत्त्वों को समर्थन देना शुरू किया, जिनके खिलाफ उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा था। दूसरी तरफ सोवियत संघ इन देशों में साम्यवादी आन्दोलन को प्रोत्साहन दे रहा था। विजित देशों में अमरीका और रूस के इसी भिन्न राष्ट्रीय हित ने शीत युद्ध को बढ़ाया।

3. राष्ट्र-हितों का अन्तर—द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब विश्व राजनीति में अमरीका और सोवियत संघ महाशक्तियों के रूप में उभरे तो महाशक्तियों के नाते इनके राष्ट्र-हित भी भिन्न-भिन्न थे। अमरीका चाहता था कि साम्यवादी विचारधारा नुस्त हो जाये और विश्व के अन्य देश पूँजीवादी व्यवस्था अपनायें। उसका हित इसमें भी निहित था कि अन्य देशों में उसकी बहुराष्ट्रीय निगमों में ज्यादा से ज्यादा भुनाका काम कर लायें। इन राष्ट्र-हितों की प्राप्ति के लिए उसके द्वारा अन्य देशों को अमरीकी समर्थक बनाना आवश्यक था। दूसरी तरफ सोवियत संघ विश्व के अन्य भागों में पूँजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंक कर साम्यवादी शान्ति का बिगुल बजाना चाहता था। जिस प्रकार अमरीका अपने समर्थक देशों का भुनाका बनना चाहता था, उसी प्रकार सोवियत संघ साम्यवादी देशों का नेतृत्व कर मारे सत्कार की साम्यवादी शान्ति के सात रंग से रबने का महत्वकांक्षी था। अतः दोनों महाशक्तियों के अन्य देशों में राष्ट्रीय हितों के टकराव से शीत युद्ध का सूत्रपात हुआ।

4. महाशक्तियों द्वारा शक्ति-संघर्ष की राजनीति—अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रवाण्ड पण्डित मार्गेन्सो ने सही कहा है कि 'अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति-संघर्ष की राजनीति है।' अर्थात् अमरीका और सोवियत संघ महाशक्ति तभी कहला सकते हैं, जब वे 'ज्यादा से ज्यादा शक्ति' अर्जित करें। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सन्दर्भ में यहाँ 'शक्ति' का तात्पर्य उनकी भौगोलिक स्थिति, आर्थिक दशा, सैनिक स्थिति, विश्व राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता, नेतृत्व आदि से है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमरीका तथा सोवियत संघ ने इसी शक्ति संघर्ष की राजनीति का सहारा लिया और 'शक्ति सन्तुलन', 'प्रभाव क्षेत्र', 'अधीनस्थ देश' आदि मिद्दान्तों को अपनाया।

शक्ति सघर्ष की इस राजनीति में दोनों महाशक्तियों का टकराव अवश्यम्भावी था और हमने शीत युद्ध को जन्म दिया।

5. एक-दूसरे के विरुद्ध प्रचार अभियान—द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमरीका तथा सोवियत सघ एक-दूसरे के विरुद्ध झूठे एवं धृष्टित प्रचार में सक्रिय हो गये। सोवियत सघ ने अमरीका को पूँजीवादी, साम्राज्यवादी, एवं उपनिवेशवादी आदि राजनीतिक गालियाँ देना शुरू किया, तो अमरीका ने अन्य देशों में सोवियत सघ द्वारा प्रचारित मार्क्सवाद की लाख नान्ति का खतरा बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया। दोनों द्वारा एक-दूसरे के विरुद्ध ऐसे झूठे एवं धृष्टित प्रचार से उनके बीच शीत युद्ध का तनाव और उग्र हुआ।

(ब) अमरीका के विरुद्ध सोवियत सघ की शिकायतें

1. द्वितीय मोर्चे का प्रश्न—द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब अमरीका और सोवियत सघ घुरी राष्ट्रों से लड़ रहे थे, तभी उनके बीच दूसरा मोर्चा खोलने पर मतभेद पैदा हो गये। हमने आगे चलकर उनके बीच अविश्वास को और बढ़ा दिया। अब हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी की सेना सोवियत सघ की भूमि में आक्रमण कर घुस गयी और जन-घन को नष्ट करने लगी तो स्टालिन ने मित्र-राष्ट्रों अमरीका तथा ब्रिटेन से अनुरोध किया कि वे पश्चिम यूरोप में हिटलर के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोल दें। स्टालिन चाहते थे कि यदि पश्चिम में मोर्चा खुल गया तो रूसी भूमि पर जर्मन सेना के जमाव एवं प्रहार में कमी आ जायगी, क्योंकि जर्मनी का ध्यान दो तरफ बँट जायेगा। किन्तु अमरीकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट एवं ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, स्टालिन के इस अनुरोध को बार-बार टालते रहे। इसके अलावा जब 1944 के प्रारम्भ में दूसरा मोर्चा खोलने की योजना बनने लगी तो चर्चिल ने यह योजना नामने रखी कि ब्रिटेन और अमरीका की सेना फ्रांस की तरफ से नहीं बल्कि बाल्कन प्रायद्वीप से यूरोप में उत्तर की ओर बढ़े, ताकि सोवियत सघ की सेना पूर्वी यूरोप में आगे न बढ़ सके। रूजवेल्ट, चर्चिल की इस योजना से सहमत थे। ऐसी विलम्ब-भरी चाल से सोवियत सघ की अमरीकी मैत्री के प्रति शका उत्पन्न हो गयी। बेसी ने इस बार में लिखा है कि 'दूसरा मोर्चा खोलने में पश्चिमी राष्ट्रों की इस विलम्ब-भरी नीति के कारण क्रैमलिन (सोवियत सघ) में यह मन्देश जड़ पकड़ गया कि पश्चिमी राष्ट्र, जो युद्ध के बाद एक गतिशील सोवियत सघ की सम्भावनाओं से भयभीत हैं युद्ध के अग्राहों में बूढ़ने में पूर्व रुक कर पूर्ण आरुत और शक्तिहीन बनना चाहते हैं। सोवियत इतिहासकार जी० वैदायात्म ने इसी विश्लेषण को कमोवेश अन्य शब्दों में प्रकट करते हुए कहा है कि 'अमरीका और ब्रिटेन ने लंबे मोच-मसाकर तथा जानझंकर यह देरी की, ताकि जर्मनी किसी तरह रूस की साम्यवादी व्यवस्था का काम तमाम कर दे।'

2. अमरीका द्वारा परमाणु बम का रहस्य गुप्त रखना—द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब अमरीका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगरों पर परमाणु बम गिराये तो नाश्वियत सघ को इस पर अत्यन्त आश्चर्य हुआ, क्योंकि अमरीका ने उसके पास परमाणु बम होना का रहस्य उससे छिपाये रखा, जबकि ब्रिटेन और फ्रांस का उमन यह बना दिया था। इससे अमरीका और सोवियत सघ की मित्रता अविश्वास में बदल गयी और दोनों में शीत युद्ध का मार्ग प्रगष्ट हुआ।

3. **रूस को मिलने वाली सहायता पर रोक**—रूस उसकी क्षतिपूर्ति मांगों के विरोध के कारण अमरीका से पहले से ही नाराज था। 'लैंड लीज' अधिनियम के तहत सोवियत सघ को दी जाने वाली अमरीकी आशिक सहायता से वह सन्तुष्ट नहीं था। किन्तु जब अमरीकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने यह आशिक सहायता बन्द कर दी तो सोवियत सघ एकाएक चौखन्ना गया। स्वामाधिक या कि यह घटना अमरीका तथा सोवियत सघ में चल रहे शीत युद्ध की तीव्रता और बढ़ावी।

4. **पोलैण्ड एवं बाल्टिक देशों में रूस-विरोधी अमरीकी कदम**—रूस का मानना था कि जब उसने पोलैण्ड व बाल्टिक देशों की अपनी भूतपूर्व भूमि पर अधिकार किया तो अमरीका को चाहिए था कि वह इन परिवर्तित स्थितियों को मान्यता देता। इसके विपरीत अमरीका ने ब्रिटेन के साथ मिलकर पोलैण्ड की हान्दन स्थित रूस विरोधी 'निर्वासित सरकार' (Government in Exile) को मान्यता प्रदान कर दी। इसके अतिरिक्त, 1939 में जब सोवियत सघ ने लेनिनग्राद की सुरक्षा के लिए जब फिनलैण्ड से भूमि का छोटा-सा टुकड़ा प्राप्त करना चाहा तो अमरीका, ब्रिटेन तथा फ्रांस जैसे पश्चिमी देशों ने ऐसे कदम उठाये जो कभी भी युद्ध भड़का सकते थे। जितने दिनों तक द्वितीय महायुद्ध चलता रहा, अमरीका ने बाल्टिक के देशों—लाटविया, लिथुनिया, एम्थोनिया के बर्लिंगटन-स्मित दूतों को मान्यता दिये रखी।

(स) सोवियत सघ के विरुद्ध अमरीकी जिकायते

1. इस द्वारा वाट्टा समझौते का उल्लंघन—1945 के वाट्टा सम्मेलन में अमरीका, ब्रिटेन और सोवियत सघ के बीच कुछ समझौते किये गये, किन्तु सोवियत सघ ने आगे चलकर उनका उल्लंघन किया।

(अ) पोलैण्ड में सोवियत सघ द्वारा संरक्षित लुबलिन शासन और पश्चिमी देशों द्वारा 'संरक्षित शासन' के स्थान पर स्वतन्त्र और निष्पक्ष निर्वाचन पर आधारित एवं प्रतिनिध्यात्मक सरकार द्वारा स्थापित किया जायेगा। नये पोलैण्ड से उनके पूर्व में रूसी भागा-भागी क्षेत्र कर्जन रेखा के आधार पर पृथक् कर दिये जायेंगे, परन्तु पश्चिम में मुआवजे के रूप में उसे कुछ जर्मन भूमि प्रदान की जायेगी।

जबकि सोवियत सघ ने पोलैण्ड की जनता पर अपने द्वारा संरक्षित लुबलिन शासन को लादने का प्रयत्न किया। उसने अनेक दलों के नेताओं को जेल में डूँस दिया। जब अमरीका तथा ब्रिटेन के प्रेक्षकों ने पोलैण्ड में प्रवेश कर स्थिति का जायजा लेने की इच्छा प्रकट की तो उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी गई।

(ब) सोवियत सघ ने हंगरी, बुल्गारिया, रूमानिया और चेकोस्लावाकिया में भी युद्ध विराम समझौते और वाट्टा एवं पोर्टस्मथेम् सम्मेलन की सन्धियों का उल्लंघन किया। उसने पूर्वी यूरोप के देशों में लोकतन्त्र की पुनर्स्थापना करने में मित्र राष्ट्रों के साथ रहने से मना कर दिया। इस बारे में एच. एल. ट्राफोउजे (H. L. Trefousse) ने अपनी सम्पादित पुस्तक 'The Cold War : A Book of Documents' की भूमिका में कहा है कि जहाँ कहीं भी सोवियत या साम्यवादी सैनिक गये वहाँ सोवियत सघ की समर्थक सरकार स्थापित करवा दी तथा पश्चिमी प्रभाव को प्रायः भूय कर दिया। रूमानिया, पोलैण्ड, युगोस्लाविया, अल्बानिया तथा अन्ततः हंगरी तथा चेकोस्लाविया सभी सोवियत प्रभाव क्षेत्र में आ गये।

(स) सोवियत संघ ने यह वचन दिया कि वह चीन की सरकार को मान्यता देगा, बाह्य मंगोलिया में ग्यास्यिति का पालन करेगा और एक चीनी-रूसी सम्पत्ती द्वारा मन्चूरियाई रेलवे के समुक्त संचालन की शर्तों के साथ जर्मनी के आत्म-समर्पण के तीन माह के भीतर जापान के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित होगा। लेकिन विश्व युद्ध के समाप्त होने ही कम ने अपने वायदों से मुहरना शुरू कर दिया। जापान के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित होने में उसने अनिच्छा ही प्रकट नहीं की, बल्कि 'मित्र राष्ट्रों को साइबेरियाई अट्टो की सुविधा उपलब्ध कराने में भी आनाकानी की। मन्चूरिया में स्थित रूसी सेना ने 1946 के आरम्भ में राष्ट्रवादी सेनाओं को वहाँ प्रवेश तक नहीं करने दिया जबकि साम्यवादी सेनाओं को प्रवेश सम्बन्धी सभी सुविधाएँ देकर वह सम्पूर्ण युद्ध सामग्री भी छोड़ दी, जो जापानी सेना मागते समय छोड़ गयी थी। इस प्रकार सोवियत संघ द्वारा माल्टा समझौते की व्यवस्थाओं के उल्लंघन से शीत युद्धरूपी आग की सपटें तेज हुई।

(2) रूस द्वारा बाल्कन समझौते का उल्लंघन—रूसी सैन्य सेना जहाँ जहाँ भी जानी वहाँ साम्यवादी तत्त्वा को प्रोत्साहन-समर्थन देती। इससे अमरीका, ब्रिटेन तथा उनके मित्र राष्ट्रों की चिन्ता स्वाभाविक थी। इस मतभेद को लेकर उनके बीच बाल्कन समझौता हुआ, जिसके तहत सोवियत संघ ने बल्कन के पूर्वी यूरोप के विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ब्रिटेन ने बुल्गारिया तथा रूमानिया में सोवियत प्रभुत्व को स्वीकार किया तो सोवियत संघ ने यूनान में ब्रिटेन का प्रभुत्व। हंगरी तथा पुगोस्लाविया के बारे में तय हुआ कि हंगरी में दोनों का समुक्त प्रभाव रहेगा। किन्तु द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होते ही रूस ने खुलकर यूनान में साम्यवादी छापामारों को भेजा और साम्यवादी शासन स्थापित कराने का असफल प्रयास किया। इस प्रकार सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते का उल्लंघन करने में पूँजीवादी और साम्यवादी संघों के बीच अविश्वास की दूरी और बढ़ती गयी।

(3) रूस द्वारा ईरान से अपनी सेनाएँ हटाने से मना करना—द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत सेना में ईरान के उत्तरी भाग पर अमरीका तथा ब्रिटेन की सहमति से बल्ला कर लिया। युद्ध के पश्चात् अमरीका व ब्रिटेन ने अपनी सेनाएँ तत्काल हटा ली किन्तु सोवियत संघ ने अपनी सेना चरम बुलाने से इकार कर दिया। इससे पूर्व और पश्चिमी संघों में अविश्वास और बढ़ा। हालाँकि कुछ समय पश्चात् समुक्त राष्ट्र संघ और विश्व जनमत के दबाव में आकर रूस ने उत्तरी ईरान से अपनी सेना को हटा लिया।

(4) तुर्की पर रूसी दबाव—द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुर्की पर सोवियत संघ ने इस बात के लिए दबाव डाला कि वह उस वास्तोरण तथा कुछ अन्य भू-भागों पर सैनिक अड्डे बनान दे। पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ के इस बढ़ते हस्तक्षेप और प्रभाव को बर्तन सहन कर सकते थे ? उन्होंने रूस को चेतावनी दी कि तुर्की पर किसी भी प्रकार का दबाव या आक्रमण महन नहीं किया जायेगा और मोक्षा पड़ने पर मामल को समुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् में उठाया जायेगा। इस मामले में भी शीत युद्ध की उदना का तैज किया।

(5) सोवियत संघ द्वारा जर्मनी पर बोस साधना—द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के हमले में रूस को अपार हानि हुई। इस कारण माल्टा समझौते में स्थापित ने जर्मनी में शनिपूनि के रूप में 20 अरब डालर की मांग रखी। अमरीकी

राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने इस भांग को 'आगे वार्ता के रूप में' स्वीकार किया। इसका स्टॉलिन ने सीधा अर्थ यह लगाया कि उसकी भांग मान ली गई है। युद्धोपरान्त क्षतिपूर्ति सम्बन्धी प्रावधानों का अनुचित लाभ उठाते हुए रूस ने जर्मनी के उद्योग अस्त-व्यस्त कर कीमती मशीनों का अपने देश में स्थानान्तरण आरम्भ कर दिया। इससे जर्मनी की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी। परिणाम-स्वरूप ब्रिटेन और अमरीका को मजबूरन जर्मनी को भारी धनराशि सहाय्यार्थ प्रदान करनी पड़ी। जर्मनी के प्रति सोवियत संघ के इस कड़े रुख के कारण पश्चिमी देशों का नाराज होना स्वाभाविक था। इस मामले ने भी शीत युद्ध की आग में घी का काम किया।

(6) रूस द्वारा वीटो का बारंबार प्रयोग—संयुक्त राष्ट्र सभ जैसे विश्व संगठन में उस समय अमरीका और सोवियत संघ के बीच टकराव पैदा हो गया, जब पश्चिमी देशों ने अपनी संव्यात्मक शक्ति तथा अन्य तरीकों से इस संगठन पर अपना वर्चस्व जमाना आरम्भ कर दिया। रूस ने यह माना कि अमरीका अपने राष्ट्र हित पूरा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सभ का प्रयोग कर रहा है। यह महसूस कर सोवियत संघ ने पश्चिमी देशों के प्रस्तावों के विरुद्ध सुरक्षा परिषद में खुलकर बार-बार 'वीटो' का प्रयोग कर कार्रवाई में अड़ने लगाया आरम्भ कर दिया। इससे पश्चिमी देश नाराज हो गये और उन्होंने रूस विरोधी कार्रवाई और तेज कर दी।

(7) बर्लिन की नाकेबन्दी—सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबन्दी से दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध के तनाव में और उग्रता आयी। जून, 1948 में लन्दन प्रोटोकाल का अतिक्रमण करके रूस ने बर्लिन एवं पश्चिमी जर्मनी के मध्य की सभी रेल, मड़क तथा जल यातायात बन्द कर दिये। इतना ही नहीं, उसने हजारों निरीह जर्मन युद्धबन्दिनों और नागरिकों को उनके देश लौटाने से मना कर दिया। पीटर लायन ने बर्लिन की नाकेबन्दी से शीत युद्ध पर पड़े प्रभाव के बारे में टिप्पणी करते हुए लिखा है कि 'यद्यपि रूस की बर्लिन नाकेबन्दी असफल सिद्ध हो गयी और मई, 1949 में इस नाकेबन्दी को समाप्त कर दिया गया परन्तु इस घटना का एक गम्भीर परिणाम यह निकला कि अब सोवियत संघ का विरोध करने के लिए अमरीका तरह-तरह के सैनिक संगठनों की स्थापना करने की दिशा में सक्रिय हो गया'। इस प्रकार, शीत युद्ध की उग्रता बढ़ती गयी।

(8) अमरीका में रूस द्वारा साम्यवादी धर्तिविधियाँ भड़काना—1945 के आरम्भ में ही 'सामरिक सेवा' (Strategic Service) के अधिकारियों ने पाया कि उनकी सस्था के अनेक गोपनीय दस्तावेज साम्यवादी सरक्षण से चलने वाले 'अमरेशिया' नामक मासिक पत्र के फ़िलिप जाके के हाथ पहुँच जाते हैं। इससे चिन्तित होकर अमरीकी सरकार ने कनाडियायी शाही आयोग (केनेडियन रॉयल कमीशन) को इस मामले की छानबीन के लिए नियुक्त किया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 'इस जामूसी के पीछे सोवियत हाथ है। कनाडा का साम्यवादी दल सोवियत संघ की एक भुजा है।' उसने यह भी सनसनीखेज रहस्योद्घाटन किया कि कम से कम विश्वास के पद पर कार्यरत 23 कनाडावासी (जिनमें एक विधायक और एक प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक भी शामिल हैं) साम्यवादी गुट के एजेंट हैं तथा उन्होंने मास्को को परमाणु श्रेष्ठ व यूरेनियम के बमूने भेजे हैं। सोवियत संघ की ऐसी जामूसी

कारवाई तब अमरीका सहित पश्चिमी देशों में उत्तक प्रति गहर विक्षाम की भावना उठ खड़ी हुई।

शात युद्ध के दौरान अमरीका व रूस द्वारा अपनाए गए प्रमुख साधन

शीत युद्ध के दौरान अमरीका तथा रूस ने विश्व में अपना प्रभाव जमाने के अनेक प्रयास आरम्भ किये। एक दूसरे के विरुद्ध प्रभाव-क्षेत्र कायम करने में उनके द्वारा अपनाय गये प्रमुख साधन निम्नांकित हैं—

(i) सांस्कृतिक घुसपैठ—दोना महाशक्तियाँ न केवल के अर्थ देशों में एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करने के लिए सांस्कृतिक घुसपैठ आरम्भ की। दोनों ने यह काम विभिन्न सांस्कृतिक संगठनों का निर्माण पुस्तकालयों एवं वाचनालयों की स्थापना एवं फिल्म दिवानों के जरिए सम्पन्न किया। पाल्मरनाथ को मरि जाते वाले नोबल पुरस्कार और एनकॉर्डर माल्मनिस्सिन के उत्पन्न की पश्चिमी दुनिया में लोकप्रियता के लिए एक बड़ी सीमा तक शीत युद्ध की यही मानसिकता जिम्मेदार थी। इसके जवाब में सोवियत संघ मकार्थी, एडवर हूवर आदिनामक गणराज्य स्वातन्त्रता और क्यूबा आदि के उन्नाहरण मिलाता रहा।

(ii) विचारधारा का प्रचार—दोना महाशक्तियों ने विश्व में जमकर अपनी विचारधारा का माहिज तथा अर्थ प्रचार के प्रकाशन द्वारा प्रचार आरम्भ किया। अमरीकी सरकार के भुजना केन्द्रों ने अमराकन रिपोटर अमरीकन रिव्यू और 'प्रोजेन्स आफ कम्पूनिज्म' जैसी पत्रिकाओं का प्रकाशन और इनका मुफ्त वितरण बड़े पैमाने पर किया। प्रत्युत्तर में सोवियत 'रैण' मास्का 'यूड एण्ड म्यूज' सोवियत विमन' सोवियत मादम 'यू टांम्स' आदि का प्रकाशन सोवियत संघ ने किया। दोनों पक्षों का उद्देश्य तीसरी दुनिया के भारत जैसे गूट निरपन्न देशों में अपनी व्यवस्था को प्रष्ट और दूसरे की व्यवस्था का निरुष्ट मिट्ट करन का था। इस प्रक्रिया में नेहरू जी का यह कथन सदैव प्रमाणित हुआ किम उन्हां शीत युद्ध को लोका के नित और निमाग में हानि बाता रण (Battle in the minds of men) कहा था। यह काम सिर्फ दूतावासा में सम्पन्न नहीं हुआ बकि अमरीकी या रूसी कृपा का नाभ उठाने वाले छात्रवृत्ति-अनुदान पान वाले व्यक्तियों और संगठनों में भी किया। शीत युद्ध के इस चरण में कनरमुक्त के छन के समान स्त्रना तथा मस्याभा का गजन हुआ। फोरम आफ फा इटर्प्राज स नेकर अफा एणियन मालिडरती कमटी या बंड पीम काग्रम' जमा मस्याएं कमक उन्नाहरण है। दोनों महाशक्तियाँ न छात्र संगठनों अथिक् संगठनों में घुसपैठ कर अपन राजनीतिक प्रभाव को अज्ञान का उपग्रम किया।

(iii) आर्थिक सहायता के आद में प्रभाव—दोना महाशक्तियाँ न एणिया अशीका सानानी अमरीका तथा कगिगिपार्ट महादीश के देशों को आर्थिक सहायता देकर उनका आन्तरिक राजनीति एवं विप्ल नीति का प्रभावित करना चांन। भारत मित्र और इण्डोनेशिया जैसे अनेक देशों निवन्धित गुनामी का जुझा उतारने के बां आन निमर आर्थिक विकास का माग चुन रह थे परन्तु पूँजी और समुचित तकनीक के अभाव में उह समय दोनों का भूह ताकना पड रहा था। इनको मित्रने बाता नमाम आर्थिक सहायता शीत युद्ध के तब में अनुगामित हानी रही। 1950-51

मे भारत ने जब खाद्यान्न की याचना की तो उसे अमरीका के हाथों बुरी तरह तिरस्कात होना पड़ा। इसी तरह मिस्र में स्वेज संकट का उद्गम, आस्वान बांध के निर्माण को लेकर उत्पन्न मनोमालिन्य से जुड़ा था। बड़े उत्सोहों के क्षेत्र में इस्पात निर्माण आदि की पूरी प्रणालियों के आयात के विषय में भारत और इण्डोनेशिया के अनुभव बार-बार यही झलकाते रहे। शीत युद्ध के युग में विदेशी आर्थिक सहायता को एक अस्त्र के अतिरिक्त और किसी रूप में नहीं देखा जा सकता। दुर्भाग्यवश आज तक परस्पर लाभप्रद, अन्तरनिर्भर नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की इन प्राथमिकताओं को इस विषय में शीत युद्धयुगीन पूर्वाग्रह पथभ्रष्ट करता रहा है।

(iv) सैनिक संगठनों की स्थापना—दोनों महाशक्तियों ने सैनिक समझौते कर विश्व के अन्य देशों को अपने गुट की ओर मिलाने का प्रयास किया। अगरीका-प्रवर्तित 'नाटो', 'सिएटो' और 'सेन्टो' तथा सोवियत सघ-प्रवर्तित 'वार्सा' सैनिक समझौते इस सिलसिले में उल्लेखनीय हैं। इन सैनिक संगठनों ने शीत युद्ध की लपेट में उन देशों को भी ला दिया जो इस दण्ड के बाहर रहना चाहते थे। मसलन 'सिएटो' और 'सेन्टो' की सदस्यता पाने के बाद पाकिस्तान ने भारत की बहुशीज तक शीत युद्ध पहुँचा दिया। अमरीकी या रूसी समर नीति में पाकिस्तान का जो भी महत्वपूर्ण स्थान रहा हो, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि भारत-पाक सम्बन्धों के क्षेत्रीय सन्तुलन को इसने खतरनाक ढंग से गड़बड़ा दिया। इसी तरह दशकों तक अनेक देशों को विमाजित रहना पड़ा, जिनमें कोरिया, वियतनाम, जर्मनी आदि उल्लेखनीय हैं। पूर्वी यूरोप में अनेक 'उपग्रह राष्ट्रों' (Satellite States) की सीमित सम्प्रभुता के सिद्धान्त का प्रतिपादन भी शीत युद्ध की विरासत समझा जाना चाहिए। 1950 के दशक में पोलैण्ड और हंगरी में सोवियत हस्तक्षेप शीत युद्ध की ही देन थे।

(v) खुफिया संगठनों के घड्यन्त्र—अमरीकी 'सी० आई० ए०' तथा सोवियत 'के० जी० बी०' नामक खुफिया संगठन गरीब देशों में विरोधी सरकार को गिराने तथा अपनी समर्थक सरकार को प्रतिष्ठित कराने के राजनीतिक तोड़-फोड़ कार्य में सक्रिय हो गये। तृतीय विश्व युद्ध समाप्त होते-होते अपदस्थ होने वालों में ईरान के प्रधानमन्त्री मुसद्दिक थे, जिन्होंने अपने देश को तैस सम्पदा को विदेशी कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर अपने हाथ में लेने का प्रयत्न किया था। कोरिया में सिंह मान री और लाइवान में च्यांग काई शेक को बौह पुरुष मानने-अनमाने का तूट शीत युद्ध की जरूरतों से ही प्रेरित था।

(vi) सैनिक अड्डों की स्थापना—दोनों महाशक्तियों ने अन्य देशों में एक-दूसरे के विरुद्ध सैनिक अड्डे स्थापित करना आरम्भ किया। क्लार्क एयर बेस, सुबिक बे (फिलीपींस), दानाम और कामराह में अमरीका ने ऐसे अड्डे बनाये, जबकि सोवियत संघ ने इथियोपिया और सोमालिया में सोकोत्रा जैसी जगह पर सैनिक अड्डा स्थापित किया।

(vii) रैशणल क्षेत्र में घुस पैंठ—दोनों महाशक्तियों ने अन्य देशों के रैशणल जगत को भी प्रभावित किया। अमरीका ने फुलब्राइट छात्रवृत्ति शुरू की तो सोवियत संघ ने पेट्रिस शुभुदा विश्वविद्यालय में रैशणल आदान-प्रदान कार्यक्रमों के सहित अन्य देशों के छात्रों, गव्वापकों और विद्वानों को अध्ययन-अध्यापन के लिए अपने यहाँ बुलाया तथा अपने नागरिकों को वहाँ भेजा।

शीत युद्ध का विकास प्रमुख घटनाएँ (Evolution of Cold War Major Events)

द्वितीय विश्व युद्ध के उपरान्त दुनिया में ऐसी अनेक घटनाएँ घटी, जिन्हें अमरीका तथा सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध का सूचक माना जाता है। संक्षेप में प्रमुख घटनाएँ निम्नांकित हैं—

पहला चरण (1946 से 1953)

1 **वॉशिंग्टन का फुल्टन भाषण**—अनेक विद्वान शीत युद्ध का उद्भव विमटन वॉशिंग्टन के फुल्टन भाषण में मानते हैं, जिसका उल्लेख दूसरे अध्याय में पहले किया जा चुका है। इस भाषण के फलस्वरूप अमरीका में हम-विरोधी भावनाएँ मजबूत लगीं। 19 फरवरी, 1947 को अमरीकी सीनेट के सम्मुख राज्य सचिव डीन एचिमन ने कहा कि 'सोवियत संघ की विदेश नीति धांपामक और विस्तारवादी है।' इस प्रकार पूर्व और पश्चिम में एक-दूसरे के विरुद्ध शीत युद्ध का वातावरण उत्पन्न होता गया।

2 **ट्रूमेन सिद्धान्त**—साम्यवाद विरोध के नाम पर अमरीका ने 12 मार्च, 1947 को विश्व के अन्य देशों के लिए ट्रूमेन सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। कहा गया कि सत्ता में जहाँ वहाँ भी शान्ति को भंग करने वाला परोक्ष या अपरोक्ष आक्रामक कार्य होगा, वहाँ अमरीका सुरक्षा सशक्त समर्थन तथा वह उसे रोकने के लिए सशक्त प्रयास करेगा। अमरीका द्वारा ट्रूमेन सिद्धान्त की घोषणा से स्पष्ट है कि यह उसने सोवियत संघ के प्रति अपने मनमुटाव, घृणा, वैमनस्य और अविश्वास के कारण की।

3 **मार्शल योजना**—विश्व का साम्यवादी कालि के वधित खतर से बचाने के लिए 8 जून, 1947 को अमरीका ने मार्शल योजना की घोषणा की। 26 अप्रैल, 1947 को इसकी जल्दतर पर धन देते हुए अमरीकी विदेश सचिव ने कहा था कि यदि इस समय तरकाज यूरोप के आर्थिक पुनरुत्थान का प्रयत्न नहीं किया गया तो वह साम्यवादी हो जायेगा। इस प्रकार, मार्शल योजना समसामयिक अन्तर्राष्ट्रीय श्रुतिनीति की नवने दितस्वरूप एक युग प्रवर्तक घटना थी। इससे अमरीका और इस के बीच विरोध पहले की अवस्था और बढ़ा।

4 **कोमिनकोन की स्थापना**—यूरोप के अनेक देशों ने अमरीकी मार्शल योजना में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली। सोवियत गुट ने भी यूरोपीय देशों ने तो मार्शल योजना का करारा जवाब देने के लिए 25 अक्तूबर, 1947 को 'कोमिनकोन' का गठन कर दिया। इसका उद्देश्य फ्रांस और इटली सहित यूरोप के साम्यवादी दलों को संगठित करना था। इससे अमरीका तथा उसके पश्चिम यूरोप के मित्र देश सोवियत संघ के विनाश हो गये।

5 **'नाटो' का गठन**—4 अप्रैल, 1949 को अमरीका के नेतृत्व में कनाडा और पश्चिम यूरोप के दस देश (बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, लाक्जमबर्ग, होर्लेण्ड, पुर्तगाल, ब्रिटेन और नाबे) ने 'नाटो' (NATO) नामक सैनिक समझौते पर हस्ताक्षर किये। इसमें कहा गया कि यूरोप तथा उत्तरी अमरीका में किसी एक या अनेक देशों पर किया गया सशस्त्र आक्रमण समझौते के सभी सदस्यों

के खिलाफ हमला समझा जायेगा। यह सोवियत संघ को खुली चेतावनी थी कि यदि उसने 'नाटो' के किसी भी देश पर हमला किया तो अमरीका उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। अमरीका द्वारा 'नाटो' का निर्माण, सोवियत संघ का सैनिक स्तर पर विरोध करना था।

6. चीन में साम्यवादी क्रान्ति—एक अक्टूबर, 1949 को बीजिंग में राष्ट्रवादी सरकार को हटाकर माओत्से तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार स्थापित हो गयी। राष्ट्रवादी सरकार के अध्यक्ष च्यांग काई शेक ने भागकर ताइवान में अपनी अलग सरकार बना ली। चीन में साम्यवादी शासन के गाँव जमने से अमरीका नाराज हो गया तथा उसने ताइवान की च्यांग काई शेक सरकार को चीन की असली सरकार के रूप में मान्यता प्रदान की। साम्यवादी चीन की संयुक्त राष्ट्र सच में सदस्यता के मामले पर अमरीका ने बारम्बार 'वीटो' का प्रयोग कर उसका रास्ता रोकें रखा। उसने ताइवान को संयुक्त राष्ट्र सच का सदस्य तथा उसी को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनवाया। अन्त में 1971 में ताइवान को निष्कासित कर साम्यवादी चीन को यह सदस्यता प्रदान की गई।

7. बर्लिन की घेराबन्दी और दो जर्मनी का उदय—एक मार्च, 1948 को रूस ने स्थानीय मुद्रा विपयक झगड़े का बहाना बनाकर पश्चिमी बर्लिन के स्थल और जलमार्ग सभी की नाकेबन्दी कर दी, जिससे दोनों महाशक्तियों के बीच एक और सकट उत्पन्न हो गया तथा उनकी अपनी ताकत की आजमाइश का एक और मौका प्राप्त लगा। हालांकि सोवियत सच बर्लिन की नाकेबन्दी करने में असफल रहा और मई, 1948 में ही उसे नाकेबन्दी समाप्त करनी पड़ी, फिर भी इसके दूरगामी परिणाम हुए। पहला, अमरीका ने रूस के खिलाफ अनेक सैनिक समूहों का निर्माण कर अन्य देशों को अपने गुट की ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया। दूसरा, जर्मनी दोनों महाशक्तियों के शीत युद्ध का क्रीडा-स्थल बन गया। अमरीका, ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने अधीनस्थ जर्मनी के तीनों पश्चिमी क्षेत्रों का एकीकरण कर दिया, जिससे 21 सितम्बर 1949 को संघीय जर्मन गणराज्य (Federal Republic of Germany) का निर्माण हुआ। यह अमरीकी गुट का प्रभाव क्षेत्र बन गया। दूसरी ओर इसके प्रत्युत्तर में 7 अक्टूबर, 1949 को रूस ने अपने अधीनस्थ जर्मन क्षेत्र में जर्मन प्रजातन्त्रात्मक राज्य (German Democratic Republic) की स्थापना करवा दी। इसी रूप में अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लिया। इस प्रकार महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध की ज्वाला धधकती रही।

8. अमरीका-जापान शान्ति सन्धि—1951 में अमरीका तथा उसके मित्र राष्ट्रों ने जापान के साथ शान्ति सन्धि पर हस्ताक्षर किये। सोवियत सच द्वारा परोक्ष रूप से इसे अपने खिलाफ मानने के कारण उसने इस शान्ति सन्धि की कड़े शब्दों में आलोचना की। इस प्रकार अमरीका-जापान सन्धि अमरीका-सोवियत सम्बन्धों में तनाव का कारण बनी।

9. कोरिया संकट—कोरिया भी महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा का शिकार हो गया, क्योंकि सोवियत संघ और अमरीका दोनों उसकी अपनी छवि के अनुरूप बनाना चाहते थे। रूस ने उसे साम्यवादी बनाना चाहा, जो उनका पड़ोसी, मित्र एवं समर्थक हो, जबकि अमरीका ने एक मोन्टेनान्द्रिक कोरिया चाहा जो पश्चिमी गुट का अंग हो। इस प्रतिस्पर्धा से कोरिया के दो टुकड़े हो गये। जहाँ उत्तरी कोरिया में रूस

समर्थक सरकार बनी तो दक्षिण कोरिया में अमरीकी समर्थक सरकार। जून, 1950 में चीनी एवं रूसी सैनिक मदद के बलबूते पर उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर फौजी हमला कर दिया। फिर क्या था, उधर से अमरीका ने दक्षिण कोरिया को सैनिक सहायता देकर मुठभेड़ को और उग्र बना दिया। इस प्रकार कोरिया संकट को लेकर जहाँ अमरीका और पश्चिम यूरोप के राष्ट्र एक हो गये, वहीं रूस और चीन एकजुट हो गये। असल में उत्तरी व दक्षिण कोरिया के बीच की मुठभेड़ रूस एवं अमरीका में ही थी। सशस्त्र युद्ध रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सभ में बहसें आरम्भ हुईं। दोनों महाशक्तियों ने खुलकर एक-दूसरे के विचारों का कड़ा प्रतिवाद किया। संयुक्त राष्ट्र सभ ने उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित किया। अन्ततः 8 जून, 1953 को युद्ध बिराम हुआ।

शीत युद्ध का दूसरा चरण (1953 से 1958)

शीत युद्ध के दूसरे चरण में महाशक्तियों के राजनीतिक नेतृत्व में परिवर्तन हुआ। अमरीका में ट्रूमैन की जगह पर आइज़नहावर राष्ट्रपति बने तो सोवियत सभ में स्टालिन की मृत्यु व बाद कुल्गानिन और उसके बाद ख्रुश्चेव ने शासन-सत्ता की बागडोर संभाली। शीत युद्ध के दूसरे चरण की प्रमुख घटनाएँ निम्नांकित हैं।

1. रूस द्वारा परमाणु परीक्षण—1953 में सोवियत सभ ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया। इससे उसका परमाणु क्षेत्र में अमरीका के समकक्ष होने का मार्ग प्रशस्त हो गया। रूस ने सफल परमाणु परीक्षण सम्पन्न कर जहाँ परमाणु हथियारों का निर्माण आरम्भ किया, वही उसके प्रतिद्वन्द्वी अमरीका तथा पश्चिम के राष्ट्रों की सुरक्षा का खतरा महसूस हुआ। परिणामस्वरूप दोनों महाशक्तियों में नये घातक परमाणु दारनाशूरी का आविष्कार कर उनका डेर लगाने की होड़ आरम्भ हो गयी। सावियत सभ द्वारा स्पूतनिक नामक कृत्रिम उपग्रह का परीक्षण इसका अच्छा उदाहरण है।

विद्वम्बना तो यह यह है कि स्पूतनिक के सफल परीक्षण के अक्त आइज़नहावर जैसे अनुभवी सेनानायक ने टिप्पणी की थी कि 'इसका कोई सैनिक महत्व नहीं है। यह सिर्फ वैज्ञानिक वाजीगरी है, जिससे पीछे किसी को अपनी नींद खराब नहीं करनी चाहिए। तानाशाही अक्सर इस तरह के खमत्कारी स्मारक बनाती है।' बस्तुतः इन वैज्ञानिक आविष्कारों का अत्यधिक सामरिक महत्व था, जिसका यथार्थ-वादी मूल्यांकन प्रसिद्ध विज्ञान एडवर्ड ज़ेन्ज़ा ने किया है। उसके अनुसार 'सोवियत अन्तर-महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र न केवल एशिया और अफ्रीका के किसी भी ठिकाने तक पहुँच सकते हैं, बल्कि पृथ्वी गार ऐसा हुआ है कि अमरीका इनकी चपेट में आने से नहीं बच सका।' ¹ इसका दायमिर के मत में इस उपलब्धि ने चीनियों के मुकाबले में सोवियत सभ और ख्रुश्चेव की स्थिति मजबूत की। ²

■ हिन्द चीन की समस्या—हिन्द चीन क्षेत्र (वियतनाम, कम्पुचिया और लाओस) में दोनों महाशक्तियाँ अपनी-अपनी समर्थक सरकारें स्थापित करने के प्रयत्न में लगे रहीं। इस क्षेत्र में फाषीसी साम्राज्यवाद के विरुद्ध चलने वाले गणपं में यह युद्ध, सैनिक खराब या अच्छावस्था आम बात हो गयी। फाषीसी औपनिवेशिक

¹ Edward Crankshaw, *The New Cold War* (London, 1963)

² Isaac Deutscher, *Russia China and the West* (London, 1970)

शासकों द्वारा हिन्द चीन छोड़ने के निर्णय के बाद अमरीका का बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में प्रवेश शीत युद्ध के कारण ही प्रेरित था। अपने को मुकाबले की विश्व शक्ति प्रमाणित करने के लिए सोवियत संघ को भी रणभूमि में उतरना पड़ा। 1954 में दिएन-थीएन फू के सैनिक गढ़ के पतन के बाद जेनेवा सम्मेलन बुलाया गया, जिसने हिन्द चीन में कम्युनिज्म और लाओस को स्वतन्त्र राष्ट्रों के रूप में स्थापित किया। वियतनाम का विभाजन अन्तर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त हुआ। जेनेवा समझौतों में यह बात मानी गयी कि दो वर्ष बाद जनमत संग्रह होगा और वियतनाम के राजनीतिक भविष्य, एकीकरण आदि का निर्णय लिया जायेगा। तब तक विभाजक सीमा रेखा पर विसैन्यीकृत क्षेत्र की घोषणा की गयी और अन्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की व्यवस्था की गयी। हिन्द चीन में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण नियंत्रक आयोग में भारत, कनाडा और पोर्तुगल शामिल किये गये। परन्तु शीत युद्ध के इस चरण में इस समझौते का लागू किया जाना सम्भव नहीं हुआ। अमरीकियों का प्रयत्न यही रहा कि वे दक्षिण में राष्ट्रपति जियेग को अपने मोहरे-कठपुतले के रूप में इस्तेमाल करते रहे और दूसरी ओर 1956 में चुनाव स्थगित किये जाने के बाद उत्तरी वियतनाम के साम्यवादियों द्वारा प्रेरित घुमसैठिये छापामारों की गतिविधियों ने जोर पकड़ा। क्रमशः लाओस और कम्युनिज्म भी छापागार रणनीति के अनुसार इस घुह युद्ध की चपेट में आ गये। यह शीत युद्ध का ही प्रभाव था कि दोनों प्रांतस्पर्धी पक्षों को एक या दूसरी महाशक्ति का समर्थन मिल गया।

3. 'सिएटो' एवं 'सेन्टो' का गठन—अमरीका ने तीसरी दुनिया के देशों में साम्यवाद का प्रसार रोकने के लिए 'सिएटो' (SEATO) एवं 'सेन्टो' (CENTO) सैनिक समझौते को क्रमशः 1954 एवं 1955 में प्रवर्तित किया। इन समझौतों द्वारा सदस्य देशों को सैनिक एवं अन्य प्रकार की सुरक्षा गारन्टी दी गयी। निश्चित रूप से यह रूस-विरोधी अमरीकी प्रयास था।

4. 'वारसा पैक्ट' का गठन—अमरीका द्वारा साम्यवाद का प्रसार रोकने के लिए प्रवर्तित 'सिएटो', 'सेन्टो' एवं 'नाटो' (NATO) के निर्माण के प्रत्युत्तर में सोवियत संघ भी वहाँ चूकने वाला था। उसने जवाबी कार्यवाही के रूप में 14 मई, 1955 को पूर्व-यूरोपीय देशों को वारसा पैक्ट में शामिल कर सैनिक तथा अन्य प्रकार की सुरक्षा की गारन्टी प्रदान की। निश्चित रूप से यह सोवियत प्रयास अमरीका-विरोधी था। वारसा पैक्ट मूलतः अमरीकी 'नाटो' का जवाब था। इसमें रूस और उसके आठ-पूर्व यूरोपीय साथी राष्ट्र सम्मिलित हुए। 1991 में वारसा पैक्ट समाप्त कर दिया गया।

5. आइजनहावर सिद्धान्त की घोषणा—जून, 1957 में अमरीका द्वारा 'आइजनहावर सिद्धान्त' की घोषणा की गयी। इस सिद्धान्त के अनुसार अमरीकी कांग्रेस ने राष्ट्रपति को पश्चिम एशिया के किसी भी देश में साम्यवादी आक्रमण को रोकने के लिए अपने विवेक के अनुसार सेना भेजने तथा सैनिक कार्रवाई करने का अधिकार दिया। आइजनहावर सिद्धान्त की घोषणा से पश्चिम एशिया के देशों में महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध की गर्मी और बढ़ गयी। परिणामस्वरूप सामरिक महत्व के पश्चिम एशियाई क्षेत्र और तेल कुओं पर प्रभुमत्ता जमाने के लिए अमरीका और इस दोनो एक-दूसरे के विरुद्ध गूढ़नीतिक चाने चलते रहे।

6. पश्चिम एशिया का संकट—आइजनहावर सिद्धान्त की घोषणा पर रूसी

प्रतिक्रिया यह हुई कि उसने इसको पश्चिम एशिया के लिए घातक बताया। दूसरी तरफ अमरीका तथा ब्रिटेन ने पश्चिम एशियाई देशों में मोबियत घुसपैठ तथा राजनीतिक तोड़ फोड़ की आलोचना की। फलस्वरूप इस क्षेत्र में अमरीका तथा रूस ने अपने-अपने प्रभाव क्षेत्र जमाना आरम्भ किया। अमरीका ने इजराईल का पक्ष लिया तो सोवियत संघ ने फिनलैंड का समर्थन कर अरब देशों को अपनी ओर खींचने का प्रयास किया। इसकी परिणति 1956 में अरब-इजराईल युद्ध में हुई।

7 स्वेज नहर का संकट—1956 में स्वेज नहर ने राष्ट्रीयकरण के जवाब में फ्रान्स और ब्रिटेन ने मिस्र पर सैनिक हमला कर दिया। अमरीका ने मिस्र पर हमले में फ्रान्स और ब्रिटेन का साथ नहीं दिया। फिर भी यह हमला उसके मित्र राष्ट्रों द्वारा किया गया था। सोवियत संघ ने इस हमले की कड़ी आलोचना की। इसने एक बार फिर शीत युद्ध में गरमाहट उत्पन्न की।

शीत युद्ध के अनेक स्थानीय संकट हासिलमुख, औपनिवेशिक सामर्यों के अहंकार और अपयार्थवादी दृष्टिकोण से उत्पन्न थे। स्वेज संकट के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री ईडन ने कहा—‘तानाशाहों की भ्रूख समझौतों के साथ बड़ती जाती है। हम लोग सूटपाट को सहन नहीं कर सकते और न ही नासिर (मिस्र के राष्ट्रपति) की गतिविधियों को अपराधपूर्ण नपसकता के भरोसे छोड़ सकते। सभी अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियों को मिलाकर यह तय कर लेना चाहिए कि हम नासिर को समर्थन के लिए तैयार कर लेंगे।’ ईडन की समझ में यह बात नहीं आ सकती थी कि इस तरह का अन्तर्राष्ट्रीय संकट निवारण एक स्वतन्त्र राष्ट्र के आन्तरिक मामलों में आक्रमणकारी हस्तक्षेप था।

शीत युद्ध के इस द्वितीय चरण में कुछेक अन्य घटनाएँ घटीं। मसलन, 1956 में हंगरी में सोवियत सैनिक हस्तक्षेप एवं उसकी पश्चिम के देशों द्वारा भरतना, रूस और अमरीका द्वारा हाइड्रोजन बम का निर्माण, फारस का तेल विवाद, लिबनान में अमरीकी फौज का प्रयोग तथा इराक की क्रांति। इन छुटपुट घटनाओं में महा-शक्तियों के बीच शीत युद्ध की लपटों की और तेज किया।

शीत युद्ध का तीसरा चरण (1959-1962)

तीसरे चरण में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति अमरीका और रूस की अनबन, ‘पिपलाव’ और ‘गरमाहट’ दोनों की ओर धुनगि लगाती रही। स्ट्रुस्चेव द्वारा शान्ति-पूर्ण महा-अस्तित्व की वचावत से अनेक राजनीतिक टिप्पणीकारों ने सोचा कि अब महानाशियों के बीच शीत युद्ध सिमित हो जायेगा, किन्तु प्रारम्भिक सफलताओं के बाद दोनों में बन्नी पिपलाव, बन्नी गरमाहट रही। इस चरण की प्रमुख घटनाएँ निम्नांकित हैं—

1 1959 में स्ट्रुस्चेव की अमरीका यात्रा—स्टालिन की मृत्यु (1953) के बाद बुल्गारिन और उसके हटने के पश्चात स्ट्रुस्चेव के सत्ता में आन (1956) के बाद 3 अगस्त, 1959 को मास्को और वाशिंगटन से एक साथ घोषणा हुई कि कुछ ही दिनों में सोवियत प्रधानमंत्री स्ट्रुस्चेव अमरीका की, और अमरीकी राष्ट्रपति आइजनहावर सोवियत संघ की यात्रा पर जायेंगे। 15 गितम्बर, 1959 को स्ट्रुस्चेव अमरीका पहुँचे और वह एक महीन तह उम दस व विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते

रहे। उनका सर्वत्र भव्य स्वागत किया गया। केम्प डेविड नामक स्थान पर उन्होंने आइजनहावर से विचार-विमर्श किया। यह तय किया गया कि 16 मई, 1960 से पेरिस में निःशस्त्रीकरण की समस्या सुलझाने के लिए शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाये और वहीं से राष्ट्रपति आइजनहावर सोवियत सभ की यात्रा पर रवाना हो। इस प्रकार ख्रुश्चेव की अमरीका-यात्रा से दोनों देशों के बीच शीत युद्ध की शिथिलता के आसार दिखाई देने लगे। इसे 'केम्प डेविड की भावना' के नाम से पुकारा गया।

2. यू-2 विमान काण्ड एवं पेरिस शिखर सम्मेलन की असफलता—पेरिस सम्मेलन के दो सप्ताह पूर्व अर्थात् एक मई, 1960 को यू-2 विमान काण्ड के होने से 'केम्प डेविड की भावना' पर पानी फिर गया। अमरीका का एक जासूसी विमान सोवियत सीमा का उल्लंघन करके दो हजार किलोमीटर अन्दर घुसा गया। इस को इसका पता चलने पर उसने विमान चालक को पहले नीचे उतरने को कहा। ऐसा न करने पर उसने रॉकेटों की सहायता से उसे नीचे गिराकर उसके चालक गैरी पायर्स को जिन्दा गिरफ्तार कर लिया। अमरीका ने इसके प्रति पहले अपनी अनभिज्ञता प्रकट की। पर गैरी पायर्स द्वारा जासूसी के इराबे की स्वीकारोक्ति से अमरीका ने भी यह मांगा। सोवियत सभ ने अमरीका की इस कार्यवाही की कड़े शब्दों में आलोचना की। इसका परिणाम पेरिस शिखर सम्मेलन की असफलता के रूप में सामने आया। यू-2 विमान काण्ड के कारण सोवियत सभ ने अमरीका से कहा कि वह अपने इस जासूसी कार्य की निन्दा करे, माफ़ी मागे, भविष्य में ऐसी उत्तेजक गतिविधियाँ नहीं करे तथा इस निन्दनीय घटना के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को सजा दे। ख्रुश्चेव ने आइजनहावर की सोवियत यात्रा का निमन्त्रण वापस लेते हुए कहा कि अब अमरीकी राष्ट्रपति यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं।

जब पेरिस शिखर सम्मेलन आरम्भ हुआ तो ख्रुश्चेव ने यू-2 विमान काण्ड को उठाते हुए अपनी उक्त भाँगे रखी। अमरीकी राष्ट्रपति आइजनहावर इसके लिए तैयार नहीं थे। सम्मेलन में ख्रुश्चेव ने कामीसी राष्ट्रपति बेगोल और ब्रिटिश प्रधानमन्त्री मेकमिलन से तो हाथ मिलाया किन्तु आइजनहावर के हाथ बढाने पर ख्रुश्चेव ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। आइजनहावर द्वारा भविष्य में ऐसी कार्यवाही न करने के आश्वासन एवं बेगोल और मेकमिलन द्वारा गतिरोध को दूर करने के प्रयास भी सफल नहीं हुए। यहाँ तक कि सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन में ख्रुश्चेव ने भाग नहीं लिया। फलस्वरूप सम्मेलन की कार्यवाही बन्द करनी पड़ी। इस प्रकार पेरिस सम्मेलन असफल हो गया और शीत युद्ध की शिथिलता के आसार फीके नजर आने लगे।

3. ब्यूबा संकट—पेरिस शिखर सम्मेलन की असफलता से सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय समाज में गहरी निराशा छा गयी। ख्रुश्चेव ने भी महसूस किया कि उन्हें इतना कड़ा एज नहीं अपनाना चाहिए था। इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने गुलह की पहल की। ख्रुश्चेव ने 10 नवम्बर, 1960 को बक्तव्य जारी कर कहा कि 'अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में सब प्रकार के तनाव उत्पन्न होते हैं किन्तु समय बीतने के साथ ऐसे सम्बन्धों की मट्टा दूर हो जाती है। इसकी परवाह न कीजिए कि समुद्र बितना तूफानी है? तूफानों के बाद हमेशा शान्ति आती है। यही अन्ततः यू-2

विमान की घटना के बाद होगा। इसकी ज़ामूसी उद्धान अन्तुनापूर्ण कार्य थी, किन्तु कुछ समय बाद यह तूफान भी शान्त हो जायेगा।' उधर अमरीका में राष्ट्रपति पद के चुनाव में जॉन एफ० कनेडी के विजयी होने से एक नई आशा का संचार हुआ। क्लूस्चेव ने कनेडी को बधाई दी, जिसका उन्हें आशापूर्ण जवाब मिला। अमरीकी राष्ट्रपति कनेडी ने कहा—'हम किस तरह की शान्ति चाहते हैं? कब्रिस्तान की शान्ति या खामोश बंटे गुलामों की शान्ति नहीं, बल्कि एक ऐसी शान्ति, जिसमें जीवन जीने लायक लग तथा जिसमें मनुष्य जाति और विभिन्न राष्ट्र आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर ससार छोड़कर जा सकें। हम सिर्फ अपने समय के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए शान्ति चाहते हैं। शान्ति की हमारी यह अभिलाषा सोवियत अभिलाषा के समानान्तर है।' किन्तु यह आशावादिता ज्यादा समय तक नहीं चल सकी। क्यूबा मसल ने रूस और अमरीका को एक बार फिर शत्रु के रूप में आमने-सामने खड़ा कर दिया।

केरिबियाई महाद्वीप में स्थित क्यूबा हर दृष्टि में दोनों महाशक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है। एक ओर रूस के लिए वह लकड़घोड़ा (Trojan-horse) हो सकता है तो दूसरी ओर अमरीका के लिए वह गठिया रोग जैसा हो सकता है। सामरिक दृष्टि से दोनों महाशक्तियों के लिए इस महत्वपूर्ण राष्ट्र में 1958 में डाक्टर फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। उनके द्वारा सोवियत सघ के साथ सम्बन्ध बढ़ाने से अमरीका का चिन्तित होना स्वाभाविक था, क्योंकि क्यूबा के जरिये रूस उसके पड़ोसी देशों में प्रभाव जमाने का प्रयत्न कर रहा था। कास्त्रो सरकार की विनाश सोवियत सैनिक एवं आर्थिक मदद मिल रही थी। 1962 में सोवियत सघ ने क्यूबा में नये सैनिक अड्डे स्थापित किये, जिनमें राकेट-प्रक्षेपास्त्र रले गये। अमरीका ने अपनी सुरक्षा के हितों को ध्यान में रखकर 22 अक्टूबर, 1962 को क्यूबा की तटबन्दी पर दी। उसने अपनी नीमना को आदेश दिया कि क्यूबा की ओर जाने वाले वह उसे ममस्त जहाजों को रोक दे, जिनमें आश्रामक दस्त्रास्त्र भरे हों। सोवियत सघ ने मामले की गम्भीरता महसूस करने हुए सीधे ही क्यूबा से सैनिक अड्डे हटाने की घोषणा कर दी। यदि रूस ऐसा निर्णय नहीं लेता और अमरीका उसका प्रतिकार करता तो शायद शीत युद्ध की परिणति तीसरे विश्व युद्ध के रूप में होती। क्यूबा मसल के बारे में दोनों महाशक्तियों द्वारा बुद्धिमत्तापूर्ण कदम उठाना शीत युद्ध के शिविलीकरण में 'शील का पत्थर' माना जा सकता है। इस सम्बन्ध में एडवर्ड क्रेण्डा का मानना एकदम सही है कि 'क्यूबा के बाद से ज्वार एक ही दिशा में बह रहा है। वाशिंगटन के साथ लगातार और गुप्त बचावबचन के साथ उष्ण स्थलों का प्रतिक शीतनीकरण (damping down) हुआ है।'

शीत युद्ध का चौथा चरण (1963-1979)

चौथे चरण में जहाँ दोनों महाशक्तियों के बीच 'तनाव-नैपित्य' आरम्भ हुआ, वहाँ 'एन्गुट प्रतिद्वन्द्विता' चलती रही। इस चरण में शीत युद्ध की गिथिलता की प्रमुख घटनाएँ निम्नांकित हैं—

1. परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि—क्यूबा मसल के बाद दोनों महाशक्तियों ने महसूस किया कि यदि उन्होंने आपसी टकराव को रोकने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया तो महायुद्ध अभी भी छिड़ सकना है। निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में

23 जुलाई, 1963 को मास्को में रूस, अमरीका और ब्रिटेन ने वायुमण्डल, बाह्य अन्तरिक्ष और समुद्र में परमाणु परीक्षण पर प्रतिबन्ध सन्धि पर हस्ताक्षर किये। इसके बाद चीन, फ्रांस तथा कुछ अन्य राष्ट्रों को छोड़कर करीब सौ से अधिक देशों ने इस सन्धि पर हस्ताक्षर किये।

2. 'हॉट लाईन' (Hot Line) समझौता—1963 में क्रेमलिन (मास्को) तथा ह्वाइट हाउस (वॉशिंगटन) के बीच 'हॉट लाईन' के जरिये सीधा सम्पर्क स्थापित करने का समझौता हुआ। इस सीधे सम्पर्क का उद्देश्य यह था कि किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय या द्विपक्षीय संकट के दौरान महाशक्तियों में भूल, आकस्मिक दुर्घटना या गलतफहमी के कारण उत्पन्न टकराव को टाला जाये। इसके द्वारा दोनों देशों के शासनाध्यक्ष सीधा सम्पर्क करके संकट का निवारण कर सकते हैं।

3 परमाणु अस्त्र-प्रसार रोक सन्धि—1968 में सोवियत संघ, अमरीका और ब्रिटेन ने अन्य देशों के साथ 'परमाणु अस्त्र-प्रसार विरोध सन्धि' पर हस्ताक्षर किये। सन्धि के अनुसार वे अन्य देशों द्वारा परमाणु अस्त्र प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की सहायता नहीं करेंगे। इसका उद्देश्य परमाणु अस्त्रों की होड़ रोककर तनाव कम करना था।

4. मास्को-बोन समझौता—1970 में सोवियत संघ और पश्चिम जर्मनी के बीच यह समझौता हुआ। इस समझौते के द्वारा दोनों देशों ने यथास्थिति को स्वीकार कर एक-दूसरे के खिलाफ शक्ति प्रयोग नहीं करने का निर्णय लिया। इससे दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का तनाव काफी कम हुआ।

5. बर्लिन समझौता—3 सितम्बर, 1971 को अमरीका, सोवियत संघ, ब्रिटेन तथा फ्रांस के बीच करीब अठारह महीने की लम्बी बातचीत के बाद बर्लिन समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके अन्तर्गत पश्चिमी बर्लिन के निवासियों को पूर्वी बर्लिन तथा पूर्वी जर्मनी आने की अनुमति देने की व्यवस्था थी। इसके पहले इस पर रोक थी। बर्लिन समस्या का यह हल खोजकर तनाव कम किया गया।

6. दो जर्मन राज्यों का सिद्धान्त—8 नवम्बर, 1972 को पश्चिम जर्मनी की राजधानी बोन में दो जर्मन राज्यों का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया। इसमें हुए समझौते में पूर्वी तथा पश्चिम जर्मनी के बीच सन्धि हुई। इन दोनों देशों को 1973 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान की गई। इस मामले पर सुरक्षा परिषद् में दोनों महाशक्तियों ने न तो कोई आपत्ति प्रकट की और न ही 'वीटो' की प्रयोग किया। इसने महाशक्तियों के बीच तनाव को कम करने का मार्ग प्रशस्त किया।

7. यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन—3 जुलाई, 1973 को पिजलैण्ड की राजधानी हेलसिंकी में यूरोपीय सुरक्षा और सहयोग सम्मेलन हुआ। जेनेवा में यह सम्मेलन 17 सितम्बर, 1973 से 21 जुलाई, 1975 तक जारी रहा और 1 अगस्त, 1975 को यह हेलसिंकी में समाप्त हुआ। इसमें 35 देशों ने भाग लिया। सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य यूरोपीय देशों में आपसी सम्बन्ध सुधारना तथा उन्हें सुदृढ़ करना एवं यूरोप में शान्ति, न्याय और सहयोग बढ़ाना था। सम्मेलन में निम्नांकित सिद्धान्तों की घोषणा की गयी :

1. संयुक्त राष्ट्र संघ में आस्था तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति, सुरक्षा और न्याय की स्थापना में उसकी भूमिका तथा प्रभावकारिता को बढ़ावा देना;

- 2 राज्यो में मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का विकास करना;
- 3 समस्त राज्यों की सार्वभौमिक समानता का आदर करना,
- 4 शक्ति का प्रयोग या उसके प्रयोग की धमकी न देना;
- 5 सीमाओं का उल्लंघन न करना,
- 6 राज्यों की क्षेत्रीय अखण्डता में विश्वास,
- 7 राज्यों के आन्तरिक मामलों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अकेले या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप न करना,
- 8 विचार, अन्तरात्मा, धर्म या विश्वास सहित मानव अधिकारों और मूल स्वतन्त्रताओं के प्रति आदर रखना,
- 9 लोगों के समान अधिकारों और आत्म-निर्णय के अधिकार को स्वीकार करना,
- 10 राज्यों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना,
- 11 अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत उत्तरदायित्व का स्वेच्छा से पालन करना इत्यादि।

8 हिन्द चीन का सघर्ष—शीत युद्ध के इस चौथे चरण में हिन्द चीन में सघर्ष में भीषण रूप ले लिया और कम से कम कुछ समय के लिए ऐसा प्रतीत होती या कि विश्व शान्ति को सबसे बड़ा सबोट इसी क्षेत्र में है। 1965 से अमरीकी 'सलाहकारों' ने युद्धरत विदेशी सैनिकों का रूप ले लिया था और आधुनिकतम शस्त्रास्त्रों से सज्जित होने के बावजूद उन्हें मुक्ति सैनिकों के हाथों लगातार मृह की खानी पड़ रही थी। 1968 में टॉमकिन की खाड़ी बाड़ के बाद अमरीकी युद्ध संचालन निरन्तर बर्बर होता गया। प्रतिपक्ष ने भी जवाबी हमलों में क्रूरता बढ़ायी। 'टॉमकिन की खाड़ी में उठे बवंडर ने एक बार फिर यह प्रमाणित किया कि वास्तव में अमरीका और सोवियत संघ के बीच नैतिक, राजनीतिक और सैनिक क्षेत्र में कितनी गैर-बराबरी है। यह गैर बराबरी लगभग पूरे शीत युद्ध के दौर में इन दो महाशक्तियों के सम्बन्धों में बार-बार झलकती रही। जब रूसियों ने बमूबा में प्रक्षेपास्त्र रले तो अमरीकियों ने उन्हें हटाने पर विवश किया। सातवीं अमरीका में सोवियत संघ का प्रवेश बर्जित रहा और विवशनाम, लाओस आदि में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार करने के अलावा उनके पास कोई चारा न था। इन वर्षों में सोवियत संघ इसी आधार पर समझा जा सकता है। इन्हीं कारणों से सोवियत संघ के लिए निम्नी परमाणु भण्डार जुटाना परमावश्यक हुआ था। इसी कारण चीनियों को रूसियों पर समझौतापरस्ती, मशोधनवाद और अवसरवादिता का आरोप लगाने का अवसर मिला।

1968 से 1970 के दौरान सैन्य में आतंककारी बमबारी, बौद्ध भिक्षुओं का आत्मशह, ग्रेट आत्ममर्ष के दौरान अमरीकी दूतावास पर छामापात्रों का कब्जा ऐसी घटनाएँ थी, जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ाया। युद्ध की गति तेज होने के साथ सन्धु का मनोबल तोड़ने के लिए हवाई व हार्डफोर्ग की बेराबन्दी की गयी और घरे पमाने पर नागरिक ठिकानों पर बमबारी शुरू हुई। 1970 में गुट-निरपेक्ष सम्मुचिया में मित्रानुच अपदस्थ हुए और लाओस लगभग पूरी तरह साम्यवादी प्रभाव क्षेत्र में घना गया। इस मन्दर्भ में एक महत्वपूर्ण ज्ञान याद रखने की है कि हिन्द

चीन में संघर्ष के बारे में सोवियत-चीन विवाद के बावजूद दोनों देशों में मतभेद या और दोनों विषयनाम को सहायता देते रहे।

हिन्द चीन में प्रकृति संघर्ष का अन्तर्राष्ट्रीय महत्व और इससे पैदा हुए अन्तर्राष्ट्रीय संकट का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि इन वर्षों में एकाधिक बार युद्ध भयानिक के लिए परमाणु अस्त्रों के उपयोग की बात सुनायी गयी। इनके अलावा अमरीका के सख्त मित्र 'मिएटो' के सदस्य फिलीपीन्स, थाइलैण्ड आदि अनायास ही इन संघर्ष में खिंच गये और उनके सम्बन्ध अपने पड़ोसी देश के साथ बिगड़ गए। इस तरह हिन्द चीन में संघर्ष का अगर महा-शक्तियों के आपसी सम्बन्धों, क्षेत्रीय-सहकार, गुट-निरपेक्ष देशों के राजनय आदि पर देखा जा सकता है। अतः तनाव-सौमित्र्य और अमरीका-चीन सम्बन्धों में सामान्यीकरण के बारे में विषयनाम में युद्ध विराम का मार्ग प्रशस्त हो सका। यह तथ्य इस बात को पूरी तरह प्रमाणित करता है कि विषयनाम सम्बन्ध मूलतः शीत युद्ध-जनित थी।

अक्सर हिन्द चीन की समस्या की तुलना म्यान पृष्ठभूमि के कारण पश्चिम एशिया से की जाती है। परन्तु इसे अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए कि हिन्द चीन में कम से कम एक महाशक्ति अमरीका प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी थी और इस समस्या का समाधान शीत युद्ध में कभी भी नहीं, बल्कि अमरीका के बक जाने के कारण आन्तरिक राजनीति के दबावों के अनुसार हुआ। हिन्द चीन का संघर्ष विकट और दीर्घकालीन होने के बावजूद यह तनाव-सौमित्र्य के कारण ही सम्भव हुआ कि दोनों महाशक्तियों में घातक मुठभेड़ नहीं हुई।

चौथे चरण में महाशक्तियों के बीच छुटपुट टकराव या प्रतिद्वन्द्विता वाली प्रमुख घटनाएँ निम्नांकित हैं -

1. भारत-पाक युद्ध—भारत और पाकिस्तान में 1965 और 1971 में युद्ध हुए। इन मुठभेड़ों के बारे में मजेदार बात यह थी कि दोनों ही पक्ष शत्रुतापूर्ण के आघात के लिए महाशक्तियों पर निर्भर थे और इनका विस्फोट बिना दोनों महाशक्तियों के बीच सहमति के होना नहीं जा सकता था। 1965 के बाद ताम्रबन्द समझौते के दौरान महाशक्तियों ने उपमहाद्वीप में घाति बनाये रखने के लिए सम्पत्ति की भूमिका अपनाने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखायी। 1971 तक यह बात बाकी हद तक प्रत्यक्ष चुली थी। दंगला देश मुक्ति अभियान के दौरान भारत-सोवियत सहयोग व रूसी सख्त ने अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। इन मिलजुल में जानने योग्य बात यह है कि तब तक अमरीका ने चीन के साथ अपने सम्बन्धों का सामान्यीकरण आरम्भ कर दिया था और सोवियत मध्य को अपनी राजनीतिक स्थिति निरूपित नहीं कर रही थी। पाकिस्तान ने फौजी सान्नागाह को अमरीका व चीन का समर्थन प्राप्त था और इसलिए एक बार फिर शीत युद्धजनित दबावों के अनुसार महाशक्तियों ने भारत-पाकिस्तान टकराव में अपनी भूमिका निभायी।

2. पश्चिम एशिया संकट—तेन जैमी सनिज वस्तु के सामरिक महत्व के कारण पश्चिम एशिया का क्षेत्र महाशक्तियों की उपस्थिति का प्रमुख कारण रहा है। अमरीकी सरकार ने दृढ़ी दशाव के कारण इजरायल का समर्थन किया। हम ने इसके विरुद्ध अन्य पश्चिम एशियाई राष्ट्रों को फिनलैंड की गांव के समर्थन में आग्रह करना आरम्भ किया। उनके ही एक-दूसरे के विरुद्ध खड़ा करने के कारण

इजराइल एवं अरब देशों के बीच 1956 के बाद 1967 एवं 1973 में दो और युद्ध हुए। 1978 में पश्चिम एशिया संकट सुलझाने के लिए तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति कार्टर की पहल पर इजराइल और मिस्र के बीच कैम्प डेविड समझौता हुआ। इससे एक बार फिर महाशक्तियाँ आमने-सामने खड़ी हो गईं। अरब देश भी इस समझौते के बारे में विभाजित हो गये। शीत युद्ध के पहले चरण में पश्चिम एशिया का संकट मूलतः अरब राष्ट्रवाद के उदय, तेल सम्पदा पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रभुत्व, यहूदी-अरब टकराव तथा सोवियत संघ की घेराबन्दी से जुड़ा था। 1973 के बाद से इस स्थिति में नाटकीय परिवर्तन हुआ और पश्चिमी एशिया का संकट फिलिस्तीनी शरणार्थियों के भविष्य, लेबनान में साम्प्रदायिक हिंसा और अराजकतावादी आतंकवाद से जुड़ गया। सीबिया के कर्नल कदाफी ही नहीं, ईरान के खुमैनी भी इस जटिल गुरुपी से अनिवार्यतः जुड़ गये।

3 हिन्द महासागर—हिन्द महासागर भू-राजनीतिक दृष्टि से इस और अमरीका दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहा है। इस जल राशि में उपस्थिति के जरिए महाशक्तियाँ इसके 44 तटीय देशों पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव रख सकती हैं। उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी नौसैनिक उपस्थिति बायम करना आरम्भ किया। वर्तमान में भी दोनों महाशक्तियों के नौसैनिक जहाज घूमते रहते हैं। हालाँकि 1971 में समुक्त राष्ट्र संघ महासभा में भारी बहुमत से पारित प्रस्ताव ■ अनुसार यह बड़ी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा से मुक्त क्षेत्र बनना चाहिए। किन्तु बड़ी शक्तियों ने इस दिशा में अभी तक कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाया। यह बात उल्लेखनीय है कि हिन्द महासागर क्षेत्र में शक्ति संपर्क सोवियत पहलू के कारण धुर नहीं हुआ। वस्तुतः ग्रेट ब्रिटेन की बापमी के बाद शक्ति शून्य के स्वयमेव भर जाने वाले सिद्धान्त ■ अनुसार इस जल राशि पर अमरीकियों का एकाधिकार रहा है। यह बात भी ध्यान में रखने की है कि अमरीका की बराबरी करना सोवियत संघ के लिए सिर्फ प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं रहा बल्कि पनडुब्बी से लेकर प्रक्षिप्त परमाणु अस्त्रों की तकनीक तक में परिष्कार के कारण बहुत बड़ी सामरिक प्राथमिकता थी।

4 अफ्रीका में महाशक्तियों का टकराव—अनेक अफ्रीकी देश शीत युद्ध के चौथे चाल के दौरान औपनिवेशिक दामता से स्वतन्त्र हुए। अंगोला एवं जायरे के उदाहरण ज्यादा पुराने नहीं हैं, जहाँ उनकी स्वतन्त्रता मिलने के दौरान महाशक्तियों ने जी-नोट प्रभाव दिया कि उनकी सत्ता सम्भालने वाली सरकारें उनकी समर्थक हों। दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया में अल्पसंख्यक बोरो के विरुद्ध बहुसंख्यक बालो की सत्ता मोपन के बारे में रूस और अमरीका दोनों इस तान में रहे कि आगामी सरकार उनकी समर्थक हो। इसके लिए वे एक-दूसरे के विरुद्ध वहाँ दोनों प्रतिस्पर्धी गुटों की मदद करने लगे। अफ्रीका में महाशक्तियों के टकराव की गुंजाइश सिर्फ रणभेद की उत्प्रेरक नीति के कारण ही नहीं रही। कैम्प डेविड समझौते के बाद से सोवियत संघ को यह लगना रहा है कि अमरीका उसे इस पूरे क्षेत्र में उसके न्यायोचित हिस्से से वंचित रखना चाहता है। अतः अमरीकी राजनय को तनावग्रस्त रखने के लिए क्यूबा के माध्यम से सोवियत संघ का प्रयत्न अंगोला, मोजाबिक आदि सीमान्ती देशों की जुझारू आजापकता बनावे रखना रहा।

शीत युद्ध के प्रभाव (Effects of Cold War)

उपरोक्त घटनाक्रम के विश्लेषण से स्पष्ट है कि शीत युद्ध के अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर अनेक प्रभाव पड़े। संक्षेप में, उन्हें इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है—

1. भय एवं सन्देह का वातावरण—महाशक्तियों के आपसी टकराव के कारण विश्व समुदाय के देशों में एक-दूसरे के प्रति निरन्तर भय एवं सन्देह का वातावरण बना रहा। इस प्रतिकूल वातावरण ने अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में सहयोग एवं विश्वास उत्पन्न करने में अनेक बाधाएँ खड़ी की।

2. शस्त्रों की होड़ एवं निशस्त्रीकरण की असफलता—शीत युद्ध के कारण अधिकांश देशों ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए शस्त्रास्त्रों के भण्डार भरने आरम्भ किये। फलस्वरूप शस्त्रास्त्रों के निर्माण का अपार खर्च सहन करने के बाद लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों के सम्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ा। शस्त्रास्त्रों का भण्डार जमा करने की होड़ ने निशस्त्रीकरण प्रयास विफल हो गये।

3. सैनिक एवं प्रादेशिक संगठनों का गठन—शीत युद्ध के प्रारम्भिक काल में गरीब गुन्कों ने महाशक्तियों द्वारा प्रवर्तित सैनिक एवं प्रादेशिक संगठनों जैसे नाटो, सेन्टो, सिएटो एवं थारसा पैक्ट में शामिल होकर सुरक्षा पाही।

4. विश्व का दो गुटों में विभाजन व गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का आरम्भ—शीत युद्ध के कारण अमरीका और रूस के नेतृत्व में अन्तर्राष्ट्रीय समाज अनेक मामलों पर दो गुटों में घंट गया। इन गुटों के नेता देश अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए दूसरों की आड़ में सामन बनाते रहे। आरम्भ में भारत, मिस्र और यूगोस्लाविया ने महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा में किसी एक की तरफ़दारी करने से साफ़ इन्कार कर गुट-निरपेक्ष नीति अपनायी। बाद में इसका तीसरी दुनिया के अनेक देशों ने अनुसरण किया।

5. संयुक्त राष्ट्र संघ का अवमूल्यन—विश्व शान्ति एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से 1945 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मण्डल में महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा से उसके प्रभावशाली कार्य में अनेक अड़ने उत्पन्न हुए। यह मंगठन उनकी राजनीतिक का अखाड़ा बन गया। इस विश्व मंगठन में भी अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय गुटबाजी के बगुल में अडूता न रहा। दोनों महाशक्तियों ने अपनी हठधर्मिता के कारण 'वीटो' का दुरुपयोग किया। अमरीका ने चीन और वियतनाम द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यता पाने के सवाल पर वीटो का इस्तेमाल कर उनके प्रवेश को अनेक वर्षों तक रोके रखा।

6. अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता—विश्व के अन्य भागों में अपने-अपने राजनीतिक एवं आर्थिक स्वार्थों के कारण महाशक्तियों ने परोक्ष एवं अपरोक्ष हस्तक्षेप द्वारा वहाँ की मौजूदा सरकारों को बदलने का असफल एवं सफल प्रयास किया। इससे अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना रहा।

शीत युद्ध के प्रभाव के बारे में एक बार फिर इसाक डोयभर की टिप्पणियाँ विचारोत्तेजक और महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने लिखा है—'जैसा अक्सर ऐसे सैद्धान्तिक संघर्षों में होता है, कोई भी पक्ष यह नहीं देख सकता कि विवाद भविष्य में क्या

रूप लेगा ? विपत्ती की या स्वयं उसकी स्थिति क्या होगी ? इसी कारण चीन युद्ध के परिणामस्वरूप सोवियत आर्थिक नीतियों में सचीलापन, साम्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के प्रति उसका अधिष्ट और सोवियत चीन-विग्रह देखने की मिते ।

चीन युद्ध सैद्धान्तिक संघर्ष बनाम शक्ति राजनीति (Cold War Ideological Conflict vs Power Politics)

यहाँ पर यह सवाल उठना जरूरी है कि क्या चीन युद्ध विशुद्ध रूप से राष्ट्र हितों के संरक्षण के लिए शक्ति सन्तुलन एवं शक्ति प्रसार की राजनीति से प्रेरित था या इसके पीछे कोई सैद्धान्तिक कारण थे ? चीन युद्ध मूल रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के दो खेमों में विभाजित हो जाने की प्रक्रिया का परिणाम था । 1945 के पूर्व भी विश्व मोटे तौर पर समान रूप से शक्तिशाली दो ध्रुवों में विभाजित रहा । सैद्धान्तिक दृष्टि से भी द्वितीय विश्व युद्ध अधिनायकवादी एवं फासिस्ट शक्तियों के विरुद्ध लोकतन्त्रीय शक्तियों द्वारा लड़ा गया था । अतः सैद्धान्तिक रंग तब भी था, किन्तु 1945 के बाद ग्रेट ब्रिटेन के शक्ति पराभव ने यूरोप में शक्ति सन्तुलन को एकतरफा बना दिया और हम की शक्ति इतनी अधिष्ठ हो गई कि उसे यूरोपीय देश सन्तुलित करने में विफल रहे । अमरीका यद्यपि यूरोप में बहुत दूरी पर स्थित था किन्तु वह इस को सन्तुलित कर सकता था । इस दृष्टि से यूरोप के वे सभी देश, जो रूसी साम्यवादी पद्धति के विरुद्ध थे, अमरीका का मूँह ताकने लगे । उधर रूस साम्यवाद के प्रसार के लिए यूरोप और एशिया में पूँजीवादी खेमे को सतवारने लगा । द्वितीय विश्व युद्ध के तुरन्त बाद चीन, कोरिया एवं पश्चिम एशिया के कुछ देशों में साम्यवाद एवं रूस के बड़ते हुए प्रभाव से विचलित होकर पूँजीवादी खेमे ने अमरीका के नेतृत्व में साम्यवाद को 'अन्तर्राष्ट्रीय नासूर' की सजा देते हुए उसका प्रसार रोकने की कटिबद्धता स्पष्ट कर दी ।

विश्व के इस प्रकार दो खेमों में विभाजन के पीछे सैद्धान्तिक कारण थे । अमरीका और उसके साथी पश्चिम यूरोपीय देश जनतान्त्रिक व्यवस्था के पोषक थे एवं आर्थिक क्षेत्र में निजी सम्पत्ति एवं मुक्त व्यापार के दर्शन को सर्वाधिक महत्त्व देते थे । साम्यवादी व्यवस्था में इन बातों के लिए कोई स्थान न था । साम्यवाद दास्य एवं शक्ति के अन्त पर वैचारिक प्रचार को उचित मानता था । जहाँ रूस इस मिडान के तहत साम्यवाद का प्रसार करना चाहता था, वही अमरीका एवं मित्र राष्ट्र अपनी आर्थिक एवं सैनिक शक्ति के अन्त पर साम्यवाद का प्रसार रोकने दखला चाहते थे । यही चीन युद्ध के पीछे मुख्य मुद्दा था और इसी के साथ सैद्धान्तिक एवं राष्ट्र हित जुड़े हुए थे ।

वैसे दोनों खेमों ने चीन युद्ध को सैद्धान्तिक संघर्ष बतलाया है । उदाहरणार्थ, हर्नगंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री बिगटन चर्चिल ने अपने फ्लूटन भाषण में सोवियत व्यवस्था को लोह-दीवार (Iron curtain) बनाने हुए उसे ईसाई सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा माना था तथा साम्यवाद के अन्तर्गत परतन्त्र व्यक्तियों की स्वतन्त्र बनने के लिए एक आन्त-अमरीकी सन्धि आवश्यक मानी । पूँजीवादी खेमे के एक इतिहासकार बारतोड टोयनबी ने भी चीन युद्ध को उदारवादी लोकतन्त्र तथा सर्वाधिकारवादी साम्यवाद के मध्य संघर्ष माना । उनके अनुसार साम्यवाद और लोकतन्त्र को लेकर विश्व द्वि-ध्रुवीय प्रणाली में विभाजित हो चुका था, त्रिनरे

नेता क्रमशः रुस और अमरीका थे। हमारे देश, टोमनवी के अनुसार, 'बुद्ध न बुद्ध मात्रा में इनके आश्रित हैं।' इनमें से अधिकांश देश अमरीका पर और बुद्ध रुस पर आश्रित हैं। इनमें से कोई भी एक या दूसरी शक्ति से पूर्ण रूप से स्वतन्त्र नहीं है।

रुस ने भी पूँजीवादी देशों के साथ अपने संबंधों को सैद्धान्तिक रंग दे दिया। 5 अक्टूबर, 1947 को रुस सहित 18 प्रमुख साम्यवादी देशों के प्रतिनिधियों द्वारा मास्को तथा वारसा से एक साथ जारी किये गये घोषणा-पत्र से स्पष्ट होता है कि साम्यवादी भी शीत युद्ध को सैद्धान्तिक युद्ध मानते थे। इस घोषणा-पत्र में कहा गया है कि 'दो विरोधी राजनीतिक विचारवाराएँ स्पष्ट हो गयी हैं। एक ओर सोवियत मध्य तथा अन्य लोकतन्त्रीय राज्यों का उद्देश्य साम्राज्यवाद का विनाश तथा लोकतन्त्र को मजबूत बनाना है। दूसरी ओर इंग्लैंड और अमरीका का उद्देश्य साम्राज्यवाद को मजबूत बनाना तथा लोकतन्त्र का गला घोटना है। चूकि सोवियत संघ और लोकतन्त्रीय देश दिव्य प्रभुत्व एवं लोकतन्त्रीय आन्दोलनों के दमन की साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति में बाधक है, इसलिए इंग्लैंड तथा अमरीका के खूनी साम्राज्यवादिषों ने सोवियत मध्य तथा नये लोकतन्त्र के प्रतीक अन्य देशों के विरुद्ध अभियान प्रारम्भ कर दिया। इन परिस्थितियों में साम्राज्यवाद-विरोधी नाकतो द्वारा लोकतन्त्रीय समुदाय के लिए संगठित होकर साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध अपना कार्यवाही निश्चिन करने हेतु एक सामान्य मध्य का निर्माण करना आवश्यक है।'

किन्तु अपने-अपने राष्ट्र हितों की रक्षा के लिए साम्यवादी और पूँजीवादी दोनों में जहाँ-जहाँ टकराव हुआ या टकराव की स्थिति पैदा हुई, उन्हें दोनों महाशक्तियों ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सैद्धान्तिक जामा पहना दिया। वस्तुतः संपूर्ण तो राष्ट्र-हितों, शक्ति प्रचार, विरोधी को शक्ति सीमित करने या शक्ति मन्तुलन के लिए ही छिड़े थे। अमरीका 'मुक्त अर्थव्यवस्था' का प्रतिपादक होने के कारण किसी भी देश में साम्यवाद के प्रसार को अपने राष्ट्र-हितों के विरुद्ध मानता था क्योंकि उस देश में न तो उसे कच्चा माल मिल सकता था और न ही खुला बाजार। यह संयोग की बात नहीं थी कि अमरीकी लेबे के सभी देश 'मुक्त-अर्थव्यवस्था' के अनुयायी थे। वस्तुस्थिति यह थी कि उनके आर्थिक हितों ने साम्यवाद के प्रसार को रोकना आवश्यक बना दिया था। अमरीकी संघ में कई उपनिवेशवादी देश थे, जो अपने उपनिवेशों को छोड़ना नहीं चाहते थे। साम्यवाद की लहर उपनिवेशों में अव्यवस्था पैदा कर शान्ति की भूमिना तैयार कर सकती थी। अतः साम्यवाद को ही धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से बुरा बताकर ये देश उपनिवेशों पर अपना वर्चस्व बनाये रखना चाहते थे। पूँजीवादी देश अपने को लोकतन्त्र का सबसे बड़ा मगीहा प्रतिपादित करते थे, किन्तु साम्यवाद विरोधी सेमा बनाने की प्रक्रिया में वे सैनिक तानाशाहों एवं निरक्षर गजाओं को अपने साथ रखने में बर्बाद नहीं हिचकिचाए। इस दृष्टि से वे ईरान व सऊदी अरब जैसे शाहों को साम्यवाद-विरोध के लिए आवश्यक मानते थे, वहीं पाइलैंड, पाकिस्तान, इण्डोनेशिया के सैनिक तानाशाहों तथा फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस जैसे जनतन्त्र-विरोधी नेताओं को भी प्रथम देने में वे नहीं चूके। अतएव शीत युद्ध का मुख्य युद्ध लोकतन्त्र की रक्षा नहीं था।

दूसरी ओर रुस के सैद्धान्तिक दावे भी राष्ट्र-हितों के सामने खोखले पड़ जाते हैं। रुस ने भी पूँजीवादी देशों को परेशान करने के लिए अनेक बार

अधिनायकवादियों को समर्थन दिया है। मिसाल के तौर पर सोमालिया, इथोपिया, सुडान, लीबिया जैसे देशों के मैनिक तानाशाहों को रूस महज इसलिए समर्थन देता रहा, क्योंकि वे पूँजीवादी खेमे के विरुद्ध थे। यहाँ तक कि उगांडा के दादा अमीन को भी रूस ने कभी बुरा नहीं कहा। रूस के सैद्धान्तिक नकाब को उतारने के लिए एक ही उदाहरण काफी है। 1970 में अमरीका के इशारे पर जब लोन नोल ने वम्पुचिया के राजकुमार सिहानुव को अपदस्थ कर सत्ता हथिया ली एवं 1975 तक साम्यवादियों के दमन में उसने कोई कसर न छोड़ी, तब भी उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई करना तो दूर रहा, रूस ने उससे राजनीतिक सम्बन्ध विच्छेद भी नहीं किये। कुस मिलाकर शीत युद्ध के पीछे रूस का प्रमुख उद्देश्य ससार को दो खेमों में विभाजित रखते हुए स्वयं को एक खेमे का सर्वोत्तम बनाये रखना मात्र रहा। यही कारण है कि किसी तीसरे शक्ति केन्द्र के निर्माण को रूस ने साम्यवाद-विरोधी माना क्योंकि वह उसके राष्ट्र-हितों के विरुद्ध है। चीन के साथ मतभेद इस पृष्ठभूमि में ज्यादा अच्छी तरह समझे जा सकते हैं।

चौथा अध्याय

क्षेत्रवाद, क्षेत्रीय तथा सैनिक संगठन

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में 'क्षेत्रवाद' का प्रयोग नया नहीं। गैरपॉलिटिक सामीप्य, सांस्कृतिक एकरूपता तथा सहयोगी राजनीतिक सम्बन्धों या परस्पर आर्थिक निर्भरता के अनुसार अवसर राज्यों को एक खास समूह में रखा-गहना जा सकता है। यह समूह अपनी एक अलग पहचान बना लेता है। प्राचीन काल में यूनानी साम्राज्य के विभिन्न होने के बाद भी यूनानी प्रभाव क्षेत्र में एक बार भा चुकी इकाइयों की विशिष्ट क्षेत्रीय पहचान सदियों तक धनी रही। कमोबेश यही बात रोमन साम्राज्य (होलो रोमन एम्पायर तक), चीनी साम्राज्य तथा मध्य-युगीन इस्लामी खलीफाओं तक बनी रही।

क्षेत्रवाद का एक दूसरा प्रयोग तिरस्कारपूर्ण तथा अपमानजनक ढंग से 'क्षेत्रीयता' के रूप में होता है। इस सन्दर्भ में इसे प्रान्तीयता या प्रादेशिकता के पर्याय के रूप में क्रूरमंडकता की निशानी की तरह लिया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सामरिक क्षेत्रवाद इन दोनों ही प्रवृत्तियों को झटकाता है। एक ओर नवोदित राष्ट्रों ने औपनिवेशिक गुलामी का जुआ उतार फेंकने के बाद अपनी स्वाधीनता बरकरार रखने तथा आर्थिक स्वावलम्बन की आकांक्षा से अपने संकीर्ण स्वार्थों को पीछे रखकर एकता की उपयोगिता समझी। इस क्षेत्रवाद की मूल प्रेरणा यह थी कि साम्राज्यवादी औपनिवेशिक ताकतों ने 'फूट डालकर राज करने' की नीति अपनायी थी और उनकी वापसी के बाद अलग्गै बनाये रखने की कोई जरूरत नहीं रह गयी थी।

इसके बाद एक और प्रवृत्ति ने क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया। औपनिवेशिक काल में विभिन्न यूरोपीय शक्तियों ने अपने-अपने उपनिवेशों को अपने राजनीतिक साँची में डालने का प्रयत्न किया। इसकी गहरी छाप आज भी हिन्द चीन, अलजीरिया और लातीनी अमेरिका में देखने को मिलती है। ऐतिहासिक महत्व की इस प्रक्रिया ने एक भू-भाग के कई उप-क्षेत्रीय विभाजन कर दिये। 1945 के बाद विश्व भर में अनेक जगह क्षेत्रवाद और क्षेत्रीय संगठन इन उप-क्षेत्रीय हितों, स्वार्थों, महत्वा-कांक्षाओं से पुष्ट होते रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ और महाशक्तियों ने अपने-अपने ढंग से क्षेत्रवाद और क्षेत्रीय संगठनों को प्रेरित-प्रोत्साहित किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इस आशा के साथ की गई थी कि इसके द्वारा प्रयत्न: विश्व सरकार की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। इसी क़ोड जैसे विद्वानों का यह मानना रहा की क्षेत्रीय संगठन सम्प्रभु-स्वतन्त्र राज्यों और विश्व सरकार के बीच आवश्यक-अनिवार्य तंतु बन सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र मध्य ने आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए जिस तरह 'इकाफे' (ECAFE; बाद में ESCAPE) जैसे संगठनों की स्थापना की,

उसे एक तरह से क्षेत्रीय संगठनों को प्रतिष्ठा देने का आरम्भ समझा जा सकता है।

जहाँ तक अमरीका का प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमरीकी सरकार के लिए यह चिन्ता निरन्तर बनी रही कि यूरोप में साम्यवादी लान सेना का जमाव व व्यापक सामाजिक-आर्थिक उथल-पुथल मिफं साम्यवादियों ने प्रसार-विस्तार में सहायक हो सकते हैं। इस कारण मार्शल योजना के जरिये या वलिन की चेराग्रन्दी तोड़ने के लिए बड़ा जोखिम उठा सकने की अमरीकी तत्परता बारम्बार कभी प्रत्यक्ष तो कभी परोक्ष रूप से यूरोप की राजनीतिक एकता व भौगोलिक इकाई, अलग क्षेत्रीय पहचान को प्रमाणित करने वाली सिद्ध हुई। बाद के वर्षों में जनरल देगोल जैसे यूरोपीय नेताओं ने मध्ययुगीन सांस्कृतिक उत्तराधिकार में नव-जीवन का संचार करने हुए यूरोपीय साम्राज्य का शिलाग्याम किया।

इसकी प्रतिक्रिया में साक्षित सच ने अपने प्रभाव क्षेत्र में आ चुके पूर्वी यूरोप के उपग्रह राज्यों को 'कोमेकोन' (COMECON) के झण्डे तले संगठित करना आवश्यक समझा। यहाँ बाद रखना जरूरी है कि यूरोप में पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्रों में विभाजन सिर्फं शीत युद्ध के कारण नहीं सम्पन्न हुआ, बल्कि जहाँ एक ओर आधुनिक यूरोप के ऐतिहासिक घटनाक्रम में पिछली दो तीन सदियों में फ्रांस, ब्रिटेन, आस्ट्रिया घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आस्ट्रिया, हंगरी, पोलैण्ड, रूस आदि अधिकांश यूरोपीय देश राजनीतिक व सांस्कृतिक उथल-पुथल से बड़ी सीमा तक अछूते रहे हैं। शीत युद्ध के आविर्भाव के बाद सैनिक संगठनों की स्थापना ने इन क्षेत्रीय विभाजनों को और पक्का किया। 'नाटो' और 'वारसा' शक्तियों का द्वन्द्व तथा 'यूरोपीय आर्थिक संगठन' (European Economic Community) और 'कोमेकोन' की स्पष्ट-प्रतिद्वन्द्विता तथा बिग्रह इनके उदाहरणस्वरूप बतलाये जा सकते हैं।

अन्य औपनिवेशिक शक्तियों ने उपनिवेशवाद की समाप्ति के बाद अपने भूतपूर्व उपनिवेशों में प्रचारान्तर से अपना वर्चस्व बनाये रखने के लिए भी क्षेत्रीय संगठनों का निर्माण किया। जिस समय मलयेशिया महासंघ की प्रस्तावना की गयी, उस समय इण्डोनेशिया ने स्पष्टतः आक्षेप लगाया कि यह अफ्रीका का दक्षिण-पूर्व एशिया में बने रहने का पड़मन्त्र था। इसी तरह फ्रांस ने अफ्रीका में फ्रेंच भाषी इकाइयों को संगठित करने में कोई कमर नहीं छोड़ी। आग चलकर 'आमा', 'मापिलिदो', 'आमियान' या अफ्रीकी एका संगठन (Organisation of African Unity) के रूप में इनकी परिणति हुई। कई बार इस पूर्व भूमिका को भुलाकर यह दावा किया जाता रहा है कि ये सभी क्षेत्रीय संगठन स्वतः स्फूर्त और न्यायोपेय प्रेरणा से उपजे हैं।

क्षेत्रवाद की परिभाषा

(Definition of Regionalism)

उपरोक्त सर्वेक्षण के बाद क्षेत्रवाद की परिभाषा एवं उसके स्वरूप के बारे में सोचना सहज होगा। क्षेत्रीय संगठन भौगोलिक सामोप्य और सामूहिक हित, प्रतिरक्षा एवं आर्थिक विकास की जरूरतों के अनुसार राज्यों की वैकल्पिक ढंग से एकत्र होने की प्रेरणा देने रहे हैं। इस प्रवृत्ति को वैचारिक मिडान एना पुष्ट करती हैं। यही क्षेत्रवाद या क्षेत्रीय संगठनों की मूल प्रेरणा है।

डॉ० ई० एन० वान करेफेंस का कहना है—क्षेत्रीय व्यवस्था या समझौता एक क्षेत्र में सांस्कृतिक राज्यों का ऐच्छिक समुदाय है जिनके उद्देश्य में

सामान्य उद्देश्य होते हैं, परन्तु जो उस क्षेत्र के लिए आक्रमक नहीं होने चाहिए।¹ लेकिन, यह परिभाषा शीत युद्ध के एक विशेष दौर के सदर्भ में ही सटीक बँठती है। पिछले 30-40 वर्षों में यह स्पष्ट हो चुका है कि अनेक क्षेत्रीय संगठनों के तेवर और उनकी प्रकृति मुख्यतः आक्रमक हो सकते हैं। इसी सिलसिले में अर्नेस्ट हास जैसे विद्वानों ने इस ओर ध्यान दिलाया है कि छोटी-छोटी राजनीतिक इकाइयाँ बड़े क्षेत्रीय संगठनों में विलय के बाद ही अपना अस्तित्व बनाये रख सकती हैं। इस प्रकार शक्ति-संतुलन सिद्धान्त की तरह क्षेत्रीयकरण और क्षेत्रवाद को एक शाश्वत सिद्धान्त के रूप में भी प्रचारित किया जाने लगा है।

क्षेत्रीय संगठनों के प्रकार

(Kinds of Regional Organizations)

क्षेत्रीय संगठनों की मोटे तौर पर तीन ध्रेणियों में रखा जा सकता है। पहले वर्ग में एक ही भौगोलिक क्षेत्र या सांस्कृतिक परिधि में रहने वाले देशों का संगमग अवचेतन ढंग से एकता को प्रच्छन्न रूप से स्वीकार करने वाले क्रियाकलाप या संगठन रखे जा सकते हैं। धर्म और नस्लीय तत्व इनकी पुष्ट करते हैं। अफ़मर ऐसा भी होता है कि इन देशों की आर्थिक व सुरक्षा समस्याएँ मिलती जुलती हैं। इस तरह भौगोलिक निकटता, सांस्कृतिक समरूपता तथा सामूहिक आर्थिक हितों के आधार पर 'संगठित' क्षेत्रीय संरचनाओं में अरब राष्ट्रों की बिरादरी में अरब लीग प्रमुख है। इस अमूर्त सी एकता से कालक्रम में अधिक विशेषीकृत संरचनाएँ उभरती हैं। इस्लामी बिरादरी और अरब माईचारे ने नित क्षेत्रवाद को पुष्ट किया, उसकी परिणति 'अरब लीग', 'ओपेक' और 'गल्फ कॉन्फ़रेंशन कौंसिल' में हुई। इस तरह के क्षेत्रीय संगठन भौगोलिक सांस्कृतिक कहे जा सकते हैं। इसी तरह के और उदाहरण 'आसियान', 'अफ्रीका एकता सभ' और 'लाफ़टा' हैं।

क्षेत्रीय संगठनों की दूसरी किस्म सैनिक संगठनों वाली है। शीत युद्ध के पहले दौर में सामरिक समस्याओं को क्षेत्र विक्षेप के साथ जोड़कर देखा जाता रहा। यूरोप, पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया तथा सुदूर पूर्व में 'डोमिनो सिद्धान्त' के आधार पर अपने-अपने समर्थकों-वक्षधरों को मजबूत करने के लिए सैनिक सहबन्ध (Alliances) का निर्माण किया गया। इनमें 'नाटो', 'सेन्टो', 'सिण्टो' और 'बारमा सन्धि' उल्लेखनीय हैं। इनमें से प्रत्येक किसी क्षेत्र विक्षेप की समस्याओं से जुड़ा हुआ है। अनायास ही इस प्रवृत्ति ने क्षेत्रवाद की पहचान बनायी और संकीर्ण राष्ट्र हित के स्थान पर क्षेत्रीय हित रेखांकित किये।

परन्तु यह भी स्मरणीय है कि इन सैन्य संगठनों के कारण क्षेत्रीयता में अनेक बार दरारें भी पड़ीं। उदाहरणार्थ, दक्षिण पूर्व एशिया में हिन्द चीन और मलय राष्ट्रों के बीच मुठभेड़ या पश्चिम एशिया में अरब-इजराईल सभ्य में बिगाड़ इसी कारण आया। नायड इसका सबसे अच्छा उदाहरण यूरोप में मिलता है, जिसमें नाटो और बारसा सभ्य के बीच 'सत्रुता' के कारण लंबे समय तक यूरोप का विभाजन

¹ 'A regional arrangement or pact is a voluntary association of sovereign states within a certain area or having common interest so that for joint purpose, which should not be of an offensive nature, in relation to that area.' E. N. Van Kleeft, Regionalism and Political Pacts, *The American Journal of International Law*, (Washington D. C., October, 1949), 669.

कटुतापूर्ण बना रहा। यूरोपीय साझा बाजार और 'कोमेकोन' का गठन तथा ओस्न पोलिटिक भी इसको मिटा नहीं पाये। कमोवेश यह बात अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण सैनिक सहबन्धों पर भी लागू होती है। जैसे अनुम (ANJUS) सन्धि में मागीदारी ने दक्षिण-पूर्व एशिया और दक्षिण-प्रशान्त क्षेत्र में क्षेत्रीय शक्तियों और राज्यों को एक-दूसरे से अलग किए रखा।

क्षेत्रीय संगठनों का तीसरा प्रकार यह है, जो या तो समुक्त राष्ट्र सच द्वारा प्रेरित-प्रोत्साहित होता है (जैसे 'इकाफे', 'एस्केफ' आदि) या फिर सैनिक संगठनों के क्षय और पुराने गठबन्धनों के अवमूल्यन के बाद क्षेत्र की ही किसी शक्ति द्वारा सुझाया जाता है। इस परम्परा में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सच (SAARC) या अपदस्य होने के पहले ईरान के शाह द्वारा सुझायी गयी क्षेत्रीय विकास की सहकारी परियोजना उल्लेखनीय हैं। 'आसियान' और खाड़ी सहयोग सच (Gulf Cooperation Council) दोनों का नाम इस सूची में जोड़ा जाता है। अधिकतर विद्वानों का मानना है कि ऐसा करना उचित नहीं। इन दोनों संगठनों का आविर्भाव जिन परिस्थितियों में हुआ, उनसे यही पता चलता है कि पश्चिमी रणनीति जिन संगठनों पर आधारित थी, उनके अवमूल्यन के बाद उनका स्थान लेने के लिए ही प्रकट स्वधीन संगठनों के रूप में ये भूतिमान हुए।

प्रादेशिक संगठनों की उपादेयता (Utility of Regional Organizations)

विरह शान्ति और सुरक्षा के उद्देश्य से बने राष्ट्र सच और समुक्त राष्ट्र सच में उनके सदस्य-राष्ट्रों को प्रादेशिक संगठनों के निर्माण की इजाजत दी गयी। इनका स्वाभाविक तौर पर यह अर्थ लगाया जा सकता है कि इन प्रादेशिक संगठनों की उपादेयता है। इसकी उपादेयता निम्नांकित बिन्दुओं के सहित अभिव्यक्त की जा सकती है—

(क) क्षेत्रीय सहयोग और एकता की स्थापना—प्रादेशिक संगठन अपने सदस्य देशों में क्षेत्रीय सहयोग एवं एकता स्थापित करते हैं। एक क्षेत्र के देशों की तमाम समस्याओं तथा हिंनों के कारण उनमें सहयोग एवं एकता की स्थापना आवश्यक हो जाती है और इसको प्राप्त करने में ज्यादा दिक्कतों का सामना भी नहीं करना पड़ता। क्षेत्र के विभिन्न राष्ट्र क्षेत्रीय संगठन बनाकर आपस में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में सहयोग कर लाभ उठाते हैं।

(ख) बाहरी हस्तक्षेप का डटकर मुकाबला—प्रादेशिक संगठनों में आम तौर पर यह प्रावधान रखा जाता है कि क्षेत्र के किसी एक देश में बाहरी हस्तक्षेप होने पर संगठन के अन्य सदस्य उस देश की सहायता करेंगे। ऐसे संकटकालीन समय में समस्त क्षेत्रीय देश बाहरी हस्तक्षेप का डटकर मुकाबला कर सकते हैं।

(ग) अन्तर-क्षेत्रीय समस्याओं का क्षेत्रीय स्तर पर हल ढूँढना—प्रादेशिक संगठन अन्तर-क्षेत्रीय समस्याओं का क्षेत्रीय स्तर पर हल ढूँढने में अन्य संगठनों की अपेक्षा अधिक कामयाब हो सकते हैं। यदि किसी क्षेत्र के किन्हीं दो राष्ट्रों में किसी मामले को लेकर विवाद है तो उसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने से दोनों देशों में बढ़ता बढ़ेगी। यदि प्रादेशिक संगठन अपने इन सदस्य देशों के आपसी विवाद का हल ढूँढने में कामयाब रहते हैं तो अनावश्यक ट्रेप में बचा जा सकता है।

(घ) संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य सुगम बनाना—संयुक्त राष्ट्र संघ में समस्त प्रादेशिक समस्याओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाना मुश्किल ही नहीं, बल्कि कभी-कभी असम्भव भी हो जाता है। यदि छोटी-मोटी क्षेत्रीय समस्याओं को प्रादेशिक संगठनों द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर ही हल कर लिया जाये तो संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य हल्का हो जायेगा। इससे संयुक्त राष्ट्र संघ सेप जटिल प्रादेशिक समस्याएँ सुलझाने पर अधिक ध्यान दे सकेगा।

प्रमुख प्रादेशिक संगठन (Major Regional Organizations)

अरब संघ (Arab League)

ब्रिटिश आसोबाँव एब सहयोग से 22 मार्च, 1945 को अरब संघ की स्थापना की गयी। मिस्र, इराक, सीरिया, लेबनान, जोर्डन, सऊदी अरब और यमन इसके सात प्रारम्भिक सदस्य थे। बाद में जो अन्य देश इसके सदस्य बने, वे हैं—लीबिया, सुडान, द्यूनीतिया, मोरक्को, नुबेत, अल्जीरिया, बहरीन, मारोतानिया, ओमान, कतार, सोमालिया, दक्षिण यमन, संयुक्त अरब अमीरात। इस समय फिलीस्तीनी मुक्ति मोर्चे के प्रतिनिधि को मिलाकर अरब संघ के 21 सदस्य हैं।

अरब संघ के उद्देश्य (Objectives)

अरब संघ के चार्टर में उसके निम्नांकित उद्देश्य गिनाये गये हैं—

(क) अरब देशों की सम्प्रभुता की रक्षा;

(ख) फिलस्तीन में यहूदी राज्य की स्थापना का विरोध;

(ग) सदस्य राष्ट्रों में आर्थिक, वितीय, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में सहयोग की स्थापना;

(घ) पश्चिम एशिया में यूरोपीय उपनिवेशवाद की समाप्ति आदि।

अरब संघ के अंग (Organs)

अरब संघ के प्रमुख अंग निम्नांकित हैं—

(क) परिषद—अरब संघ में परिषद अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग है। इसे मजलिस भी कहा जाता है। सदस्य देशों से गठित परिषद की बैठकें वर्ष में दो बार होती हैं। इसमें निर्णय सर्वसम्मति से लेने का प्रयास किया जाता है। लेकिन कोई भी सदस्य राष्ट्र इसके बहुमत का निर्णय मानने के लिए बाध्य नहीं है। महासचिव परिषद के कार्यों को निपटाता है।

(ख) विदेश समितियाँ—अरब संघ में कुछ विदेश समितियों की स्थापना की व्यवस्था की गयी है। इनमें राजनीतिक समिति अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस समिति में सदस्य राज्यों के विदेश मंत्री होते हैं। समय-समय पर उठे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक संकटों पर यह विचार करती है।

(ग) सचिवालय—अरब संघ का सचिवालय पहले काहिरा (मिस्र) में था, लेकिन अब यह द्यूनिस्त (द्यूनिसिया) में है। यह अरब संघ के विभिन्न कार्यों में तालमेल बिठाने का कार्य करता है। इसमें एक महासचिव होता है। इसके प्रथम

महासचिव मिल के अब्दुल रहमान आजम पाशा थे ।

अरब संध में संकट (Crisis)

अरब संध के सदस्य देशों में पारस्परिक मत-भिन्नता तथा झगडों के कारण समय-समय पर कई संकट उठे हैं । इन संकटों को निम्नांकित बिन्दुओं में अभिव्यक्त किया जा सकता है

(क) अरब जगत के देशों का नेतृत्व इथियोपिया के लिए मिल और इराक के बीच हमेशा प्रतिद्वन्द्विता रही है । अनेक बार इराक ने अरब संध की बैठकों का बहिष्कार किया है ।

(ख) 1946 में 1956 तक जोर्डन तथा मजदी अरब के शासकों के बीच राजवंशीय प्रतिद्वन्द्विता के कारण अरब संध में तनाव बढ़ा है । लेकिन 29 अगस्त, 1962 को दोनों देशों के बीच सैनिक, राजनीतिक तथा आर्थिक सहयोग करने के लिए एक समझौता हुआ ।

(ग) 1978 में अमरीकी मध्यस्थता में इजराईल और मिल के बीच कैम्प डेविड समझौता होने के बाद बहुमूल्य अरब देशों में मिल की कड़ी आलोचना की । यही नहीं, कैम्प डेविड समझौते के बारे में कुछ अरब देशों ने अतिवादी विरोध का रत्न अपनाया, जबकि कुछ मध्यम-मार्गी रत्न के हामी रहे । यह उनकी पारस्परिक मतभेद और फूट का सूचक है ।

(घ) अरब देशों में आपसी झगडों को लेकर उनमें समय-समय पर तनावपूर्ण स्थिति पैदा होती रहती है । मिस्रन, मोरक्को और अल्जीरिया तथा ओमान और दक्षिण यमन में अनेक मतभेदों पर मत-भिन्नता के कारण वे एक-दूसरे से बिडे रहते हैं । इसी प्रकार पश्चिमी सहारा को लेकर भारतको और अल्जीरिया तथा मिल और लीबिया में भी ऐसी ही घीसाना चलती रहती है ।

ईरान-इराक संघर्ष (1980) और कुवैत पर इराक की हमले (1990) के कारण भी अरब राष्ट्रों की एकता खण्डित हुई और अरब लीग की 'अक्षमता' उजागर हुई ।

अरब संध का मूल्यांकन (Assessment)

अरब संध में उठे अनेक संकटों का बावजूद उनकी अनेक सफलताएँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । पहली, समुक्त राष्ट्र संध तथा अन्तर्-एशियाई समुदाय की सहायता से हमने अपने उपनिवेशवाद विरोधी अभियान के द्वारा अनेक अरब देशों की औपनिवेशिक शक्तियों के चंगुल से मुक्ति दिलाने में सफलता अर्जित की । दूसरी, इजराईल के मिताह फिलस्तीन के असल पर हमने विद्रोह समाप्त के बहुत बड़े वर्ग का समर्थन प्राप्त किया । तीसरी, 'तेल कूटनीति' अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में तेल की राजनीतिक हथियार के रूप में हमने अपने विरोधियों के खिलाफ दृष्टेपाल कर उनकी नीचे झुकने पर मजबूर किया । जापान ने 'तेल' की आवश्यकता के कारण ही इजराईल के बजाय अरब देशों को अपना समर्थन दिया ।

अफ्रीका एकाता संघ

(Organization of African Unity OAU)

15-25 मई, 1963 के दौरान इथियोपिया की राजधानी आदिम अवासा

में आयोजित एक सम्मेलन में 31 अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधि मिले। 25 मई, 1963 को एक चार्टर पर उन्होंने हस्ताक्षर करके अफ्रीका एकता संगठन (O.A.U.) का निर्माण किया। आज इसकी सदस्य संख्या 51 है। अर्थात् दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर समस्त अफ्रीकी देश इसके सदस्य बन चुके हैं। एक वर्ष की पूर्व सूचना देकर कोई भी देश इसकी सदस्यता को खो सकता है।

संगठन के उद्देश्य

(Objectives of the Organization)

अफ्रीका एकता संगठन के चार्टर पर दृष्टिपाठ करने पर उसके निम्नांकित उद्देश्य स्पष्ट होते हैं :

(क) सामान्यतया विश्व तथा विशेषतया अफ्रीकी राज्यों में उपनिवेशवाद एवं गैरसहमति को समाप्त करना,

(ख) गुट-निरपेक्ष नीति के अनुसरण के जरिये शीत युद्ध को समाप्त करना तथा दौलत,

(ग) अफ्रीकी देशों में मधुर सम्बन्धों की स्थापना तथा उनको बनाये रखना;

(घ) सदस्य देशों की प्रादेशिक अलगाव तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता को बनाये रखना तथा इसकी रक्षा करना;

(ङ) अफ्रीकावासियों की आर्थिक, सामाजिक तथा बौद्धिक प्रगति के लिए मदद करना; और

(च) समुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुरूप अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना।

संगठन के अंग

(Organs of the Organization)

अफ्रीका एकता संगठन के चार्टर में की गई व्यवस्थाओं के आधार पर उसके अंगों का निम्नांकित किन्तुओं के अन्तर्गत अध्ययन किया जा सकता है :

(क) सभा (Assembly)—यह अफ्रीका एकता संगठन का सर्वोच्च अंग है। इसमें संगठन के सदस्य देशों के राज्याध्यक्ष एवं शासनाध्यक्ष भाग लेते हैं। वर्ष में कम से कम एक बार इसकी बैठक होती है किन्तु आवश्यकता पड़ने पर इसकी विशेष बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है। इसकी बैठकों के लिए कुल सदस्यों के दो-तिहाई 'कोरम' की आवश्यकता होती है। सभी प्रस्ताव उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित किये जा सकते हैं। सभा सदस्य देशों के सामान्य हितों वाले विषयों पर विचार-विमर्श तथा संगठन के अन्य अंगों के कार्यों की समीक्षा करती है।

(ख) मन्त्रिपरिषद—यह संगठन के सदस्य-देशों के विदेश मन्त्रियों या उसके बराबर 'मन्त्रीय मन्त्रियों की परिषद' है। वर्ष में कम से कम दो बार इसकी बैठक होती है, किन्तु जरूरत पड़ने पर इसकी विशेष बैठक भी बुलाई जा सकती है। मन्त्रि-परिषद अपने समस्त कार्यों के लिए सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह सभा की सहायता करती है। इसने समय-समय पर उठे अनेक अन्तर्राष्ट्रीय मामलों (जैसे दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद, अफ्रीका में पुर्तगाली वस्तियों का भविष्य, रोडेेशिया (अब जिम्बाब्वे)

व कागो मकट, मयुक्त राष्ट्र सभ मे अफ्रीकी प्रतिनिधित्व आदि) पर व्यापक विचार-विमर्श किया है। इससे संगठन के सदस्य देशों में अन्तर्राष्ट्रीय मतलों पर आम सहमति कायम करने में मदद मिली।

(ग) सचिवालय—सचिवालय अफ्रीकी एकता संगठन के कार्यों में सहायता तथा उसकी गतिविधियों में तालमेल बँटाने का काम करता है। इसके प्रधान को महासचिव कहा जाता है।

(घ) मध्यस्थता, समझौता एवं पंच निर्णय आयोग (Commission of Mediation, Conciliation and Arbitration)—इस आयोग के 21 सदस्य हैं, जिनकी मसा द्वारा नियुक्ति होती है।

(ङ) विशिष्ट आयोग संगठन की मसा विशिष्ट विषयों के लिए अनेक आयोगों का निर्माण कर सकती है। इन विशिष्ट आयोगों के सदस्य संगठन के सदस्य देशों के सम्मन्वित मन्त्री होते हैं। मसा द्वारा जब तक जिन विविध आयोगों का निर्माण हुआ है वे हैं—(क) आर्थिक और सामाजिक आयोग, (ख) शैक्षणिक और सांस्कृतिक आयोग, (ग) स्वास्थ्य, मफाई और पोषण आयोग, (घ) प्रतिरक्षा आयोग, (ङ) वैज्ञानिक, तकनीकी और अनुसन्धान आयोग, (च) परिपक्व और मानापात आयोग; और (छ) विधिवेत्ता आयोग। विशिष्ट आयोग संगठन के सदस्य देशों में पारम्परिक सहयोग स्थापित करने की दिशा में कार्यरत है।

(च) अफ्रीकी मुक्ति समिति—अनेक अफ्रीकी देशों को औपनिवेशिक दासता से मुक्ति दिलाने के कार्य में तेजी लाने के लिए अफ्रीकी मुक्ति समिति की स्थापना की गयी। इसका प्रमुख कार्य अफ्रीकी उपनिवेशों में जब रहे राष्ट्रीय मुक्ति संग्रामों का समर्थन करना ही नहीं, बल्कि सदस्य-राष्ट्रों द्वारा दिये जाने वाले सहायता कार्यों में समन्वय स्थापित करना भी है। इस समिति का मुख्य कार्यालय तंजानिया की राजधानी दार-ए-मलाय में है। अफ्रीकी उपनिवेशों को औपनिवेशिक दासता से मुक्त कराकर उनको स्वतन्त्र देश के रूप में स्थापित करवाने में इस समिति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

तदर्थ आयोग—अफ्रीकी एकता संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों या अन्य मनोनीत मंत्रियों की मन्त्रि-परिषद अनेक अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर आपसी विचार-विमर्श करती है। इसके लिए वह तदर्थ आयोग की स्थापना कर विचार-विमर्श को अधिक सार्वक बनाती है। 1963 में मोरक्को-अल्जीरिया विवाद, 1964 में अफ्रीका में शरणार्थी समस्या तथा कांगो विवाद पर मन्त्रि-परिषद ने तदर्थ आयोगों की स्थापना की।

अफ्रीकी एकता संगठन में मकट (Crisis in O. A. U.)

संगठन में समय-समय पर अनेक मकट उठे हैं, जिन्होंने अफ्रीकी देशों की एकता में कई बाधाएँ उपस्थित की हैं। आज तक उठे महत्वपूर्ण मकटों को निम्नांकित तरीकों में दर्शाया जा सकता है।

(क) संगठन के उद्देश्यों के विरुद्ध के बारे में सदस्य देश दो गुट में बँट गये हैं। एक गुट के देश औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा स्थापित की गयी राज्य-व्यवस्था का समर्थन करने हैं तो दूसरा गुट पश्चिमी देशों की पूँजीवादी लोकतन्त्र की

विचारधारा के कट्टर विरोधी हैं। इन बातों को लेकर अफ्रीकी देशों में वैचारिक झड़पें होती रहती हैं।

(ख) 1970 के बाद अफ्रीकी देशों में लगातार सैनिक क्रान्तिर्मा होती रही है जिस कारण उनमें राजनीतिक स्थायित्व नहीं रहा है। अधिकांश देशों में आजकल कमोवेश निरंकुश शासन-व्यवस्था है।

(ग) क्षेत्र में विदेशी सैनिक घमकी, शीत युद्ध तथा शस्त्रीय होड़ को रोकने के लिए अफ्रीकी एकता संगठन के चार्टर में कहा गया है कि सदस्य देश गुट-निरपेक्ष नीति का पालन करेंगे। किन्तु चार्टर एवं अफ्रीकी एकता संगठन दोनों ने आज तक गुट-निरपेक्षता को निश्चित अर्थों में परिभाषित नहीं किया है। परिणामस्वरूप सदस्य देशों में गुट-निरपेक्ष नीति के तत्त्वों तथा कार्यान्वयन के बारे में सर्व-सम्मति का अभाव है।

(घ) दक्षिण अफ्रीका में अल्पसंख्यक शोरो के विरुद्ध बहुसंख्यक कालो के शासन की स्थापना करवाने में अफ्रीकी एकता संगठन को अभी तक पूर्ण सफलता नहीं मिली है।

(ङ) अधिकतर अफ्रीकी देश उपनिवेशवाद के चंगुल से तो मुक्त हो गये किन्तु औपनिवेशिक शक्तियों के नव-उपनिवेशवाद के पक्ष में वे फिर आ गये हैं। धीरे-धीरे वे अपने विकास के लिए नव-उपनिवेशवादी ताकतों पर निर्भर होते जा रहे हैं।

(च) समय-समय पर अफ्रीकी देशों में आपसी सीमा-विवाद उठे हैं, जिन्होंने क्षेत्रीय तनाव पैदा किया। हालाँकि अफ्रीकी एकता संगठन अल्जीरिया और मोरक्को, घाना और अपर वोल्टा तथा घाना और टोगो के बीच झगड़ों का शान्तिपूर्ण तरीके से हल निकालने में सफल हुआ है किन्तु अभी भी अनेक देशों में आपसी सीमा-विवाद क्षेत्रीय तनाव के कारण बने हुए हैं। मसलन, नाइजर और डायोनी, सुडान और चाड आदि देशों के आपसी सीमा-विवाद हैं। इसके अतिरिक्त मोमालीनैण्ड को लेकर मोमालिया और इथियोपिया, स्पेनिश सहारा को लेकर मोरीतानिया और मोरक्को तथा फर्गंडो को का स्पेनिश द्वीप को लेकर नाइजीरिया और केमरून के बीच सीमा-विवाद मविष्य में कभी भी सैनिक संघर्ष का रूप धारण कर सकते हैं।

संगठन की उपलब्धियाँ

(Achievements of the Organization)

संगठन में समय-समय पर अनेक संकटों के उठने पर उसे असफलताओं का सामना करना पड़ा। परन्तु उसकी सफलताओं को भी नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता। उसकी महत्वपूर्ण सफलताएँ निम्नांकित हैं—

(क) इसने अफ्रीकी क्षेत्र में चल रहे उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रीय मुक्ति संग्रामों को नैतिक एवं भौतिक समर्थन नहीं दिया, बल्कि उनके पक्ष में अन्तर्राष्ट्रीय जनमत भी तैयार किया। इससे अनेक अफ्रीकी उपनिवेश स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में उभरे।

(ग) इसने अफ्रीकी देशों के अनेक सीमा-विवादों तथा आपसी झगड़ों को सुलझाया है। मसलन, उसने अल्जीरिया और मोरक्को, घाना और अपर वोल्टा तथा घाना और टोगो के बीच मुनह करवाने में सफलता प्राप्त की।

(ग) इसने अफ्रीकी देशों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग करने की भावना को जागृत किया है। आज अनेक अफ्रीकी देश इसकी प्रेरणा में ही विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग कर रहे हैं।

(घ) यह तीसरी दुनिया के विनामशील देशों की भावों को एकजुट होकर हरेक अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर समर्थन करता आया है।

संगठन का मूल्यांकन

(Assessment of the Organization)

अफ्रीका एकता संगठन से सम्बन्धित विभिन्न पक्षों पर दृष्टिपात करने के बाद यह कहा जा सकता है कि क्षेत्रीय संगठन के रूप में यह सबसे ज्यादा व्यापक संगठन है। यह इसकी विभागत मददस्व-देशों की सहायता से स्पष्ट है। किन्तु व्यावहारिक उप-सक्रियता के दृष्टिकोण से देखा जाये तो इस अपने घोषित उद्देश्यों की तुलना में आंशिक सफलता ही प्राप्त हुई है। इसके बावजूद तीसरी दुनिया के गरीब देशों के लिए ऐसे संगठनों की काफी उपयोगिता है। अन्यथा इनकी अनुपस्थिति में विश्व की दली शक्तियाँ गरीब देशों को निगल जायेंगी।

इस संगठन का जिस समय गठन हुआ, उस समय पार्स-अफ्रीकी भाईचारे का ज्वार भूतान पर था और अफ्रीकी एकता के बारे में आत्मान्वित होना आसान था। तब से अधिकांश लोगों के निराश होने का प्रमुख कारण यह रहा कि बहुसंख्यक अफ्रीकी राष्ट्र अपनी बजायली स्वामी शक्ति से उबरने में असमर्थ रहे हैं। उगांडा माइजीरिया आदि में विभाजक गृहयुद्ध भूयान बजायली रहे हैं। विदेशी शक्तियों ने इन स्थिति का लाभ उठाया और इसी कारण संगठन के सदस्य देश अपनी समर्थक महा शक्तियों के अनुगार उनकी नीति अधिगम्यी या धामपयी तय करते रहे। एम्बूना देन्याता, ओबोटे जैसे नेताओं के राजनीतिक मंच के हट जाने के बाद सामूहिक रूप से अफ्रीकी हितों को पारिभाषित करने की गुंजाइश भी कम हुई है। ऐसा नहीं जान पड़ता कि निरुद्ध भविष्य में अफ्रीकी एकता संघ क्षेत्रीय संगठन के रूप में टोप उपलब्धियाँ हासिल कर सकेगा।

उत्तर अटलांटिक संधि संगठन अर्थात् 'नाटो'

(North Atlantic Treaty Organization 'NATO')

उत्तर अटलांटिक संधि संगठन को 'नाटो' में नाम से भी पुकारा जाता है। इसका निर्माण 4 अप्रैल, 1949 को अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में किया गया। यहाँ 12 पश्चिमी राष्ट्रों—बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैण्ड, इटली, लक्जमबर्ग, हॉलैण्ड, नार्वे, पुर्तगाल, ब्रिटेन, कनाडा तथा अमेरिका के प्रतिनिधियों ने नाटो संधि पर हस्ताक्षर किये। इसके बाद अक्टूबर, 1951 में चीम और टर्की तथा 1954 में पश्चिम जर्मनी को नए सदस्यों के रूप में इस संगठन में सम्मिलित किया गया। नाटो संधि को मूल रूप में 20 वर्षों के लिए बनाया गया था किन्तु 1969 में इसकी अवधि 20 वर्षों के लिए बढ़ा दी गयी। प्रत्येक 10 वर्षों बाद संधि का पुनर्विचार किया जाता है।

नाटो के निर्माण के कारण एवं उद्देश्य (Objectives of NATO)

'नाटो' में सम्मिलित सदस्य देश यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों से हैं। भू-भाग, जनसंख्या, प्राकृतिक सम्पदा, औद्योगिक सम्पदा, ऐतिहासिक अनुभवों तथा राजनीतिक परम्पराओं की दृष्टि से उनमें भिन्नता है। फिर भी वे अमरीका के नेतृत्व में एक सैनिक गठजोड़ के एकता सूत्र (common bonds) में बंध गये।¹ नाटो के निर्माण के पीछे प्रमुख रूप से निम्नांकित कारण एवं उद्देश्य थे—

(क) आर्थिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता—द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाटो के समस्त सदस्य देशों ने भौतिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा भावनात्मक रूप से अनेक नुकसान उठाये। दूसरी तरफ़ सोवियत संघ द्वारा उन पर वर्चस्व स्थापित करने का खतरा मौजूद था। ऐसी अवस्था में शक्तिशाली अमरीका ही उनके लिए आशा की किरण था जो उनके आर्थिक पुनर्निर्माण की सबसे बड़ी आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम था। इसी बात को महसूस करते हुए उन्होंने अमरीका के नेतृत्व में नाटो में सम्मिलित होना स्वीकार किया।

(ख) सोवियत संघ द्वारा साम्यवादी प्रसार—द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप से अपनी सेनाएँ हटाने से इन्कार कर दिया। उसने वहाँ साम्यवादी सरकारें स्थापित करने के प्रयत्न किये। अन्य स्थातों के बारे में भी उसने यही नीति अपनायी। अमरीका ने इसका लाभ उठाकर साम्यवाद-विरोधी नारा दिया और यूरोपीय देशों को साम्यवादी खतरे से सावधान किया। फलस्वरूप यूरोपीय देश नाटो में सम्मिलित हो गये।

(ग) संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य-क्षमता पर अविश्वास—संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण विश्व-शान्ति एवं सुरक्षा स्थापित करने के उद्देश्य के साथ 1945 में हुआ। परन्तु पश्चिमी राष्ट्रों ने महसूस किया कि यह अन्तर्राष्ट्रीय सगठन आक्रमणकारी राष्ट्र से उनकी सुरक्षा नहीं कर पायेगा। यह उनके द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य-क्षमता पर अविश्वास का सूचक है। इसी ने उन्हें 'नाटो' सदस्य बनने के लिए प्रेरित किया।

नाटो के अंग

(Organs of NATO)

ज्यों-ज्यों समय बीगता गया, त्यों-त्यों नाटो का संगठन भी विकसित होता गया। आज यह एक विशाल संगठन है। पहले इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में था किन्तु फ्रांस द्वारा नाटो की सदस्यता त्यागने के बाद अब यह बेलजियम में है। नाटो संगठन के निम्नांकित अंग हैं -

(क) परिषद—नाटो के अनुच्छेद-9 के अन्तर्गत परिषद की स्थापना की गयी है। नाटो संगठन में यह सर्वोच्च अंग है। इसका निर्माण सदस्य राज्यों के मन्त्रियों से होता है। इसकी मन्त्री-स्तरीय बैठक वर्ष में एक या दो बार होती है। स्थायी प्रतिनिधियों के स्तर पर इसकी बैठक वर्ष में एक या दो बार होती है। इसके सभापति प्रतिवर्ष बारी-बारी से सदस्य देशों के मन्त्री होते हैं। नाटो का महासचिव परिषद

¹ M. V. Nanda, *Alliances and Balance of Power: A Search for Conceptual Clarity* (Delhi, 1964), 42.

साथ ही सामरिक मामलों पर अमरीका के साथ उनका मतभेद तेजी से सामने आया। हाल के वर्षों में मोबियत संघ के साथ पश्चिमी यूरोपीय देशों का तननीकी आदान-प्रदान, यूरोप में कूट मिमाइलो की स्थापना तथा 'स्टार वास' परियोजना इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इसके अलावा पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्र अपनी वैदेशिक नीतियों को अमरीका के राष्ट्रीय हित के साथ इस तरह जोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं कि तनाव-नीतिस्थ या मुठभेड़ सिर्फ महाशक्ति की इच्छानुसार ही तय होती रहे। जनरल देगोल और विली ब्राट के काल में यह स्थिति निरन्तर देखने को मिलती थी। पश्चिमी यूरोप में पिछले वर्षों के दौरान शान्ति आन्दोलन का आविर्भाव और इसकी प्रगति अमरीका के लिए बेहद चिन्ताजनक रही है। जर्मनी में ग्रीन पार्टी और इंग्लैंड में लेबर पार्टी के प्रवक्ताओं द्वारा अमरीकी परमाणु नीति की आलोचना अमरीका के लिए मिरदर्द बनती रही है। हिमक आतंकवादियों के प्रति यूरोपीय सरकारों का उद्गार हल अमरीका को लज्जित करता रहा है। अमरीका के बहुराष्ट्रीय निगमों के बारे में पश्चिमी यूरोपीय उद्योगपति आत्म-रक्षात्मक ढंग से चिन्तित रहे हैं। इन सभी बातों ने नाटो की एकता को कमजोर बनाया है। महाशक्ति के रूप में मोबियत संघ के क्षय ने भी नाटो की प्रसंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाया है।

अमरीकी राज्यों का संगठन

(Organization of American States)

अमरीकी राज्यों के संगठन का उदय 1989-90 में स्थापित अखिल अमरीकी संघ (Pan-American Union) से जोड़ा जाता है। अखिल अमरीकी संघ न तो फेडरेशन था और न ही गठबन्धन, बल्कि वह राष्ट्रों का क्लब था। इस संघ का उद्देश्य संयुक्त राज्य अमरीका तथा लातीवी अमरीकी राज्यों की सरकारों में आपसी राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक सहयोग स्थापित करना था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनेक प्रयास हुए किन्तु प्रथम विश्व युद्ध तक उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली। इसके बाद भी विश्व शान्ति और सुरक्षा स्थापित करने की महान आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तेजी से अनेक प्रयास किये गये। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमरीका ने उनकी एक सामान्य विदेश नीति बनाने की पहल की। अन्ततः 1945 में मैक्सिको नगर में अन्तर-अमरीकी सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन ने तीस्रो सन्धि और अमरीकी राज्यों के संगठन की भूमिका तैयार की। बोंगोटा (बोलम्बिया) में हुए अमरीकी राज्यों के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अमरीकी राज्यों के संगठन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। इस संगठन के चार्टर में अमरीकी गोलार्द्ध के सभी राज्यों (बनाहा समेत) के सम्मिलित होने का प्रावधान है। वैसे बनाहा ने अब तक इसकी सदस्यता प्राप्त नहीं की किन्तु यदि वह चाहे तो इसका सदस्य बन सकता है। यह भी कहा गया है कि किसी सदस्य-राज्य को संगठन से नहीं निकाला जा सकता, लेकिन यदि कोई राज्य स्वेच्छा से इसकी सदस्यता छोड़ना चाहे तो वह दो वर्षों की पूर्व सूचना देकर ऐसा कर सकता है।

संगठन के उद्देश्य

(Objectives of the Organization)

इसके चार्टर में सदस्य-देशों के अधिकारों तथा कर्तव्यों का उल्लेख है।

इनमें प्रमुख रूप से विवादों के शान्तिपूर्ण हल, सामूहिक सुरक्षा, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में सहयोग पर जोर दिया गया है।

संगठन के अंग

(Organs of the Organization)

अमरीकी राज्यों के संगठन के निम्नांकित पाँच अंग हैं—

(अ) अन्तर-अमरीकी सम्मेलन (Inter-American Conference)—

अन्तर-अमरीकी सम्मेलन अमरीकी राज्यों के संगठन का सबसे प्रथम एवं सर्वोच्च अंग है। इसमें हरेक सदस्य राज्य को अपना एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। यह संगठन के अन्य समस्त अंगों के स्वरूप और कार्यों तथा संगठन की नीति और कार्यक्रम को तय करता है। सदस्य-राज्य इनको प्रियान्वित करते हैं।

(ब) विदेश मन्त्रियों की बैठक—विदेश मन्त्रियों की बैठक ज़रूरी विषयों पर विचार विमर्श करती है। संगठन के किसी सदस्य-राज्य की प्रार्थना पर इसकी बैठक बुलाई जा सकती है। इसके अलावा किसी भी सशस्त्र आक्रमण की अवस्था में इसकी बैठक बुलाई जा सकती है। इसकी सहायता के लिए एक परामर्शदात्री प्रतिरक्षा समिति भी होती है।

(ग) परिषद—परिषद में संगठन का हरेक सदस्य राज्य एक प्रतिनिधि भेजता है। उसका मुख्यालय अमरीका की राजधानी वाशिंगटन में है। इसके प्रमुख कार्य शान्ति व सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों तथा संगठन के विभिन्न अंगों के कार्यों की देखभाल करना है। साथ ही यह अखिल अमरीकी सघ के कार्य का पर्यवेक्षण करती है। अन्तर-अमरीकी आर्थिक और सामाजिक परिषद, अमरीकी निधिवेत्ताओं की परिषद तथा अन्तर-अमरीकी सांस्कृतिक परिषद सीधे ही इनके नियन्त्रण में रहती हैं।

(द) अखिल अमरीकी सघ (Pan-American Union)—अखिल अमरीकी सघ अमरीकी राज्यों के संगठन का केन्द्रीय एवं स्थायी अंग तथा सचिवालय है। संगठन का महासचिव इसका निदेशक होता है, जो अन्तर-अमरीकी सम्मेलन द्वारा दस वर्ष के लिए चुना जाता है। वह दोबारा नहीं चुना जा सकता। अखिल अमरीकी सघ के मुख्य कार्य राज्यों में आपसी आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग स्थापित करना तथा राज्यों के आपसी झगडा का शान्तिपूर्ण तरीके से निपटारा करना है।

(ध) विशिष्ट एजेंसियाँ—विशिष्ट एजेंसियाँ विशिष्ट कार्यों का सम्पादन करती हैं। ये एजेंसियाँ अमरीकी राज्यों के संगठन का अलग अंग बन चुकी हैं। जैसे, परामर्शदात्री सुरक्षा समिति, अन्तर-अमरीकी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अन्तर-अमरीकी विधिवत्ता परिषद, अन्तर-अमरीकी सांस्कृतिक परिषद, अमरीकी स्वास्थ्य ब्यूरो, अन्तर-अमरीकी कृषि विज्ञान संस्था, अखिल अमरीकी भूगोल एवं इतिहास संस्था और अन्तर-अमरीकी दूर संचार कार्यालय आदि।

संगठन का मूल्यांकन

(Assessment of the Organization)

यह संगठन वस्तुतः क्षेत्रीय महत्त्व की स्तर स्पूर्ण प्रेरणा का परिणाम नहीं, बल्कि अमरीकी महाद्वीप व अमरीका के वर्चस्व को अवरुद्ध करने वाले मुद्दों को निपटान की बीमारी मदी का महत्त्व है। इस सन्दर्भ में मगने महत्त्वपूर्ण बात यह

हे कि संगमन सभी सदस्य राष्ट्रों का राजनीतिक संस्कार और वार्षिक समस्याएँ एकजोड़ी हैं। संयुक्त राज्य अमरीका के विरोधी-प्रतिद्वन्द्वी या या वामपंथी राजान वाले क्रिस्तों भी देश के लिए इस संगठन में कोई स्थान नहीं। क्यूबा के उदाहरण से यह बात मसीभाति प्रकट होती है। जब कभी ऐसा अवसर आया है कि संगठन के सदस्य देशों के निजी या सामूहिक हित संकटग्रस्त हुए हैं तो संगठन नपुंसक और निर्बीर्य निद्रा हुआ है। घेनेडा में अमरीकी सैनिक हस्तक्षेप, अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच फॉकलैण्ड युद्ध तथा निकारागुआ एवं अल सल्वाडोर की कान्तिकारी उथल-पुथल में इस संगठन ने कोई रचनात्मक भूमिका नहीं निभाई।

दक्षिण-पूर्व एशियाई सन्धि संगठन या सिएटो

(South East Asian Treaty Organization or SEATO)

6 से 8 गितम्बर, 1954 तक फिलीपींस की राजधानी मनीला में अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, थाईलैण्ड और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ। यह सभी देश साम्यवाद के प्रसार से आतंकित थे और चाहते थे कि उसे रोकने के लिए कोई कारगर कदम उठाये जायें। सम्मेलन में लम्बे विचार-विमर्श के बाद दक्षिण-पूर्व एशियाई सन्धि संगठन का प्रस्ताव हुआ, जिसे 19 फरवरी, 1955 को कार्यान्वित किया गया। इसे मनीला समझौता या 'सिएटो' के नाम से भी जाना जाता है।

संगठन के उद्देश्य

(Objectives of the Organization)

'सिएटो' की स्थापना के पीछे जो उद्देश्य थे, वे संक्षेप में निम्नांकित हैं—

- (क) दक्षिण-पूर्व एशिया तथा दक्षिण पश्चिमी प्रशान्त महासागर में साम्यवाद का प्रसार रोकना;
- (ख) दक्षिण-पूर्व एशिया तथा दक्षिण पश्चिमी प्रशान्त महासागर में पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा अपने हितों की रक्षा करना; और
- (ग) सदस्य देशों में बहुमुखी क्षेत्रों में आपसी सहयोग स्थापित करना।

संगठन की प्रमुख व्यवस्थाएँ

सिएटो सन्धि में की गई प्रमुख व्यवस्थाएँ (major provisions) संक्षेप में निम्नांकित हैं—

(क) सन्धि की प्रस्तावना में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में आस्था व्यक्त करते हुए कहा गया है कि सन्धिकर्ता जस्यों में से किसी एक देश के विरुद्ध सशस्त्र आक्रमण की शान्ति और सुरक्षा के लिए सत्तरा माना जलिया और नदस्य राज्य इसका मुकाबला करने के लिए संवैधानिक प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य करेंगे। इसके अन्तर्गत उठाये गये कदमों की सूचना संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद को तत्काल देगे;

(ख) सन्धि का क्षेत्र दक्षिण-पूर्व एशिया का सामान्य क्षेत्र तथा दक्षिण-पश्चिमी प्रशान्त सागर का उत्तर में 21 डिग्री 30 मिनट की उत्तरी अक्षांश रेखा निरिक्त किया गया है;

(ग) अन्य किसी राष्ट्र को सदस्य-देशों की सर्वसम्मति से इस सन्धि में शामिल किया जा सकता है,

(घ) यह सन्धि अनिश्चित बाल के लिए की गई है, परन्तु कोई सदस्य-देश एक वर्ष की पूर्व सूचना देकर अपने अपने आपको सन्धि से अलग कर सकता है, और

(ङ) इस सन्धि में महासूत्र आक्रमण को रोकने तथा आन्तरिक विध्वंस के बारे में जवाबी उपायों के अलावा स्वतन्त्र सम्स्थाओं के विकास, आर्थिक विकास तथा सामाजिक कल्याण के सम्बन्ध में व्यवस्थाएँ की गयी हैं।

संगठन के अंग

(Organs of the Organization)

इसके निम्नावलि अंग हैं—

(क) परिषद—परिषद एक मन्त्रिमण्डलीय संस्था है। इसकी बैठक वर्ष में कम से कम एक बार बुलाने की व्यवस्था है। आवश्यकता पड़ने पर इसकी बैठक किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

(ख) सचिवालय एवं कार्य समूह—जब परिषद की बैठक नहीं हो रही हो इसका कार्य परिषद के प्रतिनिधि (अर्थात् विदेश मन्त्री) करते हैं। इन प्रतिनिधियों की सहायता के लिए एक सचिवालय और आवश्यकता के अनुसार कार्य समूह की व्यवस्था की गयी है।

(ग) पहचान समितियाँ (Watch Dog Committees)—मिट्टो के अन्तर्गत कुछ पहचान समितियाँ की व्यवस्था की गयी है जो सदस्य देशों में विध्वनात्मक गतिविधियों पर निगरानी रखती हैं।

(घ) मुख्यालय—परिषद का प्रधान कार्यालय चाईलैण्ड की राजधानी बैंगल में है।

सिएटो की आलोचना

(Criticism of SEATO)

निम्नावलि आचारों पर सिएटो की आलोचना की जा सकती है—

(क) सिएटो को क्षेत्रीय व्यवस्था नहीं माना जा सकता। हालांकि इसका नाम दक्षिण-पूर्व एशियाई मन्त्रि मण्डल है, किन्तु इसमें शामिल आठ देशों में सिर्फ तीन ही एशियाई देश हैं, जबकि अन्य सभी राष्ट्र पश्चिम के हैं,

(ख) सिएटो के जरिये पश्चिमी राष्ट्रों ने पाकिस्तान जैसे देश को साम्यवादी प्रसार रोकने के लिए शस्त्रों से लैस किया, जो उमने भारत के विरुद्ध प्रयोग किये। इन पश्चिमी शस्त्रों से शान्ति भंग हुई। इस अनुत्तरदायी आचरण के लिए अमरीका भी बम दोषी नहीं है,

(ग) सिएटो में आत्म-निर्णय का मिडलान्ड स्वीकार किया गया है किन्तु इसमें महसूस अमरीका ने विघननाम, लाओस और कम्पुचिया में गुप्त हस्तक्षेप किया। यह हस्तक्षेप इस सन्धि में स्वीकार किये गये आत्म-निर्णय के मिडलान्ड का स्पष्ट उल्लंघन था, और

(घ) सिएटो नव-उपनिवेशवाद का एक नया रूप है। इसके द्वारा पश्चिमी

देशों ने एशियाई सदस्य देशों को परोक्ष रूप से नियन्त्रित करना चाहा और किया। इसे 'मुनरो सिद्धान्त' जैसी सजा दी जा सकती है।

सिएटो का अवसान

सिएटो मुख्यतः डलेस की शीत युद्धकालीन रणनीति का हिस्सा था और उनके साथ ही इस संगठन का अवसान हुआ। इसके कई कारण थे। भले ही इसे क्षेत्रीय सहकार का जामा पहनाने की कोशिश की गयी, परन्तु यह एक सैनिक संगठन ही था। इसके सदस्य राष्ट्रों में आर्थिक और सैनिक सामर्थ्य का भीषण असन्तुलन था। पाकिस्तान हो या फिलीपींस या थाईलैण्ड, सभी की स्थिति अमरीका के परजीवी शिविरानुचरो की थी। 1960 के दशक में वियतनाम सघर्ष ने अमरीका के सामने इन सभी की अनुपयोगिता का रहस्योद्घाटन कर दिया। अनेक विद्वानों का मत है कि सिएटो के क्षय को देखकर अमरीका ने 1968 में 'आसियान' की प्रस्तावना को प्रोत्साहित किया। 1979 तक इसकी दुर्बलता और भी स्पष्ट हो चुकी थी। न केवल अमरीका, बल्कि पाकिस्तान तक ने अपने सामरिक हितों की रक्षा के लिए सिएटो को अक्षम पाया। 1965 और 1971 के युद्धों में इसकी सदस्यता का वाञ्छित लाभ पाकिस्तान को नहीं मिला और हताश होकर उसने इसकी सदस्यता छोड़ दी। दक्षिण वियतनाम के पतन के बाद फिलीपींस, थाईलैण्ड भी निष्क्रिय हो गये। इराक के बाद सिएटो का औपचारिक समापन सिर्फ प्रतीक्षा का विषय रह गया। 1977 में इस संगठन का विधिकत निमटन हो गया।

बगदाद समझौता या केन्द्रीय सन्धि संगठन या 'सेन्टो'

(Bagdad Pact or Central Treaty Organization or 'CENTO')

अमरीका ने यूरोप में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए नाटो का निर्माण किया, वही पश्चिम एशिया के देशों में इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु केन्द्रीय सन्धि संगठन अर्थात् 'सेन्टो' का निर्माण किया। 'सेन्टो' के निर्माण की कहानी जितनी जटिल है उतनी ही रोचक भी। अमरीकी प्रयासों ने 24 फरवरी, 1955 को इराक और टर्की के बीच सुरक्षा के बारे में एक-दूसरे की सहायता करने के लिए इराक की राजधानी बगदाद में जो समझौता हुआ वह आगे चलकर बगदाद समझौता कहलाया। 22 अप्रैल, 1955 को टर्की और पाकिस्तान के बीच एक सन्धि हुई। 24 फरवरी, 1955 को टर्की और इराक के बीच फिर एक सन्धि हुई। 4 अप्रैल, 1955 को 1930 की सन्धि के स्थान पर ब्रिटेन और इराक में एक नया समझौता हुआ। पाकिस्तान और ईरान क्रमशः सितम्बर, 1955 और अक्तूबर, 1955 में टर्की-इराक समझौते में सम्मिलित हो गये। इस प्रकार इन देशों के बीच विभिन्न द्विपक्षीय सन्धियों और समझौतों ने बगदाद समझौते का रूप धारण कर लिया। बगदाद समझौते के सदस्य देश टर्की, इराक, ईरान, ब्रिटेन और पाकिस्तान थे।

बगदाद समझौते का अवसान और सेन्टो का निर्माण—बगदाद समझौता इराक में सरकार परिवर्तन के साथ समाप्त हो गया। 14 जुलाई, 1958 को इराक में क्रान्ति हो गयी और नये शासनाध्यक्ष जनरल अब्दुल करीम कासिम ने बगदाद समझौते में अलग होने की घोषणा की। 21 अगस्त, 1959 को अन्तिम रूप से उसने इसकी सदस्यता त्याग दी। तदुपरान्त टर्की, ईरान, ब्रिटेन और पाकिस्तान ने मिलकर

इसे जो नया नाम दिया, वह था—केन्द्रीय सन्धि संगठन अर्थात् सेन्टो।

सेन्टो की प्रमुख व्यवस्थाएँ—‘सेन्टो’ संगठन में की गयी व्यवस्थाएँ वही हैं जो बगदाद समझौते के अन्तर्गत की गयी थीं। प्रमुख व्यवस्थाएँ निम्नांकित हैं :

(क) सदस्य देश सुरक्षा और प्रतिरक्षा के लिए एक-दूसरे से सहयोग करने के लिए बचनबद्ध हैं किन्तु यह भी कहा गया है कि वे एक-दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे,

(ख) अरब संध का कोई भी सदस्य और अन्य देश जो पश्चिम एशिया में शान्ति और सुरक्षा के लिए चिन्तित हैं, वे इसके सदस्य बन सकते हैं। ब्रिटेन को इसी आधार पर सदस्य बनाया गया, और

(ग) इस समझौते की पाँच वर्षों के लिए किया गया तथा पाँच-पाँच वर्षों के लिए इसके नवीनीकरण का प्रावधान रखा गया है।

सेन्टो के उद्देश्य (Objectives of CENTO)—सेन्टो के निर्माण के पीछे जो उद्देश्य रहे हैं, वे संक्षेप में निम्नांकित हैं

(क) पश्चिम एशिया के देशों को साम्यवादी विस्तार से बचना,

(ख) इस समझौते में ब्रिटेन द्वारा सम्मिलित होने का उद्देश्य पश्चिम एशिया के राष्ट्रों में साम्यवाद के प्रसार को रोकना ही नहीं, बल्कि पश्चिमी प्रभाव-क्षेत्र कायम रखना भी है, और

(ग) सदस्य देशों में चहुँमुखी क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग स्थापित करना।

संगठन के अंग

(Organs of the Organization)

इसके विभिन्न अंगों के बारे में संक्षिप्त जानकारी निम्नांकित है—

(क) परिषद—इसमें सदस्य-देशों के विदेश मंत्री सम्मिलित होते हैं। इसकी सहायता के लिए सैनिक एवं आर्थिक समिति की भी स्थापना की गयी है।

(ख) मुख्यालय—बगदाद समझौते के समय इसका मुख्यालय बगदाद में था जिसके प्रधान को महासचिव कहा जाता है। बगदाद समझौते के अवसान और सेन्टो के निर्माण के बाद उसका मुख्यालय अकारा में स्थापित किया गया।

सेन्टो की आलोचना (Criticism of CENTO)—असल में सेन्टो संगठन के निर्माण के समय जो उसके घोषित उद्देश्य थे, उनमें सदस्य देशों की अमर्यादता ही हाथ लगी। निम्नांकित आधारों पर इसकी आलोचना की जा सकती है :

(क) इसमें अरब देशों में मुठबानी उत्पन्न की;

(ख) इसके जरिये ब्रिटेन और अमरीका ने सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था ही नहीं, बल्कि राजनीतिक-नग्न में भी घुमपैठ आरम्भ कर परोक्ष रूप से नियन्त्रण कर लिया,

(ग) जब 1956 एवं 1971 में भारत-पाक युद्ध हुआ तो सदस्य राष्ट्र पाकिस्तान की मदद करने के लिए न तो ब्रिटेन आया और न ही अन्य सदस्य देश;

(घ) इसके माध्यम में सदस्य देशों को पश्चिमी देशों से जो शस्त्रास्त्र सहायता मिली, उसमें शैथीय तनाव बढ़ा, और

(ङ) ईरान में 1979 में घाटू राजा पहलवी के पतन का कारण उनके द्वारा पश्चिमी देशों का अध्यानुकरण कर जन-विराधी नीतियों का कार्यान्वयन करना था :

सेन्टो का मूल्यांकन

सिएटो की तरह सेन्टो भी एक ऐसा सैनिक संगठन था, जिसे क्षेत्रीय सहकारी संगठन का जमा पहचानने का असफल प्रयत्न किया गया। इसके अतिरिक्त इसका कार्यक्षेत्र बहुत स्पष्ट ढंग से परिभाषित नहीं किया जा सका। एक ओर सोवियत संघ से सामीप्य के कारण यह यूरोपीय घटनाक्रम से जुड़ता था तो दूसरी ओर पाकिस्तान की सदस्यता के कारण दक्षिण एशियाई तनाव से। पश्चिम एशिया के संकट का प्रभाव भी सेन्टो के सामरिक दृश्य पर पड़े बिना नहीं रह सकता था। सेन्टो के सदस्यों को भी सिएटो के सदस्यों की तरह अपने संगठन की असलियत का पता था और वे अपने आश्रयदाता समर्थक को प्रसन्न रखने के अलावा कोई पहल या लाभप्रद बहुपक्षीय सहकार की प्रक्रिया का सूत्रपात करने में अमनमन्य रहे। 1977 के बाद सेन्टो एकदम निष्क्रिय सा हो गया और उसका अस्तित्व सतम हो गया।

अंजुस : सैनिक संगठन या क्षेत्रवाद ?

(ANZUS : Military Organization or Regionalism ?)

अंजुस का गठन ठीत युद्ध के पहले चरण में फरवरी, 1951 में हुआ। इसके तहत अमरीका ने आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैण्ड को सैनिक समझौते का साथी बनाया। इसका नामकरण इनके संसिप्ताक्षरों आस्ट्रेलिया (A), न्यूजीलैण्ड (NZ) और संयुक्त राज्य अमरीका (US) से हुआ। भले ही, अंजुस कभी सिएटो, सेन्टो या नाटो की तरह चर्चित या विवादास्पद नहीं रहा, लेकिन इसके सामरिक महत्व को कम करके आँकना गलत होगा। इसके माध्यम से तत्कालीन अमरीकी विदेश मन्त्री जोन फास्टर डलेस का लक्ष्य हिन्द महासागर और प्रशान्त महानागर के बीच एक प्रतिरक्षात्मक सेतु निर्मित करना था। उनकी 'दूरदर्शिता' इसी से समझी जा सकती है कि तब न तो अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों का आविष्कार हुआ था और न ही आस्ट्रेलिया या न्यूजीलैण्ड को यूरोपीय देशों की तरह किसी बाहरी या आन्तरिक अस्थिरता का खतरा था।

अंजुस के गठन के पीछे लक्ष्य—अंजुस के द्वारा डलेस का प्रयत्न कालक्रम में ब्रिटेन की हिन्द महासागर से वापसी के बाद अपने प्रवेश के लिए जमीन तैयार करना था। इस काम में उन्हें इस बात से सहायता मिली कि अंजुस के सभी सदस्य राष्ट्र गोरे थे और पूँजीवादी मुक्त व्यापार के समर्थक। कई विद्वानों का तो यहाँ तक कहना है कि अंजुस का गठन सिर्फ इसीलिए किया गया था कि घुर दक्षिण में घसे गोरो के माथ भाईचारा निभाने के लिए उन्हें मानसिक संकल दिया जा सके। पर निश्चय ही आरम्भ से अंजुस की उपयोगिता प्रतीकात्मक भर नहीं थी। डलेस शायद यही चाहते थे कि 'कामनवेल्थ' बाने भाईचारे का लाभ वे अपनी सामरिक परिपोजनाओं को प्रियान्वित करने के लिए उठा लें। यह बात नहीं भुलायी जा सकती कि प्रारम्भिक प्रस्ताव में आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड के अलावा भारत को भी शामिल करने की बात मुझायी गयी थी।

जहाँ तक आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड का प्रश्न है, इन दोनों देशों को अमरीका की सामरिक अगुआई स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। न तो उनके मन में यूरोपीय देशों की तरह खोई हुई गरिमा का अहंकार था और न ही उनकी

स्थिति ऐसी थी वे मुद्दूर बविष्य में भी अपने पैरों पर खड़े होने की बात प्रतिरक्षा के क्षेत्र में सोच सकें।

अंजुस की व्यवस्थाएँ (Provisions of ANZUS)—अंजुस संधि के अनुच्छेद चार और पाँच में यह बात स्पष्टतः स्वीकार की गई थी कि किसी भी सदस्य राष्ट्र पर बाहरी आक्रमण की स्थिति में सामूहिक सतरे का मुकाबला सर्वव्यापक प्रावधानों को देखते हुए एक साथ किया जायेगा। वर्यो तर्क आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड मुकाबलों के व्यक्तित्व के आतंक में रहे। पश्चिमी इरियान को आजाद कराने के लिए राष्ट्रपति मुकाबलों ने लड़ने-भिड़ने की जो मुद्रा अपनाई थी, उसे देखते हुए एक बड़ी सीमा तक यह स्वाभाविक भी था। इसीलिए कई दशक तक अंजुस संधि पर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के उभार-चढ़ाव के बावजूद विशेष दबाव नहीं पड़े।

अंजुस के सदस्य राष्ट्रों में फूट (Differences among ANZUS Members)—पिछले दशक में अंजुस फिर से चर्चा का विषय बना है तो इसलिए नहीं कि मिष्टो या नाटो की तरह यह आज अमरत एवं अनुपयोगी जान पड़ने लगा है बल्कि इसलिए कि आज इसके सदस्य-राष्ट्रों के बीच सामरिक मतैक्य दोष नहीं रह गया है। न्यूजीलैंड ने परमाणु निस्संरीकरण के प्रति अपनी पक्षधरता वैदिक आह्वि की है और परमाणु शस्त्रों में सज्जित अमरीकी तथा पाकिस्तानी पोनों को अपने स्वाभित्व वाली जल राशि में न आने देने का निर्णय उमने किया है। इसकी दुवद परिणति रेनबी बोरियर-प्रिन्सीस काण्ड में हो चुकी है। न्यूजीलैंड के भूतपूर्व सुरक्षा-मन्त्री डेविड थामसन का मानना है कि इस संधि पर हस्ताक्षर परमाणु पोनों के अविष्कार के पहले हुए थे। यह स्वाभाविक है कि इसके अनुच्छेदों में इस विषय में कोई व्यवस्था नहीं हो सकती थी। उनकी ममझ में यह स्वमिद्ध है कि इस संधि को अक्षत रखने के लिए इनके प्रयोग के विषय में भी आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एवं अमरीका में सहकार जरूरी है। पर अधिकतर न्यूजीलैंडवासियों और कई आस्ट्रेलियायी विद्वानों का भी मानना है कि आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अमरीकी बद्ध में दुनिया देखना बन्द करना चाहिए। बिडबना ठो यह है कि अंजुस में दूरतें उम बक्त नजर आ रही हैं, जब इण्डोनेशिया में पश्चिमी दक्षि-रक्षान वाली सरकार पिछले 25-26 वर्षों में कार्यरत है और उत्तर की ओर सबसे भयानक सङ्कट (माओवादी चीन) का निवारण हो चुका है। जब तक दक्षिण पूर्व एशिया में हिन्द चीन में सङ्घर्ष चल रहा था, तब भी टोमिनो सिद्धान्त के अनुसार आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का आसक्ति रहना ममझ में आने वाली बात थी। परन्तु ऐसा नहीं कि मिर्क किसी एक क्षण के न रहने से यह सङ्कट दुर्बल पड़ गया है। वस्तु-स्थिति तो यह है कि अंजुस के सदस्य राष्ट्रों के सामरिक हित सामूहिक नहीं रह गये हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीयता और सैनिक सङ्गठनों के प्रतिस्पर्धी-अन्विरोधी तत्त्वों का अच्छा उदाहरण अंजुस में मिलना है। दक्षिण प्रशासन क्षेत्र फामोमी सरकार का परमाणु प्रयोग-स्थल है। यदि यह प्रयोग निरन्तर जारी रहते हैं तो इसका धातक अमर आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पर पड़े बिना नहीं रह सकता। परमाणु निगमरीकरण को लेकर न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा झगडा फाम में ही है। उपर यूरोपीय रणमच की राजनयिक विवशनाओं के दबाव तथा स्टार वार्म परि-यात्रा की प्राथमिकताओं को देखत हुए अमरीका, फाम पर अंजुस सङ्गठने का कोई

प्रयत्न नहीं करना चाहता। इससे आस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड का असंतुष्ट होना तर्क-संगत है।

क्षेत्र में सामरिक परिवर्तन (Strategic Changes in the Area)—पिछले कुछ वर्षों में एक और महत्वपूर्ण सामरिक परिवर्तन इस क्षेत्र में हुआ है, जिसने सदस्य देशों के न केवल 'भूमिरिक्त', बल्कि महत्वपूर्ण सामूहिक हितों को भी उजागर किया है। इस क्षेत्र में मोवियत प्रवेश को लेकर कई देशों की चिन्ता बड़ी है। फिजी, मोलोमन द्वीप, वानाउतु, टोवा, क्रिवात आदि अनेक ऐसे भूमि राज्य हैं, जो देखने में छोटे, मोलने में हल्के जान पड़ते हैं, परन्तु वे अपनी विस्तृत समुद्री सीमा तथा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone) के महत्वपूर्ण समावनाओं वाले हैं। निसाल के तौर पर वानाउतु के साथ मोवियत संघ का हुना मछलियाँ पकड़ने के लिए जो समझौता हुआ है, उसके तहत जटिल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से सज्जित जहाज जहाजों की भांजाजाही शुरू हुई है। कई पश्चिमी विद्वानों का मानना है कि ये मोवियत जहाज मछुआरे नहीं, बल्कि गुप्तचर हैं। दूसरी ओर, स्टारवार्म परियोजना के चर्चित होने के पहले ही ये दूरस्थ छोटे-छोटे द्वीप भी इलेक्ट्रॉनिक संचार सम्पर्क केन्द्रों के रूप में अप्रत्याशित ढंग में महत्वपूर्ण बन गये। इनमें से अनेक को यह लगता है कि उनकी यह नई सामरिक महत्ता ही उनकी स्वाधीनता और सम्प्रभुता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। घेमेका का उदाहरण इनमें से अनेक को याद है। उन्हें यह लगता रहता है कि वास्तव में सामूहिक सुरक्षा अमरीकी छत्रछाया के बाहर ही प्राप्त हो सकती है।

अंजुस की भावी करबट

इन सबसे इस निष्कर्ष तक पहुँचने में जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए कि ये तनाव अजुस के अन्त की पूर्व-सूचना दे रहे हैं। सिर्फ जीवन-यापन शैली के आधार पर ही नहीं, बल्कि आर्थिक अन्तर-निर्भरता के कारण भी अमरीका, आस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड का नाता बहुत नजदीक का है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि गुट-निरोध सम्मेलन या राष्ट्रमण्डलीय सम्मेलन में इस प्रसंग को अधिक ध्यान दिया जाये। यह सम्भव है कि न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया के आत्म-सम्मान को बचाये रखने के लिए अमरीका सिर्फ बोझी-बहुत दिवायदी रियायतें दे दे और अपनी परमाणु नाविक गतिविधियाँ थनवरत चलती रहने दे। आखिरकार जैसे मलेशिया के प्रधानमन्त्री डा० महाबीर ने कहा-- 'ऐसा कोई तरीका नहीं जो पापी की सतह से नीचे परमाणु पनडुब्बी को चलवा रोक सके।' सिर्फ सामरिक मानसों में ही नहीं, आर्थिक सामाजिक व राजनीतिक पैमानों पर भी अमरीका, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच शक्ति तथा सम्भावना का इतना असन्तुलन है कि इस सन्धि को एकतरफा ढंग में रद्द नहीं किया जा सकता। हकीकत तो यह है कि इसका गठन भी पूर्णतः वैकल्पिक नहीं था। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि आज भले ही अन्तराष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीयता की सम्भावनाओं और इससे उपजी एकीकरण की प्रवृत्ति की अनदेखा न किया जा सकता हो, परन्तु आज भी महा-शक्तियों या बड़ी शक्तियों के सामरिक परिप्रेक्ष्य हम पर हावी हैं। यह बात सिर्फ अजुस पर नहीं, अन्य क्षेत्रीय संगठनों पर भी लागू होती है।

वारसा सन्धि संगठन

(Warsaw Treaty Organization)

नाटो का गठन तथा 9 मई, 1955 में पश्चिमी जर्मनी तथा फ्रांस के हममें प्रवेश के प्रतिक्रिया स्वरूप सोवियत संघ के नेतृत्व में यूगोस्लाविया को छोड़कर यूरोप के ममस्त साम्यवादी देश पोलैण्ड की राजधानी वारसा में मिले। उन्होंने 14 मई, 1955 को मैत्री, सहयोग तथा आपसी सहायता सन्धि पर हस्ताक्षर किये, जिसे 'वारसा सन्धि' संगठन के नाम से जाना जाता है। अल्बानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, पोलैण्ड, रूमानिया तथा सोवियत संघ वारसा सन्धि पर हस्ताक्षरकर्ता देश थे। हालांकि 31 मार्च, 1991 को वारसा सन्धि-संगठन विघटित ढंग से भंग कर दिया गया, किन्तु उसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन उपयोगी है।

संगठन की व्यवस्थाएँ

वारसा सन्धि की प्रस्तावना में स्पष्ट कहा गया है कि यूरोप में सामूहिक सुरक्षा की पद्धति स्थापित की जाए। नाटो के निर्माण तथा पश्चिमी जर्मनी के पुनः शस्त्रीकरण से यह आवश्यक हो गया है कि वारसा देश अपनी सुरक्षा मजबूत करें और यूरोप में शान्ति रखें। इसमें सदस्य देशों में पारस्परिक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग की भी बात बही गयी। इसके अलावा (सन्धि के अनुच्छेद तीन में) कहा गया कि यदि किसी सदस्य-देश पर आक्रमण होता है तो उसे अन्य सदस्य-देशों पर भी हमला माना जायेगा और समस्त देश आक्रमणकारी देश के खिलाफ उसे सैनिक सहायता देंगे।

वारसा सन्धि संगठन के कारण एवं उद्देश्य

इसके निर्माण के कारण एवं उद्देश्य निम्नांकित हैं

(क) साम्यवादी प्रसार—द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा। वह चाहता था कि उसके नेतृत्व में दुनिया में साम्यवाद का प्रसार हो। सैनिक सन्धि के जरिये यह काम आसानी से हो सकता था।

(ख) नाटो का विरोध—जब अमेरिका ने साम्यवादी प्रसार रोकने तथा सम्भावित सोवियत हमले के खतरे के मुकाबले के लिए पश्चिमी यूरोप के देशों को 'नाटो संगठन' में बाँध लिया तो सोवियत संघ ने इस यूरोप में अपने हितों के लिए गम्भीर खतरा माना। इसके प्रतिकार में उसने पूर्वी यूरोपीय देशों को एकत्र कर वारसा सन्धि संगठन का निर्माण किया।

संगठन के अंग

(Organs of the Organization)

इसके प्रमुख अंग निम्नांकित हैं

(क) संयुक्त सैनिक कमान—वारसा सन्धि के अनुच्छेद पाँच के अन्तर्गत एक संयुक्त सैनिक कमान (United Military Command) बनायी गयी जिसका मुख्यालय सोवियत संघ की राजधानी मास्को में था। इसके अधीन वारसा सन्धि के

ममस्त सदस्य देशों की सेनाएँ रखी गयी। इनका सर्वोच्च सेनापति, महामन्त्री और सोवियत जनरल स्टाफ के साथ परामर्श करके सेनाओं का संगठन तथा इनका विभिन्न प्रदेशों में वितरण करेगा। यूरोप में इसकी उत्तरी, मध्य तथा दक्षिण यूरोप की तीन कमानें तथा सुदूर पूर्व की एक कमान रखी गयी।

(ख) राजनीतिक सलाहकार समिति—वारसा सन्धि में राजनीतिक सलाहकार समिति की संरचना, नीति-निर्धारक प्राधिकरण तथा प्रक्रिया के बारे में विस्तृत विवरण नहीं दिया गया। सन्धि के अनुच्छेद छह में इस समिति की संरचना के बारे में इतना भर कहा गया कि हरेक राज्य के सदस्य या विशेष रूप से निम्नलिखित प्रतिनिधि को इसमें प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। साम्यवादी दल का नेता विशेष प्रतिनिधि होगा। अनुच्छेद छह के अनुसार समिति की शक्ति परामर्श तक सीमित थी जो सन्धि के त्रिविधन के बारे में उठने वाले मुद्दों पर होगी। समिति संगठन की सलाहकार निकाय मान्य थी। इसके सहित संगठन के सदस्य देशों ने सोवियत संघ के अधीनस्थ रहना स्वीकार किया।

संगठन में संकट—गाटो की तरह वारसा सन्धि संगठन में समय-समय पर अनेक गतिरोध उत्पन्न हुए, जिससे सदस्य देशों की एकता कमजोर हुई। 1955 में संगठन की स्थापना के बाद धीरे-धीरे सोवियत संघ शक्तिशाली हो गया, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उसके द्वारा उठाये गये अनेक कदमों को वारसा सन्धि के सदस्य देशों ने पसन्द नहीं किया। प्रथमतः, 1956 में हंगरी तथा 1968 में चेकोस्लोवाकिया में सोवियत संघ ने सेनाएँ भेजकर हस्तक्षेप किया। रूमानिया तथा अन्य देशों ने इसका समर्थन नहीं किया। द्वितीयतः, वारसा सन्धि का सहारा लेकर सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोपीय देशों में अपना सैनिक जमाव किया और उन देशों को यह अपने मन-मुताबिक नियन्त्रित करने लगा। इसके विरोध में पूर्वी यूरोपीय देशों ने सोवियत-विरोध बढ़ाने लगा। तृतीयतः, सोवियत संघ द्वारा वारसा-देशों को अपने पूर्ण प्रभुत्व में रखने तथा रुडोल्फ-ब्रेसनेव द्वारा स्टालिन की आलोचना के कारण अल्बानिया ने सोवियत संघ से गुस्सा मोड़ लिया और वारसा संगठन की सदस्यता भी त्याग दी। चतुर्थतः, सोवियत संघ द्वारा प्रवर्तित आपसी आर्थिक सहायता परिषद (कोमेकोन), जिसका उद्देश्य पूर्वी यूरोपीय देशों का आर्थिक एकीकरण करना था, वारसा देशों के लिए लाभदायक नहीं, बल्कि बोझ साबित हुई। रूमानिया ने यही महसूस करते हुए अंगरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, मिस्र, अल्जीरिया तथा साम्यवादी चीन से व्यापारिक सम्बन्धों को तोड़ दिया।

संगठन का भूत्पाकन—इन संगठन के जरिए सोवियत संघ पूर्वी यूरोपीय देशों में एकाग्र प्रभाव खोज वापस कर सका था। ये देश सोवियत संघ के 'उपग्रह' बन गये। वारसा सन्धि के जरिए रूस द्वारा हस्तक्षेप करने एवं प्रभुत्व जमाने की नीति से जहाँ एक ओर सदस्य देशों में आन्तरिक विरोध बढ़ा, वहीं गैर-साम्यवादी देशों में सोवियत संघ तथा वारसा सन्धि संगठन की प्रतिष्ठा काफी घटी। पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासनों के खिलाफ आन्दोलनों और लोकतांत्रिक लहर ने वारसा पैक्ट का तेजी से अवमूल्यन किया। पोलैण्ड, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया से सोवियत की वारसा-फौजें लौटने लगी। यही नहीं, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया ने वारसा पैक्ट की मर्यादा के लिए जोरदार मांग की। जर्मनी के एकीकरण ने भी इस संगठन की प्रासंगिकता खत्म कर दी। अतः 31 मार्च, 1991 को वारसा पैक्ट औपचारिक

रूप स भग कर दिया गया ।

क्षेत्रीय सैनिक संगठनों के ह्रास के कारण

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रादेशिक एवं सैनिक संगठनों में सम्मिलित होने की जो महार चली, वह धीरे-धीरे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक गठन से ओझल होने लगी । इन संगठनों में शामिल होने के बाद राष्ट्रों ने पाया कि वे उनके राष्ट्रीय हितों, स्वतन्त्रता एवं सम्प्रभुता की रक्षा के दृष्टिकोण से ज्यादा उपयोगी नहीं । क्षेत्रीय एवं सैनिक संगठनों के ह्रास के कारणों को निम्नांकित बिन्दुओं के अन्तर्गत रखा जा सकता है ।

(क) गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का प्रचार—गुट-निरपेक्ष नीति के तैयारी से प्रसार में प्रादेशिक सैनिक संगठनों का ह्रास हुआ । गुट-निरपेक्ष आन्दोलन ने विश्व में महाशक्तियों द्वारा गुटबाजी की राजनीति करने का मईव विरोध किया । इस आन्दोलन में बड़ी राष्ट्र सम्मिलित हो सकता है जो किसी भी महाशक्ति या बड़ी शक्ति द्वारा प्रवर्तित सैनिक गठबन्धन का मदस्य न हो । इससे अनेक राष्ट्र क्षेत्रीय एवं सैनिक संगठनों में शामिल होने से विमुक्त हुए और कई राष्ट्रों ने इनकी सदस्यता त्याग कर गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में प्रवेश किया ।

(ख) नई शस्त्र टेक्नोलोजी का आविष्कार एवं विकास—नई शस्त्र टेक्नोलोजी के आविष्कार और विकास ने प्रादेशिक सैनिक संगठनों की जड़ें खोखली कर दी । जब धानक रॉकेट, मिसाइल और वमवर्षक विमानों का निर्माण होने लगा तो महाशक्तियों द्वारा किसी अन्य देश के भू-भाग में सैनिक अड्डों की स्थापना की पहले जैसी जल्द नहीं गयी, क्योंकि अब वह दूर से ही नोमना या वामु सेना के जरिए आप्रमण कर मकन की क्षमता रखने लगे । ध्यान रहे कि प्रादेशिक सैनिक संगठनों के जरिये महाशक्तियाँ मदस्य देशों में सैनिक अड्डा स्थापित करनी थी । मसलन, अमरीकी ने फ़िलीपीन, थाइलैण्ड तथा अन्य अनेक देशों में सैनिक अड्डे कायम किये । किन्तु नई शस्त्र टेक्नोलोजी के विकास के बाद इस प्रकार के सैनिक अड्डों में महाशक्तियों की ज्यादा रुचि नहीं रह गयी, क्योंकि वे अपने देश से ही दूर-मारक शस्त्रों से हमला करने की स्थिति में हो गये ।

(ग) मदस्य राष्ट्रों द्वारा क्षेत्रीय सैनिक संगठनों की निरपेक्षता महसूस करना—क्षेत्रीय सैनिक संगठन के अनेक मदस्य राष्ट्रों ने इनकी निरपेक्षता महसूस की । उन्होंने मदस्यता प्राप्त करने के बाद जब यह पाया कि उन संगठनों की प्रवर्तक बड़ी शक्तियाँ इनके द्वारा मात्र अपना हित साधन करनी हैं और सबके समय अपना हाथ पीछे खींच लेनी हैं तो उन्होंने धीरे-धीरे इन संगठनों की कार्यवाही और नीति त्रियान्वयन में रुचि लेना कम कर दिया । अन्ततः अनेक राष्ट्रों ने इनकी मदस्यता त्याग दी । मसलन, पाकिस्तान, अमरीका और ब्रिटेन जैसी दो प्रवर्तक बड़ी शक्तियों की प्रेरणा से मिएंटो और मेन्टो में सम्मिलित हुआ । किन्तु भारत के साथ दो युद्धों में इन बड़ी शक्तियों ने उनकी अपेक्षित सहायता नहीं की उन्हें उसकी दी जान गयी सैनिक सहायता एवं शस्त्र बिक्री पर रोक लगा दी हमारे पाकिस्तान, मिएंटो एवं मेन्टो के साथ अपने सम्बन्धों के प्रति निराश हुए और उनमें इनकी मदस्यता त्याग दी । इस प्रकार अन्य मदस्य देशों ने भी ऐसे ही अनेक कारणों से मदस्यता त्याग दी जिससे ये संगठन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक पटन

से लुप्त हो गये।

(घ) पूर्वी यूरोप में परिवर्तन से वारसा पैकट व नाटो को सटका—पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासनो के खिलाफ जन-आन्दोलनो व लोकतान्त्रिक लहर, सोवियत संघ की दुर्बल स्थिति और जर्मनी के एकीकरण ने जहाँ एक ओर वारसा पैकट के विघटन का मार्ग प्रशस्त किया, वहीं नाटो की उपयोगिता पर गहरा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। इन दोनों संगठनो का गठन तब हुआ था, जब अमरीका व सोवियत संघ के नेतृत्व में क्रमशः पूँजीवादी पश्चिम यूरोपीय देश और साम्यवादी पूर्वी यूरोपीय देश शीत युद्ध लड़ रहे थे। विन्तु अब जब पूर्वी यूरोपीय देश सोवियत संघ के पिछलग्गू नहीं रहे और वारसा पैकट मग कर दिया गया है तो फिर पश्चिम यूरोपीय देशों को साम्यवादी सत्तरे से अपने हितों की रक्षा के लिए नाटो की क्या जरूरत रह जाती है? हालांकि सोवियत संघ ने वारसा पैकट के साथ-साथ नाटो को मंग करने की माग उठायी, किन्तु नाटो अपने 16 सदस्यीय देशों में राजनीतिक सहयोग-वृद्धि और सोवियत ताकत के जवाब में मरुतुलन बनाये रखने में अपनी भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है। इसके अलावा, नाटो अपने क्षेत्र के बाहर की भूमिका को भी जरूरी समझता है। 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान जब अमरीका ने उर्वी स्थित नाटो देशों के अड्डो से इराक पर बमबारी की तो यह चेतावनी भी दी कि यदि इराक ने प्रतिकार कर टर्की पर हमला किया तो इसे नाटो देशों पर हमला माना जायेगा। नाटो की इन भूमिका से सदस्य देशों के इराबे साफ जाहिर हो जाते हैं।

इस सिलसिले में एक और बात का उल्लेख जरूरी है। जर्मनी के एकीकरण के बाद अमरीका और फ्रांस को समुक्त जर्मनी के एक लघु महाशक्ति (Mini-Super Power) बनने का खतरा नजर आ रहा है, जो अंततः नाटो से भी नाता तोड़ सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अमरीकी विदेश नीति निर्धारक इस भावी चुनौती का सामना करने के लिए यह भी प्रयास कर रहे हैं कि नाटो के सैनिक महत्व की समाप्ति के पहले ही उसकी राजनीतिक भूमिका बढ़ायी जाये, ताकि यह संगठन जीवित रह सके। इस राजनीतिक भूमिका के तहत पूर्वी यूरोप में लोकतान्त्रिक आन्दोलनो को समर्थन और पूर्वी व पश्चिम यूरोपीय देशों में व्यापार-सम्बन्ध एवं पूँजी निवेश सम्बन्धी मसलों पर विचार-विमर्श के लिए नाटो को एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया जायगा। बहरहाल, यह तो मानना होगा कि पूर्वी यूरोप में परिवर्तनकारी लहर ने जहाँ एक ओर वारसा पैकट को मग होने के लिए बाध्य किया, वहीं दूसरी ओर नाटो जैसे बड़े सैनिक संगठन के महत्व की एकदम घटा दिया।

क्षेत्रीय सहयोग में 'आसियान' की भूमिका (Role of 'ASEAN' in Regional Cooperation)

दक्षिण पूर्व एशिया नाम से जो क्षेत्र विख्यात है, वह भारत के पूर्व और चीन के दक्षिण में स्थित है। मलयो से इस भू-भाग की अपनी अलग पहचान बनी हुई है। इसमें इण्डोनेशिया, फिलीपीन्स जैसे बड़े द्वीप समूह हैं और हिन्द चीन, मलाया, बर्मा, थाई देश, जैसे ऐतिहासिक महत्व के प्रायद्वीप स्थित राज्य भी। औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश, फ्रांसीसी, डच आदि साम्राज्यवादी शक्तियाँ यहाँ सक्रिय रही।

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ सामरिक महत्व के अनेक युद्ध हुए। शीत युद्ध के आविर्भाव के बाद दक्षिण पूर्व एशिया के अधिकांश देश एक या दूसरे ध्रुव के शिविरानु-चर बन गये और क्षेत्रीय एकता, जो पहले ही औपनिवेशिक काल में खण्डित हो चुकी थी और भी कमजोर पड़ गयी। इस सन्दर्भ में 'आसियान' नामक संगठन एक अनूठा प्रयोग है, जिसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तत्त्व पुष्ट भी करते हैं और दुर्बल भी। 'आसियान' के सदस्य राष्ट्रों की संख्या इस समय छह है।

आसियान से पहले क्षेत्रीय सहयोग के प्रयत्नों की पृष्ठभूमि

'आसियान' से पहले दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में सहकार की अनेक योजनाएँ सुझायी गयी थीं। उनकी सफलता-असफलता को भी 'आसियान' के सदस्य देश अनदेखा नहीं कर सकते। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद समुक्त राष्ट्र सभ ने इकाए (ECAFE) की स्थापना कर इस एशियाई भू-भाग की आर्थिक विकास की समस्याओं को रेखांकित किया। सिएटो की स्थापना ने क्षेत्रीय सामूहिक सुरक्षा की सम्भावना-समस्या पर बल दिया। कोलम्बो योजना ने तकनीकी-सांस्कृतिक सहयोग के लिए जमीन तैयार की। मलय देशों के आपसी भाई-चारे को सुदृढ़ करने वाली योजनाएँ समय-समय पर प्रकाशित की जाती रही। 1959 में 'आसा' (Association of South East Asian States) की प्रस्तावना की गयी और 1961 में मलयेशिया महासभ की। इसके बाद मलेशिया-फिलीपींस विवाद निबटाने के लिए मलाया, फिलीपींस तथा इण्डोनेशिया का संगठन 'माफिलिदो' सुझाया गया। मुकाबलों की हठधर्मिता के कारण इस दिशा में प्रयास प्रगति नहीं हो सकी। 1965 में बाद वियतनाम युद्ध में निरन्तर बढ़ते अमरीकी हस्तक्षेप ने क्षेत्रीय सहकार कम किया है।

1965 में तन्हा पलट के बाद मुकाबलों अपदस्त हुए और मलेशियाई महासभ से सिंगापुर के निकल जाने के बाद एक बार फिर क्षेत्रीय सहकार की बात उठायी जाने लगी। 1967-68 में ब्रिटेन ने स्वयं के पूर्व से अपनी सेनाओं को वापस बुला लेने की घोषणा की और चीन में महान् सांस्कृतिक क्रान्ति के विस्फोट के साथ इस क्षेत्र में अपने सामरिक हिनो के लिए पश्चिमी शक्तियाँ व्यग्र होने लगी। इस समय तक सिएटो का खोखलापन अन्धरी तरह प्रकट हो चुका था। इसीलिए कुछ विश्लेषकों को लगता है कि 'आसियान' की प्रस्तावना एक नव-उपनिवेशवादी-साम्राज्यवादी रणनीति के अनुसार ही हुई थी। यह सच है कि आसियान के सभी सदस्य कमोबेश पश्चिमी क्षेत्र के पक्षधर हैं, परन्तु निजी या क्षेत्रीय हिनो को लेकर इनमें सभी मामलों में मतभेद नहीं हैं। उदाहरणार्थ, चीन के विषय में या हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों की उपस्थिति के बारे में सिंगापुर और इण्डोनेशिया दो बिन्दुन ही अलग-अलग छोरों पर खड़े दीखते हैं।

आसियान का गठन
(Formation of ASEAN)

1967 में इण्डोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एवं थाईलैंड द्वारा 'आसियान' नामक अर्धनैतिक संगठन का निर्माण दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में क्षेत्रीय सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। बाद में ब्रुनई भी इसका सदस्य

बना। इस क्षेत्र के प्राकृतिक सम्पदायुक्त एवं सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थिति में होने के कारण सातवाँ दशक समाप्त होते-होते यह बड़ी शक्तियों के लिए विशेष रूप से आर्थिक प्रतिद्वन्द्विता का क्षेत्र बनता गया। वियतनाम युद्ध के दौरान जापान, आस्ट्रेलिया एवं यूरोपीय देशों के हाथों सोया यह बुघार याप रूपी साभकारी बाजार अमरीका इन दिनों फिर से पाने की दुगुने उत्साह से चेष्टा कर रहा है। सोवियत संघ तथा साम्यवादी चीन भी बड़ी शक्तियाँ होने के नाते अपने-अपने व्यस्त राजनीतिक एवं आर्थिक स्वाधों की पुति में दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र को किसी दूसरे सेमे के चगुल में नहीं देखना चाहते। आसियान के छोटी सदस्य-राष्ट्रों में विभिन्न भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति, खान-खान, रहन-सहन वाले लोग निवास करते हैं। हालांकि इन देशों का विगत औपनिवेशिक इतिहास, वर्तमान राजनीतिक एवं आर्थिक तन्त्र तथा सामाजिक जीवन के मूल्य भी भिन्न-भिन्न हैं, फिर भी, उक्त देशों के सम्मुख आम चुनौतियों जनसंख्या विस्फोट, गरीबी, अशुभभा (आन्तरिक एवं बाहरी), आर्थिक शोषण आदि हैं, जिन्होंने उनको 'आसियान' के निर्माण के लिए उत्साहित किया। उक्त समस्त कारणों से क्षेत्रीय सहयोग में 'आसियान' की भूमिका का महत्त्व बढ़ जाता है।

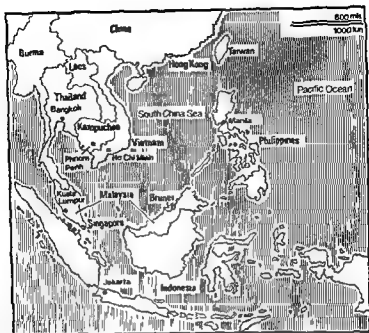
वस्तुतः दक्षिण पूर्व एशिया में क्षेत्रीय सहयोग कायम करने की दिशा में 1967 में 'आसियान' का निर्माण ही प्रथम प्रयास मही या। इससे पूर्व 'ग्रेट ईस्ट एशिया को-प्रोस्पेरिटी स्फोर', 'इकाके', 'सिएटो', 'आसा', 'माफिलिदो' आदि का निर्माण किया गया, किन्तु उनकी संरचनात्मक सुटियों, सदस्य-राष्ट्रों में आपसी मन-मुटाव एवं अविश्वास, कुछ विशेष अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ आदि कारणों से वे सफल नहीं हो सके। 1967 में 'आसियान' के निर्माण के समय पूर्वकाल की असफलताओं के कारणों को ध्यान में रखा गया, जिससे सदस्य-राष्ट्रों को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में कटु अनुभव न हो : आसियान के निर्माण के पूर्व सदस्य-राष्ट्रों की आपसी राजनीतिक मत भिन्नता को कम किया गया। 1966 में इण्डोनेशिया एवं मलेशिया के बीच झगड़े को सुलझा दिया गया। इण्डोनेशिया, मलेशिया एवं सिंगापुर में व्यापारिक एवं राजनयिक सम्बन्ध स्थापित किये गये। 1963 में मलेशिया एवं सिंगापुर के बीच माका के सम्बन्ध में उठे प्रादेशिक अधिकार के झगड़े का कुछ सीमा तक सामाज्यीकरण किया गया।

आसियान का स्वरूप व उद्देश्य

(ASEAN : Nature and Objectives)

मोटे तौर पर आसियान का उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रशासनिक, आदि क्षेत्रों में परस्पर सहायता करना तथा सामूहिक सहयोग से विभिन्न आम समस्याओं का हल ढूँढना है, जो इसके निर्माण के समय आसियान घोषणा में स्पष्ट रूप में लिखित है। इस क्षेत्रीय संगठन का स्वरूप कदापि 'मैनिक' नहीं है। सदस्य राष्ट्र 'सामूहिक सुरक्षा' जैसी किसी गठोर एवं अनिवार्य शर्त से बंधे हुए नहीं है। यह किसी महा-शक्ति से प्रोत्साहित, प्रवर्तित एवं जुड़ा नहीं है। आसियान की सदस्यता उन सभी दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के लिए खुली है जो इसके लक्ष्यों से सहमत हैं।

अग्रलिखित परिप्रेक्ष्य में विचारणीय प्रश्न यह है कि 'आसियान' क्षेत्रीय सहयोग



चित्र—दक्षिण पूर्व एशिया का मानचित्र, जिसमें 'आसियान' के छहो सदस्य देशों को दर्शाया गया है।

कायम करने के उद्देश्य में किस सीमा तक सफल रहा? अमल में इसका मूल्यांकन 'आसियान' की संरचना एवं कार्यों का निम्ना-जोखा देखकर आसानी से किया जा सकता है।

संगठन के कार्य

(Functions of the Organization)

आसियान अपने स्थापना काल के बाद दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों में आपसी सम्बन्धों को निवृत्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। हमारे सदस्य देश अपनी वैधानिक कार्यप्रणालियों की क्षेत्रीय संगठन द्वारा मुलभूतों के लिए प्रस्तुत करते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में आसियान ने अपना एक सामूहिक संगठन 'आसियान' स्थापित किया है जो बिना 'वीमा' के सदस्य राष्ट्रों में पर्यटन की सुविधा प्रदान करता है। आसियान देशों ने 1971 में हवाई सेवाओं के व्यापारिक अधिकारों की रक्षा एवं 1972 में कंटेनर जहाजों की महत्वपूर्ण पहुँचाने में सम्बन्धित समझौते पर हस्ताक्षर किए। 'आसियान' ने व्यापक मामलों के उत्पादन में प्राथमिकता देने के लिए किसानों को अर्द्धवैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा देने के कुछ कदम उठाये हैं जो विशेषकर मत्त, चावल तथा पशुपालन में महत्वपूर्ण होय।

सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों से सम्बन्धित स्थायी समिति ने अनेक परियोजनाएँ बनायी हैं जिनका उद्देश्य जनसंख्या नियन्त्रण एवं परिवार नियोजन कार्यक्रमों को प्रोत्साहन, दवाइयों के निर्माण पर नियन्त्रण, मानवीय वातावरण, शैक्षणिक खेल, सामाजिक कल्याण एवं राष्ट्रीय व्यवस्था में समुक्त कार्यप्रणाली को महत्व देना है। 1969 में संचार-व्यवस्था एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एक समझौता किया गया जिसके अन्तर्गत आसियान के सदस्य राष्ट्र रेडियो एवं दूरदर्शन के माध्यम से एक-दूसरे के कार्यक्रमों का परस्पर आदान-प्रदान करते हैं। एक आसियान फिल्म समारोह भी प्रतिवर्ष जनता की भाँवों के अनुसार वारी-वारी से सदस्य राष्ट्रों में मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त क्षेत्र की जनता तक समाचार पहुँचाने के लिए एक 'आसियान जर्नल' का प्रकाशन भी किया जाता है।

शायमिक आधार पर सीमित जस्तुओं के 'स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र' स्थापित करने के लिए आसियान के सदस्य राष्ट्र विचार कर रहे हैं। आसियान देशों में आपसी निर्यात एवं आयात उनके सीमित बाजार का विस्तार तथा विदेशी मुद्रा की बचत करेंगे। इसके अलावा आसियान वाणिज्य व उद्योग संघों के महासच के एजेन्डा पर मुख्य नियतों में आसियान देशों के समुक्त बाजार एवं व्यापार का लक्ष्य रखा जा चुका है। किस प्रकार उक्त योजनाएँ एवं कार्यक्रम सफल होंगे, इस सम्बन्ध में आसियान देशों द्वारा सामूहिक एवं वैयक्तिक रूप से विविष्ट अध्ययन किये जा रहे हैं।

1976 के बाली शिखर सम्मेलन में सदस्य राष्ट्रों के प्रधानों ने क्षेत्रीय सहयोग में आसियान की भूमिका पर एक अधिक ठोस रूपरेखा प्रस्तुत की। एक घोषणा एवं समझौते में इण्डोनेशिया एवं फिलीपींस के राष्ट्रपति और सिंगापुर, मलेशिया एवं थाइलैंड के प्रधानमन्त्रियों ने यह घोषणा की कि आसियान का कार्य-क्षेत्र मिला अधिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक मामलों तक ही सीमित रहेगा तथा उसमें 'सुरक्षा' को सम्मिलित नहीं किया जायेगा। वे आवश्यक व्यापारिक व्यवस्था के लिए औद्योगिक संयंत्र की स्थापना के लिए महमत हुए। आसियान के सदस्य राष्ट्रों ने क्षेत्र के अन्दर तथा बाहर शान्ति बनाये रखने के लिए एक सहयोग एवं मैत्री सन्धि पर हस्ताक्षर किये। क्षेत्रीय सुरक्षा कायम रखने हेतु उन्होंने गैर-एशियाई आधार पर सदस्य राष्ट्रों ने उनकी आपसी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए द्विपक्षीय सहयोग जारी रखने का निश्चय किया। इस शिखर सम्मेलन में सदस्य राष्ट्रों ने इस बात की पुनः पुष्टि की कि आसियान साम्यवाद एवं हिन्दू चीन-विरोधी नहीं है। सक्षेप में बाली शिखर सम्मेलन में आसियान के सदस्य राष्ट्रों में पारस्परिक सहयोग को बढ़ाने के मन्दर्मे में मुख्य रूप से तीन मुद्दाव रखे गये, जो निम्नांकित हैं—

1. बाहरी आयात कम करके सदस्य राष्ट्र पारस्परिक व्यापार को महत्व दें,
2. अपिसेप साथ एवं ऊर्जा शक्ति बाने राष्ट्र इन क्षेत्रों में अभाव से पीड़ित आसियान देशों को मदद दें; एवं
3. आसियान के देश व्यापार को अधिकाधिक क्षेत्रीय बनाने का प्रयास करेंगे।

वस्तुतः, आसियान के विगत रिकार्ड को देखते हुए यह कहना कदापि

अनुचित नहीं होगा कि सदस्य राष्ट्रों में वह आर्थिक एवं अन्य प्रकार का सहयोग तीव्र गति से नहीं बढ़ा पाया है। आर्थिक सहयोग में 'आसियान' की गति मन्द होने का कारण सदस्य राष्ट्रों के पास आवश्यक पूँजी एवं श्रम शक्ति का कम होना है। सदस्य राष्ट्रों के हितों में आपसी टकराव के कारण उनके बीच कई अन्तर्राष्ट्रीय झगड़े भी उठे हैं। अतः क्षेत्रीय सहयोग की दिशा में रूढ़ता से कदम उठाने हेतु 'आसियान' के सदस्य राष्ट्रों द्वारा क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय हितों में सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है।

एशिया में राष्ट्रीय मुक्ति संग्रामों की सफलता तथा अमरीकी सैनिक हस्तक्षेप की असफलता ने आसियान देशों द्वारा उनके बीच सैनिक समझौता होने को निरस्तार्हित किया, अर्थात् सामाजिक एवं आर्थिक मामलों में सैनिक गुटों के नकारात्मक अनुभव के कारण सदस्य देशों द्वारा आसियान को सैनिक संगठन बनाने के सम्बन्ध में निरस्तार्हित किया। 1972 में चीन के प्रति अमरीका की बदती विदेश नीति ने आसियान देशों के शाक्तों में अमरीका के प्रति सन्देह उत्पन्न किया कि वही अमरीका चीन के साथ 'मैत्री' के षड्यंत्र में चीन के बढ़ते राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभाव-क्षेत्र की बाध को नजरअन्दाज न कर ले।

सोवियत संघ एवं चीन 'आसियान' को समय-समय पर पश्चिमी गुट के अन्ध भक्त की सहा देते रहे हैं। यह सही है कि इण्डोनेशिया के अतिरिक्त आसियान के अन्य चार सदस्य राष्ट्र मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपीन एवं थाईलैण्ड पश्चिमी देशों के साथ सुरक्षात्मक समझौते से जुड़े हुए हैं तथा उन्होंने विश्व राजनीति के अनेक मुद्दों पर ही नहीं, बल्कि हिन्द चीन पर भी पश्चिमी शक्तियों का साथ दिया है। फिर भी, अब वे साम्यवाद के कट्टर विरोधी नहीं रहे हैं। इसी कारण वे हिन्द चीन के राष्ट्रों को आसियान में सम्मिलित करने पर राजी हैं बशर्त कि आवेदनकर्ता राष्ट्र आसियान के सदस्यों से सहमत हो।

बदला परिवेश

यह कहा जाता है कि सदस्य राष्ट्रों में विदेशी सैनिक शक्तियों के सैनिक अहंता एवं अतंगल प्रभाव की अनुपस्थिति वियतनाम के द्वारा आसियान में सम्मिलित होने की प्रथम शर्त है। अतः, बदलती क्षेत्रीय स्थिति अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अनेक तत्वों के समावेश के कारण 'आसियान' के सदस्य राष्ट्रों की हिन्द चीन के राष्ट्रों के प्रति पुरानी हठधर्मिता का रूप बदल चुका है। आसियान के सदस्य राष्ट्रों के अनेक नेताओं ने 1967 में जारी की गई आसियान घोषणा का हवाला देते हुए कई बार कहा कि 'आसियान' दक्षिण-पूर्व एशिया के उन सभी राष्ट्रों के लिए खुला है जो इसके उद्देश्य, मिश्रान्त तथा प्रयोजनों में विश्वास रखते हो। उक्त घोषणा की यह बात भी उनके द्वारा बार-बार दोहराई जा चुकी है कि 'आसियान' के सदस्य राष्ट्रों में विदेशी सैनिक अहंता अस्थाई है। वस्तुतः आसियान के सदस्य राष्ट्रों पर साम्यवादी विरोधी होने का आरोप का सुरक्षात्मक जवाब उन्होंने अनेक साम्यवादी देशों के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित कर दिया है। इस दिशा में अप्रैल, 1976 तथा मई, 1976 में मलेशिया, सिंगापुर एवं फिलीपीन द्वारा वम्पुनिया से राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इन दिनों आसियान के अनेक सदस्य राष्ट्र सोवियत संघ एवं साम्यवादी चीन से भी व्यापार द्वारा अपने

सम्बन्ध निकटतर बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। आसियान का निर्माण करते समय उसके अधिकांश सदस्य राष्ट्रों के पश्चिमी राष्ट्रों के निकटवर्ती राज्यों के मुकाबले समीप के सम्बन्ध थे, किन्तु वर्तमान समय में वे अधिक जागरूक, सच्चे पड़ोसी एवं सामूहिक सहयोग के बारे में अधिक से अधिक कार्यरत हैं। वस्तुतः आसियान के द्वारा उसके सदस्य राष्ट्रों को राजनय का एक नया आयाम मिला है। यह सही है कि आसियान द्वारा प्रारम्भिक वर्षों में क्षेत्रीय सहयोग कायम करने में सदस्य राष्ट्रों में आपसी गलतफहमियाँ थी कि उनसे निकटवर्ती राष्ट्रों में परिवर्तनों के सम्बन्ध में मन्त्रणा नहीं की गई। किन्तु अब उनके उत्साहजनक कार्यकलापों को देखकर लगता है कि उनका राजनय परिपक्व अवस्था की ओर अग्रसर हो रहा है। जनवरी, 1974 में सिंगापुर के प्रधानमन्त्री ली कुआन यू ने आसियान के सदस्य राष्ट्रों की अपनी यात्रा के दौरान फिलीपींस में कहा कि इस समय तेल मकट को लेकर सदस्य राष्ट्रों का सामूहिक दृष्टिकोण अधिक महत्वपूर्ण रहा, बनिस्वत जब वे पूर्वकाल में वैयक्तिक स्तर पर अपने राजनय को क्रियान्वित करते थे।

जैसाकि पहले कहा जा चुका है, आज आसियान के कार्यों का क्षेत्र काफी विस्तृत है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में आसियान की परियोजनाएँ हैं। आसियान घोषणा-पत्र यद्यपि राजनीतिक मामलों को क्षेत्रीय विषयों में नहीं जोड़ना चाहता, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि यह आसियान का महत्व कम कर देता है। यह आज समस्त राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रशासनिक आदि क्षेत्रों में कार्यरत है। यही केवल सबसे अधिक प्रचलित सच्चा क्षेत्रीय जन संगठन है एवं 'आसियान' के सदस्य राष्ट्रों की जनता उसकी एक ऐसी मशीनरी के रूप में मानती है जो एक देश की जनता को दूसरे देश की जनता से जोड़ती है। सदस्य राष्ट्र द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सम्बन्धों की स्थापना के विषय में नीति निर्धारण करते समय इसकी दृष्टि में रखते हैं। अन्य क्षेत्रीय संगठनों जैसे इकाई एवं यूरोपीय साझा बाजार जैसे संगठनों की बैठकों में 'आसियान' की दक्षिण-पूर्व एशियायी राष्ट्रों की एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में माना जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि में इसका महत्व यहाँ तक बढ़ गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में आसियान के सदस्य राष्ट्रों में सहयोग पर अनेक अध्ययन किये हैं।

आसियान का मूल्यांकन (Assessment of ASEAN)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ पर्यवेक्षकों का मत है कि छोटे तौर पर 'आसियान' का कार्य मन्द एवं निराशाजनक रहा है। इस कथन के समर्थन में उक्त पर्यवेक्षक आसियान की तुलना यूरोपीय आर्थिक समूह की सफलताओं का उदाहरण देकर करते हैं। वस्तुतः आसियान के कार्यों की बिगल एवं भाषी स्थिति समझने के लिए आवश्यक है कि हम उसकी तुलना यूरोपीय आर्थिक समुदाय से करते वक्त दोनों क्षेत्रीय संगठनों के उद्भव के पीछे विभिन्न कारणों एवं तत्कालीन परिस्थितियों का भी तुलनात्मक अध्ययन करें, तभी किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है।

इस प्रकार 1967 में स्थापित किये गये 'आसियान' नामक अर्धनिक संगठन का विकास मन्द गति से किन्तु नियमित एवं आयाजनक तरीके से हुआ है, जो सदस्य राष्ट्रों में बढ़ते आपसी विश्वास एवं सहयोग का सूचक है। दक्षिण पूर्व एशिया में

क्षेत्रीय सहयोग कार्यक्रम करने की दिशा में 'आसियान' तीसरी दुनिया के लिए राजनयिक मॉडल का रूप धारण कर सकता है, बशर्ते उसका सांस्थानीकरण सुचारु एवं सावधानीपूर्वक किया जाये। वस्तुतः एक मजबूत एवं सांस्थानीकृत 'आसियान' महा-शक्तियों से सम्मान प्राप्त कर सकता है, अन्यथा कमजोर 'आसियान' उनके हस्तक्षेप, दबाव एवं प्रभाव का शिकार होगा।

1975 में वियतनाम की मुक्ति और एकीकरण के बाद इस स्थिति में आमूल-धूल परिवर्तन आया है। एक ओर बड़ी शक्तियों को यह लगा कि आसियान ही वियतनाम की सैनिक, विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं पर अकुल लगा सकता है तो दूसरी ओर कम्युनिस्ट व वियतनामी हस्तक्षेप में आसियान के सदस्यों में बुनियादी मतभेद उभरने लगे। जहाँ एक ओर मिमापुर और यार्दलैण्ड जुझारू वैर का भाव दर्शाने रहे हैं, वहीं इण्डोनेशिया और मलयेसिया वही अधिक मूलह-समझौते के लिए तत्पर रहे हैं। आसियान की स्थापना से आज तक दक्षिण पूर्व एशिया के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं। चीन में माओ युग के माप ही उग्र आक्रामकता का अन्त हुआ है तथा जर्मनी-चीन सम्बन्धों में दूरगामी सुधार के आसार सामने आने लगे। स्वयं मलयेसिया व इण्डोनेशिया जैसे देशों ने सोवियत संघ और चीन जैसे साम्यवादी देशों के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने में पहल की है। इसके अलावा फिलीपींस में मार्कोस के पतन के बाद फिलीपींस के राजनीतिक संस्कार में बुनियादी परिवर्तन आया है। साथ ही वियतनाम में पुरानी पीढ़ी के कट्टरपंथी शीर्षस्थ नेताओं के अवकाश-ग्रहण के बाद वियतनाम की विदेश नीति में नरम पड़ने की आशा जगी है। ऐसा लगता है कि स्थापना के दो दशक बाद जाकर आसियान मार्चक, रचनात्मक, ठोस कदम उठाने की स्थिति तक पहुँच पाया है।¹

'सार्क' संगठन और क्षेत्रीय सहयोग

(South Asian Association of Regional Cooperation ('SAARC') and Regional Cooperation)

द्वितीय विश्व युद्ध से पहले दक्षिण एशिया के लगभग सभी देश ब्रिटिश उपनिवेश थे और एक ही प्रशासनिक ढाँचे के अधीन थे। प्रकृति ने वैसे भी भारतीय उपमहाद्वीप को जो रूप दिया है, उसमें भौगोलिक एवं आर्थिक दृष्टि में स्वेच्छ दर से लेकर कोहिमा तक और हिमाचल से लेकर हिन्द महासागर स्थित थ्रीलका व मानदीव जैसे द्वीपों तक इस एक ही 'इकाई' बनाया है। इस परिस्थिति में दक्षिण एशिया के सभी देशों के बीच क्षेत्रीय सहकार का तर्क बहुत प्रबल है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अर्थशास्त्र का तर्क हमेशा कारगर नहीं होता और यही बात दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहकार पर भी लागू होती है। साम्राज्यवादियों की 'कूट ढालों और राज करों' वाली नीति ने 'अलण्ड भारत' में साम्प्रदायिक द्वेष और नस्लीय

¹ इस परिच्छेद में आसियान और दक्षिण एशियाई देशों के बीच आर्थिक सहकार के बारे में तुल्य रूप देखा गया है। यह विषय काफी महत्वपूर्ण है और इसके सम्बन्धित विवेचन के लिए देखें, Charan D. Wadhwa and Mukul G. Easler (ed), *ASEAN-South Asia Economic Relations* (Singapore, 1983)

बैर भाव को जन्म दिया। सदियों से जो तीस एक अविभाजित सांस्कृतिक-व्यापारिक जगत के निवासी थे, वे औपनिवेशिक मुनाफाखोरी या सामरिक जरूरतों के अनुसार कृत्रिम दीवारों द्वारा एक-दूसरे से अलग कर दिये गये। भारत और पाकिस्तान का उदाहरण सबसे पहले याद आता है, परन्तु श्रीलंका, बर्मा और नेपाल के विषय में भी यही बात लागू होती है।

दक्षिण एशियाई देशों में मतभेद

(Differences among South Asian Nations)

भारत के आजाद होने के बाद नेहरू जी की प्रेरणा और निर्देशन में देश ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनायी। इस कारण भी भारत द्वारा अनेक पड़ोसियों के साथ सार्थक संवाद की सम्भावना कम हुई। पाकिस्तान, अमरीका पक्षधर और पश्चिमी सैनिक गठबन्धन का सदस्य था तथा कोटलेवाला के प्रधान-मन्त्रित्व काल में श्रीलंका भी छोटे राष्ट्रों के लिए विदेशी बड़ी शक्तियों द्वारा समर्पित सामूहिक सुरक्षा योजनाओं को लाभप्रद समझता रहा। बर्मा में व्यापक जन-जातीय विद्रोह निरन्तर जारी रहे और बर्मा गुट निरपेक्षता क्रमशः एकान्तवास में बदल गयी। नेपाल में राणा वंश की तानाशाही का अन्त भारतीय सहायता से ही सम्पन्न हुआ। इसके बाद पश्चिमी नमूने के जनतान्त्रिक प्रयोग की असफलता ने नेपाल तथा भारत दोनों को ही एक-दूसरे से खिन्न किया।

इस पृष्ठभूमि को दोहराने का प्रमुख उद्देश्य यह बताना है कि भारत के छोटे पड़ोसी उसकी ओर से अपने को निरापद नहीं समझते। इन पड़ोसियों के शक बिल्कुल बेवुनियाद भी नहीं कहे जा सकते। राणाशाही के उन्मूलन का जिफ्र ऊपर किया जा चुका है। 1971 में पाकिस्तान का विभाजन भारतीय सहयोग से ही हुआ। बर्मा तथा श्रीलंका को अलग-अलग अवसरों पर बिम्बवकारियों के दमन के लिए भारतीय सैनिक सहायता दी गयी। सैनिक बल और आर्थिक सामर्थ्य की दृष्टि से भारत का आकार सारे पड़ोसियों के एक हो जाने के बाद भी उन्हें दैत्यकार लगता है। अनेक भारतीय नेताओं ने समय-समय पर अपने पड़ोसी देशों से सरफार के स्वरूप के धारे में आलोचनात्मक टिप्पणियाँ कर उन्हें और भी आशंकित रखा है। नेपाल एवं श्रीलंका जैसे राज्यों का यह सोचना गलत भी नहीं कहा जा सकता कि भारत और उनकी समस्याएँ भिन्न हैं, उपलब्ध समाधान और तदनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सम्बन्ध में उनका दृष्टिकोण भी एकसा नहीं है।

क्षेत्रीय सहकार के प्रयत्न व भारत का संकोच
(Regional Cooperation and India)

इस सबसे यह समझना गलत होगा कि 'शार्क' की प्रस्तावना के पहले क्षेत्रीय सहकार का कोई प्रयत्न इस क्षेत्र में नहीं किया गया। नेहरू जी और लिखाकत अली खाँ के जीवन काल में गद्दी जल-विवाद के निपटारे, सलाल और फरक्का जलबन्ध के शिलानिर्माण से रचनात्मक सहकारी परियोजनाओं को अनेक बार सुलझाया गया। इसी तरह कोलम्बो योजना, आइटेक परियोजना के अन्तर्गत वैज्ञानिक व तकनीकी सहकार की प्रस्तावना—परियोजनाओं में इस समूचे दक्षिण एशियाई क्षेत्र को अधिनतर एक अविभाज्य इकाई के रूप में देखा गया। इस बात से भी इंकार नहीं किया जा

सकता कि इस तरह के सहकार के सामंदायिक परिणाम ही निक्लें। तब भी भारत अपने पड़ोसियों की सबेदनशीलता के प्रति हमेशा सतर्क रहा है। उसने स्वयं कभी क्षेत्रीय सहकार की नई रूपरेखा मुझाने में कोई पहल नहीं की है, ताकि उसके मतव्यों को गलत न समझा जायें और कोई भी छोटा पड़ोसी यह आरोप-आशं न लगा सके कि भारत इस बहाने दक्षिण एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है।

जहाँ तक पड़ोसियों के साथ भारत के उभयपक्षीय सम्बन्धों का प्रश्न है, बरमोर को छोड़कर लगभग सभी अन्य विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण परामर्श द्वारा सम्भव हुआ है और हमने क्षेत्रीय सहकार की जमीन तैयार की है। नेपाल के साथ व्यापार और परागमन संधि, श्रीलंका के साथ बच्चा तिवु समझौता, बर्मा और श्रीलंका के साथ भारतीय मूल के नागरिकों की गुंथी मुलझाना सभी उदाहरण-स्वरूप गिनाये जा सकते हैं। परन्तु हमने इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सकता कि औपनिवेशिक काल का जहर मिट चुका है या कि यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया की तरह क्षेत्रीय एकीकरण का भाव दक्षिण एशिया में भी प्रबल हुआ है। जिन समझौतों का ऊपर उल्लेख है, वे दोनों पक्षों के लिए बराबर लाभप्रद नहीं है। कई विद्वानों का मानना है कि भारत के पड़ोसियों का प्रयत्न सिर्फ इतना-भर रहा है कि क्षेत्रीय सद्भावना की दुहाई देकर वे भारत को कमोन्स अपने राष्ट्रीय हितों की बलि देने के लिए विवश कर सकें। इन्हीं कारणों से 1947 से 1981 तक क्षेत्रीय सहकार के बारे में दक्षिण एशियाई मोक्ष असमंजस बाता हो रहा। 1970 वाले दशक के मध्य में ईरान के शाह ने अपनी समृद्धि के अहंकार में एक बार व्यापक एशियाई विकासोन्मुख सहकार की बात मुझायी, जिसका आधार दक्षिण एशियाई देशों को बनना था, परन्तु उसके पतन के बाद यह प्रस्ताव खटौई में पड़ गया।

‘सार्क’ का प्रस्ताव (Proposal of SAARC)

यह मानना तर्कसंगत होगा कि जब 1981 में बंगला देश के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल जिया-उर-रहमान ने दक्षिण एशियाई देशों के सहयोग का प्रस्ताव रखा तो यह एक नई पहल थी। इस समय तक दक्षिण एशियाई अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों में व्यापक परिवर्तन हो चुके थे। भारत में आपानगर की घोषणा, चुनाव में कांग्रेस की भारी पराजय और जनता सरकार की पुराने ढर्रे की विदेश नीति ने अनेक पड़ोसियों को यह मोचने का मौका दिया था कि वे मगठित होकर अपने हितों की रक्षा भारत के मुकाबले वही बेहतर ढंग से कर सकते हैं। अने ही कुछ विद्वानों ने यह बात मुझायी हो कि जनरल जिया-उर-रहमान ने यह पहल अमरीकी इशारे पर की थी, तथापि हमने प्रमाण आशानों से नहीं जुटाये जा सके हैं। यह मोचना अधिक तर्कसंगत है कि सैनिक तानाशाही का जनप्रिय नागरिक रूपान्तरण चाहने और वैधानिकता का जामा पहनने के लिए उन्मुख जनरल जिया की यह अपनी मौलिक सूझ थी। यह नहीं भूलना चाहिए कि 1981 में अनेक पर्यवेक्षकों का मानना था कि पुनर्निर्वाचित श्रीमती गांधी बहुत सुधर चुकी हैं और पड़ोसियों के प्रति भारत का रवैया अब अपेक्षाकृत कम बटोर रहा। जनरल जिया ने इस बात की सहानुभूति बरती कि राजनीतिक मतभेद आरम्भ में ही सार्क के मार्ग में बड़ी बाधा न बन जायें। इसीलिए

साकं के मूल घोषणा-पत्र में यह बात स्पष्ट की गई कि दक्षिण एसियाई देश इस मंच पर आपसी राजनीतिक विवाद नहीं धकौटेंगे, कैसेले सर्वसम्मति से विजे जायेंगे और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रश्नों पर एक समान नीति अपनाने का प्रयत्न करेंगे। तब से आज तक विदेश मन्त्रि, विदेश मन्त्री, विशेषज्ञ स्तर पर साकं की अनेक बैठकें हो चुकी है और कुछ शिखर सम्मेलन भी। दक्षिण एसियाई सहयोग के बारे में इनके आधार पर तर्कसंगत निष्कर्ष निकालना आज सम्भव है।

1981 के बाद पहले चार-पाँच वर्षों तक साकं एक अमूर्त आन्दोलन के रूप में चर्चित रहा। इसकी एक संगठन के रूप में स्थापना करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। इसके दो कारण थे। ऊपर बिनाये गये कारणों से भारत तो इस विषय में कोई पहल कर ही नहीं सकता था। अन्य सदस्य भी कुछ रुककर औरों की प्रतिनिधिता देख परख लेना चाहते थे। दूसरे, जम्मल जिगा-उर-रहमान ने अपनी प्रस्तावना में यह सकेत दिया था कि शीर्ष सम्मेलन की सफलता के लिए विशेषज्ञों और उच्च-स्तरीय सरकारी अफसरों द्वारा जमीन पहले अच्छी तरह तैयार की जानी जरूरी है। यो डाका और बंगलौर में पहले तथा दूसरे शिखर सम्मेलनों (दिसम्बर, 1985 और नवम्बर 1986) के पहले मार्क अन्तर्राष्ट्रीय खेल समारोह तथा पिम्पू-वार्ता सम्पन्न हो चुके थे। परन्तु इनका महत्व ठोस राजनय की दृष्टि से नहीं, प्रचार के सदर्भ में ही था। पिम्पू वार्ताएँ चर्चा का विषय बनी तो सिर्फ इसलिए कि श्रीलंका की जातीय समस्या के समाधान के लिए भारत की मध्यस्थता में कोलम्बो और 'तमिल बागियो' के बीच सीमा सवाद यहाँ शुरू हो सका। 1981 से नवम्बर 1985 तक का तिथिक्रम दोहराना लाभप्रद नहीं। यहाँ सिर्फ दो-तीन ऐसी बातों की ओर इशारा जरूरी है, जिससे इन वर्षों में थोड़ी प्रगति के कारणों का विश्लेषण स्वयमेव हो जाता है। पहले बंगला देश में राष्ट्रपति जिगा-उर-रहमान की हत्या हुई और तख्ता पलट। फिर पाकिस्तान में जनतन्त्र की बहाली के लिए बेनजीर भुट्टो के लिए व्यापक जन-आन्दोलन हुआ। तदुपरान्त 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद भारत में आतंकवादी हिंसा घातक ढंग से बढ़ती। इसकी परिणति श्रीमती गांधी की हत्या में हुई। श्रीलंका में तमिलों का अक्षन्धोष बड़े पैमाने पर नष्ट जा रहे यह-मुड में बदल गया, जिसमें बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप निरन्तर दृष्टिगोचर होता रहा है। छुट्टुट ही सही, नेपाल में भी आतंकवादी बन बिस्फोट हुए। कुल मिलाकर भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, श्रीलंका सभी दक्षिण एसियाई देश (भूटान व मानदोब को छोड़कर) आन्तरिक राजनीति के दबावों में इतना झुल रहे कि क्षेत्रीय सहकार-संगठन की बात शृष्ठभूमि में चली गयी।

साकं की संगठन के रूप में विधिवत स्थापना—7 दिसम्बर, 1985 तक भारतीय उप-महाद्वीप में राजनीतिक व सामाजिक उथल-पुथल के बाद इतनी स्थिरता आ गई थी कि एक बार फिर क्षेत्रीय सहकार को संपुर्ण संरचनात्मक ढांचा देने की बात सोची जा सकती थी। जैसाकि तब पत्रकारों ने टिप्पणी की—इन चार-पाँच वर्षों में एक बरफपट परिवर्तना-अवधारणा मसार्थ में बदल चुकी थी। डाका में मने ही साकं का जन्म हुआ हो, परन्तु कुछ कर सकने की क्षमता उसे बंगलौर में ही प्राप्त हुई। इस समय तक राजनय-चार की अनेक ऐसी औपचारिकताएँ पूरी कर ली गयीं, जो आगे चलकर विवादस्पद बन सकती थी और किसी तरह की अहिंसा पंदा कर सकती थी। बंगलौर में तय किया गया कि साकं का मुख्यालय

काठमांडू (नेपाल) में होगा और इसका पहला अध्यक्ष बंगला देश द्वारा मनोनीत व्यक्ति होगा। तदुपरान्त बर्णानुक्रमानुसार बारी-बारी से इस पद पर अन्य सदस्यों द्वारा मनोनीत व्यक्ति दो वर्ष तक कार्य करेगा।

यह सोचना अनुचित नहीं कि निकट भविष्य में सचिवालय स्वयं किसी खर्चीले कार्यक्रम को नहीं उठायेगा, बल्कि जैसाकि नई दिल्ली में अगस्त, 1983 में सार्क विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में तय किया गया कि सचिवालय विभिन्न देशों के विकास कार्यक्रमों में सहकार और बेहतर समायोजन का ही प्रयत्न करेगा।

सहयोग क्षेत्रों का निर्धारण (Areas of Cooperation)

अगस्त, 1983 में ऐसे नौ क्षेत्र रेखांकित किये गये थे—कृषि, स्वास्थ्य सेवाएँ, मीम विज्ञान, डाक-तार सेवाएँ, ग्रामीण विकास, विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी, दूर-संचार तथा यातायात, खेलकूद तथा सांस्कृतिक। ठाका में दो वर्ष बाद इस सूची में कुछ और विषय जोड़ दिये गये—आनकवाद की समस्या, मादक द्रव्यों की तस्करी तथा क्षेत्रीय विज्ञान में महिलाओं की भूमिका। महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्य-सूची में विषय जोड़ने या घटाने से कोई अन्तर नहीं पड़ता, जैसा कि नवम्बर, 1986 में आयोजित बंगालीर शिखर सम्मेलन में स्पष्ट हुआ। आतंकवाद की परिभाषा तक सर्वसम्मति से तय नहीं हो सकी। श्रीलंका इसके माध्यम से भारत को सकोच में डालना चाहता था। इस बात को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता था कि प्रभाकरण और जयवर्द्धने में सीधी वार्ताएँ करने के प्रयत्न क्षेत्रीय सहकार की तमाम अन्य योजनाओं के ऊपर हावी हो गये।

दक्षिण एशिया में तनावग्रस्त माहौल (Tension in South Asia)

जितनी प्रगति दिसम्बर, 1985 से नवम्बर 1986 तक हुई थी, उससे कहीं ज्यादा विवाद 1987 में भारत-पाक, भारत-श्रीलंका और भारत-बंगला देश सम्बन्धों में हुआ। जहाँ एक ओर बहुपक्षीय साम का आर्थिक तर्क आज भी बरकरार है, वहीं पाकिस्तानी परमाणु बम, नदी जल-विवाद और तामिल सकट को लेकर सहकार के मार्ग में बड़ी-बड़ी बाधाएँ गढ़ावन् बनी हुई हैं। ऐसी स्थिति में इस आगावादिता का कोई कारण नहीं कि नई अन्तर्राष्ट्रीय अव्यवस्था और तकनीकी सहकार के क्षेत्र में सार्क के माध्यम से वांछित प्रगति हो सकेगी।

दक्षिण एशिया में भारत के तमाम पड़ोसियों के साथ सम्बन्ध पिछले दशक वर्षों में निरन्तर तनावग्रस्त हुए हैं। पहले गिफें पाकिस्तान के साथ कश्मीर विवाद था, जो क्षेत्रीय सहकार के मार्ग में बड़ी बाधा था, या पाकिस्तान को दी जाने वाली अमरीकी सैनिक सहायता थी, जिनके परिणामस्वरूप भारतीय उप-महाद्वीप में ग्रीन युद्ध का प्रवेश हुआ। परन्तु आज इस तरह की कटुता और विवाद बंगला देश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान आदि सभी के साथ है। न्यू दूर द्वीपसमूह, परक्का जलवय, चकमा आदिवासी, अमम में बिहारी भूतज घरणापियों का अनधिकृत प्रवेश, मीमा गुरला बन के साथ मुठभेड़ आदि सभी विषय ऐसे हैं, जिनमें वर्षों के सदप्रयत्ना के बावजूद कोई प्रगति नहीं हो सकी है।

जनता सरकार के शासन काल में नेपाल के साथ व्यापार और पारगमन (transit) की अलग-अलग सन्धि पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद यह आशा जगी थी कि मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का निर्वहण आसानी से निरापद रहेगा। परन्तु नेपाली सरकार की यह महत्त्वकांक्षा कि वह भारत तथा चीन को एक-दूसरे के साथ सन्तुलित कर साथ उठाती रहे, कम नहीं हुई। जब पश्चिमी बंगाल में गोरखालैंड की माँग ने सिर उठाया है, तब नेपाली इसरो के बारे में भारत सरकार निश्चित नहीं बैठ सकी। बंगला देश के साथ जन-विवाद का निपटारा हो या अरुणाचल व सिक्किम में प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन, नेपाल ने भारतीय क्रिया-कलाप की जासोचना करने में कोई सकोच नहीं दिखाया। इसके अतिरिक्त समुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा तथा सुरक्षा परिषद में विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर हुए मतदान में नेपाल ने भारत का बहुत कम अवसरों पर साथ दिया है।

इसी तरह भीमका में ताम्रिज समस्या में बिगाड़ के साथ दक्षिण अफ्रीकी और इजराइली भाड़े के सैनिकों के प्रवेश के साथ भारत और श्रीलंका के बीच लगभग बर की स्थिति विकसित हो गयी। स्वयं जयवर्द्धने ने उच्चपदीय समस्याओं का बारबार अन्तर्राष्ट्रीयकरण कर सार्क की भावना को बहुत नुकसान पहुँचाया। यहाँ कहने का अभिप्राय यह कतई नहीं है कि इन सम्बन्धों में भारत का पक्ष न्यायोचित है और छोटे पड़ोसी जान-भूझकर विवाद पैदा करते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ यह द्योत करना है कि चाहे किसी भी कारण जब तक भारत और उसके पड़ोसियों के बीच सामरिक और भू-राजनीतिक विवादों का शान्तिपूर्ण समाधान नहीं हो जाता, तब तक सार्क के उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में कोई प्रगति नहीं की जा सकती, भले ही काठमांडू में मुख्यालय का उद्घाटन हो गया हो। जब तक पाकिस्तान के साथ परमाणु विनाश कार्यक्रम के सम्बन्ध में, बंगला देश के साथ चकमा आदिवासियों के मानवाधिकारों के हलक के विवाद का निपटारा नहीं हो जाता और श्रीलंका में सान्नि नहीं मीटती, तब तक सार्क के सहकारी विकास कार्यक्रम, पशु-पालन, स्वास्थ्य सेवा, तकनीकी सहयोग और मौसम की भविष्यवाणी सम्बन्धी कार्यक्रम सार्क के किसी भी सदस्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं बन सकते। अतएव इस निष्कर्ष तक पहुँचना तर्क-संगत है कि त्रिभुज भविष्य में सार्क दक्षिण एशिया में रचनात्मक सहकार की एक 'मादर्स जवहारणा' के रूप में ही घना रहेगा।

सार्क की अन्य क्षेत्रीय सहयोग संगठनों से तुलना

यदि दक्षिण एशियाई सहकार योजना की तुलना अन्य क्षेत्रीय सहकार परियोजनाओं, आसियान या यूरोपीय सादा बाजार से करे तो अब तक की प्रगति, वर्तमान समस्याएँ और भविष्य की सम्भावना, किसी भी दृष्टि से अब तक का पटनाक्रम अस्वाभाविक नहीं लगता। भौगोलिक सामीप्य और पूरक अर्थव्यवस्थाओं का अस्तित्व अपने आप में क्षेत्रीय सहकार को कुछ बनाने के लिए मधेष्ट कहीं भी नहीं रहा है। सबसे बड़ी जबरजस्ती अभी बात की होती है कि राजनीतिक विवाद के क्षेत्र में तनाव पैदाया जा सके और अन्तर्राष्ट्रीय परिघेद में सामानता लायी जा सके। इस बात को बन्देबा करता कठिन है कि यूरोपीय सादा बाजार और आसियान में से कोई भी संगठन अपने पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता। यूरोप में यूरोपीय आर्थिक समुदाय का प्रतिद्वन्द्वी कोमेकोन है तो दक्षिण पूर्व एशिया में

आसियान का मुद्रावला हिन्द चीन के देशों से है, जबकि पूरव अर्थव्यवस्थाओं का तत्वं इन पर भी लागू होता है। दक्षिण एसियाई सहकार भी भारत-याक सम्बन्धों के सामान्यीकरण या इनमें तनाव पर टिका हुआ है। अफगान घटना-क्रम के बाद अमरीका से बड़े पैमाने पर सैनिक सहायता ग्रहण कर पाकिस्तान का आत्म-विश्वास इस सीमा तक बढ़ा कि भारत को सन्तुलित करने के लिए रचनात्मक सहकार की कोई जरूरत उस महसूस नहीं होती।

सार्क का मूल्यांकन (Assessment of SAARC)

यह झोहराने की जरूरत है कि सार्क की धीमी प्रगति के लिए पक्षीमियों पर दोषारोपण का कोई अभिप्राय हमारा नहीं। स्वयं भारत में श्रीमती गांधी की हत्या के बाद आन्तरिक राजनीति इतनी उपल-पुल्ल वाली रही है कि शान्ति और मुख्यवस्था का प्रश्न और पड़्यन्त्रकारी बाहरी हस्तक्षेप का संकट क्षेत्रीय सहकार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बन गये हैं। कमोवेश यही स्थिति पाकिस्तान और श्रीलंका पर भी लागू होती है। भूटान और मानसीव भले ही इस चिन्ता से मुक्त हैं परन्तु उनकी भूमिका इन परियोजना में अपेक्षाकृत गौण और सहायता-अनुदान के ग्राहक वाली है। ऐसा जान पड़ता है कि इन परिस्थितियों में जो कुछ भी प्रगति हुई है, चाहे कितनी ही शिथिल रही हो, उसे ही बड़ी उपलब्धि मना जाना चाहिए। यह स्मरणीय है कि 'आसियान' की प्रस्तावना 1967 में किये जाने के बाद पहला वित्तर सम्मेलन 1976 में ही आयोजित किया जा सका था और यूरोपीय साम्राज्य बाजार का स्वरूप तथा संगठन भी श्रीगणेश के दस वर्ष बाद ही तय हो पाया था। भारत की दृष्टि में यही सन्तोष का विषय समझा जाना चाहिए कि 'सार्क' के बढ़ाने इस क्षेत्र में कम से कम बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप के विरुद्ध जनमत तैयार किया जाना सम्भव हुआ है। वगला देश, नेपाल और पाकिस्तान में दीर्घकाल तक प्रतिनिधि जनमत नहीं रहा और श्रीलंका में लगभग आपातकाल की स्थिति बनी रही। ऐसी स्थिति में जनमत सार्क विषयक नीति निर्धारण को जामानी से प्रभावित नहीं कर सकता। यह जरूर है कि सार्क के कार्यक्रमों के अन्तर्गत उच्च-पदस्थ विशेषज्ञों तथा सरकारी अधिकारियों की नियमित बैठकों में परोक्ष रूप से ही नहीं, बरिष्प में सार्वक तत्त्वोंकी आर्थिक सहयोग का ढांचा तैयार होने लगा है।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय (European Economic Community or E. E. C)

यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय साम्राज्य बाजार आदि नामों से जिन क्षेत्रीय सहकार योजनाओं-संगठनों का सूत्रपात हुआ, उन्हीं के साथ युद्धोत्तर काल में क्षेत्रीय एकीकरण की प्रवृत्ति में जोर पकड़ा। क्षेत्रीय सहकार का सबसे परिष्कृत रूप यूरोपीय आर्थिक समुदाय में देखने को मिलता है। इस अवस्था को अनेक नामों से जाना जाता है, परन्तु यूरोपीय आर्थिक समुदाय का प्रयोग ही सबसे उचित है, क्योंकि 1 जनवरी, 1958 की सन्धि द्वारा स्थापित मस्या का यही अधिकारिक नाम है। यूरोपीय साम्राज्य बाजार इसके अन्तर्गत आर्थिक सहयोग की एक विशेष व्यवस्था है और यूरोपीय मुक्त व्यापार मण्डल, यूरोपीय परिषद, यूरोपीय कायला तथा इस्पात समुदाय,

आर्थिक सहयोग एवं विकास समझन (O. E. C. D.) जैसी अनेक संरचनाएँ आज यूरोपीय आर्थिक समुदाय की छतरी के नीचे आ चुकी हैं और अपने जियाऊलापों द्वारा, क्षेत्रीय सहयोग द्वारा संगठन को पुष्ट करती हैं।

यूरोप का आर्थिक पुनर्निर्माण (Economic Reconstruction of Europe)

विश्वी दो सदियों में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में यूरोपीय शक्तियों का प्रभुत्व रहा। द्वितीय विश्व युद्ध ने इस स्थिति को नाटकीय ढंग से बदल दिया। औपनिवेशिक शक्तियों का सूर्य अस्त हुआ और विजेता तथा पराजित दोनों पक्षों के यूरोपीय देश, फ्रांस तथा जर्मनी ध्वस्त तथा पस्त बने रहे। अमरीकियों ने आर्थिक ह्रास और सामाजिक असन्तोष को संबंधीय स्थिति को अपने हितों के लिए जोखिम मरा नमस्ते और यह तर्कसंगत भी था। मने ही इस समय तक गरमागु अरुनो पर अमरीका का एकाधिकार था, परन्तु सोवियत लाल सेना का अधिपत्य यूरोप में अन्तर्देश नहीं किया जा सकता था। आतंक का सन्तुलन उभरने लगा था, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं हुआ था। इसलिए साम्यवाद की विस्तारवादी चुनौती का सामना यूरोप के आर्थिक पुनर्निर्माण और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के द्वारा ही किया जा सकता था।

युद्ध समाप्ति के तत्काल बाद चर्चिल ने स्थायी शांति के हित में यूरोपीय एकता का स्वर सुन्नर किया। अमरीकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने उनका अनुसरण करते हुए यूरोप के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक और वित्तीय सहायता का प्रस्ताव रखा। भागे चलकर यह प्रस्ताव ट्रूमैन सिद्धान्त के नाम से विख्यात हुआ। इस दिशा में अगला और सबसे महत्वपूर्ण कदम अमरीकी विदेश सचिव जार्ज मार्शल ने उठाया। उन्होंने 5 जून, 1947 को हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दिये गये अपने प्रसिद्ध भाषण में यूरोप के आर्थिक पुनर्निर्माण का स्पष्ट कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस योजना के अन्तर्गत 1948 से 1952 के चार वर्षों में अमरीका ने यूरोप के 16 देशों को 20 अरब डॉलर की सहायता दी। निश्चय ही मार्शल योजना ने यूरोपीय क्षेत्रीय सहकार को बहुत मही ढंग से प्रोत्साहित किया और जड़ता तोड़कर यथास्थिति बदलने के लिए आवश्यक सहायन जुटाये।

यूरोपीय एकता की अवधारणा सदियों पुरानी

यह समझना गलत है कि यूरोप में क्षेत्रीय सहकार की प्रक्रिया बाहरी (अमरीकी) प्रेरणा पर आधारित थी। असल में यूरोपीय एकता की अवधारणा सदियों पुरानी है। पवित्र रोमन साम्राज्य और सम्राट शार्लेमा के जमाने से यूरोप की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक एकता सर्वसम्मत रही है। यूरोपीय शक्ति-सन्तुलन के रहते यूरोप की छोटी-बड़ी किसी भी शक्ति को अपनी स्वतन्त्रता गँवानी नहीं पड़ी। औपनिवेशिक ताकतों ने जिस तरह अफ्रीका और एशिया में दासन के लिए जान-बूझकर विभाजक नीतियाँ लागू की, वैसे पद्धतियों के दुष्प्रभाव से भी यूरोप बचा रहा। इसे भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि इंग्लैंड को छोड़कर फ्रांस तो सैकड़ कम तक, स्केन्डिनेवियायी देशों से लेकर इटली तक यूरोपीय महाद्वीप का 'हृदय स्थल' भौगोलिक दरावरों-बाधाओं से मुक्त है। 19वीं शताब्दी में औद्योगिकरण के विकास

के माध्यम उत्सादन और विनरण का एक ऐसा ताना-बाना बुना जा चुका था, जिमने आर्थिक एवं राजनीतिक त्रियाकलाप की किसी भी एक राष्ट्र की सरहद के पार फैला दिया था। विडम्बना तो यह है कि जिस मार्क्सवादी-माम्मवादी चुनौती का सामना करने के लिए 1947-48 में क्षेत्रीय सहकार की रूपरेखा तैयार की जा रही थी उसी विचारधारा के प्रसार ने अन्तर्राष्ट्रीय, विशेषकर यूरोपीय, एकता को रेतखिन्त किया।

यहाँ एक और बात जोड़ने की जरूरत है। नाजीवाद और फासीवाद की निर्णायक पराजय ने विजेता और पराजित दोनों ही राष्ट्रों को शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार 1914 से 1935 का अन्तराल एक अपवाद था और यह यूरोपीय एकीकरण के लिए व्यवधान डालने वाला सिद्ध हुआ। 1947 से 1958 में एक अनावश्यक अन्तराल के बाद यूरोप में क्षेत्रीय सहकार की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गयी।

ई० ई० सी० का गठन (Formation)

मांसन योजना के त्रियान्वयन के माध्यम-माध्य तकनीकी एवं वैज्ञानिक क्षेत्र में सहयोग कार्यक्रम आरम्भ हुए, जिनमें 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना, 1952 में यूरोपीय कोयला एवं इस्पात समुदाय का गठन, 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन का दिगान्वास, 1950 में यूरोपीय अदायगी मण आदि का निर्माण उल्लेखनीय हैं। इन सभी ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय के कार्यक्षेत्र को बढ़ाया और इनके त्रियाकलापों को आर्थिक दृष्टि से और भी अधिक प्रभावशाली बनाया। गठन के वक्त यूरोपीय आर्थिक समुदाय में सम्मिलित जनसंख्या 18 76 करोड़ थी और उसका क्षेत्रफल 457 7 हजार वर्गमील था। सदस्य राष्ट्रों की कुल राष्ट्रीय आय 16 47 करोड़ डालर थी। किसी भी पैमाने पर इन अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की उपस्थिति को अनदेखा नहीं किया जा सकता था। इस समय यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य देशों की संख्या 12 है।

ई० ई० सी० के उद्देश्य (Objectives)

यूरोपीय आर्थिक समुदाय मण के अनुच्छेद दो में इन संगठन के पाँच उद्देश्यों का जिक्र है। ये उद्देश्य हैं—(i) यूरोप को विभाजित करने वाले विवादों को हमेशा के लिए समाप्त करना, (ii) यूरोप की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करना तथा आर्थिक शक्ति और सांस्कृतिक परम्परा के अनुकूल भूमिका का निर्वाह करना, (iii) समुक्त कार्रवाई द्वारा यूरोपीय जनता की कार्यक्षेत्रीय एवं जीवन स्तर के स्तर में सुधार करना; (iv) यूरोप की छोटे-छोटे बाजारों में बाँटने वाले व्यवधानों का अन्त करना, और (v) बड़े पैमाने पर सामग्रद औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहन तथा मविष्य में यूरोप के समुक्त राष्ट्रों के एकीकरण का आधार प्रस्तुत करने के प्रयत्न करना।

अनुच्छेद तीन और चार में इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रस्तावित त्रियाकलाप तथा संगठन, महामन्त्रि, परिषद्, आयोग तथा न्याय मन्त्र आदि का व्योरा दिया गया है। इस प्रकार 'आदर्श' और 'माम्मव' के बीच सन्तुलन बिठाने का प्रयत्न किया गया। ई० ई० सी० की प्रगति-मपनना के बारे में विचार करने समय यह बात नहीं भुलायी जा सकती कि प्रस्तावना से योजना के मूर्त रूप ग्रहण

करने तक लगभग एक दशक बीच चुका था। अन्यत्र जहाँ क्षेत्रीय सहकार की जमीन पहले से इतनी अच्छी तरह तैयार न हो, क्षेत्रीय सहकार से अपरुद्ध होना बड़ी चिन्ता का विषय नहीं समझा जाना चाहिये। साथ ही यह भी स्मरणीय है कि आर्थिक समुदाय के सभी सदस्य राष्ट्रों का सामरिक परिदृश्य एक-सा था। इसी कारण आर्थिक एवं सामरिक तर्कों के संयोग के कारण यूरोप में क्षेत्रीय सहकार की प्रगति आसानी से रही।

संगठन की उपलब्धियाँ (Achievements)

यूरोप में क्षेत्रीय एकीकरण और सहकार में प्रगति के साथ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसके रचनात्मक प्रभाव स्पष्ट देखे जा सकते हैं। 1 जनवरी, 1973 से डेनमार्क, ग्रीस, आयरलैण्ड तथा इंग्लैंड भी ई० ई० सी० के सदस्य हो गये और आज इस संगठन के देशों की आबादी अमरीका या सोवियत संघ की जनसंख्या से अधिक है। अधिकतर देश सम्पन्न एवं विकसित हैं और बड़े हुए आर्थिक सहकार के साथ इनकी आर्थिक दशा में और भी सुधार हुआ है। फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों में प्रति व्यक्ति आय में तीन-चार गुणा वृद्धि हुई और वास्तविक मजदूरी में यह वृद्धि 75 से लेकर 109 प्रतिशत रही। 1958 में ई० ई० सी० देशों का विश्व व्यापार में आयात में हिस्सा 22.3 प्रतिशत था, जो 1975 तक बढ़कर 37 प्रतिशत हो गया। निर्यात में यह भाग 23.9 से बढ़कर 37.5 प्रतिशत पहुँच गया। संगठन आन्तरिक व्यापार कर भार से मुक्त है। श्रम, पूँजी और सेवाओं की गतिशीलता में वृद्धि हुई है। कल के शत्रु फ्रांस और जर्मनी आज मित्र ही नहीं, बल्कि सहयोगी भी बन चुके हैं। गले ही ई० ई० सी० आज एक महाशक्ति न हो, तब भी इसकी भलाग पहचान बन चुकी है—लातकर सामरिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में। पिछले कुछ वर्षों में अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस संगठन की नीतियाँ सदस्य राष्ट्रों के सामूहिक हितों को देखते हुए सन्धि मित्र अमरीका से फर्क रही हैं। बाज यह नहीं कहा जा सकता कि साम्यवाद के मुकाबले के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय एकीकरण की जिस तरह प्रोत्साहित किया गया, उसका विकास सैनिक संगठन नाटो के सहयोगी अनुचर के रूप में हुआ। सोवियत संघ से आयात की जाने वाली गैस, यूरोपीय भूमि में क्रूज मिसाइलों की तैनाती तथा यूरोपीय अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रभुत्व को लेकर ई० ई० सी० के देशों में मतभेद सामने आते रहे हैं। इसके अतिरिक्त विनाशशील देशों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता के 'परिणाम' को लेकर भी अमरीका और ई० ई० सी० के देशों में हमेशा मतभेद नहीं रहा है। दक्षिण अफ्रीका को समस्या, आणकवाद, पर्यावरण, मध्यपूर्व तेल संकट आदि अन्य विषय हैं, जिन पर यूरोपीय प्रतिनिध्या-नीतियाँ ई० ई० सी० से प्रस्तावित और अनुमोदित हुई हैं।

संगठन का विभाजक प्रभाव

इनस क्लॉड जैसे अनेक विद्वानों ने यह बात मुखरपी है कि क्षेत्रीय सहकार के जरिए व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय सहकार को नीव रखी जा सकती है, परन्तु यूरोपीय आर्थिक समुदाय के अनुभव से यह पता चलता है कि इसके विभाजक प्रभाव भी हो सकते हैं। ई० ई० सी० की प्रगति से सोवियत संघ चौकन्ना हुआ और उसने

‘कोमेकोन’ की स्थापना तत्परता के साथ की। यहाँ ‘कोमेकोन’ और ई० ई० सी० की सफलता-असफलता का तुलनात्मक अध्ययन बिना यह कहा जा सकता है कि यूरोप का पूर्व और पश्चिम में बँटवारा इन दो क्षेत्रीय संगठनों ने पक्का किया। शायद इनके अभाव में हैलसिंकी समझौता इतनी आसानी से न हो पाता। इसके अतिरिक्त लगभग हर प्रमुख यूरोपीय शक्ति ने अपने पुराने उपनिवेशों के साथ विरोध आर्थिक सम्बन्ध आज़ादी के बाद भी बने आ रहे थे। इस सिमसिते में ‘कोमनवेल्थ प्रीफरेंसेज’ तथा फ्रेंच भाषी अफ्रीका के साथ फ्रांस के सम्बन्धों का उल्लेख किया जा सकता है। यूरोपीय एकीकरण और क्षेत्रीय सहकार में वृद्धि के साथ पुरानी चली आ रही ये व्यवस्थाएँ बेमानी मिट हो गयीं। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि आपस में कर-भार घटाने व साथ बाहरी दुनिया के साथ सरसपात्मक आर्थिक नीतियाँ अपनाने का अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? इस तथ्य की भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि ई० ई० सी० मुख्यतः समृद्ध, विकसित व सांस्कृतिक दृष्टि से एकलप देशों का क्लब है। साम्यवादी सामरिक धुनीनी हो या अपेक्षाकृत अधिक समर्थ अमरीका के साथ परामर्श में अपने हित-रक्षण की समस्या, इस संगठन के सदस्य राष्ट्रों में मतभेद आसान है। अफ्रीका, एशिया तथा सातीनी अमरीका के अन्य देशों में जहाँ समृद्धि ही नहीं, विपन्नता का वातावरण भी विपन्नता बढ़ाने वाला है और हस्तक्षेप न करने के विषय में महाशक्तियों की कोई सहमति नहीं, वहाँ क्षेत्रीय सहकार का पथ इतना मुश्किल नहीं हो सकता।

ई० ई० सी० का मूल्यांकन (Assessment)

1950 के दशक के मध्य से 1960 के दशक के मध्य तक जब यूरोपीय एकीकरण व क्षेत्रीय सहकार का घटनाक्रम निर्णायक ढंग से गतिशील था, तब फ्रांस और जर्मनी में देगोल, आडिनआवर, विली ब्राट जैसे लोगों के हाथ में सत्ता रहने से इस प्रक्रिया को बड़ी मदद मिली। जहाँ देगोल ने महाशक्ति अमरीका के सामने न झुकने के तैवर अपनाकर प्रतीकात्मक ढंग से पूरे यूरोप की गरिमा को पुनः प्रतिष्ठित किया, वहीं विली ब्राट जैसे राजपुरुष सोविमत् नेताओं को यह आश्वासन देने में समर्थ हुए कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय आक्रमक या प्रच्छन्न सामरिक संगठन नहीं है। इन नेताओं की अनुपस्थिति में फ्रांस और जर्मनी जैसे शत्रुओं का मित्र के रूप में परिवर्तन कठिन बना रहता। ऐसा नहीं कि सहकार का मार्ग निष्कटक ही रहा। ई० ई० सी० में ब्रिटेन की मददगारता को लेकर वर्षों बटु विवाद चलता रहा और आज भी तुर्की जैसे सदस्यों को समानता का दर्जा अवसर नहीं मिल पाता। क्षेत्रीय सहकार के साथ के अलावा ई० ई० सी० ने यूरोपीय राष्ट्रों की सम्प्रभुता को ‘क्षीण’ कर आपसी संधि की सम्भावना को कम किया है। यूरोपीय परिपद हो या न्याय मन्त्रालय, विवादों के निपटारे (विशेषकर मानवाधिकारों व प्रमग में) के विषय में ई० ई० सी० की सफलता समुक्त राष्ट्र मण से बड़ी अधिक रही है।¹ इस प्रकार ‘राजनयिक’ तथा ‘आर्थिक’ दोनों तरह के तर्क ई० ई० सी० के पक्ष में

¹ ई० ई० सी० के विस्तृत अध्ययन विमेष के लिए देखें—K B Lal, Wolfgang Earnest and H S Chopra, (ed) *The E E C and the Global System* (Delhi, 1984)

रहे हैं। यह सोमाख्यपूर्ण मयोग अब तक तोमरी दुनिया मे देखने को नही मिला है।

राष्ट्र सघ तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रादेशिक व्यवस्थाएँ

विश्व शान्ति, सुरक्षा तथा राष्ट्रों मे आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए फ़रस 1919 एव 1945 मे स्थापित राष्ट्र सघ (League of Nations) तथा संयुक्त राष्ट्र सघ (U.N.O.) दोनों अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों मे प्रादेशिक व्यवस्थाएँ की गयी। इनके अन्तर्गत किन्ही निश्चित शर्तों पर सदस्य राष्ट्रों को प्रादेशिक संगठनों के निर्माण की इजाजत दी गई। उग्र श्रेववाद तथा कतिपय अन्य कारणों से राष्ट्र सघ असफर रहा और द्वितीय विश्व युद्ध छिट गया। इस महायुद्ध की समाप्ति के पश्चात् जब 1945 मे संयुक्त राष्ट्र सघ के निर्माण की बात बनी तो इसके चार्टर में प्रादेशिक व्यवस्थाओं का उल्लेख करते समय अत्यन्त सावधानी बरती गयी।

संयुक्त राष्ट्र सघ मे प्रादेशिक व्यवस्थाएँ रखने के कारण

यहाँ यह प्रश्न भी विचारणीय है कि जब राष्ट्र सघ की असफलता के पीछे उग्र श्रेववाद प्रमुख कारण था तो संयुक्त राष्ट्र सघ की स्थापना करते समय चार्टर मे प्रादेशिक संगठनों की बनाने की व्यवस्थाएँ क्यों रखी गयी? इसका सीधा-सादा उत्तर यह हो सकता है कि प्रादेशिकवाद नहीं, बल्कि उग्र प्रादेशिकवाद खतरनाक है। द्वितीय विश्व युद्ध के भडकने और राष्ट्र सघ की असफलता के पीछे उग्र प्रादेशिकवाद एक प्रमुख कारण था, सबसे प्रमुख कारण नहीं। संक्षेप मे, संयुक्त राष्ट्र सघ चार्टर में प्रादेशिक संगठनों को मान्यता देने के निम्नांकित कारण थे।

(i) श्रेयोय सहयोग स्थापित करने में कोई बुराई नहीं—संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माताओं ने सोचा कि यदि चार्टर के प्रयोजनों और उद्देश्यों के अनुकूल बने प्रादेशिक संगठन श्रेयोय सहयोग से स्थापित करें तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी। संयुक्त राष्ट्र सघ का प्राक्ष तैयार करते समय ब्रिटेन जैसी महत्वपूर्ण विश्व-शक्ति के प्रधान मंत्री विसटन चर्चिल ने यह सुझाव दिया कि अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के सफल संचालन के लिए तीन प्रादेशिक परिपदें होनी चाहिए। यह पश्चिमी गोलार्ध, यूरोप तथा एशियाई परिपदें होती जो विश्व परिपद के अन्तर्गत कार्य करती। इनमे अमरीका, ब्रिटेन, सांविषत सघ और सम्भवतः चीन की रचामी स्थान प्राप्त होते। इनके अलावा अन्य सदस्य देश इन तीनों परिपदों से चुन लिये जाते। इस योजना को तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट का समर्थन प्राप्त होने पर भी अन्य देशों ने इसे नहीं स्वीकारा। किन्तु इस प्रस्तावित योजना का बुरगामी प्रभाव यह पड़ा कि संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर में प्रादेशिक संगठनों के निर्माण की छूट एवं इजाजत दे दी गयी।

(ii) अमरीका तथा सातवीं अमरीकी राज्यों द्वारा अपनी भूमिका विनिष्ट मानना—अमरीका और सातवीं अमरीकी राज्य पश्चिमी गोलार्ध की समस्याओं के हल में अपनी भूमिका विनिष्ट एवं निर्णायक मानते थे। इसने संयुक्त राष्ट्र सघ चार्टर मे प्रादेशिक संगठनों के निर्माण की इजाजत का मार्ग प्रगस्त किया।

(iii) सुरक्षा परिषद की असफलता की स्थिति में प्रादेशिक संगठनों द्वारा सामूहिक सुरक्षा का बिबलप—फ्रान्स, जर्मनी द्वारा आक्रमण करने के सम्भावित खतरे

से मयमोन था। इस कारण वह चाहता था कि सुरक्षा परिषद द्वारा आक्रमणकारी राष्ट्र के विरुद्ध उचित कार्रवाई न करने पर या इससे पहले प्रादेशिक मण्डल में उसका मुकाबला किया जा सके। फ्रांस ही नहीं, बल्कि अन्य अनेक छोटे-बड़े राष्ट्रों ने इसकी आवश्यकता महसूस की।

मयुक्त राष्ट्र सभ चार्टर में प्रादेशिक व्यवस्थाएँ

मयुक्त राष्ट्र सभ चार्टर के आठवें अध्याय में अनुच्छेद 51 में लगाकर 54 तक प्रादेशिक व्यवस्थाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। इनमें प्रमुख रूप से निम्नांकित प्रादेशिक व्यवस्थाएँ हैं।

(i) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा सम्बन्धी मामलों को तय करने वाली प्रादेशिक कार्रवाई के लिए जो उपयुक्त प्रबन्ध एवं साधन इस समय हैं, यदि वे प्रबन्ध और समस्याएँ तथा उनके कार्य मयुक्त राष्ट्र सभ के प्रयोगनों और मिष्ठान्तों के अनुकूल हैं तो उनके रहने में वर्तमान चार्टर के संचालन में कोई बाधा नहीं पड़ेगी;

(ii) मयुक्त राष्ट्र सभ के सदस्य यदि ऐसी समस्याओं के सदस्य हैं और उन्होंने ऐसे प्रबन्ध किए हैं तो स्थानीय विवादों को सुरक्षा परिषद के सामने ले जाने से पूर्व इन समस्याओं का समाधान पहले इन्हीं प्रादेशिक समस्याओं या प्रबन्धों के जरिये शान्तिपूर्ण ढंग से करने का प्रयत्न किया जायेगा,

(iii) सुरक्षा परिषद इस बात को प्रोत्साहन देती कि या तो सम्बद्ध राज्यों की प्रेरणा पर अथवा सुरक्षा परिषद से सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय विवादों का प्रादेशिक प्रबन्धों अथवा प्रादेशिक अधिकरणों के माध्यम से शान्तिपूर्ण ढंग से निपटारा किया जाये,

(iv) परन्तु अनुच्छेद 52 के दूसरे पैराग्राफ में बताया किमी शत्रु राष्ट्र के विनाश अनुच्छेद 107 के अनुसार कार्रवाई की जा रही हो, तो इस प्रकार अधिकार पाले की आवश्यकता तब तक नहीं होगी, जब तक कि उस मामले से सम्बन्ध रखने वाली सरकारों की प्रार्थना पर मयुक्त राष्ट्र सभ को उस विशेष आक्रमणकारी राष्ट्र का और आगे आक्रमण करने में रहने का उत्तरदायित्व न दे दिया जाये,

(v) इन प्रादेशिक समस्याओं और प्रबन्धों के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने की जा भी कार्रवाई की गयी या की जाने वाली कार्रवाई होगी, उसकी सूचना सभी अवसरों पर सुरक्षा परिषद को दी जायेगी,

(vi) यदि किसी विवाद में विश्व शान्ति और सुरक्षा को खतरा हो तो दोनों विवादी पक्ष अन्य शान्तिपूर्ण साधनों के साथ-साथ प्रादेशिक समस्याओं का महाराज ले सकते हैं, और

(vii) आत्म-रक्षा के अधिकार के अन्तर्गत मजबूत आक्रमण को रोकने के लिए प्रत्येक राष्ट्र सभी उपायों का आश्रय तब तक ले सकते हैं, जब तक कि सुरक्षा परिषद अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के लिए स्वयं कोई कार्यवाही न करे।

प्रादेशिक मण्डल मयुक्त राष्ट्र सभ का अवमूखन

चार्टर में प्रादेशिक मण्डलों के निर्माण की इजाजत यह मानकर दी गयी थी कि वे मयुक्त राष्ट्र सभ के उद्देश्यों एवं प्रयोगनों में कोई बाधा नहीं डालेंगे। यही नहीं, बल्कि वे विश्व शान्ति, सुरक्षा तथा राष्ट्रों में आपसी सहयोग स्थापित

करने में संयुक्त राष्ट्र सभ की पूरक संस्थाओं के रूप में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। समार के लोग क्रमशः विभिन्न राष्ट्रों, राष्ट्र विभिन्न प्रादेशिक संगठनों तथा प्रादेशिक संगठन एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में 'एफा' स्थापित कर 'यसुधैव कुटुम्बकम्' की उक्ति चरितार्थ करेंगे और संयुक्त राष्ट्र सभ इस उक्ति का सबसे आदर्श प्रतीक होगा।

लेकिन वेद की बात है कि संयुक्त राष्ट्र सभ के निर्माताओं द्वारा प्रादेशिक व्यवस्थाओं के बारे में सोचे गये उद्देश्यों और प्रयोजनों पर कालान्तर में असफलता ही हाथ लगी। संयुक्त राष्ट्र सभ की स्थापना के कुछ समय पश्चात् विद्वद्व अमरीकी और सोवियत सभ के नेतृत्व में क्रमशः पूँजीवादी और साम्यवादी खेमों में बँट गया। विद्वद्व महाशक्तियों ने संयुक्त राष्ट्र सभ चार्टर में उल्लिखित प्रादेशिक व्यवस्थाओं का महारा लेकर और बहाना बनाकर नाटों, मिष्टों, सेन्टों, बारसा पैक्ट आदि प्रादेशिक संगठनों का निर्माण किया। इन प्रादेशिक संगठनों ने उग्र प्रादेशिकवाद फैलाकर महाशक्तियों की सीत युद्ध की बर्माहट को और तेज कर दिया। छोटे राष्ट्रों ने भी अरब लीग और अफ्रीकी एकाता संगठन बनाये। इन प्रादेशिक संगठनों ने हठधर्मी का रुख अपनाया। परिणामस्वरूप उग्र प्रादेशिकवाद और विश्व के अनेक गुट में विभाजन से संयुक्त राष्ट्र सभ अप्रभावित न रह सका। संयुक्त राष्ट्र सभ में शक्ति-संतुलन का खेल खेला जाने लगा। इससे इन अन्तर्राष्ट्रीय संगठन को अपने घोषित उद्देश्यों और प्रयोजनों में अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी।

प्रादेशिक व्यवस्थाओं के कारण संयुक्त राष्ट्र सभ को पहुँचे नुकसान को कुछ उदाहरणों से स्पष्ट करना उपयोगी होगा। मसलन, सोवियत सभ द्वारा 1956 में हंगरी तथा 1968 में चेकोस्लोवाकिया में मैनिक हस्तक्षेप, बारसा पैक्ट जैसे प्रादेशिक संगठन की व्यवस्था का सन्तारा एव बहाना लेकर किया गया। संयुक्त राष्ट्र सभ में जब इस पर विचार हुआ तो बारसा पैक्ट से जुड़े पूर्वी यूरोपीय साम्यवादी देशों ने पक्षपातपूर्ण तरीके से सोवियत कार्रवाई का पूरा समर्थन किया। दूसरी तरफ बारसा पैक्ट का विरोधी नाटो नामक प्रादेशिक संगठन से जुड़े पश्चिमी देशों ने आवश्यकता से अधिक सोवियत सैनिक हस्तक्षेप का हौवा लड़ा किया और वे इस मामले को लम्बे समय तक उछालते रहे। मरुका परिपद 'वीटो' के कारण जड़वत हो गयी। सोवियत सभ, बारसा देशों के समर्थन के कारण अडिग रहा और अमरीका नाटो देशों के समर्थन के कारण उमका मात्र मौखिक विरोध करता रहा। परिणामस्वरूप हंगरी और चेकोस्लोवाकिया जैसे राज्यों का समाधान नहीं हो सका।

दूसरा उदाहरण सिष्टो और सेन्टो का है। अमरीका तथा ब्रिटेन द्वारा प्रवर्तित इन प्रादेशिक संगठनों के पाकिस्तान तथा कुछ अन्य एशियाई देश इनके सदस्य बने। पाकिस्तान ने प्रवर्तक राष्ट्रों की महायत्ता से अक्षीभित मात्रा में सन्धीकरण किया और कश्मीर के मामले को लेकर भारत से युद्ध करने का दुस्माह्म कर बैठा। जहाँ पाकिस्तान आन्तरिक राजनीतिक स्थिति से अस्थिर रहा और आर्थिक विकास नहीं कर पाया, वहाँ क्षेत्रीय विकास के बजाय उमने क्षेत्रीय शान्ति को भंग दिया। इसका मुप्रभाव संयुक्त राष्ट्र सभ पर भी पड़ा। वहाँ पाकिस्तान ने मिष्टो और सेन्टो के सदस्यों को लेकर गुटबाजी आरम्भ कर दी। फलस्वरूप भारत-पाक सीमा विवाद का हल अभी तक अधर में लटका हुआ है।

सीमरा, अरब सभ का उदाहरण भी कम दिलचस्प नहीं है। अरब देश

इजराइल के खिलाफ फिलस्तीन राज्य की स्थापना के लिए लम्बे समय से एकजुट होकर सघर्ष करने रहे हैं। लेकिन अरब सघ का नेतृत्व हथियाने के लिए मिस्र और इराक के बीच हमेशा प्रतिद्वन्द्विता रही। 1978 में अमरीकी पहल से मिस्र द्वारा इजराइल के साथ कम्प डेविड समझौता कर लेने के बाद इराक जैसे मिस्र-विरोधी राष्ट्र अरब सघ के सदस्य-राष्ट्रों को मिस्र को संयुक्त राष्ट्र सघ से निकलवाने के लिए उकसाने लग। परिणामस्वरूप जहाँ एक ओर उनमें आपसी फूट के बीज बोये गये, वही संयुक्त राष्ट्र सघ द्वारा फिलस्तीन समस्या के समाधान की दिशा में आगामी प्रयासों की गति को धक्का लगा।

इस प्रकार चार्टर में प्रादेशिक संगठनों की व्यवस्थाएँ, उनको उल्लिखित करने के कारण तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय सक्तों के दौरान इससे पहुँचे मुकाम की विवचना के बाद कहा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र सघ के अवमूल्यन के लिए क्षेत्रीय संगठन काफी हद तक जिम्मेदार रहे हैं।

क्षेत्रीय सैनिक संगठनों की आलोचना

(Criticism of Regional Military Organizations)

आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग स्थापित करने हेतु जिन प्रादेशिक संगठनों की स्थापना की गयी, वे मोटे तौर पर क्षेत्रीय सहयोग स्थापित करने में उपयोगी सिद्ध हुए। किन्तु क्या प्रादेशिक सैनिक संगठन विश्व शान्ति एवं सुरक्षा की स्थापना के मार्ग में बाधक हैं? प्रादेशिक सैनिक संगठनों ने अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा की स्थापना में योगदान देना तो दूर की बात है, उन्होंने अधिकांश अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक सक्तों के दौरान तनाव को बढ़ाने का ही कार्य किया। इन संगठनों की निम्नांकित आधारों पर आलोचना की जा सकती है

(i) संयुक्त राष्ट्र सघ चार्टर में 'क्षेत्रीयता' शब्द का अस्पष्ट उल्लेख—संयुक्त राष्ट्र सघ चार्टर के आठवें अध्याय में अनुच्छेद 52 से 54 तक क्षेत्रीय व्यवस्थाओं के बारे में उल्लेख है। इनमें मुख्य रूप से कहा गया है कि यदि प्रादेशिक संगठन संयुक्त राष्ट्र सघ के प्रयोजनों तथा सिद्धान्तों के अनुरूप हैं तो उनके रहने से वर्तमान चार्टर के संचालन में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। असल में संयुक्त राष्ट्र सघ के अनुच्छेद प्रादेशिकता के स्वरूप और उद्देश्यों के बारे में एकदम स्पष्ट नहीं हैं। इस कारण प्रादेशिक संगठनों का निर्माण करने वाले राष्ट्र इन अस्पष्ट अनुच्छेदों का सहारा लेकर गलत व्याख्या करते हैं।

(ii) सुरक्षा किसी क्षेत्र विशेष की नहीं, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है—यह प्रासंगिक रूप में उचित हो सकता है कि किसी क्षेत्र के समस्या या अधिकांश देश अपनी सुरक्षा के लिए प्रादेशिक संगठनों का निर्माण करें, परन्तु यह भी नहीं भूलना चाहिये कि 'सुरक्षा' एक विश्वव्यापी समस्या है, जो क्षेत्रीय आधार पर नहीं गुनगुनाई जा सकती।¹ यदि अपवाद के तौर पर किसी एक क्षेत्र के देशों में क्षेत्रीय सैनिक संगठनों के ज़रिए सुरक्षा स्थापित हो भी गयी हो, अन्य क्षेत्रों में आप्रवास और तनाव इस अपवादजनक सुरक्षित क्षेत्र को भी चैन में नहीं रहने देंगे।

¹ Charles P. Schlickeher, *Introduction to International Relations* (New York, 1954) 691

अतः क्षेत्रीय सैनिक संगठनों से स्थायी तौर पर न तो क्षेत्रीय सुरक्षा की अपेक्षा की जा सकती है और न ही अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा की।

(iii) प्रादेशिक एवं सैनिक संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के विरुद्ध काम करते हैं—प्रादेशिक एवं सैनिक संगठन व्यवहार में संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के विरुद्ध कार्य करते हैं। मसलन, गिस ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया कि वह इजराईल को भेजे जाने वाले सामान को स्वेज नहर से गुजरने दे। नाटो के सदस्य देशों ने सुरक्षा परिषद में मोरक्को, हिन्द चीन, ट्यूनीशिया, साइप्रस आदि समस्याओं के हल में सदैव रोड़े अटकाये। इस प्रकार विश्व शान्ति एवं सुरक्षा जैसे पुनीत उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों में प्रादेशिक संगठन अनेक बाधाएँ खड़ी करते हैं।

(iv) प्रादेशिक सैनिक संगठनों में आक्रामक व्यवस्थाएँ होती हैं—नाटो, वारसा पैक्ट, सीएटो, सेन्टो आदि नयी सैनिक संगठनों में यह प्रावधान रखा गया है कि उनके किसी भी सदस्य पर अन्य देश द्वारा आक्रमण करने की स्थिति में संगठन के अन्य सदस्य देश उसकी मदद करेंगे। इसकी स्वामाविक तात्त्विक परिणति यही हुई कि वे उस आक्रमण का जवाब 'युद्ध' से ही देंगे। तभी तो इ० बी० द्वारा तथा ए० एस० व्हाइटिंग ने कहा है कि 'तनाव और अविश्वास के वातावरण में एक शत्रु देश (antagonist) के सुरक्षात्मक उपाय हमेशा उसके विरोधी देश को आक्रामक नजर आते हैं।'² अर्थात् तनाव और अविश्वास की स्थिति में क्षेत्रीय सैनिक संगठनों की सुरक्षात्मक व्यवस्थाएँ आक्रामक एवं जवाबी हमले की ओर उन्मुख करती हैं, जिससे विश्व शान्ति और सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है।

(v) क्षेत्रीय सैनिक संगठनों में क्षेत्रातीत व्यवस्थाओं की कोई छुक नहीं—आम तौर पर यह चलील दी जाती है कि क्षेत्रीय संगठन के जरिये उस क्षेत्र विशेष के देशों में आपसी सहयोग स्थापित कर क्षेत्रीय सुरक्षा काममें लयी जाती है। यदि सैद्धान्तिक तौर पर इसे मान लिया जाये तो भी यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि सिएटो और नाटो संगठनों में अन्य क्षेत्र के देशों को सदस्य रखने की क्या छुक है? अमरीका और ब्रिटेन सिएटो के सदस्य बने, जबकि वे एशिया के दक्षिण-पूर्व क्षेत्र से हजारों मील दूरी पर स्थित हैं। इसी तरह यूनायन और टर्की अटलांटिक सागर से हजारों मील दूर होने पर भी नाटो के सदस्य बने। बड़ी शक्तियाँ शक्ति-सन्तुलन के रावच के भीतर राजनीति करती हैं। क्षेत्रीय संगठनों में क्षेत्रातीत व्यवस्थाओं का मकसद नेक नहीं, बल्कि बड़ी शक्तियों द्वारा साठगाँठ और सैनिक घेराबन्दी करना होता है।

(vi) उग्र क्षेत्रवाद अन्तर्राष्ट्रीयता का विरोधी—क्षेत्रीय एवं सैनिक संगठनों के जरिये क्षेत्रीय सहयोग की स्थापना एवं विकास कोई बुरी बात नहीं, किन्तु उग्र क्षेत्रवाद उग्र रूप धारण कर लेता है तो यह अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना के विकास में बाधक सिद्ध होता है। ऐसी अवस्था में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। विश्व शान्ति और सुरक्षा की स्थापना के लिए आवश्यक है कि दुनिया में उग्र क्षेत्रवाद की भावना की जड़ों को उखाड़ दिया जाये। जब तक यह क्षेत्रीय संगठन रहेंगे, तब तक उग्र क्षेत्रवाद की भावना कभी भी खसकती होकर अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की रंग कर देगी। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीयता की खातिर

² E. B. Hass and A. S. Whiting, *Dynamics of International Relations* (New York, 1956), 529.

उप-क्षेत्रवाद को पनपने ही नहीं दिया जाये, अर्थात् क्षेत्रीय संगठनों का निर्माण अव्यावस्थिक है।

(vii) क्षेत्रीय सैनिक समझौतों का उद्देश्य बड़ी शक्तियों द्वारा छोटे देशों पर वर्चस्व जमाना है—बड़ी शक्तियाँ प्रायः आर्थिक एवं सामाजिक महयोग की व्यवस्था के नाम पर प्रादेशिक सैनिक संगठनों का निर्माण करती हैं, मगर उनका वास्तविक इरादा सदस्य देशों पर परोक्ष रूप से वर्चस्व जमाना होता है। सीएटो और सेन्टो पर दृष्टिपात करें तो पायेंगे कि उनके उद्देश्यों में क्षेत्रीय, आर्थिक एवं सामाजिक महयोग की बात ज़रूर कही गयी है, किन्तु व्यवहार में यह नहीं बराबर हुआ है। इनके द्वारा ब्रिटेन ने सदस्य देशों में अपना प्रभाव क्षेत्र बनाये रखा। इसी कारण बाद में सदस्य-देशों ने इनसे अपना नाता तोड़ लिया।

(viii) क्षेत्रीय सैनिक संगठनों द्वारा अस्त्रों की होड़ बढ़ाना—क्षेत्रीय सैनिक संगठन में सुरक्षात्मक स्वरूप का प्रावधान होते हैं। इनका महारा लेकर संगठन के प्रवर्तक राष्ट्र घातक अस्त्र उँडेलते हैं और सदस्य राष्ट्र उन्हें दोनो हाथों से बटोरते हैं। इससे क्षेत्र में शस्त्रीकरण बढ़ता है और क्षेत्रीय शान्ति भंग होती है। इसका दूसरा पक्ष भी अत्यन्त दिलचस्प है। शस्त्रीकरण के कारण गरीब राष्ट्र अपने विकास कार्यक्रमों पर अधिक समाधान खर्च नहीं कर पाते। अतः सैनिक संगठनों से एक ओर जहाँ क्षेत्र के देशों में शस्त्रीकरण की होड़ आरम्भ होती है, वही दूसरी ओर जन-कल्याणकारी विकास कार्यक्रमों की उपेक्षा होती है।

(ix) प्रादेशिक सैनिक संगठनों द्वारा तनाव उत्पन्न कर युद्ध भड़काना—प्रादेशिक सैनिक संगठन क्षेत्र में शस्त्रीकरण को बढ़ाने हैं। शस्त्रों की होड़ तनाव पैदा करती है और अनेक बार यह युद्ध का कारण बन जाती है। मंगोल, पाकिस्तान, मिण्टो और सेन्टो का सदस्य बना। उसने मोचा कि इन संगठनों के जरिये वह प्रवर्तक बड़ी शक्तियों से भारत के विरुद्ध शस्त्र एवं अन्य प्रकार का समर्थन प्राप्त करेगा। हुआ भी यही। पाकिस्तान ने इन सैनिक संगठनों के बलबूने पर प्राप्ति हथियारों से भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़े।

(x) प्रादेशिक सैनिक संगठन के द्वारा सदस्य राष्ट्रों की स्वतन्त्रता और सम्प्रभुता सीमित होना—प्रादेशिक सैनिक संगठनों के सुरक्षात्मक प्रावधानों का महारा लेकर प्रवर्तक राष्ट्र संगठन के सदस्य देशों की तब-उपनिवेशवादी पैराबन्दी करते हैं। तब उपनिवेशवादी पैराबन्दी का अर्थ है—परोक्ष रूप से उनका राष्ट्रनीतिक और आर्थिक नियन्त्रण। जब उनकी इस पैराबन्दी का विराध होता है तो प्रवर्तक राष्ट्र सदस्य देशों पर आक्रमण करने से भी नहीं चूकते। मंगोल, सीवियन मध्य ने कामकान और वारमा समझौतों की प्रादेशिक व्यवस्था का अनुचित लाभ उठाकर पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों पर परोक्ष बमबारी जमाये रखा। जब 1956 में हंगरी और 1968 में चेकोस्लोवाकिया में आन्तरिक विरोध हुआ तो गोवियन मध्य ने सैनिक हस्तक्षेप कर उस लोकप्रिय विरोध को कुचल दिया। इसे प्रादेशिक संगठनों के सदस्य देशों पर प्रवर्तक राष्ट्रों द्वारा उनकी स्वतन्त्रता और सम्प्रभुता पर हमला ही कहा जाना चाहिये। भारत के गूणगूण रसामन्वी बी० के० कृष्ण मेनन ने ठीक ही कहा था कि 'क्षेत्रीय व्यवस्थाएँ ग्लोबल भाषा में उपनिवेशवादी शासन की ओर प्रति-गमन है'।

(xi) राष्ट्रों में फूट डालना—विद्वत् की बड़ी शक्तियाँ क्षेत्रीय सैनिक संगठनों

को प्रवर्तित कर राष्ट्रों में फूट के बीज बोती है। इससे विश्व दो या अनेक गुटों में बँट जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा ही हुआ। अमरीका और सोवियत संघ ने वैचारिक और राष्ट्रीय हितों के टकराव के कारण विश्व के अन्य देशों में प्रभाव-क्षेत्र स्थापित करना चाहा। प्रभाव-क्षेत्र की स्थापना करने के लिए उन्होंने अन्य देशों को सैनिक और आर्थिक मदद का आकर्षण दिखाकर उन्हें क्षेत्रीय संगठनों में बाँध लिया। अमरीका में जहाँ एक ओर पश्चिम यूरोपीय देशों को नाटो में बाँधा, वहीं दूसरी तरफ सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोपीय देशों को वारसा पैक्ट में। इससे ये देश पूँजीवादी और साम्यवादी खेमों में बँट गये। ऐसे प्रयासों को महाशक्तियों द्वारा 'फूट डालो और राज करो' नीति अपनाने के अज्ञात और क्या सजा दी जा सकती है। सभी तो बगदाद पैक्ट के बारे में यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति गार्शल टीटो ने कहा था कि 'विश्व के इस क्षेत्र के देशों और उनकी जनता का बगदाद पैक्ट से कोई हित नहीं होगा क्योंकि वह उनको विभाजित करता है।' इस प्रकार स्पष्ट है कि क्षेत्रीय सैनिक संगठन राष्ट्रों में फूट डालकर उनको गुटों में विभाजित कर देते हैं।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रादेशिक संगठनों की स्थापना क्षेत्रीय सहयोग और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा कायम करने के दृष्टिकोण से की गयी। संयुक्त राष्ट्र सभ चार्टर में इसी भावना से अपने सदस्य-राष्ट्रों को उनके निर्माण की इजाजत दी गयी। लेकिन दुःख की बात है कि राष्ट्रों ने विभिन्न प्रादेशिक सैनिक संगठनों के माध्यम से अपने संकीर्ण राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने के प्रयास किये और अनेक बार अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति भंग की। जहाँ सिप्टो, सेप्टो, वारसा पैक्ट और कोमेकोन विघटन की ओर बढ़े, वहीं सार्क, आसियान और ई० ई० सी० जैसे संगठन एकात्मिक सहयोग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

पाँचवाँ अध्याय

गुट-निरपेक्ष नीति बदलते आयाम

द्वितीय विश्व युद्ध के अवसान के साथ जो नई व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के हृदय-मंडल पर उमरी उसमें कई बातें बड़ी क्रांतिकारी एवं आवश्यककाम कर देने वाली थीं। प्रथम जिन महाशक्तियों ने पिछले तीन सौ वर्षों से यूरोप और बसोबस समस्त विश्व को अपनी शक्ति में डबा दिया था वे घुल घूमरित हो गयीं। जर्मनी घट ब्रिटेन फ्रांस जैसे अपनी ही आंतरिक समस्याओं को निपटाने में स्वयं को असमर्थ पाने लगे। दूसरा क्रांतिकारी परिवर्तन महाशक्तियों के रूप में दो ऐसे देशों (अमेरिका व सोवियत संघ) का उभर कर आना था जिनके बारे में इस तरह की कल्पना अत्यंत दूरदर्शी राजनेता ही कर सकते थे। तीसरे यूरोपीय महाशक्तियों के परामर्श के साथ विश्व में औपनिवेशिक साम्राज्यवाद के विरुद्ध जन संग्राम की मुगलिन शक्तिशाली लहर सामने आयी जिसने पाँच वर्ष के बीच समय में ही अनेक स्वतंत्र एवं शक्तिशाली देशों का सम्भव बनाया। चौथी बात आन्तरिक तीनो बातों का परिणाम थी विश्व के दो गुटों में विभाजित होने की प्रक्रिया के रूप में सामने आयी जिसने शीत युद्ध को जन्म दिया।

गुट निरपेक्षता उपरोक्त शृंखला में का समय बिना ठीक से विश्लेषित नहीं की जा सकती। गुट निरपेक्ष आन्दोलन तीन युद्ध एवं द्विधवीय विश्व प्रणाली के विरुद्ध नवम्बरा देशों का एक ऐसा अभियान था जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शान्ति सम्भावना एवं आर्थिक विकास के साथ-साथ उनका राष्ट्रीय हितों एवं महत्वाकांक्षाओं का अभूत सामंजस्य विद्यमान था। गुट निरपेक्ष आन्दोलन के प्रमुख जनक नवम्बर देशों के स्वाधीनता संग्राम के नेता थे। वे उपनिवेशवादी राष्ट्रों के आर्थिक असमानता एवं प्रसारवाद के विरुद्ध वैश्वीय युद्ध दत्त हुए अंतर्राष्ट्रीय आन्दोलन छेड़ना चाहते थे। चूंकि गुट निरपेक्ष आन्दोलन के जनक के रूप में भारत की सर्वाधिक सम्भवपूर्ण भूमिका रही थी अतएव भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम के कुछ मूलभूत सिद्धान्त इस आन्दोलन की सद्धान्तिक विशारदपारा बन गये। इनमें प्रमुख स्वतंत्रता का अस्तित्व अस्मिता एवं विश्व-वैधुत्व के सिद्धान्त थे। पंचमौल गुट निरपेक्ष आन्दोलन की सद्धान्तिक व्याख्या माना गया जिसमें मुठों में अलग रहते हुए विश्व शान्ति के लिए सक्रिय कार्य करना एवं मुठबन्दी की प्रक्रिया को रोकना या आन्दोलन के उद्देश्यों में जुड़ गया। हम देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतने बड़े पैमाने पर इस आन्दोलन का जन्म एवं विश्व शान्ति के लिए जिस गये हमारे प्रयत्न इतने अधिक प्रगति हुए कि उह अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के इतिहास में एक विनिष्ट स्थान दिया जान गया।

गुट-निरपेक्षता का अर्थ एवं परिभाषा (Non-Alignment : Meaning and Definition)

गुट-निरपेक्षता के अर्थ एवं परिभाषा के बारे में विभिन्न लोगों ने विभिन्न कालों में विभिन्न प्रकार के मत प्रकट किये हैं। पश्चिमी देशों ने इस शब्द को 'तटस्थता' (Neutrality) या 'तटस्थवाद' की सहायता से समझने की कोशिश की है। ऐसा जान पड़ता है कि वे जानबूझकर मूलतः अर्थ एवं परिभाषा देकर विश्व के अन्य देशों को गुमराह करना चाहते रहे, ताकि अन्य देश गुट-निरपेक्ष न बनें और पश्चिमी देशों के साथ जुड़े रहें। वास्तव में 'गुट-निरपेक्ष' शब्द को समझने के लिए इससे सम्बन्धित तीन अवधारणाओं का स्पष्ट विवेचन करना आवश्यक है—'स्थायी तटस्थीकरण', 'तटस्थता' तथा 'गुट-निरपेक्षता'।

1. **स्थायी तटस्थीकरण (Permanent Neutralization)**—यह एक ऐसी स्थिति है जो सन्धे शांत तत्त्व अस्तित्व में रही है तथा उसे अन्तर्राष्ट्रीय कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसका सम्बन्ध ऐसे राज्य से है, जो ऐच्छिक या परिस्थितियों के दबाव के कारण कभी-कभी स्थायी रूप से तटस्थ रहता है। उदाहरणार्थ, स्विट्जरलैण्ड ने स्थायी तटस्थीकरण की नीति ऐच्छिक रूप से अपनायी, अर्थात् यह देश विश्व राजनीति में स्थायी रूप से तटस्थ रहता है।

2. **तटस्थता (Neutrality)**—अन्तर्राष्ट्रीय कानून में यह एक ऐसी अवधारणा है जिसका सम्बन्ध केवल युद्ध की अवस्था से है। मान लो यदि 'अ' और 'ब' नामक देशों में युद्ध छिड़ गया है और उस युद्ध के दौरान 'स' राष्ट्र तटस्थ रहता है अर्थात् यदि वह ('स' राष्ट्र) 'अ' या 'ब' राष्ट्र में से किसी की तरफ़ दायी नहीं करता है तो 'स' राष्ट्र की नीति को तटस्थता की नीति अपनाने वाला राष्ट्र माना जाएगा।

3. **गुट-निरपेक्षता (Non-Alignment)**—गुट-निरपेक्षता का अर्थ न तो 'स्थायी तटस्थीकरण' है और न 'तटस्थता'। जैगा की जवाहरलाल नेहरू ने एक बार अमरीका की प्रतिनिधि समिति में कहा था—'जहाँ स्वतन्त्रता के लिए खड़ा उपस्थित हो, न्याय को धमकी दी जाती हो अथवा जहाँ आक्रमण होता हो, वहाँ न तो हम तटस्थ रह सकते हैं और न ही तटस्थ रहेंगे।'¹

वास्तव में गुट-निरपेक्षता का अर्थ अन्य राज्यों के सैनिक समझौतों में भाग न लेना है। गुट-निरपेक्षता का अर्थ अतथावत की नीति नहीं लिया जाना चाहिये। इसके विपरीत गुट-निरपेक्ष देश विश्व की राजनीति में सक्रिय भूमिका अदा करने में विवश रहते हैं। बम्बुधिया के नरेश मोरोदेय सिंहानुक ने वेल्सलेट शिखर सम्मेलन में कहा था—'गुट-निरपेक्षता में अन्तर्राष्ट्रीय जीवन का एक प्रतिशोध स्वल्प परिवर्तित होना है; वह अस्पष्ट और निष्क्रिय अन्तर्भूमी प्रवृत्ति नहीं है।' यह सोचना भाग्यपूर्ण है कि गुट-निरपेक्ष राष्ट्र विश्व राजनीति को ज्वलन्त समस्याओं से अलग-थलग या उनके प्रति मोन बरतक बने रहने हैं। अतएव वे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भाग लेते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर किसी भी संकट के उठने पर उनके गुण-दोषों या मजबूत-जुठ के बारे में भ्रूत्याकन कर स्वतन्त्र निर्णय कर लेते हैं। जार्ज तिसका ने सही कहा है—'किसी विवाद के सन्दर्भ में यह जानते हुए कि

¹ Jawaharlal Nehru's Speeches, 1949-1953, Vol. 2 (Delhi, 1957), 125.

कौन सही है और कौन गलत है, किसी का पक्ष न लेना तटस्थता है, किन्तु असलानता या गुट-निरपक्षता का अर्थ है—सही और गलत में भेद कर सदैव सही नीति का समर्थन करना।¹ असल में जार्ज लिस्सा ही पहला पश्चिमी विद्वान था जिसने गुट-निरपक्षता को उसके वैज्ञानिक अर्थ में समझने का प्रयत्न किया। उसने बाद कुछ अन्य विद्वानों ने भी गुट-निरपक्षता को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नई अवधारणा के रूप में स्वीकार किया।

गुट-निरपेक्ष नीति अपनाने के कारण (Adoption of Non-Alignment Policy)

द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद कुछ राष्ट्रों ने गुट-निरपेक्ष नीति अपनाना आरम्भ किया। इस नीति का पालन करने वाले राष्ट्रों की संख्या बढ़कर 103 तक पहुँच गई। केवल कुछ राष्ट्रों से 101 तक गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों की संख्या बढ़ जाने के पीछे जो अनेक कारण रहे हैं, वे इस प्रकार हैं—

1. विश्व का वैचारिक आधार पर दो भागों में विभाजित होना—द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय जगत दो सेमों में बँट गया था। पूँजीवादी राष्ट्रों का नेतृत्व अहाँ अमरीका ने किया, वहीं साम्यवादी राष्ट्रों का नेतृत्व सोवियत संघ ने। दोनों महाशक्तियों—अमरीका और रूस ने नवोदित स्वतन्त्र देशों को वैचारिक आधार पर अपनी-अपनी ओर मिलाना चाहा, जिसे अन्य देशों ने पसन्द नहीं किया। इसका प्रमुख कारण यह था कि वे अपने अपने वैचारिक आधार पर विभाजित कर किसी विशेष महाशक्ति के वैचारिक आधिपत्य को न तो स्वीकार करना चाहते थे और न ही दूसरी महाशक्ति को नाराज करना चाहते थे। इस कारण, नवोदित राष्ट्रों को ऐसा लगा कि गुट-निरपेक्षता उनके लिए विशेषतः दोनों गुटों के वैचारिक संपर्क के संदर्भ में अपने पृथक् और विशिष्ट वैचारिक स्वरूप को अक्षुण्ण बनाये रखने का साधन था। वे अपने राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक समस्याओं के पृथक् स्वरूप को बनाये रखना चाहते थे और नहीं चाहते थे कि राष्ट्रों के किसी बड़े समूह में जहाँ किसी न किसी सर्वोच्च शक्ति का धोलवाला हो, उनकी अपनी कोई पहचान न रह जाये।²

2. सैनिक सन्धियों से न बँधने की इच्छा—अमरीका और रूस जब वैचारिक आधार पर नवोदित गरीब राष्ट्रों को आश्रित करने में व्यस्त रहते तो उन्होंने उनकी सैनिक सन्धियों से बाँधन की एक नयी चाल खसी। महाशक्तियों ने उनकी आश्वस्तियाँ दिया कि यदि वे 'सन्टो', 'गिण्टो', 'नाटो', 'वारसा' आदि सैनिक सन्धियों में सदस्यता ग्रहण करें तो वे उन्हें किसी अन्य देश के आश्रय से बचायेंगे। किन्तु अनेक छोटे राष्ट्र किसी भी महाशक्ति के सैनिक प्रभुत्व के तहत रहकर पिछड़ाग्नू बनने को तैयार नहीं थे। गुट-निरपक्ष दश इन सैनिक सन्धियों को विश्व शान्ति के प्रतिकूल मानते हैं। जैसाकि नेहरू जी ने अपने एक प्रसारण में कहा था—'शीत युद्ध के सैनिक गठबन्धनों ने विश्व में अच्छे प्रभाव नहीं लाये हैं। पिछले कुछ वर्षों में एशिया में इस नीति के प्रसार ने विश्व सुरक्षा या किसी भी देश की सुरक्षा को बढ़ा नहीं दिया'। वास्तव में यह देश के विनाश में बाधक रही

¹ एम० एम० राबिन, 'गुट-निरपेक्षता: कारण और परिणाम' (दिसम्बर, 1975) पृ० 15।

है।¹² इसी प्रकार, बर्मा के प्रधानमन्त्री ऊ नू ने 'सिएटो' नामक सैनिक संगठन के निर्माण के बारे में प्रतिज्ञिया व्यक्त करते हुए कहा था कि 'ऐसे संगठनों का निर्माण तीसरे विश्व युद्ध की सम्भावनाएँ बढ़ाता है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम जो समस्याएँ सुलझाना चाहते हैं, वह युद्ध नहीं सुलझा सकता है। इसलिए हम प्रस्तावित 'सिएटो' में सम्मिलित नहीं होंगे।'¹³

3. राष्ट्रवाद एवं स्वतन्त्र विदेश नीति निर्माण की भावना—द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद अफ्रीका, एशिया एवं लातीनी अमरीका में अनेक उपनिवेश राष्ट्रीय भुक्ति संग्रामों के द्वारा स्वतन्त्र हुए। औपनिवेशिक शासन के दौरान उनका हर प्रकार से शोषण किया गया किन्तु राष्ट्रवाद की भावना के कारण वे स्वतन्त्र हुए और वे चाहते थे कि बिना किसी महाशक्ति या बड़े देश के हस्तक्षेप के स्वतन्त्र विदेश नीति का निर्माण करें। जैसाकि फिलीपींस के राजनयिक कार्लोस पी० रोम्पूलो ने बलील दी है कि गुट-निरपेक्षता समकालीन राष्ट्रवाद का एक पक्ष मात्र है और यह एक मास्कुलिक तथा राजनीतिक आन्दोलन है, जो पूर्ण क्षमाम पश्चिम अथवा लोकतन्त्र बनाम साम्यवाद के परम्परागत द्वन्द्व से परे की चीज है।¹⁴ बर्मा के प्रधानमन्त्री ऊ नू ने एक बार कहा था—विदेशी मामलों के परिचालन में वह पूर्ण स्वतन्त्रता के साथ कार्य करना चाहते हैं। इसी प्रकार घाना के एन्क्रूमा ने भी कहा था कि गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों को अपने अन्तराष्ट्रीय मामलों को तय करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिये।¹⁵

4. शीत युद्ध तीसरे विश्व युद्ध का सतरा—1945 के बाद जब अमरीका और रूस ने विश्व के विभिन्न भागों में सैनिक सन्धियों और आर्थिक सहायता के दबाव से अपने-अपने प्रभाव-क्षेत्र कायम करना आरम्भ किया तो नवोदित व अन्य राष्ट्रों ने कुछ समय बाद महसूस किया कि महाशक्तियाँ प्रभाव-क्षेत्र स्थापित कर उन्हें आपस में लड़ाती हैं और कभी-कभी स्वयं आपने-सामने खड़ी हो जाती हैं। ऐसी अवस्था में तीसरे विश्व युद्ध की सम्भावना को नहीं टाला जा सकता। अतः उन्होंने तय किया कि वे महाशक्तियों के स्वार्थवश अपनी भूमि पर तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने देंगे।

5. विश्व शान्ति एवं सहयोग की बढ़ावा देने की इच्छा—शीत युद्ध के दूषित घातावरण ने गुट-निरपेक्ष देश विश्व शान्ति एवं सहयोग की भावना को बढ़ावा देना चाहते थे। उनका उद्देश्य समस्त राष्ट्रों के साथ शान्ति और मैत्री को

¹² 'I think that the policy of military alliances of the cold war has not brought any such results to the world...in the last few years, the spread of this policy to Asia has not added to the world's security, or to any country's security... It has really come in the way of a country's progress.'—Jawaharlal Nehru, *India's Foreign Policy, Selected Speeches* (Delhi, 1961), 98.

¹³ 'The formation of such organizations increases the chances of World War III. I am firmly convinced that war will not solve any of the problems we want to solve. Therefore, we will not be a party to the proposed SEATO'—Quoted by William C. Johnston in his book, *Burma's Foreign Policy* (Cambridge, 1963), 93-99.

¹⁴ Carlos P. Romulo, *Contemporary Nationalism and World Order* (Bombay, 1963), 29-31.

¹⁵ बिस्तार के लिए देखें—Kwame Nkrumah, *I Speak of Freedom: A Statement of African Ideology* (London, 1961).

बढ़ावा देना रहा, चाहे उसमें कैसे भी राजनीतिक अथवा वैचारिक मतभेद क्यों न हो। इसी कारण अनेक राष्ट्रों ने शीत युद्ध में न फँसकर गुट-निरपेक्ष नीति अपनायी। उल्लेखनीय है कि गुट-निरपेक्ष देश अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एवं विश्व शान्ति के पोषण के लिए सिर्फ़ कोरी आदर्शवादिता से प्रेरित नहीं हुए थे। नेहरू और नासिर जैसे नेताओं ने यह बात स्पष्ट कर दी थी विश्व शान्ति का नवस्वतन्त्र राष्ट्र के विकास से अभिन्न सम्बन्ध है। स्पष्ट था कि अन्तर्राष्ट्रीय सङ्कट अभीकी व एशियाई देशों में बाहरी हस्तक्षेप को बुलाने का बहाना ही हो सकते थे और ऐसा होने पर आर्थिक विकास, समतापूर्ण समाज का गठन असम्भव हो जाता। आर्थिक विकास व सामाजिक प्रगति के अभाव में राजनीतिन आजादी अधुरी होती। विश्व शान्ति की रक्षा के लिए सहयोग की माँगना ने गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के जन्मघट में बहुमुखी पारस्परिक सहयोग को प्रोत्साहित किया।

6 तकनीकी एवं आर्थिक विकास की आवश्यकता—अनेक देशों द्वारा गुट-निरपेक्ष नीति अपनाने का यह भी एक प्रमुख कारण था कि वे तकनीकी एवं आर्थिक विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए थे। उनके पास न तो पूँजी ही थी और न ही टेक्नोलोजी एवं तकनीकी ज्ञान। उन्होंने महसूस किया कि यदि वे किसी गुट में शामिल हो गये तो एक ओर वे उस गुट पर पूर्णरूपेण निर्भर हो जायेंगे तो दूसरी तरफ़ वे दूसरे गुटों से तकनीकी एवं आर्थिक विकास के लिए सहायता नहीं पा सकेंगे। अतः गुट-निरपेक्ष रहकर वे दोनों गुटों से सहायता प्राप्त कर सकते थे। लेकिन यह सहायता महाशक्तियों या बड़ी शक्तियों द्वारा किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव से मुक्त होने पर ही गुट-निरपेक्ष देशों द्वारा स्वीकार की जाती रही है। नेहरू जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि 'यदि किसी विदेशी सहायता के साथ राजनीतिक प्रतिबन्ध जुड़े हुए होंगे और यदि उन सहायता की स्वीकार करने में हमें अपनी किसी मूलभूत नीति में कोई परिवर्तन करना होगा तो भारत विदेशी सहायता स्वीकार नहीं करेगा।' ¹

गुट-निरपेक्ष ग़िलर सम्मेलन . बेलग्रेड से हरारे तक (Non-Aligned Summits . From Belgrade to Harare)

विकासशील देशों में सहयोग एवं एकता स्थापित करने का प्रारम्भिक एवं सबसे ठोस कार्य 1946 में दिम्बोरी में इण्डोनेशिया की स्वतन्त्रता के लिए बुलाए गए एशियाई सम्बन्ध सम्मेलन और 1955 में वाइबुंग में हुए अफ़ो एशियाई देशों के ग़िलर सम्मेलन द्वारा किया गया। इसके बाद गुट-निरपेक्ष देशों ने इस दिशा में अनेक कदम उठाये।

वास्तव में, गुट-निरपेक्षता का विकास इस नीति का पालन करने वाले देशों के विभिन्न ग़िलर सम्मेलनों के जरिये हुआ है। इनके कई ग़िलर सम्मेलन हुए। इन सम्मेलनों में गुट निरपेक्षता के अर्थ, समय-समय पर उठे अनेक अन्तर्राष्ट्रीय सङ्कटों पर विचार तथा कई प्रकार की योजनाएँ त्रिपक्षीय बनाने के बारे में घोषणाएँ की गयीं। इनका सक्षिप्त विवरण अधोलिखित है।

¹ If any help from abroad depends upon a variation, howsoever slight, in our policy, we shall relinquish that help completely.—Jawaharlal Nehru, *India's Foreign Policy: Selected Speeches*, 63

1961 का वेलग्रेड शिखर सम्मेलन

1961 में गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों का पहला शिखर सम्मेलन युगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ। इसमें 25 देशों ने भाग लिया। इसमें गुट-निरपेक्षता के पाँच आधारभूत तत्व निश्चित किये गये, जो इस प्रकार हैं—

- (i) जो देश गुट-निरपेक्षता और शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के आधार पर स्वतन्त्र विदेश नीति का अनुसरण करता हो,
- (ii) जो देश उपनिवेशवाद के खिनाफ स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए चल रहे आन्दोलन का समर्थन करता हो,
- (iii) जो देश शीत युद्ध से सम्बन्धित किसी सैनिक गुट का सदस्य न हो;
- (iv) जिस देश की रूस या अमरीका किसी भी महाशक्ति के साथ कोई द्विपक्षीय सैनिक सन्धि न हो; और
- (v) उस देश की घरेलू पर कोई विदेशी सैनिक अड्डा न हो।

सम्मेलन ने तत्कालीन विश्व राजनीति का जायजा लेते हुए अनेक घोषणाएँ कीं, जिनमें से प्रमुख बातें इस प्रकार हैं—

- (i) निरस्त्रीकरण और आणविक परीक्षणों पर रोक लगे;
- (ii) विश्व शान्ति एवं सह-अस्तित्व की अवधारणा का विकास हो,
- (iii) घरेलू मामलों में विदेशी हस्तक्षेप व रणभेद की निन्दा की गई; और
- (iv) आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक पिछड़ेपन को दूर करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

बेलग्रेड सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि इसने पहली बार गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सस्यायत ढाँचा प्रस्तुत किया। साथ ही इन बात की घोषणा की कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में इस तीसरी शक्ति को अनदेखा नहीं किया जा सकता। यह बात भी अच्छी तरह स्पष्ट की जा सकी कि गुट-निरपेक्षता का अर्थ निष्क्रमता नहीं, बल्कि उपनिवेशवाद-विरोध, जातिवाद-विरोध है। निरस्त्रीकरण के सन्दर्भ में भी गुट-निरपेक्ष देशों ने अपना प्रगतिशील सुझावरूप प्रमाणित किया।

1964 का काहिरा शिखर सम्मेलन

1964 में गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों का दूसरा शिखर सम्मेलन मिस्र की राजधानी काहिरा में हुआ। इसमें 47 पूर्ण सदस्य तथा 11 पर्यवेक्षक राष्ट्रों ने भाग लिया। सम्मेलन में आमन्त्रित देशों की पाँच श्रेणियों में विभाजित¹ किया जा सकता है—

- (i) वे 25 देश, जिन्होंने बेलग्रेड सम्मेलन में भाग लिया था;
- (ii) वे सभी देश, जो अफ्रीकी एकता संघ के घोषणा-पत्र में आस्था रखते थे;
- (iii) वे सभी अरब राज्य, जिन्होंने 1964 के अरब शिखर सम्मेलन में भाग लिया था;

¹ ध्यान रहे, काहिरा सम्मेलन के बाद 1970 में बुनारा, 1973 में अलजीरस, 1976 में मोनम्बो, 1979 में हवाना में गुट-निरपेक्ष देशों को नियमित करने में लगभग बड़ी काम्यता अपनाया गया, जो काहिरा शिखर सम्मेलन के लिए अपनाया गया था।

(iv) मलावी राजम मैकिमको जैमका ट्रिनिडाड और टोबगो, अर्जेंटीना बोलिविया ब्राजील चिली उरुग्वे बनेजुअला आस्ट्रिया फिनलैण्ड,

(v) जाम्बिया और म्यांमार (यदि वे सम्मेलन के पक्ष स्वतंत्र हो जायें) और

(vi) जमाला की अस्थाई सरकार (यात्रा ही यदि किसी अन्य अफ्रीकी देश में सम्मेलन शुरू होने के पहले अस्थाई सरकार बन जाये तो वह देश भी बाहिर सम्मेलन में भाग ले सकता)।

इस सम्मेलन में भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री लालबहादुर शास्त्री ने विश्व शान्ति की स्थापना के लिए पाँच सूत्री प्रस्ताव पेश किया। पाँच सूत्र निम्नांकित थे—1 अणु निस्शोकरण 2 सीमा विवादों का शांतिपूर्ण हल 3 विश्वी प्रभुत्व आक्रमण एवं तोड़फोड़ की वायवहिया से मुक्ति 4 अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा आर्थिक विकास और 5 समुक्त राष्ट्र सच के वायव्यम का समर्थन। सम्मेलन की जो दो प्रमुख घोषणाएँ विषय रूप से उल्लेखनीय हैं वे हैं—1 उपनिवेशवाद को समाप्त कर पीछित देशों को इसके अंगुल से स्वतंत्र कर दिया जाये और 2 अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा आर्थिक विकास किया जाय।

बाहिरा गुट निरपेक्ष गिटर सम्मेलन के बारे में यह उल्लेखनीय है कि इस समय तक अफ्रीकी एगियाई बिरादरी में फूट पड़ चुकी थी। भारत चीन सीमा विवाद ने निश्चय ही गुट निरपेक्ष देशों की एकता को कमजोर किया था। इसके साथ समुक्त राष्ट्र सच की वागों में गतिविधियों को लेकर अनेक तनाव पैदा हुए थे जिसके परिणामस्वरूप विश्व शांति अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग आर्थिक विकास आदि की प्राथमिकताएँ गहरे गहरे हो गयी थी। बेलगुड सम्मेलन के समय उपनिवेशवाद के उन्मूलन के साथ जुड़ा उन्साह प्रभावशाली था। बाहिरा सम्मेलन इस बात को अनदेखा नहीं कर सकता था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस तरह विघटनकारी प्रवृत्तियों चुनौतिया का सामना नये राष्ट्रों को करना पड़ सकता है। इसने परवर्ती वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय सच के साथ-साथ गुट निरपेक्ष आन्दोलन के मद्दतियों का ध्यान राष्ट्र निर्माण की ओर भी नगा रखा। इस दौर में मह्यामी आर्थिक विकास तथा सीमा विवादों के हल को प्राथमिकता दी गई। एक ओर अन्तर्राष्ट्रीय राजनयिक परिवर्तन ने इस प्रवृत्ति को पुष्ट किया। 1962 में बंगालई सच ने महाशक्तियों को सबनाना के बगैर तब सा दिया। एक बाद उनमें हाट नानन के माध्यम से आपातकारीन सवा आरम्भ हुआ। इस सवा के भूखपान के साथ गीन मुद्र की बटुता में बभी आयी और महाशक्तियों की दृष्टि में गुट निरपेक्षता की उपयोगिता बढ़ी।

1970 का तुमाना गिटर सम्मेलन

1970 में गुट निरपेक्ष राष्ट्रा का तीसरा गिटर सम्मेलन जाम्बिया की राजधानी लुसाका में हुआ। इसमें 47/54 पूर्ण सम्म्य-देश तथा 11/9 परबलक देशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में अनेक घोषणाएँ की गयी जिनमें से प्रमुख बात अधातिनि है—

(1) पंचिम एगिया सच के बारे में कहा गया कि 1967 के मुद्र के दौरान ताकत के जरिये हकपो गई जमीन इजराईल म्यानी कर। यदि इजराईल

शान्ति के विरुद्ध लगातार कार्य करता रहा और अरब सेना की भूमि खाली करने से मना करता रहा तो ऐसी परिस्थितियों में उसके विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव भी पास किया जायेगा।

(ii) सम्मेलन की यह आम राय थी अमरीकी सेना ने वियतनाम में घुस कर स्थिति बिगाड़ दी है। यह मांग की गयी कि वियतनाम से अमरीका तथा अन्य सभी देश अपनी फौजें हटावें। ध्यान रहे, वियतनाम की अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार की विदेश मंत्री श्रीमती बिन्ह को लुसाका सम्मेलन में प्रेक्षक बनाकर यह माँवित कर दिया गया कि गुट-निरपेक्ष देश राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे के साथ हैं।

(iii) हिन्द-चीन में जहाँ शान्ति प्रयत्नों को आरम्भ करने की सिफारिश की गयी, वही कम्बुधिया के घारे में यह विवाद उठा कि राजकुमार सिंहानुक या सोन नोल में किसे सम्मेलन में स्थान दिया जाये। अन्त में दोनों में से किसी को भी स्थान नहीं दिया गया। सोन नोल के विरुद्ध अनेक वक्ताओं ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि जनरल सोन नोल की सरकार ने राजकुमार सिंहानुक को अपदस्थ करके विदेशी हस्तक्षेप के लिए मार्ग सौंसा जबकि दूसरी ओर सिंहानुक सत्ता में नहीं हैं, का तर्क दिया गया।

(iv) दक्षिण अफ्रीका में उपनिवेशवाद के दारे में सम्मेलन ने सदस्य राष्ट्रों से अनुरोध किया कि दक्षिण अफ्रीका की हवाई कम्पनी के विमानों को वह अपने ऊपर से होकर जाने की अनुमति न दें। हालांकि अफ्रीकी जनता के मुक्ति संग्राम के लिए धन राशि एकत्र करने का प्रस्ताव पेश किया गया, लेकिन निश्चित व्यवस्था के अभाव में ऐसी कार्यवाही का लागू सीधे तथ्यपरत अफ्रीकी जनता को पहुँच सके, यह संभव न हो पाया।

(v) गुट-निरपेक्ष देशों में आपसी आर्थिक सहयोग पर जोर दिया गया। इसमें भारत की विशेष पहल रही।

(vi) जैसा कि गुट-निरपेक्षता का अर्थ ही गुटबन्दी का विरोध करना है, अनेक अफ्रीकी देशों ने लुसाका में गुट-निरपेक्ष देशों के सचिवालय के विचार को रद्द कर दिया। भारत ने भी इसका कड़ा विरोध किया।

लुसाका गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन बहुत कुछ हासिल करने में असमर्थ रहा। पूर्ववर्ती वर्ष अप्रत्याशित अन्तर्राष्ट्रीय संकट वाले थे और अनेक गुट-निरपेक्ष राष्ट्र आन्तरिक समस्याओं से ग्रस्त थे। इन कठिनाइयों का पता इसी बात से चलता है कि काहिरा के बाद 1967 में गुट-निरपेक्ष सम्मेलन का अधिवेशन न हो सका। वियतनाम में गृह-युद्ध में बिगाड़, इण्डोनेशिया में तत्तापभट, भारत में सत्ता परिवर्तन, मध्य पूर्व में अरब-इजरायल युद्ध के साथ-साथ 1969 में सोवियत-चीन मधर्प आदि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के लिए सरदर्द बने रहे। लुसाका सम्मेलन इस बात के लिए चिन्त था कि वह अन्तर्राष्ट्रीय संकट के राजनयिक निवारण को ही प्राथमिकता दे। अतएव आन्दोलन के घोषित उद्देश्यों को ही फिर से परिभाषित किया गया।

1973 का अल्जीरिया शिखर सम्मेलन

1973 में गुट-निरपेक्ष देशों का चौथा शिखर सम्मेलन अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरिया में हुआ। इसमें 76 देशों ने पूर्ण सदस्य, नौ ने पर्यवेक्षक और

सुझ ने विनिश्चित अनिवार्य (जैसा कि मयुक्त राष्ट्र मध्य के महामन्त्रि डा० कुतुबुद्दीन) के रूप में भाग लिया। इस सम्मेलन में प्रमुख रूप से निम्न बातें कही गयीं—

1. गुट-निरपेक्षता की अवधारणा को मजबूत करने के लिए लीबिया तथा अल्जीरिया ने यह प्रस्ताव रखा कि गुट-निरपेक्षता की नई परिभाषा की जाये और इस नीति का पालन करने वाले राष्ट्रों के लिए नया विधान तैयार किया जाये। लेकिन यह प्रस्ताव रद्द कर दिया गया। गुट-निरपेक्ष देशों के लिए एक बार फिर स्थायी सचिवालय के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। जैमेका के प्रधानमन्त्री न मुझाव दिया कि गुट-निरपेक्ष देशों का अपना एक विकास कोष होना चाहिए। इस मुझाव पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया।

2. सम्मेलन द्वारा जारी किये गये घोषणा-पत्र में सदस्य राष्ट्रों ने मिफारिह की गई कि वह राजकुमार मिहानुक की निर्वाचित सरकार को कम्बुजिया की सरकार के रूप में मान्यता दें। वियतनाम की अन्त्यावी क्रान्तिकारी सरकार को राजनयिक समर्थन देने की मिफारिह की गई।

3. मिस्र तथा जॉर्डन अपने प्रदेशों को (इजरायल द्वारा हथिये क्षेत्रों को) मुक्त कराने के लिए जो प्रयत्न कर रहे थे, उनमें गुट-निरपेक्ष देशों द्वारा राजनयिक सहयोग प्रदान करने की मिफारिह की गयी।

4. सम्मेलन में अफ्रीका में चल रहे राष्ट्रीय मुक्ति संग्रामों का समर्थन देने की बात अनेक बार उठी। किन्तु ठोस समर्थन उपलब्ध कराने की कोई व्यवस्था नहीं की जा सकी।

5. गुट-निरपेक्ष देशों के इस सम्मेलन में महाशक्तियों को लेकर पहली बार गुरी आपसी झोंक-झोंक हुई। क्यूबा के फिदेल् कास्त्रो ने मौखिक रूप से गुट-निरपेक्ष देशों का हिमायती बनाया। उन्होंने नानीनी अमरीका के देशों विशेषकर साजीन पर आरोप लगाया कि वह अमरीकी साम्राज्यवाद का गढ़ है। दूसरी ओर इस घनव्य को लेकर लीबिया के राष्ट्रपति कर्तल गद्दाफी और बान्गो के मध्य मौखिक झगडा हो गई। ट्यूनिशिया के राष्ट्रपति हबीब बोर्गोबा ने बीच-बचाव के तरीके से कहा कि गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों को अमरीकी 'बोका बोरा साम्राज्य' तथा सोवियत 'बोदना साम्राज्य' दोनों से ही सतर्क रहना चाहिए।

6. हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करने की बात कही गयी।

7. यह कहा गया कि हरेक राष्ट्र को अपने प्राकृतिक धोत्रों का राष्ट्रीय-करण करत और आन्तरिक आर्थिक गतिविधियों को नियन्त्रित करने का अधिकार है। विकासशील देशों में पारस्परिक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।

अन्तर्निर्मित गुट-निरपेक्ष गिस्तर सम्मेलन तक यह बात सामने आने लगी कि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का प्रसार उसकी धार को कुद करने लगा है। सदस्य मस्या में वृद्धि ने आन्दोलन की एकरूपता को निदरूप ही कम किया। फिर भी अन्तर्निर्मित सम्मेलन का अधिवेशन करने आर में एक बड़ी उपलब्धि था। 1969 के बाद के वर्षों में जनवादी चीन ने महान् साम्युक्तिक क्रान्ति का आरम्भ हो चुका था और उमने ध्यात उपन-पुनर् को जन्म दिया। अन्तर्गर्तीय राजनय पर इस घटनाक्रम के दूरगामी प्रभाव पड़े। इस दौर में चीन का प्रयत्न यह रहा कि गुट-निरपेक्ष

आन्दोलन को पथ-भ्रष्ट कर उसे निश्चायित किया जा सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए चीन ने अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन की पेशनश की। अल्जीरिया सम्मेलन ने यह बात स्पष्ट कर दी की गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की जड़े अब तक इतनी गहरी हो चुकी है कि जोड़-तोड़ वाले राजनयिक पङ्क्त्यन्त तक भी उसे नुकसान नहीं पहुँचा सकते।

1975 का कोलम्बो शिखर सम्मेलन

गुट-निरपेक्ष देशों का पाँचवाँ शिखर सम्मेलन भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका की राजधानी कोलम्बो में हुआ। इसमें 86 देशों ने पूर्ण सदस्य, 10 ने पर्यवेक्षक, 12 ने पर्यवेक्षक गैर राज्य (जैसे संयुक्त राष्ट्र सच, अफ्रीकी एकता संगठन और अरब लीग इत्यादि) तथा सात ने अतिथि सदस्य के रूप में भाग लिया। इस प्रकार इस सम्मेलन में 115 देशों एव अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया। कुल पूर्ण सदस्यों में 48 अफ्रीका, 28 एशिया, सात लातीनी अमरीका और तीन यूरोप के देश थे। सम्मेलन की मुख्य बानें निम्नांकित हैं—

1. गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की एकता में फूट ठासने के प्रयासों का विरोध किया गया। जब बंगला देश में मुजीब की हत्या के बाद भारत-विरोधी नये शासक मत्ता में आये तो उन्होंने इस सम्मेलन के दौरान गंगा के पानी के बँटवारे के प्रश्न को उठाने का प्रयास किया तो गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में सामुदायिक उद्देश्यों की एकता स्थापित कर उन्हें प्राप्त करने के लिए ऐसे द्विपक्षीय विवाद को न उठाने के लिए कहा गया।

2. सम्मेलन में महाशक्तियों के इन आरोपों का विरोध किया गया कि संयुक्त राष्ट्र सच में गुट-निरपेक्ष देशों की संस्थात्मक विशालता 'बहुमत का आतंक' है। श्रीलंका की तत्कालीन प्रधान मंत्री तथा सम्मेलन की अध्यक्ष श्रीमती सिरिमावो बण्डरनायके ने कहा कि गुट-निरपेक्ष देशों का सघर्ष किसी राष्ट्र या समुदाय से नहीं है बल्कि अन्याय, असहिष्णुता, असमानता, साम्राज्यवाद, हस्तक्षेप और आधिपत्य से है।

3. सम्मेलन में कहा गया कि फ्रांस और इजराइल के विरुद्ध तेल निषेध की पाबन्दियाँ (Sanctions of Oil Embargo) लगायी जाये क्योंकि इन देशों ने दक्षिण अफ्रीका की रणभेद (Apartheid) की नीति के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सच की महासभा के प्रस्तावों की अवहेलना करते हुए उन्हें हथियारों की आपूर्ति की है।

4. उन सहुराष्ट्रीय निगमों की आलोचना की गई जो घूस और अन्य साधनों के जरिये विकासशील देशों को विकसित देशों के अधीन बनाये हैं।

5. नई अन्तर्राष्ट्रीय समाचार व्यवस्था की स्थापना के लिए 'न्यूज पूल' की स्थापना की आवश्यकता पर जोर दिया गया ताकि इस क्षेत्र में तीसरी दुनिया के विकासशील राष्ट्रों की निरन्तर राष्ट्रों पर अत्यधिक निर्भरता समाप्त हो और विकासशील राष्ट्रों की खबरें बड़े देशों के समाचार संघों द्वारा तोड़ी-मरोड़ी न जायें।

6. सम्मेलन में नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना अर्थात् विश्व में मौजूदा अर्थव्यवस्था में आमूल-भूल परिवर्तन किया जाये। यह नई विश्व अर्थव्यवस्था गमानता और न्याय पर आधारित हो। गुट-निरपेक्ष देशों के लिए नई मुद्रा का

प्रचलन, व्यावसायिक बैंक की स्थापना, विकासशील अर्थात् गुट-निरपेक्ष देशों की सुरक्षित मुद्रा निधियों से विकसित देशों की मुद्राओं का व्रत्मिक निष्कासन, उत्पादक संघों (Producers' Associations) की स्थापना (विशेष तौर पर तेल, ताबा, वॉल्माइट और यूरेनियम जैसे महत्वपूर्ण कच्चे माल के लिए) पर दल दिया गया। असल में पहली बार इतने जोर के साथ इस सम्मेलन में नई विश्व अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए आवाज उठायी गयी।

7 'शान्ति-सन्तुलन', 'युद्ध की अनिवार्यता' एवं 'प्रभाव-क्षेत्र' जैसी अवधारणाओं को शान्ति-विरोधी घोषित किया गया।

8 भारतीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन 'मानवता की अन्तरात्मा' है। उन्होंने सदस्य राष्ट्रों से एक साथ मिलकर शान्ति कायम करने में योगदान करने की अपील की।

9 सम्मेलन द्वारा जारी किये गये राजनीतिक घोषणा-पत्र में 'तनाव-क्षैणिक' शब्द को स्थान न देकर 'समस्त देशों के लिए शान्ति की स्थापना' वाक्यांश का प्रयोग किया गया।

गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के इतिहास में कोलम्बो शिखर सम्मेलन का महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा कहा जा सकता है कि आन्दोलन के व्यस्क-प्रीड होने के बिन्धु इस सम्मेलन में देखे गये। सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि निरर्थक राजनयिक बहस से मुड़कर सार्थक आर्थिक सहकार की भूमिका तैयार करना था। यों अनेक अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बुलाई गई अकटाड (UNCTAD) बैठकें, राष्ट्र-मण्डलीय सम्मेलन आदि में रह-रह कर आर्थिक सहकार की बात उठायी जाती रही थी, किन्तु कोलम्बो शिखर सम्मेलन के बाद ही नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की शोज विधिवत धुरु की जा सकी।

1979 का हवाना शिखर सम्मेलन

1979 में गुटनिरपेक्ष देशों का छठा शिखर सम्मेलन क्यूबा की राजधानी हवाना में हुआ। इसमें करीब 95 राष्ट्रों ने भाग लिया। यह पहला मौका था, जबकि भारत की ओर से किसी नामनाध्यक्ष में शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया। सम्मेलन में आन्दोलन के संस्थापकों में से एकमात्र जीवित मांझल टीटो की अत्यन्त सक्रिय उपस्थिति महत्वपूर्ण थी। शिखर सम्मेलन में आठ नये सदस्यों बोलीविया, घेनेडा, ईरान, पाकिस्तान, निकारागुआ, जिम्बाब्वे के देशभक्त मोर्चे, 'स्वापो' आदि का तुमुल हर्षध्वनि के साथ स्वागत किया गया। 1961 में 25 राष्ट्रों से शुरू हुए गुट निरपेक्ष आन्दोलन के सदस्य देशों की संख्या अब बढ़कर 96 हो चुकी थी।

सम्मेलन के सानो दिन अत्यन्त गरमागर्मी से भरे हुए थे। एक ओर कुछ राष्ट्र आन्दोलन को रूमी सेमे के निकट तथा अमरीका के विरुद्ध खड़ा करना चाहते थे तो दूसरी ओर मांझल टीटो के नेतृत्व में अधिकांश राष्ट्र आन्दोलन के स्वतन्त्र चरित्र को कायम रखने के लिए कठिन संघर्ष करते रहे। बहम के हर क्षेत्र में यह दंड चलता रहा। लेकिन सम्मेलन के अन्त में हुई घोषणाओं ने स्पष्ट कर दिया कि अधिकांश गुट निरपेक्ष राष्ट्र अपने स्वतन्त्र अस्तित्व को कायम रखते हुए लगातार एकजुट रहे हैं। अर्थात्, राजनीतिक आदि हरेक क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग के ठोस कार्यक्रम बनाने का निश्चय सम्मेलन की मुख्य उपलब्धि रही।

सम्मेलन में रखे गये प्रस्ताव—सम्मेलन के शुरू होने के काफी पहले क्यूबा ने शिखर सम्मेलन में स्वीकृत होने वाली घोषणाओं को तैयार कर लिया था। उसने प्रारूप समी सदस्यों में वितरित कर दिया, जिसका अधिकांश सदस्य देशों द्वारा भारी विरोध किया गया। इसमें गुट निरपेक्ष आन्दोलन के पूरे चरित्र को बदलने की धिनीनी कोशिश की गयी थी। क्यूबा द्वारा वितरित प्रारूप में तय्यकगित समाजवादी खेमे यानि रूसी खेमे को गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का 'स्वाभाविक मित्र' बताया गया था। रूसी पिछलग्गुओं को छोड़कर सभी गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ने पूरे आन्दोलन के चरित्र को बदलने के इस कुत्सित प्रयास का जबरदस्त विरोध किया। अतएव क्यूबा को दूसरा प्रारूप प्रस्तुत करने पर मजबूर होना पड़ा। दूसरे प्रारूप में गुट निरपेक्ष आन्दोलन को रूसी खेमे के नजदीक लाने की खुसी बकालत के बजाय उसकी परोक्ष तौर पर बकालत की गयी। इस बार समाजवादी खेमे के बजाय अन्य शान्तिपूर्ण व प्रगतिशील शक्तियों के सहयोग की बात प्रारूप में कही गयी। इससे रूसी आशार्थों पर पानी फिर गया। इस तरह युगोस्लाविया के नेतृत्व में विभिन्न राष्ट्रों द्वारा प्रस्तुत सशोधन के बाद हवाना शिखर सम्मेलन की घोषणा के प्रारूप में गुट निरपेक्ष आन्दोलन की मूल गांवना की फिर से काम्य किया गया।

1. कंबुचिया का मामला—कंबुचिया के तत्कालीन शासक पोलपोट को हेग सामरिन ने वियतनाम की सहायता एवं इस के समर्थन से बाहर निकाल दिया था। मगर हेग सामरिन की 'कठपुतली' सरकार देश के अन्दर हो रहे प्रतिरोध और तयर्प को न तो दबा पायी और न ही दुनिया से मान्यता प्राप्त कर सकी। इस प्रस्ताव की विदेश मन्त्रियों के सम्मेलन ने शिखर सम्मेलन पर ही छोड़ दिया था। हवाना सम्मेलन में वियतनाम व क्यूबा ने पोलपोट सरकार को बीजिंग व वाशिंगटन के बीच में फिरने वाली सरकार बताकर हेग सामरिन को शिखर सम्मेलन में बिठाने की कोशिश की, लेकिन मार्शल टीटो, वर्मा, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, बंगला देश, श्रीलंका, 'भासियान' देशों तथा अफ्रीका एवं लातीनी अमरीका के अधिकांश देशों ने वियतनाम द्वारा कंबुचिया को हडपे जाने की निन्दा की और हेग सामरिन सरकार का सम्मेलन में प्रतिनिधित्व एकदम अस्वीकार कर दिया। जबकि भारत ने किसी का पक्ष लेने के बजाय बीच का रास्ता अख्तियार किया और यह समाधान प्रस्तुत किया कि कंबुचिया की सीट खाली रखी जाये और इस विवाद का फैसला 1981 में नई दिल्ली में होने वाले गुट निरपेक्ष देशों के विदेश मन्त्रियों के सम्मेलन में किया जाये। इससे दोनों ही पक्षों को कंबुचिया में वास्तविक सरकार बनाने का समय मिल जायेगा। अन्त में यही प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

2. मिस्र की समस्या—मिस्र को गुट निरपेक्ष आन्दोलन से निकालने की याच सम्मेलन का दूसरा महत्वपूर्ण विवादास्पद मुद्दा था। अमरीकी व रूसी साम्राज्यवादियों की होड़ ने पश्चिम एशिया में सकट की जो स्थिति उत्पन्न कर दी और अरब देशों की बीच जो छूट के बीज बोये, वह उसी का परिणाम था। यह उभर कर हवाना सम्मेलन में सामने आया। मिस्र को तीसरी दुनिया से काटकर अमरीकी साम्राज्यवाद के सामने समर्पण के लिए विवश करने तथा अरब राष्ट्रों में मिस्र की साथ घटाने के सहल ही साम्यवादी पक्ष ने अरब राष्ट्रों की माग पर मिस्र को गुट निरपेक्ष आन्दोलन से निष्कासित करने का समर्थन किया। लेकिन आन्दोलन के सत्रण प्रतिनिधियों ने साम्यवादी गुट एवं अरब राष्ट्रों की इस योजना पर पानी फेर

दिया। इन राष्ट्रों में युगोस्लाविया, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, सेनेगल, गैबोन और कैमरून आदि अफ्रीकी देशों तथा अन्य कई देशों के प्रतिनिधियों ने मिस्र को गुट निरपेक्ष देशों के सम्मेलन से निकालने का विरोध किया। अतः गत्वा, यह तय हुआ कि एक तदर्थ समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1981 में नई दिल्ली में गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में मिस्र के मामले पर फैसला किया जायेगा। इस तरह से इस समस्या को फिलहाल टाल कर सम्मेलन को सफल बनाया गया।

3 दो महाशक्तियों के बीच तीसरी दुनिया का शक्ति प्रदर्शन—सम्मेलन में हुई घोषणाओं ने निर्णायक तौर पर यह स्पष्ट कर दिया कि गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ने दोनों महाशक्तियों विशेष तौर पर रुम के घड्यत्र को नाकाम करके अपना अलग अस्तित्व कायम रखा है और आन्दोलन पहले की तरह तीसरी दुनिया की उमरती हुई ताकत के रूप में मौजूद है। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में सम्मेलन में साम्राज्यवाद, प्रभुत्ववाद, उपनिवेशवाद, रणभेद, जातिभेद, ध्विस्तारवाद, नवउपनिवेशवाद तथा असमान सम्बन्धों की बढ़ाने वाली सभी शक्तियों के खतरो को रेखांकित किया गया और उन्हें चेतावनी दी गयी। सम्मेलन में नामीबिया और जिम्बाब्वे के मुक्ति संगठनों के सधर्षों को पूरा समर्थन दिया गया और फिलिस्तीनी जनता के सधर्ष में अपनी सहभागिता का प्रदर्शन किया गया।

4 आर्थिक समस्या—आर्थिक क्षेत्र में सामूहिक आत्मनिर्भरता कि दिशा में गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की प्रगति भी हवाना शिखर सम्मेलन की घोषणा से परिलक्षित होती है। क्यूबा द्वारा प्रस्तावित घोषणा के प्रारूप में आर्थिक सहयोग का जो खाका प्रस्तुत किया गया, वह परोक्ष रूप से तीसरी दुनिया के देशों को रुम के निकट पहले आर्थिक रूप से और बाद में समग्र रूप से लाने की व्यापक साजिश का एक अंग था। प्रारूप के इस हिस्से को भी प्रतिनिधियों ने बदल दिया और पारस्परिक आर्थिक सहयोग पर बल दिया, ताकि महाशक्तियाँ गरीब देशों को अपने चंगुल में न फँसा सकें। दोनों महाशक्तियों के विरुद्ध तीसरी दुनिया का जो मोर्चा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पर्व पर उभर रहा था उसका महत्वपूर्ण पहलू आर्थिक मोर्चाबन्दी था। हवाना सम्मेलन ने इस दिशा में सकारात्मक उपलब्धि अर्जित की।

सम्मेलन की घोषणाएँ एवं उपलब्धियाँ

हवाना शिखर सम्मेलन में निम्नांकित महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गयी—

1 सम्मेलन की समापन घोषणाओं में जातिवाद, वर्णभेद, उपनिवेशवाद, बहुराष्ट्रीय निगमों परमाणु एकाधिकार, सैनिक अहो तथा सैनिक गठबन्धनों आदि पर बड़ा प्रहार किया गया। कोलम्बो सम्मेलन की तुलना में इस सम्मेलन की सन्देशवाचक अपेक्षाकृत अधिक दृढ़ थी।

2 सम्मेलन में फिलिस्तीनियों के जोरदार समर्थन का प्रस्ताव पारित किया गया।

3 सम्मेलन की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि तेर-सम्बन्ध राष्ट्रों ने अन्य गुट निरपेक्ष राष्ट्रों को समझे दाम पर तेल देने की घोषणा की। साथ ही तेल निर्यात देशों में अफ्रीकी की मंत्री कि वे दक्षिण अफ्रीका को तेल की आपूर्ति बन्द न करें। लाइबेरिया की इस बात के लिए गराहना की गयी कि उसने अपने तेल

उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। पहले नाइजीरियाई तेल कम्पनी पर आरोप लगाया गया था कि वह दक्षिण अफ्रीका को तेल सप्लाई करती है।

4. सम्मेलन ने अमरीका की पहल से मिस्र एवं इजराईल के बीच हुए कैम्प डेविड समझौते की कड़े शब्दों में आलोचना की। इसके बावजूद मिस्र को गुट निरपेक्ष आन्दोलन की सदस्यता से वंचित नहीं कर सम्मेलन ने सयम का परिषय दिया। मिस्र को गुट निरपेक्ष आन्दोलन से निलम्बित करने की जरूरत देशों की मांग पर विचार का काम गुट निरपेक्ष देशों के न्यूरो पर छोड़ दिया गया।

5. सम्मेलन ने सभी गुट निरपेक्ष देशों से अपील की कि वे दक्षिण अफ्रीका के अश्वेतों के छापामार युद्ध का समर्थन करें। साथ ही दक्षिण अफ्रीका की नस्लवादी सरकार से सम्पर्क कायम रखने के लिए पश्चिमी देशों की भर्त्सना की गयी। इसके लिए घोषणा-पत्र में अफ्रीका, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, जापान, बेल्जियम, इटली, कनाडा, आस्ट्रेलिया और इजराईल की निन्दा की गई।

हवाना शिखर सम्मेलन की असफलताएँ

हालांकि गुट निरपेक्ष देशों का छठा शिखर सम्मेलन काफी हद तक सफल रहा, किन्तु उसकी असफलताएँ भी हैं। सम्मेलन में यह तय नहीं हो सका कि क्यूबिया की असली सरकार किसे माना जाये। शिखर सम्मेलन में क्यूबा जैसे सोवियत समर्थक साम्यवादी देश में आयोजित होने के कारण कुछ हद तक उसके बाईं ओर झुक जाने का आरोप न्यायसंगत माना जा सकता है। सम्मेलन में बहु-गुटता का बोलबाला रहा। इसमें अमरीका, रूस व चीन तीनों बड़ी शक्तियों के समर्थक गुट निरपेक्ष देशों के बीच आपसी खीचातानी विभिन्न कुछ मुद्दों को लेकर होती रही। गुट निरपेक्ष आन्दोलन के अपनी 'सीक' से हट जाने के कारण बर्मा ने इससे नाता तोड़ दिया। सम्मेलन अपने सदस्य राष्ट्रों की आपसी खीचातानी को ही सुलझाने में उलझा रहा। वह उनकी आम समस्याओं जैसे तेल, आपसी सहयोग, नई विश्व समाचार व्यवस्था, नई विश्व अर्थव्यवस्था, समुद्री सम्पदा के उचित एवं समान बँटव आदि के बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठा सका।

हवाना सम्मेलन में उक्त आलोचनात्मक मूल्यांकन के बावजूद यह कहा जा सकता है कि अनेक नाजुक उतार चढ़ाव के बावजूद जहाँ सम्मेलन के समापन तक गुट निरपेक्ष देशों द्वारा अन्ततः फूट न पड़ने देने की सफलता प्रशंसा योग्य है, वहीं इस आन्दोलन में ऐसी विभाजनकारी प्रवृत्तियाँ भविष्य में पुनः न उभरे, इसके लिए पहले से एहतिपाती कदम उठाना बहुत जरूरी है। हवाना सम्मेलन ने सदस्यों का ध्यान एक बार पुनः इस ओर आकर्षित किया कि आर्थिक सहकार की बात भले ही जोर-शोर से की जाये, लेकिन राजनीतिक यथार्थ की अनदेखा नहीं किया जा सकता। गुट निरपेक्ष आन्दोलन को सोवियत संघ के साथ 'स्वाभाविक रूप से जोड़ने' के क्यूबाई प्रयत्नों ने अन्य सदस्यों को खतर्क किया। इसी तरह कैम्प डेविड समझौते के बाद मिस्र के निष्कासन के प्रश्न ने इस समस्या के एक और पहलू को उजागर किया। विवादस्पद प्रश्न का परामर्श द्वारा समाधान ढूँढने के बदले उसे पहले सम्मेलन तक स्वांगित करने को ही राजनयिक सफलता मान लिया गया। इस प्रवृत्ति ने निश्चय ही गुट निरपेक्ष आन्दोलन की सम्भावनाओं को सीमित किया है।

1983 का नई दिल्ली शिखर सम्मेलन (The New Delhi Summit)

मार्च, 1983 में नई दिल्ली में गुट निरपेक्ष देशों का सातवाँ शिखर सम्मेलन हुआ। उसने 'काम कम, बातें ज्यादा' वाली कहावत चरितार्थ की। इसमें 101 देशों के प्रतिनिधियों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के बाद जो आम सहमति प्रकट की, वह 'बिना टोम मार की आम सहमति' थी। हालांकि यह सम्मेलन प्रकट रूप से असफल तो नहीं था, किन्तु इसमें टोम सफलता भी नहीं मिली थी।

शिखर सम्मेलन के समापन दिवस पर प्रमुख रूप से दो प्रकार की घोषणाएँ की गयीं—राजनीतिक और आर्थिक। राजनीतिक घोषणाओं में प्रमुख मसलें थे—अफगानिस्तान, कपुचिया, ईरान-इराक युद्ध, दियागो गार्मिया द्वीप, हिन्द महासागर में महाशक्तियों की सैनिक प्रतिस्पर्धा, फिमिस्तीनी राज्य की स्थापना, नई समाचार व्यवस्था, निरस्त्रीकरण आदि। आर्थिक घोषणाओं में मुख्य मुद्दे थे—उत्तर-दक्षिण सवाद, विकासशील देशों में पारस्परिक सहयोग, गुट निरपेक्ष देशों के बैंक की स्थापना इत्यादि।

इन महत्वपूर्ण, किन्तु जटिल मामलों पर आम सहमति में जो निर्णय लिए गये, उनके बारे में गुट निरपेक्ष देशों के प्रतिनिधि तो मन्तुष्ट होकर लौटे, सोवियत संघ ने भी उन पर मनोप प्रकट किया तथा अमरीका इस बारे में अधिक नाराज नहीं हुआ। जबकि गुट निरपेक्ष देश महाशक्तियों की गुटबाजी और शक्ति-मयर्ष की राजनीति के विरोधी हैं और महाशक्तियों में स्वामाविक तौर पर यह आशा नहीं की जा सकती है कि वे गुट निरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन की घोषणाओं पर मनोप प्रकट करें, किन्तु यह सब सम्भव हुआ—सम्मेलन द्वारा गुट निरपेक्ष आन्दोलन में कलह का टालने के लिए पारित किये गये प्रत्येक बचकाने और सैद्धान्तिक नारेबाजी की भाषा बोलने मनोश प्रस्तावों में।

सम्मेलन में सबसे अधिक कटु बहस राजनीतिक मामलों पर हुई। निरस्त्रीकरण के बारे में कहा गया कि हथियारों की होड़ समाप्त हो और हथियारों पर लक्ष्य किया जाने वाला विज्ञान घन विकास कार्यक्रमों पर लक्ष्य किया जाये। परमाणु हथियारों पर रोक लगाई जाय। सम्मेलन की घोषणा में इन बारे में कोई ठोस उपाय नहीं सुझाया गया, जिसमें निरस्त्रीकरण की अपील सहित नारेबाजी बनकर रह गयी।

अफगानिस्तान और कपुचिया में जर्मन मोवियन संघ और वियतनाम के सैनिक हटान के स्पष्ट उल्लेख के बारे में गुट निरपेक्ष आन्दोलन के सदस्य देश—लीबिया, इराक, अफगानिस्तान, क्यूबा, वियतनाम आदि ने कड़ा विरोध किया, जिससे मिस्र 'विदेशी सैनिक' हटान का ही उल्लेख किया गया। इन मोवियन-समर्थक गुट निरपेक्ष देशों ने सम्मेलन में कपुचिया की सीट खाली रखवाने के लिए जी-नोड प्रयास किया और सफल भी हुए। इस सफलता पर मोवियन संघ और उनके समर्थक गुट निरपेक्ष देशों ने राहत की साँस ली। सम्मेलन का काफी समय इस प्रश्न पर बर्बाद हो गया कि कपुचिया की सीट पर हेम सामरिन सरकार या राजकुमार मिहानुक की निर्वाचित सरकार को प्रतिनिधित्व दिया जाये। अन्त में सम्मेलन में यह स्थान रिक्त रखा गया, किन्तु आगे विचार के लिए यह मुद्दा एक तथ्य समिति को सौंप दिया गया।

सम्मेलन में सोवियत समर्थक गुट निरपेक्ष देशों के खंबे ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि वे गुट निरपेक्ष आन्दोलन को सोवियत खेमे के निकट ले जाना चाहते हैं। खासकर म्यूबा ने यह दोहराया कि सोवियत संघ की साम्राज्यवाद-विरोधी नीति होने के कारण वह गुट निरपेक्ष आन्दोलन के मूलभूत सिद्धान्त का ही समर्थक है; जबकि इस आन्दोलन का उद्देश्य सोवियत संघ और अमरीका जैसी महाशक्तियों की गुटबाजी का जमकर विरोध करना और सदस्य देशों को उनके कंधे साथे से बचाना है।

हालांकि सम्मेलन में सोवियत संघ का नाम लेकर उसे भला-बुरा नहीं कहा गया, किन्तु अमरीका को बिल्कुम नहीं बर्खा गया। दियागो गांसिया पर अमरीकी सैन्य ब्रह्मा बनाने की कटु आलोचना करते हुए यह द्वीप मारीजस को लौटाने की बात कही गयी। हिन्द महासागर के 'विसैन्यीकरण' पर आम सहमति का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया।

सम्मेलन में ईरान-इराक युद्ध पर पूरे एक दिन चर्चा हुई, किन्तु शान्ति प्रेमी गुट निरपेक्ष देश अपनी विरादरी के इन दोनों देशों को युद्ध रोकने के लिए सहमत नहीं कर पाये। हालांकि इराक शान्ति वार्ता के लिए तैयार हो गया, किन्तु ईरान अपनी जिद्द पर अड़ा रहा और उसने यहाँ तक कह डाला कि वह इस मामले का निबटारा युद्ध के मोर्चे पर ही करेगा। अन्ततः गुट निरपेक्ष देशों को सम्मेलन के घोषणा-पत्र में ईरान-इराक युद्ध समाप्त करने की अपील से ही संतोष करना पड़ा। यहाँ उल्लेखनीय है कि नई दिल्ली में आयोजित सातवाँ गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन सितम्बर, 1982 में इराक की राजधानी बगदाद में होने वाला था, किन्तु ईरान-इराक युद्ध के कारण इसे नई दिल्ली में करने का निर्णय किया गया था।

इस सम्मेलन में फिलिस्तीन राज्य की स्थापना, लेबनान पर इजराइली आक्रमण का विरोध और नई विश्व समाचार व्यवस्था की आवश्यकता पर आम सहमति प्रकट की गयी। म्यूबा की राजधानी हवाना में नई अन्तर्राष्ट्रीय समाचार व्यवस्था केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जो खबरों की दुनिया में विकसित देशों का एकाधिकार तोड़ने और विकासशील देशों की सही तस्वीर पेश करने के क्षेत्र में पहल करेगा। यो नई विश्व समाचार व्यवस्था का जारा खूब उठकर लगभग पिछले की स्थिति में आ गया है। यह सही है कि सवाद समितियों का बर्चस्व विकसित देशों के हाथों में न रहे और विकासशील देशों की अपनी भी कोई ऐसी व्यवस्था हो। लेकिन क्या सरकारी समाचार एजेंसियाँ निष्पक्ष और मानवीय मूल्यों के सहित अपना कर्तव्य निभा पायेंगी, यह जरूर संदेहास्पद है।

हालांकि सभी देशों ने समानता और न्याय पर आधारित नई विश्व अर्थ-व्यवस्था की स्थापना के प्रश्न पर आम सहमति प्रकट की, किन्तु इसे प्राप्त करने के लिए अपनाये जाने वाले साधनों पर गम्भीर मतभेद उभर कर सामने आये। इस कारण कोई ठोस रूपरेखा तैयार नहीं की जा सकी। यह भी सत्य नहीं हो पाया कि अन्तर्राष्ट्रीय संस्थापनों के दोहन व उपभोग तथा व्यापार के क्षेत्र में विकसित देशों के साथ विकासशील देशों की समान हिस्सेदारी पर विश्वव्यापी धार्ता तत्काल शुरू की जाये या ऋण-भार, व्यापार और सहायता जैसे मुद्दों को पहले उठाया जाये। इस पर भी कोई निर्णय नहीं हो पाया कि मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को समाप्त कर उनके स्थान पर नई संस्थाएँ बनायी जायें या फिर इन संस्थाओं के ढाँचे की

पुनर्रचना की जाये।

गुट निरपेक्ष देशों के बैंक की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया, किन्तु गुट निरपेक्ष समुदाय के अधिकतर सदस्य देश गरीब हैं, जिससे बैंक को मुचार्ज ढग से चलाने के लिए बोप को एकत्र करने की समस्या उठी। भारत, नाइजीरिया, जाम्बिया आदि ने कुछ आर्थिक योगदान देने की पेशकश की, किन्तु पर्याप्त धन देने में समर्थ तेल-निर्यातक देशों ने कोई रुचि नहीं ली। इन नव-घनाढ्य तेल-निर्यातक देशों का उक्त बैंक न होने में ही स्वार्थ निहित है, क्योंकि उनका पहले से ही इस्लामी देशों का बैंक है, जिससे वह अपना काम चला लेते हैं। स्पष्ट है कि वे अपने धन से अन्य देशों के आर्थिक कल्याण में पहल नहीं करना चाहते।

सम्मेलन में विकसित देशों के आपसी सहयोग कायम करने पर बल दिया गया। नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना का निर्णय लिया गया। विकासशील देशों में स्वास्थ्य पर भारत, मिस्र, पाकिस्तान और कुछ अन्य देशों के पास ऐसी प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक-तकनीकी ज्ञान है, जिससे वे विकासशील देशों के औद्योगिक विकास में काफी मदद कर सकते हैं। लेकिन क्या सभी विकासशील देश उक्त देशों की प्रौद्योगिकी को अपने आर्थिक ढाँचे में बिठा पायेंगे, यह सन्देहजनक है।

असल में, महाशक्तियों के प्रभाव-क्षेत्र के विस्तार की नीति ने गहराई से अनेक समस्याओं यथा, गुट निरपेक्ष देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एक-दूसरे से इतना भिन्न, प्रतियोगितात्मक और विकसित या समाजवादी देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ जकड़ दिया है कि कोई भी आर्थिक निर्णय गुट निरपेक्ष देशों के लिए समान रूप से लाभदायी नहीं कहा जा सकता। फिर इनकी अर्थ-व्यवस्थाएँ विकास के अलग-अलग चरणों में हैं। यदि इससे मुनाफ़ा इनकी अर्थव्यवस्थाओं को विभाजित किया जाये तो उनकी कम से कम दस श्रेणियाँ बनेंगी। इनमें एक ओर दुनिया के सम्पन्नतम तेल निर्यातक राष्ट्र हैं, वहीं दूसरी ओर तेल की मार से धूल-धूमरित अर्थव्यवस्थाएँ मौजूद हैं। एक ओर नव-औद्योगिक राष्ट्र हैं, तो दूसरी ओर समाजवादी अर्थ-व्यवस्था से जुड़े देश। जहाँ एक ओर पूर्णरूपेण कृषि प्रधान अर्थव्यवस्थाएँ हैं तो दूसरी ओर मिश्रित अर्थव्यवस्थाएँ। ऐसे में इस बात का सहज ही अन्दाजा लगाया जा सकता है कि इन सबके हितों को दृष्टि में रखते हुए नई विश्व अर्थव्यवस्था की स्थापना बिना टॉम और व्यवहारिक प्रणालियों के कैसे हो सकती है।

गुट निरपेक्ष आन्दोलन के विकास में नई दिल्ली जिसर सम्मेलन की उपरोक्त निराशाजनक तस्वीर के बावजूद न तो यह कहा जा सकता है कि यह आन्दोलन अप्रामाणिक हो चुका था और न ही यह भी कि नई दिल्ली जिसर सम्मेलन अमरपत्र रहा। वस्तुतः 101 सदस्य देशों वाले इस आन्दोलन में मतभेद होना स्वाभाविक था। इस आन्दोलन तथा नई दिल्ली सम्मेलन के सैद्धान्तिक निर्णयों का विश्व जनमत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। इससे विकसित देशों की घोषण प्रवृत्तियों पर नैतिक दबाव पड़ा। भारत ने गुट निरपेक्ष आन्दोलन की स्थापना, उसके विकास और उसे मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नई दिल्ली जिसर सम्मेलन के दौरान भारत के समीक्षा प्रस्तावों और विभिन्न मुद्दों पर उसके सन्तुलित रुख की सदस्य देशों ने सराहना की।

1986 का हरारे शिखर सम्मेलन (The Harare Summit)

यह शिखर सम्मेलन 1986 में जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में हुआ। कई वर्ष बाद शिखर सम्मेलन का आयोजन अफ्रीका महाद्वीप में हुआ और अन्तर्राष्ट्रीय राजनय का घन रंगभेद विरोधी, नव-उपनिवेशवाद विरोधी उन समस्याओं की ओर ज़बरन दिशाया गया, जिनसे अफ्रीकी देश घुसते रहते हैं, परन्तु जो आम तौर पर उपेक्षित रह जाते हैं। यो जिम्बाब्वे स्वयं न तो गुट निरपेक्ष आन्दोलन के अंगकों में एक है, और न ही अपनी आन्तरिक समस्याओं के कारण गुट निरपेक्ष आन्दोलन की गतिविधियों में उसने सक्रिय रूप से भाग लिया है। तथापि अपने स्वतन्त्रता संग्राम और दक्षिण अफ्रीका को नस्लवादी सरकार के विरुद्ध संघर्ष में उसकी भूमिका को देखते हुए उसको मेजबान बनाये जाने का निर्णय बिना ज्यादा मतभेद के लिया जा सका।

यहाँ एक और बात जोड़ने की जरूरत है। पहले गुट निरपेक्ष आन्दोलन के शिखर सम्मेलनों में युगोस्लाविया, भारत, निम्न जैसे प्रतिष्ठित अनुमती देशों का वर्चस्व देखने को मिलता था। हरारे शिखर सम्मेलन ने यह बात एक बार फिर स्पष्ट की कि सम्मेलन शिखर सम्मेलन की सफलता किन्ती अपेक्षाकृत कम दिशागत राजधानी में उसका आयोजन होने पर अधिक निरापद रह सकती है। अनेक अन्य सदस्यों की महत्वाकांक्षा मेजबानी के सन्दर्भ में उभरने लगी है। यह कहना अति-शयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि हरारे शिखर सम्मेलन में राजनय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इसी बात पर केन्द्रित रहा कि अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी के दावेदार अपना पक्ष मजबूत कर सकें, जैसे युगोस्लाविया व इण्डोनेशिया।

जहाँ तक ठोस राजनयिक उपलब्धियों का प्रश्न है, हरारे में अफ्रीकी सहामता कोष की स्थापना की घोषणा की गयी, जिसका उद्देश्य दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध सारा की जाने वाली पाबन्दियों के दुष्प्रभाव से निरीह अफ्रीकी राज्यों को बचाना है। इस प्रयत्न के पीछे काम कर रही मुख्य प्रेरणा यह थी कि सिर्फ घोषणाओं से कुछ हासिल होने वाला नहीं, बरिफ अफ्रीकी देशों के साथ अपना 'एकता' दर्शाने के लिए ठोस कार्यक्रम पर अमल आवश्यक है। आर्थिक सहकार के क्षेत्र में वांछित प्रगति के लिए दक्षिण-दक्षिण आयोग का गठन किया गया। भारत ने पहले इस पहल का विरोध किया था क्योंकि व्यापक सहमति के लिए इस तरह के प्रस्ताव में जितने समझौतों की जरूरत पड़ती है, उनमें वे लगभग निरर्थक ही जाते हैं। तथापि भारत ने अन्ततः अन्य गुट निरपेक्ष देशों के साथ एका बनाये रखा।

जहाँ तक अधूरे कार्यों की गूनी है, यह बहुत सम्बन्धी है। कम्युनिस्टों की सीट (जो हवाना से खाली चली आ रही थी) हरारे में भी खाली ही रखी गयी। इसी तरह अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप के विषय में कोई स्पष्ट राय बहुमत के रूप में नहीं रखी जा सकी। ईरान-इराक युद्ध के शमन के लिए कोई पहल सुझाने में भी हरारे सम्मेलन असफल रहा। हरारे सम्मेलन ने यह बात भी दर्शायी कि महाशक्तियों के बीच तनाव-अस्थिरता या निःसस्त्रीकरण संवाद में गुट निरपेक्ष आन्दोलन की कोई विशेष प्रासंगिकता नहीं रह गयी है। हरारे सम्मेलन में भाग लेने वाले अधिकांश प्रतिनिधि मण्डलों का प्रयत्न इस बात तक सीमित रहा कि उन्हें

व्यक्तिगत रूप से अममज्जम में डालने वाला कोई विवादास्पद प्रश्न, कोई विरोधी-शत्रु सम्मेलन की कार्यवाही के दौरान न उठाये। सम्मेलन के पूरे कार्यकाल में प्रत्यक्ष और परोक्ष राजनय की मुद्रा इसी कारण प्रतीकारात्मक रही और किसी रचनात्मक सहकारी कार्यमूची की रूपरेखा प्रस्तुत नहीं की जा सकी।

ये तो अनेक प्रस्ताव पारित हुए, परन्तु यह प्रतिश्रिया अनुष्ठान पूरा किया जाने वाली मुद्रा में जारी रही। हाँ, सिर्फ़ इस अमरीकी-घोषणा ने कि वह जिम्बाब्वे को दी जाने वाली आर्थिक सहायता बन्द कर रहा है, मेजबान राष्ट्र को सहायन ओढ़ने का मोका दिया। गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों को घमका कर चुप कराने के लिए छायाद इतना काफी था, क्योंकि इसके ठीक बाद पेरू में हुए 'गेट' (GATT) सम्मेलन में अधिकतर गुट-निरपेक्ष प्रतिनिधि दुबके-सहमे अमरीकी इच्छाओं के अनुकूल आचरण करते रहे। दिल्ली से हारारे तक आन्दोलन की सदस्य सख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई। भले ही छुटपुट छोटे देश स्वाधीन हुए, जैसे खुर्द और अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण देश न्यूजीलैंड पुराने सैनिक सगठनों से निवृत्त आये। ऐसा जान पड़ता है कि अब सदस्य राष्ट्रों के लिए गुट-निरपेक्ष सम्मेलन राष्ट्रीय हित-साधन का उपकरण नहीं समझा जा सकता।

1989 का वेलप्रेड शिखर सम्मेलन

गुट-निरपेक्ष देशों का नवां शिखर सम्मेलन एक बार फिर युगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में 4 से 7 मितम्बर, 1989 के दौरान हुआ। इसमें 102 देशों ने भाग लिया। इसमें गुट-निरपेक्ष देशों ने अमीर देशों से अपील की कि वे गरीब देशों पर बड़ रहे बाहरी ऋण के भीषण सफट के हल में सहयोग करें। उन्होंने चार देशों की 'परिम पहल' का समर्थन करते हुए कहा कि विश्व-शान्ति और सुरक्षा विकास सम्बन्धी समस्याओं से सीधी जुड़ी हुई है। सम्मेलन ने पूर्ण निराशापूर्ण, विकसित देशों में अपनी सहयोग बढ़ाने, दक्षिण अफ्रीका में रणभेद की समाप्ति और बहुमन्यक अन्तर्गत की सरकार की स्थापना, अफगान सफट के हल और फिलिपीनियों को उनके अधिकार दिलाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

सम्मेलन से इस बात की बड़ी चर्चा रही कि 1961 में जहाँ गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का जन्म हुआ, वही 28 वर्ष बाद घूम-फिरकर यह जमघट फिर पहुँचा है। परन्तु यह तर्क आन्दोलन के साम्यवादी महत्व को नहीं दर्शाता, बल्कि अनुष्ठान-मूलक समारोह-श्रेय को ही उजागर करता है। यों इसमें जो प्रस्ताव पारित किए गये, उनमें गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के आर्थिक पक्ष को अधिक स्पष्ट और सुस्तर करने के दावे किये गये, किन्तु दुर्भाग्यवश, कोई ठोस प्रगति नहीं हो सकी। इसका कारण स्पष्ट है। विद्यते दो-जीन शिखर सम्मेलन ऐसी परिस्थितियों में आयोजित हुए, जहाँ स्वयं मेजबान देश की अपनी आन्तरिक राजनीतिक स्थिति अस्थिर रही है। परन्तु यह है कि मेजबान राष्ट्र शिखर सम्मेलन को राजनीतिक दिशा देता है। लेकिन आज के युगोस्लाविया की कोई तुलना टोटोकाम्बो युगोस्लाविया से नहीं की जा सकती। विद्यते दो दशकों में उसकी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का काफी अवमूल्यन हुआ है। 1989 में वेलप्रेड में शिखर सम्मेलन आयोजित कर युगोस्लाविया का अहम भले ही गन्तुष्ट हुआ हो, किन्तु इसमें गुट-निरपेक्ष आन्दोलन को कोई साम नहीं पहुँचा। इस सम्मेलन में अमीर देशों में गरीब देशों पर बड़ रहे बाहरी ऋण की विकट समस्या के

हल पर जोर तो अवश्य दिया परन्तु इस सिलसिले में स्वयं कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलनों का तुलनात्मक मूल्यांकन (Non-Aligned Summits : A Comparative Assessment)

गुट-निरपेक्ष देशों के उक्त नौ शिखर सम्मेलनों पर तुलनात्मक दृष्टिपात करने से स्पष्ट है कि 1961 में आयोजित बेलग्रेड सम्मेलन में गुट-निरपेक्ष राष्ट्र होने के मानदण्डों को पारिभाषित किया, जबकि 1964 में काहिरा और 1970 में लुसाका में आयोजित सम्मेलनों ने उस पारिभाषित मानदण्ड को ठोस आधार प्रदान किया। काहिरा सम्मेलन की प्रमुख विशेषता यह रही कि उसने शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति में प्रगति हेतु प्रभावकारी कदम उठाने पर बल दिया। लुसाका (1970) एवं अल्जीरिस (1973) के सम्मेलनों के दौरान गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की आकृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आये। इस दौरान गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि से उन्होंने विश्व राजनीति में प्रभावकारी भूमिका अदा करने की अन्तर-वस्तु को महसूस किया। गुट-निरपेक्ष नीति के प्रसार एवं प्रचार में अब केवल भारत, युगोस्लाविया एवं मिस्र का नेतृत्व ही प्रभावकारी नहीं रहा, बल्कि राजगिरा एवं जाम्बिया जैसे छोटे-छोटे राष्ट्रों ने भी अत्यन्त दिलचस्पी से हिस्सा लेना आरम्भ किया। अल्जीरिस सम्मेलन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इसमें जनरीका एवं रुस के मध्य तनाव-सौमित्र्य (détente) की नीति एवं निरास्त्रीकरण की दिशा में उनके प्रयासों का हार्दिक स्वागत किया गया।

1976 के कोलम्बो सम्मेलन में राजनीतिक घोषणाओं के साथ-साथ आर्थिक एवं अन्य प्रकार की घोषणाएँ भी की गयीं। अन्य घोषणाओं में समानता व व्यापक पर आधारित नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा नई अन्तर्राष्ट्रीय समाचार व्यवस्था के लिए 'समाचार सत्र' (न्यूज पूल) की स्थापना का निर्णय लिया गया। इस प्रकार कोलम्बो सम्मेलन ने राजनीतिक कार्यों के अलावा गुट-निरपेक्ष आन्दोलन को आर्थिक, सांसाजिक, सांस्कृतिक दिशाओं की ओर प्रवृत्त किया। इसके बाद 1979 के हुबाना शिखर सम्मेलन ने विश्व राजनीति की अनेक समस्याओं पर विचार करने के साथ-साथ गुट-निरपेक्ष देशों में आपसी सहयोग स्थापित करने की दिशा में अनेक घोषणाएँ कीं। हुबाना सम्मेलन इसलिए विवादास्पद बन गया कि क्यूबाई नेता फिदेल रास्त्रो ने जोरदार शब्दों में मांग सामने रखी कि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन को समाजवादी राज्यों को अपना 'स्वाभाविक सन्धि-मित्र' मान लेना चाहिए और इस सम्बन्ध को औपचारिक रूप देना चाहिए। इसके विरोध में यर्मा ने गुट-निरपेक्ष आन्दोलन छोड़ दिया तथा कम्युनिज्म के प्रश्न पर चीन तथा सोवियत संघ के पक्षधर तत्वों के बीच गरमा-गरम वाद-विवाद हुआ। कुल मिलाकर, इसी गुट निरपेक्ष आन्दोलन की दृष्टि प्रमिश हुई।

दिल्ली शिखर सम्मेलन (1983) की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उसने हुबाना में पैदा हुए असन्तुलन को समाप्त किया और गुट-निरपेक्ष आन्दोलन को वस्तुतः निरपेक्ष बनाया। अनेक समस्याओं के समाधान की खोज को स्थगित करने की परम्परा हटाने सम्मेलन (1986) में भी जारी रही। इस प्रवृत्ति को दुर्भाग्यपूर्ण ही मानना चाहिए कि सम्मेलन-स्वयं को देखते हुए नाम सूची भी

क्षेत्रीय रंग में रंग जानी है। ऐसी स्थिति में अधिकतर सदस्यों की सार्वभौम भागीदारी का अवकाश कम रहता है। बेलग्रेड शिखर सम्मेलन 1989 ने अमीर देशों से गरीब देशों पर बढ़ रहे बाहरी ऋण की विपत्त समस्या के हल पर जोर अवश्य दिया, किन्तु इस मिलसिले में स्वयं कोई ठोस बंदम नहीं उठाया।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में शीत युद्ध के सकटपूर्ण दौर में गुट-निरपेक्षता की अवधारणा और गुट-निरपेक्ष आन्दोलन ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित किया। उपनिवेशवाद-विरोध, नस्लवाद-विरोध, निशस्त्रीकरण, नवोदित राष्ट्रों के आर्थिक सहकार जैसे विषयों में गुट-निरपेक्ष देशों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। अन्तर्राष्ट्रीय सत्रों में मध्यस्थता के द्वारा गुट-निरपेक्ष देशों ने तनाव-शैथिल्य का मार्ग प्रशस्त किया। ऐसे अनेक अवसर हैं, जब गुट-निरपेक्ष देशों की राजनयिक पहल ने महाशक्तियों के अन्तर-सम्बन्धों या संयुक्त राष्ट्र सभ के नियम-कलाप पर अपनी छाप छोड़ी। परन्तु हाल के वर्षों में ऐसा जान पड़ता है कि विस्तार-प्रसार के कारण गुट-निरपेक्ष आन्दोलन ने अपनी एकरूपता गंवायी है और उसके प्रभाव में कमी हुई है। बेलग्रेड सम्मेलन तक गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का सत्यागत रूप स्पष्ट नहीं था और नायब यही इसका सबसे सफल व रचनात्मक दौर रहा। निवारण शिखर सम्मेलनों के आयोजन, विदेश मंत्रियों के सम्मेलन, स्फूरो की स्थापना और सदस्य सत्त्या में विस्तार ने पारस्परिक प्रतिस्पर्धा और सर्वांग राष्ट्रीय हितों के टकराव को बढ़ावा दिया है। अब यह देखना है कि गुट-निरपेक्ष देश कैसे इन चुनौतियों का सामना करते हैं और सामयिक अन्तर्राष्ट्रीय राजनयिक दबावों को देखते हुए गुट-निरपेक्षता को आवश्यकतानुसार परिष्कृत-परिभाषित करते हैं या नहीं?

गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की उपलब्धियाँ (Non-Aligned Movement - Achievements)

द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद महाशक्तियों की शक्ति-मन्तुलन की राजनीति को अस्वीकार करते हुए कुछ राष्ट्रों ने गुट-निरपेक्ष नीति अपनायी। यह एक आन्दोलन का रूप धारण कर चुकी है तथा इसे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक 'महत्वपूर्ण ताकत' के रूप में माना जाने लगा। इसकी उपलब्धियाँ निम्नांकित हैं—

(1) विश्व की सेमेबन्दी के समुह से बचाना—गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों ने महाशक्तियों की सेमेबन्दी की राजनीति में सम्मिलित होने से मना कर दिया। जैसा कि प्रो० एम० एम राजन मानते हैं कि 'उन्होंने अमरीकी और सोवियत आदर्शों अपने ऊपर धोये जाने का विरोध किया और अपनी राष्ट्रीय प्रवृत्ति के अनुसार विकास के अपने राष्ट्रीय मार्गों और पद्धतियों का आविष्कार किया। इस तरह भारत ने अपने 'समाज के समाजवादी ढाँचे' को अपनाया और अरब राष्ट्रों ने 'अरब समाजवाद' को। यह बात राजनीतिक संस्थाओं, सामन और प्रशासन प्रणालियों के मद्दम में लागू होनी है।¹ डा० सतीश कुमार ने गुट निरपेक्ष देशों द्वारा महाशक्तियों की सेमेबन्दी की राजनीति को अस्वीकार करने के बारे में कहा है कि 'अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के रूपान्तरण (Transformation) के बारे में गुट निरपेक्ष आन्दोलन की देन है कि जहाँ तक विश्वव्यापी मन्तुलन का सम्बन्ध है, उसको उमने पूरी तरह

अस्वीकार कर दिया है।' इस प्रकार गुट निरपेक्ष देश महाशक्तियों की सेमेवन्दी से बाहर निकल आये और उन्होंने गुट निरपेक्ष आन्दोलन में सम्मिलित होकर सेमेवाजी को राजनीति पर पानी फेर दिया। अब: विश्व के अधिकांश देश महाशक्तियों की सेमेवन्दी के जंगल से बच गये।

(2) अफ्रो-एशियाई, लातीनी अमरीकी और केरिबियायी देशों की स्वतन्त्रता मिलना—1961 के बेलग्रेड सम्मेलन द्वारा गुट निरपेक्षता की निर्धारित परिभाषा के अन्तर्गत साफ लिखा गया है कि इस नीति का पालन करने वाला हर राष्ट्र अफ्रीका, एशिया, लातीनी अमरीका और केरिबियायी क्षेत्रों में औपनिवेशिक शक्तियों के खिलाफ चल रहे राष्ट्रीय मुक्ति संग्रामों का समर्थन करेगा। गुट निरपेक्ष देशों ने एकजुट होकर हर एक मंच से इन देशों में चल रहे मुक्ति संग्रामों का समर्थन किया। इससे उन्हें आजादी मिलने में काफी आसानी रही, क्योंकि औपनिवेशिक शक्तियाँ विश्व के इतने बड़े समुदाय की आलोचना एवं विरस्कार का शिकार समवे समय तक नहीं रहना चाहती थीं।

(3) विश्व शान्ति एवं सुरक्षा की स्थापना में सहायक—गुट निरपेक्ष देशों का हमेशा यही प्रयास रहा है कि राष्ट्र आपसी विवादों को शान्तिपूर्ण समाधानों के द्वारा हल करें, युद्ध से नहीं। इसके लिए उन्होंने समय-समय पर अनेक सत्रों के दौरान युद्धरत राष्ट्रों पर नैतिक दबाव डालकर यह समझाने बुझाने की कोशिश की कि वे शान्तिपूर्ण तरीकों से विवादों का समाधान ढूँढ़ें। विश्व शान्ति एवं सुरक्षा की स्थापना के लिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की हरेक कार्यवाही की प्रभावशाली बनाने के लिए उसका सबैव भरपूर समर्थन किया। इस प्रकार, गुट निरपेक्ष आन्दोलन विश्व शान्ति एवं सुरक्षा स्थापित करने में अत्यन्त सहायक सिद्ध हुआ।

(4) राष्ट्रवाद की रक्षा एवं स्वतन्त्र विदेश नीति के निर्माण को प्रोत्साहन—गुट निरपेक्ष नीति का जन्म ही महाशक्तियों द्वारा अन्य देशों को उनके अधीनस्थ बनाने की नीति के विरुद्ध हुआ था। गुट निरपेक्ष आन्दोलन ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि वह महाशक्तियों द्वारा राजनीतिक दबावों से जुड़ी अधिक या अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं करेंगे। वे किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय संकट पर दबावमुक्त होकर अपना विचार व्यक्त करेंगे। इस प्रकार उन्होंने छोटे राष्ट्रों में राष्ट्रवाद की भावना की रक्षा एवं स्वतन्त्र विदेश नीति निर्माण को पूरा प्रोत्साहन दिया।

(5) साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नव-उपनिवेशवाद एवं रंगभेद की समाप्ति—गुट निरपेक्ष आन्दोलन ने हमेशा ही बड़ी शक्तियों की साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी एवं रंगभेद की नीति का घोर विरोध किया। इससे वह विश्व में बड़ी शक्तियों की सत्ता के खिलाफ जनमत बनाने में सफल रहा। इसी का परिणाम है कि वर्तमान में बड़ी शक्तियों की उक्त धाल काफी हद तक नाकाम रही।

(6) अनेक अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर एकजुट होकर आवाज उठाना—गुट निरपेक्ष देशों ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए केवल अपने ही मंच से नहीं, बल्कि अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मंचों का भी उपयोग किया। मसलन, संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्र-मण्डल, अफ्रीकी एकाता संगठन, 'अंकटाड' (UNCTAD), समुद्री कानून सम्मेलन में अनेक मुद्दों पर एकजुट आवाज उठाकर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने में काफी हद तक सफलता अर्जित की। जे० डब्ल्यू बर्टन के अनुसार—'उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ को

छोटे राष्ट्रों के बीच शान्ति कायम रखने वाले संगठन में रूपान्तरित करने में सहामता दी, जिसमें छोटे राष्ट्र बड़े राष्ट्रों पर कुछ नियन्त्रण रख सकें।¹

(7) महाशक्तियों द्वारा गुट निरपेक्षता के महत्व को स्वीकार करना—जब आरम्भ में कुछ राष्ट्रों ने गुट निरपेक्ष नीति अपनायी तो महाशक्तियों ने उन्हें गालियाँ दी एवं आलोचना की। एक तरफ अमरीकी विदेश मंत्री जॉन फॉस्टर डलेस ने इस नीति को 'अनैतिक' एवं 'अदूरदर्शितापूर्ण' माना। उसका मानना था कि गुट निरपेक्ष राष्ट्र दोनों ही खेमों में से किसी भी खेमे में न मिलकर दोनों ही खेमों से आर्थिक सहायता का लड्डू खाना चाहते हैं, जो अनैतिक एवं अदूरदर्शितापूर्ण है।² दूसरी तरफ सोवियत संघ ने गुट निरपेक्ष देशों द्वारा उसके खेमे में नहीं मिलने के कारण उन्हें 'सूज़ीबादी अमरीकी दलाल' की उजाड़ा दी। लेकिन अब इस बारे में दोनों महाशक्तियों का रव बदला है। वे गुट निरपेक्षता के महत्व को स्वीकार करने लगी हैं। भूमलन, सोवियत संघ के रुढ़िवाद ने माना कि 'देश तटस्थ हो सकते हैं, व्यक्ति चाहे तटस्थ न हो सकते हो।' अमरीकी विदेश सचिव हेनरी किमिज़र ने 1974 की भारत-यात्रा के दौरान भारतीय गुट निरपेक्षता की मूरी-भूरी प्रशंसा की। अब जब भी कभी गुट निरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन होते हैं तो अमरीका और सोवियत संघ दोनों उनकी सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ भेजते हैं। इस प्रकार महाशक्तियों ने गुट निरपेक्ष आन्दोलन के महत्व को स्वीकार किया है।

(8) तीसरी दुनिया में आपसी सहयोग कर आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त करना—गुट निरपेक्ष देशों ने धीरे-धीरे बहुमुखी क्षेत्रों में आपसी सहयोग करने का रास्ता अपनाया। नई बिजु अर्थव्यवस्था, नई समाचार व्यवस्था, तेल का उचित दामों पर उपलब्ध होना आदि क्षेत्रों में व्यवहारिक आपसी सहयोग कर उन्होंने गुट निरपेक्ष देशों द्वारा आत्मनिर्भरता बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में उनके विकास के लिए बड़ी शक्तियों पर निर्भरता घटेगी और वे आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर होंगे।

(9) सदस्य संख्या में अपार वृद्धि—जब भारत, युगोस्लाविया और मिस्र ने पहल कर गुट निरपेक्ष नीति अपनाना आरम्भ किया तो शीघ्र ही इण्डोनेशिया, श्रीलंका, कम्बुजिया ने भी इसका अनुसरण किया। इसके बाद धीरे-धीरे कई देश गुट निरपेक्ष आन्दोलन में सम्मिलित हो गये। जहाँ गुट निरपेक्ष देशों के पहले शिखर सम्मेलन में 25 पूर्ण देशों ने भाग लिया वहीं बाहिरा में 47, गुमाका में 56, अल्जीरिया में 76, कोलम्बो में 86 तथा हवाना में 95, नई दिल्ली और हवाई में एक ही से अधिक पूर्ण सदस्य राष्ट्रों ने शिखर सम्मेलनों में भाग लिया। इन शिखर सम्मेलनों में पूर्ण सदस्य राष्ट्रों के अलावा अनेक देशों को पर्यवेक्षण के रूप में, अनेक राष्ट्रीय मुक्ति संगठनों, संयुक्त राष्ट्र तथा जैसे अनेक अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों को पर्यवेक्षण एवं अतिथि के रूप में आमन्त्रित किया गया। इस प्रकार गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की सच्चात्मक शक्ति में विस्तार होना गया।

¹ J W Burton, *International Relations A General Theory*, (London, 1965), 230-31

² 'This (Non alignment) has increasingly become an obsolete conception and except under very exceptional circumstances it is an immoral and short sighted conception'—John Foster Dulles

गुट निरपेक्ष आन्दोलन की असफलताएँ (Non-Aligned Movement : Failures)

गुट निरपेक्ष आन्दोलन के इस ऐतिहासिक विक्षेपण से कदापि यह अर्थ नहीं लिया जाना चाहिये कि उसने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सदैव सफलताएँ ही अर्जित की है, असफलताएँ नहीं। वस्तुतः गुट निरपेक्ष आन्दोलन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में आशा-तीत रूप से सफल नहीं हो पाया है। इन असफलताओं को निम्नांकित रूप में दिया जा सकता है—

1. महाशक्तियों की खेमबन्दी का प्रवेश—आरम्भ में तो गुट निरपेक्ष देशों ने महाशक्तियों की खेमबन्दी का खटकर विरोध किया, किन्तु धीरे-धीरे उनका उत्साह ढीला पड़ता गया। इससे महाशक्तियों को गुट निरपेक्ष आन्दोलन के भीतर खेमबन्दी को प्रवेश करवाने का अवसर मिल गया। यह भी एक दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि स्वयं गुट निरपेक्ष आन्दोलन के भीतर कुछ सदस्य राष्ट्र ऐसे हैं जो इस आन्दोलन की कार्यवाही के समय किसी न किसी महाशक्ति की नीति का पक्ष लेते हैं। मसलन, केरिबियायी क्षेत्र या क्यूबा, जितने सितम्बर, 1979 में हवाना में हुए शिखर सम्मेलन में सोवियत संघ को गुट निरपेक्ष देशों का 'स्वामाधिक मित्र' स्वीकार करने की वकालत की। दूसरी तरफ दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र में 'आसियान' नामक क्षेत्रीय संगठन के देश अमरीका का पक्ष लेते रहे हैं। इस प्रकार गुट निरपेक्ष आन्दोलन के भीतर महाशक्तियों की खेमबन्दी के प्रवेश को असफलता ही माना जा सकता है।

2. सैन्य संगठनों एवं सन्धियों से जुड़े राष्ट्रों को गुट निरपेक्ष आन्दोलन में प्रवेश—1961 के बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में यह तय किया गया कि जो राष्ट्र महाशक्तियों द्वारा प्रवर्तित सैन्य संगठनों एवं सन्धियों से जुड़े रहेंगे, उन्हें गुट निरपेक्ष आन्दोलन में सदस्यता नहीं दी जायेगी। परन्तु आगे चलकर इस निर्णय का उल्लंघन किया गया। मसलन, अगस्त, 1976 में कोलम्बो में गुट निरपेक्ष देशों का जो शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें पूर्णचान, फिलीपींस और रूमानिया को अतिथि के रूप में भाग लेने की अनुमति मिली। ये देश किसी न किसी तरह सैन्य-सन्धियों से जुड़े रहे हैं, फिर भी गुट निरपेक्ष आन्दोलन के विद्यमान दरवाजे से उन्हें प्रवेश दिया गया। अर्थात् पर्यवेक्षक के रूप में आमन्त्रित कर उनके द्वारा सदस्यता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया गया। गुट निरपेक्ष आन्दोलन की शुद्धि कायम रखने के दृष्टिकोण से इसे न्याय-संगत नहीं ठहराया जा सकता।

3. गुट निरपेक्ष देशों द्वारा आपसी समस्याओं में ही बक्त बर्बाद करना—असल में, गुट निरपेक्ष देशों ने बाहरी विश्व की गम्भीर चुनौतियों से पूँजने पर पर्याप्त ध्यान न देकर आपसी समस्याओं में ही बक्त बर्बाद किया है। मसलन, सितम्बर, 1979 में गुट निरपेक्ष देशों के छठे शिखर सम्मेलन का उदाहरण ही लें। इसमें भिन्न को गुट निरपेक्ष आन्दोलन से बाहर निकालने, कम्प्यूचिया में पोल पोड या हेंग सामरिन में से अगली सरकार किस माना जाये आदि आपसी खोजतान सारे शिखर सम्मेलन पर छापी रही। परिणामस्वरूप वे उनकी आम समस्याओं जैसे तेल, नई समाचार व्यवस्था, नई विश्व अर्थव्यवस्था, समुद्री सम्पदा के उचित एवं समान दोहन आदि समस्याओं के बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठा सके।

4. राष्ट्रीय भुक्ति संग्रामों को नीतिक समर्थन नहीं—हालांकि आरम्भ से

सभी गुट निरपेक्ष देशों ने अफ्रो-एशियाई, लानीनी अमरीका एव केरेबियाई क्षेत्रों में चल रहे राष्ट्रीय मुक्ति संग्रामों का स्पष्ट शब्दों में समर्थन किया है, लेकिन भौतिक समर्थन के अभाव में अनेक देशों को आजादी प्राप्त करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और वे तत्त्वे सघर्ष के बाद स्वतन्त्र हो सके। आज भी दक्षिण अफ्रीका में बहुमध्यक कालों के समर्थन की गुट निरपेक्ष देश स्पष्ट शब्दों में घोषणा करते हैं, किन्तु भौतिक समर्थन के अभाव में उन्हें सत्ता अब तक प्राप्त नहीं हुई है। इसीलिए 1979 में जाम्बिया के प्रधानमंत्री ने अपनी भारत यात्रा में दौरान यहाँ की सरकार को भौतिक समर्थन देने की अपील की थी।

5. भौतिक एवं निहित घोषणाएँ व्यापक और व्यावहारिक काम कम—समय-समय पर गुट निरपेक्ष देश विश्व शान्ति एवं सुरक्षा की अनेक सम्मेलन-चौड़ी आदर्शवादी घोषणाएँ करते रहे हैं। यह ठीक है, किन्तु उनकी प्राप्ति के लिए ठोस एवं व्यावहारिक कदम उठाने भी उनमें ही जरूरी हैं। भूमतन, नई समाचार व्यवस्था की स्थापना के लिए उन्होंने आपसी सहयोग में 'न्यूज गूल' की स्थापना की घोषणा तो कर दी, किन्तु उसकी स्थापना के बाद उस 'न्यूज गूल' से रिलीज होने वाली खबरों को खरीदने का प्रस्ताव आया तो उन्होंने पीठ दिखा दी। इस प्रकार घोषणाएँ तो वे अनेक कर देते हैं, किन्तु ठोस एवं व्यावहारिक काम की बात आने पर हिच-किचाने लगते हैं।

6 गुट निरपेक्षता की अनेक विस्मये पैदा हो जाना—गुट निरपेक्ष आन्दोलन के मध्य राष्ट्रों में भी अनेक प्रकार की गुट निरपेक्षता की विस्मये पैदा हो गयी हैं। इन पर एक विद्वान ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि 'इससे गुटबद्धता की तरह गुट निरपेक्षता की कोई अव्यन्त-एकान्वित सत्ता नहीं रह गयी है।' भूमतन, बर्मा में गुट निरपेक्षता के बजाय महाशक्तियों एवं बड़ी शक्तियों से दूर रहकर अलगवावाद (Isolationism) की नीति का पालन किया है। कुछ राष्ट्रों ने महाशक्तियों के साथ मैत्री एवं सहयोग-मन्त्रि के नाम पर मैत्रिक व्यवस्थाओं वाली मन्त्रियाँ कर दीं। भारत और मिश्र ने सोवियत संघ के साथ ऐसी मन्त्रियाँ कीं, जबकि कई गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ने ऐसा नहीं किया। इन अनेक विस्मयों के उत्पन्न होने को गुट निरपेक्ष आन्दोलन की असफलता ही माना जायेगा।

गुट निरपेक्ष आन्दोलन : नवीन चुनौतियाँ एवं समस्याएँ (New Challenges and Problems before the Movement)

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गरीब व मध्योच्च देशों के सामने प्रमुख चुनौतियाँ और समस्याएँ यह थीं कि वे महाशक्तियों की जेमेन्डी में कैसे दूर रहे, स्वतन्त्र विदेश नीति का निर्माण कैसे करें तथा बिना राजनीतिक दबाव के महाशक्तियों से अधिक व तकनीकी मदद कैसे प्राप्त करें? किन्तु तृतीय युद्ध के अवमान और देवान युग के आगमन के साथ इन चुनौतियों और समस्याओं के स्वरूप में काफी परिवर्तन आ गया। तत्पश्चात् नए तृतीय युद्ध के दौर में भी काफी-कुछ बदल जाने से इनमें और बदलाव आया। अब गुट निरपेक्ष देशों के सामने जो प्रमुख चुनौतियाँ और महत्वपूर्ण समस्याएँ मूढ़ बाएँ खड़ी हैं, वे मध्ये में इस प्रकार हैं—नव उपनिवेशवाद, तेन की बीमारी में वृद्धि, उत्तर-दक्षिण गवाद, परमाणु ऊर्जा का शान्तिपूर्ण उपयोग,

समुद्री सम्पदा का समुचित दोहन, दक्षिण-दक्षिण सहयोग आदि। यही नहीं, कई विद्वानों ने गुट निरपेक्ष आन्दोलन की नवीन परिस्थितियों में प्रासंगिकता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। उनका कहना है कि यह आन्दोलन अब निष्प्राण सा हो गया है।

प्रखर भारतीय पत्रकार प्रफुल्ल बिदवर्द ने तो कुछ समय पहले गुट निरपेक्ष आन्दोलन के देहान की पिछित घोषणा तक कर डाली, जिससे प्रोफेसर एम० एग० राजन जैसे प्रतिष्ठित विद्वान बीखला गये। प्रोफेसर राजन ने बिदवर्द के तर्कों के जवाब में यह दशानि का प्रयत्न किया कि गुट निरपेक्ष आन्दोलन अभी भी सार्थक, मजबूत और महत्वपूर्ण है। वह निराश्वरीकरण और नई विश्व अर्थव्यवस्था की तलाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। किन्तु यदि वस्तुनिष्ठ दृष्टि से देखें तो इसमें नया कुछ नहीं है। ये तर्क नारे हैं, जिनको आदत से मजबूर विशेषज्ञ चात्तू रखे हुए हैं। यही स्थिति कमोवेश विदेश मन्त्रालयों के नौकरशाहों की है, जिनकी जुबान पर गुट निरपेक्षता का मुहावरा इस तरह चड़ा है कि इनकी तुलना घूँटे रद्दू तौति से ही की जा सकती है। नई चुनौतियों का सामना करने के लिए नया कुछ सोचने की सान्ध्य उनमें नहीं। लाइओ युद्ध, जर्मनी का एकीकरण और सोवियत संघ व पूर्वी यूरोप में नाटकीय घटनाक्रम के बाद बिदवर्दवापी स्तर पर कहीं भी गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता नजर नहीं आती।

भारत एवं गुट-निरपेक्ष नीति (India and non-aligned policy)

गुट-निरपेक्ष नीति एवं भारत में विशेष सम्बन्ध रहा है। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के प्रमुख जनक नेहरू, नासिर एवं टीटो थे। भारत भी ओर से गुट-निरपेक्ष आन्दोलन को दिशा देने में नेहरू जी का विशेष योगदान रहा। मतः अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रारम्भ से ही गुट-निरपेक्षता का दृष्टिकोण होने के कारण भारत की चर्चा करना अत्यन्त प्रासंगिक है। गुट-निरपेक्षता नीति का अर्थ विश्व के किसी भी गुट के साथ द्विपक्षीय सम्बन्धों के आधार पर सैनिक समझौतों में भाग न लेना है। इस नीति का पालन करने वाले राष्ट्र जहाँ एक ओर गुटवादी की विश्व राजनीति में बिलग रहते हैं, वही दूसरी ओर विश्व-शांति और सुरक्षा में प्रगति हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संघठनों को भरपूर मदद देते हैं। इसका अर्थ कदापि 'तटस्थता' की नीति नहीं है। जैसा कि हम बता चुके हैं, भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरू जी ने गुट-निरपेक्ष नीति का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा था—'यदि स्वतन्त्रता का हनन होगा, न्याय की हत्या होगी अथवा कहीं आक्रमण होगा तो वहाँ हम न तो आज तटस्थ रह सकते हैं और न भविष्य में तटस्थ रहेंगे।' यह नीति गुट-निरपेक्ष देशों की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उठने वाली दैनंदिन की ज्वलन्त समस्याओं पर उनके गुणानुसार अपनी स्वतन्त्र प्रतिक्रिया को व्यक्त करने के योग्य बनानी है।

भारत द्वारा गुट-निरपेक्ष नीति अपनाने के कारण

भारत ने आजादी के बाद तत्कालीन राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद यह निर्णय किया कि वह गुट-निरपेक्षता की नीति अपनावेगा। इस निर्णय के प्रमुख कारण निम्नावृत्त हैं—

1 भारत द्वारा साम्यवाद या पूंजीवाद जैसे वैचारिक पक्षों में न पड़ने की इच्छा—स्वतन्त्रता के बाद भारत ने पाया कि विश्व वैचारिक तौर पर साम्यवादी एवं पूंजीवादी विचारधारा के आधार पर बँटना शुरू हो गया है। वह नहीं चाहता था कि ऐसे वैचारिक पक्षों में अनावश्यक रूप से पड़ा जाये। उसका विचार था कि हरेक राष्ट्र मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार उचित विचारधारा को अपनाये।

2 भारत द्वारा किसी भी महाशक्ति का मोहरा न बनने की इच्छा—भारत ने पाया कि विश्व राजनीति दो भागों में विभाजित हो चुकी है। अमरीका एवं सोवियत संघ के नेतृत्व में दो भीमकाय अर्थात् पश्चिमी एवं पूर्वी विश्व राजनीति रणमंच पर उद्भूत हुए। यदि भारत किसी भी गुट में सक्रिय रूप से सम्मिलित हो जाता तो उसका घातक के एक मोहरे के समान उस गुट के द्वारा मनचाहा दुरुपयोग किया जा सकता है। नेहरू जी ने अपने 7 मिनटम्बर, 1946 के प्रसारण में एकदम स्पष्ट रूप से कहा कि 'उन्हें एक-दूसरे के विरुद्ध गुटबद्ध वर्गों की शक्ति-प्रधान राजनीति में अलग रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में इसकी परिणति विश्व युद्धों में हुई और भविष्य में और भी बड़े स्तर पर विनाश हो सकता है।'

3. आर्थिक दृष्टि से भारत द्वारा गुट-निरपेक्ष नीति अपनाना उचित—प्रो० जे० वॉशिंग्टन का मानना है कि 'भारत जैसे विकसारीय देश के' संदर्भ में, जहाँ आर्थिक विकास को प्रमुखता दी जाती है, जब विकास के लक्ष्य, इसका स्वरूप और तरीका निर्धारित किये जाते हैं, तब आर्थिक पक्ष विदेश नीति निर्धारण में एक निर्णायक तत्त्व होता है।' आजादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था एकदम कमजोर थी, क्योंकि ब्रिटिश शासन के दौरान उसका खूब शोषण किया गया। आर्थिक एवं तकनीकी क्षेत्रों में अविश्वसनीय होने के कारण आवश्यक था कि वह दोनों महाशक्तियों अमरीका एवं रूस में आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्राप्त करे। गुट-निरपेक्ष नीति अपनाकर यह सहायता प्राप्त की जा सकती है।

4 स्वतन्त्र विदेश नीति-निर्माण की इच्छा—सम्बन्धी राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन और ब्रिटिश शासन के दौरान आर्थिक शोषण एवं राजनीतिक दमन के कारण भारतीय स्वतन्त्रता सेनानी यह महसूस कर चुके थे कि 'स्वतन्त्रता' का वास्तविक अर्थ क्या होता है और देश के वैदेशिक सम्बन्धों में निर्णय लेते समय स्वतन्त्र विदेश नीति-निर्माण की कितनी आवश्यक है। स्वतन्त्र विदेश नीति निर्धारण की इसी इच्छा के कारण भारत ने गुट-निरपेक्ष नीति अपनायी।¹

5 भारत विश्व शान्ति एवं सुरक्षा का गुजारी—भारत युद्ध, अशांति एवं गरीबी का देश रहा है। उन्होंने जिन्दगी भर विश्व शान्ति एवं सुरक्षा के अप्रयुक्त बनकर काम किया। आजादी के बाद भी भारत अपने आदर्शों पर ठहरा रहा और विश्व शान्ति और सुरक्षा का मन्दिर उगम गुट-निरपेक्ष नीति को अपनाने की घोषणा करके दिया।

चूँकि भारत ने सर्वप्रथम गुट-निरपेक्ष नीति अपनायी, इसी कारण वह

¹ जबकि प्राप्त अनुभवों के अनुसार ए० के० दामोदरन का मानना है कि गुट निरपेक्ष नीति अपनाना भारत की आवश्यकता थी। उसके आधार का स्वाधिनारी महत्वाकांक्षी देश न तो किसी महाशक्ति का विरुद्ध बन सकता है और न ही कोई महाशक्ति उसे आसानी से नियंत्रित-अनुशासित कर सकती है। इस निमित्त से वे निम्नलिखित विशेषण हैं लिए देखें—A. P. Misra and A. K. Damodaran (ed.) *Dynamics of Non-Alignment* (Delhi, 1983)

विशेष रूप में दोनों महाशक्तियों—अमरीका एवं सोवियत संघ की कोपभाजनता व अविश्वास का शिकार बना। प्रारम्भ में जहाँ अमरीका के विदेश सचिव जान फोर्स्टर इलेस में गुट-निरपेक्ष नीति को 'अनैतिक' बताते हुए भारत को दोनों महाशक्तियों के साथ मठबन्धन करने वाले देश के रूप में चित्रित किया, वहीं दूसरी ओर सोवियत शासक स्टालिन ने भारत को 'पूँजीवादी देशों के पिछलग्गू' की मजा दी। किन्तु जब भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर ईमानदारी से उपनिवेशवाद, पूँजीवाद, साम्राज्यवाद, नस्लवाद, नव-उपनिवेशवाद की झूले शब्दों में आलोचना की, कोरिया संकट में दोनों महाशक्तियों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कर आलोचना की, विश्व के दोनों गुटों 15 दिन का राजनीतिक दबाव के तकनीकी एवं आर्थिक मदद स्वीकार की तथा साम्यवादी चीन की समुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यता दिलाने के लिए आवाज बुलन्द की तो अमरीका और सोवियत संघ दोनों ने भी अपना पुराना भारत-विरोधी रुख बदल दिया तथा गुट निरपेक्ष नीति की महत्ता और उपयोगिता को सिद्धान्ततः महसूस किया।

भारत पर चीनी आक्रमण और गुट निरपेक्षता (Chinese Aggression and Non-alignment)

भारतीय गुट निरपेक्ष नीति की चर्चा करते समय भारत पर 1962 में चीन द्वारा अचानक फौजी हमला करने के फलस्वरूप इस नीति की प्रासंगिकता के साथ-साथ इस बात का विश्लेषण भी जरूरी है कि क्या भारत गुट निरपेक्षता के रास्ते से हटा गया? जब चीन ने भारत पर वर्बर हमला किया तो सोवियत संघ जैसे हमारे पारम्परिक मित्र ने यह तर्क देकर अपने हाथ खींच लिये कि भारत हमारा मित्र है तो चीन हमारा भाई। उसने भारत को किसी भी प्रकार उस हमले में बचाने में इन्कार कर दिया। उधर चीन एक रूस की प्रतिद्वन्द्वी शक्ति अमरीका ने भी युद्ध के दौरान भारत की ठोस मदद नहीं की। उसने उल्टे भारत पर यह दबाव डाला कि यह अमरीका द्वारा प्रवर्तित सैनिक मठबन्धनों में सम्मिलित हो जाये या फिर अमरीका की परमाणु क्षमता स्वीकार कर ले, अर्थात् भारत पर आक्रमण होने पर अमरीका उसकी रक्षा करेगा। इन्हीं तर्कों से प्रभावित होकर भारतीय संसद के अनेक सदस्यों ने यह मत व्यक्त किया था कि यदि भारत किसी महाशक्ति के सैन्य मगठन से जुड़ा होता तो उसे चीनी वर्बर हमले के दुर्दिन नहीं देखने पड़ते। इसी प्रकार के तर्क भारत द्वारा गुट-निरपेक्ष नीति अपनाये जाने की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं।

अमल में, गुट निरपेक्ष भारत पर किसी शत्रु देश द्वारा सैनिक आक्रमण करने से किसी नीति की अमर्यसता नहीं मानी जा सकती। इस बात की भी कोई गारन्टी नहीं कि संयुक्त संघटन में सम्मिलित होने पर प्रथम महाशक्ति सुरक्षा की गारन्टी देकर उसे अत-प्रतिफल व्यवहार में भी पूरा कर सके। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान का ही उदाहरण लें। 1965 के भारत-पाक युद्ध के दौरान अमरीका ने उसके द्वारा प्रवर्तित 'सेन्टो' एवं 'मिण्टो' के सदस्य होने पर भी गुट निरपेक्ष भारत के विरुद्ध अपने गुट में अपने पाकिस्तान को शस्त्रीय मदद भी रोक दी। गुट-निरपेक्ष नीति का अर्थ गुटबानी में शामिल न होकर स्वतन्त्र विदेश नीति का निर्धारण करना है। संकट की घड़ियों में भी स्वतन्त्र नीति निर्माण गुट निरपेक्षता की परिचायक है।

बुद्ध आलोचकों का यह मानना है कि 1962 में भारत पर चीनी हमले के कारण भारत ने दूसरे देशों से पड़ती बार सैनिक सहायता स्वीकार की। इससे पहले भारत अन्य देशों या महाशक्तियों से तकनीकी एवं आर्थिक मदद ही लेता था, सैन्य सामग्री नहीं। इस कारण भारत ने गुट निरपेक्षता का रास्ता छोड़ दिया। वास्तव में यह आलोचना निरर्थक एवं अमंगल है। जैसा कि प्रो० के० पी० मिश्र ने लिखा है—‘भारत द्वारा चीनी आक्रमण के समय दूसरे देशों से सैनिक सामग्री स्वीकार करने से उसकी गुट निरपेक्षता नीति में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं हुआ, जिसके दो कारण हैं—(i) साम्यवादी चीन के आक्रमण का मुकाबला करने के लिए सैन्य सामग्री की सहायता दोनों गुटों में ली गई, (ii) गुट निरपेक्ष नीति का अर्थ बड़ापि यह नहीं है कि वह राष्ट्र अपनी सुरक्षा की उपेक्षा करे। अनेक देशों ने विगत में विदेशों से सैनिक सहायता ली है और अब भी गुट निरपेक्ष है। युगोस्लाविया, इथियोपिया, घाना, लीबिया, अफगानिस्तान आदि के उदाहरण इस मत को पुष्टा करते हैं।’

भारत पर चीनी आक्रमण का हमारी गुट निरपेक्षता पर यह सकारात्मक प्रभाव डाल रहा कि पहले हम बिना शर्त और सुरक्षा के आदेश की बात अधिक करने से, परन्तु चीनी बर्बर हमले से मोह भग होने के कारण भारत ने सुरक्षा तैयारियाँ तेज कर दी। यह आदेशवाद एवं यथार्थवाद का अच्छा मिश्रण है। जब चीनी हमले के बाद अनेक आलोचकों ने भारतीय गुट-निरपेक्ष नीति की आलोचना की तो नेहरू जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ‘यदि भारत गुट निरपेक्षता छोड़ देता है तो यह भयंकर नैतिक विपन्नता होगी।’ इस प्रकार स्पष्ट है कि चीनी हमले के बावजूद भारत गुट निरपेक्ष रास्ते पर डटा रहा।

भारत-मोवियत सहयोग व मैत्री सन्धि तथा गुट निरपेक्षता (Indo-Soviet Treaty and Non-alignment)

9 अगस्त, 1971 को भारत और मोवियत संधि के बीच की गयी मैत्री व सहयोग सन्धि को लेकर सम्पूर्ण विवाद चलता रहा है कि इससे भारतीय गुट निरपेक्ष नीति का उल्लंघन हुआ है या नहीं? इस विवाद का मूल्यांकन करने से पहले यहाँ हम सन्धि के पूर्व भारत के समक्ष तत्कालीन बाहरी चुनौतियों का जिक्र कर देना प्रासंगिक होगा। 1970 में पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सरकार (याहिया खान) के बर्बर दमन के खिलाफ विद्रोह हुआ और स्वतन्त्र देश की माँग उठी। पाकिस्तानी दमन से पीड़ित पूर्वी पाकिस्तान में करीब 90 लाख लोग भारत में शरणार्थी के रूप में आ गये। एक तरफ जहाँ भारत सरकार इन शरणार्थियों के आवास, भोजन एवं कपड़ों की व्यवस्था कर रही थी, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध सैनिक युद्ध छेड़ने की जोरदार तैयारियाँ शुरू कर दी। अमरीका ने घोषणा की कि वह भारत-पाक युद्ध में निष्क्रिय नहीं रहेगा और उसने चीन से घोषणा करवा दी कि वह भारत-पाक युद्ध में भारत के विरुद्ध पाकिस्तान की सहायता करेगा। इस प्रकार भारतीय सुरक्षा के समक्ष सम्पूर्ण चुनौती उपस्थित हो गयी। ऐसी अवस्था में भारत-मोवियत मैत्री एवं सहयोग सन्धि पर हस्ताक्षर हुए।

इस सन्धि के बारे में मुख्यतः दो प्रकार की प्रतिक्रियाएँ हुईं। पश्चिमी शक्तियों ने कहा कि भारत ने इस सन्धि पर हस्ताक्षर करते गुट निरपेक्ष नीति का

उल्लंघन किया है। दूसरी तरफ भारतीय एवं सोवियत शासकों और विद्वानों के मत में इस सन्धि से भारतीय गुट निरपेक्ष नीति का किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। उनका मानना है कि यह सन्धि भारत और सोवियत संघ के बीच बढ़ती मैत्री व सहयोग की प्रतीक है। पहले इस सन्धि के पश्चिमी आलोचकों के तर्कों का उल्लेख कर लिया जाय

सन्धि से गुट निरपेक्षता का उल्लंघन ?

(क) सन्धि का स्वरूप सैनिक है—हालांकि इस सन्धि का नाम भारत-सोवियत मैत्री व सहयोग सन्धि किया गया है (अर्थात् सैनिक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया), परन्तु इसमें सैनिक व्यवस्थाएँ हैं। मसलन, इस सन्धि के नवें अनुच्छेद में कहा गया है कि दोनों देशों में से किसी पर भी अन्य देश द्वारा आक्रमण करने के दौरान वे एक-दूसरे से सम्पर्क करेंगे। अतः इस सन्धि का स्वरूप सैनिक माना जाना चाहिए।

(ख) सन्धि से भारतीय विदेश नीति की स्वतन्त्रता को ठेस पहुँची है—भारत-सोवियत मैत्री व सहयोग सन्धि से भारतीय विदेश नीति निर्माण में स्वतन्त्रता को ठेस पहुँची है, क्योंकि इसमें सोवियत संघ द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप करने की गुंजाइश छोड़ी गयी है। सन्धि के नवें अनुच्छेद में दोनों में से किसी भी एक देश पर आक्रमण के दौरान सम्पर्क साधने की व्यवस्था के फलस्वरूप भारत के सोवियत संघ की दया पर निर्भर हो जाने का सतरा बना रहेगा।

(ग) सन्धि से भारत द्वारा सोवियत संघ विरोधी राष्ट्रों से सम्बन्ध सुधारने में काफी कठिनाइयाँ उठानी पड़ेंगी—इस सन्धि से भारत को सोवियत संघ के विरोधी राष्ट्रों (जैसे साम्यवादी चीन और अमरीका) से सम्बन्ध सुधारने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस सन्धि ने सोवियत-विरोधी अमरीका और साम्यवादी चीन के मस्तिष्क में अनावश्यक रूप से यह सन्देह एवं गलतफहमी पैदा कर दी कि भारत अब गुट-निरपेक्ष न रहकर सोवियत संघ की ओर में चला गया, अर्थात् वह पश्चिम एवं चीन विरोधी है। इससे भारत को अमरीका और चीन से सम्बन्ध सुधारने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके मस्तिष्क में भारत की सोवियत-सम्पर्क ध्रुवि स्थापित हो गयी।

(घ) सन्धि से भारत का सोवियत संघ की ओर झुकाव स्पष्ट होता है—गुट निरपेक्ष नीति का अर्थ होता है—विश्व की किसी भी महाशक्ति की ओर झुकाव न हो। भारत ने सोवियत संघ के साथ मैत्री व सहयोग सन्धि पर पर हस्ताक्षर करके अपनी विदेश नीति का सोवियत संघ की तरफ झुकाव अर्थात् महाशक्तियों की प्रतिद्वन्द्विता में भाग लेना स्वीकार कर लिया है। यह 1961 के गुट निरपेक्ष देशों के बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में तय किये गये सिद्धान्तों के खिलाफ है।

(ङ) सन्धि के द्वारा भारत ने गुट निरपेक्ष रास्ता छोड़ अन्य गुट निरपेक्ष देशों द्वारा ऐसा करने का मार्ग प्रस्तुत किया है—भारत ने सिद्धान्ततः इस सन्धि का मैत्री व सहयोग सन्धि नाम रखा, किन्तु व्यवहार में इसमें सैनिक व्यवस्थाएँ हैं। इस बात का अन्य गुट निरपेक्ष राष्ट्र भी अनुसरण करेंगे और जब उन पर गुट निरपेक्षता के उल्लंघन का आरोप लगेगा, तब वे भारत का उदाहरण देकर कहेंगे कि हमारी भी उसके समान मैत्री व सहयोग सन्धि है, सैनिक नहीं। इस प्रकार गुट निरपेक्ष नीति

की विगुहता का पतन होगा ।

सन्धि से गुट निरपेक्षता का उत्पन्न नहीं

वस्तुतः, भारत-मोबियत मैत्री व सहयोग सन्धि द्वारा भारत ने गुट निरपेक्ष नीति के सिद्धान्तों या तत्वों का किसी भी प्रकार का उत्पन्न नहीं किया । पश्चिमी शासक भारत-मोबियत मैत्री व सहयोग सन्धि को जान बूझकर बदनाम करते रहें हैं । उन्हीं दो देशों के बीच बरतनी मैत्री एवं सहयोग पमन्द नहीं है । इस सन्धि के पक्ष में निम्नांकित तर्क दिये जाते हैं—

1 यह सैनिक नहीं, मैत्री व सहयोग सन्धि है—भारत-मोबियत सन्धि सैनिक नहीं, बल्कि मैत्री व सहयोग सन्धि है । जैसा के० जार० नारायणन (चीन में भूतपूर्व भारतीय राजदूत) ने कहा है— यह सन्धि कोई सैनिक संगठन नहीं है, जिसमें भारत की सुरक्षा और विदेश नीतियों का मोबियत सन्धि से अधीन कर दिया गया है । इसके सहज रूप में भारत में सैनिक अड़्डे जयवा सेनाएँ रखने का अधिकार नहीं दिया गया है । भारत को मोबियत सन्धि से जो शस्त्र एवं सैनिक उपकरण मिलते हैं, वह एक व्यापारिक मोदा है जिसमें प्रत्येक चीज की कीमत चुकाई जाती है । इस प्रकार स्पष्ट है कि इस सन्धि के द्वारा दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग का बढ़ाया गया है । अतः इसे सैनिक सन्धि कहकर भारत पर गुट निरपेक्ष मार्ग से हटने का आरोप लगाना बेईमानी है ।

2 सन्धि में गुट निरपेक्षता के महत्व को स्वीकार किया गया है—स्वयं भारत-मोबियत मैत्री व सहयोग सन्धि के चौथे अनुच्छेद के अन्तर्गत भारतीय गुट निरपेक्ष नीति के महत्व को स्वीकार किया गया है । इसका बाद इस सन्धि की आलाचना बनसुकी ही प्रतीत होती है । इसमें साफ जाहिर है कि इस सन्धि पर हस्ताक्षर करके भारत ने गुट निरपेक्ष नीति का किसी भी प्रकार में उत्पन्न नहीं किया है ।

3 भारत विदेश नीति निर्धारण में स्वतन्त्र है—भारत-मोबियत मैत्री व सहयोग सन्धि पर हस्ताक्षर करने के बावजूद भारत सरकार अपने देश की विदेश नीति निर्धारण प्रक्रिया में पूर्णतः स्वतन्त्र है । इस सन्धि में कहीं यह नहीं कहा गया है कि भारत विदेश नीति निर्धारण में मोबियत सन्धि या दबाव मानने को बाध्य है । अतः भारत अपने विदेश नीति निर्धारण में स्वतन्त्र है तो उस पर गुट निरपेक्ष मार्ग में हटने का आरोप लगाना बेकार है । आज तब व्यवहार में एक भी ऐसी घटना प्रकाश में नहीं आयी है, जिसमें भारत सरकार ने मोबियत दबाव को मान लिया हो ।

4 गुट निरपेक्षता माध्य नहीं, साधन है—भारत द्वारा मोबियत सन्धि के माध्य मैत्री व सहयोग सन्धि पर हस्ताक्षर करने पर आलोचकों ने गुट निरपेक्ष नीति का गलत अर्थ लगाकर आरोप लगाये । वस्तुतः गुट निरपेक्षता भारतीय विदेश नीति के लिए माध्य नहीं, साधन है । अर्थात् भारत ने अपनी विदेश नीति के उद्देश्यों जैसे राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा एवं आर्थिक विकास को पाने के लिए गुट निरपेक्षता को साधन के रूप में अपनाया । जैसा कि प्रा० एम्० एम्० राजन ने कहा है—'गुट निरपेक्षता अन्य किसी भी नीति की तरह तत्काल भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने का साधन है ।' गुट निरपेक्षता भारतीय विदेश नीति के राष्ट्रीय

हितो का साथ नहीं, बल्कि साथन है।

‘भारत-सोवियत मैत्री व सहयोग सन्धि तथा गुट निरपेक्षता’ के विवाद के पक्ष तथा विपक्ष दिये गये उपरोक्त तर्कों के बाद भारत द्वारा गुट निरपेक्ष नीति का उल्लेखन करने का ‘हाँ’ या ‘न’ में जवाब देना अत्यन्त कठिन हो जाता है। फिर भी यह कहा जा सकता है कि 1971 में भारत द्वारा सोवियत संघ के साथ मैत्री व सहयोग सन्धि के अन्तर्गत दोनों में से किसी भी देश पर आक्रमण की अवस्था में ‘एक-दूसरे से सम्पर्क स्थापन’ का प्रावधान रखकर भारतीय गुट निरपेक्ष नीति के इतिहास में एक अभूतपूर्व तत्व का समावेश किया। यह तत्व अनेक विद्वानों की आलोचना का शिकार बना तथा गुट निरपेक्ष आन्दोलन में भी इसको विशेष सम्मान के साथ नहीं देखा गया है।

नवीन धुनीतियाँ और भारतीय गुट निरपेक्षता

शीत युद्ध के अन्तर्धान के बाद देतात और नए शीत युद्ध के दौर में गुट निरपेक्ष आन्दोलन के समक्ष कई नवीन धुनीतियाँ और समस्याएँ खड़ी हो गईं। परमाणु ऊर्जा का शान्तिपूर्ण उपयोग, नव उपनिवेशवाद, तेल संकट, उत्तर-दक्षिण दक्षिण-पश्चिम सहयोग, आदि जैसे मामले विश्व राजनीति में हावी हो गये। भारत ने इन मसलों पर विकासशील देशों के हितों की भगुवाई की, किन्तु उसे आर्थिक सफलता ही मिल पायी। भारत ने ईरान-इराक युद्ध एकजुट के लिए सुलह प्रयास किये किन्तु कोई कामयाबी नहीं मिली। इसी प्रकार कुवैत को लेकर इराक और बहुराष्ट्रीय सेना के बीच छिड़े युद्ध को रोकवाने में भारत की भूमिका नगण्य रही।

देतात और नए शीत युद्ध के दौर में अमरीका व सोवियत संघ के बीच टकराव घटाने व सम्बन्ध-सुधार के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप ही बदलने लगा। पिछले कुछ वर्षों में पोलैंड, हंगरी, रूमानिया आदि में साम्यवादी शासन के खिलाफ जन-आन्दोलनों, सोवियत संघ में ‘पेरिस्टोपका’ व ‘ग्लामनोस्त’ नीति के अनुसरण, जर्मनी के एकीकरण, सेन्टो व बारसा पेन्ट के विघटन आदि जैसे परिवर्तनकारी घटनाक्रमों ने गुट निरपेक्ष आन्दोलन के महत्व को कम किया। सीधेपक्ष संघ के विघटन तथा सिन्ड्रेट हुए नए राजनीतिक ढाँचे तथा कुवैत मसले को लेकर इराक पर बहुराष्ट्रीय सेना की जीत के बाद अमरीका एकमात्र महाशक्ति के रूप में बचा है। इन नई परिस्थितियों में गुट निरपेक्ष आन्दोलन अपने मसलों को न तो उही ढंग से परिभाषित कर कोई नया अभिधान चला पाया है और न ही अपनी अन्य प्राथमिकताएँ निर्धारित कर सका है। इन विपक्ष परिस्थितियों के साथ-साथ भारत में पिछले कुछ वर्षों में जारी राजनीतिक अस्थिरता-अस्मिरता ने भी गुट निरोध आन्दोलन में भारत की अक्षमता की काफी कम कर दिया। गुट निरपेक्ष आन्दोलन पहले ग्ले ही सेजस्वी, प्रभावशाली और जुझारू रहा हो, किन्तु आज वह निष्प्राण-सा प्रतीत होता है। भारतीय गुट निरपेक्षता भी इन नए प्रभावों-घटनाक्रमों से अप्रभावित नहीं रह सकी है।

छठा अध्याय

देतांत (तनाव-शैथिल्य) एवं विश्व राजनीति

द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद अमरीका और रूस महाशक्तियों के रूप में उभरे। इनके साथ ही विश्व में द्विपक्षीय प्रणाली के अन्तर्गत दोनों महाशक्तियों के इर्द-गिर्द अन्य राष्ट्र जमा होने लगे। अपने प्रभाव-क्षेत्र के विस्तार एवं अधिक में अधिक देशों को अपने क्षेत्र में बंदोर लाने के लिए दोनों महाशक्तियों को सैनिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सैद्धान्तिक क्षेत्रों में एक-दूसरे के आमने-सामने लड़ा होना पड़ा। टकराव की इस स्थिति को 'शीत युद्ध' की संज्ञा दी गयी। वैसे यह कहना सम्भव नहीं कि शीत युद्ध का दौर कब समाप्त हुआ, किन्तु 1960 के दशक के आरम्भ से ही दोनों महाशक्तियाँ यह अनुभव करने लगी थी कि शीत-युद्ध दोनों के लिए यदि हानिकारक नहीं तो लाभप्रद भी नहीं था। आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक सम्बन्धों में उन्हें एक-दूसरे की कहीं न कहीं आवश्यकता हो ही जाती थी।

अनएक अपने सम्बन्ध सुधारने की दृष्टि में दोनों ने तनाव में लचीलापन परिचित किया। इस प्रक्रिया में 'देनात' अर्थात् 'तनाव-शैथिल्य' का युग आरम्भ हुआ, जिसने अमरीका और रूस के बीच 'संवाद' की प्रक्रिया शुरू की। यह द्विपक्षीय सैनिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल की दिशा में अत्यन्त उपयोगी साबित हुई और जनें जनें इस प्रक्रिया ने दोनों महाशक्तियों की नीतियों में स्थायी रूप प्राप्त कर लिया। इस प्रक्रिया के प्रभावस्वरूप एक ओर जहाँ दोनों की प्रतिस्पर्धा में कुछ कमो आयी, वहीं आर्थिक सुरों पर दोनों एक-दूसरे को सहयोग करने पर भी प्रसन्न हो गये। कुल मिलाकर यद्यपि तनाव-शैथिल्य के बावजूद सीमरी दुनिया के देशों में कमो-बकी दोनों महाशक्तियाँ अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए एक-दूसरे के आमने-सामने खड़ी हो गयी, किन्तु दोनों के बीच सीधे टकराव और परमाणु युद्ध की सम्भावना में अबतक ही कमो आयी। यही 'तनाव-शैथिल्य' की वह प्रक्रिया है, जिसे 'देनात' (Detente) का नाम दिया गया।

देनात की परिभाषा

(Definition of Detente)

'देनात' एक फ्रांसीसी शब्द है। इसका अर्थ तनाव में कमो या मिथिलता है। आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में इसका व्यापक प्रयोग अमरीका और सोवियत संघ के बीच तनाव में कमो या मिथिलता, उसमें बढ़ती मित्रता तथा सहयोग में लगाया जाता है। देनात की परिभाषा के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विशेषज्ञ एकमत नहीं है। कुछ प्रमुख विशेषज्ञों, लेखकों और जानकारों द्वारा दी गयी परिभाषाएँ निम्नांकित हैं

अमरीका के भूतपूर्व विदेश मन्त्री हेनरी किस्सिजर के अनुसार 'परमाणु युग में मैनिफेस्ट शक्ति और राजनीतिक एक्ट से व्यावहारिक शक्ति में जो असंगति है वह देतात है।'¹ अर्थात् उन्होंने देतात को पारस्परिक परमाणविक सर्वनाश के आतंक से मुक्ति के रूप में अभिव्यक्त किया है।

जार्जी ऐरावाटोव के अनुसार 'देतात से अभिप्राय है—अन्तर्राष्ट्रीय स्थितियों एवं वास्तविकताओं में समझौता।'²

ए० पी० राणा के अनुसार 'यदि देतात की व्याख्या महाशक्तियों के व्यवहार के केवल सहयोगी स्वरूप के अर्थ में की जाये तो वह वर्तमान वास्तविकता का मिथ्या वर्णन होगा, उसका प्रतिबिम्ब या स्पष्टीकरण नहीं।'³

देतात की परिभाषा एवं अर्थ के बारे में विद्वानों में इसी भ्रममय की स्थिति को व्यक्त करते हुए इलिम ज्योल ने लिखा है कि 'कभी-कभी इसे नीति के रूप में तथा किसी अन्य समय इसका प्रयोग पूर्व तथा पश्चिम में कम तनाव वाले सम्बन्धों के रूप में विवेचन करने में प्रयोग किया गया। कभी-कभी क्यूबाई मिसाइल सबूट की सोवियत नीति में निर्णायक मोड़ माना जाता है, जिसने आशिक परमाणु परीक्षण रोक सन्धि तथा परमाणु प्रसार रोक सन्धि (Non Proliferation Treaty) का मार्ग प्रशस्त किया। कभी-कभी सुल्चेव के शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्त से देतात का काल निर्धारित किया जाता है।'

यन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में रुचि रखने वाले विद्वानों, विक्षेपज्ञों एवं लेखकों की तो विसात ही बना, स्वयं देतात के जनकों में इसकी परिभाषा भी अर्थ के बारे में मतभेद हैं। मसलन 28 दिसम्बर, 1973 को अमरीका के तत्कालीन विदेश मन्त्री हेनरी किस्सिजर ने एक पत्रकार सम्मेलन में कहा कि 'हम नहीं कहते हैं कि देतात परेनू व्यवस्थाओं की अनुकूलता पर आधारित है। हमारी मान्यता है कि सोवियत संघ तथा चीन के मूल्य एवं विचारधाराएँ विरोधी तथा कभी-कभी हमसे दानुतापूर्ण हैं। हम नहीं कहते कि हमारे राष्ट्रीय हित एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। परन्तु हम यह जरूर कहेंगे कि यह पूर्वकाय की अपेक्षा अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण में एक मूलभूत परिवर्तन है।' किस्सिजर आगे कहते हैं कि 'आचरण के नियम तथा आपसी हितों के सम्बन्ध की स्थापना के लिए एक जाग्रत प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त अधिकारियों के हरेक स्तर पर संचार-सम्बन्ध हैं, जो संकट की घड़ियों में सम्भावित दुर्घटना या भूत-चूक को कम करता है।' अमरीका देतात के बारे में इसी दृष्टिकोण से सोचता है।

दूसरी तरफ सोवियत संघ द्वारा देतात के बारे में कही गयी बातों की लिया जाये। सोवियत संघ में देतात शब्द की 'मिरनाई सोमुशेस्ट वोद्यावी' अर्थात् 'शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व' के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। सोवियत शान्ति के जनक लेनिन ने भी शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्त की परिकल्पना की थी। सोवियत विदेश नीति निर्धारक देतात को इसी सिद्धान्त से जोड़ते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं।

¹ Kissinger sees the *raison d'être* of détente in the discrepancy that obtains, in the nuclear age, between military strength and politically usable power.

² Georgy Arabatov describes détente as accommodation to the new realities of the international situations.

³ A. P. Rana, *Détente and Non-alignment*, 192.

मिस्त्र, 1973 में सत्तासीन सोवियत नेता ब्रेझ्नेव ने घोषणा की कि 'दो देशों में बढ़ता तनाव-सौधित्व अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की एक नई व्यवस्था नियत करता है, जो कि सम्प्रभुता एवं आन्तरिक मामलों में अहस्तक्षेप के सिद्धान्तों का ईमानदारी और निरन्तरता के साथ पालन करने तथा सन्धि समझौतों के बिना किसी छोटे और अस्पष्ट पैनरेवाजी के दृष्टापूर्वक क्रियान्वयन पर आधारित है।'² 1973 के अन्त में उन्होंने कहा—'हम सब अपनी नीति के नवीन उद्देश्यों एवं नवीन दिशा निर्देशों की अवधारणा के लिए कार्यरत हैं। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हमारे प्रमुख ध्येय शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व को अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के अत्यावश्यक नियम के रूप में अधिक प्रभावशाली ढंग से प्राप्त कर सकते हैं।'³

देनात की परिभाषा, अर्थ एवं उद्देश्यों के बारे में अमरीका तथा सोवियत संघ के जिम्मेदार व्यक्तियों के उद्धृष्ट विचारों से स्पष्ट है कि वे इस बारे में पूर्णतः एकमत नहीं हैं। देनात के बारे में सोवियत दृष्टिकोण तनाव में कभी से ज्यादा एक विशुद्ध शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व का है। वह इसे कानूनी जामा भी पहचाना चाहता है, जबकि अमरीका का विस्तृत ऐसा नहीं। वह इसे संकट के समय स्वतंत्र को कम करने वाला बनाता है। वहीं अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी भी अवधारणा के बारे में प्रायः मतभेद रहता है। इस कारण यहाँ इसकी निश्चित परिभाषा, अर्थ एवं उद्देश्यों का विस्तार से उल्लेख कर विषय को अनावश्यक गुल देना उचित नहीं। प्रोफेसर एम० एम० अगवासी ने देनात का परिचय देते हुए जो कुछ कहा है, वह काफी हद तक इस अवधारणा के अर्थ एवं परिभाषा के प्रति न्याय करता है। उन्हीं के शब्दों में '1960 के बाद महाशक्तियों के सम्बन्ध एक ही दिशा में बढ़ने लगे हैं। समय की गति के साथ-साथ शीत-युद्ध के नकारात्मक रवियों और स्थितियाँ दोनों पक्षों में आपसी बातचीत, समायोजन तथा सह-अस्तित्व की ओर उन्मुख होने लगे। दोनों में वैचारिक मतभेद आज भी बने हुए हैं, किन्तु वे अब राजनीतिक और आर्थिक अन्तर्क्रिया में बाधा पैदा नहीं करते। यद्यपि संकटों की होड़ पूर्णतया समाप्त नहीं हुई है तथापि यह खेल प्रतिबद्ध समय के साथ नेता जाने लगा है। सैनिक गठबन्धनों का अन्त नहीं हुआ, तथापि उन्होंने अपनी मौलिक छाप एवं एकरूपता खो दिये हैं। इनके अनिश्चित परमाणु विनाश का दुस्वप्न दुनिया को पहले जितना अधिक नहीं मनाता है। अमरीका-सोवियत सम्बन्ध में इस गतिशील परिवर्तन को 'देनात' का नाम दिया गया है।'⁴

² L. I. Brezhnev, *Our Course - Peace and Socialism* (Moscow, 1974) 20

³ L. I. Brezhnev, *On the Foreign Policy of the CPSU and the Soviet State* (Moscow, 1973), 554

⁴ Super power relationship has been in a state of flux since the sixties. Over the years the negative attitudes and postures of the cold war have gradually yielded place to a new found willingness of both sides to talk, to accommodate and to co exist. The ideological differences persist, but they no longer obstruct political and economic intercourse. The arms race is not eliminated altogether, but the game is played with contractual restraint. The military alliances have not exactly disappeared into thin air, but they have lost much of their original punch and cohesion. Above all the nightmare of nuclear holocaust no longer torments the world as much as before. This outgoing change in the relations between the Soviet Union and the United States has been given the name of détente.

देतांत की प्रमुख विशेषताएँ (Salient Characteristics of Detente)

देतांत की किसी निश्चित परिभाषा, अथं एक उद्देश्य के अभाव में यही उचित होगा कि हम इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कर लें ताकि इसके अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में चर्चा आगे बढ़ायी जा सके। देतांत की कतिपय प्रमुख विशेषताएँ निम्नांकित हैं :

(अ) देतांत एक प्रक्रिया है;

(ब) देतांत-प्रक्रिया के अन्तर्गत दो देशों के बीच तनाव को कम किया जाता है,

(ग) देतांत के द्वारा तनाव में कमी की प्रक्रिया का यहाँ विशेष रूप से उल्लेख बिस्व की दो महाशक्तियों अर्थात् अमरीका और सोवियत संघ के बीच तनाव में कमी के सम्बन्ध में किया गया है,

(द) देतांत प्रक्रिया के अन्तर्गत महाशक्तियाँ शीत युद्ध के तनाव में कमी विभिन्न क्षेत्रों (जैसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रौद्योगिकी, विज्ञान आदि) में सहयोग द्वारा करती हैं, और

(र) देतांत का अर्थ कदापि यह नहीं कि महाशक्तियों के वैचारिक या धर्म्य प्रकार के मतभेद समाप्त हो गये हैं। देतांत की विशेषता यह है कि दोनों के बीच वैचारिक मतभेद या दृष्टि-समर्प की प्रतियोगिता के बावजूद उनमें विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग अधिक बाधा उपरिष्ठ नहीं होने देता।

देतांत के कारण

(Causes of Detente)

अमरीका और सोवियत संघ के बीच देतांत प्रक्रिया अर्थात् तनाव में शिथिलता आने के अनेक कारण जिम्मेदार रहे। प्रोफेसर एम० एच० राजन का मानना है कि 'शीत युद्ध के अवसन्न एवं देतांत के उदय के पीछे वास्तविक व्याख्या तथा औचित्य संक्षेप में दो आधारों में निहित है—(1) महाशक्तियों के आपसी हित एवं (2) उनकी जनता की आकांक्षाओं की अनुभूति। दोनों महाशक्तियों के तनाव-क्षीयत्व के इन्हीं दोनों आधारों में अनेक कारण गुड़े जा सकते हैं, जो निम्न हैं :

(1) परमाणु बराबरी-जनित अतंक का सन्तुलन—द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनेक वर्षों तक अमरीका का 'परमाणु एकाधिकार' रहा। हालांकि 1954 में रूस ने गफलतापूर्वक परमाणु विस्फोट कर दिया था, किन्तु इस क्षेत्र में पर्याप्त आविष्कार एवं शोध कर्षों के अभाव में वह अमरीका के मुकाबले कम ही परमाणु शस्त्रों का निर्माण कर पाया। 1962 में क्यूबा संकट के दौरान अमरीका और रूस परमाणु संघ में तत्पक्ष बराबरी के हो गये। तत्पश्चात् दोनों महाशक्तियों को यह भय महाने लगा कि यदि शीत युद्ध वास्तविक युद्ध के रूप में परिणत हो गया तो दोनों इसके हानिकारक प्रभाव से नहीं बचेंगे। यह महसूस करते हुए 1972 में 'सलिट-एक' समझौते के अन्तर्गत अमरीका तथा रूस ने प्रक्षेपास्त्री और विस्फोट-शीपों (Warheads) में बराबरी का मिडान स्वीकार किया। 1974 में निवहन-प्रेत्रनेव समझौते के अन्तर्गत दोनों ने अपने लिए एंटी-एंटी प्रक्षेपास्त्र-प्रेदी व्यवस्था (Anti-ballistic

Missile System) तय की। इस प्रकार अमरीका और सोवियत संघ के बीच परमाणु बराबरी ने उनमें आतंक का सतुलन पैदा किया। इसने दैतान का मार्ग प्रशस्त किया।

(2) स्टालिनोत्तर रूस की शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति—पहले सोवियत संघ ने इस विचारधारा का प्रतिपादन किया था कि पूँजीवादी और साम्यवादी दोनों में किसी प्रकार का सहयोग स्थापित नहीं किया जा सकता। दोनों के बीच युद्ध अवश्यम्भावी है। सोवियत शासक स्टालिन अपने राजनीतिक पतन तक यह नीति अपनाते रहे। किन्तु इसके बाद शमन की वागडोर सम्भालने वाले शासक अपने रुख में नरमी लाये। 1956 में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की बीमवी कांग्रेस में क़्रुश्चेव ने स्टालिन की खुली आलोचना की तथा युद्ध की अनिवार्यता के स्थान पर शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्त की घोषणा की। क़्रुश्चेव के बाद ब्रेज़नेव ने भी शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व का सिद्धान्त अपनाने की घोषणा की। इस प्रकार शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व का सिद्धान्त दैतान का कारण बना।

(3) संयुक्त राष्ट्र संघ में तीसरी दुनिया के देशों द्वारा महाशक्तियों के विरुद्ध एकजुट होना—जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ बना, तब उसमें 51 सदस्य राष्ट्र थे। इनमें से अधिकांश पूर्वी और पश्चिमी यूरोप के विकसित देश थे। शीत युद्ध के दौरान दोनों शक्तों ने तीसरी दुनिया के गरीब देशों को अनेक लाभ देकर अपनी तरफ रखा। किन्तु यह स्थिति धीरे-धीरे बदलने लगी और तीसरी दुनिया के राष्ट्रों ने आपसी सहयोग के द्वारा एकजुट होना शुरू किया। अनेक उपनिवेश और निवेशिक शक्तियों के चंगुल से मुक्त होकर स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आये। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश किया। आज संयुक्त राष्ट्र संघ के करीब 159 देश सदस्य हैं जिनमें गरीब देशों की संख्या दो-निहाई है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में हिन्द महासागर को 'शान्ति क्षेत्र बनाने', नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना, समुद्री कानून सम्मेलनों में प्राकृतिक सम्पदा के समान दोहन आदि के मामलों में रसे गये प्रस्तावों पर तीसरी दुनिया के राष्ट्रों द्वारा एकजुट होकर मतदान करने से दोनों महाशक्तियाँ चौंकी। उन्होंने महसूस किया कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अनेक मामलों पर दोनों महाशक्तियों के हित एक समान हैं और तीसरी दुनिया उनके खिलाफ। इसने अमरीका और रूस के बीच दैतान प्रक्रिया क्षेत्र की ताकत के अन्य विकसित देशों को अपने साथ लेकर इस विश्व सगठन में तीसरी दुनिया से मुकाबला कर सकें।

(4) शस्त्रीकरण पर अपार खर्च—शीत युद्ध के दौरान रूस और अमरीका दोनों ने एक-दूसरे के विरुद्ध सुरक्षा और घेरेला स्थापित करने के लिए नये-नये हथियारों का आविष्कार कर उनका बड़े पैमाने पर उत्पादन आरम्भ कर दिया। दोनों शस्त्रीकरण की होड़ में जुट गये। फलस्वरूप शस्त्रीकरण के बोझ में उनकी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। मार्च, 1971 में अमरीका में हुए एक गैलेप पॉन (एक प्रकार की रायनुमारी) के अनुसार 49% अमरीकियों का मानना था कि उनके देश का प्रतिरक्षा खर्च ज्यादा है। नवंबर 11 प्रतिशत लोगो ने सोचा कि यह बहुत कम है। 55 प्रतिशत बालेज में शिक्षा पाने वालों तथा 55 प्रतिशत मध्यवर्गीय आय वालों का मानना था कि प्रतिरक्षा खर्च अत्यधिक ज्यादा है। उन्होंने महसूस किया कि शस्त्रीकरण का यह अपार खर्च निरर्थक है। उनका कहना था कि शस्त्रीकरण रोककर यह खर्च अमरीकियों का जीवन स्तर बहुत बढ़ाने के लिए

किया जाये। परिणामस्वरूप दोनों महाशक्तियों के बीच दो साल्ट समझौते हुए। इस प्रकार अमरीका और सोवियत सभ द्वारा सामरिक हथियारों के निर्माण की अन्धी प्रतियोगिता रोकने की आपसी इच्छा ने इनमें देतात का मार्ग प्रशस्त किया।

(5) आर्थिक सहायता की निरर्थकता महसूस करना—शीत युद्ध के दौरान अमरीका और रूस तीसरी दुनिया के देशों को आर्थिक सहायता का लालच देकर अपने-अपने क्षेत्रों की ओर आकर्षित करने लगे थे। मदद प्राप्तकर्ता देशों ने भी महाशक्तियों की महत्वकांक्षाओं का लाभ उठाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता की मांग की। ऐसे में अमरीका और रूस ने महसूस किया कि उनके द्वारा गरीब देशों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता का प्राप्तकर्ता देश गतत हम से फायदा उठा रहे हैं तथा यह उनकी अर्थव्यवस्था पर बोझ के रूप में साबित हो रही है सो वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि दोनों को सामरबाह टकराने की क्या जरूरत है ?

(6) सैनिक गुटबाजी की निरर्थकता का महसास—द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमरीका और रूस ने क्रमशः पूँजीवादी तथा साम्यवादी क्षेत्रों के नेतृत्व की बागडोर सम्भाली थी। दोनों ने अन्य देशों को अपने क्षेत्र में शामिल होने का निमन्त्रण दिया। उन्होंने अनेक प्रादेशिक एवं सैनिक संगठनों जैसे 'नाटो', 'सिएटो', 'सेन्टो' तथा 'वारसा पैक्ट' को प्रवर्तित कर अन्य देशों को विशाल सैनिक एवं आर्थिक मदद दी। ये संगठन कुछ दिनों तक तो ठीक चले। उनके सदस्य-राष्ट्र महाशक्तियों के 'आदेशों' का पूर्णतया पालन करते रहे, किन्तु बाद में उन्होंने औसत मूँदकर आदेश पालन करने से इन्कार कर दिया। मसलन, गरिबनी जर्मनी के शासक विली ब्राद ने अमरीका की इच्छा के खिलाफ पूर्व तथा पश्चिम यूरोप के देशों में सहयोग की धारणा का प्रतिपादन किया। फ्रांस के शासक देगोल ने भी ममस्त यूरोपीय देशों में सहयोग पर बल दिया। दूसरी तरफ सोवियत सभ की इच्छा के खिलाफ रूसानिया ने रूस-प्रवर्तित वारसा पैक्ट का सैनिक बजट बढ़ाने का विरोध किया। अमरीका द्वारा प्रवर्तित सिएटो एवं सेन्टो संगठन समाप्त हो गये, क्योंकि उनमें सम्मिलित देशों ने अपनी मददगारता त्याग दी। फलस्वरूप दोनों महाशक्तियों ने सैनिक गुटबन्दी की निरर्थकता एवं प्रभावहीनता महसूस की तथा वे एक-दूसरे के बीच सहयोग की ओर अग्रसर हुईं।

(7) सैनिक शक्ति की विफलता महसूस करना—शीत युद्ध के दौरान अमरीका और रूस ने विश्व के अन्य देशों में अपने-अपने प्रभाव क्षेत्र जमाने के दृष्टिकोण से सैनिक अड्डे स्थापित करने आरम्भ किये। अमरीका ने फिलीपीन्स, थाईलैण्ड आदि में तथा सोवियत सभ ने पूर्वी यूरोप के देशों में ऐसा ही किया। कुछ वर्षों बाद जिन देशों में उनके सैनिक अड्डे थे, उन्होंने उसका विरोध शुरू किया। दोनों महाशक्तियों ने अनेक देशों में सैनिक हस्तक्षेप भी किया जो उनके लिए काफी महँगा साबित हुआ। सोवियत सभ द्वारा 1956 में हंगरी तथा 1968 में चेकोस्लोवाकिया में हस्तक्षेप करने पर अन्य देशों में उसकी काफी बदनामी हुई। अमरीका ने वियतनाम में अपने आपकी काफी सभसे सभ तक सैनिक रूप से उलझाये रखा। इससे अनेक देशों में उसकी छवि बिगड़ी। इससे दोनों महाशक्तियों ने महसूस किया कि अनेक सैनिक शक्ति के बलबूते पर अन्य राष्ट्रों को ज्यादा समय तक पकड़ में नहीं रखा जा सकता। उन्होंने एक-दूसरे के विरुद्ध ऐसा करने के बजाय आपसी सम्बन्ध सुधार

को बेहतर माना। इससे उनमें देनात सम्बन्धों की सिडकी खुली।

(8) पूर्वी और पश्चिमी यूरोप के बीच सहयोग—आरम्भ में तो पूर्वी और पश्चिमी यूरोप के देश क्रमशः सोवियत संघ तथा अमरीकी मेमो में सम्मिलित हुए, किन्तु कुछ वर्षों बाद पूर्वी और पश्चिमी यूरोप के अनेक देशों ने बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग आरम्भ करने की बहम ली। 1959 में फ्रांस के शासक चार्ल्स देगोल ने पूर्वी तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों में आपसी सहयोग का विचार प्रतिपादित किया। उन्होंने एक व्यवस्था के अन्तर्गत समस्त यूरोपीय राष्ट्रों में मेल-मिलाप और एकीकरण पर बल दिया। यूरोप के अनेक राष्ट्रों ने इस धारणा के प्रति उत्सुकता जाहिर की। उसके बाद पश्चिमी जर्मनी के विस्सी ब्राट की 'ओस्त राजनीति' ही पूर्वी तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों में आपसी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग स्थापित करने के लिए जिम्मेदार थी। 1970 से 1973 के बीच पूर्वी तथा पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रों के मध्य सहयोग का सम्बन्धित अनेक समझौते हुए। 1971 में पूर्वी तथा पश्चिमी जर्मनी के बीच किया गया वर्लिन समझौता इसी सहयोग भरे वातावरण का परिणाम था। दूसरी तरफ जैसा कि नियोग ब्राउन ने कहा है कि अमरीका और रूस यूरोप के पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों में यथास्थिति कायम रखना चाहते थे। सोवियत संघ पूर्वी यूरोप तथा अमरीका पश्चिमी यूरोप के देशों में अपना दबाव एवं अप्रत्यक्ष नियन्त्रण ज्यों का त्यों बरकरार रखना चाहते थे। यह दोनों महाशक्तियों के बीच आपसी समझ एवं सहयोग से ही सम्भव हो सकता था। अतएव पूर्वी तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों में आपसी सहयोग प्रारम्भ होने में पहले ही दोनों महाशक्तियाँ चिन्तित होने लगीं। इस कारण के यूरोप में अपने-अपने प्रभाव क्षेत्रों में यथास्थिति कायम रखने के बारे में सहमत हो गईं। इसी सहमति ने दोनों के बीच देनात की प्रक्रिया को विवर्धित किया।

(9) सोवियत संघ की कृषि-उत्पादन में असफलता—यों तो सोवियत संघ अमरीका के मुकाबल की महाशक्ति है किन्तु उसे अमरीका के समान कृषि-उत्पादन क्षेत्र में सफलता हासिल नहीं हो सकी। सोवियत संघ में खाद्यान्नों की पैदावार में गिरावट तथा उनकी माँग में वृद्धि के कारण उसे अनाज परीदन की जरूरत पड़ी। अनाज की विशाल मात्रा में आवश्यकता को पूरा करने में विश्व में अमरीका सबसे ज्यादा समर्थ था। यह महसूस करते हुए सोवियत संघ ने अमरीका की तरफ सहयोग का हाथ बढ़ाकर देनात नीति अपनायी आरम्भ की। सोवियत संघ ने देश की आन्तरिक समस्या पढ़ने मुलझाने को प्राथमिकता दी।

(10) सोवियत संघ की पश्चिमी प्रौद्योगिकी की आवश्यकता—विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के इस आधुनिक युग में अमरीका और सोवियत संघ दोनों ने अपने चरण अबाध गति में बढ़ाये हैं। पर अनेक क्षेत्रों में विशेषकर परिष्कृत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सोवियत संघ अमरीका से पीछे है। सोवियत संघ ने अमरीका में परिष्कृत प्रौद्योगिकी पाने के सान्ध में देनात नीति अपनायी।

(11) संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण भूमिका—महाशक्तियों को नजदीक सान में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका की भी उम्मेदा नहीं की जा सकती। तीस युद्ध के दौरान विश्व में लगे अनवरत सफट उठे, जिनमें युद्ध कभी भी भड़क सकता था। किन्तु संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने शान्ति प्रयामों द्वारा अनेक अन्तर्राष्ट्रीय सफटों को तीमर महानुद्ध का रूप धारण करने में बचा दिया। तीमरे महानुद्ध का अर्थ होता

सोवियत संघ और अमरीका के बीच सैनिक टकराव, अर्थात् महाविनाश। जब दोनों के बीच प्रत्यक्ष टकराव को संयुक्त राष्ट्र संघ ने टाल दिया तो उन्हें आपसी मेल-मुलाकात का मौका मिल गया।

(12) सोवियत-चीन विवाद का उग्र होना—शीत युद्ध के प्रारम्भिक वर्षों में चीन सोवियत सेने में था। किन्तु धीरे-धीरे उनके बीच वैचारिक एवं सीमा मतभेद पैदा हो गये। इन मतभेदों ने दोनों पुराने सहयोगी देशों को आगने-सागने खड़ा कर दिया। उनमें मतभेद इस हद तक बढ़ने लगे कि अनेक पर्यवेक्षक घानी महायुद्ध रुम और अमरीका के बीच न होकर साम्यवादी शक्तियों में होने की सम्भावनाएँ प्रकट करने लगे। सोवियत-चीन तनाव का अमरीका ने फायदा उठाया। उसने सोवियत संघ के दुश्मन चीन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। इससे सोवियत संघ निश्चित हुआ और उसने अमरीका से टकराव की हठधर्मिता छोड़कर बेतात की नीति अपनायी।

(13) मध्य-पूर्व में प्रत्यक्ष संघर्ष झलना—सोवियत संघ ने मध्य-पूर्व के क्षेत्र में पहले मिला गया वाद में सीरिया और इराक में प्रभाव-क्षेत्र कायम करना आरम्भ किया। अमरीका का इस क्षेत्र के अन्य देशों में पहले से प्रभाव था। सोवियत संघ ने अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के लिए अमरीकन-समर्थित इजरायल द्वारा 'लाकत' के बलबूते पर हूबपी तूमि को अरब देशों को वापस दिलाने के लिए नैतिक एवं भौतिक समर्थन देना आरम्भ किया। अमरीका इससे चिन्तित हुआ, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मध्य-पूर्व जैसे सामरिक स्थिति एवं ऐतल जैसी महत्वपूर्ण सम्पदा वाले इस क्षेत्र में उसकी प्रतिस्पर्धी महाशक्ति सोवियत संघ घुसपैठ कर उसके स्फूस राष्ट्रीय हितों के लिए गम्भीर चुनौती उपस्थित कर दे। फलस्वरूप अमरीका ने अरब-इजरायल विवाद मुलाने के प्रयास आरम्भ किए। इसकी ठोस धुआत अमरीकी विदेश मंत्री हेनरी किशजर की 'शटल डिप्लोमसी' (Shuttle Diplomacy) अर्थात् मध्य-पूर्व के एक देश से दूसरे देश की राजधानियों की यात्रा कर इस विवाद को सुलाने के प्रयास द्वारा हुई। वाद में 1979 में अमरीकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने पहल कर मिला एवं इजरायल के बीच कैम्प टेविड समझौता करवाया। हालाँकि सोवियत संघ ने इस प्रयत्न को अरब देशों के लिए आत्मघाती बताया किन्तु इससे अरब-इजरायल विवाद की आग जलकर कम हुई। इन सबका परिणाम यह हुआ कि मध्य-पूर्व में महाशक्तियों का प्रत्यक्ष संघर्ष टालने में अमरीकी प्रयास काफी सीमा तक सफल रहा। इससे बेतात को बल मिला।

(14) महाशक्तियों के तत्कालीन शासकों के व्यक्तित्व की भूमिका—बेतात प्रक्रिया तेज करने में अमरीका और रूस के तत्कालीन शासकों के व्यक्तित्व का भारी योगदान रहा। अमरीका में नेरेडी, निकसन, फोर्ड व कार्टर और सोवियत संघ में सुल्तानिन, ब्रुस्चेव एवं ग्रेस्नेव अपने देश के विगत शासकों की तरह कट्टरपथी न होकर अपेक्षाकृत अधिक दूरदर्शी, व्यावहारिक एवं उदारवादी थे। उन्हीं की उदार विद्व दृष्टि से दोनों महाशक्तियों में बेतात सम्बन्ध कायम हुए।

(15) चीन का नए शक्ति केन्द्र के रूप में उदय—द्वितीय विद्व युद्ध के बाद अमरीका और रूस विद्व महाशक्ति के रूप में उभरे। सम्पूर्ण विद्व राजनीति इन दोनों ध्रुवों के इर्द-गिर्द घूमने लगी। लेकिन 1960 के बाद चीन बड़ी शक्ति के रूप में उभरने लगा। 1970 के बाद तो चीन महाशक्ति के रूप में ही शानिरी करने

तथा। 1972 में अमरीकी राष्ट्रपति निकसन तथा विदेश मन्त्री हेनरी किमिजर ने स्वीकार किया कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन नए शक्ति पुंज के रूप में उभरा है। सोवियत संघ द्वारा चीन की शक्ति का रोकने के बारे में टिप्पणी करते हुए एडम वी० उलाम ने लिखा है कि 'सोवियत संघ द्वारा देतान नीति अपनाने का मूल कारण तथा प्रयोजन वाणिज्य और पीकिंग के बीच अत्यधिक निरवस्थता को रोकना था।'¹ दोनों महाशक्तियाँ भी नहीं चाहती थी कि चीन विश्व राजनीति में अहम भूमिका अदा करे। अतएव चीन का प्रभाव कम करने के लिए दोनों एकमत होकर निरवस्थता साथी हो गए।

(16) गुट निरपेक्ष देशों का अभ्युदय—गुट-निरपेक्ष नीति का उदय शीत युद्ध के प्रति एक तीव्र प्रतिक्रिया थी। अमरीका और रुस विश्व के अन्य भागों में शक्ति-सन्तुलन के सिद्धान्त के जरिये अन्य राष्ट्रों में अपना-अपना प्रभाव क्षेत्र जमाकर उन्हें अपनी विदेश नीति के मोहरों के रूप में प्रयोग कर रहे थे, जबकि गुट-निरपेक्ष देश किसी भी महाशक्ति के खेमे में शामिल नहीं होना चाहते थे। वे उनके शक्ति-सन्तुलन के सिद्धान्त को विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए खतरनाक मानते थे। जब महाशक्तियों ने पाया कि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में एक के बाद दूसरा राष्ट्र सम्मिलित होता जा रहा है और उनको खेमेबाजी दुर्बल पड़ती जा रही है तो उन्होंने आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध की स्थापना की धुरआन की। अतएव गुट-निरपेक्ष देशों द्वारा अमरीका और सोवियत संघ के गुटों के बहिष्कार से शीत युद्ध में कमी आयी और महाशक्तियों में तनाव कम होना आरम्भ हो गया, क्योंकि अब उनके संपर्क क्षेत्र भी कम होने लगे। इसमें उनमें देतान प्रक्रिया आरम्भ हुई।

(17) बड़ी शक्तियाँ बनाम सीमरी दुनिया—शीत युद्ध के दौरान रुस और अमरीका एक-दूसरे से टकराते रह, किन्तु 1965 के बाद धीरे-धीरे विश्व की बड़ी शक्तियों तथा एशिया, अफ्रीका और लतीनी अमरीकी देशों के बीच मतभेद के अनेक मुद्दे उभरने लगे। विशेषकर 'अक्टाड' एवं समुद्री बानून सम्मेलनों में बड़ी शक्तियों के तिलाफ व्यापारिक रियायतों पर गरीब मुल्कों ने अपनी एकता का जोरदार प्रदर्शन किया। इसमें स्पष्ट है कि महाशक्तियों के कुछ हित समान थे तथा सीमरी दुनिया के देश उनका तिलाफ थे। इसमें महाशक्तियाँ एवं-दूसरे में निरवस्था आयी और उनमें देतान का मार्ग प्रगस्त हुआ।

देतान-प्रक्रिया के विचरण के विभिन्न चरण (Various Stages of Detente)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों में देतान प्रक्रिया का आरम्भ होने के समय-काल को लेकर मतभेद हैं। अनेक लोगों का मानना है कि उसकी पुरुआत शीत युद्ध के माघ ही हुई और जब शीत युद्ध में निश्चितता आने लगी तो यह प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ने लगी। कुछ विद्वानों का मत है कि देतान का आरम्भ अमरीका में बंनडी और सोवियत संघ में न्युइचेव द्वारा शासन की बागडोर सम्भालने के माघ हुआ जबकि अनेक राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मत है कि इसका आरम्भ अमरीका

¹ Adam B. Ulam, *Detente under the Soviet Eyes* (Foreign Policy, New York, Fall, 1976), 4-6

में निम्न तथा मोचित संध में वेश्नेव के शासन काल के दौरान हुआ। देतात के उद्भव के समय-काल के बारे में विद्वानों में विभिन्न प्रकार के मतभेदों के मद्दे में न पढ़कर यह उचित होगा कि अमरीका और सोवियत संध के बीच शीत युद्ध के दौरान से 1979 तक जो सम्बन्ध सुधार हुआ, उस काल की प्रमुख घटनाओं को विभिन्न चरणों में रेखांकित कर दिया जाये। देतात प्रक्रिया के विभिन्न चरण अधोलिखित हैं—

प्रथम चरण (1953 से 1955)—शीत युद्ध के आरम्भिक वर्षों में दोनों महाशक्तियों के बीच देतात सम्बन्धों की स्थापना सम्भव नहीं थी, क्योंकि एक तरफ अमरीका ने अन्य देशों में साम्यवादी भ्रूत या स्त्री जलू का होवा सड़ा कर सोवियत संध को बदनाम करने के अनेक प्रयत्न किये, वहीं दूसरी ओर सोवियत संध ने पूँजीवादी और साम्राज्यवादी शोषण की बात उठाकर अमरीका की छवि खराब करने की कोशिश की। इस काल में दोनों महाशक्तियों के बीच अनेक क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा का वातावरण बना रहा, जिसमें 1949 में कोरिया युद्ध को लेकर दोनों में आपसी सीमांतानी का उदाहरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

लेकिन 1953 के आरम्भ में कुछ ऐसे तनेत बिसाई किये, जिन्हें महाशक्तियों के बीच 'शांति सहयोग' की सज्ञा दी जा सकती है। इनके प्रमुख संकेत निम्नांकित हैं—

(अ) 1953 में कोरिया युद्ध की समाप्ति की घोषणा हुई;

(ब) 1955 में आस्ट्रिया के भाग आन्ति-सन्धि सम्पन्न हुई, और

(स) 1955 में 'बैंकेज डील' समझौता किया गया। इस समझौते के परिणाम-स्वरूप 16 राष्ट्रों (4 पश्चिमी राज्यों के समर्थक राष्ट्रों, 4 सोवियत संध के समर्थक राष्ट्रों, तथा 8 गुट निरपेक्ष राष्ट्रों) को एक साथ सयुक्त राष्ट्र संध में सदस्यता हासिल हुई। ये घटनाएँ दोनों महाशक्तियों के बीच आंशिक सहयोग एवं विश्वास का परिणाम थी। इस आंशिक सहयोग को सम्भव बनाने में एक ओर स्टालिन की मृत्यु और सोवियत व्यवस्था में अड्डता की समाप्ति ने योगदान दिया तो दूसरी ओर इस प्रक्रिया की गुट निरपेक्ष देशों के रचनात्मक निपाकलापो जैसे 1955 का बाडुग शिखर सम्मेलन तथा अग्रे, 1954 का पञ्चशील समझौता आदि ने पुष्ट किया। सम्भवतः इन दोनों घटनाओं ने दोनों क्षेत्रों को महसूस करवा लिया कि उनके आपसी सम्बन्धों में देतात लाभदायक है।

द्वितीय चरण (1956 से 1962)—इस बीच अमरीका और सोवियत संध में तनावपूर्ण सम्बन्ध जारी रहे। मरानन 1 मई, 1960 की यू-2 विमान कांड और 1962 में क्यूबा मकट ने दोनों महाशक्तियों को सैनिक टकराव के कगार पर सड़ा कर दिया। किन्तु इनकी परिणति वास्तविक युद्ध में नहीं हुई, क्योंकि दोनों परमाणु बराबरी के आपसी भय तथा अनेक कारणों से अपने को महायुद्ध की आग में झोककर नष्ट करने से डरते थे। इस प्रकार दोनों ने शान्ति प्रयास आरम्भ किये, जिनमें प्रमुख निम्नांकित हैं—

(अ) 1959 में सोवियत शासक रुद्चेव ने अमरीका-यात्रा की, और

(ब) इस यात्रा के परिणामस्वरूप मई, 1960 में फ्रान्स की राजधानी पेरिस में शिखर सम्मेलन हुआ अर्थात् अमरीका और सोवियत संध के सामनाप्यक्षों की मुनावान सम्भव हो सकी।

तृतीय चरण (1963-1969)—इस बीच अमरीका और रूस के बीच आपसी प्रतिद्वन्द्विता चरनी रही। इसके बावजूद उन्होंने शान्ति एवं मैत्री प्रयामों द्वारा एक-दूसरे के रिश्ते आगे के लिए अनेक कदम उठाये। प्रमुख कदम इस प्रकार हैं—

(अ) 1963 में अमरीका और सोवियत संघ की राजधानियों वॉशिंगटन और मास्को के बीच 'हॉट लाइन' स्थापित की गयी, ताकि दोनों देशों के शान्ताध्यक्ष महत्वाकांक्षीन परिस्थितियों को बिनाशकारी युद्ध में बदलने से रोकने के लिए तत्काल टेलीफोन सहायता सकें।

(ब) 1963 में दोनों महाशक्तियों के बीच निस्स्त्रीकरण अर्थात् पातक परमाणु हथियारों के उत्पादन को कम करने के लिए एक 'आंशिक परमाणु परीक्षण गैर सन्धि' हुई।

(स) 1968 में एक बार पुनः निस्स्त्रीकरण प्रयाम के रूप में दोनों देशों के बीच 'परमाणु प्रसार रोक सन्धि' हुई।

चतुर्थ चरण (1970-1979)—इस दौरान अमरीका और सोवियत संघ ने आपसी सम्बन्ध सुधारने के लिए अपशाङ्क अनेक टोम प्रयाम किये। इसका अर्थ यह कहापि नहीं कि इस चरण में उनमें तनाव उत्पन्न हुआ ही नहीं। हालाँकि उनमें अनेक क्षेत्रों में तनाव जारी रहा, फिर भी पहले की अपक्षा काफी कम रहा। इस चौथे चरण में महाशक्तियों में सबसे अधिक सहयोग देखने को मिला। इस चरण की प्रमुख घटनाएँ निम्नांकित हैं—

(1) मास्को-बोन समझौता (1970)—शीत युद्ध के दौरान जहाँ अमरीका पश्चिमी जर्मनी की पीठ धक्का रहा था, वही सोवियत संघ उनके विरुद्ध पूर्वी जर्मनी को समर्थन दे रहा था। इसमें सोवियत संघ तथा पश्चिमी जर्मनी में तनाव उत्पन्न हुआ। 12 अगस्त, 1970 को सोवियत संघ तथा पश्चिमी जर्मनी के प्रधानमन्त्री वॉलफगांग केनिल्ले तथा विन्नी-ब्राट ने मास्को में एक सन्धि पर हस्ताक्षर किये। इसके अन्तर्गत दोनों देशों को प्रमुख बातों पर सहमत हो गये। प्रथम, सोवियत संघ और पश्चिमी जर्मनी एक-दूसरे के विरुद्ध शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेंगे। द्वितीय, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी की सीमाओं सहित यूरोप में जो मौजूदा राष्ट्रीय सीमाएँ हैं उन्हें दोनों देशों ने स्वीकार कर लिया। ध्यान रहे कि दोनों राष्ट्रों के बीच तनाव का मुद्दा जर्मनी के मौजूदा स्वरूप और दूसरे विश्व युद्ध के बाद की राष्ट्रीय सीमाओं का आधार बनाकर ही था। इस पर समझौता हो जाने में अमरीका और सोवियत संघ के बीच झगड़े की एक जड़ नष्ट हो गयी।

(2) कोरिया का समझौता (20 अगस्त, 1971)—शीत युद्ध के दौरान कोरियाई भूमि अमरीका और सोवियत संघ के बीच प्रतिद्वन्द्विता का मैदान बनी हुई थी। किन्तु 20 अगस्त 1971 को उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की रहस्यमयी मोमाइटी की एक बैठक हुई। इसमें तय किया गया कि कोरिया युद्ध के दौरान कार्रियावासियों के जो एक करोड़ रिश्तेदार एवं मित्र बिद्रुह गये थे, उनकी अदला-बदली की जाये। 4 जुलाई, 1972 को दोनों कोरियाई राज्यों के बीच समझौता हुआ, जिसमें उन्होंने वापदा किया कि वे एक-दूसरे को बमबोरा करने का कोई प्रयाम नहीं करेंगे। इसके अलावा एकीकरण को सम्भव बनाने के लिए एक सम्बन्ध समिति गठित की गयी। जुलाई 1973 में दोनों देशों में सहयोग स्थापित करने के लिए एक आयोग गठित किया गया। इस आयोग ने दोनों के बीच मैत्रि

तनाव कम करने के लिए अनेक मुझाव दिये। इस प्रकार कोरिया-संकट से उत्पन्न दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव कम हो गया।

(3) बर्लिन समझौता (अगस्त, 1971)—द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अमरीका और सोवियत संघ के बीच पश्चिम बर्लिन को लेकर तनावपूर्ण सम्बन्ध रहे। यहाँ तक कि 1948 में बर्लिन की नाकेबन्दी हो गयी और इस संकट ने महाशक्तियों के बीच एक और महायुद्ध जैसी विस्फोटक स्थिति उत्पन्न कर दी। इस वारुद में आग लगाने भर की देर थी। किन्तु बाद में उन्होंने संयमपूर्ण रुख अपनाया और अगस्त, 1971 में अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ के बीच पश्चिम बर्लिन के बारे में समझौता हो गया। इसके अन्तर्गत तय हुआ कि अब पश्चिम बर्लिन के लोग पूर्वी बर्लिन में जा सकेंगे। 3 सितम्बर, 1971 के समझौते के अन्तर्गत चार बातें तय हुई—

(अ) बर्लिन तक और बर्लिन से अतैनिक आयात,

(ब) संघीय जर्मनी के साथ पश्चिम बर्लिन के सम्बन्ध,

(स) बर्लिन के पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र तथा पूर्वी जर्मनी के साथ संचार सम्बन्ध; एवं

(द) बर्लिन का विदेशों में प्रतिनिधित्व।

(4) अनेक द्विपक्षीय समझौते (1971)—1971 में अमरीका और सोवियत संघ के बीच अनेक द्विपक्षीय सहयोग समझौते हुए। ये देतात प्रक्रिया के ही परिणाम थे। प्रमुख समझौते निम्नावित हैं

(अ) फरवरी, 1971 में दोनों ने समुद्री सतह से व्यापक विनाश के अस्त्रों को 'छोड़ना' निषिद्ध कर दिया;

(ब) मई, 1971 में उन्होंने उस दधि पर सहमति प्रकट की, जिसने साल्ट वातांशों को फिर से आरम्भ किया, और

(स) सितम्बर, 1971 में तीन महत्वपूर्ण समझौते हुए, जो इस प्रकार हैं :
(1) जीवाणु तथा विषों के उत्पादन एवं स्वामित्व सम्बन्धी समझौता;
(2) हॉट लाइन को 'अधिक विश्वसनीय' बनाने सम्बन्धी समझौता, (3) परमाणु युद्ध का क्षतरा कम करने के लिए सूचना एवं विचार-विमर्श सम्बन्धी समझौता।

(5) पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के मध्य समझौता (8 नवम्बर, 1972)—शीत युद्ध के दौरान अमरीका और सोवियत संघ क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के समर्थन का बहाना बनाकर 'शक्ति संधि' का नेत्र खोलते रहे, किन्तु 8 नवम्बर, 1972 को पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के बीच एक सन्धि पर हस्ताक्षर हुए। इसके अन्तर्गत दोनों देशों ने एक-दूसरे के अस्तित्व को स्वीकारा और अनेक मानवीय क्षेत्रों में आपसी सहयोग का वायदा किया। सन्धि की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि समस्या के हल के रूप में दोनों जर्मन राज्यों ने एक-दूसरे के खिलाफ 'घमकी' या 'शक्ति प्रयोग' के उपायों को सदैव के लिए त्याग दिया। इससे महाशक्तियों को यहाँ अपनी प्रतिद्वन्द्विता समाप्त करने को विवश होना पड़ा।

(6) मास्को शिखर वार्ता—22 मई, 1972 को तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन मास्को पहुँचे। वहाँ उन्होंने सोवियत शासक ब्रेझ्नेव के अलावा अनेक नेताओं से बातचीत की। वह वहाँ सात दिन तक ठहरे। इस यात्रा के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की अनेक विचारदायक समस्याओं पर दोनों महाशक्तियों

के शांति के बीच बालिष्ठ हैं। उन्होंने अपनी घोषणा के आरम्भ में कहा कि 'दोनों देश समुक्त राष्ट्र मध्य के चार्टर के अन्तर्गत स्वीकार किये गये कर्तव्यों को पूरा करने की प्रतिज्ञा करते हैं तथा ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करना चाहते हैं जिनसे तनाव में कमी हो और युद्ध की आशंका दूर हो।' शिखर वार्ता के अन्त में 2९ मई, 1972 को अमरीका और सोवियत मध्य ने अपने समुक्त वक्तव्य में निम्नांकित बातों पर जोर दिया।

(क) परमाणु आयुधों को सीमित करने के लिए सान्टो-एक सन्धि—परमाणु आयुधों को सीमित करने के लिए सान्टो-एक समझौता अर्थात् सामरिक सन्ध्यान्त्र परिसीमन सन्धि-एक पर हस्ताक्षर हुए। अमल में सान्टो-एक के अन्तर्गत दो समझौते किये गये, जो इस प्रकार हैं :

(1) प्रक्षेपास्त्र विरोधी शस्त्रों को सीमित करने सम्बन्धी सन्धि (Treaty on the Limitation of Anti-ballistic Missile System)।

(2) सामरिक आक्रमक अस्त्रों के परिसीमन सम्बन्धी कुछ उपायों पर अन्तरिम समझौता।

पहला समझौता अनिश्चित काल के लिए किया गया, जबकि दूसरा समझौता पाँच वर्ष के लिए। पहले समझौते के अन्तर्गत अमरीका और सोवियत मध्य के लिए प्रक्षेपास्त्रों की निरापद बनाने वाले स्थलों की संतक सीमित कर दिया गया—एक देशों की राजधानी की सुरक्षा के लिए और दूसरा अन्तरमहाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों (आई० सी० बी० एम०) की सुरक्षा के लिए। पचवर्षीय अन्तरिम सन्धि (जो राष्ट्रीय हितों के प्रतिरूप मिट्ट होने पर किसी भी पक्ष द्वारा छ महीने के नोटिस पर रद्द की जा सकती है) में स्वीकार किया गया कि—

(अ) 1 जुलाई, 1972 के बाद नये अन्तरमहाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण नहीं किया जायेगा,

(ब) कोई भी पक्ष हल्के या पुराने क्रिस के भू-प्रक्षेपास्त्र स्थलों का सुधार कर उन्हें भारी अन्तरमहाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों के प्रयोग के योग्य नहीं बनायेगा,

(ग) दोनों पक्ष पनडुब्बियों के प्रक्षेपास्त्र और प्रक्षेपक तथा प्रक्षेपास्त्रयुक्त आधुनिक पनडुब्बियाँ नहीं बनायेंगे, हालाँकि इसमें निर्माणाधीन पनडुब्बियों का काम करने की छूट रहेगी,

(द) इस अन्तरिम सन्धि की व्यवस्थाएँ ध्यान में रखते हुए दोनों देशों की मॉडरा आक्रामक प्रक्षेपास्त्रों और प्रक्षेपकों का आधुनिकीकरण करने या वैकल्पिक अस्त्र बनाने का अधिकार रहेगा, और

(र) सन्धि के परिपालन की जाँच के लिए हर राष्ट्र केवल अन्तर्राष्ट्रीय कानून के माध्यम मिट्टान्तों के अनुरूप ही विधियाँ अपनायेगा। दोनों पक्षों ने स्वीकार किया कि अस्त्र-शस्त्र निर्माण गुप्त रखने के लिए जान-बूझकर ऐसी व्यवस्थाएँ नहीं करेंगे, जिसमें सन्धि की भावना को ठेस पहुँचे और दूसरे देश को निगरानी रखने में कठिनाई हो।

(ध) व्यापारिक और आर्थिक सम्बन्ध—अमरीका और सोवियत मध्य ने अपनी व्यापारिक और आर्थिक सम्बन्ध बढ़ाने के लिए एक समुक्त व्यापारिक आयोग बनाने का निश्चय किया।

(ण) समुद्री घातकों पर समझौता—दोनों महासत्तियों ने समुद्र और आकाश

में उनके जहाजों और विमानों की गोपण दुर्घटनाएँ रोकने के लिए एक समझौता किया।

(घ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग—दोनों देशों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग के विस्तार के लिए संयुक्त आयोग बनाने का निश्चय किया। अन्तरिक्ष में गोपण दुर्घटनाएँ रोकने और इस क्षेत्र में शान्तिपूर्ण अनुसन्धान के दृष्टिकोण से दोनों देशों ने यह समझौता किया कि वे अन्तरिक्ष में अमरीकी और सोवियत यानों के मित-जुनकर कार्य करने की व्यवस्था करेंगे। दोनों महाशक्तियों ने विद्वद् के सम्पूर्ण मानव-समाज के स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण समस्याओं जैसे कैंसर, हृदय रोग तथा पर्यावरणीय स्वास्थ्य विज्ञान के सम्बन्ध में अनुसन्धान कार्य में सहयोग का निश्चय किया।

(7) 1972 में कुछ और द्विपक्षीय समझौते—अगस्त, 1972 में सोवियत संघ ने अमरीका से विशाल मात्रा में गेहूँ खरीदने के लिए एक समझौता किया। 18 अक्टूबर, 1972 को दोनों देशों में एक व्यापार सन्धि हुई, जिसके तहत सोवियत संघ ने वायदा किया कि द्वितीय महायुद्ध के समय उसने अमरीका से जो 'उधार पट्टा ऋण' लिया था, उस धनराशि को वह चुका देगा। इसके साथ एक और सन्धि हुई, जिसमें तय किया गया कि आगामी तीन वर्षों में दोनों का व्यापार तीन गुना कर दिया जायेगा। अमरीका के निवर्तन प्रशासन ने वायदा किया कि सोवियत ग्राहकों के आपात पर स्थानांतरण दर से कर लगाने की व्यवस्था के लिए यह काप्रेस (मंद) से अनुमति प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा।

(8) श्रेयनेव की अमरीका-यात्रा (1973)—अमरीकी राष्ट्रपति निकसन ने अपनी मास्को यात्रा के दौरान सोवियत नेताओं की अमरीका-यात्रा पर आने के लिए आमन्त्रित किया था। इसके प्रत्युत्तर में 18 जून 1973 को सोवियत शासक श्रेयनेव अमरीका की नी दिवमीय यात्रा पर गये। वाशिंगटन हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करते हुए निक्मन ने कहा—'हमने अनुभव किया है कि अपने सैद्धान्तिक मतभेदों और सामाजिक प्रणालियों में भिन्नता के बावजूद हम सामान्य सम्बन्ध बढ़ा सकते हैं।' इसके जवाब में श्रेयनेव ने कहा—'सोवियत-अमरीकी सम्बन्धों में सुधार किसी भी प्रकार से किसी तीसरे देश के हित के विरुद्ध नहीं है।' दोनों नेताओं की बातों में निम्न मुद्दों पर सहमति हुई—

(अ) दोनों देशों ने सैद्धान्तिक तौर पर स्वीकार किया कि 1974 तक वे परमाणु आयुधों के निर्माण पर स्थायी रोक लगा देंगे तथा परमाणु शक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में सहयोग करेंगे;

(ब) दोनों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग का वायदा किया जिससे उनके बीच व्यापारिक और आर्थिक सम्बन्ध बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त हुआ; और

(ग) एक सन्धि में दोनों ने सहमति किया कि उनमें से कोई भी परमाणु युद्ध नहीं करेगा और न ही एक-दूसरे तथा उनके साथी राष्ट्रों को धमकी देगा या बल प्रयोग करेगा।

(9) निक्मन की सोवियत यात्रा (1974)—27 जून, 1974 को अमरीकी राष्ट्रपति निक्मन पुनः मास्को गये। यह दो महाशक्तियों के मध्य तीसरा शिखर सम्मेलन था। इस यात्रा की उपलब्धियाँ निम्नान्वित हैं :

(अ) दोनों देशों ने जवाबी प्रलोपान्न प्रणालियों और आक्रामक परमाणु अस्त्रों को और सीमित करने एवं भूमिगत परीक्षणों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने से सम्बन्धित समझौते पर हस्ताक्षर किये, और

(ब) 1972 में हुए व्यापार समझौते के पूरक के रूप में एक दस-वर्षीय व्यापार समझौता किया। इसके तहत दोनों पक्षों के मध्य आर्थिक समस्याओं के बारे में जानकारी का प्रतिवर्ष आदान-प्रदान करना तय किया गया।

(10) यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन—यूरोपीय सुरक्षा एवं सहयोग सम्मेलन फिनलैंड की राजधानी हैलसिंकी में 3 जुलाई, 1975 को आरम्भ हुआ। जेनेवा में यह सम्मेलन 17 मितम्बर, 1973 से 2 जुलाई, 1975 तक जारी रहा और 1 अगस्त, 1975 को हैलसिंकी में समाप्त हुआ। अमरीका सहित यूरोप के 35 देशों ने इसमें भाग लिया। वस्तुतः यह अनेक दृष्टियों से ऐतिहासिक सम्मेलन था। कालान्तर की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसके दूरगामी प्रभाव पड़े। फिनलैंड के राष्ट्रपति उडो केक्कोनेन ने प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि 'यह यूरोप के लिए खुशियों और उम्मीदों का दिन है। हमारे लिए यह मानने के सभी कारण मौजूद हैं कि हमारे आपसी सम्बन्धों में नये युग की शुरुआत हो रही है।' संयुक्त राष्ट्र सभ के तत्कालीन महासचिव कुर्न वान्दाहीम ने कहा—'यह सम्मेलन पूरे मानव इतिहास का न मही, तो भी हमारी सनातनी का एक अनूठा सम्मेलन है। इसका उद्देश्य बिम्बी युद्ध को समाप्त करना या शान्ति की शर्तों की परिभाषा करना ही नहीं है, बल्कि कुछ समय से अस्तित्व में चले आ रहे शान्ति के आधार को मजबूत बनाना है।' यह सम्मेलन यूरोपीय देशों में तनाव कम करने में एक हद तक सफल रहा।

(11) ग्लादीबोल्सक शिखर सम्मेलन—अब तक अमरीका के राष्ट्रपति बदल चुके थे। निकसन के श्वाग-पत्र के बाद जेरार्ड फोर्ड ने इस पद का कार्यभार सम्भाला। उन्होंने मोक्षियत सभ के माध्यम से प्रक्रिया की 'शिखर सम्मेलनीय राजनय' द्वारा तेज करने की नीति जारी रखी। 23-24 नवम्बर, 1974 को ग्लादीबोल्सक में सोवियत एवं अमरीकी शासक ज़िमन और फोर्ड मिले। इस शिखर बार्न ने दोनों देशों में सामरिक अहम परिमोमन समझौते-दो (सान्ट-दो) की रूपरेखा तैयार की। कहा गया कि जून, 1975 में ज़िमन की अमरीका यात्रा के समय प्रस्तावित समझौते पर हस्ताक्षर हो जायेंगे। यह समझौता 1977 में माल्ट-एक (जो 1972 में हुआ था) की अवधि समाप्त होने पर लागू होगा तथा 1985 तक लागू रहेगा।

(12) अपोलो-सोयुज का अन्तरिक्ष में मिलन—17 जुलाई, 1975 को अमरीकी अपोलो और सोवियत सोयुज यान अन्तरिक्ष में अपनी कक्षा में आकर एक-दूसरे से मिले। दोनों देशों के अन्तरिक्ष यात्रियों ने एक-दूसरे का अभिवादन किया। इस वैज्ञानिक दृष्टि में ही नहीं, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण घटना माना गया, क्योंकि यह सट्याव इस बात का परिचायक था कि अमरीका और सोवियत सभ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस आधुनिक युग में एक-दूसरे के निश्चय आना चाहते हैं। यह विश्व के देशों के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ती अन्तर्-निर्भरता का ही परिणाम था।

(13) बिपना में सान्ट दो समझौता—मई, 1979 को बिपना में अमरीकी

राष्ट्रपति कार्टर तथा सोवियत राष्ट्रपति ब्रेझनेव ने साल्ट-दो समझौते पर हस्ताक्षर किये। 1985 तक की अवधि के इस समझौते की निम्नांकित दो उपलब्धियाँ हैं—

(अ) साल्ट-दो समझौते द्वारा सामरिक दृष्टियों तथा प्रक्षेपास्त्रों की संख्या और किस्मों पर एक सीमा लगा दी गयी, लेकिन इसके अन्तर्गत दोनों देशों को नये प्रक्षेपास्त्र तथा परमाणु दस्त्र बनाने की छूट दी गयी। दोनों देशों के पास अन्तर-महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों, सामरिक वगवपक विमानों तथा पनडुब्बियों से छोड़े जाने वाले परमाणु प्रक्षेपास्त्रों की संख्या 1981 तक 2400 निश्चित कर दी गयी। 1981 के बाद यह संख्या घटाकर 2250 कर दी गयी; और

(ब) हथियारों की होड़ में और कमी के लिए सोवियत संघ और अमरीका अगले समझौते 'साल्ट-तीन' के लिए वास्तवीय करेंगे।

इस प्रकार स्पष्ट है कि साल्ट-दो समझौते से विश्व में दस्त्रीकरण की बढ़ती होड़ कम हुई, जिसने अनेक क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में कमी और सहयोग का मार्ग प्रशस्त किया। साल्ट-दो समझौता ऊपर से दिखने में चाहे कितना ही प्रभावशाली हो, किन्तु उसका अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति या देतात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि अमरीकी सीनेट ने इसका अनुमोदन करने से इन्कार कर दिया। यँसे यह सुझाना तर्कसंगत होगा कि यदि सीनेट इसे अपना अनुमोदन दे भी देती तो भी इस पर अमल करना शायद असम्भव होता, क्योंकि ईरान में शाह का तख्तापलट, तुरन्त तैनाती दस्ते और अफगानिस्तान व वियतनाम के घटनाक्रम ने महाशक्तियों के बीच उस विश्वास को समाप्त कर दिया, जिस पर निश्चस्तीकरण के परागशं का बारोमडार था। 'स्टार वार' की प्रस्तावना ने साल्ट-तीन समझौते की कल्पना को भी पृष्ठभूमि में धकेल दिया। बाद के विभिन्न शिखर सम्मेलन तिरफे प्रचारात्मक महत्व के रहे।

देतांत के प्रभाव

(Impact of Detente)

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनेक वर्षों तक शीत युद्ध काल के दौरान 'न सच्ची शान्ति एवं न ही वास्तविक युद्ध की स्थिति' यनी रही। अर्थात् शीत युद्ध रूपी बारूद में आग फँकने भर की देर थी कि तीसरा महायुद्ध भड़क जाता। यह स्थिति महाशक्तियों के देतांत के कारण स्थायी नहीं रही। अमरीका और सोवियत संघ के बटुना गरे सम्बन्धों में तनाव-धींसिय की प्रक्रिया आरम्भ होने से कालान्तर ने विश्व राजनीति पर अनेक प्रभाव पड़े। एक तरफ जहाँ इसके लाभकारी प्रभाव पड़े, वहीं दूसरी ओर कुछ हानिकारक प्रभाव भी पड़े।

देतांत के लाभकारी प्रभाव—देतांत के निम्न लाभकारी प्रभाव पड़े, जिससे विश्व-शान्ति एवं सुरक्षा स्थापित करने के उद्देश्य में काफी सफलता मिली :

(1) अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में कमी—शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों के टकराव ने उनके अनेक समर्थक देशों में तनाव पैदा कर दिया। मसलन, कोरिया व वियतनाम के मामलों को ही लें, जहाँ अमरीका और सोवियत संघ ने एक-दूसरे के समर्थक राष्ट्रों के विरुद्ध मदद देकर तनाव को जन्म दिया। इससे उनके बीच भीषण युद्ध हुए। इन युद्धगरी राष्ट्रों के बीच उतने गहरे मतभेद नहीं थे जितने कि महाशक्तियों ने अपनी स्वार्थ पूर्ति के कारण पैदा किये। जब दोनों महाशक्तियों ने देतात प्रक्रिया

द्वारा एक-दूसरे के नजदीक आना आरम्भ किया तो उनके समर्थक राष्ट्रों में भी आपसी मतभेद की उग्रता कम हुई। अतः महा-शक्तियाँ व देनातः अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में काफी कमी आयी।

(2) तीसरे महायुद्ध के खतरे से मुक्ति—शीत युद्ध के दौरान अमरीका और सोवियत संघ बिच-बिच अन्य देशों को अपने क्षेत्र में आकर्षित कर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में बहुत बड़प्पन बढ़ाते रहे जिससे तीसरे महायुद्ध का खतरा उत्पन्न हो गया था। अनेक विद्वानों ने इस खतरे को और भी बड़ा दिया जब उन्होंने अनेक प्रकार की ऐसी अटकलबाजी एवं भविष्यवाणी करनी आरम्भ कर दी कि तीसरा महायुद्ध किस समय किस काल कहाँ और कैसे मड़ेगा? यह किन-किसी से लड़ा जायगा? कौन से राष्ट्र किस महाशक्ति का साथ देंगे? और अन्त में कौन किसे जीतने में सफल होगा? लेकिन महाशक्तियों में दनात सम्बन्ध आरम्भ होने में अन्तर्राष्ट्रीय समाज में ज्यों-ज्यों बड़प्पन घटने लगी और संमेबाजी टूटने लगी त्यों-त्यों लोगों के मस्तिष्क में तीसरे महायुद्ध की सम्भावना का भूत हटने लगा। अमरीका और रूस के सम्बन्ध में वृद्ध समय बाद दनात प्रक्रिया के ठोस रूप धारण करने के बाद लोगों के मस्तिष्क से तीसरे विश्व युद्ध के सम्भावित खतरे का डर काफी तजी से घटा।

(3) शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्त को मजबूती—शीत युद्ध के दौरान जहाँ सोवियत संघ मदैव इस उद्घापोह में रहता था कि विश्व के अन्य भागों में किन्हीं भी प्रकार साम्यवादी क्रांति हो उसकी ओर आकर्षित नहीं हूँ उन वाले राष्ट्रों को वह अमरीकी पूँजीवाद एवं साम्राज्यवाद का एजेंट बरार देता। दूसरी ओर अमरीका भी कहता है कि जो देश उसका साथ नहीं है वे उसका दुश्मन हैं। इस बात को लेकर दोनों महाशक्तियाँ राजनीतिक सामाजिक एवं आर्थिक प्रणालियों की भिन्नता एवं एक-दूसरे पर श्रेष्ठता का आरोप लगाकर टकराने की बातें करती। पर दोनों देशों द्वारा दनात प्रक्रिया की शुरुआत से उन्होंने यह मान लिया कि भिन्न प्रणालियों के बीच युद्ध के शान्तिपूर्ण ढंग से रह सकने के अर्थान् उन्होंने शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया। अब उन्होंने विभिन्न दिशाओं को युद्ध अर्थात् ताकत के बल पर नहीं बल्कि शान्तिपूर्ण बातों के जरिये मुसद्दान पर जोर देना शुरू किया।

(4) निगस्त्रीकरण का माय प्रगस्त करना—शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियाँ न एक-दूसरे के विरुद्ध श्रेष्ठता और गुणवत्ता स्थापित करने के दृष्टिकोण से अनीमित घातक परमाणु हथियारों का निर्माण आरम्भ किया। दूसरे देशों ने भी उनकी दशा जैसी रास्ता की नमूना हाँक में अपने समाधान पर्वत शुरू किए। इससे रास्त्रीकरण अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया। पर दोनों महाशक्तियों ने बाद में शस्त्रीकरण के घातक परिणामों को महसूस किया और उनके बीच देनात सम्बन्ध स्थापित हुए। इस भावना ने निगस्त्रीकरण का माय प्रगस्त किया। 1963 की आगिक परमाणु परीक्षण रोक संधि 1968 की परमाणु अस्त्र प्रसार रोक संधि 1972 का माल्ट-गैस और 1979 का मांट्रै-नोममसीता निगस्त्रीकरण के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं।

(5) रास्त्रीकरण के बजाए जनकल्याणकारी बायों पर ध्यान देना—शीत युद्ध के दौरान अमरीका और सोवियत संघ रास्त्रीकरण की छोड़ में लग रहे।

विनाशकारी परमाणु हथियारों का निर्माण कुछ समय बाद उनकी अर्थव्यवस्था के लिए घातक सिद्ध होने लगा, क्योंकि इन हथियारों पर विशाल खर्च हो रही थी। शस्त्रीकरण के असौमित्र खर्च के इस बोझ से उनकी अर्थव्यवस्था में अनेक संकट पैदा हो गये। जहाँ अमरीका में मुद्रा-स्फीति, बेरोजगारी एवं तेल संकट मँडू बाए पड़े हो गये, वहीं सोवियत संघ कृषि के क्षेत्र में पिछड़ गया। दोनों के मध्य देतात सम्बन्ध स्थापित होने से शस्त्रीकरण की होड़ कम हुई जिससे वे इस पर हो रहे अनाप-दानाप खर्च को देश की आन्तरिक समस्याएँ सुलझाने अर्थात् जन-कल्याणकारी कार्यों पर लगाने में समर्थ हुए। यह दोनों के लिए लाभकारी साबित हुआ।

(6) महाशक्तियों के बीच वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक, आर्थिक एवं व्यापारिक सहयोग का मार्ग प्रशस्त होना—शीत युद्ध के दौरान दोनों देशों में तनाव सम्बन्ध जारी रहे, जिससे किसी भी क्षेत्र में ठोस सहयोग स्थापित होना अत्यन्त कठिन था। पर उनके द्वारा देतात नीति अपनाने से सहयोग का मार्ग खुला। 1970 के बाद उनके बीच वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक, आर्थिक एवं व्यापारिक क्षेत्रों में अनेक सहयोग-समझौते हुए। इस सन्दर्भ में 1972 की मास्को विश्वर वार्ता के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की अनेक घोषणाएँ, 1972 में सोवियत संघ द्वारा अमरीका से गेहूँ खरीदना, 1974 में निक्सन की मास्को-यात्रा के दौरान 1972 के व्यापार समझौते के तुरक के रूप में दश-वर्षीय व्यापार समझौता, हैलसिंकी घोषणा के तहत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की घोषणाएँ, 1975 में अपोलोसोयुज का अन्तरिक्ष में मिलन महत्वपूर्ण कदम थे।

(7) संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रभावशाली ढंग से कार्य करना—अमरीका और सोवियत संघ ने शीत युद्ध के काल में विश्व के अन्य देशों को विभिन्न प्रलोभनों तथा अन्य तरीकों से अपने-अपने गुट की ओर आकर्षित किया। इससे दोनों गुटों में खींचातान पड़ी। यह खींचातान संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे विश्व संगठन में भी परिलक्षित हुई, जिसका निर्माण अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा की स्थापना के लिए किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो भी अन्तर्राष्ट्रीय विवाद चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जाता, उसी पर दोनों छेमे विरोधी मत जाहिर करते। इससे जहाँ अन्तर्राष्ट्रीय तनाव का दण्डना स्थायीकृत था, वहीं धीरे-धीरे संयुक्त राष्ट्र संघ अपने उद्देश्य में प्रभावहीन साबित होने लगा। पर महाशक्तियों द्वारा देतात अपनाने से छेमेबाजी कमजोर हुई और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी प्रभावशाली ढंग से कार्य करना आरम्भ कर दिया। अब वह विवादों के शान्तिपूर्ण ढंग से हल में अधिक सक्षम होने लगा। इस प्रकार देतात में संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभावशाली ढंग से कार्य करने लगा।

(8) गुट निरपेक्ष देशों सहित तीसरी दुनिया की एकता का मार्ग प्रशस्त होना—देतात मुग में अमरीका और सोवियत संघ एक-दूसरे के नजदीक आये। परिणाम यह हुआ कि नई विश्व अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित अनेक मुद्दों (जैसे गरीब देशों के नज्ने माल की उचित कीमत, प्रौद्योगिक हस्तान्तरण, समुद्री सम्पदा के दोहन तथा परमाणु शक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोग) पर महाशक्तियाँ तीसरी दुनिया के अल्प-विकसित देशों की माँगों के विरुद्ध हो गयी। इसने तीसरी दुनिया के देशों में एकता की भावना को मजबूत किया। नई विश्व अर्थव्यवस्था, समुद्री सम्पदा के दोहन, परमाणु शक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोग, नई समानार व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर तीसरी दुनिया के देश आगामी सहयोग द्वारा एकजुट होकर आरम्भ-निर्भरता

की दिशा में अग्रसर हुए। देनाज-अग्नि तीसरी दुनिया की एकता की विवाहशील दंगों के लिए लाभकारी ही माना जायगा।

(9) मानवाधिकार आन्दोलन प्रारम्भ होना—हैनरिकी सम्मेलन में अमरीका और नोर्वेजियन मध्य में मानव सम्पर्क बढ़ाने के लिए 'तीसरी दुनिया' के तहत अनेक धारणाएँ कीं। नाबियन सच ने काफी आनाकानी के बाद मान लिया कि परदेन में बसे अपने कुटुम्बियों से मिलने के लिए विदेश यात्रा का 'वीजा' माँगने वाले रुमियों के आवेदन पत्रों पर वह महानुभूतिपूर्वक विचार करेगा। उसने बतल दिया कि विभिन्न दंगा के नागरिकों में परस्पर विवाह और अपने मनपसन्द देना में दमन की उनकी इच्छा पर वह 'भारतीयता' एवं मानवतावादी भावना से विचार करेगा। इस अनिश्चित तीसरी दुनिया में सनी प्रकार की सूचनाओं के मुक्त तथा व्यापक आदान प्रदान और अग्र देणों से प्रवाशित समाचार पत्र-पत्रिकाओं के प्रसार में सुधार की अपील की गयी। नाबियन सच द्वारा अपने बन्द समाज (Closed Society) अर्थात् 'लोह आवरण (Iron Curtain) की नीति में ढील देने के कारण जहाँ एक तरफ राजनीतिक विरोधियों (असन्तुष्ट लोग) का हमला कम हुआ, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक विरोधियों ने सोवियत सरकार के विरुद्ध महाधिकार रक्षा आन्दोलन चलाया। इस संस्थागत तथा इन्फिडिक्सी जैसे राजनीतिक विरोधियों द्वारा चलाय गये मानवाधिकार रक्षा अभियान तेज हुए क्योंकि अग्र देना के लोपो तथा नाबियनसमिया में अन्त क्रिया (Inter action) आरम्भ हो गई। कई विद्वानों ने नाबियन सच में मरकाही दमन के विरोध में मानवाधिकार रक्षा अभियान शुरू होना लोकतन्त्र के लिए आनन्दोद्दी प्रभाव माना।

देनात के हानिकारक प्रभाव—जहाँ महाशक्तियों के बीच देनात सम्बंधों ने विश्व राजनीति पर अनेक लाभकारी प्रभाव डाले, वहीं इसमें अनेक हानिकारक प्रभाव भी पैदा किए। सबसे आर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों ने बहुत कम ध्यान दिया है। प्रमुख हानिकारक प्रभाव निम्नांकित हैं—

(1) अपने-अपने प्रभाव क्षेत्रों का विभाजन—शीत युद्ध के दौरान दाना महाशक्तियों ने विश्व में अपने-अपने प्रभाव क्षेत्र स्थापित किए और इसमें उनका बीच टकराव हुआ। हालांकि देनात सम्बंधों को अपनाकर उद्धान आपस में सहयोग स्थापित किया किन्तु इस सहयोग के आधार पर उद्धान विश्व में मौजूद अपने-अपने प्रभाव क्षेत्रों का विभाजन कर लिया। मसलन नाबियन सच ने लार्नीनी अमरीकी करिदियाई एवं पश्चिमी यूरोप के अधिकार दंगा में अमरीकी आधिपत्य स्वीकार कर लिया। दूसरी तरफ अमरीका ने पूर्वी यूरोप तथा विश्व के कुछ अन्य दंगा में नाबियन आधिपत्य स्थापित कर लिया। दाना ने अग्रन्त्यन्त रूप से स्वीकार किया कि एक-दूसरे के प्रभाव क्षेत्र में विरोधी कारवाह नहीं करेंगे। देनात का यह हानिकारक प्रभाव है क्योंकि इसमें महाशक्तियाँ के कई प्रभाव-क्षेत्र लगभग जमा के लो समदाजी में फँसे रहे। इस अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में महाशक्तियों द्वारा तन्त्रात्मीय शक्ति सन्तुलन की यथार्थता बनाय रखने की मांगिया कहा जायगा।

(2) विश्व शक्ति एवं सुरक्षा की स्थापना में तीसरी दुनिया की भागीदारी की उपेक्षा—देनात का अग्र हानिकारक प्रभाव यह हुआ कि महाशक्तियाँ विश्व शक्ति एवं सुरक्षा के नाम पर चुपके चुपके आपसी समझौते करने लगीं। विश्व शक्ति और सुरक्षा की स्थापना की जिम्मेदारी सभी राष्ट्रों की हानी है। अमरीका

और सोवियत संघ ने निरास्त्रीकरण के लिए राष्ट्र समझौते करते समय अन्य राष्ट्रों से किसी प्रकार का परामर्श नहीं किया और न ही बाद में उन्हें विश्वास में लिया। इस प्रकार महाशक्तियों ने विश्व-शान्ति और सुरक्षा को कायम रखने का ठेका लेकर जो समझौते किये उनमें उन्होंने तीसरी दुनिया की भागीदारी की उपेक्षा की। विश्व-शान्ति एवं सुरक्षा की स्थापना केवल अमरीका और सोवियत संघ के मध्य द्विपक्षीय ही नहीं, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा है।

(3) महाशक्तियाँ बनाम तीसरी दुनिया—देतांत का अन्य हानिकारक प्रभाव यह पड़ा कि इससे महाशक्तियों और तीसरी दुनिया के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गयी। शीत युद्ध के दौरान अमरीका और सोवियत संघ अन्य राष्ट्रों को अपने क्षेत्र में घिसाकर आपस में क्रमशः पूँजीवादी और साम्यवादी विचारधारा के टकराव का रूप दे रहे थे, पर देतांत को अपनाकर उन्होंने पूँजीवादी और साम्यवादी दोनों प्रणालियों के शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व का सिद्धान्त मानकर आपस में सहयोग किया। उनके बीच इस सहयोग ने उनके तथा तीसरी दुनिया के बीच टकराव पैदा कर दिया। यह अनेक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों में परिलक्षित हुआ। मसलन समुद्री संसाधनों के दोहन, समानता एवं न्याय पर आधारित नई विश्व अर्थव्यवस्था की स्थापना, परमाणु ऊर्जा के शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए उपयोग आदि अनेक मुद्दों पर महाशक्तियाँ और तीसरी दुनिया के बीच टकराव आरम्भ हो गया, क्योंकि इन मसलों पर अमरीका और सोवियत संघ के हित समान हैं और तीसरी दुनिया के हित उससे एकदम भिन्न। इस प्रकार देतांत ने विश्व राजनीति में महाशक्तियाँ बनाम तीसरी दुनिया के बिनाब को जन्म देकर हानिकारक प्रभाव डाला।

देतांत की आलोचना (Criticism of Detente)

महाशक्तियों द्वारा अपनायी गयी देतांत प्रक्रिया की अनेक आधारे पर आलोचना की जा सकती है—

(1) देतांत शक्ति-सन्तुलन के भीड़े सिद्धान्त का परिष्कृत रूप—शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों ने घुलनम-बुलना शक्ति-सन्तुलन का सिद्धान्त अपनाकर अन्तर्राष्ट्रीय समाज को नियन्त्रित करने की कोशिश की। जब इसके द्वारा वे विश्व के अन्य देशों को बेचकूत नहीं बना सके तो कुछ अन्य कारणों के साथ देतांत सम्बन्ध अपनाकर उसी प्रकार की एक नई एवं परिष्कृत साजिश रची। इसके सहित दोनों ने आपसी सन्तुष्टि के आधार पर मौजूदा शक्ति-सन्तुलन को यथास्थिति कायम रखने की चाल खेपी।

(2) देतांत यूरोप तक सीमित, विश्व के अन्य भागों में उसका फैलाव नहीं—शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों द्वारा अधिकांश राष्ट्रों में द्विपक्षीय या बहुपक्षीय तनाव उत्पन्न किया गया। महाशक्तियों ने आपसी द्विपक्षीय तनाव को तो कम कर दिया (जो अच्छी बात थी) किन्तु इसका असर केवल उनके निकटस्थ यूरोपीय देशों तक सीमित रहा। अफ्रीका-एशियाई, लातीनी अमरीकी और केरिबियाई क्षेत्र के देशों पर इसका प्रभाव नहीं हुआ।

(3) देतांत की दिशाहीनता—देतांत की दिशाहीन बहना अनुचित नहीं होना। देतांत के अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, माधन आदि के बारे में अमरीका और

सोवियत संघ के बीच व्यापक मतभेद रहे। ऐसी स्थिति में देतान को 'दिराहीन' की ही संज्ञा दी जा सकती है।

(4) स्थायी शान्ति के अत्यन्त ठोस प्रयास नहीं—महाशक्तियों द्वारा दोनों के बीच निरस्त्रीकरण, आर्थिक, मास्कुतिक या अन्य कोई भी समझौते पर घनिष्ठता बढ़ायी गयी। उन्हें स्थायी विद्व शान्ति और सुरक्षा स्थापित करने के दृष्टिकोण से अत्यन्त ठोस प्रयास नहीं माना जा सकता। इन्हें केवल अस्थायी प्रयास कहना उचित होगा, क्योंकि ये समझौते कुछ ही वर्षों के लिए किये गये। इन समझौतों की कालावधि समाप्त होने पर शान्ति की क्या गारन्टी हो सकती है?

(5) तनाव क्षेत्र फिर भी मौजूद—प्रायः कहा जाता है कि महाशक्तियों द्वारा देतान अपनाने से विद्व के अन्य भागों में तनाव क्षेत्र समाप्त हो गये। किन्तु असल में ऐसा नहीं हुआ। अनेक क्षेत्र ऐसे थे जहाँ महाशक्तियों के प्रोत्साहन के कारण तनाव मौजूद रहा। भूमध्य पश्चिम एशिया क्षेत्र को ही लिया जाये। 1978 में तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति कार्टर की मध्यस्था से इजरायल और मिस्र के बीच हुए कैम्प डेविड समझौते के बाद भी उस क्षेत्र में तनाव में कभी उल्लेखनीय कमी नहीं हुई। इसका सबसे प्रमुख कारण अमरीका तथा सोवियत संघ द्वारा पश्चिम एशिया क्षेत्र के देशों को एक-दूसरे के विरुद्ध भड़काना है। इससे वहाँ तनाव बना रहा। यही बात कई अन्य क्षेत्र में भी समान रूप से लागू होती है।

देतान का एशिया पर प्रभाव

देतान की सबसे बड़ी उपलब्धि हैलैनिकी में हुए समझौते के अनुसार यूरोप में महाशक्तियों के बीच युद्ध की आशंका टालना था। किन्तु यूरोप के बाहर इसका प्रभाव नकारात्मक ही रहा। शायद दोनों महाशक्तियाँ यह अनुभव करनी थी कि यूरोपीय टकराव की स्थिति में सीधे युद्ध की आशंका अधिक है। मगर एशिया, अफ्रीका या सानीनी अमरीकी देशों में टकराव की स्थिति बरकरार रहने हुए भी सीधे युद्ध की सम्भावनाओं का इतना खतरा नहीं था। अतएव देतान की भावना में यूरोपीय भूमित्वाओं को मुलजाने की इच्छा ही प्रमुख थी।

देतान के बादरूढ़ एशिया दोनों महाशक्तियों के टकराव का क्षेत्र बना रहा। हैलैनिकी सम्मेलन के बाद आगवा व्यक्त की गयी कि दोनों महाशक्तियाँ अपने सैनिक, राजनीतिक और आर्थिक साधन एशिया पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए और भी आसानी से प्रयोग कर सकेंगे। इससे कम द्वारा चीन पर सैनिक दबाव डालने, हिन्द महासागर और प्रशान्त महासागर में अपनी नौसैनिक गतिविधियाँ बढ़ाने और मध्य पूर्व तथा दक्षिण पूर्व एशिया में अपने प्रभाव-क्षेत्र के विस्तार के लिए अपने सशस्त्रों और साधनों का प्रयोग सामिन था। दूसरी ओर अमरीका हिन्द महासागर तथा प्रशान्त महासागर में अपना नौसैनिक वर्चस्व स्थापित करने तथा चीन, जापान और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को नीतिव्यो से हमी तत्व को समाप्त करने की कोशिश करेगा। कुल मिलाकर तीसरी दुनिया के देशों ने यह आसना व्यक्त की थी कि महाशक्तियों के इस एकरूपता सामंजस्य ने जहाँ एक ओर उमके स्वतन्त्र विकास में बाधा पैदा की है, वही दूसरी ओर उनके महत्व को भी घटा दिया है।

देतान प्रविजा के चीन और जापान पर पड़े नकारात्मक प्रभाव का उन्नेय

करते हुए आर० के० जैन ने ठीक ही लिखा कि राजनीतिक दृष्टि से यूरोप में हेल्सिंकी सम्मेलन के बाद सीमाओं के स्थिरीकरण से सोवियत भू-भाग पर चीनी दावों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। जापान के सोवियत सघ के विरुद्ध भौगोलिक दावों पर भी ऐसा ही प्रभाव होगा। सोवियत-अमरीकी मैस-मिलान जापान की भाँगों को ठण्डा कर सकती है।¹ अतएव जापान और चीन दोनों देसात की प्रक्रिया से सीधे प्रभावित होने वाले राष्ट्र थे। इधर दक्षिण पूर्व एशिया में भी अमरीकी पराजय के बाद चीन के बढ़ते प्रभाव क्षेत्र को देसात ने कुछ हद तक रोका क्योंकि चीन का खुल्लम-खुल्ला समर्थन करके अमरीका सोवियत सघ के साथ तनाव-संश्लिष्य की प्रक्रिया को ठेग पहुँचाने की हिम्मत नहीं कर सका। मध्य पूर्व में मिस्र द्वारा फिलिस्तीनियों का साथ छोड़कर इज़राइल और अमरीका से मिल जाने की प्रक्रिया को रुक रोकने में असफल रहा क्योंकि फिलिस्तीनियों का समर्थन होने के बावजूद वह अमरीका के साथ अपने सम्बन्ध पर आँच नहीं माने देना चाहता था।

देसात ने एशिया के छोटे देशों पर विश्व शक्तियों के प्रभाव को और अधिक बढ़ा दिया। शीत युद्ध के दौरान एक महाशक्ति के नाराज हो जाने पर दूसरी महाशक्ति का समर्थन किसी देश को मिल जाता था और इस प्रकार वह अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने में सफल होता था। तनाव-संश्लिष्य की प्रक्रिया ने छोटे राष्ट्रों द्वारा विश्व शक्तियों को एक-दूसरे के विरुद्ध प्रयोग करने की परम्परा पर विराम चिह्न लगा दिया। देसात के दौरान दोनों महाशक्तियाँ मिलकर यह तय करने लगी कि छोटे राष्ट्रों के सकट को कैसे सुलझाया जाये और वहाँ दोनों में से किसका प्रभाव क्षेत्र कायम किया जाये।

आर्थिक दृष्टि से देसात का प्रभाव एशिया के देशों पर लाभप्रद नहीं रहा। मध्य पूर्व के तेल-निर्मातक देशों ने स्वयं को पूँजीवादी देशों से मुक्त करने में सफलता इसलिए नहीं पायी कि रूस न तो उन्हें सैनिक संरक्षण दे सकता था और न उनका तेल खरीद सकता था। कच्चे तेल के निर्यात की दृष्टि से एशिया के सभी देश पूँजीवादी देशों पर निर्भर हो गये और रूस इस निर्भरता को कम करने की दृष्टि से कोई कदम नहीं उठाना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने से उसके अमरीका के साथ सम्बन्धों पर बुरा प्रभाव पड़ता जो वह नहीं चाहता था। दूसरी और अमरीका अपने प्रभाव क्षेत्र बाने एशियाई देशों से कच्चे तेल की रस्ती खरीद में कोई रुकावट नहीं डाल रहा था, जैसे, रूस मलयेशिया से तेल और रबड़ आसानी से प्राप्त कर रहा था। कुल मिलाकर आर्थिक क्षेत्र में भी एशियाई देशों की सोदेबाजी की क्षमता देसात के बाद कम हो गयी और कच्चे तेल की कीमतों का निर्धारण पश्चिमी राष्ट्रों के हाथों में चला गया।

देसात का मूल्यांकन (Assessment)

रोबिन एडमंड्स का मानना है कि 1962 से शुरू होने वाला दशक देसात का युग था।² उनका यह भी कहना है कि 'देसात' शब्द में जिस तरह का सम्बन्ध मोहादेपूर्ण व मधुर प्रतिध्वनि होता है, वह महाशक्तियों के मन्दमं में सटीक नहीं।

¹ R. K. Jain, *Defense in Europe - Implications for Asia* (Delhi, 1977), 244.

² Robin Edmonds, *Soviet Foreign Policy* (London, 1975), 168

पारम्परिक प्रयोग में हमसे तनाव-शैथिल्य का बोध होता है, जो इस मामले में पूरी तरह सही नहीं। जैसा कि उपरोक्त सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि देतान के अन्तराल में महानाक्तियों के बीच दान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व स्वाभाविक या नियमित नहीं रहा। अतः इसे अन्तर्राष्ट्रीय जीवन का सर्वसम्मत नियम या स्थायी नीति नहीं कहा जा सकता। एडमंड्स इस बात को स्वीकार करने से नहीं कतराने कि ब्रिटेन-फ्रांस सम्बन्धों के परिप्रेक्ष्य में इस शताब्दी के पहले चरण में जो परिकल्पना विकसित की गयी, उसकी सम-सामयिक नई व्याख्या विसंगत है। भले ही, देतान के सूत्रपात ने अमरीका-सोवियत सम्बन्धों को महत्वपूर्ण ढंग से बदला परन्तु पुरानी परिभाषा की अनुगूँज भ्रान्ति ही पैदा करती है। 25 अक्टूबर, 1973 को एक प्रेस सम्मेलन में हेनरी किमिजर ने बदली परिस्थिति और बदले परिदृश्य में इन सम्बन्धों को जिस तरह परिभाषित किया, उनको निखारना आज भी कठिन है। किमिजर ने कहा था—सोवियत संघ के साथ हमारे सम्बन्ध अटूट हैं। हम एक साथ, एक ही वक्त विपक्षी भी हैं और सहयोगी भी। एडमंड्स का यह मानना बिल्कुल सही है कि एक काल विशेष में आन्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय घटना-क्रम के दबाव से अपनायी गयी राजनयिक रणनीति ही देतात थी। इसे विश्व इतिहास में कोई भ्रान्तिकारी या निर्णायक महत्व का परिवर्तन समझना गलत होगा। इसी कारण बदली परिस्थिति में क्रिया-प्रतिक्रिया वाले मिथ्यान् के अनुसार देतान को भी स्थायना सम्भव हुआ।

1970 के दशक के अन्तिम वर्षों तक विश्व भर में ऐसी अनेक घटनाएँ घटी जिन्होंने देतात के तर्क को झुल्ला दिया। चीन में भाओ युग की समाप्ति, अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप, लेबनान संकट में विवाद, कम्बुडिया में वियतनामी अतिप्रभुता को सोवियत समर्थन, ईरान में शाह का तख्ता पतन व इस्लामी कटमुल्लापन का उद्धार, ईरान-इराक युद्ध का जारी रहना, दक्षिण अफ्रीकी मस्लवाद के आश्रमिक तैवर, निकारागुआ एक दक्षिण अमरीका में अन्यत्र परेश रूप से अमरीका द्वारा सैनिक हस्तक्षेप आदि जैसी घटनाएँ घटी, जिससे देतान की भावना को गहरा घक्का पहुँचा।

सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचोव ने एशियाई प्रगल्भ प्रदेश में शांति क्षेत्र के विस्तार के लिए जो नई योजना सुझायी, उसकी एक विशेषता यह है कि उसमें 'प्रतिस्पर्धी महकारी महानाक्ति' के रूप में सिर्फ अमरीका को ही नहीं बल्कि चीन को भी आमन्त्रित किया गया अर्थात् 'तनाव-शैथिल्य की प्रक्रिया नये दबावों के अनुसार न तो सिर्फ महाशक्तियों तक सीमित रह गयी है और न ही उसका मुख्य प्रभाव-क्षेत्र यूरोप तक सिमटा है। तनाव-शैथिल्य की वास्तविकता पर सवालिया निशान लगाता जरूरी है। भले ही रोज़मर्रा की चानचीत में सोवियत-चीन, चीन-जापान, आसियान-वियतनाम सम्बन्धों में किसी भी परिवर्तन को देतान की मज्जा देने में जल्दबाजी की जानी थी, परन्तु यह याद रखना उपयोगी होगा कि देतान एक युग नहीं, देश-काल बद्ध अन्तराल था।

सातवाँ अध्याय

नया शीत युद्ध

तनाव-शीथिल्य को जो प्रक्रिया 1962 में क्यूबाई मिसाइल संकट के बाद आरम्भ हुई थी, वह लगभग 15-16 वर्ष तक निरन्तर जारी रही। मगर 1970 में दशक के अन्तिम वर्षों में एकाएक अप्रत्याशित ढंग से ऐसे अनेक अशुभ संकेत देखने को मिले, जिन्होंने विद्वानों को यह सोचने को विवश किया कि कहीं 'नया शीत युद्ध'¹ तो आरम्भ नहीं हो रहा है। 1973 के ऊर्जा संकट के बाद अमरीकी विदेश मंत्री हेनरी किस्सिजर ने खाड़ी के तेल-उत्पादक देशों को जो प्रमोदियाँ दीं, उनसे अमरीका का 'आक्रमक अभिपति' वाला रूप झलका। निश्चय ही, तमाम तनाव-शीथिल्य के बावजूद सोवियत संघ इसका भूक दर्शन बना नहीं रह सकता था। कुछ समय बाद इस क्षेत्र में अपने हितों की रक्षा के लिए अमरीका ने तुरन्त तैनाती बल (Rapid Deployment Force) की योजना पेश की। अमरीका ने अपने सामरिक हितों के लिए यह जरूरी समझा कि हिन्द महासागर के क्षेत्र में डिएनो गाँतिया जैसे नए मैनिफेस्टो की स्थापना की जाये। ऊपर से देखने में इनमें से कोई भी घटना सोवियत संघ के खिलाफ नहीं थी। परन्तु इसका दूरगामी प्रभाव महाशक्तियों के सम्बन्ध को असंतुलित करने वाला था।

अन्तर्राष्ट्रीय संकटों का सन्निपात

1979 में दो ऐसी घटनाएँ हुईं, जिन्होंने तनाव-शीथिल्य के भ्रम को बचाये रखना असम्भव बना दिया। ये दो घटनाएँ थी—ईरान के शाह का पतन और अफगानिस्तान में सोवियत संघ का सैनिक हस्तक्षेप। ईरान के शाह अपने क्षेत्र में अमरीकी रणनीति के प्रमुख स्तम्भ थे, जो ढह गये। अफगानिस्तान में सोवियत सैनिक हस्तक्षेप ने न केवल सोवियत महारक्षाशा, बल्कि उसके सामर्थ्य की प्रमाणित किया। सोवियत शाह और समर्थन से ही वियतनाम ने कम्पुचिया में सफल हस्तक्षेप किया और वियतनाम चीन के साथ सैनिक मुठभेड़ को शेल सका। इन सब घटनाओं का संयोग अमरीका के पड़ोस में निकारागुआ और अल सल्वाडोर में मानसवादी सोवियत पराधर सरकारी के सत्ता सम्भालने से हुआ। इस तरह लगभग डेढ़ दशक बाद एक बार फिर पुराने शीत युद्ध के पहले चरण की तरह ही विश्व भर में अन्तर्राष्ट्रीय संघर्षों का सन्निपात दिखायी दिया। इनमें से अनेक जैसे ईरान में शाह का पतन या अफगानिस्तान में सोवियत प्रवेश महाशक्तियों के बीच टकराव लाने वाले थे।

¹ 'नए शीत युद्ध' को 'द्वितीय शीत युद्ध' या 'दूसरा शीत युद्ध' भी कहा गया है। इसी प्रकार 'पुराने शीत युद्ध' को 'पहला शीत युद्ध' भी कहा गया है। इस पुस्तक में सुविधानुसार इन सभी नामों-मापदण्डों का प्रयोग किया गया है।

तनाव-शैथिल्य में नए शीत युद्ध के बीज

उपर्युक्त सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि दूसरे या नए शीत युद्ध के बीज तनाव-शैथिल्य में निहित थे। तनाव-शैथिल्य का स्वागत करने के उल्हास में किसी ने इसकी सीमाओं को याद रखने की आवश्यकता नहीं समझी। 'वैरी सहकारिता' (adversary partnership) वाली गिडितेदारी में 'वैर' और 'सहकार' दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं और इनमें से किसी भी पक्ष की अवहेलना लाभप्रद नहीं हो सकती। जहाँ एक ओर माल्ट-एक समयौन और हैलसिंकी शिखर सम्मेलन ने तनाव-शैथिल्य के रचनात्मक पक्ष को स्पष्ट किया, वहीं माल्ट-दो की निष्फलता ने इसकी सीमाओं को भी झलकाया।

अमरीका में राष्ट्रपति निकसन के कार्यकाल के अन्तिम वर्षों में दो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियाँ स्पष्टगोचर हुईं। वाटरगेट प्रकरण में यह बात पता चली कि राष्ट्रपति कार्यालय में नीति-निर्धारण की प्रणाली-प्रक्रिया कितनी दोषपूर्ण है और वैदेशिक मामलों में यह एक हद तक राष्ट्र को कमजोर बनाने वाली हो सकती है। दूसरी ओर निकसन ने चीन के साथ अमरीका के सम्बन्ध सुधार कर सोवियत संघ पर एक तरह का करारा राजनयिक वार करने की अपनी क्षमता प्रदर्शित की। निकसन ने इस सारे दौर में अपने तमाम सचटो के बावजूद हिन्द महासागर में शक्ति-समर्थ और अमीबा में क्यूबाई सैनिकों के माध्यम से अस्थिरता साने के आरोप लगाकर सोवियत संघ को बचाव की मुद्रा के लिए विवश किया।

दूसरी ओर ब्रेझनेव के शासन काल में सोवियत साम्यवादी पार्टों और नेताओं को इस बात का अहसास होने लगा कि उन्हें अमरीका के सामने दबने-भुजने की कोई आवश्यकता नहीं। सोवियत शक्ति की 60वीं वर्षगांठ मनाने-मनाते सोवियत जनता अपने जीवन स्तर में बेहतरी की माँग मुखर करने लगी थी। इससे परिणामस्वरूप सोवियत विदेश नीति के निर्धारण व संचालन में एक नया आत्म-विश्वास देखने को मिला। ऐसी स्थिति में जब सोवियत संघ को महसूस हुआ कि अमरीका तनाव-शैथिल्य के अन्तर्निहित तर्कों के अनुरूप आचरण नहीं कर रहा और उसे महाशक्ति के रूप में नहीं देखा रहा है तो उसने अपने राजनयिक नियायन्त्राप में जवाबी तौर पर तनाव-शैथिल्य की शर्तों का उल्लंघन आरम्भ कर दिया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण पश्चिम एशिया सचट निवारण के लिए अमरीकी नियायन्त्राप में मिलता है जिसकी परिणति रॉस डेविड समझौते में हुई। अमरीका ने इजरायल एवं मिश्र के बीच मुनह-मन्धि कराने वक्त सावियत संघ को मध्य रखने की कोई जरूरत नहीं समझी। इथियोपिया, अंगोला आदि में बढ़ी सोवियत रुचि इसी सन्दर्भ में समझ में आती है। इसी तरह इस बात की भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि ईरान में शाह के पतन के बाद जिस इस्लामी कट्टरता का दौर शुरू हुआ, उसकी उपेक्षा सावियत संघ अपनी जनसंख्या के मुसलमान हिस्से को देगते हुए नहीं कर सकता था। अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप के घटने चीन-ईरान साठगाठ में सोवियत संघ के इस दक्षिणी सम्पर्क में 'शोक ए जावेद' जैसे छापामारों की गतिविधियाँ शोचनीय रूप से घुसी थीं। सावियत संघ द्वारा विषयनाम को दिया गया समर्थन व सहायता भी तब तक टीक में नहीं समझे जा सकते, जब तक हम इस बात को याद नहीं रखते कि हिन्द

चीन से अपनी वापसी के बाद पोब पोट और मिहानुक के पक्षधर षड्यन्त्रकारी छापामारों के जरिये परीक्षे रूप से अमरीका और चीन, वियतनाम को निरन्तर कष्ट पहुँचाते रहे। यदि सोवियत सघ वियतनाम का साथ नहीं देता तो उसे महाशक्ति के रूप में अपनी हैसियत बचाये रखना कठिन हो जाता और यह बात स्वीकार करनी पड़ती है कि उसके हित, उसकी भौगोलिक सीमाओं के भीतर सिमटे हैं, अमरीका की तरह विश्व भर में फैले हुए नहीं।

नए शीत युद्ध के उद्भव के कारण

नए शीत युद्ध के उद्भव के दो कारण हैं, जिनकी ओर ध्यान देना जरूरी है। राष्ट्रपति जिमी कार्टर के कार्यकाल में अमरीकी विदेश नीति का एक प्रमुख मुद्दा मानवाधिकारों की रक्षा बना और आलोचना का प्रमुख लक्ष्य सोवियत सघ को बनता पड़ा। अपने मित्र राष्ट्रों अर्जेंटीना और चिली में मानवाधिकारों के हनन की ओर अमरीका की आँख मूंदी रही। साथ ही बड़े पैमाने पर सैनिक एरष, वैज्ञानिक परियोजनाओं को सरकारी अनुदान की स्वीकृति देने के लिए भी तत्पाद और तबट की मानसिकता बनी रही। इन सबकी प्रतिप्रिया में सोवियत सघ ने अप्रत्यक्ष रूप से क्यूबा के माध्यम से लातीनी अमरीकी भू-भाग में अमरीका की दुर्बलता को उद्घाटित करना आवश्यक समझा। मानवाधिकारों का प्रश्न ही या सैन्यीकरण का, व्यक्तित्व का टकराव हो या सैद्धान्तिक विवाद, एक बार फिर दो व्यवस्थाओं का कुनियादी विरोध समान्त न कर सकना नए शीत युद्ध के रूप में सामने आया।

नए शीत युद्ध की परिभाषा

(New Cold War . Definition)

कुछ विद्वानों के मत में नया शीत युद्ध नया या दूसरा नहीं, बल्कि पुराने शीत युद्ध काल का एक और चरण है। दूसरी ओर फ्रेड हेलीडे और के० सुब्रह्मण्यम जैसे विश्लेषकों ने प्रकृति में मूलभूत अन्तर के कारण इन दोनों में फर्क बिचा है। सुब्रह्मण्यम के विचार से 'पहले और दूसरे शीत युद्ध में विवसशील देशों के आचरण के सन्दर्भ में दो बातों के आधार पर फर्क किया जा सकता है। पहले शीत युद्ध के दौरान सोवियत सघ के पास तातो समुद्रों के नीचे जल पर बिहार करने वाली नौसेना नहीं थी। परिणामस्वरूप उसकी शक्ति-क्षमता की पहुँच बिश्व भर में नहीं देखी जाती थी—कम से कम अमरीका में तो नहीं—।' दूसरा महत्वपूर्ण अन्तर यह है कि औपनिवेशिक काल के षडयन्त्र विकासशील देशों ने अपने क्षेत्र में प्राकृतिक ससाधनों पर राजनीतिक और कानूनी स्वामित्व ग्रहण कर लिया। तब इन देशों के पास अपने प्राकृतिक ससाधनों के समुचित दोहन के लिए सोवियत समाजवादी लेमे की वैकल्पिक टैक्नोलोजी मुलम हुई।¹

इसके अलावा सुब्रह्मण्यम के मत में नये शीत युद्ध के कुछ और पहलू पुराने शीत युद्ध से भिन्न हैं। पुराने शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों के समिध-मित्र देश सैनिक सगठनों और वार्षिक सहायता के माध्यम से उनके आजाकारी व अनुशासित शिविरानुचर बने रहते थे। लेकिन आज सिर्फ दक्षिण अफ्रीका और इजराईल ही निरपुत्र उच्छश्रुंयलता ही नहीं, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, रुमानिया जैसे

¹ K. Subrahmanyam, *The Second Cold War* (Delhi, 1993), 20-21

देशों की 'स्वाधीनता' द्विध्रुवीय विश्व को विसम त सिद्ध कर चुकी है। पुराने शीत युद्ध के दौरान दो महाशक्तियों के बीच टकराव को रोकने और शान्ति के क्षेत्र को विस्तृत करने के लिए गुट निरपेक्ष आन्दोलन का आविर्भाव हुआ और उसने एक रचनात्मक-मायंक भूमिका निभाई। इसके विपरीत सम-सामयिक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में नये शीत युद्ध के आरम्भ ने गुट निरपेक्ष आन्दोलन में दरारें पैदा कर दी। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के पहले चरण में अन्तर्राष्ट्रीय मकट का केन्द्र यूरोप था, जबकि 1978 के बाद के दशक में शक्ति-संघर्ष के लगभग भारे मौके अफ्रीका, एशिया और लातीनी अमरीका में दृष्टिगोचर हुए हैं।

अन्त में, अमरीकी शक्ति का अपेक्षाकृत ह्रास, सिर्फ सोवियत समता के विस्तार के कारण नहीं, बल्कि आर्थिक क्षेत्र में जापान और जर्मनी के आर्थिक महा-शक्ति के रूप में उदय के कारण भी शीत युद्ध के दौर में जटिलता आयी। इनमें से अनेक बानों की पुष्टि फ्रेड हेलीडे ने भी की है। उन्होंने अलग से कुछ विचारोत्तेजक टिप्पणियाँ की हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पुराने शीत युद्ध में सैद्धान्तिक या वैचारिक पक्ष जिस तरह महत्वपूर्ण था, नये शीत युद्ध के टकराव में उसकी वह स्थिति नहीं रही। इतिहासकार आर्नो मेयर का एक सटीक उदाहरण देते हुए फ्रेड हेलीडे ने इस बात पर जोर दिया है कि पुराने शीत युद्ध के दौरान अमरीका और सोवियत संघ जिन सैद्धान्तिक हथियारों से एक-दूसरे पर वार करते थे, उनका भण्डार आज खर्च हो चुका है। आज ये दोनों महाशक्तियाँ जिस दगल में बिड़ी हैं, वह तीसरी दुनिया में आधिपत्य जमाने के लिए सीधी सादी जोर आजमाइश हैं।¹

भूतपूर्वक अमरीकी विदेश मंत्री हेनरी किस्सिजर ने स्वयं यह बात स्वीकार करते हुए कहा कि 'हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम शत्रुओं के साथ अपनी प्रतिद्वन्द्विता को सीमित-निमित्त करें।' भले ही उन्होंने यह कहा कि हम सोवियत संघ विपक्ष मानसिक ध्वज-कुठा से मुक्त होना चाहते हैं, परार्थ में नीति निर्धारण और सम्पादन इस मफाई के अनुसार नहीं हुए। प्रसिद्ध विद्वान एलस्टर बेकन ने 1973 में वह भविष्यवाणी कर दी थी कि 'सोवियत संघ और अमरीका को अन्ततः तीसरी दुनिया में अपना आधिपत्य स्थापित करने के विषय में कोई न कोई समझ हासिल करनी होगी। यूरोप व पश्चिम एशिया जैसे स्थानों के बारे में एक-दूसरे की भयना (vulnerability) को देखते हुए शीत युद्ध की चपेट से छुटकारा पाया जा सकता है।'² ऐसा न हो सकने के कारण ही नये शीत युद्ध ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को संकटग्रस्त बनाया।

शीत युद्ध को परिभाषित करते हुए 'अमृति एवं निर्धनता' (Wealth and Poverty) नामक पुस्तक के लेखक जॉन गिल्डर ने यह मत अभिव्यक्त किया कि 'द्वितीय शीत युद्ध का प्रमुख कारण और इसकी प्रकृति की विशेष पहचान का एक प्रमुख तत्व साम्यवादी अपने का मर्याप्त होना है।' हैबिट ने इससे अपनी अमहमनि प्रकट करते हुए लिखा है कि 'वस्तुतः दूसरा शीत युद्ध पारम्परिक दक्षिणपंथी विचारधारा का पुनर्प्रेषण नहीं, बल्कि नव-अनुदारवाद (New-Conservatism) का

¹ Fred Halliday, *The Making of the Second Cold War* (London, 1983), 19.

² फ्रेड हेलीडे की पुस्तक पृष्ठ 19।

बलवान होना था।' इसकी पुष्टि कार्ल केमर आदि द्वारा लिखित 'पश्चिम की सुरक्षा : क्या बदला और क्या किया जाये' (Western Security What has changed and What should be done) नामक पुस्तक में प्रकाशित सागरी से होती है। इसमें विदेश नीति सम्बन्धी पारम्परिक सामान्य ज्ञान को नकारा गया है। मारशेट घेचर का ब्रिटेन हो या रोनाल्ड रीगन का अमरीका, प्रतिपक्षी को पीछे घेने वाली मानसिकता-प्रतिबद्धता पूर्ववत् रही। अमरीका द्वारा अपनी तथा अपने मित्र देशों की विदेश नीति का संचालन एक बार फिर सोवियत संघ के साथ मूठभेद के लिए किया गया।

इन परिभाषाओं के विश्लेषण, इनकी प्रवृत्तियों की ममानता और अन्तर पर दृष्टिपात करने से यह बात स्पष्ट होती है 'वस्तुतः पुराने तथा नये शीत युद्ध के मौलिक स्वरूप में अन्तर उतना बुनियादी नहीं जितना अवसर बतलाया जाता है जैसा कि हेल्ड्रे में अपने निष्कर्ष में लिखा—'शीत युद्ध के दोनों चरण (भर्भात पुराना व नया शीत युद्ध) विव्यक्ति (Impersonal) और दसक-होड़ के कारणों भर से नहीं उपजे थे, बल्कि इनका विकास विश्वव्यापी सामाजिक संघर्ष तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अन्य घटित घटकों की अन्तर-क्रिया से हुआ। द्वितीय शीत युद्ध उस बुनियादी टकराव को प्रतिबिम्बित करता है, जिसके रहते महाशक्तियों की नीतियों में सामंजस्य नहीं बिठाया जा सकता। इसका आविर्भाव इसलिए तेज हुआ कि दोनों पक्ष पुराने शीत युद्ध के दौरान हासिल सभी उपलब्धियों को बरकरार रख सकें और सन्तु का आतंक दिखाकर अपने सेना की एकरा बनाये रख सकें। यदि पहला शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्लबेल्ट प्रयासन की रणनीति-राजनय की सन्तान था तो दूसरा शीत युद्ध अमरीकी राष्ट्रपतियों और उनके सलाहकारों की सुविचारित, पूर्वनिश्चित व दूरदर्शी सामरिक योजनाओं का परिणाम। इस तरह द्वितीय शीत युद्ध न तो आकस्मिक दुर्घटना है और न ही कुटिल पदयन्त्र। यह सीमित क्षमता वाले सत्ताशुद्ध व्यक्तियों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को प्रभावित करने के प्रयत्न को प्रतिबिम्बित करता है। निरन्तर बदलती अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ महाशक्तियों के वर्चस्व को नई चुनौतियाँ पेश करती रही हैं और यही परिवर्तन प्रतिपक्षी के साथ शक्ति संघर्ष जारी रखने का नया आयाम उद्घाटित करती रही हैं। यही हमारे शीत युद्ध का संघर्ष है।¹

पुराने व नये शीत युद्ध में अन्तर

भले ही पुराने और नये शीत युद्ध के बीच कोई मूलभूत अन्तर न हो, फिर भी दोनों रिषटियों में महत्वपूर्ण अन्तर स्पष्ट दृष्टिगोचर होते थे, जिनके परिणाम दूरगामी निम्न हुए। इनमें प्रमुख अन्तर निम्नांकित हैं—

1. विस्तारपरा का अवमूल्यन—पूँजीवाद और साम्यवाद का टकराव 1945 से नहीं, बल्कि 1917 में ही विषय को दो खेमों में बाँट चुका था। 1945 से लेकर

¹ 'The Second Cold War was neither an accident, nor the product of some neat conspiracy; it reflected conscious long-term decisions taken by people in power with limited control over world events. There was a response to a changing world situation which provided new challenges to their system of domination and new opportunities for prosecuting the globalised conflict with opposing bloc'. —Fred Halliday, *Ibid.*, 23

1960-62 तक का सैद्धान्तिक कलह शीत युद्ध का मुख्य प्रेरक रहा। इसी आधार पर दोनों महाशक्तियों ने एक-दूसरे की नीतियों का मूल्यांकन किया और मविध्य के बारे में पूर्वानुमान लगाया। उनके द्वारा अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करने के लिए नैतिक व लगभग आध्यात्मिक-ताकिक शब्दावली का प्रयोग करना आम बात थी। अमरीका व हम ने तीसरी दुनिया के देशों का दिलो दिमाग जीतने के लिए मासहृतिक और आर्थिक राजनय को विदेश नीति के कारगर उपकरणों के रूप में इस्तेमाल किया। नये शीत युद्ध के वर्तमान दौर में विचारधारा का अवमूल्यन स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। ऐसा नहीं जान पड़ता कि किसी एक पक्ष के विचारधारा पर कम और दिये जाने से यह प्रक्रिया आरम्भ हुई। जैसाकि जॉन केनेथ गेल्ब्रेथ जैसे विद्वानों ने स्पष्ट किया है कि एक स्वाम स्तर की तकनीकी योग्यता हासिल करने के बाद पूँजीवादी और साम्यवादी राष्ट्र एक ही स्वरूप धारण कर लेते हैं। यह विवेचन 'अभिसरण धारणा' (Convergence Thesis) के नाम से विख्यात है और इसका विस्तृत व्योरा उनकी 'न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट' (New Industrial State) नामक पुस्तक में मिलता है। पिछले 12-13 वर्षों में भले ही अमरीका और हम की एक-दूसरे के प्रति आशंकता बढ़ी है, परन्तु इसका विस्तरेण बिना किसी सैद्धान्तिक शब्दजाल में पड़े विशुद्ध सामरिक कारणों से किया जा सकता है।

2. सघर्ष स्थल का स्थानान्तरण—पुराने शीत युद्ध में सबसे बड़ा सकट-स्थल यूरोप रहा, भले ही ईरान, कोरिया आदि समय-समय पर चर्चित रहे। आरम्भ से ही यह जान सर्वमम्मत्त थी कि विमाजित जर्मनी लोह-आवरण वाले शब्द प्रयोग की सार्यक बनाता है। द्वितीय विश्व युद्धोत्तर काल में सामाजिक व आर्थिक उथल पुथल का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। यूरोपीय क्षेत्र में साम्यवादी प्रभाव की कम करने के लिए मार्शल योजना की रूपरत्ना तैयार की गयी। बर्लिन की नाकेबन्दी इसी को स्पष्ट करती है। नये शीत युद्ध के वर्तमान चरण में सकट-स्थली का प्रवेश स्थानान्तरण होता रहा। 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक वियतनाम और हिन्द चीन अन्तर्राष्ट्रीय तनाव के मध्यमे बड़े केंद्र रहे। इसके बाद ईरान-इराक, अफगानिस्तान, कम्बुधिया, वियतनाम, अंगोला, मोजाम्बिक, इथियोपिया, सोमालिया, लेबनान आदि का घटना-क्रम निरन्तर विस्फोट बनता रहा।

3. प्रत्यक्ष मुठभेड़ की सम्भावना में वृद्धि—पुराने शीत युद्ध के दौरान उपनिवेशवाद का 'पूर्ण उन्मूलन' नहीं हुआ था। यह सम्भावना बची थी कि आन्ध्र व मनुलन के रहते महाशक्तियाँ प्रत्यक्ष टकराव से बचते हुए परोक्ष रूप से मिटकर एक-दूसरे की दामनाओं के रह सकते हैं। अफ्रीका और एशिया में चल रहे अनेक स्वाधीनता संग्रामों में पक्षधरता के कारण जहाँ एक ओर मोबियत मध्य ने लोक-प्रियता हासिल की, वहीं जन-मुक्ति आन्दोलनों को अस्थिरता पैदा करने वाला पड़पन्न घोषित कर एक यथास्थिति का बनावे रखने के अमरीकी प्रयत्न ने शीत युद्ध को अनावश्यक रूप से बटु एक तामद बनाया। अंगोला और मोजाम्बिक तथा तत्काल-पलट के बाद से अफगान घटनाक्रम इस धारणा को पुष्ट करने हैं। फिनोयोग्म से लेकर निकारागुआ तक उपनिवेशवाद तथा नव-उपनिवेशवाद की प्रत्यक्ष पकड़ कमजोर हुई। साथ ही महाशक्तियों में अग्रगण्य टकराव या रम्भाकशी की सम्भावना

का विकल्प शेष नहीं रहा। निश्चय ही, महाशक्तियों की आपसी मुठभेड़ों को कम खतरनाक बनाने वाले 'चकर' राज्यो का अभाव नये चीन युद्ध के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है। इससे अमरीका व सोवियत संघ में प्रत्यक्ष मुठभेड़ की सम्भावना बढ़ी।

4. सैनिक संगठनों का अवमूल्यन—पुराने शीत युद्ध के दौरान अमरीका और सोवियत संघ दोनों ने टकराव को बुनियादी तौर पर सैनिक माना और संकट समाधान के लिए सैनिक संगठनों को आवश्यक समझा। परिणामस्वरूप, महाशक्तियों द्वारा प्रवर्तित सिएटो, सेन्टो, वारसा सन्धि, वजुस, आग्ल-मलय आदि सैनिक समझौतों के माध्यम से तमाम विश्व में इन गठबन्धनों के साथ शीत युद्ध की मानसिकता का प्रसार हुआ। अपने को महाशक्ति बतलाने वाले राष्ट्र के लिए विश्व भर में अपने हितों को परिभाषित करने और इनकी रक्षा के लिए अपने सामर्थ्य के प्रदर्शन के लिए ये संगठन बहुत उपयोगी थे। 1950 के दशक में तत्कालीन अमरीकी विदेश मन्त्री डेलेस का 'डोमिनो सिद्धान्त' तथा 1960 के दशक में सोवियत संघ द्वारा सहयोगी राष्ट्रों की 'सीमित सम्प्रभुता के सिद्धान्त' का प्रतिपादन सैनिक संगठनों और इनके एक 'निर्विवाद नायक' की पृष्ठभूमि में ही समझा जा सकता है।

सैनिक संगठनों की स्थापना और विश्व का द्विध्रुवीकरण अभिन्न रूप से जुड़े हुए थे। सैनिक संगठनों की कटुता का क्षय और बहुध्रुवीकरण की प्रक्रियाएँ समानान्तर रूप से चलती रही। जहाँ एक ओर सोवियत-चीन विग्रह ने साम्यवादी खेमे में दरार डाली, वहीं फ्रांस द्वारा बेगेल के कार्यक्रमाल में स्वाधीन निजी परमाणु शक्ति हासिल करने एवं जर्मनी तथा जापान के आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने में यह स्पष्ट हुआ कि पश्चिमी खेमे में पहले जैसी एकता शेष नहीं बची है। विपतनाम में अमरीकी हस्तक्षेप, सभी 'सिएटो' सदस्यों तक को एकसाथ रखने में पूर्णतः सफल नहीं हुआ। इसी तरह निगन्धीकरण शिखर वास्तवों और यूरोप में सोवियत-अमरीकी मुमाबले को लेकर अमरीका और मित्र राष्ट्रों के बीच तनाव बना रहा है। 'नाटो' की जर्जरता का पता अभी पिछले वर्षों में फॉरलैंड युद्ध में पड़ा। अरब-इजराइल संघर्ष में 'सेन्टो' को अवसर से दशक पहले ही निरर्थक बना दिया था।

5. द्विध्रुवीय से बहुध्रुवीय विश्व—द्विध्रुवीय (Bi-polar) विश्व से बहु-ध्रुवीय (Multi-polar) विश्व में परिवर्तन ऐसी नाटकीय एवं महत्वपूर्ण घटना थी, जिनमें बहुत बड़ी सीमा तक द्वितीय विश्व युद्ध से पहले की स्थिति (अनेक राष्ट्रों के बीच शक्ति सन्तुलन वाली स्थिति को) की वापस ला दिया। द्वितीय महायुद्ध की हार-जीत और परमाणु अस्त्रों के आविष्कार ने महाशक्तियों के आविर्भाव के साथ विश्व को सैद्धान्तिक और भू-राजनीतिक दृष्टि से दो परस्पर विरोधी खेमों में बाँटा था। कालक्रम में सामाजिक सुस्थिरता एवं आर्थिक पुनर्निर्माण के माध्यम दोनों महाशक्तियों के परस्पर-क्षतिग्रस्त सहयोगी देश अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और विगत शक्ति फिर से हासिल करने के लिए उत्सुक हुए। 1956 का स्वेज संकट एक बड़ी सीमा तक इसी कारण पैदा हुआ, क्योंकि ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री एथोनी ईडन यह मानने को तैयार नहीं थे कि उनका देश अब दूसरे दर्जे की शक्ति समझा जाता है। इसी तरह चीन और फ्रांस ने माओ और देगोल के जीवनकाल में अपनी संरक्षक महाशक्ति तक की अपना समकक्ष नहीं माना। जापान और पश्चिम जर्मनी ने चमत्कारी ढंग से लाभप्रद आर्थिक विकास के साथ-साथ अपनी महत्वाकांक्षा को

मुखर करना आरम्भ किया। उसका प्रमुख कारण यह था कि वह वैज्ञानिक मान्यता में पथ प्रश्रान्त नहीं कर रहे थे।

[illegible][illegible][illegible]

नुकसान से अक्षत रहा। समृद्धि में उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। जो पुरानी ओपनिवेशिक ताकतें अमरीका की प्रतियोगी बन सकती थी, वे सभी ध्वस्त पड़ी थी। इनमें सोवियत संघ भी शामिल था, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में 20 लाख से अधिक जानें गवायी थीं और उसके आर्थिक विकास के सभी कार्यक्रम गड़-गड़ हो चुके थे। कुछ ही वर्षों तक सही, परमाणु अस्त्रों के क्षेत्र में अमरीका का एकाधिकार रहा था। इसके अलावा अमरीका सोवियत जड़ता-वट्टरता के मुकाबले अपनी व्यवस्था की मुक्त जनतान्त्रिक व्यवस्था के रूप में प्रचारित करता था।

परन्तु आज यह स्थिति आमूल-मूल बदल चुकी है। टेक्नोलॉजी के कुछ क्षेत्रों में भले ही सोवियत संघ अमरीका से पिछड़ा हो, लेकिन सामरिक दृष्टिकोण के क्षेत्र में दोनों देश समकक्ष हैं। इस स्थिति में दोनों पक्ष अपने को निरापद नहीं समझते। इस प्रकार इस परिवर्तन ने नये शीत युद्ध की पुराने नीत युद्ध की अपेक्षा जटिल बनाया है।

नये शीत युद्ध के कारण

(Causes of the New Cold War)

पुराने शीत युद्ध के आविर्भाव के साथ यह स्पष्ट हो गया कि न युद्ध और न ही शान्ति वाली यह स्थिति आतंक के सन्तुलन के कारण सम्भव हुई है। अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर सम्भावित घटनाक्रम के बारे में कोई भी तर्कसंगत अनुमान लगाना अभी तक सहज था, जब तक महाशक्तियों में सन्तुलन न सही, एक तरह की तुलनीयता (Comparability) दृष्टिगोचर होती थी। इस प्रकृति की परिणति महाशक्तियों के बीच तनाव-सौमित्र्य में हुई। तनाव-सौमित्र्य के समापन और नये शीत युद्ध के आरम्भ होने के साथ महाशक्तियों की समताओं में उत्पन्न असन्तुलन और तद्वर्जित अस्थिरता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बहुरहाल, नये शीत युद्ध के प्रमुख कारण निम्नांकित हैं :

1. अमरीकी शक्ति का क्षय एवं सोवियत शक्ति का विस्तार—जिस तरह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ निरन्तर सघर्षरत रहने के कारण ध्वस्त-पन्न हो गया था तथा अमरीका अपेक्षाकृत निरापद बचा रह सका था, उसी तरह विपन्नताम सघर्ष के बाद नये शीत युद्ध की पूर्व संध्या पर अमरीका क्षिप्त-नशति तथा सोवियत संघ अपेक्षाकृत आत्म-विश्वासी था। ऐसा नहीं कि अमरीकी शक्ति का व्यव-अपव्यय निरंकुश हिंस्र चीन में हुआ हो। बरूवा में फिदेल कास्त्रो के उदय के बाद में पारम्परिक मुनरो सिद्धान्त का प्रतिपादन महज नहीं रहा। बिली हो या अर्जेंटीना, अमरीकी पक्षपर सैनिक जमपट्टी को मत्तारू रखने की बली नीमत अमरीका की चुकानी पड़ी। 1973 के बाद पश्चिम एशिया ने नया सामरिक महत्व ग्रहण किया और तेल सबट ने अमरीकियों का ध्यान इस ओर दिलाया कि उनके वैभव और ऐश्वर्य की नींव किन्ती कमजोर है ? इन्ही वर्षों में पश्चिमी जर्मनी और जापान जैसे मित्र राष्ट्र आर्थिक क्षेत्र में अमरीका से बाजी मार ले गये और अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी में उनके लिए चुनौती बन गये। अमरीकी नेताओं को यह बात खिन्न करती रही कि वे ऐसे मणि-मित्र देशों की सुरक्षा का ज़ार बहन करने के लिए मजबूर हैं। फ्रान्स हो या ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी हो या इजराईल, अमरीका अपने शिविरानुचरों की नीतियों का तालमेल अपने सामरिक हितों के साथ करने में असमर्थ रहा। अमरीकी

सोवियत संघ द्वारा विगतनाम को दी जाने वाली सहायता-समर्थन तथा अफगानिस्तान के प्रति उनकी विदेश सखेदनशीलता कमोबेश अमरीका-चीन सम्बन्ध सुधार ने जुड़े हुए हैं। सोवियत संघ और चीन के पारस्परिक सम्बन्धों में सामाज्यीकरण की जो प्रक्रिया आरम्भ हुई, उसने नये शीत युद्ध को और जटिल बना दिया, क्योंकि इसके बाद शक्ति-सन्तुलन त्रिकोणीय हो गया।

3. अमरीकी कट्टरता—पुराने शीत युद्ध के बारे में अक्सर कहा जाता है कि इलेक्ट के व्यक्तिवाद का स्थापन तथा उसकी कट्टरता एक बड़ी सीमा तक सफ़रों के लिए जिम्मेदार रहे। साम्यवादी खेमे में रूसी नेता स्टालिन और चीन में माओ का उल्लेख इसी मन्दमं में किया जाता है। बिना अनावश्यक सरलीकरण के यह बात मुझायी जा सकती है कि नये शीत युद्ध के विकास के साथ अमरीकी सरकार की कट्टरता बहुत बड़ी सीमा तक जुड़ी रही है। यह बात सिर्फ़ राष्ट्रपति रीगन की जुसारू मानसिकता पर नहीं, बल्कि कार्टर जैसे अपेक्षाकृत उदार मनमें जाने वाले राष्ट्रपति के मानवाधिकार सम्बन्धी दुराग्रह पर भी लागू होनी है। यदि वस्तुनिष्ठ ढंग से देखें तो कैम्प डेविड समझौते में रुम को अलग रखने, डिप्लो गामिया में नौ-सैनिक अड्डे की स्थापना, पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य सहायता आदि के मामलों में भडकाते-उकताते वाली पहल कार्टर ने ही की।

अमरीकी कट्टरता सिर्फ़ किसी एक व्यक्ति या पदाधिकारी तक सीमित नहीं रही। आखिर राष्ट्रपति रीगन को अभूतपूर्व बहुमत से दो बार निर्वाचित करने वाले अमरीकी मतदाता उस बेग की जनसंख्या का बहुसंख्यक हिस्सा है। सोवियत संघ को घुरा और धनु मममने वाले और उनके साथ आत्मघाती मुक़ाबले के लिए तैयार रहने वाले ये मतदाता सन-सामयिक अमरीका की अहंकारी मानसिकता का वास्तविक प्रतिनिधित्व करते हैं। ग्रेटोअस्की हो या जनरल हेग या क्विंजगर्, अमरीकी विदेश नीति के निर्धारण व संचालन के तौर-तरीकों में भेद समझ पाना आसान नहीं। इन अमरीकी लोगों को लगता है कि जिस तरह धौमाधमको से घेनेडा, पनामा, कोलम्बिया आदि पर काबू किया जा सकता है, उसी तरह सोवियत संघ के साथ आभरण कर काम निचाला जा सकता है। इन भ्रान्ति ने नये शीत युद्ध के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

4. नये सोवियत नेतृत्व का आत्म-विश्वास—यों तो यह बात शुरू में कही जानी रही है कि सोवियत शक्ति की कट्टरता या लचीलापन शीर्षस्थ साम्यवादी नेता के व्यक्तिवाद पर आधारित रहते हैं, तथापि नये शीत युद्ध के सन्दर्भ में इन बात का एक नया पक्ष उजागर होता है। स्टालिन के सामने सबसे बड़ी समस्या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देश के सामाजिक-आर्थिक पुनर्निर्माण की थी, तो स्टुलचेव के मसल मयसे बड़ी चुनौती प्रक्षेपास्त्रों और परमाणु अस्त्रों के निर्माण की दौड़ में अमरीका से न पिछड़ने की। तीसरी दुनिया के देशों में सोवियत प्रभाव खींच फैलाना इन वर्षों में मामरिक महत्व का काम बना रहा। अर्थात् कुछ भिलाकर सोवियत संघ की राजनयिक मुद्रा प्रतिस्पर्धात्मक रही। छेत्रेव के कार्यकाल के अन्तिम वर्षों तक इस स्थिति में गटनोप परिवर्तन आ चुका था। जहाँ एक ओर अन्तरिक्ष अन्वेषण, वस्त्रास्त्र निर्माण आदि के क्षेत्र में सोवियत संघ 'हीनज प्रिन्स' से मुक्त हो चुका था, वहीं दूसरी ओर जीवन-स्तर सुधारने के मामले में अपनी धीमी गति रूसी जनता को सातने लगी थी। इन तरह सोवियत नेताओं के बड़े आत्म-विश्वास ने नये 'शीत युद्ध' को दो तरह

से प्रभावित किया। एक तो अफगानिस्तान, वियतनाम, कम्बुधिया जैसे रणक्षेत्रों में बेहिचक एवं लगभग दुस्माहसिक ढंग से कूद पड़ने की तत्परता सोवियत नेतृत्व ने दर्शायी। दूसरे, अमरीका के साथ मिडकर-बैदेशिक मामलों में अपना पराक्रम प्रमाणित कर सोवियत जनता के असन्तोष को नियमित-नियन्त्रित करने का प्रयत्न तर्कसंगत समझा गया।

ब्रेज़नव के बाद आद्रोपोव और गोर्बाच्योव ने अपने-अपने ढंग से इस प्रक्रिया को प्रभावित किया। जहाँ इन नये नेताओं ने 'स्वाभाविक व्यक्तित्व' ने विश्व भर को प्रभावित किया, वहीं अमरीका इस बात को लेकर प्रस्त रहता कि कहीं यह मुसोटाभर न हो या कि प्रचार अभियान में हथ आगे न निकल जाये। इसे दुर्भाग्यपूर्ण विदग्धना समझा जाना चाहिए कि सोवियत नेतृत्व के आत्म-विश्वास में महानक्तियों के बीच तनाव को घटाने के बरसे बढ़ाया।

5 मये राष्ट्रीय-सहयोगियों का गैर-जिम्मेदाराना आचरण—द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर तब के नवोदित राष्ट्र गिन चुके थे—जैसे भारत, इण्डोनेशिया आदि। इनमें से अनेक एक ही राजनीतिक इकाई के प्रशासनिक या राजनीतिक विभाजन से उत्पन्न हुए थे—जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बर्मा। इस कारण राजनीतिक संस्कार और आर्थिक विकास की दृष्टि से इनमें समरूपता थी। भारत जैसे नवोदित राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अनुभवहीन नहीं थे और उन्होंने द्विध्रुवीय विश्व में व्याप्त आतंक के सम्बलन को देखते हुए बेहद उत्तरदायी ढंग से अपनी भूमिका निभायी। नेहरू जी ने अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति, निरास्त्रीकरण, साम्राज्य-वाद-उपनिवेशवाद के विरोध आदि के बारे में जो मुहिम छेड़ी, उसने शीत युद्ध के तनाव को एक बड़ी सीमा तक कम किया। इनके लिए एक बड़ी हद तक यह बात उत्तरदायी थी कि भारत जैसे देशों ने अपनी स्वाधीनता अहिंसक तरीके से समझीय प्रणाली के साथ हासिल की थी और भारतीय नेता संघर्ष की तुलना में परामर्श को अधिक महत्वपूर्ण समझते थे।

जब हम स्थिति की तुलना नये शीत युद्ध के काल से करते हैं तो कई अन्तर स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। 1960 के बाद अफ्रीका और एशिया के जिन देशों ने स्वतन्त्रता प्राप्त की, उन्होंने अधिकांशतः यह मफरदा हिंसक जन-मुक्ति संग्राम के जरिये प्राप्त की। अल्जीरिया, पूर्वी अफ्रीका के देश, हिन्द चीन इसके अच्छे उदाहरण हैं। क्यूबा के फिदेल कास्त्रो, घाना के एन्क्रूमा तथा इण्डोनेशिया के मुकावों का यह निश्चिन्त मत था कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनय में संघर्ष का महत्व परामर्श से ज्यादा है। इनमें से अनेक देशों ने महाशक्तियों के बीच शीत युद्धजनित प्रतिस्पर्धा का साम अपने हित में उठाना चाहा। इन नेताओं के पास न तो नेहरू जी जैसी दूरदृष्टि थी और न ही कोई स्पष्ट विश्व दर्शन। अपने मकीर्ण राष्ट्रीय हितों की पुष्टि के लिए इन लोगों ने अनेक बार गैर जिम्मेदार आचरण से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को सफट में डाला। पुराने शीत युद्ध के दौरान कुन मिलाकर एकाध बार ही स्वेज और इण्डोनेशिया-मलेशिया टकराव के सन्दर्भ में इस तरह की स्थिति प्रकट हुई थी। परन्तु नये शीत युद्ध के सन्दर्भ में दोषपूर्ण प्रणाली क्षेत्र में लेकर मध्य अमरीका और बेरिवियाई सागर तक सर्वत्र हर छोट में छोटे नगण्य शक्ति वाले राज्य का आचरण महाशक्तियों के व्यवहार के लिए निर्धारक मिट्ट होने लगा। इस दौरान यह उक्ति लोकप्रिय हुई कि 'शुद्धा दुष्ट की नहीं, बल्कि दुष्ट शक्ति की हिमाती है।' अर्थात् नये

छुटमइयों राष्ट्रो-सहयोगियों का अनुत्तरदायी आचरण महाशक्तियों की नीतियों को पथ-भ्रष्ट करने लगा ।

६. संयुक्त राष्ट्र संघ, गुट निरपेक्ष आन्दोलन एवं क्षेत्रीय संगठनों की असफलता—द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दुनिया परमाणु अस्त्रों के आविष्कार के कारण आतंकग्रस्त तो थी, परन्तु सारी आशाएँ धूमिल नहीं हुई थी । तब तक संयुक्त राष्ट्र संघ की जमफलता-असमता उजागर नहीं हुई थी और ऐसा मोचना अग्यथा न था कि नेहरू व नासिर जैसे लोग अन्तर्राष्ट्रीय अन्तरत्मा (conscience) की भूमिका को निर्भार्य तथा सर्वनाश के कबार पहुँचने के पहले हमे बचा लेंगे ।

आज भले ही यह कहना आसान हो गया है कि ऐसी आकावादिता नादान भोलापन थी, परन्तु तब (1945-50) ऐसा मोचना नर्कसंगत था । संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर की पाँच बड़ी शक्तियों और निपेधाधिकार वाली व्यवस्था ऐसी थी, जो किसी भी तरह जनताधिकार या समता पोषक नहीं हो सकती थी । अन्ततः इसे महाशक्तियों के दगल में भी बदलना था । कश्मीर से लेकर कोरिया तक और बर्लिन से लेकर हिन्द चीन तक कोई भी ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय संकट नहीं था, जिसका समाधान संयुक्त राष्ट्र संघ ने कराया हो । वस्तु यह तो तक कहा जा सकता है कि कागो जैसे प्रमग में संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप के कारण गुल्मी और भी उत्पन्न गयीं । इसी तरह गुट निरपेक्ष आन्दोलन के दावों और इसकी रचनात्मक सम्भावनाओं का खोखलापन मानने आने में देर नहीं लगी । पहले गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के आयोजन तक दो प्रमुख महयोगी राष्ट्रों—इण्डोनेशिया और भारत के बीच दृष्ट स्पष्ट हो चुकी थी । बाद में यह स्थिति कही अधिक बिगड़ी । हवाना शिखर सम्मेलन में न्यूबार्ड-नियतनामी तथा कम्युनिस्ट प्रतिनिधि मण्डलों के बीच विकट टकराव ने यह बात स्पष्ट की कि गुट निरपेक्ष जमघट में समाजवादी पक्षघर सदस्य भी आपसी फूट में मुक्त नहीं । इसी तरह क्षेत्रीय संगठनों के बारे में जो भ्रम लोगों ने पाल रखे थे, वे शीघ्र टूट गये । अनेक लोगों का ऐसा मानना था कि सैनिक संगठनों के अलावा क्षेत्रीय महाकार का पोषण मित्र-राष्ट्रों के समूह की स्थापना से हो सकेगा । यूरोपीय सत्ता बाजार को छोड़कर अन्यत्र कही ऐसा सम्भव नहीं हुआ । 'आसियान' से लेकर 'सापटा' तक इनकी असफल ही कहा जाना चाहिए । इन क्षेत्रीय संगठनों ने अन्तर्राष्ट्रीय एकता को क्षणित किया और इस तरह शीत युद्ध के संकट को बढ़ाया ।

नये शीत युद्ध का विकास : प्रमुख घटनाएँ

(Evolution of the New Cold War : Major Events)

नये शीत युद्ध के विकास के साथ अनेक घटनाएँ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई हैं । इनमें से प्रमुख घटनाओं का संक्षिप्त व्योम इस प्रकार है ।¹

१. अफगान संकट—अफगानिस्तान का भूमिबद्ध कबायली राज्य अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में तटस्थ और गुट निरपेक्ष पहचान बना चुका था । अतः ही इसे सोवियत

¹ अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप, कम्युनिस्ट संकट, ईरान-इराक युद्ध, मध्य अमरीका का संकट, बाल्कन भी समस्या, स्टार वॉर्ष आदि के बारे में विस्तृत जानकारी व विश्लेषण पुस्तक में अन्यत्र दिये गये हैं ।

प्रमाण क्षेत्र में समझा जाता रहा हो, किन्तु महाशक्तियों के बीच यह महमति थी कि मोझदा स्थिति को कोई भी पक्ष नहीं बदलेगा। लेकिन दिसम्बर, 1979 में मोघियत सैनिक हस्तक्षेप ने एकपक्षीय निर्णय द्वारा इस मन्तुतन का विगाड़ दिया और नये चीन युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया। अफगान शरणार्थियों के 'सोवियत' में प्रवेश के बाद बहुत बड़े पैमाने पर दी गयी अमरीकी सैनिक-आर्थिक मदद और अफगानिस्तान में सक्रिय छापामार मुजाहिदीनों के विरुद्ध बर्बर मोघियत बल प्रयोग को लेकर दोनों महाशक्तियों के बीच निरन्तर तनाव बना रहा। जेनेवा समझौते के बाद भी अफगान सबूत का स्थायी हल नहीं निकला। सितम्बर, 1991 में अमरीका और रूस में यह समझौता हुआ कि दोनों में से कोई भी अफगानिस्तान को सैनिक सहायता नहीं देगा।

2. **कम्बुचिया सबूत**—अफगानिस्तान की ही तरह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कम्बुचिया युद्ध निरपेक्ष राष्ट्र के रूप में पहचाना जाता रहा है। वियतनाम युद्ध के अन्तिम वर्षों में मित्रानु के अपदस्थ होने के बाद कम्बुचिया का राजनयिक अवमूल्यन हुआ और फिर घोर घोर के कट्टरपथी माओवादी अनुमरण ने देश के सामाजिक व आर्थिक जीवन को तहम-तहम कर दिया। इस घृष्टभूमि में वियतनामी सेना ने जनवरी, 1979 में कम्बुचिया को मुक्त कराकर अपना प्रभुत्व स्थापित किया तो इन्होंने नये चीन युद्ध के सबूत को बढ़ाया। इस घटनाक्रम ने हिन्द चीन में वियतनामी प्रभुत्व की घोषणा की और मोघियत समर्थन से चीन के साथ मुटभेड़ के लिए वियतनाम की तत्परता को जाहिर किया। अमरीका के लिए यह मित्र मानहानि का प्रश्न था, क्योंकि इस हस्तक्षेप द्वारा क्षेत्रीय शक्ति समीकरण (वियतनाम बनाम इण्डोनेशिया, चीन बनाम सोवियत मध्य) बुनियादी ढंग से बदले जा रहे थे।

3. **ईरान-इराक युद्ध**—पुराने चीन युद्ध के दौरान पश्चिम एशिया का सबूत अरब-इजरायल मध्य तक सीमित था, परन्तु नए चीन युद्ध के काल में युद्ध का विस्फोट दो नए प्रतिपक्षियों ईरान और इराक के बीच (नवम्बर, 1980) हुआ। इस सम्बन्ध में दो बातें उल्लेखनीय हैं। इजरायल को अमरीका का और अरब देशों को मोघियत मध्य व साम्यवादी देशों का समर्थन प्राप्त था, लेकिन इस बार सैद्धांतिक विचारधारा के आधार पर पक्षधरी-मध्यको को अलग नहीं किया जा सकता। इस टकराव के कारण गठमह हों चुके हैं। शान-अन-अरब जन राशि की लहर भूमि विवाद, शिया-सुन्नी साम्प्रदायिक मध्य, कुर्मीनी और महाम हुसैन के व्यक्तित्वों का टकराव और इस्लामी कट्टरपथी तथा धर्म-निरपेक्ष व प्रगतिशीलता में द्वन्द्व ईरान-इराक मध्य में देखने को मिलते हैं। आठ वर्षों तक चले इस युद्ध का असली पायदा शम्प्रासत्री का स्थापार करने बान चीन के सीमागरी को हुआ। दोनों युद्धरत दल तेज-उत्पादक हैं और इस मध्य में उनके विकास कार्यक्रमों को अस्त-व्यस्त कर दिया। इसका नुकसान भारत जैसे तीसरी दुनिया के तेज आपातक देशों को भुगतना पड़ा। वर्ष 1988 में ईरान-इराक में युद्ध विराम होने के बाद 1991 में गारो युद्ध हुआ और उनके बाद भी अज्ञानि की स्थिति बनी रही।

4. **मध्य अमरीका का सबूत**—मध्य अमरीकी भू-भाग (अन सन्वाहोर, निजारागुआ, होडुराम, पनामा, कोनसिया आदि) हमेशा से अमरीकी भू-राजनीतिक परिधि व सीमा समझा जाता रहा है। 19वीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में मुतरो पिछान की घांठणा ने यह ज्ञान स्पष्ट कर दी थी कि अमरीका इस क्षेत्र में जितनी

अन्य शक्ति का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। पुराने शीत युद्ध के वर्षों में इन सभी देशों में सैनिक सरकारें थी और वहाँ अमरीकी बहुराष्ट्रीय सम्पत्तियों के हितों का पोषण करने वाले—एक छोटे से कुलीन वर्ग का वर्चस्व बना हुआ था। कालक्रम में ये सत्ताधारी 'सैनिक गुट' विलासी तथा दुर्बल हो गये और उन सत्ताबोर, निकारामुआ जैसे देशों में मानववादी विचारधारा से प्रभावित छापामारों ने उन्हें अपदस्थ कर दिया। अमरीका ने यह समझा कि यह सब कुछ किसी मुनिमोहित सोवियत रणनीति के अनुसार सम्पन्न किया जा रहा है और क्यूबा प्रकरण की पुनरावृत्ति हो रही है। इन नई साम्यवादी सरकारों को अपदस्थ करने के लिए अमरीका ने पड़ोसप्रकारी तरीके से प्रतिजियावादी तत्वों (कोलराजो) को सहायता देना शुरू किया। इस प्रक्रिया ने नए शीत युद्ध के सबसे नए चरण में मध्य अमरीका की उद्यत-न्यून को मध्य पूर्व में ईराक में बाघको के प्रकरण से जोड़ा है।

5. राज्य आतंकवाद—यों तो फिलस्तीन मुक्ति संगठन की गतिविधियों ने आतंकवाद की जन-मुक्ति संग्राम के एक प्रमुख राजनयिक उपकरण के रूप में दशकों पहले प्रतिष्ठित कर दिया था, परन्तु नए शीत युद्ध के दौरान इसके नए-नए आयाम सामने आये। इनमें पहला आयाम राज्य आतंकवाद (State Terrorism) वाला है। बाह्य वह अमरीका द्वारा मिसरा की खाड़ी में बर्बर बमबारी द्वारा कर्नेल गद्दाफी की रीढ़ तोड़ने का प्रयत्न हो या सोवियत संघ द्वारा बिना चेतावनी के कोरियाई नागरिक विमान को मार गिराने की घटना। इस तरह के राज्य आतंकवाद ने निश्चय ही नए शीत युद्ध के सफट को बढ़ाया। दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा सीमान्ती अफ्रीकी देशों के विरुद्ध अनुशासनात्मक सैनिक कार्रवाई इसी ध्येय में रखी जा सकती है। ईरान में बाघको के मामले में ईरान व अमरीका दोनों का आचरण ज़िम्मेदार राज्यों वाला नहीं, बल्कि 'असामाजिक अपराधी गिरोहों' जैसा था। इस मामले में सफट के शान्तिपूर्ण समाधान की राजनयिक परम्परा का अवमूल्यन किया।

6. स्टार वारस—स्टार वारस या अन्तरिक्ष युद्ध, जिसे सामरिक प्रतिरक्षात्मक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, नए शीत युद्ध का सफट बढ़ाने वाली घटना मिला हुई। पुराने शीत युद्ध को निरापद बनाने वाली सबसे बड़ी बात यह थी कि आतंक का सन्तुलन कमोबेश बरकरार रहा था। स्टार वारस परियोजना इस स्थिति को नाटकीय ढंग से बदल सकती है और अन्तराष्ट्रीय अस्थिरता-आकाशा उपजा सकती है। इस योजना का प्रमुख अंग एक ऐसी इलेक्ट्रानिक ढाल तैयार करना है जो प्रतिपक्षी देश के प्रक्षेपास्त्रों को अन्तरिक्ष में निश्चित रूप से शून्य-प्रतिशत भण्ड कर दे। यदि ऐसा किया जा सकता हो तो शत्रु पर प्रथम प्रहार का जोर-संचरण शायद ही कोई महा शक्ति कर सके। इसके अतिरिक्त, इस परियोजना के लिए तब बड़े पैमाने पर खर्च ने वैदेशिक सहायता के बजट को बड़बड़-गड़गड़ किया और महाशक्तियों के टेक्नोलॉजी हस्तान्तरण को भी अनिवार्यतः प्रभावित किया। सोवियत संघ का मानना है कि इस अन्तरिक्ष युद्ध परियोजना का एक मान उद्देश्य अस्त्रास्त्रों की नई दौड़ शुरू कर सोवियत अर्थव्यवस्था को चरमराना था। इस प्रकार स्टार वारस ने निगन्धीकरण वार्ताओं को निरर्थक साबित कर शीत युद्ध की मानसिकता को पुनः खतरनाक ढंग से बढ़ावा दिया।

नए शीत युद्ध के प्रभाव

(Impact of the New Cold War)

पुराने शीत युद्ध की तरह नए शीत युद्ध के भी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर दूरगामी और व्यापक प्रभाव देने के सिलसिले हैं, जो इस प्रकार हैं—

1. **देनात की क्षति**—नए शीत युद्ध की सबसे पहली पहचान इसके द्वारा देनात को पहुँचायी गयी क्षति है। क्यूबाई संकट के बाद दोनों महाशक्तियों के बीच सीना मवाद 'हॉट लाइन' के जरिए आरम्भ हुआ था। 1962 से 1972 के दस वर्षों में 'प्रतिस्पर्धी सहकारिता' (Adversary Partnership) में वृद्धि हुई और सान्ट-यसमस वार्ताओं व जेनवा निम्नर सम्मेलनों की शृंखला के जरिये इसका क्रमशः विस्तार हुआ। देनात की चरम परिणति हेनमिकी समझौते तथा अन्तरिक्ष में सोवियत संघ और अमरीका के बीच सामरिक महत्व के तकनीकी सहकार में देने के मिली। विपक्षनाम युद्ध की बटुना और पश्चिम एशिया के संकट का दबाव-जनाव क्षेत्रों में भी देनात बरबरात बना रह रहा है। परन्तु नए शीत युद्ध के लक्षण स्पष्ट होने के बाद महाशक्तियों का 'मवाद' निरर्थक मिट्ट हो गया। न तो सान्ट वार्ताएँ-समझौते अनुमोदित हुए और न ही हेनमिकी व्यवस्था के माध्यम से ही कुछ प्रगति हो सकी।

2. **तनाव का स्थानान्तरण**—पहले शीत युद्ध के वर्षों में तनाव के जाने-पहचाने केन्द्र बिन्दु थे। इनमें अधिकतर यूरोप के हृदयस्थान में अवस्थित थे और अन्य सीमान्तो सुरक्षा चौकियों की तरह—जैसे बर्लिन, तुर्की, ग्रीस, कोरिया, ताइवान, आदि। जागो जैसे उदाहरण लगभग अपवाद थे। साम्यवादी खेमे में भी पोलैण्ड और हंगरी का महत्व अपेक्षाकृत अधिक समझा जाता था। दूसरे नए शीत युद्ध की प्रमुख विशेषता यह है कि इसका तनाव बिन्दु स्पष्टतः महाशक्तियों की निजी सामरिक जटिलताओं और उनकी भू-राजनीतिक चिन्ताओं से नहीं जुड़े हुए हैं। इनमें ईरान-इराक, कम्बुजिया विपक्षनाम व नवोदित दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्र प्रमुख हैं। अफगानिस्तान, निजारागुआ और अन्य सत्ताक्षेत्रों को इस श्रेणी में रखना कुछ अटपटा लग सकता है, परन्तु वास्तविक यही है। मुनरा निदाल का उल्लेख किया जाये या 'बफर' राज्यों की परम्परा का, अफगानिस्तान और मध्य अमरीकी देशों की स्थिति पहले शीत युद्ध में निरन्तर निरापेक्ष ही रही थी।

3. **निष्पत्तीकरण का क्षय**—तनाव-क्षेत्रों के साथ अजिज्ञ रूप में निष्पत्तीकरण की प्रगति जुड़ी हुई थी। परमाणु अस्त्रों के परीक्षण पर लची रोक, परमाणु अस्त्र प्रसार रोक समिति, सान्ट-वार्ताओं आदि ने तनाव-क्षेत्रों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया था। किन्तु नए शीत युद्ध में यह सब क्षिप्र-क्षिप्र हो गया। स्टार वार्म परिपोषना की शक्तियों की सर्वनाशक हार का अर्थ तब का सबसे खतरनाक उदाहरण पेश किया जाता है। परन्तु नए शीत युद्ध की मानविकता ने परमाणु ही नहीं, पारम्परिक शक्तियों के सामने भी निष्पत्तीकरण को नुकसान पहुँचाया है। मसाल, ईरान और इराक के बीच आठ वर्षों तक चले युद्ध ने बड़े पैमाने पर सैनिक मात्र सामान की खपत जारी रखी। इस तरह नेबनान में निरन्तर चल रहे यह युद्ध, अफगान-प्रतिरोध और कम्बुजिया में विपक्षनामी हस्तक्षेप ने महारक-उपकरणों का बाजार गर्म रखा। इराक, सावियत संघ तथा विपक्षनाम पर बार-बार

यह आक्षेप लगाये गये कि उन्होंने अपने अनुओ के खिलाफ जेनेवा समझौते में निषिद्ध रासायनिक हथियारों का उपयोग किया है। इससे निश्चय ही निशस्त्रीकरण की 'उपलब्धियाँ' कठिन हुई हैं।

4. गुट निरपेक्षता का अवमूल्यन—तनाव-शीघ्रित्व के आविर्भाव के पहले भी पुराने शीत युद्ध के प्रारम्भिक चरण में गुट निरपेक्ष आन्दोलन ने निष्पक्ष मध्यस्थता व सान्तिपूर्ण परामर्श को प्रोत्साहित कर रचनात्मक राजनय द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना विशेष स्थान बना लिया था। कोरिया से लेकर कांगो तक, स्वेज से हिन्द-चीन तक और बर्लिन से बेलग्रेड तक, भारत, भिन्न, इण्डोनेशिया आदि ने अपने आकार और सामर्थ्य से वही अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। दूसरे शीत युद्ध में इनकी कोई गुजादश आरम्भ से ही नहीं रही। सकट केन्द्रों के स्थानान्तरण से स्वयं अनेक गुट निरपेक्ष देश आपसी झगड़ों में फँस गये और अपने समर्थन के लिए एक न एक महाशक्ति का आश्रय ढूँढ़ने लगे। इसके अलावा अब तक गुट निरपेक्ष आन्दोलन इतना बृहद् रूप धारण कर चुका था कि उसकी एकता बनाए रखना सम्भव नहीं था।

5. महाशक्तियों के आक्रामक तैवर—पुराने शीत युद्ध के दौरान आतंक के सन्तुलन के कारण दोनों महाशक्तियों के पारम्परिक सम्बन्ध शत्रुता के बावजूद सयत रहे थे। यह स्थिति आज क्षेप नहीं रह गयी है। ऐसा जान पड़ता है कि 40-45 वर्षों के अनुभव ने दोनों महाशक्तियों को यह अहसास करा दिया चाहे कुछ भी हो, परमाणु अस्त्रों का प्रयोग किया ही नहीं जायेगा। इसलिए वे एक दूसरे के साथ मुठभेड़ से बचतासी नहीं और न ही उकसाने-भड़काने वाले क्रिया-कलाप में हिच-किचाती हैं। अमरीका द्वारा ग्रेनाडा में मैनिफेस्ट हस्तक्षेप एवं सोवियत सघ द्वारा अफगान सटस्पता का अतिप्रमण, इस यात के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इसी तरह राष्ट्रपति रीगन द्वारा 'स्टार वॉर्स' के बारे में हठधर्मी रुख अपनाने, निकारागुआ के 'कोन्ट्रा-तरवों' को अवैध सहायता देने और लेबनान व ईरान के अराजकतावादी-आतंकवादी सत्त्वों के साथ सीदेबानी में भी अमरीका के आक्रामक तैवर पता चलते हैं। सोवियत सघ के इतना 'अनुतरदायी' आचरण प्रकटत. न किया हो, लेकिन उमने अपने पुसारूपन में कोई कमी नहीं दिखाई है। ब्रेज्नेव के कार्यकाल में पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों के सन्दर्भ में 'सीमित सम्प्रभुता' के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया और चित्तनाम के समर्थन में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी गयी। दिना सोवियत शह ने बयूवाई पेरोवर सैनिक अफीका और लातीनी अमरीका में स्वच्छन्द आचरण नहीं करते रह सकते थे। इसके अतिरिक्त सोवियत सघ ने हिन्द महासागर में नौ-सैनिक प्रवेस तथा दक्षिणी प्रशान्त में अपनी बड़ी रॉके के कारण भी अमरीका को बिनाबुर किया।

6. सर्वत्र स्थानीय संकटों में बिगाड़—पुराने शीत युद्ध की प्रमुख प्रवृत्ति अन्तर्राष्ट्रीय संकटों को सीमित रखने वाली थी, किन्तु दूसरे शीत युद्ध में सर्वत्र स्थानीय संकट अपेक्षाकृत अधिक जोरिम मरे बन गये हैं। अनेक स्थानों में भले ही सीधा कार्य-कारण सम्बन्ध न जोड़ा जा सकता हो, लेकिन घटनाक्रम शीत युद्ध के उतार-चढ़ाव को प्रतिबिम्बित करना दृष्टिगोचर होता है। भारतीय महाद्वीप में यह लक्षण सबसे अधिक स्पष्ट दीक्षता है। पाकिस्तान का सामरिक महत्व अमरीका और हम दोनों के लिए अफगान संकट और तुरन्त तैवानी दस्ते (Rapid Deployment

Force) के सन्दर्भ में बढ़ गया है। इसी कारण पाकिस्तानी परमाणु कार्यक्रम की ओर अनचाहे ही सही, अमरीका की आँखें मुंदी रही हैं। पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर दी गयी सैनिक सहायता का प्रभाव भारत-पाक क्षेत्रीय सन्तुलन पर पड़े बिना नहीं रह सकता। इसी तरह खाड़ी युद्ध (ईरान-इराक युद्ध) में जीतने वाले पक्ष के बारे में पूर्वानुमान लगाने और उसका साथ निभाने की आकुलता ने अस्थिरता को ही बढ़ावा दिया। यह सोचना अनुचित नहीं कि लेबनान की आमदो, दक्षिण अफ्रीकी देशों की व्यापार और वस्तुचिन्ता में एकदम समापन की अटलता तनाव-शैथिल्य के अभाव में दुपकर बनें।

उपसंहार—इस प्रकार नये शीत युद्ध के तात्कालिक एवं दूरगामी परिणाम दो तरह के हैं। एक तो वे, जिन्होंने महाशक्तियों के आपसी सम्बन्धों को प्रभावित किया, उनके आक्रमण केवर चढ़ाये और मस्त्रास्त्रों की खतरनाक होड़ तथा सीधे मुठभेड़ की प्रवृत्ति को उभराया है। दूसरे वे जिन्होंने तीसरी दुनिया के देशों का जबरन मध्य में खींचा, स्थानीय विवादों को विस्फोटक सन्दर्भों में बदला और गुट निरपेक्षता व अफ्रो-एशियाई एकता का अवमूल्यन किया है।

संक्रमण काल

बहरहाल, बीसवीं सदी के अन्तिम दशक में शीत युद्ध जनित अनेक तनाव अभी शेष हैं। तनाव शैथिल्य ने जिस आशा को जगाया था, वह निर्मूल मिट्ट हुई। पिछले कुछ वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर कई ऐसे अप्रत्याशित परिवर्तन हुए हैं, जिन्होंने विश्व राजनीति का स्वरूप ही बदल दिया। जर्मनी के एकीकरण (1990) और खाड़ी युद्ध (कुवैत) को लेकर (1990-91) में अमरीका की निर्णायक विजय के बाद यह कहा जा सकता है कि आज विश्व द्विध्रुवीय नहीं रह गया। अभी अमरीका का एक ध्रुव वर्चस्व स्पष्ट है। पर, इससे यह निष्कर्ष निकालना बिल्कुल गलत होगा कि इस घटनाक्रम से अन्तर्राष्ट्रीय तनाव अलग घटेंगे। अधिक समझ यह है कि अमरीका के निरपेक्ष स्वच्छाचार की आसना से अमरीका का प्रतिरोध बढ़ेगा। अभी फिलहाल सोवियत संघ अलग है—जिमी भी हस्तक्षेप के लिए। लेकिन, यह सोचने का कोई कारण नहीं कि बृहत् मविप्ल में भी अनुपस्थित या निष्क्रिय रहेगा। अतएव, वर्तमान स्थिति को अधिक से अधिक संक्रमण काल (Transitional Period) ही समझा जाना चाहिये। यह हमारे शीत युद्ध और नए तनाव-शैथिल्य के दौर में मात्र एक अनुराग है।

संयुक्त राष्ट्र संघ व उसकी विशिष्ट एजेंसियाँ

अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सद्भाव बनाये रखने के लिए एक मंच की आवश्यकता सम्बन्धित समय से महसूस की जाती रही है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस के शान्ति सम्मेलन में जब 1919 में राष्ट्र संघ (League of Nations) की स्थापना की गयी तो उसके पीछे विश्व के स्वतन्त्र देशों में शान्तिपूर्ण वाद-विवाद का सिलसिला स्थापित करने का उद्देश्य प्रमुख था। राष्ट्र संघ के स्वप्नदृष्टा अमरीका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन यह मानते थे कि छोटे युद्ध बड़े युद्धों में परिणत हो जाते हैं। उन्हें रोकने के लिए छोटी-छोटी समस्याओं को तत्काल सुलझा देना चाहिए। विन्तु राष्ट्र संघ की असफलता जहाँ एक ओर द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी वहीं दूसरी ओर द्वितीय विश्व युद्ध की भयावहता ने विश्व राजनेताओं के सामने और अधिक प्रभावशाली विश्व मंच बनाने की आवश्यकता को अवश्यभावी बना दिया।

द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पूर्व ही मित्र-राष्ट्रों के नेता इस निष्कर्ष पर पहुँच चुके थे कि विश्व की समस्याओं को निपटाने एवं भविष्य में विश्व युद्ध की आशंका को ढालने के लिए एक ऐसा मंच स्थापित किया जाये जो राष्ट्र संघ से अधिक प्रभावशाली हो सके।¹ अमरीकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट यह मानते थे कि विश्व के समस्त स्वतन्त्र देश इसके मददगार हो और छोटी-बड़ी सभी समस्याओं पर इसमें घुलकर वाद-विवाद एवं परामर्श हो। इस प्रकार विश्व राष्ट्रों के सम्मेलन और अन्तर्क्रिया से बातचीत के ऐसे माध्यम स्थापित हो जायेंगे, जहाँ दो या अधिक राष्ट्रों के बीच पैदा हुए सफटों को टकराव की स्थिति में पहुँचने के पूर्व ही हल करने के शान्ति पत्र लिए जायेंगे। दूसरे, उनकी यह भी मान्यता थी कि इस प्रकार के निरन्तर सम्प्रेषण-सम्पर्क से राष्ट्रों में मित्रता का वातावरण पैदा होगा। तीसरे, यह भी सोचा गया कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए हरेक देश युद्ध जैसी कार्रवाई करने से हिचकिचायेगा। यदि कोई ऐसी कार्रवाई करेगा तो वह अन्तर्राष्ट्रीय आलोचना का शिकार होकर अपनी भूल सुधारने को बाध्य हो जायेगा। इसने अलावा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों में ऐसी मंच के जरिये राष्ट्रों में सामंजस्य एवं निकटता स्थापित करके उनमें आपसी वर्तन और संघर्ष की प्रवृत्ति को समाप्त किया जा सकेगा। इस पृष्ठभूमि में और मद्दिश्य में युद्ध न हो, इस उद्देश्य को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations Organization) की स्थापना की गई।

¹ देखें, Nagendra Singh's forward in *United Nations for A Better World* (Delhi, 1985), 5.

संयुक्त राष्ट्र मध्य का उद्भव

राष्ट्र मध्य की अवस्थाना के बावजूद विश्व के देशों ने यह विश्वास मँदव बनाये रखा कि अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के जरिये दुनिया में शान्ति और सुरक्षा कायम की जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र मध्य बीसवीं शताब्दी के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित करने का दूसरा सबसे बड़ा कदम था। असल में संयुक्त राष्ट्र मध्य के अस्तित्व की कहानी अनेक चरणों से गुज़री है। इसमें अटनाटिक चार्टर, मास्को सम्मेलन, डम्बरटन ओल्स सम्मेलन, याल्टा सम्मेलन एवं सेन-फ्रांसिस्को सम्मेलन प्रमुख घटनाएँ हैं जिनका सक्षिप्त विवरण देना उचित रहेगा।

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अटनाटिक चार्टर (14 अगस्त 1941) और मास्को सम्मेलन (19-30 अक्टूबर, 1943) संयुक्त राष्ट्र की स्थापना में महत्वपूर्ण प्रारम्भिक कदम माने जा सकते हैं। अटनाटिक चार्टर के अन्तर्गत ब्रिटेन और अमरीका ने स्पष्ट किया कि वे न तो युद्धोत्तर विस्तारवादी नीति का अनुसरण करेंगे और न ही कोई ऐसे प्रादेशिक परिवर्तन करना चाहेंगे जो उस देश की जनता के विरुद्ध हों। मास्को सम्मेलन में अमरीका, ब्रिटेन और सोवियत मध्य के विदेश मंत्रियों ने यह घोषणा की कि विश्व शान्ति और सुरक्षा के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की जाये। डम्बरटन ओल्स सम्मेलन (2 अगस्त से 1 नवम्बर, 1944) में अमरीका, ब्रिटेन, सोवियत मध्य और चीन के प्रतिनिधि अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की रूपरेखा तैयार करने के लिए एकत्रित हुए। हालांकि इस प्रश्न को लेकर उनमें पारस्परिक मतभेदों के कारण वे किसी निश्चित निर्णय पर नहीं पहुँच सके किन्तु तय किया गया कि 'संयुक्त राष्ट्रों' का एक सम्मेलन 25 अप्रैल, 1945 को सेन-फ्रांसिस्को में बुलाया जाय जो डम्बरटन ओल्स सम्मेलन के विचार-विमर्श तथा प्रस्तावों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र मध्य के सविधान का निर्माण करे।

4 से 11 फरवरी, 1945 की कृष्ण माघर में स्थित ओमिया द्वीप के याल्टा नामक स्थान पर हुए सम्मेलन में अमरीकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटिश प्रधानमन्त्री चर्चिल और सोवियत प्रधानमन्त्री स्टालिन ने भाग लिया। इस बड़ा सम्मेलन ने निर्णय लिया कि विश्व संगठन की स्थापना के सम्बन्ध में 25 अप्रैल, 1945 को सेन-फ्रांसिस्को नगर में राष्ट्रों का एक सम्मेलन बुलाया जाये। 1 मार्च, 1945 तक जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित करने वाले समस्त राष्ट्रों का इसमें निमन्त्रित किया जाय, पाँच देशों—संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन, सोवियत मध्य, फ्रांस और चीन को इसकी सुरक्षा परिषद् में स्थायी स्थान और निवेधाधिकार (Veto) प्रदान किया जाय।

25 अप्रैल से 26 जून, 1945 को सेन-फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ, जिसमें 50 देशों को निमन्त्रित किया गया। इस सम्मेलन के द्वारा संयुक्त राष्ट्र मध्य के सविधान (चार्टर) का निर्माण हुआ और 26 जून, 1945 को उसमें भाग लेने वाले राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने उसके 'सविधान' को अन्तिम रूप में स्वीकार कर उस पर अपने हस्ताक्षर किये। राष्ट्रों द्वारा इस स्वीकृत चार्टर को बमिया की ओर इशारा करत हुए पामर एवं परकिन्स ने कहा कि 'हमारा प्रतिनिधियों ने इस चार्टर के कुछ आवश्यकताओं की आताचना की, फिर भी उन्होंने समझौतावादी रूप अपनाया और कई अन्यायों को स्वीकार करने हुए अन्त संयुक्त राष्ट्र मध्य का निर्माण कर

हाला 1¹ यहाँ पर उल्लेखनीय है कि हस्ताक्षरकर्ताओं में से अनेक राष्ट्रों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संधि की मददस्यता ग्रहण करने के लिए उनकी ससद की स्वीकृति आवश्यक थी। यह प्रक्रिया 24 अक्टूबर, 1945 को पूरी हो गई और इसी दिन संयुक्त राष्ट्र संधि की औपचारिक रूप से स्थापना हुई। इसी कारण 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संधि का जन्म दिवस कहा जाता है।

सं० रा० संधि के उद्देश्य

सं० रा० संधि के अनेक उद्देश्य थे। इस सगठन के चार्टर की प्रस्तावना और पहले अनुच्छेद में इसके उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है। ये निम्नांकित हैं :

- (अ) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा बनाये रखना,
- (ब) समान अधिकार और आत्म-निर्णय के सिद्धान्त के लिए आवर की भावना के आधार पर विभिन्न राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण भावना को मजबूत करना;
- (ग) आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या मानव कल्याण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को मुलजाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना; और
- (घ) इन सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न राष्ट्रों द्वारा किये गये कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए एक केन्द्रीय सगठन के रूप में कार्य करना।

सं० रा० संधि के सिद्धान्त

कोई भी सगठन अपने लिए तय किये गये उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किन्हीं निश्चित सिद्धान्तों पर आधारित होता है। संयुक्त राष्ट्र संधि भी इसका अपवाद नहीं। संक्षेप में सं० रा० संधि निम्नांकित सिद्धान्तों पर आधारित है :

- (अ) इसके सभी सदस्य सार्वभौम एवं समान हैं ;
- (ब) इसके सभी सदस्य चार्टर में उल्लिखित उत्तरदायित्वों के अनुसार आचरण करेंगे;

(ग) इसके सभी सदस्य अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान शान्तिपूर्ण तरीकों से करेंगे ताकि विरह शान्ति, सुरक्षा तथा न्याय खतरे में न पड़े,

(द) इसका कोई भी सदस्य-राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र की स्वतन्त्रता और क्षेत्रीय अखण्डता के विरुद्ध शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेगा;

(घ) इसके सदस्य इसके द्वारा सम्पादित सभी कार्यों में सहयोग देंगे, साथ ही वह ऐसे किसी भी राष्ट्र की सहायता नहीं करेंगे, जिसने विरुद्ध सं० रा० संधि निरोधात्मक या प्रवर्तन कार्य कर रखा है,

(च) सं० रा० संधि यह भी देखेगा कि गैर-सदस्य देश ऐसा कोई काम नहीं करें जिसमें विरुद्ध-शान्ति एवं सुरक्षा खतरे में पड़ जायें; तथा

(ज) अध्याय सात के अन्तर्गत प्रवर्तन नार्यों के अतिरिक्त अर्थात् विश्व-शान्ति और सुरक्षा के कार्यों को छोड़कर सं० रा० संधि किसी भी देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

इस प्रकार जहाँ एक ओर विश्व-शान्ति एवं सुरक्षा को कायम करने तथा जीवन में चहुँमुखी क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देकर विश्व के देशों में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध

स्थापित करना स० रा० सघ के प्रमुख उद्देश्य हैं, वही दूसरी ओर इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह विश्व संगठन, 'प्रजातन्त्र, आत्म-निर्णय, समानता, ससदवाद, बहुमत, कानून का शासन, न्याय, शान्तिपूर्ण परिवर्तन, शक्ति पृथक्करण, सघवाद और प्रदत्त प्राधिकार जैसे आदर्श सिद्धान्तों पर आधारित है।'¹³

स० रा० सघ की सदस्यता (Membership of the U. N. O.)

किसी भी संगठन के सदस्य बनने के लिए कुछ योग्यताओं की पूर्ति करनी पड़ती है। जहाँ तक स० रा० सघ का संबंध है, वह एक विश्वव्यापी संगठन है। यो तो विश्व के ममस्त देश इसके सदस्य बन सकते हैं किन्तु उसके पहले उन्हें कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़नी है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने पर सदस्यता मिल जाती है। सदस्य देश चाहे तो सदस्यता को त्याग भी सकता है। साथ ही संगठन द्वारा किसी सदस्य देश को निष्कासित भी किया जा सकता है। अतः संयुक्त राष्ट्र सघ की सदस्यता के मुद्दे को अनेक विन्दुओं में बाँटना श्रेयस्कर होगा।

चार्टर में सदस्यता से सम्बन्धित व्यवस्थाएँ

स० रा० सघ के चार्टर के दूसरे अध्याय के अनुच्छेद 3, 4, 5 व 6 संगठन की सदस्यता से सम्बन्धित हैं। अनुच्छेद 3 इसके भौतिक सदस्यों के बारे में है। अनुच्छेद 4 नये सदस्यों की योग्यताओं के बारे में है। अनुच्छेद 5 सदस्य-देश के निलम्बन और अनुच्छेद 6 निष्कासन के बारे में है। इनके बारे में विस्तृत व्यवस्थाओं को निम्नांकित तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है।

(अ) भौतिक सदस्यों के लिए योग्यताएँ—अनुच्छेद 3 के अनुसार स० रा० सघ के सदस्य के राज्य होना जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय संगठन पर सैन-प्रामित्वों से हुए सम्मेलन में भाग लिया अथवा जिन्होंने पहले एब्रु जनवरी, 1942 को संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पर हस्ताक्षर किये और उसके पश्चात् जिन्होंने प्रस्तुत घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किये उन्हें अनुच्छेद 110 के अनुसार सम्पादित किया। इस फार्मूले के अनुसार स० रा० सघ के भौतिक सदस्यों की संख्या 51 हुई। ये देश निम्नांकित हैं अर्जेंटीना, आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बोनिफिया, ब्राजील, ब्राइलोरशिया, कनाडा, चिली, चीन, कोलम्बिया, कोस्टारिका, क्यूबा, चेकोस्लोवाकिया, डेनमार्क, डोमिनिकन रिपब्लिक, इक्वेडोर, फ़िनलैंड, अल मन्वाडोर, इथियोपिया, फ्रांस, ग्रीस, गुआटेमाला, हाण्डुरास, भारत, ईरान, इराक, लेबनान, लाइबीरिया, लक्जमबर्ग, मैक्सिको, होलैंड, न्यूजीलैंड, निकारागुआ, नाबो, पनामा, पेरू, पोलैंड, पोर्तुगल, सऊदी अरब, मोरिया, टर्की, यूगेंड, दक्षिण अफ्रीका ग्रीनियन, मोरियत सघ, घेन-ब्रिटेन, अमरीका, उरुग्वे, वेनेजुएला, यूगोस्लाविया, पोलैंड।

(ब) नये सदस्यों के लिए योग्यताएँ—अनुच्छेद 4 में नये सदस्यों के लिए योग्यताओं का उल्लेख किया गया है जो सक्षेप में निम्नांकित हैं—(क) वह राज्य शान्तिप्रिय हो, (ख) वह वर्तमान चार्टर के उत्तरदायित्वों को स्वीकार करना हो, और (ग) वह स० रा० सघ की दृष्टि में उत्तरदायित्वों को निभाने के योग्य एवं

¹³ J. C. Plano and R. I. Riggs, *Forging World Order: The Politics of International Organization* (New York, 1967), 56.

इच्छुक हो। इसके अतिरिक्त इन योग्यताओं की पूर्ति होने के बावजूद भी दो अन्य बातें आवश्यक हैं—(1) सुरक्षा परिषद की इसके लिए सिफारिश, और (2) महासभा की उस पर स्वीकृति का निर्णय होना। सभी नये प्रत्याशी देश संयुक्त राष्ट्र सभ के सदस्य बन सकते हैं।

(स) सदस्यता का निष्कासन—अनुच्छेद 5 में सदस्य देश की सदस्यता के निष्कासन तथा उसके बाद उसे पुन. लेने का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार (i) सं० रा० सभ के ऐसे किसी सदस्य को, जिसके विरुद्ध सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर सदस्यता के अधिकारों या विशेषाधिकारों का प्रयोग करने में नित्यमित किया जा सकता है, और (ii) इन अधिकारों और विशेषाधिकारों के प्रयोग का अधिकार सुरक्षा परिषद द्वारा पुनः प्रदान किया जा सकता है।

(द) सदस्यता का निष्कासन—सं० रा० सभ की सदस्यता से किसी भी सदस्य देश को निष्कासित किया जा सकता है। अनुच्छेद ३ में यह व्यवस्था की गयी कि संयुक्त राष्ट्र सभ का कोई सदस्य यदि प्रस्तुत घोषणा पत्र के सिद्धान्तों का बार-बार उल्लंघन कर रहा है तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा उसको निष्कासित कर सकती है।

(र) सदस्यता छोड़ना—किसी सदस्य देश द्वारा सं० रा० सभ की सदस्यता त्यागने के बारे में चार्टर चुप्पी साधे हुए है। यह नये सदस्यों को रासदता छोड़ने की न तो आज्ञा देता है और न ही मनाही करता है। वैसे सं० रा० सभ से इण्डोनेशिया ने 1965 में मलयेशिया को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाने का कारण देकर सदस्यता छोड़ी थी, किन्तु वह एक वर्ष बाद पुनः सं० रा० सभ की गोद में लौट आया। इसके अतिरिक्त कुछ सदस्य देश सं० रा० सभ के विभिन्न अंगों, विशिष्ट एजेंसियों तथा उनकी बैठकों का कभी-कभी बहिष्कार करते रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र अमरीका जैसे बड़े देश ने 1 नवम्बर, 1977 को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सदस्यता का परिणाम किया। अमरीका और ब्रिटेन ने 'पूनेस्को' भी छोड़ दिया। इस प्रकार स्पष्ट है कि सदस्यता के बारे में चार्टर में स्पष्ट प्रावधान नहीं है।

सदस्यता का राजनीतिकरण

(Politicization of Membership)

सं० रा० सभ में जन्मे नये सदस्यों का प्रवेश महाशक्तियों की राजनीति में उलझा रहा है। दोनों महाशक्तियाँ स्वयं और अमरीका अपने अपने मित्र देशों को सदस्यता दिलवाने तथा प्रतिस्पर्धी महाशक्ति के समर्थक देशों द्वारा सदस्यता ग्रहण करने के मामले में रोड़ा अटकाने की नीतियाँ अपनाती रही हैं। जहाँ हम अपने मित्र राष्ट्र उत्तर कोरिया और साम्यवादी चीन को सं० रा० सभ में सदस्यता दिलाने की वकामत करता रहा, वहीं अमरीका दक्षिण कोरिया जैसे अपने समर्थक राष्ट्र की सदस्यता के लिए प्रयत्नशील रहा। दोनों ने एक-दूसरे के समर्थक देशों की सदस्यता के समर्थन पर 'वीटो' या अन्य तरीके से विरोध किया और इससे नये सदस्य देशों को सदस्यता हासिल न हो सकी। बाद में जाकर साम्यवादी चीन को 1971 में सदस्यता हासिल हो पायी। इस प्रकार नये देशों द्वारा सदस्य बनने की योग्यता होने पर भी वे महाशक्तियों की आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण लम्बे अरसे

तब इस विद्वत् सभ्यता के सदस्य न बन पाये।

स० रा० सभ के विभिन्न अंग
(Organs of the U. N.)

चार्टर के अध्याय 3 में अनुच्छेद 7 के अनुसार स० रा० सभ के छह अंगों की व्यवस्था की गई है। ये निम्नांकित हैं—(1) महासभा, (2) सुरक्षा परिषद, (3) आर्थिक व सामाजिक परिषद, (4) न्याय परिषद, (5) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, और (6) सचिवालय। इन विभिन्न अंगों के बारे में विस्तार से विवेचन करना समुचित होगा।

महासभा (General Assembly)

महासभा में समस्त राष्ट्र सभ के सभी देशों के सदस्य होते हैं। सभा में किसी भी देश के अधिक से अधिक पाँच प्रतिनिधि होते हैं। प्रत्येक देश को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है।

कार्य (Functions)

महासभा के कार्यों का विस्तरेण नीचे दिया जा रहा है—

शान्ति और सुरक्षा को कायम रखने में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के सिद्धान्त पर विचार करना तथा सुझाव देना, जिसमें निःशस्त्रीकरण और शस्त्रीकरण को मर्यादित करने का प्रश्न भी शामिल है।

जिन विवादों और परिस्थितियों पर सुरक्षा परिषद उस समय विचार कर रही हो, उन्हें छोड़कर शान्ति और सुरक्षा को भंग करने वाले किसी भी प्रश्न पर महासभा विचार कर सकती है और उस पर सुझाव दे सकती है।

उपर्युक्त अपवाद को ध्यान में रखकर महासभा चार्टर के अन्तर्गत किसी प्रश्न या स० रा० सभ की किसी शाखा के कार्य या अधिकार के बारे में विचार कर सकती है और उसपर सुझाव दे सकती है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक सहयोग बढ़ाने की व्यवस्था करना और सुझाव देना, अन्तर्राष्ट्रीय कानून और उसको सहिष्णुता बढ़ाना, सभी के लिए मानवीय अधिकार और मौखिक स्वतंत्रताओं की पूर्ण रूप देना तथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के विषय भी इसमें सम्मिलित हैं। महासभा सुरक्षा परिषद तथा स० रा० सभ की दूसरी शाखाओं में रिपोर्टें लेती है तथा उन पर विचार करती है। मूल कारण पर बिना विचार किये देशों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को नष्ट करने वाली किसी भी स्थिति के आने पर शान्तिपूर्ण समझौते के लिए सुझाव देती है।

सामरिक हथकों को छोड़कर निशेपधारी (ट्रस्टीशिप) मयमौतों का निरोध-धारी (ट्रस्टीशिप) परिषद के माध्यम द्वारा निरीक्षण करती है।

सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव करना, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद तथा ट्रस्टीशिप परिषद के लिए चुने गये सदस्यों का निर्वाचन करना, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय व न्यायाधीशों के चुनाव में सुरक्षा परिषद के साथ भाग

लेना तथा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महामन्त्रि नियुक्त करना इसका कार्य है।

महासभा सं० रा० संघ के बजट पर विचार करती है, उसे मंजूर करती है, सदस्यों के अश्वदान का निर्धारण करती है तथा विशेष शाखाओं के बजट की जाँच का काम करती है।

नवम्बर, 1950 में महासभा द्वारा स्वीकृत 'शान्ति के लिए एकता प्रस्ताव' (Uniting for Peace Resolution) के अन्तर्गत यदि सुरक्षा परिषद अपने स्थायी सदस्यों की सर्वसम्मति के अभाव में शान्ति के लिए खतरा, शान्ति भंग या आक्रमण होने की दशा में शान्ति कायम रखने की जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ रहती है तो महासभा अपने सदस्यों से मिल-जुलकर विचार करेगी तथा शान्ति भंग या आक्रमण की दशा में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बनाये रखने या पुनर्स्थापित करने के लिए सेना का उपयोग कर सकती है। यदि महासभा का अधिवेशन न चल रहा हो तब ऐसी स्थिति में यदि आवश्यकता पड़ जाये तो महामन्त्रि सुरक्षा परिषद के किन्हीं 9 सदस्यों की प्रार्थना पर अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकांश सदस्यों की सहमति पर 24 घण्टे के भीतर विशेष बैठक बुला सकता है।

शान्ति और सुरक्षा के बारे में सुझाव, शाखाओं के सदस्यों का निर्वाचन, सदस्यों के प्रवेश, निमन्त्रण और निष्काशन, निक्षेपकारी (ट्रस्टीशिप) प्रश्नों और बजट के मामलों पर दो-तिहाई बहुमत से निर्णय लिया जाता है। दोष मानने में केवल साधारण बहुमत पर्याप्त है। महासभा के प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है।

अधिवेशन (Session)

प्रतिवर्ष महामन्त्रि का एक नियमित अधिवेशन सितम्बर के तीसरे मंगलवार को शुरू होता है। सुरक्षा परिषद की प्रार्थना पर अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकांश सदस्यों अथवा अधिकांश सदस्यों द्वारा अनुमोदित एक सदस्य की प्रार्थना पर महामन्त्रि का विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। यदि सुरक्षा परिषद के 9 सदस्य पक्ष में हों, या संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों का बहुमत हो अथवा अधिकांश सदस्यों द्वारा अनुमोदित एक सदस्य की प्रार्थना पर 24 घण्टे के भीतर आपातकालीन अधिवेशन बुलाया जा सकता है।

मुख्य समितियाँ

महासभा अपना काम 6 मुख्य समितियों के द्वारा करता है, जिनमें सदस्य देशों को अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। ये समितियाँ दस प्रकार हैं—

(i) पहली समिति—राजनैतिक एवं सुरक्षा—(जिसमें दायीकरण नियमन शामिल है);

विशेष राजनैतिक समिति—जो प्रथम समिति की सहायक है;

(ii) दूसरी समिति—आर्थिक और वित्त सम्बन्धी;

(iii) तीसरी समिति—सामाजिक, मानवीय तथा सांस्कृतिक;

(iv) चौथी समिति—निक्षेपकारी (ट्रस्टीशिप), जिसमें गैर-स्वशासित क्षेत्र शामिल हैं;

(v) पाँचवी समिति—प्रशासन और बजट सम्बन्धी; और

(vi) छठी समिति—कानून सम्बन्धी ।

इसके अनिरिक्त मन्त्रों के काम को सुचारु रूप से चलाने के लिए माघारण समिति की बैठकें समय-समय पर होती रहनी हैं । इस समिति में महामन्त्रों के अध्यक्ष तथा 17 उपाध्यक्ष एवं 7 मुख्य समितियों के प्रधान होते हैं । अध्यक्ष हर अधिवेशन के समय प्रतिनिधियों के प्रमाण-पत्रों की जाँच के लिए एक प्रमाण-पत्र समिति नियुक्त करता है ।

विषय-सूची में विचारणीय प्रत्येक प्रश्न को महामन्त्र नियमानुसार किसी एक विशेष समिति, समुक्त या तदर्थ समिति को भेज देती है । ये समितियाँ मन्त्रों की पूर्वकालिक बैठक में विचारार्थ अपने प्रस्तावों को भेजती हैं । इन समितियों और उप-समितियों में सामान्य बहुमत के आधार पर मतदान होता है । मुख्य समिति को न भेजे गये विषय पर मन्त्रों की पूर्वकालिक बैठकों में विचार किया जाता है ।

इस महामन्त्र की सहायता के लिए दो समितियाँ होती हैं—एक प्रशासनिक एवं बजट सम्बन्धी प्रश्नों की सलाहकार समिति और दूसरी असादन सम्बन्धी समिति । महामन्त्र इन समितियों के सदस्यों को उनकी योग्यता एवं मौलिक आधार पर तीन साल की अवधि के लिए चुनती है । सहायक और तदर्थ समितियाँ आवश्यकता के अनुसार बनायी जाती हैं ।

सुरक्षा परिषद (Security Council)

सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्य हैं—चीन, फ्रांस, रूस, अमरीका और ब्रिटेन । 10 अस्थायी सदस्य महामन्त्रों द्वारा 2 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं । सदस्यों का तत्काल पुनर्निर्वाचन नहीं हो सकता ।

मूल रूप से सुरक्षा परिषद के 11 सदस्य थे, किन्तु बाद में घीपणा-पत्र में समीपन करके 1965 में यह संख्या 15 कर दी गयी ।

कार्य तथा अधिकार (Functions and Powers)

समुक्त राष्ट्र मन्त्रों के उद्देश्यों तथा सिद्धान्तों के अनुकूल अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा का कायम रखना, अन्तर्राष्ट्रीय झगदा पैदा करने वाली किसी भी स्थिति अथवा विवाद की छानबीन करना, इन झगदों को सुलझाने अथवा समझौते की शर्तों के उपायों का सुझाव देना, सन्धिकरण का नियमन करने की प्रणाली स्थापित करने के लिए योजना बनाना, शान्ति को खतरा या आक्रमण के कारणों का निर्धारण करना तथा क्या कार्रवाई की जाये, इसके विषय में सुझाव देना, आक्रमण को रोकना या बन्द करने के लिए सशस्त्र-प्रयोग व अनिरिक्त आधिकार सहायता पर रोक तथा अन्य प्रतिपक्षों में लिए सदस्यों में अनुरोध करना, आक्रमणकारी के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करना, जहाँ सदस्यों के प्रवेश तथा सैन्य शक्तों का सुझाव देना जिसके आधार पर सदस्य-राज्य अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के अधिनियम में भाग ले सकें, सामाजिक क्षेत्रों में स० रा० मन्त्रों के निरोधकारी (ट्रस्टीशिप) कार्यों का सुझाव देना, महामन्त्रों की महामन्त्रिणी की नियुक्ति के विषय में सुझाव देना तथा अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में महामन्त्रों के साथ मिलकर न्यायाधीशों की चुनना, महामन्त्रों की वार्षिक तथा विशेष रिपोर्ट भेजना ।

सुरक्षा परिषद सं० रा० सभ के सभी सदस्यों की ओर से कार्य करती है और वे जब इस बात पर सहमत होते हैं कि सुरक्षा परिषद की प्राथमता पर वे अपनी गणसैन्य सेनाओं को सौंप देंगे तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा को कायम रखने के लिए आवश्यक सुविधा एवं सहायता देंगे।

सुरक्षा परिषद में कार्य विधि सम्बन्धी प्रश्नों के अलावा सभी विषयों में स्थायी सदस्यों की सहमति सहित 9 सदस्यों के पक्ष में मतदान होने पर निर्णय लिया जाता है। कोई भी स्थायी या अस्थायी सदस्य अपने से सम्बन्धित किसी विवाद को सुलझाने के निर्णय के सम्बन्ध में अपना मतदान नहीं दे सकता। कार्यविधि के प्रश्नों पर किन्हीं नौ सदस्यों के मतदान पर निर्णय होता है।

सुरक्षा परिषद का गठन इस प्रकार होता है कि उसका कार्य निरन्तर चलता रहे और प्रत्येक सदस्य देश का एक प्रतिनिधि सं० रा० सभ के मुख्यालय पर सदैव विद्यमान रहे। परिषद यदि उचित समझे तो अपने मुख्यालय के अलावा अन्य स्थान पर भी अपनी बैठक बुला सकती है।

सं० रा० सभ का कोई भी सदस्य देश, चाहे वह सुरक्षा परिषद का सदस्य न भी हो, अपने देश के हित से सम्बन्धित चर्चा में भाग ले सकता है। सदस्य और गैर-सदस्य दोनों को परिषद में भाग लेने के लिए नियन्त्रित किया जाता है जबकि उनसे सम्बन्धित किसी विवाद पर चर्चा हो रही हो। गैर-सदस्य होने की दशा में भाग लेने के बारे में परिषद कुछ नियम निर्धारित कर देती है।

आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (Economic and Social Council)

आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के 27 सदस्य हैं जिनमें ॥ का चुनाव महा-सभा प्रतिवर्ष तीन साल की अवधि के लिए करती है। अवधि-निवृत्त (रिटायर) होने वाले सदस्य द्वारा चुनाव लड़ सकते हैं।

कार्य (Functions)

महासभा द्वारा अधिकृत सं० रा० की आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होना; अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी तथा अन्य सम्बद्ध विषयों पर रिपोर्ट और मुद्राव देना तथा अभ्ययन की व्यवस्था करना; सर्वे के लिए प्राग्वीक अधिकारों और मौलिक स्वतन्त्रताओं का पालन करना और उनके प्रति सम्मान को बढ़ावा देना; अपने आन्तरिक विषयों पर महासभा में विचारार्थ मसौदे तैयार करना और इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाना; सं० रा० सभ के माध्यम से उनके सम्बन्धी की परिभाषा करते हुए विशेष शाखाओं के साथ समझौते के लिए बात चलाना; सलाह-मसविदा और सुझाव के द्वारा विशेष शाखाओं के कामों में और महासभा तथा सं० रा० सभ के सदस्यों को सुझाव देकर ताल-मेल बढ़ाना, सयुक्त राष्ट्र सभ के सदस्यों के लिए महासभा द्वारा स्वीकृत और विशेष प्राथमता पर विशेष शाखाओं के लिए काम करना; जिन मामलों में परिषद का सम्बन्ध होता है उनके विषय में गैर-सरकारी संगठनों से सलाह लेना।

आर्थिक और सामाजिक परिषद् में सामान्य बहुमत के आधार पर मतदान होता है और प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है।

सहायक समस्याएँ

परिषद् का काम आयोगों, समितियों तथा कई दूसरे सहायक समस्याओं के द्वारा चलता है। इसका काम चलाने वाले आयोग निम्नलिखित हैं—(i) साम्यिकी आयोग, (ii) जनगणना आयोग, (iii) मानव अधिकार आयोग, (iv) सामाजिक विकास आयोग, (v) महिलाओं का स्तर विषयक आयोग, और (vi) मादक औषधियों का आयोग।

भेदभाव के निवारण एवं अल्पसंख्यकों के चलाव के लिए एक अनिरिक्त आयोग है, जो सीधे मानवीय अधिकारों के निर्देशन में काम करता है। इसमें अनिरिक्त चार क्षेत्रीय आयोग भी हैं, जो अपने क्षेत्रों की समस्याओं का अध्ययन करके विद्युत शक्ति, देन के भीतर मानावान और व्यापारिक उन्नति जैसे मामलों पर इन देशों की सरकारों को उपाय बनाने हैं। ये आयोग हैं

(i) यूरोप के लिए आर्थिक आयोग, (ii) एशिया एवं मध्य पूर्व के लिए आर्थिक आयोग, (iii) लातीनी अमेरिका के लिए आर्थिक आयोग, और (iv) अफ्रीका के लिए आर्थिक आयोग।

हमारे अनिरिक्त परिषद् के अन्तर्गत कई अन्य समितियाँ हैं, जो इन विषयों के सम्बन्ध में कार्य करती हैं जैसे—भवन-निर्माण तथा आयोजन, विज्ञान तथा तकनीकी, योजना तथा विकास, प्राकृतिक साधन, अपराध नियंत्रण तथा आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में स० रा० मण की कार्यविधियों में तालमेल बैठाना।

गैर सरकारी संगठन

आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् अपने अधिकार क्षेत्र से सम्बन्धित क्षेत्रों में काम करने वाले और सहायक संगठनों में भी सप्ताह से मक्ती है। परिषद् यह मानती है कि इन संगठनों का अपना इष्टिचोण अभिव्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए क्योंकि उन्हें अपने में सम्बन्धित विषयों का अनुभव तथा तकनीकी ज्ञान होता है जो परिषद् के लिए अधिक मूल्यवान् हो सकता है।

ये मलाद्वारक संगठन परिषद् और उनकी सहायक समस्याओं की साधारण बैठकों में अपने प्रेषक भेज सकते हैं और यदि चाहे तो परिषद् में सम्बन्धित कामों का विषय में उचित स्तम्भ लिखित रूप में भेज सकते हैं। ये स० रा० मण के सचिवानय में भी आयी हिता के मामले में सलाह ले सकते हैं। प्लानो एवं गिन्न के अनुसार, 'आर्थिक और सामाजिक परिषद् की गतिविधियाँ इसे अन्तर्राष्ट्रीय चिन्तन का केन्द्र और अन्तर्राष्ट्रीय कार्य का उत्प्रेरक बनाती हैं (It is a focus for international thinking and a catalyst for international action)'।

ट्रस्टीशिप परिषद् (Trusteeship Council)

ट्रस्टीशिप परिषद् में स० रा० मण द्वारा प्रस्तावित इराकों के सदस्य, इन इराकों का प्रशासन न चलाने वाले सदस्य तथा अन्य बहुत से ऐसे भी सदस्य होते हैं, जिन्हें महासभा तीन वर्षों के लिए चुनकर भेजती है। इसमें प्रशासनकर्ता व अग्रशासनकर्ता देशों के बीच उचित मन्तव्य बना रहता है। परिषद् द्वारा निर्वाचित

सदस्य अवधि समाप्त होने पर पुनः चुनाव के लिए खड़े हो सकते हैं।

कार्य (Functions)

इस परिषद का काम अपने अधीनस्थ इलाकों के प्रशासन की देखभाल करना है। अपना कार्य करने के लिए परिषद को ये अधिकार हैं : इन अधीनस्थ इलाकों के निवासियों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक प्रगति के लिए प्रस्तावली तैयार करना जिमके आधार पर प्रशासनिक अधिकारियों को हर वर्ष रिपोर्ट देनी होती है। प्रशासनिक अधिकारियों से सलाह करके याचिकाओं को जांचना; प्रशासन द्वारा नियत अवसरों पर बीच में निरीक्षण करना।

ट्रस्टीशिप परिषद में मतदान सामान्य बहुमत के आधार पर होता है, जिसमें प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice)

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय सं० रा० संघ की मुख्य न्यायिक संस्था है। इसका कार्य संचालन चार्टर के अग्रिम भाग के अधिनियम के अनुसार होता है। यह न्यायालय अधिनियम के अन्तर्गत सं० रा० संघ के सभी सदस्यों के लिए स्वतः खुला हुआ है। यदि कोई देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं भी है तो भी वह इस अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमों में भाग ले सकता है परन्तु इस प्रकार के प्रत्येक मामले में सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा उसके नियम निर्धारित करेगी।

सारे देश जो कि न्यायालय के अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं वे इसके समक्ष आये सारे मुकदमों में उपस्थित हो सकते हैं। अन्य देश सुरक्षा परिषद द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर अपना मुकदमा प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे अतिरिक्त सुरक्षा परिषद भी न्यायालय को कानूनी बाह-विवाद के मामले भेज सकती है। महासभा और सुरक्षा परिषद किसी भी कानूनी मामले पर न्यायालय से सलाह माँग सकते हैं। इसी प्रकार महामन्त्र की अनुमति से सं० रा० संघ की अन्य शाखाएँ तथा विशेष समितियाँ अपने-अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत कानूनी मामलों पर सलाह माँग सकती है।

सदस्य राज्य द्वारा भेजे गये मुकदमों, चार्टर में लिखित सभी विषयों अथवा लागू सन्धियों या परम्पराओं को इस न्यायालय को सुनने का अधिकार है। सभी सदस्य देश विशेष मामलों में सन्धि या परम्परा पर हस्ताक्षर करके अपने आपको न्यायालय की सीमा में आवद्ध कर लेते हैं। ये सदस्य यदि चाहें तो कुछ विशेष मुकदमों को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की सीमा से बाहर रख सकते हैं।

अधिनियम की धारा 38 के अनुसार विचारार्थ भेजे गये इन विवादों का निर्णय करते समय न्यायालय ध्यान रखता है कि : विवादकर्ता देशों द्वारा स्वीकृत नियमों के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय परम्पराओं; कानून द्वारा अभिमत व्यवहार का आधार मानकर अन्तर्राष्ट्रीय रीति-रिवाजों; देशों द्वारा स्वीकृत कानून के सामान्य सिद्धान्तों; कानून के नियमों का निर्धारण करने की दृष्टि से न्यायिक निर्णयों और विभिन्न देशों के सुप्रीम प्रचार विशेषज्ञों की शिलाओं के सम्बन्ध में उपर्युक्त तथ्य सामने रहें। यदि विवादकर्ता देश सहमत हो तब कानूनी बात की छाल निकालने

की अपेक्षा यह न्यायालय मामले का व्यावहारिक दृष्टि से न्याययुक्त निर्णय कर सकता है। इस प्रकार के मामलों में यदि एक पक्ष निर्णय को कार्यान्वित न करे तो दूसरा पक्ष सुरक्षा परिपद में इस पर कार्रवाई करने की माँग कर सकता है।

इस न्यायालय के 15 न्यायाधीश होते हैं और उन्हें 'मदस्य' कहा जाता है। महामन्त्री और सुरक्षा परिपद स्वतन्त्र रूप से मनदान द्वारा उनका निर्वाचन करती है। इन न्यायाधीशों का चुनाव उनकी राष्ट्रीयता के आधार पर नहीं अपितु योग्यता के आधार पर किया जाता है। इस बात का ध्यान रखा जाना है कि समार की सभी मुख्य न्याय प्रणालियों को उसमें प्रतिनिधित्व मिले। एक ही देश के दो नागरिक एक ही समय में न्यायाधीश नहीं बन सकते। न्यायाधीश 9 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं और उनका पुनर्निर्वाचन हो सकता है। वे अपने कार्यकाल में कोई अन्य व्यवसाय नहीं कर सकते। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय हंग में स्थित है।

सचिवालय (Secretariat)

सचिवालय संयुक्त राष्ट्र मध्य की अन्य शाखाओं के कार्य करता है तथा उनके द्वारा निर्धारित नीतियों तथा योजनाओं का प्रशासन करता है। उसका मुख्य प्रशासनिक अधिकारी महामन्त्रि होता है जिसकी नियुक्ति महामन्त्री सुरक्षा परिपद की सिफारिश पर करती है। उसके अनेक कार्यों में से एक कार्य यह भी है कि वह सुरक्षा परिपद का ध्यान उन मामलों की ओर दिला सकता है जो उसके विचार में अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं।

मार्च के शिखेनी मकमे पहुँचे महामन्त्रि नियुक्त हुए थे जिनका कार्यकाल 1953 तक रहा। स्वीडन के डाग हैमस्टेल्ड ने 1953 में लेकर 1961 तक कार्यभार सम्भाला। 1961 में अफ्रीका में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गयी। उनकी मृत्यु के उपरान्त बर्मा के ऊषाट महामन्त्रि बने। दिसम्बर 1971 में आस्ट्रेलिया के कुर्त विल्डार्थीम महामन्त्रि के रूप में नियुक्त हुए जिन्होंने जनवरी, 1972 में अपना कार्यभार सम्भाला। 1982 में पेरेंज डी कुयार ने यह पद सम्भाला और अक्टूबर 1987 में वह पुनः पाँच वर्ष के लिए चुने गये।

सचिवालय का मुख्य कार्यालय और विभिन्न देशों में कार्य करने वाले उसके अन्तर्राष्ट्रीय कार्यकर्ता संयुक्त राष्ट्र मध्य के दैनिक कार्यों को करते हैं। कार्यकर्ता 100 में अधिक देशों में लिये जाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के रूप में वे लोग कार्य करते हैं और प्रत्येक कर्मचारी यह मध्य ग्रहण करता है कि जब तक वह संयुक्त राष्ट्र मध्य की सेवा कर रहा है उस दौरान वह किसी और सरकार या किसी बाहरी शक्ति में कोई आदेश नहीं लगा।

महामन्त्रि और उनके कर्मचारियों का कार्यक्षेत्र संयुक्त राष्ट्र मध्य की समस्याओं का अनुगार होना है - जैसे मनाह देना और कभी-कभी प्रत्यक्ष रूप से समस्याओं में हस्तक्षेप करना, अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाना, शांति बताये रखने वाले कार्यों की देखभाल करना, विभिन्न सरकारों में बातचीत, अन्तर्राष्ट्रीय आधिकारिक प्रतिनिधियों और समस्याओं का सर्वेक्षण, मानवीय अधिकारों तथा प्राकृतिक साधनों का अध्ययन, अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठियों का आयोजन, तथ्य सङ्ग्रह, सुरक्षा परिपद तथा अन्य मन्त्रालयों के द्वारा किये गये फैसले लागू करने के बारे में सूचनाएँ एकत्रित

करना, भाषणों की व्याख्या करना, प्रमाण-पत्रों का अनुवाद करना और विश्व के सूचना प्रसारण के साधनों को संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बताना ।

संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यकर्ता समय-समय पर शान्ति बनाये रखने वाली सेनाओं या निरीक्षकों के रूप में उन स्थानों पर जाते हैं जहाँ शान्ति भंग होने का खतरा हो ।

शान्ति के लिए एकता प्रस्ताव (Uniting for Peace Resolution)

‘शान्ति के लिए एकता प्रस्ताव’ की अपनी दिखसस्य कहानी है । जब कोरिया सफ़ट उत्पन्न हुआ तो मोबियत सघ द्वारा सुरक्षा परिषद् में वोटों के प्रयोग से कोई भी कार्रवाई करना सम्भव असम्भव हो गया था । पश्चिमी गुट के देशों ने ‘शान्ति के लिए एकता’ प्रस्ताव पारित करवाकर महासभा के अधिकारों में बड़ी छूटी करवा दी । इस प्रस्ताव के पीछे मूल उद्देश्य शान्ति और सुरक्षा कायम करने के मामलों पर सुरक्षा परिषद् में वोटों से उत्पन्न प्रतिरोध की अवस्था में महासभा को कार्रवाई का अधिकार दिया गया । यह प्रस्ताव 3 नवम्बर, 1950 को पारित किया गया । प्रस्ताव में पाँच प्रमुख व्यवस्थाएँ अंकित हैं :

(अ) महासभा का संकटकालीन अधिवेशन—सुरक्षा परिषद् के किन्हीं नौ सदस्यों के बहुमत से या संघ के कुल सदस्यों के बहुमत से 24 घण्टे की सूचना देकर महासभा का अधिवेशन बुलाया जा सकता है । महासभा अपने दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर वोटों के प्रभाव से बचते हुए अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा के लिए कार्रवाई कर सकती है ।

(ब) शान्ति निरीक्षण आयोग (Peace Observation Commission)—‘शान्ति के लिए एकता प्रस्ताव’ द्वारा सुरक्षा परिषद् के पाँच स्थायी सदस्यों समेत एक चौदह सदस्यीय शान्ति निरीक्षण आयोग की स्थापना की गयी । विश्व के किसी भी भाग में अन्तर्राष्ट्रीय तनाव उत्पन्न होने पर इस आयोग का कार्य निरीक्षण करना तथा रिपोर्ट देना है । इन्हें पर्यवेक्षक (Observer) की संज्ञा दी जाती है ।

(स) सामूहिक उपाय समिति (Collective Measures Committee)—‘शान्ति के लिए एकता प्रस्ताव’ द्वारा एक चौदह सदस्यीय सामूहिक उपाय समिति की स्थापना की गई है जिसका प्रमुख कार्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को मजबूत करने वाले उपायों का अध्ययन तथा उन पर रिपोर्ट देना है ।

(द) राष्ट्रीय सेनाओं की टुकड़ियों का संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के लिए प्रशिक्षण—‘शान्ति के लिए एकता प्रस्ताव’ के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों से सिफारिश की गई है कि वह अपने स्रोतों का सर्वेक्षण कर तय करें कि वह विश्व शान्ति व सुरक्षा के लिए महासभा के कार्यक्रमों के लिए कितनी मदद दे सकते हैं । प्रस्ताव में यह भी सिफारिश की गई है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की इवाइयों को भीषण उपलब्ध कराने के लिए वह अपनी सशस्त्र सेनाओं की टुकड़ियों को प्रशिक्षित, संगठित तथा मुजज्वल करें ।

(य) सं० २५० संघ के प्रति निष्ठा तथा आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति के लिए कार्य—‘शान्ति के लिए एकता प्रस्ताव’ द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों से सिफारिश की गई है कि वह संगठन के प्रति अपनी निष्ठा को दोहराएँ, उसके

निर्णयों का आदर करें, मानव अधिकारों की रक्षा के प्रति आदर बढ़ावें। इस प्रस्ताव में आर्थिक स्थिरता तथा सामाजिक विकास के लिए कार्य करने का भी आग्रह किया गया।

शान्ति के लिए एकता प्रस्ताव का विरोध—सोवियत संघ ने 'शान्ति के लिए एकता प्रस्ताव' की उपरोक्त दूसरी और पाँचवीं व्यवस्थाओं का घोर विरोध किया था। उनका तर्क था कि यह गैर-वानुशी है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के अन्तर्गत विश्व शान्ति और सुरक्षा का कार्य सुरक्षा परिषद् को सौंपा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ अन्य राष्ट्रों ने भी इस प्रस्ताव की कुछ व्यवस्थाओं का विरोध किया। उनका मत था कि संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के अन्तर्गत सामूहिक परिपालन उपायों का अधिकार सुरक्षा परिषद् का है, महामभा का अधिकार मात्र चर्चा तथा सिफारिश तक सीमित है। इस प्रकार इस प्रस्ताव का कुछ सदस्य-राष्ट्रों ने विरोध किया था।

शान्ति के लिए एकता प्रस्ताव का मूल्यांकन—यह प्रस्ताव पारित होने से बालान्तर में इसका अनेक बार कार्यान्वयन हुआ जिसका सुरक्षा परिषद् के पाँचो सदस्यों—अमरीका, ब्रिटेन, फ्रान्स, चीन और सोवियत संघ ने समर्थन दिया। कोरिया संकट के दौरान सुरक्षा परिषद् में सोवियत संघ द्वारा वीटो के इस्तेमाल करने पर महामभा द्वारा 'शान्ति के लिए एकता प्रस्ताव' के अन्तर्गत कार्रवाई करने के निर्णय का अमरीका, ब्रिटेन, फ्रान्स तथा चीन ने समर्थन दिया। दूसरी ओर स्वेड संकट के दौरान ब्रिटेन और फ्रान्स द्वारा सुरक्षा परिषद् में वीटो के प्रयोग करने पर महामभा द्वारा इस प्रस्ताव के अन्तर्गत कार्रवाई करने के निर्णय का सोवियत संघ ने समर्थन दिया। इन सध्यों के आधार पर अब यह कहा जा सकता है कि सुरक्षा परिषद् द्वारा विश्व शान्ति व सुरक्षा कायम करने में असमर्थ रहने पर 'शान्ति के लिए एकता प्रस्ताव' द्वारा महामभा शक्तिशाली हो जाती है और दो-तिहाई बहुमत से सामूहिक सुरक्षा का उपाय कार्यान्वित कर सकती है। अतः शान्ति के लिए एकता प्रस्ताव अत्यन्त उपयोगी है। अब यह एक यथार्थ बन चुका है।¹

सुरक्षा परिषद् में वीटो (निषेधाधिकार) के प्रयोग पर विवाद
(Controversy on the use of Veto in the Security Council)

सुरक्षा परिषद् में 'वीटो' अर्थात् निषेधाधिकार के प्रयोग पर जितना उग्र विवाद खड़ा होना रहा है उतना शायद उसके चार्टर के अन्य किसी प्रावधान को लेकर नहीं हुआ। वीटो शब्द का अर्थ है—अस्वीकृत करना या किसी प्रस्ताव का विरोध करना। सुरक्षा परिषद् के सन्दर्भ में जब इस शब्द का प्रयोग किया जाना है तो इसका विनिष्ट अर्थ होता है। वीटो के प्रयोग के विवाद को समझने से पहले सुरक्षा परिषद् में होने वाली अनदान प्रक्रिया के स्वरूप को समझना जरूरी है।

अनुच्छेद 27 के अन्तर्गत कहा गया है कि सुरक्षा परिषद् के हरेक सदस्य राष्ट्र को एक मत देने का अधिकार है। सुरक्षा परिषद् के कार्यों का दो भागों में बाँटा गया है—(अ) माघारण, और (ब) अमाघारण। माघारण कार्यों के अन्तर्गत सुरक्षा परिषद् का कार्यभार, स्थान एवं समय से सम्बन्धित निर्णय आते हैं। इनके बारे में सुरक्षा परिषद् के निर्णय के लिए किन्हीं 9 सदस्यों के स्वीकारात्मक

¹ इस विस्तृत विश्लेषण के लिए देखें, Leo Mats, 'The U N and the Maintenance of International Peace and Security'.

मतों के साथ ही पाँच स्थायी सदस्य-राष्ट्रों का मत सम्मिलित होना आवश्यक है। यदि इन पाँच स्थायी सदस्यों में से कोई भी अपनी असहमति प्रकट करता है अथवा प्रस्ताव के विरुद्ध मत देता है तो प्रस्ताव अस्वीकृत समझा जाता है। इसे ही 'वीटो का इस्तेमाल' कहा जाता है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सुरक्षा परिषद् की कार्य-प्रणाली सम्बन्धी मामलों के अलावा अन्य निर्णयों के लिए पाँच स्थायी सदस्यों की सहमति आवश्यक है। लेकिन यदि स्थायी सदस्यों में से कोई सुरक्षा परिषद् की बैठक से अनुपस्थित हो या मतदान में भाग न ले तो उसे उस सदस्य के द्वारा वीटो (निर्णयाधिकार) का इस्तेमाल नहीं माना जाता है। सुरक्षा परिषद् के सदस्य-राष्ट्र से सम्बन्धित विवाद पर यदि सुरक्षा परिषद् में विचार हो रहा हो तो वह उसमें भाग तो ले सकता है लेकिन उसमें मतदान नहीं कर सकता। सुरक्षा परिषद् की बैठक में विवाद से सम्बन्धित ऐसे राज्यों को भी भाग लेने के लिए बुलाया जा सकता है, जो उसके सदस्य न हों किन्तु उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं होता।

वीटो-व्यवस्था की आलोचना

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अनेक जानकार लोगो ने वीटो-व्यवस्था की आलोचना की है। मसलन सुप्रसिद्ध विधिशास्त्री हैन्स केल्सन का मानना है कि 'निर्णयाधिकार' के द्वारा समुक्त राष्ट्र सच में पाँच स्थायी राष्ट्रों को विशेषाधिकार प्राप्त हो गया है और इस प्रकार अन्य सदस्यों पर उनकी वैधानिक प्रभुता स्थापित हो गई है। समुक्त राष्ट्र सच के चार्टर में सभी सदस्यों को समान माना गया है, किन्तु निर्णयाधिकार की व्यवस्था उसका उल्लंघन करती है। उससे संघ की व्यवस्था में गतिरोध उत्पन्न हुआ है। इसलिए उसे समाप्त किया जाना चाहिए।¹ वीटो के विपक्ष में मुख्य रूप से निम्नांकित तर्क देकर इस व्यवस्था को समाप्त करने की बात कही जाती है :

(अ) समानता के सिद्धान्त का उल्लंघन—विश्व की पाँच बड़ी शक्तियों को वीटो अधिकार देने से संयुक्त राष्ट्र सच में सदस्य राष्ट्रों की समानता के सिद्धान्त का उल्लंघन हुआ है।

(ब) अन्तर्राष्ट्रीय जनमत की अवहेलना—यदि सुरक्षा परिषद् के पाँच स्थायी सदस्यों को छोड़कर समुक्त राष्ट्र सच के अन्य सदस्य राष्ट्र किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को सम्पन्न करना चाहते हैं तो उसे इन पाँच में से कोई भी वीटो का प्रयोग कर उसमें बाधा पहुँचा सकता है। इसे अन्तर्राष्ट्रीय जनमत का उल्लंघन ही माना जायेगा।

(स) बड़ी शक्तियों की निरंकुशता का प्रतीक—सुरक्षा परिषद् में वीटो व्यवस्था विश्व की पाँच बड़ी शक्तियों की निरंकुशता स्थापित करती है। इस व्यवस्था से वह छोटे राष्ट्रों को वीटो का भय दिलाकर ब्लैकमेल, दबाव एवं शोषण की चालें चल सकती है।

(द) विश्व शान्ति एवं सुरक्षा के कार्य को ठप्प करना—विश्व के किसी भी भाग में तनाव एवं युद्ध गढ़ने की स्थिति में सुरक्षा परिषद् कोई कार्रवाई करने के प्रस्ताव पर किसी भी एक सदस्य की सनक या हठधर्मिता से विश्व शान्ति एवं सुरक्षा स्थापित करने का कार्य ठप्प पड़ सकता है। गुडरिच और हैनशे का मानना

¹ Hans Kelson, *The Law of the United Nations* (New York, 1950), 276-77.

है कि 'निपेधाधिकार सम्बन्धी विवाद ने शान्ति सन्धियों के कार्यों को विलम्बित किया है और युद्ध से घबस्त क्षेत्रों में अपने निर्माण कार्यों को रोक दिया है।'¹

(य) वीटो का सभी स्थायी सदस्यों द्वारा दुरुपयोग—वीटो के अधिकार का सभी स्थायी सदस्यों ने अनेक मौकों पर दुरुपयोग किया है। मसलन, कोरिया, वियतनाम, चीन आदि की मयुक्त राष्ट्र सभ में सदस्यता के मामलों पर अमरीका और सोवियत सभ ने एक-दूसरे के विरुद्ध वीटो का इस्तेमाल कर इस अधिकार का दुरुपयोग किया।

वीटो व्यवस्था के पक्ष में दिये जाने वाले तर्क

एक तरफ जहाँ सुरक्षा परिषद् में वीटो के अधिकार की आलोचना कर इस व्यवस्था को समाप्त करने की बकालत की गयी है वहीं दूसरी ओर अनेक विद्वानों ने इसके पक्ष में भी काफी कुछ कह कर इसका औचित्य सिद्ध किया है। मसलन, दलाइलार का मानना है कि 'निपेधाधिकार असहमति का सूचक' है न कि उसका कारण। अतः वीटो व्यवस्था समाप्त कर देने से न तो महाशक्तियों में मतभेद दूर होंगे और न ही इस दिशा में कोई प्रगति होगी। फिर निपेधाधिकार अनेक प्रकार के प्रश्नों के लिए प्रयुक्त होता है। सदस्यता और शान्तिपूर्ण समझौतों के रूप में इस व्यवस्था की समाप्ति लाभपूर्ण है, किन्तु शान्ति भंग होने अथवा आक्रमण की स्थिति में सैनिक कार्रवाई के सम्बन्ध में वीटो व्यवस्था समाप्त करना बहुत विवादास्पद और नवीन समस्याओं की उत्पन्न करने वाला है। अतः वीटो व्यवस्था बनी रहनी चाहिए।'² वीटो व्यवस्था कायम रखने के पक्ष में आम तौर पर निम्नांकित तर्क दिये जाते हैं।

(अ) विद्वद् शान्ति एवं सुरक्षा बड़ी शक्तियों के सहयोग पर निर्भर—इस वटु सत्य को स्वीकार करने में नहीं हिचकना चाहिए कि विद्वद् शान्ति और सुरक्षा बड़ी शक्तियों के सहयोग से ही कायम की जा सकती है। बड़ी शक्तियाँ छोटे राष्ट्रों की अपेक्षा उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से काम करती हैं। इस कारण सुरक्षा परिषद् द्वारा निर्णय लेते समय सभी बड़ी शक्तियों की आम सहमति अत्यन्त जरूरी है। इसी वान को अभिव्यक्त करते हुए ए० वंदेन बोस (A. Vanden Bosch) तथा डब्ल्यू० टी० होगान (W. T. Hogan) ने कहा है कि 'यदि सुरक्षा परिषद् अपना काम अच्छे ढंग से चलाना चाहती है तो पाँचों स्थायी सदस्यों में आपसी सहयोग जरूरी है। यदि सभी सदस्य एक ही तरह वोट डालने हैं तो इससे जाहिर होता है कि वे उठाये जाने वाले कदमों से सहमत हैं। यदि कुछ सदस्य देश पक्ष में और दोष सदस्य विपक्ष में वोट देते हैं तो इससे जाहिर होता है कि उनमें असहमति है और इसलिए प्रस्तावित कार्रवाई पर सहयोग करने की तैयार नहीं है।'³

¹ M. Leland Goodrich and Edward Hambro, *The Charter of the United Nations* (Boston, 1947), 224

² 'The Veto is a symptom of disagreement rather than its cause, its abolition would accomplish nothing'—Charles E. Schleicher, *International Relations* (New York, 1954), 170

³ 'Cooperation among the five permanent members is essential. If the security council is to perform its functions, . . . if all the members vote the same way, this shows that they agree on the measures to be taken. If some vote for

(व) वीटो के अधिकार से गलत कार्यवाही को रोकना—यह कहना गलत है कि हर समय वीटो का दुरुपयोग किया जाता है। अनेक उदाहरण ऐसे हैं, जहाँ सुरक्षा परिषद् के चार स्थायी सदस्य गलत कार्रवाई करना चाहते थे जिसको सोवियत संघ ने वीटो का इस्तेमाल कर रोक दिया। मसलन, अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन द्वारा भारत-पाक युद्ध के दौरान भारत-विरोधी कार्रवाई करने के प्रस्ताव को सोवियत संघ ने वीटो का इस्तेमाल कर उस गलत कार्रवाई को रोक। सोवियत संघ द्वारा इस मामले पर वीटो का प्रयोग उस अधिकार का दुरुपयोग नहीं, बल्कि सत्य की रक्षा के लिए उपयोग था।

(त) छोटे राष्ट्रों को अनुशासित करने के लिए—बड़ी शक्तियों का तर्क है कि छोटे राष्ट्र अस्तर गैर-जिम्मेदाराना ढंग से व्यवहार करते हैं। सीमा-विवाद या किसी अन्य मतभेद हो जाने पर वे युद्ध लड़ने को उत्साह हो जाते हैं। छोटे राष्ट्रों द्वारा उत्पन्न की गयी संकटकारी परिस्थितियों में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा कायम करने की जिम्मेदारी यदि बड़ी शक्तियों को दे दी जाती है तो इसमें हर्ज ही क्या है? बड़ी शक्तियों के पाम इस अधिकार के होणे से छोटे राष्ट्रों के अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार को अनुशासित करने में मदद मिलेगी।

(द) वीटो से सुरक्षा परिषद् ठप्प होने पर महासभा द्वारा कार्रवाई—वीटो के आलोचक अनेक बार यह तर्क देते हैं कि सुरक्षा परिषद् द्वारा किसी भी कार्रवाई के करने के लिए पाँचो स्थायी सदस्य राष्ट्रों की आम सहमति आवश्यक है। किसी भी एक स्थायी सदस्य द्वारा वीटो के प्रयोग से सुरक्षा परिषद् ठप्प हो जाती है। लेकिन 1950 में 'शान्ति के लिए एकता प्रस्ताव' पारित हो जाने से जहाँ एक ओर वीटो का महत्व कम हो गया वहीं दूसरी ओर महासभा शक्तिशाली हो गयी। सुरक्षा परिषद् में वीटो के प्रयोग से उत्पन्न गतिरोध के बाद विश्व-शान्ति के लिए इस प्रस्ताव को महासभा में लाया जा सकता है और यहाँ 2/3 के बहुमत से कार्रवाई की जा सकती है।

(य) वीटो-व्यवस्था दोषपूर्ण नहीं, बल्कि बड़ी शक्तियों का रबैया पक्षपातपूर्ण है—अपन में विश्व-शान्ति और सुरक्षा को कायम करने तथा उसे मजबूत बनाने के लिए वीटो-व्यवस्था अपनायी गयी। यह व्यवस्था नहीं, बल्कि बड़ी शक्तियों का रबैया दोषपूर्ण एवं पक्षपातपूर्ण रहा है जिमने वीटो की उपयोगिता पर प्रश्न-चिह्न लगाया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि वीटो-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बड़ी शक्तियाँ पक्षपातरहित एवं उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से वीटो के अधिकार का प्रयोग करें।

इस प्रकार वीटो के पक्ष तथा विपक्ष में दिये गये उक्त तर्कों से स्पष्ट है कि अनेक मामलों में बावजूद वीटो-व्यवस्था को बनाये रखना अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा के लिए वांछनीय होगा।

राष्ट्र संघ एवं सं० रा० संघ : तुलनात्मक अध्ययन

(The League of Nations and the U.N.O. : A Comparative Study)

1919 तथा 1945 में स्थापित श्रमजः राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ के

and some vote against a proposal, this shows that they disagree and therefore are not prepared to cooperate in the suggested course of action.' —V. Vanden Bosch and W. T. Hogan, *The United Nations : Background, Organization, Functions and Activities* (New York, 1952), 146

उद्देश्य एक से थे। दोनों का लक्ष्य अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना तथा शान्ति एवं सुरक्षा को कायम करना था, किन्तु अनेक मामलों में वे असमानताएँ-भिन्नताएँ लिए हुए भी थे। कुछ टीकाकार यह कहते हैं कि स० रा० सघ का चार्टर, राष्ट्र सघ की प्रसविदा की नकल है। अनेक विद्वान यह भी मानते हैं कि 'राष्ट्र सघ को नया लिबाम पहनाकर स० रा० सघ का स्वरूप दिया गया है।' अतः राष्ट्र सघ एवं स० रा० सघ के बारे में विद्वानों की इस बहस के सदर्भ में सच्चाई को खोजा जाना चाहिए। इसके लिए हमें दोनों अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में समानताओं तथा असमानताओं की पहचानना होगा तभी कुछ ठोस निष्कर्षों पर पहुँचा जा सकता है।

दोनों संगठनों में असमानताएँ

पहले राष्ट्र सघ और स० रा० सघ में असमानताओं-भिन्नताओं का तुलनात्मक विश्लेषण करना उचित रहेगा। दोनों संगठनों में अन्तर इस प्रकार है—

(1) उद्देश्यों एवं गतिविधियों में अन्तर—हालांकि राष्ट्र सघ और स० रा० सघ दोनों का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा को कायम करना था, किन्तु यदि गहराई से देखा जाये तो राष्ट्र सघ एवं स० रा० सघ के उद्देश्यों एवं गतिविधियों के क्षेत्र में अन्तर दिखाई पड़ता है। उदाहरणार्थ राष्ट्र सघ राजनीतिक संगठन था और उसकी गतिविधियाँ राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने तक सीमित थीं, जबकि स० रा० सघ को राजनीति के अनिदित्त आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय गतिविधियों से सम्बन्धित संगठन भी माना जा सकता है। इसके अनेक विशिष्ट अभिकरणों की गतिविधियों का कार्यक्षेत्र राजनीति के अलावा मानव जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी फैला हुआ है, जबकि राष्ट्र सघ जीवन के अन्य क्षेत्रों में सक्रिय नहीं रहा।

(2) समय-काल का अन्तर—राष्ट्र सघ और स० रा० सघ की स्थापना और सक्रियता के समय-काल में भी अन्तर है। राष्ट्र सघ प्रथम विश्व-युद्ध के बाद पेरिस शान्ति सम्मेलन की प्रसविदा द्वारा स्थापित हुआ, जबकि स० रा० सघ द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद आयोजित एवं विशेष सैन्य प्रामिस्को सम्मेलन के द्वारा स्थापित किया गया।

(3) राष्ट्र सघ की प्रसविदा से स० रा० सघ का चार्टर बड़ा इस्तावेज है—राष्ट्र सघ की प्रसविदा में कुल 26 धाराएँ थीं, जबकि स० रा० सघ के चार्टर में 111 धाराएँ हैं। इस प्रकार प्रसविदा से चार्टर के बड़े होने के कारण स० रा० सघ के उद्देश्य एवं कार्यों की अधिक व्यापक एवं स्पष्ट रूप दिया जाना सम्भव हो सका।

(4) संरचनात्मक अन्तर—राष्ट्र सघ और स० रा० सघ में मूलभूत संरचनात्मक अन्तर पाया जाता है। राष्ट्र सघ के तीन प्रमुख अंग थे—मेता, परिषद् और सचिवालय। दूसरी ओर स० रा० सघ के छह प्रमुख अंग हैं—सभासभा, सुरक्षा परिषद्, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद्, न्याय परिषद् (ट्रस्टीशिप बोर्ड), अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा सचिवालय। इसमें कोई सन्देह नहीं कि राष्ट्र सघ के अन्तर्गत स्थायी न्यायालय की व्यवस्था की गयी थी, किन्तु वह उसका स० रा० सघ के अन्तर्गर्तीय न्यायालय की तरह अभिन्न अंग नहीं था। वह राष्ट्र सघ में परोक्ष

रूप से सम्बद्ध था। इसी प्रकार राष्ट्र संघ के अन्तर्गत मेन्डेल्स थायोग (मेन्डेल्स कमिशन) सं० रा० संघ की न्याय परिषद् से एकदम भिन्न स्वरूप का था। इस प्रकार दोनों अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में कई प्रकार के जोर भी सरचनात्मक अन्तर पाये जाते हैं।

(5) कार्यों के स्पष्ट विभाजन का अन्तर—राष्ट्र संघ की प्रसंविदा में परिषद और सभा के कार्यों और अधिकारों के बारे में स्पष्ट विभाजन का अभाव था जबकि सं० रा० संघ के अन्तर्गत महासभा और सुरक्षा परिषद के मध्य स्पष्ट शक्ति विभाजन पाया जाता है। सं० रा० संघ के चार्टर में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सुरक्षा परिषद की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा कायम करने की है, जबकि महासभा का काम अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा के लिए शिफारिशें करना, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव करना, नये सदस्यों को प्रवेश देना आदि है। इस प्रकार सं० रा० संघ के चार्टर में सुरक्षा परिषद और महासभा के कार्यों और अधिकारों में राष्ट्र संघ की अपेक्षा स्पष्ट विभाजन है।

(6) मतदान प्रक्रिया का अन्तर—राष्ट्र संघ और सं० रा० संघ के अन्तर्गत मतदान प्रक्रिया में मूलभूत अन्तर है। राष्ट्र संघ की परिषद और सभा में उपस्थित सदस्यों के मतैक्य नियम से निर्णय लिए जाते थे जबकि सं० रा० संघ में इस 'मतैक्य मतदान' प्रक्रिया में ढील दी गयी है। महासभा में केवल गृहत्वपूर्ण विषयों पर ही उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्य राष्ट्रों के दो-तिहाई बहुमत और साधारण विषयों पर साधारण बहुमत की व्यवस्था अपनायी गयी है। सुरक्षा परिषद में महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्यों के रक्षीकारात्मक मतों की आवश्यकता होती है जिसमें गार्च स्थायी सदस्यों के समर्थनारम्भक मतों का होना भी अनिवार्य है। इस प्रकार राष्ट्र संघ की अपेक्षा सं० रा० संघ की मतदान प्रक्रिया अधिक उदार है।

(7) अमरीकी सहयोग का अन्तर—प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस शान्ति सम्मेलन में अमरीकी राष्ट्रपति वुड्रो विलसन ने फ्रांस तथा ब्रिटेन की सजीव तथा स्वार्थपरक नीतियों का घोर विरोध किया था। वह अपने चौदह सूत्रों के अनुसार विश्व शान्ति एवं सुरक्षा कायम करना चाहते थे। राष्ट्र संघ की स्थापना की योजना भी इसी का महत्वपूर्ण अंग थी। लेकिन राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद सीनेट ने अमरीका द्वारा इस विश्व संगठन की मददगारता ग्रहण करने का विरोध किया। अमरीका जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्र के राष्ट्र संघ में न होने के कारण यह विश्व संगठन अपने कार्यों और उद्देश्यों में असफल रहा। परन्तु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमरीका ने सं० रा० संघ की मददगारता ग्रहण की। इस अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में अमरीका जैसे महाशक्ति की माधोदारी के कारण विश्व शान्ति एवं सुरक्षा को अधिक प्रभावकारी ढंग में कायम करने में मदद मिली है।

(8) संशोधन प्रक्रिया का अन्तर—राष्ट्र संघ की प्रसंविदा के अनुच्छेद 26 के अनुसार 'संशोधन उसी समय लागू होये, जब परिषद में प्रतिनिधित्व प्राप्त सदस्यों तथा सभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त सदस्यों का बहुमत उनका समर्थन करेगा। संशोधन उस सदस्य पर बाध्यकारी नहीं होगा, जो उनसे अपनी अनहमति प्रकट करेगा, परन्तु ऐसी स्थिति में वह संघ का सदस्य नहीं रह जायेगा।' दूसरी तरफ

समुक्त राष्ट्र मध्य चार्टर के अनुच्छेद 108 के अनुसार 'जो भी मंशोधन होंगे वे सगठन के सभी सदस्यों पर तभी लागू होंगे जब तक कि उनको महामन्त्रा दो-तिहाई के बहुमत से मान ले और सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्यों सहित स० रा० सभ के सदस्य अपनी वैधानिक प्रक्रियाओं के अनुसार दो-तिहाई बहुमत से उनका सत्यापन कर दें। इस प्रकार राष्ट्र सभ और म० रा० सभ द्वारा मंशोधनों के मामले में मिश्र प्रक्रिया अपनाये जाने की व्यवस्था की गयी।

(9) सदस्यता के प्रत्याहार एवं निष्कासन का अन्तर—राष्ट्र सभ की प्रसविदा तथा म० रा० सभ के चार्टर दोनों में सदस्यों को सगठन की सदस्यता से च्युत करने की व्यवस्था की गयी है। स० रा० सभ चार्टर में निष्कासन की व्यवस्था न होकर 'स्वयन' की व्यवस्था की गयी है।

(10) कार्रवाई क्षमता का अन्तर—नैतिक आक्रमण होने की अवस्था में राष्ट्र सभ कोई प्रभावकारी कदम नहीं उठा सकता था जबकि म० रा० सभ चार्टर के अन्तर्गत सुरक्षा परिषद को तत्काल कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार राष्ट्र सभ की अपेक्षा म० रा० सभ अपने निर्णयों को लागू करने में अधिक सक्षम है।

(11) मानव अधिकारों पर अधिक बल का अन्तर—म० रा० सभ चार्टर में मानवाधिकार रक्षा एवं मौलिक स्वतन्त्रताओं पर अधिक बल दिया गया है। महामन्त्रा ने इस बारे में 'मानव अधिकार घोषणा' भी की है, जबकि राष्ट्र सभ ने इस बारे में ध्यान नहीं दिया।

(12) सदस्यों के अन्तर्राष्ट्रीयकरण का अन्तर—राष्ट्र सभ की सदस्यता अग्रिम सीमित थी जबकि म० रा० सभ को विश्व-व्यापी सगठन बनाया गया। राष्ट्र सभ की सदस्यता 60 देशों तक बड़ी। इसके प्रसविदा पर हस्ताक्षर करने वाले 32 राष्ट्र थे, किन्तु उनमें से 29 ने ही इसका अनुममर्शन किया। तत्कालीन विश्व की पाँच बड़ी शक्तियों में अमरीका जैसी बड़ी शक्ति कभी इसका सदस्य बनी ही नहीं। कम की इसमें निकास दिया गया। धीरे-धीरे कुल 18 देशों ने अपने को राष्ट्र सभ में अन्तर्ग कर दिया। दूसरी तरफ स० रा० सभ के 51 राष्ट्र प्रारम्भिक सदस्य थे। दक्षिण अफ्रीका और इजरायल के अन्तर्गत के अनिर्दिष्ट भाग तक किसी भी राष्ट्र को म० रा० सभ में नहीं निकास दिया गया। अफ्रीका-एशियाई एवं लातीनी अमरीकी देशों ने उपनिवेशवादी शक्तियों के चक्र से मुक्ति पान के बाद म० रा० सभ में प्रवेश किया। इस प्रकार राष्ट्र सभ जहाँ यूरोपीय देशों तक सीमित था वहीं म० रा० सभ विश्व-व्यापी सगठन है।

(13) अधिवेशनों के स्वयं में अन्तर—राष्ट्र सभ और म० रा० सभ के अधिवेशनों में भी अन्तर पाया जाता है। राष्ट्र सभ की परिषद के अधिवेशन एक वर्ष में तीन या चार भागों में और मन्त्रा के अधिवेशन अन्तर्जातीय होने से, जबकि म० रा० सभ की सुरक्षा परिषद निरन्तर कार्य करने वाली सम्पा है। सुरक्षा परिषद का विशेष अधिवेशन 24 घण्टे की पूर्व-सूचना पर बुलाया जा सकता है। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र का एक प्रतिनिधि कार्य-स्थान पर सदैव उपस्थित रहता है। इसके विपरीत राष्ट्र सभ के अन्तर्गत परिषद के सदस्य-राष्ट्र के प्रतिनिधि के लिए यह आवश्यक नहीं था। इस प्रकार राष्ट्र सभ और म० रा० सभ के अधिवेशनों के सम्बन्ध में अन्तर पाया जाता है।

(14) आत्म-रक्षा की व्यवस्था में अन्तर—राष्ट्र संघ की प्रसविदा के अन्तर्गत सदस्य-देशों को आत्म-रक्षा के वास्ते किसी प्रकार की वैयक्तिक एवं सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गयी थी। किन्तु सं० रा० संघ चार्टर के अनुच्छेद 51 में आक्रमण की अवस्था में सदस्य-देश आत्मरक्षा के वास्ते तब तक वैयक्तिक तथा सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं जब तक सं० रा० संघ शान्ति कायम करने के लिए आवश्यक उपाय न जुटा ले। इस प्रकार सं० रा० संघ में वैयक्तिक एवं सामूहिक सुरक्षा को अधिक व्यावहारिक एवं स्पष्ट बनाने का प्रयास किया गया है।

अन्य अन्तर—राष्ट्र संघ और सं० रा० संघ में और भी अनेक अन्तर हैं जो निम्नांकित हैं—

(क) राष्ट्र संघ की प्रसविदा (Covenant) में अपनी किसी सेना का उल्लेख नहीं किया गया है जबकि सं० रा० संघ के चार्टर में अपनी सेना की व्यवस्था का उल्लेख है।

(ख) राष्ट्र संघ की प्रसविदा और सं० रा० संघ के चार्टर में सचिवालय तथा महासचिव का उल्लेख है, परन्तु चार्टर में प्रसविदा से ज्यादा स्पष्ट रूप से सचिवालय तथा महासचिव के कार्यों का उल्लेख मिलता है।

(ग) राष्ट्र संघ की प्रसविदा तथा सं० रा० संघ चार्टर दोनों में सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्रीय संगठन की आवश्यकता को स्वीकारा गया है, किन्तु प्रसविदा की तरह चार्टर में इनका विस्तृत उल्लेख नहीं है।

(घ) राष्ट्र संघ की प्रसविदा में अधिवेश पद्धति (Mandatory System) के बारे में अधिवेश आयोग (Mandatory Commission) की व्यवस्था की गयी थी, जबकि सं० रा० संघ के चार्टर में एक स्थायी न्याय परिषद का उल्लेख किया गया है, जिसका कार्यक्षेत्र और अधिकार अधिक व्यापक है।

राष्ट्र संघ तथा सं० रा० संघ के तुलनात्मक अध्ययन का मूल्यकन—राष्ट्र संघ तथा सं० रा० संघ के उपरोक्त तुलनात्मक अध्ययन के उपरान्त यह कहा जा सकता है कि जहाँ राष्ट्र संघ की अनेक अच्छी व्यवस्थाओं को सं० रा० संघ की स्थापना करते समय अपनाया गया, वहीं दूसरी ओर उसकी कमजोरियों के अनुभवों का ध्यान में रखते हुए कई नई व्यवस्थाएँ की गयीं। इसका उद्देश्य सं० रा० संघ की विश्व शान्ति एवं सुरक्षा स्थापित करने में सक्षम एवं प्रभावी बनाना था। इसी बात का ध्यान में रखते हुए सं० रा० संघ की 'नक्स' या 'नये लिबास में पुरानी वस्तु' की सहा देना अनुचित होगा।

सं० रा० संघ चार्टर का पुनरीक्षण एवं संशोधन
(Revision and Amendment of the U. N. Charter)

सं० रा० संघ जैसे महत्वपूर्ण विश्व संगठन की स्थापित हुए अब तक करीब पाँच दशक हो रहे हैं। इस काल के दौरान इसने कई उतार-चढ़ाव अनुभव किये हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूँजीवादी एवं साम्यवादी शक्तों के बीच युद्ध में गुटबाजी का बोलबाला रहा और तत्पश्चात् वेतात युग में विकसित बनाम विकासशील देशों में टकराव उत्पन्न हुआ जो 'नये शीत युद्ध' के मोर्चेदार दौर में भी काफ़ी हद तक जारी है। इस मूलभूत परिवर्तन की प्रक्रिया के दौर में अनेक विद्वानों ने सं० रा०

सभ के चार्टर के पुनरीक्षण एवं संशोधन की बात उठायी है, ताकि यह विश्व सगठन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की नई चुनौतियों का मुकाबला कर सके।²

पुनरीक्षण एवं संशोधन सम्बन्धी व्यवस्था—इस सन्दर्भ में पहले चार्टर में दी गयी पुनरीक्षण एवं संशोधन सम्बन्धी व्यवस्थाओं का उल्लेख कर देना उचित रहेगा। अध्याय 18 के अनुच्छेद 108 एवं 109 में चार्टर के पुनरीक्षण एवं संशोधन सम्बन्धी उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 108 के अनुसार महासभा के सदस्यों के दो-तिहाई मतों का समर्थन प्राप्त होने पर और सर्वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार स० रा० सभ के सदस्यों के दो-तिहाई का, जिसमें सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य सम्मिलित होंगे, अनुममर्थन प्राप्त हो जाने पर ही घोषणा-पत्र में स० रा० सभ के सभी सदस्यों के लिए संशोधन प्रभावी हो सकेंगे। अनुच्छेद 109 में तीन बातें कही गयी हैं। पहली बात, महासभा के सदस्यों के दो तिहाई मतों और सुरक्षा परिषद के किसी नौ सदस्यों के मतों द्वारा तारीख और स्थान का निर्धारण होने पर ही घोषणा-पत्र का पुनरीक्षण करने के लिए स० रा० सभ के सदस्यों का साधारण सम्मेलन नियत तारीख और स्थान पर आयोजित किया जा सकेगा। दूसरी बात, घोषणा-पत्र में कोई भी परिवर्तन तभी प्रभावी होगा जब उससे समर्थन में सम्मेलन के दो-तिहाई मतों के आधार पर सिफारिश की जायेगी और सर्वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्यों सहित स० रा० सभ के दो-तिहाई सदस्य उसका अनुसमर्थन करें। तीसरी बात, यदि ऐसा सम्मेलन घोषणा-पत्र के लागू होने के बाद महासभा के दसवें वार्षिक अधिवेशन के पूर्व आयोजित नहीं किया जाता है तो यह सम्मेलन करने का प्रस्ताव महासभा के उस अधिवेशन की कार्य मूची में रखा जा सकता है और महासभा के सदस्यों के अधिकांश मतों और सुरक्षा परिषद के सात सदस्यों के मतों के समर्थन पर यह सम्मेलन आयोजित किया जा सकता है।

चार्टर में बाह्यीय संशोधन—चार्टर में संशोधन करने के अब तक कोई ठोस प्रयास नहीं हुए हैं जिस कारण इसके निम्नांकित प्रावधानों के बारे में अनेक प्रकार से संशोधन बाह्यीय है।

(1) **सदस्यता—**हानाकि स० रा० सभ के चार्टर में कहा गया है कि विश्व शांति में विकास रखने वाले सभी देश इस सगठन के सदस्य बन सकते हैं किन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं हुआ है। इसका प्रमुख कारण सुरक्षा परिषद में पाँच बड़े देशों के पास 'वीटो' शक्ति होने के कारण अन्य देश जैसे वियतनाम, चीन, उत्तरी कोरिया तथा दक्षिण कोरिया आदि को काफी समय तक सदस्यता नहीं मिल पायी। इस कारण किसी भी देश द्वारा स० रा० सभ की सदस्यता के लिए आवेदन करने पर 'वीटो' के प्रावधान को ममान्त किया जाना बाह्यीय है।

(2) **वीटो का अधिकार—**सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्य देशों—अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस के पास 'वीटो' का अधिकार है। किसी भी नातु अन्तर्राष्ट्रीय सङ्घ के समय स० रा० सभ द्वारा कोई भी कार्रवाई करने के प्रस्ताव पर किसी भी एक स्थायी सदस्य देश द्वारा वीटो का प्रयोग करने की अवस्था में विश्व शांति एवं सुरक्षा गतरे में पड़ सकती है। कुछ लोगों ने 'वीटो' के अधिकार

² इसकी विमर्श व्याख्या के लिए देखें—Robert W Gregg and Michael Barkin (ed) *The United Nations System and its Functions*, (New York, 1970)

को खत्म करने का सुझाव दिया है किन्तु वर्तमान में यह सम्भव नहीं प्रतीत होता, क्योंकि पांच बड़े देशों से 'वीटो' के अधिकार को छीन लेने के बाद वे सं० रा० संघ की सदस्यता ही छोड़ देंगे। इससे इस विश्व संगठन का ही अस्तित्व समाप्त हो जाने का डर है। अतएव यही अच्छा रहेगा कि सुरक्षा परिषद के अलावा सं० रा० संघ के अन्य अंगों जैसे महासभा और अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की शक्तियों में वृद्धोत्तरी की जाये। उनके निर्णय के प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने के बारे में प्रावधान किया जाये।

(3) स्वतन्त्र वित्त—सं० रा० संघ की जिम्मेदारियाँ दिनो-दिन बढ़ रही हैं। राजनीतिक कार्यों को सम्पन्न करने के बाद अब वह आर्थिक कार्यों को आयोजित करने में सबसे ज्यादा जोर दे रहा है, जिस कारण उसका आर्थिक रूप से सक्षम रहना अति आवश्यक है। चार्टर में यह व्यवस्था है कि सं० रा० संघ का खर्चा सदस्य देश वहन करेंगे। सदस्य देश अपनी क्षमता के अनुसार धन देंगे। लेकिन अनेक बार यह देखने में आया है कि सोवियत संघ और फ्रांस सं० रा० संघ की अनेक गतिविधियों से सहमत नहीं होते हैं और उनके खर्च के लिए धन देने से मुकर जाते हैं। इस दृष्टि से सं० रा० संघ को आर्थिक दृष्टि के स्वतन्त्र एवं सक्षम बनाना अत्यन्त जरूरी है। इसके लिए नये आर्थिक ससाधनों की व्यवस्था करनी होगी। राष्ट्रों द्वारा राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार के बाहर समुद्री सम्पदा के दोहन करने पर, अन्तर्राष्ट्रीय डाक एवं संचार पर कर लगाकर या अन्य प्रकार से सं० रा० संघ अपनी आवश्यकता के लिये सहायता है।

(4) संरचनात्मक संशोधन—सं० रा० संघ को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए चार्टर में इस विश्व संगठन में संरचनात्मक संशोधन बाध्यनीय है। विशेष तौर से सुरक्षा परिषद, महासभा और अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में अनेक प्रकार के संरचनात्मक संशोधन सं० रा० संघ के घोषित उद्देश्यों की प्राप्ति में अत्यन्त सहायक सिद्ध होंगे। इन संशोधनों को निम्नांकित तरीके से अभिव्यक्त किया जा सकता है :

(क) सुरक्षा परिषद—सुरक्षा परिषद की स्थापना विश्व शान्ति एवं सुरक्षा बनाये रखने के लिए हुई थी। 'शान्ति के लिए एकता प्रस्ताव' के द्वारा इसकी कुछ हद तक जिम्मेदारी महासभा को सौंपी गयी। सुरक्षा परिषद में किसी भी स्थायी सदस्य द्वारा वीटो का प्रयोग करने की स्थिति में महासभा की आगे की कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी। ऐसा करने का प्रमुख कारण विगत में स्थायी सदस्यों द्वारा बारंबार 'वीटो' का इस्तेमाल करना था। किन्तु इस स्थिति में परिवर्तन आ गया है। एक तरफ जहाँ स्थायी सदस्य बारंबार वीटो का प्रयोग नहीं कर शान्ति के साथ आचरण कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारत, जापान और पश्चिम जर्मनी जैसे देश अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को दिशा देने में महत्वपूर्ण कारक बनते जा रहे हैं। इस सबको देखते हुए भारत, जापान और पश्चिम जर्मनी को भी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना लेना चाहिए, क्योंकि यह विश्व शान्ति को मजबूत करने के पक्ष में होगा। इसी पुराने स्थायी सदस्यों के मतदान-आचरण पर भी नियन्त्रण रखा जा सकेगा।

(ख) महासभा—महासभा ने अनेक सराहनीय कार्य किये हैं। इसके बावजूद उसमें अनेक संरचनात्मक संशोधन करना बाध्यनीय है। पहली बात, इसकी प्रमुख समितियों की बैठक के अधिवेशन हमेशा जारी रहने चाहिए। दूसरी बात, महासभा

के अधिवेशन के दौरान रखे जाने वाले मुद्दों पर विशेष समितियाँ हो। तीसरी बात, महासभा के अधिवेशन के दौरान यक्तों को विश्व के हरेक भाग से समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। चौथी बात, अधिवेशन में वाद-विवाद (चर्चा) को सीमित रखने के लिए महासभा के अध्यक्ष तथा समितियों के अध्यक्ष को न्यायिक शक्तियाँ दी जानी चाहिए। इस प्रकार महाममा में इन चार मरचनात्मक संशोधन को करना उचित होगा।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय—अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय मुख्यतया दो प्रकार के काम करता है। प्रथम, सदस्य राष्ट्रों द्वारा इसको सौंपे गये विवादों को सुनता है। दूसरे, सं. रा. सघ के विभिन्न अंगों तथा विशिष्ट अभिकरणों को कानूनी प्रश्नों पर सलाह (Advisory Opinion) देता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इसने निर्णय बाध्यकारी नहीं होते। साथ ही यह भी पाया गया है कि अधिकांश सदस्य राष्ट्र अपने विवाद अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के बजाय सं. रा. सघ के राजनीतिक अंगों जैसे महासभा एवं सुरक्षा परिषद में प्रस्तुत कर समाधान ढूँढना पसन्द करते हैं। इसे देखते हुए आवश्यक है कि अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को प्रभावकारी बनाने के लिए सं. राष्ट्र सघ चार्टर में संशोधन किया जाये। इन सम्बन्ध में निम्नांकित दो संशोधन विशेष तौर से ध्यान देने योग्य हैं (i) सभी सदस्य राष्ट्रों द्वारा कानूनी मामलों को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में ही सौंपने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इससे महाममा और सुरक्षा परिषद का कानून के तत्त्वों की पक्ष के बारे में अधिक वाद-विवाद करने में मक्त बर्बाद नहीं होगा, और (ii) जिन विवादों को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में सौंपा गया है, उन पर महाममा और सुरक्षा परिषद विचार न करें।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सं. रा. सघ को प्रभावशाली बनाने के लिए चार्टर का पुनरीक्षण एवं संशोधन करना अत्यन्त आवश्यक है। किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि अब तक इसकी ममीक्षा के लिए कोई भी सम्मेलन आयोजित नहीं हो पाया है। प्रो० आइशेलबर्गर (Eichelberger) ने 'चार्टर संशोधन सम्मेलन' नहीं होने के दो कारण माने हैं। पहला कारण यह भय है कि कुछ बड़ी शक्तियाँ ममीक्षा सम्मेलन कीटो व्यवस्था के बाहर उनकी तानाशाही के विस्तार तथा महाममा की सत्ता (Authority) को कम करने के लिए चाहते हैं। महाममा में बहुमत वाले छोटे राष्ट्र महाममा की सत्ता को प्रबलित करना तथा साधारण बहुमत के लिए काम करना चाहते हैं। दूसरा कारण यह कहा जाता है कि सं. रा. सघ उसके चार्टर की भाषा से मजबूत नहीं होगा, बल्कि उसकी हिचक का कारण अनेक शक्तियों द्वारा अपने उत्तरदायित्व को नकारना है, जिन्हें वे अपनी सहायित व सुविधा के अनुसार ही निभाती हैं।¹ कुल मिलाकर यह कहना उचित होगा कि सं. रा. सघ को प्रभावशाली बनाने के लिए चार्टर का पुनरीक्षण एवं उसमें संशोधन अत्यन्त आवश्यक है ताकि वह बदलती अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की चुनौतियों का मुकाबला कर सके।

¹ "The U.N. is not being held back by the language of the Charter but by the refusal of many powers to fulfil their obligations under the Charter, unless it suits their convenience"—Clarke M. Eichelberger, *The U.N. : The First Twenty-five Years* (New York, 1970), 157.

सं० रा० संघ के राजनीतिक कार्य (Political Activities of the U.N.)

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व शान्ति एवं सुरक्षा को कायम करने के लिए विश्व संगठन के रूप में स्थापित सं० रा० संघ ने अनेक राजनीतिक कार्य सम्पादित किये हैं। आज के युद्ध में जीवन के हरेक क्षेत्र में राजनीतिक क्रियाकलापों का वर्चस्व है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक मंच पर अनेक राष्ट्रों के मध्य सीमा विवाद तथा अन्य मतभेदों ने युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया है। यदि ऐसे नालुक मौकों पर सं० रा० संघ चतुरार्थ, कार्यकुशलता और प्रभावशाली तरीकों से काम नहीं लेता तो सम्भवतः अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय तीसरे विश्व युद्ध की चपेट में आ जाता। इस दृष्टि से सं० रा० संघ ने अनेक राजनीतिक कार्य सम्पादित किये हैं। यहाँ मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक कार्यों का ही संक्षिप्त उल्लेख किया जायेगा।

(1) बर्लिन का प्रश्न (1945-49)—1945 में आयोजित 'पोट्सडाम' सम्मेलन के अन्तर्गत बर्लिन नगर को ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ के बीच विभाजित कर दिया गया था। जहाँ पश्चिमी बर्लिन, ब्रिटेन व फ्रांस के कब्जे में हो गया, वहीं पूर्वी बर्लिन रूस को दे दिया गया। इस सम्मेलन के अन्तर्गत यह तय किया गया था कि बर्लिन के पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों हिस्सों में समान आर्थिक व्यवस्था रखी जायेगी। लेकिन ब्रिटेन तथा फ्रांस ने इस व्यवस्था का उल्लंघन किया जिससे चिढ़कर सोवियत संघ ने बर्लिन की नाकेबन्दी कर ली। इससे फ्रांस एवं ब्रिटेन द्वारा पूर्वी जर्मनी के जरिये ५० जर्मनी पहुँचने का मार्ग अवरोध हो गया। 4 अक्टूबर, 1948 को फ्रांस एवं ब्रिटेन ने सोवियत-नाकेबन्दी को सं० रा० संघ में शिकायत की। अन्त में अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस में परस्पर बातचीत हुई, जिसके परिणामस्वरूप 4 मई, 1949 को रूस ने बर्लिन की घेराबन्दी डहा ली। इस प्रकार सं० रा० संघ ने बर्लिन समस्या सुलझाने में उल्लेखनीय पहल की।

(2) इण्डोनेशिया का विवाद (1945-49)—यह विवाद इण्डोनेशिया की स्वतन्त्रता से सम्बन्धित है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब हार्लैण्ड ने इण्डोनेशिया में अपना प्रभुत्व फिर से स्थापित करना चाहा तो यह मामला सुरक्षा परिषद के सामने लाया गया, क्योंकि हार्लैण्ड और इण्डोनेशिया के राष्ट्रवादी नागरिकों के बीच युद्ध छिड़ गया था। 17 जनवरी, 1948 को सुरक्षा परिषद की 'सहप्रवास समिति' ने दोनों देशों में युद्ध विराम कराने और तत्पश्चात् सं० रा० संघ स्थायी सम्मेलन करवाने में सफल हो गया। इस प्रकार 27 दिसम्बर, 1949 को इण्डोनेशिया का स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में उद्घाटन हुआ।

(3) सीरिया-लैबनान विवाद (1946)—4 जनवरी, 1946 को सीरिया तथा लेबनान ने सुरक्षा परिषद में यह मांग रखी कि उनकी भूमि पर ब्रिटिश तथा फ्रान्सीसी सेनाओं की उपस्थिति सं० रा० संघ के चार्टर के अनुसार तुरन्त हटा ली जाये, हार्ताकि अमरीका, ब्रिटेन एवं फ्रांस से निकट होने के कारण वह इस मामले को टालना चाहता था। दूसरी तरफ अमरीका का प्रतिस्पर्धी सोवियत संघ विदेशी सेनाओं के उक्त सैन्य से हटने के लिए दबाव डाल रहा था। विश्व जनमत के दूर से 30 अप्रैल, 1946 तक ब्रिटेन और फ्रांस ने अपनी सेनाओं के हटा लेने का विश्वास दिनाया और बाद में जाकर उसका पालन भी किया।

(4) यूनान का विवाद (1946-49)—सीमान्त देशों द्वारा यूनान में छापामारो को युद्ध सहायता पहुँचाने के कारण यूनान ने स० रा० संधि का ध्यान आकर्षित किया। सुरक्षा परिषद ने एक विशेष जाँच आयोग की परिस्थिति का जायजा लेने के लिए नियुक्त किया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अल्बानिया, बुल्गारिया तथा यूगोस्लाविया यूनान में छापामार युद्ध को सहायता पहुँचा रहे हैं। सोवियत संधि द्वारा सुरक्षा परिषद में चींटों के इस्तेमाल से यह मामला 3 सितम्बर, 1947 को महामन्त्री को सौंपा गया, पर इसका कोई समाधान नहीं किया जा सका। फिर भी महामन्त्री ने एक प्रस्ताव पारित किया कि यूनान के तीनों सीमान्त देश छापामारो को मदद बन्द करें और शान्तिपूर्ण तरीकों से विवादों का निपटारा करें। आगे चलकर रूस और यूगोस्लाविया में बढ़ता उत्पन्न होने से यूगोस्लाविया ने छापामारो को मदद बन्द कर दी। उधर यूनान का अमरीकी भारीय योजना के अन्तर्गत भारी मात्रा में सैनिक एवं आर्थिक मदद मिलने ली। यूनान के विरोधी राष्ट्र चुप बैठ गये।

(5) ईरान (1946)—19 जनवरी, 1946 को ईरान ने स० रा० संधि की सुरक्षा परिषद में यह आरोप लगाया गया कि उसके अजरबाइजान नामक प्रान्त में रूसी सेना ने प्रवेश कर आन्तरिक हस्तक्षेप किया है। सुरक्षा परिषद ने इस अनुरोध पर ईरान और रूस के मध्य बातचीत आरम्भ करवाई ताकि इस झगड़े को टाला जा सके। 23 मई, 1946 को ईरान से रूसी सेनाएँ हटा ली गईं। इस प्रकार स० रा० संधि में ईरान और रूस के बीच विवाद का समाधान कर दिया।

(6) काश्मीर-विवाद (1947)—भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन के समय देशी रियासतों पर अधिकार के बारे में विवाद उत्पन्न हो गया। पाकिस्तान ने उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त के कश्मीरियों की सहायता से 22 अक्टूबर, 1947 को कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। चार दिन के अन्दर ही वे कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में 15 मील दूर बारामूला तक पहुँच गये। ऐसी नाजुक घड़ी में कश्मीर के शासक ने भारत में मिलने की इच्छा प्रकट की तथा उसे आक्रमणकारियों से बचाने के लिए सैनिक सहायता का अनुरोध किया। भारत ने इस अनुरोध पर तुरन्त अपनी सेनाएँ भेज दी। इसके बाद यह मामला स० रा० संधि में प्रस्तुत किया गया। सुरक्षा परिषद ने इस विवाद के समाधान के लिए पाँच देशों का मधुक्त राष्ट्र आयोग नियुक्त किया। साथ ही सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें दोनों देशों को अपनी सेनाएँ हटाने और भारत को कश्मीर में अनमत मग़्ग करवाने का आदेश दिया। 1 जनवरी, 1949 को दोनों पक्ष युद्ध विराम के लिए सहमत हो गये। लेकिन बाद में दोनों पक्षों के बीच काश्मीर के भाग्य को लेकर अनेक बातचीतें हुईं, फिर भी कोई ठोस समाधान न हो पाया। दोनों देशों के बीच 1965 तथा 1971 में युद्ध हुए। इन युद्धों को रोकने में स० रा० संधि ने सफलतापूर्वक भूमिका अदा की।

(7) किलिस्तीन-विवाद (1947)—स० रा० संधि में आज तक प्रस्तुत सफलतया में किलिस्तीन विवाद सबसे अधिक अट्टल है। युद्ध के बाद राष्ट्र संधि के जरिये इस पर ब्रिटेन का मरतलन कायम किया गया था। किन्तु यहूदियों द्वारा इसकी तीव्र स्थान तथा अरबों द्वारा मानुषभूमि मानने के कारण इसमें कोई सफलता का रूप धारण कर निया। दोनों द्वाग इते हथियाने के प्रयासों के

कारण आपसी संघर्ष हुए। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थिति ने ओर उग्र रूप धारण कर लिया। जब ब्रिटेन ने 1947 में वहाँ से अपनी फौजें। अगस्त, 1948 तक हटाने का निर्णय किया तो यहूदी और अरब दोनों लड़ पड़े। परिणाम-स्वरूप सुरक्षा परिषद ने दोनों में एक विराम सन्धि करवाकर युद्ध को रोक। 15 मई, 1948 को ब्रिटेन द्वारा फिलस्तीन से अपना संरक्षण उठा लेने के तुरन्त बाद यहूदियों ने फिलस्तीन में 'इजराईल' राज्य की स्थापना की घोषणा कर दी। उपर अमरीका ने तत्काल उसे मान्यता प्रदान कर दी। इससे अरब देशों ने इजराईल के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की। सुरक्षा परिषद की बैठक आयोजित कर एक प्रस्ताव द्वारा यह अपील की गयी कि फिलस्तीन में सभी राज्य सैनिक कार्रवाई बन्द कर दें। युद्ध बन्द तो हो गया, किन्तु आज तक इस समस्या के बारे में इजराईल और अरब देशों में तनाव बना हुआ है। इसको लेकर उनके बीच 1948, 1956, 1967 तथा 1973 में चार युद्ध हो चुके हैं।

(8) अरब-इजराईल संघर्ष — 1948 में इजराईल के एक स्वतन्त्र देश के रूप में उदय होने के बाद इजराईल और अरब देशों में हमेशा तनावपूर्ण स्थिति रही है। 1948, 1956, 1967 तथा 1973 में चार युद्ध भी हो चुके हैं, लेकिन वही तनावपूर्ण स्थिति जारी है। इजराईल के अड़ियल हल के कारण उसको सं० रा० संघ से बाहर निकाल दिया गया तथा उसको अरब देशों की भूमि वापस करने का महासभा ने आदेश दिया। स्थायी हल न निकलने के बावजूद भी इजराईल के मड़ियल हल के विरोध में विद्व जनमत जाग्रत करने में सं० रा० संघ एक हद तक सफल रहा है।

(9) कोरिया-विवाद (1950-53)—सम्भवतः कोरिया का संकट सं० रा० संघ के शक्ति-सामर्थ्य का सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण था। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वान शूमा ने इसे 'नामूहिक सुरक्षा परीक्षण' की संज्ञा दी है।¹ द्वितीय विश्व युद्ध के अन्तिम दिनों में मित्र-राष्ट्रों में यह तय हुआ था कि जापानी आत्म-समर्पण के बाद सोवियत सेना उत्तरी कोरिया के 38° अक्षांश तक तथा सं० रा० संघ की सेना दक्षिण साइन के दक्षिण भाग की नियंत्राणी करेगी। दोनों शक्तिशाली ने 'अन्तरिम कोरियाई प्रजासत्त्विक सरकार' की स्थापना के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना की। किन्तु 25 जून, 1950 को उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया। इसी दिन सुरक्षा परिषद में सोवियत अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए अमरीका ने अन्य सदस्यों से उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित करवा दिया। सुरक्षा परिषद ने यह बिफारिश की सं० रा० संघ के सदस्य कोरियाई गणराज्य को आवश्यक सहायता प्रदान करें जिससे वह सशस्त्र आक्रमण का मुकाबला कर सके तथा उन क्षेत्र में शान्ति और सुरक्षा स्थापित की जा सके। पहली बार 7 जुलाई, 1950 को अमरीकी जनरल मैकार्थर की कमान में सं० रा० संघ के झण्डे के नीचे संयुक्त कमान का निर्माण किया गया।

लेकिन सोवियत संघ ने बाद में सुरक्षा परिषद की कार्रवाई में भाग लेना थारम्भ कर दिया और कोरिया में सं० रा० संघ की कार्रवाई रोकने के लिए 'वीटो' का प्रयोग कर दिया। इसके परिणामस्वरूप 3 नवम्बर, 1950 को महासभा ने 'शान्ति के लिए एकता प्रस्ताव' पास कर अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा का

उत्तरदायित्व स्वयं से लिया। फलस्वरूप अमरीकी और चीनी सेनाएँ कोरियाई मामले को लेकर उत्तम पड़ी। अतः भारत तथा कुछ अन्य शान्तिप्रिय राष्ट्रों की पहल के कारण 27 जुलाई, 1953 में दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम-सन्धि हुई। इस प्रकार कोरिया युद्ध को स. रा. संधि रोकने में सफल हुआ। वैसे उत्तरी तथा दक्षिणी कोरिया में आपसी तनाव जारी रहा।

(10) वियतनाम विवाद—1954 में जेनेवा में सम्पन्न हुए एक सम्मेलन के अन्तर्गत वियतनाम को उत्तर तथा दक्षिण वियतनाम नामक दो देशों में विभाजित कर दिया गया। किन्तु 1954 में उत्तरी वियतनाम ने टोंकिन की खाड़ी में स्थित अमरीकी विज्वसक पर चौकी हमला बोल दिया। फलस्वरूप उत्तर वियतनाम और अमरीका में झगड़ा हुआ। अमरीका इस मामले को सुरक्षा परिषद में ले गया, किन्तु कोई आसन्नक परिणाम न निकला। हालांकि इस समस्या को 1975 में स. रा. संधि के बाहर ही हल कर लिया गया। फिर भी यह कहा जा सकता है कि स. रा. संधि की मौजूदगी के कारण वियतनाम समस्या को विश्व युद्ध के रूप में बढ़ने से रोका।

(11) मोरक्को, ट्यूनीशिया तथा अल्जीरिया की स्वतन्त्रता का विवाद (1955-62)—द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मोरक्को, ट्यूनीशिया तथा अल्जीरिया तीनों देशों में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के विरुद्ध राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन तेजी से शुरू हुए। इससे दोनों में खून-खराबा होने लगा। फ्रांस ने इन देशों को मुक्त करने में काफी आनाकानी की। स. रा. संधि की महासभा ने अनेक बार दोनों पक्षों से शान्तिपूर्ण तरीके से हल ढूँढ़ने की अपील की। अन्त में विश्व जनमत के इन तीनों देशों की स्वतन्त्रता के पक्ष में होने के कारण फ्रांस को झुकना पड़ा। इस प्रकार 1955 में ट्यूनीशिया, 1956 में मोरक्को तथा 1962 में अल्जीरिया स्वतन्त्र हुए।

(12) स्वेज संकट (1956)—मिस्र के भूतपूर्व राष्ट्रपति बर्नेस नामिक द्वारा आस्वान बांध का राष्ट्रीयकरण कर देने से फ्रांस और ब्रिटेन ने इसका विरोध किया। इसका कारण यह था कि स्वेज नहर बम्पनी के अधिकांश हिस्से इन दोनों देशों के स्वामित्व में थे, उनकी संपत्ति को जप्त कर लिया गया था। फ्रांस और ब्रिटेन इस विवाद की सुरक्षा परिषद में ले गये, लेकिन मोक्षियत 'वीटो' के कारण कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। इसमें बृद्ध होकर 29 अक्टूबर, 1956 को ब्रिटेन, फ्रांस, और इजरायल ने मिस्र पर हमला बोल दिया। 12 नवम्बर, 1956 को महासभा ने 'तत्काल युद्ध विराम करने और सेनाओं की वापसी' से सम्बन्धित प्रस्ताव पारित कर फ्रांस, ब्रिटेन व इजरायल द्वारा आक्रमण करने की निन्दा की। अन्त महासभा के प्रयासों से 6 दिसम्बर 1956 को युद्ध विराम हो गया। 22 दिसम्बर, 1956 तक फ्रांस एवं ब्रिटेन ने मिस्र में अपनी सेनाएँ हटा लीं, हालांकि इजरायल ने गाजा पट्टी को अपने नियन्त्रण में ही रखा। भविष्य में युद्ध न होने देने के लिए स. रा. संधि द्वारा एक संकटकारीन सेना (UNEF) का निर्माण कर उसे युद्ध विराम रेखा की सुरक्षा के लिए वहाँ नियुक्त किया गया। इस प्रकार स. रा. संधि ने स्वेज विवाद का बड़े युद्ध के खतरे में टाक दिया।

(13) हंगरी भूकट (1956)—द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हंगरी के मोक्षियत संधि द्वारा प्रवर्तित वारसा सैनिक संगठन में शामिल हो जाने से वहाँ रूसी प्रभाव क्षेत्र कायम हो गया था। 23 अक्टूबर, 1956 को तत्कालीन मार्क्सवादी सरकार के

खिलाफ जन-विद्रोह हुआ जिसके फलस्वरूप 1 नवम्बर, 1956 को इन्ने नेगी की अध्यक्षता में एक संयुक्त सरकार की स्थापना की गयी। किन्तु रूसी समर्थक जानोस कादार ने नेगी सरकार के विरुद्ध एक समानान्तर सरकार की स्थापना कर विद्रोह दबाने के लिए सोवियत संघ से मदद मांगी। 4 नवम्बर, 1956 को वारसा सन्धि के अन्तर्गत सुविधाओं का उपयोग करते हुए रूसी सेनाओं ने हंगरी में प्रवेश कर दिया। इन्ने नेगी ने सुरक्षा परिषद से रक्षा की मांग की, किन्तु रूसी 'वीटो' के कारण कोई कदम नहीं उठाया जा सका। अफ्रीका ने अपने मित्र राष्ट्रों की मदद से महाममा के विशेष अधिवेशन में रूसी हस्तक्षेप की निन्दा का प्रस्ताव पारित करवाया तथा मांग की कि सोवियत मध्य हस्तक्षेप बन्द करके मानव अधिकारों की स्थापना करे। हंगरी विवाद में सं० रा० संघ की उक्त भूमिका से स्पष्ट है कि सोवियत 'वीटो' के कारण हंगरी हस्तक्षेप का शिकार हुआ। साथ ही महाममा भी कोई विशेष प्रभावशाली कदम नहीं उठा सकी।

(14) कागो संकट (1960-63)—30 जून, 1960 को कागो का बेल्जियम के औपनिवेशिक दामन से मुक्त होकर एक नये राष्ट्र के रूप में उदय हुआ। परन्तु स्वतन्त्रता के पश्चात् कटंगा नामक प्रान्त के राष्ट्रपति गोम्बे ने 11 जुलाई, 1960 को केन्द्रीय सरकार ने सम्बन्ध तोड़ दिया। इस विघटन से दुखी कागो की केन्द्रीय सरकार ने इस प्रश्न को सुरक्षा परिषद में रखा। सुरक्षा परिषद से आदेश प्राप्त कर महाममिब हेमरशोल्ड ने कागो के लिए सं० रा० संघ की कार्रवाई को संगठित किया। अफ्रीका के लिए एशिया और अफ्रीका के प्रतिनिधियों ने एक आयोग की स्थापना भी कर दी। 1962-63 में सं० रा० संघ की सेनाओं ने कटंगा में प्रवेश कर जब अनेक महत्वपूर्ण नगरों को अपने कब्जे में ले लिया तो हारकर गोम्बे ने केन्द्रीय सरकार से पुनः सम्बन्ध स्थापित करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार सं० रा० संघ ने कागो को विघटित होने से बचा लिया।

(15) यमन-विवाद (1962)—1962 में यमन में सैनिक क्रांति हुई। नई सरकार मित्र और सोवियत समर्थक थी। क्रांति होने के बाद पड़ोसी देश यमन में हस्तक्षेप करने लगे। 1962 के पहले तीन महीनों में इस प्रदेश में उग्र युद्ध चलने के कारण स्थिति अत्यन्त विवकट और गम्भीर हो गयी। इस विस्फोटक स्थिति को रोकने के लिए सं० रा० संघ ने रास्क ध्रुव के तथ्यों की जांच करने के लिए भेजा। सं० रा० संघ के प्रयत्नों से बाहरी शक्तियों ने यमन में हस्तक्षेप करना छोड़ दिया तथा शान्ति कायम हो गयी। इस विवाद को सुलझाने में सं० रा० संघ की भूमिका अत्यन्त सहाय्य रही।

(16) पश्चिमी दूरियन की समस्या (1962)—पश्चिमी दूरियन दक्षिण पूर्व एशिया के इण्डोनेशिया द्वीप समूह में है। 1962 में पश्चिमी दूरियन के इण्डोनेशिया में चिनय को लेकर इण्डोनेशिया और नीदरलैंड (हॉलैण्ड) में मतभेद उठे। इस मतभेद ने युद्ध स्थिति पैदा कर दी। अबस्त 1962 में सं० रा० संघ की पहल से दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया गया। समझौते के अन्तर्गत 1 मई, 1962 को हॉलैण्ड ने पश्चिमी दूरियन इण्डोनेशिया को सौंप दिया। इस प्रकार सं० रा० संघ ने उक्त विवाद को हल कर दिया।

(17) क्यूबा विवाद (1962)—अक्टूबर, 1962 में क्यूबा में एक अत्यन्त विवकट अन्तर्राष्ट्रीय संकट उत्पन्न हो गया। हुआ यह कि फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में

क्यूबा में साम्यवादी सरकार स्थापित होने के बाद सोवियत संघ ने वहाँ परमाणु प्रक्षेपास्त्रों का जमाव करना शुरू कर दिया। अमरीका ने इसको अपने तथा अपने मित्र देशों के विरुद्ध कदम माना। अमरीकी राष्ट्रपति केनेडी ने 22 अक्टूबर 1962 को क्यूबा की नौसैनिक नाकेबन्दी कर दी, ताकि सोवियत नौसैनिक युद्धपोत क्यूबा न पहुँच सकें। इससे अमरीका तथा सोवियत संघ में बड़े युद्ध के भड़कने की स्थिति पैदा होने की आशंका प्रतीत होने लगी। स० रा० संघ के तत्कालीन महामन्त्रि ऊयात ने पहल कर इस संकट को सुलझाने में प्रयत्नशील भूमिका अदा की। दोनों पक्षों में समझौता हुआ, जिसके अनुसार सोवियत संघ द्वारा क्यूबा से अपने प्रक्षेपास्त्र हटाने तथा अमरीका द्वारा नौसैनिक नाकेबन्दी समाप्त करना तय हुआ। इस प्रकार स० रा० संघ ने एक बहुत बड़े अन्तर्राष्ट्रीय संकट को युद्ध के रूप में भड़कने से टाल दिया।

(18) साइप्रस संकट (1963-64)—16 अगस्त, 1960 को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से मुक्त होकर साइप्रस का एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में उदय हुआ। इस देश में यूनानी और तुर्की जाति के लोग हैं किन्तु यूनानी बहुसंख्या में हैं और तुर्की अल्पसंख्यक हैं। मिनम्बर, 1963 में यूनानी और तुर्की लोगों के बीच साम्प्रदायिक दंगों के भड़कने से इस विवाद को 1964 में सुरक्षा परिषद में ले जाया गया। स० रा० संघ ने अपनी सेना भेजकर वहाँ शांति स्थापित करवायी। फिर भी दोनों सम्प्रदायों के बीच तनावपूर्ण सम्बन्ध कायम रहे। 15 जुलाई, 1974 में साइप्रस के राष्ट्रपति मकारिओस को यूनानी पक्षधर से हटाने तथा उसके जवाब में साइप्रस पर तुर्की का आक्रमण हुआ। 30 जुलाई, 1974 को वहाँ स० रा० संघ के जरिये युद्ध विराम हो गया। उसके बाद राष्ट्रपति मकारिओस पुनः साइप्रस लौट आये और अपना पद सम्भाल लिया।

(19) ओमिनिजन गणराज्य विवाद (1965-66)—वेस्ट इन्डीज के इस छोटे से टापू में 25 अगस्त, 1965 को अचानक ही बृहत् युद्ध भड़क उठा। विद्रोहियों ने अमरीका समर्थित सरकार को हटाने का शासन पर कब्जा जमाने के लिए युद्ध शुरू कर दिया। अमरीकी नागरिकों की रक्षा के बहाने अमरीका ने 14 हजार सैनिक इस टापू पर भेज दिये। 1 मई, 1965 को सोवियत संघ ने सुरक्षा परिषद की बैठक में यह प्रस्ताव रखा कि अमरीका ने ओमिनिजन गणराज्य के आन्तरिक मामलों में जो हस्तक्षेप किया है उस पर विचार किया जाये। स० रा० संघ ने अपना एक मिशन वहाँ स्थापित किया तथा जब चुनाव के परिणाम नई सरकार स्थापित हो गयी तब इस मिशन को 1966 में वापस बुला लिया गया। इस प्रकार स० रा० संघ ने मराठीय दंग में कार्य किया।

(20) चेकोस्लोवाकिया विवाद—21 अगस्त, 1968 को बिना किसी सूचना के सोवियत संघ तथा उसके द्वारा प्रवर्तित वाग्यवा मन्त्रि के मित्र देशों की सेनाओं ने चेकोस्लोवाकिया में प्रवेश कर दिया। रूस ने यह तर्क दिया कि प्रतिक्रियावादी ताकतों द्वारा चेकोस्लोवाकिया में साम्यवादी सरकार को उलटने के कारण वहाँ साम्यवादी नहीं रहें। तब उसने नेत्रों के सहित के लिए नेत्रों के नेत्रों का निवेदन किया था। 22 अगस्त, 1968 को सुरक्षा परिषद की विशेष बैठक बुलाकर उसमें यह मामला रखा गया। इसमें अमरीका, फ्रांस और ब्रिटेन ने एक प्रस्ताव रखा, जिसमें सोवियत सैनिक हस्तक्षेप की निन्दा की गयी तथा संघ का सुरक्षा हटाने के लिए कहा

गया। सोवियत संघ ने इस पर 'वीटो' का इस्तेमाल कर इस प्रस्ताव को व्यर्थ कर दिया। बाद में 27 अगस्त को रूस एवं चेकोस्लोवाकिया की सरकारों ने एक समझौता हुआ, जिसके अन्तर्गत यह तय हुआ कि चेकोस्लोवाकिया का मौजूदा नेतृत्व मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धान्तों के अनुसार शासन करेगा तथा पश्चिमी जर्मनी और आस्ट्रिया की सीमाओं के अलावा चेकोस्लोवाकिया के सभी जगहों से सोवियत एवं वारसा सेनाएँ हट जायेंगी। इस प्रकार चेकोस्लोवाकिया विवाद में सं० रा० तथे निष्क्रिय साबित हुआ।

(21) दक्षिण अफ्रीका तथा रोडेशिया विवाद—दक्षिण अफ्रीका तथा रोडेशिया में बहुसंख्यक कालो पर अल्पसंख्यक गोरो का शासन रहा है। गोरी सरकार कालो के प्रति अत्यायपूर्ण व्यवहार कर रही है। इन सब बातों के विरुद्ध हीनरी दुनिया के राष्ट्रों ने एकजुट होकर आवाज उठाई, जिससे सं० रा० संघ महासभा में दक्षिण अफ्रीका तथा रोडेशिया में गोरी सरकार के अत्यायपूर्ण व्यवहार के विरुद्ध अनेक प्रस्ताव पारित किये गये। इसके परिणामस्वरूप उक्त दोनों देशों की अल्पसंख्यक गोरी सरकारें अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में अचिन्ती पड़ गयीं। परिणामस्वरूप, रोडेशिया (अब जिम्बाब्वे) में अखेर सरकार स्थापित हो गयी। दक्षिण अफ्रीका में गोरी सरकार के प्रति सं० रा० संघ में विरोध जारी रहा।

सं० रा० संघ के सामाजिक व आर्थिक कार्य (Social and Economic Activities of the U. N.)

सं० रा० संघ की स्थापना केवल अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा के राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही नहीं की गयी, बल्कि अनेक गैर राजनीतिक कार्य आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, विज्ञान, टेक्नोलॉजी आदि के क्षेत्रों में सहयोग का वातावरण निर्माण करने हेतु की गई थी। चार्टर के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सं० रा० संघ का उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय प्रकरणों में अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सं० रा० संघ की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, परिषद के आयोग तथा विशिष्ट अभिकरण, ट्रस्टीशिप परिषद तथा सचिवालय मदद करते हैं। यहाँ सुविधा के तौर पर सं० रा० संघ की गतिविधियों को सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित कर अध्ययन करना उचित होगा।

सं० रा० संघ की सामाजिक उपस्थितियाँ—सामाजिक क्षेत्र में सं० रा० संघ के अनेक विशिष्ट अभिकरण एवं सहायक संस्थाएँ सक्रिय हैं। मसलन, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्व स्वास्थ्य संगठन; युद्ध के विनाश से पीड़ित बच्चों की सहायता (भोजन, कपड़ा, चिकित्सा आदि) करने में 'युनीसेफ'; शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्रों में युनेस्को; मानवाधिकार-रक्षा के क्षेत्र में महासभा द्वारा पारित घोषणा-पत्र आदि प्रमुख हैं। सं० रा० संघ ने महिलाओं के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के लिए भी अनेक मराहनीय कार्य किये हैं। जातिभेद, रंगभेद आदि बुराइयों के उन्मूलन के लिए भी उसने अनेक ठोस कदम उठाये हैं।

आर्थिक उपस्थितियाँ—आर्थिक क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने अनेक समस्याएँ हमेशा झूँझ बाधें पड़ी रही हैं। संसार के दो-तिहाई देश अल्पविकसित हैं

जिनमें लोगों का जीवन-स्तर अत्यन्त गरीब है तथा व्यापक बेरोजगारी है। ये देश आर्थिक विकास की दौड़ में विकसित देशों से बहुत पीछे हैं। दुन्ही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए स. २० स. २० स. २० अन्तर्राष्ट्रीय समाज की आर्थिक हातहत मुधारणों की आवश्यकता महसूस की। इस क्षेत्र में भी वह अपने अनेक विविष्ट अभिकरणों तथा सहायक समस्याओं के जरिये सक्रिय रहा है। ममलन, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय विकास परिषद, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन, 'अकटाइ' सम्मेलन, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि प्रमुख रूप में उल्लेखनीय हैं।¹

स. २० स. २० के विविष्ट अभिकरण—यद्यपि स. २० स. २० स. २० का मुख्य उद्देश्य विश्व शांति एवं सुरक्षा स्थापित करना है, तथापि अन्य क्षेत्रों में भी राष्ट्रों के आपसी सहयोग द्वारा उन उद्देश्यों की प्राप्ति को सुगम बनाने के लिए विविष्ट अभिकरणों की व्यवस्था की गयी है। पापर एवं परकिम्स ने मही ही लिखा है कि स. २० स. २० स. २० के 'विविष्ट अभिकरण' का सम्बन्ध मानवता की सभी मूलभूत आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं से है जिस कारण अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने तथा विश्व के लोगों के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।² स. २० स. २० स. २० के विविष्ट अभिकरणों को मोटे तौर पर चार भागों में बाँटा जा सकता है। इन विभाजित चार भागों को निम्नांकित शर्तों से प्रस्तुत किया जा सकता है। स. २० स. २० स. २० के विविष्ट अभिकरणों के मूल्य तथा कार्यों के बारे में विविष्ट विवरण अप्रापित तांत्रिका में दिया गया है।

तकनीकी मामलों में सक्रिय अभिकरण

(1) अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (International Civil Aviation Organization)—इसकी स्थापना एक सम्मेलन (convention) द्वारा हुई, जो मिकामी में दिसम्बर, 1944 में अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डानों की सुरक्षित और व्यवस्थित बनाई करने के लिए की गयी। इसका मुख्य कार्य विश्व में हवाई यातायात की स्वतन्त्रता की रक्षा करना व उसका सम्बन्ध में उन्नत जगहों को निपटाना है। इसका मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल नगर में है।

(2) विश्व मौसम विज्ञान सम्बंधी संगठन (World Meteorological Organization)—इसकी स्थापना 1947 में हुई, किन्तु इसने 1950 में विधिवत् अपना कार्य प्रारम्भ किया। इसका प्रमुख कार्य मौसम की सूचना और अपने परीक्षणों के आधार पर मौसमिकीय अंकितों का विवरण और अंतरिक्ष के मन्दर्भ में उपलब्ध सूचनाएँ देना है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैण्ड के मायो शहर में है।

(3) अन्तर्राष्ट्रीय नौपरिषद सलाहकार संगठन (Inter-Governmental Maritime Consultative Organization)—उक्त सलाहकार संगठन प्रमुख रूप से वाणिज्य-सम्बंधी नौपरिषद में सम्बन्धित है। इस समस्या का उद्देश्य उन तकनीकी प्रश्नों पर सदस्यों को सुविधा देना है जिसमें नौपरिषद प्रभावित होता है।

¹ रिचार्ड रिचर्ड्स के लिए देखें : *Living Labs. & Humanities, The United Nations and the Third World East West Conflict in Focus*, in Robert W. Greer and Michael Barkin, *Ibid.*, 350-67.

² पापर एवं परकिम्स की बुद्धि वृत्त में पृ. 360

सं० रा० संघ के विशिष्ट अभिकरण
(Specialised Agencies of the U.N.)

1. तकनीकी मामलों में सक्रिय अभिकरण

- (i) अन्तर्राष्ट्रीय नाविक उद्भव्य समन्वय (I. C. A. O.)
- (ii) विश्व श्रुतु विज्ञान समन्वय (W. M. O.)
- (iii) अन्तर्राष्ट्रीय सामुदायिक सहायकार समन्वय (I. M. C. O.)
- (iv) विश्व डाक संघ (U. P. U.)
- (v) अन्तर्राष्ट्रीय दूर-संचार संघ (I. T. U.)

3. अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय समस्याओं विशेषकर आर्थिक विकास में सक्रिय अभिकरण

- (i) अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (I. B. R. D.)
- (ii) अन्तर्राष्ट्रीय विकास परिषद (I. D. C.)

2. सामाजिक व मानवीय गतिविधियों में सक्रिय अभिकरण

- (i) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम समन्वय (I. L. O.)
- (ii) सं० रा० संघ शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक समन्वय (UNESCO)
- (iii) विश्व स्वास्थ्य समन्वय (W. H. O.)

4. विस्तृत रूप से आर्थिक समस्याओं से सम्बद्ध अभिकरण

- (i) खाद्य एवं कृषि समन्वय (F. A. O.)
- (ii) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार समन्वय (I. T. O.)
- (iii) अन्य सभी अभिकरण इस बीजे भाग में आते हैं।

(4) **सार्वजनिक डाक संघ (Universal Postal Union)**—सार्वजनिक डाक संघ की स्थापना जुलाई, 1875 में हुई। सं० रा० संघ की स्थापना के बाद उसने इसे अपने तत्वावधान में ले लिया। सं० रा० संघ के विशिष्ट अभिकरण के रूप में जुलाई, 1952 में इसके लिए एक सविधान का निर्माण किया गया। सार्वजनिक डाक संघ का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय डाक सेवाओं में सुधार लाना तथा विभिन्न प्रकार की डाक सेवाओं की दरें तय करना है। इसका कार्य-संचालन विश्व डाक महासभा द्वारा निर्वाचित 20 सदस्यों की एक कार्यकारिणी समिति करती है। सार्वजनिक डाक संघ का कार्यालय स्विट्जरलैण्ड के बर्न नगर में है। यहाँ विशेष रूप से यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि इसके द्वारा विकासशील देशों के अनेक डाक अधिकारियों को विकसित राष्ट्रों में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया और कई देशों की डाक सेवाओं के पुनर्गठन में मदद हुई।

(5) **अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ (International Telecommunication Union)**—अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ की 1865 में स्थापना हुई। सं० रा० संघ ने 1951 में इसे अपने तत्वावधान में ले लिया। इसका प्रमुख उद्देश्य विश्व में संचार की सुनियोजित रूप से सेवा प्रदान करना है। वह तार, टेलीफोन तथा रेडियो की सेवाओं के उत्तरोत्तर प्रसार, विकास और सर्वसाधारण को न्यूनतम दर पर इनकी सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय नियम आदि बनाती है।

सामाजिक तथा मानवीय गतिविधियों में सक्रिय अभिकरण

(1) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organization)—सोवो को सामाजिक न्याय प्रदान करना विश्व-शान्ति को मजबूत बनाने के दृष्टिकोण से अत्यन्त आवश्यक है। इसी बात को महसूस करते हुए अप्रैल 1919 में इसकी स्थापना की गयी तथा राष्ट्र सघ के तत्वावधान में इसको ले लिया गया। 1946 में यह स० रा० सघ का पहला विनिष्ट अभिकरण बना। वर्तमान में 135 राष्ट्रों से भी ज्यादा इसके सदस्य हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का प्रमुख उद्देश्य विश्व के मजदूरों की दशा सुधारना है। इसके लिए यह विभिन्न प्रकार के श्रमिक समझौतों तथा संधियों के प्रावधान तैयार करता है। यह अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, अधिशासी निवाय तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय नामक अंगों के जरिये अपने कार्य सम्पादित करता है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की महामभा कहा जा सकता है। इसकी बैठकों में हरेक सदस्य राष्ट्र से दो सरकारी, एक मातृकी तथा एक मजदूरों का प्रतिनिधि सम्मिलित होता है। यह अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का वार्षिक बजट भी पार करता है। अधिशासी निवाय को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की कार्यकारिणी परिषद कहा जा सकता है। इसमें 48 सदस्य होते हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा तीन वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ये सदस्य ही महानिदेशक (डायरेक्टर जनरल) को नियुक्त करते हैं। अधिशासी निवाय ही श्रम सम्मेलन के कार्यक्रमों की तैयार करती है और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय (सचिवालय) के कार्य की देखरेख करती है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सचिवालय कहा जा सकता है। यह स्विट्जरलैण्ड के जिनेवा नगर में है। यह संगठन को विविध प्रकार की सेवाएँ प्रदान करना है तथा इसकी गतिविधियों में तालमेल बिटाना है।

(2) स० रा० सघ शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO)—युनेस्को 4 नवम्बर, 1946 को अस्तित्व में आया। इसका सचिवालय पहले पेरिस ब्रिटेन और फ्रांस की सरकारों द्वारा तैयार किया गया जिसकी बाद में स० रा० सघ के 43 सदस्यों ने अपनाया। 14 दिसम्बर, 1946 को एक समझौते द्वारा युनेस्को को स० रा० सघ के एक विनिष्ट अभिकरण के रूप में मान्यता मिली।

'युनेस्को' की संरचना—युनेस्को के तीन अंग हैं—महामभा सम्मेलन, अधिशासी मण्डल और सचिवालय। महामभा सम्मेलन की प्रति 2 वर्षों में एक बैठक होती है। इसमें प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का एक प्रतिनिधि होता है। यह इसका बजट और कार्यक्रम तय करती है। अधिशासी मण्डल का निर्वाचन महामभा सम्मेलन द्वारा होता है। इसमें 25 सदस्य होते हैं तथा एक देश का एक से अधिक प्रतिनिधि नहीं लिया जाता। युनेस्को का सचिवालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। इसके महानिदेशक की नियुक्ति अधिशासी मण्डल द्वारा की जाती है।

युनेस्को का उद्देश्य एवं कार्य—'युनेस्को' के नाम में ही स्पष्ट है कि इसका कार्यक्षेत्र शिक्षा, विज्ञान तथा सांस्कृतिक जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसके कार्यों को मुख्यतया तीन बिन्दुओं के अन्तर्गत रखा जा सकता है। (i) शिक्षा, (ii) प्राकृतिक विज्ञान, तथा (iii) सामाजिक एवं मानवीय विज्ञान तथा संस्कृति।

शिक्षा के क्षेत्र में 'युनेस्को' शिक्षा का विस्तार, शिक्षा की उन्नति तथा विश्व समुदाय में रहने की शिक्षा प्रदान करता है। प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्र में 'युनेस्को' प्राकृतिक और सामाजिक ज्ञान में प्रगति के उद्देश्य को पाने के लिए इसके द्वारा वैज्ञानिकों के सम्मेलन, वैज्ञानिक संगठनों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, अनुसन्धान, प्रकाशन आदि की व्यवस्था करना आते हैं। सामाजिक, मानवीय तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में 'युनेस्को' समस्त मानवीय ज्ञान की आवश्यक एकता पर बल देता है। यह निशस्त्रीकरण के आर्थिक एवं सामाजिक परिणामों तथा मातवाधिकार पर भी बल देता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसन्धान, सभा-सम्मेलन, विचार-गोष्ठियाँ तथा साहित्य-प्रकाशन आदि कार्य करता है। सामूहिक ज्ञान के प्रचार के लिए इसके द्वारा फिल्म, प्रेस, रेडियो आदि को प्रयोग में लाया जाता है। तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत युनेस्को अपने विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न देशों को परामर्श देकर लाभ पहुँचाता है। इसके द्वारा विभिन्न देशों के विद्वानों को दूसरे राष्ट्रों में भेजा जाता है जिससे ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रों में आपसी सहयोग स्थापित हो सके।

युनेस्को में संकट—युनेस्को उस समय गहरे संकट में पड़ा गया, जब अमरीका ने एक जनवरी, 1985 और ब्रिटेन ने एक जनवरी, 1986 से इसकी सदस्यता छोड़ दी। यही नहीं, जापान व सिंगापुर ने भी धमकी दी कि यदि युनेस्को में 'आवश्यक सुधार' नहीं किये गये तो वे भी इसकी सदस्यता त्याग देंगे। इससे जहाँ एक ओर युनेस्को के प्रति उदासीनता बढ़ी, वहीं दूसरी तरफ इस संगठन के समक्ष गहरा वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया, क्योंकि अमरीका और ब्रिटेन युनेस्को के बजट में क्रमशः 25 व 5 प्रतिशत योगदान देने से, वह मिलना बन्द हो गया। इससे संगठन के कर्मचारियों और कार्यक्रमों में कटौती करने की मोखत आ गई।

गौनवें और छठे दशक में इस संगठन के सदस्य देशों की संख्या कम थी, जिन कारण पश्चिमी देश प्रायः ऐसे प्रस्ताव और कार्यक्रम मंजूर करवा लेते थे, जिनसे उनके हित पूरा होते थे। विन्तु ज्यों-ज्यों अंतरनिवेशिक शिकंजे में एक के बाद दूसरे देश आजाद होते गये, त्यों-त्यों पश्चिमी देशों की समस्या भी पर अधिक बढ़ता गया। आठवें दशक के दौरान युनेस्को के सदस्यों में विकासशील देशों की संख्या बढ़कर दो-तिहाई हो गई। परिणामस्वरूप ऐसे प्रस्ताव पास हुए, जिनमें पश्चिमी देशों की भेदभावपूर्ण नीतियों की कड़ी आलोचना की गई। दक्षिण-अफ्रीका में अस्लवाद, अरब देशों पर इजराइल के गैर कानूनी कब्जे, नई विश्व समाचार व्यवस्था आदि के बारे में पारित प्रस्तावों में यह आलोचना मुखर हुई। विकासशील देशों के बहुमत के कारण ऐसे कार्यक्रम मंजूर हुए, जिनसे पश्चिम देश सहमत नहीं थे। पश्चिम देश इस बात से चिढ़ने-झोझने लगे कि युनेस्को के लिए वे बड़ी मात्रा में चन्द्रा देते हैं, लेकिन उसके खर्च के मामले में चलती विकासशील देशों की है।

अमरीका और ब्रिटेन का तर्क था कि इस संगठन में गन्दी राजनीति ने जड़ें जमा ली हैं, जिससे उसके कार्यक्रमों का बुनियादी उद्देश्यों के साथ कोई तादात्म्य नहीं रह गया है। युनेस्को पश्चिम विरोध का अखाड़ा बन गया है। युनेस्को में प्रणामनिक अव्यवस्था है और उसके कोप को मनमाने एवं अर्थहीन कार्यक्रम पर खर्च किया जा रहा है।

अमरीका व ब्रिटेन में अनुदान बन्द होने पर यह समस्या उठ खड़ी हुई कि

युनेस्को के किन कार्यक्रमों और कर्मचारियों में कटौती कर गाड़ी को पटरी से उतरने न दी जाय। 1987 में डा० एम० बोव के कार्यकाल की समाप्ति के बाद फेडरल मेयर युनेस्को के नये महानिदेशक चुने गये, किन्तु न तो अमरीका और ब्रिटेन इस सगठन में लौटे और न ही इस सगठन की आर्थिक हालत में उल्लेखनीय सुधार हुआ। युनेस्को का मबिप्य इस बात पर निर्भर करेगा कि इसमें 'अपेक्षित सुधार' कैसे क्रियान्वित होते हैं और महानिदेशक सदस्य देशों का समर्थन एवं विश्वास कितनी क्षमता से हासिल कर कृशल नेतृत्व दे पाता है? अतएव इस सगठन के मबिप्य के बारे में महानिदेशक की भूमिका निर्णायक होगी।

(3) विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization)—विश्व स्वास्थ्य संगठन अधिकारिक तौर पर 7 अप्रैल, 1948 को अस्तित्व में आया। हर वर्ष इस दिन को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के तीन अंग हैं—(i) विश्व स्वास्थ्य सभा, (ii) अधिसासी मण्डल, और (iii) सचिवालय। विश्व स्वास्थ्य सभा में समस्त राष्ट्रों के प्रतिनिधि होते हैं। वर्ष में एक बार इसकी बैठक होती है। यह नीति निर्धारण का कार्य करती है।

अधिसासी मण्डल में 24 सदस्य होते हैं। इसका निर्वाचन विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा किया जाता है। अधिसासी मण्डल अचानक आये प्राकृतिक प्रकोपों में सक्रिय रहता है। सचिवालय का अध्यक्ष महानिदेशक होता है जो विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैण्ड के जिनेवा नगर में है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्य—विश्व स्वास्थ्य संगठन के विभिन्न कार्यों को संभव में निम्नांकित चार बिन्दुओं के अन्तर्गत अवित किया जा सकता है (1) बीमारी की रोकथाम (2) बीमारी का उपचार, (3) सार्वजनिक सेवा में सक्रिय लोगों को प्रशिक्षण, तथा (4) स्वास्थ्य प्रणाली को सुधारने में मदद। विश्व स्वास्थ्य संगठन में अनेक कामियाँ होने के बावजूद भी उसका कार्य काफी अराहनीय रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय समस्याओं विशेषकर आर्थिक विकास में सक्रिय अभिवरण

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (International Bank for Reconstruction and Development)—अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना डिसेम्बर, 1945 में हुई। इसे विश्व बैंक (World Bank WB) का नाम से पुकारा जाता है। वैसे इसने अपना कार्य 1946 में आरम्भ किया। हमारे प्रमुख उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रों को 'विकास' के लिए आर्थिक मदद देना है। युद्ध में नृप्रभावित देशों को पुनर्निर्माण के लिए धन प्रदान करना और अविकसित देशों को विकसित बनाने, उत्पादन बढ़ाने, जीवन-स्तर को ऊँचा करना और विश्व व्यापार में सन्तुलन लाने के लिए यह बैंक सहायता देता है।

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के चार अंग हैं—(अ) गवर्नर्स का बोर्ड, (ब) कार्यपालिका निदेशक, (स) अध्यक्ष, और (द) अधिकारी तथा कर्मचारी बग। इस बैंक ने विश्व के अनेक जबरनमन्द राष्ट्रों को उनका आर्थिक विकास के लिए अनेक प्रकार की सहायता प्रदान की है। प्रो० जेम्स व एण्डरसन का मानना है कि 'यह बैंक सिर्फ अगुवा आर्थिक के रूप में ही काम नहीं करना बल्कि एक तेज

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिभा पूंज के रूप में सक्रिय रहता है, जो पुनर्निर्माण के लिए मूल्यवान् व विकास सम्बन्धी रचनाएँ तैयार करता है।¹ इस बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन (अमरीका) में है। ज़्यूरिख, लन्दन और पेरिस में भी इसके कार्यालय हैं।

विशुद्ध रूप से आर्थिक समस्याओं से सम्बद्ध अभिकारण

1 **खाद्य एवं कृषि संगठन (Food and Agricultural Organization : FAO)**—खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर, 1945 को हुई। इसके प्रमुख उद्देश्य विद्वत् के विभिन्न राष्ट्रों की आम जनता के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना, उसे पोष्टिक आहार उपलब्ध कराना, उत्पादन क्षमता बढ़ाना, गाँवों की स्थिति सुधारना आदि हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु यह विश्व की विभिन्न सरकारों को साक्षात्तो तथा अन्य फर्मों के अधिक उत्पादन, नाशी बीमों (Pests) के नियन्त्रण, पौधों एवं पशुओं के रोगों के नियन्त्रण, भण्डारों-गोदामों के खाद्यान्नों की सुरक्षा करने, कृषि, मछली तथा जंगलों से अधिक पैदावार करने के समय में तकनीकी सहायता देना है। यह भू-संरक्षण (Soil Conservation), सिंचाई के साधनों में विकास तथा बंजर भूमि की कृषि-योग्य बनाने में इनको परामर्श देता है।

खाद्य एवं कृषि संगठन के तीन प्रमुख अंग हैं—(अ) महासम्मेलन, (ब) कार्य-कारिणी परिषद्, और (स) सचिवालय। महासम्मेलन महासभा के समान है। कार्यकारिणी परिषद् में 24 सदस्य होते हैं जिनका चुनाव महासम्मेलन करता है। सचिवालय संगठन को सेवाएँ प्रदान करता है। इसके प्रधान को महानिदेशक (डायरेक्टर जनरल) कहा जाता है। इसका प्रमुख कार्यालय रोम में है।

(2) **अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष (International Monetary Fund : IMF)**—अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की स्थापना 27 दिसम्बर, 1946 को की गयी। इसका उद्देश्य विद्वत् के विभिन्न देशों में मुद्रा सम्बन्धी सहयोग बढ़ाना, विनिमय में स्थिरता लाना, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सुविधाएँ प्रदान करना, उत्पादन में वृद्धि करना तथा सदस्य राष्ट्रों की आर्थिक सहायता प्रदान करना इत्यादि हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के तीन प्रमुख अंग हैं—(अ) गवर्नर मण्डल (Board of Governors), (ब) अधिनासी निदेशक मण्डल (Board of Executive Directors), और (स) प्रबन्ध निदेशक (Managing Director)। गवर्नर मण्डल संयुक्त पूँजी वाली बम्पनियों की महासभा के समान है। यह मुद्रा कोष की नीति निर्धारित करता है। अधिनासी निदेशक मण्डल कोष की कार्यकारिणी परिषद् है। इसमें कुल 20 सदस्य होते हैं जिनमें 5 सदस्यों की नियुक्ति वे देश करते हैं जिनके सबसे अधिक अर्थशास्त्र होते हैं तथा शेष 15 सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्रीय आधार पर गवर्नर मण्डल द्वारा किया जाता है। यह कोष के नियमित कार्य संचालन के लिए उत्तरदायी होता है। प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति अधिनासी निदेशक मण्डल करता है। निदेशक, अधिनासी निदेशक मण्डल की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा कोष के दैनिक कार्य-संचालन के लिए उत्तरदायी होता है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष का मुख्यालय अमरीका की राजधानी वाशिंगटन में है।

¹ This Bank functions not only as a leader and guarantor but also as an international brain-trust for the evaluation and guidance of reconstruction and development strategy.—P. E. Jacob and A. L. Atherton, *The Dynamics of International Organization*, (Dorsey Press, 1965), 38.

(3) स० रा० सघ अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (U. N. International Children's Emergency Fund . UNICEF)—स० रा० सघ अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष की स्थापना महासभा द्वारा 1946 में की गयी। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य पोषण इत्यादि कार्यों के माध्यम से बच्चों के कल्याण में सहयोग देना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बच्चों के स्वास्थ्य सुधार, पौष्टिक आहार, शिक्षा व्यवस्था तथा अन्य अनेक कार्यक्रम सम्पादित किये जाते हैं। इसके अलावा भूकम्प, बाढ़ आदि दैवी प्रकोपों के समय भी यह कोष शिशुओं और उनकी माताओं की सहायता करता है। यूनिसेफ की सर्वत्र सराहना की गयी है। प्रोफेसर जेवक और एथेस्टन ने इसी बात को अभिव्यक्त करते हुए लिखा है कि 'मनक नियोजन, पक्षपात रहित प्रदान, उच्च कोटि की विषादतशारी और कौशल, इस सबसे पहले मानवीय कार्यों के प्रति अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व के कारण यूनिसेफ ने यह बात प्रमाणित की है कि एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था मानवीय सभ्यता को दूर करने और राहण कार्यों में मार्गक भूमिका निभा सकती है।'²

स० राष्ट्र सघ एवं मानव अधिकार (U N and Human Rights)

क्लार्क एम० आइसेलवर्जर का मानना है कि 'राष्ट्र स्थायी शान्ति की ओर अपसर होते हैं तो यह भी अपरिहार्य है कि मानव अधिकारों की भी प्रगति होगी तथा वे सरक्षित होंगे।' इस प्रकार अधिकार मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। इसी आवश्यकता को महसूस करते हुए स० रा० सघ जैम अन्तर्राष्ट्रीय सगठन की स्थापना के वक्त इससे बारे में पर्याप्त विचार किया गया। स० रा० सघ को मानव अधिकारों के प्रति सभी देशों में सम्मान बढ़ाने तथा प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी। चार्टर के प्रस्तावना के अलावा अनुच्छेद 1, 13, 55, 62, 68 तथा 76 में स० रा० सघ के इस सम्बन्ध में कर्तव्यों पर बल दिया गया है। हानाजि चार्टर में स० रा० सघ को मानव अधिकार की सम्मान दिवाने तथा प्रोत्साहित करने की बात कही गयी है किन्तु इसमें अधिकारों की सूची नहीं दी गयी है। यह काम मानव अधिकार आयोग (The Commission on Human Rights) द्वारा किया गया। इसने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा तैयार की जिम्मे को महासभा ने पारित किया।

मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा

10 दिसम्बर, 1948 को महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को स्वीकार किया जिसके अन्तर्गत इतिहास में पहली बार मानव अधिकारों की रक्षा और परिपालन की जिम्मेदारी अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने अपने ऊपर ले ली और यह उसका एक स्थायी कर्तव्य स्वीकार किया गया।

इस सार्वभौम घोषणा की तीन धारणाएँ हैं जिनमें नागरिक और राजनीतिक

² By its careful planning, scrupulous non partisan administration, high operating efficiency and economy, and above all, the over riding sense of international responsibility for a humanitarian purpose that permeated the organization, UNICEF, vindicated the role of international organization as agent for the relief of human need and misery

अधिकारों के साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार भी शामिल हैं।

पहली और दूसरी धारा सामान्य है। इनमें कहा गया है कि सब मनुष्य जन्म से स्वतन्त्र हैं और सबकी प्रतिष्ठा तथा अधिकार समान हैं, और उन्हें घोषणा में निहित सारे अधिकार और उनकी स्वतन्त्रताएँ, जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य विचार, राष्ट्रीय अथवा सामाजिक उद्गम, सम्पत्ति, जन्म या अन्य स्थिति के आधार पर बिना भेदभाव किये पाने का अधिकार है।

घोषणा की धारा 3 से 21 तक में नागरिक व राजनीतिक अधिकार माने गये हैं। इनमें मनुष्य का जीवन, स्वाधीनता और सुरक्षा का अधिकार, गुलामी व मधीनता से मुक्ति, सताने या अपमानपूर्ण व्यवहार या दण्ड से मुक्ति, कानून से समान संरक्षण पाना, अदालत में जाने का अधिकार, मनमाने ढंग से गिरफ्तारी, नजरबन्दी या निर्वासन से मुक्ति, स्वतन्त्र व निष्पक्ष अदालत के सम्मुख ठीक ढंग से मुकदमा पैदा होने, और उसमें सुनवाई पाने के अधिकार, परिवार, घर या पत्र-व्यवहार तथा अपने बारे में गोपनीयता, मनमाने ढंग से हस्तक्षेप न होने देना, आने-जाने में स्वतन्त्रता, शरण लेने का अधिकार, नागरिकता का अधिकार, विवाह करने व परिवार बनाने का अधिकार, सम्पत्ति पर भातिकाना अधिकार, विचार, अन्तःकरण व धर्म की स्वतन्त्रता, सम्पत्ति रखने व उसे खर्च करने की स्वतन्त्रता, एकत्र होने का अधिकार, शासन में भाग लेने का अधिकार तथा सार्वजनिक सेवाओं में समान रूप से प्रवेश शामिल है।

22 से 27 तक की धाराओं में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार शामिल हैं, जैसे सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, काम का अधिकार व आराम और छुट्टी समय बिताने या अच्छी तरह रहने व स्वास्थ्य के लिए आवश्यक जीवन-स्तर बिताने का, शिक्षा का और अपने समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है।

28 से 30 तक की अन्तिम धाराओं में इस बात को स्वीकार किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी सामाजिक अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था पाने का अधिकार है जिसके अन्तर्गत इन अधिकारों व स्वतन्त्रताओं को पूरी तरह माना जाये। इनमें समाज के प्रति व्यक्ति की जिम्मेदारी और कर्तव्यों पर जोर दिया गया है।

महासभा ने (सब लोगों और देशों द्वारा समान स्तर पाने के लिए) मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र निकाला और अपने सब सदस्य देशों और लोगों से इस घोषणा-पत्र में निहित अधिकारों व स्वतन्त्रताओं का पूरा पालन और स्वीकृति के लिए प्रयत्न करने को कहा। महासभा द्वारा 1950 में इस प्रस्ताव को स्वीकृत करने के बाद से सारे संसार में हर साल 10 दिसम्बर को 'मानव अधिकार दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

इस घोषणा-पत्र में निहित अधिकारों की अब दो प्रतिज्ञा-पत्रों में शामिल कर दिया गया है। इसमें से पहला नागरिक व राजनीतिक अधिकारों और दूसरा आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों के विषय में है। इनको महासभा ने 1966 में सर्वसम्मति से पारित किया। जिन सरकारों ने इसकी छुट्टि की, वहाँ इन प्रतिज्ञा-पत्रों को कानूनी स्थिति बना जायगा। नागरिक व राजनीतिक अधिकारों के विषय में प्रतिज्ञा-पत्र के संकल्पित गिफ्टाचार वा मतलब उसे लागू करना है।

दिसम्बर, 1965 में महासभा ने एक प्रस्ताव पारित करके अन्तर्राष्ट्रीय

प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर कराने शुरू किए, जिसमें सभी प्रकार के जातीय भेदभाव को समाप्त करने और इस काम के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था बनाने के लिए कहा गया। इस ध्येय को पूरा करने के लिए 18 विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई। यह प्रतिज्ञा-पत्र 4 जनवरी, 1969 को लागू हुआ। उक्त समिति को बैठकें 1970 से होने लगीं।

मानव अधिकारों की घोषणा के स्वीकार होने के 20 वर्ष बाद 1968 को मानव अधिकारों के अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर अप्रैल-मई में तेहरान में मानव अधिकारों के सम्बन्ध में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया और यह 1968 की एक महत्वपूर्ण घटना थी। सम्मेलन में 'तेहरान घोषणा-पत्र' जारी करके मानव अधिकारों को पूरी तरह दिलाने की जिम्मेदारी सम्बद्ध देशों की मानी गई। इसमें उत्पन्न होने वाली विशेष समस्याओं और कठिनाइयों को आँका गया। सभी सरकारों से सभी मनुष्यों के लिए नारीरिक, मानसिक, सामाजिक व आध्यात्मिक कल्याण में सहायक और स्वतन्त्रता से युक्त जीवन की व्यवस्था दिलाने के प्रयत्न पूरे जोर-शोर से करने के लिए कहा गया।

महासभा ने 1971 का वर्ष जातिवाद और जातीय भेदभाव को दूर करने की कार्रवाई का वर्ष कहा है। मानव अधिकार वर्ष मनाने का प्रयोजन जातिवाद और जातीय भेदभाव के सभी चिह्नों व तरीकों को हटाना और मानवीय अधिकारों का आनन्द उठाने में सबको समानता दिलाने की दिशा में ठोस प्रयत्न करना था।

मानव अधिकारों से सम्बन्धित अन्य प्रश्न

महिलाओं की स्थिति में सुधार, बच्चों के अधिकार, भेदभाव को रोकना, सूचना की आजादी जैसे दूसरे मानव अधिकार सम्बन्धी प्रश्नों पर भी ध्यान दिया गया है। स्त्रियों के लिए राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन जुलाई 1954 में हुआ और विवाह की स्वीकृति, विवाह के लिए न्यूनतम आयु और विवाह के पंजीकरण के सम्बन्ध में दिसम्बर, 1964 में सम्मेलन किया गया। 1967 में महासभा ने औरतों के प्रति भेदभाव समाप्त करने के दिपर में एक घोषणा मजूर की।

नवम्बर, 1959 में बच्चों के अधिकार के सम्बन्ध में एक घोषणा-पत्र सर्व-सम्मति से स्वीकृत हुआ, जिसके अनुसार अपना सर्वोत्तम जितना भी हो सहर्य बच्चों को देने के लिए मनुष्यों से कहा गया। इसके अनिर्दिष्ट मानव अधिकार आयोग ने सभी प्रकार की घातक अमहिष्णुता दूर करने के लिए एक प्रतिज्ञा-पत्र तैयार किया।

मानव अधिकारों के सम्बन्ध में अन्य कार्रवाईयों में विशेष शाखाओं के सहयोग में विशेष अध्ययन और तकनीकी सहायता देना शामिल है। मानव अधिकारों के प्रति सम्मान बढ़ाने के लिए मनुक्त राष्ट्र सच के सदस्य देशों को विशेषज्ञों में सलाह दिलाना, क्षमतावृत्ति देना तथा विचार गोष्ठियाँ बुलाना जैसी सेवाएँ उपलब्ध हैं।

मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का महत्व

मनुक्त राष्ट्र सच द्वारा की गयी मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अत्यधिक महत्व है—

(क) मानवाधिकार घोषणा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के इतिहास में एक प्रकार की

पहली मिसाल थी। इससे इस सम्बन्ध में और जाने बहने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

(ख) यह घोषणा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम था। जैसा कि प्रोफेसर आइखेनबर्जर (Eichelberger) का मानना है कि 'वास्तव में राष्ट्रों के कानून के विकास में यह घोषणा विशिष्ट है। हालांकि यह सन्धि के समान बाध्यकारी नहीं है, तथापि इसने ऐसी 'सत्ता' का विकास किया है, जो कानून का खोस ही नहीं, बल्कि कानून की ताकत भी है।'

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यह घोषणा उपयोगी रही है। किसी भी देश द्वारा मांगव अधिकार का उल्लंघन करने पर यह तर्क देकर उसकी आलोचना की जा सकती है कि वह इस घोषणा का उल्लंघन कर रहा है। इससे उस देश के खिलाफ विरोध जनमत तैयार करने में मदद मिलती है।

इस प्रकार सं० रा० संधि एवं उसके अनेक निकाय मानवाधिकार रक्षा के विभिन्न कार्य में सक्रिय है। अतः इस क्षेत्र में इसका कार्य बड़ा ही सराहनीय रहा है।

सं० रा० संधि एवं निशस्त्रीकरण (U. N. and Disarmament)

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई अपार जन व धन की हानि ने दुनिया को यह महसूस करवा दिया कि घातक शस्त्रों पर रोक नहीं लगाई गई तो मानवता को बचाना अत्यन्त कठिन हो जायेगा। सं० रा० संधि के चार्टर में कहा गया है कि संगठन का प्रमुख कार्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा को बनाये रखना है। अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि विश्व के मानवीय तथा आर्थिक साधनों का शस्त्रीकरण की दिशा में तनिक भी प्रयोग न करके विश्व शान्ति का कार्य सम्पन्न किया जायेगा। घोषणा-पत्र के द्वारा महाममा को निशस्त्रीकरण तथा शस्त्रों पर प्रतिबन्ध लगाने का सिद्धान्त निर्धारित करने का अधिकार दिया गया एवं सुरक्षा परिषद को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि यह शस्त्रों के नियमन की प्रणाली स्थिर करने के लिए सं० रा० संधि के सदस्यों के समक्ष योजना प्रस्तुत करे। परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले अमरीका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगरों पर परमाणु बम गिराया। कालान्तर में शीत युद्ध के दौरान शस्त्रीकरण बढ़ता गया। तनाव-दीप्ति का प्रक्रिया कुछ सालों तक चली, मगर पुनः शीत युद्ध का तथा दौर शुरू हो गया। इस प्रकार शस्त्रीकरण से मानव समाज को एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया। अतएव इस परिदृश्य में निशस्त्रीकरण में सं० रा० संधि की भूमिका का मूल्यांकन करना अत्यधिक प्रासंगिक होगा।

निशस्त्रीकरण : सं० रा० संधि के विभिन्न प्रयास

महाममा में 24 जनवरी, 1946 को निशस्त्रीकरण के सम्बन्ध में पहला प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। तब से सं० रा० संधि ने लगातार शस्त्रों की होड़ रोकने तथा उसे धीरे-धीरे समाप्त करने के भरपूर प्रयत्न किये हैं। यह संगठन निशस्त्रीकरण पर विचार-विमर्श और समझौतों का स्वागी मंच रहा है। उसका उद्देश्य है— निशस्त्रीकरण को प्राप्त करना। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा शक्तिशाली देशों को इसके विषय में सिफारिशें करना और इस सम्बन्ध में प्रभावशाली अध्ययन करना (भयान परमाणु ऊर्जा के प्रयोग का प्रभाव, रासायनिक तथा जैविक शस्त्रों के प्रयोग

का प्रभाव और निशस्त्रीकरण के आर्थिक प्रभाव)।

स० रा० सघ ने सबसे पहले परमाणु ऊर्जा आयोग और परम्परागत शस्त्र आयोग गठित किये। 1952 में महामन्त्र ने इन दोनों के स्थान पर सुरक्षा परिषद के नीचे निशस्त्रीकरण आयोग बना दिया और उसे एक या अधिक सभ्या में शामिल किये जान वाले प्रस्ताव का मसौदा तैयार करने का आदेश दिया। सभी प्रकार की सेनाओं और शस्त्रों को नियमित और सीमित करना, उनमें सन्तुलित कमी करना, बड़े पैमाने पर महार करने वाले सभी भीषण शस्त्रों की समाप्ति, अणु शस्त्रों पर पूरी पाबन्दी लगाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु शक्ति पर पूर्ण नियन्त्रण और केवल शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु शक्ति का प्रयोग जैसे विषय आयोग को सौंपे गये।

बाद में निशस्त्रीकरण आयोग की पाँच राष्ट्रों वाली उपसमिति ने बानचीन बचाई। इससे मतभेद अवश्य कम हो गए, परन्तु परमाणु निशस्त्रीकरण की तुलना में परम्परागत निशस्त्रीकरण के अनुपात और उस पर अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण और जाँच जैसे सवालियों पर बड़े राष्ट्रों में मतभेद बने रहे।

20 नवम्बर, 1959 को महामन्त्र ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया कि पूर्ण निशस्त्रीकरण का प्रश्न समार को सबसे बड़ी समस्या है। आशा व्यक्त की कि प्रभावशाली निशस्त्रीकरण की दिशा में अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण के विषय में सहमति होने और इसे लागू करने के लिए शीघ्र कदम उठाए जायेंगे।

1961 की घटनाओं से आशा बँधी कि इस विषय में जल्दी प्रगति होगी। 20 दिसम्बर, 1961 को महामन्त्र ने अपने सर्वसम्मति प्रस्ताव में रूसी और अमरीकी सरकारों द्वारा पूर्ण निशस्त्रीकरण की दिशा में की गई बानचीन के आधार पर स्वीकृत मिझानों वाले मधुन वक्तव्य की मराहना की। साथ ही महामन्त्र ने रूस और अमरीका के उस मुझाव की पुष्टि की, जिसमें 18 देशों की निशस्त्रीकरण समिति बनाने के लिए कहा गया था।

निशस्त्रीकरण समिति

1969 में इस समिति के सदस्यों की मरुया बढ़ाकर 26 कर दी गई और इसका नाम निशस्त्रीकरण समिति सम्मिलन (सी० सी० डी०) रखा गया। यह महामन्त्र की अपने काम की रिपोर्ट देती है। महामन्त्र हर साल उसको कुछ विषय देती है, और उन पर उनकी मिफारिश माँगती है तथा हथियारों की होड सीमित करने व रोकने के सम्बन्ध में मनाह देती है। विभिन्न देशों ने आपसी बानचीन, सी० सी० डी० तथा स० रा० सघ की अन्य मरुयाओं जैसे बाह्य अन्तरिक्ष के शान्तिपूर्ण प्रयोग की समिति तथा मरुडी जन के शान्तिपूर्ण प्रयोग की समिति ने बानचीन करके अनेक मन्थियों को अपनाया।

5 अगस्त, 1963 को रूस, अमरीका और ब्रिटेन के प्रतिनिधियों ने मास्को में एक मन्थि पर हस्ताक्षर किये, जिसमें बायुमण्डल, अन्तरिक्ष व जन में परमाणु शस्त्रों के परीक्षणों पर प्रतिबन्ध लगाया गया। यह मन्थि अगले वर्ष अक्टूबर में लागू हुई। इस पर 100 से अधिक देशों ने हस्ताक्षर किये। 1963 की मन्थि पर हस्ताक्षर होने से पहले महामन्त्र ने अणु-परीक्षण पर गहरी चिन्ता प्रकट की तथा कई प्रस्ताव पारित किये थे। 1963 के बाद महामन्त्र ने परमाणु-अस्त्रों के परीक्षणों पर

प्रतिबन्ध लगाने के लिए मध्य देशों को बड़े पैमाने पर समझौता करने को कहा।

1966 में चन्द्रमा तथा अन्य ग्रहों सहित बाह्य अन्तरिक्ष के उपयोग के सम्बन्ध में देशों की कार्यवाही से सम्बन्धित प्रस्तावों वाली पहली सन्धि हुई। इस सन्धि के अनुसार बाह्य अन्तरिक्ष में राष्ट्रीय प्रभुसत्ता का परमाणु शस्त्रों के लिए उपयोग करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया। 1966 में महासभा ने इस सन्धि की पुष्टि की।

1967 में महासभा ने उस सन्धि का भी स्वागत किया, जिसमें लातीनी अमरीका को परमाणु शस्त्रों से मुक्त क्षेत्र माना गया।

1968 में महासभा ने परमाणु शस्त्रों के परीक्षण पर प्रतिबन्ध लगाने वाली सन्धि की पुष्टि की। इस सन्धि का प्रस्ताव 1965 में महासभा ने रखा था और इसकी स्वीकृति 18 देशों की निरास्त्रीकरण समिति ने काफ़ी लम्बी बहस के बाद बनाई थी। यह सन्धि 5 मार्च, 1970 से लागू हुई। सन्धि के अनुसार परमाणु शक्ति सम्पन्न देशों ने यह वचन दिया कि वे दूसरे देशों को परमाणु अस्त्र नहीं देंगे और जो देश परमाणु आयुध बनाना नहीं जानते थे, उन्होंने वचन दिया कि वे देश न तो दूसरे देशों से परमाणु अस्त्र लेंगे और न इनका निर्माण करेंगे। इस विषय में सुरक्षा परिषद ने अपनी तथा विशेष रूप से परमाणु हथियारों से लैस स्थाई सदस्यों ने जिम्मेदारी ली कि गैर-परमाणु शक्ति सम्पन्न देश पर परमाणु हथियारों से हमला होने या उसकी आशंका होने की दशा में तुरन्त कार्यवाही की जायेगी।

अगस्त-सितम्बर, 1968 में जेनेवा में गैर-परमाणु देशों का सम्मेलन हुआ। इसमें परमाणु शस्त्रों की होड़ की समाप्ति पर जोर देते हुए कई प्रस्ताव पारित किये गये, जिनमें पूर्ण निरास्त्रीकरण तथा केवल शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु शक्ति का उपयोग शामिल था। 1955, 1958, 1964, 1971 में सं० रा० सभ ने परमाणु शक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोग के लिए चार अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाये।

1969 में महासभा ने 1970 के दशक की 'निरास्त्रीकरण दशक' घोषित किया तथा सरकारों से परमाणु अस्त्रों की होड़ बन्द करने, परमाणु निरास्त्रीकरण करने और सामूहिक विनाश के दूसरे हथियारों की समाप्ति के लिए पूरा प्रयत्न करने का अनुरोध किया। इन देशों से कहा गया कि वे कठोर अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण के सहित पूर्ण निरास्त्रीकरण की सन्धि को स्वीकार करें।

निरास्त्रीकरण समिति सम्मेलन ने 1970 में परमाणु एवं सामूहिक विनाश के दूसरे शस्त्रों की समुद्र तल तथा भूमि के अन्दर से जाने की रोक के लिए सन्धि का समर्थन संघार किया। 1970 में इस सन्धि की 'पुष्टि' की गई।

1971 में निरास्त्रीकरण समिति सम्मेलन ने विगंले और जैविक अस्त्रों के विकास, निर्माण व संग्रह की समाप्ति की समस्या के बारे में पहलुओं पर व्यापक विचार और प्रयत्न किये। इस सन्धि में, जो आधुनिक युग में अपने दम की पहली सन्धि थी, सभी प्रकार के परमाणु आयुधों की समाप्ति के लिए कहा गया। 1971 में महासभा ने देशों में इस पर हस्ताक्षर एवं इसके अनुमोदन के लिए कहा। 1971 में ही महासभा ने रासायनिक शस्त्रों के विकास, निर्माण व संग्रह को रोकने के लिए सुरक्षा परिषद की सन्धि के लिए अपनी भाँग छोड़राखी। साथ ही उसने परमाणु हथियार-सम्पन्न देशों से कहा कि वे परमाणु शस्त्रों के परीक्षण पर तुरन्त रोक लगाएँ और यह कार्य 5 अगस्त, 1973 तक पूरा हो जाना चाहिए। महासभा ने विद्व

निशस्त्रीकरण सम्मेलन बुलाने पर भी जोर दिया।

1970 में स० रा० सभ की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर महासभा ने एक घोषणा पारित कर देशों से कहा कि वे 'शस्त्र नियमन' से आगे बढ़ें और सभी प्रकार के तथा विशेषकर परमाणु अस्त्रों को परमाणु शक्ति सम्पन्न देशों की सहायता से कम तथा अन्त में समाप्त करने का प्रयत्न करें।

महासभा ने विश्वास प्रकट किया कि निशस्त्रीकरण में यदि तेजी से प्रगति करनी है तो परमाणु शक्ति-सम्पन्न देश नये परमाणु अस्त्रों के विकास को रोकें और परमाणु परीक्षण बन्द कर दें। सदस्य देशों से कहा गया कि वे युद्ध में जैविक तथा हम धोतू गैसों वाले अस्त्रों का प्रयोग न करें। उसने निशस्त्रीकरण से विश्व में सामाजिक तथा आर्थिक प्रगति होने की ओर ध्यान दिलाया।

1968 में महासभा ने रूस और अमरीका को शस्त्र नियमन सन्धि पर सीधे बातचीत करने के लिए कहा। बातचीत 1969 में आरम्भ हुई। मई 1972 में दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि प्रक्षेपास्त्रों तथा दूर तक मार करने वाले शस्त्रों की सख्या कम कर दी जाये। महामन्त्रि ने इस समझौते की शस्त्र होड़ विशेषकर परमाणु अस्त्रों की सख्या को रोकने में एक विशेष कदम बताया। उन्होंने आशा प्रकट की कि 'इस समझौते से अधिक हानि करने वाले शस्त्रों की सख्या कम होगी और निशस्त्रीकरण की दिशा में एक महान् तथा पूर्ण कदम उठाया जायेगा।'

महामन्त्रि की भूमिका

(Role of the Secretary General)

प्लाना तथा रिज़ ने महामन्त्रि के कार्यों के बारे में कहा है—'महामन्त्रि का कार्य उतना ही विस्तार है, जितना कि वह उसे बना सकता है' (as big as he can make it)। स० रा० सभ की संरचना और कार्यप्रणाली को देखते हुए उनके महामन्त्रि की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। महामन्त्रि सगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। उसकी जिम्मेदारी सिर्फ किसी समिति या सभा के सदस्य-मन्त्रि जितनी सीमित नहीं है, जो बैठकों-बहसों की गतिविधियों का लेखा रखना हो और जिसके कर्तव्य मुख्य तौर पर कार्मिक होने हो।

महामन्त्रि की निश्चित किन्तु महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ—स० रा० सभ के चार्टर के अनुसार महामन्त्रि को विभिन्न क्षीपकों के अस्तर्जन निश्चित जिम्मेदारियाँ सौंपी गयी हैं। इनमें सुरक्षा परिषद और महासभा के ब्रिगावलाप निश्चय ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। विशिष्ट एजेन्डिया के काम के निरीक्षण, नियन्त्रण और संचालन की जिम्मेदारी भी उसी की है। इनके अलावा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व मुख्यवस्था बरकरार रखना हो या तनाव घटाना या फिर समस्या का समाधान ढूँढना, महामन्त्रि द्वारा पहल करने पर स० रा० सभ की पूरी व्यवस्था की सफलता का दारोमदार टिका हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध और शक्ति संघर्ष के कारण अन्तर्राष्ट्रीय सगठन की प्रस्तावित व्यवस्था आरम्भ में ही ज़िच की स्थिति में पड़ गयी थी। अतः स्वाभाविक ढंग से कार्य संचालन के लिए यह परमावश्यक था कि महामन्त्रि कमोवेश (या अधिकाधिक) तटस्थ पक्ष की भूमिका निभा सके। इन्हीं परिस्थितियों के कारण महामन्त्रि के व्यक्तित्व का महत्व राष्ट्रीय ढंग से रेखांकित किया गया।

कुशल महासचिव के वांछित गुण—महामन्त्रि अपने पद के कार्यभार ग्रहण करने के साथ अपनी निजी राष्ट्रीय पहचान मिटाने के लिए विवश है। अन्तर्राष्ट्रीय नोकरशाह के रूप में उसकी एकमात्र प्रतिबद्धता स० रा० संघ, अन्तर्राष्ट्रीय महकार, गुट निरपेक्षता, निरास्त्रीकरण और विश्व शान्ति के प्रति ही हो सकती है। स्पष्टतः किसी तरह की पक्षधरता (जातीय, राष्ट्रीय या सैद्धान्तिक) महासचिव पद के उत्तरदायित्व निर्वाह में बाधक बन सकती हैं। जो व्यक्ति इस कुर्सी पर बैठे, वह ईमानदार, मनोबल वाला, आत्म-सम्मानी, साहसी व आदर्शवादी होना चाहिए। परन्तु वह ऐसा हो, जिसके पैर धर्माध्यवाद की जमीन पर निरन्तर टिके रहें। यह भी जरूरी है कि महामन्त्रि पद ग्रहण करने वाला व्यक्ति इसके पहले महत्वपूर्ण राजनीतिक या राजनयिक जिम्मेदारी का निर्वाह कर चुका हो। योग्यता व प्रशासनिक कौशल के साथ-साथ निश्चित मात्रा में प्रतिष्ठा और यश-कीर्ति का स्वामी होना भी उसके लिए उपयोगी है। जाहिर है कि इन सभी शर्तों को देखते हुए योग्य मात्र कम ही बचते हैं।

विभिन्न महासचिवों के कामकाज का मूल्यांकन—महामन्त्रि की नियुक्ति के लिए महासचिवों की सहमति और सगठन के सदस्यों के बहुमत का समर्पण आवश्यक है। अतः छोटे गुट-निरपेक्ष राष्ट्र के लोकप्रिय और राजनीतिक दृष्टि से अविवादास्पद व्यक्ति की नियुक्ति की सम्भावनाएँ सबसे अधिक मानी जाती हैं। लेकिन इन सभी गुणों को किसी एक कसौटी पर तमा आना सम्भव नहीं। कई बार उम्मीदवार को परमने में चूक हो सकती है। नियुक्ति के बाद ही चुने गये व्यक्तित्व की खोट सामने आती है और स० रा० संघ के कामकाज पर असर पड़ता है। पिछले पाँच दशकों का अनुभव इन मित्रों को प्रमाणित और पुष्ट करता है।

1. त्रिगवेली—पहले महासचिव त्रिगवेली नार्वे के प्रधानमन्त्री रह चुके थे। वह एक ऐसे देश के प्रतिनिधि थे जिसकी भौगोलिक स्थिति पूर्व और पश्चिमी तथा समाजवादी और पूँजीवादी दुनिया के बीच थी। नार्वे औपनिवेश शक्ति भी नहीं था। अधिकतर अफ्रो-एशियाई देशों के मन में त्रिगवेली के प्रति किसी प्रकार का पूर्वाग्रह और दुश्प्रह नहीं था। चूँकि नार्वे यूरोपीय इतिहास और राजनीति की मुख्य धारा से अलग-थलग कटा सा रहा, अतः शीत युद्धकालीन पक्षधरता या संकीर्ण स्वार्थों का आरोप त्रिगवेली पर आसानी से नहीं लगाया जा सकता था। दुर्भाग्यवश, त्रिगवेली ने इन सभी आशाओं को निर्मूल मावित किया। वह न केवल एक दुर्बल अहंकारी व्यक्ति थे, बल्कि एक साम विरुद्ध की नस्वादी मानसिकता (प्रध्वन्यहीनता ग्रन्थि से ग्रस्त) से भी ग्रस्त थे। अफ्रो-एशियाई देशों की आशा-आकांक्षाओं से उनका कोई मरोहारा नहीं था। पहल करना तो दूर, अमरीका और पश्चिमी देशों का पिछलग्गू बनने में त्रिगवेली गौरव का अनुभव करते थे। उनके पूरे कार्यकाल में कोई भी ऐसी उत्प्रेरणीय घटना या उपलब्धि नहीं गिनायी जा सकती, जिससे यह दर्शाया जा सके कि उनका आचरण अपने पद की गरिमा के अनुकूल रहा। आज उनकी स्मृति शेष है तो सिर्फ इसलिए कि वह गिननी में पहले महामन्त्रि थे।

2. डेग हेमरशोल्ड—दूसरे महामन्त्रि स्वीडन के डेग हेमरशोल्ड थे। स्वीडन नार्वे का पड़ोसी देश है, जो कई मामलों (राजनीतिक व सांस्कृतिक) में उसी को प्रतिबिम्बित करता है। सिर्फ अपनी व्यक्तित्व प्रतिभा, आकर्षक और तेजस्वी व्यक्तित्व के बल पर ही हेमरशोल्ड महामन्त्रि पद की बँवाई गरिमा को पुनः प्रतिष्ठित

करने में सफल हुए और स० रा० मध की रचनात्मक भूमिका को उजागर कर सके। यो स्वयं हेमरशोन्ड अमिजात्य वर्ष के अन्तर्मुखी कुलीन थे और त्रिग्वेली की तरह कई लोगों के लिए आकर्षणहीन और अजनबी बने रह सकते थे। परन्तु वह इस अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में अपनी सारी आस्था के कारण करिदमानी ढंग से प्रभावशाली रचनात्मक जन-मध्यकें साधने में सफल हुए।

डेग हेमरशोन्ड के गुणो-विशेषताओं का गहरीरिक्त पक्ष भी उल्लेखनीय है। वह जीवन-पर्यन्त कुबारे रहे, परन्तु उनकी तेजस्विता और उत्साह उनके अधुण्य जीवन का प्रमाण देते थे। वह स० रा० मध के न्यूयाक स्थिति मुख्यालय में अपने दफ्तर की ऊँची मजिल तक पहुँचने के लिए लिफ्ट की अपेक्षा सीढ़िया चढ़ना ही बेहतर समझते थे। उनके कुछ आलोचक उन्हें भले ही दम्भी-पाखण्डी कहते रहे, किन्तु उनका स्वाभिमान स० रा० मध के लिए बहुमूल्य पूँजी साबित हुआ। वह न तो अमरीका के दबाव में आने थे और न ही सोवियत मध की गलत बात सुनने को कभी तैयार हुए। इसी कारण वह नेहरू जी तथा अन्य मुट निरपेक्ष नेताओं के सहित बन सके। हेमरशोन्ड लकीर के फकीर नहीं थे। जरूरत पड़ने पर वह अन्तर्राष्ट्रीय हित में बाटें की लचीली रचनात्मक व्याख्या स्वीकार करने के लिए तैयार रहते थे। निःस्त्रीकरण और कोरिया सफ्ट के समय हम मध्यम में उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही। इसी तरह गाजा पट्टी और कागो में अन्तर्राष्ट्रीय सैनिक दस्ते भेजकर युद्ध विराम करवाने और दाम्नि लौटाने में उनकी पहल महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। स्वयं एक मध्यम यूरोपीय देश के नागरिक होने के बावजूद अफ्रीका और एशिया के विपन्न देशों की दरिद्रता का दुःख समझन वाला दिलोदिमाग हेमरशोन्ड के पास था। अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को, यूनिस्फ आदि के कार्यक्रमों की हफरेला जिन तरह तैयार की गयी, उनमें पीछे हेमरशोन्ड का हाथ सहजता से देखा जा सकता है। दिसम्बर, 1960 में उपनिवेशवाद के उन्मूलन के बारे में जो प्रस्ताव महासभा में पारित किया, उसकी प्रेरणा मने ही हेमरशोन्ड की न रही हो, किन्तु उनको प्रोत्साहन देने में वह बड़ी पीछे नहीं रहे।

इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि अपने कार्यकाल के अन्तिम दो वर्षों में हेमरशोन्ड अंशम दीवत लगे थे। उन पर भी अमरीका के प्रति अपेक्षाकृत उदार नवीय अपनाने के आदेश लगाये जाने लगे। इसके लिए दो बातें जिम्मेदार थी। एक तो यह कि यह हेमरशोन्ड का दूसरा कार्यकाल था और कई देशों विशेषकर समाजवादी और उग्र रूप में उपनिवेशवाद-विरोधी देशों को यह लगने लगा था कि जो महासक्ति मध्यममार्गी व मुधारवादी गम्ना मुज्ञान और अपनाता है, वह व्याप्यति का वनाये रखने तथा न्यस्त स्थापों को बचाने वाला मिट्ट होता है। अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं से दिन-रात क्यों पूछते झूझते किसी भी व्यक्ति का उत्साह हमेशा उफान पर नहीं रह सकता। यदि हेमरशोन्ड के आचरण में भी 1960 तक यह हाउरने लगा था तो यह अस्वाभाविक नहीं था। दूसरी बात, महासक्तियों के बीच बढ़ते तनाव व प्रतिद्वन्द्विता के साथ स० रा० मध की मरचनान्मक कमजोरियाँ और कमियाँ भी सामने आने लगी थीं। मिमान के तौर पर चीन का माओ के नेतृत्व में महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय घटक के रूप में उदय, कागो अभिधान के कारण स० रा० मध के दिवानियेन का सफ्ट, ह्यूडनेव द्वारा महासक्ति के स्थान पर रोखा धरम्या (नीन घोही द्वारा मोची जाने वाली घोषा गाही) के अनुमरण का

मुलाव, ऐसी परेशानियाँ थी, जिन पर सिर्फ व्यक्तित्व के आधार पर काबू नहीं पाया जा सकता था।

इसके अलावा एक ऐसी कठिनाई है, जिसका समाधान आसान नहीं। महा-मन्त्रि कितना ही समय और प्रतिभाशाली क्यों न हो, उसे दैनंदिन कार्रवाई के लिए अपने महयोगियों खासकर अधीनस्थ वारिण्ट कर्मचारियों पर निर्भर होना पड़ता है। इन कर्मचारियों की निर्यात के लिए संगठन के सदस्यों के अनुसार राष्ट्रीय कोटा तय किया जा चुका है। इन सभी कर्मचारियों में महासचिव की तरह संकीर्ण राष्ट्रीय स्तरों से ऊपर उठने की अपेक्षा नहीं जाती है, परन्तु यथार्थ में इसकी सम्भावना नगण्य है। एक बार नियुक्त होने के बाद किसी भी अन्य नौकरगारों की तरह अन्तर्राष्ट्रीय नौकरगारों की भी एक विरादरी पनपने लगती है, जिसकी मददसे महत्वपूर्ण प्राप्तिमान अपने स्वस्त स्तरों को सुरक्षित रखना और बढ़ाना होती है। इन व्यक्तियों के माध्यम से महामन्त्रि की पहल को काफी दूर तक निष्पन्न किया जा सकता है।

डैग हेमरगोल्ड की अकाल मृत्यु के बाद उनकी जो डायरियाँ प्रकाशित हुईं, उनसे ऐसा लगता है कि हेमरगोल्ड आत्म-केन्द्रित और दार्शनिक रत्न के व्यक्ति थे, जिनके लिए अपने राजनयिक उत्तरदायित्व मन बहलाव के साधन भर थे। कई विद्वानों ने इसे उनकी आलोचना का प्रमुख मुद्दा बनाया है। परन्तु ऐसा करना व्यापक नहीं लगता। यदि हेमरगोल्ड की तुलना उनके परवर्ती उत्तराधिकारियों से की जाये तो इस बात की अनीमांति समझा जा सकता है कि महामन्त्रि की भूमिका को हेमरगोल्ड ने दितने निर्णायक ढंग से परिष्कारित किया था।

3. ऊ घाट—डैग हेमरगोल्ड की मृत्यु के बाद बर्मा के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री ऊ घाट ने महामन्त्रि पद संभाला। इस तरह पहली बार अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी एक एशियाई देश का प्रतिनिधि बना था। ऊ घाट के चुनाव और नियुक्ति के पीछे भी उसी तरह के तर्क काम कर रहे थे, जो ब्रिगेलेली और हेमरगोल्ड के पक्ष में दिये जाते थे। बर्मा एक छोटा-सा गुट निरपेक्ष (अब नहीं) राष्ट्र है और ऊ घाट स्वभाव से मृदु और अनुभवी राजनीतिज्ञ थे। वह दोनों महाशक्तियों को ताँ मँबाये थे ही, उनसे अफ्रो-एशियाई देशों को यह उम्मीद थी कि वह भीमती दुनिया के विभिन्न तबकों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए सक्रिय रहेंगे। बर्मा स्वयं मत्ता मर्पण की राजनीति से अलग-थलग रहा था और चीन तथा भारत जैसे मर्पणरत बड़े एशियाई देशों को भी अपनाते सावक लगता था। दुर्भाग्यवश ऊ घाट ने अपने कार्यकाल में अपने तथा सं० रा० संघ के सभी चुनौतियों को निरास ही किया।

ऊ घाट के मूल्यांकन के लिए उनके व्यक्तित्व को ठटोलना उपयुगी भावित होगा। जिन गुणों ने उन्हें आकर्षक उम्मीदवार बनाया था, वे ही पद ग्रहण के बाद दुर्बलता बन गये। हेमरगोल्ड मितभाषी और अन्तर्मुखी व्यक्ति थे, परन्तु जिद्दी और अहिंसक भी। जबरन पड़ने पर वह किसी भी बात को अपनी या अपने पद की प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते थे। इसके विपरीत ऊ घाट समझौता-मरस्त थे और हर बग्न विनीत मुद्रा अपनाये रखते थे। आरम्भ से ही उनकी स्थिति नीचे अर्थात् कमजोर व्यक्ति के रूप में फैल गयी। यदि हेमरगोल्ड के तैवर यूरोपीय, वृत्तीय और मानव्यी के तो ऊ घाट के नदृष्ट्य बौद्ध-मिश्र वाले।

परन्तु ऐसा भी नहीं कि ऊ घाट का व्यक्तित्व उनके काम में हमेशा आड़े आया हो। अमल में इस समय तक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में स० रा० सघ का अवमूल्यन भी बहुत तेजी से हो रहा था। भारत-चीन सीमा विवाद के बाद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत का प्रभाव बहुत कम हो गया था। इसने अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में गुट-निरपेक्ष राजनय को क्षति पहुँचायी। अनेक अफ्रो-एशियाई देश भारत और चीन के बीच विस्तृत तटस्थ रहना चाहते थे और चीन इस बात के लिए सक्षम था कि 'सहकार' या 'संधि' दोनों के सम्पादन के लिए परामर्श स० रा० सघ के बाहर चलाया जाये। यह समय में आने वाली बात थी, क्योंकि अब तक चीन स्वयं इस संगठन का सदस्य नहीं था। कुछ और राष्ट्रों का मोहभंग भी स० रा० सघ से हो चुका था। वेल्लेड सम्मेलन में नेहरू जी से टनराव के बाद सुकार्णों ने स० रा० सघ की सदस्यता त्याग दी थी। इसी तरह ऊ नु के देश वर्मा ने अपने 'गुट निरपेक्ष नीति' को अलग रखने के लिए गुट निरपेक्ष आन्दोलन को छोड़ दिया था। कुल मिलाकर, स० रा० सघ का मध्य महाशक्तियों और बड़ी शक्तियों तक विभक्त गया था।

इसके साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और प्रवृत्तियाँ इस तरह विकसित हुए कि महाशक्ति ही यही, पूरा स० रा० सघ भी अप्रासंगिक निम्न होने लगा। एक ओर महाशक्तियाँ यूएनई मिमाइन सत्र के दौरान सर्वनाश के बग़ार तक पहुँचकर इस महाशक्ति के साथ बाधम लीटी कि उनका आपसी सम्पर्क कभी नहीं टूटना चाहिए। इसकी परिणति उनके बीच 'हॉट लाइन' की स्थापना से हुई, जिनमें ऐसे मौकों पर स० रा० सघ और महाशक्ति की तथाकथित भूमिका का सोचना-पन उजागर किया। महाशक्तियों से इतर बड़ी शक्तियों ने भी अपने राजनयिक त्रिप्राकलाप अन्त्य ही महत्वपूर्ण समझे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण फ़ामीमी राष्ट्रपति देगोन ने प्रस्तुत किया—फ़ाम के लिए यूरोपीय साम्राज्यवाद की स्थापना और अपने ही बन्धुत्व पर फेंच मारी अफ्रीकी देशों में अपना आधिप और मास्टरिक वर्चस्व बरकरार रखकर। इन्हीं वर्षों में वियतनाम युद्ध असाध्य बीमारी के रूप में फैला और अमरीकी 'राष्ट्र दिन' इसके साथ जुड़े होने के कारण स० रा० सघ की अक्षमता बहुत ही बेशक्यता के साथ प्रकट हुई।

कुल मिलाकर तनाव-नैतिक के पूर्वाभाम, जनवादी चीन में सांस्कृतिक क्रान्ति और सोवियत चीन-विग्रह में निरन्तर विवाद ने इस बात की कोई सम्भावना दी नहीं रखी कि ऊ घाट अपने पूर्ववर्ती हेमरगोन्ड की तरह अग़रदार हो सकें। फिर भी यह सोचना गलत होगा कि वह कुछ नहीं कर पाये। आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में स० रा० सघ की गतिविधियों का प्रमत्त प्रसार ऊ घाट के उदय में ही त्वरित गति से हो मचा और इस अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का महत्व राजनीति के दलदल के बाहर मार्थक ढग में झलकाया जा मचा। अक्टोबर सम्मेलन की शृङ्खलाओं को ले या विशेष अधिवर्षों को, आर्थिक मामलों में सदस्यों की रुचि और मनोबल बढ़ान में ऊ घाट का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

4. **चुर्त वाल्दाहीम**—ऊ घाट के बाद एक बार फिर महाशक्ति का पद तटस्थ यूरोपीय देश आस्ट्रिया की ओर सौटा। चुर्त वाल्दाहीम पूर्व खनिज गुणों के स्वामी थे और नमाम ज़रूरी धन पुरी करने थे। वाल्दाहीम की 'उपनयियाँ' भी उल्लेखनीय बर्राष्ट्रिय सम्मेलन/15

नहीं रही। फिर भी यह आज याद किये जाते हैं, क्योंकि महासचिव पद त्यागने के कुछ समय बाद उन्हें अपने देश में राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान जिस बदनामी का सामना करना पड़ा, उसे देखते हुए वाल्टाहीम के जीवन के पिछले वर्ष अपेक्षाकृत पगलबी नजर आते हैं। वाल्टाहीम के कार्यकाल में लम्बे समय से चले जा रहे अनेक अन्तर्राष्ट्रीय संकट स्वयं ही बिना महासचिव के विशेष प्रयत्न के विलीन हो चुके थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन चीन और अमरीका के बीच वैननस्य का अन्त तथा अमरीका और वियतनाम के बीच लम्बे गोपनीय परामर्श के बाद वियतनाम युद्ध की समाप्ति थे। चीन में न केवल सांस्कृतिक क्रान्ति का अन्त हुआ, दलित भावों के बाद बौद्ध सिद्धांतों का पुनर्जागरण और उनके समर्थकों ने गमल्लदार, व्यावहारिक और मध्यममार्गी रास्ता अपनाया। महासचिवों के बीच तनाव-अंधिलक्य की प्रक्रिया प्रगतिशील रही और इस कारण पश्चिम एशिया में और निराशाजनकता के मामले में 'प्रगति' देखी जा सकती। पश्चिम एशिया में केम्प डेविड समझौता हो सका और फिलिस्तीन मुक्ति संगठन सं० रा० संघ का पर्यवेक्षक सदस्य बन गया। सर्वत्र तनाव घटने से निश्चय ही महासचिव वाल्टाहीम का उत्तरदायित्व निर्वाह के याद के मुकाबले सहज बना।

वाल्टाहीम के मृत्युकाल में इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि जहाँ भी महासचिव के व्यक्तिगत कौशल और उनकी प्रतिष्ठा के माध्यम से समस्या के हरा की बात उठी, वही वाल्टाहीम असफल-असमर्थ सिद्ध हुए। इसका एक अच्छा उदाहरण ईरान में अमरीकी बंधकों वाला प्रकरण है।

5. **पेरज वी कुइयार**—वाल्टाहीम के अवकाश ग्रहण करते-करते शायद यह बात समझ भी गयी कि यूरोप और एशिया के बाद अब लातीनी अमरीका की बारी है। अतएव पेरज वी कुइयार महासचिव नियुक्त हुए। अब तक यह सोचने का कोई कारण नहीं कि उनका व्यक्तित्व उनके कृतित्व को ऐसे प्रभावित करेगा कि यहाँ प्रस्तुत निष्कर्षों में संशोधन की आवश्यकता पड़े। उन्हें भी दूगरा कार्यकाल मिल चुका है, जिससे यही बात उजागर होती है कि महासचिव योग्य हो या अक्षम, संगठन के सदस्यगण जहाँ तक हो सके, जाने-पहुँचाने आदमी को ही अपने काम का समझते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में ईरान-इराक युद्ध हो या अफगानिस्तान संकट या फिर दक्षिण अफ्रीकी पण्डा, महासचिव की निष्पक्षता अब तक अच्छी तरह जगजाहिर हो चुकी है।

सं० रा० संघ और तीसरी दुनिया (U. N. and the Third World)

सं० रा० संघ का निर्माण अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति, आर्थिक विकास, सामाजिक एवं मानव अधिकारों की रक्षा तथा राष्ट्रों में पारस्परिक आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया गया था। इसके प्रारम्भिक सदस्य राष्ट्रों की संख्या 51 थी। उत्तरोत्तर समय में एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमरीका के अनेक देश औपनिवेशिक दासता से मुक्त होते गये और उन्होंने इसकी सदस्यता ग्रहण की। आज इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या 161 है जिनमें से करीब 110 तीसरी दुनिया के विकासशील देश हैं, अर्थात् साम्यवादी शक्ति के हिमाय से तीसरी दुनिया के देश दो तिहाई से अधिक हैं। जहाँ पहले सं० रा० संघ में यूरोपीय देश अपना वर्चस्व बनाये हुए थे, वहाँ अब विकासशील देशों ने उनके

दबदबे को अपनी सत्प्राप्त्यक शक्ति के बलश्रुते पर काफी कमजोर कर दिया है। जैसाकि भारतीय विद्वान टी० एस० रामाराव ने लिखा है—स० रा० सघ एक ऐसी अन्तराष्ट्रीय संस्था है, जिस पर विकासशील राष्ट्रों को बड़ी आस्था है। इसकी महामात्रा में उनका बहुमत है और उन्हें लगता है कि वे इसका प्रयोग अपने हित-संवर्धन के लिए कर सकेंगे हैं।

उपलब्धियाँ—द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अफ्रो-एशियाई एवं लतीनी अमरीकी देशों में औपनिवेशिक दासता के विरुद्ध राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम प्रारम्भ हुए। स० रा० सघ के जरिये ऐसे अनेक प्रयास किये गये जिसमें ज्यादा खून-खराबा हुए बिना कई उपनिवेशों को आजादी हासिल हो सकी। ज्यों-ज्यों नवोदित देश स० रा० सघ की सदस्यता ग्रहण करते गये, त्यों-त्यों इस विश्व संगठन में राष्ट्रीय मुक्ति संग्रामों के प्रति समर्थन भी बढ़ता गया।

रूपभेद तथा जातिभेद मिटाने के लिए स० रा० सघ की महासभा में अनेक प्रकार के प्रस्ताव पारित किये गये। स० रा० सघ द्वारा समय-समय पर इस सम्बन्ध में की गयी घोषणाएँ मानव-समाज में समानता और न्याय पर बल देती हैं। दक्षिण अफ्रीका की गौरी सरकार द्वारा वहाँ के बहुसंख्यक कालों पर थोपे गये बंदर नस्लवाद की इस विश्व संगठन ने अनेक बार कड़ी भर्मना की तथा सदस्य राष्ट्रों से इस गौरी सरकार के साथ बूटनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक बहिष्कार की अपील की। इसका कई राष्ट्रों ने अनुमरण किया।

अनेक नए राष्ट्रों के उदय ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उपल-धुमल मचा दी। महाशक्तियों के बहुकावे में आकर या किसी अन्य कारण से वे आपस में लड़ने लगे थे। इस लड़ाई में सीमा-विवाद प्रमुख रहे हैं। वैसे भी अमरीका और रूस के बीच चीन युद्ध के तनाव के कारण स्थिति संकटपूर्ण थी। इस मिलजुलने में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की स्थापना तथा विकासशील राष्ट्रों में अस्थिर विवादों के शान्तिपूर्ण हल में स० रा० सघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। स्वेज, अलिन, बांगो, कोरिया तथा सबाना के विवादों में उनका योगदान इतना सराहनीय रहा है कि उनमें विश्व को तीसरा महायुद्ध के विनाश के कगार पर जाने से रोका।

स० रा० सघ के गैर-राजनीतिक कार्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं रहे हैं। इसके विभिन्न संगठनों जैसे यूनेस्को, अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय डाक सघ, दूर संचार सघ, स्वास्थ्य एवं कृषि संगठन आदि में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और कृषि क्षेत्रों में ऐसे अनेक कार्य किये हैं जो तीसरी दुनिया के अल्प विकसित राष्ट्रों के लिए कल्याणकारी साबित हुए हैं। आज स० रा० सघ की 80 प्रतिशत गतिविधियाँ सामाजिक और आर्थिक समस्याओं में सम्बद्ध हैं। इस प्रकार उनका ध्यान अब मानव समाज के बहुमुखी विकास और कल्याण की ओर बढ़ा है।

असफलताएँ—दुनिया हाथ हुए भी स० रा० सघ का निराश्वरीकरण, हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाने तथा दक्षिण अफ्रीका में बहुसंख्यक अश्वेतों के शासन स्थापित करवाने, विकसित एवं विकासशील देशों के बीच आर्थिक दूरी कम करने, विकसित एवं अविकसित देशों द्वारा समुद्री सम्पदा के उचित दोहन, गरीब राष्ट्रों को उनका बचत मान की वाजिब कीमत दिलाने आदि समस्याओं में आर्थिक मरम्मत ही मिली है।

विकसित देशों ने सं० रा० संघ को एक ऐसा मंच बनाये रखा है जहाँ से वे तीसरी दुनिया के विकासमान राष्ट्रों में गरीबी मिटाने की बात तो करते हैं, किन्तु उन्होंने अपनी 'कपनी' की 'करनी' में बदलने के लिए कभी हठ राजनीतिक इच्छा शक्ति का व्यवहार में प्रयोग नहीं किया। इसमें दो राय नहीं कि समृद्ध देश अपनी आय का एक छोटा-सा हिस्सा सं० रा० संघ के माध्यम से दुनिया के अविकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास के लिए देते हैं। निश्चय ही इससे इन देशों में लाभकारी योजनाएँ जरूर क्रियान्वित हुईं, लेकिन कुछ विकासशील देशों द्वारा इसे अब बाहरी हस्तक्षेप के नजरिये से देखा जाने लगा है, जो एक हद तक सही भी है।

विश्व बैंक का ही उदाहरण लें। विश्व बैंक में पश्चिमी देशों के वर्चस्व के कारण मदद में प्राथमिकता भी तीसरी दुनिया में पश्चिम-समर्थक राष्ट्रों को ही ज्यादा मिलती है तथा जरूरतमन्द गरीब राष्ट्रों को कम। तब पर सं० रा० संघ के जरिये विकसित देश आर्थिक सहायता प्रदान कर अल्प-विकसित राष्ट्रों में वैसा ही आर्थिक एवं तकनीकी विकास करवाना चाहते हैं जैसा वे चाहते हैं। इससे प्राप्तकर्ता देश की निर्भरता दाता देशों पर और बढ़ती है। यही नहीं, दाता देश अपनी तकनीकी जानकारी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं करवाते और तकनीकी विशेषज्ञों की जमात को भी अपने देश से ही भेजकर असंमित खर्चों का बोझ उन पर जबरदस्ती थोपते हैं। जहाँ एक ओर इन खर्चों से गरीब राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाती है, वहीं दूसरी ओर विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों को मेजबान देश के बारे में पर्याप्त जानकारी के अभाव के कारण योजनाएँ अधिकांशतः आंशिक सफलता ही प्राप्त कर पाती हैं।

उत्तर-दक्षिण संघर्ष—सं० रा० संघ के सामने एक बड़ी चुनौती, जो उसके अस्तित्व तक को खतरा पहुँचा सकती है, उत्तर तथा दक्षिण के बीच टकराव की है। अब अमेरिका और हम के बीच उतनी कटुता नहीं रही। ऐसे कई उदाहरण सामने आये हैं, जिनसे यह स्पष्ट हो चुका है कि जहाँ अमेरिका और हम की उग्र कटुता धीरे-धीरे घट रही है, वहीं विरामित एवं विकाशशील देशों के बीच टकराव की स्थिति बढ़ती जा रही है। सं० रा० संघ के तहत कार्यरत विभिन्न 'अकटाड' तथा 'मसूरी बानून सम्मेलनों' में उत्तर अर्थात् विकसित राष्ट्र और दक्षिण अर्थात् तीसरी दुनिया के विकासशील राष्ट्रों के बीच टकराव को स्पष्ट तौर पर पामा जाता है।

उत्तर-दक्षिण संघर्ष को सुलझाने के लिए कुछ वर्षों पूर्व मनीला में आयोजित अकटाड सम्मेलन का यहाँ उल्लेख करना वाछनीय होगा। वहाँ विकासशील देशों ने एनता के साथ विकसित देशों से 'व्यापार' में कुछ रिश्वतों के लिए परामर्श किश लेकिन समृद्ध राष्ट्रों की हठमिती के कारण उसके परिणाम उत्पादजनक नहीं रहे।

आस्था कम होने के कारण—हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाने का मामला ही या दक्षिण अफ्रीका में वृत्तस्वक अखिली को धामन-सत्ता सौंपने का, सं० रा० संघ में तीसरी दुनिया के राष्ट्र मत्वात्मक शक्ति के जोर पर विकसित राष्ट्रों के मुकाबले अपने प्रस्तावों को हमेशा पारित करवाते आये हैं। किन्तु व्यवहार में ऐसे प्रस्तावों का पर्याप्त रूप से विचारविमर्श नहीं हुआ है। अभी भी दक्षिण अफ्रीका में अल्पसंख्यक गरीब सरकार शामिल में है। असल में विश्व महाशक्तियाँ ऐसे प्रस्तावों के बारे में ईमानदार नहीं हैं।

उदाहरणार्थ, महाशक्तियों के बीच साल्ट समझौते और हिन्द महासागर के विसैन्यीकरण के लिए किये गये प्रयासों को ही लें। निरस्त्रीकरण और हिन्द महासागर दोनों के बारे में स्वयं स० रा० सघ ने अनेक प्रस्ताव पारित किये और उसने विश्व के समस्त देशों को इस बारे में कोई आम राय बनाने के लिए 'अन्तर्राष्ट्रीय पचायत' जैसा मंच प्रदान किया। हालांकि अमरीका और रूस निरस्त्रीकरण और हिन्द महासागर की शान्ति क्षेत्र बनाने के लिए स० रा० सघ में सैद्धान्तिक तौर पर राजी हो गये किन्तु जब उनके कार्यान्वयन जैसी महत्वपूर्ण बातें आयी तो दोनों चुपके-चुपके एकान्त में परामर्श करते रहे। अर्थात् निरस्त्रीकरण और हिन्द महासागर जैसे महत्वपूर्ण मसलों पर विकासशील राष्ट्रों से सलाह-मशवरा करना तो दूर रहा, वार्ता के बाद भी उन्होंने न तो उनकी विरवास में लेने का प्रयत्न किया और न परामर्श की विस्तृत जानकारी दी। ऐसे ही अनेक कारणों से स० रा० सघ में तीसरी दुनिया के अनेक देशों की आस्था अपेक्षाकृत कम होनी गयी है।

इसके बावजूद यह मानना होगा कि स० रा० सघ का विश्व शान्ति एवं सुरक्षा कायम रखने में काफी योगदान रहा है। तीसरी दुनिया के अविक्लित राष्ट्रों में भी इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के जन-नित्याण कार्य सम्पन्न हुए हैं। अब यह अन्तर्राष्ट्रीय पचायत समृद्ध या विकसित राष्ट्रों की बर्पाती नहीं रह गयी है, जो गरीब राष्ट्रों को अपने झुझारों पर नचाये। विगत कुछ वर्षों से विकसित एवं विकसाम-शील देशों के बीच टकराव के कुछ नये मुद्दे सामने आये हैं, जिन कारण समय की पुकार यही है कि यदि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा को कायम करना है तो तीसरी दुनिया के गमस्त देशों को एकजुट होकर चलना चाहिए। इसके लिए पूर्व धर्म के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में स्वयं उनमें आपसी सद्भाव एवं सहयोग जरूरी है अन्यथा विश्व महाशक्तियाँ एवं अन्य विकसित देश उनकी 'फूट दासों और राज करी' वाली उक्ति के अनुसार अपनी उगलियों के झुझारों पर मचाते रहेंगे। स० रा० सघ में तीसरी दुनिया के राष्ट्र अपनी विशाल सत्वात्मक शक्ति के माध्यम से बड़ी शक्तियों की शोषणकारी नीतियों एवं हथकण्डों को नाकाम कर सकते हैं। यह अलग बात है कि बड़ी शक्तियों के पास बीटो होने से तीसरी दुनिया के देशों की आघातीत मरुतता मिलने में अनेक अड़चने महसूस हो सकती हैं। फिर भी, उनकी नैतिक विजय अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उनके लिए कुछ लाभकारी रण अवसर लायेगी। वस्तुतः उपर्युक्त प्रयत्नों की सफलता को अवश्यमावी बनाने के लिए समष्टि नीति के साथ नैतिक माहम की भी भारी जरूरत है।

स० रा० सघ में भारत की भूमिका (India's Role in the U. N.)

भारत इस अन्तर्राष्ट्रीय मण्डल के प्रारम्भिक सदस्यों में से एक था। 1945 में भारत यद्यपि स्वतन्त्र नहीं था, पर द्वितीय विश्व युद्ध के समय मित्र राष्ट्र (ब्रिटेन) के उपनिवेश होने के कारण उसने सैन-प्रामिमकी सम्मेलन में भाग लिया। 1947 में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के पड़े में मुक्त होने के बाद उसने स० रा० सघ में स्वतन्त्र सदस्य राष्ट्र के रूप में प्रवेश किया। स० रा० सघ विषयक अध्ययन के विशेषज्ञ के० पी० मन्नेना का मानना है कि 'विदेश नीति के उद्देश्यों की दृष्टि में

गुटनिरपेक्ष भारत के लिए सं० रा० संघ उसकी विदेश नीति का प्रमुख उपकरण और साधन समझा जाता रहा है।¹ भारत उन गिने चुने सदस्य राष्ट्रों में है, जिनका त्रिव्याकलाप यह स्पष्ट दर्शाता है कि वे सं० रा० संघ को मजबूत बनाना चाहते हैं।²

गुटनिरपेक्षता एवं शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व भारतीय विदेश नीति के आधारभूत सिद्धान्त रहे हैं, जिनके जरिये हम दुनिया में शान्ति एवं सुरक्षा लाना चाहते हैं। भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय सितिज पर इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए रंगभेद, जाति-भेद, नस्लभेद, आर्थिक शोषण, उपनिवेशवाद, नव-उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद का आरम्भ से ही दृढ़ विरोध किया है। इन लक्ष्यों में सफलता पाने के लिए उसने सं० रा० संघ में सदैव आवाज उठाई है। भारत ने सं० रा० संघ के प्रति यह धोषणा की कि वह विद्वद शान्ति एवं सुरक्षा लाने के उसके सभी प्रयत्नों में निःसंकोच होकर सुव्यवस्था तथा कार्यो से भरपूर सहयोग देगा। भारत उसकी उन सभी गतिविधियों में भाग लेगा, जिनमें उसे भौगोलिक स्थिति, आबादी और शान्तिपूर्ण उन्नति में सहयोग मिल सके।

भारत ने आरम्भ से ही सं० रा० संघ में अफ्रो-एशियाई एवं लातीनी अमरीकी महाद्वीप के देशों में विद्यमान उपनिवेशवाद की कड़ी आलोचना की और उसे 'मानव गरिमा के अपमान' की संज्ञा दी। उसने कहा कि उपनिवेशवाद विश्व शान्ति एवं प्रगति में बाधक ही नहीं, अपितु सं० रा० संघ चार्टर का स्पष्ट उल्लंघन है। औपनिवेशिक दासता से मुक्ति दिलाने के विषय में भारत ने अन्य राष्ट्रों के साथ मिलकर एक प्रस्ताव रखा। इसे सं० रा० संघ महासभा ने स्वीकार किया। परिणामस्वरूप सं० रा० संघ की महासभा ने 1961 के इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने की जाँच करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया। भारत ने इस समिति का एक सदस्य होने के नाते सदैव सक्रिय भाग लिया। उपनिवेशवाद के तहत ही पला जातिभेद, रंगभेद एवं नस्लवाद का भारत विरोध करता आया है। जब 1946 में महासभा के पहले अधिवेशन में भारत ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के निवासियों के प्रति जातिभेद की नीति का प्रश्न उठाया, तो महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर जातिभेद को सं० रा० संघ के चार्टर के खिलाफ घोषित कर दिया। भारत सरकार ने इसके सम्बन्धित सभी प्रस्तावों के पूर्णरूपेण त्रिव्यान्वयन के लिए दक्षिण अफ्रीका की सरकार के साथ अपने कूटनीतिक, आर्थिक एवं वाणिज्यिक सम्बन्ध तोड़ लिये।

अफ्रो-एशियाई तथा लातीनी अमरीकी उपनिवेश ज्यों-ज्यों औपनिवेशिक दासता से मुक्त होते गये, त्यों-त्यों इस विश्व संगठन के सदस्य-राष्ट्रों की संख्या निरन्तर बढ़ती गयी। नवोदित राष्ट्रों द्वारा सदस्यता पाने का आवेदन करने पर विश्व की बड़ी शक्तियों ने अनेक तकनीकी रोड़े बरकाकर उन्हें इसमें जाने से रोका। विपक्षनाम, कोरिया तथा साम्यवादी चीन के उदाहरण विश्व शक्तियों के वद्वेष्यों को बाद ताजा कर देते हैं। भारत ने इन देशों को सं० रा० संघ में स्वागत देने के बारे में भरमक वकालत की। हालाँकि 1962 में बहोमी चीन भारत का शत्रु बन चुका था फिर भी उसने विद्वद की बड़ी शक्तियों की इच्छा के विरुद्ध उसको इस अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में प्रवेश दिलाने की पूरी कोशिश कर अन्ततोगत्वा सफलता

¹ K. P. Saxena, *The United Nations in India's Foreign Strategy*, in M. S. Rajan et. al., *Ibid.*, 188-89.

प्राप्त की।

भारत ने स० रा० सघ में निशस्त्रीकरण के हरेक प्रयास को भरपूर समर्थन दिया है। भारत का मत है कि शस्त्रास्त्रों पर व्यय को जाने वाली अपार धन राशि मानवता के कल्याण में लगायी जाये। 1958 में महासभा के तेरहवें अधिवेशन में निशस्त्रीकरण के बारे में भारत ने दो प्रस्ताव रखे। पहला, सम्झौता होने की अवधि तक परमाणु आयुधों के परीक्षण तुरन्त बन्द कर दिये जायें। दूसरा, आकस्मिक आक्रमण बन्द करने की सम्भावना के प्रश्न पर विचार किया जाये। यह भी कहा गया कि निशस्त्रीकरण छोटे एवं बड़े दोनों ही प्रकार के मुल्कों पर समान रूप से लागू हो।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसे अनेक माजुब खण भी आये हैं, जहाँ राष्ट्रों के मध्य युद्ध भावना से जन्म लिया और महायुद्ध की नौशत तक बात पहुँच गई। ऐसे अवसरों पर भारत ने शान्ति का अग्रदूत बनकर विश्व को विनाश के कगार से बचाया। कोरिया, हिन्द चीन, वियतनाम, स्वेज, हंगरी, कंगो, सीरिया-टर्की विवाद, अल्जीरिया आदि मक्दों के दौरान युद्ध भड़काने वाली ज्वाला को भारत जैसे शान्ति-प्रिय राष्ट्र ने ही अपनी सूझबूझ के बल पर घात किया।

1945 में स० रा० सघ की स्थापना के वक्त और वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में अनेक परिवर्तन के कारण कई नई चुनौतियाँ मुँह बाए पड़ी रह गयी हैं। इनका माहसपूर्ण मुकाबला करने में भी भारत अग्रगामी रहा है। मसलन, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के शीत युद्ध के दौरान दोना महाशक्तियों अमरीका व हम ने तीसरी दुनिया में अपने-अपने प्रभाव क्षेत्र स्थापित आरम्भ किये और उनमें परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध भी करवा दिये किन्तु फिर स्थिति बदली। तीसरी दुनिया के देशों में गुट निरपेक्ष आन्दोलन एवं अग्र्य मंचों के जरिये उनमें अपेक्षाकृत आपसी एकता स्थापित हुई, जिससे विश्व राजनीति के अनेक मुद्दों के बारे में विश्व महाशक्तियाँ एक तरफ और तीसरी दुनिया के गरीब राष्ट्र दूसरी तरफ आमने-सामने खड़े हो गये। ऐसी अवस्था में महाशक्तियों के शोषण के विरुद्ध भारत गरीब राष्ट्रों की अगुवाई करता रहा है। स० रा० सघ के तत्वावधान में आयोजित विभिन्न मंचों जैसे अबटाड सम्मेलनों तथा समुद्री कानून सम्मेलनों में भारत तीसरी दुनिया के देशों को एकजुट कर महाशक्तियों की शोषणकारी नीतियों की खिलाफत कर रहा है। वह चाहता है कि नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था समानता एवं न्याय पर आधारित हो।

उपरोक्त विवक्षेण में स्पष्ट है कि विश्व शान्ति एवं सुरक्षा कायम करने के उद्देश्य से स्थापित स० रा० सघ का भारत प्रबल समर्थक रहा है। आरम्भ से ही उसने उसके हरेक शान्ति प्रयासों में भरसक समर्थन दिया है। भारत की सूझबूझ एवं रचनात्मक भूमिका के कारण जहाँ एक ओर अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय तीसरे महायुद्ध की तबाही से बचा है, वहीं दूसरी ओर तीसरी दुनिया के गरीब राष्ट्र अनेक नई चुनौतियों का मुकाबला करने में अधिक समर्थ हैं। प्रो० एम० एस० राजन का मानना है कि 'भारत जैसे गुट निरपेक्ष देशों ने स० रा० सघ में राजनय को इसलिए प्राथमिकता दी है, क्योंकि बहुपक्षीय राजनय के लिए यह सर्वोत्तम मंच है, हालांकि कभी-कभी ऐसा होता है कि पूर्णतः उभयपक्षीय समस्याओं का अवाधनीय अन्तर्राष्ट्रीयकरण हो जाता है, जैसा कि 1976 में बंगला देश ने नदी

जस के बँटवारे के प्रश्न पर किया। पर, ऐसे दुष्प्रयोग से बचा नहीं जा सकता और इन्हें अपवाद ही समझना चाहिए।

सं० रा० संघ के समक्ष आर्थिक संकट (U. N. in Economic Crisis)

सं० रा० संघ कुछ वर्षों पहले गहरे आर्थिक संकट के दौर से गुजरा। अमरीका व ब्रिटेन ने 'यूनेस्को' जैसी उसकी विशिष्ट एजेन्सी की सदस्यता तो बहुत पहले छोड़ दी, जिससे उसे इन दोनों देशों से बड़ी मात्रा में मिलने वाला चढ़ा बन्द हो गया और इस एजेन्सी के अनेक कार्यक्रमों के लिए धन की भारी तंगी पैदा हो गयी। मगर कुछ समय बाद स्वयं मातृ-संस्था सं० रा० संघ आर्थिक संकट के घेरे में आ गयी। जहाँ एक ओर अमरीका ने उसके बजट में दिये जाने वाले योगदान को 25 से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया, वहीं सोवियत संघ और पूर्वी यूरोपीय देशों ने उसके कुछ कार्यक्रमों से असहमति प्रकट कर उनके लिए चढ़ा देने से इन्कार कर दिया। कई सदस्य देश उनके लिए निर्धारित चढ़ा राशि का पूरा भुगतान नहीं कर पाये। इसका कुल मिलाकर प्रभाव यह हुआ है कि सं० रा० संघ को कार्यक्रमों और अधिकारियों-कर्मचारियों में कटौती के बारे में सोचने पर विवक्षित होना पड़ा।

सं० रा० संघ के समक्ष गहरा आर्थिक संकट अमरीकी संसद द्वारा पारित उक्त कानून से खड़ा हुआ, जिसके तहत अमरीकी सरकार को इस संगठन के बजट में अपना योगदान 25 से घटाकर 20 प्रतिशत करने को बह्ता। इस संगठन के अपने सदस्य उसके बजट में 0.01% योगदान देते रहे हैं, जबकि अमरीका, सोवियत संघ और आठ अन्य देश मिलकर 80% चढ़ा देते रहे हैं। सं० रा० संघ के बजट में अमरीका 25%, सोवियत संघ 12.22% और जापान 10.32% मदद देते रहे हैं। सोवियत संघ ने शान्ति व्यवस्था सम्बन्धी कुछ कार्यक्रमों (peace-keeping operations) से असहमत होकर 40 मिलियन डॉलर की राशि का भुगतान रोक लिया। पूर्वी यूरोप के कुछ देशों ने भी सोवियत संघ का साथ देते हुए इसका भुगतान करने से इन्कार कर दिया। 40 अन्य देश भी निर्धारित चढ़ा राशि का पूरा भुगतान नहीं कर पाये।

अप्रैल, 1986 में सं० रा० संघ की महासभा का 40वाँ अधिवेशन हुआ, जिसमें महासचिव पेरैज दी कुइयार ने बताया कि 1985 के अन्त में संगठन पर 242 मिलियन डॉलर का कर्ज था। यदि इस बारे में ठोस कदम नहीं उठाये गये तो 1986 में यह कर्ज बढ़कर 275 मिलियन डॉलर हो जायेगा। वर्ष 1984-85 के लिए 80 देशों ने निर्धारित राशि का पूरा भुगतान नहीं किया, जबकि 1985-86 के लिए मात्र 14 देशों ने ही पूरा भुगतान किया। पश्चिमी और विकासशील देशों ने सं० रा० संघ शरणार्थी, मानवीय विपत्तियों आर्थिक एवं विपदा राहत गतिविधियों के लिए 1983 में 425 मिलियन डॉलर चढ़ा दिया, जबकि 1984 में 427 मिलियन डॉलर का। सोवियत संघ और पूर्वी यूरोपीय देशों ने इन दो वर्षों में उक्त गतिविधियों के लिए एक भी डॉलर नहीं दिया।

नवम्बर, 1987 तक तो स्थिति इतनी बिगड़ गयी कि महासचिव कुइयार ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर यह घोषणा की कि सं० राष्ट्र संघ लगभग दिवालिया हो चुका है तथा उसके पास अपने माह का वेतन देने के लिए पर्याप्त धन तक नहीं है।

उन्होंने कहा कि मगटन के सबसे बड़े अगुदानी तथा देनदार अमरीका ने अपने हिस्से का 34 करोड़ 28 लाख डालर अभी तक जमा नहीं कराया है। मगटन के तत्कालीन 159 सदस्य राष्ट्रों में से 93 ने अभी तक अपने हिस्से का 45 करोड़ 64 लाख डालर का भुगतान नहीं किया, जबकि वे उसे देने का वचन दे चुके हैं। यह राशि मगटन के मानाना बचत 80 करोड़ डालर की लगभग आधी है। दिसम्बर, 1987 में कुदियार ने कहा कि स० रा० सघ अपने अभूतपूर्व वित्तीय सङ्कट से निपटने के लिए अब खुले बाजार से कर्ज लेने की सम्भावना पर विचार कर रहा है। वह ऋण-मित्र अथवा बाढ़ जारी किये जाने के लिए महात्ममा से अनुमति मागे जाने पर भी विचार कर रहा है। कुदियार चाहते थे कि स० रा० सघ की महानममा उग्र पाँच करोड़ डालर का ऋण लेने की इजाजत दे दे। उन्मत्तनीय है कि स० रा० सघ ने इससे पहले खुले बाजार में कभी भी ऋण लेने का प्रयास नहीं किया।

अफगान धरणाधी आदि मामलों पर अभहमति के कारण जहाँ एक ओर सोवियत सघ और पूर्वी यूरोपीय देश चढ़ा देने से इकार करते रहे, वहीं दूसरी तरफ अमरीका, फिन्लैन्ड और नाभीरिया से सबद्ध मसलों पर अडगा डानरर योगदान रोकता रहा है। अमरीका का कहना है कि जब तक उसे मनदान में प्रभावी भूमिका नहीं दी जाती, तब तक वह पाँच प्रतिशत कटौती जारी रखेगा। उनमें और भी कटौती की घमकी दी है। हालांकि मुरक्षा परिषद् में पाँच बड़ी शक्तियों को मनदान में निवेद्याधिकार (वीटो) प्राप्त है, लेकिन अन्यत्र 'एक देश, एक मत का मिढान्त, सगटन की स्थापना के वक्त से ही लागू है। अमरीका का तर्क था कि नई राष्ट्र स० रा० सघ को अपने निहित स्वार्थों, प्रोपगेंडा और अमरीका के विलाफ मपर्य के लिए साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं।

विभिन्न राष्ट्रों द्वारा चढ़े में कटौती या कनिषय कार्यक्रमों के लिए चढ़ा देने से इकार करते में स० रा० सघ के कुछ कार्यक्रमों पर अमल में बाधाएँ लड़ी हो गई। मगर बाद में अमरीका, सोवियत सघ, जापान आदि ने मकारात्मक हर अपनाते हुए स० रा० सघ को 'समुचित चढ़ा' देना शुरू कर दिया, त्रिमने उमका आधिक सङ्कट काफी कम जरूर हुआ, किन्तु आज भी उनके पाम आधिक समापन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। इस मुद्दे पर विचार के लिए बनी 18 सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट दी। उनके प्रमुख गुणाव थे—मगटन के अधिकारियों-कर्मचारियों में 15 प्रतिशत की कटौती, कम बैठकों का आयोजन, कम दस्तावेज बनाना, नौकरशाही का पुनर्गठन आदि।

इन मकारात्मक सुझावों पर अमल होना ही चाहिए, मगर सगटन के कुछ बेनुके कार्यक्रमों पर भी रोक लगनी चाहिए। मतदान में प्रभावी भूमिका सम्बन्धी अमरीका की माग नहीं मानी जा सकती, क्योंकि सगटन की स्थापना के वक्त मुरक्षा-परिषद् को छोड़कर अन्यत्र 'एक राष्ट्र, एक मत का मिढान्त' तय किया गया था। इसे अब बदलना व्यावहारिक नहीं क्योंकि किसी बड़े राष्ट्र को हर जगह उमके योगदान को देखकर मनदान में प्रभावी भूमिका देने से उनकी मनमानियाँ बढ़ेंगी और नई परेमानियाँ पैदा होंगी। फिर भी सगटन में अनेक मरचनात्मक सुधार कर उमर कार्यक्रमों को जरूर अधिक सार्थक बनाया जा सकता है।

सं० रा० संघ की विफलताएँ (Failures of the U. N.)

सं० रा० संघ की जहाँ अनेक सफलताएँ रही हैं, वहाँ अनेक क्षेत्रों में यह विफल भी रहा है। इन विफलताओं को इसकी आंशिक सफलता भी माना जा सकता है। संक्षेप में उसकी विफलताएँ निम्नांकित हैं—

(अ) यह शस्त्रीकरण की होड़ को रोकने में असफल रहा है।

(ब) यह अपने जीवन के साढ़े चार दशक बीत जाने के बावजूद दक्षिण अफ्रीका में अल्पसंख्यक गोरो को हटाकर बहुसंख्यक काबो को शासन सत्ता सौंपने में अब तक सफल नहीं हुआ है।

(स) छह अनेक स्थानों पर युद्ध रोकने में अनश्वर सफल हुआ है, किन्तु समस्या का स्थायी हल ढूँढ पाने में विफल रहा है—मसलन, भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर-समस्या।

(द) विश्व के बरीब और अमीर देशों के बीच विवादास्पद मुद्दों के बारे में उसने अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं की है—मसलन, नई विश्व अर्थव्यवस्था, समुद्री सम्पदा का अधिकार, मोहन आदि।

सं० रा० संघ की असफलता के कारण

सं० रा० संघ की असफलता के लिए अनेक कारण जिम्मेदार रहे हैं, जिनमें से प्रमुख निम्नांकित हैं—

(अ) इसका ढाँचा दोषपूर्ण है। मसलन, 'वीटो' के अधिकार से सुरक्षा परिषद में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है जिससे वह विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए समुचित कार्रवाई नहीं कर पाता।

(ब) अनेक राष्ट्रों के संकीर्ण राष्ट्रीय हितों के कारण वह कुशल ढंग से कार्य नहीं कर पाया है।

(स) उसके पास कार्यपालिका शक्ति नहीं होने के कारण वह अपने निर्णयों को मनीभाँति चिमान्वित नहीं कर पाया है।

(द) विश्व की बड़ी शक्तियों ने सं० रा० संघ की विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाये रखने में अपेक्षित सहयोग नहीं दिया। उन्होंने उसको कुछ राष्ट्रीय हितों के कारण प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बना दिया।

(य) स्वतंत्र बिल नहीं होने के कारण वह सामाजिक एवं आर्थिक बह्याण के अनेक कार्य सम्पादित नहीं कर सका।

(र) महाशक्तियों ने सं० रा० संघ के माध्यम को छोड़कर द्विपक्षीय समझौते कर समस्याएँ सुलझाने की अनेक कोशिशें की हैं। सॉल्ट-एक और सॉल्ट-टो समझौते इसके जीते-जागते उदाहरण हैं। इससे सं० रा० संघ के प्रभाव का ह्रास हुआ है।

सं० रा० संघ की उपलब्धियाँ (Achievements of the U. N.)

सं० रा० संघ की प्रमुख उपलब्धियों को संक्षेप में निम्नांकित बिन्दुओं में अभिव्यक्त किया जा सकता है—

(1) स० रा० सभ ने अधिकांश अन्तर्राष्ट्रीय सक्टो में दूरदर्शितापूर्ण कदम उठाकर विश्व को तीसरे महायुद्ध के विनाश में बचाया।

(2) इसने विश्व शान्ति एवं सुरक्षा स्थापित करने में सराहनीय कार्य किया है।

(3) इसने राष्ट्रों में आपसी चहुँपुंसी सहयोग बढ़ाकर अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव का वातावरण तैयार किया।

(4) निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में इसने अनेक प्रयाग किये हैं।

(5) मानवाधिकार-रक्षा में इसने अनेक कदम उठाये हैं।

(6) राष्ट्रों में आपसी तनाव की स्थिति में यह अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क-स्थल या मंच प्रदान करता है।

(7) इसने विश्व-स्तर पर व्यापक रूप से अन्तर्राष्ट्रीय भावना विकसित की है।

(8) इसने अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास में योगदान दिया है।

(9) इसने राजनीतिक कार्यों के अतिरिक्त अनेक सामाजिक तथा आर्थिक कार्य सम्पादित किये हैं, जिनके बिना विश्व शान्ति एवं सुरक्षा अघूरी रह जाती।

स० रा० सभ के समक्ष नई चुनौतियाँ (New Challenges before the U N)

स० रा० सभ की स्थापना अक्टूबर, 1945 में हुई थी। तब की ओर आज की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थितियों में अनेक परिवर्तन आ गये हैं। इससे संगठन के समक्ष अनेक नई चुनौतियाँ उपस्थित हो गयी हैं जिनका मुकाबला करना समय की सबसे बड़ी पुकार है। ये नई चुनौतियाँ संक्षेप में निम्नावित हैं—

(अ) घातक परमाणु हथियारों का निर्माण विशाल मात्रा में बढ़ रहा है। इसकी रोकना बहुत जरूरी है।

(ब) समुद्री सम्पदा के दोहन को लेकर विकसित और विकासशील देशों में मतभेद बढ़ रहे हैं। इनके बीच सहमति स्थापित कराना आवश्यक है।

(स) विकासशील देशों के पास आर्थिक विकास के लिए तकनीकी ज्ञान की कमी है, जिसकी विकसित देश देने की तैयार नहीं हैं। इस सम्बन्ध में स० रा० सभ को ठोस कदम उठाना चाहिये।

(द) विकसित देश विकासशील देशों के परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग में अनेक प्रकार की बाधाएँ पैदा कर रहे हैं। इनको स० रा० सभ द्वारा रोकना जाना चाहिए।

(य) विकसित देश विकासशील देशों में बच्चे माल को अत्याधिक सस्ते दामों पर खरीदने हैं तथा आगान छूने मंहंगे दामों पर अपना तैयार माल खरीदने के लिए उन्हें विवश करते हैं। इस बारे में स० रा० सभ को ठोस प्रयाग करना चाहिए।

स० रा० सभ को मजबूत बनाने के मुद्दाव

स० रा० सभ ने जहाँ अनेक सफलताएँ हासिल की हैं वहीं कुछ असफलताएँ भी रही हैं। इन असफलताओं के लिए जिम्मेदार कारणों का खला लगाकर उमड़ो मजबूत करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इस मिलमिले में बतियप गुंजाव

निम्नांकित है—

(1) चार्टर में संशोधन व्यवस्था को आसान बनाया जाये—सं० रा० संघ के चार्टर में संशोधन के लिए अत्यन्त कठोर व्यवस्था की गयी है। किसी भी संशोधन के लिए महासभा के 2/3 बहुमत और सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों सहित 9 अन्य सदस्यों के बहुमत का समर्थन आवश्यक है। ऐसी कठोर व्यवस्थाओं के कारण बदनती अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में चार्टर में आवश्यक संशोधन नहीं हो सके। अतः चार्टर में संशोधन व्यवस्था को आसान किया जाना चाहिये ताकि विश्व शान्ति और सुरक्षा स्थापित कराने में संगठन प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें।

(2) चार्टर की व्याख्या की समस्या को निराकरण किया जाये—लोकतन्त्रीय देशों में सविधान की आधिकारिक व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया जाता है। किन्तु सं० रा० संघ चार्टर की धाराओं की आधिकारिक व्याख्या करने का अधिकार किसे है, इस बारे में निश्चित व्यवस्था का अभाव है। परिणाम-स्वरूप संगठन के सदस्य राष्ट्रों द्वारा मकीर्ण राष्ट्रीय हितों के बलीभूत होकर चार्टर की व्यवस्थाओं की मनमानी व्याख्या करने का खतरा सदैव बना रहता है। महामभा के पारित प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं या नहीं, इस प्रश्न पर अभी तक सहमति नहीं हो पायी है। अतः क्यों नहीं अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को चार्टर की आधिकारिक व्याख्या करने का अधिकार सौंपा जाये।

(3) सदस्यता का प्रश्न हल किया जाय—चार्टर के अनुच्छेद 4 में सदस्यता सम्बन्धी विषय में कहा गया है कि दृष्टिकोण राष्ट्र शान्ति-प्रेमी और चार्टर में दिये गये दायित्वों को पूरा करने की इच्छा और योग्यता रखता हो। इसके अलावा पाँच स्थायी सदस्यों महित सुरक्षा परिषद के बहुमत की शिफारिश और महामभा के दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत का समर्थन आवश्यक है। सं० रा० संघ को अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का स्वरूप देने के लिए उक्त व्यवस्थाएँ अनुचित नहीं हैं, किन्तु व्यवहार में इनका बड़ी शक्तियों ने दुरुपयोग कर अनेक देशों को सदस्य बनने से रोका है। सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्यों की आम सहमति की व्यवस्था सं० रा० संघ के सदस्य बनाने के लिए बहुत सरल है। इसे समाप्त किया जाना चाहिये ताकि इसकी योग्यता को पूरा करने वाले राष्ट्रों को सदस्यता प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े।

(4) क्षेत्रीय संगठनों के निर्माण करने की व्यवस्था में सुधार हो—चार्टर के अनुच्छेद 51 एवं 52 में सदस्य राष्ट्रों को क्षेत्रीय संगठन बनाने की इजाजत दी गयी है। साथ ही यह भी कहा गया है कि क्षेत्रीय संगठन सं० रा० संघ के सहायक के रूप में कार्य करेंगे। इसका प्रमुख उद्देश्य यह था कि क्षेत्रीय संगठनों द्वारा सदस्य राष्ट्र आपसी सहयोग करें तथा क्षेत्रीय समस्याओं को इनके जरिये सुलझाएँ। किन्तु व्यवहार में यह उल्टा साबित हुआ है। नाटो, वारसा आदि क्षेत्रीय सैनिक संगठनों ने जहाँ एक ओर क्षेत्रीय समस्याओं को भड़काया वहीं दूसरी ओर महायुद्ध के रूप में कार्य करने के बजाय उन्होंने सं० रा० संघ के मागने अनेक संकट पैदा किये। चार्टर में ऐसे क्षेत्रीय संगठनों को स्थापित करने की स्वतन्त्रता को समाप्त कर दिया जाये ताकि अन्तर्राष्ट्रीय तनाव से बचा जा सके।

(5) आम के स्वतन्त्र एवं विद्रोहसन्धीय स्रोतों की व्यवस्था हो—सं० रा० संघ के आम के स्रोत स्वतन्त्र एवं विद्रोहसन्धीय नहीं हैं। सदस्य राष्ट्र अपनी इच्छा

एव सामर्थ्य के आधार पर स्वर्षों के लिए धनराशि देने हैं। बड़ी शक्तियाँ छोटे राष्ट्रों की अपेक्षा ज्यादा धनराशि देती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि सगठन अपने कार्यों की सम्पादन करने के लिए बड़ी शक्तियों पर निर्भर हो जाता है। वह स्वतन्त्र रूप से कार्य नहीं कर पाता। स्वेच्छ और कारो सक्तों का उदाहरण ही लिया जाये, जहाँ श्रमश्रम प्राप्त और सोवियत संघ ने शान्ति सेनाओं (यु० एन० इ० एफ०) के स्वर्षों के अपने हिस्से का यह तर्क देकर भुगतान नहीं किया कि चार्टर की व्यवस्थाानुसार इन्हें सुरक्षा परिषद द्वारा प्राधिकृत नहीं किया गया है। इस बटु अनुभव के बाद आवश्यक हो गया है कि स० रा० संघ के लिए अन्तर्राष्ट्रीय जतमार्गों एव मानियों पर कर लपाने तथा अन्य अनेक निश्चित अनुदान व्यवस्थाओं द्वारा स्वतन्त्र एव विश्वमनीय आय के स्रोत तय किये जायें।

स० रा० संघ का भविष्य (Future of the U. N.)

स० रा० संघ के भविष्य के बारे में विद्वानों के मोट तौर पर दो प्रकार के विचार हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह सगठन अधिकतर अन्तर्राष्ट्रीय मसलों के हल में असफल रहा है जिससे उसका भविष्य उज्ज्वल नहीं माना जा सकता। किन्तु अधिकांश विद्वानों का विचार है कि उसका भविष्य उज्ज्वल है। वे यह बात स० रा० संघ की असफलताओं का हवाला दते हुए तुलनात्मक मूल्यांकन करने प्रवृत्त करते हैं। इस बारे में बर्नार्ड एम० आइसेनबर्गर का कहना है कि 'राष्ट्रों ने भते ही कुछ क्षणों के लिए हमकी अपेक्षा की हो किन्तु शायद वे हमसे लौट आने हैं, क्योंकि यही एक ऐसा माध्यम है जहाँ विश्व की समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है।'¹ प्लानो एव रीग्स (Plano and Riggs) के अनुसार 'अनेक बार तो स० रा० संघ की उपस्थिति मात्र ने ही प्रतिद्वन्द्वियों को मनुष्यत्व किया है और घटनाओं की विश्वासों पर प्रभाव डाला है।'² पामर एव परकिंस का मानना है कि स० रा० संघ ने अपने आपको राष्ट्रों के जीवन में अपरिहार्य बना दिया है।³ इस प्रकार स० रा० संघ अन्तर्राष्ट्रीय समाज में एक कार्यात्मक वास्तविकता (a working reality) बन गया है।

अमल में स० रा० संघ के भविष्य की सराव बनाने वाले विद्वानों अनेक बातों का ध्यान करते हैं। वे सगठन की उन मर्यादाओं-सीमाओं को नजरअन्दाज करते हैं जिस कारण वह विश्व शान्ति एवं सुरक्षा स्थापित करने में अपेक्षित सफलताएँ हासिल नहीं कर पाया। उसकी प्रमुख मर्यादाएँ-सीमाएँ निम्नांकित हैं—

(क) राष्ट्रीय सरकार की तरह स० रा० संघ कोई विश्व सरकार नहीं है, जिस कारण वह अपने निर्णयों को मानन के लिए राष्ट्रों को बाध्य नहीं कर सकता।

(ख) राष्ट्रीय सरकार के समान उसके पास अपनी सेना नहीं है जो बड़ी आवश्यकता होने पर उचित सैनिक बलवाही कर सके।

¹ बर्नार्ड एम० आइसेनबर्गर की पुस्तक पृष्ठ 34 में पृ० 6।

² प्लानो एव रीग्स की पुस्तक पृष्ठ 3 में पृ० 56।

³ 'The U N has made itself indispensable in the lives of nations'

—पामर एव परकिंस की पुस्तक पृष्ठ 3 में पृ० 378।

(ग) महाशक्तियों को 'वीटो' का अधिकार दे देने से यह अनेक अन्तर्राष्ट्रीय संघटो में असमर्थ हो जाता है।

(घ) सं० रा० संध विश्व सरकार न होकर राष्ट्रों के मध्य घाद-विवाद के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय मंच की सुविधा प्रदान करता है।

इस प्रकार यदि सं० रा० संध की उपरोक्त मर्यादाओं को मद्दे नजर रखते हुए उसकी असफलताओं और सफलताओं का मूल्यांकन किया जाये तो निसकोच कहा जा सकता है कि उसका भविष्य उज्ज्वल है। अनेक असफलताओं के बावजूद उसकी सफलताएँ भी कम नहीं हैं, जिससे आशा की जा सकती है कि वह अपनी स्थापना के घोषित उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल होगा। यदि हम चाहते हैं कि सं० रा० संध 21वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाये और तीसरी दुनिया के देश इसकी गतिविधियों में महाशक्तियों के पिछलग्गू भर न बने रहे तो नवोपित राष्ट्रों के नेताओं को अपने दिलों दिमाग अर्द्धी तरह टटोलने होंगे तथा उन्हें अपना अभिगम अनुशासित, मानवाधिकारों का पोषण करने वाला और जनतान्त्रिक रखना होगा।

नवा अध्याय निशस्त्रीकरण

विनाशकारी युद्धों के पीछे सम्प्रीकरण की होड़ प्रमुख कारण रही है। इसी सदी में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुए, जो राष्ट्रों द्वारा सम्प्रीकरण के क्षेत्र में शक्ति-सन्तुलन की सीमा लाघ जाने की प्रक्रिया या उसमें जुड़े हुए भय के कारण भड़े थे। पहले विश्व युद्ध के बाद पेरिस सान्नि-सम्मेलन में मित्र राष्ट्रों के प्रति-निधियों ने जर्मनी और उसके मित्र देशों को विमैन्यीकृत (Demilitarised) घोषित करके उनकी सैनिक शक्ति और सम्प्रीकरण की सीमा पर रोक लगा दी थी। किन्तु इससे यूरोप के देशों में सम्प्रीकरण की होड़ कम नहीं हुई। अतएव 1920 और 1936 के बीच अनेक सम्मेलनों के द्वारा विश्व की प्रमुख शक्तियों ने निशस्त्रीकरण की दिशा में कुछ निर्णय लिये। उनका कारणर माबित न होना द्वितीय विश्व युद्ध को भड़काने का प्रमुख कारण था। इस कारण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही मित्र-राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने विश्व में कारणर ढग से निशस्त्रीकरण लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण बातचीत कर ली थी।

द्वितीय विश्व युद्ध की भयानक विभीषिका के बावजूद विश्व का साम्यवादी और गैर-साम्यवादी समूहों में बँटना निशस्त्रीकरण का घोर शत्रु माबित हुआ। सोवियत संघ और अमरीका दोनों परमाणु शस्त्रों की होड़ में एक-दूसरे को पीछे छोड़ दन की नीयत में अधिक-अधिक परमाणु सम्प्राप्ति जमा करने लगे, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और चीन भी शामिल हो गये। परमाणु आगुशों की विनाशकारी शक्ति को मद्दे नजर रगन हुए प्रसिद्ध वैज्ञानिक-दार्शनिक आइंस्टीन न कहा था—‘तीसरा विश्व युद्ध यदि परमाणु हथियारों से लड़ा गया, तो मानव-सभ्यता जटमूल से नष्ट हो जायेगी और उसके बाद कोई भी आगामी युद्ध पचरी और लाटियों में ही लड़ा जायेगा।’

सम्प्रास्त्रों की प्रतिस्पर्धा के बावजूद बड़ी शक्तियों ने निशस्त्रीकरण और परमाणु शस्त्रों के प्रसार पर रोक लगाने के लिए समय-समय पर कोशिशें की, जिनका दापरा स० रा० संघ के सहज और फिर उसके बाहर भी फैल गया। इस शक्ति में महाशक्तियों द्वारा परमाणु प्रसार रोक संघि तथा अमरीका और सोवियत संघ के बीच सान्ट-सन्त्रियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। फिर भी विश्व शक्तियों के बीच आगामी मनमुटाव इतने गहरे हैं कि समस्त मानव-जाति की दुच्छा के बावजूद वे निशस्त्रीकरण पर कोई निश्चित कार्यवाही नहीं कर पाये हैं।

निशस्त्रीकरण की परिभाषा (Disarmament Definition)

निशस्त्रीकरण की सही एवं स्पष्ट परिभाषा देने में इस विषय में सम्बन्धित विद्वान आज तब असफल रहे हैं। फिर भी मोट तौर पर कहा जा सकता है कि

निशस्त्रीकरण विनाशकारी शस्त्रास्त्रों पर रोक के लिए दो देशों की सरकारों द्वारा सीधी बातचीत एवं प्रयत्नों से लिये गये उक्त दिशा में ऐसे निर्णयों की प्रतिपादित करता है, जिन्हें लागू करने में केवल शस्त्रों, बल्कि सैनिक साज-सामग्री और सेनाओं की वृद्धि, उत्पादन और नव-अन्वेषणों पर रोक लगायी जाती हो। उक्त ढाँचे में ही निशस्त्रीकरण एक में अधिक राष्ट्रों के बीच आपसी बातचीत द्वारा भी लागू किया जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किये गये प्रयत्नों में स० रा० सघ के माध्यम से विदेश के सभी देशों ने निशस्त्रीकरण की दिशा में अपने मत प्रस्तुत किये हैं और बहुमत के निर्णयों को माना है। परमाणु हथियारों से सम्पन्न राष्ट्रों के 'परमाणु क्लब' ने भी समय-समय पर परमाणु शस्त्रों की सीमाओं पर रोक तथा विस्फोटों के कुछ निश्चित नियम बनाने की दिशा में बातचीत कर कुछ निर्णय लिये हैं। इसके अतिरिक्त दोनों महाशक्तियों—सोवियत सघ और अमरीका ने आपसी बातचीत से भी इसे सुलझाने की कोशिश की है। किन्तु खेद है कि परम्परागत शस्त्रों पर रोक के लिए कोई ठोस बातचीत अब तक नहीं हो सकी है जबकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होने वाले युद्धों में सर्वाधिक विनाश इसी परम्परागत हथियारों से हुआ है।

निशस्त्रीकरण के विभेद (Types of Disarmament)

'निशस्त्रीकरण' शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किये जाने से इसका निश्चित अर्थ तथा परिभाषा तय करने में अनेक समस्याएँ खड़ी हो जाती हैं। इस कारण इससे मिलते-जुलते शब्दों के अर्थ का तुलनात्मक अध्ययन करना उचित होगा। ये शब्द हैं—गुणात्मक निशस्त्रीकरण (Qualitative Disarmament), मात्रात्मक निशस्त्रीकरण (Quantitative Disarmament), सामान्य निशस्त्रीकरण (General Disarmament), व्यापक निशस्त्रीकरण (Comprehensive Disarmament) और हथियार नियन्त्रण (Arms Control)। इन शब्दों का अर्थ तुलनात्मक दृष्टि से आगे पृष्ठ पर दी गई तालिका से स्पष्ट किया जा सकता है।

निशस्त्रीकरण की आवश्यकता

दुनिया में आज इतने घातक शस्त्रास्त्र बने गये हैं कि उनके प्रयोग से कुछ मिनटों में व्यापक स्तर पर विनाश सम्भव है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आशा जगी थी कि राष्ट्र अपने सर्वाधिक हिन त्याग कर अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बचावा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अस्त्रीकरण की होड़ तेज होती गयी। इस प्रकार, निशस्त्रीकरण बड़ी जरूरतों से जखरी समझा गया। प्रमुख कारण निम्नांकित हैं—

(1) शस्त्रीकरण से युद्ध की सम्भावना—विश्व राष्ट्रों में शस्त्रों की होड़ के कारण युद्ध की सम्भावना बढ़ जाती है जिससे अपार जन एवं धन की हानि होती है। प्रथम विश्व युद्ध होने का प्रमुख कारण भी राष्ट्रों में शस्त्रों की होड़ ही था। उत्पन्न-उत्पादन पर असीमित व्यय कर शासक उनका युद्ध में इस्तेमाल करके जनता को यह दिशानि है कि इस पर किया गया खर्च राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मामले पर था। मसलन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमरीका ने जापान के हिरोशिमा और

नागामाकी नगरी पर बम गिराये। इस बम के उत्पादन पर अमरीका ने अरबो डालर व्यय किया था। बम का प्रयोग कर अमरीकी शासक ने अपनी जनता को परोक्ष रूप से यह दर्शाना चाहा था कि 'सब' किया गया धन व्यर्थ नहीं गया। इसी बलोड में टीक ही कहा है—'शस्त्रों से राष्ट्र-नेताओं को युद्ध में कूटने का प्रलोभन हो जाता है।'¹ वन निशस्त्रीकरण का मार्ग अपनाकर विश्व समाज को महायुद्ध से होने वाली अपार जन एवं धन की हानि को रोका जाना अत्यन्त जरूरी है।

निशस्त्रीकरण के विभेद

गुणात्मक निशस्त्रीकरण	'कुछ सात किम्म के शस्त्रों पर सीमा या 'रोक' लगाने को गुणात्मक निशस्त्रीकरण कहा जाता है।
मात्रात्मक निशस्त्रीकरण	'समस्त प्रकार के शस्त्रों के नियन्त्रण' को मात्रात्मक निशस्त्रीकरण कहा जाता है।
सामान्य निशस्त्रीकरण	इसमें सभी या अधिकांश महाशक्तियाँ भाग लेती हैं, किन्तु उन्हें लिए यह जरूरी नहीं है कि वे समस्त प्रकार के शस्त्रों के त्याग के लिए प्रतिबद्ध हों।
व्यापक निशस्त्रीकरण	इसमें समस्त प्रकार के सभी शस्त्रों का नियन्त्रण व निषेध होना है। इसे पूर्ण या सम्पूर्ण निशस्त्रीकरण (total-disarmament) भी कहा जाता है। इसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था लाना है जिसमें युद्ध संभवनिष्ठ सभी मानवीय और मौलिक साधन समाप्त कर दिये जायें।
शस्त्र नियन्त्रण	शस्त्र नियन्त्रण शब्द मरिप्य के शस्त्रों के नियन्त्रण के सम्बन्ध में प्रयुक्त किया जाता है। निशस्त्रीकरण, शस्त्रों पर नियन्त्रण करने का प्रयत्न करना है, जबकि शस्त्र नियन्त्रण शस्त्रों की होड़ रोकने का प्रयत्न है।
निशस्त्रीकरण	सीधे तौर पर निशस्त्रीकरण का प्रयोग शस्त्रों की सीमा निश्चित करने या उनको नियन्त्रित करने या उन्हें घटाने के अर्थ में होता है।

(2) शस्त्रीकरण से अन्तर्राष्ट्रीय तनाव उत्पन्न होना—राष्ट्रों में शस्त्र-निर्माण की होड़ अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा में गड़बड़ करती है। इससे अन्तर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ता है। विभिन्न राष्ट्रों में राष्ट्रीय हितों का टकराव अस्वाभाविक तथ्य नहीं है। इस टकराव में शस्त्रीकरण आग में घी का काम करता है और अन्तर्राष्ट्रीय तनाव उत्पन्न होता है। इसी ध्यान को ध्यान में रखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रख्यात जानकार हैडली बुल ने कहा कि 'शस्त्रों की होड़ स्वयं ही तनाव की

¹ 'The instant availability of armaments makes it feasible or even tempting for statesmen to plunge into war' —Imre L. Claude, Jr., *Swords into Ploughshares*, (New York, 1971), 237

अनिव्यक्ति है।¹² इसलिए निरस्त्रीकरण द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय तनाव को बढ़ने से रोका जा सकता है।

(3) शस्त्रीकरण पर असीमित खर्च से जन कल्याणकारी कार्यों की उपेक्षा—शस्त्र उत्पादन में असीमित समाधन व्यय किये जाते हैं। विश्व के छोटे-बड़े सभी राष्ट्र ऐसा करते हैं। बनेक बड़े देशों द्वारा अरबों डॉलर खर्च करके ऐसे परमाणु बम एवं प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण किया गया है, जिनका भविष्य में प्रयोग किये जाने की कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होती। कुछ समय बाद ये अस्त्रास्त्र नष्ट कर दिये जायेंगे और नई खोज करके और महँगे अस्त्रों का निर्माण किया जायेगा। दूसरी तरफ अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय व्यापक रूप से भ्रूखपरी, बेरोजगारी आदि जैसी गम्भीर समस्याओं से पीड़ित है। यदि शस्त्रीकरण पर किया जाने वाला अनाप-शनाप खर्च जन-कल्याणकारी कार्यों पर लगाया जाये तो उक्त मानवीय समस्याएँ सुलझायी जा सकती हैं। यह मानवता की महान सेवा होगी। इस प्रकार शस्त्रीकरण पर किया जाने वाला असीमित खर्च निरस्त्रीकरण का मार्ग मगनाकर बचाया जा सकता है और उसे जन-कल्याणकारी कार्यों पर खर्च किया जाना चाहिए। सेमूर मैलमैन ने अस्त्रों की होड़ के चिकित्सा के रूप में 'पोस रैस' अर्थात् शांति की होड़ का विचार सुझाया है। उसका कहना है कि हमियारों पर खर्च होने वाले संसाधन विश्व में औद्योगिकीकरण के विस्तार और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने पर लगाये जायें।¹³ कमोबेश यही विचार एमिटार्ड एटजियोनी से भी सुझाया है। उनका कहना है कि 'अमरीका के लिए सोवियत संघ के साथ हो रहे 'युद्ध' में विजय पाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वह अल्प विकसित देशों के विकास कार्यक्रमों में मदद देने में सोवियत संघ के साथ प्रतियोगिता करे।'¹⁴ इस प्रकार यदि अस्त्रों पर होने वाला खर्च मृजनात्मक विकास कार्यक्रमों में लगाया जाये, तो निरस्त्रीकरण सम्पूर्ण मानव समाज की भलाई में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है।

(4) शस्त्रीकरण नैतिकता के खिलाफ—शस्त्रीकरण युद्ध को जन्म देकर मानव समाज को विनाश की ओर दबेलता है। इस कारण यह नैतिकता के खिलाफ है। बर्न धर्म गुरुजों, सामाजिक नायवर्ताओं तथा प्रबुद्ध लेखकों का तर्क है कि किसी भी अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधन भी उतने ही विधुष्ट होने चाहियें। ममलन, यदि कोई राष्ट्र शत्रु देश से सुरक्षा के लिए अस्त्रों का उत्पादन करता है तो यह नैतिकता के खिलाफ है, क्योंकि ऐसा शस्त्रीकरण युद्ध को जन्म देता है। युद्ध रूढ़ी अनुचित साधन से किसी भी अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति नैतिक रूप से न्यायोचित नहीं ठहरायी जा सकती।¹⁵

(5) शस्त्रीकरण से अन्य देशों में हस्तक्षेप—शस्त्रीकरण दूसरे देशों द्वारा हस्तक्षेप का मार्ग भी प्रशस्त करता है। विश्व के छोटे राष्ट्र बड़े राष्ट्रों से शस्त्र तथा

¹² 'Arms race itself is a manifestation of inherent tension and hence disarmament can be brought only in the wake of a political agreement'—Hedley Bull, *The Control of the Arms Race*, (London, 1961), 7-8

¹³ विस्तृत विश्लेषण के लिए देखें—Seymour Melman, *The Peace Race* (New York, 1962).

¹⁴ देखें—Amos Etzioni, *Winning Without War* (New York, 1964).

¹⁵ नैतिक दृष्टि के विस्तृत विश्लेषण के लिए देखें—Victor Gollancz, *The Devil's Repertoire or Nuclear Bombing and the Life of Man* (London, 1958)

राष्ट्रीय शोधोपयोगिता का आकाश करते हैं। आम तौर पर यह देखा गया है कि बड़े राष्ट्र शस्त्र-निर्माता और शस्त्र सहायता को राजनीतिक दबाव के साथ देते हैं, ठाकिए परोक्ष रूप से प्राप्तकर्ता-देश दाता-देश पर निर्भर रहें। यही नहीं, शस्त्र-निर्माता एवं शस्त्र सहायता के जरिये बड़े देश छोटे देशों की अर्थव्यवस्था में भी घुनपैठ करते हैं। नमनन अमरीका ने 'नाटो', 'निएटो', 'नेन्टो' तथा मोल्डोव सच ने 'दारना पैक' द्वारा इनके मरुस्थ-राष्ट्रों को शस्त्र निर्माता किये एवं शस्त्र सहायता दी। उन्होंने इनके जरिये उन्हें विश्व में लेकर उनकी अर्थव्यवस्था में घुनपैठ की। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बाहरी घुनपैठ उनको दूसरी पर निर्भर बना देती है और यह कई बार राजनीतिक हत्याओं का भी मार्ग प्रशस्त करती है। अब तीसरी दुनिया के गरीब मुल्कों में बाह्य हस्तक्षेप रोकने के लिए आवश्यक है कि शस्त्रीकरण की नीति छोड़कर निराशस्त्रीकरण के मार्ग को अपनाया जाये।

(6) शस्त्रीकरण से आर्थिक विकास का मार्ग अवरोध होना—शस्त्रीकरण पर राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च होने में बिनाशकारी तीसरी दुनिया के विकासशील देशों के आर्थिक विकास का मार्ग अवरोध हो जाता है। अफ्रीका, एशिया, लातीनी अमरीकी महाद्वीप के राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध के बाद औद्योगिकीकृत साम्राज्य के शत्रु से मुक्त हुए थे। इस दानना के दौरान औद्योगिकीकृत शक्तियों ने उन पर राजनीतिक रूप से शासन ही नहीं किया बल्कि उनकी अर्थव्यवस्था को भी अपने नियंत्रण में रखा। उन्होंने उनका अनीमित आर्थिक जोड़ा दिया। स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय होने के बाद अब तीसरी दुनिया के देशों को अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने पर सर्वाधिक जोर देना चाहिए। ऐसा स्वतंत्र आर्थिक विकास के माध्यम से ही सम्भव है। जब इन गरीब राष्ट्रों द्वारा शस्त्रीकरण पर अनीमित व्यय किया जायेगा, तो स्वाभाविक है कि आर्थिक विकास की उद्देश्य होगी। अतएव शस्त्रीकरण त्याग कर निराशस्त्रीकरण नीति को अपनाया जाना तीसरी दुनिया के देशों के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें वे अपने समाधान ज्यादा में ज्यादा आर्थिक विकास में लगा सकेंगे।

निराशस्त्रीकरण की आलोचना

निराशस्त्रीकरण का मतलब इतना अधिक जटिल है कि उनकी अनेक भाषाओं पर आलोचना की जा सकती है। प्रमुख तर्क निम्नांकित हैं।

(1) आतंक के समुत्पन्न (Balance of Terror) से युद्ध न होना—अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रख्यात लेखक क्विन्सी राइट का कहना है कि 'निराशस्त्रीकरण' में सम्भवतः युद्ध अधिक होने की प्रवृत्ति पैदा होगी। यह आगे बढ़ते हैं कि 'युद्ध की सम्भावना उम समय तक अधिक रहती है जब राष्ट्रों के पास शस्त्र कम हो।'। क्विन्सी राइट के तर्कों को यह कहकर आगे बढ़ाया जा सकता है कि मान लो यदि दो राष्ट्रों में परस्पर शत्रुता है। यदि एक के पास हथियार कम या नहीं है और दूसरा राष्ट्र हथियारों में सैन्य है तो ऐसी अवस्था में दूसरा राष्ट्र पहले देश पर सैनिक आक्रमण करने में नहीं चूकेगा। दूसरी तरफ यदि दोनों राष्ट्रों के पास हथियार हैं तो वे अनीमित-अनि इस तथ्य में परिवर्तित रहेंगे कि सैनिक संपर्क दोनों के लिए आनन्ददायी होगा। इसमें दोनों ही बर्बाद हो जायेंगे। ऐसी स्थिति की 'आतंक का

सन्तुलन' कहा जाता है। इसमें शत्रु-राष्ट्र एक-दूसरे को सैनिक ताकत से आतंकित होकर सैनिक आक्रमण का खतरा मोल नहीं लेते। वर्तमान में परमाणु हथियारों से लैस अमरीका और सोवियत संघ जैसी महाशक्तियाँ भी इसी 'आतंक के सन्तुलन' के कारण सीधे सैनिक संघर्ष का मार्ग नहीं अपना रही हैं। इस प्रकार निशस्त्रीकरण से युद्ध भड़क सकता है, जबकि शस्त्रीकरण-जनित आतंक के सन्तुलन से युद्ध से बचा जा सकता है।

(2) अनेक क्षेत्रों में विकास का मार्ग अवरुद्ध होना—यदि निशस्त्रीकरण हो जाता है तो अनेक क्षेत्रों जैसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जायेगा। निशस्त्रीकरण होने पर इन क्षेत्रों में नित नये आविष्कार की प्रतियोगिता शिथिल पड़ जायेगी। इन क्षेत्रों में विकास नहीं होने पर निशस्त्रीकरण अपनाते वाले देश शस्त्रीकरण करने वाले राष्ट्रों से पिछड़ जायेंगे। इस प्रकार निशस्त्रीकरण अनेक क्षेत्रों में विकास का मार्ग अवरुद्ध कर देता है।

(3) आर्थिक मन्दी उत्पन्न होना—निशस्त्रीकरण की शकालत करने वाले लेखक तर्क देते हैं कि शस्त्रीकरण पर आधारित खनन अनावश्यक है। इसलिए निशस्त्रीकरण का मार्ग अपनाकर उस विशाल धन को जन-वल्याणकारी कार्यों पर लगाया जाना चाहिए। जबकि इस मत के आलोचकों का कहना है कि निशस्त्रीकरण से आर्थिक मन्दी (Recession) उत्पन्न होती है जो देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। वे तर्क देते हैं कि शस्त्र उत्पादन के साथ-साथ जहाँ खनिज पदार्थों का बौहून तथा ऊर्जा उत्पादन होता है वही दूसरी और शस्त्र-निर्माता देशों में लोगों को रोजगार उपलब्ध, शस्त्रों के निर्यात से मुनाफा और विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। अगर शस्त्र उत्पादन को एक खास सीमा तक जारी रखा जाये तो उसके साथ अनेक लाभकारी आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ती हैं। इस प्रकार शस्त्र निर्माण को रोककर यदि निशस्त्रीकरण का रास्ता अपनाया जायेगा तो नुकसानदायक आर्थिक मन्दी उत्पन्न हो जायेगी। निशस्त्रीकरण से 'हथियार अर्थव्यवस्था' को 'निशस्त्रीकरण अर्थव्यवस्था' में परिवर्तित करने की समस्या उठ खड़ी होगी।¹

(4) निशस्त्रीकरण स्वयं एक समस्या—अनेक विद्वानों ने शस्त्रीकरण त्याग कर निशस्त्रीकरण पर बल दिया है किन्तु निशस्त्रीकरण अपने आप में स्वयं एक समस्या है। कई बार शस्त्रास्त्र कम करने के समझौते हुए, किन्तु राष्ट्रों द्वारा इनका पालन हो रहा है या नहीं, इस बात की विश्वव्यापीयता सदैव प्रश्न चिन्ह बन कर रही है। निशस्त्रीकरण समझौतों के बाद उनके कार्यान्वयन के समय 'निरीक्षण की समस्या' का सामना करना पड़ता है। समझौता करने वाले राष्ट्र इसके लिए जल्दी तैयार नहीं होते। यदि वे तैयार हो जाते हैं तो निरीक्षण का खर्चा भी अभीमित होता है। इनाइशर के अनुसार 'अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण व्यवस्था के लिए जो व्यय होगा, यह निशस्त्रीकरण के कारण हुई वृद्धि से कहीं अधिक ही होगा।'² इस प्रकार निशस्त्रीकरण अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण व्यवस्था के मन्दमं में अपने आप स्वयं एक समस्या बन गया है। सेमूर मैलपेन ने काफी वर्षों पहले अन्दाजा लगाया था कि 'अनेक अमरीका में हथियार उत्पादन के परिवीक्षण (Monitoring) के

¹ इस समस्या के वस्तुनिष्ठ विश्लेषण के लिए देखें—B. N. Ganguli, *Economic Consequences of Disarmament* (London, 1963), 16-32.

² Charles F. Schuchter, *International Relations* (Delhi, 1963), 418.

लिए कम से कम 30 हजार व्यक्तियों की जरूरत होगी और विश्व स्तर पर अनेक इस काम के लिए एक लाख से ज्यादा लोगों की आवश्यकता होगी जिन पर लगभग एक अरब डॉलर वार्षिक खर्च आयेगा।¹

(5) अधिकांश निशस्त्रीकरण समझौते भेदभावपूर्ण—आज तक जो भी निशस्त्रीकरण समझौते हुए हैं, उनमें अधिकतर भेदभावपूर्ण (Discriminatory) हैं। इनमें विजयी या बड़े राष्ट्रों ने पराजित या छोटे राष्ट्रों पर अपनी महत्वाकांक्षाएँ एक भेदभावपूर्ण शर्तों, घमबी या अन्य प्रकार के गैर-नैतिक तरीके घोषे हैं। मसलन, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी, बुल्गारिया, आस्ट्रिया तथा हंगरी जैसे कमजोर देशों पर बड़ी शक्तियों ने सैनिक रूप से उनको कमजोर बनाने के लिए गैर-नैतिक तरीकों से अपनी शर्तें घोषी। वर्तमान में बड़ी शक्तियाँ परमाणु प्रसार रोक सन्धि (Non-Proliferation Treaty) के माध्यम से स्वयं उनके द्वारा परमाणु बम बनाने पर किसी प्रतिबन्ध की बात नहीं करती, जबकि भारत जैसे शान्तिप्रिय देशों पर दबाव डाल रही हैं कि वह इस सन्धि पर हस्ताक्षर करके परमाणु विस्फोट न करने तथा बम न बनाने की वाग़ मान लें। भारत का मानना है कि वह ऐसा तभी स्वीकार करेगा, जब बड़ी शक्तियाँ भी स्वयं ये बातें मानने को तैयार हों। इस प्रकार भेदभावपूर्ण निशस्त्रीकरण समझौते अस्त्रास्त्रों की होड़ रोकने में कामयाब नहीं हो सकते।

(6) निशस्त्रीकरण विश्व-शान्ति की गारन्टी नहीं दे सकता—यह तर्क एकपक्षीय है कि निशस्त्रीकरण से विश्व-शान्ति एवं सुरक्षा स्थापित हो जायेगी। विश्व-शान्ति एवं सुरक्षा निशस्त्रीकरण के अलावा अन्य अनेक बातों पर निर्भर करती है। जैसे राष्ट्रों में आपसी विद्वेष, आर्थिक जन-ममृद्धि, स्वल्प राजनीतिक परम्पराओं का विकास, दूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्व इत्यादि। इस दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि निशस्त्रीकरण विश्व-शान्ति एवं सुरक्षा कायम करने की एक-मात्र नहीं, बल्कि अनेक में से एक घटक है। अतएव केवल निशस्त्रीकरण विश्व-शान्ति की कोई ठोस गारन्टी नहीं दे सकता।

(7) निशस्त्रीकरण वर्तमान जगत में अव्यावहारिक एवं अप्राप्तगिक—आधुनिक युग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का युग है। लोगों का 'काल्पनिक' आदर्शवाद' में नहीं, बल्कि 'व्यापारवाद' में विद्वान है। इसी कारण किसी भी राष्ट्र का कोई भी राजनेता राष्ट्रीय सुरक्षा पहले चाहता है और जन-ममृद्धि बाद में। पर्याप्त राष्ट्रीय सुरक्षा के अभाव में आर्थिक विकास सम्भव नहीं। 1962 में साम्यवादी चीन द्वारा भारत पर अचानक बर्बर सैनिक हमले के बाद हमने भी यही सबक लिया। इसी राजनीतिक व्यापार को महसूस करते हुए राष्ट्र निशस्त्रीकरण में पर्याप्त रुचि नहीं दिखाते हैं। व इस घोषी नारवाजी में पड़कर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में नहीं डालना चाहते। प्रसिद्ध विद्वान् एडम स्मिथ की भी धारणा है कि प्रतिरक्षा समृद्धि से बड़ी अधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार कई लोग निशस्त्रीकरण को वर्तमान जगत में अव्यावहारिक व अप्राप्तगिक सा मानते हैं।

निशस्त्रीकरण के विभिन्न प्रयास

(Various Efforts for Disarmament)

निशस्त्रीकरण की अवधारणा काफी पुरानी है। 1648 में वेस्टफैलिया संधि,

¹ Seymour Melman *Inspection For Disarmament* (New York, 1955)

1889 में पहला हेग शान्ति सम्मेलन, 1907 में दूसरा हेग शान्ति सम्मेलन आदि के द्वारा निशस्त्रीकरण के प्रयास हुए, किन्तु उनकी सफलता ज्यादा उल्लेखनीय नहीं रही। प्रथम विश्व युद्ध से हुई अपार धन एवं जन की हानि से लोगो ने निशस्त्रीकरण की आवश्यकता एवं महत्व को महसूस करना शुरू किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद दो सत्रों पर निशस्त्रीकरण के प्रयास हुए—(अ) राष्ट्र संध द्वारा किये गये प्रयास, और (ब) राष्ट्र संध के बाहर किये गये प्रयास।

राष्ट्र संध (League of Nations) द्वारा निशस्त्रीकरण प्रयास

प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संध की स्थापना की गयी। राष्ट्र संध प्रतिलिपि के आठवें अनुच्छेद के दूसरे प्रावधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 'प्रत्येक राज्य की भौगोलिक व्यवस्था एवं परिस्थितियों का लेखा रखकर परिषद् विभिन्न सरकारों द्वारा विचार और कार्यवाही के लिए शस्त्रास्त्रों की कमी की योजना बनाये।' राष्ट्र संध द्वारा किये गये निशस्त्रीकरण प्रयासों का निम्नांकित तीन बिन्दुओं के अन्तर्गत अध्ययन किया जाता है।

(1) अस्थायी मिश्रित आयोग—1921 में राष्ट्र संध की परिषद् ने अस्थायी मिश्रित समिति (Temporary Mixed Commission) की स्थापना की। इसने मुख्य रूप से जो चार प्रयास किये, वे इस प्रकार हैं—(अ) इसने राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार स्थल सेना (Land Forces) विधिवत करने का एक प्रयास किया, किन्तु अन्ततः यह प्रस्ताव निष्फल रहा; (ब) इसने 1922 में की गई वाशिंगटन सम्मेलन सन्धि के सिद्धान्तों को उस पर हस्ताक्षर न करने वाली शक्तियों पर भी लागू (extend) करने का प्रयास किया। यह प्रयास भी अन्ततः निष्फल रहा; (स) इसने आपसी सहायता सन्धि का मसौदा तैयार किया, जो शस्त्रास्त्र घटाने का एक प्रयास था, किन्तु यह विश्व राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत नहीं हो सका; और (द) इसने जेनेवा प्रोटोकॉल द्वारा आग्रामक राज्यों के विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव रखा। इसे भी स्वीकृति न मिल सकी। इस प्रकार अस्थायी आयोग के निशस्त्रीकरण प्रयास निष्फल रहे।

(2) तैयारी आयोग—राष्ट्र संध द्वारा निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में अगला कदम 1925 में एक प्रारम्भिक आयोग (Preparatory Commission) की स्थापना था। इसने दिसम्बर, 1930 में निशस्त्रीकरण की योजना का एक अस्थायी प्राकल्प-प्रस्ताव (Dummy Draft Convention) पारित कराने में सफलता हासिल की। इसकी मुख्य व्यवस्थाएँ थी—वेजट द्वारा स्थल युद्ध-सामग्री पर नियन्त्रण करना; अनिवार्य सैनिक सेवा की अन्तिम घटाना, सैनिकों की संख्या बिना किसी भेदभाव के नियन्त्रित करना, सामायनिक एवं कीटाणु युद्ध रोकना आदि। हालांकि फरवरी, 1932 में होने वाले निशस्त्रीकरण सम्मेलन में इसका उपयोग नहीं किया गया, तथापि यह परिणाम अवश्य निकला कि निशस्त्रीकरण के बारे में वे मूलभूत मतभेद प्रकाश में आ गये जिनका समर्थन सम्मेलन को करना पड़ता था।

(3) जेनेवा सम्मेलन—फरवरी, 1932 में ब्रिटिश विदेश सचिव आर्थर हैडरसन की अध्यक्षता में 'शस्त्रों की कटौती' (Reduction) और उन्हें सीमित करने (Limitation) के प्राकल्प-प्रस्ताव पर विचार करने के लिए जेनेवा में एक सम्मेलन हुआ। इसमें 61 राष्ट्रों ने भाग लिया, जिनमें से पाँच देश राष्ट्र संध के सदस्य नहीं

ये। सम्मेलन में राष्ट्र सभ के अधीन एक ऐसे पुतिर बल के गठन की सिफारिश की गयी, जिसका बमबर्षकों पर एकाधिकार हो। आक्रामक देशों को बड़ीरता से दण्ड देने एवं पंच निर्णय आवश्यक बनाने की बात कही गयी। अनसुलझे विवादों पर अन्तिम रूप से कानूनी निर्णय देने पर बल दिया गया। रासायनिक एवं जैविक हथियारों की आक्रमणकारी प्रकृति के बारे में सबसे अधिक सहमति हो सकी। किन्तु कुछ समय बाद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति ने ऐसा मोड़ लिया कि यह सम्मेलन असफल हो गया। 1933 में जर्मनी ने सम्मेलन का बहिष्कार किया। मई, 1934 में पुनः निरास्त्रीकरण सम्मेलन हुआ। इस बार एक तरफ रूस और फ्रांस तथा दूसरी ओर इंग्लैंड, इटली तथा अमरीका के बीच मतभेद उभरे। रूस और फ्रांस ने सुरक्षा पर बल दिया, जबकि इंग्लैंड, इटली तथा अमरीका ने निरास्त्रीकरण पर। 11 जून, 1934 को यह सम्मेलन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। इस प्रकार राष्ट्र सभ के निरास्त्रीकरण प्रयास असफल रहे। राष्ट्र सभ के निरास्त्रीकरण के प्रति दृष्टिकोण तथा उसके लिये किये गये प्रयासों के बारे में लार्ड डेविस ने ठीक ही कहा है कि यह सब एक वर्ग को एक बूँट में फिट करने का उपहासास्पद प्रयत्न था।

राष्ट्र सभ के बाहर किये गये निरास्त्रीकरण प्रयास

एक तरफ जहाँ राष्ट्र सभ निरास्त्रीकरण के प्रयास कर रहा था वहीं दूसरी ओर कुछ राष्ट्र उसके दायरे के बाहर भी ऐसे प्रयास कर रहे थे।

(1) वार्सिंगटन सम्मेलन—1921-22 में आयोजित वार्सिंगटन सम्मेलन के अन्त में एक सन्धि पर ब्रेट ब्रिटेन, अमरीका, फ्रांस, जापान तथा इटली ने हस्ताक्षर किये। इसको 'पाँच शक्तियों की सन्धि' के नाम से भी जाना जाता है। इसके द्वारा हस्ताक्षरकर्ता देशों की नौमैनिक होठ दस वर्ष के लिए कम हो गयी। मगर लड़ाकू पनडुब्बियाँ (क्रूजर), ध्वसक पोत (डेट्रोयर्स) तथा सहायक जहाजों के बारे में कोई समझौता नहीं हो पाया। इसे दुर्भाग्य ही कहा जायेगा कि कुछ समय बाद बड़ी शक्तियों ने विभिन्न आधारों पर अपनी नौमैनिक शक्ति में अधिक बढ़ती करने में असमर्थता प्रकट की, जिससे यह सम्मेलन अपने घोषित उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहा। फिर भी, इसने मबिष्य में ऐसी ही अन्य सम्मेलन के आयोजन का मार्ग अवश्य प्रशस्त किया।

(2) 1927 का जेनेवा सम्मेलन—वार्सिंगटन सम्मेलन की असफलता के बाद अमरीका के राष्ट्रपति कुलीज (Coolidge) ने 1927 में जेनेवा में द्वितीय नौमैनिक सम्मेलन बुलाया। फ्रांस ने इस सम्मेलन के आयोजन को पसन्द नहीं किया। इंग्लैंड, जापान और अमरीका ने ही इसमें भाग लिया। इसमें तीनों राष्ट्रों के विख्यात नौमनायक एवं नौमना विशेषज्ञ सम्मिलित हुए। मगर 'क्रूजर' के मुद्दे को लेकर जल्दी ही अमरीका और इंग्लैंड में गम्भीर मतभेद पैदा हो गये, जिससे यह सम्मेलन बिना किसी सफलता के समाप्त हो गया।

(3) 1930 की लन्दन नौमैनिक सन्धि—1930 में अमरीका, जापान, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन आदि राष्ट्रों का एक सम्मेलन लन्दन में हुआ। इसमें 1927 के जेनेवा सम्मेलन में उभरे मतभेदों को लन्दन नौमैनिक सन्धि पर हस्ताक्षर करके सुलझाया गया। इस पर अमरीका, ब्रिटेन तथा जापान ने ही हस्ताक्षर किये। फ्रांस तथा

इटली ने इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। किन्तु बाद में हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा इस सन्धि का पालन नहीं करने से निराश्रीकरण का यह प्रयास निष्फल रहा।

(4) 1935-36 का लन्दन नौसैनिक सम्मेलन—1935-36 में लन्दन में नौसैनिक सम्मेलन हुआ, जिसमें सभी महाशक्तियों ने भाग लिया। यह सम्मेलन प्रतिबन्ध अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आयोजित हुआ। जापान द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण और जर्मनी द्वारा वर्साय सन्धि का उल्लंघन करके राइनलैण्ड पुनः सैन्यीकृत करने आदि से अन्तर्राष्ट्रीय तनाव पैदा हुआ। अतएव इस सम्मेलन का असफल होना स्वाभाविक था।

(5) 1935 का आंग्ल-जर्मन नौसैनिक समझौता—जून, 1935 में ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत ब्रिटेन ने जर्मनी का यह दावा स्वीकार किया कि उसे अपने नौसैनिक शक्ति ब्रिटेन की नौसैनिक शक्ति के 35 प्रतिशत के बराबर करने दो जाये और सभी तरह के युद्धपोत बनाने दिये जायें। ब्रिटेन द्वारा यह सन्धि करने का प्रमुख कारण उसके विरुद्ध सम्भावित जर्मन आक्रमण से रक्षा करना था। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध तक कोई महत्वपूर्ण निराश्रीकरण समझौता नहीं हुआ।

निराश्रीकरण प्रयासों की अराफलता के कारण

प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ द्वारा तथा उसके बाहर किये गये निराश्रीकरण प्रयासों की असफलता के अनेक कारण थे।

(अ) विभिन्न राष्ट्रों द्वारा अपने-अपने हितों पर बल देना—विभिन्न राष्ट्रों ने निराश्रीकरण समझौते तथा उनके कार्यान्वयन के दौरान अपने-अपने हितों पर बल देने से इस क्षेत्र में सफलता हासिल नहीं हो सकी। उदाहरणार्थ, फ्रांस निराश्रीकरण के पहले मुरझा चक्क्या का हामी था। वह अमेरिका तथा ग्रेट-ब्रिटेन से यूरोपीय सीमाओं (Frontiers) की प्रतिरक्षा के बारे में डढ़ मचन चाहता था। लन्दन नौसैनिक सम्मेलन में जापान अन्य नौसैनिक शक्तियों के साथ 'बराबरी' चाहता था, किन्तु जब अन्य शक्तियों ने इसकी बात नहीं मानी तो वह सम्मेलन से हट गया। यहाँ तक कि बाद में उसने अन्तर्राष्ट्रीय कानून एवं नैतिकता का खुला उल्लंघन करते हुए मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया। हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी ने वर्साय सन्धि के अपमान का बदला लेने के लिए निराश्रीकरण किया और वह फौजी हमले पर उतार आया। इस प्रकार विभिन्न राष्ट्रों द्वारा अपने-अपने हितों पर बल देने से निराश्रीकरण प्रयास असफल हो गये।

(ब) राष्ट्र संघ द्वारा बोधी देशों के विरुद्ध कार्रवाई में मौन रहना—जब जापान, इटली, जर्मनी आदि राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ की प्रमविदा तथा अन्तर्राष्ट्रीय कर्तव्यों (obligations) का उल्लंघन कर सैनिक आक्रमण का सहारा लिया, तब राष्ट्र संघ या तो चुपचाप देखता रहा या फिर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने में असफल रहा। इससे निराश्रीकरण प्रयासों पर पानी फिर गया।

(ग) सदस्य देशों की प्राथमिकताओं में अन्तर—निराश्रीकरण सम्मेलनों या मंचों में भाग लेने वाले देशों की प्राथमिकताओं में अन्तर था मतभेद होने से निराश्रीकरण के प्रयासों को मारो चक्का लगा। विशेष रूप से प्राथमिकताओं का यह मतभेद

इंग्लैण्ड, फ्रांस, अमरीका और जर्मनी के बीच था। एक तरफ भारत ने सुरक्षा के आधार पर जर्मनी के मुकाबले शस्त्रों में श्रेष्ठता पर जोर दिया तो दूसरी ओर जर्मनी ने फ्रांस के साथ समकक्षता की मांग की। इस प्रकार निशस्त्रीकरण प्रयास धराशायी हो गये।

(द) आक्रामक और सुरक्षात्मक शस्त्रों में भेद की कठिनाई—आक्रामक और सुरक्षात्मक शस्त्रों में भेद न कर सक्ने ने भी निशस्त्रीकरण प्रयासों के मार्ग में बाधा खड़ी कर दी। एक तरफ इंग्लैण्ड ने पनडुब्बियों को आक्रामक शस्त्र माना, जबकि अन्य देशों ने इन्हें सुरक्षात्मक। इस शस्त्र विभेद की समस्या ने निशस्त्रीकरण समझौता बातोंएँ आगे नहीं बढ़ने दी। इससे निशस्त्रीकरण प्रयास निष्फल होना स्वामाविव था।

(य) विभिन्न देशों में तत्कालीन मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों की उपेक्षा—विभिन्न राष्ट्रों में विद्यमान तत्कालीन मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों की उपेक्षा ने निशस्त्रीकरण के प्रयासों को सफल नहीं होने दिया। असल में निशस्त्रीकरण की सफलता के लिए राष्ट्रों में आपसी अविश्वास एवं भय की समाप्ति आवश्यक है। अर्थात् पहले 'मनोवैज्ञानिक' निशस्त्रीकरण' जरूरी है, जिसकी उपेक्षा की गयी। इस प्रकार अधिश्वास निशस्त्रीकरण प्रयासों में असफलता ही हाथ लगी।

सं० रा० सघ एवं निशस्त्रीकरण (The U N and Disarmament)

द्वितीय विश्व युद्ध के विस्फोट के लिए एक बड़ी सीमा तक राष्ट्र सघ की अग्रपंक्ति जिम्मेदार थी। सर्वनाशक ध्म ने एक बार फिर निशस्त्रीकरण की जरूरत को रेखांकित किया। परमाणु अस्त्रों के प्रयोग ने इस समस्या का एक महत्वपूर्ण पक्ष उजागर किया। सं० रा० सघ ने अपनी स्थापना के साथ ही अपने चाटेर और प्रस्तावित कार्यक्रमों में निशस्त्रीकरण को महत्वपूर्ण स्थान दिया। निशस्त्रीकरण की दिशा में सं० रा० सघ का योगदान उल्लेखनीय रहा है।

(1) परमाणु ऊर्जा आयोग—सं० रा० सघ द्वारा निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में पहला प्रयास महानभा द्वारा 1946 में एक प्रस्ताव पारित कर परमाणु ऊर्जा आयोग (Nuclear Energy Commission) की स्थापना था। इस आयोग को शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के नियन्त्रण के बारे में उपयोगी सुझाव देने की कहा गया। इसमें अपनी रपट में परमाणु ऊर्जा के लिए एक प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण व्यवस्था की सिफारिश की। सोवियत सघ ने इसे मानने में इन्कार कर दिया। परिणामस्वरूप फरवरी, 1947 में सं० रा० सघ की सुरक्षा परिषद् ने एक प्रस्ताव पारित कर परम्परागत शस्त्रों सम्बन्धी आयोग की स्थापना की। इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जायेगा कि इन दोनों आयोगों को अग्रपंक्ति हाथ लगी, क्योंकि उनमें मुझाबों और सिफारिशों पर अमरीका और सोवियत सघ में मतभेद बन रहे।

(2) निशस्त्रीकरण आयोग—अक्तूबर, 1950 और उसके बाद अमरीकी राष्ट्रपति ट्रुमैन ने सं० रा० सघ में मुझाव रखा कि परमाणु ऊर्जा आयोग तथा परम्परागत शस्त्र आयोग के कार्यों को मिला दिया जाये। अन्ततः 11 जनवरी,

1952 को महाममा ने दोनो आयोग मिलाकर एक निशस्त्रीकरण आयोग (Disarmament Commission) की स्थापना की। इस आयोग के सदस्यों की संख्या 12 रखी गयी—5 सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्य, छह अस्थायी सदस्य तथा कनाडा। इस आयोग ने शस्त्रास्त्रो एवं सैनिक दस्तों में कमी, निशस्त्रीकरण समझौते, शास्त्र सूची और सत्यापन आदि जैसे कई निशस्त्रीकरण प्रस्ताव पेश किए, किन्तु विश्व राष्ट्रों का उनके बारे में नकारात्मक रुख रहा। इस कारण यह आयोग भी निशस्त्रीकरण प्रयास में असफल ही रहा।

(3) शान्ति के लिए परमाणु योजना—दिसम्बर, 1953 में अमरीकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने 'शान्ति के लिए परमाणु' योजना (Atom for Peace Plan) का प्रस्ताव रखा। इसका प्रमुख उद्देश्य परमाणु ऊर्जा का शान्तिपूर्ण उपयोग था। इस योजना में परमाणु शक्तियों से इसका पालन करने को कहा गया, किन्तु सोवियत संघ द्वारा इसके विरोध के कारण अमरीकी राष्ट्रपति का यह प्रस्ताव निष्फल हो गया। सोवियत संघ का मानना था कि शान्ति के लिए परमाणु ऊर्जा योजना के पहले अस्त्रों के निषेध पर समझौता किया जाये।

(4) 1954-57 में दौरान निशस्त्रीकरण प्रयास—1954-57 के दौरान अनेक छिटपुट निशस्त्रीकरण प्रयास किये गये। सं० रा० संघ के निशस्त्रीकरण आयोग ने पाँच शक्तियों—अमरीका, सोवियत संघ, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस तथा कनाडा को निशस्त्रीकरण की समस्याओं पर विचार के लिए एक उपममिति नियुक्त की। एक जुलाई, 1955 में जेनेवा में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें सोवियत संघ, अमरीका, ब्रिटेन और फ्रांस ने भाग लिया। इसमें अमरीका के तत्कालीन राष्ट्रपति आइजनहावर ने 'उपमुक्त आकाश योजना' (Open Skies Plan) रखी। इसमें अमरीका और सोवियत संघ दोनों द्वारा अपने सैनिक बजट, उत्पादन, वर्तमान शक्ति एवं उसके विकास की सम्भावनाओं के बारे में एक-दूसरे को सूचना देने तथा परस्पर जाँच एवं निरीक्षण करने की बातें कही गयीं। दोनों देशों को एक-दूसरे के आकाश पर से निरीक्षण करने (फोटो लेने) के अधिकार का भी उल्लेख था। किन्तु तत्कालीन सोवियत प्रधानमंत्री बुल्गानिन ने इसे अस्वीकृत करते हुए यह प्रस्ताव रखा कि निशस्त्रीकरण को कार्यान्वित करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण अभिकरण की स्थापना की जाये, उसे जाँच एवं निरीक्षण का कार्य सौंपा जाये, सभी देशों से विदेशी सैनिक अड्डों को समाप्त किया जाये, परमाणु शस्त्रों के परीक्षण पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये तथा परम्परागत शस्त्रों में निश्चित कटौती की जाये। इस प्रस्ताव को अन्य शक्तियों ने गार्मजूर कर दिया।

मार्च, 1957 में पश्चिमी देशों ने एक और व्यापक निशस्त्रीकरण योजना रखी। इसे भी सोवियत संघ ने अस्वीकृत कर दिया। सं० रा० संघ महाममा के 12वें अधिवेशन में सोवियत संघ ने घोषणा की कि वह निशस्त्रीकरण आयोग तथा उसकी उप-ममिति की आगे की बार्ता एवं परामर्श में भाग नहीं लेगा। इस प्रकार इन प्रयासों के लाभकारी परिणाम नहीं निकले।

(5) परमाणु प्रशिक्षण पर प्रतिबन्ध—जेनेवा सम्मेलन की असफलता के बावजूद परमाणु परीक्षण पर प्रतिबन्ध (Nuclear Test Ban) के बारे में बार्ता चलती रही। अक्टूबर, 1958 से 3 अप्रैल, 1961 तक चले जेनेवा सम्मेलन के बाद तीन विश्व शक्तियाँ—ग्रेट ब्रिटेन, अमरीका और सोवियत संघ इस बात पर सहमत

हुई कि बाह्य अन्तरिक्ष, महासागर तथा भूमि में सभी प्रकार के परमाणु परीक्षण बन्द कर दिये जाने चाहिए। इस प्रकार की सन्धि को अन्तर्राष्ट्रीय स्टाफ के सख्त नियन्त्रण एवं निरीक्षण (Control and Supervision) के अन्तर्गत लागू किया जाना था। किन्तु यह प्रयास मोवियत सघ के प्रतिकूल रुख के कारण असफल हो गया। उसने मांग की कि एक निष्पक्ष प्रशासक की तीन सदस्यों (एक तटस्थ देशों से, एक पश्चिमी क्षेत्र से तथा एक मोवियत क्षेत्र से) के आयोग से प्रतिस्थापित (Replace) किया जाये। इसमें परमाणु परीक्षण पर प्रतिबन्ध के बारे में आग का परामर्श रूक गया और इस बारे में किसी भी प्रकार का समझौता न हो सका।

(6) इस राष्ट्रों का निशस्त्रीकरण आयोग—1960 में जेनेवा में निशस्त्रीकरण सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें दस राष्ट्रों ने भाग लिया। पश्चिमी क्षेत्र में अमरीका, ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस एवं इटली तथा साम्यवादी क्षेत्र में मोवियत सघ, युगोस्लाविया, पोलैण्ड, रमानिया एवं बुल्गारिया सम्मेलन में उपस्थित थे। दोनों क्षेत्रों की ओर से परमाणु हथियारों पर रोक लगाने, राकेट नष्ट करने तथा सैनिक सन्ना घटाने जैसे अनेक प्रकार के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। किन्तु सम्मेलन का अन्त बहुत निराशापूर्ण बानाकरण में हुआ, क्योंकि अन्तिम समय में मोवियत सघ ने अपने क्षेत्र में अन्य देशों के साथ सम्मेलन से बहिर्गमन कर दिया।

(7) 18 राष्ट्रों का निशस्त्रीकरण सम्मेलन—1962 में एक बार पुनः निशस्त्रीकरण सम्मेलन हुआ। इसमें भाग लेने वाले 17 देश थे—अमरीका, ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, इटली, मोवियत सघ, रमानिया, बुल्गारिया, पोलैण्ड, चेकोस्लोवाकिया, ब्राजील, भारत, बर्मा, समुद्र अरब अमीरात, मैक्सिको, इक्वाडोरिया, स्वीडन तथा नाइजीरिया। हालांकि इसमें 17 राष्ट्रों ने भाग लिया, किन्तु इन 18 राष्ट्रों का निशस्त्रीकरण सम्मेलन कहने का कारण यह है कि अद्वितीय देश फ्रांस ने इसका बहिष्कार किया। सम्मेलन में अमरीका ने प्रमुख परमाणु शस्त्रास्त्रों में 30 प्रतिशत कटौती का प्रस्ताव पेश किया। मोवियत सघ ने सामान्य और पूर्ण निशस्त्रीकरण का प्रस्ताव रखा, जिसके तहत तीन चरणों में सभी विश्वीय सैनिक अस्त्रों तथा परमाणु अस्त्रों न बाह्य-आघातों के उन्मूलन की व्यवस्था थी। तटस्थ देशों ने परमाणु विस्फोट पर रिपोर्ट देने के लिए वैज्ञानिकों के एक अन्तर्राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रस्ताव रखा। इस सम्मेलन के भी कोई सामगरी नतीजे सामने नहीं आये।

(8) आंशिक परीक्षण रोक सन्धि (Partial Test Ban Treaty)—5 अगस्त, 1963 को अमरीका, ग्रेट ब्रिटेन तथा मोवियत सघ ने आंशिक परीक्षण रोक सन्धि पर हस्ताक्षर किये, जो निशस्त्रीकरण की दिशा में किये गये अत्यन्त के प्रयासों में सबसे महत्वपूर्ण कदम था। यह सन्धि होने के पीछे इसने लिए पूर्ण में किये गये कई प्रयास उन्मूलनीय हैं। पहला, इस सन्धि के पहले म० रा० सघ महासभा अपने प्रयत्न अधिवेशन में समस्त राज्यों द्वारा परमाणु परीक्षण में बाध आने के प्रस्ताव पारित करती रही थी। दूसरा, यह प्रस्ताव फ्रेंच अधिवेशन में पारित कराने में मुट निष्पक्ष देशों का उन्मूलनीय योगदान रहा है। निशस्त्रीकरण आयोग के आठ मुट निरपेक्ष देशों ने आंशिक परीक्षण रोक सन्धि होने में भी सक्रिय भूमिका अदा की। इन देशों ने परमाणु शक्तियों को 16 अगस्त, 1962 को एक समुदाय स्मरण पत्र दिया, जिसमें परमाणु परीक्षण रोकने के बारे में बातचीत करने के गुस्ताव दिये गये। बाद में म० रा० सघ महासभा ने इस स्मरण पत्र का अनुमोदन किया।

आंशिक परीक्षण रोक सन्धि में निम्नांकित प्रमुख व्यवस्थाएँ थी :

(अ) सन्धि की भूमिका में अमरीका, सोवियत संघ और ग्रेट ब्रिटेन को मूल पक्ष कहा गया है तथा अपना प्रधान ध्येय यह घोषित किया गया है कि कठोर अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण के लिए जल्दी से जल्दी परमाणु समझौता हो;

(ब) सन्धि की धारा एक के 'पैरेग्राफ' एक में कहा गया है कि सन्धि का प्रत्येक पक्षकार कोई भी परमाणु विस्फोट अपने अधिकार क्षेत्र या नियन्त्रणाधीन किसी भी जगह पर बन्द करने, रोकने और न करने के लिए बचनबद्ध है;

(स) सन्धि की धारा एक के 'पैरेग्राफ' दो में कहा गया है कि हरेक पक्ष का दायित्व है कि वह कोई भी परमाणु विस्फोट करने, उसे प्रोत्साहित करने, या किसी भी प्रकार उसके करने में भाग लेने से दूर रहेगा;

(द) सन्धि की धारा तीन के 'पैरेग्राफ' एक में कहा गया है कि कोई भी राज्य इस सन्धि पर हस्ताक्षर कर सकता है। हस्ताक्षरकर्ता राज्य वे हैं, जो इसके लागू होने से पहले इस पर हस्ताक्षर कर सकते थे और धारा तीन के 'पैरेग्राफ' तीन के अनुसार इसका अनुसमर्थन कर सकते थे। परन्तु गैर-हस्ताक्षरकर्ता राज्य 'अधिमिलन' द्वारा ही सन्धि के पक्षकार बन सकते हैं; अनुसमर्थन द्वारा नहीं। पक्षकार बन जाने पर उनकी और हस्ताक्षरकर्ता राज्यों की स्थिति एक-सी हो जाती है और उन्हें सभी अधिकार और दायित्व मिल जाते हैं; और

(य) सन्धि की कोई काल सीमा नहीं है, किन्तु यदि कोई सविदाकारी यह समझे कि इस सन्धि से सम्बन्धित किन्हीं असाधारण घटनाओं से उसके देश के सर्वोच्च हितों को खतरा उत्पन्न हो गया है तो वह इससे अलग हो सकता है, जिसके निम्नांकित कारण हो सकते हैं :

(i) यह गव्हेह कि परमाणु परीक्षण स्थगित रखने से दूसरे सविदाकारी पक्षों को सैनिक दृष्टि से लाभ हो रहा है;

(ii) किसी अन्य पक्षकार द्वारा सन्धि का अतिक्रमण; और

(iii) यह मय कि किसी ऐसे राज्य द्वारा किये गये परीक्षणों से वास्तु-मन्तुलभ विगड़ सकता है, जिसने सन्धि में 'अधिमिलन' से इन्कार कर दिया हो। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि सन्धि की धारा चार में कहा गया है कि अलग होने का अधिकार राष्ट्रीय प्रभुमत्ता का परिणाम है, जिसका अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों से छूटने की समस्या पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है।

(र) सन्धि की धारा दो में आंशिक परीक्षण रोक सन्धि में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसमें यह व्यवस्था है कि कोई पक्षकार, जो संशोधन कराना चाहे, उसका पाठ निक्षेपकारी सरकारों अर्थात् 'मूल पक्षकारों' की सरकारों को भेज दिया जायेगा। निक्षेपकारी सरकारें प्रस्तावित संशोधन सन्धि को सभी पक्षकारों में प्रसारित करेंगी। इसके बाद यदि दो-तिहाई या अधिक पक्षकार चाहेंगे तो निक्षेपकारी सरकारें एक सम्मेलन बुलायेंगी, जिसमें संशोधन पर विचार के लिए समस्त पक्षकारों को निमन्त्रित किया जायेगा।

आंशिक परीक्षण रोक सन्धि की आलोचना—आंशिक परीक्षण रोक सन्धि की अनेक आधारों पर आलोचना की जा सकती है, जिसमें से प्रमुख आधार निम्नांकित हैं :

(i) इस सन्धि में जमीन के अन्दर (भूमिगत) विस्फोट करने पर रोक

लगाने के बारे में स्पष्ट व्यवस्था का अभाव है;

- (ii) सधि में परमाणु अस्त्रों की त्रित्री पर रोक नहीं लगायी गयी है;
- (iii) इसमें उल्लिखित सशोधन प्रावधान भी नुटितपूर्ण हैं। इस बारे में किसी प्रकार का स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि निधेपकारी सरकारें कितने समय के भीतर वह सशोधन पक्षकारों में प्रसारित करें और कितने समय में वे सशोधन पर विचार के लिए सम्मेलन बुलायें। यहाँ तक कि इस सधि में सशोधन के लिए सम्मेलन का स्थान भी निश्चित नहीं किया गया है, और
- (iv) सधि में इसके प्रावधानों के अर्थ के बारे में मतभिन्नता की अवस्था में उदका हन डूँडने के लिए किसी भी प्रकार के 'मानक अनुच्छेद' की व्यवस्था नहीं है।

(9) 1966 में जोनसन की सात-सूत्री योजना—1966 में अमरीकी राष्ट्रपति लिटन जोनसन ने सात-सूत्री योजना का मुद्राव दिया, जिसमें घेर-परमाणु देशों में परमाणु शस्त्रों के फैलाव को रोकने की बात कही गयी। इस योजना की अन्य बातें शान्तिपूर्ण परमाणु गतिविधियों का अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण, सुरक्षा-मगटन मजबूत बनाना तथा निरीक्षण व्यवस्था की स्थापना थीं। योजना में 'आत्रामक तथा सुरक्षामक' सामरिक बमबर्षकों तथा प्रक्षेपास्त्रों को, जो परमाणु शस्त्रों के बाहुक हैं, मघावन रोक देने (Freeze) की भी बात कही गयी। साथ ही राष्ट्री को मुद्राव दिया गया कि वे भूँगे हथियारों की प्रतियोगिता भीमित करें, जो आम तौर पर 'झूठी प्रतिष्ठा' के लिए प्राप्त किये जाने हैं। फिर भी इन बातों पर विचार के लिए जो सम्मेलन हुआ उसके परिणाम निराशाजनक थे। अन्त में यह सम्मेलन बिना किसी उपलब्धि के स्थगित हो गया।

परमाणु प्रसार रोक सधि

5 मार्च, 1968 को परमाणु प्रसार रोक सधि (Non-Proliferation Treaty)—दुनिया में हथियारों की होड भीमित करन तथा निगस्त्रीकरण के लिए अनुकूल शात्रावरण तैयार करन में इस सधि की महत्वपूर्ण सीमा-बिन्दु माना जा सकता है। नवम्बर, 1966 में म० रा० मघ महामन्त्रा की राजनीतिक समिति ने परमाणु आयुधों के निर्माण एक प्रकार पर रोक लगाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। इसमें कहा गया कि परमाणु हथियार-विहीन राष्ट्र परमाणु अस्त्रों का निर्माण नहीं करें और परमाणु आयुध-मध्यम राष्ट्र इसका निर्माण बन्द करें। इसको सधि के समविद का रूप देने के लिए निगस्त्रीकरण आयोग का प्रस्तुत किया गया। इस आयोग द्वारा तैयार सधि का समविद महामन्त्रा ने 13 जून, 1968 को स्वीकार कर लिया तथा मध्यम देशों को इस पर हस्ताक्षर करन के लिए कहा गया। अमरीका और मोवियन मघ जैम महत्वपूर्ण देशों सहित 40 देशों का अनुममयन मिलने पर इस सधि को 5 मार्च, 1970 को लागू कर दिया गया। इस सधि को प्रमुख व्यवस्थाएँ निम्नांकित हैं

(अ) परमाणु हथियार-मध्यम राष्ट्र, परमाणु आयुध-विहीन देशों को परमाणु अस्त्र प्राप्त करने में किसी प्रकार की महामन्त्रा नहीं देंगे,

(ब) हस्ताक्षरकर्ता परमाणु-अस्त्र-विहीन राष्ट्र परमाणु हथियार बनाने का

कोई प्रयास नहीं करेंगे;

(स) हस्ताक्षरकर्ता देशों को अर्सेनिक कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के विकास की पूरी छूट रहेगी। अर्थात् वे परमाणु ऊर्जा का शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए उपयोग कर सकेंगे; और

(द) परमाणु अस्त्रों के परीक्षण पर रोक लगाने की अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था हो। इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को अधिकार दिया गया। साथ ही कहा गया कि गैर परमाणु राष्ट्रों द्वारा परमाणु ऊर्जा के शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए प्रयोग के बारे में वे इस एजेंसी के साथ ममझौता कर ऐसा करें।

परमाणु प्रसार रोक संधि की आलोचना—इस संधि पर अब तक लगभग एक सौ देशों ने हस्ताक्षर कर दिये हैं। इसके बावजूद भारत, चीन, पाकिस्तान आदि सहित कई अन्य महत्वपूर्ण देशों ने अनेक बाधाएँ पर इसकी आलोचना कर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है। संक्षेप में, इस संधि का विरोध करने वाले देशों ने निम्नांकित आपारों पर इसकी आलोचना की है।

(i) बड़ी शक्तियों द्वारा परमाणु एकाधिकार को स्थापित—परमाणु प्रसार रोक संधि पर अन्य राष्ट्रों के हस्ताक्षर करवा कर विश्व की पाँच परमाणु शक्तियाँ अपना परमाणु एकाधिकार कायम रखने की स्थापना का खेस खेसना चाहती हैं। इस संधि में परमाणु शक्तियों द्वारा परमाणु हथियार बनाने पर नहीं, बल्कि अन्य देशों द्वारा परमाणु हथियार न बनाने और विस्फोट नहीं करने की व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार बड़ी शक्तियाँ अन्य देशों को शक्तिशाली नहीं देखना चाहती।

(ii) फ्रांस और चीन द्वारा मन्थि पर हस्ताक्षर करने से इनकार—दुनिया की पाँच परमाणु एवं बड़ी शक्तियों में फ्रांस एवं चीन शामिल हैं। उन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। जब इन जैसे बड़े देशों ने इस संधि के प्रति उपेक्षा भाव दिखाया तो यह महज ही अन्दाजा लगाया जा सकता है कि विश्व के गैर-परमाणु देश क्यों गंवारारमक रण अपनाते लगे। हालांकि चीन ने अगस्त, 1991 में कहा कि वह अब इस संधि पर हस्ताक्षर करने को तैयार है, किन्तु ऐसा लगता कि वह इनके माथ अपनी कनिष्ठ शक्तों भी जोड़ेगा, जिससे इसका कोई विशेष महत्व नहीं रह जायेगा। यह चीन द्वारा हस्ताक्षर न करने के समान ही होगा।

(iii) इसे सामान्य या पूर्ण निशस्त्रीकरण सन्धि नहीं माना जा सकता—अनेक लोग इस संधि को निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम मानते हैं जो सही नहीं है। इसमें केवल परमाणु हथियारों पर रोक की ही व्यवस्था है, अन्य परम्परागत शस्त्रास्त्रों का उत्पादन रोकने या उन्हें सीमित करने के बारे में यह एवढम मौन है। इन कारण इसे सामान्य या पूर्ण निशस्त्रीकरण सन्धि कहाँ नहीं माना जा सकता।

(iv) सन्धि भेदभावपूर्ण—सन्धि पर अनेक देशों द्वारा हस्ताक्षर न करने का प्रमुख कारण उनकी भेदभावपूर्ण व्यवस्थाएँ हैं। इसमें बड़ी शक्तियों द्वारा परमाणु शस्त्रों के उत्पादन, शस्त्र जमा करने (Stock piling) तथा उनके प्रयोग पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगायी गयी है। इनके विपरीत गैर-परमाणु देशों द्वारा ऐसे हथियार नहीं बनाने के सम्बन्ध में तत्त्वीय-नौड़ी व्यवस्थाएँ की गयी हैं। इसे दोहरे मानदण्ड अपनाने वाली सन्धि ही कहा जा सकता है क्योंकि परमाणु और गैर-परमाणु देशों के बारे में इनकी व्यवस्थाएँ अलग-अलग हैं।

(v) सन्धि से परमाणु ऊर्जा के शान्तिपूर्ण उपयोग में बाधा—इस सन्धि में गैर-परमाणु राष्ट्रों में कहा गया है कि वे परमाणु विस्फोट न करें तथा इसके बदले परमाणु हथियार सम्पन्न राष्ट्र परमाणु ऊर्जा के शान्तिपूर्ण प्रयोग के लिए तबनीकी जानकारी एवं मदद देंगे। अनेक तबनीकी बातों का बहाना बनाकर परमाणु शक्तियाँ इस महायत्ना के आद्वामन को पूरा करने से मुक्ति मक्ती हैं। इस प्रकार परमाणु ऊर्जा के अभाव में विकासशील देशों द्वारा विनाश कार्यक्रमों को सम्पादित करने में अनेक प्रकार की बाधाएँ उठेंगी।¹

साल्ट-एक व साल्ट-टो समझौता

साल्ट एक समझौता (Strategic Arms Limitation Treaty One or SALT-I)—नवरनाथ एवं विनाशकारी परमाणु आनुषों को सीमित करने के लिए साल्ट-एक समझौता अर्थात् सामरिक सम्बन्ध परिसीमन सन्धि पर अमरीका और सोवियत सघ ने हस्ताक्षर किये। इस समझौते के अन्तर्गत दो समझौते किये गये (क) प्रक्षेपास्त्र विरोधी सन्धियों को सीमित करने सम्बन्धी सन्धि (Treaty on the Limitation of Anti-Ballistic Missiles System), और (ब) सामरिक आक्रमक अस्त्रों के परिसीमन सम्बन्धी कुछ उपायों पर अन्तरिम समझौता।

पहला समझौता जहाँ अनिश्चित काल के लिए किया गया, वहीं दूसरा समझौता पाँच वर्ष के लिए। पहले समझौते के तहत अमरीका और सोवियत सघ के लिए प्रक्षेपास्त्रों की सुरक्षा प्रदान करने वाले स्वतंत्रों को दो तरफ सीमित कर दिया गया—एक, देशों की राखधानी की सुरक्षा के लिए और दूसरा, अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों (आई० सी० सी० एस०) की सुरक्षा के लिए। दूसरे समझौते के तहत पंचवर्षीय अन्तरिम सन्धि में, जो राष्ट्रीय हितों के अनुरूप मिट्ट होत पर निम्नी भी पक्ष द्वारा छ. महीने के नोटिस पर रद्द की जा सकती है, निम्नांकित बातें तय की गईं—

(क) 1 जुलाई, 1972 के बाद नये अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण नहीं किया जायेगा,

(ब) कोई भी पक्ष हल्क या पुराने किस्म के भू-प्रक्षेपास्त्र स्वतंत्रों को सुधार कर भारी अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों का प्रयोग योग्य नहीं बनायेगा,

(स) दाता पक्ष पनडुब्बियों के प्रक्षेपास्त्र, प्रक्षेपक तथा प्रक्षेपास्त्रयुक्त आधुनिक पनडुब्बियाँ नहीं बनायेगा; ज्ञातकि इसमें निर्माणाधीन पनडुब्बियों का काम पूरा करने की छूट रहेगी,

¹ इस सन्धि के बारे में सक्षम मार्गदर्शन प्रिन्सिपल भारतीय रक्षा अध्यापन एवं विश्लेषण सम्पान के सूनपुत्र निदेशक व० सुब्रह्मण्यम (K. Subrahmanyam) ने की है। उन्होंने अपनी सम्पादित पुस्तक 'Nuclear Proliferation and International Security (Delhi, 1965), की मूद्रिका में लिखा है—कुछ बावें व्यक्तियों का तर्क यह है कि परमाणु प्रसार राक्ष सन्धि बाधा विरुद्ध इस सन्धि से बहुत विरुद्ध में कहकर है। 'इसी तरह के सूनपुत्रों के आधार पर यह भी प्रमाणित किया जा सकता है कि वर्तमान सन्धि और भी अच्छी है, जिसमें सन्धि तो है, ही और इसके रूप आनाकरी भी है। हर बाई इस हास्यास्पद व्यवस्था का निम्ना नहीं। यदि वास्तुनिष्ठ इस में सन्धि या उर्वर या स्वाधीन परमाणु आस्त्र प्रसार में अनेक बावें वर्तमान सून क खनरे या बाधकवादियों के हाथ में हथियार करने के अधिकार को काय रखकर देखें तो नए राष्ट्रों द्वारा परमाणु अस्त्र हासिल करने का खतरा नष्ट्य बनता, पृ० 18-19।

(द) अन्तरिक्ष सन्धि की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों द्वारा आक्रामक प्रक्षेपास्त्रों और प्रक्षेपकों का आधुनिकीकरण करने के लिए वैकल्पिक अस्त्र बनाने का अधिकार रहेगा; और

(घ) सन्धि के परिपालन की जाच के लिए हर राष्ट्र केवल अन्तर्राष्ट्रीय कानून के मान्य सिद्धान्तों के अनुरूप ही विधियाँ अपनायेगा। दोनों पक्षों ने स्वीकार किया कि सत्वास्त्र निर्माण को मुफ्त रखने के लिए जान-बूझकर ऐसी व्यवस्थाएँ नहीं करेंगे, जिनसे सन्धि की भावना को ठेस पहुँचे और दूसरे देश को निभरानी रखने में कठिनाई हो।¹

विद्यमान में साल्ट-दो समझौता—मई, 1979 में वियना (आस्ट्रिया) में तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति कार्टर और सोवियत शासक ब्रेज़नेव ने साल्ट-दो समझौते (SALT-II Agreement) पर हस्ताक्षर किये। 1985 तक की अवधि वाले इस समझौते में निम्नांकित व्यवस्थाएँ थी :

(अ) साल्ट-दो समझौते द्वारा सामरिक दस्त्रों, प्रक्षेपास्त्रों की संख्या और किसमें पर एक सीमा लगा दी गयी। लेकिन इसके अन्तर्गत दोनों देशों को नए प्रक्षेपास्त्र तथा परमाणु दस्त्र बनाने की छूट थी। हरेक देश के पास अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों, सामरिक दम-वर्षक विमानों तथा पनडुब्बियों से छोड़ने वाले परमाणु प्रक्षेपास्त्रों की संख्या 1981 तक 2400 निश्चित कर दी गयी। 1981 के बाद यह संख्या घटाकर 2250 कर दी गयी, और

(ब) हथियारों की होड़ में और कमी के लिए सोवियत संघ और अमरीका अपने साल्ट-तीन समझौते (SALT-III Agreement) के लिए बातचीत करेंगे।

मध्यम दूरी मारक परमाणु प्रक्षेपास्त्र संधि

(Intermediate Range Nuclear Force Treaty or I.N.F. Treaty)

अमरीकी राष्ट्रपति रीनाल्ड रीगन और सोवियत नेता मिलाइल गोर्बाच्चेव ने ॥ दिसम्बर, 1987 को जेनेवा में मध्यम दूरी मारक परमाणु प्रक्षेपास्त्र संधि पर हस्ताक्षर किये। संधि में इसे आई० एन० एफ० संधि कहा गया। इसे निरास्त्रीकरण की दिशा में सबसे प्रगतिशील कदम और रचनात्मक पहल माना गया।

संधि में प्रमुख व्यवस्थाएँ—संधि के तहत अमरीका और सोवियत संघ ने 500 किमी० से 5000 किमी० की दूरी तक भूमि पर से मार करने वाले सभी परमाणु प्रक्षेपास्त्रों को नष्ट करना स्वीकार किया। ये सभी परमाणु प्रक्षेपास्त्र मध्यम व कम दूरी तक मार करने की क्षमता रखते हैं। मास्को से 1050 किमी० दक्षिण पूर्व में वापुस्किन मार स्थित सोवियत सैनिक अड्डे से एस० एस०-12 और एस० एस०-22 प्रक्षेपास्त्रों को पूर्व की ओर छोड़कर नष्ट करने की बात कही गई। उधर

¹ अनेक विद्वानों के साथ रे० सुब्रह्मण्यम का भी यह मानना है कि साल्ट एक समझौता देशों की बर्तित करने वाला एक प्रमुख कदम था। उनका मानना है कि 'एक समझौते की सम्पन्न करने में तत्कालीन अमरीकी विदेश मंत्री हेनरी किस्सिजर ने अग्रगणित और अग्रगण्य भूमिका निभायी। उनके दिमाग में ही बाजें उड़ी जान पड़ती हैं। पहले बात तो यह थी कि चीन के साथ सम्बन्धों में मुधार के बाद किस्सिजर ज्यादा आत्म-विश्वास थे। दूसरी बात, उन्हें लगता था कि एक बार समझौता हो जाने पर सोवियत संघ को अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में यथा-स्थिति बनाने रखने के बारे में गहन मासिकारी के लिए तैयार किया जा सकेगा।' देखें, के० सुब्रह्मण्यम की पुस्तक पुनरुक्त में स्वयं उनका लेख *A Chaotic Doctrine*, 38-39.

अमरीका ने कैम्प केनावल से पश्चिम-2 प्रक्षेपास्त्रों को अटलांटिक की ओर छोड़कर नष्ट करने का निश्चय किया। संधि में इस तरह के प्रक्षेपास्त्र तीन साल के भीतर नष्ट करने पर सहमति हुई।

परमाणु प्रक्षेपास्त्रों की परीक्षण स्थल पर विशेष प्रकार से बनाये गये गड्ढों में जलाकर भी नष्ट किया जा सकता है, किन्तु इससे वायु प्रदूषण की आशंका अधिक है। अतः दोनों महाशक्तियों ने प्रक्षेपास्त्रों को एक विशेष दिशा में छोड़कर ही नष्ट करने का निश्चय किया। अमरीकी सीनेट और सुप्रीम सोवियत द्वारा आई० एन० एफ० संधि की पुष्टि (जून, 1988 में पुष्टि हो गयी) के तीन माह के भीतर निरीक्षक दल द्वारा उन सभी स्थलों के निरीक्षण की बात तय की गयी, जिनके नाम मूल संधि के साथ लगे सौ पृष्ठों में शामिल हैं।

आई० एन० एफ० संधि का मूल्यांकन—आई० एन० एफ० संधि की उपरोक्त व्यवस्थाओं से स्पष्ट है कि मध्यम और कम दूरी तक मार करने वाले सभी परमाणु प्रक्षेपास्त्र नष्ट कर दिये गये। संधि के हिसाब से देखें तो यह कुल परमाणु प्रक्षेपास्त्रों का मात्र 4 प्रतिशत है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पहला मौका था, जब परमाणु प्रक्षेपास्त्रों को 'समूल नष्ट' करने पर सहमति हुई। इससे पूर्व अब तक सिर्फ उनके उत्पादन पर 'नियन्त्रण' की बात कही जाती थी। यह संधि इस दृष्टि से भी ऐतिहासिक कदम है कि दोनों महाशक्तियों ने लम्बी मार के परमाणु प्रक्षेपास्त्रों को नष्ट करने की दिशा में प्रयास किया।

इस संधि के आलोचक यह कह सकते हैं कि संधि पर हस्ताक्षर इसलिए सहन हुए कि राष्ट्रपति रीगन ईरान-इराक की बदनामी के बाद इस माध्यम से अपना स्थान इतिहास में सुरक्षित करना चाहते थे। इसी तरह गोर्बाचोव देश में अपने 'सुधार कार्यक्रम' को सफल बनाने एवं तीव्र आर्थिक विकास के लिए सैनिक प्रतिस्पर्धा को घेरकर हस्तान्तरण निर्माण के खर्च में कटौती करना चाहते थे। इस बात को भी अनइस्का नहीं किया जा सकता कि इस संधि से दोनों महाशक्तियों के बीच सामरिक मतभेदों में कोई अन्तर नहीं पड़ा। मजली मार के परमाणु प्रक्षेपास्त्र यूरोपीय रणक्षेत्र में तैनात थे, जिसकी स्थिति को हेरमिरी समझने के बाद कतई संकटपूर्ण नहीं समझा जा सकता। कुल मिलाकर आई० एन० एफ० संधि निःसस्त्रीकरण का ठोस प्रयत्न है, इस बात का सकेत अधिक है कि महाशक्तियों ने आपसी सम्बन्धों में सुधार के लिए अपने-अपने मित्ररानुचर/आधिन देशों के सामरिक सुरक्षा हिੱसों को गौण माना।

वाशिंगटन वार्ता, 1990

जून 1990 में अमरीकी राष्ट्रपति जार्ज बुश और सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने बीच वाशिंगटन में शिखर वार्ता हुई, जिसके नतीजे काफी उत्साहवर्धक माने गये। दोनों नेता कुछ घण्टियों के सामरिक परमाणु अस्त्रों में 50 प्रतिशत तक की कटौती पर सिद्धान्त रूप में सहमत हुए। वे यूरोप में तैनात पारम्परिक सेनाओं और हथियारों में कमी के काम में तेजी लाने के लिए भी तैयार हुए। इस सम्बन्ध में पूरी संधि पर दिसम्बर 1990 तक हस्ताक्षर करना तय हुआ, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण इस 'स्टार्ट संधि' पर अगस्त, 1991 में ही हस्ताक्षर हो सके।

वाशिंगटन विश्वर-वार्ता के दौरान अमरीका और सोवियत संघ के बीच परमाणु एवं रासायनिक हथियारों में कटौती तथा व्यापार-वृद्धि सम्बन्धी महत्वपूर्ण समझौते हुए। हालांकि कुछ टिप्पणीकारों का मानना है कि बदले अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय परिवेश ने ये समझौते ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे, क्योंकि दोनों देश स्वयंसेव अपने रक्षा बजट पर खर्च लगातार कम करते जा रहे थे। दोनों देश हजारों टन विनाशकारी रासायनिक हथियार नष्ट करने और अपना शस्त्र भंडार पांच हजार टन तक घटाने पर सहमत हुए। इन्हे नष्ट करने का काम 1992 से शुरू होकर 2002 तक चलेगा। दोनों नए रासायनिक हथियारों का उत्पादन नहीं करेंगे।

दोनों नेताओं के बीच जर्मनी के एकीकरण और यूरोप में नई सुरक्षा व्यवस्था पर कोई सहमति कायम नहीं हो सकी। बुश चाहते थे कि एकीकृत जर्मनी 'नाटो' का सदस्य बने और 'नाटो' यूरोपीय सुरक्षा का केन्द्र बिन्दु रहे, जबकि गोर्बाच्योव ने बुश के समस्त सैनिक गठनों को धीरे-धीरे भंग करने और यूरोपीय देशों की सुरक्षा तथा उनमें सहयोग बढ़ाने के लिए 35 देशों का सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। गोर्बाच्योव ने मुझाव दिया कि एकीकृत जर्मनी दोनों श्रेणियों के बीच सदस्य रहे या दोनों गठनों में सदस्यता हासिल करे या फिर 'नाटो' के राजनीतिक ढांचे में भले ही शामिल हो किन्तु उसकी सैनिकी कमान से दूर रहे। किन्तु अमरीका को इनमें से कोई भी विकल्प मजूर नहीं था, जिससे उनमें इस पर मतभेद बने रहे।

हमारी समझ में वाशिंगटन विश्वर सम्मेलन को जबरन से ज्यादा तूल दिया गया, क्योंकि इनमें एक पक्ष का नेतृत्व ऐसे व्यक्ति ने किया, जिसकी अपनी स्थिति निरापेक्ष नहीं थी। यह बैठक ठीक उस समय हुई, जब सोवियत संघ के वास्तविक गणतंत्र जोर-शोर से आजादी या स्वातंत्र्य उठा रहे थे और गोर्बाच्योव अपनी 'पेरिस्त्रोयका' और 'ग्लासनोस्त्' की नीतियों में अपेक्षित सफलता न मिलने के कारण आलोचना के शिकार बन रहे थे। अफगानिस्तान से 'घायल यापसी' के बाद सोवियत संघ अमरीका से टकराने की स्थिति में गहरी रह गया आंतरिक व बाह्य परिस्थितियों के दबाव में अपनाया गया 'रियायती राजनय' अमरीका-सोवियत सम्बन्धी में स्थायित्व नहीं ला सकता था।

'स्टार्ट' संधि

(Strategic Arms Reduction Treaty or START)

अमरीका और सोवियत संघ ने 31 जुलाई, 1991 को मास्को में सम्मोहरी के हजारों नाभिकीय प्रयोगास्त्र खत्म करने के लिए साप्ताहिक अस्त्र परिसीमन संधि 'स्टार्ट' पर हस्ताक्षर किये। परमाणु अस्त्रों की कटौती की दिशा में इस संधि को ऐतिहासिक महत्व का प्रचारित किया गया। 600 पृष्ठों के इस समझौते पर अमरीकी राष्ट्रपति जार्ज बुश और सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाच्योव ने जिन शर्तों में दस्तखत किये वे 1987 की आई० एन० एफ० संधि के तहत नष्ट किये गये प्रयोगास्त्रों के टुकड़ों से बनी थी। ऐसा इस संधि को नाटकीय तरीके से अत्यन्त महत्वपूर्ण सलवाने-दशाने के लिए किया गया।

अमल में, स्टार्ट संधि दोनों महाशक्तियों के बीच नौ साल तक चली गम्भीर बार्ता का परिणाम है। इससे सोवियत संघ के परमाणु भंडार में 35 प्रतिशत और

अमरीकी नगर में 28 प्रतिशत का कृतीता हुआ। हमने दाना दाना के परमाणु हथियारों का मस्यौदा उतना ही ही जायदा जितना 1982 में बाजो गुरु हान के समय था।

हम कृतीता के बावजूद अमरीकी और मादियन मध्य में स हथियार के पास 6 000 सामरिक परमाणु हथियार बचे रहेंगे। जितना के नगर में अतिर-महाद्वारा और पनडुब्बी में छान जान बाव दनामिक प्रभुताओं तथा हवा में भार करने वाले कूट प्रभुताओं का मस्यौदा 1 600 रहे जायदा। हमने बावजूद अमरीकी के पास नौ हथियार और मादियन मध्य के पास मान हथियार परमाणु हथियार बचे रहेंगे। हम मध्य के मताधिक अव जितना में स प्रत्येक के पास सामरिक परमाणु हथियार प्रभुता बाह्य (एम० एन० ए० बा० सा०) का मस्यौदा 1600 में जितना नही ही मक्की।

मध्य के लहान जितना पस एल-डूमेर के महा जाकर मौके पर त्रितीय कर मक्की। पृष्टि और जाव के लिए दाना पस एक मनुज आगत मक्की।

हम मध्य 15 मान तक बंधे रहेंगे। हम अवधि के समान हान में बहुत न मध्य के स हम जितना जितना जा मक्की। अगर 15 वर्ष के बाव दाना पस मस्यौदा जा ता हम अवधि पाव बंधों के लिए बंधा जा जा मक्की।

हम मध्य का हम जितना में माधु माना जायदा जब अमरीकी हान हम दो निम्न बम में मक्की दाना। हम अमरीकी निम्न प्रक्रिया के लहान जितना मस्यौदा मान मान के मान तीन वर्षों में परमाणु हथियारों में मध्य की मक्की कृतीता करेंगे।

मगर हम मध्य में मस्यौदा में छान जान कूट प्रभुताओं का गामित नही किया गया है। मोविन मध्य में मा मध्य का परिधि में गामित करने पर जाव जितना छान किन्तु अमरीकी के मताधिक मता करने पर हमने हम छान किया। अतः जितना जितना न एक एक-दूसरे का 600 किनासातर में अधिक उम्मा दूरी के अतः परमाणु प्रभुताओं का हारी जितना मजूर कर दिया।

हम मध्य का पतिविक गुरुआन का मस्यौदा अवधि दो जा मक्की है किन्तु जाव जितना मताधिक के पास जितना अधिक विविध शक्तों में हमने मस्यौदा में हम मध्य बंधे बंधे पतिविक नही माना जा मक्की।

हम बंधे का एक मताधिक पस हम जा कि अमरीकी न मादियन मध्य का सामरिक हथियार में मध्य अनुकूल गुरु का मताधिक के धारणा का निम्न जितना के मताधिक मस्यौदा में वृद्धि और मादियन मध्य का बंध पमान पर अमरीकी मस्यौदा एक मस्यौदा मितन का जाव बंधा।

निम्नांकित के भाग में मस्यौदा में मध्य बाधा

निम्नांकित के बाव में मस्यौदा विनियम में मस्यौदा है कि हम मध्य में अतः प्रयास किए गए किन्तु आर्थिक मस्यौदा ही हाथ नहीं। निम्नांकित के भाग में जान बाव प्रमुख मस्यौदा एक बाधा निम्नांकित है

(अ) बंधा पतिविक का मताधिक मध्य अवधि बंधे—मताधिक का चार बंधा मताधिक—अमरीकी मादियन मध्य जितना और जान की अवधि बंधे मताधिक मताधिक है। हम मध्य जितना का मस्यौदा बंधे प्रतिक्रिया अतः हान के मताधिक है। हमने अवधि बंधे मताधिक मताधिक मताधिक मताधिक मताधिक है कि ब

उसे एकदम बदल भी नहीं सकते। इस प्रकार बड़ी शक्तियों की 'शस्त्रामिमुख अर्थव्यवस्थाएँ' निशस्त्रीकरण के मार्ग में एक महत्वपूर्ण बाधा के रूप में खड़ी हैं।

(व) संकीर्ण राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता—विभिन्न राष्ट्रों द्वारा अपने-अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए विदेश नीति निर्धारण करना स्वाभाविक एवं उचित है। परन्तु, उनके द्वारा मकीर्ण राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने पर निशस्त्रीकरण अभियान को गहरी ठेग पहुँचती है। एक राष्ट्र द्वारा संकीर्ण राष्ट्रीय हित की प्राथमिकता देने पर दूसरे राष्ट्र भी ऐसा ही करते हैं और निशस्त्रीकरण प्रयास अमफल हो जाते हैं।

(ग) शस्त्र लॉबी का दुष्प्रचार—बड़ी शक्तियों की शस्त्र लॉबियाँ (Arms Lobbies) निशस्त्रीकरण के विरुद्ध प्रचार करती रहती हैं। वे विभिन्न देशों में हमेशा यह प्रचार करवाती रहती हैं कि उनके शत्रु देश का सालाना प्रतिरक्षा बजट लगातार बढ़ता जा रहा है, ताकि नित नए शस्त्रों का आविष्कार एवं उत्पादन होता रहे और उन्हें मुक्तता मिलता रहे। किसी निशस्त्रीकरण समझौते के सम्पन्न होने पर वे उसकी आलोचना भी करती हैं। मसलन, मई 1979 में अमरीका और सोवियत संघ के बीच साल्ट-दो समझौता होने पर अमरीकी शस्त्र कम्पनियों की अनेक लॉबियों ने प्रचार किया कि साल्ट-दो समझौते से सोवियत संघ के मुकाबले अमरीका सैनिक रूप में कमजोर हो जायेगा। इस प्रकार इन शस्त्र लॉबियों के दुष्प्रचार से निशस्त्रीकरण अभियान की गति में अनेक प्रकार की रुकावटें उत्पन्न हो जाती हैं।

(द) एक-दूसरे पर श्रेष्ठता की स्थापना की महत्वाकांक्षा—राष्ट्रों द्वारा एक-दूसरे के विरुद्ध श्रेष्ठता (superiority) और सुरक्षा स्थापित करने की महत्वाकांक्षा से शस्त्रीकरण की होड़ आरम्भ हो जाती है। एक देश द्वारा शस्त्रास्त्र बनाने पर दूसरा देश क्रिया-प्रतिक्रिया सिद्धान्त (Action-Reaction Theory) के अनुसार स्वतः उसकी अपेक्षा अधिक अच्छे शस्त्र बनाने लगता है। मसलन, अमरीका और सोवियत संघ की ही हैं, जो शस्त्रीकरण की होड़ में सबसे आगे रहे हैं। अमरीका ने कुछ प्रक्षेपास्त्र बनाये तो सोवियत संघ ने उसके जवाब में 'बैकफायर' बमबर्षक (Backfire Bombers)। दोनों महाशक्तियाँ अनेक विस्फोटों के घातक परमाणु हथियार बनाने में सक्रिय रही हैं। उनके पास इन हथियारों की एक सतक निम्नान्वित उदाहरण से अधिक स्पष्ट हो जायेगी।

(1) भूतल से छोड़े जाने वाले प्रक्षेपास्त्र, जिनके कोने पर बम लगे होते हैं, जैसे अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र (Inter-Continental Ballistic Missiles) एवं मझौली दूर करने वाले प्रक्षेपास्त्र (Medium Range Ballistic Missiles);

(2) पानी में अन्दर से छोड़े जाने वाले प्रक्षेपास्त्रों जैसे (Submarine Launched Ballistic Missiles), और

(3) विमान स्थित प्रक्षेपास्त्र (Air-Borne Missiles), जो लड़ाकू विमानों से छोड़े जाते हैं। इस प्रकार राष्ट्रों द्वारा एक-दूसरे पर श्रेष्ठता एवं सुरक्षा स्थापित करने की महत्वाकांक्षा ने नित नई-नई विस्फोटों के हथियारों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है। यह प्रवृत्ति निशस्त्रीकरण के मार्ग में एक महत्वपूर्ण बाधा सिद्ध हो रही है।

(प) निरीक्षण एवं सत्यापन की समस्या (Problem of Inspection and Verification)—निशस्त्रीकरण के मार्ग में एक प्रमुख बाधा निरीक्षण तथा सत्यापन

की है। निशस्त्रीकरण वार्ताओं में प्रायः इस बात पर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है कि शस्त्रास्त्रों की कटौती और उनकी समाप्ति के लिए निरीक्षण और सत्यापन कर निशस्त्रीकरण के पूर्णतः पालन के बारे में यथार्थ का कैसे पता लगाया जाये ? किस गति से शस्त्र भण्डार समाप्त किये जायें ? कितने चरण में उन्हें समाप्त किये जायें ? इन सबका निरीक्षण एवं सत्यापन करने वाली सत्ता (Authority) कौन हो ? इसमें कौन से व्यक्ति होंगे ? आदि ।

(२) मार्गों को द्वारा बतायी गयी चार समस्याएँ—अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विख्यात विद्वान् हंस मार्गेंथो ने निशस्त्रीकरण के मार्ग में आने वाली जिन चार प्रमुख समस्याओं का उल्लेख किया है, वे निम्नांकित हैं

(i) विभिन्न राष्ट्रों के शस्त्रास्त्रों के बीच अनुपात कितना होगा ?

(ii) वह मापदण्ड क्या है, जिसके अनुसार इस अनुपात के तहत विभिन्न किस्मों एवं गुणों के शस्त्र विभिन्न देशों के लिए निर्धारित किये जायेंगे ?

(iii) उक्त दो प्रश्नों के उत्तरों का हृदयारो की मोधी गयी कमी पर वास्तविक प्रभाव क्या पड़ेगा ?

(iv) निशस्त्रीकरण का अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?¹ मार्गेंथो आगे कहते हैं कि किसी भी निशस्त्रीकरण प्रयास का सूर्यावन उक्त चार प्रश्नों के सन्दर्भ में किया जाना चाहिए। निशस्त्रीकरण की सफलता एवं असफलता इन्हीं पर निर्भर है। लेकिन ये चारों तथ्य करना अत्यन्त मुश्किल ही नहीं, बल्कि लगभग असम्भव है।

भारत और निशस्त्रीकरण (India and Disarmament)

समय-समय पर भारत की निशस्त्रीकरण नीति विभिन्न राष्ट्रों और विद्वान-विशेषज्ञों की अत्यधिक आलोचना का शिकार बनी है। इसका प्रमुख कारण यह है कि इसकी अजीब भू राजनीतिक स्थिति होने के साथ-साथ राष्ट्रीय हितों के विचार-धारा व साथ जटिल मन की आलोचक मही दम से समझ नहीं पाये हैं। आजादी के बाद प्रारम्भिक वर्षों में भारत सैनिक दृष्टि से ताकतवर देश नहीं था। इन वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में आ बोटा-बहुत प्रभाव भारत ने डालना चाहा, वह उसके द्वारा गुट निरपेक्षता अर्थात् महाशक्तियों और बड़ी शक्तियों की गुटबाजी से दूर रहने की नीति का पालन करने से पडा था। 1962 तक अफो-एशियाई महाद्वीपीय व कम ही दम म० रा० सघ के सदस्य बन थे, जिस कारण इस संगठन के अन्तर्गत होने वाले निशस्त्रीकरण प्रयासों में भारत द्वारा बहुत सक्रिय भूमिका निभाना सम्भव नहीं था। मगर 1962 में 18 देशों की निशस्त्रीकरण समिति में भारत को सदस्य बनाया गया, क्योंकि बड़े देश गुट-निरपेक्ष नीति की लोकप्रियता को देखते हुए सान गुट-निरपेक्ष देशों को इस समिति में सदस्य बनाना चाहत थे।

धीर-धीर निशस्त्रीकरण वार्ताओं में भारत की भूमिका का महत्व बढ़त लगा। अमरीका और सोवियत सघ के बीच मत-भिन्नता में भारतीय गुट-निरपेक्ष नीति की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। भारत ने बड़ी शक्तियों से अपील की कि उन्हें न तो गुट या

घमकी ओर न हो 'शीत युद्ध' के मुहावरों में बोलना चाहिए।¹ उसने निशस्त्रीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया।

भारत निशस्त्रीकरण का जोरदार पक्षधर क्यों ?

(अ) परमाणु शस्त्र आक्रामक—भारत द्वारा निशस्त्रीकरण का समर्थन करने का पहला कारण उसने परमाणु शस्त्रों को हमेशा सुरक्षात्मक नहीं, बल्कि आक्रामक और आत्मघाती माना है। उसने अपने विभिन्न प्रयासों में परम्परागत शस्त्रास्त्रों को भी कम करने पर सदैव जोर दिया है।

(ब) गरीब देशों की सहायता—भारत का मानना है कि शस्त्रीकरण पर किया जाने वाला असीमित खर्च यदि गरीब देशों को उनके विकास के लिए सहायता के रूप में दिया जाये तो यह अत्यन्त उपयोगी होगा। 1950 में इसी को भारत ने सं० रा० संघ में एक प्रस्ताव रखकर शान्ति कोष की स्थापना की सिफारिश की थी।

(स) आन्तरिक विकास के लिए जरूरी—निशस्त्रीकरण भारत के आन्तरिक विकास के लिए अत्यन्त उपयोगी है। नेहरू जी ने एक साक्षात्कार में कहा था कि शस्त्रीकरण पर हमारे ससाधन खर्च करने पर मुझे दुःख होता है, जबकि सामाजिक-आर्थिक विकास के क्षेत्र में बहुत कुछ किया जाना शेष है। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सामाजिक और आर्थिक स्थिति हमें निशस्त्रीकरण अपनाते की दिवंग करती है।²

(द) भारत विश्व शान्ति का पुजारी—भारत विश्व शान्ति एवं सुरक्षा का पुजारी है। यह अन्तर्राष्ट्रीय महयोग एवं सद्भाव कायम करने की कामना रखता है। उसका मानना है कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच के समझे हथियारों की लड़ाई से नहीं बल्कि शान्तिपूर्ण समाधान से हल किये जा सकते हैं।

भारत सं० रा० संघ के अधीन हुई निशस्त्रीकरण वार्ताओं के स्वरूप से असन्तुष्ट रहा। मसलन, जेनेवा स्थित निशस्त्रीकरण समिति की अध्यक्षता महाशक्तियों को ही करने का अधिकार था। भारत लगातार यह तर्क देता रहा कि यह समिति सं० रा० संघ के समस्त सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। 1979 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने सं० रा० संघ महासभा के विशेष अधिवेशन में बोलते हुए तीन बातें मुख्य रूप से कही—(अ) परमाणु अस्त्र गूँथ किये जायें; (ब) परम्परागत शस्त्रास्त्रों की होड़ रोकी जाये; और (स) निशस्त्रीकरण की गति तेज करने के लिए सं० रा० संघ की निशस्त्रीकरण समिति का ढाँचा बदला जाये। देसाई के इन प्रस्तावों से निम्नांकित ठोस प्रभाव पड़े—(अ) जेनेवा निशस्त्रीकरण समिति की सदस्य संख्या 18 में बढ़ाकर 33 कर दी गयी; (ब) निशस्त्रीकरण समिति की अध्यक्षता की बारी-बारी से सौंपने (Rotate) का निर्णय लिया गया; और (स) निशस्त्रीकरण समिति को सं० रा० संघ में ऊँचे दर्जे का स्थान दिया गया। मसलन, निशस्त्रीकरण समिति के सचिव को सं० रा० संघ के उपसचिव के समकक्ष माना गया।

¹ Jawaharlal Nehru, *India's Foreign Policy : 1946-61* (Delhi, 1961), 185.

² Narayan M. Gahate, *Disarmament in India's Foreign Policy, 1947-1965*, (Washington D C., 1966), 4.

भारतीय निशस्त्रीकरण नीति की आलोचना

ज्यो-ज्यो भारत मध्यम-स्तरीय विश्व शक्ति के रूप में उभरने लगा, त्यो-त्यो इसकी निशस्त्रीकरण नीति बहुत आलोचना का निशाना बनने लगी। आलोचकों द्वारा कहा जाने लगा कि 1963 वाली आंशिक परीक्षण रोक सन्धि पर भारत ने हस्ताक्षर किये थे जो उसने निशस्त्रीकरण में पूर्ण विश्वास का सूचक थी, किन्तु 1968 वाली परमाणु प्रसार रोक सन्धि पर हस्ताक्षर करने से मना करना उसने निशस्त्रीकरण में विश्वास को सन्देहास्पद बना देना है। इस समय भारत स्थल सैनिकों की संख्या के हिसाब से विश्व में दूसरा और वायु सैनिकों के हिसाब से पाँचवाँ स्थान रखता है। परम्परागत शस्त्रास्त्रों के क्षेत्र में यह विकसित देशों के समतुल्य हो गया है। मई, 1974 में राजस्थान के पोखरण नामक स्थान पर परमाणु परीक्षण उनका शस्त्रीकरण के इरादों को जाहिर करता है। भारतीय निशस्त्रीकरण नीति के अलोचन इस प्रकार के अनेक तर्क देते हैं।

परमाणु प्रसार रोक सन्धि पर हस्ताक्षर न करने का कारण

भारत द्वारा इस सन्धि पर हस्ताक्षर न करने का अर्थ कदापि यह नहीं लिया जाना चाहिए कि वह निशस्त्रीकरण का विरोधी है। इस सन्धि में अनेक प्रकार के दोष होने के कारण उसने इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। प्रमुख कारण निम्नावृत्त हैं—

(क) सन्धि भेदभावपूर्ण—इस सन्धि में की गयी व्यवस्थाएँ बड़ी शक्तियों और छोटे राष्ट्रों में भेदभाव करती हैं। मसलन, इस सन्धि के द्वारा बड़ी शक्तियाँ अपने परमाणु सयन्त्र अन्तर्राष्ट्रीय निरोक्षण के लिए खोलने को तैयार नहीं, जबकि छोटे राष्ट्रों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निरोक्षण अनिवार्य बन रही गयी है। भारत का तर्क है कि सभी राष्ट्रों के लिए बिना भेदभाव के समान व्यवस्था हो।

(ख) सन्धि परमाणु ऊर्जा के शान्तिपूर्ण कार्यों के उपयोग में बाधक—इस सन्धि पर हस्ताक्षरकर्ता दस द्वारा परमाणु ऊर्जा व शान्तिपूर्ण उपयोग में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। सन्धि में कहा गया है कि हस्ताक्षरकर्ता दस परमाणु ऊर्जा व शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए प्रयोग के बार में वे अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ समझौता कर ही ऐसा करेंगे। इसने होगा यह कि बड़ी शक्तियाँ दबाव की कूटनीति अपनाकर या तकनीकी आधार का बहाना बनाकर अनेक प्रकार की बाधाएँ खड़ी कर देंगी, जिससे छोटे राष्ट्र परमाणु ऊर्जा का शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए प्रयास नहीं कर सकेंगे। भारत इस आधार पर इसका विरोध करता है।

(ग) चीन का आक्रामक रवैया जग-जाहिर—1954 में 'पंचशील' समझौता करने वाले पड़ोसी दल साम्यवादी चीन 1962 में भारत के साथ सैनिक मुठभेड़ पर उतर आया। 1964 में उसने परमाणु बम बना लिया। यद्यपि वह भारत को धमकी देता रहता है। उसने वियतनाम पर 1979 में हमला कर दिया। इन सब बातों को देखते हुए भारत का चीन के आक्रामक परमाणु रवैया से भावधान रहना पड़ता है, जिस कारण भारत परमाणु प्रसार रोक सन्धि पर बँस हस्ताक्षर कर सकता है।

(घ) पाकिस्तान परमाणु बम बनाने में सक्षम—पाकिस्तान काफी वर्षों से परमाणु बम बनाने का बरमक प्रयास कर रहा है। इसके लिए उसने पश्चिमी यूरोपीय देशों से परमाणु साज-समान की चोरी तथा तस्करी की। लीबिया एवं सऊदी अरब, इजराईल के खिलाफ लड़ने के लिए पाकिस्तान द्वारा परमाणु बम बनाने के प्रयास में विजाल आर्थिक मदद देते रहे हैं। हालाँकि वे उसे इजराईल के विरुद्ध इस्लामी बम की सहायता देते हैं, किन्तु पाकिस्तान इसे भारत के विरुद्ध प्रयोग करेगा क्योंकि वह भारत को पढ़ने दर्जे का शत्रु मानता है, इजराईल को नहीं। ऐसी अवस्था में भारत परमाणु प्रसार रोक सन्धि पर हस्ताक्षर कर सदैव के लिए अपने हाथ कैसे बँधवा सकता है ?

(ङ) भारत एक शान्तिप्रिय देश है—भारत हमेशा शान्तिप्रिय देश रहा है। उसने निशस्त्रीकरण का सदैव समर्थन किया है। 1974 में पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण करने के बावजूद उसने परमाणु बम का निर्माण नहीं किया, जो उसके परमाणु ऊर्जा के शान्तिपूर्ण कार्यों के प्रयोग का सूचक है। परमाणु प्रसार रोक सन्धि पर द्विपक्षीय करते हुए मेसन विलरिच (Mason Willich) ने नहीं ही कहा है कि 'इस सन्धि का अर्थ है—परमाणु हथियारों पर अनिश्चित काल तक मौजूदा पाँच परमाणु देशों का एकाधिकारपूर्ण नियन्त्रण (exclusive control) रहना। इस सन्धि का मकसद किसी छठे देश को परमाणु हथियार सम्पन्न बनने से रोकना है। सन्धि में यह बात भी निहित है कि परमाणु आयुध-विहीन राष्ट्र को किसी भी हमले से सुरक्षा के लिए एक या अधिक परमाणु हथियार सम्पन्न देशों पर अनिश्चित काल तक के लिए निर्भर रहना पड़ेगा।'¹ यही कारण है कि शान्तिपूर्ण राष्ट्र होने के बावजूद भारत ने इस सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं। के० सुब्रह्मण्यम ने ठीक ही कहा है कि 'परमाणु निशस्त्रीकरण का प्रश्न औद्योगिक जगत की जनता के दिलों-दिमाग में ही जीता जायेगा। इसके लिए यह जरूरी है कि परमाणु अस्त्र प्रसार पर रोक की अपेक्षा परमाणु अस्त्रों के विरुद्ध मुहिम खड़ी आये। दुनिया को यह बात समझनी होगी कि परमाणु अस्त्र युद्ध के नहीं, बल्कि आतंकवाद के उपकरण हैं। पिछले ढाई दशकों में यह बात भलीभाँति स्पष्ट हो चुकी है कि परमाणु अस्त्र प्रसार रोक सन्धि विषयक भारतीय मत तर्कसंगत है और इसको मिलने वाला अन्तर्राष्ट्रीय समर्थन क्रमशः बढ़ता जा रहा है।

¹ The Non-Proliferation Treaty implies that nuclear weapons will remain under the exclusive control of the present five nuclear weapon states for the indefinite future. The treaty is intended to prohibit any Sixth State from acquiring nuclear weapons and to foreclose the possibility of transferring nuclear weapons to multilateral structure, even though no increase should occur in the number of powers in the global system having control of nuclear weapons. The treaty also inescapably implies that, in a world limited to five nuclear weapon States, non-nuclear States will have to rely for the indefinite future on one or more nuclear weapon States as guarantors of their security against aggression.—Mason Willich, 'Non-Proliferation Treaty: Framework for Nuclear Arms Control' (Charlottesville, Va., 1969), 178

पश्चिमी एशिया की राजनीति

मिस्र से लेकर इराक तक फैला भू-भाग 'पश्चिम एशिया' के रूप से विख्यात है। जैसे यह परिभाषा बहुत सन्तोषजनक नहीं, क्योंकि लगभग इसी क्षेत्र के लिए अबसर 'मध्य-पूर्व' का प्रयोग भी होता है। हाल में इसमें सीरिया और कभी-कभी अफ्रीका के उत्तर-पश्चिमी छोर पर स्थित अल्जीरिया को जोड़ दिया जाता है। इसी तरह 'अरब विश्व' का उल्लेख किया जाये तो इस परिभाषा में छाड़ी देशों (ओमान, समुक्त अरब अमीरात, दुबई, यमन आदि) को जोड़ना आवश्यक हो जाता है। प्रथम विश्व-युद्ध के बाद के वर्षों से ही इस क्षेत्र की ये अलग-अलग परिभाषाएँ—मिक्ट-पूर्व, मध्य-पूर्व, पश्चिम एशिया और 'अरब विश्व' एक साथ प्रचलित हैं।

वस्तुतः यह असमंजस में डालने वाली बात नहीं, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के लगभग सभी अध्येता इस बात को भली-भाँति जानते हैं कि इन सभी नामों का अर्थ ईरान से लेकर अल्जीरिया तक फैले उस क्षेत्र से है, जिसकी बहुमहत्व आबादी अरब है और इस्लाम धर्मावलम्बी है। यह भी सच है कि इन दो महाद्वीपों को मिला देने वाले क्षेत्र की भौगोलिक व भू-राजनीतिक परिभाषा भी काफी अस्पष्ट है। एक ओर भू-मध्य सागर तो दूसरी ओर अरब सागर की जल राशि इस यूरोप तथा मुख्य एशियाई भू-भाग से अलग करती है। स्वेज नहर के निर्माण तक अफ्रीका और एशिया के बीच कोई प्राकृतिक या कृत्रिम व्यवधान भी नहीं था। इसी तरह स्वयं अफ्रीकी महाद्वीप में पश्चिम एशियाई भू-भाग को महारा का महसूस अफ्रीकी नीपों मस्कार बाने हिस्से में अलग करता है। धार्मिक समानता के बावजूद जानिगन अन्दर के कारण उनमें समानता से अधिक भेद स्पष्ट होता है। इतना ही नहीं, पश्चिम एशियाई देश एक सांस्कृतिक विषय में भी भागीदार हैं। आज से नहीं, सैकड़ों वर्ष पहले से अरब लोग अपने नौमनिक, व्यापारिक, उद्यम और वैज्ञानिक-राजनीकी उपलब्धियों के लिए विख्यात रहे हैं। यह भी नहीं भुलाया जा सकता कि ईसा के जन्म व हजारों वर्ष पहले नील नदी के तट पर और दक्कन परहद की घाटियों में उत्कृष्ट नागरिक सभ्यता का विकास हो चुका था। जब मध्ययुगीन यूरोप अंध-विश्वास की बेड़ियों में जकड़ा था, तब अरब सैनिक विजेता स्पेन तक की अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने में सफल हुए। अधिकांश अरब देश दस ऐतिहासिक दौर में एक जैसे स्थानावरोधन बचावली रूप में समझिं थे। उनके आर्थिक विकास का स्वरूप भी बनावेन एवं जैसा रहा। इस तरह यह बात प्रमाणित होनी है कि आदि काल से ही पश्चिम एशिया (मध्य पूर्व या चाहे किसी अन्य नाम से पुकारा जाये) अपनी अलग भौगोलिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान बनाये हुए है।¹

¹ अरब लोगों के प्रारम्भिक इतिहास, उनके साम्राज्यिक महत्त्व और विश्व को उनके सांस्कृतिक योगदान के लिए देखें—Petter Mansfield, *The Arabs* (London, 1978)

पश्चिम एशियायी क्षेत्र का महत्व

यूरोपीय शक्तियों औपनिवेशिक काल के प्रारम्भिक दौर से ही इस क्षेत्र के राज्यों का भू-राजनीतिक महत्व भलीभाँति समझती रही है। नेपोलियन मिस्र में फ्रांस की जड़ें झमीलाने रोपना चाहता था कि ब्रिटेन एशिया में अन्यत्र अपना प्रसार निर्द्वन्द्व रूप से न कर सके। स्वेज-नहर के निर्माण के बाद इस क्षेत्र का सामरिक महत्व और भी बढ़ गया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में जर्मनी और रूस की रुचि साम्राज्यवादी प्रतिद्वन्द्विता के कारण इस क्षेत्र में बढ़ी। बर्लिन-बग्दाद रेल मार्ग का निर्माण और मोरक्को-अल्जीर संकट इस प्रकृति के प्रमाण हैं। पहले विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की रुचि अरब राजनीतिक उतार-चढ़ाव में और गहरी हुई तथा राष्ट्र-राज्यों के निर्माण व संरक्षण के मध्य ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियाँ अनिवार्यतः जुड़ गयीं। टी. ई. लॉरेंस (T. E. Laurence) जैसे दुस्साहसिकों की शौर्य गाथाएँ इसी युग की देन हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फोर्ड मार्शल रोमेल और मोटगोमरी की नाटकीय मुठभेड़ों ने भी इस क्षेत्र के सामरिक महत्व को रेखांकित किया।

यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात की ओर ध्यान दिमाया जाना जरूरी है। प्रथम विश्व युद्ध के ठीक बाद पश्चिम एशिया के रेगिस्तानी इलाकों में बड़े पैमाने पर उत्कृष्ट किसम के तेल मयारों का पता चला। विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण यूरोप के लगभग सभी राष्ट्र इन पर अपना कब्जा करने के लिए व्याकुल हो उठे। इनमें सम्भवतः सबसे दूरदर्शी राजनयिक ब्रिटिश प्रशासक सर ओलेफ़ केरो थे, जिन्होंने इन तेलक्षूपों को 'शक्ति का कुूप भण्डार' नाम दिया और 'वेल्ल ऑफ़ पावर' (Wells of Power) नामक एक पुस्तक भी लिखी।

अधिकतर अरब देश इस स्थिति में नहीं थे कि वे अपनी तेल सम्पदा का दोहन अपने बूते पर करते। कयायमी वैमनस्य के कारण अनेक राजवंश अपने को निरापद रखने के लिए विदेशी औपनिवेशिक सहायता पर निर्भर थे। ऐसे में पश्चिमी तेल सम्पत्तियों की धुलपेठ का काम आसान हो गया। इन पश्चिमी स्वार्थों के हित में यह निहित था कि इस क्षेत्र को आदिम हालत में ही रखा जाये। प्रगति-परिवर्तन की दर तेज होने से उनकी अपनी स्थिति को खतरा पैदा हो सकता था। यदि आज पश्चिम एशिया की राजनीति का सत्कार सामन्ती, मध्ययुगीन और कबायली है तो हमारे लिए पश्चिमी औपनिवेशिक नीतियाँ ही जिम्मेदार हैं। अधिकतर अरब देश कमी गुलाम नहीं रहे, परन्तु उनकी स्थिति संरक्षित (Protectorate) पर निर्भर इकाइयों की रही।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिम एशिया में निर्णायक मोड़

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो ऐसी घटनाएँ हुईं, जिन्होंने पश्चिम एशिया की राजनीति को अप्रत्याशित और निर्णायक मोड़ दिया। इनमें एक पा इजरायल का गठन और दूसरा, चीत युद्ध का आविर्भाव। वस्तुतः ये दोनों घटनाएँ आपस में मिली हुई हैं और सत्रिणात के कारण ज्यादा घातनाक बन गयीं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में नाजी तानाशाही ने यहूदियों पर अमानवीय अत्याचार किये और इन यहूदियों के प्रति सहानुभूति का विश्वव्यापी ज्वार उठा। 19वीं शताब्दी के आखिरी चरण से ही यत्र-तत्र बिखरे हुए यहूदी अगनी मातृभूमि

फिलस्तीन लौटने की माँग उठाते रहते। परन्तु दो हजार वर्ष पुराने महानिष्क्रमण (Exodus) को अनकिया करना यथार्थवादी नहीं समझा जाता था। 1945 के बाद बदली परिस्थिति में विजिता और पराजित दोनों ही तरह के यूरोपीय लोग यहूदियों के प्रति अपराध-शोध में ग्रस्त थे और यहूदियों की मानृभूमि के पुनर्निर्माण के लिए तैयार हो गये। उम वक्त किसी को यह सोचने की पुर्नत नहीं थी कि दो हजार वर्षों से फिलस्तीन में रहने वाले इन अरबों का क्या होगा? धर्म और जाति के आधार पर गठित इजराईल न केवल एक कृत्रिम-आरोपित राज्य था, बल्कि इसके नागरिक अनेक देशों से लाये गये थे। अपनी अस्मिता की तलाश में उनको यही बात सबसे सहज लगी कि बाहरी अरब शत्रु को तलाश कर लिया जाये। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह हुई कि नाजी अत्याचारों के फलस्वरूप प्रतिशोध की जो भावना यहूदियों के मन में दलबली हुई थी, उसका शिकार निर्दोष फिलस्तीनियों और हरिज-दुबल अरबों को बनना पड़ा।¹

शीत युद्ध ने अपने कुतर्कों द्वारा पश्चिम एशिया के चेहरे को और भी कुरूप बना दिया। डलेमकालीन अमरीका को यह लगता था कि अनेक दुर्बल अरब राज्य अस्तिर हैं और समाजवादी र्ज्ञान के कारण खतरनाक। इनमें साम्यवाद का प्रसार आसानी से हो सकता है। इसी कारण इजराईल को भरपूर सैनिक व आर्थिक सहायता देने में अमरीका कभी हिचकिचाया नहीं। यह भी जोड़ने की जरूरत है कि अमरीका की आन्तरिक राजनीति में यहूदी मतदानार्थों का महत्वपूर्ण स्थान है। उनके प्रभाव एवं सक्रियता के कारण इजराईल का समर्थन अमरीका की विद्यता बन गया। शीत युद्ध के प्रारम्भिक दौर में 'नोर्दर्न टियर' (Northern Tier) वाली रणनीति के अनुसार अमरीका ने 'सेण्टो' के गठन का प्रयत्न किया, परन्तु इसकी निरर्थकता मिस्र तथा इराक में तरना पतल के बाद सामने आ गयी। साथ ही अनेक अरब राष्ट्रों में (जैसे मऊदी अरब) में बड़े पैमाने पर अमरीकी पूँजी निवेश के कारण इनसे रिश्ते तीव्रता सम्भव न था। इन्हें पूँजी-बहुलाकर या डरा-धमका कर साथ रखना अमरीका के लिए आवश्यक था। कुल मिलाकर परिणाम यह हुआ कि पश्चिम एशिया की राजनीति में 1945 के बाद दो गहरी दरारें पड़ गयी। इनमें एक दरार इजराईल और अरब राष्ट्रों के बीच थी तो दूसरी अमरीका के पिछलग्गू अरब राज्या तथा मोवियन सघ के पक्षधर अरबों के बीच। पश्चिम एशिया की राजनीति के तमाम उत्तार-चढ़ाव इस ऐतिहासिक घृष्टभूमि का ध्यान में रखते हुए बिन्देपित किये जाने चाहिए।

अरब-इजराईल संघर्ष के कारण (Causes of Arab-Israel Conflict)

अरब इजराईल संघर्ष के प्रमुख कारण निम्नांकित हैं -

1. साम्प्रदायिक वैमनस्य—यह बड़ी विचित्र बात है कि अरब और यहूदी इजराईली, जो पिछले चार दशक से एक-दूसरे के खून के प्यासे बन हैं और चार बार सर्वनाशक दंग में रक्तशेय में डूबकर चुक हैं, वे एक ही नस्ल के हैं और इस बात को झुठलाने हैं कि अरब-इजराईल संघर्ष का एक आधार जातीय वैमनस्य वाला

¹ इसका जानकारी के लिए देखें—Walter Laquer, *Confrontation : The Middle East and World Politics*, (London, 1974)

है। अरब और यहूदी 'सिमेटिक' भस्ल के हैं और ईसा के जन्म के पहले इनकी जीवन-यापन शैली, रहन-सहन व धार्मिक मान्यताएँ एक सी थी। लेकिन प्रमदा ईसाई धर्म के प्रसार तथा इस्लाम के अधिर्भाव के कारण विभिन्न धर्मावलम्बियों के बीच की खाई में उनकी जीवन-यापन शैली को इतने बुनियादी ढंग से परिवर्तित किया कि एक ही जग-जाति के लोग एक-दूसरे के लिए अपरिचित हो गये। इस्लाम और यहूदी धर्म दोनों ही कट्टर हैं। वे अपनी व्यवस्था के बाहर किसी और ईश्वर को नहीं पहचानते। सैदान्तिक रूप से सहिष्णुता की बात भले ही नाम-गान को कही जाये, किन्तु व्यवहार में ऐसा अपवादस्वरूप ही होता है। इसी कारण बाइबिल के पुराने 'टेस्टामेंट' में वर्णित पैगम्बरों, हजरत मूसा, इब्राहीम आदि की साक्षेदारी होने पर भी ईसाइयों और यहूदियों के बीच सदियों से न पाटी जा सकने वाली दरार रही है। इस्लाम के साथ तो यह अन्तर और भी गहरा है। फिलस्तीनी प्रदेश में ईसाई वर्चस्व बढ़ने के साथ हिब्रू लोगों का निष्क्रमण तेज हुआ। इधर-उधर तितार-बितर होने के बाद अपनी अस्मिता अखत रखने के लिए उन्हें धार्मिक कट्टरता का सहारा लेना पड़ा। उनके मन में निरन्तर यह भावना घनी रही कि उन्हें बेधर किया गया है और एक न एक दिन वे वापस अपनी जन्मभूमि में लौट जायेंगे—जियोन पर्वत की तलहटी में स्थित फिलस्तीन में।

यहूदी लोगों का फिलस्तीन के बाहर 'प्रवास' लगभग दो हजार वर्ष लम्बा रहा। इस बीच धर्म युद्धों के दौर में यह प्रदेश ईसाईयों और मुसलमानों के बीच धार्मिक कहर का बन गया। अतः जब 1945-46 में इस स्थान में यहूदियों को फिर से बसाया गया, तो अनेक मुसलमानों और कुछ ईसाइयों को इस बात में असन्तोष हुआ। उन्हें लगा कि उनके धार्मिक स्थानों की पवित्रता कट्टर यहूदियों द्वारा नष्ट कर दी जायेगी। अरब-इजराईल संघर्ष की कटुता-कट्टरता और हिंसा को बढ़ाने के लिए यह धार्मिक-मातृप्रदायिक कारण मुख्य रूप से उत्तरदायी है। अधिकांश अरब राष्ट्रों में, जहाँ साक्षरता का विस्तार अधिक नहीं और सामाजिक विग्रसता व्याप्त है, धर्म के नाम पर ही एकता और दिशा प्राप्त की जा सकती है। द्वितीय विश्व युद्ध के काल से ही अरब देशों के लिए इजराईल के माथ मुठभेड़ 'जिहाद' का नया संस्करण है। इसी तरह इजराईल का निर्माण धर्म के आधार पर ही किया गया। यहूदी धर्म तथा सभ्यता के बीच विभाजन रेखा बहुत अस्पष्ट है। यहूदियों के सांस्कृतिक अवचेतन में यह अनुभूति गहरी रही है कि बार-बार आक्रमणकारी उनके प्राचीन मन्दिरों को तोड़ने के लिए दुस्माहसिक अत्याचार करते रहे और उन्हें शरणार्थी बनाते रहे। छापामारी के बाद ही वे अपने संसूचे (इजराईल को स्थापना) प्राप्त कर सके और आज भी अपनी रक्षा शस्त्र से ही कर सकते हैं। इस धार्मिक-मातृप्रदायिक स्वर के कारण अरब-इजराईल संघर्ष का तर्कसंगत विदलेपन करना असम्भव कठिन हो जाता है, क्योंकि धर्म एवं आस्था के प्रश्न भावावेश, आवेग और अन्ध-विराग से जुड़े रहते हैं, विवेक और बुद्धि से नहीं। हम अपने वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण को अरब देशों और इजराईलियों पर प्रत्यारोपित नहीं कर सकते और न पश्चिम एशिया में मजहब की राजनीति को अनदेखा कर सकते हैं।

2. सामाजिक व आर्थिक कारण—प्रसिद्ध यहूदी इतिहासकार इसाक डोवशर का कहना था की यहूदी लोग सीमान्ती होते हैं। ऐसे सीमान्ती शरणार्थी व्यक्ति या समूह के लिए हमेशा यह विवशता होती है कि वे अपने उत्थान, कीदल, प्रभुत्वप्रयत्न,

अध्यवसाय आदि से जीविकोपार्जन करें और अपने ऊपर होने वाले शोषण-उत्पीड़न के दुष्परिणामोन्मुक्तभावों को कम कर सहनीय बना सकें। यहूदी शरणार्थियों का दो हजार वर्षों सम्बन्धी इतिहास इस तर्क को मजबूत सिद्ध करता है। न केवल इधर-उधर भटकने वाले यहूदी बचे रहे, बल्कि उन्होंने अपनी पहचान सुरक्षित रखी एवं संगीत, कला, विज्ञान, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व पूँजी निवेश के क्षेत्र में अद्भुत मौलिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इन क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियाँ उल्लेखनीय रहीं। विडम्बना तो यह है कि इस सफलता ने 20वीं सदी में अरबों के साथ वैमनस्य को बढ़ावा ही दिया। फिनलैंड प्रदेस प्रथम विश्व युद्ध तक तुर्की साम्राज्य का हिस्सा था। 1920 में उसे मेडेट क्षेत्र घोषित कर दिया गया और वह ब्रिटेन के नियन्त्रण में आया। 1925 की वेल्फूर घोषणा के अनुसार इसके बाद प्रथम यहूदी दूसरे देशों से साकर यहाँ बसाये जाने लगे। 1920 में कुल आबादी में यहूदियों का 16 प्रतिशत हिस्सा था और 1947 तक यह बढ़कर 24 प्रतिशत हो गया। स्थानीय अरब इनकी मुलना में अपेक्षाकृत कम शिक्षित और कम परिश्रमी थे। उन्हें लगता रहा कि ये बाहरी दुमपंथियों धीरे-धीरे उन्हें बेघर कर देंगे और सभी सामग्र्य उद्योग-धन्य हथिया लेंगे। एक सीमा तक हुआ भी यही।

3. इजराईल की स्थापना—यों तो वेल्फूर घोषणा ने यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय निवास (National Home) की व्यवस्था सुझायी थी और मेडेट कान में इस दिशा में कुछ प्रगति भी हुई थी, किन्तु अरब राष्ट्र यह मतलब को तैयार नहीं थे कि उनकी भूमि में कोई इजिप्त राज्य जबरन बनाया जायेगा। अरबों की भूमि यहूदियों को हस्तान्तरित करने में साम्प्रदायिक बैर को आधिक्य हिमों के घातक टकराव में बदल दिया था। फिर भी थोड़ी आशा बची थी कि संयुक्त राष्ट्र सभ के तत्वावधान में परामर्श द्वारा सर्वसम्मति से कोई व्यवस्था ही सकती है। अनेक प्रयत्नों के बाद भी ऐसा सम्भव नहीं हुआ। अन्ततः 14 मई, 1948 को ब्रिटेन ने फिनलैंड में मेडेट सम्पत्ति की घोषणा की और इसके साथ ही यहूदी राज्य 'इजराईल' की स्थापना कर दी गयी। बेहद नाटकीय ढंग से अमरीका ने पाँच मिनट के भीतर इस नये राज्य को मान्यता दे दी। शीघ्र ही सोवियत सभ ने भी इसे मान्यता दे दी। दोनों महाशक्तियों के अलावा ब्रिटेन और फ्रान्स द्वारा सहायता का आश्वासन पाने के बाद इजराईल अपनी सुरक्षा के लिए हथियार उठाने को तैयार हुआ। वह न केवल अरब देशों के संयुक्त आक्रमण को झेलने में सफल हुआ, बल्कि उसने आक्रमणकारियों के बहुत बड़े भू-भाग को भी अपने अधिकार में ले लिया। शुरु में इजराईल का क्षेत्रफल कुल 14,100 वर्ग किमी० था परन्तु इस युद्ध के बाद उसने इसे 20,700 वर्ग किमी० तक बढ़ा लिया। पश्चिमी गैलीली, मिनाई तथा पश्चिमी नेगेव का बड़ा हिस्सा इजराईल में जुड़ गया। जेरुसलम नगर का बड़ा हिस्सा तथा गाजा पट्टी के कुछ हिस्से पर इजराईल का अधिकार हो गया। अरबों की इस हार न विश्व भर में उनका भयकर जातीय एवं राष्ट्रीय अपमान कर दिया। इसके बाद अरबों में अपने राष्ट्रीय गौरव और जातीय अहंकार की पुनर्स्थापना के लिए प्रतिशोध की भावना भविष्य में युद्ध का एक और कारण बनी।

4. भू-राजनीतिक कारण—प्रथम अरब-इजराईल युद्ध के बाद इस वैमनस्य में एक भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा (Geo-Political Rivalry) भी जुड़ गयी। मिस्र न गाजा पट्टी (Gaza Strip) के हिस्से पर कब्जा कर लिया (अन्यत्र हार के

वायजूद) जो आक्वा की खाड़ी के रास्ते इजराईल को भू-मध्य सागर से जोड़ती थी। इजराईल के लिए यह सामरिक महत्व की पट्टी थी। इसी तरह सिनाई और गोलान पहाड़ियों पर कब्जा करने के बाद इजराईल, सीरिया तथा जोर्डन के लिए आगलवा खतरा बन गया। इसके बाद क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे अरब-इजराईल युद्धों ने संधि के नये-नये धीज बोये। 1956 में स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के बाद पश्चिमी राष्ट्रों ने उत्तेजित होकर मित्र पर हमला किया और इजराईल को फिर इस बात का मौका मिला कि वह कुछ अरब क्षेत्र पर कब्जा कर ले। अरबों को अपमान का एक घूंट तो पीना ही पड़ा, किन्तु साथ ही यह सकट भी उजागर हो गया कि स्वेज जल-मार्ग पर आवागमन अबाध रहना इजराईली कृपा पर निर्भर है। स्वेज जल-मार्ग का सामरिक महत्व न केवल अरब राष्ट्रों, बल्कि सभी पश्चिमी देशों के लिए भी है। स्वेज नहर के नाटकीय ढंग से राष्ट्रीयकरण के बाद अनेक पश्चिमी राष्ट्रों को यह लगना स्वाभाविक था कि अस्थिर अरब सरकारों की अपेक्षा कुशल-सफल इजराईल ही उनके हिन्नों के सर्वर्धन में गहायक सिद्ध हो सकता है। बड़े पश्चिमी समर्थन ने इजराईल को उस आक्रामकता को बढ़ावा दिया।

इसी तरह 1967 में आक्वा की खाड़ी की नाविकी (अब अबसा पश्चिम जलाने के बाद) के साथ मित्र ने इजराईल को एक तरह से आक्रमण के लिए आमन्त्रित किया। इस बार अरबों ने और भी करारी हार का मुँह देखना पड़ा। इजराईल ने बहुत बड़े भू-भाग पर कब्जा कर लिया और लाखों फिलस्तीनी लोग शरणार्थी बन गये। इस ऐतिहासिक संधि के दौरान यह प्रमाणित हो गया कि संपुक्त राष्ट्र संघ के कोई भी प्रस्ताव इस क्षेत्र में युद्ध विराम को बरकरार रखने और शान्ति लौटाने के लिए गीमित दामता चाले है। अरबों के लिए प्रतिशोध और भी अधिक महत्वपूर्ण बन गया तो इजराइलियों का अहंकार और दुस्साहस भी बढ़ गये। इन दोनों ही बातों ने पश्चिम एशिया में संवट बढ़ाया।

5. तीसरा युद्ध—पश्चिम एशिया का सकट तीसरा युद्ध के कारण भी गहरा हुआ। भले ही आरम्भ में सोवियत संध ने इजराईल को धान्यता दी, किन्तु आगे चलकर विशेषकर स्वेज प्रसंग के बाद से सोवियत संध ने अरब राष्ट्रों का पक्ष लेना आरम्भ किया। स्वेज नहर में पश्चिमी देशों के हस्तक्षेप के बाद युद्ध विराम सब ही सम्पन्न हुआ, जब सोवियत संध ने परमाणु अस्त्रों के प्रयोग की घमनी दी। इसी तरह यह बात भी स्पष्ट देनी जा सकती है कि इजराईल संपुक्त राष्ट्र संघ की तथा सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों की इनकी आसानी से अवहेलना इसलिए करता रहा है कि उसे अमरीकी वोटों का समर्थन-विश्वास प्राप्त है। 1956 का युद्ध हो या 1967 का इजराइली वायु सेना का अद्भुत प्रदर्शन, वह तब तक सम्मद नहीं था, जब तक अमरीकी दस्त्रास्थ और बड़े पैमाने पर सुलभ नहीं कराये जाते। इसके जवाब में सोवियत संध ने गिब, इराक और सीरिया की हथियारबन्दी की तथा 1967 के बाद मिस्र की जमीन में आगमन पर बार कर सकने वाले परिष्कृत प्रक्षेपास्त्र सुलभ कराये। तीसरा युद्ध के तर्क और दवाव के अनुसार लिये गये इन फैसलों ने पश्चिम एशिया में प्रतिद्वन्द्वियों को परस्पर मुठभेड़ के लिए बढ़ाया।

महाशक्तियों ने लिए पश्चिम एशिया का सामरिक महत्व दो तरह से था। अमरीका और रूस दोनों अपनी तेल-जूरतें अपने संगमर्धनों में पूरी कर सकते थे। परन्तु दोनों पश्चिमी यूरोप, जापान तथा गुट निरपेक्ष देशों तक पहुँचने वाले तेल पर

अपना अधिकार व प्रभाव बनाये रखना चाहते हैं। इनके अतिरिक्त अमरीका यह प्रचारित करता रहा कि नास्निक साम्यवादियों के विस्तार को रोकने के लिए घर्म-भीरु इस्लामी राजनयन के पाये मजबूत करना जरूरी है। इनके विपक्ष में मोवियन तर्क यह था कि मध्ययुगीन अन्व-विश्वाम और मामन्नी सामाजिक विपमता से तब तक मुक्ति नहीं पायी जा सकती, जब तक कि प्रगतिशील समाजवादी विचार-धारा का प्रसार इस क्षेत्र में नहीं होता। इसी विचित्र तर्क प्रणाली के आधार पर इजराईल का समर्थन करने के साथ-साथ अमरीका मऊदी अरब, मोरक्को और ओडन जैसी जगहों में राजवश को सैनिक साज-सामान बेचना रहा है। पश्चिम एशिया के दशों में बड़े पैमाने पर महँगे हथियारों और सड़क विमानों आदि की खरीद पश्चिमी साम्राज्यवादी दशों में सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान को लाभप्रद ढंग से व्यस्त रखती है। इसका अच्छा वर्णन एंथनी सैम्पसन (Anthony Sampson) ने अपनी पुस्तक 'दि आम्स बाजार' (तदन, 1977) में किया है। स्पष्ट है कि जब तक पश्चिम एशिया में तनाव बना रहता है, तब तक मोन के इन सौदागरी का काम सहज रहगा। इस प्रकार मोन युद्ध ने अरब-इजराईल संपर्क में 'आग में घी' डालने वाली शक्ति चरितार्थ की।

चार युद्ध और उनके प्रभाव (Four Wars and their Impact)

1948 का पहला युद्ध : अरब देशों में उथल-पुथल—इजराईल की स्थापना के साथ 1948 में पहला अरब-इजराईल युद्ध का सूत्रपात हुआ। इसकी परिणति तक दो बातें स्पष्ट हो गयीं। अरब राष्ट्र इजराईल के मुकाबले सैनिक दृष्टि में अधम और दुर्बल हैं तथा समुक्त राष्ट्र मध्य इस क्षेत्र में युद्ध विराम लागू करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। अमरीकी पक्षधरता के कारण शीत युद्ध का इस क्षेत्र में प्रवेश हुआ तथा इस युद्ध में अमरुतता के बाद अनेक अरब राष्ट्रों में राजनीतिक व सामाजिक उथल पुथल आरम्भ हो गयी। उदाहरणार्थ, सिव में शाह फारुक के खिलाफ तख्तापलट की वृष्टभूमि इस हार के बाद ही बनी। इसके अनिर्दिष्ट इजराईल ने अरबों की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा किया और बड़े पैमाने पर कितम्मीनियों को बेघर किया। तबिय में विवाद के ओर मुँह पैदा हुए।

1956 का दूसरा युद्ध : अरबों की हार के बावजूद जोत—हालांकि 1956 में स्वेज मघर्ष में अरबों को एक बार फिर हार का झुँड दगना पड़ा, परन्तु इस मुठभेड़ के कुछ लाभप्रद परिणाम भी सामने आये। नासिर के जीवट और माहम ने अरबों में नई प्रेरणा व उत्साह का मचार किया तथा पान-अरब (Pan-Arab) भावना का उदय हुआ। समाजवादी राष्ट्रवादी हा या राजशाही बचावनी, इसके बाद से सभी अरब दशों को अपने मामूजिक हितों का अहसास हुआ। इस घटना के बाद मोवियन मध्य ने अरबों को अपना बेहिक ममर्थन देना आरम्भ किया और भारत जैसे प्रमुख गुट-निरपेक्ष देशों ने इजराईल का अन्तर्राष्ट्रीय बहिष्कार करना शुरू किया। कुछ मितारर अरब देशों के लिए स्वतंत्र युद्ध हारकर भी जीत मिद हुआ। यह भी कहा जा सकता है कि अतः यह स्थिति अरबों के लिए धानक मिद हुई। त्रिनी मज्जता में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण ममर्थन हो गया, उसने अरबों को मट माचने का मोरा नहीं दिया कि उनकी रणनीति इसीतिष्ठ काग्यर हो सकती थी कि इस बार उनका

कोई सीधा टकराव अमरीका से नहीं था। मिस्र के साथ युद्ध के मैदान में फ्रांस और ब्रिटेन उतरे थे, जो धके हुए दूसरे दर्जे के राष्ट्र थे।

1967 का तीसरा युद्ध : फिलिस्तीनी जातकवाद का जन्म—1967 की मुठभेड़ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझी जा सकती है। इसमें हारने के बाद मिस्र में नासिर के नेतृत्व की नींव मोखती हो गयी और इन तीसरी लगातार हार के बाद असंतुष्ट अरब यह मोचने को विवश हुए कि पारम्परिक सैनिक-सागरिक तरीको से वे इजराईल से पार नहीं पा सकते। इसके अलावा इस बार इजराईल ने इतने बड़े अरब भू-भाग पर जबरन अधिकार कर लिया कि लाखों फिलिस्तीनी शरणार्थी के



अरब-इजराईल मध्यम को दर्शाना मानचित्र

रूप में पशुवन जीवन यापन के लिए मजबूर हुए। इस परिस्थिति में पिलस्तीनी शरणार्थियों में हिंसक व अराजकतावादी भावनाओं का उफान स्वभाविक था। पिलस्तीनी मुक्ति संगठन की आतंकवादी गतिविधियों का आविर्भाव इसी के साथ हुआ। आज अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को आतंकवाद की जिम चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, उसका जन्म 1967 के अरब-इजराइल संघर्ष के साथ अनिवार्यतः जुड़ा हुआ है। इस युद्ध के बाद सुरक्षा परिषद् ने प्रस्ताव संख्या 242 को पारित किया और इसको त्रिपलान्वित करने में असमर्थ रहने के कारण एक बार फिर स० स० संघ की निरर्थकता प्रमाणित हुई।

1973 का चौथा युद्ध : तेल संकट से कई देश जस्त—1973 का 'ओमकीपर' मसाम कई मामलों में पहले तीन युद्धों से फर्क था। भले ही अन्त में इजराइल एक बार फिर अरबों पर हावी हो गया, किन्तु आरम्भ में अप्रत्याशित व अति नाटकीय जीत के द्वारा अरबों ने यह प्रमाणित कर दिया कि इजराइली अपराज्य नहीं है। उन्हें हराया जा सकता है। इसके अनिश्चित युद्ध विराम के बाद अरब देशों ने तेल को एक अस्त्र के रूप में काम में लाने की घोषणा की और इजराइल के समर्थक पश्चिम राष्ट्रों व अमरीका को ऊर्जा संकट के घबरे ने असमंजस में डाल दिया।

1973 के बाद मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात ने इजराइल के साथ सम्बन्धों के सामान्यीकरण का दौर (मुलह नहीं) आरम्भ किया और अमरीका की सहायता-प्रेरणा से जोर्डन, मोरक्को और सऊदी अरब के शासक इस प्रक्रिया में जुड़ गये। यदि 1973 में इजराइल को अरबों ने अपने अप्रत्याशित हमले में मौचकरा न कर दिया होता तो इस तरह का राजनयिक घटनाक्रम मौचातक नहीं जा सकता था। यदि पहले तीन युद्ध क्षेत्रीय महत्व के थे तो चौथा अरब-इजराइल युद्ध वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का मिद्ध हुआ। 1973 के बाद पश्चिम एशिया में अमरीका की स्थिति मजबूत हुई। वाल्टर लवर के अनुसार '1973 के युद्ध के बाद अमरीका ने पश्चिम एशिया में अपने आपको मिलक्षण स्थिति में पाया और अरब देशों की हालत निवेदक की सी थी। प्रमुख अरब देशों ने महसूस किया कि इजराइल के ऊपर अमरीका ही ठोस ढंग से दबाव डाल सकता है।'¹

पश्चिम एशिया में महा-शक्तियों की प्रतिस्पर्धा (Super Power Rivalry in West Asia)

पश्चिम एशिया में पूरे औपनिवेशिक काल में ब्रिटेन का वर्चस्व बना रहा। इसके अनेक कारण थे। ब्रिटिश नीतिना विश्व में मजबूत अधिक शक्तिशाली थी और तटवर्ती बन्दरगाहों पर विभी प्रतिस्पर्धी को अधिकतर स्थापित करने से सहज ही रोक सकती थी। इसके साथ ही एन छोरे पर मिस्र तो दूसरे छोरे पर भारत के माध्यम में पूरे पश्चिम-एशिया में नजर-निगरानी रखी जा सकती थी। हाँ, इतना

¹ 'At the end of 1973 war, America found itself in the unaccustomed position of being wooed by the leading Arab countries, who had realised effective pressure could be brought to bear on Israel only by Washington'. —Walter Laquer, *op cit*, 229

जल्द था कि मोरक्को और अल्जीरिया में फ्रांसीसी प्रभुत्व था तथा बीच-बीच में उदीयमान जर्मनी की रुबि बगदाद के रास्ते से मास्को पहुँचने की होती थी। टी० ई० मारेन्स, ओलेफ केरो, म्लव बाशा और किमनर जैसे लोग ब्रिटेन में पश्चिम एशिया विवेकज्ञ समझे जाते थे। अन्य यूरोपीय शक्तियों की तुलना में कबाइली अरबों के बारे में अग्नेजों की जानकारी अधिक विशद् थी। फास, हालैंड और बेल्जियम, हिन्द चीन, इण्डोनेशिया एवं सहारा मरुभूमि के दक्षिण में स्थित अफीकी भू-भाग में ही व्यस्त थे। एक कारण यह भी था कि रेगिस्तान में तेल पाये जाने के पहले इस क्षेत्र के साथ लाभप्रद व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने की कोई सम्भावना नहीं थी। किन्तु प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही यह स्थिति नाटकीय ढंग से बदल गयी।

तेल के बड़े पैमाने पर पता लगने तथा इसकी उत्खनन व शोधन प्रणाली विकसित होने के साथ-साथ कुछ और आविष्कारों ने इनके सामरिक महत्व को क्रान्तिकारी ढंग से बढ़ा दिया। मोटर-गाड़ियों की लोकप्रियता, विमानों का आविष्कार, जलपोतों और रेतगाड़ियों के लिए डीजल का प्रयोग ऐसे ही परिवर्तन थे। इस घटनाक्रम ने पश्चिम एशिया की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय सभी शक्तियों के लिए आकर्षक बना दिया। साथ ही तेल शोधन के लिए बड़े पैमाने पर लगायी गयी पश्चिमी खासकर अमरीकी और ब्रिटिश पूँजी ने शेखों की रियासतों में औपनिवेशिक शक्तियों के साथ सामोदारो वालें नए न्वरत स्वायों की सृष्टि की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों की कमजोर बनाने के लिए धुरी राष्ट्रों के गठबन्धन ने अनेक ऐसे ठिकानों को अपना निराना बनाया।

अपने निजी सक्षीणं स्वायों की पूर्ति के लिए ब्रिटेन ने अवसरानुसार कभी एक तो कभी दूसरे कबाइली पक्ष का समर्थन दिया। उसने नए राजवंशों की स्थापना की (जैसे फोर्ड में हाशमी और ईरान में पहातवी) और अपने राष्ट्रीय हित फो देखते हुए इनके राज्यो की कृत्रिम सीमा रेखा खींची। इस तरह भविष्य में सर्व-नाशक संपर्प का बीजारोपण किया गया। स्थिति तभी तक निरापद रह सकती थी, जब तक ब्रिटेन सर्वशक्तिशाली महाप्रभु के रूप में प्रतिष्ठित था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद औपनिवेशिक शक्ति के रूप में ब्रिटेन का क्षय होने के साथ असन्तोष और आक्रोश को मुखर करने वाली उपल-पुबल आरम्भ हो गयी और ब्रिटेन का स्थान अमरीका ने ले लिया।

पश्चिमी एशिया और अमरीका—इस क्षेत्र में ब्रिटेन के पारम्परिक हितों का उत्तराधिकारी बनने के अतिरिक्त अमरीका की रुचि के विस्तार निजी कारण भी है। अमरीकी जनता का एक बड़ा हिस्सा यहूदियों का है। यहूदी समुदाय है और सुशिक्षित-मुसर भी। अनेक यहूदी अमरीकी राष्ट्रपतियों के प्रभावशाली सलाहकार रहे हैं। इजराईल की स्थापना के बाद उन्होंने अमरीका की पश्चिम एशिया नीति को निरन्तर प्रभावित किया है। इजराईल ना सैन्यीकरण 1975 तक तेल कम्पनियों के हितों के साथ लगभग अनायास ही मन्तुलित किया जाता रहा।

शीत युद्ध के दौरान अमरीका की राजनयिक व सामरिक रणनीति मोचियत मध्य की घेराबन्दी पर आधारित थी। इसका कोई टकराव इजराईल-मध्यन या अरब राज्यों में तेल पर अमरीकी अधिपत्य बनाये रखने में नहीं था। अमरीका की यह मान्यता रही है कि कट्टर धार्मिक श्रान्त वालें जश्न देन नाम्तिन साम्यवादियों का

मुकाबला करने में बेहतर मन्धि-मित्र भाविन हो सकते हैं। इसीलिए अमरीका की प्रगति-परिवर्तन में कोई रुचि नहीं रही है। इसके अनिश्चित तेल ऊर्जा में स्वयं आत्म-निर्भर होने के बावजूद अमरीका की आकांक्षा यही है कि पश्चिमी एशिया का तेल उसके विपक्षियों के हाथ न लगने पाये और यह तेल उसके यूरोपीय मित्र राष्ट्र तथा जापान को मुक्त होना रहे। इसी सामरिक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 1973 के तेल मकट के बाद अमरीका ने इजराईल और अरब राष्ट्रों में मुंह बराने में पहल की और हेनरी किमिजर के 'शटल राजनय' (Shuttle Diplomacy) के बाद केम्प डेविड समझौते (1978) का मार्ग प्रशस्त किया। पश्चिम एशिया के अमीर तेल उत्पादक राष्ट्र अमरीका के लिए एक और तरह से भी महत्वपूर्ण हैं। पेट्रो-डॉलर के अपने विपुल भण्डार का निवेश अमरीकी कम्पनियों व बैंकों में हुआ है। इसका बड़ा लाभ अमरीकी मूल्य उत्पादकों का हुआ है।

पश्चिम एशिया और मोविद्यत सघ—इस क्षेत्र में मोविद्यत सघ की रचि और नीतियाँ अमरीकी क्रियाकलाप की प्रतिरिया के रूप में मंचालित होती रही हैं। स्वयं तेल समाधानों के मामले में आत्म-निर्भर है, किन्तु अमरीका की तरह उसका लक्ष्य भी यही है कि पश्चिम एशिया का तेल उसके प्रतिद्वन्द्वियों के हाथ न लगे और उसके मित्रों तक सीमित रहे। जिस प्रकार अमरीका का प्रयत्न चीन युद्ध के तर्कों के दबाव में इस क्षेत्र में यथास्थिति बनाये रखने वाला रहा, उसी तरह मोविद्यत प्रयत्न 'परिवर्तनाकांक्षी नीति नियोजन' का रहा। राजशाही के विरुद्ध जन-मुक्ति सप्राप्तों को समर्थन देना प्राथमिक महत्त्व का समझा गया। स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण ने नेकर मित्र से मोविद्यत समाट्कारों के निराने जाने तक निष्पक्ष ही माविद्यत सघ ने इस दिशा में महत्वपूर्ण उपरगियाँ हासिल कीं। उसे भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि केम्प डेविड समझौते के बाद महाशक्ति के रूप में मोविद्यत सघ की भूमिका का निरन्तर अवमूल्यन हुआ। इसके अलावा पारम्परिक रूप में माविद्यत सघ इस बान के लिए प्रयत्नशील रहा कि उसके नीमैत्रिक बहे के लिए बरें भर 'ऊँचा जल मार्ग' मुक्त रहे। बैसे कुछ विद्वानों का यह मानना है कि अन्तर-महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों के इस दौर में औपनिवेशिक युग के इस होत्रे का बनाव रखना और इसके आधार पर मोविद्यत सघ की पश्चिम एशिया नीति का विवरण करना व्यर्थ है। माविद्यत सघ को इस बान में भी नुकसान हुआ है कि उसने पितृभूत मुक्ति संगठन के त्रिन सदस्यों पर बड़ा दांव लगाया, उनका महत्व निरन्तर घटता गया।

अमरीका और मोविद्यत सघ दोनों की ही इस क्षेत्र में एक और अटपटी समझौता का सामना करना पड़ा, जिसे अक्सर उनकी नीतियों को गहमगह कर दिया। नीतिशा में 'जालिकारी' व मनकी बर्नर गद्दारी के उदय के बाद अराजकतावादी आतङ्कवाद ने दोनों महाशक्तियों को अमरीका की ज्यादा परेशान रखा। ईराक में बयको वाले प्रमय और साडी युद्ध ने इस गुण्ठों को और भी पेशीदा बनाया।

महाशक्तियों के अनिश्चित अन्य बही शक्तियों को भी तेल मकट के बाद पश्चिम एशिया के बार में अपनी नीति बदलने को बाध्य होना पड़ा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जापान है, जो अमरीका का मन्धि-मित्र और पक्षधर होने के बावजूद अपना इजराईल-विरोध मुखर करने का प्रेरित हुआ।

फिलस्तीन मुक्ति संगठन

(Palestine Liberation Organization or P.L.O.)

1967 के अरब-इजराईल युद्ध के बाद पश्चिम एशिया के राजनीतिक मंच पर फिलस्तीनी लोग बहुत तेजी से उभरे। एक तरह से फिलस्तीनियों का भविष्य इस क्षेत्र के तनाव और संकट के साथ आरम्भ में जुड़ा हुआ है। इजराईल की स्थापना के साथ यही लोग बेघर हुए थे। 1967 के बाद इनकी स्थिति सत्तार में सबसे बस्त-उत्पीड़ित शरणार्थियों की हो गयी, जिन्हें न केवल इजराईली आक्रमण, बल्कि सहोदर अरबों के अत्याचारों का भी निरन्तर सामना करना पड़ा। फिलस्तीनियों की समस्या यदि सिर्फ मानवीय ही बनी रहती तो सम्भवतः अन्तर्राष्ट्रीय राजनेता इसे अनदेखा कर देते। परन्तु आतंकवादी छापामारी का सहारा लेकर फिलस्तीन मुक्ति संगठन के सदस्यों तथा अन्य उग्रवादी तत्वों ने महाशक्तियों के सत्ता समीकरणों को गड़बड़ा दिया। अन्य अरबों की तुलना में अपने आधुनिक प्रगतिशील संस्कार और गुट निरपेक्ष अन्तर्राष्ट्रीय नजरिये के कारण विकासशील अफ्री-एशियाई जगत में फिलस्तीनी तेजी से लोकप्रिय हुए। 1980 तक पश्चिम एशिया के संकट समाधान में किसी भी राज्य की अपेक्षा इस 'राज्य-बिहीन राष्ट्र' (फिलस्तीन) की भूमिका निर्णायक समझी जाने लगी। पिछले दस वर्षों में लेबनान के एह युद्ध के कारण फिलस्तीन मुक्ति संगठन का राजनयिक अवमूल्यन अवश्य हुआ, परन्तु आज भी इन्हें चुका हुआ नहीं समझा जा सकता। पश्चिम एशिया की समस्या का सबसे महत्वपूर्ण आयाम फिलस्तीनी लोग ही हैं। इनकी सहमति के बिना इस संकट का कोई समाधान नहीं ढूँढा जा सकता।

फिलस्तीनियों की मौजूदा आबादी—संयुक्त राष्ट्र सच के आँकड़ों के अनुसार फिलस्तीनियों की आबादी वर्तमान में लगभग 45 लाख है। मूल रूप से ये उस क्षेत्र के निवासी हैं, जहाँ इजराईल है और उसने इनकी जमीन पर कब्जा कर रखा है। इनमें से करीब 5-50 लाख फिलस्तीनी इजराइली नागरिक हैं। करीब 12 लाख फिलस्तीनी इजराईल अधिकृत क्षेत्र पश्चिमी तट और गाजा पट्टी में रहते हैं। करीब 19 लाख फिलस्तीनी शरणार्थी सं. रा. सघ की राहत एवं निर्माण एजेंसी में पंजीकृत हैं।

संकट की शुरुआत—फिलस्तीनियों के अनुसार उनके संघर्ष की शुरुआत तब हुई, जब 1925 में तत्कालीन ब्रिटिश विदेश मंत्री लार्ड आर्थर वेल्फोर्ड और एक प्रमुख यहूदी नेता एडमंड डे रोयस्विल्ड ने वेल्फोर्ड घोषणा पर हस्ताक्षर किये। इस घोषणा में फिलस्तीनी भूमि पर यहूदी राज्य बनाने और उसके लिए ब्रिटिश समर्थन देने की बात बनी गयी। फिलस्तीनियों के लिए यह घोषणा विनाशकारी थी। 1920 में राष्ट्र सच ने ब्रिटेन को फिलस्तीन पर शासन करने के लिए 'मेन्डेट' दिया। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो यहूदी शरणार्थी यूरोप से भागकर फिलस्तीन में आ गये। 1948 में सं. रा. सघ ने ब्रिटिश शासन समाप्त कर फिलस्तीन का विभाजन करने का फैसला किया। अरब देशों और फिलस्तीन के प्रति सहानुभूति रखने वाले भारत जैसे अनेक देशों ने सं. रा. सघ में इस विभाजन योजना के विपक्ष में मत दिया, लेकिन यहूदियों ने ब्रिटिश व अमरीकी समर्थन के वनबूते पर इजराईल बना ही डाला। फिलस्तीनियों ने इजराईल के विनाश 1948,

1967, 1973 और 1982 में चार युद्ध लड़े, लेकिन अब वे दबी जुबान से मानते हैं कि उक्त विभाजन योजना को न मानना उनकी भारी भूल थी, क्योंकि इस योजना से कम से कम उनके पास रहने को 'अपना राज्य' तो होता। आज उन्हें शरणार्थी के रूप में घटकना पड़ रहा है।

फिलस्तीन मुक्ति संगठन की स्थापना—बहरहाल, फिलस्तीन मुक्ति संगठन (पी० एल० ओ०) की स्थापना 1964 में की गई। इसमें कुल नौ फिलस्तीनी गुट शामिल हुए। यामिर अराफत इसमें अपने गुट 'अल फतह' के साथ 1968 में शामिल हुए। जून 1968 में संगठन की नेशनल कांग्रेस बनायी गयी, जिसमें फिलस्तीनी नेशनल चार्टर पारित किया गया। चार्टर में कहा गया कि फिलस्तीन राज्य की स्थापना मजस्र सघर्ष के जरिये ही की जा सकती है। असल में, यह नेशनल कांग्रेस समद जैसी है, जिसमें विभिन्न फिलस्तीनी गुट अपने-अपने प्रतिनिधि भेजते हैं। नशनल कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का चुनाव करती है, जो मन्त्रिमंडल के रूप में कार्य करती है। नेशनल कांग्रेस में अराफात के गुट 'अल फतह' के ज्यादा प्रतिनिधि हैं, जिन कारण अराफात 1968 में ही पी० एल० ओ० के अध्यक्ष बनाये गये और सभी से इसी पद पर बने हुए हैं। उन्हीं के कुशल नेतृत्व के कारण इस संगठन को विनाश विश्व जनमत का समर्थन एवं सम्मान प्राप्त हुआ है। इसी कारण वह कई वर्षों तक पी० एल० ओ० के निर्विवाद नेता माने जाते रहे हैं।

कालान्तर में अराफात के गुट 'अल फतह' में जो विद्रोह 1983 में हुआ, उसने उनकी कमजोर स्थिति को स्पष्ट कर दिया। स्थिति यहाँ तक बिगड़ी कि लेबनान स्थित बेका घाटी में अराफात समर्थकों और विरोधियों ने जमकर मुठभेड़ें हुईं जिनमें कई फिलस्तीनी हताहत हुए। यही नहीं, फिलस्तीनियों के समर्थक सीरिया ने अराफात का छू घण्टे में देश छोड़ने को कहा और उन्हें 'अस्वीकार्य व्यक्ति' (Persona non-grata) घोषित कर दिया। सीरिया भी अराफात का खुला विरोध कर रहा था।

फिलस्तीन आन्दोलन व अरब राष्ट्र—यों इजराईल के साथ युद्ध में मिस्र, सीरिया और जॉर्डन ने फिलस्तीनियों का काफी साथ दिया और नुकसान भी सहन किया मगर फिलस्तीनी लोग जग के मोर्चे पर सदैव अग्रिम पंक्ति में रहकर भारी मारपीत में मरने और घायल होते रहे हैं, जबकि सऊदी अरब और कुवैत जैसे राष्ट्रों ने वित्तीय मदद ही की है। उन्होंने सैनिक महायत्ना कभी नहीं की। द्यूनीशिया, लीबिया, अल्जीरिया और मोरक्को भी फिलस्तीनियों के साथ रहने की घोषणाएँ करते रहे हैं, लेकिन वे कभी भी युद्ध में शामिल नहीं हुए। अर्थात् जो अरब राष्ट्र भौगोलिक दृष्टि में इजराईल से जिनने अधिक दूर स्थित हैं, वे इजराईल की उतनी ही अधिक आलोचना करत रहें हैं। ऐसे भौतिक समर्थन से फिलस्तीनियों को लाभ कम एवं नुकसान अधिक पहुँचा है।

मिस्र के कर्नल नसिर ने जरूर इजराईल से लोहा लेने का प्रयास किया। उसका बाद राष्ट्रपति अनवर सादत ने भी यह नीति जारी रखी, लेकिन मोवियन मध्य में सम्बन्ध बिगड़ने के कारण यह अमरीका के साथ हो गये। उन्होंने 1978 में अमरीकी दम-रेम में इजराईल के साथ 'कैम्प डेविड समझौता' कर अपना मित्राई अरब आपस से लिया, जो मिस्र ने 1967 के युद्ध में लोया था। जानाकि इसमें मिस्र अरब इमारात में अकता पड़ गया, लेकिन कैम्प डेविड समझौते में फिलस्तीनी

आन्दोलन को गहरा घक्का लगा, क्योंकि मिस्र फिलिस्तीनियों की सुरक्षा के लिए पहले छाते की तरह काम करता रहा था। सादात की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक के सत्ता में आने पर कोई नीतिगत परिवर्तन नहीं हुआ।

मिस्र के बाद सीरिया ही सबसे अधिक सन्नत अरब राष्ट्र रह गया, जो इजराईल के खिलाफ फिलिस्तीनियों को ठोस मदद दे सकता है। सीरिया का गोलान पहाड़ियों वाला क्षेत्र इजराईल ने अपने कब्जे में कर रखा है। सीरियाई राष्ट्रपति हफीज असद पश्चिमी एशियाई राजनीति में अपनी 'बोमराहट' जमाने के महत्वकांक्षी रहे, जिस कारण सीरिया इजराईल के खिलाफ लड़ने की बारबार घोषणाएँ करता रहा है। सोवियत संघ सीरिया के माध्यम से पश्चिम एशिया में अपना प्रभाव क्षेत्र कायम करना चाहता है, जिस कारण सोवियत संघ ने सीरिया को उसकी महत्वकांक्षा के लिये प्रोत्साहित भी किया है। सीरिया भी सोवियत राह पर इस कार्य में लगा रहा। परिणामस्वरूप अरब राष्ट्रों में प्रमुख रूप से दो भेद बन गये—उग्रपंथी और उदारपंथी। उग्रपंथी सीरिया, लीबिया जाबि और उदारपंथी सऊदी अरब, जोर्डन, कुवैत आदि ने पी० एल० ओ० की राजनीति को प्रभावित किया। परिणामस्वरूप पी० एल० ओ० के विभिन्न गुट भी सत्ता-संघर्ष में शामिल हो गये और उग्रपंथी और मध्यमार्गी नीति की पैरवी करने लगे।

लेवाना युद्ध ने फिलिस्तीनी आन्दोलन को भारी धक्का पहुँचाया। उग्रपंथी फिलिस्तीनियों, सीरिया और लीबिया का यह था कि इस युद्ध में अन्तिम क्षण तक लड़ा जाये, क्योंकि इजराइली सैनिक अब 'अवेय' नहीं रहे हैं। लेकिन अराफात एवं उनके गुट 'अल फतह' के अधिकतर सदस्य मध्यमार्गी नीति अपनाने पर जोर देते रहे। वे समग्र संघर्ष के साथ-साथ राजनयिक वार्ता के जरिये सफ़ल-समाधान की वकालत करते रहे। इस कारण उग्रपंथी नीति के हिमायती लोग अराफात के विरुद्ध हो गये और 'अल फतह' के कुछ सदस्यों ने भी उनके विरुद्ध विद्रोह का झंडा फड़ा कर दिया। विरोधियों का आरोप था कि अराफात अब यह महसूस करने लगे हैं कि अमरीकी सहयोग से ही फिलिस्तीन समस्या का हल सम्भव है। वह अमरीका से गोपनीय वार्ता करते रहे हैं। इसी कारण उन्होंने रोगन शान्ति योजना में दिलचस्पी दिखायी।

रोगन शान्ति योजना में कहा गया था कि जोर्डन के अर्धन पश्चिमी तट और गजा पट्टी क्षेत्र में फिलिस्तीन राज्य बनाया जाये। जोर्डन ने कुछ शर्तों के साथ इस प्रस्ताव को मान लेने के संकेत दिये, जबकि सीरिया ने इस प्रस्ताव को नामज़ूर कर दिया। समझा है कि सीरिया ने यह महसूस किया कि मिस्र ने कैम्प डेविड समझौते के जरिये सोचा हुआ अपना सिनाई क्षेत्र प्राप्त कर लिया और जोर्डन रोगन शान्ति योजना से अपने पश्चिमी तट और गजा पट्टी क्षेत्र प्राप्त कर लेगा। किन्तु सीरिया का गोलान पहाड़ियों वाला क्षेत्र इजराइली कब्जे में ही रहेगा। अर्थात् उनके हाथ कुछ नहीं समेगा। अतएव सीरिया, लीबिया और सोवियत संघ अरबनी तौर पर नहीं चाहते थे कि अराफात समय से पूर्ण शान्ति समझौता कर लें और इससे उनकी सामरिक महत्वकांक्षाओं और हितों पर चोट लगे।

स्वतन्त्र फिलिस्तीन राज्य की घोषणा—फिलिस्तीन मुक्ति संगठन ने 15 नवम्बर, 1988 को वेस्ट बैक और गजा पट्टी की भूमि पर स्वतन्त्र फिलिस्तीन राज्य की घोषणा की। पी० एल० ओ० के अध्यक्ष यासिर अराफात ने यह घोषणा करते हुए

समुक्त राष्ट्र सभ की सुरक्षा-परिषद के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय विवाद के हल के लिए आतंकवाद का महारा लेन ओर बल प्रयोग की मत्संज्ञा की गयी। भारत सहित कई देशों ने स्वतन्त्र फिलस्तीन राज्य की मान्यता प्रदान कर दी। बाद में अराफात राष्ट्रपति निर्वाचित किये गये। इजराईल न अमरीका ने पी० एल० ओ० के उक्त कदम की निन्दा की। हालांकि अमरीका ने स्वतन्त्र फिलस्तीन राज्य की मान्यता नहीं दी, किन्तु बाद में अमरीका अपने अधिकारियों के स्तर पर स्वतन्त्र फिलस्तीन राज्य के प्रतिनिधियों से बानचीन के लिए राजी हो गया, जो उनकी नीति में बदलाव का सूचक था।

पी० एल० ओ० में फूट—पी० एल० ओ० और अन्य फिलस्तीनी गुटों में व्याप्त फूट ने फिलस्तीनियों के हितों को सर्वाधिक नुकसान पहुँचाया है। अन्य गुटों में 'Popular Front for the Liberation of the Palestine General Command' की विया मर्यादित है। 'Democratic Front for the Liberation of Palestine' इराक के नजदीक रहो है। ऐसे में यदि अराफात का प्रभाव कम होता है तो पी० एल० ओ० में जाजं हवाज और अन्नू मूसा जैसे उपवादियों का वर्चस्व बढ़ता, जो पश्चिम एशियाई राजनीति में सीरिया, लीबिया और सोवियत सघ का दबदबा बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करता। लेकिन अराफात ने पी० एल० ओ० का नेतृत्व संभालने में विलक्षण योग्यता का परिचय दिया। अराफात की सबसे बड़ी उपलब्धि पी० एल० ओ० को अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाना थी।

फिलस्तीन आन्दोलन का भविष्य

पिछले लगभग ढाई दशकों में फिलस्तीन मुक्ति संगठन के जीवन में कई उतार-चढ़ाव आये हैं। पहले इसका स्वरूप राजनीतिक चेतना एवं सामरिक एकाता जगाने वाला रहा तो बाद में आतंकवादी छापामारी के दौर में इसने महत्वपूर्ण सैनिक भूमिका निभायी। इस महत्वपूर्ण बात की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि फिलस्तीनियों ने हिंसा का अराजकतावादी उपयोग नहीं किया। उनका उद्देश्य बल-प्रयोग द्वारा राजनयिक सवाद का मार्ग ही प्रशस्त करना था। दुर्भाग्यवश अरबों की आपसी फूट और अमरीकियों की अदूरदर्शिता के कारण फिलस्तीन मुक्ति संगठन को प्रत्यागित प्रतिष्ठा नहीं मिल पायी और पश्चिम एशिया की राजनीति में अपेक्षित रचनात्मक भूमिका निभाने में वह असमर्थ रहा। एक ओर फिलस्तीनियों की धर्म निरपेक्ष और समाजवादी श्रान्त वाला मानकर पारम्परिक अरब शासक उन्हें अपना शत्रु समझते हैं तो दूसरी ओर अमरीका उन्हें सिर्फ 'अपराधी आतंकवादी' मानता रहा है। इनकी क्षमता में आशंकित इजराईल बवंर डग से फिलस्तीनी शरणार्थियों के मानवाधिकारों का हनन करता रहा है। लेबनान मुकट में बिगाड के माध्यम से मबरा तथा सटिला के शरणार्थी मित्रों के सर्वनाश में यह बान पना चलती है। 1982 में लेबनान में इजराइली हमले के बाद फिलस्तीनी सैनिक शक्ति की रोड टूट गयी और तभी से इसका राजनयिक महत्व भी तेजी में कम हुआ। आज स्थिति यह है कि कभी पश्चिम एशिया की राजनीति में कई रचनात्मक सुधार कर सकने वाले सर्वोच्च महत्वपूर्ण घटक फिलस्तीनी आज इस शहरजी विमान पर शुद्ध एक मोहरे में बदल चुका है।¹

¹ Mehmoood Hussain, *The Palestine Liberation Organization* (Delhi, 1975)

लेबनान संकट (Lebanon Crisis)

शीत युद्ध के दौर में लेबनान शायद सबसे अधिक विस्फोटक संकट स्थल रहा है।¹ फ़िलिस्तीनी मुक्ति सैनिक हो या अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति-स्थापक दस्ता, इजराइली हस्तक्षेपकारी सैनिक हो या मामूलाधिक जातकवादी, इन सबके बीच रक्तपात वाली रस्साकशी पिछले कई वर्षों से निरन्तर चलती रही है। ऐसा कहना अतिशयोक्ति न होगा कि सन् 1960 वाले दशक के उत्तरार्द्ध में जो स्थिति दक्षिण बियतनामी क्षेत्र की थी, वही लेबनान की रही है—एक ऐसा वधनाशक (genocidal) गृह युद्ध, जिसने एक छोटे शुद्धहाल देश को तबाह कर दिया। लेबनान समस्या को ठीक से समझने के लिए ऐतिहासिक घटनाक्रम का पुनरावलोकन आवश्यक है।

प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र सघ ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का जो पुनर्गठन किया, उसके अन्तर्गत सीरिया के अधिपत्य में अब तक रहे पाँच तुर्क निलों को अलग कर स्वतन्त्र राज्य का दर्जा दिये जाने के साथ लेबनान का जन्म 1920 में हुआ। इसके बाद से 1943 तक उस पर फ्रांस की निगरानी बनी रही। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर फ्रांसीसी सेनाएँ यहाँ से लौट गयीं और बाद के लगभग दस वर्षों तक शान्ति बनी रही। भूगर्भगत और तटवर्ती लेबनान की भौगोलिक स्थिति इस दौरान भू-राजनीतिक दृष्टि से कम और पर्यटन व्यवसाय की दृष्टि से बड़ी अधिक लाभप्रद सिद्ध हुई और वेरुत का विकास अरबों के लिए ही नहीं, यूरोपीय देशों के लिए भी एक क्रीडास्थल के रूप में हो सका। पर सीरिया ने लेबनान की स्वतन्त्रता को कभी भी पूर्णतः स्वीकार नहीं किया और सीरिया ने क्रान्तिकारी राजनीतिक परिवर्तनों के साथ लेबनान की स्थिति भी अस्थिर हुई। सीरिया की प्रेरणा और समर्थन से 1958 में लेबनान में सैनिक क्रान्ति हुई और तत्कालीन धीन युद्ध के तर्क के अनुसार अमरीकी सेनाओं ने मुख्यस्था स्थापित करने के लिए वहाँ हस्तक्षेप किया। बाहरी बड़ी शक्ति के इस हस्तक्षेप ने इस बात की जमीन तैयार की कि स्थानीय असन्तुष्ट तत्व अपने हित में इस परिस्थिति का लाभ उठा सकें। गृह युद्ध के बीच इसी समय बोये गये। यह स्वाभाविक था कि अमरीकियों के प्रवेग के साथ सोवियत सघ की रुचि भी इस भू-भाग में बढ़ी। यह भी याद रखने लायक बात है कि इससे ठीक पहले 1956 में असफल आंग्ल-फ्रांसीसी सैनिक हस्तक्षेप ने अरब-यहूदी सघर्ष को अन्तर्राष्ट्रीय महत्व दिला दिया था और मध्य पूर्व में वही भी किसी परिवर्तन का धीन युद्धकालीन सामरिक महत्व उजागर किया था। स्वेज मकद (1956) के पहले पश्चिम एशियाई संकट में बाकी देशों की रुचि नगण्य थी। नासिर और नेहरु की घनिष्ठता ने इस क्षेत्र की उथल-पुथल में गुट निरपेक्ष देशों की रुचि बढ़ायी थी।

¹ लेबनान में इजराइली आक्रमण (1982) के फलस्वरूप अमरीका के लिए यह सम्भव हुआ कि वह इजराइल और एक अन्य अरब देश के बीच 'समझौता' करा सके। 'सीरिया को छोड़कर बाकी सारे अरब मजार पर अमरीकी न इजराइली वर्चस्व कारणर इग से पोषा जा चुका है और ऐसा नहीं जान पड़ता कि अबसे कुछ वर्षों तक इसे चुनौती दी जा सकेगी।' इस तिलमिले में विस्तार के लिए देखें—Christopher S. Raj, *West Asia*, in K. Subrahmanyam (ed.), *The Second Cold War*, (Delhi, 1983)

लेबनान की जनसंख्या ईसाइयों और मुसलमानों में लगभग बराबर-बराबर बंटी है। दोनों ही अरब वंशज हैं और उनके बीच की खाई सिर्फ धार्मिक है। इसके अलावा ईसाई एक विशिष्ट 'मैरोनाइट' सम्प्रदाय के हैं, जिनके कोई निकट या घनिष्ठ सम्बन्ध-आत्मीयता किसी प्रमुख यूरोपीय-अमरीकी ईसाई चर्च या सम्प्रदाय से नहीं। ये मैरोनाइट लेबनानी पढ़े लिखे हैं और आर्थिक दृष्टि से अपने मुसलमान भाईयों से कहीं अधिक सम्पन्न भी। जनतान्त्रिक शासन प्रणाली के विकास के साथ देश के राजनीतिक जीवन में इनकी भूमिका बढ़ती रही है और कई बार लेबनानी कट्टर मुसलमान नेता इस मन्तुलन के विरुद्ध अपना अमनोप मुखर करते रहे हैं। हिमक टकराव से बचने के लिए जो समझौता 1943 के राष्ट्रीय सम्मेलन में हुआ गया, वह यह था कि राष्ट्रीय जीवन में सभी मार्गजनिक पदों को विभिन्न सम्प्रदायों के लोगों में जनसंख्या के अनुपात के अनुसार बाँटा जाये। मसलन, यह परम्परा रही है कि राष्ट्रपति ईसाई और प्रधान मन्त्री मुसलमान होता है।



लेबनान मकद में अवस्थित स्थान

लेबनान में साम्प्रदायिकता का जहर सिर्फ ईसाइयों और मुसलमानों को एक-दूसरे का शत्रु बनाने वाला ही नहीं, मुसलमानों को भी विभिन्न धर्मों में बाँटने वाला रहा है। मुसलमान शिया और सुन्नी सम्प्रदायों में तो बँटे हुए हैं ही, इनके अलावा पहाड़ी इलाकों में रहने वाले 'द्रुजे' कबायली मुसलमान होने पर भी इन दोनों से बिम्बुल चर्च है। उनकी स्वायत्तता की माँग गुन्धों को और भी प्रोत्साहित करती है। अरब-इजरायली सैनिक मुठभेड़ों के बाद जोर्डन में बड़ी तादाद में निकासने जाने के बाद अनेक स्थितिस्थानी शरणार्थी लेबनान में बस गये। इनके आगमन के साथ साम्प्रदायिक तनाव जोरों में बढ़ा। धोड़े में ही शरतीकरण करने

के साथ ऐसा कहा जा सकता है कि सीरिया, जो अब तक लेबनान में मोरोनाइट ईसाइयों का समर्थक रहा था, वह अब फिलिस्तीनियों का पक्षधर बन गया। इसके साथ ही फिलिस्तीनी छापामार गतिविधियों के कारण लेबनान को इजराइल के जवाबी हमलों का निशाना बनना पड़ा। राष्ट्रपति गमाइल की हत्या के बाद मोरोनाइट ईसाइयों को ऐसा लगने लगा कि शान्ति व सुव्यवस्था की पुनर्स्थापना, एवं देश की स्वाधीनता की रक्षा के लिए इजराइलियों के साथ सहकार न सही, समान जरूरी है। एक प्रकार का व्यावहारिक राजनयिक समीकरण बिठा सकना सम्भव हुआ।

चाहूरी शरणार्थियों के आगमन और अमरीका के परोक्ष गठजोड़ ने साम्प्रदायिक वैमनस्य को इस कदर बढ़ाया कि 1975 में हिंसा के विस्फोट में 60 हजार से भी अधिक जानें गयीं और अरबों डॉलर की सम्पत्ति का नाश हुआ। लेबनान की अस्थिरता-कमजोरी को देखते हुए इजराइलियों को यह लालच हुआ कि सायद सीपे हम्नलेप से वे फिलिस्तीनी काँटे को एक ही बार में निकाल कर दूर कर सकते हैं और मध्य पूर्व के रणक्षेत्र में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर सकते हैं। लगभग इसी तरह का लालच सीरिया के राष्ट्रपति असद का हुआ। उन्होंने न केवल मुस्लिम मिलिशिया को अपना भरपूर समर्थन दिया बल्कि सीरियाई जमीन से लगे लेबनानी प्रदेश में अपनी सैनिक टुकड़ियाँ भी तैनात कीं। सीरियाई वागुसेना ने बेरूत के हवाई इलाके पर विध्वंसकारी हमले भी किये।

इजराइली-सीरियाई शोलादारी तथा साम्प्रदायिक आतंकवादियों के एक-दूसरे के ऊपर घुनी हमलों ने बेरूत को एक हमतान भूमि में बदल दिया। सायद यह स्थिति इसी तरह चलती रहती, एक दुश्मन पर स्थानीय त्रामदी, यदि जून 1982 में इजराइल ने जोशिम बढ़ाने वाली सैनिक पहल न की होती। इजराइल का आरोप था कि लेबनान का उपयोग फिलिस्तीनी आतंकवादी एक शरण-स्थल के रूप में कर रहे थे और वहाँ के सैनिक बड़ी से निर्दोष इजराइली नागरिकों को अपनी हिंसा का शिकार बना रहे थे। इजराइल इन तरह की जन-धन की क्षति उठाने के लिए तैयार नहीं था और सिर्फ तीन दिन के तेज अभियान के बाद इजराइली टुकड़ियाँ बेरूत तक पहुँच गयीं। बेका पाटी से सीरियाई मिसाइल अट्टे मष्ट कर दिये गये और फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात को अपने समर्थकों के साथ 1983 में लेबनान में झुक करना पड़ा। इस इजराइली सैनिक अभियान के दौरान बर्बर नरमहार किया गया। इस क्रूरता के दो उदाहरण गाबरा और जटिला की शरणार्थी बस्तियों में औरतों और बच्चों की निर्भय हत्या है। इस हत्याकाण्ड में, जिसका कोई सैनिक महत्व नहीं था, सिर्फ प्रतिरोध के शोखों को दहकाया। इजराइलियों के लेबनान में लौट आने के बाद भी आज लेबनान में भ्रमलमान और ईमाई एक-दूसरे के साथ इस हिंसा के बराबर करने में लगे हैं कि आक्रमणकारी सैनिकों के साथ सहनार करने वालों को क्या सजा दी जाये। इसके साथ ही एक ओर बात जोड़ी जाती जरूरी है कि लेबनान में इजराइली नार्वार्ड ने फिलिस्तीनी काँटे को मले ही निकाल दिया हो, आतंकवाद के मूल का कोई समाधान प्रस्तुत नहीं किया। अनेक भाड़े के आतंकवादी जो किसी भी राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित नहीं, विभिन्न साम्प्रदायों की अपनी सेवाएँ देते रहे हैं और अपनी विद्वव्यायी गतिविधियों का मुख्य केन्द्र लेबनान को बनाये हुए है। इन पर अंकुश लगाने के लिए कोई भी

अन्तर्राष्ट्रीय प्रयत्न सफल नहीं हो सका। कुछ वर्ष पहले अन्तर्राष्ट्रीय दस्ते के सदस्य अनेक फ़ामीनी सैनिकों की हत्या के बाद फ़्रांस ने इस तरह की गतिविधि में रुचि लेना बन्द कर दिया। इसी तरह दर्ज़नो अमरीकी मेरिन बमाडो की हत्या के बाद अमरीकियों ने भी यह बात जान ली है कि बाहरी 'तटस्थ' सैनिक टुकड़ियों को तैनात करने से तबनाजी गृह युद्ध शान्त नहीं हो सकता और न ही युद्ध विराम बरकरार रखा जा सकता है।

एक परधानी यह भी है कि लेबनान में नियुक्त अन्तर्राष्ट्रीय 'राहत सत्पात्रों' के कर्मचारियों, विभिन्न देशों के राजनयिकों के अपहरण और उनकी हत्या का मक़द आतंकवादी त्रिपाकलाप के कारण निरन्तर बना रहता है। अमरीका जैसी महाशक्ति और अन्य बड़ी शक्तियाँ इस बात के लिए विवश हैं कि व्यक्तिगत या सामूहिक अपहरण के बाद अपने नागरिकों की रक्षा या मुक्ति के लिए वे सक्रिय और सफल दिखें अन्यथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक दबाव लेबनान सम्बन्धी उनकी नीति को अमूल्य रूप से अलोच्य बना सकते हैं। इस बात की अमरीकी पत्रकारों तथा मिशनरियों के सन्दर्भ में ज़मीनीयता परखा जा सकता है। इनमें से कुछ अपहृत व्यक्ति मानो में बंदी हैं पर तब भी इलेक्ट्रोनिक प्रचार-तन्त्र के जादू के कारण मतवाता के सामने इनकी याद सजी रहे और अन्तर्राष्ट्रीय शतरंज के ये दुर्भाग्यप्रस्त मोहरे बड़ा महत्व रखते हैं। हाल के दिनों में लेबनान जब-जब भी क्षुब्ध रहा है, विश्लेषक उन ग़ैर-सरकारी राजनयिक पहलुओं और मध्यस्थताओं की ख़बर ही ब्यस्त रहे हैं, जिन्होंने इन आतंकवादियों के साथ सम्पर्क साधकर सबाद शुरू किया है। आर्चबिशप आफ केंटरबरी के विशेष सहायक एन्ड्रयू वेट न इस तरह के परामर्श में नागो विशेषता शामिल कर ली है।

निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि लेबनान का सकट निकट भविष्य में दूर होने वाला नहीं। युनियादी बात तो यह है कि साम्प्रदायिक वैरियों की बाहरी पक्षधर मिल चुके हैं और पिछले चार दशकों से हत्याकाण्ड-नरमहार में पारिवारिक बलाघात प्रतिगोचर के बीच व्यापक रूप में बंटे दिये हैं। इससे अलावा लेबनान में विशेषकर राजधानी बेरुत में पूरी जवान पीढ़ी अराजकता और हिंसा के दानावरण में व्यस्त हुई है। इसलिए अपहरण हिंसा, अपराधपूर्ण सामाजिक आचरण, दैनिक जीवन की अस्थिरता स्वाभाविक है। पारिवारिक या सामाजिक सामूहिक सहकारी जीवन में इसका कोई परिचय नहीं। आतंकवाद का बेहतर भामानी है पहचाना जा सके वाला नहीं। एक आतंकवादी इकाई धातक केंसर की उम्र कोगिचा की तरह है जिसे नष्ट किया जा सकता है, पर जिसके द्वारा फँसता प्राणनाशक विष जब पकड़ में आता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। लेबनान के सन्दर्भ में कोई बहुत भोला व्यक्ति ही आतंकवादी हो सकता है। इज़राइली सैनिक हस्तक्षेप से पहले इस बात की आशा बची थी कि शायद 1943 वाले राष्ट्रीय सम्झौते के त्रिनी मशोविन-परिष्कृत संस्करण को यदि सभी पक्ष ईमानदारी से लागू करने को तैयार हो जायें तो शायद शान्ति और खुशहाली इस अभाग्य देश में वापस लौटाये जा सकत है। आज इसकी कोई सम्भावना शेष नहीं। आज हिंसा का टकराव सिर्फ़ इमारतों मुमलमानों, शियाओं, सुन्नीयों और द्रुज़ों के बीच नहीं, दशकों में चने आ रहे गृह युद्ध ने अनेक छुटपुट न्यून स्वार्यों को जन्म दिया है। ये छुटपुट भले ही हों, पर बट्टर और बख़ेर हैं। लेबनान समस्या के समाधान में संयुक्त राष्ट्र मध्य, गुट निरपेक्ष

आन्दोलन और अरब विरादरी की असमर्थता पहले ही उद्धाटित हो चुकी है। लेबनान की हालत में किसी बेहतरी की उम्मीद तब तक नहीं की जा सकती, जब तक पश्चिम एशिया की बृहत्तर समस्या का हल ढूँढ़ नहीं लिया जाता। लेबनान का सकट आज सिर्फ उसका अपना सकट नहीं, बल्कि फिलिस्तीनी समस्या, भीरियाई आधरण की जटिलता, इजरायली आक्रमण, आतंकवादी असामाजिकता का सक्षिपात है। ऐसे जानलेवा ज्वर का निदान एवं उपचार सरल नहीं है।

ईरान-इराक युद्ध (Iran-Iraq War)

ईरान व इराक के बीच लगभग आठ वर्ष तक युद्ध चलने के बाद 1988 में युद्ध विराम हो गया किन्तु इस बात के कोई आधार गजर नहीं आते थे कि निकट भविष्य में उनके बीच मौजूदा जटिल समस्या का समाधान हो सकेगा। इस विनाशकारी युद्ध में ईराक के दार्ढ़ लाय और इराक के एक लाख सैनिक एवं नागरिक हताहत हुए। सम्पत्ति का गुरस्ताग अरबों डालर गँगा गया। दोनों देशों की उत्पादकता और उनके आर्थिक विकास पर इस खाड़ी युद्ध का घातक प्रभाव पड़ा। सैनिक विस्फोट के पहले ईरान में तेल का दैनिक उत्पादन 16 लाख बैरल प्रतिदिन था, किन्तु बाद में यह घटकर सिर्फ 10 लाख बैरल रह गया। इसी तरह इराक के महत्वकांक्षी सड़क, पुल, भवन-निर्माण कार्यक्रम लगभग ठप्प से हो गये। ईरान की कुल भावदारी 4.80 करोड़ है, जिसमें से दस लाख सैनिक हैं। इनका भुकावला करने के लिए इराक ने भी अपनी कुल डेढ़ करोड़ आबादी में से इतना ही बड़ा हिस्सा मोर्चे पर तैनात कर दिया। दोनों देशों ने इतने ज्यादा ससाधन, व्यक्तित्व साख और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दाँव पर लगा दिये कि कोई भी पक्ष हार मानने को तैयार नहीं था। अन्ततः अगस्त, 1988 में संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पर दोनों देशों में युद्ध विराम सम्भव हो पाया।

ईरान और इराक में ऐतिहासिक व पारम्परिक मतभेद—ईरान और इराक के बीच युद्ध की पृष्ठभूमि में उनके ऐतिहासिक और परम्परागत मतभेद हैं। इराक, जिसे पहले मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था, अपने सामरिक महत्व के कारण विश्व शक्तियों के आकर्षण का सदैव केन्द्र रहा है। 4 लाख 38 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला यह देश 1958 में राजशाही के पतन के बाद एक लम्बे समय तक सैनिक तानाशाही की गिरफ्त में रहा। 1979 में स्वास्थ्य खराब होने के कारण जनरल अहमद हुसैन अलबकर ने देश का नेतृत्व 42 वर्षीय सद्दाम हुसैन को सौंपा। सद्दाम हुसैन ने 22 जून, 1980 को इराक को 250 सदस्यीय असेम्बली के चुनाव कराकर देश के इतिहास में पहली बार यहाँ के नागरिकों को अपने मनाधिकार के प्रयोग का अवसर प्रदान किया। पश्चिमी एशिया के देशों में सऊदी अरब के बाद तेज उत्पादक देशों में इराक का स्थान दूसरा अंतिम है। 1979 में वह 30.43 लाख बैरल प्रतिदिन तेल उत्पादन करता रहा था। इस प्रकार वह अपने राजस्व का तीन-चौथाई भाग (36 अरब डॉलर) तेल का निर्यात करके प्राप्त करता रहा था।

दूसरी ओर 16 लाख 48 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला ईरान आदि बान से फारसी सभ्यता का केन्द्र रहा है। इस शताब्दी के मध्य तक ईरान

विश्व शक्तियों की छोना-छपटी के बीच अपनी नियति की खोज करता रहा, किन्तु भूतपूर्व शाह रजा पहलवी ने पश्चिमी शक्तियों से मिलकर एक ओर जहाँ एक आधुनिक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में ईरान को खड़ा करने में सफलता प्राप्त की, वहीं दूसरी ओर अपने परम्परागत शत्रु इराक की शक्तिविधियों पर अक्रुश लगाने में उन्हें अद्भुत सफलता मिली। इराक की शक्ति को सीमित करने में शाह को पश्चिमी देशों का पूर्ण सहयोग एवं समर्थन प्राप्त था। इस सबके बावजूद 1978 में शाह के पतन और कट्टरपंथी इस्लामी नेता अयातुल्लाह खुमेनी के नेतृत्व में उठी इस्लामी क्रान्ति की लहर ने जहाँ पश्चिमी शक्तियों के स्वप्नों को चकनाचूर कर दिया, वहीं आन्तरिक अस्थिरता ने ईरान के मध्यिष्णु की अनिश्चय के दौर में डाल दिया।

समर्पण के कारण—इराक और ईरान के बीच समर्पण का कारण 17 मिनम्बर, 1980 को इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन द्वारा उस समझौते को रद्द घोषित कर देना था, जो उन्होंने 1975 में ईरान के शाह से किया था। इस समर्पण को समझौते के लिए 1975 के उक्त समझौते का खुलासा करना आवश्यक है। इराक के उत्तर-पूर्वी प्रदेश कुर्दिस्तान में अदिब सल्मा में बसे 'गिया' अताबलन्जियों को ईरान मदद हो बगदाद के विरुद्ध प्रयुक्त करता रहा है। 1974-75 में कुर्दिस्तान के भयंकर विद्रोह ने बगदाद की सरकार को डोबाडोल कर दिया था। जैसाकि बाद में स्वयं राष्ट्रपति सद्दाम ने स्वीकार किया कि उस विद्रोह को दबाने में इराकी सेना के कम से कम 16 हजार सैनिक हताहत हुए। जाहिर है कि इस विद्रोह के पीछे शाह और सी० आई० ए० का हाथ था। इस विद्रोह से ब्रह्म बगदाद सरकार शाह के सम्मुख पुटने टेक देने को बाध्य हुई थी और उसका मतीजा उक्त समझौते के रूप में सामने आया था।

शत-अल-अरब किसका—1975 के समझौते के तहत शाह ने एक ओर कुछ विद्रोहियों को समर्थन न देने का वचन दिया, वहीं इराक ने शत-अल-अरब नामक सामरिक सहत्व के तहत 100 मील चौड़े जलमार्ग को ईरान के साथ बाँटा बाँट देने की पेशकश स्वीकार कर ली। वैसे 1913 में इराक और ईरान के बीच हुए समझौते के अन्तर्गत शत-अल-अरब इराक का हो गया था, किन्तु 1975 के समझौते के द्वारा ईरान को खाड़ी में अपना बर्चस्व स्थापित करने में सफलता मिल गयी। जिन अपमानजनक परिस्थितियों में और जहाँ पर इराक का 1975 का समझौता करना पड़ा था, उसमें जाहिर था कि मोटा पढ़ने पर इराक, ईरान से इस अपमान का बदला लेगा। शायद यही कारण है कि इराक ने युद्ध की घोषणा के पूर्व ममस्त शत-अल-अरब पर अपना दावा घोषित किया था। स्पष्ट है कि उस दावे को पूरा करने की दृष्टि से ही वर्तमान समर्पण छेड़ा गया।

शत-अल-अरब भू-सामरिक दृष्टि से न केवल खाड़ी देशों की प्रतिद्वन्द्विता में निर्णायक साबित होगा, बरन पश्चिम के तेल आयातक देशों की मजल को हाथ में रखने के लिए भी इस पर अधिकार कारगर और सानदायक है। यह हम जान से स्पष्ट है कि ईरान का प्रमुख तेल उत्पादक प्रान्त कुवेम्मान का समुद्री तट शत-अल-अरब पर ही है। इराक का युद्ध-उद्देश्य के पीछे न केवल शत-अल-अरब पर पुन अधिकार करना शामिल था, बरन कुवेम्मान को घेर लेने की प्रक्रिया भी जुड़ी हुई थी। कुवेम्मान में इराक की वही साम प्राप्त है जो कुर्दिस्तान में ईरान की है। अर्थात् कुवेम्मान की अधिकान्त आबादी मुन्नी मनावनबी अरबों की है, जो मदद

तेहरान के शिया शायकों द्वारा खोपित होते रहे हैं। इस दृष्टि से सद्दाम हुसैन ने शायद ठीक ही सोचा हो कि ख़ुजेस्तान को निशाना बनाकर वह न केवल अधिकांश अरब राष्ट्रों की सहानुभूति हासिल कर लेंगे, बरन ईरान के समस्त गैर-फ़ारसी गैर-शिया लोगों का समर्थन प्राप्त कर खुर्मेनी की उगमगाती सत्ता के विरुद्ध आन्तरिक विस्फोट की आग को हवा देने में भी सफल होगा।

नेतृत्व की महत्ववोक्षा—इराक का अपनी सोवियत-परस्त नीति से शर्न: शर्न: हटकर कुछ-कुछ पश्चिम परस्त और कुछ मुट-निरपेक्ष नीति को अस्तित्वार कर लेना कम महत्वपूर्ण घटना नहीं नहीं जा सकती। यो भी इराक पश्चिमी राष्ट्रों की तेल-आवश्यकताओं की दो-तिहाई पूर्ति करना रहा है। पश्चिमी राष्ट्र 1972 की सोवियत-इराक मैत्री के बावजूद इराक को खोया हुआ देश नहीं मानते रहे थे। इसके पक्ष में 1980 के दशक में इराक द्वारा फ्रांस, इटली और ब्राजील जैसे पश्चिमी सेमे के देशों से परमाणु साज-सामान, यूरेनियम और तपनीकी जानकारी हासिल कर लेने के उदाहरण दिये जा सकते हैं। दूसरे, इराक ने सोवियत सघ का कई मामलों में डटकर विरोध किया। इराक द्वारा दक्षिण यमन, इथियोपिया और अफगानिस्तान के मामलों पर सोवियत सघ का विरोध करने पर वह पश्चिम देशों के और करीब आ गया। इन नीतियों से स्पष्ट है कि इराक पश्चिम एशिया में एक शक्ति केन्द्र और पश्चिमी राष्ट्रों के लिए एक 'समर' का काम करने के लिए युद्ध की शुरूआत से पूर्व स्वयं की प्रस्तुत कर चुका था।

पश्चिमी सेमे की सदस्यता—दूमरी ओर शाह के पतन के बाद खुर्मेनी का धर्मान्ध और बबले की भावना से भरत ईरान दिशा-प्रमित हो चुका था। जाहिर कि पश्चिमी राष्ट्र ईरान की घटनाओं से भयभीत अवश्य थे, किन्तु दूरगामी आशका से वे हाथ पर हाथ धर कर बैठने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते थे। ईरान द्वारा अमरीकी दूतावास के कर्मचारियों की बचक बना लिये जाने की घटना ने अमरीका और उसने मित्र देशों को कार्रवाई के लिए बाध्य कर दिया। यो ईरान विरोधी कार्रवाई आधिक प्रतिबन्धों तक सीमित रही, लेकिन अब गौर करने पर पता चलता है कि अप्रैल, 1980 में ही तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति के रक्षा सलाहकार ब्रैड्जिस्की ने यह घोषित कर दिया था कि यदि भविष्य में इराक और ईरान के बीच सघर्ष स्थानीय संघर्ष न रहे मन्त्र, तो अमरीका की हस्तक्षेप करना पड़ेगा। ब्रूटनीति पर्यवेक्षकों ने ब्रैड्जिस्की की उक्त घोषणा का मीवा-भाषा अर्थ यह लगाया कि अमरीका इराक को ईरान में निपटने के लिए हथी शण्डो दिता रहा है। यो भी अप्रैल, 1980 से ही सद्दाम हुसैन ने ईरान के साथ निर्णायक संघर्ष का इरादा दबे स्वरों में जाहिर करना शुरू कर दिया था।

फारसी नस्लवाद—जून, 1980 के इराकी चुनावों के बाद राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने ईरान के विरुद्ध मास्कूनिन संघर्ष की रूपरेखा बनायी। इसमें उन्होंने खुर्मेनी की इस्लामी शान्ति को 'फारसी नस्लवाद' और 'अरबों के विरुद्ध दबी हुई मुटन' की संज्ञा दी। वैसे दशक पूर्व ही खुर्मेनी ने सद्दाम हुसैन के विरुद्ध जिहाद छेड़ते हुए यह घोषित कर दिया था कि वह अमरीकी एजेन्ट है। साथ ही उन्होंने इराक में रहने वाले शियाओं को सद्दाम हुसैन का तस्ना उलटने का आदेश दिया। ईरान में सद्दाम हुसैन का तस्ना उलटने के उद्देश्य से एक 'इस्लामी शान्तिकारी सेना' का विधिवत गठन कर दिया गया। यह आत्मानो से अन्दाजा लगाया जा सकता है

कि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन पर खुर्मेनी के ईरान की ऐसी वचकानो हरकतो का क्या असर हुआ होगा, सामकर तब जबकि वह इस तथ्य से भलीभाँति परिचित है कि उनके देश की कोई 50 प्रतिशत जनसंख्या शिया मतावलम्बी है और वह ईरान के शासकों के आदेशों से अधिक प्रभावित होती है, बनिस्बिन बगदाद सरकार के आदेशों के।

एक म्यान में दो तलवारें—युद्ध के पूर्व ही इराक और ईरान के बीच जीवन और मृत्यु का सघर्ष परिपक्व हो चुका था। कुछ-कुछ स्थिति ऐसी आ गयी थी कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती थी और न रहनी थीं। इसी पृष्ठभूमि में यह समझ लेना जरूरी है कि अन्तर्राष्ट्रीय घटनाचक्र की अनुकूल स्थिति ने राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के होमने काफी बुलन्द कर दिये थे। जहाँ रॉयल डेविड समझौते के बाद अरब जगत पर मिस्र का दबदबा समाप्त हो गया, वहीं ईरान के शाह के पतन और सऊदी अरब की आन्तरिक गड़बड़ी ने न केवल पश्चिम एशिया, बरन् समस्त इस्लामी जगत में नेतृत्व की रित्तना पैदा कर दी। ऐसी स्थिति में सद्दाम हुसैन जैसा महत्वकांक्षी और अपेक्षाकृत युवा व्यक्ति निस्संदेह मुस्लिम जगत पर अपना नेतृत्व स्थापित करने की दृष्टि में पापदा क्यों न उठाना? सद्दाम हुसैन जानते थे कि ईरान की सेना के अधिकांश योग्य सनाधिकारी खुर्मेनी की व्यक्तिगत रजिदा के शिकार हो चुके थे। ईरान का कोई दोस्त नहीं था तथा अमरीका और पश्चिमी राष्ट्र उसमें दानु थे। अधिक दृष्टि से ईरान की स्थिति यह थी कि जहाँ 1974 में वह 60 लाख बैरल प्रतिदिन के हिसाब में बच्चे तेल का उत्पादन कर रहा था, वहाँ 1979 में केवल 30 लाख बैरल प्रतिदिन तक घट कर आ गया।

अरबों की चुप्पी—ऐसी परिस्थितियों में सद्दाम हुसैन ने सर्वप्रथम अरब राष्ट्रों में खुर्मेनी के विरुद्ध धार्मिक अमनोप पैदा करना आरम्भ किया। जोर्डन के शाह हुसैन ने सर्वप्रथम ईरान के विरुद्ध इराक का समर्थन किया। जब सद्दाम हुसैन ने सऊदी अरब, कतार, उत्तरी यमन और खाड़ी के अन्य देशों में शिया-सांघाज्यवाद के विरुद्ध महायत्ना की अपील की तो उनका महानुभूतिपूर्ण स्तर देखने में आया। इराक के लिए इतना काफी था; इधर पश्चिमी राष्ट्रों की ओर सद्दाम हुसैन को भी निर्दिष्टन थे। अपनी योजना की सफलता में कोई बमर न रखने की दृष्टि से उन्होंने एक तुर्प घात और चली। सम्पूर्ण सघर्ष की शुरुआत के एक दिन पूर्व अपन एक बिनिष्ट दून को मास्को भेजकर उन्होंने सोवियत संध को न केवल इराकी पक्ष में अवगत करा दिया, बरन कहते हैं कि 1972 की सोवियत-इराक सन्धि के तहत हथियारों की मांग भी की। यो भी खुर्मेनी का कट्टरपंथी ईरान, सोवियत स्पृह रचना में वही भी फिट नहीं हो सकता था। इस प्रकार स्पष्ट है कि इराक ने सामरिक महत्व के टिकानों में अपने मोहरे फिट करने के बाद ईरान में युद्ध करने का निर्णयक कदम उठाया।

ईरान-इराक युद्ध सम्बा लिखने के कारण—त्रिम समय ईरान-इराक युद्ध छिड़ा, उस समय अनक समय विद्या विचारदोष का मानना था कि कुछ ही हफ्तों में यह सघर्ष समाप्त हो जायगा। अधिकतर लोगो का मानना था कि इराक इस युद्धभेद में विजयी प्रकट होगा। ऐसा सोचने के अनेक कारण थे। 1979 में ईरान में शाह के बाद अयानुल्ला खुर्मेनी के नेतृत्व में कट्टरवादी, पुरातनपंथी, मध्ययुगीन व धार्मिक शासकों का बोनब्रता था और सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन

में मयकर उथल-पुथल चल रही थी। तेल का उत्पादन गटबड़ा गया था। ईरान के वैदेशिक सम्बन्धों में अनिश्चय की स्थिति और सेना में प्रशिक्षित-अनुभवी शाह के विद्रोहवादी अफसरों के निष्कासन-दृष्टि बिजे जाने के बाद ईरान की सैनिक क्षमता को काफी नुकसान पहुँचा था। ऐसा भी सोचा जाता था शाह के आतंकवादी-अत्याचारी प्रशासन से मुक्त होने पर ईरानियों की प्रसन्नता क्षण-भंगुर रही। खुमेनी के कट्टर समर्थकों ने ईरानियों की जान कम मूँगीवत में नहीं डाल रखी थी और इस्लामी शासकों के विरुद्ध दशों और बाकोश व्यापक रूप से गुगुगा रहा था, जिसका विस्फोट कभी भी तत्नापलट के रूप में हो सकता था। अमरीकी घबको के प्रसंग के सन्दर्भ में यह अटकलें भी लगायी गयी कि अमरीका जैसी महाशक्ति अपने हितों की रक्षा के लिए ईरानी घटनाक्रम में हस्तक्षेप कर सकती है। इस्लामी आगितकारिता के प्चार से मोचिबल संघ भी शक्ति था। संक्षेप में 1980-81 के दौर में ईरान चारों ओर में घिरा हुआ था और उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं लगती थी।

इनके विपरीत इराक़ी सरकार अपेक्षाकृत 'प्रगतिशील' समझी जाती थी— अपनी धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी दलाल और तनवीकी उपलब्धियों के कारण।



ईरान-इराक़ संघर्ष से सम्बन्धित नुदे

जहाँ एक ओर इराक को सोवियत संघ का 'समर्थन' प्राप्त था, वहीं अमरीकियों को ईरानियों की तुलना में इराक की अधिक रास आते थे। युद्ध छिड़ने तक तेल से इराक की कमाई काफी थी। इराक तेल निर्यात में हुई आमदनी का उपयोग अपने परमाणु कार्यक्रम के विकास या फ्रांस जैसे देशों से 'एकममो सेट' जैसे प्रक्षेपास्त्रों की खरीद के लिए कर रहा था।

इस समय युद्ध के निर्णय का सीधा सम्बन्ध सुर्मनी और सहाम हुसैन के अस्तित्व से था। पारम्परिक, जातीय, भू-राजनीतिक, आर्थिक तथा आन्तरिक राजनीतिक दबाव के कारण पराजित नेतृत्व बचे रहने की कोई भी सम्भावना नहीं थी। पिछले कुछ वर्षों के अनुभव से यह बान एक बार फिर स्पष्ट हुई कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के मामले में अविष्यवाणी करना कभी भी निरापन्न नहीं होता। ईरान-इराक युद्ध का बमबंदर यह बान भी उजागर करता है कि नए शीत युद्ध के इस चरण में सामरिक लक्ष्य और शक्ति समीकरण कितने नाटकीय ढंग से तथा कितने आमूल धूल बदल चुक है। तेजी से युद्ध जीत मकने में इराक की विफलता ने उसके अनेक सहयोगी राष्ट्रों को ईरान की ओर आकृष्ट किया। इसका एक उदाहरण राष्ट्रपति रीघन के भूतपूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मेकफर्लेन के गोपनीय राजनय से पता चलता है। कल तक ईरान रीघन को अमरीका का 'घैतान' कहना था और बंधकों के बाद के प्रकरण में अमरीका की नजर में ईरानी सरकार 'अराजकता-बादी-आतंकवादियों का जमघट' थी। किन्तु बाद में ईरान और अमरीका एक-दूसरे के साथ शास्त्र व्यापार के लिए तैयार हो गये। इसी तरह जनवादी चीन ईरान और इराक दोनों पक्षों की सैनिक साज-सामान की बिक्री कर मुनाफा कमाता रहा। इस लम्बी रस्माकशी के दौरान दोनों पक्षों पर युद्ध-अपराध सम्बन्धी विचना 'क्वैशन' के उत्तरघन एक मानवाधिकार हनन के आरोप लगाये जाने रह। ईरान युद्ध के मोर्चों पर 13-14 वर्ष के किशोरों को कुर्बान करने रहने के लिए विवश हुआ तो इराक ने सामायनिक अस्त्रों और जहरीली गैस का प्रयोग करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखायी। इन सबमें यह बान उजागर होती है कि ईरान-इराक युद्ध (शीत युद्ध की दृष्टि से) की एक बहुत बड़ी उपयोगिता 'शस्त्रास्त्रों की प्रयोगशाला' के रूप में थी।

शीत युद्ध के पहले चरण (1945 में 1962 तक) में अमरीका के सैनिक-औद्योगिक प्रतिष्ठान (Military Industrial Complex) का उन्मेष रिया जाता था। आज इस तरह के सामरिक महत्व वाले मुनाफाखोर प्रतिष्ठान मार्जनीक या निम्नी क्षेत्र में हर जगह देखे जा सकते हैं—ममाजवादी देशों में भी।¹ महाशक्तियों के ही नहीं, बल्कि अन्य बड़ी शक्तियों के भी हिन में यह है कि अपनी सीमा से दूर दराज निम्नी रणभेन में दूसरे की सामरिक जख्खने पूरी करने के बहाने अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मन्दी, बढ़ती बेरोजगारी आदि का मुकाबला रिया जाये।

1 वे. सुब्रह्मण्यम द्वारा सम्पादित पुस्तक "The Second Cold War" (दिसम्बर 1983) में किटोकर एस. राज ने स्पष्ट लिखा है कि 'सोवियत संघ ने ईरान इराक युद्ध शुरू होने के बाद भी इराक को हथियारों की सप्लाई नहीं रोकी। ऐसा बान रहता है कि उसका इरादा यही था कि किभी भी पक्ष को निर्लाभक जीत न मिले। जिस समय यह महाबना की गयी, सोवियत संघ और इराक के बीच सम्बन्ध अच्छे भी नहीं थे।

ईरान-इराक युद्ध का आर्थिक पक्ष—इस युद्ध का बाह्यिक पक्ष भी कम महत्वपूर्ण नहीं। ईरान और इराक दोनों प्रमुख तेल उत्पादक देश हैं। भले ही आज तेल उत्पादक निर्यातक देशों के संघठन 'ओपेक' में वैसे 'एका' नहीं रह गया, जैसा 1973 में देखने को मिला था। फिर भी, तेल की कमाई और इसके खर्च की चिन्ता हमेशा अमरीकियों तथा पश्चिमी दुनिया के अन्य देशों की रही है। उनकी अपनी खुशहाली और आम उपभोक्ता का जीवन-यापन स्तर कहीं न कहीं इससे जुड़ा हुआ है। जब तक यह युद्ध जारी रहा, तब तक न केवल ईरान व इराक के तेल उत्पादन को वस्तुि अन्य तेल उत्पादक राष्ट्रों की गतिविधियों को भी परोक्ष रूप से प्रभावित किया जा सकता था।

सऊदी अरब के तत्कालीन तेल मन्त्री शेख अली यमनी ने जब यह प्रस्ताव रखा कि 'ओपेक' के सदस्य देश तेल उत्पादन में कटौती करें तो ईरानी सरकार ने यह स्पष्ट करने में देर नहीं की कि वह इसे युद्ध की कार्रवाई समझेगा। जाहिर है कि यमनी का उद्देश्य उत्पादन घटाकर कीमतें बढ़ाना था, परन्तु ईरान के लिए तेल उत्पादन घटाना असम्भव था, क्योंकि तेल निर्यात ही उसके युद्ध प्रयास में जान डालता था। अन्ततः यमनी को ओपेक की एकता के लिए अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा।

दूसी जवाहरण से समस्या के एक और पहलू का पता चलता है। यह प्रष्टा जा सकता है कि आखिर सऊदी अरब क्यों ईरानी भावनाओं का आदर करता है? वह स्वयं बड़ा तेल उत्पादक है। यद्यपि यह है कि अरब ससार में ही नहीं, पूरे पश्चिम एशिया में ईरान और इराक औरो के मामले भविष्य की दो बैकलिफ रूपरेखाएँ प्रस्तुत करते हैं। सऊदी अरब के लिए इनमें से किसी एक को चुनना कठिन है। वह न तो समाजवादी सैनिक तानाशाही को आकर्षक समझता है और न ही धार्मिक कठमुत्प्रेषण को, जिसके तेवर विद्वम्बायी शान्तिकारिता के हैं। इसी तरह बड़े-घटे तेल उत्पादन या छाड़ी युद्ध के उत्तार-चढ़ाव का प्रभाव जापान, पश्चिमी यूरोप आदि पर पड़े बिना नहीं रह सकता। ईरान से सीधित राश को डी जाने पानी गैस का भी कम आर्थिक व सामरिक महत्व नहीं। ईरान-इराक के बीच बाहुरी शक्तियों की पक्षधरता निश्चय ही औरो के साथ इनके सम्बन्धों में प्रतिबिम्बित होने लगी थी।

अगस्त, 1988 में संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पर अन्ततः ईरान व इराक के बीच में युद्ध विराम कराने में सफलता मिली, लेकिन दोनों देशों में तनाव खत्म होने के आसार नजर नहीं आये, जिससे सम्पूर्ण अरब जगत की राजनीति प्रभावित रही।

खाड़ी युद्ध, 1991 (The Gulf War)

कुर्बत पर इराकी कब्जा

ईरान-इराक युद्ध की आग अभी शान्त हुई थी कि खाड़ी में दूसरा विस्फोट हो गया। इराक ने पड़ोसी कुर्बत पर हमला कर दिया और भये संकट को जन्म दिया। समस्या के शान्तिपूर्ण समाधान के लिए किये गये सारे प्रयत्न निष्फल रहे

और अतः स० रा० सघ के तत्वावधान में अमरीका और मित्र राष्ट्रों की सेनाओं को हमलावर इराक को अनुशासित करना पड़ा। इस खाड़ी युद्ध ने सम-सामयिक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को नाटकीय ढंग से नया मोड़ दिया। सोवियत सघ जैसा देश इराक के साथ विरोध में भी सन्धि के बावजूद इस मामले में कोई प्रभावी एवं मार्पक भूमिका नहीं निभा पाया।

प्रमुख घटनाएँ—कुवैत के मामले को लेकर इराक और अमरीका के नेतृत्व में बहुराष्ट्रीय सेना के बीच हुए इस भयंकर युद्ध और अतः इराक की पराजय से सम्बन्धित सभी पहलुओं के विस्तरेण के पहले तिथिक्रम के अनुसार प्रमुख घटनाओं का उल्लेख जरूरी है। 18 जुलाई, 1990 को इराक ने कुवैत पर अपने कुओं से तेल चोरी करने और इराकी सीमा पर सैनिक ठिकानों की स्थापना का आरोप लगाया। 24 जुलाई, 1990 को करीब एक लाख इराकी सैनिकों ने कुवैत को घेर लिया। 2 अगस्त, 1990 को इराक ने कुवैत पर हमला बोल दिया। इसकी प्रति-क्रिया में स० रा० सघ ने एक प्रस्ताव (संख्या 660) पारित कर इराक को कुवैत से हटने को कहा। 3 अगस्त, 1990 को अरब लीग के सदस्य-देशों, अमरीका और सोवियत सघ के साथ-साथ अनेक देशों ने इराकी हमले की तीव्र भर्त्सना की। 6 अगस्त, 1990 को मऊदी अरब ने मित्र देशों को इराक के खिलाफ सुरक्षा के लिए आमन्त्रित किया। स० रा० सघ ने एक प्रस्ताव (संख्या 661) पारित कर इराक के खिलाफ आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने की घोषणा की। 8 अगस्त, 1990 को इराक ने कुवैत का अपने देश में विधिवत विलय कर लिया। 12 अगस्त, 1990 को इराक ने कुछ शर्तों के साथ यह कहा कि यदि इजराइल अरबों की हथपी हुई भूमि खाली कर देता है तो वह भी कुवैत से हट जायेगा। 28 अगस्त, 1990 को इराक ने कुवैत को अपना 19वाँ प्रान्त घोषित कर दिया। 9 अक्टूबर, 1990 को युद्ध की भयंकर स्थिति को देखते हुए कच्चे तेल के दाम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में 40 डॉलर प्रति बैरल की ऊँचाई पहुँचे। 29 नवम्बर, 1990 को स० रा० सघ ने एक प्रस्ताव (संख्या 678) पारित कर मित्र देशों को इस बात के लिए प्राधिकृत किया कि यदि इराक 15 जनवरी, 1991 तक कुवैत से नहीं हटता है तो वे स० रा० सघ के प्रस्ताव पर त्रिपक्षीयता के लिए 'सभी आवश्यक' कदम उठा सकते हैं। 10 जनवरी, 1991 को स० रा० सघ के महासचिव बुइयार शान्तिवार्ता के लिए बगदाद गये, किन्तु खाली हाथ लौटे। 12 जनवरी, 1991 को अमरीकी सेंसर ने बुरा प्रशासन को कुवैत की मुक्ति के लिए इराक के खिलाफ असं प्रयोग का अधिकार दिया। जब 15 जनवरी, 1991 की अर्द्ध रात्रि की समय सीमा तक इराक कुवैत से नहीं हटा तो 16 जनवरी, 1991 को अमरीका के नेतृत्व में बहुराष्ट्रीय सेनाओं ने 'आपरेसन डेजट स्टोर्म' शुरू कर इराक पर सैनिक हमला बोल दिया। 17 जनवरी, 1991 से इराक ने इजराइल पर स्वड प्रक्षेपास्त्र दागकर अरब देशों का समर्थन हासिल करने का प्रयत्न किया, किन्तु वह नाकाम रहा। 19 जनवरी, 1991 से अमरीका ने इराक पर 'पैट्रियोट' प्रक्षेपास्त्र से हमला प्रारम्भ किया। 25 जनवरी, 1991 से इराक ने समुद्र में बड़े पैमाने पर तेल उन्टेना जिससे पर्यावरण व समस्त गम्भीर जनसंख्या पैदा होने की आशंका पैदा हुई। 6 फरवरी, 1991 को इराक ने मित्र, फ्रांस, ब्रिटेन, मऊदी अरब, जर्मन और अमरीका से 'राजनयिक' सम्बन्ध तोड़ लिये। इस दौरान अमरीका ने इराक पर हवाई हमलारी तेज कर दी, जिसमें इराक में जन-धन

की भारी हानि होने लगी। 15 फरवरी, 1991 को इराक ने कुवैत से हटने की सख्त घोषणा की। 18 फरवरी, 1991 को मास्को में सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाच्योव व इराकी विदेश मन्त्री अजीज की भेंट एवं शान्ति योजना की घोषणा हुई। 22 फरवरी, 1991 को इराक ने सोवियत शान्ति योजना ठुकरा दी। उपर अमरीकी राष्ट्रपति बुश ने मांग की कि 23 फरवरी से इराक कुवैत से हटना शुरू कर दे। 22-25 फरवरी, 1991 को इराक ने अपने कुवैती ठिकानों और तेल प्रतिष्ठानों को गष्ट करना शुरू कर दिया। 25 फरवरी, 1991 को अमरीका के नेतृत्व में बहुराष्ट्रीय सेनाओं ने इराक के खिलाफ जमीनी हमला शुरू कर दिया, जिसके लिए इराक कई दिनों से तैयार रहा था। 26 फरवरी, 1991 को लगातार पिटने के बावजूद इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने 'जीत' की घोषणा की और कुवैत से इराकी सैनिकों की वापसी शुरू हो गई। 26-27 फरवरी, 1991 को कुवैत बाहर मुक्त हो गया और इराकी सेना की पराजय जग-जाहिर हो गयी। 27 फरवरी, 1991 को इराकी सरकार ने कुवैत पर ५० लाख सघ के प्रस्ताव को बिना शर्त मंजूर कर लिया। 28 फरवरी, 1991 को बहुराष्ट्रीय सेना ने अपनी सैनिक कार्रवाई स्थगित कर दी। तत्पश्चात् इराक में सद्दाम हुसैन के खिलाफ कई प्रदर्शन हुए और बुद्धों ने बिद्रोह भी किया।

खाड़ी युद्ध के कारण

कई विद्वानों का मानना है कि खाड़ी युद्ध के विस्फोट का प्रमुख कारण बगदाद के 'कत्तई तानाशाह' सद्दाम हुसैन की बैलगाढ़ महत्वाकांक्षाएँ और इराक का आक्रामक विस्तारवाद था। पश्चिम एशिया में इराक अपने को दजला फरात की घाटियों की प्रागैतिक सभ्यता का वारिस मानता है और आधुनिक काल में धर्म-निरपेक्ष तथा प्रगतिशील सामाजिक ताकतों का मुखर अधिवक्ता भी। सद्दाम हुसैन के सत्तारूढ़ होने के बाद इराक अपने को अरब राष्ट्रों के नेता के रूप में प्रस्तुत करता रहा है। मित में नागर की मृत्यु और अनवर मादात की हत्या के बाद यह प्रवृत्ति और भी जोर पकड़ती गयी। पिछले कुछ वर्षों में इराक फिलिस्तीनियों का प्रमुख सहायक और सहायक रहा है। यो छोट युद्ध के दौर में इराक को मिलने वाली 'सैनिक सहायता का प्रमुख क्षेत्र सोवियत संघ था, परन्तु जब से इराक ने अयातुल्ला खुर्मेनी के कठमुल्ले नेतृत्व वाले ईरान का मुकाबला करने के लिए अपनी कमर कसी, तब से वह अमरीका एवं पश्चिमी देशों का स्नेह-भाजन भी बन गया।

इस विषय में दो राय नहीं हो सकती कि इराक खाड़ी युद्ध के पहले पश्चिम एशियाई क्षेत्र में प्रमुख सैनिक शक्ति के रूप में पहचाना जाता था—एक ऐसा राष्ट्र, जो परमाणु सामर्थ्य हासिल करने की दहलीज पर खड़ा था। उसके पास खतरनाक प्रक्षेपास्त्र क्षमता थी और यह अटकल लगायी जाती थी कि उसके पास रासायनिक एवं जीवाणु आगुधों का विशाल भण्डार है। इसके साथ-साथ इराक तेल उत्पादक राष्ट्रों में विशेष स्थान रखता है और उसकी उच्च महत्वाकांक्षाओं वाली बात समझ में आती है।

तब भी, गौरवपूर्ण अतीत हो या निरवृत्त तानाशाही, इसको आक्रामक विस्तारवाद का पर्याय नहीं गमना जा सकता। यह खोजबीन जरूरी है कि वे कौन-से बुनियादी कारण थे, जिन्होंने इराक को कुवैत पर हमले के लिए प्रेरित किया।

1 ईरान-इराक युद्ध के बाद इराक पर अन्तर्राष्ट्रीय कर्ज का बोझ—आठ वर्षों तक ईरान-इराक में चले महासमर (1980 से 1988 तक) ने इराक की अर्थव्यवस्था को तहस-नहस कर दिया। तेल निर्यात से अर्जित उमकी पूंजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों से हथियारों के आयात पर खर्च हो गया था। इराक के जन हितकारी विकासात्मक कार्य ठप्प थे और उसके लिए यह जरूरी हो गया था कि वह कर्ज चुकाने के लिए विचाल घनराशि जुटाये। वास्तव में, युद्ध के साथ विवाद का आरम्भ हो इस बात के साथ हुआ कि इराक द्वारा ईरान के साथ लड़े गये युद्ध के खर्च को पूरा करने में कुर्बत हाथ बँटाये। इसी विवाद के साथ दो-तीन और पहलू जुड़े हुए हैं।

2 तेल कूपों और तेल कीमतों से सम्बन्धित विवाद—1988 में ईरान के साथ युद्ध विराम के बाद इराक की यह अभिलाषा स्वामित्व थी कि तेल की कीमतें बढ़ी रहें, ताकि वह जल्दी से जल्दी ज्यादा मुनाफा कमाकर कर्ज का बोझ कम कर सके। इसके लिए यह जरूरी था कि सभी तेल उत्पादक राष्ट्र सहमत सीमा के भीतर ही तेल उत्पादन करें और तेल की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें गिरने न पायें। मगर कुर्बत अपने आचरण से यह प्रवृत्ति बंद रहा था कि उसे इस तरह की कोई बंदिश मंजूर नहीं। इसके अलावा इराक में इस बात को लेकर भी आश्रय बना रहा कि कुर्बत के सबसे लाभप्रद तेल कूपों पर इराक अपने स्वामित्व का दावा करता है। एक राष्ट्र राज्य के रूप में कुर्बत का उदय ब्रिटिश नीति के फलस्वरूप 1950 वाले इराक में हुआ। इससे पहले यह भू-भाग ऐतिहासिक इराक का प्रान्त ही था।

3 इराक में आन्तरिक असन्तोष—ईरान-इराक युद्ध के बाद इराक में व्यापक जन-आक्रोश व्याप्त था। जब ईरान और इराक में सैनिक मुठभेड़ आरम्भ हुई थी तो लोगों का यह मानना था कि इराक बहुत जल्दी ईरान को शिकस्त दे देगा। परन्तु ऐसा कुछ नहीं हुआ और इराकी जनता को राष्ट्र प्रेम के नाम पर तरह-तरह की बहुत बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ी। शान्ति की पुन स्थापना के बाद सद्दाम हुसैन के लिए यह परमावश्यक हो गया कि वह अपनी जनता का ध्यान आन्तरिक समस्याओं से हटाकर किसी और दिशा में मोड़े। इराक में कुर्बत की समस्या एक शामक विरादरी में आन्तरिक जानलेवा बैर विकट सबूत का रूप ग्रहण कर चुके थे। इराक द्वारा अमरीका को चुनौती देने के लिए सम टोकना-टुकारना इसीलिए जरूरी हुआ। परन्तु ऐसा नहीं कि खाड़ी युद्ध के लिए सिर्फ इराक ही जिम्मेदार था। इराक को युद्ध की बगार तक ले जाना और उसमें घबेलना अमरीका के कुटिल राजनय के कारण सम्भव हुआ।

4 अमरीका का कुटिल राजनय—पश्चिम एशिया में अमरीका के सरक्षित इजराइल का अस्तित्व तब तक निरापद नहीं समझा जा सकता, जब तक कि इराक की सैनिक क्षमता का पूरी तरह ध्वस्त नहीं कर दिया जाये। विलस्तीनियों की रीढ़ तोड़ने के लिए इराकियों को मटियामट करना जरूरी था। अतीत में इराकी परमाणु मयंत्र पर इजराइली बमबारी के बाद भी यह मसूवा पूरा नहीं हो सका। किन्तु इस बार अमरीका ने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुटिल राजनय का जाल फैलाया। जहाँ एक ओर उसने मऊदी अरब जैसे देश को इस सौफ से परमान रखा कि जो हाल आज कुर्बत का है, कम उमरों में हो सकता है। दूसरी ओर उसने निशाने की मागूम अंदा के साथ म० रा० मय का चार्टर की रक्षा की दुर्गई

दी। साथ ही, अमरीका ने इराक को इस भ्रम में उलझाये रखा कि समस्या के हल के लिए संवाद जारी है और आखिरी क्षण तक सैनिक मुठभेड़ को टाला जा सकता है। अमरीकी राजनय की कुदृष्टता अप्रत्याशित रूप से सफल हुई, जिसके लिए सिर्फ अमरीकी कौशल ही नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य भी जिम्मेदार रहा।

5. तनावग्रस्त सोवियत संघ—पेरेश्चोयका और ग्लासनोस्त वाले दौर में गोर्बाचोव का सोवियत संघ अपनी आन्तरिक समस्याओं में बहुत बुरी तरह उलझ गया। मध्य एशियाई गणराज्यों में बगावत का संयोग जन-जातीय और इस्लामी अल्पसंख्यकों के साथ हुआ। यूरोप के एकीकरण ने भी साम्यवादियों पर भारी दबाव डाला। सोवियत संघ ने एक तरह से स्वेच्छा से पश्चिम एशियाई रण छोड़ दिया। अब मध्य पर एक ही महाशक्ति अमरीका बची रही और इराक के सामने अकेले खड़े रहने के सिवाय कोई विकल्प नहीं था। युद्ध से बचने का कोई राजनयिक द्वार सुझाने वाला नहीं बचा, न ही कोई ऐसा व्यक्ति-सन्तुलन था जो शक्ति को बरकरार रखता।

6. गुट निरपेक्ष आन्दोलन की अक्षमता—इराक के ध्वंस के लिए गुट निरपेक्ष आन्दोलन की अक्षमता एक बड़ी सीमा तक उत्तरदायी रही। भारत जैसे अनेक गुट निरपेक्ष आन्दोलन के प्रमुख सदस्य अपनी आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक कठिनाइयों और आपसी विवादों में ऐसे फसे थे कि वे खाड़ी युद्ध में मध्यस्थता की बात सौच भी नहीं सकते थे। तथापि इस मुद्दे को अनावश्यक तुल देने की जरूरत नहीं, क्योंकि सोवियत संघ के समर्थन और सहायता के बिना गुट निरपेक्ष जमावड़ा अमरीका की सैनिक क्षमता के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता था। वैसे भी गुट निरपेक्ष आन्दोलन की मरुसकता ईरान-इराक युद्ध के दौरान भी जगजाहिर हो चुकी थी।

खाड़ी युद्ध के प्रभाव

इस युद्ध के प्रभाव सग-सामयिक अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर बहुआयामी ढंग से पड़े। सबसे पहले तो यह बात सिद्ध हुई कि अब संसार में सिर्फ एक ही महाशक्ति रह गयी है। अमरीका के वर्चस्व की चुनौती देने वाला कोई प्रतिद्वन्द्वी नहीं बचा, जबकि पारम्परिक रूप से यह भूमिका सोवियत संघ निभाता रहा था। आणविक अस्त्रों के आविष्कार के बाद आतंक के सन्तुलन ने शक्ति सन्तुलन का स्थान ले लिया था और तनाव शैथिल्य के बाद क्षेत्रीय समस्याओं के निपटारे के द्वारे में दोनों महाशक्तियों के सामरिक हितों का संयोग अनेक जगह देखने को मिला था। परन्तु, खाड़ी युद्ध में यह बात साफ़ झलकी कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का यह दौर समाप्त हो चुका है। खाड़ी युद्ध के अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़े प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं—

1. सोवियत संघ का अवमूल्यन—खाड़ी युद्ध का एक प्रमुख प्रभाव सोवियत संघ के भारी अवमूल्यन के रूप में सामने आया। गोर्बाचोव ने जब सोवियत व्यवस्था के सुधार और नव-निर्माण के लिए पेरेश्चोयका और ग्लासनोस्त का मार्ग चुना तो उन्होंने यह जोखिम जान-भूझकर उठाया कि भविष्य में आगे बढ़ने के लिए उन्हें वर्तमान में एक नदम पीछे हटना पड़ सकता है। सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के मरुदरपी नेता उनकी आलोचना यह कहकर करते रहे कि मुलह का मार्ग चुनना

सोवियन सभ की कमजोरी समझा जा सकता है। इसका लाभ अमरीका अधिक आशामक तेवर अपना कर उठा सकता है। दुर्भाग्यवश, सोवियन मन्दमं में तब तक निराशावादी भविष्यवाणियाँ ही सभ साबित होनी रही हैं। पश्चिमी पूँजी और तकनीकी को आमन्त्रण देने के लिए गोर्बाच्चेव ने यह भी ज़रूरी समझा कि पूर्वी यूरोप में अवहमति या अमनोप को मुखर होने दे, जर्मनी से लाल सेना को वापस बुला लें और यूरोपीय एकीकरण में बाधक न बनें। परन्तु, इस सबके बावजूद सोवियन सभ में न तो आर्थिक विकास की दर तेज की जा सकी और न ही मध्य एशियाई सोवियत गणराज्यों में बिप्लव के विस्फोट को नियन्त्रित रखा जा सका। कुल मिलाकर, सोवियन सभ आन्तरिक चुनौतियों से घुसने में इतना व्यस्त रहा कि खाड़ी युद्ध के बाद वह न तो इस अन्तर्राष्ट्रीय मकड़ का समुचित मूल्यांकन कर सका और न ही इसके अनुकूल सामरिक व राजनयिक नीति का संचालन।

2. आधुनिक शास्त्रास्त्रों का कमत्कारी प्रयोग—आधुनिक शास्त्रास्त्रों का कमत्कारी प्रयोग खाड़ी युद्ध की एक प्रमुख विशेषता थी। जब अमरीका ने आक्रमणकारी इराक को दण्डित करने के लिए सैनिक कदम उठाये, तब स्वयं अमरीका में कई लोगो ने यह आशंका व्यक्त की कि बिपतनाम का दुस्स्वप्न फिर से दयार्थ में बदलने वाला है। कुछ लोगो का यह भी मानना था कि जब जमीनी लड़ाई के दौरान रेगिस्तान में अमरीकी सैनिक हताहत होने लगे अमरीकी जनमत प्रतिकूल होने का कारण इस युद्ध को सम्भे समय तक जारी रखना उनके लिए सम्भव नहीं रह जायेगा। इराक के पक्षधर अयो-एशियाई और इस्लामी देशों ने यह सन्देह भी प्रकट किया कि बिपतनाम की भासदी अब एक पौड़ी पुरानी हो गई है। आज का अमरीकी सैनिक पश्चिम एशियाई रेगिस्तान की गर्मी सेवन और वहाँ लड़ने लायक नहीं रह गया है। अमरीकी सैनिक आधुनिकतम इलेक्ट्रोनिक उपकरणों से सैत थे, जिनके बारे में यह अटकल लगयी गयी कि इनका प्रदर्शन और परीक्षण अभी तक किसी रणक्षेत्र में नहीं हुआ है। कही ऐसा न हो कि वास्तविक युद्ध में यह सब सार्थक सिध्दान्त ही साबित हो। सबसे पहले तो यह सवाल उठाया गया है कि क्या धार्मिक और राजनीतिक विचारधारा ने मजबूत इराकी सैनिकों का मुकाबला बेतन मीगी अमरीकी सैनिक कर भी सकते हैं? जैसाकि पहले कहा जा चुका है कि इराक के परमाणु, रासायनिक और जीवाणु हथियारों का भी बड़ा हन्ता था, जो अमरीकी विजय के बारे में सन्देह पैदा कर रहे थे।

मगर, अमरीका ने नाममात्र का मुकाना उठाकर ही इराक को परास्त और ध्वस्त कर सारे विद्वत् को विस्मृत कर दिया। पहले तो यह लगा कि इराक सम्भवतः अपने लाव-लज्जर को किसी बड़े नाटकीय जवाबी हमले के लिए मुरशिन रख रहा है। परन्तु जल्दी ही यह स्पष्ट हो गया कि वह अमरीका के सामन टिक नहीं सकता। सोवियन सभ सेहामित विये गये स्वड प्रसेवास्त्र सीरी हुई आतिशबाजी के समान ही निकले। उधर, अमरीका ने बीडियो-गेलों की तरह घर बैठे इराकी सेना को तबाह कर दिया। जिस सर्जनि तामसाम के कारण स्टार वॉर्न परियोजना की बदनामी हुई थी, उसकी अब कमत्कारी मपमना देखने को मिली। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में भी अमरीकियों की तुलना में सोवियन सभ की कार्यकुशलता और तकनीक का निष्प्रहापन ही देखने को मिला। न केवल यह बीडिया-युद्ध खाड़ी के लिए निर्धारक मिड हुआ, बल्कि इससे बाकी दुनिया को भारी झेठावनी मिल गयी कि

अमरीका अपने सैनिकों की जान बचाते हुए दूसरों का पैसा खर्च करवा कर कितनी दूर तक कितनी खतरनाक मार कर सकता है।

(3) संयुक्त राष्ट्र संघ की निष्क्रियता—संयुक्त राष्ट्र सभ की निष्क्रियता ने ही अमरीका की दिव्यध्यायी कोतवालों को संभव बनाया। विदम्बना तो यह है कि सैनिक गतिविधियाँ शुरू करने के पहले अमरीका ने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के प्रावधानों का पूरा लाभ अपने राष्ट्रीय हित के पोषण-संरक्षण के लिए उठाया। संयुक्त राष्ट्र सभ के सदस्यों में भारत जैसे इराक के मित्र-राष्ट्रों के लिए भी यह संभव नहीं था कि वे खुल्लमखुल्ला आक्रमणकारी इराक का समर्थन करते। दुर्भाग्यवश, आरम्भ से ही हठी और अहंकारी सद्दाम हुसैन के तेवर 'चोरी और सीनाचोरी' वाले रहे। उसने स्वयं इस बात का कोई प्रयत्न नहीं किया कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्था का लाभ अपने हित में उठा सके। यहाँ इस बात की फिर दोहराना जरूरी है कि सोवियत सभ के राजनयिक भवमूत्पन ने भी संयुक्त राष्ट्र सभ की महासभा में आम तौर पर मुसर रहने वाले अफ़ो-एशियाई देश भी असहाय ही बने रहे—कुछ आतंकित तो अन्य आसक्ति। दोनों ही हालात में इनका राजनयिक आचरण पक्षाघातग्रस्त-भा था।

अमरीका ने बड़े राजनयिक कौशल या घुंतीता के साथ उस प्रस्ताव का ममीदा तैयार किया, जिसके अनुसार यदि इराक बिना शर्त कुवैत से नहीं हटता है तो उसे मित्र राष्ट्रों की सैनिक कार्रवाई का सामना करना था। अनेक विद्वानों का मानना है कि आर्थिक प्रतिबंधों या तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को ईमानदारी से आजमाया ही नहीं गया। फिर, यदि आक्रमण समाप्त करने और अन्तर्राष्ट्रीय शांति की पुनर्स्थापना के लिए 'सैनिक उपकरण' का प्रयोग करना अनिवार्य ही हो गया था तो यह अभियान संयुक्त राष्ट्र सभ के तत्वावधान में होना चाहिये था, अमरीकी छत्रछाया में नहीं।

(4) तेल संकट—खाड़ी युद्ध के कारण विकासशील देशों को 1973 के बाद फिर से तेल संकट का अहंसा हुआ। इस युद्ध के बाद न सिर्फ तेल के दाम बढ़े बल्कि कुछ दिनों के लिए यह बाजार से गायब ही हो गया। इराक ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि युद्ध के दौरान जो देश उसका साथ नहीं देंगे, वे युद्ध के बाद उससे सहायुभूति या सहायता की उम्मीद नहीं कर सकते। इस कारण भी बहुत तारे अफ़ो-एशियाई देश असमंजस में पड़े रहे और उन्हें निजामत कर अपनी नीति स्पष्ट नहीं की।

(5) पश्चिम एशिया में पर्यावरण के लिए अप्रत्याशित संकट—इस युद्ध के दौरान अभूतपूर्व बम वर्षा और तेल कूपों में आग के कारण खाड़ी क्षेत्र का पर्यावरण बुरी तरह प्रदूषित हो गया। तेन शोषक वास्तुानों से तेल के समुद्र में बहने से सागर तक और मानववासी जीव-जन्तु संकटग्रस्त हो गये। यह बिपय सिर्फ पर्यावरण प्रेमियों की चिन्ता का नहीं था। खाड़ी का रेगिस्तानी इलाका पेयजल तक के लिए आत्मनिर्भर नहीं है और यहाँ का वातावरण तापमान की दृष्टि, कुछ अंश भी बदलित नहीं कर सकता। इस युद्ध जनित प्रदूषण को दूर करने के लिए अब बड़े पैमाने पर खर्च आवश्यक हो गया। इससे भी इराक और कुवैत के विकास कार्यक्रम प्रभावित हुए।

(6) मिश्रकों का अन्त—इस खाड़ी युद्ध से जिन बहुत-मारे मिश्रकों का बचे

रहना असमभव हो गया, वे निम्नांकित हैं

(i) बाहरी-विदेशी-परधर्मी आक्रमणकारी के विरुद्ध सभी अरब एक हो जाते हैं,

(ii) इराक घर्मेनिरपक्ष, समाजवादी और आधुनिक राष्ट्र है,

(iii) जमीनी सड़ाई प्रक्षेपास्त्रों की नवीनतम पीढ़ी के सामने अपनी अहमियत रखती है और बड़े पैमाने पर सैनिकों का जमाव या धापाकारी दूर संचालित परिष्कृत टेक्नोलोजी का मुकाबला कर सकती है। इस प्रकार, इराक के उच्चतम उत्तेजित आचरण के बारे में हमारा क्षणाएँ निर्मूल साबित हुईं। इजराइल का नीति निर्धारण व्यस्क ढंग से सम्पादित हुआ और अपने समय द्वारा इजराइलियों ने अरबों का अमरीका-विरोधी संयुक्त मोर्चा संयोजित नहीं होने दिया। फिनलैंड की अपनी गणना में बुरी तरह चूके और जो कुछ सद्भावना उन्होंने यूरोप और अमरीका में अर्जित की थी, इस एक् ही जुए में गँवा डाली।

(7) दक्षिण एशियायी भूभाग पर प्रभाव—खाड़ी युद्ध से यह बात पता चली कि भारत के लिए इस इलाके में विदेशी मुद्रा का अर्जन निकट भविष्य में संभव नहीं। इराक और कुवैत एक साथ खर्च करने में असम हुए हैं। जहाँ एक ओर इराक के ऊपर युद्ध के हर्ज-खर्च का बोझ पड़ गया तो दूसरी ओर कुवैत इस बात के लिए विवश है कि आभार प्रकट करने के लिए पुनर्निर्माण, उद्योगों की स्थापना आदि के सबसे सामग्रद ठेके मित्र राष्ट्रों को दे। हाँ, पाकिस्तान ने जरूर इस सैनिक मुठभेड़ के दौरान अनात हो नहीं, अमरीका के साथ अपना मतभेद प्रकट होने दिया। सऊदी अरब जैसे देशों के लिए लंबे समय तक अपनी भूमि पर विदेशी सेना की उपस्थिति असह्य थी। ऐसी स्थिति में इस युद्ध ने पाकिस्तान व अरब देशों के बीच नई सामरिक समस्याओं का उद्घाटन किया। कुत मिलाकर, पश्चिम एशिया में धार्मिक कट्टरता प्रकारान्तर से प्रोत्साहित हुई है और इसे दक्षिण एशियाई सदम में अपने पक्ष में मूकाने के बारे में पाकिस्तान प्रयत्नशील हो सकता था। कुत मिलाकर, इस मुठभेड़ में ईरान की प्रतिष्ठा बढ़ी।

(8) अन्य प्रभाव—इस पूरे प्रसंग में संयुक्त राष्ट्र सच और गुट निरपेक्ष आन्दोलन दोनों की ही भूमिका नगण्य रही। यो पिछले दशक में ये दोनों नामोन्लेख के लिए शेष रहे हैं। खाड़ी युद्ध में भारतीय राजनय बिल्कुल पगु बना रहा। न तो गुट निरपेक्ष आन्दोलन के सदस्य में कोई पहल की जा सकी और न ही संयुक्त राष्ट्र सच का सदुपयोग किया जा सका। इस युद्ध का एक अन्य सबसे बुरा परिणाम यह हुआ कि त्रिम जोर-शोर से खाड़ी युद्ध के आरम्भ में इराक को अमरीका के मुकाबले तीमरी व विकासशील दुनिया के प्रतिनिधि के रूप में वेत किया गया, इस कारण इराक की हार भी इस पूरी विश्वदरी-जमान के लिए मामूहिक क्षय का कारण बनी, जगमे उबरने में काफी समय लगेगा।

यथास्थिति में बड़े परिवर्तन की आशा नहीं—उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि खाड़ी युद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था आमूह-जूल रूप में बदल गई है। बिना किसी अनिश्चयों के यह कहा जा सकता है कि पश्चिम एशिया के तेल भण्डार पर अमरीकी आधिपत्य एवध्वन है। जुझारू अरब आन्निवारिता का दम भरने वाले सीरिया, लीबिया, फिनलैंडियों की हानत आतिरी दाव हारे पुजारी सी हो चुकी है। ये पिटी हुई मोटियाँ हैं। जोहॉन के शाह और मिथ तो पहले ही अमरीका के

महमोमी बन चुके थे। इस्लामी गवित्र स्थानों का संरक्षक और अरबों में सबसे बड़ा धन कुँवर सऊदी अरब है, जो अपने अस्तित्व और समृद्धि की रक्षा के लिए बाहरी पश्चिमी शक्तियों पर बुरी तरह निर्भर है। ऐसी हालत में इस क्षेत्र में यथास्थिति में किसी बड़े परिवर्तन की आशा नहीं की जा सकती।

यहाँ यह भी ओड़ने की जरूरत है कि इस संघर्ष के बाद अमरीका और इजराईल दोनों ही फिलिस्तीन समस्या को संवाद के माध्यम से सुलझाने के लिए तत्पर हो चुके हैं। यह चार्ज अमरीका, अरब राष्ट्रों और इजराईल में मीडिड में सवम्बर 1991 में शुरू हुई। इसक में सद्दाम हुतैन का गद्दी पर बने रहना अल्प-संख्यक कुर्दों के लिए वशनाशक सिद्ध हो सकता है। यदि खाड़ी युद्ध में उनके मन में यह आशा नहीं जगायी होती कि सद्दाम का तख्ता पलटा जा सकता है तो कुर्दों ने आत्मघाती विद्रोह का मार्ग नहीं चुना होता।

पश्चिम एशिया का भविष्य

इस बात के कोई संशय रहितगोचर नहीं होते कि निकट भविष्य में पश्चिम एशिया में शान्ति स्थापित होगी। फिलिस्तीनी छरणाशियों की समस्या, लेबनान का गृह-युद्ध, अराजकतावादी आतंकवाद, कट्टरपंथी इस्लाम का ज्वार आदि इस क्षेत्र की अपनी समस्याएँ भी कम जटिल नहीं हैं। सऊदी अरब में सामाजिक परिषर्जन, समतापूर्ण समाज की स्थापना तथा आपुनिकीकरण से पैदा होने वाले तनाव मनवैले नहीं किये जा सकते। प्रचुर तेल भण्डार होने के कारण महाशक्तियों और बड़ी शक्तियों की घबि इस क्षेत्र में बनी रहेंगी। ऐसा नहीं लगता कि इस क्षेत्र के अनेक राष्ट्रों में अर्थ-व्यवस्था, राजनीति और समाज में 'सहज सन्तुलन' देखने को मिलेगा। कवायली बैमनस्य और निरंकुश शासकों की उच्छ्रुसलता इस क्षेत्र की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर असन्तुलनकारी प्रभाव ही डालेंगे।¹

¹ इन विविध आयामों के विषय में प्रमाणित और रोचक जानकारी ■ लिए देखें— Robert G. Donas, John W. Amos-II and Rolf H. Magnus (ed.), *Gulf Security into the 1980's: Perceptual and Strategic Dimensions* (California, 1984), and M. S. Agwan (ed.), *The Gulf in Transition* (Delhi, 1987).

विदेश नीति : सैद्धान्तिक विश्लेषण

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय इकाइयाँ राष्ट्र-समूह होती हैं। एक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के साथ अपने सम्बन्ध निर्वाह में जिस नीति का अनुसरण करता है, उसे विदेश नीति कहते हैं। अर्थात् विदेश नीति का स्पष्ट अन्तर राष्ट्र की आन्तरिक प्रशासनिक नीति से बिछा जाता है। परन्तु इस तरह का अन्तर विदेश नीति के विधिवत् वैज्ञानिक अध्ययन-विश्लेषण के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। यह भी कहा जाता है कि किसी देश की विदेश नीति उसके राष्ट्रीय हितों के मरक्षण-संवर्धन का काम करती है। इससे यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि राष्ट्र की आन्तरिक नीतियाँ राष्ट्रीय हित से सम्बन्धित नहीं हैं। वस्तुतः राष्ट्र के समस्त क्रियाकलाप राष्ट्र-हित-वैश्वित होते हैं। इस प्रकार आन्तरिक नीति और विदेश नीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इन दोनों का परस्पर सम्बन्ध सीधा, जटिल एवं पनिष्ठ होता है।

विदेश नीति की परिभाषा (Concept of Foreign Policy)

दिगिर गुप्त जैसे प्रखर विदेश नीति विश्लेषकों का मानना है कि 'विदेश नीति किसी भी देश की आन्तरिक नीतियों का अन्तर्राष्ट्रीय प्रक्षेपण (Projection) होती है।' यहाँ यह पूछा जा सकता है कि यह प्रक्षेपण क्यों आवश्यक होता है? इसको समझने के लिए अन्तर-सम्बन्ध निदान (Linkage Theory) प्रतिपादित करने वाले जेम्स रोसोनी तथा जोजफ फ्रैंकल जैसे दिग्गजोंवालों के विचारों पर दृष्टि-पात आवश्यक है।

इन विद्वानों का मत है कि आन्तरिक राजनीतिक घटनाक्रम बाहरी वातावरण अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से अनुसूचित होता है। इसीलिए किसी भी आन्तरिक नीति की सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए समुचित विदेश नीति निर्धारण तथा कारगर राजनय अनिवार्य है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद अरबों एक भाषण में नेहरू जी ने बहुत सही ढंग से इस बात को उजागर किया। उनके इस भाषण का प्रीत्यंघा—'अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हम पर बरबस प्रभाव डालता है' (World affairs impinge on us)। हम इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। विदेश नीति की मार्गिक परिभाषा यही है—'निर्धारित आन्तरिक नीतियों के सफल क्रियान्वयन के लिए कुशलतापूर्वक अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण को अपने अनुसूचित बनाने की रणनीति।' यह स्मरणीय है कि मनोनुसृत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए क्रिया-प्रतिक्रिया वाले आचरण को विदेश नीति नहीं माना जा सकता। 'नीति का दर्जा प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्र-हित संवर्धन के लिए वांछित सध्य रेखांकित किये जायें।

तदुपरान्त उपलब्ध तथा सम्भावित संसाधनों को देखते हुए साध्य-साधन समीकरण बैधाना जाये एवं निर्धारित सध्य प्राप्त के लिए साम-लागत (Cost-Benefit) और अवसर-लागत (Opportunity Cost) के अनुसार एक से अधिक विकल्प विश्लेषित किये जायें।¹ दूरदर्शी नीति नियोजन अपने आप के काफी नहीं, बल्कि इस नीति का सफल सम्पादन (राजनय) समग्र विदेश नीति का ही हिस्सा है। महाकाव्य महाभारत के दूत धर्मयुध्न प्रकरण में श्रीकृष्ण ने कौरवों के दरबार में जाते वक्त अपने अभियान का वर्णन करते हुए विदेश नीति के इन सभी पक्षों पर अच्छा प्रकाश डाला है। श्रीकृष्ण ने कहा—‘मेरा पहला उद्देश्य अपनी न्यायोचित भाग को मनवाना है। यदि ऐसा सम्भव न हो तो वन प्रयोध (युद्ध) द्वारा अपने हितों की रक्षा का प्रयत्न सफल बनाने व विपक्ष को कमजोर करने के लिए मित्रों की सहायता बढ़ाना तथा जो मित्र नहीं हैं, उन्हें कम से कम तटस्थ रखना है।’² कौटिल्य और मेकियावेली जैसे अति यथार्थवादी चिन्तकों ने ‘मण्डल सिद्धान्त’ के विविध रूपान्तरणों द्वारा विदेश नीति सम्बन्धी कुछ ‘शाश्वत सत्य’ उजागर करने का प्रयत्न किया है। इनमें कुछ प्रमुख ‘शाश्वत सत्य’ इस प्रकार हैं—सीमान्त का साक्षात् करने वाला पड़ोसी शत्रु ही होता है तथा शत्रु का शत्रु गृहजना से मित्र बनाना जा सकता है।

इस तरह की सूक्तियों के अनुसार विदेश नीति निर्धारण 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध तक होता रहा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामरस्टन का मानना था कि किसी देश के न तो शाश्वत मित्र होते हैं और न ही स्थायी शत्रु होते हैं—होते हैं ‘मिर्क राष्ट्रीय-हित’।³ इस परिचलना के अनुसार विदेश नीति घुमा-फिराकर शक्ति सन्तुलन की कसौटी पर कसी जाने वाली स्वार्थी अवसरवादिता भर रहती है। सत्ता का संघर्ष व शक्ति सन्तुलन, गुप्त मन्त्रियों तथा वैवाहिक सम्बन्धों की खोसली नींव पर टिके रहते हैं। इसका जोखिम प्रथम विश्व युद्ध के विस्फोट से स्पष्ट हो गया। तभी से विद्वान् लेकर अन्तर्राष्ट्रीय ज्ञानि व सुव्यवस्था बनाये रखने के लिए विदेश नीति विश्लेषण के वैज्ञानिक तर्कसंगत तरीके बँदते रहे।

नीति नियोजक तथा नीति निर्धारक (Policy Planners and Policy Makers)

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अमरीकी समाजशास्त्रियों के शोध के फलस्वरूप विदेश नीति विश्लेषण की दो प्रमुख धाराएँ प्रकट हुई—(i) उदाहरण परीक्षण (Case Study) तथा (ii) तुलनात्मक अध्ययन (Comparative Study)।

एक पद्धति (approach) विदेश नीति से सम्बन्धित किसी भी निर्णय विरोध के माफ़ार होने को सबसे महत्वपूर्ण सम्पत्ति है। स्नाइडर ने यह पद्धति मुतायी और परिष्कृत की। इसे ‘डिसिजन मेकिंग एनालिसिस’ (Decision Making Analysis) के नाम से जाना जाता है।⁴ मोटे तौर पर इसे व्यक्ति-केन्द्रित कहा जा सकता है। इसके अनुसार सबसे पहली जरूरत इस बात की होती है कि उन निर्णायक व्यक्तियों को पहचाना जाये जो विदेश नीति के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं। इसके बाद इन व्यक्तियों के प्रतिक्षण, अनुभव और इनकी योग्यता-प्रतिभा का मन्वन्ध उनके रजान, पूर्वग्रह, दृष्टिकोण आदि से जोड़ा जाये। इस तरह के विश्लेषण

¹ Richard C. Snyder, H. W. Brock and Burton Sapin, *Decision Making as an Approach to the Study of International Politics*, (Princeton, 1954)

में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, वर्गों के स्वार्थ व राष्ट्र हित का टकराव और समायोजन महत्वपूर्ण बन जाते हैं। व्यक्ति विशेष का विश्व द्योतन यथासंभव है या भ्रान्त, इसका परीक्षण भी आवश्यक होता है। इस व्यापक परिप्रेक्ष्य में इस तरह के सवाल उठाये जाते हैं कि वैदेशिक मामलों में किसी विशेष पंखले, बिकल्प और पहल को किमने मुझाया था तथा इस मुझाव का रूपान्तरण किस प्रकार हुआ और जब यह ऐसा निर्णय बना जिसे बदला न जा सकता हो। एक तरह से प्रमुख अभिनेता वाले पारम्परिक विश्लेषण से ही विदेश नीति विश्लेषण की यह पद्धति प्रेरित है। हाँ, इतना परिष्कार अवश्य किया गया है कि अब अद्वय नीति निर्धारकों (जैसे मौकरसाह) को पहचानने का प्रयत्न किया जाने लगा है।

व्यक्ति बनाम संस्थाएँ

(Individual vs Institutions)

विदेश नीति विश्लेषण की दूसरी पद्धति प्रणाली विश्लेषण (System Analysis) की है। यह व्यक्ति केन्द्रित न होकर व्यवस्थापरक होती है। इसके प्रणेता मोर्टन काप्लान हैं। उनके मतानुसार विदेश नीति निर्धारण में व्यक्ति की भूमिका गौण रहती है। व्यवस्था (System) और संस्थागत संरचना (Institutional Framework) के अन्तर्निहित तत्व इतने प्रभावशाली होते हैं कि किसी भी निर्णय का स्वरूप वे ही तय करने हैं। तथ्याकथित नीति निर्धारकों का विश्व द्योतन, उनके उपलब्ध जानकारी, आधारभूत मूल्य, बिकल्पों के मूल्यांकन की पद्धति-सम्भावना सब कुछ व्यवस्था पर निर्भर होते हैं। अतः उनका मुझाव है कि हमारा प्रयत्न व्यवस्था की संरचना में परीक्षण व विश्लेषण पर केन्द्रित होना चाहिये। इस तरह के विद्वानों का यह भी मानना है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक व्यवस्था दूसरी व्यवस्था के साथ अन्तर-क्रियारत (Inter-active) रहती है तथा हर व्यवस्था में अनेक उप-व्यवस्थाएँ (Sub-systems) समाविष्ट रहते हैं।¹

आजकल अधिस्तरीय विदेश नीति विश्लेषण विदेश नीति के अध्ययन के लिए 'डिजिटल मैकिंग' तथा 'मिस्टम एनालिसिस' (Decision Making and System Analysis) को सन्तुलित करते हुए वह काम सम्पन्न करते हैं। यह ठीक भी है, क्योंकि व्यक्ति और प्रणाली में से किसी एक की उपेक्षा करने पर यथास्थिति का पता नहीं चलता। साथ ही विदेश नीति के विविध घटकों व अन्तर-सम्बन्धों को अन्वेष्टा नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए विदेश नीति के विधिवत अध्ययन के लिए परम्परा और परिवर्तन, व्यक्ति और विदेश विभाग, माध्यम तथा साधन सभी का तात्तमेल बिठाना परमावश्यक है। इस प्रणाली से तर्कमग्न निष्कर्ष तभी निकाले जा सकते हैं, जब हमारा परिप्रेक्ष्य तुलनात्मक हो, क्योंकि कोई भी विदेश नीति मूल्य में निष्पादित नहीं होती।

विदेश नीति के बुनियादी तत्व

(Basic Elements of Foreign Policy)

हाम मौर्येण्यो जैम विद्वाना का मानना है कि समस्त अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध नीति गणन का प्रतिबिम्बित करण हैं। नीति सिद्धान्त व आधार पर ही विदेश

¹ Morton A. Kaplan, *System and Process in International Politics*

नीति का विश्लेषण किया जाना चाहिये।¹ इस बात में मतभेद की गुंजाइश नहीं, परन्तु कठिनाई यह है कि शक्ति को किस प्रकार परिभाषित किया जाये? वट्टेड रसल जैसे दार्शनिकों ने सुझाया है कि शक्ति का अर्थ है—‘किसी दूसरे व्यक्ति, समूह, यन्त्र-उपकरण आदि के क्रिया-बलाप को अपनी इच्छानुसार प्रभावित कर सकना।’ यह परिभाषा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में भी गटीक बैठती है। इस तरह शक्ति, सत्ता, बल, क्षमता, सामर्थ्य, प्रभुत्व इस सन्दर्भ में उपयोगी और अक्सर लचीले ढंग से प्रयुक्त की जाने वाली अवधारणाएँ हैं।

तथापि हमारी अटकलें इतना भर जान लेने से सहाय्य नहीं होती। दूसरों को प्रभावित करने वाली शक्ति या क्षमता सैनिक भी हो सकती है और आर्थिक भी। कई बार हम सांस्कृतिक प्रभाव से ही मनोवाञ्छित लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा भी सम्भव है कि विदेश नीति नियोजन व सम्पादन में इन तीनों तरहों का समुचित समन्वय देखने को मिले। बहरहाल, विदेश नीति के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए हम शक्ति शब्द की जाँच-परख यथार्थवादी विद्वानों द्वारा सबसे महत्वपूर्ण समझी जाती है।

यथार्थवादी शक्ति सिद्धान्त के समर्थकों की तरह इसके आलोचक भी कम सुलभ नहीं। भारतीय विद्वान जमन्तनुज बघोपाध्याय ने गौर्गेन्सो के यथार्थवादी सम्प्रदाय की तीखी आलोचना की है। उनके अनुसार ‘अमूर्त विचार स्थूल शक्ति की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और इनका प्रभाव विदेश नीति पर स्पष्ट देखा जा सकता है। समुचित सार्थक विचार शक्ति साधना को सफल बनाते हैं और भ्रष्ट व भ्रमिष्ठ विचार निश्चित रूप से अमफलता तक पहुँचाते हैं।’ यह दृष्टिकोण आदर्शवादी है, परन्तु ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यह अवास्तविक है। स्वयं मार्क्स और लेनिन जैसे क्रान्तिकारियों के विचारों में और उनके क्रियाकलापों-उपनयनों से हम स्थापना की पुष्टि होती है। वह पुरानी बहस यूनानी दार्शनिक प्लेटो के जमाने से चली आ रही है और समुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र तक में यह बात स्वीकार की गयी है कि युद्धों का जन्म मनुष्य के मस्तिष्क में होता है और इनका जन्मलन भी वही किया जा सकता है। इसके पहले भी बुडरो विलसन ने अपने प्रसिद्ध सिद्धान्तों में भय से मुक्ति की वान की थी। समसामयिक राजनीति में मार्शवादी क्रान्तिकारिता तथा नीविया व ईरान के कट्टरपक्षी आचरण से यह बात रेखांकित होती है कि विदेश नीति के सैद्धान्तिक वैचारिक पक्ष को अनदेखा नहीं किया जा सकता।

विरोधकर साम्यवादी देशों के सन्दर्भ में यह बहस काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि उनकी विदेश नीति यथार्थ के आधार पर संचालित होती है या सैद्धान्तिक स्थापनाओं के अनुसार। यह सुझाना तर्कसंगत है कि अनेक बार सिद्धान्त या विचारधारा शक्ति भ्रमर्ष के ऊपर पड़े आचरण ही होते हैं। यह भी सच है कि शक्ति की साधना किसी न किसी विचारधारा द्वारा परिभाषित तथ्यों की प्राप्ति के लिए की जाती है। इसलिए शक्ति और विचारधारा दोनों ऐसे बुनियादी तत्व हैं, जिन पर किसी भी देश की विदेश नीति के अध्ययन के वक्त ध्यान केन्द्रित करना परमावश्यक है।

¹ Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations* (New York, 1954).

परम्परा व मूल्य (Tradition and Values)

शक्ति एवं विद्वान् के साथ जुड़ा हुआ यह परम्परा और मूल्यों का है। किसी भी राष्ट्र का जातीय मस्कार उसके भौगोलिक और ऐतिहासिक अनुभव से अनुकूलित होता है। परम्परा के आधार पर समाज में कुछ ऐसे मूल्य प्रतिष्ठापित होते हैं, जो राजनीतिक नीति निर्धारण की दिशा निश्चित करते हैं। कुछ उदाहरणों से यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जायेगी। फ्रांसीसी क्रान्ति के वर्षों से प्राप्त की महत्वाकांक्षा विश्वव्यापी विदेश नीति संचालन की रही। अपना सांस्कृतिक प्रभाव क्षेत्र फैलाने तथा राष्ट्रीय शौर्य को अक्षत रखने का लक्ष्य नेपोलियन से लेकर देगोल तक एक समान देखा जा सकता है। इसी तरह बोन्डेविल क्रान्ति की सफलता के साथ अन्तर्राष्ट्रीय क्रान्तिकारिता को प्रोत्साहन देना सोवियत राष्ट्र हित का अभिन्न हिस्सा बन गया था। बाद में स्टालिन काल में मने ही व्यावहारिक स्तर पर इस नीति में महत्वपूर्ण संशोधन आवश्यक हुए, तथापि मूल्य के रूप में इनकी स्थिति बरकरार रही। परन्तु अब सोवियत संघ विखर रहा है। राज्य के स्तर पर पुराने साम्यवादी मूल्य समाप्त हो गए हैं। इस बात को वहाँ की विदेश नीति में देखा जा सकता है। इसी तरह भारतीय विदेश नीति निर्धारण के परिप्रेक्ष्य में बुद्ध एवं अशोक की अहिंसा, मध्ययुगीन समन्वय, महा-अस्तित्व का परिवार नियार जवाहर लाल नेहरू के विश्व दर्शन में झलकता है। परन्तु हम के बित्तराव से भारतीय विदेश नीति के मूल्य भी बदले जा रहे हैं। इसी प्रकार राष्ट्र मण्डल के अनेक देशों के साथ आज भी ब्रिटेन के जो 'विरोध सम्बन्ध' (भने ही हाल के वर्षों में इनका तेज़ी से अवमूल्यन हुआ है) हैं, वे साम्राज्य के रूप में ही तर्कसंगत सिद्ध होत हैं। जापान आज भने ही सामन्ती सैनिक साम्राज्य न रह गया हो, परन्तु आर्थिक महा-शक्ति के रूप में उसके आचरण में पारम्परिक मूल्य तथा सैली स्पष्ट दिखायी देते हैं। इसी तरह अनेक विद्वानों ने माओवादी चीन का साम्य प्राचीन चीनी साम्राज्य में ढूँढ़ा। जाहिर है कि विदेश नीति के अध्ययन के समय शक्ति सन्तुलन व विचारधारा के साथ-साथ परम्परा तथा प्रतिष्ठापित मूल्यों पर दृष्टिपात करना जरूरी है। नीति निर्धारकों का विश्व दर्शन इन्हीं पर आधारित होता है। इसी के अनुसार वे अपने राष्ट्र की विदेश नीति के लक्ष्य तथा उद्देश्य तय करते हैं।

आन्तरिक घटक तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य (Domestic Determinants and International Context)

उपरोक्त अमूर्तता (abstractions) के अतिरिक्त विदेश नीति निर्धारण के क्षेत्र में ऐसी अनेक आन्तरिक घटक होते हैं, जो उसके स्वरूप को निर्धारित करते हैं। इनका परीक्षण वस्तुनिष्ठ ढंग से सम्भव है और इन्हें किसी भी देश की विदेश-नीति का मूल्य-निर्धारक कहा जा सकता है। ये आन्तरिक घटक हैं - (i) भौगोलिक स्थिति एवं भू-राजनीतिक महत्व, (ii) जनसंख्या, (iii) आर्थिक क्षमता तथा प्राकृतिक सम्पदा, (iv) नेतृत्व शैली तथा (v) राजनीतिक विकास का स्तर। यहाँ इन सभी का अपेक्षाकृत विस्तार से विश्लेषण उपयोगी होगा।

1 भौगोलिक स्थिति एवं भू-राजनीतिक महत्व (Geographical Situation and Geo-Political Importance)—किसी भी देश की विदेश नीति पर उसकी

भौगोलिक स्थिति, आकार तथा स्वरूप का निर्णायक प्रमाण पड़ता है। जिस देश की भौगोलिक सीमाएँ दो महासागरों को छूती हैं या जिनके भू-भाग का विस्तार दो महाद्वीपों में विस्तृत हुआ है, विपुल आकार उस देश को न केवल बाहरी हमलों से निरापद बनाता है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के मामले में उसे इतना आत्म-निर्भर बना देता है कि एक खात तरह का आत्म-विश्वास और स्वाधीनता उसके आचरण में झलकते हैं। इतने बड़े आकार, जनसंख्या, भाषायी व सांस्कृतिक विविधता के कारण इनका राजनीतिक और सामाजिक संगठन बहुतन्त्री होता है। स्पष्ट है कि पड़ोस के छोटे देशों के साथ उमरे सम्बन्ध बराबरी के नहीं हो सकते। अवसर ऐसे देशों की विदेश नीति के स्वरूप प्रभुतावादी एवं विस्तारवादी रहते हैं। अंग्रेजों द्वारा दिये गये उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जायेगी कि कैसे भौगोलिक परिस्थितियाँ देश का भू-राजनीतिक महत्व तय करती हैं और कालक्रम में यह ऐतिहासिक अनुभव का साक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण हितों बन जाती हैं। सामूहिक जातीय चेतना, समृद्धि और दृढ़ता बड़ी सीमा तक इस यथार्थ पर टिके रहते हैं।

अटलांटिक और प्रशांत महासागर परकोटे की खाड़ी की तरह अमरीकी 'हृदयस्थल' (Heartland) की रक्षा करते हैं। 19वीं शताब्दी के पहले चरण से ही अमरीकी नेता इस बात का एतान करते रहे हैं कि मुनरो सिद्धांत के अनुसार अमरीकी महाद्वीपों में किसी बाहरी शक्ति का प्रवेश या हस्तक्षेप के महन नहीं कर सकते। इसी तरह नेपोलियन के मृत्यु से हिटलर के आक्रमणों तक सोवियत संघ बारम्बार यह प्रमाणित करता रहा है कि मात्र बल प्रयोग से उस पर काबू नहीं पाया जा सकता। देश की 'गहराई' (Depth) इतनी ज्यादा है कि आक्रमणकारी जीतने के पहले ही फट जाता है। अमरीका के कनाडा या दक्षिण अमरीका के अन्य देशों के साथ सम्बन्ध स्पष्ट करते हैं कि सामरिक, सीमांत और सांस्कृतिक प्रभाव क्षेत्र में तात्कालिकी के कारण महाशक्ति के राष्ट्रीय हित पड़ोसियों के भी राष्ट्रीय हित सामूहिक रूप से स्वयमेव बन जाते हैं।

इस तरह अनेक भूमिबद्ध राज्य (land-locked states) हैं—जैसे नेपाल, अफगानिस्तान, लाओस, आस्ट्रिया, बंगोलिया इत्यादि। शहर तक पहुँच न होने के कारण ये अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सक्रिय भाग लेने से वंचित रहे हैं और परोक्ष रूप से शान्त-विशान्त की अवस्थिति द्वारा से भी अछूने रहे हैं। इन देशों की मानसिकता में बस्तीवादी प्रादेशिक दृष्टि साफ देखी जा सकती है। ये देश अपने ऐसे पड़ोसियों पर निर्भर रहते हैं, जिनके माध्यम से वे सागर तक पहुँचते हैं।

परन्तु ऐसा मानना गलत होगा कि भौगोलिक स्थिति ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। बहुत बड़े विस्तार और बड़ी जनसंख्या के बावजूद अभी हाल तक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन ने यैसी भूमिका नहीं निभायी, जैसी अमरीका ने। चीन के अन्तर्राष्ट्रीय आचरण में अहंकारी-साम्राज्यवादी भाव ही देखने को मिलता रहा। बड़े भू-भाग की अस्पष्टता बनाये रखना और उस पर अपना आधिपत्य कायम रखने की चुनौती ही चीन की वैश्वीय सत्ता के लिए विनष्ट बनी रही। आकार और स्वरूप के साथ-साथ स्थिति के संयोग से ही राजनीतिक महत्व निर्धारित होता है। भौगोलिक व औपनिवेशिक विस्तार के युग में यूरोपीय मुख्य धारा से अलग-थलग होने के कारण चीन पिछड़ गया और साम्राजवादियों के सत्ता ग्रहण करने पर उसकी वैदेशिक मामलों में स्थिति बड़ी शक्ति वाली नहीं रही।

बड़े राज्यों के अतिरिक्त अनेक ऐसे छोटे व मध्यवर्ती (Buffer) राज्य होते हैं, जो दो प्रतिद्वन्द्वियों को टकराने से रोकने हैं और कुशल राजनय के द्वारा अपनी स्वायत्तता बचाने में सफल होते हैं। ममलन, बाइलैण्ड, नेपाल और स्विट्जरलैण्ड। 1979 तक अफगानिस्तान की स्थिति भी ऐसे ही बफर राज्य की रही। दक्षिण अमरीकी महाद्वीप में चिली का विचित्र आकार आन्तरिक राजनीति में इतने विरट दबाव डालता है कि एक तरफ से आन्तरिक नीति विदेश नीति का परिशिष्ट बन जाती है। राष्ट्रपति अयाद का पतन जिस घटनाक्रम के अनुसार हुआ, उसमें यही प्रमाणित होना है।

द्वीपों और द्वीप समूहों (Islands and Archipelagos) की भू-राजनीतिक स्थिति भूमिबद्ध राज्यों से बिल्कुल एक हानती है। इनको सागर अनेक देशों से जोड़कर विविध प्रकार के प्रयासों के लिए 'बोलना' है। सदियों से औपनिवेशिक शक्तियों की नौमैत्रिक शक्ति पर निर्भरता के कारण इनका विशेष सामरिक महत्व रहा है। हाल में परमाणु पनडुब्बियों पर आधारित अन्तर-महाद्वीपीय प्रसंचात्मक यानी रणनीति तथा इलेक्ट्रॉनिक संचार मध्यक प्रणालियों की प्राथमिकताओं ने तगव्य बिन्दु मात्र लगभग निजंन द्वीपों का महत्व कई गुना बढ़ा दिया है। डिएगो गार्मिया, बाना, ऊतु तथा मोलोमन द्वीप इसके उदाहरण हैं। अने ही ऐसे द्वीप अपनी स्वतन्त्र विदेश नीति का नियोजन-निर्वाह करने में अममर्थ हो परन्तु, मोहुरी के रूप में इनका प्रयोग करने की सम्भावना ने महाशक्तियों तक की विदेश नीतियों को खनरनाक ढंग से अन्विर किया है।

2. जनसंख्या (Population)—विदेश नीति के सन्दर्भ में जनसंख्या के मामले में अति सरलीकरण से बचने की जरूरत है। भारत और चीन यही जनसंख्या के कारण स्वमेव महाशक्ति नहीं बन सकते, क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या सीमित प्राकृतिक मसाधनों पर अमल्य बोझ डालती है। इसके विपरीत 19वीं और 20वीं शताब्दी व अधिराज्य वर्षों में जब विदेश साम्राज्यवादी शक्ति रहा, तब उसकी आरादी बहुत कम थी। जनता की संख्या उनकी महत्वपूर्ण नहीं, जितना कि उसमें व्याप्त शिक्षा और कौशल का स्तर। फिर भी यह कहा जा सकता है कि आज बहुत छोटी जनसंख्या वाला देश मिर्च बुद्धिबल या कृटिलता घूर्णना के आधार पर अपने से कई गुने बड़े राज्य पर कब्जा नहीं कर सकता। आदर्श स्थिति अमरीका और पुर्गले मोवियन मध की थी, जहाँ जनसंख्या, भू-भाग और उपलब्ध प्राकृतिक मसाधनों का एक समुचित समुतुन देवन को मिलता रहा। जनसंख्या के बारे में एक और बात उन्नत्यनीय है। यदि आवादी समग्र (homogenous) हों तो जनसंख्या वैदेशिक मामलों में अधिक सार्थक भूमिका निभा सकती है। यदि आवादी के कुछ घटक अल्पसंख्यक अमनुष्ट साम्प्रदायिक भेदभाव में घल्ल होते हैं तो इनका प्रभाव विघटनकारी ही हो सकता है। ऐसी स्थिति में विदेशी हस्तक्षेप और तोड़-फोड़ व मरुट के कारण विदेशी नीति महज ही अमनुनित हो जाती है। भारत के उत्तर पूर्वी सीमाना पर नागा व मिजो मसम्पार, उत्तर पश्चिम में ताजिस्तानी आतंकवाद की धुनी और श्रीलंका में तमिल उग्रपणियों की समस्या इस तथ्य को दर्शानी है। पश्चिम एशिया के देशों में विदेश नीति का प्रमुग तन्व जानीय व साम्प्रदायिक ही है।

3. आर्थिक क्षमता व प्राकृतिक संसाधन (Economic Potential and Natural Resources)

Natural Resources)—राष्ट्रीय हित की परिभाषा और उसका विस्तार देश की आर्थिक क्षमता तथा उसके प्राकृतिक ससाधनों के आकलन के बिना नहीं किया जा सकता। कोई भी देश विनती बड़ी सेना का भार वहन कर सकता है और उसकी जनता का जीवन-यापन स्तर किम् तरह का हो सकता है, यह उसकी आर्थिक क्षमता पर निर्भर करता है। अमरीका गुप्त से महाशक्ति समझा जाता रहा है, जिसका एक प्रमुख कारण यह है कि वह आर्थिक दृष्टि से न केवल आत्मनिर्भर रहा है बल्कि अपने आश्रितों व निधिरानुचरों की ज़रूरतें पूरी करने की सामर्थ्य भी रखता रहा है। यहाँ तक कि एक गमय महाशक्ति समझा जाने वाला इसके विपरीत दूसरे छोर पर जापान जैसे देश है, जिसकी आर्थिक क्षमता और समृद्धि लगभग हर तरह के अच्छे मांस और ऊर्जा ससाधनों के आवाज पर पूरी तरह निर्भर है। कुछ ऐसी ही विश्वव्यापी स्थिति पश्चिम एशिया के अरब राष्ट्रों की है जो तेल निर्यातकों होने के कारण दूसरों के आर्थिक विकास को तो संकट में डाल सकते हैं, पर स्वयं अपनी ज़रूरतों की लाज सामग्री, आवश्यक उपकरण आदि के लिए परावलम्बी हैं। औपनिवेशिक काल में इस परम्परा का सूत्रपात हुआ कि औद्योगिक दृष्टि से प्रगतिशील शक्ति ने बलपूर्वक अपनी ज़रूरत के अनुसार दूसरों के प्राकृतिक ससाधनों और धन शक्ति का लोपण ज़रूरतें पूरा दिया। आज भले ही उपनिवेशवाद का अन्त हो चुका है, किन्तु परोपजीवी आर्थिक विकास तथा विषमतापूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, तब उपनिवेशवाद के आधार है। लगभग हर देश की विदेश-नीति आर्थिक सहायता-राजनय को महत्वपूर्ण उपकरण समझती है। आर्थिक पक्ष राष्ट्रों के उत्तमवर्गीय सम्बन्धों में ही नहीं, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय सस्याओं और बहुराष्ट्रीय समागमों में भी बेहद महत्वपूर्ण समझा जाता है।

पारम्परिक रूप से घले ही राष्ट्र हित को सामरिक हितों का पर्याय समझा जाता रहा हो, किन्तु आधुनिक दौर में विशेषकर दूसरे महायुद्ध के बाद सामरिक साधन, आर्थिक हितों की रक्षा के लिए ही एकत्र किये जाते हैं। हेरी मेकडोफ की प्रसिद्ध पुस्तक 'दि एज ऑफ़ इम्पीरियलिज्म' (The Age of Imperialism) में अमरीकी विदेश-नीति के आर्थिक आधार पर स्पष्ट विश्लेषण किया गया है। थिऑडोर जेम्स की जैसे विद्वानों ने 'समर्थों की विरादरी' (Gathering of the Affluent) व 'क्लब ऑफ़ रोम' (Club of Rome) के माध्यम से यह प्रस्तावित किया कि विपन्न देशों की हानत में गुधार का ठेका पहली खुशहाल दुनिया के शक्तिशाली ने रखा है। उसके अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय राष्ट्रों की भूमिका उनकी आर्थिक हैसियत के साथ ही जोड़ी जानी चाहिए। अमरीका ने हाल के वर्षों में 'ग्लोबल' के बारे में जो रुख अपनाया, उसमें भी यही बात झलकती है।

आजादी के ठीक बाद के वर्षों में अपने विघात आकार और बड़ी जनसंख्या में बावजूद भारत को अक्षम और निरक्षर का सामना करना पड़ा क्योंकि गांधीजी के आवाज के लिए वह अमरीका पर निर्भर था। 1951-52 का गैर-भूषण तथा 1960 के दशक का पी० एन०-480 कार्यक्रम इसी के उदाहरण हैं। आज भले ही भारत गांधीजी के सामने में आत्म-निर्भर बन चुका है, किन्तु जटिल टैक्नोलॉजी के हस्तान्तरण—स्वदेशीकरण को चुनौती अन्तर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत को बाधक के रूप में पेश करती है। निम्नलिखित ही राजनयिक परामर्श में इससे हमारा पक्ष दुर्बल होता है।

कुछ विद्वानों का मानना है कि वैज्ञानिक आविष्कारों तथा टेक्नोलॉजी के परिष्कार के कारण प्राकृतिक ससाधनों का अक्षयमूल्यन हुआ है। परन्तु यह बात अलग ही ठीक है। तब यह है कि खड और टीन के अनुकूल्य (Substitute) ढूँढ लिये गये हैं और इनके परिणामस्वरूप मतभेदित्वा की आनदनी पर अतर पड़ा है। यह भी कहा जा सकता है कि मतभेदित्वा का सामरिक महत्व घटा है। फिर भी इन निष्कर्ष तक पहुँचने की अलदबादी नहीं की जानी चाहिए कि मनी प्राकृतिक उत्पाद एक ही बटखरे से तोले जा सकते हैं। निरख ही खोरण, बाय, कौरी आदि के अन्तराष्ट्रीय बाजार भाव उत्पादकों के लिए चिन्ता का विषय हो नकने हैं, परन्तु बड़ी शक्तिशाली के गणि में इनकी तुलना तेल से नहीं की जा सकती। इस तरह कुछ ऐसे समाधान हैं, जिनके उपलब्ध बाजार बहुत सीमित हैं—जैसे कोमिजन, मोनोडिडिनम तथा यूरेनियम, जिनके स्थानी देज अन्तराष्ट्रीय राजनीति में मनभावा आधारन कर सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका की पादविक नीतियों का परिचनो शक्तिशाली द्वारा अनदेखा किया जाना इसी आधार पर समझा जा सकता है।

इसी प्रकार आर्थिक समता जहाँ एक ओर उपलब्ध प्राकृतिक समाधानों पर टिकी रहती है और जिनो भी राज्य को 'महत्वपूर्ण' बनानी है, वही दूसरी ओर अन्तराष्ट्रीय राजनीति के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण ढूँढे जा सकते हैं, जो यह प्रमाणित करने हैं कि प्राकृतिक समाधानों की कमी दूर करने के लिए बटिबद्ध राज्य विस्तारवादी और नव-उपनिवेशवादी नीति अकनाने हैं। इनके अलावा प्राकृतिक समाधानों का समुचित दोहन बिना समोचित तकनीक के नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिक व तकनीकी शिक्षण के लिए समुद्रि का समुनयन स्वर अनिवार्य है। उपलब्ध प्राकृतिक समाधान और बाह्य तकनीकी योग्यता का समोकरण बँडाने के लिए विदेश नीति और राजनय में निरन्तर उल्लेख रहना पडता है। इस क्षेत्र में नाम-नामन का अनुमान लगाने और उपलब्ध विकल्पों में सबसे सार्थक बिलत्व को चुनने की चुनौती विदेश नीति के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में एक है। आर्थिक समता, नीमोलिक स्थिति एवं जनसंख्या के माध-माध यह नेतृत्व योग्य और राजनीतिक विकास के स्तर से भी जुड़ी हुई है।

4. नेतृत्व योग्यता (Quality of Leadership)—विदेश नीति निर्माण और सम्यादन के क्षेत्र में सबसे स्पष्ट दृष्टिकोण होने वाला तत्व नेतृत्व योग्यता है। इस गुण को बहुत सरलता से किसी एक व्यक्ति में समुनिमान देता जा सकता है। इसीलिए इनका विरूपण करता आमान माना जाता है। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, विदेशमन्त्री, जिनो विशेष राजदूत का मलाइकार के माध्यम से विदेश नीति के लक्ष्य पहचाने जा सकते हैं। उन व्यक्ति विशेष के बियाबलाय राजनयिक योग्यता की बनीटी पर बस जा सकते हैं। इसके लिए बहुत लम्बी-बोडी व्याख्या की आवश्यकता नहीं। कुछ चुनिन्दा उदाहरणों में ही यह बात स्पष्ट हो जायेगी।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपने योग्य हुए राष्ट्रीय गौरव की पुनर्सार्जना के लिए पश्चिम के प्रमुख शक्तियों दलों के बिना अवलम्बनीय हो रहने। इसी तरह शीत युद्धकालीन अमरीकी विदेश नीति की रूपरेखा की तराजना डलेन के बिना सम्भव नहीं था। बीमवी पार्टी बाडेन के बाद मोविदन विदेश नीति की दिशा में मोड़ने का काम स्टुडेचे ने माधा जो काफी चुनौतीपूर्ण था। चीन में साम्यवादी सरकार के गठन व बाद माओ और बाऊ-न-याई की ज़ुगवबन्दी के बिना अन्तराष्ट्रीय मंच

पर जनवादी चीन की प्रतिष्ठा असम्भव ही थी। ऐसा नहीं कि सारे उदाहरण सफलतावादी ही रहे हैं।

नेतृत्व कौशल का अभाव सुविचारित विदेश नीति को भी असफलता के कगार तक पहुँचा देता है। न्यूवार्ड प्रक्षेपास्त्र संकट के दौरान खुद्देव का आचरण, कॅनेडी और जोनसन के काल में वियतनामी दलदल में अमरीका का घँसना और स्वेज मण्ड में एयनी ईडन का आत्मघात दूसरी तरह के उदाहरण पेश करते हैं। हेनरी किंसाजर का क्रियाकलाप तथा पहले भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरू जी का अनुभव कुल मिलाकर सफलता और असफलता का एक सन्तुलित लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हैं।

5. राजनीतिक विकास का स्तर (Level of Political Development)---

राजनीतिक विकास के स्तर को व्यक्तिगत नेतृत्व कौशल से अलग नहीं देखा जा सकता। जिस देश में राजनीतिक विकास का स्तर जितना जँचा होगा, उसे व्यक्तिगत प्रतिभा पर निर्भर रहने की उतनी ही कम जरूरत होती है। ऐसी स्थिति में सरकारें अधिक उत्तरदायी होती हैं और नेताओं का स्वरूप चमत्कारी-करिश्माती फाम, प्रबन्धक वाला अधिक होता है। भले ही यथार्थ में आदर्श स्थिति कभी भी देखने को नहीं मिलती, तब भी यह कहा जा सकता है कि पश्चिमी जनतन्त्र वाले शुने समाजों में वैदेशिक मामलों में विकल्पो से सम्बन्धित घुली बहस, गलत निष्कर्षों आलोचना आदि विदेश नीति निर्धारकों पर भ्रम का काम करते हैं और सम्बन्धित महत्वपूर्ण व्यक्तियों को भुगत नेतृत्व प्रदर्शन के लिए तत्पर-सतर्क रखते हैं। मध्य अमरीका में रीगन के हस्तक्षेप की आलोचना और ईरान बैठ का रहस्योद्घाटन इसी परम्परा में रसे जाने चाहिए।

विश्व दर्शन : लक्ष्य तथा उद्देश्य

(World View : Aims and Objectives)

जैनाकि पहले कहा गया है कि किसी भी देश के विदेश नीति निर्धारकों का विश्व दर्शन देश-विदेश की भू-राजनीतिक स्थिति तथा उसके ऐतिहासिक अनुभव से अनुसृत होता है। यह एक तरह का मस्कार भर है। यह विदेश नीति की आधार शिला अवश्य है, परन्तु इसे विदेश नीति का पर्याय नहीं समझा जा सकता। विश्व दर्शन राष्ट्रीय अभिलाषाओं को अस्पष्ट रूप से गुंथर करता है। यह मोटे तौर पर राजनयिक कर्म की दिशा तय करता है। परन्तु इतने भर से राष्ट्रीय हित सर्वार्थ-संरक्षण का नाम पूरा नहीं हो सकता। मकल विदेश नीति नियोजन के लिए यह जरूरी है कि इन मूलतः अमूर्त परिप्रेक्ष्य को उपलब्ध गणाधनों के साथ जोड़कर भविष्य की गतिविधियों का कार्यक्रम तय किया जाये। प्रसिद्ध विदेश नीति विश्लेषक जेम्स रीगनो के अनुसार विदेश नीति के सम्बन्ध में उद्देश्य तथा लक्ष्य दोनों महत्वपूर्ण हैं और मार्गेक अन्तर-दृष्टि प्राप्त करने के लिए इन दोनों के अन्तर-सम्बन्ध और फर्क को समझना परावश्यक है। अंग्रेजी शब्द 'Objectives' (उद्देश्य) व 'Goals' (लक्ष्य) से यह बात स्पष्ट होती है।¹ मोटे तौर पर उद्देश्य दीर्घकालिक होते हैं तथा लक्ष्य अपेक्षाकृत निकट भविष्य के मन्दर्मे में परिभाषित किये जाते हैं।

¹ James N. Rosenau, *International Politics and Foreign Policy : A Reader in Research and Theory* (New York, 1961).

फिर भी यह समझना गलत होगा कि इनमें कोई द्वन्द्व या अन्तर-विरोध है। सतही दृष्टिपात से भले ही ऐसा प्रतीत हो, वस्तुतः ये एक-दूसरे के पूरक ही हैं। इस सिलसिले में दो महत्वपूर्ण बातें याद रखने की हैं। एक तो यह कि विदेश नीति के लक्ष्य एवं उद्देश्य किसी देश की आन्तरिक नीति का विरोध वाले नहीं हो सकते। दूसरे, यह अनिवार्य नहीं कि किसी देश की विदेश नीति के लक्ष्य एवं उद्देश्य शाश्वत और अपरिवर्तनीय ही होने हों। समसामयिक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में ब्रिटिश राजनयिक फामरस्टन की यह उक्ति निश्चय ही भ्रान्तिपूर्ण है कि 'किसी देश के मित्र या शत्रु नहीं, बरन् उनके राष्ट्रीय हित शाश्वत होते हैं।' विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में लगभग सभी प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियों की विदेश-नीतियों के अध्ययन से यह लक्ष्य उद्घाटित होता है कि अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में ऐतिहासिक परिवर्तनों के साथ या आन्तरिक उचल-खुचल के साथ-साथ सामाजिक या आर्थिक राष्ट्रीय हित भी पुनर्परिमाणित होने रहते हैं।

विदेश नीति का सैद्धान्तिक अध्ययन या सार्वक विश्लेषण करते वक्त उपर्युक्त सभी बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है।

अमरीका की विदेश नीति

यदि विश्व भर के सभी देशों की विदेश नीतियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण का चुनाव करने को कहा जाये तो अमरीकी विदेश नीति ही चुनी जायेगी। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध से ही विद्वानों ने यह बात स्वीकार कर ली कि इस 'नई दुनिया' (अमरीका) का अपना विशेष महत्व है, जो पुरानी दुनिया (यूरोप) के शक्ति-सन्तुलन को निर्णायक ढंग से प्रभावित कर सक्ता है। अपार प्राकृतिक सम्पदा से समृद्ध अमरीकी भू-भाग दो महासागरों द्वारा सुरक्षित है। प्रवासी निवासियों के उद्यम और टेक्नोलॉजी के परिष्कार के संयोग से अमरीका का आविर्भाव द्वितीय महायुद्ध के बाद पहली महाशक्ति के रूप में हुआ। मले ही बाद में सोवियत संघ ने भी महाशक्ति का दर्जा प्राप्त कर लिया, परन्तु पहली महाशक्ति का दर्जा आज भी अमरीका को दिया जाता है। एक ओर सोवियत संघ के साथ अन्तर-क्रिया के परिणामस्वरूप अमरीकी विदेश नीति ने शीत युद्ध को प्रभावित किया तो दूसरी ओर चीन के साथ बैर या मैत्री, इनमें से किसी एक विकल्प के चुनाव के माध्यम से अमरीका ने पिछले दशकों में न जाने कितने और देशों की विदेश नीतियाँ निर्धारित की।

अमरीकी विदेश नीति : कुछ बुनियादी बातें
(U. S. Foreign Policy : Some Basic Factors)

अमरीकी विदेश नीति के महत्व एवं इसकी विशेषताओं समझने के लिए कुछ बुनियादी बातों को याद रखना उपयोगी होगा। आरम्भ से ही अमरीकी विदेश नीति का एक प्रमुख स्वर दूसरों को भेदत्व देने वाला रहा है। अमरीकी क्रांति के समय इसकी प्रेरणा उपनिवेशवाद-विरोधी थी तो अब्राहम लिंकन के शासन काल में दामता के उन्मूलन अभियान ने इसे आदर्शवाद का जामा पहनाया। चूँकि अमरीका के स्वाधीनता संघाम ने फ्रांसीसी क्रांति के नायकों की प्रेरणा दी थी और उसके भविष्य के आमुष में बुनियादी मानवाधिकारों की घोषणा की गयी थी, इसलिए अमरीकी राजनयिकों को हमेशा यह लगता रहा कि वे दूसरों को मार्ग दिखा सकते हैं। इस धारणा को विस्तृत निर्मूल भी नहीं कहा जा सकता। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में जब यूरोप के अधिकांश देश एशिया और अफ्रीका की लूट-खसोट में लगे थे और साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का दौर तेज था, तब अमरीका जनतात्मिक परम्पराओं का निर्वाह कर रहा था। अमरीका ने कभी किसी अन्य देश को गुलामी की बेड़ियों में जकड़कर उपनिवेश नहीं बनाया, जबकि ब्रिटेन, फ्रान्स आदि ऐसा करते रहे थे।

यहाँ इन सब बातों की विस्तृत चर्चा इसलिए जरूरी है कि यह बात उजागर की जा सके कि अमरीकी विदेश नीति में विचारधारा और सैद्धान्तिक पक्ष कितने

महत्वपूर्ण हैं। अमरीका के मस्थापको, जो मूलतः प्रोटेस्टेंट ईसाई थे, रोमन कैथोलिक-उन्नीडन के शिकार रहे थे। नये मुल्क में नई जड़ें जमाने के बाद उनके आचरण और चिन्तन में एक खास तरह की बट्टरपची छिद्रान्वेषी (Puritan) प्रवृत्ति झलकती रही है।

अमरीकी राजनेता मिफं मोह या अह्मदख्त ही दुनिया भर में जनतन्त्र की अगुवाई का ठेका नहीं लेते। यह सम्भव है कि वास्तव में उन्हें लगता हो कि यह उन्हीं का उत्तरदायित्व है। गणराज्य की स्थापना करने वाले अमरीकी पहले लोग थे। उनका यह सोचना तर्कसंगत है कि अमरीका ने जनतन्त्र के आधुनिक संस्करण का उत्पादन व निर्यात किया। अमरीकी औपनिवेशिक दासता का जुआ उतार फेंकने वाले ये पहले लोग थे। कुछ ऐसी ही बात अमरीकी जीवन-यापन शैली पर भी लागू होती है। सीमान्नी कृपका, 'पायनियर्स' व 'काऊ बोएज' का संस्कार हो या बाद में 'लाइन असेम्बली' वाली फैक्ट्री का दौड़ावार विकास, अमरीका में ही देहात और नगरी में जड़ता की तोड़ने वाले जनतान्त्रिक आधुनिकीकरण का सूत्रपात हुआ। अमरीका स्वयं अपने अनुभव से यह सीख चुका है कि पूँजी, विचार और तकनीक के अबाध व्यापार से किन तरह सामान्यजन हुआ जा सकता है। यदि वह दूसरी को भी अपना आजमाया मुस्ला सुझाये तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है?

इन वैचारिक व सैद्धान्तिक अवधारणों का एक सीमरा पक्ष भी है। अमरीका आज सत्तार का सबसे खुशहाल दश है। इस खुशहाली की नींव प्राकृतिक मसाधनों के निरन्तर और वृक्षों दोहन पर टिकी हुई है। अमरीका में आज औद्योगिकोत्तर समाज (Post-Industrial Society) प्रतिबिम्बित होना है, जिसका अनुकरण करने के लिए विकसमशील ही नहीं, बल्कि अन्य पश्चिमी समृद्ध देश भी साक्षात् रूढ़े हैं। इस जीवन-यापन शैली को बनाने व बचाये रखने के लिए सभी अमरीकी सरकारें (चाहे वे रिपब्लिकन हों या डेमोक्रेटिक) वृत्त सकल्प रहती हैं और रहेगी। इस अहसास की पुष्ता जमीन पर मुक्त व्यापार की तमाम दूसरी दलीलें टिकी हैं। आर्थिक सहायता हो या मासुहिक आदान-प्रदान, अमरीकी विदेश नीति का पहला उद्देश्य यह रहता है कि वह दूसरे देशों को अपनी छवि में डार सके। इस प्रयत्न के अमफल होने पर वह 'अन्तर्राष्ट्रीय पुलिसमैन' (International Police-man) का वेग धारण कर लेता है ताकि राष्ट्र हित की 'बुद्धि' से नहीं तो 'बल' द्वारा सुरक्षित रखा जाये।

इस व्यापक परिवेष्ट में व्यक्ति तथा संस्थाएँ प्रकट एवं परोक्ष रूप से अपनी भूमिकाएँ निभाते हैं। अमरीकी प्रणाली में इस पूरे ताम-झाम को 'नियन्त्रण एवं सन्तुलन' (Checks and Balances) कहा गया है। अभीष्ट तथा प्रस्तावित कुछ भी रहा हो, द्वितीय विद्व युद्ध के बाद के दशकों का अनुभव यही दर्शाता है कि यह वर्णन पूर्ण रूप में यथार्थपरक नहीं है। अमूर्त औद्योगिक-मैनिफ तन्त्र हो या अमरीकी गुप्तचर मस्था मी० आई० ए०, अमरीकी विदेश नीति नियोजन एवं निष्पादन में इसकी गैर साध्यानिध भूमिका (मविधानेतर) अकसर सबैधानिक प्रावधानों से अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होती रही है। साथ ही यह बात कम महत्वपूर्ण नहीं कि राष्ट्रपति या उसके महत्वपूर्ण सलाहकार के व्यक्तिगत ज्ञान के कारण अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के प्रति अमरीकी दम-रवैया हस्तक्षेपकारी रहता है या एकान्त प्रेमी? इन सभी टिप्पणियों को ठीक से समझने के लिए प्रमुख अमरीकी राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में अमरीकी

विदेश नीति की बुनिन्दा घटनाओं का विस्तृततात्मक सर्वेक्षण आवश्यक है।¹

विदेश नीति-निर्धारण का तन्त्र

(Mechanism of US Foreign Policy-Making)

अमरीकी विदेश नीति नियोजन, निर्धारण और इसके क्रियान्वयन के तन्त्र में राष्ट्रपति, विदेश सचिव, राष्ट्रपति के सुरक्षा सलाहकार व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके अतिरिक्त अमरीकी विदेश मन्त्रालय (State Department) और रक्षा मन्त्रालय (Pentagon) की नौकरशाही तथा सीनेट के सदस्य (विनोदकर इसकी विदेश नीति विषयक उपसमितियाँ) काफी प्रभावशाली सिद्ध होते रहे हैं। अमरीकी विदेश नीति का नियोजन व सम्पादन सिर्फ कार्यपालिका और विधायिका तक ही सीमित नहीं रहता। सातकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में अमरीकी जनमत ने विदेश नीति की विधा को कई बार निर्णायक मोड़ दिया है। अमरीकी राजनीति में 'लॉबीइंग' (Lobbying) की पुरानी परम्परा है। अर्थात् कोई भी व्यक्ति या समूह, जो किसी एक पक्ष का समर्थन करता हो, वह मन्त्रालयों के नौकरशाह विरोधों से लेकर राष्ट्रपति तक का निर्णय अपने अनुकूल बनवाने का प्रयत्न करता है। इसे कोई भी गलत या अनैतिक नहीं समझता। अमरीका के यूद्धी नागरिकों का इजराईल के पक्ष में आचरण इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इस प्रक्रिया के कारण अमरीकी विदेश नीति के सन्दर्भ में प्रेस व दूरदर्शन की भूमिका दुनिया के किसी भी और देश की अपेक्षा महत्वपूर्ण बन जाती है। आज जिन ही तीसरी दुनिया के अनेक विकासशील देशों में व्यापक जन सन्नर्क के अमरीकी साधन सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के उपकरण समझे जाते हैं, परन्तु स्वयं अमरीका निजो सन्दर्भ में इन्हें सार्वक व स्वतन्त्र अभिव्यक्ति का साधन बताया जाता रहा है। ममलन, वियतनाम युद्ध के दौरान टेलीविजन पर अमरीकी सैनिकों की कुर्बानियों के हृदय विदारक चित्रण ने ही अमरीकी विश्वविद्यालय के परिसरों में युद्ध विरोधी जनार्थन का सावा फैलाया। भूतपूर्व राष्ट्रपति रीगन के अन्तरिक्ष युद्ध कार्यक्रम (Star Wars) के विरुद्ध जनमत बना तो इसका श्रेय एक सीमा तक 'दि डे अपार्टर' जैसी फिल्मों को दिया जा सकता है।

इन सभी घटकों में अमरीकी राष्ट्रपति की केन्द्रीय भूमिका है। अनेक विद्वानों का मानना है कि अमरीकी राष्ट्रपति अन्तर्राष्ट्रीय नीति निर्धारकों की बिरादरी में सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति है। वह अमरीकी मतदाताओं द्वारा सीधे निर्वाचित होता है। वह एक बार पद ग्रहण कर लेने के बाद आसानी से विन्यास नहीं जा सकता। जिन ही नियन्त्रण व सन्तुलन (Checks and Balances) की व्यवस्था उन पर अनुसूचनाने का प्रयत्न करती है, परन्तु व्यवहार में उसे निरन्तर शासक ही कहा जा सकता है। जिन तरह सोवियत नेता को कम्युनिस्ट

¹ अमरीकी विदेश नीति में सम्बद्ध अवधारणाएँ मधी महारसियों-विद्वानों ने 'अमरीकी तपने' का 'अमरीकी अनुभव' को विदेश नीति निर्धारण और क्रियान्वयन के लिए निर्णायक महत्व का समया है। अमरीकी विदेश नीति की अन्धी तरह से मयमने के लिए निम्नांकित लेखकों की पुस्तकें बादी उपयोगी हैं—George F. Kennan, *American Diplomacy, 1900-1950*. (Chicago, 1951), *Memoirs, 1925-1950*, (London, 1968), and *Memoirs, 1950-1963*, (London, 1963); Henry Kissinger, *The White House Years*, (Boston, 1979) and *Years of Upheaval*, (Boston, 1982).

पार्टी और सेना के प्रभावशाली तबकों के स्वार्थों का निरन्तर सन्तुलन करना पड़ता है, वंसी कोई विवशता अमरीकी राष्ट्रपति की नहीं होती। पिछले 50 वर्ष के तीन-चार पुनिदा उदाहरणों से यह बात बिल्कुल साफ हो जायेगी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने अपने प्रसिद्ध चौदह सिद्धान्तों की घोषणा की। इस भूमिका के बाद उन्होंने नई अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना के प्रयत्न किये। मने ही अमरीकी मीनेट ने राष्ट्र सघ (League of Nations) विषयक उनके किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया परन्तु विल्सन के मसीहाई तेवर आज तक अमरीकी विदेश नीति में झलकते रहे हैं। इसी तरह एक बार आन्तरिक राजनीति में अपने 'ग्लो डील' कार्यक्रम द्वारा स्थिरता और खुशहाली लौटा देने के बाद फ्रेंकलिन डिलानो रूजवेल्ट ने अपने राजनय के लिए किसी मलाहवार की जरूरत नहीं समझी। मने ही यह कहा जा सकता है कि रूजवेल्ट एक अम्बाभाविक परिस्थिति में बार-बार अमरीका के राष्ट्रपति बने। उनके कार्यकाल के दो निर्वाचन सत्र महायुद्ध युगों से और यह स्वामाविक था कि स्टालिन और चर्चिल जैसों के साथ समतापूर्ण व्यवहार के लिए बेहिचक दृढ़ व्यक्तित्व की ही आवश्यकता थी, आदि। पर्ल हार्बर से लेकर हिरोशिमा तक और तेहरान, बाल्टा, पोद्मडेम आदि में रूजवेल्ट की गतिविधियों ने निश्चय ही मीनेट व विदेश मन्त्रालय का अवमूल्यन किया और विदेश नीति के क्षेत्र में राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र को अनाधाम ही अमरदार ढंग से फैलाया।

रूजवेल्ट के उत्तराधिकारी ट्रूमैन और आइजनहावर उनकी तुलना में अल्पमूर्खी व्यक्ति थे। युद्ध के बाद के वर्षों में ये दो नेता अपेक्षाकृत निष्क्रिय नीति के पक्षधर थे। ये दोनों नेता यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए 'महकरी अन्तर्राष्ट्रीय भूमिका' मुझा रहे थे, परन्तु, तीन युद्ध के आधिर्भाव ने ऐसा नहीं होने दिया। अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में विशेष हथि न रखने पर भी इन दोनों राष्ट्रपतियों ने साम्यवादी सोवियत सघ के विरोध-प्रतिरोध की रणनीति तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। ट्रूमैन सिद्धान्त और आइजनहावर सिद्धान्त त्रमस प्रभाव रोकना (Containment) और पीछे ठकेलना (Roll Back) की अवधारणाओं से जुड़े थे। वे एक तरह से दक्षिण अमरीकी मन्दर्म में परिभाषित किये गये मुनरा सिद्धान्त के परिभाषित अन्तर्राष्ट्रीय संस्करण थे। 1970 के दशक के मध्य में गुआम द्वीप में निवसन द्वारा अपने सिद्धान्त (Nixon Doctrine) का प्रतिपादन करने तक अमरीकी विदेश नीति में बुनियादी परिवर्तन करने वाली 'राष्ट्रपति की पहलों' की परम्परा साफ परिवर्धित होती है।

जॉन एफ० कॅनेडी का कार्यकाल इस मन्दर्म में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एक ओर 'बे आफ पिंग' (Bay of Pigs) प्रकरण के अपरिपक्व नीतिमिथे अमरीकी राष्ट्रपति कॅनेडी की कमजोरी उजागर होती है तो दूसरी ओर बर्तन दीवार पर दिया गया उनका भाषण और ब्यूबाई प्रशेपास्त्र मकट के अवसर पर उनकी दृढ़ सक्क्य शक्ति राष्ट्रपति व विरोधाधिकारों और विनिष्ट भूमिका के साथ भी उद्घाटित करती है। कॅनेडी और उनके उत्तराधिकारी जानसन का कार्यकाल वियतनाम और हिन्द चीन की घामदी के साथ अमिष्ट रूप में जुड़ा रहा। वियतनाम युद्ध सम्बन्धी अमरीकी विदेश नीति निर्धारण का विस्तृत विवरण डेविड हेबरस्टाम ने अपनी पुस्तक 'दि वेस्ट एण्ड बाइटेस्ट' में बखूबी किया है।¹ इस घामदी का मार मधेप

¹ David Halberstam *The Best and the Brightest*, New York, 1972.

अन्यत्र विदेशी सलाहकारों के मन्दर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है, तथापि इस सिलमिले में एक महत्वपूर्ण तथ्य रेखांकित करने की जरूरत है। सलाहकार चाहे कितने ही महत्वपूर्ण और अधिक खर्चा में क्यों न हों, सुझाये गये विकल्पों में से किसी एक को चुनने का अधिकार सिर्फ अमरीकी राष्ट्रपति का ही है। इसलिए अनेक अमरीकी राष्ट्रपति अपनी भेज पर यह तल्ली लगाये रखते हैं कि 'दी बक स्टॉप्स हिथर' अर्थात् अब यह काम किसी और पर टाला नहीं जा सकता।

निक्सन, कार्टर और रीगन के कार्यकाल से भी यही बात पुष्ट होती है। चीन के साथ सम्बन्धों का सामान्यीकरण हो या ईरान द्वारा बन्धक बनाये गये राजनयिकों को छल-बल से छुड़ाने की योजना, अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति समीकरणों को पुनर्व्यवस्थित करने वाली फार्वार्ड की जिम्मेदारी अमरीकी राष्ट्रपति की ही है। निकारागुआ में कोन्त्रा छापामारों को सहायता व समर्थन देना हो या परमाणु निश्चितीकरण को ध्वस्त कर देने वाली स्टार वासं परियोजना, तत्कालीन राष्ट्रपति रीगन स्वयं इस नीति के विधाना कहे जा सकते हैं। वियतनाम और निकारागुआ दोनों प्रसंगों में यह बात अच्छी तरह उभरती है कि भले ही सीनेट, समान्तर-पत्र आदि राष्ट्रपति को अनुशासित करते रहते हैं, फिर भी सबूत राष्ट्रपति द्वारा मनमानी किये जाने के कई कहाने और अवैधानिक रास्ते हैं। इसका उदाहरण ईरान गेट कांड में कर्नेल मोलीनोस तथा मेकफालेन एव एडमिरल पोइट डेक्लटर की गवाही है।¹

विदेश सचिव, विदेश मन्त्रालय तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
(Secretary of State, State Department and
National Security Adviser)

अमरीकी विदेश नीति निर्धारण में राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति विदेश सचिव अर्थात् विदेश मंत्री होता है। द्वितीय विश्व-युद्ध के तत्काल बाद ट्रूमैन और आइज़नहावर के राष्ट्रपति काल में जोन फोर्स्टर डेलेस ने जो भूमिका निभायी, उससे इसी स्थापना की पुष्टि होती है। द्वितीय युद्ध के आधिमर्ष में डेलेस का योगदान अनदेखा नहीं किया जा सकता। यह डेलेस की ही स्थापना थी कि 'जो हमारे साथ नहीं, वह हमारे विरुद्ध है और हमारा शत्रु है।' यदि डेलेस जैसा व्यक्ति 1950 के दशक के पूर्वार्ध में अमरीकी विदेश सचिव न होता तो सीनेटर मेकार्थी जैसे साम्यवाद-विरोधियों को धुली सूट नहीं गिनती और न ही 'फेडरल व्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन' के प्रमुख एडगर हूवर गुप्तचर विरोधक अभियान (Counter-Intelligence Move) इतने बड़े पैमाने पर चला पाते। कम सींग जानते हैं कि डेलेस के कार्यकाल में सी० आई० ए० के मुख्यालय उनके आई एनएन डेलेस रहे थे। सिएटो व संग्टो जैसे सैनिक सचि-संगठनों की स्थापना डेलेस की प्रेरणा से ही हुई। चीन युद्धकालीन सांस्कृतिक प्रचार एवं बहम का संचालन भी इस पूरे दशक में अमरीकी राष्ट्रपति ने नहीं, बरन् विदेश सचिव ने किया। जेमेका सम्मेलन में चीनी प्रधानमंत्री झांग एन साई की मान हानि हो या संयुक्त राष्ट्र सभ में गुट निरपेक्ष भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले कृष्ण मेनन की अवहेलना, ये सभी निर्णय डेलेस द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिये गये।

¹ अमरीकी सचिवाय में सशस्त्र एवं उत्तरदायित्व के वितरण की जाहे जो की व्यवस्था की गयी हो, विष्णु पदार्थ में मुक्तिदानुसार इस सैद्धान्तिक प्रणाली में व्यवहारिक योजन किया जाता है।

इस पूरे अन्तराल में इलेस की सक्रियता का एक और कारण रहा। ट्रुमेन और आइज़नहावर दोनों ऐसे राष्ट्रपति थे, जिनकी विशेषज्ञता विदेश नीति के मामले में नहीं थी। जब आइज़नहावर को यह पता चला कि इलेस अमाध्य कैंसर से पीड़ित हैं तो उन्होंने उनके अन्तिम दिन सुखद बनाने के लिए वैदेशिक मामलों में उन्हें खुली छूट दे दी। स्वयं प्रकरण के दौरान अमरीकी अममजम और अनिश्चित नीति को इसी तर्क के आधार पर विस्तारित किया जाता है।

कैनेडी और जोनसन के राष्ट्रपति काल में विदेश सचिव रोजर्स और होन रस्क, इलेस सरोम्ही भूमिका नहीं निभा सके, क्योंकि राष्ट्रपति स्वयं प्रमुख नीति-निर्धारक बन चुके थे। इसके अतिरिक्त वियतनाम युद्ध के दौरान विदेश मंत्रालय की अपेक्षा पेंटागन (अर्थात् रक्षा-मंत्रालय) का राजनयिक महत्व कई गुना बढ़ चुका था। निक्मन के शासन काल में भले ही हेनरी किमिजर का प्रभामण्डल चौंधियाने वाला रहा, परन्तु इसका बुनियादी कारण उनका विदेश सचिव होना नहीं था। बल्कि यह कहना अधिक तर्कमय होगा कि राष्ट्रपति के सुरक्षा सलाहकार के रूप में किमिजर ने इतनी प्रतिष्ठा अर्जित कर ली थी कि विदेश सचिव का पद देखकर उन्हें पुरस्कृत किया गया। रोगन के प्रभामन में एनेक्जेंडर हेग को जिन परिस्थितियों में पद त्याग करना पड़ा उससे यही पता चलता है कि अमरीकी विदेश नीति में विदेश सचिव की भूमिका तभी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है जब राष्ट्रपति के साथ उसके सम्बन्धों का समीकरण सन्तुलित हो या जब उसका अपना व्यक्तित्व एक कृत्रिम राष्ट्रपति से अधिक माटवीय ढंग से प्रभावशाली हो।

विदेश सचिव का प्रमुख प्रतिद्वन्दी राष्ट्रपति का सुरक्षा सलाहकार होता है। मेक जार्ज बडी, हेनरी किमिजर और ब्रेन्नेजिस्की अपने व्यवहार में यह प्रमाणित करते रहे कि किसी भी विदेश सचिव से उनका महत्व एक बजन ज्यादा है। अमरीकी राष्ट्रपति का सुरक्षा सलाहकार राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का केन्द्रीय सदस्य होता है और उसकी विदेश मंत्रालय द्वारा मुद्राये गये विक्तियों के अतिरिक्त सी० आई० ए० की गुप्त सामरिक पढ़नात तथा रक्षा-मंत्रालय की जानकारीयों तक पहुँच होती है। उसके ऊपर अपने विभाग की नीवरसाही का कोई दबाव नहीं होता। अतः विदेश सचिव की तुलना में वह कहीं अधिक स्वाधीन होता है। हेनरी किमिजर और ब्रेन्नेजिस्की दोनों ने इस बात को उद्घाटित किया कि यदि ऐसा व्यक्ति जन-मण्डल में कुशल हो तो प्रचार मापनों पर काबू पाकर विदेश सचिव और विदेश मंत्रालय को दरकिनार कर अपनी इच्छानुसार विदेश नीति का संचालन कर सकता है। जब अमरीकी व्यवस्था में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद अलग से तय नहीं था, तब भी बुलेट एव हेरी होपकिन्स जैसे व्यक्ति राष्ट्रपति के विशेष विश्वासपात्र होने के कारण महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे।

पूरे वियतनाम युद्ध के दौरान यह बात भी स्पष्ट हुई कि विदेश सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अलावा भी अन्य योग्य व्यक्ति विदेश नीति निर्धारण और राजनय की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। रक्षा सचिव रोबर्ट मेकनमारा इसका सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। क्यूबार्ई प्रभोपासत्र सत्र के समय रोबर्ट कैनेडी मात्र एटोनी जनरन थे और उनका उत्तरदायित्व बृहद् मन्त्री सरोसा था। फिर भी अपने आई जान एफ० कैनेडी का विश्वासपात्र होने के कारण इस प्रसंग में उनका योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा था।

मगर, इससे यह निष्कर्ष निकालना गलत होया कि विदेश सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार या कैबिनेट के अन्य सदस्य ही अमरीकी विदेश नीति निर्धारण और क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण घटक होते हैं। ये सारे पद राजनीतिक कारणों से प्रदान किये जाते हैं और फर्मोवेश अस्थायी होते हैं। 'ट्रिप्टी सेक्रेटरी', 'अमिस्टेंट सेक्रेटरी' और 'अडर सेक्रेटरी' जैसे पद पेशेवर राजनयिकों के लिए सुरक्षित होते हैं और इन पोस्टामीन अधिकारियों की विशेषज्ञता का अवमूल्यन नहीं किया जाना चाहिए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जार्ज एफ० केनन प्रस्तुत करते हैं, जिन्होंने विदेश सेवा में रहते हुए 'Containment' (प्रभाव रोकना) के सिद्धान्त का प्रतिपादन कर अमरीकी विदेश नीति को कई दशकों तक प्रभावित किया। इसी तरह कमी मी अमरीकी विदेश सेवा के साथ सम्बद्ध न रहने और राजनीति में सक्रिय न रहने पर भी एडगर स्नो जैसे पत्रकारों ने चीन के साथ अमरीकी सम्बन्धों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया।¹ वियतनाम युद्ध के दौरान बोल्टर फ्रोकस्ट, मेरी मेबार्थी, वर्नाड फॉल, डेविड हेवरस्टोम जैसे पत्रकारों की विदेश नीति में भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता।

विदेश नीति और सी० आई० ए० की गतिविधियाँ (Foreign Policy and Activities of C.I.A.)

पिछले पाँच-छः वर्षों में ऐसे अनेक रहस्योद्घाटन हुए हैं, जिन्होंने यह बात रेखांकित की है कि अमरीकी विदेश नीति-निर्धारण एवं संचालन में संवैधानिक प्रावधानों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण असंवैधानिक गतिविधियाँ और गुप्तचर संस्थाओं के पदग्रस्त रहे हैं। यो 'थे आफ पिम्स' के प्रसंग से इस बात का पता चल गया कि फीनेडी जैसे युवा आदर्शवादी राष्ट्रपति को गलत सूचनाएँ और विश्लेषण देकर पथ-भ्रष्ट किया जा सकता है। इस रहस्योद्घाटन करने वाली पुस्तकों में फिलिप एजी की 'C.I.A. : Inside the Company' तथा विकटर भासोटी की 'C.I.A. and the Cult of Intelligence' प्रमुख हैं। इन लेखकों ने तफसील में यह ब्यौरे पेश किये हैं कि किस प्रकार सी० आई० ए० (Central Intelligence Agency) की भूमिका अमरीकी राजनीति में महत्वपूर्ण हो गयी है।

वस्तुतः सी० आई० ए० द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संगठित ओ० एस० एस० (Office of Strategic Services) का उत्तराधिकारी संगठन है, जिसका संचालन बर्नस विलियम मो० टीनावन करते थे। इसकी जिम्मेदारी शत्रु से खुफिया सूचनाएँ एकत्र करना तथा शत्रु क्षेत्र में तोड़-फोड़ की कार्यवाही करना शामिल था। द्वितीय विश्व युद्ध के आविर्भाव के बाद यह स्वाभाविक था कि विचारधारा के टकराव के कारण इसकी गतिविधियों में दुष्प्रचार (Propaganda) और प्रचार (Publicity) भी जुड़ गये। मासहृत्तिक व आर्थिक राजनयिक गुप्तचरी के लिए सांस्कृतिक व आर्थिक आदान-प्रदान के नाम पर सलाहकार-विशेषज्ञ बनकर बहुत आसानी से औपचारिक ढंग में जुड़ सकते हैं। सभी बड़ी शक्तियों के आचरण में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का यह मूल्य प्रतिबिम्बित होता है। मसलन दूतावागों में नियुक्त शिक्षा व संस्कृति सलाहकार गैर-सरकारी संस्थाओं में घुसपैठ कर सी० आई० ए० का काम

¹ रेने, Edgar Snow, *Red China Today: The Other Side of the Rlier* (London, 1974), और *Red Star over China* (London, 1972)

कर सकता है। पाल त्राइमवर्ग का नाम इसी सिलसिले में लिया जाता है।

सी० आई० ए० अपने आप में एक अवैधानिक संगठन नहीं है। इसकी स्थापना एक विधि-मम्मत चार्टर द्वारा हुई है। यदि लोग इसके प्रति विरोध रूप में शक्ति रहते हैं तो सिर्फ इस कारण कि अक्सर यह अपने सीमा क्षेत्र का अतिरिक्त करना है। इसकी तोड़-फोड़ वाली पड़्यन्त्रकारी गतिविधियाँ आर्थिक और सांस्कृतिक राजनय की आवाज के पीछे छुपायी नहीं जा सकती। सी० आई० ए० के पास जितने विपुल आर्थिक एवं सैनिक साधन मुलभ हैं, उतने ससार के अनेक छोटे-मोटे राज्यों तक की भी मुलभ नहीं होने। सी० आई० ए० जनतान्त्रिक परम्परा-व्यवस्था को सुरक्षित रखने के बहाने असन्तुष्ट विपक्षियों को प्रोत्साहित कर किसी भी नवोदित राष्ट्र में अस्थिरता पैदा कर सकता है। वह परोक्ष रूप से बिचौलियों के माध्यम से हथियार पहुँचाकर सीमान्त पर बचाइलियों में घातक बगावत पैदा कर सकता है। यह छुफ़िया संगठन कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर लोकप्रिय अमरीका-विरोधी या 'स्वाधीन नेता' की हत्या द्वारा राह से हटा देता है। तस्तापलट और विप्लव सी० आई० ए० के प्रिय अस्त्र रहे।

द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद एलन डेसेस सी० आई० ए० के प्रमुख थे, जो विदेश सचिव जोन फोस्टर डलेम के भाई थे। ऐसी स्थिति में सी० आई० ए० तथा विदेश विभाग की गतिविधियों में समायोजन सहज था। सीनेटर मेकार्पी ने शीत युद्ध की जिस घेराबन्दी वाली मानसिकता को जन्म दिया, उसमें सी० आई० ए० को देश की सुरक्षा का प्रमुख प्रहरी समझा गया। इन 'देश प्रेमियों' की दुस्ताहसिकता को अवैधानिक कहने वाला व्यक्ति देशद्रोही बरार दिया जा सकता था। ईरान में मुसद्दिक का तत्त्वापलट, पूर्वी यूरोप में 'रेडियो फ्री यूरोप' की स्थापना, तिब्बत में खपा विद्रोहियों को प्रोत्साहन और 'साओम-बर्मा-थाईलैण्ड' के मुनहर त्रिकोण में अफीम की तस्करी, इन सभी में सी० आई० ए० का गहरा हाथ रहा। क्यूबा के घासक फिदेल कास्त्रो की हत्या के असफल पड़्यन्त्र से लेकर पिली में राष्ट्रपति अयादे के उन्मूलन तक सी० आई० ए० की रणनीति एक तरह से निरक्षर, स्वाधीन व वैकल्पिक विदेश नीति के रूप में संचालित होनी रही। हिन्द-चीन युद्ध के दौरान इसका सबसे नासद रूप सामने आया, जब सी० आई० ए० ने सरकार को ठगुरमुहानी मूचनाएँ देकर धुस करने के सातथ में लाखों अमरीकियों को इन जान-लेवा दलदल में फँसा दिया।

1960 वाले दशक के मध्य में अमरीकी राजनीति में नव बामपथ का जो आत्मालोचक ज्वार (Self Criticism) उठा, उसमें सी० आई० ए० के प्रति स्वयं अमरीकी नागरिकों का आक्राश मुखर किया। डेनियल एलसबर्ग जैसे जिम्मेदार वैज्ञानिकों ने अपनी अन्तरात्मा की आवाज पर इस गुप्तचर मस्या के पड़्यन्त्रकारी काम में हिस्सा लेने से इन्कार कर दिया। इन्ही वर्षों में 'पेंटागन पेपर्स' का प्रकाशन और मिहानुष की जीवनी 'माई वार विथ दी सी० आई० ए०' ने सी० आई० ए० की ओर लोगों का ध्यान केन्द्रित किया।¹

स्वयं भारतीय उपमहाद्वीप के सन्दर्भ में सी० आई० ए० की भूमिका काफी कुख्यात रही है। भने ही इन बान की कभी भी दात-प्रतिपात प्रमाणित नहीं

¹ देखिये—'Pentagon Papers', Published by New York Times (1971) और Norodom Sihanouk, 'My War with the C I A' (London, 1974)

किया जा सके, फिर भी यह बात चर्चित रही कि राष्ट्रपति अम्बूब खान सी० आई० ए० के वेतन भोगी रहे थे। इसी प्रकार इन्दिरा गांधी के अपदस्थ होने के बाद चंडे परिष्कार के साथ यह स्बोद्घाटन किया गया कि उनके मन्त्रिमण्डल में सी० आई० ए० का एक 'वेतनभोगी भेदिया' था। बाद में तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई ने इसी बात को लेकर एक अमरीकी पत्रकार पर करोड़ों रु० की मानहानि का दावा ठोक दिया था। इस सिलसिले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे आक्षेप सच्चे हों या झूठे, लेकिन इनके उल्लेख मात्र से शका और अस्थिरता पैदा होती है, जो विकासशील देश के राजनीतिक वातावरण को दूषित करती है। इससे सम्बन्धित देश की गुट निरपेक्षता का प्रभाव सन्तुलित होना है और अपने महाप्रभु आश्रयदाता देश पर निर्भर होने की प्रवृत्ति बढ़नी है।

हमारे अनिरुक्त सी० आई० ए० पड़ोसी देशों में एक-दूसरे के प्रति सन्देह पैदा कर अमरीकी शस्त्र व्यापार को प्रोत्साहित करता रहा है। यदि अमरीका पाकिस्तान को एफ०-16 विमान बेचता है तो इसके साथ ही भारतीय समाचार पत्रों में जोर जोर से इस विमान की चमत्कारिक क्षमता के बारे में विज्ञापनों के विचार प्रकाशित होते हैं। अतः भारत को भी मुकाबले के लिए इसी जोड़ का कोई विमान खरीदना पड़ता है।

यही नहीं, सी० आई० ए० का होना ही ऐसा है कि शुद्ध वैज्ञानिक और अन्वेषी कार्यक्रम भी निरुपद्रव नहीं रह पाते। इस सिलसिले में भारतीय अनुभव के दो उदाहरण देना पर्याप्त होगा। बोम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के तत्वावधान में मच्छरों के वेक्टर नियन्त्रण कार्यक्रम को सी० आई० ए० की मागीदारी के कारण बीच में ही रोकना पड़ा। मदा देवी पर्वत गिरार पर परमाणु उपकरण के आरोपण में पर्यावरण प्रदूषण का संकट चर्चित रह चुका है। इसके पहले भी सी० आई० ए० मानविक विध्वंसि पैदा करने वाले एस० एस० डी० जैसे रासायनों के शोध के माध्यम से जुड़ा रहा था।

इस प्रकार तमाम बदनामी के बावजूद अमरीकी विदेश नीति के क्षेत्र में सी० आई० ए० का महत्व घटा नहीं, बल्कि निरन्तर बढ़ा ही है। सी० आई० ए० के एक भूतपूर्व अध्यक्ष जार्ज बुश चीन में अमरीका के राजदूत बने, फिर अमरीका के उपराष्ट्रपति और बाद में राष्ट्रपति भी। एक अन्य अध्यक्ष विलियम बेसी ईरान-कोत्रा प्रकरण में केन्द्रीय भूमिका निभा चुके थे। कोई भी भ्रष्टाचार संस्था किसी अन्य सरकारी विभाग की तरह अपने स्वर्च का हितार्थ गार्वजनिक रूप से देने को बाध्य नहीं की जा सकती और न ही संसद और समाचार पत्र उसके दिनदिन सतिविधियों की निगरानी कर सकते हैं। यही सी० आई० ए० की शक्ति का अमली रहस्य है। इसे कभी-कभी अमरीका की 'समानान्तर व्यवस्था सरकार' कहा जाता है। अमरीकी राष्ट्रपति का विशेष गुरुता सलाहकार हों या सलाहकार या विदेश सचिव, ये सभी विदेश नीति नियोजन के लिए सी० आई० ए० की सेवाओं पर निर्भर रहते हैं। इस कारण, अमरीकी विदेश नीति निर्धारण में इसकी भूमिका घनिष्ठ में भी महत्वपूर्ण बनी रहेगी। यह जोड़ने की भी जरूरत है कि सी० आई० ए० की अमर्यताएँ मने ही समाचार पत्रों की सुनियी बननी रही हैं, फिर भी इसकी सफलताएँ चाहे कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों न हों, उन माध्यम के लिए अज्ञान ही रहेगी।

अमरीकी विदेश नीति व सैनिक-औद्योगिक तन्त्र (US Foreign Policy and Military-Industrial Complex)

विश्वी भी देश की विदेश नीति उसके राष्ट्रीय हितों में संचालित होती है। वहुधा इस विश्लेषण की चेष्टा नहीं की जाती कि ये राष्ट्रीय हित क्या हैं और इन्हें कौन परिभाषित करता है? बहुत हुआ तो यह कह दिया जाता है कि राष्ट्रीय हित सामरिक, आर्थिक और सांस्कृतिक होते हैं और परस्पर बंधे हुए भी। मैक्सिमेलिन अपनी चर्चित पुस्तक 'भारत का चीन युद्ध' (India's China War) में यह सटीक टिप्पणी की है कि वस्तुतः राष्ट्रीय हित सामक वर्ग के न्यस्त स्वार्थ होते हैं जिन्हें प्रबल वर्ग (Elite) राष्ट्रीय हित बनाकर पेश करता है। अमरीका के मन्दर्म में यह यथार्थ और भी जटिल है। इसीलिए 'सैनिक-औद्योगिक तन्त्र' की परिवर्तना वस्तु-निष्ठ अध्ययन में भी उपयोगी मिट्ट होनी है।

विदम्बना तो यह है कि इस दशकावली (सैनिक-औद्योगिक तन्त्र) का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले भूतपूर्व अमरीकी राष्ट्रपति आइजनहावर स्वयं इसी तन्त्र की उपज थे। उन्होंने अपने मापण में यह इस्तेमाल किया कि जो लोग गहियों पर बैठे नजर आते हैं, वे वस्तुतः अमरीका के असली शासक नहीं हैं। असली सत्ता-भूत तो परदे के पीछे लड़े लोग सम्मालने हैं, जो 'सैनिक-औद्योगिक तन्त्र के प्रतिनिधि' होते हैं। चीन युद्ध के काल में राष्ट्रपति आइजनहावर की यह स्वोपरोधि बहुत चर्चित हुई और मार्क्सवादी आलोचकों ने इसका उपयोग अमरीका के आक्रमक-मार्शाग्र-वादी चेहरे का पर्दाशाय करने के लिए किया। वास्तव में बड़ी औद्योगिक हस्त्रियों का प्रभाव अमरीकी विदेश नीति पर ही नहीं, बल्कि समग्र राजनीति पर काफी असरदार रहा है।

19वीं शताब्दी में जब अमरीकी महाद्वीप में नए प्रांतों का ज्ञान फैलाया गया, तब-जुबो का दोहन शुरू हुआ और इस्पात मिरां की कार्यकुशलता बढ़ाने के साथ माटर उद्योग की नींव रखी गयी तो औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के नए कीर्तिमान स्थापित किये गये। अमरीका के जिन दुम्माहमी पूँजीरानियों ने छद्म-बन में इन क्षेत्रों में अपना एकाधिपत्य स्थापित किया, वे स्वभावतः महत्त्वपूर्ण राजनीतिक हस्त्रियों भी बन गये। इनमें कारनेगी, रोकफेलर, फोर्ड आदि प्रमुख हैं। ऐसे 'मारी उद्योग' सामरिक दृष्टि में महत्त्वपूर्ण होते हैं। अतः मेना मुख्यालय, विदेश मन्त्रालय और यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी इन घरानों के साथ घनिष्ठ मीठादपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने के लिए तत्पर रहते थे।

उद्योगों का मेना में घनिष्ठ सम्बन्ध प्रथम विश्व युद्ध के दौरान स्थापित हुआ। अमरीका इस महायुद्ध में बहुत देर तक तटस्थ रहा और उसे आर्थिक उत्पादन के क्षेत्र में युद्ध की कोई विशेष स्थिति नहीं उठानी पड़ी। यही बात बर्माबेन दूसरे महायुद्ध पर भी लागू होती है। जिनकी देर तक युद्ध चलता रहा, तब तक सैनिक मात्र सामान की आपूर्ति के जरिये अमरीकी उद्योग धन्यों की साम-वृद्धि होनी रही। इस प्रकार अमरीकी सम्पत्तियों ने सैनिक मात्र सामान के उत्पादन में साम विशेषज्ञता प्राप्त कर ली।

इसमें साथ एक और महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। अमरीकी आर्थिक जीवन में औद्योगिक घरानों का स्थान त्रयण दैव्याकार निर्यंतिक नियमों (Impersonal

Corporations) ने लिया। फोर्ड, रोकफ़ेजर, कारनेगी, डुपोट आदि पारिवारिक नाम आज प्रतिष्ठित शीर्ष चिन्ह या बलकरणाभर रह गये हैं। जनरल इलेक्ट्रिकल्स, जनरल मोटर्स, मेग्नाटोल्ड, बोइंग, नोर्थकोर, आई० बी० एम०, ए० टी० टी० आदि कम्पनियाँ दैत्याकार निर्व्यक्तिक निगमों की श्रेणी में रखी जा सकती हैं। इनमें से अनेक कम्पनियों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुराष्ट्रीय निगमों का रूप ले लिया और इनकी आर्थिक क्षमता में वृद्धि के साथ-साथ उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा में भी अपार वृद्धि देखी जा सकती है। इन्होंने अपने व्यावसायिक हितों के दर्पण में अमरीका के राष्ट्रीय हितों को परित्यागित करने की प्रक्रिया का सूत्रपात किया।

यहाँ दो-तीन अन्य बातों की ओर ध्यान दिलाया जाना जरूरी है। कई कम्पनियों के नामों से ऐसा लग सकता है कि सामरिक विषयों से उनका क्या घाला? जैसे इन्टरनेशनल बिजनेस मशीन या अमरीकन टेलीफोन एण्ड टेलीग्राफ कम्पनी। इनमें से अनेक की प्रमुख गतिविधि विशेषकर शोध एवं विकास के क्षेत्र में सेना से मिलने वाले अरबों डॉलर के ठेको पर आधारित होती है। इसके अलावा इन कम्पनियों के स्वामित्व में या इनके सहयोग में काम करने वाले अन्य निगम-कम्पनियाँ मूलमखुला सैनिक उत्पादन से जुड़े रहते हैं। चिली में ए० टी० टी० और पश्चिम एशिया में टेनिसम्बो, कालटेक्स एवं मोबेल जैसी कम्पनियों के हित और क्रियाकलाप अमरीकी राष्ट्र हित के साथ अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। जैसाकि एथनी सेम्नन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'दि आर्म्स बाजार' में बताया है कि सैन्य व्यापार की अपनी गति और तर्क होते हैं।¹ एक बार उत्पादन आरम्भ होने के बाद सामान को बरकरार रखने के लिए इसका निरन्तर विस्तार आवश्यक है। जब तक शीत युद्ध जारी था, तब तक नये-नये सठावूँ पिमानों, प्रक्षेपास्त्रों आदि की निर्माण-प्रक्रिया अबाध रूप से चलती रही। इनके परीक्षण के लिए तीसरी दुनिया के रण-क्षेत्रों को प्रयोगघाता के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा। कभी-कभार सैनिक-औद्योगिक तन्त्र में ईरान के शाह जैसे अति महत्वनाशक व्यक्तियों के अहवार की दुर्बलता का काम भी उठाया। मार यह है कि इस सैनिक-औद्योगिक तन्त्र का निहित स्वार्थ यही है कि अन्तर्राष्ट्रीय तनाव घटने न पाये और अमरीकी विदेश नीति के तैवर मुडभेद बाते बने रहें।

एक और विचित्र बात है। जहाँ एक ओर सैनिक-औद्योगिक तन्त्र सरकारी ढेरों पर आश्रित है, वहीं निरवविद्यालयी तथा अकादमिक संस्थानों की शोध परियोजनाएँ इनके अनुदानों पर टिकी हुई हैं। 'दि इम्पोरिवल वैन ट्रस्ट' नामक पुस्तक में इस बात का अच्छा खुलासा पेश किया गया है कि कैसे 'फोरेम रिलेशन्स कौमिल', 'फोर्ड फाउण्डेशन' और 'रोकफ़ेजर सेंटर' जैसी संस्थाएँ इस तन्त्र की 'कठपुतली संस्थाएँ' हैं।² अमरीकी राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था के बारे में मजेश्वर बात यह है कि प्रतिमाशाली व्यक्ति विशेषतः सत्ताहकार व परामर्शदाता के रूप में कभी निजी निगमों के तो कभी सरकार के हिस्सा बन जाते हैं। रीवर्ट मेरनमारा, हेनरी निमिजर, मेक जार्ज बंडी आदि सभी इसी श्रेणी-बिरादरी के लोग रहे हैं।

¹ Anthony Sampson, *The Arms Bazar* (London, 1977).

² H. Laurence and William Minter, *'The Imperial Brain Trust'*. (New York, 1977)

अमरीकी सैनिक-औद्योगिक तन्त्र की आतङ्कारी छाया उसके सन्धि-मित्र देशों पर भी पड़ती रही है और इसने पश्चिम यूरोप के साथ उसके सम्बन्धों को क्लृप्त किया है। अमरीकी बहुराष्ट्रीय निगम आक्रमक ढंग से अपने प्रियाङ्गुप यूरोप में फैलाते रहे हैं। जनरल मोटर्स, आई० बी० एम०, जनरल इलेक्ट्रिक आदि ने बड़े पैमाने पर यूरोपीय देशों के प्रतिष्ठित उद्योगों का स्वामित्व अपने हाथ में ले लिया है। इससे चिन्तित होकर जे० जे० थोर्कर जैसे लोगों ने अमरीकी चुनौती की बात करना आरम्भ किया था। शस्त्रों के व्यापार को लेकर भी अमरीका व पश्चिम यूरोपीय देशों के बीच प्रतिस्पर्धा और मनमुटाव बढ़े। जब नागरिक विमानन की दुनिया में अमरीकी कम्पनियों का वर्चस्व था और इनमें टक्काने की क्षमता किसी एक यूरोपीय कम्पनी की नहीं थी, तब फ्राम और इगनैड ने अपनी पारम्परिक प्रतिद्वन्द्विता धुलाकर ध्वनि की गति से तेज उड़ने वाले कोनकोई विमान के लिए सहयोगी बनना स्वीकार किया था। अनेक राष्ट्रप्रेमी यूरोपीयनों को यह लगता रहा है कि अमरीकी बहुराष्ट्रीय निगम उनकी सम्प्रभुता का हनन करते हैं और अन्तराष्ट्रीय स्तर पर अमरीका की सामरिक नीति उनको निरुत्थित बनाकर उनकी स्वाधीनता का अवमूल्यन करती है। ब्रिटेन द्वारा परमाणु अस्त्रों के मामले में आत्म निर्भरता तथा इसी तरह की उपलब्धि का फामीसी हठ यही दर्शाते हैं। हाल के वर्षों में शक्तिशाली राकेट के द्वारा अन्तरिक्ष में उपग्रह फेंकने की मान्यता ऐसी ही एक चुनौती बन गयी, जिसका सामना कर यूरोपीय राष्ट्र अमरीकी महाशक्ति के सामने अपने को घीना महसूस न करें। फ्रांस का आरियन राकेट कार्यक्रम यही दर्शाता है।

जब फ्राम में देगोल का प्रभुत्व था, तब उन्होंने अपने राष्ट्र हित में और प्राणीनी उद्योगपतियों के हित-लाभ की ध्यान में रखते हुए माओवादी चीन के साथ व्यापार आरम्भ कर दिया। इससे अमरीकी सैनिक-औद्योगिक तन्त्र का क्षिप्त होना स्वाभाविक था और निरन्तर यह प्रश्न निया गया कि देगोल को तुनक मित्राङ्गमनकी मिश्र किया जा सके। कुछ वर्षों पहले जब मानवाधिकारों के उत्सर्जन को लेकर अमरीका ने सोवियत संघ पर व्यापार प्रतिबन्ध लगाने की घोषणा की, तब भी फ्राम तथा अन्य यूरोपीय देशों ने माइवेरिया लायी जाने वाली गैस पाइपलाइन के क्रियान्वयन में कोई गतिरोध नहीं आने दिया। इस प्रकार अमरीकी सैनिक-औद्योगिक तन्त्र और यूरोपीय राष्ट्रवाद के बीच एक बार फिर टक्कर देखने को मिला।

यूरोप के जनमानस में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महाशक्तियों द्वारा थोड़ी गई व्यवस्था एवं यूरोप के विभाजन को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है। विली ब्राट की 'ओस्त पोलिटिक' का विकास तथा 'यूरो कम्युनिज्म' का आविर्भाव प्रकारानुसार ने यूरोपीय एकीकरण और इस महाद्वीप की खोई हुई गरिमा को लौटाने के प्रयत्न ही थे।

परन्तु, उपरोक्त सर्वेक्षण से यह समझना गमन होगा कि अमरीकी सैनिक-औद्योगिक तन्त्र का पश्चिम यूरोप में सर्वत्र विरोध ही हो रहा है। हालांकि 'नाटो' जैसा सैनिक संगठन का शय आरम्भ हुआ है, परन्तु आज भी यूरोपीय सामक वर्ग अनिष्ट रूप से अमरीकी सैनिक-औद्योगिक तन्त्र से सम्बन्धित है। वह बाव अन्तरिक्ष

युद्ध कार्यक्रम में ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी सरकारों की सहज साझेदारी से भली-भांति प्रमाणित होती है और जॉन मेजर (ब्रिटेन) और हेल्मुट कोल (FRG जर्मनी) जैसे नेताओं की विदेश नीति विषयक भाव्यताओं से भी। यह याद रखने लायक है कि इन देशों के अमरीकी-विरोधी विपक्षी नेताओं की मतदाताओं का समर्थन नाममात्र का ही प्राप्त है। पश्चिम यूरोप के शासकों तथा अमरीका के हितों के बीच सामंजस्य स्थापित करने में अमरीकी साम्राज्यवाद का सांस्कृतिक अभियान उपयोगी रहा।

अमरीकी सांस्कृतिक साम्राज्यवाद (U.S. Cultural Imperialism)

तीसरी दुनिया के विकासशील देश बहुधा 'कोनो कोला साम्राज्यवाद' को लेकर चिन्तित रहे। उनको इस बात से सन्तोष था कि यूरोप के समृद्ध-सम्पन्न देश भी इसी आतंक से ग्रस्त रहे। विशेषकर फ्रांस और जर्मनी के सुसंस्कृत बुद्धिजीवी इस बात की ओर ध्यान दिलाते रहे कि नव-व्यवस्था अमरीकी अपने असम्य तौर-तरीके यूरोप की सम्य जनता पर थोपते रहे थे। उनको इस बात से शिकायत रही कि अमरीकी यूरोप के प्रतिमाशानी बुद्धिजीवियों-कलाकारों को 'मूहमागी' कीमत देकर 'लरीद' लेते हैं। यह स्थिति कलाकृतियों पर भी लागू होती है। यूरोपीय सप्रहालय अमरीकी व्यक्तिगत आह्वानों का 'मुकाबला' करने में असमर्थ रहे हैं। इस तरह का असन्तोष होने के बावजूद इस बात को अनदेखा करना कठिन है कि अधिकांश यूरोपियन इस बात को स्वीकार करते हैं कि वे और अमरीकावासी एक ही 'मूल' के हैं और आज भी 'एक ही तरह के व्यक्ति' हैं—अर्थात् गैरे ईसाई और पूँजीवादी, रोग सत्तार से भिन्न। यह सब है कि इंग्लैंड के अलावा यूरोप का कोई भी अन्य देश असेजी भाषा नहीं, परन्तु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद (इसके पहले भी) यूरोप से अमरीका में इतने बड़े पैमाने पर आव्रजन हुआ कि जर्मन, हिस्पानी (स्पेन), इटालियन और पोलिश मूल के अमरीकी नागरिक बराबर अमरीका के साथ यूरोप का माता जीवित रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिम जर्मनी में अमरीकी उपस्थिति और 'नाटो' संगठन ने इस रिस्ते को पुष्ट किया। अमरीकी राष्ट्रपति कैंनेडी ने प्रतीकात्मक ढंग और नाटकीयता के साथ इस भावना को अपने बर्लिन-प्रवचन के दौरान उद्घोषित किया था, जब उन्होंने कहा था कि 'मैं भी एक बर्लिनवासी हूँ।'

एक ओर रेमो आरों जैसे यूरोपीय विद्वान दक्षिणपथी अमरीकियों को तार्किक समर्थन देते रहे, वहीं ब्रेजेन्जिन्स्की और विसिजर जैसे यूरोपीय मूल के अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की अपनी रूपरेखाओं (क्लब आफ रोम या ट्राई कोन्टीनेंटल जर्मी) में भविष्य में नई और पुरानी दुनिया के हितों का अनिवार्य संयोग रेखांकित करते रहे। 'यूनेस्को' के गामले में यह बात भली-भांति प्रमाणित हो गयी कि अमरीका और अधिकांश यूरोपीय देश आज भी सूचना और ज्ञान के अबाध प्रसार के बहाने अपने सच में ही बाकी विश्व को डालना चाहते हैं। इस तरह साम्राज्यवाद का मास्टरनिक उपकरण अमरीकी विदेश नीति के लिए चरम महत्वपूर्ण सैनिक-औद्योगिक तन्त्र का ही एक और स्तम्भ समझा जाना चाहिए।

अमरीकी विदेश नीति चुनौतियाँ, समस्याएँ और सम्भावनाएँ (US Foreign Policy - Challenges, Problems and Prospects)

अमरीकी विदेश नीति के सामने सबसे बड़ी चुनौती महाशक्ति के रूप में अपनी विश्वनीयता बनाये रखने की है।¹ सिर्फ इतना भर नहीं है कि भूतपूर्व अमरीकी राष्ट्रपति रीगन निकारागुआ के मामले में झूठ बोलत हुए पाये गये या कि ईरान काण्ड में उन पर एतबार नहीं किया जा सका। इसके पहले भी अनेक बार अमरीकी राष्ट्रपति मिथ्याभाषी या अपना ख़चन निभाने में असमर्थ प्रमाणित होते रहे हैं। ईरान में अमरीकी वन्धकों को छुड़ाने में कार्टर का दुस्साहसिक अभियान असफल रहा और लीबिया जैसे उग्र-आक्रमक छोटे से राज्य पर काबू पाने में यह महाशक्ति असम रही। इसमें पहले भी हिन्द चीन में वियतनाम युद्ध के दौरान कैंडी और जॉनसन के वक्तव्यों व घोषणाओं की प्रामाणिकता सन्देह हो चुकी थी। निकमन ने जिम माटकीय ढग से चीन के साथ अपने सम्बन्ध सुधारे, उमने ताइवान तथा जापान जैसे देशों में सन्धि मित्र के रूप में अमरीका की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिये। वियतनाम से अमरीका की वापसी और ईरान के शहनाह के अन्तिम वर्षों में तथा मार्कोस की सकट की घड़ी में उसकी सहायता देने से इन्कार करना भी अमरीका की प्रतिष्ठा में बड़ा सगाते रहे। अफ्रीका में अगोला व मोजाबिक का घटनाक्रम तथा दक्षिण अमरीका में फाक्लैण्ड युद्ध प्रकरण यही दर्शाते हैं कि अमरीकी विदेश नीति उसके मित्र राष्ट्रों के लिए सुनिश्चित तथा सुनियोजित नहीं थी। अनेक विद्वानों ने इस ओर भी ध्यान दिलाया है कि दक्षिण अफ्रीका और इजराईल के साथ अमरीकी विवशता को देखते हुए यही भिन्नता पाद आती है कि 'कुत्ता अपनी दुम को नहीं, बल्कि दुम उभे नचा रही।'।

विश्वसनीयता का यह प्रश्न इसलिए और भी महत्वपूर्ण है कि आज अमरीका निर्विवाद रूप से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में 'नम्बर एक' शक्ति हो गयी है, उमी तरह जिस तरह द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर थी। तब भारत योजना के जरिए यूरोप और जापान के आर्थिक पुनर्निर्माण में अमरीका की निर्णायक भूमिका थी और विदेशी सहायता का विदेश नीति के प्रमुख अस्त्र के रूप में उपयोग किया जा सकता था। आज जापान और जर्मनी के साथ अमरीकी विदेश व्यापार शोचनीय ढग में असन्तुलित है। जब विकासशील देश नई विश्व अर्थव्यवस्था की तलाश में जुटे हैं तो अमरीका उनकी राह में सबसे बड़े रोड़े के रूप में दृष्टिगोचर होता है। अन्तर्राष्ट्रीय सूचना व्यवस्था हो या समुद्री कानून का विनियम, अमरीकी राजनय के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती यह है कि वह वृत्तसम्यक राष्ट्रों को यह भरोसा दिला सके कि सामूहिक अन्तर्राष्ट्रीय हित में उनकी भी साझेदारी है।

¹ समग्र मभी राष्ट्रपति और उनके विचार-सनाहकार इसी दबाव के तले नीति निर्धारण करत हैं और राजनय में सक्रिय होते हैं। इन निम्नलिखित में विम्वन अध्ययन विशेषण के लिए निम्नलिखित पुस्तकें देखें—Z. Brzezinski, *Political Power U S A versus U S S R* (New York 1964) Henry Kissinger, *White House Years* (Boston 1979) and *Years of Upheaval* (Boston 1982) Richard Nixon *The Memoirs of Richard Nixon* (New York, 1978), Jimmy Carter *Keeping Faith Memoirs of a President* (London, 1982) Alexander M Haig Jr., *Caveat Realism Reagan and Foreign Policy* (London 1984) and C Theodore Sorenson, *The Kennedy Legacy* (New York, 1965)

जिस समय रीगन ने सत्ता ग्रहण की, उन्होंने अमरीकी मतदाताओं को वचन दिया था कि वह अमरीका का खोया हुआ गौरवपूर्ण स्थान उसे अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर वापस दिलायेंगे। कार्टरयुगीन नरमी के बाद रीगन के अहकारी तैवर बड़े आकर्षक सगे, परन्तु उनके कार्यकाल की समाप्ति तक अमरीकी जनमानस एक बार फिर 'हस्तक्षेप से एकान्त की खोर' मुडने लगा। इसका एक बड़ा कारण यह है कि ईरान व कोना कांड में जर्नेल नौर्य की भूमिका ने यह बात अन्धरी तरह रेखांकित की है कि 'रेम्बो' (शीत युद्धकालीन काल्पनिक अमरीकी हीरो) सरीखी फिल्मी दुस्साहसिकता बड़ी आसानी से राष्ट्र हित के संरक्षण के नाम पर अमरीका को सर्वनाश के कगार तक पहुँचा सकती है। घेनेझ, सीबिया और अब खाड़ी युद्ध में धौस-धमकी और बल प्रयोग से दबाने का प्रत्यक्ष अमरीकी राजनय की सीमाओं को ही स्पष्ट करते हैं।

जाज बुश 1989 में राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के बाद बड़े उत्साह के साथ चीन-यात्रा पर निकले, लेकिन कोई ठोस उपलब्धि हासिल नहीं हुई। इन विचलनों की सीमाएँ और समस्याएँ छिपाना या कम कर बताना सहज नहीं। अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप के बाद पाकिस्तान के साथ अमरीका के सम्बन्धों में बिगाड़ कम हुआ, परन्तु पाकिस्तानी परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव फिर से बढने लगा। अन्तर्राष्ट्रीय आतङ्कवाद और इस्लामी कट्टरता का प्जार किसी भी अग्र्य देश की अपेक्षा अमरीका के लिए सबसे पहले सामरिक चुनौती बनने हैं।

राष्ट्रपति बुश के कार्यकाल में अमरीकी विदेश नीति का दायरा अप्रत्याशित रूप में विस्तृत हुआ है। किसी को भी यह अंदाज नहीं था कि यूरोपीय एकीकरण की प्रक्रिया इतनी तेजी से सम्पन्न होगी और सोवियत संघ की आन्तरिक राजनीतिक व आर्थिक स्थिति में अत्यन्त तेजी से बिगाड़ होगा। बुर्वत के मसले पर छिड़े खाड़ी युद्ध ने हम बात को उद्घाटित किया कि सोवियत संघ महाशक्ति रह ही नहीं गया है। अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर अमरीकी महत्वाकांक्षाओं को चुनौती दे सकने की बात तो छोड़िये, कमी-कमाल उसे सन्तुलित करने की सामर्थ्य भी सोवियत संघ की नहीं रह गयी है। विदेशी ऋण और टेक्नोलोजी के आयात की सोवियत जरूरतें इतनी बिचट हैं कि लगभग हर विषय पर अमरीका के साथ सहमति प्रबट करना गोर्वाध्योव के लिए अनिवार्यता भी बन गई है। यह कहा जा सकता है कि इस बदली विश्व व्यवस्था में अमरीका सहित विभिन्न राष्ट्रों के आचरण के बारे में अभी भटक्लें ही लगायी जा सकती हैं। क्या एक छत्र राजनयिक आधिपत्य करने के बाद अमरीका अपनी गरिमा बनाये रखेगा? वह भंगत रहेगा या उसका व्यवहार उच्छ्रभ्रंखल-अह्वारी होगा? इनके साथ ही यह वान जोड़ी जा सकती है कि निकट भविष्य में अमरीकी विदेश नीति के चिन्ता के प्रमुख केन्द्र विश्वव्यापी न होकर क्षेत्रीय रहेंगे। मध्य अमरीका और दक्षिण अमरीका के राज्यों से समुक्त राज्य अमरीका में मादक द्रव्यों की तस्करी अमरीकी सरकार का बड़ा सिरदर्द बनी है। जनरल नोरियेगा के अपहरण के बाद से यह प्राथमिकता साफ दिखती रही है। कहने का अर्थ यह है कि दूर-दराज के दोस्तों-दुश्मनों के बारे में बेफिक्र होकर अमरीका अब कुछ समय तक अपने आंगन या घर-पिछवाड़े की ही मुभाता रहेगा।

इस घटनाक्रम से जटिल रहा। ये सभी बातें सोवियत विदेश नीति के अध्ययन-विवेचन के लिए उत्तराधिकार प्रभाव के रूप में महत्वपूर्ण हैं। संक्षेप में, अपने आकार, शक्ति-सामर्थ्य, सम्भावना एवं ऐतिहासिक अनुभव के कारण यदि सोवियत संघ अपने को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी और निर्णायक हस्ती समझता रहा तो वह समझ में आने वाली बात है। इसके अतिरिक्त यूरोपीय राजनीति एवं संस्कृति की मुख्य पाप त्रिभुजे रहने के कारण सोवियत संघ के नेताओं एवं जनता में एक अनगाव की मानसिकता देखी जा सकती है। जासिक व तकनीकी वजन के क्षेत्र में परिवर्तनीय देशों की अपेक्षा पिछड़े रहने के कारण राष्ट्रीय अहंकार की अभिव्यक्ति के लिए आरम्भिक शक्तों की तरह साम्यवादी नेताओं के पास सामरिक-सैनिक उपकरण ही बचे रहे। आज स्थिति चाहे जिस कारण उभरी हो, किन्तु रूसियों के नाथे पर साम्राज्यवादी व उपनिवेशवादी होने का कतक नहीं लगाया जा सकता। इसका साथ उनके राजनय को निरन्तर मिलता रहा। जैसे पूर्वी यूरोप के अनेक देशों—पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया की स्थिति वहाँ तक उपनिवेश जैसी न लगी, उपग्रह जैसी रही, पर इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि ये राष्ट्र 'कृत्रिम' रूप से निर्मित हैं और बड़ी यूरोपीय शक्तियों के पारम्परिक प्रभाव क्षेत्रों के आरम्भिक विभाजन से सामने आये। स्वयं इनके बाहरी दुनिया से सम्बन्ध सीमित रहे और सोवियत संघ की स्थाव विरादरी से इनका नाता कहीं अधिक घनिष्ठ रहा।

आरम्भाही के दिनों में इसी विदेश नीति की दो प्रमुख प्रवृत्तियाँ देखी जा सकती हैं—जब आर शक्तिशाली हो तो बहिर्मुखी (Extrovert) अथवा अपने में निकुड़ने-सिमटने वाली अन्तर्मुखी (Introvert) प्रवृत्ति। ये दोनों ही तक्षण समय-समय पर सोवियत संघ के आचरण में भी परिलक्षित होते रहे हैं। आरम्भासीन इसी विदेश नीति के बारे में एक और टिप्पणी जरूरी है। इस सारे दौर में प्रमुख यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्ति ब्रिटेन के साथ इसकी प्रतिद्वन्द्विता चलती रही। इसका एक प्रमुख पक्ष उष्ण सागर (Warm Waters) तक सोवियत नीतिना के लिए मार्ग अबाध करना था। साथ ही सोवियत संघ, तिब्बत और अफगानिस्तान जैसे 'बर्फर' प्रदेशों में सामरिक महत्व के दरौ-पठारों में अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए सदैव तानाबिस्त रहता।¹

बोलशेविक क्रान्ति और इसी विदेश नीति में परिवर्तन

(Bolshevik Revolution and Change in Russian Foreign Policy)

1917 की बोलशेविक क्रान्ति के बाद निदान्त और आचरण दोनों ही दृष्टि से सोवियत विदेश नीति में नाटकीय और आनुत्-भूत परिवर्तन हुए। जिस समय यह क्रान्ति सम्पन्न हुई, उस समय प्रथम विश्व युद्ध जारी था। इस मन्दन में ही सोवियत विदेश नीति के निबोधन-क्रियान्वयन में निदान्त एवं मपार्थवाद के बीच मनमौतो या विचारधारा तथा राष्ट्रीय हित के सम्बुनन-समायोजन का मनम-विवेचन किया जाना चाहिए।

¹ क्रान्ति के रहने इसी विदेश नीति का अन्त विवेचन राजनयिक इतिहासकारों द्वारा किया जा चुका है। इसके सार संक्षेप के लिए देखें—David Thompson, *Europe Since Napoleon* (London, 1976)।

विश्व भर के बानस्राधियों मात्सवाधियों और सबहारा वष के नेतृत्व की जिम्मेदारी सोवियत संघ की है। चीन ने जपानी हत्याकांड के बाद यह युद्ध ने सोवियत युनिन तथा अन्य औपनिवाहिक सनाओं न नाज़ीवादो सनाओं क विरुद्ध स्वयं दत्ता सनानिदा की महामुद्रा देकर नोबियत संघ ने अपन विपक्षियों की और भी आग्रह किये। भारत से जनक कान्तिवारी बरस्ता अफ़ानिस्तान साविनत संघ न पहुँचे और वहाँ नल हो उह सक्षम या प्रभावित सहायता न मिली हो किन्तु सोवियत संघ क पान विभिन्न नरकार को विन न उत्तावन करन क लिए श्रेष्ठानो की सहायता बची रही।

स्टालिन रिबत्रोफ सचिव (1936) क द्वारा साविनत संघ न नाशियों क उत्पन्न क दौर म अपन को निरापद रखन क लिए जननी के साथ एक एनो मित्र की जिसे कितना हो युना किराकर दख अधनरवानी हो मानना पड़त। यह स्थिति देर तक नहीं चल सकी। नाज़ी जननी ने 1942 में नाविनत संघ पर आक्रमण किया तो स्टालिन को यह मानन पर विवश होना पड़ा कि अब महामुद्रा का स्वरूप राष्ट्र प्रतीक दश-पत्रक (Pamphlet) बन चुका है। इसके बाद ही अमरीका और ब्रिटेन के साथ मित्र राष्ट्रों की गठनी सम्भव हुई।

द्वितीय विश्व युद्ध के घटनाक्रम का सोवियत विशेष नीति पर दो तरह स प्रभाव पड़ा। नाज़ी युनोनी का सानना करत हुए नाविनत संघ न बड़ पैमाने पर जन धन की क्षति उठानी। साविनत महामुद्रा क मन म यह सिफ़ायत (जो बड़ी साना तक आग्रह की) बची रही कि मित्र राष्ट्रों न सबूत का पट्टी ने उनकी अवधि सानरिक महामुद्रा नहीं की। मित्र राष्ट्रों न जिन दूसरे नाशों को खालन का वचन दिया उसन बनाबसक दर तपायी गयी और लण्डन लीज (Lend Lease) समनोन को भी मान्यगरी क साथ तातू नहीं दिया गया। स्टालिन के मन म यह धक पैदा होना बावज़ब था कि नाज़ी जननी से भिडाकर सोवियत संघ की साम्यवादी सरकार को कमजोर करना मित्र राष्ट्रों का एकमात्र उद्देश्य है। एनो स्थिति म 1945 क दार बटुना पैदा होना साजनी पर विमन गान युद्ध क सबूत का बड़ाया। इनक अतिरिक्त साला पाटसमन तहरान आद म आनाजिन युद्ध कानीन अन्तराष्ट्रीय गिखर सम्मेलनो न युद्ध-तर विश्व के भाव्य निधारण ने विवशता की जो विशेषाधिकार युनिनता तब की उसने स्टालिन के मन म इस बहुकारी धारणा की पुष्टि की कि अब साविनत संघ को स्वयं को दूसरे दर्जे की गति मानन की कोई जरूरत नहीं है। अटलांटिक चार्टर क बाद संयुक्त राष्ट्र संघ क जिन प्रारूप को प्रस्ताविन किया गया उनमे भी नाविनत संघ का बीटो मान्य विविष्ट स्थिति दी गयी था।

1923 न 1945 क बीच की नाविनत विश्व नीति का एक ओर राबक पहलू 'लनवनाय' है। साविनत संघ न आक्रमकतानुसार जैन हित नाशन क लिए पारम्परिक राजनय का अवनम्बन किया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण लम्ब बरस तक मानाताय का साविनत विश्व नशी बना रहना है। फ्रान्स टार पहनने सिवार पान और फरण म कचकी कालन वान मानाताय पारम्परिक राजनय क पड़वर राजनयिक थ। इस तरह विपक्ष और सहकार की जदूनी प्रक्रिया का सनाय द्वितीय महामुद्रा की सानरिक विवशताका कारण सम्भव हुआ। इसी न आा बनकर तनाव-साधत्व क युग न प्रतिसर्धी सहकार (Adversary Partnership)

स्टालिनकालीन विदेश नीति : राष्ट्र हित बनाम विचारधारा (1923-53) (National Interest vs Ideology : The Stalin Era)

स्टालिन काल की सोवियत विदेश नीति को मोटे तौर पर दो कालखण्डों में बांटा जा सकता है । इनमें से पहला कालखण्ड 1923 से 1945 तक का है जिसे अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से द्वितीय विश्व युद्ध के काल में सोवियत संघ की अन्तर्राष्ट्रीय भूमिका के रूप में देखा जा सकता है । दूसरा कालखण्ड, शीत युद्ध के उद्भव 1945 से 1953 तक का है ।³ इन दोनों कालखण्डों के बारे में एक बात समान रूप से लागू होती है । स्टालिन अपने को लेनिन का एकमात्र ज़ायज उत्तराधिकारी समझते थे और उनके राजनयिक विश्लेषण में एक खास तरह की तैयारिक कट्टरता देखने को मिलती है । इससे अतिरिक्त उनके काल में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति व विदेश नीति के क्षेत्र में शक्ति के यथार्थ (Reality of Power) को ही सर्वोपरि समझा जाता रहा । द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक बार जब इटली में पोप और ब्रेटिकन की चर्चा हो रही थी और पोप के सांस्कृतिक व धार्मिक महत्व को भाका जा रहा था तो स्टालिन ने अपने सचिव-मित्रों से दो दूक पूछा था—‘आखिर पोप के पास ‘पट्टन’ कितनी है ?’

स्टालिन के पास लेनिन के समान विश्लेषणात्मक मेधा नहीं थी और न ही व्यापक इतिहास दर्शन । इस कारण सोवियत संघ के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को परिष्कृत या जड़ित बन से परिभाषित करने की क्षमता स्टालिन में नहीं थी । फिर भी ऐसा नहीं था कि सोवियत विदेश नीति का अवमूल्यन हुआ हो । इत्याण डोयशर जैसे विद्वानों का मानना है कि स्टालिन स्वयं को सिर्फ लेनिन का ही नहीं, बल्कि पुराने महान् जारों का उत्तराधिकारी भी समझते थे और सोवियत संघ की भौगोलिक अलक्षता को अक्षत रखने तथा उसकी सामरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए निरन्तर श्रुत-समरप रहे ।

स्टालिन अपने को मानसंवादी और लेनिनवादी मानते थे । उन्होंने अपने क्रांतिकारी अनुभव के आधार पर देश का व्यापक रूपान्तरण किया । विपक्षियों के दमन, आन्तरिक उत्पीड़न आदि से हमारा यहाँ कोई यास्ता नहीं । परन्तु इस सर्वेक्षण से हम जिस बात पर जोर देना चाहते हैं, वह यह है कि 1923 से 1952-53 तक के शीत युद्धों में स्टालिन के अधीन सोवियत संघ की एक अलग स्पष्ट पहचान अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में बनी, जो पारम्परिक पूँजीवादी शक्तियों के लिए विरोधी बानी थी । जार्ज केनन जैसे प्रखर विपक्षकों का तो यहाँ तक मानना है कि पश्चिमी औपनिवेशिक शक्तियाँ ‘स्टालिन के सोवियत संघ’ को शत्रु के रूप में ही देखती थी । केनन और मन्ट्रे फोलेन दोनों का यह मानना है कि यस्तुतः शीत युद्ध का आरम्भ 1945 में नहीं, 1917 में हो चुका था ।

यह तथ्य है कि लेनिन की मृत्यु और ब्रोतस्की के अपदस्थ होने के बाद सोवियत विदेश नीति के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर क्षीण हुए । परन्तु, स्टालिन ने आन्तरिक भाषिक विकास को चुनौतियों से जूझते हुए कभी भी इस दावे को त्यागा नहीं कि

² देखें—Progress Publishers, *Soviet Foreign Policy* (Moscow, 1981).

³ इस काल की प्रमुख घटनाओं के विस्तृत विश्लेषण के लिए शीत युद्ध बनाम मध्यय देखें ।

रुष्ट्र-पंचेवकालीन विदेश नीति बदलते लक्ष्य एवं नए साधन

(1955 से 1964 तक)

(Changing objectives and New means the Khrushchev Era)

जब 5 मार्च, 1953 को स्टालिन की मृत्यु हुई, तब यह अटकल लगायी जाने लगी कि अब सोवियत विदेश नीति की क्या दिशा होगी ? स्टालिन की कितनी भी निन्दा की जाये, परन्तु यह बात नहीं गुठलायी जा सकती कि अपने जीवन काल में वह सोवियत सभ को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर चुके थे। हर मामले में विशेषकर उपभोक्ता सामग्री के क्षेत्र में, अमरीका की बराबरी न की जा सकती हो, किन्तु दोनों देशों के बीच सैनिक व सामरिक दृष्टि से जोड़ बराबर का था। सोवियत सभ में न केवल 'आणविक अस्त्र' हासिल कर लिये, बल्कि परमाणु अस्त्रों के निर्माण में भी यथेष्ट प्रगति कर ली थी। दोनों महाशक्तियों के बीच 'शक्ति के पारस्परिक सन्तुलन' की जगह 'आतंक का सन्तुलन' स्थापित हो चुका था। ग्रीस, बर्लिन कोरिया, आदि सबट-स्थलों में स्टालिन यह स्पष्ट कर चुके थे कि वह घाँस-घमकी म आने वाले नहीं। पर्यवेक्षक उत्सुकता से इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि स्टालिन का उत्तराधिकारी क्या उतना ही जीवट और मनोबल वाला होगा ?

स्टालिन की मृत्यु के बाद पहले दो वर्षों (1953-54) तक विदेश नीति के सन्दर्भ में स्थिति कुछ अस्पष्ट-भी रही। इस दौरान रुष्ट्र-चेव, मेलेन्कोफ एवं बुल्गानिन के बीच एक त्रिकोणीय संघर्ष चला, परन्तु इसका लाभ पश्चिमी देश नहीं उठा सके, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध निर्वाह में सोवियत सभ के सामूहिक-सहकारी नेतृत्व में कोई दरार नहीं पड़ी थी। अन्ततः रुष्ट्र-चेव प्रमुख नेता के रूप में उभरे।

रुष्ट्र-चेवकालीन सोवियत विदेश नीति (1955-64) के बारे में दो बातें लगभग बराबर महत्व की हैं। इनमें एक सैद्धांतिक और दूसरी व्यक्तित्व-सम्बन्धी है। अपनी स्थिति निरापद बनाने के साथ ही रुष्ट्र-चेव ने 'विस्तारिणीकरण' की प्रक्रिया आरम्भ कर दी। उन्होंने यह दो टूक घोषणा की कि आणविक अस्त्रों के सर्वनाशक संकट को देखते हुए मानव जाति के लिए शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व का मार्ग ही एकमात्र विकल्प बचा रह जाता है। इससे निरसने वाला स्वामाविक निष्कर्ष यह था कि अमरीका के साथ परस्पर विद्वेष्ट बढाने वाला संवाद आरम्भ किया जा सकता है। स्वयं रुष्ट्र-चेव का व्यक्तित्व भेदम, मजाकिया, अनौपचारिक और बहिर्मुखी था। स्टालिन की तुलना में रुष्ट्र-चेव कहीं अधिक सहृदय और मानवीय नजर आते थे। उनके इन व्यक्तिगत गुणों या दुर्बलताओं ने विदेश नीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण रचनात्मक भूमिका निभायी। जब तत्कालीन अमरीकी उपराष्ट्रपति निक्सन ने सोवियत-न्याता की तो रुष्ट्र-चेव के साथ 'अनियोजित परामर्श' ने दत्तात प्रक्रिया को काफी तेज गति प्रदान की।

लेकिन यह मोचना गलत होया कि शीत युद्ध के पान को विघटन करने का काम अपन रुष्ट्र-चेव ने किया। निश्चय ही अनक एस वस्तुनिष्ठ एवं ऐतिहासिक कारण थे, जिन्होंने इस दत्तात प्रक्रिया को अनिवार्य बना दिया। स्टालिन के चणुल से मुक्त सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की 'नता मडली' यह माचने लगी कि आर्थिक विकास के क्षेत्र में अमरीका की बराबरी करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय तनाव घटाना आवश्यक है। यदि इस समय सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के सहयोगियों का समर्थन रुष्ट्र-चेव को

को आसान बनाया।

एक बात और। स्टालिन इतने सन्ने समय (तीन दशक) तक सोवियत संघ का एक छत्र निरंकुश अधिपति रहा कि वैदेशिक मामलों में उसके नीति-निर्धारण और 'दूरदर्शी ज्ञान' को चुनौती देने वाला कोई प्रतिद्वन्द्वी उमर नहीं सका। विदेश मन्त्रालय के बुद्धिजीवी और पार्टी के विशेषज्ञ अपनी जान बचाने के लिए स्टालिन के मुसान की मुक्त कठ में प्रशंसा को ही अपना एकमात्र उत्तरदायित्व समझते रहे। किसी के अनुमोदन की कोई आवश्यकता स्टालिन को कभी नहीं रही। इस कारण स्टालिन-काल में नीति-विधोक्त संस्थाओं और प्रक्रियाओं का घातक अवमूल्यन हुआ। स्टालिन की मृत्यु के बाद भी यथास्थिति को सौदानी-सामान्य करना संभव नहीं था, क्योंकि आन्तरिक सत्ता संघर्ष में स्टालिन के उत्तराधिकार का कोई भी प्रत्याग्री मुल्ह को पहल कर अपने को कमजोर या देशद्रोही प्रकट नहीं करना चाहता था। 1953 में स्टालिन के निधन के बाद तीन-चार वर्ष बीतने पर ही 20वीं पार्टी कांग्रेस के अवसर पर 'विस्तारिनीकरण' (De-Stalinisation) की बात सोची जा सकी।

अनेक बार यह बात कही जाती है कि अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में स्टालिन मानसिक रूप से रोग-ग्रस्त और कुठिल थे तथा सोवियत संघ को 'सीहू आवरण' के पीछे धकेल कर रुसियों को खुद ही अपने देश में वदी बनाने की गलती उन्होंने की थी। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमन्त्री चर्चिल का सीहू आवरण के बारे में फुल्टन का भाषण बड़ा प्रसिद्ध है, तथापि यदि भ्रम-सामयिक भाटकीयता से अलग कर इसका वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाये तो इस बात को उपेक्षा नहीं जा सकती कि इस विभाजन के लिए सोवियत संघ नहीं, बल्कि अमरीका अधिक जिम्मेदार था। शीत युद्ध की मानसिकता के प्रसार एवं मुठभेड़ की मुद्दा को लोकप्रिय बनाने के लिए स्टालिन को अपेक्षा अमरीकी विदेश मन्त्री उल्लेख रही अधिक उत्तरदायी थे।

द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमरीकी संगठन ओ० एस० एस० का रूपान्तरण गुप्तचर संस्था सी० आई० ए० में कर दिया गया और जर्मनी तथा पूर्वी यूरोप में सोवियत लाल सेना की उपस्थिति को नकारने के लिए पदपद्मकारी गुप्तचरी एवं घुमपेठ का भूतपात किया गया। 1949 में चीन में साम्यवादियों द्वारा सत्ता ग्रहण करने के बाद अमरीका की यह सगा कि उसको अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और भी संकटमय हुई है।

अमरीका ने यूरोप के युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिये जो मार्शलस परियोजना प्रस्तावित की, उसके तहत भी सोवियत संघ के लाभान्वित होने का कोई अवसर न था। इन सबसे महत्वपूर्ण एक बात और भी थी। जापान के विरुद्ध परमाणु अस्त्रों के प्रयोग के बाद अमरीकी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह इस नये अस्त्र पर अपना एकाधिकार बनाये रखेगी। ऐसी स्थिति में यदि स्टालिन ने अपने देश को घिरा हुआ महसूस किया और पाँचवीं शक्तियों के प्रति अपना रुख कड़ा रखा तो यह समझ में आने वाली बात है।¹

¹ स्टालिन-कालीन सोवियत विदेश नीति के उपर्युक्त सर्वक्षण के लिए अनेक सरल एवं प्रामाणिक पुस्तकें-ग्रन्थों का उपयोग किया गया है, जिनमें प्रमुख हैं—Isaac Deutscher, 'Stalin' (New York, 1949); 'Russia, China and the West' (London, 1970); Andre Fontaine, 'History of the Cold War: From the Korean War to the Present' (New York, 1970).

खतरनाक दम से स्थायी बनाने के लिए बर्लिन दीवार की चिनाई सोवियत नेताओं के ही इशारे पर हुई। अमरीका के गुप्तचर विमान यू-2 को गिराकर एक मित्र सम्मेलन की सम्भावनाओं को उन्हें व्यर्थ ही ध्वस्त किया। कागो सकट के दौरान छद्मचेव ने यह बात स्पष्ट कर दी कि यदि स० रा० सघ का खंबा इसी तरह पक्ष-पातपूर्ण रहा तो उसे कम से कम भी तरह के आर्थिक व नैतिक समर्थन की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसी दौरान छद्मचेव ने स० रा० सघ के प्रशामन के लिए अनूठी 'मोयका' व्यवस्था मुझावी और बहुत देर तक अपनी आन्तरिक आलोचना से इन अन्तर्राष्ट्रीय मस्या को निष्क्रिय और असम्य बना दिया।

अपने प्रतिद्वन्द्वियों के उन्मूलन तथा आलोचकों को 'मूक' करने के बाद छद्मचेव के राजनयिक आचरण में दुस्माहमिकता का अंश बढ़ने लगा। जिस तरह परमाणु युग के लिए जरूरी परिष्कृत सामरिक समझ के अभाव में विश्व सर्वनाश के कगार पर पहुँच सकता है, यह बात क्यूबाई प्रक्षेपास्त्र सकट के अवसर पर स्पष्ट हुई। अतः क्यूबा सकट के समय की आत्मघाती रैर-जिम्मेदारी और कम-चीन विग्रह को नियन्त्रित करने में असमर्थता के कारण छद्मचेव को अक्टूबर, 1964 में पद त्यागना पड़ा। परन्तु हमने यह नहीं कहा जा सकता कि छद्मचेवकालीन सोवियत विदेश नीति असफल रही या उसे सोवियत राष्ट्रीय हितों का साधन नहीं हुआ।

यह बात निर्विवाद रूप से कही जा सकती है कि अन्तरिक्ष में साबित उपग्रह स्पूननिक को तेजकर छद्मचेव ने दुनिया के सामने यह बात प्रमाणित कर दी कि सोवियत सघ राकेट विज्ञान के मामले में अमरीका से कहीं आगे है। इस उपलब्धि ने सोवियत जनता का मनोबल तो बढ़ाया ही, तीसरी दुनिया की नज़रों में भी इस महाशक्ति की छवि रातों-रात तेजस्वी बना दी। इसके बाद शीत युद्ध-कालीन प्रकार अभियान में अमरीकी प्रभाव निरन्तर घटता गया। यह सब है कि क्यूबाई सकट के बाद छद्मचेव की राजनयिक मूख पर प्रश्न चिन्ह लग गये, तथापि स्टालिन युग की घेराबन्दी वाली मानसिकता में अपने देश को मुक्त कराने में उनका सचहनीय योगदान रहा। इस बात का भी अन्वेष्टा नहीं किया जाना चाहिए कि छद्मचेव की सामन्तावधि एक तरह से 'सक्रिय बाल' थी। स्टालिन का लम्बा प्रशामन साम्यवादी प्रणाली में एक तरह का 'अप्राकृतिक व्यवधान' था। द्वितीय विश्व युद्ध ने इस और भी ज्यादा अटपटा बना दिया। सोवियत विदेश नीति में आदर्श एवं पथार्य, राष्ट्र हित एवं विचारधारा का द्वन्द्व, इन तीन दंगकों में निरन्तर चलता रहा था। ऐसा सोचना तर्कसंगत नहीं कि छद्मचेव एक दशक में ही इन सारी उनकी गुलियाओं की मुद्रा लेने। उन्होंने स्थिति को सामान्य बनाने की प्रक्रिया का सूत्रपात किया। जब ही छद्मचेव पर अति-ग्रन्थीकरण का आरोप लगाया जा सकता हो, किन्तु उनकी सदाशयता पर सन्देह करना अनुचित है। यह बात नहीं भुलायी जा सकती कि हिन्द चीन का सकट हो या पश्चिम एशिया का मामला या फिर परमाणु शस्त्रीकरण व परीक्षण के कारण अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में वृद्धि, छद्मचेव ने सकट के कगार पर खड़े रहते हुए राजनयिक मन्त्रालय बनाये रखने के उद्यम में कोई कमर नहीं छोड़ी।¹

¹ छद्मचेवकाव्यो विद्वज्जी के लिए—Issac Deutscher, *Russia, China and the West* (London, 1970), K. Anatolov, *Modern Diplomacy* (Moscow, 1972), and Arthur M. Schlesinger, Jr., *A Thousand Days* (Boston, 1965)

प्राप्त नहीं होता तो उन्होंने इस दिशा में कोई साधन पहले नहीं की होती। रुझनेव ने यह दूरदर्शिता भी दर्शायी कि उन्होंने शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के पक्ष में अन्तराष्ट्रीय जनमत बनाने के लिए तीव्र दुनिया के अफ्रो-एशियाई देशों को आरम्भ से अपने साथ किया। स्टालिन अपने जीवन काल में गुट निरपेक्ष देशों को सन्देह की दृष्टि से देखते रहे थे। सोवियत विश्वकोष में नेहरू और गांधी की निन्दा-आलोचना तक की गयी थी। इसके विपरीत रुझनेव ने भारत के प्रति वैहिकक मंत्री का हाथ बढ़ाया। यह कदम सिर्फ़ शब्दाडंबर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बड़े पैमाने पर आर्थिक व तकनीकी सहायता (मिलाई, षोकारो आदि) तथा कश्मीर के मामले में भारत के समर्थन तक विस्तृत हुआ। इसी तरह मिस्र में नासिर की 'प्रगतिशीलता' को मंत्रीपूर्ण प्रोत्साहन देकर रुझनेव ने सोवियत राष के नये बढ़ते हुये उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद विरोधी स्वरूप का प्रचार किया। इस तरह जमीन तैयार करने के बाद रुझनेव ने अमरीका के साथ सघाद आरम्भ करने की पेशकश अधिक विद्यमान बनायी।

तथापि रुझनेव ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, जिससे प्रतिपक्षी देश को सोवियत सभ की दुर्बलता का संकेत मिल सके। शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व पर बल देते हुए रुझनेव ने यह स्पष्ट कर दिया कि प्रभाव क्षेत्र का एक वह हिस्सा (पूर्वी यूरोप के 'उपग्रह देशों' वाला हिस्सा) भी है, जिसमें सोवियत राष किसी की इसलदाजी वर्धास्त नहीं करेगा। हुगरी और पोलैंड में पार्टों व सरकार के विच्छेद जनान्त्रिक का वर्बर दमन सोवियत सभ की इच्छानुसार ही हुआ। इतना ही नहीं, वास्तव सन्धि संगठन के सदस्य देशों द्वारा नाटो, मिष्टो और मँटो की परियोजनाओं व क्रियाकलापों का वैहिकक उडकर मुकाबला निरन्तर किया जाता रहा।

1956 में बीसवीं पार्टी काग्रेस के बाद सोवियत विदेश नीति में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। यह परिवर्तन सोवियत सभ तथा चीन के बीच विवाद का सतह पर आना था।¹ इसके अनेक जटिल-सहित्क कारण थे। चीन के माओ तथा कुछ अन्य कट्टर साम्यवादी नेताओं का मानना था कि 'विस्तारितनीकरण' की प्रक्रिया बिना साम्यवादी खेम में आपसी परामर्श के नहीं की जानी चाहिए थी। इससे एक तरह से बहुध्रुवीकरण (Multi-polarisation) की प्रक्रिया का सूत्रपात हुआ। सोवियत-चीन विग्रह ने अमरीका व रूस के बीच परस्पर विरोध को प्रतिस्पर्धी सहकार (Adversary Partnership) में बदलने की प्रेरणा दी। यह उल्लेखनीय है कि इस समय तक चीन के पास आणविक बल्य नहीं थे और चीनी नेताओं को लगा कि सोवियत नेता अपने राष्ट्रीय हित के सामने समाजवादी खेम के सामूहिक हितों की बलि देने को तैयार थे। बाद के कुछ वर्षों में माओ ने तीन विश्व (Three Worlds) वाली जो स्थापना प्रस्तुत की और तीन पिपाओं ने विश्व के सहरो को गावों द्वारा परेजों की जो स्थापना रणनीति मुझायी, वे भी रुझनेव की विदेश नीति सम्बन्धी परिवर्तनों से अनिवार्यतः जुड़ी थी।

रुझनेव की विदेश नीति का एक और पक्ष उल्लेखनीय है। जहाँ एक ओर हमी नेता समस्तशरी-मुलह की बात करते थे, वहीं कमी-कमार अप्रत्याशित ढंग से उनका रुग्-रुग्णा अडियल टट्टू वाना हो जाता था। कुछ चुनिन्दा उदाहरणों में यह बात स्पष्ट हो जायेगी। पश्चिमी और पूर्वी यूरोप के विमानन को और भी

¹ यह, चीन विवाद का बिलुत विस्तेषण पुस्तक में बन्धित किया गया है।

अधिकांश देशों के साथ सोवियत संघ के व्यापक और घनिष्ठ आर्थिक एवं तकनीकी सहकार की मजबूत आधार मिला थी, तो कुछ अन्य देशों के साथ ये सम्बन्ध सामरिक हितों के मयोग पर नियोजित होते थे। ऐसा कहा जा सकता है कि ब्रेझनेव के काल में सोवियत विदेश नीति नयेपन के लिए नहीं, बल्कि 'प्रवृत्तियों की परिणति' के लिए उल्लेखनीय समझी जानी चाहिए।

ब्रेझनेव की सबसे बड़ी उपलब्धि 'देतान्त' और मार्ट-एक समझौते पर हस्ताक्षर मानो जाती है। आगे चलकर इन 'समझौतों' (Compromises) के आधार पर हेलसिंकी समझौता सम्भव हुआ। स्पष्ट है कि इनमें से कुछ भी ब्रेझनेव की अपनी मौलिक मूल या प्रयत्न पर आधारित नहीं था। वियतनाम युद्ध से प्रस्त और अपने महयोगी राष्ट्रों से असन्तुष्ट अमरीका, चीन कम विवाद का लाभ उठाकर अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कम सखटप्रस्त बनाना चाहता था। इन महत्वपूर्ण राजनयिक परिवर्तनों के लिए बौद्धिक परिवेश वातावरण अमरीका में ही तैयार किया गया था।

जॉन कैंनेथ गॉलब्रेथ ने 'ममृद्ध समाज' (The Affluent Society) पुस्तक में मयोग सिद्धान्त (Convergence Thesis) का प्रतिपादन किया है। इसमें कहा गया है कि औद्योगिकीकरण तथा तकनीकी प्रगति की एक सीमा के बाद मर्याद व्यवस्थाओं का स्वरूप एक जैसा हो जाना है, चाहे वे समाजवादी हो या पूँजीवादी पार्टी और नौकरशाही में एस 'टैक्नोक्रेट' महत्वपूर्ण पदों पर पहुँचते हैं, जिनका मजरिया एन-सा होता है। इसी तरह प्रसिद्ध 'थैमलिन दास्त्री' इसाक डोयनर ने सुझाया है कि बोल्लेविक क्रान्ति ५० वर्ष बाद सावियत जनता अब और त्याग बलिदान के लिए प्रस्तुत नहीं तथा वह युद्ध की मानमिकता त्यागने के लिए अपने नेताओं पर दबाव डालने लगी थी। अनक प्रमिद्ध सोवियत कलाकार, दिलाजी व लाखक स्वतन्त्रता की तलाश में पश्चिमी देशों में मरणार्थी बन गये और सोवियत व्यवस्था के भी योगदान होने के लक्षण दिखायी देने लगे। जहाँ एक ओर पूँजीवादी पश्चिम ने निरंकुश प्रतिद्वन्द्विता का मार्ग त्याग कर 'इन-वल्याणकारी मुद्रा अपनायी, वहाँ सोवियत संघ ने व्यक्तिगत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए लाभ, बोनस आदि का मार्ग अपनाया। इसका बाद अमरीका और सोवियत संघ द्वारा एक-दूसरे को विरोधी के रूप में दर्शना या शत्रु के रूप में प्रचारित करना बंठिन हो गया। इस बात की भी अनदला नहीं किया जाना चाहिए कि इन्हीं वर्षों में उग्र माओवादी मास्त्रुतिन क्रान्ति के ज्वार के कारण विश्व भर में द्वापामारी रणनीति पर आधारित जन मुक्ति मधर्म बन रहे थे। कम चीन विवाद के चलते सोवियत संघ ने इनकी ममयन नहीं दिया। इसमें से अनेक गृह युद्धों में निगाना सोवियत संघ पर आभिन शासन थे। इसने भी अमरीका और सावियत संघ के बीच 'सहकार' सहज बनाया।

इस मर्वेक्षण से यह नहीं समझना चाहिए कि ब्रेझनेव के शासन काल में सोवियत विदेश नीति के मार्ग में कोई अडचन नहीं आयी या कि अमरीका के साथ मवाद अनवरत चलता रहा। ऊपर बही गयी अधिकांश बातें ब्रेझनेव युग के पूर्वार्द्ध पर ही मटीव रूप से लागू होती हैं। उत्तरार्द्ध में एक साम्य तरह की यथास्थिति पापक बढता और प्रमाद (आतम्य) की जन्म देने वाला अहंकार ब्रेझनेव के राजनयिक आचरण में देखा जा सकता है। इसमें कई जगह मुठभट्ट के लिए उग्र दुस्मादमिक क्रिया-कलाप की जन्म दिया। इसकी पहली मिमाल 1968 में हुई जा

ब्रेझनेवकालीन विदेश नीति : देतान्त का ययार्थ (1964-1982) (Reality of Detente : The Brezhnev Era)

जिस तरह स्टालिन की मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक शासन पर अपना एकाधिपत्य स्थापित करने में क्यूबचेव को कुछ समय लगा था और अन्तराल के कुछ वर्षों में सोवियत विदेश नीति में कोई विरूप या मौलिक परिवर्तन नहीं किया गया, उसी तरह क्यूबचेव की अपदस्थ करने के बाद ब्रेझनेव ने भी समय से काम लिया। ब्रेझनेव न तो स्टालिन की तरह निर्भय अनुशासक थे और न ही उनका व्यक्तित्व क्यूबचेव की तरह मनोरञ्जक-जाकर्षक था। स्टालिन के बारे में और कुछ भी कहा जाये, परन्तु वह बोल्शेविक क्रान्ति के अधिकारियों की पहली पीढ़ी के सदस्य थे और ऐतिहासिक 'अग्र्यतम सहयोगी' होने के कारण सैद्धान्तिक विस्लेषण का महत्व समझते थे। स्टालिन काल में सोवियत विदेश नीति के किसी भी पहलू का निर्धारण-नियोजन मार्क्सवादी व लेनिनवादी स्थापनाओं और परिकल्पनाओं के सम्पर्क में ही किया जाता था। स्टालिन को अपनी यौद्धिक क्षमता कितनी ही शीघ्रता से पता चली थी, किन्तु उन्होंने सैद्धान्तिक कठोरता के हठ को कभी नहीं छोड़ा। बीसवीं पार्टी काँग्रेस के बाद क्यूबचेव ने विस्तारितनीकरण की जो प्रक्रिया आरम्भ की, वह भी सैद्धान्तिक सशोधनवाद (Ideological Revisionism) ही थी। जब ब्रेझनेव सोवियत सभ के भाष्य-विधाता बने, तब तक यह स्थिति विल्कुल स्पष्ट हो चुकी थी कि मूल, समोचित या परिष्कृत सैद्धान्तिक स्थापनाएँ क्या हैं? इनको लेकर आन्तरिक या वैदेशिक मामलों में विकल्पों के चुनाव के विषय में बहस करने की गुंजाइश नहीं बची थी।

ब्रेझनेव काल में सोवियत सभ किसी भी तरह की हीनता की प्रशंसा से पीड़ित नहीं रह गया था। बने ही उपभोक्ता सामग्री के उत्पादन व जीवन-मापन के स्तर की तुलना कर अमरीकी अपनी पीठ धक्काते रहे, किन्तु रूसियों को इससे कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि वे विद्यमानाभी हलदल में कैसे अमरीकी हाथी की बुद्धिमानता देखकर मनुष्ट हो सकते थे। 1960 के दशक में कई ऐसे सक्षण प्रकट हुए, जिनसे लगा था कि अमरीकी समाज रोगग्रस्त है और अमरीकी व्यवस्था चरमराने लगी है। अमरीका के कई घरों में अद्वैत साम्प्रदायिक हिंसा का विस्फोट और बढ़ती अपराध-वृत्ति, नशाखोरी, घायल असन्तोष भावि इसके उदाहरण थे।

यह सब है कि गोपियत-चीन विग्रह के कारण साम्यवादी खेमे में दरारें पड़ गयी थी, परन्तु ऐसा नहीं था कि इसका फायदा अमरीका को हुआ हो। पश्चिमी पूँजीवादी शक्ति में भी अमरीकी नेतृत्व के प्रति असन्तोष स्पष्ट था। आरम्भ में इसको मुपद करने वाले फ्राय के राष्ट्रपति देवोस थे। परन्तु यूरोपीय एकता का भाव बढ़ने के साथ आडेनावर, विली शॉट (पश्चिमी जर्मनी) जैसे लोग अन्तर्राष्ट्रीय राजनय में महत्त्वपूर्ण बन गये। द्विध्रुवीय (Bi-polar) विश्व के बहु-ध्रुवीय (Multi-polar) जगत में परिवर्तित होने का चित्र अन्यत्र किया जा चुका है। यहाँ इसके उल्लेख का अभिप्रायः इतना मर है कि यह स्पष्ट किया जा सके कि स्टालिन और क्यूबचेव की तुलना में ब्रेझनेव का काम कितना आसान था।

इसी तरह तीसरी दुनिया के जफो-एशियाई देशों के साथ सोवियत संघ के सम्बन्धों की नींव क्यूबचेव के काल में सन्तोषप्रद ढंग से रखी जा चुकी थी। इनमें से

ब्रेझनेव के बाद सम-सामयिक सोवियत विदेश नीति :

परम्परा और परिवर्तन (1982 से आज तक)

(Contemporary Soviet Foreign Policy after Brezhnev)

आधुनिक सोवियत संघ के इतिहास में स्टालिन के बाद ब्रेझनेव ने ही इतने लम्बे समय तक शासन किया। देश की आन्तरिक और विदेश नीतियों पर उनकी गहरी छाप छूटना स्वाभाविक था। बिडम्बना तो यह है कि विस्वातिनीकरण के दौर में जिन व्यक्ति-पूजा और उत्पीड़क-अमानवीय नीकराहाही की वेडियाँ तोड़ने की कोशिश की गयी, वह ब्रेझनेव के काल में फिर से बलवान हो गयी। ब्रेझनेव के जीवन काल के अन्तिम वर्षों में सोवियत व्यवस्था पर लाल फीतासराही, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और जड़ता व विधिलता के आरोप निरन्तर लगाये जाते रहे। इसी कारण विद्वान यह अटकल लगाने लगे कि क्या ब्रेझनेव की मृत्यु के बाद भी स्टालिन युग के अन्त की तरह सोवियत विदेश नीति नाटकीय मोड़ लेगी? जिन परिस्थितियों में ब्रेझनेव के उत्तराधिकारी का 'निर्वाचन' हुआ, उससे भी ऐसी आशा प्रबल हुई। नवम्बर, 1982 में ब्रेझनेव की मृत्यु के बाद यूरी आर्द्रोपोव ने सोवियत संघ के शासन की बागदोर संभाली।

यूरी आर्द्रोपोव सोवियत गुप्तचर सेवा के ० जी० बी० के शीर्षस्थ अफसर रह चुके थे, और भ्रष्टाचार के बटूर विरोधी के रूप में जाने जाते थे। सत्ता ग्रहण करने के साथ ही उन्होंने ब्रेझनेव के भ्रष्ट रिश्तेदारों की घरपकड़ आरम्भ कर दी और पार्टी में सदस्यों को यह सदेश दिया कि वे जनमाधारण के शासक नहीं, बल्कि सेवक हैं। स्वयं आर्द्रोपोव को अग्नेजी का अक्षुब्ध ज्ञान था और पश्चिमी यानि अमरीकी खुली जीवन मापन पैली के प्रति उनका मुकाब भी चर्चा का विषय बना। अभी पश्चिमी विद्वान यही मानने में लगे थे कि आर्द्रोपोव किस मिट्टी के बने हैं और अपने सामने की चुनौतियों में कैसे जूझेंगे, उनके सम्भीर रूप से रोगग्रस्त होने के समाचार प्रमाणिक स्रोतों से मिले। लगभग सवा वर्ष के शासन-काल में अन्तिम सात-आठ माह तक आर्द्रोपोव अस्वस्थ ही रहे। पहले जिसे वाइरम ज्वर कहा जाता था, वह अन्ततः गुर्दा का बेराम होना सिद्ध हुआ और बिना किसी महत्वपूर्ण योगदान के आर्द्रोपोव ने इस दुनिया में विदा ली।

यहाँ सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत मुनेपन और गुप्तचरी की अपनी विमोपजना के कारण आर्द्रोपोव भ्रष्ट ही नस्त या चिन्तित नहीं रहे और न ही उन्होंने कोई दुस्माहमिक कदम उठाया। उनके कार्यकाल में सोवियत संघ ने एक कोरियाई नागरिक विमान को मार गिराया। इससे थोड़ा अन्तर्राष्ट्रीय तनाव जरूर पैदा हुआ, परन्तु दो महाशक्तियों के बीच सीपे टकराव की स्थिति नहीं आयी। आर्द्रोपोव ने सीरिया के साथ सवाद आरम्भ कर और सीरिया के साथ सम्बन्ध सुधारने का प्रयत्न कर इस क्षेत्र में ब्रेझनेव युग की दुर्बलता को दूर करने का प्रयत्न किया।

9 फरवरी, 1984 में आर्द्रोपोव के निधन के बाद चेरनेन्को सोवियत राष्ट्रपति बने। मगर वह भी एक वर्ष तक ही जिन्दा रहे। आर्द्रोपोव व चेरनेन्को के अत्यन्त छोटे शासन-काल के कारण उन्हें 'जटिल राष्ट्रपति' या 'समयमगवालीन नेता' की

सकती है, जब सोवियत सेनाओं ने चेकोस्लोवाकिया में हस्तक्षेप किया और पूर्वी यूरोप के उपग्रह राज्यों की सीमित प्रभुसत्ता के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। बाद के वर्षों में पोलैण्ड का पटनाक्रम इस बात को उजागर करता है कि ब्रेझनेव के सामने देताला की सोमाएँ स्पष्ट थी। आर्देई सत्कारोव की नजरबन्दी और मास्को से उनका निष्कासन हो या पोलैण्ड के 'सोलिडेरिटी' संगठन का दमन, ब्रेझनेव हेल्सिंकी समझौते का अर्थ बहुत विस्तार से सामू नहीं करते थे। बाद के वर्षों में सोवियत संघ ने न केवल शिबिरानुसार देशों, बल्कि महत्वपूर्ण पड़ोसी गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की भ्रान्तरिक स्थिति में हस्तक्षेप का लोभ संवरण नहीं किया। दिसम्बर, 1979 में अफगानिस्तान की घासदी इसी से जन्मी।

ब्रेझनेव के ज़ात में हिन्द महासागर में सोवियत नौसैनिक उपस्थिति बड़ी और छोटे-छोटे अन्तरालों के बावजूद परिष्कृत परमाणु परीक्षणों की शृंखला जारी रही। बीच-बीच में सामूहिक एशियाई सुरक्षा योजना को खर्चा कर प्रेलनेय अपनी महावाकाशा मुखर करते रहे। इस योजना में सोवियत संघ की भगुवाई स्वीकार करते हुए ईरान से लेकर दक्षिणी प्रशान्त प्रदेश के द्वीप समूह को एक छतरी के नीचे धाने का आमन्त्रण दिया था। अने ही यह स्पष्ट नहीं किया गया कि यह योजना सैनिक संगठन से किस तरह और कितनी निम्न होगी या इसका आर्थिक व सांस्कृतिक पक्ष कान कर रहे क्षेत्रीय संगठनों के पूरक होने या प्रतिद्वन्द्वी, किन्तु इस मुझाव में अमरीकियों को चौकला कर दिया। भारत और इण्डोनेशिया की ओर से प्रत्याशित प्रतिक्रिया के अभाव में इस विषय में प्यादा प्रगति नहीं हो सकी। ब्रेझनेव ने कम्यूनिया में 'वियतनामी हस्तक्षेप' को (जनवरी, 1979) सैनिक तथा राजनयिक समर्थन देकर इस क्षेत्र में राजनयिक सन्तुलन बदलने का प्रयत्न किया और यह दर्शाया कि सोवियत संघ को अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर 'शक्ति निक्षेप' (Projection of Power) में कोई हिचकिचाहट नहीं।

ब्रेझनेव के अधीन सोवियत संघ को सिर्फ पश्चिम एशियाई क्षेत्र में पीछे हटना पड़ा। मिला ने सादात के जीवन-काल में ही सोवियत सत्ताहकारों को वापस स्वदेश भिजवा दिया था और बैम्प डेविड बातों के दौरान पश्चिम एशियाई सनट के ममाधान में सोवियत संघ की मागीदारी की निर्यंकता दर्शाते में अमरीका सफल हुआ। ईरान में साहू के पतन और अमरीकी बन्धकों वाले संकट का कोई तान सोवियत संघ नहीं उठा सका। शायद दुनका एक बड़ा कारण यह था कि अपने जीवन के अन्तिम दो-तीन वर्षों में ब्रेझनेव मम्मीर रूप से रोगग्रस्त थे और बंदेशिक मामलों में तेजी से बदलते पटनाक्रम से समुचित टन से जुड़ने में असमर्थ थे।¹

¹ ब्रेझनेवकापीन सोवियट विदेश नीति को धनी-धरि मपझने के लिए उनके प्रमुख विपक्षियों के सम्मरण अग्रन्त उपयोकी हैं। इनमें प्रमुख हैं—Henry Kissinger, *White House Years* (Boston, 1979); *Years of Upheaval* (Boston, 1982); Richard Nixon, *The Memoirs of Richard Nixon* (New York, 1978), Jimmy Carter, *Keeping Faith: Memoirs of a President* (London, 1982); Alexander M. Haig Jr, *Caveat: Realism, Reagan and Foreign Policy* (London, 1984). रिपतनाम प्रकरण के विस्तृत, वातुनिष्ट और मर्षाशर्षी विमेषण और सोवियत विदेश नीति के मर्यों को समझने के लिए देखें—David Halberstam, *The Best and the Brightest* (New York, 1972), सोवियत दल के अग्रजन के लिए देखें—Progress Publishers, *Soviet Foreign Policy, 1945-60*, Vol 2 (Moscow, 1981).

रक्षा की है। बहुत महानुभूति रखने वाला ममालोचक यह कह सकता है कि गोर्बाच्योव का प्रयत्न बदले आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में सोवियत राष्ट्रीय हितों को पुनर्परिभाषित करने का रहा है।

क्रैमलिन में असफल तख्तापलट एवं सोवियत विदेश नीति

गोर्बाच्योव को अपदस्थ करने के उद्देश्य से एक असफल तख्तापलट का षड्यंत्र कट्टरपंथी सोवियत कम्युनिस्टों ने 19 अगस्त, 1991 को रचा। मगर उनके मसूबे ब्यापक जन असंतोष तथा बोर्जिस येल्टसिन की दिलेरी के कारण सफल नहीं हो सके और गोर्बाच्योव वापस मास्को लौट आये। पर यह नहीं कहा जा सकता कि यथा-स्थिति तख्तापलट के पहले जैसी हो गई है। इस घटनाक्रम का प्रभाव सोवियत संघ की आंतरिक राजनीति, विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर पड़े बिना नहीं रह सकता।

नवमं पहली बात सोवियत संघ की आंतरिक राजनीति में शक्ति समीकरणों के बदलने की है। आज दुनिया भर की नजरें गोर्बाच्योव पर नहीं, बल्कि येल्टसिन पर टिकी हैं। कई गणराज्यों में कम्युनिस्ट पार्टी को अवैध घोषित कर दिया गया है, और कई में इसकी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है, जिससे इसकी अन्त्येष्टि दूर नहीं। बहुत वर्ष पहले ही सर्वहारा वर्ग की हितंशी होने की दावेदारी सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी को चुकी थी। अधिक संगठनों और पार्टी के हिन्तों का टकराव भी सामने आने लगा था। सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की पहचान एक विधेयाधिकार मन्दप्र क्लब के रूप में बन गई थी। यह पार्टी सर्वहारा का तो छोट्टे, अपनी जान बचाने के लिए सेना और के० जी० बी० पर निर्भर हो गई थी। केन्द्रीय नियोजन की धीरे-धीरे असफलता न उद्घाटन को ठप्प कर दिया था और सोवियत समाज अभाव-ग्रस्त था। सीमावर्ती गणराज्यों में जनजातीय असंतोष विस्फोटक ढंग से मुखर हो रहा था। महाशक्ति के रूप में सोवियत संघ का क्षय गोर्बाच्योव की नीतियों के कारण नहीं, बल्कि इन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों के कारण हुआ है। गोर्बाच्योव की नीतियाँ इनके जोरदार दबाव में ही निर्धारित की गई हैं। यदि पूर्वी यूरोप के उपग्रह राज्य आज उरमाहू के साथ पश्चिमी यूरोप के साथ जुड़ने की उतावले में रहे हैं तो यह गोर्बाच्योव की कमजोरी के कारण नहीं, बल्कि सोवियत संघ की कमजोरी के कारण है।

आज स्थिति यह है कि अधिकांश सोवियत गणराज्य अपनी स्वाधीनता की घोषणा कर चुके हैं। यह मोचना तर्क संगत है कि आने वाले वर्षों में सोवियत संघ अपनी गणराज्य का पर्याय बना रह जायेगा। परमाणु प्रक्षेपास्त्रों के सोवियत भू-भाग में वितरण को लेकर हल्का अन्तर्राष्ट्रीय तनाव पैदा हो सकता है, परन्तु ऐसा नहीं कि जिसका समाधान न ढूँढ़ा जा सके। रूसियों की नई पीढ़ी यह सोचती है कि महाशक्ति बनने की नाममत्त महत्वकांक्षा न ही सोवियत संघ को आर्थिक रूप से क्षयग्रस्त किया है और नाजायज तानाशाही को बढ़ावा दिया है। गुगहाली के लिए आर्थिक नियोजन को बदलना होगा। अगस्त, 1991 में सोवियत संघ में तख्तापलट के उमड़ें बाद के मसब के दौरान अमरीकी और पश्चिमी देशों की प्रतिनिधियों में यह बात प्रचलती है कि सोवियत संघ का एक महत्वपूर्ण इकाई तो माना जायेगा, परन्तु निर्णायक घटक या बराबरी की महाशक्ति नहीं।

सजा दी गयी है। 10 मार्च, 1985 को चेचेनको की मृत्यु के बाद सोवियत संघ की बागडोर सँभाली — गोर्बाच्योव ने। उन्होंने यह स्पष्ट घोषणा की कि वह खुलेपन व भ्रष्टाचार-विरोध की नीति बरकरार रखेंगे। गोर्बाच्योव ने अनूठे आत्म विश्वास के साथ सोवियत व्यवस्था के सभी जिम्मेदार पद सेनाल लिये और बेहूचक 'ग्लासनोस्त' (खुलेपन से राजनीतिक व्यवहार) व 'पेरैस्त्रोयका' (पुनर्रचना) का प्रचार किया। निश्चय ही, उन्होंने अपनी विश्वसनीयता बनाये रखने के लिए बड़ा जोरिम उठाया। उन्होंने आर्द्रेई सखारोव जैसे प्रसर आलोचक को रिहा करने का खतरा उठाया और स्वयं एकपक्षीय ढंग से परमाणु परीक्षणों का त्याग किया।

इसके साथ-साथ गोर्बाच्योव ने सोवियत संघ की नई आधुनिक छवि का जोर-शोर से प्रचार-प्रसार किया। उन्होंने अपनी युबमूरत पत्नी रईसा के साथ कई अन्तर्राष्ट्रीय यात्राएँ की और वस्तुनिष्ठ ढंग से अपने देश की कमजोरियों का विश्लेषण आरम्भ किया। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि उन्होंने बिना मोर्चे-समझे अमरीका की हितायत आरम्भ की। गोर्बाच्योव अमरीकी राष्ट्रपति रीगन की आतुरित्त युद्ध परियोजना की जबरदस्त आलोचना करते रहे। उन्होंने जेनेवा में मिखर सम्मेलन के वक्त यह बात मलीभाँति प्रमाणित की कि वह जल्दस्त पड़ने पर अद्भुत कौशल के साथ ऐसी पहल कर सकते हैं, जिससे प्रतिपक्षी किकर्तम्भविमूढ रह जायें। इस बात में कोई सन्देह नहीं कि अन्तर्राष्ट्रीय जन सम्पर्क अभियान में इस साम्यवादी नेता ने पैसेवर रीगन को कहीं पीछे छोड़ दिया।

जब गोर्बाच्योव ने सत्ता ग्रहण कर 'पेरैस्त्रोयका' व 'ग्लासनोस्त' वाली पहल की थी तो लश्न से प्रकाशित होने वाली साम्नाहिक पत्रिका 'इकोनोमिस्ट' ने एक रोचक व विचारोत्तेजक टिप्पणी की थी। इस सम्पादकीय अग्रलेख का सुबोनुबाव यह था कि गोर्बाच्योव की सफलता में ही उनकी असफलता के बीज छिपे हुए हैं। खुलेपन और सुचारो में यह जोरिम था कि सोवियत साम्राज्य का विघटन टाला नहीं जा सकता। पिछले दो-तीन साल का घटनाक्रम सोवियत संघ को बेरहमी से इस परिणति की ओर ले जाता रहा है। सोवियत गणराज्यों की बगावत, निरतर बिगड़ती आर्थिक स्थिति, यूरोप के कार्याकल्प और पूर्वी जर्मनी से सोवियत सेना की वापसी ने सोवियत संघ की अन्तर्राष्ट्रीय पहचान को बिल्कुल बदल दिया है। इसके जनेक उदनाक उदाहरण पिछले दिनों देखने को मिले। पहले ह्मानिया, फिर पूर्वी जर्मनी और हाल में लादी युद्ध में सकट के दौरान इराक के सधि-मिश्र होने के बावजूद उसकी (इराक की) सहायता करने में निपट असमर्थता के कारण सोवियत संघ का अपमानजनक अवमूल्यन हुआ।

आज अटकलें यह नहीं लगायी जाती की गोर्बाच्योव कितने दिन यही पर बने रहेंगे, बल्कि इस बात का विश्लेषण जारी है कि सोवियत संघ का वर्तमान भू-राजनीतिक रूप और स्वरूप कितने दिन तक बरकरार रहेगा? साम्यवादी जीवन-दर्शन और साम्यवादी व्यवस्था की असफलता-अप्रासंगिकता ने सोवियत संघ के भविष्य के बारे में कई प्रश्न जड़ दिये हैं। बिडबना यह है कि जहाँ इस बात को सभी स्वीकार करते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय तनाव घटाने में गोर्बाच्योव की भूमिका अभूतपूर्व रही है, वहीं यह बात निबिबाद नहीं कि गोर्बाच्योव के राजनयिक प्रयासों में आन्तरिक सुधारों ने सोवियत जीवन में बेहतरी को निरापद बनाया है। यह भी नहीं रहा या सस्ता कि गोर्बाच्योव की बिडेस नीति ने पारम्परिक सोवियत हितों की

राष्ट्रीय बहुकार और विद्वानों का प्रति विरस्कार का अनिश्चित चीनी विद्वान नीति की दो और प्रमुख विशेषताएँ हैं। एक, ऐतिहासिक युग में चीनी सैनिक शक्ति का वृद्धतम विस्तार का चीनी अपनी भौगोलिक सीमा के रूप में परिभाषित करते हैं और इस खाई हुई जमीन को वापस पाना उनकी विद्वान नीति का प्रमुख उद्देश्य है। इसी कारण सादियन मध्य और भारत के साथ चीन के सीमा विवाद विस्फोटक बन रहे हैं। उनके साथ जुड़ा दूसरा पहलू विद्वानों में रहने वाले चीनी वंशजों (प्रवासी चीनी) का है। इन्हें चीन अपना नागरिक मानता है और इनका हित रक्षण की जिम्मेदारी स्वीकार करता है। मलयेशिया, इण्डोनेशिया, बर्मा जैसे देशों के साथ चीनी सम्बन्धों में तनाव इसका कारण घटता-बढ़ता रहा है। इसका अलावा औपनिवेशिक काल में हाकांग, मकाओ जैसे स्थानों को चीन ने संभाला था। उन पर अपना अधिकार फिर से करने की इच्छा भी जनवादी चीन में बनवनी रही है।

इन गल्लू की, परन्तु कई मामलों में दूसरा निम्न समस्या ताइवान की है। जब चीना भूमि पर साम्यवादिया न बसा कर लिया तो बाग पार्टी नेक न पलायन कर ताइवान में धरन लायी। यहाँ समस्या सिर्फ साथ भू-भाग को वापस हासिल करने की नहीं, बल्कि प्रतिद्वन्द्वी को चुनौती का नकार कर अन्तराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने की भी थी। लगभग पहलू दस वर्षों तक (1949 से 1957-58 तक) ताइवान जनवादी चीन के लिए सैनिक आश्रित बना रहा। वयूमेओ और माज्जु की शासकाली न एक बार विद्वान को आपत्तिक युद्ध के कगार तक पहुँचा दिया था।

इन बातों पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि कम्युनिस्ट चीन ने अपने वैदेशिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पारम्परिक साधना के अभाव में नए राजनयिक उपकरणों का इस्तेमाल आरम्भ किया। अपने अनुभव में मनुष्य चीनिया न अना-भूमि का बचन-अन्वीष्टि समाज में छापामार राजनीति पर आधारित जन-भुक्ति समर, तथा आर्थिक विकास और सामाजिक पुनर्निर्माण के माध्यमों से विकास का प्रचार किया। यह महत्वपूर्ण अन्तर है कि जहाँ मार्क्सवादी-लनिनवादी स्थानांतरी औद्योगिक मजदूरों के क्रियाकलाप पर टिकी है। माओ का चिन्तन एमियाई इण्डोनेशिया के रूप में कल्पित हान के कारण अधिक सतत जान पड़ता था। 'आइस' और 'थ्रूवार्ड' का मनुष्य विद्वान हुए माओ ने मासिक क्रांति की सफलता के बाद के दौर की तरह औद्योगिक राजनय के स्थान पर जनवादी, लोकप्रिय और मजदूरवादी सम्बन्धों का महत्त्व दिया। 'चिन्ती चीनी माओ-बाओ' वाला दौर इसी का उदाहरण है।

चीन की विद्वान नीति का अध्ययन करने समय 20वीं सताब्दी में मोवियन विद्वान नीति का स्मरण हो जाना स्वाभाविक है। दाना जगह एक पुराने साम्राज्य का स्थानांतरण एक कम्युनिस्टी व्यवस्था में हुआ, परन्तु इससे यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि उस देश का राष्ट्रीय हित बिना बदल गया। सैद्धांतिक कटुता और राष्ट्र हित, परम्परा एवं परिवर्तन के मनुष्य के साथ-साथ व्यक्ति विशेष की विचारधारा का विद्वान नीति में सम्मिश्रित समझ पर प्रभाव दोनों जगह समान रूप में दमन का मिश्रण है। इसका अलावा एक और समझना है। अन्तर यह कहा जाता है कि मासिक मध्य और चीन अन्तराष्ट्रीय विवादों के सभी सदस्य हैं जिनका आचरण अन्तर्-सम्बन्ध ही होता है। यदि मनुष्य इतने सारे दलों का यह बात मानने

साम्यवादी चीन की विदेश नीति

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण विषयों में एक जनबादी चीन की विदेश नीति रही है। चीन संसार की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। प्राचीनतम सभ्यताओं में एक सभ्यता इस क्षेत्र में जन्मी और विकसित हुई है। तबियों तक एक बड़ी शक्ति के रूप में चीनी साम्राज्य का प्रभाव क्षेत्र रहा है। मूलर पूर्व में कोरिया व जापान से लेकर पश्चिम में मध्य एशिया (Central Asia) की आधुनिक सोवियत संघ की मरहद तक, उत्तर में मंगोलिया से लेकर दक्षिण में दक्षिण-पूर्व एशिया के द्वीप समूहों तक चीनी प्रभुत्व घटता-बढ़ता रहा है। यह सच है कि 19वीं सताब्दी तक यूरोपीय औपनिवेशिक विस्तार के दौर में चीनी शक्ति का ह्रास हो चुका था और चीनी समाज कुरीतियों-कुप्रथाओं से रोग-ग्रस्त था। तब भी अन्य एशियाई देशों की तरह बिराट भौगोलिक विस्तार के कारण उसे पूरी तरह कभी गुलाम नहीं बनाया जा सका। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में मानहानि और तिरस्कार के बावजूद उसकी एक हस्ती बची रही। इसी कारण, चीनी विदेश नीति का अहंकारी राष्ट्र प्रेम, विदेशियों के प्रति तिरस्कार तथा अपने की विश्व राजनीति का केन्द्र समझने वाला स्वर बचा रहा।

बीसवीं सताब्दी में पहले दशक से ही चीन में प्रगतिकारी हलचल आरम्भ हुईं। यह घटनाक्रम साम्यवादियों के प्रभावशाली होने के काफी समय पहले आरम्भ हो गया। मन यात सेन की बुद्धिमान पार्टी की स्थापना, 1911 की क्रान्ति आदि इन सन्दर्भ में महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं। गणराज्य की स्थापना के बाद ग्रह युद्ध का चरण आरम्भ हुआ, जिसकी परिणति जापानी मैन्यवाद-विस्तारवाद से प्रेरित मन्चूरियाई हस्तक्षेप में हुई। इन ऐतिहासिक तथ्यों को दोहराने का उद्देश्य यह है कि यह बात स्पष्ट हो सके कि चीनी राजनीति में व्यापक प्रगतिकारी उदय-पुनर्जागरण, जस्मिरता और हिंसक परिवर्तन कोई नई चीज नहीं। चीनी सरकारें, वे चाहे साम्राज्यवादी हो, गणतन्त्रीय या साम्यवादी, इन सबका तालमेल चीन के वैदेशिक सम्बन्धों के निर्वाह के साथ लगनग्न अनावार बिठानी रही हैं। माइकल हन्ट ने चीनी विदेश नीति के ऐतिहासिक उत्तराधिकार के बारे में लिखा है कि चीन के वैदेशिक सम्बन्धों की एक नहीं, बल्कि अनेक परम्पराएँ (वर्तमान सामक इन सबी के समान रूप में उत्तराधिकारी बने) हैं। 'इनमें सबसे बड़ा प्रयोग का स्वरूप मिलता है और गुप्त सन्धि-समझौतों का भी; व्यापारिक व सांस्कृतिक आदान-प्रदान के अनुभव का उल्लेख भी; दूसरों पर अपना प्रभुत्व धोने की चेष्टा है तो विजेता के समक्ष समर्पण व उसके पान महार की तयारता भी।'¹

¹ Michael Hunt, *Chinese Foreign Relations in Historical Perspective*, in Gary Harding's, *Chinese Foreign Relations in 1980's* (New Heaven, 1984), 10

बात को अच्छी तरह समझते थे कि परमाणु अस्त्रों को शामिल करने के बाद वे स्वर को भले ही न्यायोहिन (ब्लैंक मेल) से बचा सकते हों, पर इनके प्रयोग की कोई सम्भावना नहीं। इन कारण उन्होंने सामरिक उपयोग के लिए नाभोवाद का प्रचार कर छापामार बग़ावत के द्वारा बल प्रयोग का राजनय बननाया। भारत के उत्तर-पूर्वी सीमान्त पर नाया-मित्रो विद्रोह और बर्मा में साम्यवादी टुकड़ियों की बग़ावत इसी के उदाहरण हैं। इस प्रकार, आन्तरिक सत्ता परिवर्तन के माध्य-माध्य कुशल राजनय तथा बल प्रयोग में हिचकिचा कर चीन ने अपने को समर्थ शक्ति के रूप में प्रतिस्थापित कर लिया।

चीन की विदेश नीति के उद्देश्य (Objectives of Chinese Foreign Policy)

अन्य सभी राष्ट्रों की तरह चीनी विदेश नीति का प्राथमिक उद्देश्य अपनी भौगोलिक अखण्डता की रक्षा करना और आन्तरिक मामलों में अपनी स्वायत्तता बनाये रखना है।¹ ऐतिहासिक अनुभव के कारण निश्चय ही इन उद्देश्यों का थोड़ा-बहुत रूपान्तरण 1949 के बाद देखा जा सकता है। उदाहरणार्थ, प्राचीन काल में चीनी सम्राट बाहरी आक्रान्तकारियों में अपनी रक्षा विराट दीवार (The Great Wall of China) के निर्माण पर से कर सकते थे। यथेष्ट टेक्नोलोजी के अभाव में दुर्गम और विस्तृत भू-भाग पर किसी विदेशी शक्ति का स्थायी हस्तक्षेप नहीं हो सकता था। 19वीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में पश्चिम में विदेशी राजदूतवासियों के घेराव ने इसी बात को स्पष्ट किया।

1949 तक यह स्थिति बदल चुकी थी। वायुयानों और प्रक्षेपास्त्रों के प्रसार के बाद चीन का आकार पर उसे निरापेक्ष रखने में असमर्थ है। इसके अतिरिक्त शीत युद्ध के आरम्भिक वर्षों में सीमान्त की कुतरने वाली मोड़फोड़ (subversion) की रणनीति का विकास हुआ। चीनी विदेश नीति-निर्धारकों के लिए दो तत्त्व स्पष्ट थे—(i) विवादग्रस्त सीमान्तों पर अपना अधिपत्य निर्दिष्ट रूप से प्रमाणित करें, और (ii) अपने मर्नस्थान को सैनिक गठबन्धनों की महापता में प्रक्षेपास्त्रों की मार से बाहर रखें। उल्लेखनीय है कि 1945 से 1960 तक परमाणु प्रक्षेपास्त्रों की मारक दूरी 2500 से 3000 किलोमीटर तक सीमित थी।

पहले यह कहा जा चुका है कि चीनी नेताओं का अन्तर्राष्ट्रीय आचरण उस राष्ट्र प्रेम और अहंकार झलकाता रहा है। एक सीमा तक यह बात निराधार भी नहीं। कांग, बासुद, चीनी मिट्टी, छापामार आदि के आविष्कार के अतिरिक्त संगीत व कला में अपनी हजारों वर्ष पुरानी परिष्कृत उपलब्धियों का कारण चीन अपने पड़ोसियों और सभी विदेशियों को अमम्य तथा बर्बर समझते रहें हैं। जापान, कोरिया, और वियतनाम की अपने ढाँचे में डालने के उनके प्रयत्न हजारों माल पुराने हैं। प्रचाली चीनियों की इन अभिमान में महत्वपूर्ण भूमिका समझी गयी है। 1949 में राजनीतिक एकीकरण के बाद चीन सरकार ने दूसरा का मन्त्र बनाने और उन्हें अपने नाँव में डालने के काम को कारी धमनीरता से लिया। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि 20वीं सदी के मध्य में पारम्परिक चीनी मर्यादा या जीवन-दान

¹ देखें—Michael Yahuda, *Towards the End of the Isolations: China's Foreign Policy after Mao* (London, 1983), 81-82.

आजो है कि अधिकांश समय इन दोनों के सामने बाहरी शक्तियों से सफट बना रहा है और जनता तथा नेतृत्व की मानसिकता सफट से घिरी हुई रही है।

चीन ने हमेशा अपने को न केवल एक बड़ी शक्ति माना है, बल्कि अपनी छवि सबसे महत्वपूर्ण महाशक्ति वाली रखी है। वस्तुतः चीन की अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता का प्रश्न बुनियादी रूप से इस बात से जुड़ा था कि ताइवान को विस्थापित कर वह स० रा० सघ में सुरक्षा परिषद के निपेयाधिकार का प्रयोग कर सकने वाली शक्ति के रूप में अपना स्थान ले ले। अफ्यस माओ की 'तीन विश्वों' (Three Worlds) की परिकल्पना की मूल प्रेरणा भी वही थी कि तीसरे विश्व के स्वामाधिक नेता के रूप में जनवादी चीन, सोवियत सघ और अमरीका के समकक्ष, उनके प्रतिरोधी के रूप में अपना स्थान ले ले।

विश्व राजनीति में चीन का महत्त्व (Importance of China in World Politics)

औपनिवेशिक काल में चीन की आन्तरिक दुर्बलता के कारण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उसकी भूमिका समझ नगण्य थी। इसका पूरा दोष चीनी असमर्थता पर नहीं डाला जा सकता। इन बर्षों में औद्योगिकीकरण और साम्राज्यवाद के सन्निपात से यूरोपीय ताकतों को चुनौती दे सकना किसी और के लिए सहज नहीं था। बाइ में, जब जापान ने चीन को दबाना आरम्भ किया तो उसकी सफलता का रहस्य भी पश्चिमी तीर-तरीके का आधुनिकीकरण था।

1945-49 के अन्तरास ने इस स्थिति को नाटकीय ढंग से बदल दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में पराजित होने के बाद जापान कम से कम एक दशक के लिए चीन के सन्दर्भ में निष्क्रिय हो गया। दूसरी ओर साम्यवादियों की शक्ति में वृद्धि के साथ दशकों बाद चीन का राजनीतिक एकीकरण सम्पन्न हुआ तथा उसका राष्ट्रीय गौरव पुनः खोद सका। माओ के नेतृत्व वाली साम्यवादी सरकार ने कड़े अनुशासन को लागू किया और भ्रष्टाचार का उन्मूलन आरम्भ किया। विचारधारा में साम्य के कारण सोवियत सघ के साथ उसका सामरिक गठबन्धन हो सका और अक्रो-एशियाई भाईचारे के आधार पर उपनिवेशवाद-विरोधी रणियां अपनाकर चीन ने अपने पक्ष में व्यापक जनमत तैयार किया। इन राजनयिक उपलब्धियों के कारण सैनिक और आर्थिक सहायनों के अभाव में भी सत्ता ग्रहण करने के बाद चार-बीस वर्षों में बाहुग सम्मेलन (1955) तक चीन अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर चुका था।

चीन के अपनी शक्ति का आधार मजबूत करने के लिए इन तात्कालिक क्रियाकलापों के अतिरिक्त एक दूरदर्शी कार्यक्रम अपनाया। चीन युद्ध के पहले चरण में सोवियत समर्थन के कारण उसकी सामरिक स्थिति भले ही निरापद रह सकी, किन्तु चीनी नेता इस बात को अतीर्णति समझते थे कि वैदेशिक मामलों में अपनी स्वाधीनता बनाये रखने के लिए उन्हें परमाणु शक्तों के क्षेत्र में आत्म निर्भर होना पड़ेगा। जब सोवियत सघ ने इस मामले में उदासीनता दर्शायी तो आर्थिक विकास की बलि देकर भी चीनियों ने 1964 में परमाणु बम की क्षमता हासिल कर ली।

परमाणु बिरादरी में वलपूर्वक प्रवेश कर चीन ने अपनी सामर्थ्य, महत्वाकांक्षा तथा मनोबल को एक साथ प्रमाणित किया। परन्तु माओ तथा पण्ड एन लाई इस

भूवास आ जायेगा।' स्वयं अध्यक्ष माओ ने चीन युद्ध के चरम बिन्दु पर कहा था कि 'परमाणु अस्त्रों में हम नहीं डरते। अमरीका सिर्फ एक कागजी शेर है। यदि सर्वनाशक परमाणु युद्ध छिड़ना भी है तो बचे हुए लाख व्यक्तियों (चीनी माम्बादियों) की सख्या रणक्षेत्र में बिछी लाशों से अधिक रहेंगी।' कम आवादी वाला कोई देश ऐसा कहने का माहम नहीं कर सकता। कारियाई युद्ध, भारत तथा वियतनाम के साथ भीमा मध्य में भी यह बात प्रकट हुई कि किसी मौनिक मुठभेड़ में वेगुमार कुर्बानी देने के लिए चीनी इस जनसख्या के आत्म-विश्वास से ही अपना जीवट बनाये रखते हैं।

(2) आक्रामक विचारधारा व छापामार रणनीति—पिछले कई दशकों में बिराट आकार व विपुल जनसख्या के बावजूद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में मज्जिम महामक्तियों या बड़ी शक्तियों की तुलना में चीन की आर्थिक एवं सामरिक स्थिति दुर्बल रही है। यह अमनुलन दूर करने के लिए चीन सरकार ने एक बिभिष्ट रणनीति का दो बार वाली तनवार की तरह इस्तमान किया। एक ओर वह यथा-स्थिति को अस्थिर करने वाली उग्र आन्तिकारी स्थापनाएँ पैदा कर अपने बिरोधियों-विपक्षियों के बिबिर में अमहमन-जमन्पुष्ट तरकों की मडकानी-उकमाती रही और दूसरी ओर इनको गरण देकर, मौनिक तथा आर्थिक महायत्ना पहुँचाने हेतुक छापाकारी का प्रान्माहित करती रही। यह सिर्फ चीनी पाखण्ड या पड्यन नहीं बल्कि वह अपने मुक्ति अभियान में 'गुरिला' युद्ध की उपयोगिता को देखकर ऐसा करता रहा है। भारत में उत्तर-पूर्वी सीमान्त, बर्मा, थाईलैण्ड व उत्तरी प्रदेस में मगोल मूनज आदिवातियों की मगलन बगावन चीनी प्रेरणा-प्रोत्साहन से चलती रही है और इन देशों के साथ चीन के राजनयिक सम्बन्धों में एक महत्वपूर्ण घटक रही है। माओ के निघन व वर्षों बाद इधियापिया से लेकर फिरीपीस तक माओवादी हिमक दम्ते कार्यरत रहे हैं।

(3) सुरक्षा परिपद में बौटो शक्ति—नदिया में चीन अपनी हों बनायी सहारदीवारी के भीतर मिमटा रहा है और भौवातिक दूरी तथा तकनीकी माधनों के अनाव में अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम (जिमका मुख्य मध मूराप रहा) में गौण मदस्य रहा है। आन्तरिक दुर्बलता, फूट, गृह युद्ध और औपनिबेमिक ताकतों का प्रभाव इस अक्षमता को रेखांकित करते रहे। मगर 1949 के बाद यह स्थिति एकाएक बदल गयी। भले ही चीन की माम्यता का प्रश्न लम्बे ममम तक बिवादास्पद बना रहा, परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय सम्मननों में अन्य राष्ट्रों द्वारा चीन का मधयन एक महत्वपूर्ण विषय और राजनयिक सत्य बन गया। दसवीं परिणति 1971 में हुई, जब चीन ने निरेवाधिकार (बौटो) सम्मध सुरक्षा परिपद के स्यायी मदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण किया। इसके बाद चीन अद्भुत बौधन के साथ इस राजनयिक शक्ति का अवन पक्ष में मुनाता रहा है। बगना देस हा या पाकिस्तान, या वम्पुबिया में पाउ-गोट का गिराह, वे सभी बिना चीनी पड्यरता के मयुक राष्ट्र मध म ज्यक्षित हो रहने। चीन-अमरीका मठबोड के बाद इसका प्रभाव और भी बढ गया।

(4) आर्थिक सहायता—बौटि चीन स्वयं एन विकासगीन देश है और उसकी स्थिति अमरीका या अन्य पदचिमी देश की तरह ममृडि का बंटवारा कर सकने वाली नहीं। मगर यह मोचना गतन होमा कि उसके पास अपनी बिदश नीति के क्रियान्दयन के लिए कोई आर्थिक उपकरण नहीं है। चीन के अन्तर्राष्ट्रीय

संघी के प्रत्यारोपण की बात नहीं सोची जा सकती थी। मार्क्सवाद-लेनिनवाद के चीनी-संस्करण-माओवाद के निर्वात के द्वारा पुनः उद्देश्यों को नये ढंग से प्राप्त किये जाने का प्रयत्न 1949 से 1974-75 तक जारी रहा गया। आज भते ही अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में चीनी पक्ष अलग से नहीं पहचाना जा सकता, परन्तु इस निष्कर्ष तक पहुँचने की जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए कि चीनी विदेश नीति का यह निश्चय भुला दिया गया है। हाँ, प्रकट रूप से इस पर आज जोर नहीं दिया जाता।

चीन का राष्ट्रीय स्वभाव तथा वैदेशिक आचरण औरों के साथ समानता वाला नहीं रहा है। चीन या तो अपने से अधिक शक्तिशाली देश के सामने झुकता रहा है या दूसरों से अपना प्रभुत्व मनवाने के लिए प्रयत्नशील रहा है। 1949 के बाद चीनी विदेश नीति की दो रूपरेखा स्पष्ट होती है, उसमें साम्यवादी जगत तथा अक्रो-एगिपार्ड विचारों के नेतृत्व को हथियाने के लिए चीनी क्रियान्ताप इसको रेखांकित करते हैं। सोवियत संघ के साथ बैंगनत्व, अक्रो-एगिपार्ड संगठन की स्थापना तथा भारत एवं वियतनाम को 'दण्डित' करने वाले चीन के सैनिक अभियानों से भी वे ही इसी बात का पता चलता है।

1975 के बाद जब चीन में दंग तियाजो पिंग और उनके अनुचरों ने अधिक व्यावहारिक उपार्पणवादी मार्ग चुना तो कुछ लोगों ने यह सुझाया कि चीनी विदेश नीति में उद्देश्य महत्वपूर्ण ढंग से बदल गये हैं। इस सितसिते में चार आयुनिर्णीकरणों (कृषि, उद्योग, विज्ञान व टेक्नोलॉजी) की बात की जाती रही है। तथैही दृष्टि से देखें तो ऐसा लगता है कि चीनी आचरण में परिवर्तन हो रहा है। जैसे विदेशी टेक्नोलॉजी और पूँजी का आयात, मुक्त व्यापार के सिद्धान्तों, तान-बागत, प्रतिस्पर्धा की उपयोगिता स्वीकार करना आदि। परन्तु अधिक गहरा विश्लेषण करने से स्पष्ट बात छिपी नहीं रहती कि चार आयुनिर्णीकरणों की चुनने की रणनीति चीन की शक्ति-शाली, आत्म-निर्भर और स्वाधीन बनाने वाले पुनः परिचित लक्ष्यों के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। क्त के साथ विवाद या अनरीखा के साथ सम्बन्धों का सामन्धीकरण, दोनों तरह की राजनीतिक पहलों के लिए परम्परा का दबाव परिवर्तन की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुआ है। आज भते ही चीन में स्वयं मार्क्सवाद पहले जैसी प्रतिष्ठित स्थिति में नहीं है, किन्तु यह मानने का कोई कारण नहीं कि आपामी बपों ने चीनी नेतृत्व अक्रो-एगिपार्ड जनता के सामने अमरीका और रूस से अलग अपना सुझाया कोई नया विकल्प नहीं रखेंगे।

चीन की विदेश नीति के साधन

अब यहाँ चीनी विदेश नीति के साधनों का जिक्र करना उचित होगा। उसके प्रमुख साधन निम्नांकित हैं—

(1) विराट आकार व विपुल जनसंख्या—चीनी विदेश नीति के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सबसे बड़ा उपलब्ध साधन चीन का विपट आकार और इसकी विपुल जनसंख्या है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनय पर कितनी ही बड़ी उपलब्धता क्यों न मचे तथा चीन में माओजारी सरकार हो या नाजो-बिरोधी, इस देव को अनदेखा नहीं किया जा सकता। लगभग पैंने दो सौ वर्ष पहले मेथोतिपन ने कहा था—'चीनी दस्य अभी भी रहा है। जब करवट लेकर जायगा तो अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में

पहलू उभर कर सामने आया है। चुनिन्दा मरोचे के मित्रों को हथियारों की सप्लाई कर चीन ने अपना असर बढ़ाया है। ईरान, पाकिस्तान, अफ़ग़ान मुजाहोदीन एवं नाना विद्रोही इस सूची में प्रमुख हैं।

(5) कुशल व लचीला राजनय—कुशल राजनय ने हमारा अनिश्चय सिर्फं व्यक्तिगत राजनयिक बौद्धि नहीं है। एक राज्य के रूप में चीन ने अनूठे लचीलेपन का परिचय दिया है। रोस टेरिल जैसे विद्वानों ने इस बात पर जोर दिया है कि चीन तीन स्तरों पर अपना राजनय सम्पादित करता है। चीनी सरकार एक ओर औपचारिक स्तर पर विलुप्त सही डग ने दूसरी सरकारों के साथ अपने सम्बन्धों का निर्वाह करती है। परन्तु इसके साथ-साथ मामूली पार्टी की एकता और अन्तर्राष्ट्रीयता की दुहाई देकर पार्टी अपने स्तर पर अपने तरह से सम्पर्क बनाये रखती है। यह जरूरी नहीं कि दोनों रणनीतियों में साम्य हो। हालांकि 1962 के बाद भारत के साथ दौलत सम्बन्धों में विच्छिन्न पड़ गया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन भी हुआ। परन्तु चीनी साम्यवादी पार्टी का विभिन्न भारतीय नक्सल टोलीयों को समर्थन मिलता रहा। इसी तरह की स्थिति बर्मा, इण्डोनेशिया, ईरान आदि अनेक देशों के साथ रही। तीसरे स्तर पर विलुप्त हो गई सरकारी जनता के आपसी सम्बन्धों पर चीनी राजनय सम्पादित होता है। चीनी यह तर्क देते रहते हैं कि इस पर उनका कोई नियन्त्रण नहीं रहता। जहाँ चीनी अपने सामाजिक-राजनीतिक संरचना के कारण इन तीनों स्तरों पर एक साथ चलते जा रहे ऊपर से परस्पर विरोधी लगने वाले राजनयिक अभियानों का समायोजन कर सकते हैं, वहाँ औरों के लिए ऐसा करना कठिन होता है।

चीन अपने राजनय में तमाम क्रान्तिकारी स्थापनाओं के बावजूद आवश्यकता पड़ने पर शारस्त्रिक गुप्त राजनय का वैदिक अवलम्बन कर सकता है। वियतनाम में शान्ति की पुनर्स्थापना के पहले भी बारमा (पोलैण्ड) में अमरीका के साथ सम्पन्न गुप्त बातों की सम्बन्धी शृंखला ने यह बात प्रतीति प्रकट कर दी। इस दूसरे ध्रुव पर महान सांस्कृतिक शान्ति के दीपन अनुत्तरदायी, अराजकतावादी, भयावी होने वाले क्रियाकलाप को रखा जा सकता है, जिसमें चीनियों ने दावा किया था कि पारम्परिक औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय राजनयिक प्रणाली में उनकी मातेदारी नहीं हो सकती। वस्तुतः चीनी राजनयिक आचरण विचारधारा से कहीं अधिक अति यथार्थपरक अवसरवादिता को झलकाता है। अल्पक्षेत्रों का चिन्तन दर्शन, जिसमें 'दो कदम आगे बढ़ने के लिए एक कदम पीछे हटने' की बात कही गयी है और अन्तर्विरोधों का वर्गीकरण किया गया है, आवश्यकतानुसार समझौतों या मुंह की सहजियत भी देखता है।

जहाँ तक चीनी विदेश नीति व उपकरण-आधनों का प्रश्न है, यह आसानी से देखा जा सकता है कि इनका मजबूत एवं परिष्कार माओ तथा उनके उत्तराधिकारियों ने अपने आपसी मतभेदों-संघर्षों के बावजूद असाधारण सफलता से किया है। आकार और जनसंख्या का साथ चीन की पारम्परिक उत्तराधिकार में मिला है तथा राजनीतिक एकीकरण और अनुशासन साम्यवाद की देन है। इनका संयोग हुआ है—परमाणु समता हासिल करने तथा आत्म-निर्भर आर्थिक विकास की नींव रखने में सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता इस कारावत्स के साथ जुड़ी हुई है, परन्तु उसमें चीन की क्षमता-सामर्थ्य को कई गुना बढ़ा दिया है। संयोगवश ही सही,

आर्थिक सहायता कार्यक्रम का विलुप्त विस्तारण प० जर्मनी के वार्टोफ नामक विद्वान् ने किया है। उन्होंने इन मजदूरों वान की ओर ध्यान दिलाया है कि जब चीन स्वयं मोविपन सच में अपने तकनीकी-इंजीनियरिंग परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर सहायता प्राप्त कर रहा था, तब भी अपनी जरूरतों में बढ़ती कर सामरिक दृष्टि से उपयोगी या महत्वपूर्ण परीक्षियों को अनुदान देने को चीनी नेताओं ने प्राथमिकता दी थी। इनके दो प्रमुख उदाहरण हैं। चीन ने नंगस में भारत के प्रभाव को कम करने के लिए क्वाङ्गडू-केंद्रित खननार्थ के विमान में योगदान दिया और चीनी विदेश इन बात के लिए विशेष रूप में प्रयत्नशील रहे कि उनके भेजे मताहकार, नहुयोनी-श्रमिकों के रूप में सामने आये, जिनसे तुलना औसतनियेनिक मित्राङ बाये भारतीय अधिकारियों से की जा सके। इन बात का उल्लेख यहाँ इसलिए आवश्यक है कि इनने पता चलता है कि किस प्रकार चीनी नेता कुरखी इस से अपने आर्थिक राजनय में प्राथमिक सांस्कृतिक पुट देते रहे हैं। दूसरा उदाहरण श्रीलंका का है। 1970 बाये दत्तक के प्रारम्भिक वर्षों में जब चीनी साक्षात् सन्द और भभाव श्रेत रहे थे, तब स्वयं उन्होंने श्रीलंका को चावल का निर्यात किया। चावल का परिमाण उनका महत्वपूर्ण नहीं था, जिसका कि इसका भवसरानुवृत्त नाटकीय प्रतीकात्मक प्रयोग।

चीन का आर्थिक राजनय पड़ोस में एशिया तक ही सीमित नहीं रहा है। 1960 बाये दशक में जब चाऊ-एन-नाई अपने अत्यन्त-नछरी (यात्रा) पर निकले, तो फ्रान्स के निर्यात के लिए बड़े उत्साह के साथ अश्लीला में समुक्त उद्यम के उत्पादन की घोषणा की गयी। इनका तबने प्रसिद्ध उदाहरण तबाम-चीन रेलमार्ग परियोजना (तबानिया में) थी। आपे समकर भले ही इसके क्रियान्वयन में अड़चनें आयी, लेकिन इससे उसका महत्व कम नहीं होता। मुख्य मुद्दा यह है कि जिन समय विदेशी सहायता विदेश नीति के क्षेत्र में पुराधनर बनती आ रही थी, उस समय चीन अपने राष्ट्रीय हित में इसका प्रयोग करने में हिंसी से पीछे नहीं था। मात्रो युग में इसको तर्कनय सिद्ध करने के लिए विचारधार का नुस्खा जरूर बढ़ाया जाता रहा।

चीनी आर्थिक राजनय के विषय में दो बातें विशेष रूप से रेखांकित करने की हैं। आरम्भिक मोविपन अनुभव के बाद चीन स्वयं अपने आरको पूँजी और टेक्नोलॉजी के आपात से मुक्त रहने का प्रयत्न करता रहा है। वहाँ बाजा के रूप में कुरखी को प्रभावित करने की उनकी समता बड़ी है, वहीं समने बाचक की मुद्रा कमी रहन नहीं की और उसी अपनी विदेश नीति अमानाम्य रूप से स्वाधीन रही है। दूसरी बात, चीन आरम्भ से ही अपने आरको विस्मयगीत तीनरी दुनिया का दिला घोषित करता रहा है और उनके शक्तिशाली तैवर उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद के प्रवर विरोध के रहे हैं। इस कारण चीन के साथ आर्थिक-तकनीकी सहकार उन देशों के लिए विशेष रूप से सह्य और बाध्यक रहा है, जिन्हें शेष विश्व हिमक जन-मुक्ति सचाम में मन्त्रता के कारण सतरनाक अछूत मन्त्रता रहा। चीनी नेता निरन्तर इन बात पर बत देते रहे हैं कि उनके मूल्यामक तकनीकी गमाना, पूँजी या सामरिक कोमत पर नहीं, यन्त्र-शक्ति और मौलिक आविष्कारों पर आधारित है। बाजः अरो-एशियाई देशों के लिए ये अधिक सच है।

हान के वर्षों में विदेश नीति के आर्थिक उपकरण का एक ओर विनोदीकृत

रखा कि समुक्त राष्ट्र सच में चीन को उसका न्यायोचित स्थान दिलाया जाये। यहाँ दो-तीन महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान दिलाया जाना जरूरी है। 1949-50 में अफ्रीका और एशिया में स्वाधीन देशों की संख्या बहुत कम थी। दक्षिण-पूर्व एशिया में मलयेशिया, सिंगापुर तथा हिन्द चीन के देश पराधीन थे और उत्तरीय एश एशिया की महाद्वीप के अन्य देश गुलामी का बोझ ढो रहे थे। इन परिस्थितियों में चीन को अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने के लिए भारतीय राजनय की सक्रियता ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। इस विषय में भारत का वस्तुनिष्ठ, सैद्धान्तिक आचरण इस बात में प्रमाणित होता है कि 1957 से 1962 तक चीन के साथ समयपक्षीय सम्बन्धों में निरन्तर बिगाड़ के बावजूद भारत ने इस विषय में चीन का समर्थन नहीं छोड़ा।

चीन की अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता का एक और पहलू है। मान्यता की वैधानिकता से अधिक महत्वपूर्ण बात साम्यविक प्रतिष्ठा की है। इस प्रतिष्ठा को प्रभाव में रूपान्तरित किया गया है। इस मिलकिल में भी भारत द्वारा चीन की तरफदारी प्रभावशाली रही। तिब्बत सम्बन्धी पंचमील समझौते (1954) पर हस्ताक्षर हो या बाहुग में आयोजित अंग्रे-एशियाई सम्मेलन (1955) में चीन की आमन्त्रण, भारत के मन्त्रिमण्डल से चीन की अन्तर्राष्ट्रीय छवि निर्धारित गयी। नेहरू और कृष्णा मदन हमेशा इस बात पर जोर देने रहे कि नया चीन साम्यवादी और जुझारू जलें ही हो, उस हिंसक, आक्रामक और विस्तारवादी समझना गलत है। यदि उसे अन्तर्राष्ट्रीय विरादरी और समुक्त राष्ट्र सच में उसका न्यायोचित स्थान मिल जायेगा तो वह सन्तुष्ट हो जायेगा तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए अस्थिरता या संकट पैदा करने वाला नहीं होगा। 'हिन्दी चीनी, भाई भाई' और बाहुग वाले दौर में इस बात के अनक प्रभाव जुटाये जा सकते थे कि चीन की नई सरकार व्यावहारिक है और उसका साथ शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व सम्भव है। इन वर्षों में चीन ने अप्रत्याशित धीरे-धीरे का परिचय दिया और अमरीका द्वारा बारम्बार तिरस्कार, अपमानित होने पर भी मरम नहीं खाया। इसका अच्छा उदाहरण हिन्द चीन के मामले में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय जेनवा सम्मेलन है, जिसमें डेमो ने मुलहू के लिए बताया चाऊ एन लाई का हाथ ठुकरा दिया। इन वर्षों में अमरीका में सीनेटर मैकार्थी का उग्र साम्यवाद-विराधी उपान पुर जारा पर था और साम्यवादियों के साथ किसी भी तरह के सवाद को आरम्भ करना घोर दण्ड-द्रोह की धेनी में रखा जा सकता था। इन दौरान अमरीकी विदेश विभाग में अनेक समझदार और दूरदर्शी व्यक्तियों को अपनी ईमानदारी का मोन चुकाना पड़ा। जिस किसी ने चीन के साथ रचनात्मक सहकार का एक अपनाया उस 'साम्यवादी एजेंट' के रूप में बदनाम किया गया। विदेश सेवा के अधिकारियों के अतिरिक्त पत्रकारों, प्राध्यापकों को भी चीन की पक्षधरता के कारण दण्डित किया गया। विदम्बना तो यह है कि चीन के मित्रों का दमन (persecution) सोवियत सच में मित्रों की अपेक्षा कई गुना ज्यादा दृढ़ था। यह स्थिति 1950 के दशक में निरन्तर बनी रही।

1960 वाले दशक में चीन द्वारा परमाणु अस्त्र हासिल करने के बाद अमरीका के लिए यह असम्भव हो गया कि वह अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति के रूप में चीन की उपेक्षा करे। सोवियत-चीन विग्रह के बाद यह भी स्पष्ट हो गया कि सोवियत सच के साथ तनाव-शैथिल्य में स्वयंसेव चीन के साथ भी अमरीका के सम्बन्धों का सामान्यीकरण

‘देतात’ के अन्त, विश्व के बहुपक्षीकरण तथा नये शीत युद्ध के आविर्भाव ने चीनी विदेश नीति के नियोजकों-निर्वाहकों को इन विविध उपकरणों के इच्छानुसार प्रयोग का अवसर दिया है।

चीन की मान्यता का प्रश्न (Question of China's Recognition)

चीन में साम्यवादियों द्वारा सत्ता ग्रहण करने के साथ अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने के प्रश्न ने प्राथमिकता ग्रहण की। जिन परिस्थितियों में चीनी साम्यवादियों ने चांग काई शेक को अपदस्थ किया, वे वृहद् युद्ध वाली थी। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसी परिस्थिति में यह बात बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है कि नई सरकार को कौन-कौन अन्तः राज्य मान्यता देते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय कानून में सदाय स्थितियों में ‘वास्तविक मान्यता’ (de facto) तथा ‘कानूनी मान्यता’ (de jure) में अन्तर है। चीन के संदर्भ में यह गुत्थी और भी जटिल इस कारण हो गयी कि चांग काई शेक का पूरी तरह खण्डना नहीं किया जा सका। चीनी मुख्य भाषा (मैनलैण्ड भाषा) में पराजित होने के बाद वह अपने निकटतम सहयोगियों को साथ लेकर ताइवान द्वीप में जा बसे। उन्होंने चीन की असली सरकार होने का दावा बरकरार रखा। स्पष्ट है कि यह किसी प्रवासी या निर्वासित सरकार को नये शिरे से मान्यता देने का प्रश्न नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चांग काई शेक सोवियत संघ समेत सभी मित्र-राष्ट्रों के सन्धि-मित्र रहे थे और जापान की पराजय के बाद सुदूर पूर्व में विजय के बाद वाली घन्दर बाट में उनका अपना हिस्सा चाहना स्वाभाविक था।

युद्ध के वर्षों में ही अटलांटिक चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया तथा वीटो सम्पन्न सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में एक स्थान चीन के लिए सुरक्षित रखा गया। इस तरह साम्यवादी चीनी सरकार को दी जाने वाली मान्यता का सवाल न सिर्फ उनकी अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृति से जुड़ा था, बल्कि इसी पर यह दारोमदार भी टिका था कि सुरक्षा परिषद में चीनी वीटो का प्रयोग किस तरह किया जायेगा?

दुर्भाग्यवश चीन की मान्यता का प्रश्न शीत युद्ध की रस्माकसी से जुड़ गया। सोवियत संघ ने तत्काल साम्यवादी चीन की मान्यता दे दी। अमरीकियों को लगने लगा कि साम्यवादी चीन के आविर्भाव के साथ सुदूर पूर्व में शक्ति-सन्तुलन उनके विपक्ष में बदल रहा है। सत्ता भूत सम्भालने के साथ नई चीनी सरकार की भोषणाएँ और उसका आचरण पश्चिमी ताकतों के लिए चिन्ताजनक था। माओ और उनके सहयोगियों ने तिब्बत को मुक्त कराने का अभियान 1950 में आरम्भ किया और चीन में रह रहे उच्छृंखल विदेशी राजनयिकों के विशेषाधिकारों में नटौती करती शुरू कर दी। इससे अमरीका ही नहीं, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया आदि का सतर्क होना स्वाभाविक था। अगर पश्चिमी नजरिये से देखें तो कोरियाई प्रायद्वीप में 39वीं समानान्तर रेखा को पार कर चीनी जात सेना का अतिक्रमण अमरीका के साथ अभोषित युद्ध का भूतपात कर चुका था।

जहाँ पश्चिमी देशों ने चीन की मान्यता देने में हिचकियाहट दिखायी, वहीं भोषित अफ्रो-एशियाई राष्ट्रों ने पुनर्जागृत चीन का सहर्ष स्वागत किया। चीन की मान्यता देने वाला पहला राज्य जर्मा था और भारत ने इस अभियान को तेज

माओ के बाद चीनी विदेश नीति निरन्तरता एव परिवर्तन (Chinese Foreign Policy after Mao)

अधिकतर विद्वान अध्ययन की मुविधा की दृष्टि से चीनी विदेश नीति को माओवादी विदेश नीति और माओ के बाद की विदेश नीति में बांटते हैं। इसके कई तकसगत कारण हैं। माओ के जीवन काल में उनके व्यक्तित्व का प्रभाव और उनके जीवन दर्शन की अमिट छाप चीनी विदेश नीति के निर्धारण पर पड़ती रही है। वह 'महान खेवनहार' के नाम से जाने जाते थे। अपनी जीवन सध्या में उनकी स्थिति देवपुत्र (Sun of Heaven) या पारम्परिक चीनी सम्राटों जैसी हो गई थी। यह मित्र अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में व्यक्ति विशेष की भूमिका से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है। माओ मित्र मात्रवाद नहीं थे। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अपने विश्लेषण में मार्क्स और लेनिन की विरासत में मौलिक भी बहुत कुछ जोड़ा था। उदाहरणार्थ, 'विरोधी और विरोध रहित अन्तर्द्वन्द्व' (Antagonistic and Non-antagonistic Contradictions) की स्थापना के इसी आधार पर 'सैद्धान्तिक शुद्धि' और लाभप्रद अवसरवादिता में वह जीवन भर तालमेल बिठाते रहे। चीनी विदेश नीति का नियोजन कभी दि 'ग्रैंट लीप फॉरवर्ड' (The Great Leap Forward) के आधार पर किया जाता था तो कभी 'लेट हन्ड्रेड फ्लावर्स ब्लूम' (Let hundred flowers bloom) की घोषणा दान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व का आह्वान करती। आर्थिक विकास के मामले में माओस्त तुल्य स्वावलम्बी आत्म-निर्भरता के पक्षधर थे। हालांकि माओ के चिन्तन के बारे में सरकारीकरण के खतरे से बचने की जरूरत है परन्तु यह उल्लेख किया जाना भी अनिवार्य है कि 'राजनीतिक शक्ति बढ़क की ताल से पैदा होनी है' या 'एक दिन मसाले के सारे गीब ममूड सहरो की घेर लेंगे और उन्हें घुटने टेकना पड़ेगा' विदेश बरेंग, जैसी उनकी प्रान्तिकारी स्थापनाओं में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर भारी अमर डाला।

इसके विपरीत माओ के उत्तराधिकारी दैंग सियाओ पिंग की छवि सशोधनवादी (Revisionist), 'अपेक्षाकृत व्यावहारिक' (Practical) और यथार्थवादी (Realist) पक्ष की जाती है। उन्होंने न तो कभी विदेश नीति और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के सैद्धान्तिक पक्ष को अति महत्वपूर्ण बतलाया और न ही कभी आधुनिकीकरण और विकास के लिए विदेशी सहायता स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट दिखायी। चार आधुनिकीकरणों (रक्षा, कृषि, उद्योग और विज्ञान व टेक्नोलॉजी) का उनका महत्वाकांक्षी पायत्रम विदेशी टेक्नोलॉजी और पूँजी के आयात पर टिका हुआ है। उन्होंने सत्ता ग्रहण करने के साथ ही लान रक्षकों एव अति उत्साही आग्रामक तबरे वाले पार्टी कार्यकर्ताओं पर अनुश्रुता लगाया और चीनी राजनय की जिम्मेदारी एक बार फिर पदेवर अधिनायिका के हाथ में सौंप दी। यह भी जाड़ा जा सकता है कि सुरक्षा परिपद् के स्थायी मदस्य के रूप में चीन का राजनयिक आचरण इस पद की प्रतिष्ठा के अनुकूल ही रहा है—अर्थात् यथास्थिति का पोषण। अगर ज्यादा गहराई में न जायें तो हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि माओ के बाद के युग में चीनी विदेश नीति में बुनियादी परिवर्तन हुआ है। मक्षेप में कहा जा सकता है कि प्रान्तिकारी उपान का स्थान व्यावहारिक दूरदर्शिता में ले लिया है। परन्तु गहराई में जाय बिना काम नहीं करना और सब बिल्कुल ही दूसरे तरीके

हो जाये, यह आवश्यक नहीं। विद्यतनाम युद्ध में अमरीकी स्थिति पतली होने के कारण अमरीकियों के लिए यह भी असम्भन हो गया कि चीन के साथ सवाद से वे कतराते रहे। वस्तुस्थिति स्वीकार करने के बाद वैधानिक मान्यता देने में देर नहीं की जा सकती थी।

इस समय तक अमरीका के अनेक सन्धि-मित्रो तथा शिष्टिवाचनचरो ने अपने राष्ट्रीय हितों के दबाव में चीन के साथ अपने सम्बन्ध सामान्य कर लिये थे। इनमें फ्रांस, ब्रिटेन और ५० जर्मनी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जापान भी इस ओर अग्रसर होने लगा था। तनाव संश्लेष की सीमाएँ दृष्टिगोचर होने के साथ अमरीका भी नीति-परिवर्तन के लिए उद्यत हुआ। इस सन्दर्भ में पाकिस्तान ने, विशेषकर तत्कालीन विदेश मन्त्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने गुप्त राजनय द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। हेनरी किमिजर ने 'दी व्हाइट हाउस इयर्स' नामक अपने सस्मरणों में इस राजनय का विस्तृत व्योरा प्रस्तुत किया है। इस बात का भी भ्रष्टा असर पड़ा कि तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति रिक्सन विदेश नीति विशेषज्ञ थे और उस समय उनकी आन्तरिक स्थिति इतनी निरापद थी कि वह इस तरह कि रचनात्मक पहल की जोखिम उठा सकते थे। फरवरी, 1972 में रिक्सन ने चीन-यात्रा की और माओ तथा चाऊ एन साई के साथ परामर्श किया। यह सब जल मथार साधनों से लोकप्रिय मनोरंजन और विस्तृत विश्लेषण के विषय रहे। पिब थोम राजनय हो या एडगर स्नो जैसे पत्रकारी का योगदान, वे सभी इसी बात को दर्शाते हैं कि इस समय तक वातावरण चीन के पक्ष में ढल चुका था और उसको सं० रा० संघ में स्थान दिलाया और अधिक टाला नहीं जा सकता था।

अमरीका ने चीन के साथ सम्बन्धों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया आरम्भ होने के बाद भी तत्काल राजपूतों का आदान-प्रदान नहीं किया और विशेष दूत की व्यवस्था से ही सत्तोष किया। मगर अमरीका ने यह स्पष्ट करने में देर नहीं लगायी कि वह वास्तव में जनवादी चीन को मान्यता दे चुका है। अमरीका द्वारा 'नए' माओवादी चीन को मान्यता दिये जाने का संयोज सं० रा० संघ की सुरक्षा परिषद में चीन के प्रवेश (अक्तूबर, 1971) के साथ हुआ। इससे यह बात मनीमालि प्रमाणित हो जाती है कि चीन की मान्यता का प्रश्न विवादास्पद सिर्फ इसलिये बना था कि अमरीका मान्यता देने को तैयार न था। अमरीकी मान्यता मिल जाने के बाद चीन के प्रयोग की सम्भावना के साथ चीन का प्रभुत्व बड़ा और माओ के बाद चार महान भाषुनिरीकरणों की बात सोची जा सकी। 1971-72 में ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विचारियों के लिए 'दो चीनो' का सवाल निरर्थक हो गया। इसके बाद भले ही चीन को महाशक्ति के रूप में फरवरी का दर्जा न मिला हो, किन्तु किसी भी अन्य बड़ी शक्ति से अधिक प्राथमिकता मिल चुकी है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि चीन को अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता का प्रदान मूलतः अमरीका-चीन सम्बन्धों का एक पहलू था और इसका अध्ययन इस विषय से हटकर नहीं किया जा सकता। अमरीका द्वारा मान्यता दिये जाने के बाद भी कुछ अन्य पड़ोसी देशों के साथ 'पूर्ण मान्यता' के अभाव में चीन के सम्बन्ध आज तक अमहज बने हुए हैं। इनमें मलयेशिया व इण्डोनेशिया प्रमुख हैं। कुछ तनाव पोल-पोट की प्रवासी सरकार के कारण कपुचिया एवं वियतनाम के साथ भी है। अब ऐसा भोचना तर्कसंगत है कि आगामी कुछ वर्षों में मान्यता का प्रदान चीनी राजनय के लिए महत्वपूर्ण बना रहेगा।

केन्द्र'। सभी विदेशी बहुधा समझे जाते थे। अनेक विद्वानों ने चीनी विदेश नीति को केन्द्रीय राज्य होने की कूठा (Middle Kingdom Complex) से ग्रस्त, देन-प्रेमाघ (Chauvinist) तथा विदेश भयाभात (Zenophobic) समझा है। दंग मियाओ पिंग के पहले के सभी प्रशासनों के राजनयिक सम्बन्धों में ये तत्व आमानी से पहचाने जा सकते हैं। अब तक भले ही दंग मियाओ पिंग की विदेश नीति में इनका कर्कश स्वरूप प्रकट नहीं हुआ है, फिर भी भारत और वियतनाम के साथ चीन के सम्बन्धों में पुराने आचरण की अनुमूर्ख आज मुनी जा सकती है।

(2) विचारधारा व राष्ट्र हित का अन्तर-द्वन्द्व नहीं—चीन की विदेश नीति में सीधियत सध की तरह विचारधारा और राष्ट्र-हित का अन्तर द्वन्द्व नहीं झलकता क्योंकि सत्ताह्वय मरफारें आवश्यकतानुसार सैद्धान्तिक परिवर्तनाओं-अवधारणाओं को संशोधित-परिमाजित करती रही हैं। अमल में, भाओ की दायनिकता और दंग मियाओ पिंग की व्यावहारिकता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

(3) सर्वोच्च नेता के व्यक्तित्व की अमिट छाप—चीन की विदेश नीति की एन और उल्लेखनीय विशेषता यह है कि भू-राजनीतिक स्थिति और ऐतिहासिक परम्परा की अपेक्षा सर्वोच्च नेता के व्यक्तित्व की गहरी छाप विदेश नीति नियोजन और उसके संचालन पर पड़ती रही है। साथ ही सत्तार के किसी भी दूसरे देश की अपेक्षा चीन अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सैनिक उपकरणों और बल प्रयोग के अवलम्बन को तैयार रहा है।

(4) छद्म पैतरेबाजी—जैसाकि रोम टेरिल ने लिखा है कि चीनी विदेश नीति के नियोजन और सम्पादन के विस्तारण के लिए एक वाद्य बृद (orchestra) के रूप का सहारा लिना जा सकता है, जिसमें कभी तो रणघोष के अन्दाज में जोरदार झोल-जगाड़े बजाये जाते हैं, और कभी मधुर मिसन यामिनी (romantic tryst) के लिए उपयुक्त अवेसी बाँसुरी का कोमल-सुमधुर प्रयोग किया जाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि चीन के असादा कोई ऐसा दूसरा दण नहीं, जो इतनी सहजता के साथ टकराव से शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व में ध्रुव तब लोट सकता है। चीनी विदेश नीति की इस विशेषता के लिए बहुत बड़ी सीमा तक उनकी आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्था जिम्मेदार है, जिसमें आस्मातापन (self-criticism) की पद्धति का महारा नजर जतीव की गतिधियों के लिए पूर्ववर्ती शासक-नेताओं की उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। परन्तु आज सत्तार के अनेक दण चीन के साथ राजनयिक सम्बन्धों के संचालन का इतना अनुभव प्राप्त कर चुके हैं कि वे चीन के छद्म पैतरा और वास्तविक स्थिति में अन्तर कर सकते हैं। भाओ के युग में चीनी विदेश नीति कई बार ज़नूटी एव 'शान्तिकारी' लगती थी, परन्तु आज वे 'विशेषताएँ' उतनी जस्वाभाविक नहीं जान पड़ती। यामकर मुरक्षा परिपद् की स्थायी सदस्यता की प्राप्ति के बाद चीन का आचरण किभी भी दूसरी यथा-स्थिति पोषक बड़ी शक्ति की तरह प्रत्यागित (predictable) रहा है। अमरीका और रुम की तरह चीनी विदेश नीति में भी उसकी भौगोलिक स्थिति एव उसके ऐतिहासिक अनुभव का प्रभाव देखे जा सकता है, परन्तु ऐसा कुछ नहीं, जिस विदेश नीति के सुननात्मक अध्ययन के विद्यार्थी अटपटा महसूस करें।

मानने आयेगे।

माओ की बहुप्रचारित क्रान्तिकारिता का आवरण हटाने का प्रयत्न करें तो यह बात स्पष्ट होते ज्यादा देर नहीं लगेगी कि चीन के राष्ट्रीय हित के संवर्धन-संरक्षण के लिए माओ की व्यावहारिकता देंग सियाओ पिंग से किसी भी तरह कम नहीं रही। इसे प्रमाणित करने के लिए दो-बार सदाहरण देना काफी होगा। उसूरी नदी के तट पर 1969 में सोवियत सघ और चीन के बीच सैनिक मुठभेड़ भले ही हुई हो, मगर रेखांकित किये जाने लायक बात यह है कि दोनों देशों के बीच 1960 में ही मतभेदों का सिलसिला शुरू हो जाने के बाद चीन ने इतना समय बरता कि ऐसे बबमर और न आयें। इसी तरह यह बात याद रखने लायक है कि अपने प्रमुख शत्रु अमरीका के साथ सम्बन्धों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया का मूलपात माओ ने अपने जीवन काल में ही कर दिया था। जहाँ तक देंग सियाओ पिंग का प्रश्न है, समाजवादी धामन प्रणाली के अनुसूच सर्वोच्च नेता को बने-बने रहने के लिए अपनी निर्द्वन्द्व छवि प्रस्तुत करनी पड़ती है। परन्तु देंग सियाओ पिंग माओ सरीखे करिश्माती व्यक्तित्व के स्वामी नहीं हैं और न ही उनका कोई मौलिक विद्व दर्शन है। देंग सियाओ पिंग की चार आपुनिकीकरणों वाली विदेश नीति की व्याख्या माओ की 'विरोधी एवं विरोध-रहित अतद्वन्द्व' वाली स्थापना और 'दि जामट सीप फारवर्ड' की महात्वाकांक्षा के आधार पर वलूवी की जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र सघ में चीन का राजनयिक आचरण भी माओ के जीवन काल में तय किया जा चुका था। स० रा० सघ में या अन्यत्र कई राजनयिकों की पदावनति, स्थानान्तरण आदि से पश्चिमी चीन विरोधियों ने चीन की विदेश नीति में परिवर्तनों के बारे में अटकलें लगायी हैं। परन्तु, इस तरह की घटनाओं का मूल कारण चीनी पार्टी में सत्ता संघर्ष एवं आन्तरिक नीति के सम्बन्ध में विवाद-मतांतर अधिक रहे हैं।

देंग सियाओ पिंग ने विपत्तनाम की 'सबक' सिलाने के लिए जो सैनिक अभियान माया, उसके दौरान उन्होंने स्वयं इसकी तुलना 1962 में माओ के कार्य-काल में भारत को मित्राय गये 'सबक' से की थी। इसी तरह परमाणु दत्तशास्त्रों के मामले में चीनी विदेश नीति में माओ युग से आज तक कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाई देता। यह ठीक है कि देंग सियाओ पिंग बार-बार 'तीन विस्त्रों' की अय-धारणा प्रस्तुत नहीं करते परन्तु चीन का राजनयिक आचरण इस मामले में एक की कोई गुनाह नही रखता कि महाशक्तियों की वास्तविकता और तीसरी दुनिया के विकास की पुनर्निर्माण के बारे में देंग सियाओ पिंग ना सोच माओ के चिन्तन से दुनियादी तौर पर फर्क है।

चीनी विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएँ (Salient Features of Chinese Foreign Policy)

चीन की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएँ निम्नांकित हैं—

(1) केन्द्रीय राज्य होने की कृष्ठा से प्रसूत—चीनी सम्राटों के काल से परिनामित पारस्परिक चीन की भौगोलिक सीमा को सभी चीनी सरकारें निर्विवाद मानती हैं। माचू, कुमिनताग, माओवादी तथा माओ की परवर्ती सभी चीनी सरकारों में जातीय अहंकार और विदेशियों के प्रति मन्देह का भाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। पहले चीनी सम्राट अपने को 'देवपुत्र' मानते थे और चीन को 'सम्पत्ता का

19वीं शताब्दी में जब अन्य पश्चिमी औपनिवेशिक शक्तियाँ चीन की 'बंदरगाहों' में लगी हुई थी, तब इस घोषण-उत्पीड़न में अमरीका का योगदान नहीं रहा था। इस दौर में अनेक अमरीकी मिशनरियों ने चीन में ईसाई धर्म का प्रचार कार्य किया। चीन के मानचू वन के अन्तिम वर्षों के बारे में उनके द्वारा जुटायी जानकारी काफी प्रामाणिक थी। 19वीं सदी, विशेषकर गृह-युद्ध के बाद का काल, अमरीका में 'पूँजीवाद के प्रसार का युग' था। विदेशों में लोग यह समझने लगे कि वे व्यक्तिगत समृद्धि की प्राप्ति अमरीका में कर सकते हैं, जहाँ उन्नति के अवसर थे। ऐसा सोचने वाले अनेक चीनी अमरीका पहुँचे। इतनी बड़ी समस्या में कि आज भी न्यूयार्क और सान फ्रांसिस्को जैसे शहरों में 'चायना टाउन' के नाम से प्रतिष्ठित इनकी बस्तियाँ महत्वपूर्ण हैं। अनेक समृद्ध चीनी अमरीका में पढ़ने-लिखने पहुँचते थे। इनकी समस्या मने ही बहुत ज्यादा न रही हो, परन्तु उनका प्रभाव कम नहीं आँका जा सकता। बाद में इनमें से अनेक के सामग्र्य व्यापारिक सम्बन्ध अमरीकियों के साथ स्थापित हो सकते थे। सन यात सेन, चांग काई शेक क निकट सम्बन्धी मूग परिवार की स्थिति ऐसी ही थी।

जब साम्यवादियों ने छापामार युद्ध आरम्भ किया, तब अनेक अमरीकी पत्रकार इन घटना का आँखों से देखा हाल बखानने के लिए चीन पहुँचे और दक्षिण-पूर्व एशियाई रण-क्षेत्र में तथा जापान पर काबू पाने के मन्द्य में चीन की सामरिक उपयोगिता अमरीका के लिए उजागर हुई। 'पर्स बक' के उपन्यासों, थियोडोर ड्रूयेर के रिपोर्टों और एडगर स्नो की पुस्तक पत्रकारिता से इसी बात का पता चलता है।

1949 में चीन में साम्यवादी सरकार के गठन के बाद शीत-युद्ध के काल में दूरदर्ष्टि का धोर अभाव दिखात हुए अमरीका ने चीन को अपना शत्रु मानना आरम्भ कर दिया और उसे मान्यता देने से इकार कर दिया। तिब्बत की मुक्ति और कोरिया युद्ध के बाद अमरीका चीन सम्बन्ध और भी तनावग्रस्त हुए। उनके बीच सम्बन्धों का सामान्यीकरण तनाव-पूर्णता (अमरीका व रूस के बीच) की प्रक्रिया के काफी आगे बढ़ जाने व बहुत बाद 1971 में शुरू हुआ।

कट्टर शत्रुता—आज अमरीका व चीन आपसी सम्बन्ध मजबूत करने के लिए बताव नजर आत है, मगर पहल व एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे। द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद अमरीका और मावियत मध्य विश्व महाशक्ति के रूप में उभर और दोनों न अन्य राष्ट्रों को अपने-अपने प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहें। अमरीका ने जहाँ पूँजीवादी देशों के सम का नेतृत्व किया, वही सोवियत मध्य में साम्यवादी देशों की बागडोर जपन हाथ में ली। 1949 में जब चीन में साम्यवादी सरकार कायम हुई तो वह मावियत मध्य में शामिल हुआ और उस अपने चहुँमुखी विकास के लिए सोवियत मध्य से भारी मात्रा में मदद भी मिली। उधर चीन में जगमग हुए ताइवान को अमरीकी आशीर्वाद प्राप्त था, जिसकी बदौलत वह समुक्त राष्ट्र मध्य जैसे महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मण्डल का मददगार बनने के अलावा मुख्यतः-परिषद का स्थायी मददगार भी बन बैठा। चीन जहाँ एक ओर अमरीका को पूँजीवादी, साम्राज्यवादी एवं नव-उपनिवेशवादी की सजा देकर उसकी नीनिया का विरोध करता रहा, वहीं दूसरी ओर अमरीका ने एशिया में साम्यवाद का विस्तार रोकने के लिए चीन की धराबन्दी करना आरम्भ किया। अमरीका ने अनेक एशियाई देशों के साथ मिलकर 'मण्टा' व 'मिएटा' नामक मैत्रिक मण्डल बनाए और इन देशों में साम्यवाद का विस्तार रोकने

चीनी विदेश नीति का भविष्य (Future of Chinese Foreign Policy)

चीन में साम्यवादी सरकार का गठन हुए चार दशक समाप्त हो गये हैं। इस दौर के उतार-चढ़ाव को देखते हुए यह अनुमान लगाने का प्रयत्न किया जा सकता है कि भविष्य में चीनी विदेश नीति की क्या दिशा रहेगी? जैसाकि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि चीन की विदेश नीति में छद्म-हित के आधार पर मित्रान्त और यथार्थ के बीच सन्तुलन-सम्योकरण बरकरार रहेगा। चीन ने अमरीका के साथ सम्बन्ध सुधार के बाद, सोवियत संघ के साथ राजनयिक सम्बन्धों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया आरम्भ की थी। 1987 में मंगोलिया में सोवियत विदेश मंत्रों ने इन बातों के स्पष्ट संकेत दिये कि कम चीन के साथ तनाव घटाने के लिए तैयार है। इसी प्रकार जब गोर्बाच्चेव ने दक्षिण-पश्चिम-प्रदान्त क्षेत्र में स्थिरता बनाये रखने के लिए एक योजना प्रस्तावित की, जिसके प्रचलन के लिए अमरीका, जापान और आस्ट्रेलिया के साथ-साथ चीन को भी आमन्त्रित किया। भारत-पाक और भारत-चीन विवाद के सन्दर्भ में भी बाद की सोवियत घोषणाएँ यही मत अभिव्यक्त करती रही कि भविष्य में उनका खैया मित्रों से फर्क करने वाला नहीं रहेगा। इस सबके आधार पर यह कहा जा सकता है कि आगामी वर्षों में चीन एशिया के राजनीतिक समूह पर प्रमुख हस्ती के रूप में प्रतिष्ठित और स्वीकृत हो जाने के बाद अनेकांकृत अधिक सयत और पया-स्थिति पोषक आचरण करेगा। इस मिलनिले में एक महत्वपूर्ण बात का जिक्र जरूरी है। परमाणु प्रक्षेपास्त्र सम्पन्न होने के बाद भी समुचित नौसैनिक शक्ति के अभाव में चीन अपनी प्रभुता का प्रक्षेपण करने में अमरीका की तुलना में दुर्बल है। निश्चय ही आगामी वर्षों में वह यह अनमर्त्यता दूर करने की पूरी कोशिश करेगा।

इनके अतिरिक्त दो-चार ऐसी अन्य बातें हैं, जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। अब तक अमरीका-चीन सम्बन्धों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया की सीमाएँ-सम्भावनाएँ स्पष्ट हो चुकी हैं। चीन ने चार महान् आधुनिकीकरणों के मिलनिले में जिस मुक्त व्यापार और मुनाफाखोरी की नीति को अपनाया, उसके चीनी सामाजिक व्यवस्था पर स्पष्ट कुप्रभाव डीखने लगे हैं। राजनीतिक प्रणाली पर इसके दबाव बहुत लम्बे समय तक रोके नहीं जा सकते। 1987 के पूर्वार्द्ध में छाप एष बोर्डिक वर्ग के व्यापक असन्तोष-आन्दोलन और इनको अनुशासित करने के सरकारी प्रयत्नों से यह बात भनी-गति प्रमाणित होती है। इस बात को भी नहीं भुलाया जा सकता कि देश मियाओ पिंग क्योचूट व्यक्ति हैं। यह सम्भावना नगण्य नहीं कि उनके बाद उनकी व्यावहारिक नीतियों का पुनर्मूल्यांकन आरम्भ कर दिया जाये, जिसके सहज विदेश नीति के सन्दर्भ में व्यापक फेर-बदल हो सकता है। तब भी ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं कि भविष्य में चीन फिर से सामोकासीन एकात्मतासी या दुष्प्रकार रूप ग्रहण करेगा।

चीन-अमरीका सम्बन्ध (Sino-U.S. Relations)

अमरीका और चीन के बीच सम्बन्ध हमेशा में वैमनस्यपूर्ण नहीं रहे हैं।

कर सकता था।

इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जनवरी, 1979 में तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने चीन के साथ पूर्ण स्तर के कूटनीतिक सम्बन्ध कायम करने की घोषणा कर दी। अमरीका ने ताइवान के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध और आपसी सुरक्षा मन्त्रि तोड़ने के अलावा उसे (ताइवान) साम्प्रदायी चीन का कानूनी तौर पर एक अंग मान लिया। परन्तु अमरीका ने ताइवान-मसला के शान्तिपूर्ण समाधान और भविष्य में उसके साथ आर्थिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध कायम रखने की बात कही। इसी बढ़ती निकटता के कारण अमरीका व चीन ने अफगानिस्तान, कम्बुधिया आदि अनेक मसलों पर समान रुख अपनाया। इस बीच दोनों देशों में अनेक प्रतिनिधि मण्डलों का आदान-प्रदान हुआ और सहयोग-समझौते हुए।

जनवरी, 1981 में जब रोनाल्ड रीगन ने सोवियत संघ के साथ कड़ा रुख अपनाते की घोषणा के साथ अमरीकी राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण किया तो चीनी नेता काफी खुश नजर आये, क्योंकि उनका अनुमान था कि वे रीगन के इस रुख से अमरीका के साथ कूटनीतिक नाज उठान में अधिक भयंर्य होंगे, वही दूसरी ओर अमरीका से निकटता की तुरूप दिखाकर सोवियत संघ के साथ सम्बन्ध सुधार में सौदेबाजी की स्थिति भी मजबूत कर सकेंगे। मगर न तो रीगन ने चीन के प्रति अधिक उत्साह दिखाया और न ही सोवियत संघ ने। अगस्त, 1982 में अमरीका और चीन ने संयुक्त विज्ञप्ती में घोषणा की कि 'चीन शान्तिपूर्ण तरीके से ताइवान का अपने देश में विलय करेगा, जबकि अमरीका ताइवान को धीरे-धीरे हथियार देना बन्द कर देगा।' मगर जुलाई, 1983 में अमरीका ने ताइवान को 5030 करोड़ डॉलर के हथियार बेचने की घोषणा की, जिसकी चीनी नेताओं ने बड़ा आलोचना की। अमरीका ने अपनी सफाई में कहा कि मुद्रा स्थिति बढ जाने के कारण ये हथियार विधान रक्षि के लगे हैं।

बढ़ते व्यापार सम्बन्ध—अमरीका और चीन के रिश्तों में इस ठडेन के बावजूद सम्बन्ध सुधार के लिए कूटनीतिक भागदौड़ जारी रही और आर्थिक सम्बन्ध भी मजबूत हुए। 1983 में तत्कालीन अमरीकी विदेश मन्त्री जार्ज शूल्ज, वाणिज्य मन्त्री मार्लकोन बालड्रिज और रक्षा मन्त्री केपमर बेनबर्गर चीन यात्रा पर गये। जनवरी, 1984 में चीनी प्रधानमन्त्री झाओ जियांग ने अमरीका की नौ दिवसीय यात्रा की। जहाँ तब आर्थिक सम्बन्धों का मवाल है, दोनों देशों के बीच 1971 में 960 करोड़ डॉलर का व्यापार हुआ था, जो 1983 में बढ़कर 43 अरब डॉलर हो गया, हालांकि 1988 में 14 अरब डॉलर का रिकार्ड व्यापार हुआ। चीन में अमरीका का प्रत्यक्ष पूँजी निवेश 500 मिलियन डॉलर है, जो चीन में किसी भी अन्य देश का सर्वाधिक विदेशी पूँजी निवेश है। बीजिंग में 120 अमरीकी कम्पनियों के प्रतिनिधि केन्टन तथा शंघाई में निवृत्त है। 1978 में लगभग 10 हजार अमरीकी पर्यटक चीन गये, जबकि 1983 में यह संख्या बढ़कर डेढ़ लाख हो गयी। चीन के 10-12 हजार छात्र व शिक्षक अमरीका में अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं। चीन के 23 में से 13 विदेश व्यापार कार्यालय अमरीका में हैं।

रीगन की अग्रेत, 1983 की चीन की छह दिवसीय यात्रा ने दौरान दोनों देशों ने बीच एक परमाणु समझौता हुआ, जिसके तहत अमरीकी कम्पनियाँ चीन में परमाणु रिएक्टर बनायेंगी। इनके अलावा दोनों देशों में आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक

के हेतु उन्हें विशाल मात्रा में सैनिक व आर्थिक मदद दी। अमरीका सुरक्षा-परिषद में 'वीटो' (निषेधाधिकार) के बूते पर चीन को संयुक्त राष्ट्र सभ का सदस्य बनने से भी रोकता रहा। इस प्रकार अमरीका व चीन एक-दूसरे के विरोधी रहे।

बदली परिस्थितियों में मेल-मिलाप—लेकिन छठे दशक के अन्तिम वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अनेक बुनियादी परिवर्तन होने शुरू हो गये। एक तरफ अमरीका व सोवियत सभ में शीत-युद्ध की घघकती ज्वाला की गर्मी कम होने लगी तो दूसरी ओर मोवियत सभ व चीन में वैचारिक मतभेद एवं राष्ट्रीय हितों के टकराव का सिलसिला शुरू हुआ। अब तक चीन ने अपनी सामरिक शक्ति और आर्थिक विकास के बल पर साबित कर दिया था कि वह भी विद्व की एक बड़ी शक्ति है। चीन को यह खतरा मलाने लगा कि सोवियत सभ के साथ उसके वैचारिक और सीमा सम्बन्धी मतभेद कहीं सैनिक मुठभेड का रूप न ले लें। वह अमरीका एवं सोवियत सभ में एताव-शेषित्व के प्रति भी चिन्तित था, क्योंकि इससे वह अपने आपको अलग-थलग पाने लगा। अतएव उसने अमरीका से सम्बन्ध कायम कर सोवियत खतरे को कम करने का निर्णय लिया। इससे वह एशिया में तनात अमरीकी सैनिकों के खतरे से भी मुक्त हो सकता था। दूसरी ओर अमरीका भी विश्व में बढ़ते सोवियत प्रभाव को रोकना चाहता था, लेकिन साथ ही वह चीन से सम्बन्ध सुधार रूपी तुरूप का इस्तेमाल कर सोवियत सभ के साथ साल्ट समझौते (सामरिक शस्त्र कटौती सम्बन्धी) और अन्य मसलों पर अपनी सौदेबाजी की स्थिति भी मजबूत करना चाहता था। इसके अलावा जापान तथा पश्चिम यूरोपीय देशों के साथ व्यापारिक प्रतिस्पर्धा तेज होने के कारण अमरीकी उत्पादों के निर्यात पर काफी प्रतिकूल असर पड़ा था, जिस कारण अमरीका को किसी नए बड़े बाजार की जरूरत थी। चीन इस दृष्टि से उसके लिए फायदेमन्द बाजार साबित हो सकता था। इस प्रकार अमरीका एवं चीन ने इसी बदली परिस्थितियों में एक-दूसरे का हाथ थामा।

अमरीका की त्रिकोणीय कूटनीति—जुलाई, 1971 में तत्कालीन अमरीकी विदेश मंत्री हेनरी किस्सिजर आठवीं अन्दाज में चीन गये। फरवरी, 1972 में तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने चीन-यात्रा की, जिसमें सोवियत सभ के ही नहीं, बल्कि अमरीका के मित्र-देशों के भी कान खड़े हो गये। अमरीका ने यही से अपनी 'त्रिकोणीय कूटनीति' का मिलासिला शुरू किया, जिसके तहत उसने अपने व सोवियत सभ के अलावा चीन को भी शक्ति का एक प्रमुख तीसरा केन्द्र माना। अमरीका व चीन में आर्थिक व सांस्कृतिक सम्बन्ध कायम हुए।¹ इसपर जनवरी, 1976 में चाऊ एवं लाई तथा सितम्बर, 1976 में माओत्से तुंग के निधन के बाद चीन में नया नेतृत्व उभरा, जिम्हने नई नीतियों की घोषणा की। दंग लियाओ पिंग के नेतृत्व में चीन ने कृषि, रसायन, उद्योग एवं विज्ञान व टेक्नोलोजी नामक चार क्षेत्रों में आधुनिकीकरण करने के कार्यक्रम को चलाया। चीनी नेताओं ने इस मिल-सिले में पश्चिमी देशों और सामकर अमरीकी पूंजी और टेक्नोलोजी में अत्यधिक दिनचस्पी दिसाई। अमरीका ने भी इसके प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की, क्योंकि वह चीन में सम्बन्ध सुधार कर राजनीतिक व आर्थिक दोनों प्रकार के लाभ प्राप्त

¹ इस पूरे दौर के संभव के विश्लेषण के लिए देखें—Henry Kissinger, *White House Years* (Boston, 1979), James Reston, *Report on China*, in the 'New York Times'.

अपन आधीन किया। सुदूर पूव एशिया के इतिहास में चीन और जापान का द्वन्द्व पारम्परिक शक्ति संघर्ष का रूप वर्षों पहले ले चुका था।

19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध और 20वीं शताब्दी के पहले चरण में इन दोनों देशों की आन्तरिक राजनीति में बुनियादी महत्व का घटनाक्रम सम्पन्न हुआ, जिसने दोनों के सम्बन्धों को आमूल चूल ढंग से बदल डाला। एक ओर मानू साम्राज्य की अवमान देला में चीन पश्चिमी औपनिवेशिक शक्तियों के सामने पस्त पड़ा था तथा अमीर के नरों और सामाजिक कुरीतियों द्वारा सौंभला किया हुआ था तो दूसरी ओर अमरीकी कमोडोर पेरी से मुठभट्ट के बाद मजीकाजीन जापान आधुनिकीकरण का मार्ग चुन चुका था। उसने अपने द्वार पश्चिम के लिए खोल दिए थे। औद्योगिकीकरण से जापान में बहुत तेजी से प्रगति की और 1905 में एक बड़ी यूरोपीय शक्ति रूप को युद्ध में पराजित किया। 1922 में वॉशिंगटन में नौसैनिक सम्मेलन तक अमरीकी तथा अन्य यूरोपीय बड़ी शक्तियों ने भी जापान का बराबरी का दर्जा दे दिया।

दो विश्व युद्धों के अंतराल में जापानी शक्ति निरन्तर बढ़ती रही। मंचूरिया तथा कोरिया में जापानी विस्तारवादी-साम्राज्यवादी सैनिक हस्तक्षेप का निराकरण करने में राष्ट्र संघ (League of Nations) तथा अन्य बड़े राष्ट्र बिल्कुल असमर्थ रहे। इसके अतिरिक्त द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब जापान ने दक्षिण पूव एशिया में अपने पैर जमाए तो इसकी सबसे बड़ी और दुखद कीमत प्रवासी चीनियों का चुकानी पड़ी। जापानियों के नस्लवादी तत्त्व तथा चीनियों के प्रति उनका दुर्भाव इन वर्षों में बहुत बीभत्स रूप से उभर कर सामने आया।

स्थिति में नाटकीय परिवर्तन—यह सारा ऐतिहासिक पुनरावलोकन बेहद आवश्यक है क्योंकि इनके बिना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की स्थिति का मूल्यांकन विरलेपण मायका ढंग में नहीं किया जा सकता। जापान की पराजय के बाद सुदूर पूव में स्थिति एक बार फिर नाटकीय ढंग से बदली। चीन मित्र राष्ट्रों के साथ लड़ा था और उसकी यह अपेक्षा स्वाभाविक थी कि अब सुदूर पूव में उसका एकछत्र अस्तित्व होगा परन्तु कई कारणों से ऐसा नहीं हो सका। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही मित्र राष्ट्रों के संगठन में पूरा पड़ गयी और शीत युद्ध का आविर्भाव हुआ। सुदूर-पूव के भू राजनीतिक महत्व का सम्बन्ध हुए सोवियत संघ अमरीका के मित्र पिछड़े चांग काई शक के मरास चीन की व्यवस्था नहीं छोड़ना चाहता था। स्वयं चीन की आन्तरिक स्थिति ढावाडोल थी। साम्यवादियों की छापामारी सफल होने की ही थी और चीन के बहुत बड़े भाग पर किसी भी एक पक्ष का निरन्तर अधिकार नहीं था। जापान में अमरीकी सनाध्यक्ष अनुरोध के आधार का मानना था कि पराजित जापान को अपमानित करने और दुश्मन बनाने के परिणाम अमरीका और पश्चिमी दुनिया के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने जापान की भौगोलिक अव्यवस्था को अक्षत रखने एवं युद्धांतर आर्थिक पुनर्निर्माण में सहायता देने का बीड़ा उठाया।

1949 में चीन में साम्यवादियों ने सत्ता ग्रहण की और उपर माज्रावाद मुद्रा में सुदूर-पूव में शक्ति-सन्तुलन को एक बार फिर सबट्रस्ट कर दिया। 1949 में 1964-65 तक के वर्षों में दो महत्वपूर्ण और अप्रत्याशित बातें सामने आयीं। माओ के चीन ने मैक्सिक और राजनयिक दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध पर अपने लिए

व प्रौद्योगिकी सम्बन्ध और मजबूत करने का फैसला किया गया। फरवरी, 1989 में अमरीकी राष्ट्रपति जार्ज बुश ने चीन-याना की, जिस दौरान दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में सम्बन्ध और घनिष्ठ बनाने की ज़रूरत पर बल दिया गया।

मतभेदों के बावजूद आत्मीय सम्बन्ध—दूसके बावजूद अमरीका और चीन के बीच महत्वपूर्ण विषयों पर आज भी मतभेद बने हुए हैं। हालांकि अमरीका ने चीन को पूर्ण मान्यता दे दी है, परन्तु उसने ताइवान को सहायता देना बन्द नहीं किया है। इसी तरह दो कोरियाओं के एकीकरण के बारे में चीन और अमरीका का सोच एक-सा नहीं रहा। फिर भी इन दोनों ही मसलों में ऐसा नहीं कि अमरीका और चीन अपने सम्बन्धों में कोई बिगाड़ आने देंगे। इससे अधिक असन्तोष इस विषय को लेकर है कि आर्थिक आदान-प्रदान के क्षेत्र में किसी भी पक्ष को उतना लाभ नहीं हुआ, जितना अपेक्षित था। अमरीकियों ने आरम्भ में चीन के बाजार के आकार को मुनाफे की गारन्टी मान लिया था। चीनियों की क़द समझा के बारे में सोचने की कुसंत उन्हें नहीं थी। दूसरी ओर चीन इस बात से सिन्न है कि सैनिक-सामरिक महत्व की टेक्नोलोजी के निर्यात के बारे में अमरीका का सकोच बना हुआ है। चीन की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा और उसके द्वारा अमरीकी नीति की आलोचना (जैसे छाओ युद्ध और परमाणु निक्षेत्रीकरण के मागलों पर) दोनों देशों के बीच मौजूदा मतभेदों को उजागर करते रहे हैं, परन्तु इनका निर्णायक प्रभाव अमरीका-चीन सम्बन्धों पर पड़ने की सम्भावना नहीं है। असल में, इन दो महत्वपूर्ण राष्ट्रों ने इतिहास से सबक लेते हुए यह बात समझ ली है कि उन्हें एक-दूसरे के साथ पर्याप्त-वादी और व्यावहारिक ढंग से रहना पड़ेगा। जले ही वे इसे 'शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व' कहने में हिचकते हों, परन्तु वास्तविकता यह कि इनके आपसी सम्बन्ध अपने सन्धि-मित्रों की ज़ेम्ना अधिक आत्मीय और घनिष्ठ है।

चीन-जापान सम्बन्ध (Sino-Japanese Relations)

चीन और जापान के बीच आपसी सम्बन्ध सहस्रों वर्षों से मित्रता और शत्रुता का एक अद्वितीय मर्मिथण दर्शाते हैं। दोनों देशों के निवासी मंगोल वंशज हैं और बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे हैं। जापानी सम्यता की शाख चीनी दुश् के तने से फूटी है और भौतिक सामर्थ्य के कारण एक देश की घटनाओं का प्रभाव दूसरे देश पर पड़े बिना नहीं रह सकता।

समानताएँ व विभिन्नताएँ एक साथ—दोनों देशों के बीच अनेक समान तत्व हैं, जो उनमें सहकार एवं मैत्री को पुष्ट करते हैं। परन्तु इतने ही महत्वपूर्ण घटक वे भी हैं, जो उन्हें एक-दूसरे से अलग करते हैं। चीन में बौद्ध धर्म के साथ-साथ कन्फ्यूजियस और लाओत्से के दर्शन का प्रभाव सामाजिक मंगठनों और राजनीतिक चिन्तन पर आज तक देखा जा सकता है। इनके अतिरिक्त चीनियों को सदैव इस बात का अहसास रहता है कि जापानियों को उन्होंने ही सम्य बनाया। दूसरी ओर जापान में साम्राज्यवादी-सामन्ती युग में जिस सामुराई व्यवस्था का विकास हुआ, उसने अन्ध राष्ट्र प्रेम और विस्तारवाद को प्रोत्साहित किया। अपने उत्कर्ष काल में जापान स्वयं एक विक्रामशील औद्योगिक शक्ति के रूप में प्रकट हुआ। विभिन्न जापानी सम्राटों ने अपनी महत्वाकांक्षाएँ साकार करने के लिए कोरिया, मन्चूरिया आदि को

रोका न होता तो बहुत सम्भव है कि कम से कम प्रायद्वीपीय दक्षिण-पूर्व एशिया चीन का प्रान्त बनकर रह जाता। यो चीन के ऐतिहासिक ग्रन्थ दक्षिण-पूर्व एशिया को चीनी साम्राज्य के अन्तर्गत कर देने वाले प्रदेशों में वर्णित करते आये हैं।

चीन की साम्यवादी शान्ति और दक्षिण-पूर्व एशिया के यूरोपीय व अमरीकी शासकों ने पनायन के बाद इस क्षेत्र को चीन ने अपना प्रभुत्व क्षेत्र बनाने की कोशिश की। 1948 के बाद इण्डोनेशिया, मलाया, फिलीपीन और वियतनाम में साम्यवादी शान्तियों का एक दौर चला। इन देशों में जो साम्यवादी दल स्थापित हुए, वे चीन को अपना नेता घोषित रूप से मानते रहे हैं। यह और बात है कि वियतनाम को छोड़कर किसी अन्य देश में साम्यवादी शान्ति सफल नहीं हो सकी। वियतनाम की शान्ति की सफलता के पीछे भी हो ची मिन्ह का नेतृत्व और वियतनामियों के अभूतपूर्व बलिदान रहे थे, न कि चीन द्वारा दी गयी मदद।

1955 में इण्डोनेशिया के बाहुग नगर में हुए अफ्रो-एशियाई देशों के सम्मेलन में चीन को किमी अन्तर्राष्ट्रीय जमघट में साम्यवादी पहली बार प्रतिनिधित्व दिया गया था। चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चाऊ-एन-लाई इस सम्मेलन में एक लोकप्रिय और दूरदृष्टा कूटनीतिज्ञ के रूप में उभर कर सामने आये। असल में साम्यवादी चीन की विदेश नीति का निर्धारण 1950 वाले दशक के आरम्भ से ही चाऊ-एन-लाई के पाम आ गया था। भारत और एशिया के अन्य देशों से मिलकर चीन ने अन्तर्राष्ट्रीय जगत में तेजी से अपने पांव जमाने शुरू किये। बाहुग सम्मेलन के बाद दक्षिण-पूर्व एशिया की राजधानियों में बहुत शीघ्र चाऊ-एन-लाई नेहरू जी से कहीं अधिक लोकप्रिय विदेशी नेता के रूप में माने जाने लगे। तभी इण्डोनेशिया के रगीते राष्ट्रपति सुकार्णो के साथ उनकी दोस्ती बढी, जो बढती ही गयी। इण्डोनेशिया चीन के लिए महत्वपूर्ण बन गया।

बुनियादी समस्याएँ—इन सबके बावजूद चीन और दक्षिण एशिया के देशों के बीच कुछ मूलभूत समस्याएँ बरकरार रही। इन समस्याओं में सबसे ज़रूरी प्रचामी चीनियों की समस्या समझी जाती रही है जिसका कोई मत्तोपजनक समाधान आज तक सामने नहीं आ पाया है। यूरोपीय उपनिवेशीकरण के लम्बे समय में हजारों की संख्या में चीनी नागरिक देश छोड़कर समुद्री रास्ते से मलयेशिया, इण्डोनेशिया, फिलीपीन और वियतनाम के दक्षिणी हिस्से में बसते रहे थे। बर्मा, थाईलैण्ड, लाओस और वियतनाम के उत्तरी भाग में स्थित मार्ग से भी अनेक चीनी आकर बसे। गर्नै: गर्नै: इन प्रवासी चीनियों ने दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के अर्थतन्त्र पर बड़ा जमाना शुरू किया। यहाँ तक कि दक्षिण-पूर्व एशिया की अर्थ-व्यवस्था प्रचामी चीनियों की आर्थिक स्थिति की पर्याप्तवाची बनकर रह गयी। इसी बिन्दु पर आकर प्रचामी चीनियों और स्थानीय नागरिकों के बीच टकराव शुरू हुई जो आज भी जारी है।

प्रचामी चीनियों के अलावा साम्यवादी चीन द्वारा दक्षिण-पूर्व एशिया के स्थानीय साम्यवादी दलों को नैतिक और भौतिक समर्थन दिये जाने से चीन के इन देशों की सरकारों के मध्य सम्बन्धों में अदृष्ट आये लगे। बर्मा, थाईलैण्ड, मलयेशिया, इण्डोनेशिया और फिलीपीन के साम्यवादी दलों को चीन निरन्तर समर्थन देता रहा। सांस्कृतिक शान्ति के दौरान चीन ने दक्षिण-पूर्व एशिया के साम्यवादी दलों से इन देशों में शान्ति करने की माग की थी। इसी दौरान

महत्वपूर्ण भूमिका हासिल कर ली तो जापान का उदय एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में हुआ। एक ओर जापान परमाणु शक्ति-सम्पन्न चीन के आक्रामक इरादों के बारे में नये सिरे से सोचने की विवश हुआ तो दूसरी ओर महाभुद्ध के 25 वर्ष बाद सैनिक और आर्थिक शक्ति से सम्पन्न 'यंगोल गठजोड़' के बारे में पश्चिमी राष्ट्र और भविष्यतः सप आसक्ति होने लगे।

तब से अब तक अन्त्य घटित दो और राजनयिक घटनाओं ने विद्वानों को चीन-जापान सम्बन्धों के बारे में सोचने के लिए विवश किया है। तनाव-शैथिल्य के प्रारम्भिक दौर में, विशेषकर सोवियत-चीन विग्रह के बाद, चीन की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति अकेला पड़ने वाली हुई थी। 1969 से जिस सांस्कृतिक क्रान्ति का मूलपात हुआ, उसने चीन के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में ऐसी उथल-पुथल आरम्भ की जिससे चीन के भविष्य के बारे में अनेक प्रश्न चिन्ह खड़े हो गये। बाद के वर्षों में चीन-अमरीका सम्बन्धों में सुधार एवं सामान्यीकरण से जापानियों का परेशान होता स्वभाविक था। जापानी नेतावर्ग निरस्त की चीन-यात्रा का उत्तेजक 'निकसन-सोकु' (निकसन-गोक) के रूप में कर रहे रहे। कुछ विद्वेषकों का यह भी मानना है कि अन्तर्राष्ट्रीय तेल संकट के दौरान जापानी इस वेवाकवी को भी आत्मसात कर चुके थे कि उनकी समृद्धि की नींव कितनी कमजोर है और पश्चिमी कृपा पर टिकी है। अपनी स्थिति को निरापद रखने के लिए उन्हें स्वयं ही अपने पड़ोस को सम्भालना होगा।

शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व निभाने की मजबूर—इस प्रकार स्पष्ट है कि चीन के साथ जापान के सम्बन्धों के दो पक्ष हैं। एक, पारम्परिक-ऐतिहासिक, जो इन दोनों देशों के बीच उभयपक्षीय सम्बन्धों की सांस्कृतिक व मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि है। इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। दूसरा पक्ष, सम-सामयिक यथार्थ का है, जिसमें मैक्रान्तिक विचारधारा का टकराव, सामरिक परिदृश्य का अन्तर एवं महा-शक्तियों के आपसी सम्बन्धों के बदलते तथ्यीकरणों के प्रतिबिम्ब एक साथ देखे जा सकते हैं। इसके बावजूद रोचक तथ्य यह है कि भले ही तरह-तरह के अनुमान लगाये जाते रहे हों, लेकिन चीन-जापान सम्बन्धों का स्वरूप पिछले दशक में लगभग अपावत रहा है। चीन-अमरीका सम्बन्धों के सामान्यीकरण के बाद जापान-चीन टकराव की सम्भावना घटी है और दोनों के बीच व्यापार में क्रमशः वृद्धि हुई है। आज न तो चीन और न ही जापान एक-दूसरे की उपेक्षा-अवहेलना कर सकते हैं या एक-दूसरे पर अपना औपनिवेशिक अधिपत्य स्थापित करने की बात सोच सकते हैं। चीन और जापान एक-दूसरे के साथ असह्य ही सही, शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व निभाने के लिए मजबूर हैं।

चीन और दक्षिण-पूर्व एशिया (China and Southeast Asia)

ऐतिहासिक परिवेश में देखा जाये तो दक्षिण-पूर्व एशिया चीन के विस्तार-वादी मन्त्रों का मर्द हो घरातल रहा है। इसकी बख्त शायद दस शोध की चीन से जुड़ी हुई भूगोलिक स्थिति है। ईस्वी सन के प्रारम्भ से ही चीन ने दक्षिण-पूर्व एशिया में अपनी सभ्यता और सैनिक दबदबे का योजनावद्ध विस्तार आरम्भ कर दिया था। यदि विपत्तनाम के स्वतन्त्रता-श्रेणी लोगों ने चीनी प्रवाहों को दृढ़ता से

आरम्भ कर दिया। यही नहीं, अमरीकी पराजय के बाद 'आसियान' देशों ने चीन के साथ सम्बन्ध सुधारने की कलावाजी में एक-दूसरे से आगे बढ़ जाने की होड़ लगायी। वैसे 1974 में मलेशिया चीन के साथ दौत्य सम्बन्ध स्थापित कर चुका था, किन्तु थाईलैण्ड और फिलीपीन्स हिन्द-चीन में अमरीकी पराजय के प्रभाव के अन्तर्गत ही चीन को अपना नया आका घोषित करने को बाध्य हुए। इण्डोनेशिया इस दौड़ भाग से पृथक् रहा। आज भी वह चीन से दौत्य सम्बन्ध पुनर्जीवित नहीं करना चाहता, क्योंकि सुहातों-सरकार का मानना है कि प्रवासी चीनियों की समस्या और इण्डोनेशिया की साम्यवादी पार्टों को चीनी समर्थन और मदद उनके सम्बन्धों के लिए गम्भीर समस्याएँ हैं। सिंगापुर प्रकट रूप में यही कहता आ रहा है कि जब तक इण्डोनेशिया चीन के साथ दौत्य सम्बन्ध स्थापित नहीं करता, तब तक वह भी ऐसा नहीं करेगा। या सिंगापुर और चीन के मध्य कूटनीतिक सम्बन्ध न होत हुए भी सम्पर्क के दायरे इनने घनिष्ठ हैं कि सिंगापुर को अक्सर 'तृतीय चीन' की सजा दी जाती रही है। किन्तु वियतनाम के एकीकरण से चीन बौखला उठा। इधर जनवरी, 1976 में चाऊ-एन-लाई और सितम्बर, 1976 में माओसे तुंग की मृत्यु के बाद चीन आन्तरिक सत्ता सघर्ष में उलझकर रह गया। तथापि अमरीका के माध्य उसके निरन्तर सुघरने सम्बन्धों ने दक्षिण-पूर्व एशिया में चीन के पुन प्रतिष्ठित होने में काफी मदद दी। राष्ट्रपति वाटर ने चीन और अमरीका के मध्य पूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित (1979) करके आसियान देशों में चीन को महत्वपूर्ण कूटनीतिक भूमिका अदा करने का मार्ग प्रशस्त किया। पाँचो आसियान देश साम्यवाद-विरोधी और अमरीका-प्रस्त हैं। जब अमरीका और चीन अपने प्रमुख शत्रु सोवियत सघ के विरुद्ध एकजुट हो गए तो आसियान देशों ने चीन को मित्र रूप में स्वीकार करने में कोई आनाचानी नहीं की। चीन-अमरीकी सम्बन्धों की इस नयी पैतरेवाजी ने सोवियत सघ को जहाँ आसियान देशों से दूर कर दिया, वहीं हिन्द-चीन में सोवियत-चीन सम्पर्क अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया। यहीं से वियतनाम और सोवियत सघ में घनिष्ठ सम्बन्धों का वर्तमान युग आरम्भ हुआ।

चीन वियतनाम सघर्ष—नवम्बर, 1978 में सोवियत वियतनाम मैत्री सन्धि का जन्म हुआ। वियतनाम चीन के इरादों को सत्य मानने-मानिती भावें चुका पा और वह चीन द्वारा प्रत्यक्ष आक्रमण के खतरे को महसूस करने लगा था। इस सन्धि से चीन इतना अधिक नाराज हुआ कि उसने वियतनाम को दक्षिण-पूर्व एशिया में सोवियत सघ का पिट्टू घोषित कर दिया। यही नहीं, उसने आसियान देशों को आगाह किया कि वियतनाम सोवियत सघ के बहुबाव में जाकर समस्त दक्षिण-पूर्व एशिया में अपना साम्राज्य स्थापित करने का इरादा रखता है। चीन की कूटनीतिक कला-वाजिया को निरस्त करत हुए वियतनाम ने पोल पोटा के विरुद्ध वम्पुचिया की जनता में आन्तरिक अमान्तोष का काम उठात हुए जनवरी, 1979 में पाल पोटा सरकार का नाम पन्ध्र स विस्तर मोल कर दिए। यह सही है कि वम्पुचिया की हग सामरिन सरकार वियतनामों सेना की सहायता में सत्ता में आयी, किन्तु इस वम्पुचिया की जनता ने भारी सङ्घर्ष सहसूस की। चीन इस कारवाई पर पुन चेष्टा करना नहीं था। फरवरी, 1979 में उसने वियतनाम को 'मदक मिलान' का घोषित इरादा के साथ बड़े पैमाने पर वियतनाम पर आक्रमण कर दिया।

नये युग का सुत्रपात—चीन की इस सैनिक कारवाई ने दक्षिण पूर्व एशिया

दक्षिण-पूर्व एशिया के बर-साम्यवादी देशों के साथ चीन के सम्बन्ध बदतर स्थिति में पहुँचे। 1965 में इण्डोनेशिया की साम्यवादी पार्टी ने क्रान्ति द्वारा सत्ता हथियाने की असफल कोशिश की। इस घटना के बाद वहाँ सत्ता साम्यवाद-विरोधी सेना के पास आ गयी और चीन के मित्र राष्ट्रपति मुकाबलों का पतन हो गया।

बाद में मफकर दमन चक्र के अन्तर्गत साम्यवादियों को समाप्त किया गया। लेकिन कुछ साम्यवादी नेता बीजिंग जाकर कारण से झुके थे। चीन ने उन्हें इण्डोनेशिया की साम्यवादी पार्टी का प्रतिनिधि मानते हुए सम्पूर्ण सुविधाएँ प्रदान की। यही नहीं, चीन अपनी भूमि में बर्मा, थाईलैण्ड, मलेज़िया, सिंगापुर और इण्डोनेशिया की जनता में साम्यवाद और साम्यवादी क्रान्ति के सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिए रेडियो स्टेशन भी चलाता रहा। ये रेडियो स्टेशन चीन के जन-प्रचार माध्यमों द्वारा इन देशों के राष्ट्रीय रेडियो स्टेशनों के समकक्ष माने गए। कुल मिलाकर, चीन की नीति दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में समानान्तर सरकारें स्थापित करने की रही थी जिसमें स्थानीय साम्यवादी पार्टियाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती थी।

चीन की नीति में बदलाव—1970 वाले दशक में दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रति चीन की नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव आये। ये बदलाव जहाँ एक ओर सांस्कृतिक क्रान्ति की समाप्ति से जुड़े हुए थे तो दूसरी ओर इनका सम्बन्ध रक्त-चीन विवाद और चीन की पश्चिमी राष्ट्रों से सम्बन्ध सुधारने की नई कूटनीति से भी था। 1971 में संयुक्त राष्ट्र सभ का सदस्य बन जाने के बाद चीन ने तेज़ी से अमरीका के साथ मित्रता बढ़ाना शुरू किया। 1972 में राष्ट्रपति निसन की चीन-यात्रा के परिणाम के रूप में ही शायद चीन वियतनाम के स्वतन्त्रता सपर्य और राष्ट्रीय आकांक्षाओं को ताक में रखकर वियतनाम समस्या का हल ढूँढ़ने में अमरीका की मदद करने के लिए राजी हो गया। फलस्वरूप 1973 में पेरिस में वियतनाम को लेकर जो समझौता हुआ, उससे जहाँ वियतनाम की एकता के सिद्धान्त को चोट पहुँचायी गयी, वही वियतनाम की चीन इस हद तक नापसंद कर बैठा कि उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ रहा है।

किन्तु इसके पूर्व 1970 में कम्पुचिया में सिहनुक के पतन और लोन नोल के सत्ताधीन हो जाने के पीछे रही अमरीकी चालों से भी चीन अधिक परेशान नहीं हुआ था। यों सिहनुक को बीजिंग में बाकायदा एक राष्ट्राध्यक्ष के रूप में प्रयास-सुविधाएँ प्रदान की गयी, किन्तु पास्तविक शक्ति-संचयन के मामले में चीन अपने अनुयायियों, बिनका नेतृत्व पीपल फ्रीट, इस सारी और खई सम्फल करते थे, को भागे बढ़ाता रहा। यहाँ चीन की चाल साफ़ यह रही थी कि वह अमरीकियों के पतायन के बाद अपने इन गुरगों को कम्पुचिया में सत्ताधीन करना चाहता था। इस प्रकार, चीन सामरिक दृष्टि में अत्यधिक महत्वपूर्ण इस छोटे से देश पर अपना प्रभुत्व स्थापित करके वियतनाम और आसियान देशों को समान रूप से डके दिखाने की स्थिति में आ जाना चाहता था।

1975 को चीन की योजनाओं की सफलता का वर्ण कदां जा सकता है। इस वर्ष अग्रेज में अमरीकी कम्पुचिया और दक्षिण वियतनाम में पराजित होकर भाग राखे हो गये। बिना युक्त गवाये पीपल फ्रीट के चीन-समर्थक गुरिस्तों ने कम्पुचिया पर कब्ज़ा कर लिया और दक्षिण वियतनामी भू-भाग में वियतनामियों को परेशान करना

अपनी ओर आकर्षित करने में चीनी राजनयिकों को विशेष कठिनाई नहीं हुई। इसका सबसे अच्छा उदाहरण इण्डोनेशिया है। 1965 में असफल तख्ता पलट (गेस्टापू) के बाद जावा में प्रवासी चीनियों का भीषण नरसंहार हुआ। इस रक्तपात के बाद किसी ने यह कल्पना तक नहीं की कि 'मलय मूल के लोग' कभी 'भगोलो' के साथ सह-अस्तित्व की बात सोचेंगे भी। आरम्भ में आसियान को चीन-विरोधी और नस्लवादी संगठन समझा गया। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली क्वान यू ने यह दावा सुन्नर भी की थी। लेकिन बाद में इसी सिंगापुर के जरिये इण्डोनेशिया ने चीन के साथ बड़े पैमाने पर इतना सामप्रद व्यापार किया कि चीन के साथ पुनः दौलत सम्बन्ध स्थापित कर सीधे सामान्य सम्बन्धों की स्थापना की बात सोची जाने लगी।

अमरीका की महत्वपूर्ण भूमिका—इसी तरह बर्मा, मलयेशिया तथा फिलीपीन चीन-प्रेरित छापामार विद्रोह का वण्ट बर्षों तक झेलते रहे। आज ये देश चीन के बड़े बाजार के तालब में पीछे नहीं रहना चाहते। ये चीनी नेताओं द्वारा मौलिक आश्वासन दिये जाने भर से यह मान लेने को तैयार हैं कि चीन ने अपनी पुरानी आनामक-विस्तारवादी नीति हमेशा के लिए त्याग दी है। इन पूरे प्रसंग में अमरीका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी, जिसने दक्षिण-पूर्व एशियाई नेताओं को यह सोचने को विवश किया कि उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा को अमली अंतरा सोवियत घुमपैठ और उसके बढ़ते प्रभाव से है। परन्तु इस विषय में चीन से निश्चिन्त होना घातक मिथ्या हो सकता है। चीन दक्षिण-पूर्व एशिया को पारम्परिक रूप से अपना प्रभाव क्षेत्र मानता है और यह सोचने का कोई कारण नहीं कि चीनियों का हृदय परिवर्तन हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि अमरीका ने चीन से सम्बन्ध सुधार के बाद यह दावा स्वीकार कर लिया है और इसीलिए कोई टकराव दृष्टिगोचर नहीं होता।

चीन और अफ्रीका (China and Africa)

अक्सर यह साधा जाता है कि बड़ी शक्तियों की जमात में जा बैठन के पहले चीन की महत्वाकांक्षा निर्णय लेनी थी। वह अपने पड़ोस में भारत, नेपाल तथा दक्षिण-पूर्व एशिया में अपना प्रभाव क्षेत्र जमाना चाहता था। अफ्रीका और सातीनी अमरीका के देशों में उसकी कोई रुचि नहीं थी। परन्तु यह धारणा भ्रान्तिपूर्ण है। चीन ने शुरू से ही अफ्रीकी देशों के साथ निजी सम्बन्ध स्थापित करने के प्रयत्न जारी रखे।

अफ्रीकी देशों से सम्बन्ध बढ़ाने के चीनी प्रभाव—बाद में का पहला प्रमुख अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन (1955) था, जिसमें चाऊ एन साई न मिस्र के नासिर जैसे महत्वपूर्ण नेताओं ने व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित किए और अफ्रीकी देशों को यह जताया कि चीन भी भारत की तरह रंगभेद और उपनिवेशवाद का विरोधी है। शीघ्र ही चीन की स्थिति भारत में बेहतर हो गयी क्योंकि अधिकांश अफ्रीकी देश महसूस मुक्ति सपने का मार्ग चुन चुके थे और उन्हें अपने सन्दर्भ में भारत का अग्रणी चीनी दिक्कत अधिक उपयुक्त प्रतीत होता था।

मोबियत संधि के तत्वावधान में जब साम्यवादी खेल में अफ्रो-एशियायी एकरा संगठन (Afro-Asian Solidarity Organization) की स्थापना की तो इसका नाम भी चीन को हुआ। बाद में जब मोबियत-चीन विवाद बढ़ा तो 1965 में चीन

की राजनीति में एक नए युग का सूत्रपात किया। इसके पूर्व भी चीन दक्षिण-पूर्व एशिया और खासकर आसियान देशों में वियतनाम के विरुद्ध अपनी कूटनीतिक गतिविधियाँ बढ़ाता रहा था। 1978 में चीन के नए शक्ति-सम्राट् देंग सियाओ पिंग ने याइलैण्ड, मलयेशिया और सिंगापुर का दौरा करके यह प्रकट किया कि वियतनामी खतरे के विरुद्ध चीन आसियान देशों की मदद करने को कृत-संकल्प है। वियतनाम पर आक्रमण करके चीन ने अपने इस संकल्प की पुष्टि कर दी। फलस्वरूप आसियान देशों में उनकी स्थिति निश्चित रूप से मजबूत हुई। किन्तु वियतनाम को सबक सिखाने में यह पूर्णतया नाकामयाब रहा। हैंग सामरिन सरकार और अधिक मुखर हो गयी। उसे भारत जैसे मुटु निरपेक्ष देशों से मान्यता भी प्राप्त हुई। अतएव कहा जा सकता है कि वियतनाम की शक्ति को क्षीण करने में या उस पर अपनी इच्छा थोपने में चीन नितांत असफल रहा। फिर भी वियतनाम पर चीन के आक्रमण से जहाँ एक ओर चीन का महत्व वियतनाम को मन्तुवित रखने की दृष्टि से आसियान देशों ने स्वीकार किया, वही आसियान देश वियतनाम की शक्ति से भी बाकिफ हो गए। इण्डोनेशिया तथा मलयेशिया जैसे आसियान देश चीनी खतरे को दूर रखने के लिए एक शक्तिशाली वियतनाम का अस्तित्व अनिवार्य मानते हैं।

1980 के मध्य में दक्षिण-पूर्व एशिया में याइलैण्ड की तरह पर याइलैण्ड और वियतनाम के सैनिकों के बीच एक छोटा-सा संघर्ष हुआ। इसका कारण याइलैण्ड और चीन द्वारा कम्बुचिया के शरणार्थियों को पुनः कम्बुचिया में डकेलने की योजना था। वास्तव में, शरणार्थियों के रूप में पोल पोट के गुरिल्लाओं को कम्बुचिया भेजा जा रहा था। इसे रोकने के लिए कम्बुचिया ने वियतनाम की मदद से सैनिक कार्रवाई की। इस कार्रवाई ने आसियान देशों को वियतनाम के विरुद्ध कठोर रुख अपनाने के लिए प्रेरित किया। इसमें चीन के साथ मित्र थाइलैण्ड और सिंगापुर ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इधर पोल-पोट को कम्बुचिया में पुनः स्थापित करने की अनेक योजनाओं की अमफलता और विश्व जनमत द्वारा पोल पोट के खूनी दृष्यकण्डों का जबरदस्त विरोध होने के कारण चीन पोल पोट के बजाय कोई तीसरा विकल्प स्वीकार करने को राजी हो गया।

अब तक का इतिहास यह प्रकट करता है कि दक्षिण-पूर्व एशिया विश्व शक्तियों के टकराव का एक प्रमुख केन्द्र रहा है। मोबियत सच, अमरीका और चीन इस क्षेत्र में अपने-अपने प्रभाव-क्षेत्र रखते रहे। आसियान देशों द्वारा इस क्षेत्र को शान्ति, स्वतन्त्रता और तटस्थता का क्षेत्र घोषित करने के इरादे विश्व शक्तियों के हितों की टकराव के कारण नाकाम होते रहे। चीन लगातार दक्षिण-पूर्व एशिया में अपना प्रभाव क्षेत्र विलुप्त करने में लगा रहा है। देखना यह है कि वियतनाम उसके इस इरादे को रोक पाने में कहीं तक सफल होता है ?

1972-73 के बाद चीन और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच सम्बन्ध नाटकीय ढंग से बदले। एक ओर उनका वियतनाम व कम्बुनिया जैसी साम्यवादी सरकारों के साथ तनाव व संघर्ष और युद्ध का निष्कोट हुआ, वहीं पूँजीवादी व्यवस्था की ओर झुकें आसियान बिरादरी के देशों के साथ सम्बन्धों में अप्रत्यागित सुधार हुआ। इसका एक कारण यह रहा कि आसियान देशों ने माओ के उत्तराधिकारी देंग सियाओ पिंग और उनके सहयोगियों को अधिक व्यावहारिक, उदार व लचीला माना। दूसरे, अमरीका के साथ सम्बन्धों के सामान्यीकरण के बाद उसके शिबिरानुचरों की

किया और चीन ने मुडान को 80 लाख डालर का ऋण दिया। इस प्रकार अन्य देशों के साथ चीन के व्यापारिक सम्बन्ध बढ़े; तैवानिया तम्रन जाम रेलवे निर्माण में 15 हजार चीनी कार्यरत रहे और चीन को इससे काफी फायदा मिला। चीन ने ऐसी आर्थिक गतिविधियों के द्वारा अफ्रीकी देशों में अच्छी खासी कूटनीतिक फसल काटी। अनेक अफ्रीकी देशों के नेताओं ने 1973-74 के दौरान बीजिंग यात्रा की जिससे चीन-अफ्रीका सम्बन्ध प्रगाढ़ हुए।

चीन की अफ्रीका में घटती रुचि—माओ की मृत्यु (1976) के बाद चीन में सत्ता परिवर्तन की धुनी तो ने विदेश नीति के सामरिक महत्व वाले पहलुओं को ही सामने रहने दिया। अमरीका के साथ सम्बन्ध सुधार और सोवियत संघ के साथ सन्तुष्टा का निर्वाह इस श्रेणी में आते थे, अफ्रीका नहीं। इसके अलावा सुरक्षा परिपद में स्थायी सदस्यता पाने के बाद चीन स्वयं एक तरह से यथास्थिति का पोषक नहीं तो कम से कम प्रबन्धक बन गया। उसके तैवर पहले जैसे शान्तिकारी नहीं रहे। परिणामस्वरूप अफ्रीका में उसकी रुचि कम हुई। 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप और लगभग इसी समय कम्बुधिया में विद्यतनामी हस्तक्षेप ने चीन के पड़ोस में शक्ति सन्तुलन उसके विपक्ष में परिवर्तित कर दिया। इसका प्रभाव यह पड़ा कि चीन की राजनयिक गणना में अफ्रीका का 'अवमूल्यन' हुआ। ऐसा नहीं लगता कि निकट भविष्य में इस स्थिति में कोई खास परिवर्तन होगा।¹

नाटकीय परिवर्तन की आशा नहीं—एक आश्चर्यजनक बात यह है कि एकान्तवास वाला तैवर अपनाते के बाद भी चीन के अन्तर्राष्ट्रीय सामरिक महत्व में कोई कमी नहीं है। ध्वन जानमन चीक की दुग्द घटना के बाद अमरीका ने यह नकत दिया कि चीन के साथ इन बढ़ते हालातों (मानवाधिकार हनन) में व्यापार व वाणिज्य सम्बन्धों में बृद्धि के बारे में फिर से सोचना पड़ सकता है। परन्तु अतत ऐसा कुछ हुआ नहीं। सोवियत संघ आन्तरिक मकट से ग्रस्त है और भारत अपनी आन्तरिक समस्याओं के दानदल में इतनी जुरी तरह फँसा है कि वह चीन के मन्दम में प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा किसी भी तरह के सन्तुलन की बात सोच ही नहीं सकता। तत मकट हो या अफ्रीका में नस्तवादी घेराबन्दी का अन्त चीन के राजनयिक बेहरे पर किसी भी परिवर्तन की शिकन नजर नहीं आती। चीन के शीपस्थ नेता दैंग सियाओ पिंग 85 वर्ष पार कर चुक हैं और उन्होंने औपचारिक रूप से जवमात ग्रहण कर लिया है। परन्तु पर्व के पीछे से उनका प्रभाव साफ महसूस किया जा सकता है। उत्तराधिकारियों के बार में कोई कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता। बहरहाल चीनी विदेश नीति के बार में पुरान अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निकट भविष्य में किसी नाटकीय परिवर्तन या उत्साहवचक पहल की आशा करना व्यर्थ है।

¹ विस्तार के लिए देख—Bruce D Larkin, *China and Africa, 1949-70*, (London 1971)

ने इसके समानान्तर गुट विरुद्ध आन्दोलन के रूप में अफ्रो-एशियायी एकता संगठन के गठन का प्रयास किया। चीन ने मुक्ति मोर्चों और प्रावधानिक सरकारों को मान्यता देने में कभी देर नहीं समायी। इनको ही जाने वाली चीनी सहायता का परिमाण भले ही कम रहता था, परन्तु नाटकीय घोषणा और 'प्रतीक के प्रचार' का पूरा लाभ चीन बहुत ही उदात्त रहा। अनुकूल वातावरण तैयार करने के बाद चीन ने 1960 वाले दशक में जनवादी लोक संगठनों के माध्यम से अफ्रीकी महाद्वीप में अपना प्रभाव बढ़ाया। इसी दौरान चीनी आर्थिक कूटनीति का अभियान तेज हुआ और एक बहु-प्रचारित अफ्रीकन-मफारो (याया) के द्वारा चाऊ एन लाई ने अपने व्यक्तित्व के आकर्षण को भी राष्ट्र हित साधने में लगाया। ये वे वर्ष थे, जब माओवादी विचारधारा का आकर्षण विश्व भर में फैल रहा था। घाना, माली, मोमालिया, तजानिया आदि देशों में चीन को एक प्रमुख वैदेशिक शक्ति के रूप में मान्यता मिल चुकी थी। 1962 के युद्ध में भारत को पराजित कर चीन ने यह दिखा दिया कि तीसरी दुनिया के नवोदित राष्ट्रों के नेतृत्व के लिए उनका कोई प्रतिद्वन्द्वी नहीं रहा।

चीन के प्रति अफ्रीकी देशों में नाराजगी—1965-66 के बाद अफ्रीकी महाद्वीप में चीन के प्रभाव में क्रमशः ह्रास हुआ। अफ्रीका में चीन की विध्वंसक गतिविधियों ने उसके प्रति नाराजगी फैली। अफ्रीकी देशों में स्थित चीनी वृत्तावासों द्वारा उन देशों के आन्तरिक मामलों में दखलदाजी करने से कुछ देशों ने चीन के साथ अपने कूटनीतिक सम्बन्ध तोड़ दिखे। फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि विध्वंसक गतिविधियों तथा पाँच देशों द्वारा कूटनीतिक सम्बन्ध तोड़ने के बावजूब अफ्रीकी देशों में चीन की एक बड़ी शक्ति के रूप में शक्ति जम गयी। चीन की बड़ी शक्ति के रूप में प्रतिष्ठा ■ प्रमुख कारणों में उसके द्वारा राष्ट्रीय मुक्ति मशानों का समर्थन, पश्चिमी साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध, महाशक्तियों के अधिपत्य का विरोध तथा अनेक अफ्रीकी देशों को आर्थिक, भौतिक एवं तकनीकी सहायता देना विशेष रूप में उल्लेखनीय हैं। चीन ने अफ्रीका को इतना अधिक महत्व दिया कि उनकी विदेशी सहायता का बहुत बड़ा भाग अफ्रीका के ही हिस्से में जाता था। विदेशी सहायता के साथ-साथ चीन ने अफ्रीकी देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध भी बढ़ाये।

आर्थिक सम्बन्धों में वृद्धि—1966-69 की सांस्कृतिक क्रान्ति के दौरान चीन ने विदेशी राजधानियों से अपने अधिकांश राजदूत स्वदेश बुला लिये। इस फारंवाई से उसने अनेक साम्यवादी और गैर-साम्यवादी दोनों प्रकार के देशों को विरोधी बना लिया, किन्तु इससे अफ्रीकी देशों के साथ उसके सम्बन्धों पर कोई गाम बुरा बमर नहीं पड़ा। 1969 में चीनी राजदूत पुनः विश्व राजधानियों में लौट आये और 1970 तक अफ्रीका में 15 चीनी कूटनीतिक नियोग सक्रिय हो गये। 1972 में चीन ने अनेक अफ्रीकी देशों के साथ नामरिक विमानन समझौते करने की इच्छा प्रकट की। 1971 में संयुक्त राष्ट्र मंच में चीन को सदस्यता मिलने के बाद अनेक अफ्रीकी देशों ने उसके साथ जल्दी ही कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित कर डाले। व्यापारिक और आर्थिक सम्बन्धों के विस्तार में प्रमुख रूप से मिस्र, मुगान, अल्जीरिया, इथियोपिया, जाम्बिया तथा तजानिया लाभ उठाते रहे हैं। उदाहरणार्थ, चीन ने मुगान के साथ 70 लाख डॉलर का आपसी व्यापार समझौता

देशों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकी। मले ही इण्डोनेशिया जैसा देश सिर्फ औपचारिक रूप से भारत से पहले आजाद हो चुका था, किन्तु यह युद्ध में स्वतंत्र होने के कारण उसकी सार्वक जन्तराष्ट्रीय भूमिका निम्नाने की स्थिति नहीं थी। चीन में भयंकर उथल-पुथल मची थी और जापान युद्ध के सर्वनाश के बाद पुनर्निर्माण का राष्ट्रीय अभियान शुरू करने जा रहा था। इन सब घटनाओं के संयोग से नेहरूवादी भारत को आजादी के तत्काल बाद के वर्षों में अपनी विदेश नीति को प्रभावशाली ढंग से पक्ष करने का अवसर मिला। इन सभी कारणों के संयोग में भारतीय विदेश नीति का अध्ययन आजादी के समय में ही अन्तराष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों के लिए आकर्षक और महत्वपूर्ण विषय रहा है।

भारतीय विदेश नीति ऐतिहासिक परम्परा (India's Foreign Policy Historical Tradition)

भारतीय सभ्यता का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। एक राष्ट्रीय शक्ति के रूप में भारत की पहचान भी कम पुरानी नहीं है। पुराणों और मिथकों में भारत का हिमालय से लेकर समुद्र-पर्यन्त उस क्षेत्र को परिभाषित करने का प्रयत्न किया गया है, जो एक चतुर्दलीय साम्राज्य के शासन के योग्य भू-भाग समझा जाता था। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक 'अर्थशास्त्र' में यथार्थवादी निर्देशों से यह बात पुष्ट की कि इस तरह का चिन्तन कभी बलपना नहीं था। इस ग्रन्थ में यह मलाह दी गयी है कि विजयीपु (विजय का अमिलापी) राजा को पड़ोसी राज्यों के साथ किन प्रकार के सम्बन्ध रखने चाहिए। मण्डन मिश्रान्त का प्रतिपादन अर्थात् शत्रु के शत्रु के साथ मित्रता की हिदायत इसी ग्रन्थ में दी गई है।¹

इसके अतिरिक्त महाभारत के शांति पर्व तथा अन्य सूत्रा-स्मृतियों में अनेक ऐसी सारगर्भित टिप्पणियाँ मिलती हैं, जिनसे पता चलता है कि प्राचीन काल में भारतीय विद्वानों व प्रशासकों ने विदेश नीति और राजनय का कितना महत्वपूर्ण समझा था। प्रसिद्ध भारतीय राजनयिक एवं इतिहासकार मरदार व० एम० पणिकर ने इसी सन्दर्भ में महामाहर्षि के दूत वाक्यम् प्रसंग का उल्लेख किया है। यह समझना अतिप्रसन्न है कि यह सब विशेषण सैद्धान्तिक स्तर पर ही चलता था। व्यवहार और अनुभव के क्षेत्र में भी भारत नीतिविद्या नहीं रहा। कौटिल्य के गिण्ट चन्द्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकटोर नामक क्षत्रप द्वारा भेजा गया राजदूत मात्स्यनीज था। चन्द्रगुप्त के पुत्र बिन्दुसार ने राजदूत का आदान प्रदान किया। साम्राट् अशोक द्वारा सिंहली द्वीप (श्रीलंका) तथा दक्षिण पूर्व एशिया में भेजे गये विशेष दूतों का उपयोग धर्म विजय के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ था। बाद के वर्षों में कुशाणा, गुप्तों तथा हर्षवर्द्धन व काल में धार्मिक व सांस्कृतिक गिण्टमण्डलों की आजाजाही चलती रही। इन सब ऐतिहासिक पुनरीक्षण का अभीष्ट यह प्रमाणित करना है कि विदेश नीति नियोजन और राजनयिक सम्बन्धों की भारतीय परम्परा उतनी ही पुरानी है जितनी चीन या यूरॉप के प्राचीनतम देशों की। इसमें यूरोपीय औपनिवेशिक शक्ति व आने के बाद ही व्यवधान पड़ा। परन्तु भारत की तुलना उन राष्ट्रा के साथ नहीं की जा सकती, जिनका बाहरी दुनिया में परिचय साम्राज्यवाद

¹ Kautilya's Arthashastra Translated by R. Shamasastry (Mysore 1961).

भारतीय विदेश नीति

भारत संसार में सबसे बड़ी आबादी वाला दूसरा देश है। इसकी ऐतिहासिक परम्परा की जड़ें हजारों वर्षों पुरानी हैं और अनेक निकतवर्ती-मनस्क पड़ोसी राष्ट्र 'भारतीय क्षेत्र' के अन्तर्गत ही अपनी असल पहचान बनाये रखने का प्रयत्न कर सकते हैं। नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बंगला देश और श्रीलंका सम्प्रभु राष्ट्र हैं और इनके अपने असल राष्ट्रीय हित स्पष्ट हैं। परन्तु इनमें से कोई भी देश भारतीय विदेश नीति के उत्तार-चढ़ाव की उपेक्षा नहीं कर सकता। इसी कारण कोई भी महाशक्ति, चाहे वह अमेरिका हो या सोवियत संघ, लगभग एक अरब आबादी वाले दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप में राजनयिक दृष्टि में भारत की प्रमुख भूमिका की उपेक्षा नहीं कर सकती। भारत का महत्व क्षिप्त जनसंख्या को लेकर ही नहीं, बल्कि भौगोलिक राष्ट्रों की गिनती में उसका दसवाँ स्थान है और वैज्ञानिक व तकनीकी समाधानों के मन्दार के रूप में वह तीसरे स्थान पर है। भारत की इस तकनीकी व वैज्ञानिक क्षमता की उपेक्षा नहीं की जा सकती। भारत की भू-राजनैतिक स्थिति भी कुछ ऐसी है कि उसका अन्तर्राष्ट्रीय राजनयिक महत्व बहुत बढ जाता है। स्वयं नेहरू जी ने एक बार कहा था कि 'भारत अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के बीराहे पर स्थित है। उसके एक ओर पश्चिम एशिया तो दूसरी तरफ दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रति महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है जिनका प्रवेश द्वार भारत को बनाया जा सकता है। उत्तर में चीन और दक्षिण में हिन्द महासागर भारत को और अधिक महत्वपूर्ण देश बना देते हैं।'

इन सब स्पष्ट बातों के अतिरिक्त विचारपारा का पक्ष कम महत्वपूर्ण नहीं। नेहरू जी द्वारा सुझावी गयी मुद्रा निरपेक्षता की अवधारणा को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण, मौलिक व रचनात्मक पहल समझा जा सकता है। जिस समय भारत आजाद हुआ, अन्तर्राष्ट्रीय रणमंच पर उसकी स्थिति मनुठी थी। भारत के गरीब होने पर भी स्वाभिमान के साथ नेहरू जी ने स्वाधीन विदेश नीति का मार्ग चुना और किसी भी बड़ी शक्ति का 'पिछलगुरू' बनना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अल्दी ही आजाद होने वाले छोटे-बड़े जफो-एशियाई देशों की अभिलाषा महत्वाकांक्षा को मुखर किया। इस रचनात्मक पहल का एक और पहलू था—निर्भय यथार्थवादी विकल्प (Real Political Alternative) का विकल्प ठुकराकर आदर्शवादी विकल्प सुझाना। नेहरू जी जोर देकर यह बात बौद्धरणे थे 'आज का आदर्शवाद आने वाले कस का यथार्थवाद ही है।' भारतीय विदेश नीति के अध्ययन का महत्व इसलिए और भी बढ जाता है कि वह किसी एक बड़े देश के साथ नहीं जुड़ी थी, बल्कि विचारपारा और रणनीति के क्षेत्र में रचनात्मक पहल करने के साथ-साथ वह तीसरी दुनिया के बहुत मारे

अधिकारों से लैस बरिष्ठ दूतों के रूप में की गई। इन्हें 'एजेंट जनरल' कहा जाता था। अमरीका में जफरल्ला खान और गिरजा शंकर बाजपेयी और चीन में के० पी० एम० मेनन ने यह उत्तरदायित्व संभाला। इनके अलावा ब्रिटिश साम्राज्य के जिन हिस्सों में भारतीय मूल के नागरिकों का बाहुल्य था, वहाँ वाणिज्य दूतों के समकक्ष भारतीय उच्चायुक्तों की नियुक्ति की गयी। थोल्का, पूर्वी अफ्रीका तथा इंग्लैंड में इस तरह के राजनयिक पद थे। इस तथ्य को भी बड़ा विस्तार में याद दिलाना इसलिए आवश्यक है कि इन विशेषज्ञ अधिकारियों में अन्तः 1947 के बाद नहरू जी के सहयोगी व सलाहकार बने और कुछ ने महत्वपूर्ण मामलों में नहरू के चिंतन को प्रभावित किया। ऐसा नहीं कि ये लोग दक्ष प्रभो नहीं थे, परन्तु यह अनदेखा नहीं किया जा सकता कि उनका विश्व-दशन औपनिवेशिक साधने में ढला था, और उनका राजनयिक संस्कार भारतीय वैदेशिक सम्बन्धों की ऐतिहासिक परम्परा से नहीं बल्कि पश्चिमी दीक्षा से अधिक प्रभावित था।¹

भारतीय विदेश नीति की ऐतिहासिक परम्परा और उसके उत्तराधिकार की खोज करते समय अन्तः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के योगदान और खासकर नहरू जी के मौलिक यशस्वी कृतित्व की बात उठायी जाती है। इसका विस्तृत विश्लेषण आगे किया जा रहा है, परन्तु यहाँ उन अन्य महानुभावों के प्रति कृतज्ञताज्ञापन आवश्यक है, जिन्होंने भारतीय कांग्रेस के अलग रहते हुए भी सीमित साधनों से तमाम बठिनाइयों से संचर्ष करते हुए अद्भुत राजनयिक कौशल द्वारा विदेशों में भारत की आजादी की लड़ाई जारी रखी। इनमें राजा महेंद्र प्रताप एवं वीर सावरकर के अलावा लाला लाजपत राय और लाला हरदयाल के अनुयायी, गदर पार्टी के तमाम नाग शामिल हैं, जिन्होंने अमरीका, फ्रांस तथा सावियत संघ में उल्लेखनीय राजनयिक काम किया। इसमें अतिरिक्त वीरेन्द्र नाथ चट्टोपाध्याय और मानचन्द्र नाथ राय जैसे लोग भी थे, जो अपने साम्यवादी दृष्टान्त के कारण अन्तर्राष्ट्रीयता के प्रेमी बन। कुन मिलाकर एस लाला ने बीसवीं सदी में भारतीय विश्व-दृष्टान्त को प्रभावित किया। इनमें वीरेन्द्र नाथ चट्टोपाध्याय को तो प्रत्यक्ष रूप से नहरू जी का प्रेरक-उत्प्रेरक कहा जा सकता है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर की स्थिति और भी अनूठी है। राजनीति से सीधे न जुड़ते हुए भी उन्होंने अपने मानवतावादी दृष्टान्त के कारण दूर दूरवाले व तमाम देशों के साथ समन्वयवादी सांस्कृतिक आदान-प्रदान का सूत्रपात किया। इसका लाभ आगे चढ़कर एसियाई भानुभाव व विश्व-बधुत्व की भावना को पुष्ट करने में नहरू जी का मिला।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और विदेश नीति

(Indian National Congress and Foreign Policy)

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यमवर्गीय मद्रासवादी द्वारा की गयी थी। यह स्वाभाविक था कि ऐसे लोगों की रचि और जानकारी वैदेशिक मामलों में सामान्य से ज्यादा थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व हमारे अधिवक्ता (1892) में ही इस बात का विरासत मिया गया था कि भारतीय सैनिकों का प्रथम उपनिवेशवादी प्रशासन अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति व लिए बर्मा और अफगानिस्तान में कर रहे थे। परन्तु, कुन मिलाकर अपने प्रारम्भिक वर्षों

¹ दृष्टं—K. P. S Menon *Many Worlds* (London 1965)

के युग में परदेसियों के माध्यम से पराधीन उपनिवेशों के रूप में हुआ।¹

स्वतन्त्र भारत न तो हीनता की दृष्टि से प्रसन्न था और न ही किसी प्रकार के अपराध बोध से। हजारों वर्षों से भारत के वैदेशिक सम्बन्ध शान्तिपूर्ण, समता वाले एवं महकार की भावना से ओत-प्रोत रहे हैं। यह मात्र संयोग या अवसर-वादिता नहीं कि नेहरू जी ने स्वतन्त्र भारत की विदेश नीति की आधार शिला असोक और बुद्ध के शाश्वत सिद्धान्तों एवं दर्शन पर रखी। इस मिलनमिले में यह बात याद रखने लायक है कि जब भारत ने बाहरी विश्व से अपना नाता तोड़ा एवं अपने विश्वकी-दरवाजे बन्द किये, तभी भारतीय क्रूर मद्दक बन गये और भारतीय राजनयिक क्षमता का ह्रास आरम्भ हो गया। अरब यात्री अलबरूनी ने अपने यात्रा वृत्तान्त में यह बात बहुत अच्छी तरह से उद्घाटित की है।

ऐसा नहीं कि भारतीय विदेश नीति की ऐतिहासिक परम्परा सिर्फ हजारों वर्ष पहले ही हुई थी या तकती है। मुगलों के बाद केन्द्रीय सत्ता के दृष्ट-उधर धिक्कर जाने पर भी विदेशों के साथ प्रमुख भारतीय राजनयिक हस्तियों के सम्बन्धों का सिलसिला चलता रहा। मराठों और टीपू सल्तान ने अंग्रेजों से लोहा लेते वक्त फ्रांसियों से सहायता व गमर्पण पाने का प्रयत्न किया, तो राजा राम मोहन राम प्रसाद व्यक्ति मुगल सम्राट की पैरवी करने के लिए बिलायत तक पहुँचा। 1858 के बाद ही यह स्थिति पैदा हुई, जब भारतीयों को इस सम्प्रभु अधिकार से वंचित किया गया और ब्रिटेन में लन्दन स्थित इण्डिया आफिस ने भारतीय रियामतो और ब्रिटिश सामनाधीन भारत के वैदेशिक सम्बन्धों का बीड़ा उठाया। तब भी भारत की स्थिति अल्प उपनिवेशों से भिन्न थी। भारत के आकार और सामरिक महत्व को देखते हुए यह संभव नहीं था कि उसके बारे में विदेश नीति सम्बन्धी मारे निर्णय लन्दन में लिये जायें। ब्रिटिश सम्राट का भारत में नियुक्त प्रतिनिधि गवर्नर जनरल नहीं, बल्कि वायसराय कहलाता था। उसका अधिकार क्षेत्र काफी विस्तृत था। अनेक विद्वानों ने यह मत प्रकट किया है कि भारतीय हितों को लेकर इण्डिया आफिस, ब्रिटिश विदेश विभाग और वायसराय के बीच एक त्रिकोणीय रस्माकमी चलती रहती थी। अफगानिस्तान और तिब्बत के सम्बन्ध में इसी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए भारतीय अंग्रेज अधिकारियों को काफी स्वायत्तता स्वयंसेव मिल जाती थी।²

प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों की सार्थक भागीदारी के बाद भारत की विशेष स्थिति और भी मजबूत हुई। जब राष्ट्र सघ (League of Nations) की स्थापना हुई तो भारत की स्वतन्त्र रूप से इसका सदस्य बनाया गया। इसी तरह जब द्वितीय विश्व युद्ध की सामरिक जरूरतों के अनुसार भारत के औपनिवेशिक प्रशासकों को अपने सन्निहित देशों के साथ रणनीति के बेहतर समाधानों की जरूरत महसूस हुई तो अमरीका और चीन में भारतीयों की निरुक्ति लगभग 'पूर्ण राजदूत' के

¹ भारत में वैदेशिक सम्बन्धों की ऐतिहासिक परिदृश्य में बचाने के लिए देखें—A. L. Basham, *Wonder that was India* (London, 1969) and D. P. Sinha, *India and the World Civilization* (Calcutta, 1972).

² अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी में भारत के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की उपयोगी जानकारी के लिए देखें—Bimal Prasad, *Origins of Indian Foreign Policy: The Indian National Congress and World Affairs* (Calcutta, 1962).

बुद्धि बनी रही और उन्होंने साम्राज्यवादी-उपनिवेशवादी शोषण से औरो को भी मुक्त करने का बड़ा उद्योग। जेतस्की के नेतृत्व में कोमिनतार्न की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मानवेन्द्र नाथ राय और वीरेन्द्र नाथ चट्टोपाध्याय सरीखे भारतीयों ने सैद्धान्तिक और व्यावहारिक रूप से समाजवाद के अन्तर्राष्ट्रीयकरण के प्रकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। साम्राज्यवाद और समाजवाद के बीच जन्मजात वैर है। लेनिन की प्रसिद्ध उक्ति है—पूँजीवाद का चरमोत्कर्ष साम्राज्यवाद है अतः साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्षरत स्वतन्त्रता सेनानियों को हर सम्भव सहायता देना मोवियत सघ की भावनात्मक ही नहीं, बल्कि सामरिक जरूरत भी थी।¹

इन दोनों महत्वपूर्ण घटनाओं के पहले रूस पर जापान की विजय ने इस घर्षण को रेखांकित किया कि आवश्यक मनोबल और वांछित आधुनिकीकरण के बाद 'निकृष्ट' समझी जाने वाली एशियाई जनता भी बड़ी शक्तियों में से किसी एक को ध्वस्त कर सकती है। चीन में राष्ट्रवादी क्रान्ति ने भी यही प्रमाणित किया कि इस ऐतिहासिक राष्ट्र का आत्मसंय और नशे की लत अब और अधिक समय तक उसे बीमार नहीं रख सकत। निस्संशय ही इन दोनों घटनाओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं को प्रभावित किया।¹ गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं और सावरकर जैसे लोगों का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। कहने का अभिप्राय यह है कि कुल मिलाकर, गांधी और नेहरू के आधिपत्य तक भारत के मन्दर्भ में आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ तेजी से बदल रही थी। और वैदेशिक मामलों में हचि न लेना असम्भव-सा हो गया था। यूरोप और एशिया में इतनी जोरदार सामाजिक व राजनीतिक उथल-पुथल मची थी, जिसे किसी समझदार-मनबदनशील व्यक्ति द्वारा अनदेखा करना सम्भव नहीं था। विलायत के एक स्कूल में पढ़ रहे किशोर जवाहर लाल नेहरू ने अपन पिता को सिख एक पत्र में बहुत उत्साह के साथ आयरलैण्ड के प्रवास के दौरान आयरलैण्डवासियों के राष्ट्र प्रेम और उनके स्वतन्त्रता संग्राम के बारे में अजित जानकारी उद्धृत की। नेहरू जी के योगदान का अधमूल्यान किए बिना यह बात स्वीकार की जा सकती है कि बीमबी शताब्दी के पहल दो दशकों के समाप्त होते ही उपनिवेशवाद विरोध विश्वव्यापी बन चुका था। किसी भी दश का स्वाधीनता संघर्ष किसी न किसी बड़ी शक्ति के लिए (जो औपनिवेशिक शक्ति की प्रतिद्वन्द्वी हो) विदेश नीति का प्रश्न भी बन जाता था। अनेक महत्वपूर्ण निर्वासित प्रवासी स्वाधीनता सेनानी ऐसी जगह शरण लेते थे। मोवियत सघ ने ऐसे तत्वों को शिक्षित कर पथ प्रदर्शक का काम करना चाहा। इनके लिए जो रणनीति अपनायी गयी, वह शत्रु के विरुद्ध संयुक्त मार्च बारी और पूँजीवादी देशों में वामपंथी-समाजवादी रुझान के बुद्धिजीवियों व पत्रकारों को अपन पक्ष में इस्तेमाल करने वाली थी। बरनार्ड शा, एच० जी० वेल्स, बर्ट्रेण्ड रसेल और एल० एन० लैन, ई० पी० टोमसन जैम लार्ग व नाम इस मिलमिड में गाम तौर पर उल्लेखनीय हैं।

1927 में ब्रसेल्स में 'साम्राज्यवाद विरोधी नीम' की पहली अन्तर्राष्ट्रीय बैठक हुई। इसमें एक सत्र का महापतित्व नेहरू जी ने किया। इस बैठक को एक मील का पत्थर समझा जाता है और इसमें माध्यम में यह दर्शाने का प्रयत्न किया जाता है कि किस प्रकार नेहरू जी अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में हचि रणन चाल अनेक व्यक्ति

¹ एशियाई राष्ट्रवाद के उदय और इसके अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रकाश पर विमलेषण के लिए देखें—K. M. Panikkar *Asia and the Western Dominance* (London 1967)

में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व्यापक जनधार वाली कोई क्रान्तिकारी संस्था नहीं थी। इसका तथा इसके नेताओं का स्व-रवेया मुधारवादी और समझौतावादी था। अतः आने वाले वर्षों में मले ही इसने विदेश नीति विषयक कई प्रस्ताव पारित किये, परन्तु उनका महत्व सीमित ही रहा। लेकिन इसकी यह एक महत्वपूर्ण दूरदर्शिता थी कि इस मस्या ने आरम्भ से ही भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम को एशियाई-अफ्रीकी भाईचारे और साम्राज्य-विरोध के साथ जोड़कर देवना शुरू किया।¹

अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में रुचि अधिक स्पष्ट रूप से दर्शाना और विदेश विदेश नीति के प्रति असहमति का स्वर सुन्न करना वास्तव में भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी के आधिपत्य के साथ ही आरम्भ हुआ। सित्ताफ्त आन्दोलन के दौरान विदेश नीति के मामलों (धर्म के आधार पर ही सही) के साथ भारत की आम जनता को जोड़ा गया। इस बार फिर अरब-एशियाई एकता तथा उपनिवेशवाद विरोधी स्वर गूँट हुआ। महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका में अनुभव उन्हें नस्लवादी वर्गों का असली चेहरा दिखा चुका था। उनके लेखन, भाषणों आदि में रणभेद व नस्लवाद विरोध भी विदेश नीति में रुचि लेने वालों के लिए महत्वपूर्ण बन गये।

लगभग इसी समय दो ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएँ हुईं, जिन्होंने इस विषय को प्रेरितकारी ढंग से प्रभावित किया। एक थी—1914 में प्रथम विश्व युद्ध का विस्फोट और दूसरा था—1917 में सोवियत संघ में बोल्शेविक पार्टी द्वारा सत्ता ग्रहण करना। कुछ विद्वानों का यह मानना भी तर्कसंगत है कि इसमें दो बातें और जोड़ी जानी चाहियें—1905 में जारशाही रुस की जापान के हाथों पराजय और 1911 में चीन में भक्त राष्ट्रवादी प्रगति। इन सब ऐतिहासिक घटनाओं का पुनरीक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि स्वतन्त्रता के शारम्भिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विदेश नीति का अध्ययन करते वक्त अक्सर नेहरू जी जैसे प्रतिभा-शाली व्यक्तियों के करिष्माती योगदान का मूल्यांकन करते हुए निर्णायक व ऐतिहासिक धाराओं की उपेक्षा की जाती रही है।

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर भारतीय सैनिकों को यूरोपीय तथा अन्य अफ्रीका-एशियाई मोर्चों पर लड़ने का मौका मिला। इस अनुभव ने उनके सामने यह कटु सत्य उद्घाटित किया कि औपनिवेशिक शासकों के लिए 'भारतीय जान' की कीमत बलि के बकरों जितनी ही है। इसके अलावा उन्हें यह समझने का मौका मिला कि उन्हें गुलाम बनाने वाले बोरे राष्ट्र युद्ध अपनी आजादी की कितनी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार हैं। राजनीतिक चेतना से सम्पन्न बुद्धिजीवियों के लिए इन निष्कर्षों पर पहुँचना कठिन नहीं था कि साम्राज्यवादी प्रभुत्व उपनिवेशवाद की किसी विशेषता पर नहीं, बल्कि भाड़े के देशी टट्टियों पर ही टिका है। इसी तरह मौखिक प्रगति की सफलता ने यह बात मजबूती से साबित दी कि सामान्य मले ही कितना उत्पीड़क और सैनिक शक्ति-सम्पन्न क्यों न दीयता हो, परन्तु विले-दुर्वन दिखने वाला प्रतिद्वन्दी उसका तत्ता पसंद सकता है। इसके अतिरिक्त लेनिन और शोव्स्की जैसे बोल्शेविक नेताओं की मूल प्रेरणा मार्क्सवादी विचारधारा थी, जिसमें मजदूर वर्ग के सर्वहाराओं को एक होने के लिए आह्वान किया गया था। कम से कम सफलता प्राप्ति के तत्काल बाद के वर्षों में बोल्शेविकों की वैचारिक

¹ इस सिद्धि में व. बखित भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा प्रकाशित दस्तावेजों का संकलन उपयोगी है—N. V. Raj Kumar (ed.), *Indians Outside India* (Delhi, 1951)

मनन न नेहरू जी को अपनी जन-सम्पर्क प्रतिभा से प्रभावित किया परन्तु वह स्वयं भी नेहरू जी के सम्मोहक आकषण से नहीं बचे रह सके। 1935-36 की यात्राओं के दौरान विलायत में ही नहीं, बल्कि यूरोप में अन्यत्र भी कृष्ण मेनन ने ही नेहरू के पत्रकार सम्मेलनों, उनकी भेंट वार्ताओं आदि का आयोजन किया। कृष्णा मेनन के आग्रह पर ही नेहरू जी ने गृह-युद्धग्रस्त स्पेन का दौरा किया और जापानी आक्रमणकारियों में जूझते हुए चीन के साथ सहानुभूति प्रकट की। यह उल्लेखनीय है कि इन मामलों में सिर्फ साप्ताहिक समर्थन प्रकट कर ही नेहरू जी सन्तुष्ट नहीं हो जाते थे। कम से कम चीन के सन्दर्भ में देश भर से चन्दा एकत्र कर डा० कोटनीम के नेतृत्व में एक चिकित्सा मिशन चीन भेजा गया और इस परोपकार का लाभ समय बीत जाने के बाद भी भारत को मिला। इन्हीं वर्षों में नेहरू जी ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का भी दौरा किया और प्रवासी भारतीयों के मामले में अपनी दृष्टि दर्शायी। इन यात्राओं के अतिरिक्त अपने कारावास के दौरान नेहरू जी को विविध पढ़ने लिखने का अवसर मिला और उपनिवेशवाद के तुलनात्मक अध्ययन ने उन्हें भारत के भविष्य के बारे में और देशों के सन्दर्भ में सोचन की प्रेरणा दी। कारावास में नेहरू जी की लिखी पुस्तक—पिता के पत्र पुत्री के नाम (*Letters to the Daughter*), विश्व इतिहास की झलक (*Glimpses of World History*), भारत की खोज (*Discovery of India*) और उनके विलुप्त पत्राचार से इस बात की पुष्टि होती है।¹

उपरोक्त वर्णन से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वैदेशिक मामलों में रुचि लेने वाले नेहरू जी अकेले व्यक्ति थे। 1936 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विदेश विभाग का भी गठन किया गया। नेहरू जी के अतिरिक्त राम मनोहर लोहिया, जय प्रकाश नारायण व आचार्य नरेन्द्र देव इसका सक्रिय सदस्य थे। इनमें लोहिया की पढाइ-लिखाई जमनी में हुई थी तो जयप्रकाश नारायण वर्षों अमरीका में रह चुके थे। बाहरी दुनिया के बारे में उनकी जानकारी नेहरू जी से कम नहीं थी। बल्कि यह कहा जा सकता है कि नेहरू जी की तरह अंग्रेजीपरस्त और अंग्रेज प्रेमी न होने के कारण उनका दिमाग इस मामले में ज्यादा खुला था। भीमू मसानी ने अपनी पुस्तक 'Bliss was it in that Dawn' में इस बात पर स्पष्ट टिप्पणी की है कि इनमें से कोई भी व्यक्ति भारत के वैदेशिक सम्बन्धों के मामले में नेहरू जी के पतन को अस्वीकार नहीं स्वीकार करता था। लोहिया और जयप्रकाश सोवियत संघ के प्रति उस तरह मोहविष्ट नहीं नहीं रह जिस तरह नेहरू जी। बाद में वर्षों में नेहरू जी को मल ही बनने ही स्वतन्त्र भारत की विदेश नीति निर्माण का श्रेय दिया जाय परन्तु यह मानने का कोई कारण नहीं कि 1947 के पहले भी उनकी ऐसी ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे व्यक्ति अपने विविष्ट परिवेश के कारण अरब जगत के बारे में एक सामान्य रह ही विशेषज्ञता रखते थे।

नेहरू के विश्व-दर्शन की सीधा टकराव सुभाष चन्द्र बोस के विश्व-दर्शन से

¹ यह वर्णन निम्नांकित लेखकों द्वारा रचित नेहरू जी की जीवनिओं पर आधारित है—
B R Nanda *The Nehrus Motilal and Jawaharlal* (London 1965) B N Pandey *Nehru* (London 1976) और S Gopal *Jawaharlal Nehru A Biography* (Delhi 1976)

थे और कितने कौशल से भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम का अन्तर्राष्ट्रीयकरण करने में वे सफल हुए। यदि गृहयुद्ध से छानबीन की जाये तो यह बात छिपी नहीं रह सकती कि इस मामले में पहले नेहरू जी ने ही की थी, बल्कि सोवियत संघ में क्रोमिनतार्न में सक्रिय अफो-एशियाई तत्वों ने वुसेल्स सम्मेलन के लिए जमीन तैयार की थी। 1927 में वुसेल्स सम्मेलन की नींव बस्तुतः लगभग एक वर्ष पहले बाकुनगर में आयोजित एक सम्मेलन में रखी जा चुकी थी। सम्मेलन-स्थल के रूप में वुसेल्स का चुनाव सिर्फ इसलिए किया गया था कि रूस में इस सम्मेलन का आयोजन किये जाने पर इसे सत्तावादी पक्षान्तर के रूप में बदनाम करना आसान होता। अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के बारे में नेहरू जी का 'भार्य दर्शन' वीरेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय निरन्तर करते रहे। उन्हें समझ था कि नेहरू जी के प्रगतिशील तैवरों को वे अपनी इच्छानुसार ढाल सकेंगे। बाद में जब महात्मा गांधी के प्रभाव में नेहरू जी ने कठपुतली बनना अस्वीकार कर दिया तो बड़े भाववेश के साथ वीरेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय ने अपनी निराशा व्यक्त की। वुसेल्स सम्मेलन के बारे में इन सब बातों की पुष्टि नेहरू जी आत्मकथा और 'कुछ पुरानी चिट्ठियाँ' (A Bunch of Old Letters) में संकलित पत्रों से होती है।

सोवियत संघ और साम्यवादियों के साथ मोह भग होने के बाद कुछ समय के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में नेहरू जी को हचि कम हुई। दोबारा इस ओर उनका ध्यान तब गया, जब अपनी पत्नी कमला नेहरू के इलाज के लिए उन्हें स्विट्जरलैंड जाना पड़ा। नेहरू जैसा व्यक्ति अस्पताल के गलियारों में खाली नहीं बैठा रह सकता था। उन्होंने समय काटने के लिए जेनेवा में होने वाले वैदेशिक मामलों के सम्बन्धित व्याख्यान-मीटिंगों में भाग लेना शुरू किया और अवसर मिलने पर यूरोप के विभिन्न देशों का भ्रमण किया। इन्हीं दिनों उनकी मुलाकात यूरोपीय चिन्तक रोमा रोला से हुई और बेकोस्लोवाकिया के प्रखर राष्ट्रवादियों से भी। जैसाकि नेहरू जी के जीवनीकार बी० एन० पाण्डे ने लिखा है—'यह एक सौभाग्यपूर्ण संयोग था, जब दो विश्व युद्धों के बीच के अन्तराल में यूरोप की निर्यात बढ़त रही थी, उस समय नेहरू जी इसके प्रत्यक्षदर्शी रह सके। इसने उन्हें पारम्परिक शक्ति-सन्तुलन का पथार्थ आत्मसात करने का ठो अवसर दिया ही, उनके चिन्तन को फासीवाद-नाजीवाद बनाम जनतन्त्र की बहस के बारे में भी साफ किया, इस समय तक नेहरू जी भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में प्रवेश कर रहे नौसित्तिये, आदर्शवादी एवं मोति-भाति रूमानी व्यक्ति नहीं रह गये थे। उन्होंने किसान आन्दोलन के नेतृत्व द्वारा अपनी अलग निजी पहचान बना ली थी। पश्चिमी देशों में उनकी तीव्रता और उनकी मुखरता के कारण उन्हें भारतीय स्वाधीनता संग्राम की मुख्य धारा का प्रवक्ता स्वीकार किये जाने लगा था। इस प्रमाण्डल के निर्माण में वामपंथी रक्षान के अग्रज बुद्धिजीवियों जगन्ना हेरिसन और ई० पी० टॉमसन जैसे लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था। नेहरू जी की आत्मकथा के प्रकाशन के बाद उनकी अन्तर्राष्ट्रीय लोकप्रियता में असाधारण वृद्धि हुई।

इस आत्मकथा के प्रकाशन में नेहरू जी की कृष्णा मेनन से बड़ी सहायता मिली। कृष्ण मेनन पहले से इंग्लैंड में दृष्टिग्राह्य लोग का संचालन कर रहे थे और लेबर पार्टी के साथ सम्बन्ध गुप्तार कर भारतीय स्वधीनता संग्राम के विषय में विचारियों व पत्रकारों के बीच जनमत तैयार करने का काम कर रहे थे। कृष्णा

सकते हैं।¹ ऐसा नहीं था कि ये सब बातें नेहरू जी के व्यक्तिगत आदर्शवादी द्ष्टान्त में प्रेरित थीं और उनका कोई सम्बन्ध भारत के राष्ट्रीय हित में नहीं था। जैसा कि नेहरू जी अक्सर कहा करते थे कि वर्तमान का आदर्शवाद नविष्य का द्वापरादर्शवाद होता है। ये नयी सिद्धान्त आपस में बँधे हुए थे और अद्भुत ढंग से दूरदर्शी थे। भारतीय विद्वान् नीति के प्रमुख सिद्धान्तों का विश्लेषण निम्नान्वित बिन्दुओं के तहत किया जा सकता है—

1. विश्व शान्ति (World Peace)—विश्व शान्ति में नेहरू की आस्था सिर्फ इसलिए नहीं थी कि वह बुद्ध और अशोक के देश में जन्मे थे या अहिंसक महात्मा गांधी के पट्ट शिष्य थे। नेहरू में व्यक्तिगत माहस की कोई कमी नहीं थी। उनके जीवन के अनेक प्रकरण उन्हें दुस्साहिक ही बताते हैं। विश्व शान्ति के प्रति उनका आकर्षण उन व्यक्तिगत अनुभव से उपजा था जिसमें उन्होंने यूरोप के समृद्ध-सम्पन्न देशों को युद्ध की आय में झुलमते और बर्बाद होते देखा था। जिस समय भारत आजाद हुआ, उस समय सारा विश्व द्वितीय महायुद्ध के ध्वंस का बोझ उठा रहा था। नेहरू जी इन बातों को भत्तोभाँति नमज़ते थे कि यदि विश्व शान्ति अक्षत नहीं रखी जा सकती तो अमीबा और एशिया के अनगिनत देशों को आजाद होने का मौका नहीं मिलेगा। जब तक बड़ी शक्तियाँ सुघर्षरत रह्यो, उन्हें सामरिक दृष्टि से साम्राज्यवादी रणनीति के अनुसार अपने-अपने प्रभाव क्षेत्र बनाने हों होंगे। इन प्रभाव क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले छोटे राष्ट्र-विपन्न समाज ऐसी हालत में स्वाधीनता की कल्पना भी नहीं कर सकते। नेहरू जी ने यह बात बहुत पहले आत्ममात कर ली थी कि विकास और विनाश के बीच गहरा अन्तर-सम्बन्ध है। जब तक विश्व पर युद्ध के बादश मँडराएँ रहेय, तब तक विकासशील-नवोदित राष्ट्रों के लिए राष्ट्र-निर्माण के सत्साधन गुलब नहीं हो सकते। नेहरू पूराप में महायुद्ध तथा अफ़्ग़ानिस्तान देशों में गृह युद्ध के अपने निजी अनुभवों से यह बात मस्तीनाँति समझते थे कि युद्ध का दबाव अन्य सभी सामाजिक प्राथमिकताओं को पीछे धकेल देता है। वह मनुष्य के पारिवारिक पक्ष को उकसाना-उमरता है तथा अधिनायकवाद को बढ़ावा देता है। फ़ासीवाद-नाज़ीवाद का उदय प्रथम विश्व युद्ध के मलब के बिना सम्भव नहीं था। परमाणु अस्त्रों के आविष्कार ने नेहरू जी के शान्तिवादी चिन्तन को और भी पुष्ट किया। भारत की स्वाधीनता को मार्गक बनाने तथा विकास की गति तेज़ रखने के लिए लिए विश्व शान्ति अनिवार्य थी। इसीलिए नेहरू जी ने अपने विदेश नीति नियोजन में विश्व शान्ति को प्राथमिकता दी।

2. गृह-निरपेक्षता (Non-alignment)—गृह-निरपेक्षता की अवधारणा विश्व शान्ति की स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू थी। द्वितीय महायुद्ध के बाद युद्ध-विराम तो हो गया परन्तु शान्ति नहीं लौटी। मित्र राष्ट्रों में फूट पड़ गयी और शत्रु युद्ध का आविर्भाव हुआ। परमाणु अस्त्रों के आविष्कार के बाद पारस्परिक शान्ति-मन्तुलन का स्थान आतंक के सन्तुलन ने ले लिया। इस विषय पर विशद टिप्पणों अन्वय की गयी है। यहाँ सिर्फ इतना स्ताकिन करना यथष्ट रहगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति बेहद तनावपूर्ण और जोखिम भरी हो

¹ दृष्टे—A. Appadorai and M. S. Rajan (ed.) *India's Foreign Policy and Relations*, (Delhi, 1965) तथा A. Appadorai, *Domestic Roots of Indian Foreign Policy, 1947-1972*, (Delhi, 1981)

था। सुभाष भी विलायत में पढ़े थे और तेजस्वी-करिमाती व्यक्तित्व के धनी थे। वह नेहरू जी की तरह दो विश्व युद्धों के बीच के अन्तराल में यूरोप का विस्तृत दौरा कर चुके थे। ऐतिहासिक साहित्य का अध्ययन करने और उसके आधार पर भारत के भविष्य के बारे में निष्कर्ष निकालने की प्रवृत्ति भी उनमें नेहरू जी जैसी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि सुभाष चन्द्र बोस उन्हीं परिस्थितियों और सामग्री का अध्ययन कर नेहरू के बिल्कुल विपरीत निष्कर्ष पर पहुँचे थे। सुभाष का मानना था कि ब्रिटेन एक ह्रासोन्मुख शक्ति है। अतः भारत ब्रिटेन के शत्रुओं को सहायता देकर ही उनको अपना मित्र प्रमाणित कर सकता है और इस तरह अपने स्वाधीनता सपना की गति तेज कर सकता है। अबगर सुभाष चन्द्र बोस पर फासीवादी-नाजीवादी होने का आरोप लगाया जाता है, परन्तु यह बिल्कुल निर्मूल है। स्वयं गांधी जी ने यह बात बेहिसाब स्वीकार की थी कि सुभाष के देशप्रेम पर कोई भी अंगुली नहीं उठा सकता। इसी तरह यह भी एक अति सरलीकरण है कि नेहरू जी के विदेश नीति विषयक सुझाव भावसंगीर्षी थे और सुभाष चन्द्र बोस के अति यथार्थवादी। वस्तुतः 1939 में जब क्षितिज पर युद्ध के बादल मड़रा रहे थे तो कोई भी यह भविष्यवाणी नहीं कर सकता था कि सैनिक मुठभेड़ में कौन-सा पक्ष विजयी होगा। 1943 तक पलड़ा पुरी राष्ट्रीय पक्ष में झुका रहा। इन्हीं दिनों सुभाष ने आजाद हिन्द फौज का गठन किया और दक्षिण-पूर्व एशिया के अनेक राष्ट्रों को गुलामी के जुए से छुड़ाने (प्रतीकात्मक डग से ही सही) में भारतीय योगदान उद्घाटित किया।

1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश पक्ष को समर्थन देने का सवाल उठा तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी में टकराव असल में नेहरू जी और सुभाषचन्द्र बोस के द्वन्द्व का ही रूपान्तर व विस्तार था। 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन के बाद सभी प्रमुख भारतीय नेता बन्दी बना लिये गये और इनकी रिहाई युद्ध की अवसान बेला में डिमल्टा सम्मेलन (1945) के लिए ही हुई। परन्तु इसमें यह नहीं समझना चाहिये कि अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निष्क्रिय हो गयी थी। विमान दुर्घटना में अपनी अकाल मृत्यु तक सुभाषचन्द्र बोस ने स्वाधीन भारत की अन्तर्राष्ट्रीय महावकाश को जीवित रखा। इसके अलावा 1943 के सान फ्रांसिस्को सम्मेलन में गैर-सरकारी प्रतिनिधि के रूप में श्रीमती बिजय लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया और सरकारी प्रतिनिधियों को प्रभावहीन बना दिया। जेल में बन्दी होने के बावजूद नेहरू जी का अपने मित्रों के साथ पत्राचार जारी रहा और वह बाग काई शोक तथा ह्यूबेल्ड जैसे सहानुभूति रखने वाले शीर्षस्थ विदेशी नेताओं के माध्यम से राजनय अनवरत रख सके। इस अनुभव ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारतीय विदेश नीति निर्धारण-नियोजन में भारी योगदान दिया।

भारतीय विदेश नीति के नीति निर्धारक तत्व व सिद्धान्त (Basic Principles of Indian Foreign Policy)

विश्व शान्ति, गुट निरपेक्षता, निष्पक्षीकरण का समर्थन, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद व नस्लवाद का विरोध, अफ्रो-एशियाई एकता का आह्वान और समुक्त राष्ट्र सभ के सिद्धान्तों में आस्था भारतीय विदेश नीति की नींव के परस्पर समझे जा

निःशस्त्रीकरण के प्रति आकर्षण किसी दुर्बलता से नहीं उपजा था। न्यायमगत विषय पर आत्मरक्षा के लिए शस्त्र प्रयोग से नेहरू जी को कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी। गोवा, वदमीर और चीन के प्रसंग इसका अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।

4 साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद व रगभेद का विरोध (Opposition to Imperialism, Colonialism and Apartheid)—विश्व-शान्ति, गुट निरपेक्षता व निःशस्त्रीकरण की पक्षधरता के बावजूद नेहरू द्वारा निर्धारित भारतीय विदेश नीति के सिद्धान्तों में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद व नस्लवाद का कटु विरोध शामिल था। सतही दृष्टि से इसमें भले ही विरोधाभास जान पड़े, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। नेहरू जी ने यह बात बहुत पहले स्पष्ट कर दी थी कि विश्व शान्ति को सबसे बड़ा सफ़ट साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद एवं नस्लवाद से है। नेहरू जी का ऐतिहासिक अध्ययन और राजनीतिक अनुभव उन्हें यह बात भी भली-भाँति आत्मसात करवा चुका था कि नस्लवाद और उपनिवेशवाद बिना साम्राज्यवादी समर्थन के टिक नहीं रह सकते। भारतीय अनुभव के कारण नेहरू जी वास्तव में इस सपर्य का शान्तिपूर्ण परामर्श द्वारा समाधान चाहते थे परन्तु आवश्यकता पड़ने पर सशस्त्र जन-मुक्ति संग्राम को भारतीय समर्थन देने में उन्हें सकोच नहीं होता था।

5. अफ्रो-एशियाई एकता (Afro-Asian Solidarity)—नेहरू जी ने यह बात बहुत पहले अच्छी तरह गाँठ बाँध ली थी कि ससार के सभी विपन्न और दबित राष्ट्रों और समाजों के हित एक ममान हैं। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद व नस्लवाद का विरोध हो या गुट निरपेक्षवाद आन्दोलन के मंचालन द्वारा विश्व शान्ति और निःशस्त्रीकरण को आगे बढ़ाने का मंचाल, इसके लिए अफ्रो-एशियाई एकता की पुष्टि परमावश्यक थी। इस प्रकार नेहरू द्वारा अफ्रो-एशियाई भाईचारे की बात उठाना कोरा भावावेश नहीं, बल्कि एक तर्कसंगत वदम था।

6 सयुक्त राष्ट्र सभ में आस्था (Faith in the U.N.)—इसी तरह सयुक्त राष्ट्र सभ के प्रति नेहरू जी का आकर्षण किसी आदर्शवाद नादानी से प्रेरित नहीं था। बल्कि उपर्युक्त 'अन्तर-मन्बन्धित सिद्धान्तों' के व्यवहार में रूपान्तरण की सम्भावना के कारण उपजा था। नेहरू जी निहायत यथार्थवादी ढंग में जानते थे कि बीटो के कारण सं महाशक्तियों के बीच त्रिब की स्थिति पैदा हो जाने से सं० रा० सभ में भारत जैसे गुट निरपेक्ष देश को रचनात्मक भूमिका निभाने का मौका मिल सकता है और सदस्य देशों की जमात में अफ्रो-एशियाई देशों की वृद्धि होने के साथ इन मंच का उपयोग विश्व शान्ति की स्थापना, निःशस्त्रीकरण के प्रसार और साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद व नस्लवाद के विरुद्ध सघर्ष के लिए बागूबी किया जा सकता है।

भारतीय विदेश नीति . विभिन्न चरण

भारतीय विदेश नीति में निरन्तरता और परिवर्तन की दोनों धाराएँ साप-साप चलती रही है। आजादी के बाद भारत ने जहाँ उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद व रगभेद और बड़ी शक्तियों की गुटबाजी का बड़ा विरोध किया, वहीं 1962 के बाद भारतीय विदेश नीति की प्राथमिकताएँ और जोर कुछ अन्य मामलों पर केन्द्रित हो गया। कुछ और वर्षों बाद नई विश्व अर्थव्यवस्था की तलाश, समुद्री कानून सम्मेलन, उत्तर-दक्षिण सवाद, दक्षिण-दक्षिण सवाद और परमाणु निःशस्त्रीकरण जैसे

गयी थी। नेहरू जी ने बेहद समझदारी के साथ नवोदित राष्ट्रों के सामने गुट-निरपेक्ष नीति अपनाने का सुझाव रखा। जाहिर है कि गुट-निरपेक्षता का अर्थ निष्क्रिय उदासीनता, तटस्थता या अवसरवादिता नहीं था। अपनी स्वाधीनता को भुलकर कर स्व-विवेक के अनुसार अपने राष्ट्र हित के अनुकूल विकल्प चुनना असली गुट-निरपेक्षता थी। इस नीति पर डटे रहना कठोरपन नहीं, बल्कि साहस का काम था।

नेहरू जी ने यह बात आरम्भ में ही स्पष्ट कर दी कि उनका इरादा अपने देश को महाशक्तियों के दगल से अलग बचाकर रखने का है और क्रमशः शान्ति के धेन के विस्तार का। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि भारत की कोई भी महत्वाकांक्षा तीसरे खेमे के गठन और उसके मुखिया के हथ में उभरने की नहीं है। नेहरू जी यह बात अच्छी तरह समझते थे कि गुट-निरपेक्षता त्यागने का अर्थ किसी न किसी महाशक्ति का शिविरानुचर बनना ही हो सकता है और ऐसा करना कठिनाई से अर्जित आजादी को खोना होता है। नेहरू जी ने कभी यह समझने-मनमाने की सादानी नहीं की कि गुट निरपेक्षता का अर्थ निष्क्रिय रहना है। इसके अतिरिक्त गुट-निरपेक्षता के कारण भारत जैसा नवोदित राष्ट्र दोनों खेमों में आर्थिक महायत्ना ग्रहण कर सकता था। आरम्भ में सत्ते की तत्कालीन सीमित सासक स्टालिन और अमरीकी विदेश सचिव डेले ने गुट निरपेक्षता को उपहास का विषय समझा, किन्तु कौरिया और हिन्द चीन के अनुभव के बाद उनके द्वारा भारत की ईमानदारी पर प्रत्यक्ष-विश्व लगाना सम्भव नहीं रहा। नेहरू जी ने गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के बहाने, मित्र, कम्युनिस्ट, इण्डोनेशिया और युगोस्लाविया जैसे देशों से सम्बन्ध प्रतिष्ठ कर अफ्रीका, एशियाई भाईचारे और विद्वत्-बन्धुत्व के माब को पुष्ट किया। जब साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद के विरुद्ध मुस्लिम छेड़ना जरूरी समझा गया तब गुट निरपेक्षता का मन्त्र बेहद उपयोगी सिद्ध हुआ। इसीलिए मिश्रित गुप्त जैसे विद्वानों ने टिप्पणी की है कि शायद गुट निरपेक्षता को भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख सिद्धान्त कहने की अपेक्षा इसे विदेश नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपनायी गयी रणनीति कहना समीचीन है।

3. निरास्त्रीकरण (Disarmament)—जिस तरह गुट निरपेक्षता विश्व शान्ति से जुड़ी हुई थी, उसी तरह निरास्त्रीकरण का मुद्दा गुट निरपेक्षता से गुंथा हुआ था। जब तक शस्त्रास्त्रों की अन्धी दौड़ जारी थी, तब तक विश्व शान्ति को निरापद नहीं समझा जा सकता था। शस्त्रीकरण की प्रक्रिया अनिवार्यतः गुट की मान्यिकता को पुष्ट करती थी, जिसमें सैनिक संगठन, सशस्त्र की घेरावन्दी, जोर-आजमाइश आदि से बचना कठिन था। परमाणु अस्त्रों के आविष्कार ने शस्त्रीकरण की समस्या के और भी गहराया आयात उद्घाटित किये थे। कई लोगों का यह भी मानना है कि नेहरू जी के लिए विश्व शान्ति और निरास्त्रीकरण अलग-अलग मुद्दे नहीं थे। नेहरू जी ने हर उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रीय मंच से निरास्त्रीकरण का सन्देश प्रसारित किया। इसके खातिर वह अपने आत्मीय मित्रों से टकराने में भी कमी करवाये नहीं। गुट निरपेक्ष देशों के बेसब्रेड जिएनर सम्मेलन (1961) में सुधारों के साथ उनकी मुठभेड़ निरास्त्रीकरण बनाम नव-उपनिवेशवाद को लेकर ही हुई थी। कुछ अन्य विद्वानों का यह भी मानना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में नेहरू जी की आस्था इसीलिए गहरी थी, क्योंकि वह समझते थे कि बिना व्यावहारिक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के सम्प्रभु राष्ट्र स्वेच्छा से शस्त्र त्याग नहीं करने वाले। नेहरू जी का

शान्तिपूर्ण समाधान की प्रस्तावना के बिना यह अस्तित्व की बात सोची भी नहीं जा सकती थी। पंचशील योजना में यह बात अन्तर्निहित थी कि इसका अभिगम निरपेक्ष प्रतिरक्षात्मक नहीं बल्कि रचनात्मक भी है। पंचशील समझौते में साप्ताहिक पक्षों के लिए लाभप्रद उभयपक्षीय सहकार के लक्ष्य तय करना नेहरू जी की दूरदर्शिता थी।

पंचशील के बारे में विदेशी और भारतीय विद्वानों के मत स्पष्टतः दो ध्रुवों के बीच घूमते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि पंचशील की बात उठाना नेहरू जी की दुर्बलताजनित विवशता थी। सैनिक शक्ति और आर्थिक संसाधनों के अभाव में वह और कुछ कर भी नहीं सकते थे। जयन्तनुज बन्धोपाध्याय जैसे कुछेक विद्वान अपवाद हैं जो मानते हैं कि नेहरू जी ने जान बूझकर यह जोखिमभरा कदम उठाया, ताकि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को नई दिशा दी जा सके। दूसरी ओर लोन आर्थिक और नेविल मेक्सवेल सरीखे लेखक हैं जिनकी समझ में पंचशील एक धृत्तापूर्ण पाखण्ड था, जिसका एकमात्र उद्देश्य भारत को सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ मोहलत जुटाना था। वैसे, इन दोनों बातों में कोई बुनियादी अन्तर विरोध नहीं है। आर्थिक और सैनिक उपकरणों के अभाव में यदि बाहुग सम्मेलन (1955) के अवसर पर नेहरू जी ने भारत को अदभुत प्रतिष्ठा दिला दी थी तो उसके आधार में पंचशील की सफलता ही थी।

बाहुग सम्मेलन के बारे में मजबूत बात यह है कि अफ्रो-एशियाई देशों के इन जमघट का आयोजन भारत के मुसुआ पर नहीं किया गया था। कोलम्बो परि-योजना में शामिल पश्चिमी लैमे के पक्षधर राष्ट्रों ने इसकी पहल की, परन्तु नेहरू जी और कृष्णा मेनन ने समपदारी दिखाते हुए इसे नवोदित राष्ट्रों की स्वाधीनता और गुट निरपेक्षता का प्रतीक बना दिया। आज कई दशक बाद बाहुग सम्मेलन की सीमाओं और असफलताओं का छिद्रावेपथ सहज है। परन्तु नेहरू जी ने शीत युद्ध के मकड़ा से झूपते हुए जिस तरह सैनिक गठबन्धनों की निरस्त करने का प्रयास किया वह प्रशंसनीय था। ऐसा सोचना ठीक नहीं कि नेहरू जी ने निरपेक्षता के बन्धन से तीसरी दुनिया का नेतृत्व हथियाने के लिए ऐसा किया। बाहुग सम्मेलन के आयोजन के पहल कारिया में अपनी निष्पक्ष मध्यस्थता और हिंद चीन में युद्ध विराम के लिए सक्रियता से भारत ने अपनी पात्रता प्रमाणित कर दी थी। नासिर, मुकारों आदि न माय व्यक्तिगत स्तर पर साथ-साथ सवाद का मूत्रपात भी बाहुग सम्मेलन से ही सम्भव बना।

बाहुग सम्मेलन का एक और दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय महत्व है। इस सम्मेलन में हिस्सेदारी के बाद ही चीन की साम्यवादी सरकार का मानवीय पक्ष अन्य देशों के सामने आया और उसको बाधित स्वीकृति मिल सकी। इस सम्मेलन में अपनाये गये प्रस्तावों का अध्ययन करने पर यह बात स्पष्ट होती है कि पंचशील समझौते की तरह इस बार भी नेहरू जी ने आदर्श और यथार्थ का सतुलन बँटाने की कोशिश की थी। उनका प्रमुख प्रयत्न यही था कि अधिकाधिक अफ्रो-एशियाई देशों का ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से प्रेरित मना-सम्मेलनीय राजनय में शामिल किया जा सके ताकि नविष्य में उठने वाला विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान की सम्भावना बची रहे। बाहुग सम्मेलन की उपलब्धि यही थी कि दोनों महाशक्ति को यह बात स्पष्ट समझायी जा सकी कि अफ्रो-एशियाई देशों का उनसे कोई जमझट बर सैद्धान्तिक

मसले विश्व राजनीति में छा गये। जाहिर है कि भारत इनके प्रति मौन नहीं रह सकता था। इनके अतिरिक्त पड़ोसी देशों के साथ भारत के सम्बन्ध भी अनेक बार काफी तनावग्रस्त हुए। इन सभी बातों का अध्ययन विभिन्न भारतीय प्रधान मन्त्रियों के शासन काल के दौरान अपनायी गई विदेश नीति के विश्लेषण से करना उचित होगा।

नेहरूकालीन विदेश नीति : सिद्धान्त व व्यवहार का टकराव (Foreign Policy during Nehru Era)

नेहरू की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धान्त स्वाधीनता संग्राम के दिनों में ही सुनिश्चित हो गये थे। व्यावहारिक रूप में इनको औपचारिक ढंग से पंचशील के नाम से परिभाषित किया गया। पहले ही भारत व चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर अप्रैल, 1954 में किये गये, परन्तु 1947 से लेकर 1954 तक भारत के अन्तर्राष्ट्रीय फ़िर्माक़नाम इसी आधार पर संचालित व समायोजित होते रहे।

पंचशील के पाँच सिद्धान्त निम्नलिखित हैं—

- (i) सभी राष्ट्र एक दूसरे की प्रादेशिक अश्रुता व सम्प्रभुता का सम्मान करें;
- (ii) कोई राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण न करे और दूसरों की राष्ट्रीय सीमाओं का अतिक्रमण न करे;
- (iii) कोई राज्य किसी दूसरे राज्य के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे;
- (iv) प्रत्येक राज्य एक-दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करे तथा पारस्परिक हित में सहयोग प्रदान करे (अर्थात् न कोई देश बड़ा है और न ही छोटा);
- (v) सभी राष्ट्र शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्त में विश्वास करें तथा इसी सिद्धान्त के आधार पर एक-दूसरे के साथ शान्तिपूर्वक रहे और अपनी घृणकृ मत्ता एवं स्वतन्त्रता बनाये रखे।

कुछ विद्वानों का मानना है कि 'पंचशील योजना' नेहरू जी की आदर्शवादी रुमानियत का उदाहरण भर थी, और कुछ नहीं। परन्तु यह बात अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि पंचशील की राजनयिक रणनीति भारतीय राष्ट्रीय हितों की पर्याप्तवादी कमीदी पर खरी उतरती है। भारत का विभाजन आजादी के साथ ही गया और पाकिस्तानी राजकारण ने कश्मीर को हथियाने के साक्ष्य में भारतीय सीमा का अतिक्रमण किया। यह अपोषित युद्ध लगभग दो वर्ष तक चलता रहा। 1947 में सारा भारतीय भू-भाग एक साथ स्वतन्त्र नहीं हुआ। राजवाड़ों की स्थिति सिन्धु घाटी और गोवा, दमन, दीव, चण्डी नगर व पाण्डिचेरी जैसे इलाक़े अंग्रेजों से इतर दूसरी औपनिवेशिक शक्तियों के आधिपत्य में थे।

इसके शीघ्र बाद एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। 1949 में चीन ने साम्यवादियों ने सरकार का गठन किया और 1950 में तिब्बत को मुक्त करने का प्रयास शुरू किया। इसके साथ ही ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन काल में सीमांकित किया गया भारत हिमालयी सीमान्त विवादालय बन गया। ऐसी परिस्थिति में यदि नेहरू जी ने नवोदित राष्ट्रों की सम्प्रभुता की रक्षा, भौगोलिक सीमाओं के सम्मान और आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप से बचने के पक्ष में अन्तर्राष्ट्रीय जनमत तैयार करने की चेष्टा की तो इसे आदर्शवादी कतई नहीं समझा जा सकता। समस्याओं के

शास्त्रीकालीन विदेश-नीति

(Foreign Policy during Shastri Era)

1964 में नेहरू जी की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने देश की बागडोर संभाली। शास्त्री जी का व्यक्तित्व अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री नेहरू जी से इतना भिन्न था कि कई लोगो के मन में यह प्रश्न पैदा होना स्वाभाविक था कि विदेश-नीति नियोजन और निर्धारण के मामले में शास्त्री जी अलग रहेंगे। न तो उनकी शिक्षा दीक्षा विदेश में हुई थी और न ही प्रधानमंत्री बनने के पहले उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में कोई विशेष रुचि दर्शायी थी। इसी कारण जब शास्त्रीकालीन भारतीय विदेश-नीति का विश्लेषण किया जाता है तो नेहरू-युगीन विदेश-नीति के साथ उमका फर्क दर्शाने का लोभ सबरण कम ही लोभ कर पाते हैं। शास्त्रीकालीन विदेश-नीति के सन्दर्भ में अक्सर यह कहा जाता है कि उन्होंने निरवैक आदर्शवाद को सार्वक यथार्थवाद में विस्थापित किया और शान्ति प्रेमी होने के बावजूद राष्ट्र-हित के संरक्षण-संवर्धन के लिए सैनिक उपयोगों की उपयोगिता स्वीकार की। उनके कार्य-काल का विशेष अध्ययन करने वाले प्रोफेसर एस० पी० मिह का मानना है कि 'भले ही उन्होंने भारतीय विदेश-नीति के क्षितिज सकुचित किये, किन्तु उन्हें कुल मिलाकर मौलिक मूल में घचित नहीं समझा जा सकता और न ही उनके योगदान को नगण्य माना जा सकता।'।

शास्त्री युग की भारतीय विदेश नीति में दो प्रमुख स्मारक बिन्दु हैं— (i) पाकिस्तान के साथ मैत्रिक मुठभेड़ के बाद ताशकन्द समझौता, और (ii) श्रीलंका की प्रधानमंत्री श्रीमती सिरिमावो बण्डरनायक के साथ परामर्श के बाद नागरिकता-विहीन प्रवासी तमिलों के बारे में शान्तिपूर्ण समाधान। जहाँ एक ओर रक्त के रण में और उसके बाद पाकिस्तान के साथ युद्ध में शास्त्री जी ने यह स्पष्ट किया कि वह शान्ति प्रिय और शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के नाम पर भारतीय राष्ट्रीय हित की रक्षा करने के लिए तैयार नहीं है, वहीं श्रीलंका के साथ समझौते में उन्होंने अन्य छोटे पड़ोसी देशों को इस बारे में आश्चर्य किया कि भारत का कोई इरादा बल प्रयोग द्वारा उन पर हावी होने का नहीं था। मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों की स्थापना के लिए वह रियायतें देने को प्रस्तुत थे। नेहरू जी की तरह अपनी अन्तर्राष्ट्रीय छवि या अह का बरकरार रखने की कोई समस्या शास्त्री जी के मामले नहीं थी।

शास्त्री जी की विदेश नीति के बारे में दो-तीन और बातें उल्लेखनीय हैं। एक तो उन्होंने प्रधानमंत्री मन्मथलाल बख्शाला का गठन कर अपने सलाहकारों की एक नई टोली जुटायी। इससे विदेश मन्त्रालय के अवमूल्यन की प्रक्रिया चाहे-अनचाहे शुरू हुई। इससे अतिरिक्त परमाणु नीति के मामले में शास्त्री जी ने यह निर्णय लिया कि सामरिक विकल्प को त्यागा न जाये।

ताशकन्द सम्मेलन में दिन का दौरा पड़ने में शास्त्री जी की मृत्यु हो गयी। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन, राष्ट्रमण्डलीय राजनय, अफ़्गानिस्तान भाईचारे आदि के क्षेत्र में निजी द्वाप छोड़ने का कोई अवसर उन्हें नहीं मिला। यह भी स्मरणीय है कि

विचारधारा या नस्ल के आधार पर नहीं है। पाकिस्तान और चीन (अब श्रीलंका) के साथ भारतीय प्रतिनिधियों की नोक-झोंक भले ही होती रही, परन्तु बाइगु में ही उस अफ्रो-एशियाई गुट का गठन हुआ, जिसने संयुक्त राष्ट्र सभ में इनकी हस्ती को महत्वपूर्ण बनाया। बाइगु भावना के बिना गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का बेगवान बनना कठिन होता।

परन्तु इस सबसे यह समझना उचित नहीं कि नेहरू जी की विदेश-नीति तर्क-संगत और दूरदर्शी होने के कारण सभी प्रकार की दुर्बलताओं से मुक्त थी। नेहरू जी सदैव इस बात को अनदेखा करते रहे कि अधिकतर अफ्रो-एशियाई नेताओं का स्वभाव और मस्कार उनसे भिन्न है और यह जरूरी नहीं कि वे हमेशा बदली परिस्थिति में भी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति विषयक उनकी सभी स्थापनाओं को लाभप्रद-उपयोगी उपदेश के रूप में ग्रहण करते रहे। बाइगु सम्मेलन के सम्मरण लिखते पत्त नाशिर और चाऊ एन सार्दी दोनों ने यह स्वीकार किया है कि नेहरू जी हमेशा इस तरह आचरण करते थे जैसे वह उनके बड़े भाई या पय-प्रदशक हों। दोनों नेताओं को यह बात अपमानजनक लगती रही थी। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि नेहरू जी की विदेश-नीति और राजनय व्यक्ति-केन्द्रित थे और व्यक्तिगत समीकरण बदलने पर विदेश-नीति और राजनय बहुत सीमित प्रभाव जाले रह जाते थे। बेलग्रेड सम्मेलन में मुकार्पो और नेहरू जी के बीच टकराव में बाद पुरानी सुखद स्थिति कभी लौटायी नहीं जा सकी।

नेहरू जी की एक और कमजोरी थी। वह अपनी पतन्त्र-नापसन्द को छिपाकर नहीं रख सकते थे। उनकी आस्था समाजवादी जनतन्त्र में थी। वह राजशाही, सामन्तवाद तथा सैनिक शासन को प्रतिश्रियावादी समझते थे। नेपाल तथा पाकिस्तान के साथ उनका व्यवहार इसी कारण कभी सहज नहीं हो सका। श्रीलंका के प्रधान-मन्त्री जोन कोटलेबाला ने एक बार यह मटीक टिप्पणी की थी कि 'भारत जैसा बड़ा राष्ट्र गुट-निरपेक्षता की विलासिता भोग सकता है परन्तु छोटे राष्ट्रों के लाने यह सुविधापूर्ण मार्ग उपलब्ध नहीं।' आचरण में व्यावहारिक होने के बावजूद घोषणाओं के स्तर पर सैद्धांतिक छुट्टि का दुराग्रह नेहरू जी की विद्वमनीयता और भारतीय विदेश-नीति का प्रभाव कम करता रहा। समस्याओं के शान्तिपूर्ण निपटारे की बात करते वक्त नेहरू जी कद्मौर थे जनमत संग्रह के अपने आश्वासन को निरन्तर टालते रहने के लिए बाध्य हुए। वह गोवा की मुक्ति के लिए बल-प्रयोग के बाद कथनी और करनी में दोहरे मानदण्डों के लिए भी बबनाम हुए। इसी तरह भारत-चीन सम्बन्धों की गलतफहमी एक बड़ी सीमा तक इस बात से पैदा हुई कि जहाँ नेहरू जी एक ओर स्वयं को स्वतन्त्र भारत के प्रतिशील प्रधानमन्त्री के रूप में पेश करते थे, वही देश की भौगोलिक सीमा के बारे में औपनिवेशिक उत्तराधिकार को अक्षत रखने के लिए वह वचनबद्ध थे। नेहरूमानी भारतीय विदेश-नीति की सबसे बड़ी विशेषता यही पुराने और नये व परम्परा और परिवर्तन का अन्तर्द्वन्द्व थी। महाशक्तियों और पक्षीक्षियों के साथ 1947 से 1964 तक भारत के राजनयिक सम्बन्धों के उनाट-चढ़ाव में इसका तनाव स्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बित होता है।¹

¹ भारतीय विदेश-नीति के आधारभूत विद्वानों का उपरोक्त तार सर्वे व व्यापकवाद बनाम आदर्शवाद के द्वन्द्व का विश्लेषण भारतीय विदेश नीति के प्राथमिक सन्दर्भ पथों पर आधारित है। इनमें से दिग्गमिन्ड यह उल्लेखनीय है—Charles H. Helmuth, *Diplomatic History of*

नहीं किया जाना चाहिए कि उन्होंने कठिनतम आन्तरिक चुनौतियों से जूझते हुए भारत को अन्तर्राष्ट्रीय राजनय का केन्द्र-बिन्दु बनाये रखने में सफलता प्राप्त की। 1966 से 1969-70 तक कांग्रेस पार्टी में उनकी अपनी स्थिति निरापद नहीं थी और भारत विकट आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था। रुपये का अवमूल्यन, प्रिवीपर्स की समस्या, बैंक का राष्ट्रीयकरण, कांग्रेस का विभाजन, बिहार में अकाल का सामना आदि चुनौतियाँ उन्हें अपने कार्यकाल के पहले चरण में पूरी तरह व्यस्त रखे रही। दगला देश प्रचरण में पराक्रमी प्रदर्शन और 1971 के चुनाव में अभूतपूर्व सफलता के बाद थोड़े ही समय के लिए उन्हें वैदेशिक मामलों में एकाग्रचित होने का अवसर मिला। 1972 में शिमला सम्मेलन सम्पन्न हुआ तो 1973-75 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में उनके राजनीतिक अस्तित्व की चुनौती देने वाला व्यापक जन-आन्दोलन शुरू हुआ। इसकी परिणति जून, 1975 में आपातकाल की घोषणा और अन्ततः मार्च, 1977 के समदोष आम चुनाव में श्रीमती गांधी की हार में हुई।¹

जनता सरकार की विदेश नीति • निरन्तरता और परिवर्तन (Janta Government's Foreign Policy)

मार्च, 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी ने शासन की बागडोर सम्भाली। जिन परिस्थितियों में जनता सरकार का गठन हुआ, उसमें श्रीमती गांधी ही नहीं, बल्कि नेहरू वंश के प्रति रोष-आक्रोश का स्वर तेज था। आपातकाल की तानाशाही की दुस्मन् जैसी स्मृति जनता के मन में थी। जनता सरकार का नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी की सभी नीतियों को बदलने के लिए ध्येय थे। फिर भी नए विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कार्यभार सम्भालने के बाद यह घोषणा की कि वह नेहरू की विदेश नीति के अनुसार ही आचरण करेंगे। कहने को मले ही उन्होंने 'वास्तविक गूट-निरपेक्षता' (Genuine Non-alignment) की बात की परन्तु इसका प्रमुख अभिप्राय यह दर्शाना था कि इन्दिरा गांधी ही अपने पिता के मार्ग से विचलित हुई थी। पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्धों के क्षेत्र में जल्दतर से ज्यादा रिवायती व नरम रुख अपनाना जनता सरकार के लिए धायद इसलिए जरूरी हुआ कि उसके विदेश मंत्री वाजपेयी की अब तक छवि 'आक्रामक हिन्दू राष्ट्रवादी' वाली थी। जनता सरकार का गठन विभिन्न वैचारिक दृष्टान्तों वाले राजनीतिक दलों को मिलाकर हुआ था। इसी कारण किसी स्पष्ट अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य या सैद्धान्तिक अभिगम की अपेक्षा उनमें नहीं की जा सकती थी। यह स्वाभाविक था कि नौकरशाही का महत्व विदेश नीति नियोजन के क्षेत्र में बढ़ा।

अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में जनता सरकार का वरिष्ठ सदस्या की अनुसन्धानता भी भारत के लिए हानिप्रद सिद्ध हुई। तत्कालीन जर्मनीकी राष्ट्रपति कार्टर की भारत-यात्रा (1978) के दौरान मोरारजी देसाई के साथ उपजी गतफहमी और जनता सरकार (चरण सिंह के नेतृत्व में) के दूसरे विदेश मंत्री दयामन्दन मिश्र की विदेश यात्राएँ इसका उदाहरण हैं। जहाँ एक ओर गृह मंत्री चरण सिंह इसे

¹ इन्दिरा गांधीकालीन विदेश नीति के विषय अध्ययन के लिये देखें—Indira Gandhi, *India and the World (Foreign Affairs, New York, October, 1972)*

1964-66 में भारत भयकर दुर्भिक्ष से ग्रस्त था और अपमानजनक ढंग से विदेशों में खाद्यान्न के आयात पर निर्भर था। ऐसी परिस्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय रणमंच पर भारत की भूमिका कतई प्रमुख नहीं हो सकती थी। इसे शास्त्री जी की एक बड़ी उपलब्धी समझा जाना चाहिए कि 1962 के घाव को भरने का काम उन्होंने अपने छोटे से कार्यकाल में कबूली लिया।¹

इन्दिरा गांधी-कालीन विदेश नीति : बदला परिप्रेक्ष्य (Foreign Policy during Indira Gandhi Era)

जनवरी, 1966 में शास्त्री जी के निधन के बाद इन्दिरा गांधी प्रधानमन्त्री बनीं। जिस तरह की भ्रांतियाँ शास्त्री जी के बारे में फैली हैं, उसी तरह तर्कहीन अति सरलीकरण इन्दिरा गांधी की विदेश नीति और राजनय के बारे में भी प्रचलित है। पत्रकारों और जीवनीकारों की कृपा से श्रीमती गांधी की छवि लौह महिला और रणचण्डी वाली प्रसिद्ध हुई है। जोगी के मन में आज भी या तो 1971 के बंगला देश मुक्ति अभियान की याद ताजा है या मई, 1974 में बोलरन में परमाणु विस्फोट और जून, 1975 में आपातकाल की घोषणा की। यदि चुन-चुन कर ऐसे उदाहरण पेश किये जायें तो श्रीमती गांधी को अति यथार्थवादी प्रमाणित करना कठिन नहीं होगा। इसी तरह के प्रचलन श्रीमती गांधी के अन्तर्मुखी स्वभाव, उनके पारिवारिक एकाकीपन और मानसिक अमरुता के भाव को उनके अन्तर्राष्ट्रीय आचरण के साथ जोड़ने के लिए किये जाते हैं। ऐसा नहीं कि यह विश्लेषण सिर्फ श्रीमती गांधी के आलोचक-बिरोधी हो करते रहे हैं, बल्कि श्रीमती गांधी के साथ सहानुभूति रखने वाले विद्वान भी इस भ्रांति के निकार हुए हैं। उदाहरणार्थ, इन्दिरा गांधी की विदेश नीति का विस्तार से विश्लेषण प्रस्तुत करने वाली लेखिका सुरजीत मातमिह की पुस्तक का शीर्षक ही 'India's Search for Power' अर्थात् 'भारत शक्ति की तलाश में' है। यदि भ्रमंता तत्कालीन न बरतें तो इन निष्कर्ष तक अनामान पहुँचा जा सकता है कि श्रीमती गांधी ने ही सर्वप्रथम पारम्परिक शक्ति-सन्तुलन के आधार पर राष्ट्र हित के हित सम्पादन का काम किया। जैसाकि ऊपर कहा जा चुका है कि पश्चिम, पाकिस्तान, चीन आदि के सन्दर्भ में नेहरू और शास्त्री का आचरण भी भावार्थवादी नहीं समझा जा सकता।

श्रीमती गांधी के सन्दर्भ में यह टिप्पणी अधिक सार्थक लगती है कि उनकी विदेश नीति का अमूर्त वैचारिक पक्ष कहीं अधिक मुखर था। तीसरी दुनिया का स्वाध्याय सफट हों या पर्यावरण के संरक्षण का प्रश्न, श्रीमती गांधी का उद्बोधन-प्राप्तान सिर्फ भारतीय जनता के लिए ही नहीं, बल्कि समस्त विश्व के लिए होता था। इसी तरह यह भी कहा जा सकता है कि पड़ोसी देशों और परमाणु नीति के सन्दर्भ में वह उन्हीं दिशा में आगे बढ़ी, जिस पर शास्त्री जी नवम उठा चुके थे। श्रीमती गांधी को अपनी घोषणाओं-वक्तव्यों में कान्तिकारी प्रगतिशील मुद्रा ग्रहण करना अच्छा लगता था, परन्तु व्यवहार में उन्होंने नेहरू जी की मुद्रावी मुद्रा-निरपेक्ष नीति में किंचित मात्र परिवर्तन या संशोधन की जरूरत नहीं समझी।

श्रीमती गांधी की विदेश नीति का अध्ययन करते वक्त इस बात को अनदेखा

¹ शास्त्रीराष्ट्रीय विदेश नीति के बीरेवार वस्तुनिष्ठ अध्ययन-विश्लेषण के लिए देखें—

I. P. Singh, *India's Foreign Policy: The Shastri Period* (Delhi, 1980)

दलों के बीच देश की अखण्डता को बचाये रखना ही सबसे बड़ी उपलब्धि मंजूर हो गई और उनके कार्यकाल के प्रारम्भिक वर्षों में विदेश नीति के क्षेत्र में उनसे किसी पहल की उम्मीद नहीं की गयी। तथापि राजीव गांधी ने यह स्पष्ट करने में देर नहीं लगायी कि आर्थिक जीवन में उदार नीतियाँ अपनाने के बावजूद भारत की गुट निरपेक्षता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उन्होंने आन्तरिक समस्याओं से जूझते हुए भी विश्वव्यापी भ्रमण किया और सश्रम राजनय का प्रभाव-मण्डल बनाये रखा। उनकी आलोचना इस बात को लेकर की गयी कि 'राजीववासीन विदेश नीति में सौन्दर्य प्रसाधन तो था, स्वास्थ्य नहीं, गति थी तो दिशा नहीं।

इस बात को बिल्कुल निराचार भी नहीं कहा जा सकता। राजीव गांधी के कार्यकाल में विदेश मंत्री कई बार बदले गए तथा विदेश सचिव (ए० पी० वेंकटेश्वरन) को निकाला जाना काफी विवादस्पद बना। राजीव ने नए ही अनेक लम्बे विदेश यात्राएँ कीं किन्तु नीति-सम्बन्धी कोई ठोस मुझाव या दिशा-निर्देश देने में वह अक्षम रहे। इस विषय में उन्होंने अपनी विभी प्रतिभा का परिचय नहीं दिया।

राजीव गांधी के शासन काल में उदार आर्थिक नीतियाँ अपनाकर तथा कुछ अन्य कदम उठाकर अमरीका के साथ भारत के सम्बन्धों में सुधार की कोशिश की गई, किन्तु कोई सफलता हाथ नहीं लगी। पाक को अमरीकी सशस्त्र व आर्थिक मदद के मामले में अमरीका के दृष्ट में कोई परिवर्तन नहीं आया। हाँ, श्री गांधी सोवियत संघ के साथ भारत के पारम्परिक घनिष्ठ रिश्तों के निर्वाह में अवश्य कामयाब रहे। फ्रान्स, जर्मनी और अन्य यूरोपीय राष्ट्रों के साथ सहयोग सम्बन्ध बनाने में मामूली सफलता अर्जित हुई। सब वही देशों में सर्चिले भारत महोत्सव धूमधाम से आयोजित किये गये, किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि भारतीय सांस्कृतिक राजनय ने विदेशी नामांकों या सरकारों पर अपनी कोई छाप छोड़ी।

श्री गांधी को पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्ध सुधार में कोई उत्कल्लेखनीय सफलता नहीं मिली। 1987 में हुए राजीव-जयबर्द्धन समझौते के तहत श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी गई, जिसका नवराष्ट्रवाक अमर ही पड़ा और मिहली नेताओं ने शांति सभा की वापसी की मांग कर भारत को परेशान में डाला। श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल और बंगला देश में भारत को मशकिल नज़रों में देखा गया।

श्री गांधी अपने शासन काल के अन्तिम दिनों में आन्तरिक राजनीति में काफी उलझते गये और बोफोर्स व अन्य मुद्दों ने उनके प्रति जनता में भारी असंतोष पैदा किया। एम म श्री गांधी के लिए विदेश नीति सबसे कमलता पर पहुँचे जैसे उत्साह में ध्यान देना सम्भव नहीं रहे गया। कुल मिलाकर, यह कहा जा सकता है कि काफी उत्साह के बावजूद श्री गांधी भारतीय विदेश नीति के मोर्चे पर अपनी कोई छाप नहीं छाप पाये।

राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की विदेश नीति

(Foreign Policy of National Front Government) -

या न भारतीय विदेश नीति के बारे में यह खान मुख से नहीं जानी रही है कि वह संवैधानिक है, राष्ट्रीय हित व मदद में पक्ष-विपक्ष का ध्यान ही नहीं उठता; फिर भी नवंबर, 1989 में लोक सभा के चुनावों में बाईसेस की हार और राष्ट्रीय

गोरख का विषय सभ्यता ये कि उन्हें चीन-युनिया की कोई खबर नहीं रहती, वही उन्हें बिना किसी प्रमाण के अपने मन्त्रिमण्डल के एक सहयोगी को विदेशी गुप्तचर बताने में कोई संकोच नहीं हुआ। इसी तरह प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई शान्ति प्रेमी थे परन्तु इतने नहीं कि सिद्धान्तों के लिए वह राष्ट्र के सामरिक हित बलि कर देते। परमाणु नीति के मामले में एकपक्षीय घोषणाएँ या पाकिस्तान में भुट्टो की कानूनी हत्या की भर्त्सना न करना उनकी निरपेक्षता ही प्रकट करते हैं।

अनेक बार जनता सरकार की विदेश नीति का अध्ययन-विश्लेषण करते वक्त परिवर्तन और निरन्तरता की बात कही जाती है। यह कहना अधिक सटीक होगा कि दार्ढ्य का यह नमूना एक तरह का व्यवधान था। यह एक ऐसा अन्तराल था जिसमें मुचिन्तित विदेश नीति के रचन नहीं होते। अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के प्रति अपनी इच्छानुसार व्यक्ति विरोध की प्रत्यावर्तित क्रियाएँ (reflex action) ही देखने को मिलती रहीं।¹

श्रीमती इन्दिरा गांधी की वापसी और विदेश नीति

1980 के आम चुनाव में श्रीमती इन्दिरा गांधी की अत्यन्त नाटकीय ढंग से अभूतपूर्व विजय हुई। परन्तु जहाँ से व्यवधान पड़ा था, वही से झुटा काम आगे बढ़ाने का प्रयत्न नहीं उठता था। जनता सरकार के कार्यकाल में श्रीमती इन्दिरा गांधी को अपने अनेक मित्रों को परखने का अवसर मिला। इसके अतिरिक्त अपनी वापसी के बाद उनके मन में निश्चय ही इन बात का अहसास गहरा हुआ कि नियति ने उन्हें कुछ ऐतिहासिक उपलब्धियों के लिए चुना है। इस दूसरे कार्यकाल के विषय में यह कहा जा सकता है कि एक साथ मोहम्मद के बाद श्रीमती इन्दिरा गांधी की विदेश नीति में अति यवार्थवादी और आदर्शवादी महत्वाकांक्षाओं का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। गयोगवश ही सही, मार्च 1983 में गुट निरपेक्ष आन्दोलन का नेतृत्व ग्रहण करने के साथ श्रीमती इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय नेताओं की पहली वरिष्ठ थैली में आ गयी। भारत की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और राजनयिक प्रभाव में उनके जीवन-मरम्मत कोई क्षय नहीं हुआ।²

राजीव गांधी और विदेश नीति : नई चुनौतियाँ (Rajiv Gandhi and Foreign Policy)

अक्तूबर, 1984 में श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद उनके पुत्र राजीव गांधी ने सत्ता की बागडोर सम्भाली। राष्ट्रीय संकट की दृष्ट घड़ी में उन्हें स्वदेश और विदेश में अपार सहानुभूति मिली। आन्दोलनवादी हिंसा और साम्प्रदायिक

¹ विस्तृत विश्लेषण के लिए देखिये—Bimal Prasad (ed), *India's Foreign Policy : Studies in Continuity and Change* (Delhi, 1979); और S. C. Gangal, *Foreign Policy : A Documentary Study of India's Foreign Policy since the installation of the Janata Government* (Delhi, 1980)

² श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासनकाल में भारतीय विदेश नीति का सबसे अच्छा अध्ययन मुरोथ मानसिंह ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में किया है। श्रीमती इन्दिरा गांधी की विदेश नीति के वैचारिक एवं स्पष्टीकरण के लिए उनके भाषणों-लेखों का संकलन देखें—Indira Gandhi, *People and Problems*, (Delhi, 1983).

गांधी ने उन्हें सोवियत मध्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया था, जो उनके वामपंथी रुचि-रश्मन के कारण की गयी राजनीतिक नियुक्ती थी। श्रीमती गांधी के पतन के बाद भी गुजराल ने राजनयिक परम्परा के प्रतिकूल पद त्याग की कोई जरूरत नहीं समझी। गुजराल भारत के विभाजन के समय आने वाले पंजाबी शरणार्थी हैं और पाकिस्तान में उनकी गहरी रुचि है। वैदेशिक मामलों में उनकी रुचि और विशेषज्ञता का रहस्य यही था। उनके पास मुचितित विश्व दर्शन का अभाव है। उनके बारे में इनने विस्तार से टिप्पणी इसलिए जरूरी है, क्योंकि ऐसा लगता है कि विद्वनाय प्रताप मिह ने विदेश नीति की जागीर अपने पूरे कार्यकाल के लिए उन्हीं के नाम लिख दी। एक पत्रकार सम्मेलन में विदेश नीति सम्बन्धी एक प्रश्न पूछे जान पर श्री मिह ने निहायन मामूलीयत के साथ प्रश्नकर्ता को विदेश मंत्री से यह सवाल पूछने की सलाह दी थी। इसी तरह अपन एक साक्षात्कार में गुजराल यह घोषणा कर चुके थे कि तब और अब में सबसे बड़ा अन्तर यह है कि भारतीय विदेश नीति अब विदेश मन्त्रालय में अर्थात् उनके द्वारा बनायी जाती है।

तुलुक-निजाजी में विद्वनाय प्रताप मिह (राजा माहब) राजीव गांधी से कम नहीं थे। जिस तरह श्री गांधी ने तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव वेंकटेश्वरन की छुट्टी की थी, उसमें बहुत-कुछ न सीखत हुए ही श्री मिह ने एम० के० मिह से छुटकावा पा लिया। जिस तरह की पहल की उम्मीद नये प्रधान मंत्री से की गयी उनमें वह अक्षम रहे। घुमा-फिराकर हम उमी यथार्थ तक पहुँचते हैं कि भारत को वैदेशिक मामलों में सबसे बड़ी चुनौती पाकिस्तान बानी है, और पाकिस्तान भारत की आंतरिक राजनीति में साम्प्रदायिकता की समस्या से अमित्र रूप से जुड़ा है। पंजाब हो या कश्मीर, तब तक विदेश नीति का निर्धारण सही ढंग से नहीं हो सकना, जब तक हम इस बात की यथार्थवादी ढंग से स्वीकार नहीं करते। विद्वनाय प्रताप मिह की अटकल यह रही कि एक ओर उनकी सरकार को अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की आवश्यकता थी तो दूसरी ओर चन्द्रशेखर जैसे विधुन्व असनुष्ट सहयोगी उन पर ऐसा दबाव बनाय रहा कि वह (श्री मिह) हर दिन बाढ़ो पहर अपनी सरकार की क्षम-निरपक्षता के प्रमाण प्रकाशित करते रहे। इन परिस्थितियों में विद्वनाय प्रताप मिह ने समझदारी इसी बात में देखी कि चुप्पी गांधी जाये और अपन माच का अल्पष्ट ही रखा जाये। इस विचित्र रणनीति में थोड़ी मोहलत भर मिल सकती थी, भुमीवन से स्थायी मुक्ति नहीं।

यह भी अत्यन्त विचित्र स्थिति थी कि वि० प्र० मिह मन्त्रिमण्डल के सदस्य जार्ज पत्राडिम या पार्टी के मामान्य सदस्य भी अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर अपन विचार व्यक्त करते थे, बहुत में हिस्सा लेते थे, कभी-कभार व्यापस में टकराते भी थे, परन्तु प्रधान मंत्री न तो कोई सलाह-समाधान करते थे और न कोई दिशा-निर्देश देते थे। किसी वाकपटु व्यक्ति ने टिप्पणी की थी कि 'उन (श्री मिह) के लिए सबसे पराया विद्वन नायद हरियाणा या और जपदस्य करने में पहुँचे अपने उप-प्रधान मंत्री दशोवाल की पारिवारिक महत्ववाधायों में देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा में ही उनका मारा समय बीत जाता था।'

श्रीमती म शान्ति महा को वापस बुलाने और नषान में जनतन्त्र की आगिक मरतता के बाद भी 'दक्षेय' (SAARC) क्षेत्र में किसी मार्चक सवाद की शुरुआत नहीं

मोर्चा सरकार द्वारा तत्ता संभालने के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक समीकरणों के बारे में सोच-विचार स्वाभाविक था। इस बार भारतीय महत्वाकांक्ष ने इतने क्रांतिकारी ढंग से पलटा था कि यह विश्लेषण आरंभ हो गया कि राजीव गांधी और कांग्रेस को जपदस्व करने वाली राष्ट्रीय मोर्चा सरकार क्या वैदेशिक मामलों में निरंतरता बनाये रखेगी ?

देश की विदेश नीति में आमूल-मूल परिवर्तन के पक्ष में दो-तीन प्रभावशाली चर्चे प्रस्तुत किये जाते रहे। राजीव गांधी के सत्ता काल में भारतीय विदेश नीति का स्वरूप निश्चय ही यह नहीं रह गया था, जो नेहरू और श्रीमती इन्दिरा गांधी के दौर में था। बात भिन्न इतनी भर नहीं थी कि राजीव गांधी में वैसी विशेषज्ञता या महत्वाकांक्षा नहीं थी, जैसी नेहरू और श्रीमती गांधी में। उन्होंने जिन परिस्थितियों में सत्ता की बाखंडोर संभाली, उसमें आंतरिक शांति और सुव्यवस्था की स्थिति पर भी ध्यान केन्द्रित रखना परमावश्यक था। संयोगवश, आतंकवाद का उफान और हिमात्मक विस्फोट, चाहे कश्मीर में हो या पंजाब में, पाकिस्तान के राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ गये। दूसरे शब्दों में, भारतीय विदेश नीति के सिद्धि पक्षों तक संकुचित हो गये। इसी तरह श्रीलंका में साम्प्रदायिक युद्ध पुड के उतार-चढ़ाव पर राजीव गांधी का कोई 'बरा' नहीं था। परन्तु, एक बार सैनिक हस्तक्षेप का निर्णय लेने के बाद इस सामरिक दमदल में फँसना उनकी दुर्लभ नियति बन गयी। अपनी विषमता के लिए एक बहुत बड़ी सीमा तक राजीव गांधी खुद ही जिम्मेदार रहे। जहाँ गुट निरपेक्ष सम्मेलन या महाशक्तियों के साथ भारत के सम्बन्धों के सुचारु रूप से सम्पादन में उनके आकर्षक व्यक्तित्व ने निश्चय ही उनका काम सहज बनाया, वही तुलकभिजाती तथा चाटुकारों के जमघट ने उन्हें वरिष्ठ अनुभवी सलाहकारों से वंचित रखा। कुल परिणाम यही रहा कि 21वीं सदी का स्वागत करने की उनकी महत्वाकांक्षा शनि शकर अम्बर सरीसृपों की दयनीय कितरेबाजी से धूल-धूसरित हो गयी।

इस परिदृश्य में नये प्रधान मंत्री विदेनाराय प्रताप सिंह से जनसाधारण को यह अपेक्षा थी कि भारत की विदेश नीति, जो अपनी पारम्परिक राह से भटक मोड़ी रही थी, पुनः और दीर्घ व्यवस्थित होगी। यह सोचना मूलतः नहीं था कि राजीव गांधी की अदूरदर्शिता, अहंकार, आदि की इत्तीनें देकर भारतीय विदेश नीति की बहुत सारी गलतियों की सुचारा जा सकेगा। तियाचिन हो या श्रीलंका, नेपाल हो या अन्ध्रप्रदेश, इसका सान उठाया जा सकता था। यह अनुमान भी लगाया गया कि भारतीय राजनय अब व्यक्ति-केन्द्रित नहीं होगा और विदेश नीति का नियोजन अधिक सुलेपन के साथ होगा। दुर्भाग्यवश, इनमें से रचनात्मक परिवर्तन की कोई भी आशा पूरी नहीं हुई।

इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार नहीं मामलों में राष्ट्रीय सरकार नहीं थी। केन्द्रीय मन्त्रिमंडल के विभागों का चितरण मोर्चे के घटक मदद्यों की शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार किया गया। विडंबना यह कि इस घर-बैठवारे में विदेश नीति को सबसे कम महत्व दिया गया। एक ऐसे व्यक्ति को विदेश मंत्रालय का कार्य-भार सौंपा गया, जो राजनीतिक निहाज में हलके बजन का था। इतना ही नहीं, नये विदेश मंत्री इन्द्र कुमार गुजराल पर अवतरादिता का आरोप भी लगाया जाता रहा था। भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती

के साथ सम्बन्धों में भावावेश रहित या आत्मस्तानि से मुक्त परिवर्तन के संकेत मिलने लगे थे। दुर्भाग्यवश, इस दशा में कोई प्रगति होती, उसके पहले ही चन्द्र शेखर को पदत्याग करना पड़ा।

बहुमत खोने के सङ्कट की तलवार उनके सिर पर हर घड़ी लटकी रही। चन्द्र शेखर सरकार का सत्तारूढ़ रहना कांग्रेस (ई) पर आधारित था और इस कारण वैदेशिक मामलों में दिशा-परिवर्तन की गुंजाइश कम थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यकाल में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को यह सुखद आदत पड़ गयी थी कि अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर वह अपनी भूमिका पूर्ववत् निभा सकते हैं। गुट निरपेक्ष आन्दोलन हो या खाड़ी में सङ्कट या फिर नामीबिया का स्वाधीनता समाराह, भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहचान और पूछ राजीव गांधी की ही रही। यह स्वाभाविक ही था कि देश की आन्तरिक राजनीति में समर्थन का भरोसा बनाये रखने के लिए चन्द्र शेखर ने इस क्षेत्र को राजीव के लिए ही एक तरह से छोड़ दिया था।

यहाँ इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि ऐसा कर चन्द्र शेखर अपनी जिम्मेदारी से कतरा रहे थे। यह मुझाना तर्कसंगत है कि वे इस बटु यथार्थ को पहचानते थे कि तेजी से बदले अन्तर्राष्ट्रीय परिपक्ष में भारत की भूमिका का अवमूल्यन हुआ है। विशेषकर जब सोवियत संघ स्वयं घोर आर्थिक मरुट से ग्रस्त है, उसके मध्य एशियाई गमराज्य बगावत का बिगुल बजा चुके हैं और अमरीका ही भूमण्डल पर अकेली महाशक्ति बचा है, तब भारतीय राजनय का प्रतीकात्मक महत्व ही हो सकता है। ऐसे में जान पड़ता है कि उन्होंने अपनी शक्ति और समय को आन्तरिक राजनीति पर केन्द्रित करने को ही ठीक समझा।

1991 में इराक द्वारा कुवैत पर कब्जा और तदनन्तर अमरीका द्वारा इराक में सैनिक हस्तक्षेप ने दुनिया भर को हिलाकर रख दिया था। एक ओर विक्रामगील देशों पर पेट्रोल सङ्कट के नये काले बादल मझाने लगे थे तो दूसरी ओर अफो-एशियाई एकता या अरब एकता की नपुंसकता भी जग-जाहिर हो गई। इराक, कुवैत आदि में बहुत बड़ी समस्या में भारतीय प्रवासी रहते थे। उनके द्वारा अजित और स्वदेश भेजी जाने वाली विदेशी मुद्रा भारत के लिए सामरिक महत्व की थी। इस युद्ध ने विदेशी मुद्रा के भण्डार को तहम-नहस कर दिया। इसके अतिरिक्त भविष्य के लिए भी समृद्धि का यह स्रोत सूख गया। हमले के हर्जाने या हस्तक्षेप के खर्च की भरपाई के लिए इराक को जो आर्थिक दण्ड मिला, उसका लाभ अनुशासक-आश्रामक अमरीका और मित्र राष्ट्रों को ही हुआ। जाहिर है कि इस शान्तिकारी चुनौती के दूरगामी समाधान का अन्वेषण चन्द्र शेखर सरकार नहीं कर सकती थी। पर, यह स्वीकार करने में किसी को भी हिचक नहीं होनी चाहिए कि युद्ध क्षेत्र में फँस प्रवासी भारतीयों को और उनको वापस लाने के काम में तत्कालीन सरकार ने काफी चुस्ती और कार्यकुशलता दर्शायी।

इसी सन्दर्भ में एक जोर बात विवादास्पद बनी। युद्ध के दौरान कुछ अमरीकी लड़ाकू विमानों को भारतीय हवाई अड्डों पर उतरने और इधर मरने की सुविधा मुहैया कराई गई। शेखर के इस 'कैमले' की कांग्रेस ने बटु भर्त्सना और आलोचना की। चन्द्र शेखर ने यह बात जगजाहिर करने में देर नहीं लगाई कि अमरीकी विमानों को यह सुविधा राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यकाल में दी गई 'अनुमति' के अन्तर्गत ही 'हटीन' रूप में मिली थी। उन्होंने यह भी

हो सकी। सोवित सप में मध्य एशियाई गणराज्यों की बग़ावत हो या यूरोप में जर्मनी का एकीकरण, अफ्रीका में नेल्सन मंडेला की रिहाई हो या चीन में असन्तोष की सुगबुगाहट, किसी भी क्षेत्र या मुद्दे पर नये सन्दर्भ में भारतीय हितों को परिभाषित करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया।

कुल मिलाकर, वी० पी० सिंह की छवि कमजोर-भावुक, निपट भोले और अहंकारी व्यक्ति के रूप में ही उभरी, जो पदों के पीछे के जोड़-तोड़ में ज्यादा सिद्धहस्त है और वह आदर्शवादी शब्दाडम्बर से अपने को मुक्त नहीं रख सकते। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस असफल रुमानी हिन्दी कवि को वाशिंगटन, मास्को, बीजिंग या इस्लामाबाद में से किसी ने गम्भीरता से नहीं लिया। वह रटे-रटाये कुछ मुहावरों को दोहराने के अलावा कुछ नहीं कर सके। हाँ, इस पूरे दौर में विदेश सचिव मुफ़्फ़ुद हुवे नाफ़ी सत्रिय और म्यस्त रहे और उन्हीं का व्यक्तिगत राजनय भारत की अन्तर्राष्ट्रीय उपस्थिति का पर्याय बन गया।

चन्द्र शेखर सरकार की विदेश नीति (Foreign Policy of Chandra Shekhar Govt.)

अपनी सनक में देवीलास को काबू में रखने के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मण्डल आयोग की सिफारिशें लागू करने वाला बह्मस्त्र छोड़ा, जो उनकी सरकार के लिए आत्मघातक सिद्ध हुआ। अग्रस्थापित और नाटकीय ढंग से बूढ़े युवा तुर्क चन्द्रशेखर प्रधानमंत्री बने। उनके साथ अपने विश्वासपात्र समर्थक 50-60 लोकसभा सांसद ही थे। ऐसी स्थिति में यह उम्मीद करना कि वे भारतीय विदेश नीति को नई दिशा या गति दे सकते थे, कहना उनके साथ नाइन्साफी होगी। उन्होंने आरम्भ में ही यह बात दो ठूक शब्दों में कह दी थी कि वह अपना पहला कर्तव्य और सबसे बड़ा उत्तरदायित्व देश के क्षत-विक्षत शरीर पर मलहम लगाना समझते हैं।

विश्वनाथ प्रताप सिंह के विपरीत चन्द्र शेखर इन्दिरा गांधी से लेकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण के अग्रणी सहयोगी के रूप में उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय स्थािति भर्जित की। पुराने समाजवादी होने के नाते अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी आन्दोलन के साथ वह जुड़े रहे और इसी कारण उनका अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के बारे में एक अलग नजरिया रहा है। अमरीका, रूस तथा ब्रिटेन के अलावा भी और देशों के नक्षत्रों की अहमियत उन्हें नजर आती रही। पर, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि दुनिया भर के नेता उन्हें पिता-पिताया शांतिर नेता समझते थे—एक ऐसा व्यावहारिक-समार्थवादी नेता, जिसके साथ सार्थक परामर्श की बात सोची जा सकती है। इसके अलावा पड़ोसी देश नेपाल के शीर्षस्थ नेताओं के साथ चन्द्र शेखर के अभिन्न और आत्मीय सम्बन्धों का लाभ भारत को मिल सका। नेपाल में जनतन्त्र की पुनर्स्थापना के लिए प्रधानमन्त्री बनने के पहले ही चन्द्र शेखर मेहियक अपना समर्थन दे चुके थे। प्रधानमन्त्री बनने के बाद भी उन्होंने कोई सकोच नहीं दिखाया। नेपाल में चुनाव के दौरान भले ही कुछ विपक्षी दलों ने भारतीय प्रधानमन्त्री की भूमिका को आलोचना की किन्तु इस बारे से दो राय नहीं हो सकती कि पिछले वर्षों के उमयपक्षीय तनाव और मनोमासिन्य को दूर करने में चन्द्र शेखर के तत्पर राजनय ने रचनात्मक योगदान दिया। इसी तरह पाकिस्तान और श्रीलंका

मौजूद हैं। इसके आधारभूत सिद्धान्तों में कोई बदलाव नहीं आया है, भले ही आवश्यकतानुसार इनमें से किसी एक का महत्व अधिक रेखांकित किया गया है। भारतीय विदेश नीति की शाश्वत समस्याएँ पाकिस्तान, चीन और अमरीका तथा पड़ोसी देशों (श्रीलंका, बंगला देश) के साथ सम्बन्ध आज भी प्राथमिकता बने हुए हैं। भारत-सोवियत मैत्री, पश्चिम एशिया व दक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीय हित एवं आर्थिक तथा सांस्कृतिक राजनय आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना 1947 में थे। भारतीय विदेश नीति में परिवर्तन की अपेक्षा निरन्तरता की धारा अधिक प्रबल रही है।

भारत और महाशक्तियाँ (India and Super Powers)

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमरीका और सोवियत संघ का महाशक्तियों के रूप में उदय हुआ। ये ऐसे राज्य थे, जो सिर्फ पारम्परिक बड़ी शक्तियाँ नहीं थे, बल्कि इनके वैज्ञानिक बल, आर्थिक क्षमता, तकनीकी सम्भावनाओं आदि की कोई तुलना और किसी बड़ी शक्ति के साथ नहीं की जा सकती थी। यह बात जल्दी ही स्पष्ट हो गयी कि महाशक्तियों की दृष्टि में उनके अपने राष्ट्रीय हित विश्वव्यापी हैं और वे इनकी रक्षा तथा संचयन के लिए विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्य में अपना नीति-निर्धारण एवं राजनय का संचालन करती हैं। इन महाशक्तियों की नीतियाँ सुदृढ़ और एक-दूसरे के अस्तित्व को चुनौती देने वाली परस्पर विरोधी विचारधारा पर टिकी हैं। स्पष्ट था कि इनके साथ दूसरे राष्ट्रों के सम्बन्ध सिर्फ उभयपक्षीय नहीं रह सकते थे। भारत के महाशक्तियों के साथ सम्बन्धों का सर्वेक्षण-विश्लेषण करते समय यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए। वस्तुतः भारत-अमरीका या भारत-रूस सम्बन्धों पर दूसरी महाशक्ति के साथ उसके सम्बन्धों की छाया अनिवार्यतः पड़ती रही है। भारत की गुट निरपेक्ष नीति के कारण शीत युद्ध के प्रारम्भिक चरण में इन दोनों के ही साथ भारत के सम्बन्ध अमूर्त रहे। परन्तु इस नीति पर पहुँचने की जल्द-बाजी नहीं करनी चाहिए कि महाशक्तियों के साथ 'असलमता' या सम-आमोष्य बनाये रखने की कोई विवकता भारत को है।

भारत-अमरीका सम्बन्ध (Indo-US Relations)

भारत और अमरीका दोनों लोकतान्त्रिक देश हैं और मानवीय स्वतन्त्रता, विश्व शान्ति आदि के पापक भी। इन बुनियादी समानताओं के बावजूद उनके बीच समय-समय पर ऐसे अनेक तनाव बिन्दु उभरे, जिस कारण उनमें घनिष्ठ मैत्री सम्बन्धों की स्थापना का मार्ग अभी प्रशस्त नहीं हो पाया। पाकिस्तान को अमरीकी सशस्त्र सहायता, पी० एन०—480 समझौता, यूरनियम की सप्लाय रोकना, बंगला देश मुक्ति अभियान के दौरान अमरीका द्वारा पाकिस्तान का पक्ष लेना, हिन्द महा-सागर का शान्ति क्षेत्र बनाने, परमाणु प्रसार रोक सन्धि, कम्युनिज्म व अफगान संकट आदि ऐसे अनेक मामले हैं, जिन्होंने दोनों देशों के बीच सम्बन्धों को कटू बना रखा। दोनों देशों के नेताएँ शुरू से ही सम्बन्ध सुधार की दिशा में प्रयत्नशील रहे हैं, किन्तु उन्हें इसमें आशियन सफलता ही मिली।

स्पष्ट किया कि इन विमानों से कोई युद्ध सामग्री नहीं ले जायी जा रही थी। बहरहाल, कुल मिलाकर इस घटना को तिल का तार ही कहा जा सकता है। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि भारतीय गुट निरपेक्षता का अन्त इसी से हुआ।

नरसिंह राव सरकार और भारतीय विदेश नीति (Indian Foreign Policy after June 1991)

जून, 1991 से आयोजित लोकसभा चुनाव में कांग्रेस (इ) को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया, किन्तु सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभरने के कारण उसी ने सरकार बनाई। नरसिंह राव के प्रधानमन्त्री पद ग्रहण करने के बाद उन्हें विदेश नीति के मोर्चे पर कोई महत्वपूर्ण राजनयिक कौशल दिखाने का समय नहीं मिला। राव सरकार के समय जहाँ एक ओर गहरा आर्थिक संकट भूँह बाएँ खड़ा था, वहीं दूसरी ओर कश्मीर और पंजाब में आतंकवाद की समस्या और उत्पन्न हो गई, जिससे उसका सारा ध्यान इन्हीं मसलों की ओर बँटा रहा। भारत के वैदेशिक सम्बन्धों में राव सरकार से ज्यादा अपेक्षा भी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि सोवियत संघ के महाशक्ति के रूप में क्षय और अन्य परिवर्तनों ने उसके सामने विकल्पों को काफी सीमित बना दिया। राव ने जर्मनों की यात्रा कर विदेशों पूँजी आकर्षित करने का प्रयास किया, किन्तु कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी। अक्टूबर, 1991 में दूरारे में आयोजित राष्ट्र मण्डल सम्मेलन में आतंकवाद के विरोध और बाल कल्याण पर भारतीय प्रस्तावों को पारित करवाना भी महज नारेबाजी की सभा ही जा सकती है, ठोस राजनयिक उपलब्धि नहीं। कारण यह कि इन मसलों पर अमल के लिए कारगर कदम नहीं उठाये गये।

सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न यह है कि मित्र सोवियत संघ के ह्रास, तीसरी दुनिया की एकता के क्षय, अमरीका के बढ़ते वर्चस्व और यूरोपीय शक्ति के उदय के बाद भारत के लिए नया विकल्प क्या रहता है? भारत में बढ़ते आतंकवाद, अलगाववाद और साम्प्रदायिकता के विघटनकारी मूल पड़ोसी देशों तक बूँटे जा सकते हैं और लाख चाहने पर भी भारत निकट भविष्य में इनसे छुटकारा नहीं पा सकता।

नरसिंह राव प्रधानमन्त्री हों या कोई अन्य व्यक्ति, उसे भारतीय विदेश नीति का सम्पादन-मंचालन इस कटु यथार्थ को ध्यान में रखकर ही करना होगा कि 'वर्तमान भारत' और 'वर्तमान विश्व' 1947 या 1971 वाले नहीं हैं। देश का मुद्रा भण्डार रीता है, सैनिक विकल्प की अधमता थीतका में उजागर हो चुकी है और सांस्कृतिक अस्त्र का प्रयोग भी व्यर्थ हो चुका है। ऐसे में 'तेरे पैर पमारिये, जेती लायी सौर' वाली बहावत के अनुगार आचरण करना ही बुद्धिमत्ता है।

नेहरू जी से लेकर नरसिंह राव सरकार की विदेश नीति सबकी उपरोक्त सर्वेक्षण का प्रमुख उद्देश्य यह दर्शाना है कि भारतीय विदेश नीति अन्य प्रमुख शक्तियों की विदेश नीतियों की तरह भूगोल और इतिहास से प्रभावित होती है तथा बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के अनुसार संशोधित होती रही है परन्तु इसका बुनियादी नेहरूवादी ढाँचा बदला नहीं है। नेहरूवादी विदेश नीति में आदर्शवाद और यथार्थवाद का संतुलन था और आज भी यह दोनों तत्व भारतीय विदेश नीति में

भारत की एक बड़ी समस्या आर्थिक विकास की थी। उसे बड़े पैमाने पर विदेशी पूँजी और तकनीक की जरूरत थी। जिस समय अमरीका खुले हाथों से युद्ध में घबस्त यूरोप के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए मार्शल योजना को प्रस्तावना कर रहा था, उस वक्त दारुण अकाल से जूझते भारत को किसी भी तरह की राहत पहुँचाने के लिए वह कोई उत्साह नहीं दिखा रहा था। 1951 में साक्षात्त्र ऋण पाने के लिए जब भारतीय राजदूत श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने अमरीका के सामने हाथ पमारे तो उन्हें बुरी तरह अपमानित-तिरस्कृत होना पड़ा।

कोरिया हो या स्वेज मकट, हिन्द चीन हो या बर्लिन में तनाव, 1950 से 1954-55 के बीच हर महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में भारत और अमरीका एक-दूसरे से विरुद्ध खड़े दिखायी दिये। पञ्चशील समझौते पर हस्ताक्षर के बाद भारत स्वयं को चीन के मित्र-हितैषी के रूप में पेश कर रहा था और स्टालिन की मृत्यु के बाद मोक्षित सघ के साथ नेहरू सरकार के सम्बन्ध सहज और मधुर हुए। अमरीका के लिए ये बातें सहा नहीं थी।

1954 में जब अमरीका ने पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर सैनिक सहायता दी और उस अपने सैनिक सगठनों का सदस्य बनाया तो उसका पक्षपात स्पष्ट हो गया। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में इस तरह का कृत्रिम मन्तुवन स्थापित करना भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण कार्रवाई ही समझी जा सकती थी। इलेस की मृत्यु के बाद कई जिम्मेदार भारतीयों के मन में इस तरह की भ्रान्ति उत्पन्न हुई थी जब अमरीका में डेमोक्रेटिक पार्टी सत्तारूढ़ होगी या भारत के ये स्नेही मित्र (अर्थात् डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य) प्रभावशाली बनेंगे तो इस तनावपूर्ण स्थिति में फेरबदल होगा। चेस्टर बाल्स जैसे समझदार अमरीकी राजनयिक की भारत में राजदूत के रूप में नियुक्ति ने इस धारणा को पुष्ट किया। परन्तु बहुत शीघ्र यह बात सामने आ गयी कि भारत-अमरीका सम्बन्धों में व्यक्ति इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, जितने कि मुद्दे। 1950 के दशक में अमरीका ने भारत को बड़े पैमाने पर साक्षात्त्र मदद देना मजूर किया। यह एक तरह से पाकिस्तान को दी जा रही अमरीकी सैनिक सहायता के मुआवजे के रूप में था। यह भी सोचा जा सकता है कि इस अवधि में नेहरू जी का अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव चरमोत्कर्ष पर था और अमरीका के लिए तीसरी दुनिया के इस प्रवक्ता की अवहेलना करना कठिन था। परन्तु यह सुखद अन्तराल बहुत लम्बा नहीं रहा।

अमरीकी सहायता नि सञ्चोच ग्रहण करने के बाद नेहरू जी अमरीकी नीतियों और आवरण का ग्राह्य भूँदकर समर्थन करने को तैयार नहीं थे। साथ ही साथ भारत में पंचवर्षीय योजनाका की स्थिति प्रगति से अमरीका यह सोचने की विषय हुआ कि भारत पेंदे में छेद वाली एक ऐसी बाट्टी है, जिसमें चाहे कितनी भी अनुदान रूपी जलराशि डाली जाये, कुछ लाभ नहीं होगा। आइजन्हावर के उत्तराधिकारी राष्ट्रपति कनेडी नेहरू जी के बड़े प्रशमक थे। उन्होंने अपने मित्र और गुरु प्रख्यात अर्थशास्त्री जॉन कनेथ गेलब्रेथ को विशेष विश्वासपात्र समझकर भारत में राजदूत नियुक्त किया। परन्तु जब कनेडी की मृत्युवात नेहरू जी से हुई तो कनेडी बहुत निराश हुए। गेलब्रेथ ने अपने सस्मरणों में लिखा है कि 'कनेडी को नेहरू जी दमी, अह्वारी, उवाऊ बिस्म के बूढ़े ही लग।' यहाँ इस बात पर फिर जोर देने की जरूरत है कि भारत-अमरीका सम्बन्धों में गतिहीनता मिर्फ शौर्यश्व नेताओं के

स्वाधीनता के पहले भारत-अमरीका सम्बन्ध—भारत की आजादी के पहले दोनों देशों के बीच सम्बन्ध काफी मधुर और सद्भावनापूर्ण रहे हैं। अमरीका स्वयं कभी औपनिवेशिक शक्ति नहीं रहा और उसने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़कर अपनी एक स्वतन्त्र राष्ट्र राज्य के रूप में पहचान बनायी। अमरीकी क्रान्ति के भाव जुड़े हुए हैं—मानवाधिकारों का घोषणापत्र और न्यूयार्क में स्थापित स्वाधीनता की मूर्ति, जो विश्व भर में उत्पीड़ितों-शोषितों को मुक्ति सघर्ष के लिए प्रेरित करते रहे हैं। भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के साथ जुड़े लोग भी इसके अपवाद नहीं, अर्थात् भारतीय स्वतन्त्रता सेनानी इसमें अछूते नहीं रहे।

बीसवीं शताब्दी के पहले दशक में प्रसिद्ध आर्यसमाजी लाला हरदयाल तथा गदर पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं ने अमरीका में अंग्रेजों के विरुद्ध सघर्ष के लिए समर्थन व सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। इस सिलसिले में उन्हें जिस तरह की सहानुभूतिपूर्ण मेजबानी मिली, उसका बाद के वर्षों में भारत-अमरीकी सम्बन्धों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट ने मित्र राष्ट्रों के पक्ष को प्रबल करने के लिए ही सही, भारत की आजादी दिलाने का समर्थन किया और भारतीयों के मन में मित्र के रूप में अपनी जगह बनायी। अमरीका का जनतन्त्र, अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, आधिपत्यों का अदम्य उत्साह और समतापूर्ण सामाजिक जीवन अन्य देशों की तरह भारत के नेताओं को भी मुग्ध करते रहे हैं। भले ही नेहरू को अमरीका का कोई आत्मीय ज्ञान नहीं था, तथापि जयप्रकाश नारायण जैसे अनेक सहयोगी विद्यार्थी जीवन में अपनी युवावस्था के अनेक वर्ष अमरीका में बिता चुके थे। 1930 और 1940 के दशक में जब महात्मा गांधी अंग्रेजों की जेलों में बंद थे तो उनको विश्वविख्यात बनाने में लुई फिशर जैसे अमरीकी पत्रकारों और मार्सेट बुक स्ट्राइट जैसे फोटोग्राफरों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया।

इलेस की शीत युद्धकालीन नीतियाँ व भारत का मोहभंग—1949 में जब नेहरू जी पहली बार अमरीका की यात्रा पर गये तो उन्होंने अपने दौर को 'लोज-यात्रा' (Voyage of Discovery) का नाम दिया। तब उनके मन में यह आशा बची थी कि अमरीका और भारत दोनों बड़े जनतान्त्रिक देश हैं और भविष्य में अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर इन दोनों के बीच 'सहकार' सम्भव होगा। किन्तु अतीत की गुस्सह स्मृतियाँ, जिनके साथ थियेकरानन्द, थोरो, ईमरसन और रवीन्द्रनाथ ठाकुर के नाम जुड़े थे, दोनों देशों के राष्ट्रीय हितों के समायोजन में ज्यादा काम नहीं आ सकी। शीत युद्ध के आविर्भाव के साथ तत्कालीन अमरीकी विदेश मंत्री डेलेस ने यह बात साफ कर दी कि जो भी देश अपने को मुटु निरपेक्ष कहता है, अमरीका उसे अपना मनु मानेगा। शान्तिप्रिय नेहरू जी निराश्वरीकरण के पक्षधर थे और सैनिक समझौतों के कट्टर विरोधी। इसके अनिश्चित नेहरू जी द्वारा रंगभेद, नस्लवाद और उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई में अफ्री-एशियाई जगत के नेतृत्व के कारण भी भारत-अमरीका बँधनस्थ गहरा हुआ। नेहरू जी के लिए यह समझना कठिन था कि जनतन्त्र का हिमायती अमरीका क्यों और कैसे शीत युद्ध-जनित दबावों के कारण 'षट्पक्ष तानाशाहों' का समर्थन कर रहा था। उसी तरह अमरीका को यह बात सानती थी कि नेहरू जी जैसे स्वतन्त्रता प्रेमी शीत युद्ध के दौर में मुटु निरपेक्षता के नाम पर 'वैतस्य' बने रहते थे।

पोतो में इस अन्न की दुलाई होगी, उसका 50 प्रतिशत किराया विदेशी मुद्रा में चुकाना होगा। इसके अतिरिक्त इस खाद्यान्न की कीमत के रूप में एक अपार घन राशि (Counterpart Funds) भारत में जमा हो गयी। मने ही यह मुद्रा रूप्यो में थी, किन्तु पी० एल०—480 समझौते के अनुसार अमरीकी सरकार इसे अपनी इच्छानुसार किसी भी भारतीय विकास कार्यक्रम पर खर्च कर सकती थी। 1963-64 से 1966-67 तक अनेक महत्वनाक्षी योजनाओं का खर्च इस पी० एल०—480 मुद्रा मण्डार से किया गया। वामपंथी खदान के अनेक भारतीय अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस व्यवस्था ने अमरीकियों को भारतीय आर्थिक जीवन और सांस्कृतिक जगत में पड़वन्त्रकारी घुमपंठ की छूट दी। बड़े पैमाने पर अमरीकी विचारधारा को प्रोत्साहित करने वाली पाठ्य पुस्तकों की छपाई, गोष्ठियों आदि के आयोजन ने इस धारणा को पुष्ट किया। स्वयं श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने को प्रगतिशील समाजवादी सिद्ध करने के लिए अपनी पार्टी के युवा तुर्कों (Young Turks) का प्रयोग अमरीकी विरोधी प्रचार के लिए किया। 1965-66 के दौर में शशि भूषण जैसे लोक सचिव पी० आई० ए० का हाथ देखते थे और पीलू मोदी जैसे सयत व्यक्ति को सदन में एक बार अपने विरोधियों को चुप करने के लिए एक बिल्ला लगाकर घूमने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिस पर लिखा था—‘मैं पी० आई० ए० एजेन्ड हूँ।’

यदि अमरीकी राष्ट्रपति जॉनसन को इस बात पर गुस्सा आता था कि भारत दक्षिण-पूर्व एशिया में अमरीका के बढ़ते हस्तक्षेप का कटु आलोचक है तो इन्दिरा गांधी की सरकार इस बात पर वाजिब आपत्ति करती थी कि 1965-66 में कुछ ही समय के लिए रोक लगाने के बाद अमरीका ने भारत के विरुद्ध फिर से पाकिस्तान को सैनिक सहायता देना आरम्भ कर दिया। श्रीमती गांधी इन वर्षों में दक्षिणपंथी और अमरीका के पक्षधर ‘मिण्डोनेट क क्षत्रपों’ से लड़ रही थी। वह एक अल्पसंख्यक पार्टी की सदस्य में नेता थी। सरकार बचाव रखन बात बहुमत के लिए उन्हें भारतीय साम्यवादी पार्टी के समर्थन की जरूरत थी और इसी कारण अमरीका को चुनौती देते रहना एक तरह से उनकी विवशता बन गयी थी। इन वर्षों में ऐसे अनेक उदाहरण जुटाये जा सकते हैं, जिन्होंने भारत-अमरीका सम्बन्धों में तनाव बढ़ाया। इनमें से प्रमुख हैं—भारत में अमरीकी सांस्कृतिक केन्द्रों की गतिविवियों का विस्तार पर रोक, दिनेश सिंह के विदेश मंत्री बालू में उत्तर वियतनामी नेता मदाम विन्ह को भारत में आमन्त्रित किये जाने पर अमरीकी रोष तथा भारत द्वारा अमरीका के बैरी क्यूबा से व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाने पर अमरीकी सद।

इन दिनों पाकिस्तान में अय्यूब खान का शासन था, जो ‘अमरीका के विशेष मित्र’ थे। उनके युवा और तेज विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने नेहरू जी की मृत्यु के बाद भारत की कठिनाइयाँ का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने राष्ट्रमण्डल और संयुक्त राष्ट्रसंघ में सोवियत संघ के मित्र गुट निरपेक्ष भारत के विरुद्ध कटु प्रचार कर अमरीका के नैतिक-औद्योगिक प्रतिष्ठान से जुड़े लोगों को अपने पक्ष में कर लिया।

इन वर्षों में यदि अमरीका और भारत के सम्बन्ध टूट नहो तो उसका सीधा सम्बन्ध अमरीका वियतनाम युद्ध का उतार-चढ़ाव से है। सोवियत-चीन मुठभेड़ के

आपसी सम्पर्कों के अमान से नहीं आयी थी। इस समय तक अमरीका का दक्षिण-पूर्व एशियाई मामलों में सैनिक हस्तक्षेप बढ़ने लगा था और भारत की सोवियत संघ के साथ मैत्री घनिष्ठ होने लगी थी। जहाँ एक ओर चीन के साथ सम्बन्धों में तनाव बढ़ने के कारण भारत के लिए अमरीका महत्वपूर्ण बना, वहीं क्यूबाई मिसाइल संकट (1962) के बाद अमरीका नव सोवियत संघ के साथ 'होट लाइन' के माध्यम से संवाद का सूत्रपात होने से भारत की गुट निरपेक्ष मध्यस्थ-सन्देशवाहक के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय भूमिका का अवमूल्यन हुआ। कागजी संकट में भारतीय नीति समुक्त राष्ट्र मंच के सत्वावधान में अमरीका की हित साधक रही, परन्तु ऐसा संयोगवश ही हुआ। भारत सरकार की सहायुभूति और समर्थन अफ्रीका में एवं अन्यत्र सभी जगह उन प्रगतिशील व आजादवादी विरोधी शक्तों को प्राप्त था, जिन्हें अमरीका अपना शत्रु समझता था।

1961 में गोवा में सैनिक बल प्रयोग ने नेहरू जी को अमरीका की नजर में पात्रगुनी सिद्ध किया तो 1962 में चीन के साथ सैनिक मुठभेड़ के दौरान भारत को दी गयी सहायता की कीमत वसूल करने के अमरीकी प्रयत्नों ने भारत को खिन्न किया। जैसे-जैसे भारत की निर्भरता अमरीकी खाद्यान्नों के आयात पर बढ़ती गयी, वैसे-वैसे अमरीका के मन में भारत की स्वाधीनता पर अकुल लगाने का सातव बढ़ता गया। 1964 में नेहरू जी की मृत्यु तक भारत-अमरीका सम्बन्ध एक ताजुक असामान्य स्थिति तक पहुँच चुके थे। भूमिका अमरीकी नेता और जनता श्रृणी भारत को कृतघ्न समझते थे तो बहुसंख्यक भारतीयों के मन में अमरीका की छवि कुटिल-कृपण की थी। कश्मीर और पाकिस्तान के प्रसंग में अमरीका भारत के शत्रु का पक्षधर था तो भारत अमरीकी नीतियों के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय जनमत तैयार करवाने में सबसे आगे रहता था। 1965 में सत्ता ग्रहण करने के बाद श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भारत की विदेश नीति की रूपरेखा स्पष्ट करने वाले अपने एक वेल में इन सभी बातों को निस्संकोच स्वीकार किया।¹

श्रीमती इन्दिरा गांधी के काल में भारत-अमरीका सम्बन्ध (1965-1977) — जिस समय श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधानमन्त्री बनीं, उस समय भारत-अमरीका सम्बन्ध काफी अमधुर हो चुके थे। इसके आन्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों कारण थे। भारत के साथ रचनात्मक पहल चाहने वाले अमरीकी राष्ट्रपति कर्नेडी की हत्या हो चुकी थी और उनका स्थान जोनसन ने ले लिया। जोनसन की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में विशेष रुचि नहीं थी और न ही उनमें बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में अटिल यथार्थ का परिष्कृत विश्लेषण करने की क्षमता थी। अति यथार्थवादी शक्ति-सन्तुलन के पारम्परिक ढाँचे को समझने वाले जोनसन को यह बात हमेशा शोभ और आशोचदायक लगती थी कि भारत जनतन्त्र का हिमायती होने के बावजूद हर क्षण में अमरीका का विरोध क्यों करता था। दुर्भाग्यवश इसी दौर में अमरीका को विघटनार्थ युद्ध की दलदल में गुरी तरह फँसना पड़ा और उसकी मित्र व समर्थक देशों से अपेक्षाएँ बढ़ती गयीं। इन्हीं दिनों थी ० एल० 480 खाद्यान्न आयात कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत को अमरीका पर निर्भरता निरन्तर बढ़ी। आरम्भ में कहा गया कि इस अमरीकी सहायता के लिए भारत को विदेशी मुद्रा में कुछ भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा। परन्तु बाद में यह बात स्पष्ट हुई कि बिना अमरीकी

¹ विदेश, भाग एच० विशेष व सर्वोच्च माननिष्ठ की पुरोक्त पुस्तकें।

मार्च, 1977 में भारतीय दूताई भारतीय प्रबानमन्त्री बन ता अनेक नीगा को लगा कि भारत अमरीका सम्बन्ध नाटकीय ढंग से सुधरेगे। दूताई क गृहमन्त्री चौधरी चरणसिंह, विदेश मन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी दक्षिणपंथी थे और जार्ज फर्नांडीस, मधु सिमर्य आदि का समाजवाद साम्यवादियों की बरखा पश्चिमी जनतांत्रिक समाजवाद का निकट सम्बन्धी था। इसके अनिरिक्त आगत काल में अमरीकियों ने इन्दिरा गांधी के विराधिया (अर्थात् जनता पार्टी नेताओं का) गरण और प्रोत्साहन दिया था। मुद्रास्फीय स्वामी समर्थ में उद्विग्न हाकर नाटकीय ढंग से अल्प हान का पराक्रम अमरीकी महायता के बिना नहीं कर सकते थे। विद्यार्थी जीवन में जयप्रकाश नारायण के अमरीका प्रवास का उल्लेख पहले किया जा चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी आरम्भ में ही यह स्पष्ट कर चुके थे कि उनका प्रयत्न भारत की गूट निरपेक्षता का स्वतन्त्रानिय (Genuine Non-alignment) बनाने वाला होगा। अतः यह अपेक्षा अनुचित नहीं थी कि सावित्रय सय के साथ भारत के विपक्ष सम्बन्धों पर पुनर्विचार किया जायगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने यह उल्लाह भी दर्शाया कि वह भारत के पड़ोसी पाकिस्तान एवं चीन के साथ सम्बन्धों को मजबूत-सामान्य बनाना चाहते हैं। इस राजनयिक अभियान के शीघ्रगत् के बाद अमरीका के साथ भारत के सम्बन्धों में सुधार की बात माँची जा सकती थी। इस धारणा की पुष्टि अमरीका में भारतीय राजदूत के रूप में प्रस्थान दक्षिणपंथी बकौन नानी पालसीवाला की निवृत्ति से हुई। इस सबके बावजूद यदि भारत अमरीका सम्बन्धों में प्रभावशालि सुधार नहीं हो सका तो इसका कारण पर विधिवत् विचार करना आवश्यक है।

सबसे पहली बात तो यह है कि सत्ता ग्रहण करने के बाद जनता सरकार का यह स्वीकार करने का विवक्ष्य होना पड़ा कि भारत-सावित्रय सम्बन्धों में किसी आन्तरिक परिवर्तन की तत्काल गृहाह्न नहीं। चीन और पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों के सामान्यीकरण में भी भारत का निराशा ही हाथ लगी। वाजपेयी जी की जान माना (फरवरी, 1979) के दौरान चीन ने विपन्नता पर आक्रमण किया और अपमानजनक ढंग से 1962 के भारत-चीन युद्ध की याद ताजा की। इसी तरह पाकिस्तान में भूट्टा का फासी की मुखा देकर जनरल लिया उन हक ने इस आन्ति की निर्मूलक मिट्ट कर दिया कि उनका काद इयादा अपन दंग में जनतन्त्र की पुनर्स्थापना का है। भारत ने नएन और बफला दंग के साथ त्रिम तरह के समझौते किए उनसे ना अमरीका का यही मुकदम मिला कि जनता सरकार में राजनयिक कौशल का अभाव है। अमरीका को यह लगा कि भारत का रिनायने दंग के बजाय उन पर दबाव डालकर जल राष्ट्रिय हित का मानना बहुर है। इसीलिए अमरीका ने परमाणु टेक्नलाजी के हस्तान्तरण के मामल में भारत के साथ बहद म्बाई का व्यवहार किया। राष्ट्रिय क्रांति की भारत माना (1978) के दौरान दो पीढ़ियों, व्यक्तित्व और जीवन दशना का टकराव ना उभर कर सामने आया। नोबारी दहाई पुरान पासीबंदी, कुटार उद्या नमयंक पीढ़ी के प्रतिनिधि थे। अमरीका की जफरत ने उनका नजर आतो थी और न ही चरण सिंह का। उन्हीं के मन्त्रिमण्डल के एक वरिष्ठ सदस्य हमरनी नन्दन बटुमुषा प्रकट ह्म से सावित्रय सय के पराधर थे। एक अन्य प्रभावशाली मन्त्री उद्याय मन्त्री जार्ज फर्नांडीस वपों में अमरीकी बहुराष्ट्रीय कम्पनिया के विरुद्ध मुस्लिम चलात आ रहे थे और अपन कार्यकाल में

वाद बड़े अन्तर्राष्ट्रीय तनाव से अमरीका भारत को दुस्कारने का जोखिम नहीं उठा सकता था। इस बात का श्रेय श्रीमती गांधी को दिया जाना चाहिए कि उन्होंने परिस्थितियों का पूरा लाभ उठाया। यह स्थिति कमोबेश 1969 से लेकर 1971 तक बरकरार रही। बंगला देश मुक्ति संग्राम और पाकिस्तान के विघटन वाले प्रसंग ने भारत और अमरीका के बीच अन्तर-द्वन्द्व खतरनाक दंग से उभारे। इनका विस्तृत विस्तरेण अन्वय किया गया है। वतः यहाँ उस दोहराने की आवश्यकता नहीं। परन्तु इस निष्कर्ष को रेखांकित किया जाना जरूरी है कि दक्षिण एशियाई सन्दर्भ में अपने निजी सामरिक दवावों के कारण अमरीका ने अपने मित्र के रूप में पाकिस्तान को चुन लिया। इसके बाद भारत के साथ सम्बन्धों का असहज होना स्वाभाविक ही था। यह सच है कि अमरीका ने बड़े पैमाने पर भारत को आर्थिक सहायता दी है परन्तु वह जिस तरह की हतभत्ता और स्वामी भक्ति की भाशा कोरेखा, ताइवान व सिंगापुर से कर सकता है, वसी अपेक्षा भारत में नहीं की जा सकती। बंगला देश मुक्ति अभियान के दौरान हेनरी किशिजर और निक्सन ने खुले आम भारत के विरुद्ध पाकिस्तान के पक्ष में झुकाव वाली नीति की घोषणा की और बंगाल की खाड़ी में युद्धपोत (सातवाँ पैदा) भेजकर भारत के मपाडोहन (ब्लैकमेल) का असफल प्रयत्न किया। इसके परिणामस्वरूप भारत-अमरीका टकराव उनमें सम्बन्ध विच्छेद की सीमा तक पहुँच गया। 1971 के बाद भले ही यह कहा जाता रहा कि अमरीका भारत के साथ सम्बन्धों के सामान्यीकरण का इच्छुक है, किन्तु बंगला देश को अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने के प्रश्न पर अमरीका के पड़ोस्यकारी बियाकस्ताप ने भारत को आशंकित रखा। 1973 में जब टी. एन. कौल को अमरीका में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया, तब जाकर दोनों देशों में 'वयस्क सम्बन्धों' (mature relations) की बात गम्भीरता से उठायी गयी। सम्बन्धों में वयस्कता की बात करने का यह अर्थ था कि दोनों देश यह स्वीकार करते हैं कि उनके राष्ट्रीय हितों में टकराव है और विश्व दृष्टि में भी। फिर भी मतभेदों को छिपाये बिना उनके बीच सहकार के क्षेत्र को विस्तृत करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। परन्तु सदाशिवता का यह दौर ज्यादा समय तक टिका नहीं। जब 1973-75 में श्रीमती गांधी के दुशामन के विरुद्ध जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व वाले आन्दोलन ने जोर पकड़ा तो अमरीका में जयप्रकाश नारायण की लोकप्रियता को देखते हुए इन्दिरा गांधी के लिए यह आशय लगावा सहज हुआ कि अमरीकी सरकार भारत को अस्थिर करने का प्रयत्न कर रही है। इसके कुछ पहले भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमान्त में आदिवासियों की बगल और बगल में उग्र वामपंथी नान्तिकारी हिंसा के विस्फोट के विस्तरेण में अमरीकी विद्वानों की रुचि ने अनेक भारतीय नागरिकों को सतर्क किया। 1975 में आपातकाल की घोषणा ने भारत में जनतन्त्र को मानवाधिकार हनन के प्रश्न से जोड़ दिया और अमरीकी मिनेटर एडवर्ड कनेडी जैसे पारम्परिक मित्र भी इन्दिरा गांधी के कटु आलोचक बन गये। अमरीका में टी. एन. कौल के दभी आचरण ने भी भारत की छवि को नुकसान पहुँचाया। 1977 में इन्दिरा गांधी के अपदस्थ होने के बाद एक बार फिर बाधा की किरण पैदा हुई कि अब साम्य भारत-अमरीका सम्बन्धों में सुधार हो सकेगा।¹

जनता सरकार के काल में भारत-अमरीका सम्बन्ध (1977-1979)—जब

¹ देखें—सुरेश मानविहारी की प्रसिद्ध पुस्तक में पृ. 64 से 128 तक।

सांस्कृतिक आयात की सीमाएँ—भारत-अमरीका सम्बन्धों के सांस्कृतिक आयातों और इनकी सम्भावनाओं का चाहे कितने ही जोर शोर से प्रचार किया जाये, इसकी सीमाएँ स्पष्ट हैं। तट्टरी मुर्ग, महेश योगी व रवि शंकर के सितार से अमरीकी पर्यटकों को भले आकर्षित किया जा सके, किन्तु अमरीकी सरकार की नीतियों को प्रभावित करना कठिन रहेगा। भारत की उत्सव-धर्मी राजनीति (सन्दर्भ भारत महोत्सव का आयोजन) से कुछ हासिल होने वाला नहीं। अमरीका में सोलिस्तानी आतंकवादियों को दिये जा रहे शस्त्र-प्रशिक्षण से यह बात अच्छी तरह प्रमाणित हो जाती है। सरकारी प्रचार-तन्त्र यह दोहराते नहीं बतता कि आज अमरीका में भारतीय मूल के पाँच लाख नागरिक हैं जो काफी समृद्ध हैं और जिनमें से अनेक प्रभावशाली हैं। भारत के राष्ट्रीय हित में इन नागरिकों के इस्तेमाल की बात सुझाना मूल्यतापूर्ण है। इनमें से अधिकांश नागरिक व्यक्तिगत और पारिवारिक लाभ से ही प्रेरित हैं। वे लोग अपनी मातृभूमि के विनाश या उसके हितों की रक्षा के लिए अमरीका की नजरों में मदिग्ध नहीं बनना चाहते। भारत की गरीबी व जड़ता से 'प्रस्त' इन पलायन करने वाले भारतीय मूल के लोगों से अपक्षा रखना व्यर्थ है। भविष्य में भी अमरीका के साथ सम्बन्धों को व्यस्क व स्थिर आधार पर तभी रखा जा सकेगा, जब हम राजनीतिक व सामाजिक जीवन में अनुपस्थिति साम्य को छोड़कर मतभेदों के यथार्थ को सहे नजर रखकर नीति निर्धारण करेंगे।

भारत सोवियत सघ सम्बन्ध (Indo Soviet Relations)

भारत और सोवियत सघ (रूस) एक दूसरे के पड़ोसी देश अवश्य हैं, किन्तु विचारधारा, राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था आदि की दृष्टि से काफी भिन्न हैं। भारत की आजादी के बाद प्रारम्भिक वर्षों में भारत व रूस के बीच सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण नहीं थे, किन्तु 1954 में स्टालिन की मृत्यु के बाद सोवियत सघ की आन्तरिक राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में ऐसे निर्णायक मोड़ आये कि दोनों देश एक-दूसरे के काफी नजदीक आते गये। कश्मीर के मामले पर सोवियत सघ द्वारा भारत को समर्थन देने में दोनों देशों के बीच मैत्री सम्बन्धों का मूलपात हुआ, जिसका चरमोत्पल बंगला देश युद्ध के पूर्व अगस्त, 1971 में सम्पन्न भारत-सोवियत मैत्री एवं सहयोग सन्धि के रूप में देखने को मिला। दोनों देश बरसों तक विश्व राजनीति में अनेक समस्या पर समान राय रखते रहे और उनके बीच मैत्री सम्बन्ध कायम रहे।

स्वाधीनता के पूर्व भारत-सोवियत सम्बन्ध—भारत और सोवियत सघ का एक-दूसरे के साथ परिचय बहुत आत्मीय न होने पर भी सदियों पुराना है। कश्मीर में भारतीय सीमान्त में सोवियत भू भाग लगभग 15-20 किलोमीटर दूर है और अविभाजित भारत में उत्तर पश्चिमी प्रदेश सोवियत दक्षिणी एशियाई गणराज्यों की 'पहुँच' (reach) में थे। सोवियत सघ की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा एशियाई है और भाषा, धर्म व संस्कृति की दृष्टि से हिन्दुस्तानी उपमहाद्वीप (कभी गन्दावली) में रहने वालों के रिश्तेदार हैं। 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में औपनिवेशिक शक्ति ब्रिटन का प्रतिद्वन्द्वी होना व कारण सोवियत सघ स्वाभाविक रूप से भारत के स्वाधीनता सैनिका व निष्पक्ष निरापद स्वामी रहा। बाल्सेविक क्रान्ति (1917) के

उन्होंने भारत में इन्टरनेशनल बिजनेस मशीन्स (I. B. M.) और कोका कोला कम्पनी पर इतने कठोर प्रतिबन्ध लगाये कि इन दोनों कम्पनियों को भारत से अपना कारोबार समेटने के लिए बाध्य होना पड़ा। यह नहीं कि जार्ज फर्नांडीस पूँजीवाद विरोध थे, वरन् यह अमरीका के वनिस्वत अपने जर्मन तथा अन्य पश्चिमी यूरोपीय साथियों के साथ जनतांत्रिक समाजवादी साझेदारी के पक्षधर थे। इन सब बातों से अमरीका का सिद्ध होना स्वाभाविक था।

दूसरी ओर इन वर्षों में अमरीकी राष्ट्रपति के बंदेधिक मामलों के प्रमुख सत्ताहकार व्हेनेजुएस्की थे। उनकी 'Tri Continental' परियोजना में भारत जैसी 'पटिया दरिद्र शक्ति' के लिए कोई स्थान नहीं था। डेमोक्रेटिक पार्टी का सदस्य होने के बावजूद वह गर्व यिजाज के पीछे खड़ा थे। ईरान और अफगानिस्तान के घटनाक्रम के जरिये उन्हीं की आन्तरिक नीतियों ने नये चीन युद्ध का सूत्रपात किया। कार्टर प्रमाणन ने ही पाकिस्तान को 3-2 अरब डालर की सैनिक सहायता देकर भारत को इस नए चीन युद्ध की सपटों से दूरतमाना भारस्त्र किया। इस सबका प्रभाव भारत-अमरीका सम्बन्धों पर पड़ना स्वामाविक था। बहुद्दाल, जनता सरकार के शीघ्र गिर जाने से इस अन्तराल का कोई विशेष महत्वपूर्ण प्रभाव भारत-अमरीका सम्बन्धों पर नहीं पड़ा।¹

भारत-अमरीका सम्बन्ध (1980 से अब तक)—श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा जनवरी, 1980 में पुनः सरकार बनाने पर भारत-अमरीका सम्बन्धों में सुधार के लिए अनेक प्रयत्न किये गये। वयस्क रिश्तों की पुनः वात की गयी परन्तु बुनियादी मैक्रानिक मतभेदों के कारण राष्ट्रीय हितों का मामजसब कठिन ही बना रहा। अमरीका द्वारा पाकिस्तान के प्रति पक्षपातपूर्ण आचरण और पाकिस्तान को दी जाने वाली सैनिक सहायता तो बीमारी के सिर्फ लक्षण है, असली रोग अमरीका द्वारा भारत की गृह निरपेक्षता-स्वाधीनता को स्वीकार न करना रहा। इसी कारण अमरीका की किसी भी राजनयिक व सामरिक रणनीति में भारत को सहयोगी नहीं, बल्कि शिरोधी समझा जाता रहा। भारत दुनिया के अन्य साम्यवादी व समाजवादी देशों की तुलना में भूने ही अधिक जनतांत्रिक और स्वतन्त्र दिलावी देता हो किन्तु अमरीका की रण्टि में केन्द्रीकृत नियोजित विकास कार्यक्रम और मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत को सोवियत छाप वाला ही सिद्ध करते रहे। इन बुनियादी मतभेदों के रहते भविष्य में भी अमरीका के साथ भारत की नीतियों का तालमेल बिठाना कैसे महज होता। 1984 में राजीव गांधी द्वारा भारत की बाबटोर सम्मालने के बाद भी भारत-अमरीका सम्बन्ध में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ।

जून, 1989 में अमरीका ने सुपर-301 के तहत भारत के विनाश लक्ष्ये जाने वाले आर्थिक प्रतिबन्धों की चमकी ने भारत-अमरीका सम्बन्धों में एक कटु तनाव को जन्म दिया, किन्तु जुलाई, 1990 में अमरीका ने आश्वासन दिया कि उल्लेख चक्र की वापसी तक वह भारत के विनाश कार्यक्रम नहीं करेगा। जून, 1991 में नरसिंह राव सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद भारत ने अर्थव्यवस्था को ओर उदार बनाया, जिससे यह कटु तनाव लगभग समाप्त हो गया, किन्तु पाकिस्तान को अमरीकी मरुत मन्पाई तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर दोनों देशों के बीच मतभेद जारी है।

¹ देखें: Baldev Raj Nayar, *American Geo-Politics and India* (Delhi, 1976).

को हिंसक बगावत की प्रेरणा उस कलकत्ता सम्मेलन में मिली थी, जिसका आयोजन सोवियत संघ ने करवाया था। अन्य शब्दों में, सत्ता गृहण करने और सरकार बनाने के बाद नेहरू जी यह समझने लगे थे कि सोवियत संघ ने जिस तंत्र का निर्माण औपनिवेशिक शक्ति को खोखला करने के लिए किया था, उसका बखूबी प्रयोग वह नवोदित सरकारों पर अकुशल लगाने के लिए भी कर सकता है। दूसरी ओर सोवियत संघ को इस बात से बेहद सतोष था कि अपने को नान्तिकारी और प्रगतिशील कहकर पैदा करने वाले नेहरू, हर निर्णायक लड़ाई में समझौता-परस्त और अनिश्चय में रहने वाले एक 'दुर्बल' व्यक्ति सिद्ध होते जा रहे थे। जिस समय चीन में माओ के नेतृत्व में साम्यवादी पार्टी विजय की ओर अग्रसर थी, उस समय नेहरू चांग काई शेक के साथ व्यक्तिगत पारिवारिक मित्रता का प्रदर्शन कर रहे थे। इसी तरह 'ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल' में बने रहने के भारत के फैसले ने भी इस की दृष्टि में भारत की आजादी पर प्रदत्त चिह्न लगा दिये। सोवियत संघ में श्रीमती पंडित के बाद भारतीय राजदूत के रूप में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भेजा गया, जो अघ्यात्म-वादी दार्शनिक थे और अंग्रेजों द्वारा 'सर' की उपाधि से सम्मानित किये जा चुके थे। संक्षेप में, वह भी कमियों को अपने मित्राज के या विरोध काम के आदमी नहीं लमे।

यदि भूतपूर्व भारतीय राजनयिक के० पी० एम० मेनन की आत्मकथा के सम्मरणों पर विश्वास करें तो मानना पड़ेगा कि अकेले उन्हीं के भगीरथ प्रयत्नों से स्टालिन का हृदय परिवर्तन हो सका और भारत-सोवियत सम्बन्ध सुधार की प्रक्रिया आरम्भ हुई। वास्तविकता यह है कि चीन युद्ध में तेजी के साथ स्टालिन के सामने गृह-निरपेक्षता के दाबजूद भारत जैसी सम्भावनाओं वाली शक्ति का महत्त्व झलकने लगा था। कोरिया युद्ध में निष्पक्ष मध्यस्थता द्वारा नेहरू जी ने अपनी ईमानदारी प्रमाणित कर दी थी। 1950 से 1963 के दौरान यह बात भी अच्छी तरह प्रमाणित हो चुकी थी कि भारत ने मन ही मन से नाता न तोड़ा हो, किन्तु स्वतन्त्र भारत के द्वार पश्चिमी पूंजी के लिए अबाध नहीं थे। नेहरू जी की सरकार यह स्पष्ट कर चुकी थी कि रूसी नमूने के केन्द्रीकृत नियोजित विकास के प्रति उनकी आस्था है और आर्थिक उत्पादन के निर्णायक महत्त्व वाले क्षेत्रों में सरकारी नियंत्रण व एकाधिकार बना रहूँगा। 1951 में दक्षिणपंथी समझे जाने वाले सरदार पटेल की प्रेरणा से रियासतों-रजवाड़ों का उन्मूलन किया गया और 'भारतीय राज्य' का एकीकरण की कलाका माकार हुई। इस सारे घटनाक्रम से भारत के प्रति सोवियत संघ में परिवर्तन हुआ स्वाभाविक था। परन्तु तब भी इसमें बदलाव स्टालिन के जीवन काल में नहीं आया। स्टालिन की मृत्यु के बाद सोवियत संघ में एक सामूहिक नवृत्ति (अतः ही थोड़े से समय के लिए) उभरा। इसी दौर में ख्रुश्चेव तथा बुल्गानिन ने भारत की यात्रा की।

इस समय तक साम्यवादी व समाजवादी दलों के प्रति भारतीय हमान स्पष्ट हो चुका था। अमरीकी विदेश मंत्री डेनिस द्वारा भारत की बटु आलोचना ने भारत की छवि प्रगतिशील बनायी। भारत और सोवियत संघ को पाम लाने में वैश्विक मामला में नेहरू जी के प्रमुख मलाहकार कृष्णा मन्नन और उनके विदेशी वामपंथी मित्रों ने भी महत्वपूर्ण योगदान किया। बदले अन्तर्राष्ट्रीय और स्वदेशी यथार्थ की नाटकीय अभिव्यक्ति करते हुए ख्रुश्चेव ने अपनी भारत यात्रा के दौरान यह घोषणा की कि कर्मीर विवाद में सोवियत संघ भारत का साथ देगा। सोवियत संघ भारत

वाद सोवियत सभ विचारधारा के स्तर पर भी पूँजीवादी-साम्राज्यवादी व्यवस्था के विरोध में भारतीय राष्ट्रवादियों की सहायता व समर्थन देता रहा। इन सब कारणों से भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के नेताओं और आम जनता के मन में सोवियत सभ के प्रति सद्भाव का बड़ा बण्डार रहा। इसका प्रभाव आजादी के बाद भारत-रूस सम्बन्धों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

अनसर यह कहा जाता है कि सोवियत संघ के प्रति नेहरू जी का गहरा आकर्षण था और इससे भारतीय नीति प्रभावित हुई। यह सच है कि नेहरू जी ने 1920 के दशक में भारतीय राजनीति में सक्रिय होने के साथ ही सोवियत सभ का दौरा किया और उन्होंने 'सोवियत प्रयोग' को भारत में लागू करने के लिए उत्साह दर्शाया था। नेहरू जी अपनी किशोर व युवा अवस्था में जब इंग्लैंड में रह रहे थे, तब वह 'फेबियन' समाजवादियों के सम्पर्क में आये थे और मार्क्सवादी-लेनिनवादी रुझानों को यह साम्राज्यवाद के विरुद्ध अपनी लड़ाई के दौर में महत्वपूर्ण साथी मानते थे। सोवियत सभ ने भी प्रोत्सुकी आदि की प्रेरणा से कोमिनतर्न (कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल) के जरिये मणौ-एशियाई उत्पीड़ित जनता को जुझारू दम से सगठित करने का प्रयत्न किया। रूस की ही प्रेरणा से साम्राज्यवाद विरोधी सीमा ने दसवें में 1927 में उस अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें नेहरू जी ने सोल्साह भाग लिया। द्वितीय विश्व युद्ध की पूर्ण सन्ध्या में नेहरू के नाजी और फासीवाद विरोधी लेखर सोवियत सभ को अपने हित साधक लगे, क्योंकि नाजी और फासीवादी तानाशाह मूलतः साम्यवाद-विरोधी थे।

स्वातंत्र्य काल में भारत-रूस सम्बन्ध—इसके बावजूद 1947 में भारत को सोवियत सभ से अपेक्षित स्नेह और मैत्री नहीं मिली। तत्कालीन सर्वोच्च सोवियत नेता स्टालिन भावनाओं में बहने वाले व्यक्ति नहीं थे। वह शक्ति-मतुलन के साथ-साथ नैदान्तिक मनोकरणों की भी साधने का प्रयत्न करते थे। उनकी समझ में अहिंसक गांधी के मुधारवादी सिद्ध नेहरू अश्रेष्ठ-परस्त थे और उनका 'जनतान्त्रिक समाजवाद' साम्यवादी-समाजवाद की परिकल्पना से विल्कुल भिन्न था। फिर जब नेहरू जी ने गुट-निरपेक्षता की अपनी अवधारणा स्पष्ट की तो भारत-रूस सम्बन्धों को घनिष्ठ बना सकने की रही-भरी आशा धूमिल हो गयी। उस समय प्रकाशित सोवियत विद्वान कोस में गांधी और नेहरू के लिए 'ब्रिटिश साम्राज्यवाद के पिछलग्गु-इवार' (Running Dogs of British Imperialism) जैसे विरोधों का प्रयोग किया गया था।

आज कई भारतीय इस बात से बेहद खिन्न होते हैं कि जिस वक्त भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू जी अपनी गरीब बहन धीमती बिजय लक्ष्मी पंडित को सोवियत सभ में स्वतन्त्र भारत का पहला राजदूत बनाकर अपनी सम्बन्धों की आत्मीयता का पुट देना चाह रहे थे, उस वक्त सोवियत सभ से ऐसा तिरस्कार झेलना पड़ रहा था। परन्तु यदि बस्तुनिष्ठ दृष्टि से देखें तो सोवियत आचरण एक हद तक तर्कसंगत जान पड़ता है। सोवियत नेताओं की दृष्टि में धीमती पंडित की राजदूत के रूप में नियुक्ति मार्क्स-भगोजवाद का लक्षण थी। इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि उस समय नेहरू जी भारत में अपने साम्यवादी विपक्षियों का दमन कर रहे थे। तेलवाना में साम्यवादी विद्रोह का दमन किया गया। भारत सरकार ने अपने बलपूर्वक में यह आरोप भी लगाया कि भारतीय साम्यवादियों

संघ के नए हस्तक्षेप (1956) का समर्थन करने में असमर्थ रहा। बाद में कारो ने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने समान शान्ति रक्षक कार्रवाई को गोविन्द संघ ने न केवल बर्र जरूरी बल्कि परम्पराकारो समझा। कारो संघ के दोहन सैनिक और राजनयिक दोनों ही पक्षों में भारत की महत्वपूर्ण भागीदारी थी। बंब रह कृष्णा अधिक उचित लगा कि भारत व संघ के बीच मतभेद नहीं, बल्कि मतभेद रह। यदि न मतभेद कमिनाई का कारण नहीं बन तो इसके मूल में एक बड़ी बात रह थी कि मनोव्यवस्था भारत और गोविन्द संघ दोनों का ही चीन के साथ विद्रोह समर्थन एक साथ बारम्बार हुआ। 1956 में गोविन्द कम्युनिस्ट पार्टी की बोसबो कायेस के बाद विस्थापितकरण की जो प्रक्रिया आरम्भ हुई, उसने गोविन्द-चीन विवाद ज्ञानन आया। 1962 तक स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि संघ ने 'भाई' (चीन) की अग्रणी मित्र (भारत) का साथ निभान का निमन्त्रण किया। भारत-चीन सैनिक मुठभेद के बाद भारत ने बड़े पैमाने पर गोविन्द संघ से सामरिक सहायता का आग्रह किया। इन्हीं वर्षों में अमेरिका ने अपने शक्तिशाली हथियारों के कारण पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर सैनिक सहायता दी। भारत के लिए इस अव्यवस्था का गोविन्द नामक स हूर करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह गया था।

नहक जी की मृत्यु (1964) तक इस स्थिति में काफी परिवर्तन का भुका था। क्यूबाई प्रवेशक संकट (1962) के बाद दोनों महाशक्तिों बीच सहाय की जरूरत समझन लगी थी। युवा अमेरिकी राष्ट्रपति कैनडी ने शुरू में यह दवाया कि रचनात्मक प्रश्न के प्रश्न को वह समर्थन नहीं समझत। इसी कारण कैनडी तथा खुदसब के बीच समझौते स उत्त प्रक्रिया का सूत्रपात हुआ, जिसकी परिणति 1960 के दशक के उत्तरार्ध में 'देताई' के रूप में हुई। दो महाशक्तियों के निकट जान के परिणामस्वरूप भारत का ही नहीं, बल्कि सभी मुठ-निरपक्ष देशों का अवमूल्यन हुआ। यह बात 1965 की भारत-पाक सैनिक मुठभेद में विन्तुन स्पष्ट हो गयी। गोविन्द संघ ने दोनों मुठभेद राष्ट्रों के बीच पूर्णतः तटस्थ नीति का निर्धारण और तटस्थता समर्थन में अपनी समर्थता के दोहन भी अमेरिकी हिता का ध्यान रखा।

यह अत्यंत स्थिति कनोबा 1969 तक बनी रही। इसके कई कारण थे। आरम्भिक वर्षों में चीन की इन्दिरा साधो एक एकी पार्टी का महत्व कर रही थी जिस समर्थन में स्पष्ट महान्त प्राप्त नहीं था। अन्त में बन रहने के लिए भारतीय साम्यवादी पक्षों का समर्थन जुटाना चीन की इन्दिरा साधो की विवकता थी। गोविन्द नेता इस बात का बनी-भाति समझत थे। यह स्वाभाविक भी था कि वे इस स्थिति का लाभ उठाने का प्रयत्न करते। 1968 में जब खुदसब के उत्तर-पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में दुष्साहसिक तरीके से बकोम्नावादिना में सैनिक हस्तक्षेप किया और चीन की समर्थता के निमित्त का प्रतिपादन किया तो चीन की इन्दिरा साधो के समर्थन के प्रमुख सदस्य अमेरिका ने इस घटनाक्रम को समर्थन करत हुए अपनी पद स त्याग-पत्र दे दिया। इन्हीं दिनों बेजिंग ने बहुकारी इस स समर्थन एशिया के लिए एक मानविकीय सुरक्षा योजना प्रस्तुत की। इस तकर भी कई भारतीय असन्तुष्ट हुए। यहाँ एक ओर वे सब बातें बेजिंग के बड़े हुए समर्थन-विवरण का समर्थन थी, वहीं इनके लिए यह बात भी जिम्मेदार थी कि 1964 से 1968 के

के आर्थिक विकास के लिए बड़े पैमाने पर आर्थिक तकनीकी सहायता देगा। असल में रूस का यह बदला हुआ रवैया भारत के हार्दिक आतिथ्य के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन नहीं, बल्कि तीमरी दुनिया के करोड़ों अफो-एशियाइयों के दिलों-दिमाग जीतकर शीत युद्ध में अमरीका को पस्त-परास्त करने वाली सुनियोजित रणनीति का एक हिस्सा था।

रुश्चेव काल में भारत-सोवियत सम्बन्ध (1954 से 1964 तक)—रुश्चेव ने सत्ता के सारे मूत्र अपने हाथ में एकत्र करने के साथ ही शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व वाले राजनय का प्रतिपादन किया जिसके अन्तर्गत गैर-समाजवादी देशों के साथ भी विशेष मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सम्भव थे। जहाँ तक भारत का प्रश्न था, अब तबक पश्चिमी जगत के साथ उसका मोड़ यह हो चुका था। राष्ट्रमण्डल की सदस्यता ग्रहण करने के बावजूब नेहरू सरकार ब्रिटेन से अपेक्षित आर्थिक व तकनीकी सहायता जुटाने में असमर्थ रही थी। विशेषकर इस्पात सवन्त्र हासिल करने और खाद्यान्नों के सिलसिले में उसे अमरीका से तिरस्कृत होना पड़ा था। सोवियत नेताओं ने भारत को सूचित किया कि वे इस्पात, कोयला तथा विद्युत, प्राण-रक्षक दवाइयों, मैनिक साज सामान के क्षेत्र में भारत के साथ खुले हाथों से सहयोग करने को तैयार हैं।

इसके बाद भारत-सोवियत सम्बन्धों में निरन्तर धनिष्ठता स्थापित होती गयी। जब नेहरू जी ने सोवियत नेताओं के निमन्त्रण पर रूस का जयाघी दौरा किया तो रूसियों ने उनका इतनी गर्मजोशी से स्वागत किया कि नेहरू जी अतीत की मारी वसाई और उपेक्षा भूल गये। बात सिर्फ एक व्यक्ति के मुग्ध होने की नहीं थी। रुश्चेव शायद विश्व के सामने एक मानवीय चेहरा पेश कर रहे थे, जो स्तालिन की तुलना में कहीं अधिक आकर्षक था। इसी समय भारतीय साम्यवादियों ने भी नेहरू जी की प्रगतिशील मरनार को वैदिकक समर्थन देना आरम्भ कर दिया। भारतीय साम्यवादी पार्टी की अमृतसर शांसे (1955) ने यह बात तय की गयी कि पार्टी सशस्त्र शान्ति का रास्ता छोड़कर अब ससरीय प्रणाली से सत्ता ग्रहण करने का प्रयत्न करेगी। सोवियत संघ के लिए नेहरू जी को प्रगतिशील मानना इसलिए भी आसान हुआ कि 1950 वाले दशक में आजाद भारत में औद्योगिकीकरण, सुनियोजित विकास, बड़े पैमाने पर भूमि सुधार के कार्यक्रम आदि उत्साह में चलाये जा रहे थे और अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय विदेश नीति के तेवर बुझाक डग में उपनिवेशवाद-आध्यात्मवाद विरोधी तथा निगस्त्रीकरण के पोषक थे। हिन्दू धर्म की समस्या हो या अफ्रीका में रगभेद के विरुद्ध लड़ाई, भारतीय नीतियों का साम्य-मयोंग अमरीका की तुलना में सोवियत संघ के साथ कहीं अधिक था।²

भारत-सोवियत मतभेद—यह समझना गलत होगा कि 1954 से 1964 तक भारत व सोवियत संघ के बीच मतभेद उभरे ही नहीं। भारत पहले हगरी में सोवियत

¹ भारत-सोवियत सम्बन्धों के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए देखें - Devendra Kaushik, *Soviet Relations with India and Pakistan*, (Delhi, 1971), Girish Mishra, *Contours of Indo-Soviet Economic Cooperation*, (Delhi, 1976), Arther Stein, *India and Soviet Union: The Nehru Era* (Chicago, 1969), Vijay Sen Budhraj *Soviet Russia and Hindustan Sub-Continent*, (Delhi, 1973) और J. P. Premdas, *Indo-Soviet Relations* (Meerut, 1984)

सामंजस्य व सहयोग 1977 तक अच्छी तरह स्पष्ट हो चुका था। इसी वक्त नए शीत युद्ध के आविर्भाव ने विदम्बनापूर्ण ढंग से भारत और सोवियत संघ को फिर एक-दूसरे के पास ला दिया।¹

नया शीत युद्ध और भारत-सोवियत सम्बन्ध—प्रधानमंत्री बनने के वयो पहले मोरारजी देसाई अपने को स्पष्ट रूप से साम्यवाद विरोधी घोषित कर चुके थे। थत उनका धारणा-काव म नेहरू जी या श्रीमती इन्दिरा गांधी क जैसे वामपंथी रत्नान की बात सोची नहीं जा सकती थी। वैसे भी जनता पार्टी के प्रेरणा-स्रोत लोकनायक जयप्रकाश नारायण पश्चिमी जगत के पक्ष में थे और जनता पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी आदि सोवियत संघ की अपेक्षा अमरीका की ओर झुकाव रखते थे। चरण सिंह की वाई विशेष रुचि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों म नहीं थी, किन्तु उन्होंने अपने एक वरिष्ठ कबिनेट सहयोगी हृमवती नन्दन बहुगुणा को क० जी० बी० एजेंट कहकर दोनों देशों के सम्बन्धों को अपेक्षाकृत तनावग्रस्त किया। मोरारजी देसाई आदि के मन म हम बात को लेकर भी मालिन्य था कि जब मसार भर में आपातकालीन तानाशाही की निन्दा हुई थी तब सोवियत संघ ने श्रीमती इन्दिरा गांधी को ममर्शन दिया था।

सोवियत संघ ने इस कठिन दौर में दूरदर्शी राजनयिक सूझ का परिचय दिया। जब अटल बिहारी वाजपेयी आदि ने खानिख गुट निरपेक्षता (Genuine Non alignment) की बात की तो सोवियत नेता उत्तेजित नहीं हुए। उन्होंने देसाई का भी सोवियत संघ में उतनी ही गर्मजोशी से स्वागत किया, जितना उनके पूर्ववर्ती भारतीय प्रधान मन्त्रियों का किया जाता रहा था। मोरारजी देसाई इससे नरम पड़े हो या नहीं, लेकिन रूमी नता भारतीय विदेश मन्त्री वाजपेयी को रत्नाने में सफल हुए। सोवियत संघ को दो अप्रत्याशित कारणों से इस प्रयास म सहायता मिली— (1) काटर सरकार की अहकारी रत्नाई और पाकिस्तान की पक्षधरता, तथा (2) चीन यात्रा के दौरान वाजपेयी की मानहानि। इसने भारत सरकार क मामने यह तथ्य उजागर किया कि आड़े वक्त म काम आने वाली आजमायी दोस्ती सोवियत संघ के साथ टिकाऊ रहेगी। जनता सरकार द्वारा सोवियत संघ म नियुक्त राजदूत इन्द्र कुमार गुजराल (जो वास्तव म इन्दिरा गांधी द्वारा भेजे गये थे) वामपंथी रत्नान के ब्यक्ति थे। उन्होंने स्वामीभक्तिपूर्ण तरीके से जनता सरकार क पक्ष में सोवियत मत निर्धारण म महत्वपूर्ण योगदान दिया।

भारत सोवियत आर्थिक सम्बन्ध—इस सन्दर्भ म सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि 1977 तक भारत-सावियत आर्थिक सम्बन्धों का ताना-बाना बहुत लाभप्रद ढंग से इतना बुना जा चुका था कि ब्यापक नीति परिवर्तन की गुंजाइश ही नहीं बची थी। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सोवियत संघ भारत का सबसे बड़ा साझेदार था। इस व्यापार का मानाना बाराबार दो हजार करोड़ रु० से ऊपर पहुँच गया। सोवियत संघ ने मिलाई और बाकरी इत्याद सयन्त्र स्थापित करवाने में मदद की। मधुरा तेल शोधन कारखाना, हरिद्वार म प्राणरक्षक एन्टी बायोटिक ओपधि निर्माणशाला की स्थापना भी सोवियत संघ ने तकनीकी सहकार स ही संभव हुई।

मैनिक मात्र-समान के बायात एवं उत्पादन के मामल म भारत की निर्भरता और भी नाजुक (critical) रही। बारम्भ से ही मिग सड़कू विमानों की 'असम्बन्धी'

¹ रबिरे—K. P. S. Menon, *Indian Soviet Treaty* (Delhi, 1971)

बीच अमरीकी साक्षात् आयात पर भारत की निर्भरता तेजी से बढ़ी थी। अमरीकी दबाव के कारण भारत सरकार को रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा था। ऐसा सोचा जा सकता था कि यदि लगातार कमी नहीं गयी तो भारत क्रमशः दूसरे खेमे में किमत्त जायेगा।

1969 के आते-आते एक बार स्थिति महत्वपूर्ण ढंग से बदल गयी। इस बार भी आन्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों कारण प्रभावशाली और संयुक्त रूप से कारगर सिद्ध हुए। 1969 तक श्रीमती इन्दिरा गांधी अपने दक्षिणपंथी, पश्चिम के पक्षपर निष्क्षिप्ति व सिण्टीकेट के सदस्यों पर हवाई हमले शुरू की थी। बैंक राष्ट्रीयकरण, द्वितीयपक्ष के उन्मूलन आदि केंसलों से उनकी प्रगतिशील छवि पुष्ट हुई। इसके साथ ही उत्तरी नदी के तट पर चीन के साथ हिंसक सैनिक झड़पों के बाद सोवियत नेता चीन के संघर्ष में भारत के साथ अपने हितों का संयोजन किए से देखने लगे थे। ऊपर हिन्द चीन के एगसेत्र में तेजी से विगाड़ हो रहा था और अन्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण नियन्त्रण आयोग के समापति के रूप में भारत के राजनयिक महत्व का एक और असंग पहलू उद्घाटित हो रहा था। इसी कारण जब बंगला देश मुक्ति संघर्ष के दौरान भारत ने उस से मैत्री व सहयोग सन्धि की देशकष की तो इस अनुदान पर आसानी से हस्ताक्षर हो सके।

भारत-सोवियत मैत्री व सहयोग सन्धि (9 अगस्त, 1971)—कई बार आलोचक यह आरोप लगाते हैं कि भारत ने इस सन्धि के बाद गुट निरपेक्षता त्याग दी। परन्तु सन्धि के अनुच्छेदों का विस्तरेण करने से यह बात निर्विवाद रूप में सामने आती है कि वस्तुतः इसने भारतीय गुट निरपेक्षता को अक्षत रखा। इस सन्धि के तहत आसन्न संकट की स्थिति में दोनों पक्षों के लिए एक-दूसरे को सूचित करना और परामर्श के बाद कोई कदम उठाना तय किया गया। इस व्यवस्था को किसी भी तरह सैनिक सन्धि के समानार्थक नहीं समझा जा सकता। बंगला देश मुक्ति अभियान के दौरान भी इस सन्धि के प्रावधानों का सैनिक नहीं, बल्कि राजनयिक लाभ ही उठाया गया। वास्तव में, यह सन्धि भारत और सोवियत संघ के बीच विरोध सम्बन्धों के यथार्थ का तारकीतिक स्थिति में मनोवैज्ञानिक लाभ उठाने का एक प्रयत्न थी। परवर्ती वर्षों का अनुभव इसी धारणा को पुष्ट करता है।

1971 के बाद 1975 तक भारत-सोवियत सम्बन्धों में निरन्तर सुधार होता रहा। दोनों देशों के बीच बड़े पैमाने पर आर्थिक सहकार का विस्तार किया गया। भारत ने उस से बड़े पैमाने पर सैनिक साज-सामान का आयात किया। इस दौर में भी चीन-अमरीका सम्बन्धों में सुधार ने भारत-सोवियत आत्मीयता की वृद्धि प्रोत्साहित की। 1975 में जब भारत में आपातकाल की घोषणा के बाद भीमती इन्दिरा गांधी के 'असहैतानिक प्रयासन' की विश्व भर में आलोचना हुई तो सोवियत संघ ने उनका सहर्ष सपरिवार आतिथ्य स्वीकार किया।

1977 में जब श्रीमती इन्दिरा गांधी अपदस्थ हुई और उनका स्थान मोरारजी देसाई ने लिया तो ऐसी अटकलें लगायी गयीं कि नई जवता सरकार अब थापद सोवियत संघ के प्रति अपना रवैया बदलेगी। परन्तु ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारत-सोवियत सम्बन्ध व्यक्तिगत आकर्षण और दलगत पूर्वाग्रहों पर नहीं, बल्कि हितों के सामंजस्य पर टिके हुए थे। इनका

सैनिक हस्तक्षेप किया। उसे जनवरी, 1979 में चाहे-अनचाहे कम्युनिशम में वियतनामी हस्तक्षेप की समर्थन देना पड़ा। इन दोनों प्रसंगों में सोवियत संघ अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर अकेला पड़ गया और समाजवादी खेमे के बाहर उसका साथ देने वाला एकमात्र गुट-निरपेक्ष राष्ट्र भारत सिद्ध हुआ। यहाँ इस बात को रेखांकित करना बेहद जरूरी है कि ऐसा किसी सुनियोजित नीति के कारण नहीं, बल्कि असमंजस और दुनिया की स्थिति में हुआ। जब संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी स्थिति स्पष्ट करने की घड़ी आयी तो भारत के स्थायी प्रतिनिधि ब्रजेश मिश्र को नई दिल्ली के निर्देशों के अभाव में अपने विचारों के अनुसार एक बक्तव्य देना पड़ा। अफगान मंच के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में मोरारजी देसाई का स्थान चौधरी चरण सिंह ले चुके थे और उनकी अपनी कुर्सी दावाइल थी। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जनता सरकार के विरुद्ध अपने अभियान में विदेश नीति के मुद्दा को महत्वपूर्ण समझा। निश्चय ही भारत की आन्तरिक राजनीति में अस्थिरता ने राजनय के क्षेत्र में परिवर्तन की अपेक्षा निरन्तरता को अधिक महत्वपूर्ण समझा गया और नये शीत युद्ध के आधिपत्य के साथ भारत-सोवियत द्विती के साम्य को भी जगजाहिर किया। तब से भारतीय प्रवक्ता भन ही अपनी गुट-निरपेक्षता प्रमाणित करने के लिए बारम्बार यह घोषणा करते रहे कि भारत विदेशी सेनाओं की वापसी के पक्ष में है लेकिन भारत को सोवियत संघ के 'समर्थन' के कारण अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में रक्षार्थक रथ (भले ही प्रच्छन्न रूप से) अपनाना पड़ा।

भारत-सोवियत सम्बन्धों का सांस्कृतिक आयाम—पिछले लगभग 38 वर्षों में भारत और सोवियत संघ दोनों का यह प्रयत्न रहा है कि आर्थिक व सामरिक परिप्रेक्ष्य में साम्य को सांस्कृतिक आदान-प्रदान का आकर्षक जामा पहनाया जाये। सोवियत संघ की यह कोशिश रही कि सांस्कृतिक सम्पर्क सरकार और पार्टी के स्तर पर अलग-अलग चलाये जायें और 'जनाभिमुख राजनय' को सोवियत ढंग से सम्पादित किया जाये। रूसी कलाविद्या के भारतीय मायाओं में विफावर्ती प्रकाशन-वितरण की व्यवस्था हो या बोल्टोविक थियेटर में 'सानुत्सम्' जैसे भारतीय महाकाव्यों के रूसी रूपान्तरणों की प्रस्तुति, दोनों इसी सुनियोजित सांस्कृतिक अभियान के अंग थे। यह भी उल्लेखनीय है कि भारत ने इस आदान-प्रदान में विशेष पहल नहीं की बल्कि स्वयं रूस ने साम्यवादी-मार्क्सवादी-वामपंथी द्वाज तख्त सभी प्रगतिशील तत्वों के माध्य उपयोगी मोर्चा बनाते हुए इस दिशा में पहल की। यह सच है कि राजकपूर की 'अवार्ड' जैसी फ़िल्म सोवियत संघ में बेहद लोकप्रिय हुई, परन्तु सरकारी समर्थन एवं सहायता के बिना ऐसा होना सम्भव न था। 1960 वाले दशक में सोवियत संघ में पैट्रिम लुमुबा विश्वविद्यालय की स्थापना ही इस उद्देश्य से की गयी कि अफ्रीका व एशिया के तत्कालीन एवं सोवियत संघ से सहानुभूति रखने वाले छात्रों को इसके तत्त्वविधान में छात्र-वृत्तियाँ दी जा सकें।

यह घारा वास्तव में दूसरी तरफ भी बहने लगी। जितने बड़े पैमाने पर सोवियत संघ में 'भारत महोत्सव' का आयोजन किया गया, उससे यही पता चलता है कि भारत-रूस सम्बन्धों का सांस्कृतिक पक्ष कम महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। तब भी इस बात को अनदेखा करना कठिन है कि सोवियत संघ में भारत महोत्सव का आयोजन अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस में कराने के बाद किया गया और अब तक विदेशों में भारत महोत्सवों का आयोजन करने वाले न्यस्त स्वार्थ इतने मजबूत

लाइसेंस मुद्रा ढंग से हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स के कारखाने में सोवियत मदद पर ही निर्भर रही। लड़ाख के सीमान्त पर तैनात सिपाहियों तक हथियार व रखद पहुँचाने वाले मिग-16 व मिग-32 हेलीकोप्टर और ए० एन०-12 व ए० एन०-32 माल-वाहक जहाज भी भारत को सोवियत संघ ने ही मुलम कराये। इसके अतिरिक्त पश्चिमी पानिस्तानी मोर्चे पर प्राणरक्षक सी-50 टैंकों का उत्पादन भी इसी मित्र देश की सहायता में होता रहा है। भले ही परमाणु प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सोवियत संघ ने भारत की अपेक्षाओं को हमेशा पूरा न किया हो, किन्तु भारत के मन में यह आशा बची रही कि और कुछ नहीं तो 'भारी पानी' हासिल करने में सोवियत संघ भारत का मददगार साबित होगा।

जनता सरकार के आरम्भिक काल में भले ही यह बात कई बार उठायी गयी कि भारत को सैनिक साज सामान के आयात व उत्पादन के बारे में किसी एक देश पर इतनी बुरी तरह निर्भर नहो होना चाहिये। भारत ने स्वीडन, ब्रिटेन, फ्रांस आदि से कमरा: किंगन, जगुआर और चिराज जैसे परिष्कृत सड़ाकू विमान पाने का प्रयत्न भी किया। परन्तु पश्चिमी जगत में घटन व्यापार सरकारी के नहीं बल्कि स्वतन्त्र उद्योगपतियों के हाथ में है और अन्तर्राष्ट्रीय छोटे दसाली, मुनाफाखोरी आदि के साथ अनिवार्यत जुड़ जाते हैं। चूँकि सोवियत संघ के सन्धर्म में सारा कार्य-व्यापार सरकार के साथ सम्पन्न होता था, इसलिए इस तरह के किसी आक्षेप से मुक्त रहा जा सकता था। इसके अलावा जहाँ पश्चिमी देशों के साथ सारी खरीद करोखत बुलम विदेशी मुद्रा में होती थी, वही सोवियत संघ के साथ रुपये और रुबल के विनिमय तथा आदान-प्रदान (barter) की सुविधा रही।

बैसे अनेक दिज्ञानों का यह मानना है कि रुपया-रुबल विनिमय प्रणाली भारत के लिए कम शोषक नही। सोवियत संघ भारत में अर्जित वषयों से या उनके आदान-प्रदान के माध्यम से वे ही चीजें खरीदता रहता था, जिनसे भारत विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। भारतीय विदेश व्यापार अध्यायन संस्थान के विशेषज्ञ डा० सुमित्रा चिन्ती ने इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर ध्यान दिलाया है कि सोवियत संघ ने भारतीय विदेश व्यापार की स्वाधीनता परोक्ष रूप से समाप्त कर दी। प्रकारान्तर से सोवियत संघ ही यह तय करता था कि किन देशों की भारत क्या चीज बेचे। सोवियत संघ भारत से बड़े पैमाने पर ऊनी व चमड़े के सामान, प्रसायन सामग्री आदि की खरीद करता था। यदि वह एकाएक इस खरीद को स्थगित कर दे तो भारत के लिए इस तरह के उत्पाद के लिए दूसरा वैकल्पिक बाजार ढूँढना बहुत कठिन होता। भारत में इस तरह की सामग्री का उत्पादन सोवियत संघ के उपभोक्ता की रुचि और जरूरत के अनुसार किया जा रहा है। इससे उत्पादकों और विक्रेताओं को किसी प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ता और न ही किसी विशेष विज्ञापन का खर्च उठाना पड़ता। इनके जलझवा एक ओर पेचीदगी थी। उन वषों में भारत-सोवियत व्यापार का स्वरूप बेहद असन्तुलित (भारत के पक्ष में) बन गया। सोवियत संघ आवश्यकता पड़ने पर इनका प्रयोग भारत पर दबाव डालने के लिए कर सकता था।

बहरहाल, सोवियत संघ ने जनता शासन के काल में नई सरकार को किसी तरह के दबाव से नहीं, बल्कि सौहार्द से अपनी ओर खींचा। अभी भारत में जनता सरकार ही सत्तारूढ़ थी कि सोवियत संघ ने दिसम्बर, 1979 में अफगानिस्तान में

गणराज्यों को बगावत के बाद स्वाधीनता की घोषणा करने से या जानीब वैमनस्य के कारण आपस में सैनिक मुठभेड़ से राकन के लिए बल प्रयोग तक करना पड़ा। सावित्र सभ की अध्यक्षता चरमरा गई और शार्वाङ्गाव की मुद्रा अन्तराष्ट्रीय शृणानाजा और अन्तराष्ट्रीय बैंक के मामल भारत में भी ज्यादा दमनीय है। सावित्र सभ यह स्पष्ट कर चुका है भविष्य में उगवा मारा अन्तराष्ट्रीय व्यापार परिवर्तनाय विदेशी मुद्रा में ही होगा। इसका सबसे ज्यादा नुकसान भारत को ही उठाना पड़ेगा। साथ ही टैक्सानाओं का आयात हा या विदेशी पूँजी की आमरण सावित्र सभ के लिए बमरोका एकाइन यूरोप जापान आदि नहीं अधिक महत्वपूर्ण मापदार है। साठी मुद्रा के बाद महार्गात्त हान का दम बरकरार रखना सावित्र सभ के लिए सम्भव नहीं रहे गया अतएव भारत-मोवित्र सम्बन्ध भी पहले जैसा नहीं रहे सके। सावित्र सभ से उपक्षा और अवहसनान मही उदासीनता भारत के हिंस पड़ेगी।

भारत और उसके पड़ोसी देश (India and Her Neighbours)

प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ चिन्तक एवं अग्रगण्य के रचितता कौटिल्य की यह मान्यता थी कि किसी भी चक्रवर्ती सामक या विजिगीनु (विजय की अभिनाया रखन वाला) के लिए पड़ोसी राज्य हा सबसे बिकट समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। कौटिल्य के मण्डन सिद्धान्त की नींव इसी शास्त्र सिद्धान्त पर रखी गयी थी। आधुनिक युग में भी किसी भी देश के वैश्विक सम्बन्धों में पड़ोसी राज का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यदि पड़ोसी देश अनुबल हा तो राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे प्रसन्न हो जाती है। यदि पड़ोसी देश के साथ सम्बन्ध मधुर हा तो राष्ट्रीय हित विस्तृत गतिविज तलाग सके हैं।

भारत और उसके पड़ोसी राजों के सम्बन्धों पर ये बातें अवश्य लागू हानी हैं परन्तु इनके साथ कुछ कम अनूठ तत्व भी हैं जिनका रेखांकित किया जाना जरूरत है। इस बात के और म जान से पहले यह स्पष्ट करना उपयोगी होगा कि भारत के निकटस्थ किन देशों का हम भारत के पड़ोसी देश मानते हैं। देश के विभाजन से दमा पाकिस्तान और पाकिस्तान के विषय में पैदा हुआ बगला दम निश्चय ही इस श्रेणी में आता है। नपान भूगोल तथा आवाका की पड़ोसी देश मानते हैं किसी को कोई हिचकिचाहट नहीं हा सकती। भौगोलिक दृष्टि से चीन अफगानिस्तान बर्मा दुष्मानिया माननीय और मारोम इसी श्रेणी में रख जान चाहिये। इस प्रकार में भारत के विभिन्न पड़ोसी देशों के साथ समय-मधीय सम्बन्धों का विवरण विविध रूप के साथ करने के अतिरिक्त तत्कालीन विवरण का प्रयत्न भी किया गया है। पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के सम्बन्ध विविध और जटिल हैं तथा एक बहुत बड़ी मामा तक महार्गात्तों के साथ हमारे सम्बन्धों में अनुमानित हाते हैं। उन इनका अपभाहृत अविक विस्तार के साथ परमा गया है। माननीय के साथ सम्पर्क इतने बिबर हुए और छिटपुट रहे हैं कि उनकी सिफ स्पृति पर तैयार करने का कोई उपयोगिता नहा। इस स्थिति में नू राजनातिक विप्रिय या धनीय सद्कार की प्रस्तावना कम-दम में इनका उत्पन्न हो सकता है। अत यही पाकिस्तान, बगला दम चीन नपान भयान और थीलका के साथ भारत के सम्बन्धों का

हो चुके थे कि यह कहा जा सकता था कि इस सारे खर्चीले क्रियाकलाप का कोई सीधा सम्बन्ध शायद विदेश नीति के उद्देश्यों के साथ नहीं है। यह शक भी पैदा हुई कि सांस्कृतिक राजनय के उभार में गोर्बाच्चेव के खुलेपन (ग्लासनेस्त) की नीति शायद भारत की दूरदर्शी पहल से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। कुछ विद्वानों का यह भी मानना था कि भारत-सोवियत सम्बन्धों में सांस्कृतिक आयाम विशेष महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि इसमें आम तौर पर जनता का वही तबका खिंचेला रहा और सक्रिय रहा, जो पहले से सोवियत संघ का पक्षधर रहा।

भारत-सोवियत सम्बन्धों का नविष्य—भारत और सोवियत संघ में शीर्षस्थ सत्ताधारी नेताओं का बदलना एवं अपनी जड़ें मजबूत करना लगभग साथ-साथ हुआ। जिन तरह राजीव गांधी को लेकर भारत में नई आशा जग रही थी, उसी तरह सोवियत संघ में गोर्बाच्चेव को लेकर उरसाहुजनक वातावरण पैदा हो रहा था। ऐसे में यह अटपटी बात है कि भारत और सोवियत संघ के आपसी सम्बन्ध इतने घनिष्ठ और भारतीय ढंग से विकसित नहीं हुए, जितने होने चाहिये थे। इसका सबसे बड़ा कारण शायद यह रहा कि 1984 में सत्ता ग्रहण करने के ठीक बाद राजीव गांधी और उनके समर्थकों ने यह बात स्पष्ट कर दी कि भारतीय आर्थिक विकास की जड़ता तोड़ने के लिए वे उदार व सचीली आर्थिक नीतियों का अनुसरण करेंगे। जाहिर था कि इस सबसे तिर्क पश्चिमी देशों को ही हानि हो सकती थी।

आरम्भ में सोवियत संघ का इस बात से शक्ति होना स्वाभाविक था कि शायद राजीव गांधी का हस्तान्तरण उसकी अपेक्षा अमरीका की ओर अधिक रहेगा। वैसे शायद इस बात को अनावश्यक तूल दिया जाता रहा है, क्योंकि राजीव गांधी के नाई सत्य गांधी उनसे कहीं अधिक दक्षिणपंथी और साम्यवाद विरोधी थे परन्तु सभी नेताओं को उनके साथ बातचीत करने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। दूसरी अड़चन यह रही कि माओ के उत्तराधिकारी देग सिपाओ पिंग द्वारा चीन में व्यावहारिक एक शुभारंभवादी नीतियों के क्रियान्वयन से सोवियत संघ और चीन के बीच कटुता कम हुई तथा सामान्यीकरण की सम्भावना बढ़ी। इस बदली परिस्थिति में अनेक भारतीय विश्लेषक इस बात से चिन्तित रहे कि निकट भविष्य में सोवियत संघ के लिए भारत के साथ मैत्री सामरिक महत्व की नहीं रहे जायेगी। अफगान संकट ने भी सोवियत संघ को पाकिस्तान के बारे के नये सिरे से सोचने के लिए विवश किया। सोवियत नेताओं के भाषणों एवं व्यक्तियों का जारीकी से विश्लेषण करने वालों का मानना है कि गोर्बाच्चेव के शासन काल में रूस ने भारत के प्रति बेहिचक पक्षपात के स्थान पर इन दो देशों के बीच 'सम-सामोप्य का भाव' अपनाया आरम्भ किया। ये लोग यह भी मुखाते हैं कि भारत-सोवियत आर्थिक सम्बन्धों में जिस तरह के गतिरोध और तनाव अप्रत्याशित तथा अभूतपूर्व ढंग से सामने आये हैं, उनसे भी यही खरोह मिलता है कि पहले जैसी आत्मीयता अब दोष नहीं रही। 1986 में मंगोलिया में सोवियत विदेश मन्त्री की चीनी अधिकारियों से बातचीत और पाकिस्तान के माध्य अप्रत्यक्ष राजनयिक सम्पर्क स्थापित करने के सोवियत प्रयत्नों ने भारत को मर्क किया।

'दूसरे देवात' के आविर्भाव के पहले ही अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में जैसे भूकम्प सा आ गया। सोवियत संघ में आन्तरिक स्थिति बहुत तेजी से बदली। गणराज्यों में व्यापक असन्तोष ने विस्फोटक आन्दोलन का रूप ले लिया और अनेक स्थानों में इन

जी के व्यक्तिगत मित्र। उनकी लोकप्रियता में कोई सन्देह करने की गुंजाइश नहीं थी। उनकी राजनीतिक पार्टी नेशनल फ्रन्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहयोगी थी। इसके विपरीत हिन्दू शासक राजा हरिसिंह ने भारत में विलय के लिए कोई विशेष उत्सुकता नहीं दिखायी। जब पाकिस्तानी आक्रमण के कारण उनकी गद्दी और जान खतरे में पड़ी, तभी उन्होंने भारतीय सैनिक संरक्षण पाने के लिए विलय-सन्धि पर हस्ताक्षर किये।

वस्तुतः कश्मीर की विद्रोही मौलिक स्थिति उसकी जासदी का कारण बनी। कुछ घूर्णन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों के भड़काने से राजा हरिसिंह के मन में यह भ्रान्ति घर कर गयी कि जो काम जूनागढ़ और हैदराबाद के शासक नहीं कर पाये, उसे वह साब लेंगे। चीन, पाकिस्तान और भारत के साथ अन्तर्राष्ट्रीय सीमाएँ स्पष्ट रखकर वह कश्मीर को एशिया का स्विट्ज़रलैण्ड बनाना चाहते थे। बाद के वर्षों में इसी तरह की भ्रान्ति के शिकार शेख अब्दुल्ला भी हुए। परन्तु भारत और पाकिस्तान के लिए इस महत्वाकांक्षा को पूरा होने दना सम्भव नहीं था। दोनों के लिए कश्मीर की भू-राजनीतिक स्थिति मामरिक महत्व की थी। 1948, 1965 तथा 1971 के युद्धों में यह बात अच्छी तरह उजागर हो चुकी थी।

इसके अतिरिक्त नेहरू के लिए कश्मीर का प्रश्न भारतीय धर्म निरपेक्षता की कमीटी बन गया। वह यह किसी भी हानत में सहन नहीं कर सकते थे कि कश्मीरी मुसलमान भारत के धर्म निरपेक्ष स्वरूप में अविश्वाम प्रकट करें। नेहरू जी को इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने कश्मीरवासियों को बलपूर्वक अपने पक्ष में करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। उन्होंने विवाद के शान्तिपूर्ण निपटारे के लिए स्वयं ही इस प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र सच को सौंपा और जनमत संग्रह का वचन दिया।

सिर्फ यही एक ऐसा मामला है, जिसमें नेहरू जी को आदर्शवादित्वा भारी पड़ी। संयुक्त राष्ट्र सच भीत युद्ध से ग्रसित था। अमरीका ने अपने राष्ट्रीय हित साधने के लिए तत्काल पाकिस्तान की पक्षधरता आरम्भ कर दी। बाद में नेहरू जी यह कहते रहे कि कश्मीरवासी बारबार आम चुनावों में हिस्सा लेकर अपना मत भारत के पक्ष में दे चुके हैं, तथापि पाकिस्तान उन पर बचन देकर मुक़रने का आरोप लगाता रहा। ब्रिटेन, फ्रांस और अमरीका की साठगांठ यह रही कि संयुक्त राष्ट्र सच के तत्वावधान में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक मंडली के बहाने भारत की सम्प्रभुता को नीमित करने वाली आपात सैनिक दुरुद्विष्ट कश्मीर में तैनात की जा सकें। भारत को अपनी स्वतन्त्रता अधुण्य रखने के लिए अग्रहमति का स्वर मुखर करना पड़ा। फिर भी, 1953 में सुरक्षा परिषद् में सोवियत सच का दृढ़ समर्थन मिलने तक कश्मीर को लेकर भारत की राजनयिक स्थिति निरापद नहीं रह सकी।

पाकिस्तान के लिए यह स्थिति सन्तोषजनक थी। कश्मीर में युद्ध-विराम लागू होने तक लगभग 50 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर उमन अपना नाजायज कब्जा कर लिया और मात सात आवादी बाल इस क्षेत्र को आजाद कश्मीर घोषित कर दिया। यह उत्तमसनीय है कि इस समय भीत युद्ध अपने चरमोत्कर्ष पर था और सोवियत सच तथा चीन-तिब्बत पर निगरानी रखने के लिए अमरीका को इस क्षेत्र में सैनिक अड्डों की जरूरत थी। इसी कारण अमरीका जैसी महाशक्ति के हित में यह था कि कश्मीर के मामले में भारत और पाकिस्तान के बीच शान्तिपूर्ण

विस्लेषण किया जा रहा है।

भारत-पाक सम्बन्ध (Indo-Pakistan Relations)

भारत की स्वाधीनता और विभाजन के साथ ही बहुत बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक रक्तपात हुआ। इससे भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच मतभेदों और गहरी हो गया। जैसाकि अक्सर घर के बेटवारे में होता है, विभाजन के बाद भी विवाद के कई गम्भीर मुद्दे बचे रहे। जिस तरह पाकिस्तानी राजकार्त्तों ने कश्मीर पर जबरन कब्जे की कोशिश की, उसकी परिणति युद्ध में ही होनी थी। इन प्रकार आरम्भ से ही पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों का निर्वाह एक पेचीदा गुत्थी बन गया जिसके साम्प्रदायिक, सामरिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पक्ष आपस में घुरी तरह गुँथे हुए हैं।

पाकिस्तान के सामने बड़ी समस्या यह रही कि वह स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में अपनी अस्मिता प्रदर्शित करना चाहता है तो धार्मिक व कट्टरपंथी वाला भारत-विरोध ही उसके लिए सबसे आसान रास्ता है। दोनों देशों के बीच विभाजन का कोई तर्कसंगत आधार नहीं। विडम्बना तो यह थी कि 1947 से 1971 तक स्वयं पाकिस्तान के दो हिस्से (पूर्वी पाकिस्तान व पश्चिमी पाकिस्तान) भाषा और संस्कृति की गहरी खाई के कारण अलग थे। इनके बीच की भौगोलिक दूरी राष्ट्रीय एकता के प्रश्न को और भी दुबल बनाती रही। इसी तरह भारत के सामने भी यह समस्या रही है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा करने भर से सफ़ट निवारण नहीं हो जाता। जब तक साम्प्रदायिक अनहिष्णुता लेशमात्र भी बची रहती है और छिटपुट साम्प्रदायिक दंगे होते रहते हैं, तब तक भारत में रहने वाले करोड़ों मुसलमानों के लिए भी इस्लामी धर्म राज्य पाकिस्तान का आकर्षण अपने बल के रूप में बना रहेगा। इसका यह अर्थ नहीं कि भारतीय मुसलमानों का राष्ट्र प्रेम सारा नहीं। इसका एकमात्र उद्देश्य यही सकेत करना है कि पाकिस्तान को भारत में अल्पमंड्यको, असन्तुष्टों, भ्रष्टाचारित व वंचित तबकों को उकसा-मड़काकर सामरिक सफ़ट उत्पन्न करने की सलूकियात रहेगी। वस्तुतः विचारधारा का बुनियादी टकराव भारत और पाकिस्तान के बीच विभिन्न विवाद पैदा करता है और इन्हें अनापस्यक मूल देता है।

कश्मीर समस्या—भारत के घुर उत्तर में स्थित अद्भुत सुन्दर प्रदेश कश्मीर रियासत की बहुमंज्यक जनसंख्या मुसलमान है परन्तु वहाँ शासन करने वाला राज्यम सदियों से हिन्दू रहा। इसके अतिरिक्त वहाँ अनेक आदिवासी जनजातियाँ बौद्ध धर्मानुयायी हैं। पूरी रियासत को बहुत आसानी से तीन स्पष्ट क्षेत्रों में बाँटा जाता रहा है—जम्मू का हिन्दू-बहुल मैदानी इलाका, इस्लामी प्रभाव वाली कश्मीर घाटी और महास का बौद्ध प्रदेश। एक और सामरिक कठिनाई यह थी कि कश्मीर का (फासकर घाटी का) संचार और यातायात साधनों द्वारा सीमा सम्बन्ध देश के उस हिस्से से था, जो पाकिस्तान बना। परन्तु ऐसा सोचना गलत था कि मुस्लिम-बहुलजन्य जनता पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी। स्वाधीनता संग्राम के दौरान राजवंश के उत्पीड़न के विरुद्ध दोष धुत्ला ने व्यापक जन-आन्दोलन का नेतृत्व किया था। दोष अन्दुला निबिबाद रूप से धर्म-निरपेक्ष व्यक्ति थे तथा नेहरू

लिए ऐसा करना अपरिहार्य अनिवार्यता है, क्योंकि औपनिवेशिक शासन बाल में अग्रजों ने अविभाजित पंजाब की चुनौती के लिए नहरो का जो जाल बिछाया था वह देश के बँटवारे के बाद पूरा का पूरा पश्चिमी पंजाब में अर्थात् पाकिस्तान में ही चला गया। सलाल नदी जल परियोजना हो या फरक्का जलबध, पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों में इनसे पेचदशी बढ़ी। फिर भी इन मामलों में परामर्श द्वारा समस्या का समाधान अपेक्षाकृत सहज रहा है क्योंकि दोनों देशों की सरकारें यह बात भली-भाँति समझती रही कि विश्व बैंक या किसी अन्य बड़े स्रोत से बड़े पैमाने पर सिंचाई परियोजना के लिए अनुदान बिना इस विवाद का निपटारा सम्भव नहीं होगा। 1960 में सम्पन्न मिथु जब सन्धि इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करती है। दुर्भाग्य का विषय यह है कि इस तरह के समझौते को आधार बनाकर इसी तरह का कोई अन्य समझौता कर बड़ी दुरुआत करने की दूरदर्शिता किसी भी पक्ष ने नहीं दिखायी।

शरणार्थी समस्या—भारत और पाकिस्तान के आपसी सम्बन्धों में समय-समय पर अस्थायी ही नहीं परन्तु जोखिमभरी उत्तेजना भरने के लिए शरणार्थियों की समस्या प्रमुख कारण रही है। विभाजन के बाद भी करोड़ों की तादाद में मुमलमान भारत में बचे रहे और लाखों हिन्दू पाकिस्तानी भूमि में अपना जीवन-यापन करते रहे। विभाजन के साथ साम्प्रदायिक हिंसा का जितना बड़े पैमाने पर विस्फोट हुआ, उसने इन अल्पसंख्यकों को आघातों से घूर घूसरित कर दिया। धर्म-निरपेक्ष भारत में, विशेषकर नेहरू जी के जीवन काल में अल्पसंख्यकों को सरकारी संरक्षण प्राप्त था और उनके अधिकारों के हनन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। परन्तु पाकिस्तान में ऐसा नहीं था, विशेषकर पूर्वी बंगाल में रहने वाले हिन्दू अल्पसंख्यकों का जीवन प्रमत्त घूमर होना गया। 1950 से 1953 के बीच लहरो के रूप में ऐसे शरणार्थियों का भारत में प्रवास हुआ और उनकी लुटी पिटी दशा ने पश्चिम बंगाल में साम्प्रदायिक तनाव को जन्म दिया। इससे भारत-पाक सम्बन्धों में बिगाड़ जाना स्वाभाविक था। इस समस्या पर नियन्त्रण पाने के लिए नेहरू जी और तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के बीच एक समझौता भी हुआ। परन्तु इसका प्रति पाकिस्तानी प्रतिबद्धता खरी न होने के कारण इसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। लियाकत अली खान की हत्या और पाकिस्तान में ससदीय जनतन्त्र के पतन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच खाई और भी चौड़ी हो गयी।

पाकिस्तान का संघोकरण—भारतीय राजनीति में अनेक आन्तरिक दबावों के कारण 1947 में पाकिस्तान का जन्म को टालना तो असंभव हो चुका था, परन्तु पाकिस्तान की स्थापना के साथ राष्ट्र निर्माण की चुनौती मुँह बाएँ खड़ी थी। पाकिस्तान एक कृत्रिम संरचना थी और इसके जन्म के साथ ही एक आन्तरिक दबाव व्यवस्था पर पड़ रहा था कि पाकिस्तान का अस्तित्व संकट में था। पंजाबियों, पठानों, खूषो, सिंधियों, बिहारियों, बंगालियों, दिल्ली वालों, उत्तर प्रदेश के निवासियों और दक्षिण से आने वाले मुसलमानों के बीच सिर्फ इस्लाम ही एकमात्र समानता थी। बल्कि इस्लाम के अनुसरण में भी इन लोगों की उपमना पद्धति में प्रादिक-सौश्रीय संस्कार इतना गहरा था कि एकता के बजाय दरारें ही ज्यादा नज़र आती थीं। भारत से आने वाले शरणार्थियों को पंजाब के मूल निवासी, नीची

परामर्श की प्रगति न हो। इसी वजहसे राष्ट्रमण्डल में मध्यस्थता के नाम पर ब्रिटेन भी अपने दोनों भूतपूर्व उपनिवेशों पर अपना सामरिक प्रभाव बनाये रखना चाहता था।

1950 और 1960 के दशक में जब प्रकाश नारायण जैसे नेता यह मुद्दा बढे रहे कि कश्मीर की वादी पाकिस्तान को देकर भी भारत-पाक सम्बन्धों में सुधार वादनीय है। किन्तु भारत-चीन सम्बन्ध में विगाड के बाद भारत के लिए सहायी सोमान्ता को देश के धोर हिस्से से अलग करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। साथ ही कालक्रम में शेख अब्दुल्ला का शुकाब कश्मीरी उपराष्ट्रीय धातु-सम्मान की रक्षा के नाम पर पाकिस्तान और अमरीका की ओर बढ़ने लगा। शेख अब्दुल्ला की राजमन्दी से न सही परन्तु उनकी जानकारी में कश्मीर में पाकिस्तान की घुमपैठ तेजी से बढ़ने लगी और नेहरू जी को शेख अब्दुल्ला को नजरबन्द करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इसके बाद पाकिस्तानी शासकों को यह कहने का मौका मिल गया कि भारत सिर्फ सैनिक शक्ति के बल पर कश्मीर पर अपना कब्जा बनाये रखना चाहता था।

1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमले की योजना इसी उद्देश्य से बनायी थी कि कश्मीर में बहुसंख्यक मुस्लिम जनसंख्या का समर्थन उनकी सेनाओं को प्राप्त होगी, परन्तु यह आशा निर्भूल निम्न हुई। यह भी ध्यान रखते लायक बात है कि जिस समय नेहरू जी का निधन हुआ, कश्मीर विवाद के निपटारे के लिए नेहरू का गोपनीय व्यक्तिगत संदेश लेकर शेख अब्दुल्ला पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ■ पास गये थे। सगता है कि नेहरू जी की मृत्यु के साथ ही पाकिस्तानी शासकों ने इस विषय में सान्तिपूर्ण समाधान की आशा छोड़ दी। तब से आज तक कश्मीर समस्या के अन्तर्राष्ट्रीयकरण से पाकिस्तानी नेता भारत की सखीय में झलने का प्रयत्न करते रहे हैं, परन्तु हकीकत यह है कि आज दोनों पक्ष युद्ध विराम के बाद पर्याप्तवधि को स्वीकार कर चुके हैं। वे अन्धरी तरह जानते हैं कि इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। एक तरह से भारत-पाक संघर्ष में कश्मीर का अब सिर्फ प्रतीकात्मक महत्व रह गया है।

शरणार्थी सम्पत्ति समस्या—विभाजन के साथ लाखों की तादाद में दोनों देशों के शरणार्थी सीमा पार गये। उनके द्वारा छोड़ी गयी सम्पत्ति का मूल्यांकन उसकी देखभाल, उनका हस्तान्तरण आदि बहिल एव विवादास्पद मूद्दे थे। केन्द्रीय निधि का प्रंटवारा और संचार के संसाधनों का समुचित वितरण औपचारिक रूप से तो इससे अलग थे परन्तु कटता के कारण अनियंत्रित रूप से इसमें जुड़ गये। जहाँ सरदार पटेल जैसे नेता कियो भी तरह की रियायतें देने के पक्ष में नहीं थे, वहीं साहिवा, जयप्रकाश और श्रीप्रकाश जैसे व्यक्ति भारत-पाक सम्बन्धों के सामाजिकरण के लिए भारत सरकार को लचोता रूप अपनाने की राय देते रहे। इस समस्या का निपटारा कालक्रम में चार-पाच साल बीतते स्वयमेव हो गया।

नदी जन विवाद—चूँकि भारत व पाकिस्तान एक ही भौगोलिक इकाई हैं, इसलिए देश के कृषि सम्बन्धी विभाजन ने प्राकृतिक संसाधनों की साझेदारी को टुंकर बना दिया। सिन्धु, सेलम, चिनाब आदि नदियाँ, जो पाकिस्तान के क्षेत्रों को सींचती हैं, भारत में ही बहकर जाती हैं। यदि भारत इन पर बाध बनाता है तो पाकिस्तान तक पहुंचने वाली उस राशि में कटौती होना अवसम्भावनी है। भारत के

अमरीका से सहायता का अनुरोध किया और अमरीका ने भारत पर पाकिस्तान के साथ कश्मीर तथा अन्य विवादों के निपटारे के लिए दबाव डाला।

पाकिस्तान में निर्वाचित भरकार (गुलाम मोहम्मद चौधरी) का सेना द्वारा तख्ता पलटने के बाद भारत-पाक सम्बन्ध और भी बटु एवं तनावपूर्ण हुए। जहाँ अपनी बगावत को न्यायसंगत बनाने के लिए अधिकारियों के लिए वैधानिकता का जामा ओढ़ना आवश्यक था और बाहरी सफट की तलाश एक अनिवार्यता थी, वहीं नेहरू जी जैसे भारतीय नेताओं के लिए ऐसे तानाशाहों के साथ सवाद की बात असम्भव नहीं, तो बेहद कठिन अवश्य थी। 1962 में चीन के हाथों भारत की हार के बाद पाकिस्तान का अहंकार निरन्तर बढ़ता गया और पाकिस्तानी नेता सोचने लगे कि नेहरू जी की मृत्यु के बाद भारत के विघटन की प्रक्रिया आरम्भ हो जायेगी। इससे वे भारत से मनचाही रियायतें-ममलोंतें प्राप्त कर सकेंगे। नेहरू जी ने अपने जीवनकाल में अनेक बार मुलहू की पहल की। परन्तु पाकिस्तान ने हर बार मुड़-बर्जन सम्वि (No War Pact) का प्रस्ताव ठुकरा दिया। 1960 में जुलिकार अली भुट्टो बिदल मंत्री बने। अपनी ध्वनित राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण उन्होंने भारत को ललकारने और उसमें टकराने की रणनीति अपनायी। उन्हें भारत के शत्रु चीन के साथ पाकिस्तान के सम्बन्ध सुधारने में अभूतपूर्व मफलता मिली। 1965 तक पाकिस्तान की दुस्माहसितता इस हद तक बढ़ गयी थी कि अयूब खान तथा भुट्टो ने सवाद नहीं, बल्कि सैनिक सघर्ष द्वारा 'दुर्बल भारत' को अपनी बात मनवाने का तेवर अपना लिया था। कच्छ के रण का विवाद इसी से उपजा और इसी कारण 1965 के युद्ध का विस्फोट हुआ।¹

1965 का युद्ध—1964 में नेहरू जी का निधन हुआ और इसके साथ भारत का आधुनिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हो गया। स्पष्टतः इसका प्रभाव भारत-पाक सम्बन्ध पर पड़ा। नेहरू जी सही मायनों में घमं निरपेक्ष व्यक्ति थे और पाकिस्तान का इस्लामी स्वरूप उन्हें ज्यादा परेशान नहीं करता था। उन्होंने आजादी के समय देश का विभाजन स्वीकार अवश्य किया, किन्तु बटवारे से कोई बटुता या अनुप उनके मन में नहीं बचे थे। लिपाकत अली आदि से उनकी मित्रता जीवन-पर्यन्त बनी रही। वह गुट निरपेक्ष अवश्य थे और पाकिस्तान के सैनिक-मगठनों में शामिल होने से विभ्र। परन्तु वह पाकिस्तान को भारत का अनिवार्य शत्रु नहीं समझते थे। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों के सामान्यीकरण की सम्भावना प्रबल रही। नेहरू जी की मृत्यु के बाद सत्ता के हस्तान्तरण का प्रश्न महत्वपूर्ण बन गया और पाकिस्तानी शासकों को यह लगा कि वे भारत की इस अनिश्चित स्थिति का लाभ उठा सकने हैं। नेहरू जी के उत्तराधिकारी जाल बहादुर शास्त्री का व्यक्तित्व भी अक्सर लोगों को इस भ्रान्ति में डालता था कि वह दुर्बल या अममजम में पड़े रहने वाले व्यक्ति हैं।

1965 का भारत-पाक सघर्ष इसी मानसिकता ने उपजाया, जिसके दो पहलू

¹ विस्तार के लिए देखें—Dinesh Chandra Jha, *Indo-Pak Relations* (Patna, 1972), G W Choudhary, *Pakistan's Relations with India* (Meerut, 1971), Russel Brians, *The Indo-Pakistan Conflict* (London, 1963), William J Burns, *India, Pakistan and the Great Powers* (New York, 1972)

दृष्टि से देखते थे। उन्हें लगता था कि ये दरिद्र लोग उनके जीवन स्तर को सिर्फ गिरा ही सकते हैं और इनकी नियति परोपजीवी बनकर रहना है। पठानों व पञ्जाबियों का संस्कार सैनिक-किसानों वाला था और वे पड़े लिखे बाबूओं, कारकुनों, और वनियों को अपने से हेय समझते थे। साथ ही, उनके मन में यह शका भी थी कि भारत से आने वाले ये मुसलमान जल्दी ही सरकार में अपनी जड़ें जमा लेंगे। एक सीमा तक ऐसा हुआ भी। भारत से पाकिस्तान आने वाले शरणार्थी अपने को पञ्जाबियों व पठानों की तुलना में सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध समझते थे और यह मानने को तैयार नहीं थे कि पाकिस्तान के निर्माण के बाद सिर्फ शरणार्थी होने के कारण वे दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का यह दुर्भाग्य रहा कि काबूदे आजम जिन्ना ज्यादा दिन तक नए राष्ट्र का दिशा निर्देश नहीं कर सके। बंगाली तथ्य पञ्जाबी राजनीतिक नेताओं में खकीर्ण स्वार्थी प्रतिस्पर्धा ने एक ऐसी रस्माकशी का रूप ले लिया जिसने दलगत राजनीति को जानबूझकर दलदल में बदल दिया।

उस समय चीत गुट आरम्भ हो चुका था। यह स्थिति अमरीका के हित में थी। गुट निरपेक्ष भारत को अपनी ओर लाने में असफल होने के बाद अमरीका का प्रयत्न यही रहा कि यह पाकिस्तान को अपना खमूरा बनाकर भारतीय उपमहाद्वीप में अपने हित साधन के लिए एक कृत्रिम शक्ति-गन्तुलन स्थापित कर सके। पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता से अमरीका का चिन्तित होना स्वाभाविक था। अनेक अमरीकी विद्वानों ने इस दौरान यह भ्रांति की कि पाकिस्तान जैसे विकासशील समाज में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने और आधुनिकीकरण का काम सेना ही बखूबी कर सकती है। अनेक पाकिस्तानी रोनाष्वधों की अपनी ओर आकर्षित करने में अमरीका सफल हुआ।

1954 में पाकिस्तान अमरीकी सैनिक संगठन 'सिएटो' का सदस्य बना। इसके साथ पाकिस्तानी सैनिक अधिकारियों की राजनीतिक सहृदयताकाशायें बढ़ी। यह बात तो स्पष्ट थी ही कि अमरीका का सन्धि-मित्र बन जाने के बाद पाकिस्तान को अमरीका में बड़े पैमाने पर सैनिक सहायता मिलेगी और परिणामस्वरूप सैनिक अधिकारियों की भ्रष्टाचार और प्रभाव में वृद्धि होगी। ऐसा सोचना गलत होगा कि अमरीका की ओर पाकिस्तान का झुकाव सिर्फ सैनिक अधिकारियों की खोनुषता के कारण हुआ। ऐसा समझा जा सकता है कि इनमें से कुछ सैनिक अधिकारी वास्तव में राष्ट्र-प्रेमी थे, जो अपने नेताओं की उठा-पटक से उब चुके थे और भारत को पाकिस्तान की अस्थिरता के लिए खतरा समझते थे। जो भी हो, पाकिस्तान के संघीकरण के भारत-पाक सम्बन्धों पर बहुत दुःख प्रभाव पड़े। पहले ही अमरीका का यह कहना था कि पाकिस्तान को सैनिक सहायता देते वक्त यह ध्यान रखी गयी कि इन हथियारों का प्रयोग भारत के खिलाफ नहीं होगा। अनेक भारतीय विद्वानों ने सटीक टिप्पणी की कि 'ऐसी किसी बन्दूक का आज तक आविष्कार नहीं हुआ है, जो सिर्फ एक ही दिशा में बार करती हो।' नेहरू जी इस बात से काफी चिन्तित थे कि पाकिस्तान चीत गुट को भारत के आगमन तक से आया और अपने सन्धि-मित्र को गुप्त रखने के लिए अमरीका ने पाकिस्तान का अन्ध पक्षपात कश्मीर से लेकर नदी जल विवाद तक होने तक किया है। भारत के लिए सबसे अरमानजनक स्थिति यह थी, जब 1962 में चीनी हमले के दौरान भारत ने

हथियारों से सज्जित पाक सेना को नाको चने चबवा दिये। भारतीय नेट विमानों में पाकिस्तानी सेवर विमानों को बुरी तरह ध्वस्त कर दिया। भारतीय सेनाएँ लाहौर शहर की परिधि पर बनी इच्छोगिल नहर तक जा पहुँची। इसी समय संयुक्त राष्ट्र सभ में पारित प्रस्तावों तथा राष्ट्रमण्डलीय (Commonwealth) मित्र राष्ट्रों के सद्प्रश्नों से युद्ध-विराम हो गया। इस सैनिक मुठभेड़ ने कई प्रचलित मिथक तोड़ डाले। सबसे पहला यह कि चीन के हाथों हार के बाद भारत इतना खोखला हो गया है कि पाकिस्तान तक उसको हरा सकता है। दूसरा यह कि चीन भारत-पाक संघर्ष में पाकिस्तान की मदद सार्यक ढंग से कर सकता है। पाकिस्तान ने इण्डोनेशिया के साथ मिलकर यह साठवाँठ भी की थी कि अण्डमान निकोबार पर कब्जा किया जा सके। यह मसूबा भी पूरा नहीं किया जा सका। इसके विपरीत रणक्षेत्र में सफलता के कारण भारत को 1962 की ग्लानि और मानहानि घोने का अवसर मिला। बाहरी आक्रमण का सामना करने के लिए सारा राष्ट्र एक हो गया और राष्ट्रीय एकीकरण का काम अपेक्षाकृत सहज हो सका। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि नहीं लगाया जा सकता कि सैनिक मुठभेड़ का अन्त भारत के पक्ष में हुआ। यथार्थ तो यह था कि दोनों पक्ष सैनिक साज-सामग्री के लिए बाहरी शक्तियों पर निर्भर थे और विशेषकर महाशक्तियों के मतैक्य के बाद सड़ते नहीं रह सकते थे। तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति ऐसी थी कि भले ही 'देतात' का आरम्भ नहीं हुआ था, परन्तु रूस व अमरीका के बीच सार्यक सवाद आरम्भ हो चुका था। भारत-पाक सम्बन्धों के विश्लेषक डा० मोहम्मद अय्यूब ने इसे भारतीय उपमहाद्वीप के सन्दर्भ में इनके हितों का मध्य नहीं, बल्कि संयोग का दौर कहा है। हितों के इस संयोग के कारण ही भारत और पाकिस्तान के बीच ताम्रकन्द समझौता सम्भव हुआ।

ताम्रकन्द समझौता—युद्ध विराम के बाद स्पाई शान्ति की तलाश ताम्रकन्द में जारी रही। आज मने ही भारत और पाकिस्तान के इतिहासकार इस सम्मेलन को आयोजित करने का श्रेय जनरल अय्यूब खा और लाल बहादुर शास्त्री की दूर-दर्शिता को देते हों, परन्तु इस बात को अनदेखा करना कठिन है कि तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के बिना इन दो बैरी देशों को परामर्श की मेज तक नहीं लाया जा सकता था। भूतपूर्व अमरीकी राष्ट्रपति जोनसन ने एक पत्रकार से बातचीत के दौरान यह टिप्पणी की थी कि भले ही ताम्रकन्द में किसी को नजर नहीं आ रहा था, किन्तु वहाँ मैं भी उपस्थित था। वह प्रकारान्तर से इसी बात पर जोर दे रहे थे कि भारत-पाक सम्बन्धों के मामलों में उनमें और सावित्त नेता में मतैक्य था।

इन सबका अन्तिमप्राय यह विलुप्त नहीं कि शास्त्री जी और अय्यूब खा पर महाशक्तियों ने दबाव डाला था कि उनकी अपनी भूमिका रचनात्मक या महत्वपूर्ण नहीं थी। परन्तु उस समय महाशक्तियों के योगदान के बिना भारत-पाक सम्बन्धों में किसी नई पहल की आशा नहीं की जा सकती थी। ताम्रकन्द समझौते (1966) की मुख्य महमति-बार्त इस प्रकार थी : दोनों देश आपसी विवाद के निपटारे के लिए युद्ध का त्याग करते हैं और भविष्य में समस्याओं के शान्तिपूर्ण समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र सभ के निदानों के प्रति सम्मान दर्शाते हुए परामर्श का अवलम्बन करेंगे। दोनों देश एक दूसरे के प्रति मैत्री भावना का का प्रदर्शन करेंगे और पारस्परिक सम्बन्धों को बिगाड़ने वाले कोई कदम नहीं उठावेंगे।

ताम्रकन्द समझौते पर हुए हस्ताक्षरों की स्वाही अभी मूखी भी नहीं थी कि

ये। एक तो यह कि नेहरू जी के बाद वाले भारत में पाकिस्तान सदस्यता या न्यायोचित आचरण की आशा नहीं कर सकता था। दूसरा यह कि वल-प्रयोग के लिए इससे अच्छा अवसर क्यों तक नहीं मिल सकता था। जिस भूमि को लेकर विवाद हुआ, वह बजर, दलदली मरुभूमि थी, जिसे कच्छ का रण कहा जाता है। उसकी कोई आर्थिक उपयोगिता नहीं थी। वर्षों के मौसम में पानी भर जाने के बाद यह नीची जमीन एक दुन्दुभ जल-राशि में बदल जाती है। परन्तु सीमान्ती प्रदेश होने के कारण इसका सामरिक महत्व है। इस लम्बे भू-भाग पर हर क्षण चौकस निगरानी नहीं रखी जा सकती थी और गैर-कानूनी अतिक्रमण, तस्करी, पड़ोस-पड़ोसी घुसपैठ के लिए इसका उपयोग बढ़ती किया जा सकता है। पाकिस्तान को इस बात का भी अहसास था कि कश्मीर या पंजाब के पारम्परिक मोर्चों पर पुस्त सामबन्दी के कारण सीमा हमला उतना सफल नहीं हो सकता, जितना कच्छ में ताकत की आजमाइश। ऐसा भी सोचा गया कि येन केन प्रकारेण इस जमीन को हथियारा जा गये तो भविष्य में राजनीतिक परामर्श के दौरान लेज-देन के वक्त इसका उपयोग किया जा सकेगा। सीमाव्यवस्था, भारतीय सीमा सुरक्षा बल न केवल सतर्क था, बल्कि सीमा रक्षा में सनर्थ भी। पाकिस्तान को कच्छ के रण में प्रत्यागित सैनिक सफलता नहीं मिल सकी और जब मामला अन्तराष्ट्रीय पंचाट के लिए सीमा गया तो इससे भी मनोनुकूल परिणाम नहीं निकले।

पाकिस्तानी नेता इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं थे। बिहार के अकाल ने केन्द्र सरकार को परेशानी में डाल रखा था। चीनी प्रयत्न से इण्डोनेशिया, पाना आदि भारत के कट्टर विरोधी बन चुके थे और सोवियत संघ में भारत में धनिष्ठ मित्र भू-द्वेष को अपदस्थ किया जा चुका था। पाकिस्तान इन लाभप्रद मनीकरणों का फायदा उठाना चाहता था। उसने भारत को अवैला करने के लिए एक उग्र राजनयिक अभियान छेड़ा जिसका प्रमुख मंच संयुक्त राष्ट्र संघ बना। भूटो ने इसके दौरान अपनी राजनयिक प्रतिभा का भरपूर प्रदर्शन किया। उनके आक्षेपों का प्रमुख मुद्दा यह था कि कश्मीर में मुसलमानों पर तरह-तरह के अमानुषिक अत्याचार किये जा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप आजाद कश्मीर के निवासियों में उत्तेजना फैल रही है। यस्तुतः इस सबका एकमात्र उद्देश्य कश्मीर में पाकिस्तानी हमले की भूमिका तैयार करना था। तत्कालीन भारतीय विदेश मन्त्री स्वर्ण सिंह ने यथा-शक्ति इन लाभप्रदों का तर्कसंगत उत्तर देने का प्रयत्न किया। परन्तु वह इस बात को नहीं समझ पाये कि पाकिस्तान राजनीतिक सवाद नहीं चाहता था। उसका लक्ष्य मुद्दोन्माद फैलाना भर था। इस बीच कुछ ऐसी घटनाएँ घटी, जिन्होंने पाकिस्तान को बहाना भी दे दिया। कश्मीर की प्रतिष्ठ हज़रत बल दरगाह से पवित्र बाल चोरी चला गया, जिससे साम्प्रदायिक हिंसा भड़क उठी। पाकिस्तानी तानाशाहों को लगा कि यदि ऐसी स्थिति में घुसपैठिये भेजे जाएँ तो कश्मीर की बहुसंख्यक मुस्लिम जनसंख्या केन्द्र सरकार के विरुद्ध बग़ावत के लिए उठ खड़ी होगी। उन्होंने इस शततफहमी के आधार पर ही भारत पर आक्रमण कर दिया।

पाकिस्तान की सभी सामरिक बग़ावतें गलत साबित हुईं। संकट की इन पड़ी में शास्त्री जी ने अद्भुत जीवद और साहस का परिचय दिया। 'जय बवान, जय किसान' का नारा चमत्कारी ढंग से देश के मनोबल को बढ़ाने वाला मिड हुआ और भारतीय सेना के तीनों अर्थों में अपने से कहीं अधिक आधुनिक

हो चुकी थी एवं 1967 के पश्चिम एशियाई संकट के निवारण के बाद विश्व चीन में 'महान सांस्कृतिक शान्ति' की उषल-गुल्ल का भी आदी हो चुका था। अन्य शब्दों में, भारत और पाकिस्तान के बीच सैनिक मुठभेड़ की जमीन फिर से तैयार हो चुकी थी। दोनों देशों में तादात्म्य भावना के क्षय के अनेक कारण थे। एक ओर भारत में श्रीमती इन्दिरा गांधी अपने राजनय को शास्त्री जी के योगदान तक ही सीमित नहीं रखना चाहती थी तो दूसरी ओर अय्यूब खान के उत्तराधिकारी याहिया खान अपने भ्रष्टाचार को सिर्फ भारत के प्रति दुराचरण से ही छुपा सकते थे। याहिया खान का स्थान ग्रहण करने के लिए उत्तुंग उनके विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो उनको पक्ष-प्रष्ट करने को तत्पर रहे। पूर्वी बंगाल के शटनाक्रम ने उनकी महत्वा-कांक्षाओं को पूरा करने के लिए परिस्थितियाँ तैयार की।

जैसाकि पहले कहा जा चुका है कि भारत की आजादी के वक्त देश के विभाजन से जिस पाकिस्तान का निर्माण हुआ, वह एक कृत्रिम इकाई था और देश के दो हिस्सों (पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान) की भौगोलिक दूरी के असावा मापा, संस्कृति और आर्थिक विकास की असमानता भी एक दूसरे से अलग करते थे। यहाँ अधिक विस्तार में जाने का अवकाश नहीं, परन्तु यह टिप्पणी जरूरी है कि 1969-70 तक पश्चिमी पाकिस्तान की पंजाबी सैनिक शानाशाही पूर्वी बंगाल को एक आन्तरिक उपनिवेश के रूप में बदल चुकी थी। बंगाली बहुसंख्यक थे और बौद्धिक दृष्टि से समृद्ध, परन्तु देश की खूबहाली में उनका कोई हिस्सा नहीं था। वे दूसरे दर्जे के नागरिक समझे जाते थे। पूर्वी बंगाल की आवासीय लीग पार्टी प्रादेशिक स्वायत्तता और ममानता की माँग जोरदार रूप से शर्षों में उठाती आ रही थी। मार्च, 1970 के आम चुनाव में आवासीय लीग को बहुमत मिला। इस चुनाव में यह बात मनी भाँति स्पष्ट हो गयी कि बंगाली मतदाता अब पंजाबी अधिपत्य को ज्यादा दिनों तक धुपचाप सहन करने वाले नहीं। एक ओर बात ध्यान में रखने की है। पूर्वी बंगाल में प्रांतीय सरकार के शासकों व जनता के मन में भारत की छवि धनु के रूप में बैसी नहीं थी, जैसी पंजाबी पाकिस्तानियों के मन में।

मार्च, 1970 के आम चुनाव के बाद पाकिस्तान के सैनिक शासकों ने बंगालियों की न्यायोचित मांगों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रुख दर्शाने के बजाय अमानुषिक दमन का मार्ग अपनाया। कुछ ही महीने में इस वशनाशक नरसंहार का रूप ले लिया। एम्पोनी मेसकरनास जैसे खोजी पत्रकाराने 'रफ आफ बंगला देश' जैसी अपनी पुस्तक में जनरल टिक्का खान के बाल कारनामों को दुनिया भर के सामने उद्घाटित किया। हत्या, बलात्कार, आगजनी आदि से घबर कर बहुत बड़ी संख्या में बंगाली मुसलमान घरणार्थी मरहद पार कर भारत में घुसने लगे। जुलाई-अगस्त, 1971 तक इनकी संख्या दस-बारह लाख से ऊपर पहुँच गई। भारत सरकार ने मानवीय कारणों से इनको बलपूर्वक वापस भेजने का कोई प्रयत्न नहीं किया। परन्तु शीघ्र ही यह बात प्रकट हो गयी कि सिर्फ इन घरणाधियों को राहत पहुँचाने भर समस्या का समाधान नहीं हो सकता। श्रीमती इन्दिरा गांधी को शीघ्र ही यह बात स्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ा कि घरणाधियों के मैलाब का रख भारत की ओर मोड़कर पाकिस्तान परीक्ष रूप से भारत पर अत्यधिक परन्तु प्रभावशाली आक्रमण कर रहा था। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने पहले यह प्रयत्न किया कि अन्तराष्ट्रीय जनमत का दबाव इसकाकर पाकिस्तान को अपनी

दिन का दौरा पड़ने से यास्वी जी की मृत्यु हो गयी। इस बलिदान का एक प्रमाण यह भी पड़ा की ताशकन्द भावना (सदाशयता और मैत्री की जलक) फुट हुई। जनरल अय्यूब खा के लिए यह क्षम आसान हुआ कि वह दिवंगत भारतीय नेता के प्रति सम्मान के नाम पर बिना घुटने टेके रियायतें देने को तैयार हो सकें और अपने देशवासियों के सामने यह प्रमाणित कर सकें कि पाकिस्तान पराजित नहीं हुआ या कि किसी महाशक्ति ने उसकी बांह नहीं मरोड़ी। एक बार अय्यूब खा द्वारा समझौते के लिए तैयार हो जाने पर भारतीय पक्ष भी यह कह सकता था कि पीछे हटने वाले सारे कदम उसी ने नहीं उठाये। ताशकन्द समझौते की सबसे बड़ी असलियत यही थी कि किसी भी ठोस व्यवस्था के अभाव के बावजूद उसने दोनों पक्षों को अपना राष्ट्रीय गौरव बचाये रखने की सुविधा और नया सार्थक सवाद शुरू करने का मौका दिया। ताशकन्द समझौते की कृपा से ही भारत-पाक सम्बन्ध पूर्वी बंगाल में ज्वालामुखी के विस्फोट तक लगभग पाँच-छह वर्षों तक अपेक्षाकृत तनावरहित रह सका।¹

ताशकन्द समझौते के साथ जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है। 1965 के बाद कम से कम कुछ समय के लिए सोवियत संघ ने भारतीय उपमहाद्वीप के मामलों में इन दोनों देशों—भारत और पाकिस्तान के बीच तटस्थता का रुख अपना लिया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण वह घटना है जब सोवियत संघ ने 1966 में पहली बार पाकिस्तान को भौतिक सामग्री बेची।

बंगला देश का उदय—ऐसा नहीं था कि 1966 से 1971 तक भारत-पाक सम्बन्ध ताशकन्द समझौते के कारण ही निरापद और तनावहीन रहे। टकराव न होने का प्रमुख कारण यह भी था कि दोनों देशों का नेतृत्व आन्तरिक समस्याओं से झुमने में इतना व्यस्त था कि वैदेशिक मामलों की पृष्ठभूमि में धकेलना लाजिमी हो गया। भारत में श्रीमती इन्दिरा गांधी 'मिन्टीकेट' का मामला करती हुई अपना बर्चस्व स्थापित करने की चेष्टा कर रही थी। उनके क्रिया-कलापों की परिणति 1969 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन और व्यापक नीति-परिवर्तनों में हुई। 1967-68 में राज्यों में कांग्रेस-विरोध की जोरदार लहर उठी और देश के बहुत बड़े हिस्से में कांग्रेसी शासन समाप्त हो गया। इससे भारतीय संघ व्यवस्था पर नये दबाव पड़े और इसी दौरान उग्र दानपणियों की अराजक हिंसा का विस्फोट प० बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले के नक्सलबाड़ी नामक स्थान में हुआ। इसी तरह अय्यूब खा के 'युनिफाई लोकतन्त्र' के प्रति पाकिस्तानियों का मोहभंग हो चुका था और उनके विरुद्ध छात्र आक्रोश के विस्फोट के बाद उनकी सरकार का पतन हो गया। उन समय भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे। 1969 में सोवियत संघ और चीन के बीच उमूरी नदी के तट पर टकराव हुआ। 1968 में बेनोस्तोवाकिया में भौतिक हस्तक्षेप के बाद सोवियत संघ को अन्तर्राष्ट्रीय मण्डली में भारत जैसे मित्र की जरूरत फिर महसूस होने लगी। विपतनाम युद्ध में बड़ी तेजी के साथ बृट निरपेक्ष भारत का महत्व फिर से रेखांकित हुआ।

1970 तक पाकिस्तान और भारत की आन्तरिक राजनीतिक स्थिति स्थिर

¹ पाकिस्तानी पत्रिका के इस बटनारथ को समझने के लिए देखें—General Ayub Khan, *Friends, Not Masters* (London, 1967)

नहीं थी।¹

शिमला सम्मेलन—युद्ध के बाद जुलिकार अनी भुट्टो यादिया मान के उत्तराधिकारी के रूप में थीमती इन्दिरा गांधी म¹ परामर्श के लिए शिमला पहुँचे तो वह एक पराजित राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और थीमती इन्दिरा गांधी निरिक्त रूप में विजिता थी। शिमला सम्मेलन का विशेषण-सूचकन करत समय यह बात कदापि नहीं भुनायी जानी चाहिए। इन बात का श्रेय थीमती इन्दिरा गांधी को दिया जाना चाहिए कि उन्होंने शिमला शिखर सम्मेलन का उपयोग जीत के लाना के बेटवार का पाकिस्तान का दण्डित करने के लिए नहीं, बल्कि भारत-पाक सम्बन्धों के सामान्यीकरण के लिए किया। इसी तरह यह बात भी स्वीकार करनी पड़ेगी कि पराजित हान के बाद भी भुट्टो अनेक राजनयिक कोशल से बहुत कुछ हासिल कर सके। तामकन्द सम्मेलन का ही तरह शिमला सम्मेलन भी भारत-पाक सम्बन्धों की राह में मोम का एक महत्वपूर्ण पत्थर है।

शिमला सम्मेलन में विवाद के तीन प्रमुख विषय थे (i) भारत द्वारा पाकिस्तान की दिशे जमीन पर कब्जा किया गया था, उसे वापसी करना, (ii) भारत-बंगला देश मयुक्त बंगला द्वारा बन्दी बनाये गये मंत्रियों की रिहाई, तथा (iii) पाकिस्तान द्वारा नवीदित बंगला देश का मान्यता। इनके साथ ही दो और पहलु भी जुड़े हुए थे—(i) युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाया जाना और (ii) मुलाकात का प्रश्न। कई बार यह बात कही जाती है कि थीमती इन्दिरा गांधी शिमला में जुलिकार अनी भुट्टो द्वारा ठम नी गयी क्योंकि विजिता हान के बाद भी उन्हें हर मामले में भुट्टो की मांग स्वीकार करनी पड़ी। परन्तु शिमला सम्मेलन के साथ यह बात अनिवार्य जुड़ी थी कि बंगला देश का मान्यता विमान और उपमहाद्वीप में सम्बन्धों का सामाग्य करना किसी भी अन्य प्रश्न से अधिक महत्वपूर्ण था। भुट्टो का राजनयिक कोशल इस बात में अत्यन्त-निहित था कि उन्होंने कम से कम उन बल्ल प्रत्यर्पण्य जनमत को यह सम्मेलन में सफलता प्राप्त कर ली कि वह पाकिस्तान के विपटन और भारत पर हमल के लिए विम्वरदार नहीं समझे जा सकन। वह यह बात नवीनानि सम्मेलन से कि मात्र तन्त्र समय तक दो लाख पाकिस्तानी युद्धबन्धियों का भार नहीं हो सकता और इनकी रिहाई के लिए अन्तराष्ट्रीय दबाव बढ़ना शुरू हो जायगा। भुट्टो ने यह ठक नी तारदार दबा में पना किया कि यदि शिमला सम्मेलन में रिहाई पान में वह सफल नहीं हुए तो उनकी सरकार गिर जायगी और पाकिस्तान में जनतन्त्र की पुनर्स्थापना की अन्तिम आशा नष्ट हो जायगी। थीमती इन्दिरा गांधी के पाम एक ही अस्त्र था—युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाया जाना। उसी को लेकर मोदबाजी हो सकी। जन ध्वनित्व के तान का अहसान थीमती इन्दिरा गांधी को था और भुट्टो का भी। इन दावा नताजा के विशेषज्ञ-मताहकार योग्य एवं प्रतिनागानी थे। तब भी यदि शिमला सम्मेलन का शिथानित करन-करन एक वर्ष नब गया तो सम्मेलन जा सकता है कि पचीसवियाँ किर्ती बटन रही होगी।

1972 के अन्त में दिन्नी सम्मेलन के बाद शिमला सम्मेलन में तय कदम मोदवाचित रूप में उद्घाटन हो सक। तामकन्द की तरह दोनो देशों में शिमला

¹ इस विद्वित में विष्णु विवरण के लिए रवे—Mohammad Ayub, India, Pakistan and Bangla Desh, (Delhi, 1975)

नीतियों में परिवर्तन करने पर विवश किया जा सके। इसके लिए औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार के राजनय का अवसम्बन्ध सिद्ध किया गया। इस अभियान में अपनी सरकार के जय प्रकाश नारायण जैसे प्रखर आलोचकों का समर्थन पाने में श्रीमती इन्दिरा गांधी सफल रही। दुर्भाग्यवश पाकिस्तान पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कई विद्वानों का मानना है कि भुट्टो ने जान-बूझकर भूतंता के साथ ऐसा नहीं होने दिया, क्योंकि वह जानते थे कि सेना की पराजय के बिना पाकिस्तान में सैनिक तानाशाही का अन्त नहीं हो सकता। वह यही भी अच्छी तरह समझते थे कि नागरिक सरकार बनने पर भी वह अविभाजित पाकिस्तान के एकछत्र शासक नहीं बन सकते। शेख मुजीब जैसे लोकप्रिय बंगाली नेता का दावा प्रमाणमन्त्री पद के लिए उनकी तुलना में कहीं अधिक भारी बैठता था।

इस बीच भारत में सरण पाने वाले बंगालियों में कुछ विशोध्यों ने हथियार जुटाकर, पूर्वी बंगाल की सरहद फिर से पारकर वहाँ छापाभार लगाई शुरू कर दी। पूर्वी बंगाल की जमीन इस तरह के रण के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है और अपनी इच्छा के विरुद्ध वहाँ सैन्य किये गये भ्रष्ट, अवैध, अनुभवहीन किशोर सैनिक रणरुद्ध इनका सामना करने की स्थिति में नहीं थे। इस प्रकार पूर्वी बंगाल के नगरों में सिविल लाफरमानी ओर फैल रही थी और व्यापक जन असहयोग के कारण प्रशासन ठप्प था। पाकिस्तान सरकार का झुक था कि बंगाली छापामारों की मुक्ति चाहिनी सेना को भारत सरकार प्रसिद्ध कर रही है और शस्त्रों से सुनस्जित भी। इससे भारत-पाक सम्बन्धों में तनाव बहुत तेजी से बढ़ा। अक्टूबर 1971 तक यह बात साफ हो चुकी थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी वक्त लड़ाई छिड़ सकती है।

इस क्षण श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अद्भुत दूरदर्शिता और राजनयिक कौशल का परिचय दिया। उनके विशेष दूत दुर्गा प्रसाद धर ने सोवियत संघ की अनेक यात्राएँ कीं और नाटकीय ढंग से यह घोषणा की गयी कि भारत ने सोवियत संघ के साथ मैत्री व सहयोग सन्धि पर हस्ताक्षर कर लिये हैं। कई विद्वानों ने यह आक्षेप लगाया कि इस सन्धि से भारत ने अपनी गुट निर्भरता की नीति त्याग दी है। बंगला देश के मुक्ति संग्राम के सिलसिले में इस सन्धि का विशेष मामरिक महत्व है। इस सन्धि पर हस्ताक्षर के बाद पाकिस्तानी सैनिक हमले का सामना भारत बेहिचक कर सका।

5 दिसम्बर, 1971 को पाकिस्तानी विमानों ने भारतीय ठिकानों पर हमले बोले और गुट की घोषणा कर दी। इस गुट में स्थिति 1965 से बहुत फर्क थी। भारतीय सेना के तीनों जग एक प्रभावशाली इकाई के रूप में काम में लाये गये और 13 दिनों में ही ढाका से पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ दिया गया। इतना समय भी इसलिए लगा कि भारत-बंगला देश समुक्त कमान जन-घन की कम से कम हानि चाहती थी। गुट के दौरान चीन ने भारत को डराने-धमकाने का प्रयत्न किया। अमरीका ने भी अपने युद्धपोत 'एण्टरप्राइज' को बंगाल की खाड़ी में भेजकर भारत के नयादांहन (blackmail) की कोशिश की। परन्तु श्रीमती इन्दिरा गांधी के दृढ़ संकल्प, साहस और नेतृत्व के सामने ये सब कुटिल प्रयत्न निष्फल हो गये। लगभग दो लाख पाकिस्तानी सैनिक युद्धबन्दी बना लिये गये और पाकिस्तान के बड़े भू-भाग पर भारतीय सेना का कब्जा हो गया। इस बार स्थिति 1965 जैसी

घटिया, साधारण और बिश्वासघाती थे। इन्हीं दिनों अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम ने भी भारत-पाक सम्बन्धों में तनाव पैदा किया। दिसम्बर, 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत सैनिक हस्तक्षेप के बाद नए शीत युद्ध का सूत्रपात हुआ और पुराने शीत युद्ध की तरह पाकिस्तान एक बार फिर अमरीकी शतरंजी बिसात का महत्वपूर्ण मोहरा बन गया। इसके अलावा ईरान में मोहम्मद रजा पहलवी के पतन के बाद तथा खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामी कट्टरपंथी ज्वार ने अन्य अमरीकी गणनाओं को भी गड़गड़ कर दिया। खाड़ी के इलाके में तुरत तैनाती दस्ते (Rapid Deployment Force) की परियोजना में भी अमरीका द्वारा पाकिस्तान का महत्वपूर्ण योगदान तय किया गया। इसी विश्लेषण के आधार पर अमरीका में वाटर गेट प्रणालि ने जनरल जिया उल हक को अरबों डॉलर की सैनिक सहायता देकर प्राणरक्षक समर्थन किया। इसका कुप्रभाव भारत-पाक सम्बन्धों पर पड़ना स्वभाविक था। एक बार अपनी स्थिति दृढ़ करने के बाद जनरल जिया ने नए सिरे से (कभी गरम, कभी गरम अन्दाज में) भारत को दुविधा में रखने वाले ढंग से उसके साथ पाकिस्तान का सम्बन्ध संचालन आरम्भ किया।

परमाणु बम—जनरल जिया के सासन काल में भारत-पाक सम्बन्धों में जिस परमाणु कार्यक्रम को लेकर सबसे अधिक तनाव रहा, उसकी शुरुआत जिया ने नहीं, बल्कि भुट्टो ने की थी। यह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में दृष्टि रखने वाले अध्येताओं के लिए महत्वपूर्ण विषय है, इसीलिए इस पर विस्तृत टिप्पणी की जा रही है। यहाँ सिर्फ़ उन बातों को रेखांकित किया गया है, जिनकी भारत-पाक सम्बन्धों के सम्बन्ध में अनदेखी नहीं की जा सकती। यदि पाकिस्तान परमाणु अस्त्र बना लेता है तो वह भारत की तुलना में कमजोर होने की हीन भावना में छुटकारा पा लेगा। बल्कि यह भी कहा जा सकता है कि इसके बाद पाकिस्तानी धातुक परमाणु म्यादोहन (Nuclear Blackmail) की दुस्ताहसिकता तक उतर सकते हैं। वस्तुतः पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का जितना बुरा असर भारत-पाक सम्बन्धों पर पड़ा है, उससे कहीं अधिक भारत-अमरीका सम्बन्धों पर। यद्यपि भी यही है कि पाकिस्तान का परमाणु सामर्थ्य से सैत करने का पड़्याग्र दिना अमरीकी महायुद्ध के पूरा नहीं हो सकता था। परमाणु अप्रसार (Nuclear non-proliferation) के लिए प्रतिबद्ध अमरीका सिर्फ़ इस मामले में दोहरे मानदण्ड दर्शाता रहा है तो इसीलिए कि अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप के बाद पाकिस्तान की सामरिक उपयोगिता बढ़ी।

पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का एक और पहलू उल्लेखनीय है। भुट्टो ने अपने जीवन काल में ही पाकिस्तान की एटम बम की तलाश को इस्लामी माईचार् से जोड़ दिया था और पाकिस्तानी बम को इस्लामी बम की सज़ा दी गई। पाकिस्तान का पश्चिम एशियोग्मुख होना इस कारण सहज हुआ है।

भारत के साथ युद्धवर्जन सन्धि का प्रस्ताव इसी प्रकार से जुड़ा हुआ है। जनरल जिया का ऐसा सोचना था कि यदि भारत को इस विषय में आश्वस्त किया जा सके कि भारत के प्रति पाकिस्तान का रुख आश्रमक नहीं है तो भारतीय नेता-राजनयिक उसके परमाणु कार्यक्रमों को शान्तिपूर्ण मान लेंगे और इसके अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण-निरीक्षण के लिए कोशिश छोड़ देंगे। इसके अतिरिक्त युद्धवर्जन सन्धि के प्रस्ताव का एक प्रचार वातावरण भी है। जब भारत ने बाव में इसे अस्वीकार

समझौते को लेकर चढ़े पैमाने पर नई आशा जगी थी। यदि इसके प्रत्याशित परिणाम नहीं निकले तो यह बात पृथ्वी जानी चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं हुआ? जहाँ तक भारत का प्रश्न है, श्रीमती गांधी के इर्द-बिर्द बंगला देश मुक्ति अभियान से जन्मा प्रणामण्डल ज्यादा दिन बचा नहीं रह सका। 1973 तक गुजरात और बिहार में उनके विरुद्ध व्यापक युवा जन आन्दोलन आरम्भ हो चुका था। इसका स्वरूप सिविल नाफरमानी संपर्प बाना बन चुका था। श्रीमती गांधी को अतत. इस चुनौती का सामना करने के लिए अपना जनतान्त्रिक मुखौटा उतार फेंकना पड़ा और जून 1975 में आपात काल की घोषणा करनी पड़ी। इस प्रकार शिमता समझौते में पाकिस्तान के साथ भारत के सम्बन्ध सुधारने के लिए व्यापार, वाणिज्य आदि में साधारण वृद्धि (Deliberate Increase) को जो प्रस्तावना की गयी थी, उसका क्रियान्वयन लगभग असम्भव बन गया। दूसरी ओर भुट्टो का पाकिस्तान, निक्सन के अफरोका को माओ के चीन के करीब लाने के काम में मध्यस्थ बन चुका था और भारत के साथ सम्बन्ध सुधारने के लिए प्रेरणा दुर्बल पड़ने लगी थी। इतना ही नहीं, क्षणिक संकट निवारण के बाद भुट्टो को ऐसा लगने लगा था कि पाकिस्तान का मध्यम भारत के साथ उस तरह नहीं जुड़ा है, जिस तरह पश्चिम एशिया के देशों के साथ। 1975 के मध्य तक बंगला देश को बहुसंख्यक जनता का खेल मुजीब के साथ मोहमग हो चुका था। एक दुस्वप्न की तरह 15 अगस्त, 1975 को बग बन्धु मुजीब की मपरिवार निर्बन्ध हत्या कर दी गयी और बंगला देश में पड़ी की मुद्रयाँ बलपूर्वक पीछे खिसका दी गयीं। ऐसी परिस्थिति में शिमता भावना का क्षय स्वाभाविक था।¹

भारत में आपात काल की घोषणा के बाद पाकिस्तान को यह कहने का अवसर मिल गया कि अब भारत इस बात का दम्भ नहीं भर सकता कि उसका जनतन्त्र पाकिस्तान की तानाशाही से श्रेष्ठ है। भुट्टो अवसर अपने जनतन्त्र की तुलना भारत के अधिनायकत्व से करते थे। संयोग कुछ ऐसा हुआ कि श्रीमती गांधी और भुट्टो 1977 में लगभग एक साथ अर्पवत्स्य हुए और यह सारी दुस्माहसिकता बेमानी सिद्ध हुई।

मार्च, 1977 में भारत में जनतन्त्र की पुर्नस्थापना और जनता सरकार के गठन के साथ पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्ध सुधारने की बात ने जोर पकड़ा। तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यह प्रवर्तित करने को उत्सुक थे कि हिन्दू राष्ट्रवादी हीन के बावजूद उन्हें पाकिस्तान से कोई व्यक्तिगत वैर नहीं है। तथापि, तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई किसी भी दूसरे देश के आन्तरिक घटनाक्रम में दाव प्रतिपादित तटस्थ रहने के अपने आग्रह के कारण वाजपेयी पर हावी रहे।

इन सब बातों का भारत-पाक सम्बन्धों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। चूंकि वाजपेयी समझौते के लिए तालमिट थे, इसलिए पाकिस्तान का अहंकार पुष्ट हुआ। 1980 में वापस प्रधानमन्त्री पद प्राप्त करने के बाद भुट्टो की पक्षधर समझें जाने के कारण श्रीमती गांधी जनरल जिन्ना की नजरो में -संदग्धि बनी रही। जहाँ तक श्रीमती गांधी का प्रश्न है, उनकी दृष्टि में जनरल जिन्ना, भुट्टो की तुलना में बड़ी

¹ देखें—Z. A. Bhutto *Myth of Independence*, (London, 1988) और Ministry of External Affairs, *Bangla Desh: Documents*, (Delhi, 1971)।

परन्तु इनको सीमा पर अबाध-बेरोकटोक भेजा या ले जाया नहीं जा सकता। पाक सरकार बारम्बार यह आरोप भी लगाती रही है कि भारत अपने दूरदर्शन प्रसारण द्वारा 'सांस्कृतिक साम्राज्यवाद' फैला रहा है और पाक जनता में असन्तोष फैलाने के लिए प्रयत्नशील है। निश्चय ही ऐसी स्थिति में सांस्कृतिक आदान-प्रदान साधक नहीं हो सकता।

ज्ञानकर 1983 के बाद से पंजाब में साहित्यानी गतिविधियों के सन्दर्भ में पाकिस्तान की भूमिका चिन्ताजनक रही है। अब तक यह बात निर्विवाद रूप से प्रमाणित हो चुकी है कि पाकिस्तान में भारत के पद्यभ्रष्ट सिख आतंकवादियों को बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण दिया जाता रहा है। इस बात के कोई संकेत नहीं कि तमाम आशवासनों के बावजूद भविष्य में इस स्थिति में कुछ सुधार हो सकेगा। असामाजिक तत्वों के द्वारा तस्करी और मादक द्रव्यों का व्यापार इसी आतंकवाद के साथ अनिवार्यतः जुड़े हैं।

अक्टूबर, 1984 में श्रीमती गांधी की हत्या और पंजाब में आतंकवादी हिंसा के उफान के बाद भारत के भाष टकराने की पाकिस्तान की दुस्साहसिकता और भी बढ़ गयी। सिमरलीन मणियर को लेकर जो सबूत पैदा हुआ, वह इसके बिना असम्भव था। इस दुर्गम बर्फीले प्रदेश में विदेशी टोलियों को पर्वतारोहण और अन्वेषण की अनुमति भारत को भड़काने-उकसाने और उसका मनोबल तोड़ने के लिए दी गयी थी। इसी तरह पाकिस्तान द्वारा अधिकृत कश्मीर में चीन को ऐतिहासिक रेघमी राजमार्ग के पुनर्निर्माण की अनुमति देना इसी उद्देश्य से प्रेरित था।

वास्तव में, भारत-पाक सम्बन्ध तब तक तनावरहित या बमनस्य से भुक्त नहीं हो सकते, जब तक इस उपमहाद्वीप में बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप समाप्त नहीं होता। काटेंट हो या रीमन या फिर जाजें बुद्ध पाकिस्तान को मिलन वाली अरबा डालर की विदेशी सहायता में जब तक कटौती नहीं होती, तब तक पाकिस्तान के मैनिफेस्त तानाशाही या दासको को अनुशासित करने का प्रयत्न अमफल रहगा। जब तक पाकिस्तान का यह लगता रहगा कि उसका स्वर्णिम भविष्य अमरीका के माथ जुड़ा हुआ है, तब तक, बुलंदीप नैम्बर क शब्दों में, 'भारत दूरस्थ पड़ोसी' (Distant Neighbour) ही बना रहगा। जब दजेम (SAARC) का गठन किया गया, तब यह आशा जकड़ जगी थी कि पाकिस्तान के द्वेष को भारत अन्य पड़ोसियों में सद्भाव से निरस्त कर सकेगा। किन्तु दुर्भाग्यवश थीलना की विस्फोटक स्थिति ने घटनाक्रम को अप्रत्याशित विपरीत दिशा में मुपासित किया।

अहाँ तक भारत-पाक सम्बन्धों क बार में सम्भावनाओं का प्रश्न है, वे बहुत आशाजनक नहीं। जहाँ तक समस्याएँ हैं, वे न कबल बची हैं, बल्कि उनकी सूची बढ़ती ही जा रही है। पाकिस्तान कश्मीर का 'विवाद' अपनी दृष्टानुसार अवसर-वादी ढंग में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान-सम्मेलनों में उठाता रहता है। पाकिस्तानी सहायता न केवल पंजाब में सक्रिय आतंकवादियों को बल्कि भारत के अन्य भागों में भी विघटनकारी साम्प्रदायिक तत्वों को निरन्तर मिलती रहती है। पाकिस्तान भारत को राजनयिक दृष्टि से संकोच में डालने के लिए बार-बार सम्पूर्ण दक्षिण एशिया को 'परमाणु हथियार-मुक्त क्षेत्र' (Nuclear Weapon Free Zone) घोषित करने की माँग उठाता रहता है। नेपाल, बंगला देश, और श्रीलंका को भारत के प्रति शकानु

किया तो पाकिस्तान के लिए यह कहना सम्भव हुआ कि भारत उसके साथ सुलह या सम्बन्धों में सामन्यीकरण के लिए तैयार नहीं। वास्तव में इस दलील में कोई दम नहीं है। भारतीय पक्ष यह बात बहुत तर्कवन्त ढंग से दोहराता रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी विशेष मुद्देबर्जन मन्त्रि को कोई आवश्यकता नहीं। ज़िम्मा समझोते पर हस्ताक्षर करने के साथ दोनों पक्ष पहले ही विवादों के निराकरण के लिए मुड़ का बहिष्कार कर चुके हैं। परन्तु यह बात भी याद दिलायी जाती रही है कि जब कभी अतीत में नेहरू जी ने मुद्देबर्जन मन्त्रि का प्रस्ताव किया था, तब पाकिस्तान ने इसे गैर-अस्वीकृत माना था। जहाँ तक परमाणु कार्यक्रम का सम्बन्ध है, उसके सन्दर्भ में मुद्देबर्जन मन्त्रि निरर्थक है। इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि प्रचार के रणक्षेत्र में निरन्तर हो इस प्रस्ताव का पाकिस्तानी राजनयिकों ने भरपूर लाभ उठाया। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अनुनयनीयता और कुछ भारतीय पत्रकारों की ऐसे-बरे पाकिस्तानी प्रतिबद्धता ने इस काम को आसान बनाया।

आर्थिक सम्बन्ध—जब मुद्देबर्जन मन्त्रि की बात चल रही थी, तभी इस बात पर भी जोर दिया गया कि भारत व पाकिस्तान के बीच व्यापार और वाणिज्य सम्बन्धों का विस्तार क्यों नहीं होता? क्यों पाकिस्तान अपनी उद्योग का सीमेंट और लोहा कोरिया जैसे सुदूर देशों से आयात करता है? क्यों भारत कपास आदि क्षेत्र में पाकिस्तान को मदद करता है? बुनियादी तर्क यह है कि यदि कालान्तर में भारत और पाकिस्तान के बीच आर्थिक हितों और विकास कार्यक्रमों का सामंजस्य बिठाया जा सके तो राजनीतिक मामलों में भी टकराव-संमत्त कम हो सकेगा। परन्तु पिछला अनुभव नहीं बतलाता है कि यह कुछ वैसी ही पहली है कि भुर्गो या मछड़े में से पहले किसका जन्म हुआ। जब तक राजनीतिक सम्बन्धों में कम से कम थोड़ा सुधार नहीं होता, तब तक व्यापारी-उद्यमी इन क्षेत्र में जोखिम नहीं उठावेंगे। इनका एक सदाहरण उस सल्ली से पता चलता है, जिनके आधार पर दोनों देश एक-दूसरे को 'बीबा' देते हैं। इनके भतिरिक्त भारत कम से कम आरम्भ में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रबन्ध राज्य व्यापार निगम जैसे निगमों के माध्यम से करना चाहता है और पाकिस्तान निजी क्षेत्र के लोगों के साथ। इस बात की भी उम्मीद नहीं की जा सकती कि नवें ही 1947 में दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएँ पूरक नहीं हो, किन्तु आज ऐसा नहीं है। भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था का मूल संस्कार समाजवादी रहा तो पाकिस्तान का पूँजीवादी मुक्त व्यापार बाधा। पिछले साढ़े बार दशकों में पाकिस्तान ने आत्मनिर्भर बनने का मोह छोड़कर बड़े पैमाने पर अमेरिकी सहायता का आश्रय लिया है और पाकिस्तान का उपभोक्ता शक्ति का मूलतः परदेसीवो है। यह आवश्यक नहीं कि भारत के साथ आर्थिक सहकार पाकिस्तान में भी राष्ट्र हिज साथ-समझ आये। इसी कारण इस क्षेत्र में प्रगति नग्न रही है।

सांस्कृतिक सम्बन्ध—दूसरी दोर में सांस्कृतिक अदान-प्रदान को सरकारी तौर पर बढ़ावा दिया गया। क्रिकेट और हॉकी दोनों के अलावा नेहरो हमन, गुलान अली, रतना, मलिका पुष्पाज, जैसे पाकिस्तानी सित्रारे बारम्बार भारत आये। परन्तु इस सितसित में भी पाकिस्तानी आचरण आवश्यकता से अधिक बुरा प्रभावित हुआ। भारतीय कलाकारों व सित्रायों को पाकिस्तान बुलाने का काम अधूरा हो रहा। भारत में प्रकाशित होने वाली पत्र-पत्रिकाओं की पाकिस्तान में बड़ी सपट है,

बड़ी सख्या मे अफगान शरणार्थियो ने भी पाकिस्तान की सामाजिक व्यवस्था पर दबाव डाला और 1960 व 1970 वाले दशक मे अमरीकी आर्थिक सहायता के कारण जो प्रगति आरम्भ हुई थी, उसकी दर बरकरार नहीं रखी जा सकी। देहाती और पाहरी इलाको के बीच भेदभाव-विषमता बढ़ी है और अनियोजित नगरीकरण ने भी संगठित अपराध को बढ़ावा दिया है।

पाकिस्तानी जीवन मे एक कटु यथार्थ व्यापक भ्रष्टाचार है। जनरल जिया-उल-हक के शासन काल मे दबी जुबान से ही सेना की आलोचना होती रही। इसी तरह के आरोप बेनजीर के पति जरदारी और उनके श्वसुर पर लगाये गये। भ्रष्टाचार हो या मानवाधिकार हनन, साम्प्रदायिक हिंसा हो या भौतिक विघटन, पाकिस्तान की तुलना हर बार भारत के साथ की जाती है। ऐसी स्थिति मे यह पाकिस्तान की मजबूरी बन जाती है कि वह भारत के साथ अपने सम्बन्धो



विवादग्रस्त कश्मीर

और द्वेषी बनाने में पाकिस्तान की सफलता मिली है। पाक-अमरीकी-चीनी गठजोड़ आज भारतीय राजनय का सबसे बड़ा सरदर्द है। आजादी और विभाजन के बाद 45 साल बीत गये हैं, फिर भी भारत-पाक सम्बन्धों में सामान्यीकरण की अपेक्षा 'संकट निवारण' (Crisis Management) और मैत्री की अपेक्षा 'अनुता के निर्वाह' (Conduct of Enmity) की प्राथमिकता बनी हुई है।

भारत पाक सम्बन्धों में नये तनाव-विन्दु (New Tensions in Indo-Pak Relations)

दिसम्बर, 1988 में वेनजोर भुट्टो के प्रधानमंत्री बनने पर कुछ समय के लिए यह आशा जगी थी कि इन दो देशों के सम्बन्धों में सुधार होगा और फिर भारत में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के सत्तानशीन (दिसम्बर 1989) होने के साथ यह सोचा जाने लगा था कि राजीव गांधी की तरह अपने अहंकार की कोई समस्या नए प्रधानमंत्री विद्वनाथ प्रताप सिंह को नहीं होगी। किन्तु दोनों ही आशाएँ धूमिल हो गईं।

वास्तव में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्बन्धों में नए तनाव-विन्दु बही पुराने हैं। तर्क ऐसा है कि पिछले कई वर्षों में विशेषकर शिमला समझौते (1972) के बाद के वर्षों में हम इनके प्रति उदारनीन हो गए हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण नदमीर है। इस समस्या का जन्म स्वतंत्रता और विभाजन के साथ ही हुआ था। 1947-48 में भी पाकिस्तान का प्रयत्न तौड़-फोड़ करने वाले धुमपैठियों को भारत में भेजकर श्रीनगर व कश्मीर घाटी को अस्थिर कर साम्प्रदायिक तनाव बढ़ाना था। आज भी इस रणनीति में कोई बदलाव नहीं आया है। हाँ, स्थिति इस बात से अवश्य संकटग्रस्त हुई है कि आज पाकिस्तान में प्रशिक्षित आतंकवादी धुमपैठिये कश्मीर में नहीं, पंजाब में भी सक्रिय हैं और इन दोनों के बीच गठजोड़ भारत के सामरिक हितों के लिए शोचनीय है।

एक और महत्वपूर्ण बात है, जो पहले नहीं थी। पाकिस्तान आज मादक द्रव्यों की तस्करी का एक बड़ा मूक है और अफगानिस्तान में सोवियत सशस्त्र के असफल हस्तक्षेप के बाद महत्वपूर्ण पोक बाजार भी। मादक द्रव्यों, हथियारों और अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद की घनिष्ठ रिश्तेदारी अब बच्ची तरह स्पष्ट हो चुकी है। दक्षिण अमरीका हो, पश्चिम एशिया या श्रीलंका, पाकिस्तान एक बार इस 'बाय की सवारी' शुरू करने के बाद उतरने का खतरा कभी नहीं उठा सकता। बल्कि कुछ उदार लोग तो यह सुझाने लगे हैं कि अपने यहाँ इतने असामाजिक तत्वों की सक्रियता रोकने के लिए पाकिस्तान इन्हे वापस भेजने के लिए मजबूर हुआ है।

भारत-पाक सम्बन्धों में बढ़ते तनाव के लिए निश्चय ही पाकिस्तान के आन्तरिक हालात उत्तरदायी हैं। पाकिस्तान में सेना और नागरिक सरकार के बीच सम्बन्ध इसका भिन्न एक पहलू है। कराची में और अन्यत्र भी स्थानीय मुसलमानों और मुहाजिरो (मुहाजिर अर्थात् विभाजन के बाद भारत से पढ़ेंचे शरणार्थी) के बीच वैमनस्य साम्प्रदायिक रूप से पुका है और सर्वनाशक हिंसा का विस्फोट समय-समय पर हुआ है। एक दसक पहले तक पाकिस्तान की राष्ट्रीय एकता को तर्क पल्लून राष्ट्रवाद की पुनीती का सामना करना पड़ रहा था। फिर इसमें बलूप कवायती जुड़े। परन्तु आज सिन्धी, पंजाबी, मुहाजिर सभी अपनी अलग-अलग पहचान बना चुके हैं।

भारत-चीन सम्बन्ध (India-China Relations)

भारत और चीन दोनों ही देश हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं और इस सांस्कृतिक परम्परा को जीवित रखे हुए हैं। इनके अतिरिक्त ये देश (चीन और भारत) समार की सबसे बड़ी आबादी वाले दो देश हैं। इनमें चीन कट्टर साम्यवादी रहा है तो भारत भुट निरपेक्ष। सदियों से दोनों देशों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान चलता रहा है। ये सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ या व्यापक होते ही न रहे हों, परन्तु इन दोनों देशों के बीच सद्भाव और आत्मीयता बनाये रहे। आजादी की लड़ाई के वर्षों में दोनों देशों के राष्ट्रवादी नेताओं के बीच सवाद बना रहा था। चांग बाई शेक के साथ नेहरू जी की व्यक्तिगत मित्रता और माओ के नेतृत्व में लड़ रहे साम्यवादी छापाभारों को राहत के लिए भेजी गयी काप्रेम पार्टी की चिकित्सा टीम इसी के उदाहरण हैं। इसे एक विडम्बना ही समझा जाना चाहिए कि 'हिन्दी-चीनी, भाई-भाई' वाला मैत्री का दौर अधिक समय तक नहीं चल सका और तिब्बत को मुक्त कराने वाले चीन के अभियान के साथ ही 1950 में भारत-चीन सम्बन्ध तनावग्रस्त हो गये। इसके बाद भी भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों व सम्मेलनों में चीन का समर्थन किया और चीन के साथ शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की घोषणा करने वाला पंचशील समझौता (1954) भी किया। परन्तु कुछ समय बाद तनाव फिर से उभरने लगे, जब तिब्बत में चीनी नीतियों से परेगान दलाई लामा ने भारत में शरण लेने की प्रेरणा दी। कोरिया युद्ध विराम के बाद भारत की सभ्यस्यता की कोई आवश्यकता चीन को नहीं रह गयी थी और हिन्द चीन सम्बन्धी जेनेवा सम्मेलन के बाद तो एक तरफ से चीनी नेता निरापद हो चुके थे।

इन्हीं दिनों चीन ने कुछ ऐसे नये छापे जिनमें भारतीय भू-भाग पर चीनी दावा किया गया था। पहले-पहल सीमा विवाद प्रकट हुआ और ये दो देश मैत्रिक मुठभेड़ के रास्ते पर उतर आये। चीनी दावों को नकारते हुए भारत ने सीमा सुरक्षा बल के मैत्रिकों को आदेश दिये कि वे अपनी भूमि पर कब्जा कतई न छोड़ें। सीमान्त पर अग्रगामी नीति का अनुसरण करने के कारण 1958 में लोंग जू और कोमका दर्रा पर हुई छाप में तेरह भारतीय सिपाहियों की जानें गयीं। तब से इन दो देशों के बीच सम्बन्धों में निरन्तर बिगड़त आई। मार्च-अप्रैल, 1959 में दलाई लामा के पलायन और भारत में शरण लेने में चीनी नेताओं को उत्तेजित किया और मितम्बर, 1960 में चाऊ एन लाई की भारत यात्रा के दौरान सीमा विवाद के निपटारे के लिए आयोजित बातचीत निष्फल रही। अब तब बड़े पैमाने पर मैत्रिक टकराव की जमीन तैयार हो चुकी थी। एक मार्क्सवादी भाषण में नेहरू जी ने भाषावम में यह स्वीकार किया कि उन्होंने चीनियों को भारतीय भूमि से लडेड निकालने का आदेश दे दिया है। चीनी इसके लिए तैयार बैठे थे और इस शक्ति परीक्षण में भारत को मुंह की खानी पड़ी। सदियों की मैत्री पत्रक क्षपकते ही समाप्त हो गयी और पीढ़ियों तक चलने वाले बैर ने जड़ पकड़ ली।

जवाहरलाल नेहरू के मार्क्सवादी जीवन की कोई और घटना इतनी सालने वाली नहीं, जितनी कि भारत-चीन सीमा विवाद और 1962 में मैत्रिक मुठभेड़

में तनाव में कभी न आने दे।

पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भारत की चिन्ता नई नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि जब पाकिस्तानी वैज्ञानिक अब्दुल कादिर ख़ाँ यह घोषणा करते हैं कि उनके प्राणों को भारतीय गुप्तचर सस्था 'रॉ' (RAW) के एजेंटों से खतरा है, तब थोड़ी सनसनी जरूर फैलती है।

यहाँ ईमानदारी का तकाबा है कि यह बात भी स्वीकार की जाये कि भारत-पाक सम्बन्धों में तनाव-वृद्धि के लिए सिर्फ पाकिस्तान ही जिम्मेदार नहीं है। पाक के साथ नरम नैवीपूर्ण रुख के लिए पूर्व विदेश मंत्री इन्दु कुमार गुजराल काफी बदनाम रहे, विशेषकर जब मुल्ह के लिए बड़े उनके हाथ को पाक विदेश मंत्री याक़ूब ख़ाँ ने एक से अधिक बार ठुकरा दिया।

अभी भी कुल मिलाकर, भारत-पाक सम्बन्धों के नए तनाव-बिन्दु वही पुराने हैं—विवादग्रस्त कश्मीर, आतंकवादियों की सुरक्षण, साम्प्रदायिक विष घमन और परमाणु चुनौती। वस्तुतः इन दो देशों के बीच राष्ट्रीय हितों का टकराव इतना जबरदस्त है कि हर नई ख़रोब या नया घाव कहीं न कहीं पुराने साइज़ान भाँसूर से पुड़ जाते हैं। स्वयं पाकिस्तान की यह मजबूरी है कि अपने ईरानी और पश्चिम एशियायी सम्पर्कों का साथ उठाने के लिए वह मध्य-यूरीन धार्मिक कठमुल्लेपन के आगे घुटने टेके। जैसे यह भी कोई नई बात नहीं।

आतंकवाद और भारत-पाक युद्ध का संकट

अक्सर ऐसा होता है कि औपचारिकता के रूप में हर वर्ष की जाने वाली सैनिक कसरतें (चाहे भारत का आपरेटन ब्राइटेंस हो या पाक का जर्वे मोमिन) युद्ध की आशंका को बढ़ा देते हैं। सिपाचिन की रस्मों गोलाबारी (जिसका मकसद कड़ाके की ठंड में 'धून' गर्म रखना है, और फौजी दिव्यजनों का एक मुकाम से दूसरे मुकाम को स्थानांतरण होता है) विशेषज्ञों को विद्रोहापूर्ण अटकलें लगाने का मौका देते हैं।

वस्तुस्थिति यह है कि पाकिस्तान का हाथ भारत की दुखती रग पर है। संज्ञा हो या कश्मीर, दोनों ही तनावग्रस्त अमान्य क्षेत्रों में अलगायवादी-आतंकवादी गतिविधियाँ बिना पाकिस्तानी सह्ययता, समर्थन और धारण के नहीं चल सकती। यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ने जगता देश वाला सबक बहुत अच्छी तरह समझ लिया है। जब तक तथ्याकथित मुक्ति सैनिकों के माध्यम से शत्रु पर परीक्षण रूप से विघटनकारी हमला किफायतसारी से चलाया जा सकता है, तब तक पारम्परिक युद्ध की आवश्यकता ही किसे है? विडंबना तो यह है कि अमरीका भारत और पाकिस्तान को परमाणु के मामले में एक ही छत्राँ से तोलता है। बल्कि स्थिति तो यह है कि सस्ता धार्मिक हाल के कारण भारत के लिए यह दबाव ज्यादा दर्दनाक है। पाकिस्तान को इस बात का अहसास भी है कि चुनावों में वर्ण-संपर्क और साम्प्रदायिक वंमनरुष के कारण भारत में राजनीतिक स्थिरता, शांति और मुख्यवस्था कंकटाकीर्ण है। वहाँ के शासक वर्ग का यह सोचना तर्कसंगत है कि ऐसी स्थिति में भारत पर दबाव बनाये रखना ही सही रणनीति है।

नी छिद्रान्वेयी ने आज तक प्रस्तुति नहीं लगाये हैं। अगर और गहरे पैराना हो तो डा० एन० गोपाल द्वारा सम्पादित नेहरू जी के पुनिन्दा कृतित्व के सकलन और 1962 के पहले प्रकाशित मरदार पणिकर के सम्मरणों से उस स्थापना की पुष्टि की जा सकती है, जिसे यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।

पहली बात तो यह है कि नेहरू जी को सीमा-विवाद का जनक मानना निपट मूलतः है। यदि हजारों मील लम्बे दुर्गम हिमालयी सीमान्त में औपनिवेशिक शासक और स्थानीय प्रशासक समुचित सीमा रेखांकन और हदबन्दी नहीं कर सके तो पलक झपकत ही आजाद भारत के प्रजासत्तानी नेहरू जी से इस उपलब्धि की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। यह नहना भी गलत है कि इस मामले में नेहरू जी ने देशवासियों को अन्वकार में रखा और उन्हें कुछ पता ही नहीं लगने दिया। प० हृदय नाथ कृष्ण, डा० राम मनोहर लोहिया आदि जैसे विदेश नीति में महती रुचि रखन वाले प्रखर मामद-राजनेता आँख मूंद कर मुँह लोसने (वाने) लगे नहीं थे। कांग्रेस पार्टी में ही गोविन्द वल्लभ पन्त और मोरारजी देसाई जैसे महारपी विद्वान थे, जिनका दक्षिणपन्थी व साम्यवाद-विरोधी नहीं तो उन्हें थक की नजर से देखने वाला समान प्रभावशाली था। मरदार पटल न नवम्बर, 1950 में ही एक लम्बे पत्र (नोट) द्वारा नेहरू जी को चीनी खजर के प्रति आग्रह करते हुए लिखा था कि चीनी लोग साम्यवादी बनने के बाद और भी 'नासद नाभ्राज्यवादी' साबित हो सकते हैं। 'नय चीन' में पहले भारतीय राजदूत पणिकर ने भी यह बात महसूस कर ली थी कि चीनी नेता अपने को ही 'कौरव' समझते हैं और दूसरों को छुटनेवा। यह अन्दाज उनके बर्ताव में झलकता रहता था। यदि समय रहते आसन्न सबट के मुकदों का सही मूल्यांकन नहीं किया जा सका तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अधिकांश भारतीय राजनयिक और नेता आत्म-मुग्ध और मलुष्ट थे। उन्हें लगता रहा कि चीन भी भारत जैसा ही देश है—मुधारवादी, शान्तिप्रिय और परामर्श द्वारा हर समस्या व समाधान के लिए प्रतिबद्ध।

शान्तिप्रस्त भारतीय राजनयिक—नेहरू जी 'चीनी मरदे' से बलबद नहीं थे। परन्तु इसका मतलब यह नहीं कि चीन में निपुक्त भारतीय राजनयिकों ने अप्रतिष्ठ समझदायी करनी। ये भारतीय राजनयिक 'नय चीन' में भारत के आँख-कान के समान थे लेकिन उनमें से कई चीन की वास्तविक स्थिति का सही ज्ञापना लेने में असमर्थ रहे। कई राजनयिकों का आचरण इतना अजीब था कि आज उनको यादकर बरबस हँसी आती है। इन शान्तिप्रस्त भारतीय राजनयिकों के 'राजनयिक आचरण' के बारे में कुछ बातों का यहाँ खुलासा किया जा रहा है।

क० पी० एम० मनन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही औपनिवेशिक मरदार द्वारा 'एजेंट जनरल' बनाकर पश्चिम (अब चीन) भेज दिए गये। वह पणिकर की निपुक्ति तब चीन में भारत व राजदूत रह। उन्होंने अपने कार्यकाल का एक बड़ा हिस्सा बिताया—गोंबी के रेसिस्त्रान का पैदल नारने। इस पुष्करी से उन्हें या इन को कुछ राबक सम्मरणों के अलावा कोई ठोस राजनयिक उपलब्धि हासिल नहीं हुई।

क० एम० पणिकर पारम्परिक चीनी के राजमी राजनयिक थे। वह

¹ देखें—Neville Maxwell, *India's China War* (Bombay, 1971)

में दुःखद परिणति। अनेक विद्वानों का मानना है कि भारतीय विदेश नीति की सबसे बड़ी असफलता चीन के साथ सम्बन्धों में बिबाड़ है। इससे नेहरू जी का नादान भोलापन ही नहीं पता चलता, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवाद की निरर्थकता भी उजागर होती है। आज तक यह धाव धूने पर दर्द करता है। 1979 में वियतनाम पर हमला करते वक्त चीन ने यह घोषणा की थी कि 'दण्डानुशासन वाली यह कार्रवाई' 1962 के नमूने पर ही की गई थी। इस तरह के वक्तव्यों को अनमुना करना असम्भव है। अर्थात् दशकों बाद भी इस 'संघर्ष' और भारत-चीन सम्बन्ध के विद्वेषण की सार्थकता बनी हुई है।

भारत की चीन नीति : नेहरू जी की नादानी—भारत-चीन सीमा विवाद का जिक्र होने पर कुछ लोगों के तबिर '1962 के अपराधी' ढूँढ़ने वाले होते हैं।¹ अधिकांश आलोचकों को लगता है कि भारत-चीन मनमुटाप के घातक चिस्फोट की जिम्मेदारी सिर्फ नेहरू जी की थी। कृष्णा मेनन और सरदार पणिकर जैसे गलाहकार उन्हीं के विश्वासपात्र मिन थे। पंचशील का सपना किसने सच समझा या भला? चीनी नेताओं के साथ व्यक्तिगत मैत्री के क़मानी शिकंजे में फँसकर वरसो मुग-सन्तुष्ट नेहरू जी के अलावा और कौन रहा था? ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं जो मानते हैं कि भारत-चीन विवाद सिर्फ नेहरू जी की 'मोली-मलमनसाहव', 'नादानी-नासमझी' या 'आत्मघाती बहिषा' से उपजा था। इनका कहना है कि नेहरू जी का अहंकार, सीमान्त के मामले में उनका ब्रिटिश औपनिवेशिक रवैया तथा कपनी व करजी में अन्तर दोनों देनों में अलगाव और अन्ततः शत्रुता पैदा करने की काफी थे। मैक्सवेल और लोर्न काविक जैसे लोगों को नेहरू 'शान्तिदूत' नहीं, बल्कि 'मक्खन' लगते हैं। 'टकराव' का रास्ता माना उन्होंने स्वयं चुना था और बैचारे चीनी भूँह तोड़ जवाब देने की विवश रहे ही।

1962 के बाद 'सफाईयो' व बचाव पक्ष की दलीलों के नमूने पर बड़े पैमाने पर आत्मकथार्थ प्रकाशित हुई। इनमें जनरल कौल की 'अनकही नहानी' तथा इंग्लैंडलैंड्स झूरी के बी० एन० मलिक की 'माई इयर्स विथ नेहरू: दि चापनीज बिट्टमल' विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।² परन्तु इनमें उपलब्ध जानकारी को 'प्रामाणिक' निश्चय करना कठिन है। मोर्चे पर उसके पहले भी जनरल कौल का आचरण बिबादास्पद रहा। मलिक के ऊपर यह आरोप लगाया जा सकता है कि उनके विभाग की लापरवाही और असफलता ने ही सेना की तैयारी को कमजोर किया था। थूक के बाद अपनी हीशियारी और दूसरों की कमियाँ-गलतियाँ दर्जाने का लालच ये लोग नहीं छोड़ पाये। जनरल निरजन सिंह, मुखबन्त सिंह आदि की पुस्तकें 1962 के दुस्वप्न पर नई रोशनी उद्धर डालती हैं, परन्तु हमारी समझ में उनका मूल विषय सैनिक इतिहास, रण संचालन और समर नीति है। मामले की तह तक पहुँचने के लिए हमें मैक्सवेल और लोर्न काविक द्वारा जुटाई सामग्री उपयोगी लगती है। मैक्सवेल की India's China War और लोर्न काविक की 'India's Quest for Security' में प्रकाशित दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर किसी

¹ देखें—D. R. Manekkar, *The Guilty Men of 1962* (Bombay, 1968) और Brigadier J. P. Datta, *The Himalayan Blunder* (Bombay, 1970).

² देखें—General B. M. Kaul, *Untold Story* (Bombay, 1971) और B. N. Mullick, *My Years with Nehru, 1948-1964* (Bombay, 1972).

जा दुबके तो अनुवादक सैनिक विद्यालयों में। 1962 के बाद चीनी पत्र-पत्रिकाओं के पन्नों पर रोक लगा दी गयी। इन प्रकार 'चीन विद्या विनारदा' की एक पूरी पीढ़ी निकम्मी बना दी गयी।

1962 के बाद लगभग एक दशक तक अमरीका को यह लगता रहा कि उनका चीन विषयक नामरिक हितों का संयोग भारत के साथ हो रहा है। इस दौरान 'भारतीय चीन विचारदों' की एक नई पीढ़ी तैयार की गयी। फोड़े निचि की उदारता में इनकी विविधन दीक्षा केनिष्ठाविया आदि में हुई। अन्तर्राष्ट्रीय महयोग से स्थापित चीनी अध्ययन विभागों में ऐसे कोई आधा दर्जन लोग आज भी प्रतिष्ठित हैं। इनका 'विदेशपन' अपने अमरीकी सहकर्मियों के दृष्टि-रुझानों और स्थापनाओं की ही प्रतिबिम्बित करता है। चीन के बारे में जानकारीयों, चीन विषयक प्रकाशनों, विदेश भ्रमण आदि के लिए अमरीकी संयुक्त की उपयोगिता बनाए रखना ही इनमें से अधिकांश को 'राष्ट्र-हित' नजर आता है। कुछ का यह भी लगता है कि जब तक भारत-चीन सम्बन्ध ननावपूर्ण रहते हैं, तभी तक उनकी कुछ होगी। निश्चय ही, भारत-चीन विवाद का निबटारा इन 'पण्डितों' के योग्यपूर्ण कृपा बटाओं या इनके स्वयं प्रचारित 'भितर-राजनय' पर निर्भर नहीं, तथापि ठगुर-नुहाती कहन-मुनने का सामान्य और विषय को अनावश्यक रूप में दुबह-गहन बनाता निरंक पाठक धान्तियों की ही पनपा सकता है।

भारत-चीन सीमा विवाद . ऐतिहासिक परिच्छेद—भारत व चीन में सीमा विवाद एक मतभेद काफ़ी पुराने हैं। हालांकि दोनों देशों का स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व लगभग एक साथ हुआ, किन्तु राष्ट्रीय हितों के टकराव से उनमें मतभेद की दीवार नहीं होने में अधिक देर नहीं गयी। पश्चिमी देशों ने साम्यवाद-विरोध की रणनीति व तत्काल कई वर्षों तक साम्यवादी चीन की सरकार को साम्यता नहीं दी और संयुक्त राष्ट्र में उसका प्रवेश नहीं करने दिया। जबकि ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भारत ने चीन का पक्ष लिया और विभिन्न सभा पर उस संयुक्त राष्ट्र में का मदद बनाने की ओरदार बकात की। 1954 में 'हिन्दी-चीनी, भाई-भाई' के नाम पर और 1955 में इण्डोनेशिया व बाङ्गलादेश में हुए अने-एशियाई सम्मेलन में नहरू जी ने चीनी नेता चाऊ गन माई की भरपूर सरहना की। मगर 1955 के बाद चीन ने भारत में मिलन वाली सीमाओं पर अपनी सैनिक गति-विधियाँ तब कर दीं और 1956 में अकनाई चिन में सैनिक महत्व की एक महक बना ली। चीन ने इस महक का निर्माण दीर्घकालिक योजना के तहत किया, जिसमें पाकिस्तान में स्थित मार्ग द्वारा सीमा सम्बन्ध स्थापित करना आवश्यक था, ताकि भारत के साथ चीन सदैव सौदभात्री की स्थिति में रहे। चीन ने पाकिस्तान के साथ स्थित मार्ग को भारत हुए काराकारम महक का कुछ वर्षों पूर्व निर्माण किया, जिसमें उस योजना की ही पूर्णता होती है।

1956 में चीन भारत की हजारा वर्ग मील जूमि पर अपने दावे जनाता रहा है। उसमें वे दावे मनुष्य नवनों के प्रकाशन, नागरिक सीमा में अवैध घुसपैठ, सरकारी बगानों आदि के जरिये उछाने। 1957-58 में सीमावर्ती मन्त्रों दस्ता के बीच जा जाननवा मुठभेड़ें हुईं, वे भारत की अग्रगामी नीति (Forward Policy) का नवीन बजायी जानी है। परन्तु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि सीमा पर महकाने वाली पहल नहरू जी ने की थी। हाँ, यह अवश्य प्रकट होता है

सुसंस्कृत, सुशिक्षित और चोड़िक भद्र पुरुष थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में विस्तार से इस बात का वर्णन किया है कि कैसे यह-मुझरत चीन में संस्कृत नाटकों का, मलयालम में अनुवाद कर वह अपने को व्यस्त रखते थे। उन्होंने आगे बैठे (अधिकतर पश्चिमी) राजनयिकों के मनोरंजन के लिए एक 'लास क्लब' भी चलाया। उनके शिकवे-शिकायतें इस तरह के भी मिलते हैं कि अन्ति के बाद चीन में नौकर कितने महंगे और सरसबंद हो गये थे। ऐसे मिजाज वाले राजदूत को देखकर यदि चीनी नेता भारत को सामन्ती वैदियों में जफला समझते रहे तो उन्हें ज्यादा दोष नहीं दिया जा सकता।

मेनन और पणिनकर के कार्यकाल में जो 'तेजस्वी' होनहार युवा राजनयिक चीन में कार्यरत थे उनके पराक्रम भी विचित्र नहीं। प्रोफेसर जयन्तनुज बद्योपाध्याय (जो स्वयं राजनयिक रह चुके हैं) ने अपनी पुस्तक में वह प्रसंग दिया है, जब इन्द्रजीत बहादुर सिंह ने चाऊ एन लाई की 'राजनयिक' पुनीती 'माओ ताई' (चावल की गराब) पीने के बोर्च पर स्वीकार की थी और उन्हें पित्त कर दिया था। इस तरह की अपनी उपनयि का मर्म वर्णन टी० एन० फौल ने अपनी जीवनी 'शान्ति और युद्ध का राजनय' (Diplomacy in Peace and War) में किया है जब उन्होंने एक बार राष्ट्र हित में अपना जिगर जताते हुए शराब के ॥ प्याले गटक किये थे। पता नहीं ये यथार्थवादी-अनुभवी राजनयिक कैसे यह समझ रहे थे कि इतिहास विप्लवाचारी, सामन्ती और औपनिवेशिक शैली अपनाता द्रामा-कारी चीन में लाभ का काम सिद्ध होगा? इस तरह के मूढयोगियों से पते की बात कैसे मातुम हो सकती थी?

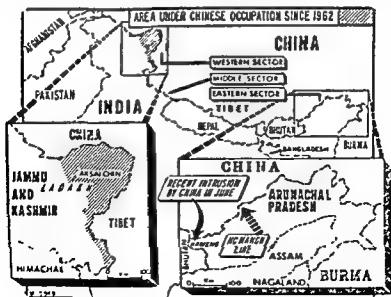
कृष्ण मेनन ने माइकल ब्रेकर के साथ जो सम्बन्ध बातचीत की, उसके प्रकाशन से भी यही पता चलता है कि भारत व चीन के बीच राजनयिक सम्भार और शैली के टकराव ने मोमा विवाद को विकट बनाया। कृष्ण मेनन ने यह बात बेहिसक स्वीकार की है कि नेहरू जी और वह (स्वयं) अर्थोन्ने-अभरीकियों के भाष वान करना सहज पते थे। चाऊ एन लाई को वह सुलझा हुआ, ससदीय प्रणाली में निष्ठा रखने वाला उदारमयी व मध्यममार्गी समझते थे। पता नहीं चीनी यह मुद्दा व साम्यवादी द्रान्ति के इतिहास से सुपरिचित होने के बावजूद उन्होंने किस आधार पर ऐसी मान्यता बनाई थी? ¹

चीन के बारे में हमारी आधी-अधूरी जानकारी के लिए सिर्फ राजनेता, नौकरशाही और राजनयिक ही जिम्मेदार नहीं थे। बुद्धिजीवी और विशेषज्ञ विद्यार्थी ने भी देश को निराज्ञ ही किया है। इस सन्दर्भ में नेहरू युग के अनुभव की याद ताजा रखना आज भी मार्पक है और मविध्य के लिए भी उपयोगी। 'हिन्दी-चीनी, नाई-नाई' वाले ज्यों ने जड़ें बंधाने पर विप्लवकलां, विद्वानों एवं छात्रों का आदान-प्रदान हुआ। इनमें से कुछ ने उल्लेखनीय विशेषज्ञता भी हासिल कर ली। परन्तु भारत-चीन सम्बन्धों में तनाव बढ़ने के साथ ही ये रातो-रात 'चीन के मित्र' व देवप्रोही के रूप में घूरे जाने लगे। कुछ ने चुप्पी साध ली तो कुछ ने जान बचाने या ऊपर उठकर आगे बढ़ने को सरकार का दामन धाम लिया। सरकारी गोपनीयता के अनुष्ठान ने बंधो-मुबो कगर पूरी कर ली। दुनापिये तीन विदेश मन्त्रालय में

¹ Michael Brecher, *India and World Politics: Krishna Menon's View of the World* (London, 1968)

क्यूशेव के 'शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व' का स्थान नहीं था। ऐसी हानत में जब सोवियत संघ की घनिष्ठता साम्यवादी माई (चीन) की जगह तटस्थ मित्र (भारत) के साथ बढ़ने लगी तो चीन का धैर्य पूरी तरह चुक गया। चीनी नेताओं ने अपने तत्कालीन वक्तव्यों में यह बात स्पष्ट रूप से स्वीकार की है।

अक्सार्ड-चिन सड़क का सामरिक महत्व चीन के लिए भारत के मन्दन में नहीं, बल्कि इसमें द्तर वृहत्तर मन्दन में ही है। लोप नौर (मिक्काग प्रात) में चीन का प्रक्षेपास्त्र परीक्षण स्पष्ट है और मुक्त तिब्बत की नियन्त्रण में रखने के लिए भी इस संचार व यातायात सुविधा की आवश्यकता पड़ती है। कुछ लोग यह अटकल लगाते हैं कि यदि नेहरू जी चाहते तो 'अक्सार्ड-चिन' देर नेफा ले सकते थे। परन्तु इस तरह की कालवृत्तकही आज निरर्थक है। सबसे पहला सवाल तो यह कि क्या नेहरू जी को ऐसा करने दिया जाता? कहने को तो यह भी कहा जा सकता है कि यदि कश्मीर की घाटी पाकिस्तान को सौंप दी जाये तो क्या भारत-पाक विवाद का हल हो जायेगा? कोई भी सरकार इस तरह का 'समझौता' करने के बाद क्या बची रहती? असल में 'रियायतों' से विस्मरवादियों को रोका-बामा नहीं जा सकता। 1936 के म्युनिख प्रमग की याद आज भी ताजा है। नेफा वाला पुर्वोत्तरी सीमान्त भी चीन के लिए सिर्फ भारत के मन्दन में ही नहीं, बल्कि बंगला दम, भूटान आदि के मन्दन में सामरिक महत्व का है। चीनी लोग यहाँ बसने वाली जन-जातियों के साथ अपन 'रक्त सम्बन्धों' की विवेकता याद रखत रहे। मने ही छापामार-आतंकवादी मुक्ति सैनिक कार्रवाई देंग मियाओं गिंग के चीन में किनहाल विद्रो-शान्ति का अमिन्न हिस्सा न हो, लेकिन इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस भू-भाग (नेफा) में जमानि जोर अस्थिरता चीन के लिए उपयोगी बने रहते हैं।



सन् 1962 के बाद चीन के अधिग्रहण में भारतीय भूमि

कि नेहरू जी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे थे। भारत की अग्रगामी नीति बदले परिवेश में उपनिवेशवादी विस्तारोन्मुख नहीं, बल्कि प्रतिरक्षात्मक थी। सरहद पर सजग रहे बिना चीनी घुमपैठ को नहीं रोका जा सकता था और न ही अनधिकृत कब्जे को। यह आलोचना भी ठीकसगलत नहीं कि तब भारत ने धुरू से ही जुझाऊ तैयार क्यों नहीं अपनाये? चीन को 1950 में ही चुनौती क्यों नहीं दे दी गई? आखिर खाली खम ठोकने-सलकारने से क्या हासिल हो सकता था, जब हाथ में अस्त्र ही नहीं था? तथ्य यह है कि आजादी के साथ ही आया था—देश का रक्त-रञ्जित विभाजन और कश्मीर के मोर्चे पर युद्ध। छरणाधियों का पुनर्वास, साम्प्रदायिक सद्भाव का मृजन, देश का एकीकरण (रियासतों-रजवाड़ों के विलय के बाद), संविधान निर्माण, आग बुनाद की नींव पर जनतन्त्र का शिलाग्यास और दरिद्रता से पिण्ड छुड़ाने के लिए परमावश्यक आर्थिक नियोजन ऐसी चुनौतियाँ थीं, जिनमें से किसी की प्राथमिकता नहीं बदली जा सकती थी। यदि चीन के साथ टकराव को ढालने और विवाद को शान्तिपूर्ण परामर्श से निबटाने का प्रयत्न किया गया तो इसे हुरदशिता ही समझा जाना चाहिए। तब ही यदि भारतीय सैन्य-शक्ति बढ़ाने का अभियान जारी रहा तो इसे समझदारी ही कहा जा सकता है, पाखण्ड नहीं।

'हिन्दी-चीनी, भाई-भाई' वाले दौर तथा 'पंचशील' प्रकरण का मूल्यांकन इसी परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए। नेहरू जी की कोशिश यह रही कि यदि चीन को अन्तर्राष्ट्रीय विरादरी में प्रविष्ट कराया जाये तो उसे सर्वसम्मत राजनयिक आचरण के लिए बाध्य किया जा सकेगा। कोरिया युद्ध, जेनेवा शान्ति सम्मेलन और वाइगु सम्मेलन में यदि नेहरू जी ने चीन का पक्ष लिया तो इसके लिए व्यक्तिगत मंत्री नहीं, बल्कि राष्ट्र हित की गणना महत्वपूर्ण थी। नेहरू जी की मंत्री सन वात सेन एवं चांग काई शेक परिवारों में थी, साम्यवादी छापामारों में नहीं। नेहरू, अन्य भारतीय राष्ट्रवादी नेता और स्वतन्त्रता सेनानी भारत की आजादी की लड़ाई को उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद के विरुद्ध विद्रोहाधी सघर्ष का हिस्सा समझते थे। हान हो या चीन, सोवियत सघ हो या इण्डोनेशिया, उत्पीड़न एवं शोषण के उन्मूलन में भारत की हिस्मदारी जरूरी समझी जाती थी। यह सही भी था।¹

भारत-चीन सम्बंधों की अन्तर्राष्ट्रीय घूँटभूमि—भारत-चीन सीमा विवाद सिर्फ दो देशों के बीच का मामला नहीं है। इसके बहुपक्षीय, अन्तर्राष्ट्रीय, राजनयिक और भू-मानसिक पक्ष भी हैं, जो घामद मक्के महत्वपूर्ण हैं। चीनियों का महाशक्ति भव, जातीय अहंकार व विदेशियों के प्रति विरसकार सिर्फ भारत को ही भारी नहीं पड़ा है बल्कि सोवियत सघ भी इसकी चपेट में आया है। 1960 तक रुम-चीन मतभेद कटुतापूर्ण ढंग से उमरने लगे थे। उनके बीच सीमा विवाद ने गीघ्र ही इतना यतनायक रूप ले लिया कि चीनी नेता सोवियत सघ को पहले नवंबर का दशक समझने लगे और नववर्ष में गर्भावित सघर्ष के लिए सामरिक तैयारी में जुट गये। चीनी नेता इस बात से क्षिप्र हुए कि स्टालिनवाद के विस्थापन के पहले उनसे सलाह-मसविदा नहीं किया गया। सोवियत सघ परमाणु अस्त्रों के निर्माण में चीन को समर्थ बनाने से कतरता रहा। यह साइवान को मुक्त कराने के लिए परमाणु अस्त्रों के प्रयोग या इसकी धमकी देने के लिए तैयार नहीं हुआ। माओवादी विश्व दर्शन में

¹ A. Appadorai and M.S. Rajan, *India's Foreign Relations* (Delhi, 1985).

सामरिक व वैज्ञानिक उपलब्धियाँ उल्लेखनीय रही। चीनियों ने उद्‌जन बम (हाइड्रोजन बम) बना लिया और इसे दूरस्थ निशानों तक पहुँचाने वाला प्रक्षेपास्त्र भी। इससे चीन कम से कम आधी महाशक्ति के रूप में तो प्रतिष्ठित हो ही गया। इस विवरण से यह समझना गलत होगा कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने सहम कर फरवरी, 1976 में एक बार फिर चीन की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इन्हीं वर्षों में भारत ने भी स्वयं को दक्षिण एशिया के प्रमुख राष्ट्र के रूप में स्थापित कर लिया। हरित क्रान्ति ने विदेशी सहायता पर हमारी दुखद-अपमानजनक निर्भरता का अन्त कर दिया। 1971 के सैनिक अभियान ने 1962 की ग्लानि से भी भारतवासियों को मुक्ति दिलायी। मई, 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण में यह दर्शा दिया कि वैज्ञानिक क्षमता में भारत किसी भी विकासशील राष्ट्र से पीछे नहीं। नेहरू व गाँधी की मृत्यु के बाद सत्ता के सहज हस्तान्तरण, गैर-वापसवाद के उदय और परमाणु परीक्षण ने भारतीय जनतन्त्र की जड़ों की मजबूती प्रमाणित कर दी। श्रीमती गांधी ने 1976 में चीन के साथ सम्बन्धों के सामान्यीकरण के लिए पहल की और बीजिंग में भारतीय राजदूत नियुक्त किया। यह पहल अविवेकी या दुस्माहसिक नहीं, बल्कि आत्मविश्वासपूर्ण कदम था। जब बीजिंग में 14 वर्ष बाद भारतीय राजदूत के रूप में के० आर० नारायणन को भेजा गया तो 'सम्भावनाओं' के साथ 'सीमाओं' का अहसास भी श्रीमती गांधी और उनके सलाहकारों को था।

जनता सरकार को चीन सम्बन्धों पहल—जनता मरनार के काल में तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कुछ चमत्कार दिसलाने को व्यग्र रहे। चीन यात्रा के निमन्त्रण को स्वीकार करने में उन्होंने कुछ ज्यादा ही उतावली दिखाई। फरवरी, 1979 की इस यात्रा के दौरान चीन ने वियतनाम पर अचानक हमला बोल दिया। अतः वाजपेयी को अपने दौरे में कटौती कर स्वदेश लौटना पड़ा।

जनवरी, 1980 में इन्दिरा गांधी के द्वारा गद्दी सनालने तक मात्रा चीनी राजनीतिक रणमंच से विदा हो चुके थे। 'सघाई मिरोह' या 'चोकड़ी' का सफाया शुरू हो चुका था। चीन के नए श्रमक दैव मियाओ पिंग ने माओवाद को तिलाजलि देने के साथ-साथ 2000 ई० तक चार आधुनिकीकरणों का लक्ष्य अपने देशवासियों के लिए तय कर दिया। इस कार्यक्रम की पूर्ति के लिए अमरीका और एकाध अन्य तबनीकी-वितीय दृष्टि से सम्पन्न राष्ट्रों के अलावा किसी घुमसिक्क साथी की चीन को जरूरत नहीं रही। इस बदले सन्दर्भ में भारत के साथ सम्बन्धों का सामान्यीकरण चीन के लिए बहुत सीमित महत्त्व का प्रश्न रह गया। भारत भी अब चीनी भाषा भविष्य की बम अहमियत देना है। यह संयोग नहीं की बीच में काफी दिनों तक चीन में भारतीय राजदूत का पद खाली रहा।

सीमा विवाद के हल के लिए प्रस्ताव—भारत-चीन सीमा विवाद के हल के लिए अब तक प्रमुख रूप से तीन प्रस्ताव सामने आये हैं—बोलम्बो योजना, एक्मुरत समझौता और क्षेत्र दर क्षेत्र निपटारा (Sectorwise Approach)। इन प्रस्तावों की विलुप्त चर्चा के पूर्व सीमा विवाद के प्रसंगों को स्पष्ट करना उचित होगा। इस सीमा विवाद को तीन हिस्सों में बाँटा जा सकता है—पश्चिमी, मध्य, और पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग में दोनों देशों की 1600 किलोमीटर लम्बी सीमा है, जो जम्मू-कश्मीर को चीन के गिलगंध तथा तिब्बत के इसाका से अलग करती है। इसमें लगभग 25 हजार वर्ग किलोमीटर भू-भाग विवादालक्ष्य है, जिसमें पेगोन्ग झील के

सारी हिमालयी सरहद संकटग्रस्त रहने पर नेपाल पर दबाव बना रहता है। इस तरह दक्षिण एशिया प्रमण्डलीय की प्रमुख शक्ति भारत को 'व्यस्त' कर चीनी नेता अपनी अगुआई अन्तर्राष्ट्रीय भूमिका के बारे में निश्चित हो सकते हैं।

इस संक्षिप्त सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि भारत-चीन सीमा विवाद को नेहरू युग की एक बड़ याद के रूप में देखने की जरूरत नहीं। भारत-चीन सैनिक मुठभेड़ निश्चय ही दुर्भाग्यपूर्ण हो और जिन घोर सैनिकों ने देश के सम्मान तथा जमीन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, वे चिर-स्मरणीय रहेंगे। तथापि इतिहास हम बात का गवाही है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्तिशाली सैनिक-हस्तान और दूरदर्शी मूजबूत हो सबसे महत्वपूर्ण तत्व नहीं होते। राष्ट्र हित का सम्पादन कभी-कभार ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और नृहत्तर सामाजिक व राजनीतिक परिवर्तन-प्रवृत्तियों पर निर्भर होता है, जिन्हें हमेशा स्वेच्छानुसार नहीं मोड़ा जा सकता। इस बारे में जरूरत से ज्यादा धुंध होना व्यर्थ है।

इन्विरा युग में भारत की चीन नीति—श्रीमती इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के उक्त मथारों की भली-भांति समझती थी। उन्होंने चीन के बारे में कभी कोई 'भ्रम' नहीं पाला। प्रयाणमन्त्री पर ग्रहण करने के साथ ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भारत चीन के साथ सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रखना चाहता है, परन्तु आत्म सम्मान गवाकर या 'राष्ट्रहित' की बलि देकर नहीं। उन्होंने इस सिलसिले में कुछ बेहद बिचारोत्तेजक टिप्पणियों की हैं, जिनका यहाँ उल्लेख उपयोगी होगा। श्रीमती गांधी की राय में भारत-चीन संपर्क को सिर्फ सीमा-विवाद समाप्तता अति सरलीकरण है। समसामयिक या परवर्ती घटनाक्रम, चीन द्वारा भारत के विरुद्ध पाकिस्तान को समर्थन, आन्तरिक विग्रह को प्रोत्साहन आदि हमें यही सोचने को विवश करते हैं। 'सीमा विवाद' एक जटिल नीति का हिस्सा था—भारत को अस्थिर बनाने और उसकी प्रगति को अवरोध करने वाली राजनीति का अंग। तथापि 1971 तक भारत ने इस बात को अजगहिर कर दिया था कि उसकी इच्छा कटु याव को कुरेदने की नहीं, बल्कि शान्तिपूर्ण ऐतिहासिक मंत्री भी गधुर स्मृति को ताजा रखने की है। श्रीमती गांधी ने चीन को आश्वासन करते हुए बार-बार यह दाव दोहराई कि भारत की चीन के साथ कोई प्रतिद्वन्द्वता नहीं है, और न ही उसके इरादे जुझारू हैं। परन्तु बंगला देश मुक्ति संधि के दौरान यह आभा निर्मूल सिद्ध हुई कि चीनी नेतागण चीनी को बिसारने को तैयार हैं। इस प्रकार, वर्ष पिघलने के पहले पाला फिर से पड़ जाने से वह सख्त हो गयी। ऐसी स्थिति में सिर्फ यह आशा व्यक्त करने के विनाश और निमा भी क्या जा सकता था कि एक न एक दिन भारत के अस्पी करीब तीसों के साथ एक अरब चीनियों के हितों का मयोग और उनके बीच 'सहकार' सम्भव होगा।

1972 के आरम्भ में तत्कालीन अमरीकी विदेश मन्त्री जॉर्ज मेडोवेल के जोड़-तोड़ के बाद राष्ट्रपति निसन की चीन यात्रा सम्पन्न हुई और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के समीकरण खेती से बदलने लगे। गो पहले ही उत्तरी नदी के तट पर 1969 में सोवियत-चीन मुठभेड़ हो चुकी थी और 1971 में भारत-सोवियत मैत्री व सहयोग संधि के बाद चीन के साथ निकट पविष्य में सम्बन्ध सुधार की आभा प्रमित हो गयी थी। अमरीका द्वारा 'पहुचान' लिए जाने के बाद, सं० रा० संधि की सुरक्षा परिपद का सदस्य बन जाने के साथ चीनी दृष्टिकोण सिर्फ एशियाई नहीं रह गया था। इन वर्षों में आन्तरिक राजनीति में विप्लवी उपान-पुनत के बावजूद चीन की

सफलता' जरूर मिली। चीन ने पाँच पक्ष-प्रदर्शक सिद्धान्त पेश किये—बराबरी, मंत्रीपूर्ण वार्ता, लेन-देन की भावना, उचित एवं व्यापक फँसता। भारत ने छह सिद्धान्त प्रस्तुत किये—सीमा विवाद का शीघ्र हल, दोनों पक्षों के हित सामने रखना, वार्ता के लिए सर्वसम्मति तरीका तय करना, एक-दूसरे के मुझावों पर विचार करना, हल के लिए अनुकूल वातावरण पैदा करना और क्षेत्रवार निर्णय। हालाँकि दोनों देशों ने एक-दूसरे के ये सिद्धान्त मंजूर नहीं किये, फिर भी यह माना कि सीमा समस्या का हल ढूँढने वक्त वहाँ के ऐतिहासिक, परम्परागत और रीति रिवाज के पहलुओं को भी सामने रखा जाये तथा एक-दूसरे के इनाके पाने के लिए 'बल प्रयोग' न हो। पाँचवें, छठे और सातवें दौर की वार्ताएँ बिना किसी ठोस नतीजे के समाप्त हो गईं। वार्ता के आठवें दौर में भी कोई ठोस प्रगति होने की मार्गजनिक घोषणा नहीं हुई। हाँ इससे राजनीतिक स्तर पर वार्ता होने की आशा जरूर बँधी।

यहाँ सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब सीमा विवाद से सम्बन्धित वार्ताओं में उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो रही है क्यों नहीं आर्थिक, व्यापारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आदि क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का कार्य तेजी से किया जाये ताकि सम्बन्ध सुधार के साथ-साथ सीमा विवाद के हल के लिए भी अनुकूल वातावरण तैयार हो। चीन इसी तर्क पर जोर देता रहा है और उसने जून, 1985 में पेशकश की कि भारत ल्हासा और शवाई में वाणिज्य दूतावास खोलें दे, जिसके बदले चीन भी कलकत्ता और बम्बई में ऐसे दूतावास स्थापित कर लेगा। चीन ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में विद्रोहियों को समर्थन देना लगभग बन्द कर दिया है। उसके प्रचार-प्रसार माध्यमों में भारत-विरोधी अभियान नहीं चल रहा है। वह कश्मीर का मामला न उधालते हुए उस भारत-पाक का द्विपक्षीय मामला बता रहा है और उसने कैलास-मानसरोवर में भारतीय तीर्थ यात्रियों के प्रवेश की इजाजत दे दी है। किंतु इस मिला-सिले में कोई आभावादिता बकार है, क्योंकि पिछले इस सालों में इस तीर्थ यात्रा के स्वरूप में कोई विस्तार नहीं हुआ है। न तो तीर्थ यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है और न ही इन पर चीनी सरकार की नियंत्रण में कोई रूमी आयी है। बराल्ता नेपाल बुनिया भर के विदेशी तिब्बत जा सकते हैं, परन्तु आम भारतीयों पर इसका लिए प्रतिबन्ध लागू है।

वेद का विषय यह है कि भारत-चीन सीमा समस्या की गुन्थी इतनी पेचीदा समझी जाने लगी है कि लोग यह मानकर चलते हैं कि इस कोई मुलझा ही नहीं सकेगा। इसीलिए कोई 'पक्षेधर राजनयिक' बीजिंग में भारत का राजदूत बनकर अपनी प्रतिष्ठा या भविष्य की दौब पर नहीं लपाना चाहता। यदि कभी वेंजेटेडरन या कै० पी० एम० मेन्टन जैसे योग्य व्यक्ति नियुक्त किये जाते हैं, तो ज्यादा दिन तक रहें बिना उन्हें वापस बुलाये भारत का नाम नहीं चलता। यही बात बमबम अन्य राजनेताओं पर लागू होती है। रक्षा मंत्री हो या विदेश मंत्री, सभी जानते हैं कि जड़ता तोड़ने वाला कदम सिर्फ प्रधानमंत्री ही उठा सकता है। नायद इसीलिए कोई अन्य व्यक्ति सामान्यीकरण की दिशा में कोई मार्थक कदम नहीं उठाता। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की विवशता यह है कि जब तक 'अनुकूल जमीन' तैयार न दिखायी दे, तब तक असफलता का जोखिम उठाना उस समझदार ही लगती।

भारत और चीन के बीच सीमा वार्ता के अब तक नौ दौर बिना किसी ठोस नतीजे के समाप्त हो चुके हैं। हरेक दौर के बाद राजनयिक शिष्टाचार निभाते हुए

निकटवर्ती अवसाई चिन तथा चिंगहेनम घाटी के क्षेत्र शामिल हैं। मध्य भाग में करीब 650 किलोमीटर लम्बी सीमा है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थिति, बाराहोती और नोलाग के पहाड़ी क्षेत्रों को अलग करती है। इसमें केवल 1600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र विवादास्पद है। पूर्वी भाग में 1100 किलोमीटर लम्बी सीमा है, जिसे मेकमोहन रेखा कहा जाता है। यह नेफा (वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश) को तिब्बत से अलग करती है। इसमें लगभग 50 हजार वर्ग किलोमीटर जमीन विवादास्पद है।

1. कोलम्बो योजना—1962 की सैनिक मिशन के कुछ समय बाद ही सीमा विवाद के हल के लिए छह अफ्रो-एशियाई देशों ने कोलम्बो योजना पेश की। इसमें तत्कालीन मौजूदा स्थिति को समझौते का आधार मानने पर बल दिया गया। चीन से कहा गया कि यह पश्चिमी क्षेत्र से अपनी सेना 20 किलोमीटर पीछे हटा ले और इस क्षेत्र में दोनों देशों का नागरिक प्रशासन कायम हो। पूर्वी क्षेत्र में पर्याप्तता का सुझाव दिया गया। मध्य क्षेत्र में 'लेन-देन' का रवैया अपनाते हुए बार्ता के जरिए हल की बात कही गयी। भारत यह योजना मानने को तैयार था, लेकिन चीन ने साफ इन्कार कर दिया, जिससे यह योजना खटाई में पड़ गई और उसके बाद सीमा-बार्ता के दौरान इसके जरिये हल की बात कभी नहीं उठी।

2. एकमुश्त समझौता—चीन सीमा विवाद के हल के लिए एकमुश्त समझौते की पेशकश (Package Deal Proposal) लम्बे समय तक करता रहा है। 1960 में चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चाऊ एन लाई ने सर्वप्रथम यह प्रस्ताव रखा था, जिस पर पिछले कुछ वर्षों से दैनिक सियाओ पिंग भी जोर देते रहे हैं। इसके तहत कहा गया कि सीमा विवाद के हल के लिए दोनों पक्ष एक-दूसरे को कुछ भू-भाग की छूट दें। चीन पूर्वी क्षेत्र में भारत को कुछ छूट दे और भारत चीन को 'वास्तविक नियन्त्रण वाली इलाक़ों' के आधार पर पश्चिमी क्षेत्र में। मौजूदा नियन्त्रण के तहत चीन पूर्वी क्षेत्र में मेकमोहन रेखा को मान ले और भारत 1962 में पश्चिमी क्षेत्र में चीन द्वारा जबरन हथियाये गये अवसाई चिन और और अन्य क्षेत्रों पर चीन का अधिकार मजूर कर ले। इसका मतलब यह हुआ कि इस एकमुश्त समझौते से भारत को न केवल अवसाई चिन, बल्कि 5000 वर्ग मील वाले उस अतिरिक्त इलाके से भी हाथ धोना पड़ेगा, जो 1962 के सैनिक-संघर्ष के दौरान चीन ने भारत से हड़प लिया था। इसी कारण भारत इस प्रस्ताव को मानने से इन्कार करता रहा है।

3. क्षेत्र दर क्षेत्र निपटारा—भारत सीमा विवाद का हल क्षेत्र दर क्षेत्र के हिसाब (Sectorwise Approach) से चाहता है। हालांकि इसका विस्तृत ब्योरा अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है, किन्तु भारत गीटे तौर पर चाहता है कि दोनों देश पूर्वी और मध्य देशों के विवादास्पद इलाकों का निपटारा पहले करें क्योंकि इनके हल में जटिल पेचीदगियाँ नहीं लड़ी होंगी। तत्पश्चात् पश्चिमी क्षेत्र के समाधान पर बातचीत आरम्भ की जाये। मगर चीन ने क्षेत्र दर क्षेत्र निपटारे का प्रस्ताव नहीं माना।

जब दोनों देशों ने एक-दूसरे के प्रस्तावों को नहीं माना तो अधिकारी-स्तर की बार्ताओं में इस बात पर ध्यान केन्द्रित किया गया कि सीमा विवाद के समाधान के लिए पथ-प्रदर्शक सिद्धान्त (guide lines) क्या हों? अब तक हुए बार्ता के नौ दौर में से पहले तीन दौर में कोई सास प्रगति नहीं हुई, मगर चौथे दौर में 'मामूली

दाना देगों का चाहिये कि वे इन वार्ताओं का पूरा वैकल्पिक तौर पर एक-दूसरे को साथ हीन वान ठाम प्रस्ताव तैयार करने पर ध्यान कन्द्रित करें। इससे सीमा-विवाद का विभिन्न जटिल पहलुओं पर ठाम चानचीन में मदद मिलेगी।

यह भी साधन की बात है कि मान लीजिए भारत चीन सम्बन्ध एक बार फिर से पुनरुत्थान में पहुँच जाते हैं तो वे कितना दूर एक ही वन रहेंगे? चीनी स्वभाव, परम्परा, आनीय स्मृति, एतिहासिक अनुभव आदि का बार में अनि सरलता निष्कर्षों का जामिम उठाया गया यह अटकल लगाई जा सकती है कि समय शक्ति का रूप में चीन का उभरना पड़ोसियों के लिए एक पचीसा चुनौती पेश करेगा। छोट्टा दुबला पड़ोसी आसानी से समझोता कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास और बाई विरल्य नष्ट होना भारत के लिए यह सम्भव नहीं। भारत-चीन सम्बन्धों का गणिता अनिर्वापत चीन रुम और चीन जमकेका व समीकरणों से जुड़ा हुआ है। स्मृतियों की कृता या मातुष की वान की इस हिमाय में कोई जगह नहीं। निरुद्धान दोन पक्षों के लिए आवश्यकतानुसार उपायों औरचारिक उभयपक्षीय राजनय ही लाभप्रद होगा। तहक युग के अनुभव और उमर बाद के दमका के घटनाक्रम से यही सबक मिलता है।

भारत श्रीलंका सम्बन्ध (Indo-Sri Lanka Relations)

भारत व श्रीलंका दोन पड़ोसी एवं गुप्त निरपण देश हैं। दाना के बीच अनेक समानताओं का गौरव मदन की दीवारों में कम ऊँची नष्टा रही है। औपनिवेशिक गुलामी से मुक्त होन के बाद दोन दाना के बीच चदन मुद्रा पर मामूली मतान्तर उभर कर अवश्य सामन आय सिन्धु स्थिति नियन्त्रण में रही। सक्रिय बुद्ध माना बाद दाना पक्षों के बीच अनेक समता पर विवादों ने गहराई लाई पैदा की। 1983 के बाद भी श्रीलंका में हिन्दी-नमिन मध्य न हिंसक माह के निपा और स्थिति काफा विस्फोटक बन गयी। इससे भारत-श्रीलंका सम्बन्धों पर बहुत बुरा असर पड़ा। 1987 में भारत-श्रीलंका समझोता होन के बावजूद उनमें मतभेदों की खाई पाती नहीं जा सती। मवाल उठता है कि दाना दाना के बीच आरम्भ में मामूली मतभेद क्या गहरा होन गये, जिहान द्विपक्षीय सम्बन्धों को मकट प्रमत्त बना दाना? इसका जवाब पान के लिए सबसेसम दाना के बीच प्रागैतिहासिक, पौराणिक व मासृत्तिक सम्बन्धों और भूराजनीतिक पक्ष पर प्रकाश डालना प्रासंगिक होगा।

एतिहासिक व सांस्कृतिक सम्बन्ध और भूराजनीतिक पक्ष—भारत श्रीलंका सम्बन्ध प्रागैतिहासिक व पौराणिक वान तक दूर जा सकते हैं। हिन्दुओं के महासम्य रामायण में तका द्वीप का उल्लेख मिलता है। बौद्ध जातका आदि में इस द्वीप के निवासियों के साथ भारत के नामप्रद व्यापार, मासृत्तिक आदान प्रदान की स्मृति पाए हैं। मस्रष्ट व्याप्त न बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र एवं पुत्री का श्रीलंका नवा पा। चीनी यात्री फाह्यान व ह्वान साय आदि ने भारतीय भू-भाग के के साथ हिन्दी द्वीप श्रीलंका के वासियों के पनिष्ठ सम्बन्धों का ब्योरा दिया है। यह कहना अतिवाक्तिपूर्ण नहीं होगा कि यह द्वीप न ही मन्नार की खाड़ी की जल राशि द्वारा मुख्य भाग से कटा होन के कारण विदेशी आक्रमणकारियों के हस्तक्षेप से

कहा गया कि 'दोनों देशों के बीच बाताई सद्भाव और मैत्रीपूर्ण वातावरण में हुई और इससे एक दूसरे के दृष्टिकोण समझने में काफी मदद मिली। दोनों पक्षों ने सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी आदान-प्रदान के बारे में साभयद बाताई की।' मविध्य के बारे में उम्मीद बायने के लिए कहा गया कि 'दोनों देश अगले दौर की बाताई करने पर राजी हो गये हैं।' ऐसी आशाजनक बातें 'औपचारिक शिष्टाचार' और 'शांतिन' तौर-तरीकों का परिचय अवश्य देती हैं, किन्तु बुनियादी सीमा विवाद के हल की दिशा में जल्दोदनीय प्रगति का होस सकेत नहीं। यह भी कम आश्चर्यजनक नहीं कि सातवें दौर की बातचीत में अरुणाचल प्रदेश के समदोरोम धु पाटी इलाके के बागदोम में हुई चीनी घुमोंठ पर लम्बी बातचीत हुई, लेकिन यह मामला भी नहीं सुलझ पाया। चीन इस बात पर अडा रहा कि यह क्षेत्र वास्तविक नियन्त्रण रेखा के उत्तर में है और उसके इलाके में परता है। ऐसी परिस्थितियों में क्या यह प्रदन किहू जोड़ना उचित नहीं कि दोनों देशों में जल्दी-जल्दी होने वाली सीमा बाताई अपना औचित्य खोती जा रही हैं। निष्कर्षतः दिसम्बर, 1981 से अब तक हुई नौ धार की सीमा बाताई 'नौ दिन चले हाई कोम' वाली कहावत ही चरितार्थ करती रही है।

राज्यीय माथी की चीन यात्रा (दिसम्बर, 1988)—तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव माथी तरह-तरह की अटकलों के बीच चीन की पाँच दिवसीय यात्रा पर निकले। कई लोगों को इस बात पर आपत्ति थी कि जब तक चीन सम्बन्धों में सामान्यीकरण का आश्वासन (अनौपचारिक ही रही) न है, तब तक भारत को अपनी राजनयिक प्रतिष्ठा बाब पर नहीं लगानी चाहिए। कुछ अन्य लोगों का मानता था कि राजीव माथी की चीन यात्रा 'महत्त्व बुनावी हथकंडा' थी।

इस यात्रा के दौरान राजीव माथी की चीन के सर्वाधिक शक्तिमाली नेता डैंग सियापोंग शिग और अन्य नेताओं, अधिकारियों से बातचीत हुई। मगर सीमा विवाद के हल और सम्बन्धों के सामान्यीकरण की दिशा में कोई ठोस उपलब्धि हासिल नहीं हुई। यदि बस्तुनिष्ठ ढंग से देखें तो किसी भी भारतीय प्रधानमन्त्री द्वारा भारत-चीन सम्बन्ध गुधार के लिए कोई होस पेशकश करना जोसिम भरत नाम ही है। राजीव राज किता नाटकीय सुधार की आशा करना स्पष्ट है। बहुश्रुत, श्री माथी की चीन-यात्रा राजनयिक दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण नहीं लगती जा सकती।

दिसम्बर 1991 में चीन के प्रधान मन्त्री ली केंग ने भारत यात्रा की—31 साल के बाद कोई चीनी प्रधान मन्त्री भारत आया—राजीव माथी ते जो चीन की यात्रा इससे तीन साल पहले की थी, चीन के प्रधान मन्त्री की यह यात्रा सम्बन्धों के सामान्यीकरण के उनी प्रयास की एक कड़ी मानी गई। दोनों देशों में इस बात पर सहमति प्रकट की कि सीमा विवाद के संगोषजनक हल होने तक वास्तविक नियन्त्रण रेखा पर सान्ति बनाए रखनी जाए। साथ ही यह भी घोषणा की गई कि इस विवाद के हल की सोत्र का नाम तेज किया जाय। भारतीय प्रधान मन्त्री नरसिंह राव के अनुसार सीमा विवाद पर हुई धर्चा की समीक्षा की जायेगी तथा सीमा विवाद के हल के लिए तीन मास पहले बरिष्ठ समुक्त आधिकारी दल के कार्य में तेजी लाई जाने की कोसिदा की जायेगी। दोनों देशों के प्रधान मन्त्री इसमें व्यक्तित्व दिसचस्पी सेते।

उपरोक्त विनिेषण से स्पष्ट है कि सीमा बाताई के दौरान दोनों पक्षों में अब तक बाताई के स्वरूप, औपचारिकताओं, स्तर तथा पक्ष-प्रदर्शक सिद्धान्त तय करने में ही समय गैरवाया है। क्या ये बाताई मान अनुष्ठान बनकर नहीं रह गयी हैं?

से दें तो हम तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि नेहरू, मेनन आदि के अहमारी आवरण से भारत के छोटे पड़ोसी देशों का खिन्न होना स्वाभाविक था। श्रीलंका जैसे देश एक तरह की आश्रयकता ओडन को विवश थे, ताकि भारत जैसे बड़े पड़ोसी देश के मुकाबले वे अपनी आजादी को प्रमाणित कर सकें।

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान श्रीलंका की आन्तरिक राजनीति में जो परिवर्तन हुए, उन्होंने भी 1947 के बाद भारत और श्रीलंका के बीच तनाव पैदा किये। भारत की तरह औपनिवेशिक शासन व उत्पीड़न के विरुद्ध कोई व्यापक जन-आन्दोलन या स्वाधीनता संग्राम श्रीलंका में नहीं हुआ। परन्तु श्रीलंका में राजनीतिक चेतना का आविर्भाव मिहली राष्ट्रवाद के विकास के माध्यम हुआ। दूसरी ओर भारतीय मूल के श्रीलंकावासी समिल लोग अपने नेताओं के माध्यम से ही सही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संचालित उपनिवेशवाद विरोधी आन्दोलनों से जुड़े रहे। बी० बी० गिरी जैसे लोग श्रीलंका में ट्रेड यूनियन गतिविधियाँ से जुड़े रहे।

1950 के दशक के मध्य तक दो-तीन परस्पर विरोधी प्रवृत्तियाँ स्पष्ट हो रही थी। एक ओर नेहरूयुगीन भारत श्रीलंका को किमी सैनिक सगठन का सदस्य न होने पर भी अपनी तुलना में कम गुट निरपक्ष और औपनिवेशिक शक्तियों का पक्षधर समझना था तो दूसरी ओर श्रीलंका की सरकारें अपने दैत्यकार पड़ोसी देश भारत के इसदो के बारे में आशंकित रहती थी और उन्हें भारतीय नेताओं का बड़े भाई जैसा आवरण रास नहीं जाता था। श्रीलंका में जिन बक्त सोनोमन मण्डारनायके की श्रीलंका फ्रीडम पार्टी मिहली भाषा और बौद्ध धर्म को आधार बनाकर अपनी जड़ें मजबूत कर रही थी उस समय भारत व दक्षिणी राज्यों में तमिल पुनर्जागरण का दौर चल रहा था। इसका प्रसार श्रीलंका के तमिलों तक होना अवश्यभावी था। औपनिवेशिक शासन की समाप्ति के साथ श्रीलंका की सामाजिक व आर्थिक संरचना में परिवर्तन भी अनिवार्य थे। इनमें पैदा हान वाले तनाव कई बार साम्प्रदायिक घन्टावली में मुखर हुए। श्रीलंका के उदीयमान मिहली नेताओं के लिए यह सहज था कि वे अपनी हताशा व आक्रामकता निशाना उन अल्पसंख्यक तमिलों को बनायें, जो बहुसंख्यक जनता की तुलना में अधिक ममूद-मनुष्ट दीखत थे। साथ ही माय लदाना व वागानो में काम करने वाले तमिल श्रमिकों की स्थिति में ह्रास होता गया और उनके मन में स्वदेश लौटने की ललक बढ़ने लगी। इन सब बातों का समुक्त परिणाम यह हुआ कि जब श्रीलंका में संविधान बनाने का बीड़ा उठाया गया तो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ रहते आये अनर तमिलों ने अपने को नागरिकता के अधिकार से वंचित पाया। एक तरह से हम समस्या की तुलना बर्मा व मलाया में रहने वाले प्रवासी भारतीयों से की जा सकती है, परन्तु भौगोलिक सामीप्य विशेषकर तमिलनाडु (मद्रास) में तमिल पुनर्जागरण ने हम समस्या को कहीं अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। 1972 तक मिहली-तमिल समस्या नियन्त्रण में रही। इसका एकमात्र कारण नेहरू जी का करिदमावी नृत्व और भारत की अन्तराष्ट्रीय प्रतिष्ठा थी। परन्तु भारत-चीन विवाद के उभरने के साथ भारत-श्रीलंका सम्बन्धों में नाटकीय परिवर्तन हुआ।

चीन के प्रति श्रीलंका का झुकाव—भारत-चीन सीमा विवाद के माय यह बात मानन आयी कि श्रीलंका का झुकाव पड़ोसी भारत की ओर नहीं, बल्कि दूरस्थ चीन के प्रति है। यो बढ़ने को श्रीलंका ने भारत-चीन सीमा विवाद के प्रति गुट

बचा रहा तथापि आर्थिक व सांस्कृतिक दृष्टि से इसे भारत से 'अलग' करना कठिन है। नेहरू जी ने एक बार यन्त्र नहीं कहा था कि 'श्रीलंकावासी' हमारे ही हाड़-मांस के दाने हैं और हम उनकी निर्वृत्ति से बचने नहीं रह सकते।'

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस बात को स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि जो लोग आज अपने को श्रीलंका का मूल निवासी बताते हैं, या सिंहली भूमि पुत्र घोषित कर रहे हैं, वे हजारों वर्ष पूर्व भारत के पूर्वी तट (वर्तमान में उड़ीसा) से यहाँ गये थे। पिछले कुछ वर्षों से श्रीलंका में जिन तमिलों के साथ गृह युद्ध की सी स्थिति चल रही है, वे भी सदियों पहले वर्तमान तमिलनाडु से इस द्वीप में जाकर बसे। श्रीलंका की आजादी का जातीय व भाषायी विस्फेपण किया जाये तो भारत के साथ उनके घनिष्ठ सम्बन्धों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने इन सम्बन्धों को और पुराना किया। ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के लिए भारत उनके औपनिवेशिक साम्राज्य की 'मुकुट मणि' था और श्रीलंका, बर्मा, अफग, सिंगापुर आदि देश इस बहुमूल्य निधि की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण थे। भारत में नियुक्त गवर्नर जनरल या बायसराय इन सब पर नियन्त्रण रखने वाला लगभग निरंकुश अधिकारी होता था। इस व्यवस्था में भारतीय औपनिवेशिक प्रशासन की केन्द्रीय भूमिका थी। अंग्रेजी भाषा, शिक्षा प्रणाली, प्रिवी काउंसिल वाली न्याय व्यवस्था तथा औपनिवेशिक आर्थिक स्वाधों के लाने-बाने के कारण भारत व श्रीलंका दोनों के बीच पारम्परिक सम्बन्धों का आधुनिक स्यान्तरण हुआ।

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान श्रीलंका में ब्रिटिश नौसैनिक मुख्यालय की स्थापना की गयी और लार्ड माउण्टबेटन के नेतृत्व में भारत के लिए इस द्वीप का भू-राजनीतिक महत्व माटकीय ढंग से उद्घाटित हुआ। इस सच्चे अलावा औपनिवेशिक काल में बहुत बड़े पैमाने पर भारत से बम्बुआ मजदूरों का निर्यात श्रीलंका की खदानों व बागानों पर काम करने के लिए किया गया। कालक्रम में इसने श्रीलंका की जनसंख्या का स्वरूप बदल डाला और राजनीतिक समीकरणों को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित किया। दो पीढ़ी के अन्तराल में ही भारतीय भाषावासी अपने उद्यम और बर्मंडता से प्रशासन, शिक्षा, व्यापार एवं व्यवसाय में बेहद महत्वपूर्ण बन बैठे और आजादी प्राप्त होने के बाद वे भारत-श्रीलंका सम्बन्धों को अनुसासित करते रहे हैं।

आजादी के बाद भारत-श्रीलंका सम्बन्ध—1947 में आजाद होने पर भारत राष्ट्रमण्डल का सदस्य बना रहा और नातेदारी के कारण प्रारम्भिक चरण में श्रीलंका के साथ उसका सौहार्द बना रहा। इसके तत्काल बाद भारत ने गुट निरपेक्ष नीति का चरण किया और भारत के साथ श्रीलंका के विवाद संतुह पर आने लगे। श्रीलंका के तत्कालीन प्रधान मंत्री सर जेन कोटनेवाला दक्षिणपथी रतान के परिचय-परस्त व्यक्ति थे। उनका मानना था कि गुट निरपेक्षता की वितासिता भारत जैसा बड़ा देश ही मह सकता है। श्रीलंका जैसे छोटे देश के लिए सामूहिक सुरक्षा परियोजनाएँ व मैत्रिक सन्धि नकल हो उपयुक्त हो सकते हैं। इसी निदान के अनुसार उन्होंने श्रीलंका में 'बांग्ला आरु जमरीका' को प्रसारण की अनुमति दी और ब्रिटेन को अपने पक्ष में रखने के लिए आजादी की घोषणा के बाद भी एक बड़ी सीमा तक औपनिवेशिक सामग्राह्य की बरकरार रखा। बाइस सम्मेलन (1955) में गुट निरपेक्षता को लेकर नेहरू जी के साथ उनकी काफी गोरु-गोरु हुई। वस्तुनिष्ठ ढंग

नहीं पड़ा। भारत द्वारा श्रीलंका को कच्चा तिवु द्वीप समूह सौंपे जाने पर मद्भावना का भण्डार और नी बड़ा। श्रीलंका में 1971 में जब त्रोटस्कीवादी सिंहली युवकों ने हिंसक बगावत की तो बिद्रोह दमन के लिए इन्दिरा सरकार ने सिरिमाओ भण्डारनायके सरकार को तत्काल भारतीय सैनिक सहायता पहुँचायी। जून, 1975 में भारत में आपातकाल की घोषणा के बाद जिन गिनी-चुनी सरकारों के साथ इन्दिरा गांधी के सम्बन्ध सधुर बने रहे, उनमें श्रीलंका एक था। विवादों को अनदेखा करने और सहकार के क्षेत्र को बड़ावा देने वाली यह स्थिति सिरिमाओ भण्डारनायक और इन्दिरा गांधी के कार्यकाल तक बनी रही। यह भी एक संयोग ही था कि भारत में इन्दिरा गांधी और श्रीलंका में सिरिमाओ भण्डारनायके 1977 में लगभग एक साथ अपदस्थ हुए। दोनों नेताओं पर तानाशाही और भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये। दोनों देशों में उत्तराधिकारी सरकारों ने चली आ रही नीतियों में बुनियादी परिवर्तन करने का प्रयत्न किया। 1980 में इन्दिरा गांधी के पुनर्-सत्ता में आने के बाद भारत-श्रीलंका सम्बन्धों में बड़ी अड़चन पैदा हुई।

भारत-श्रीलंका सम्बन्धों में पुनः बिगाड़—श्रीलंका के राष्ट्रपति जूनीयस जयवर्द्धने ने 1977 में सत्ता में आने के बाद महत्वपूर्ण संवैधानिक परिवर्तन किये और देश के आर्थिक बिगाड़ के लिए दक्षिणपंथी मुक्त व्यापार वाला मार्ग चुना। 1971 के बाद सोवियत संघ के साथ भारत के विशिष्ट सम्बन्धों की घनिष्ठता को दलते हुए भारत के साथ श्रीलंका के शारम्भिक मतभेद अवश्यम्भावी थे। जयवर्द्धने के लिए श्रीमाओ शास्त्री समझौते की कोई अहमियत नहीं थी और उनके कार्यकाल के आरम्भ से ही इसकी शर्तों की अवहेलना की गयी। जयवर्द्धने मद्रिभण्डल के गरम मित्राज सदस्य प्रेमदाम, ललित अबुलथमुददी सरकार का भ्रमश 'मिहसीवरण' करने में सफल हुए। इनकी यह पाकर सेना व पुलिस के सह-सैनिक दस्ते निरीह-निर्धन तमिलों पर अत्याचार करते रहे। श्रीलंका की राजधानी कोलम्बो से दूर उत्तरी छोर में रहने काल तमिलों की यह वाचिव धिक्कायत रही कि सिंहली लोगों द्वारा उनकी भूमि का औपनिवेशिकीकरण किया जा रहा है, उनकी भाषा का अवमूल्यन हो रहा है तथा उनके पूजा-उपासना भ्रष्ट कर परोक्ष रूप से उनके वंशनाश का पदग्रन्थ जारी है। 1980-81 तक कुछ तमिल युवकों ने अपना आश्रीत मुनर करने के लिए आतङ्कवाद का मार्ग चुन लिया और पश्चिमी देशों की सतर्क पत्र-पत्रिकाओं में 'तमिल चीतों' की दिग्दर्शक कार्यकारियों के बारे में लेख, बित्र आदि छपने लगे। इसमें भारत-श्रीलंका सम्बन्धों में तनाव पैदा हुआ। इस वर्षों तक भारत के दक्षिणी प्रान्त तमिलनाडु में मत्तारुढ दल अन्ना द्रमुक मुनेत्र कण्णम (अन्ना द्रमुक) श्रीलंका में तमिलों का पक्षधर रहा। तमिलनाडु में तब मत्तारुढ द्रविड मुनत्र कण्णम (द्रमुक) की सरकार का भी ऐसा ही रवैया रहा। श्रीलंका सरकार का यह शक निराधार नहीं कि तमिल चीतों को भारत से सहायता और भारतीय भूमि पर प्ररण मिलनी रही है।

श्रीलंका में उपवादी साम्प्रदायिक हिंसा का विस्फोट—1983 का आरम्भ तक जातीय तनाव की यह स्थिति विस्फोटक बन चुकी थी। इसका बर्दाश्त न कर पाया श्रीलंका के उत्तरी प्रांत जाफना में बहुमुखक जनता तमिल वसाज है। पूर्वी इलाक बट्टीगमाओ और त्रिबोयानी में भी तमिल आवादी बांधी पनी है। इन तमिलों को लगन लगा कि जयवर्द्धन सरकार उनका अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ है।

निरपेक्ष तथा तटस्थ रवैया अपनाया परन्तु पारम्परिक सम्बन्धों और भू-राजनैतिक स्थिति को देखते हुए उसका स्वरु संकट की घड़ी में भारत को अकेला छोड़ देने वाला था। यह रेखांकित किया जाना जरूरी है कि चीन के सितसिते में श्रीलंका की कोई विवशता नेपाल, बर्मा और भूटान जैसी नहीं थी। श्रीलंका को किसी चीनी हमले का खतरा नहीं था। कम से कम इस समय तक श्रीलंका को चीन से मिलने वाली आर्थिक सहायता भी नाममात्र की थी।

यह सोचना तर्कसंगत है कि यदि श्रीलंका ने भारत के प्रति विशेष अन्तरंगता नहीं दर्शायी तो उसका उद्देश्य 'मैत्री की कीमत' बढ़ाना था। इस समय तक श्रीलंका के तमिलों और सिंहली लोगों में पुनाबी राजनीति के प्रसार के साथ बहुतायुक्त वैमनस्य बढ़ने लगा था। और तारकी तमिल अपने भविष्य के बारे में चिन्तित थे। श्रीलंका सरकार की दृष्टि में तमिलों की देशभक्ति सदृश्य थी और एक सिंहली उपद्रवादी द्वारा प्रधानमन्त्री सोलोमन भण्डारनायके की हत्या के बाद सिंहली साम्प्रदायिकता के प्रति श्रीलंका सरकार उदासीन नहीं रह सकती थी। कुछ विद्वानों ने यह भी सुझाया कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में गतिरोध और चीन व पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों में तनाव-वृद्धि के संयोग ने श्रीलंका को भारत से अलग अपना मार्ग चुनने के लिए प्रोत्साहित किया। 1961 में बेलग्रेड में आयोजित पहले गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में नेहरू जी तथा मुक्तियों की भिड़त ने यह बात उजागर कर दी थी कि तीसरी दुनिया के सभी देश भारत को अपना मुनिया नहीं मानते। यह स्वाभाविक था कि भारत के पड़ोसी देशों ने अपने राष्ट्रीय हित में इनका लाभ उठाने का प्रयत्न किया।

शास्त्री-तिरिमाओ समझौता—भौमायवश, नेहरू जी के उत्तराधिकारी जाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में भारत-श्रीलंका सम्बन्धों में आघातीत सुधार हुआ। अपने शत्रुओं चीन और पाकिस्तान के प्रति सख्त यथार्थवादी रुख अपनाने के कारण शास्त्री-युगीन भारत का मनोबल सुधरा। दूसरे, अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में विश्वव्यापी रुचि न रखने के कारण शास्त्री जी के पास पड़ोसी देशों के लिए अधिक समय था। इसके अतिरिक्त शास्त्री जी के साथ राजनयिक परामर्श करने वालों को यह अहमाम कतई नहीं होता था कि वे स्वयं सुच्छ या बीन हैं। इस दृष्टि में मुक्त होने पर वे आसानी से रियायतें दे सकते हैं। 1965 में तिरिमाओ भण्डारनायके और शास्त्री जी के बीच हुए समझौते के तहत भारत सरकार ने श्रीलंका में बसे लगभग दो लाख कारकिर्ता-विहीन तमिलों को ग्रहण करना स्वीकार किया। उनमें ऐसा एक मानवीय समस्या के समाधान की प्राथमिकता देते हुए किया। दूसरी ओर श्रीलंका सरकार ने यह बात स्वीकार की कि बचे हुए तमिलों को यथाशीघ्र नागरिकता प्रदान की जायेगी और उनके साथ किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं बरला जायेगा। इसी समझौते में भारतीय और श्रीलंकाई मधुआरों के मधुनी पर करने वाले क्षेत्र के भौमान्न का मूलपात्र भी विषय गया।

इन्दिरा-तिरिमाओ काल : पविष्ठ सम्बन्धों का दौर—शास्त्री जी के बाद इन्दिरा गांधी भारत की प्रधानमन्त्री बनी। उनके कार्यकाल में भारत और श्रीलंका के बीच सम्बन्ध और भी पविष्ठ हुए। दोनों देशों की महिला प्रधानमन्त्री (इन्दिरा गांधी व तिरिमाओ भण्डारनायके) स्नेह, राजनीतिक रुझान व कार्यशैली में एक-दूसरे के करीब थी। इसी कारण उनके बीच मार्थक राजनीतिक भवाद में कोई व्यवधान

हो गया। इसके साथ ही इस बात को अनदेखा करना कठिन है कि तमिल छापामारो को मिलने वाली सैनिक सहायता भारत के माध्यम से ही पहुँच रही थी। यह सच है कि भारत सरकार का इससे सीधा लेना-देना नहीं रहा, तथापि उसने तमिलनाडु की अन्ना द्रमुक सरकार की सहानुभूति और खुले समर्थन पर कोई रोक लगाने का प्रयत्न नहीं किया। उससे थ्रीलका का सिद्ध होना स्वाभाविक था। जयवर्द्धने और उनके सहयोगियों को यह लगता रहा कि भारत में सत्ताह्द काग्रेस पार्टी तमिलनाडु में अपनी सहयोगी अन्ना द्रमुक पार्टी को अप्रसन्न नहीं करना चाहती। तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव रमण भण्डारी थ्रीलका के साथ मुलह वाला तचीला मार्ग सुझाते थे, परन्तु प्रधानमन्त्री के अन्य वरिष्ठ सलाहकार जी० पार्षसारपी, वेंकटेश्वरन, रंगराजन, कुमारमगतम आदि अति यथार्थवादी ढंग से सख्त रह अपने-अपने के हिमायती थे। परिणामस्वरूप, 1984-85 में स्थिति जटिलतर तथा और अधिक जाह्नमग्रस्त हो गयी। 1986 में बंगलूर में आयोजित सार्क (SAARC) शिखर सम्मेलन के दौरान इस समस्या का नाटकीय राजनीतिक समाधान का प्रयत्न किया गया, परन्तु इसमें कोई प्रगति नहीं हो सकी। इससे पहले भी थिम्पू वार्ताओं की सम्भावनाओं का आर-शोर स प्रचार किया गया, किन्तु तमिल उग्रवादियों की हठमतिता के कारण कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया।

इस समस्या के हल में परेशानी के कई कारण थे। जहाँ एक ओर भारत सरकार तमिल छापामारो पर एक सीमा तक ही दबाव डाल सकती थी, वही तमिलों के लिए थ्रीलका सरकार की दिव्यमनीयता समाप्त हो चुकी थी। उन्हें लगता था कि थ्रीलका सरकार वार्ताओं के बहाने मिफं इस बात की मोहलत चाह रही है कि मैनिम दस्ता को समुचित ढंग में नैनात कर समस्या का निर्णायक हिसक समाधान किया जा सके। यह सच भी है कि 1986 के दौरान जयवर्द्धने सरकार के आचरण से ऐसा नहीं लगता था कि जयवर्द्धने भारत सरकार की मध्यस्थता की कोई अकुरत समझते हैं। जयवर्द्धने ने स्वयं कई बार भडकाने-उबसाने वाले ढंग में यह घोषणा की कि आपातकाल में वह अपने देश की अखंडता की रक्षा के लिए बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप को सहर्ष निमग्नण देंगे। थ्रीलका में बड़े पैमाने पर इजराइली, दक्षिण अफ्रीकी, पाकिस्तानी, ब्रिटिश और अमरीकी सैनिक सलाहकार तथा भाड़े के सैनिक तैनात किए गए और इस तरह के सकेन मिल कि शिकोमाली का महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डा अमरीका का सौंपा जायेगा। यह सारा सामरिक घटनाक्रम भारतीय सामरिक हितों के प्रतिमूल था। इनके अलावा स्वयं थ्रीलका के नौसैनिक अधिकारियों का आचरण उत्तरोत्तर भडकाने-उबसाने वाला बनता गया। मद्रास की छाडी में रामेश्वरम के ममीप मछली पकड़ने वाले अनेक निरीह मछुआरों की जानें इन दिनों गयी और उनके जीविकोपार्जन में बाधा पड़ी। थ्रीलका से तमिलनाडु पहुँचने वाले शरणार्थियों की संख्या मगवह ढंग में बढ़ने लगी और बंगला देश का प्रसंग अनायास याद आने लगा। अब थ्रीलका की समस्या मिफं तमिलनाडु की दृष्टि का नहीं, बल्कि भारतीय विदेश नीति के सन्दर्भ में प्राथमिक महत्व का विषय बन गयी।¹

एक ओर घटनाक्रम ने स्थिति को मकटाकीर्ण बनाया। तमिल छापामारो का नेतृत्व कालक्रम में मध्यममार्गी-ममदीय विपक्षियों के हाथों स निरल कर हिसक

¹ देखें—V. P. Vaidik, *Ethnic Crisis in Sri Lanka* (Delhi, 1986).

उन्हें इस सरकार की नीयत और इरादों पर सन्देह होने लगा था। न केवल सेना और सरकारी नौकरी में नियुक्त किये जाने वाले तमिलों का अनुपात तेजी से घट रहा था बल्कि बड़े पैमाने पर देश के और भागों से सिहूलियों को लाकर जाफना में बसाने के प्रयत्न किये जा रहे थे। नवामन्तुक सिहूलियों के प्रति तमिलों का रोष-आक्रोश स्वाभाविक था। चूँकि इन सिहूलियों को पुलिस और सेना का समर्थन एवं संरक्षण प्राप्त था, जिस कारण उनका प्रतिरोध करना आसान नहीं था। सिहूलियों ने उत्तरी और पूर्वी प्रान्त के मूल तमिल निवासियों को अनुशासित रखने के लिए आतंक का सहारा लिया। निर्दोष तमिलों की बलात्कार, आगजनी, लूटपाट का शिकार बनाया गया।

अब तक 'ईलम' अर्थात् तमिलों के स्वाधीन राज्य की माँग इस्लाम-दुश्मन जोशीले तमिल चीत हो उठा रहे थे। अधिकांश तमिलों के लिए ईलम का अर्थ था—उत्तरी तथा पूर्वी प्रांत में स्वायत्त प्रशासन। लेकिन सिहूलियों की बर्बरता ने अनेक मध्यमार्गी तमिलों को भी यह सोचने को विवश किया कि स्वायत्तता नहीं, स्वाधीनता में ही उनकी मुक्ति है। जब स्थानीय प्रशासन मिहली पक्षधरता के कारण तमिलों को बचाने में असमर्थ हो गया तो तमिल युवकों ने अपने लोगों को बचाने की जिम्मेदारी उठायी और इन तमिल चीतों की छापाकारी में तेजी से वृद्धि हुई। जाफना में मानवाधिकारों के हनन के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय जनमत बनाने के लिए तमिल उपद्रवादी छापाकार सनसनीखेज आतंकवाद का सहारा लेने को बाध्य थे। उनके पट्टमन्नों के शिकार इस इलाके में बड़ी संख्या में वैवात सिहली पुलिस एवं सैनिक अधिकारी हुए। अपने साथी जवानों की मौत का बदला लेने के धनकर में मिहली सैनिक एवं सह-सैनिक दलों का आचरण क्रमशः लगभग पामादिक हो गया। जो तमिल युवक भरपूर में गिरफ्तार होते, उनका जेल में अमानवीय यातनाएँ दी जाती और उनके स्वजनों व मित्रों की भी उल्टीठक गन्धणा का शिकार बनना पड़ता। दंगों के समय के घहाने श्रीलंका की जेलों में बड़ी संख्या में तमिल बन्दिनों की हत्या की गयी। इस प्रकार असन्तुष्टों के नेताओं का मकसद करने का प्रयत्न किया गया। इस क्रिया-प्रतिक्रिया ने हिंसा के दुष्चक्र को बढ़ाया। अनुराधापुर के हत्याकाण्ड ने इस बात की कोई मुजाइरा नहीं छोड़ी कि बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक रक्तपात को टाला जा सके। इसके बाद कोलम्बो शहर को आगजनी की लपटों में झुलमना पड़ा और लगातार कई हफ्तों तक इस राजधानी की कर्मप्रस्त रचना जरूरी हो गया। जाफना में लगभग गृह युद्ध वाली स्थिति पैदा हो गयी और सिहली सैनिकों को अपने शत्रु के रूप में देखने लगे। इस प्रकार तमिल उपद्रवादी एक तरह का समानान्तर प्रतिद्वन्द्वी प्रशासन स्थापित करने में सफल हुए।

एक ओर श्रीलंका सरकार के लिए यह समस्या रही है कि यदि वह छापा-कारों का उन्मूलन किंव बिना तमिलों की माँग मान लेती है या उनसे बातचीत करने को राजी होती है तो इसको परिणति देश के विभाजन-विघटन में ही हो सकती है। दूसरी ओर कोई भी जिम्मेदार सरकार इस बात को अनदेखा नहीं कर सकती कि बुल आबादी के लगभग 19-20 प्रतिशत हिस्से की जायज माँगों को अनदेखा कर बहुमत के नाम पर साम्प्रदायिकता का जहर फैलाने दिया जाये। दुर्भाग्यवश जयवर्द्धने के मन्त्रिमण्डल में भुटनेइ-पसन्द उपद्रवियों के गतिजाली हो जाने में राष्ट्रपति जयवर्द्धने के लिए तमिलों के साथ मवाद शुरू करना बहुत कठिन

से सिंहली सैनिका का हटाकर तमिल और भारतीय सैनिकों को एक-दूसरे के सामने खड़ा कर दिया। राहतकारी हस्तक्षेप की बदनामी के बाद पड़ोसी देश में सैनिक उपस्थिति का खर्च और बोझ भारतीय राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक ही हो सकता था।

जनवरी, 1989 में श्रीलंका में प्रेमदास ने राष्ट्रपति पद सम्माला। आरम्भ में भारत के प्रति उनका रवैया सयत और जिम्मेदार नजर आया, किन्तु कुछ ही दिनों बाद उन्होंने श्रीलंका के जातीय तनाव के लिए भारत को कोसना और शान्ति सेना की वापसी की मांग जोर-शोर में शुरू कर दी। अन्ततः मार्च, 1990 तक भारत ने शान्ति सेना (Peace Keeping Force) की सभी टुकड़ियों को स्वदेश बुला लिया। इसके बावजूद श्रीलंका में जातीय समस्या की गुत्थी मुलमने के बजाय उलझती ही गयी।

शान्ति सेना की वापसी के बाद भारत-श्रीलंका सम्बन्ध

दशकों में यह बात कही जाती रही है कि भारत और श्रीलंका आपस में अमित्र रूप से गुंथे हैं। हम लोग एक ही हाड-भास के हैं और हमारे राष्ट्रीय हितों में कोई टकराव हो ही नहीं सकता। दुर्भाग्यवश कट्टर यथार्थ इस सदाशयी भावुकता को हमेशा झुठलाता रहा है। पिछले छह-सात वर्षों के अनुभव के बाद यह सोच मक्का सम्भव है कि निरुद्ध भविष्य में कभी भारत और श्रीलंका के सम्बन्ध, मैत्रीपूर्ण तो छोड़िए, सामान्य भी होंगे।

श्रीलंका साम्प्रदायिक गृह युद्ध के कारण मक्का के कगार पर खड़ा है। विडम्बना यह है कि यह कोई निर्णायक घड़ी नहीं। श्रीलंका से भारतीय शान्ति सेना (मार्च 1990) लौटने के बाद युद्ध विराम कुछ ही महीने जारी रहा। लिट्टे और श्रीलंकाई सैनिकों की हिंसक मुठभेड़ फिर से शुरू हो गई। उपपक्षी तमिलों का मामला करने के लिए श्रीलंका ने वायु सैनिक बमबारी का नूतन रास्ता तनाया। दश के दक्षिणी भाग में ज० वी० पी० के हिंसक आतंकवादियों के बीच फूट के बीज बोने और उन पर काबू पान के बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति प्रेमदास का मनोबल फिलहाल मजबूत है। दूसरी ओर भारतीय शान्ति सैनिकों की क्षमता पर प्रश्न चिह्न उगाने के बाद लिट्टे के मुक्ति चीत भी सम्पूर्ण ममझौते के लिए तैयार नहीं। यह स्थिति भारत-श्रीलंका सम्बन्धों के लिए निश्चय ही दुःखदायी है। यदि श्रीलंकाई सैनिक तमिल आतंकवाद का उन्मूलन करने में विनम्ब करते हैं तो सरकार के लिए अपनी अमफनता के लिए भारत वाला बहाना पत्र करना ही बचा रहगा। प्रेमदास जब यह आक्षेप लगायेंगे कि प्रभावजनक बर्बर मित्र इमीनिए रणक्षेत्र में बच है कि उन्हें भारत में निरन्तर महायत्ना भिन रही है। यह सच है कि तमिलनाडु की बहुमन्थ जनता की महानुभूति और ममर्षन लिट्टे को प्राप्ता है, परन्तु इसके लिए नई दिल्ली सरकार उत्तरदायी नहीं ममझी जा सकती।

यदि सिंहली सेना लिट्टे का मफाय करे म, या कम से कम ज० वी० पी० के तरीके पर कुछ बड़े मलाओ का ही मही, दमन-ममन करती है तो भी यह स्थिति भारत के लिए बहुत अनुकूल नहीं ममझी जा सकती। शान्ति रक्षक सैनिक दस्तों की वापसी से लिट्टे छापामारों के प्राणों की और श्रीलंका के राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा एक माय हा सकती और इस घटनाक्रम में अन्तर्राष्ट्रीय रणमंच पर हस्तक्षेपकारी कार्य

छापामारों के पास चला गया। 'तुल्फ' (तमिल लिबरेशन फ्रंट) के अमृतलिंगम जैसे नेता भुला-मिट्टा दिखे गये और 'लिट्टे' (लिबरेशन टाइम्स आफ तमिल ईलम) के प्रभाकरण और किट्टू जैसे नेता चर्चित बन गये। तमिल गिरोहों के आपसी वैमनस्य ने भी प्राणनाशक संघर्ष का रूप ले लिया और अन्ततः 'लिट्टे', 'प्लोट', 'इरोस' आदि गिरोहों के आपसी संघर्ष ने इनको जबर्र कर दिया। इसने सहरी सेनाओं का मनोबल बढ़ाया और श्रीलंका सरकार के सैनिक समाधान के प्रयत्न सफलता की कगार तक पहुँच गये। अनेक विद्वेषकों का मानना था कि श्रीमती गांधी की मृत्यु (अक्टूबर, 1984) के बाद जयवर्द्धने राजीव गांधी के भोलेपन व उनकी अनुमोदनीयता का निरन्तर साम उठाते रहे।

जून-जुलाई, 1987 में तमिलों ने यह घोषणा की कि वे निकट भविष्य में एकपक्षीय स्वाधीनता की घोषणा कर देंगे। इसके जवाब में श्रीलंका सरकार ने जाफना की नाकेबन्दी कर दी। इन घिरे हुए भूखे-प्यासे तमिलों को राहत सामग्री पहुँचाने वाले निरालन भारतीय नाविक बड़े को श्रीलंका ने अपमानजनक ढंग से रोका। अन्ततः भारत को वायुसैनिक शक्ति के प्रदर्शन के साथ प्रतीकात्मक राहत सामग्री पहुँचाने के अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करना पड़ा।

भारत-श्रीलंका समझौता—यहाँ इस बात की विस्मृत व्याख्या की जरूरत नहीं कि उपरोक्त भारतीय आचरण श्रीलंका की सम्प्रभुता का हनन था या नहीं या अन्तर्राष्ट्रीय विधि के परिणतो का इस विषय में क्या विचार है? यह निर्बिबाध है कि इन हस्तक्षेप के बिना राजीव गांधी और जयवर्द्धने के बीच जुलाई, 1987 में भारत-श्रीलंका समझौता नहीं होना। इस समझौते में पक्षों से मुखर की जा रही असंतुष्ट तमिलों की लगभग सभी मांगें मान ली गयीं। तमिल-बहुल उत्तरी एवं पूर्वी प्रांतों का एकीकरण, स्थानीय प्रशासन को स्वायत्तता, राष्ट्रीय जीवन में तमिलों के साथ भेदभाव की समाप्ति आदि। इसके बदले में तमिलों द्वारा दत्त नमर्पण किया जाना था और स्वतन्त्र ईलम (राज्य) की भाग छोड़ना था। गिरफ्तार राजनीतिक बंदियों की रिहाई होनी थी। एक मुनिश्चित कार्यक्रम के अनुरूप इन प्रावधानों की पुष्टि के लिए इन प्रांतों में जनमत संग्रह की व्यवस्था की गयी। इस समझौते में जाफना में सिङ्गी सैनिक दलों को वापस बुलाने की बात कही गयी। भारत ने इस समझौते को लागू करने के लिए गारंटी (गारंटी) बनाना स्वीकार किया। श्रीलंका सरकार ने भारत को यह आश्वासन दिया कि श्रीलंका में भारत सरकार का नुकसान पहुँचा सकने वाली किसी भी विदेशी उपस्थिति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। त्रिकोमाली के सैनिक बड़े की बात तो छोड़िये, किसी भी विदेशी रेडियो प्रसारण को भी पुनर्पठ का मोका नहीं दिया जाएगा। इन आश्वासनों की विद्वत्सनीयता बनाये रखने के लिए भारतीय गारंटी रखक सैनिक दलों का इन्तजाम किया गया।

भारत-श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर करने के तत्काल बाद भारतीय प्रधान मंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्द्धने पर अलग-अलग जगह असफल कार्रवाना हमले हुए। इससे कई विश्वासों ने बहू मुझाया कि दोनों पक्षों के उपपक्षियों की नाराजगी इस बात का प्रमाण है कि समझौता निष्फल है। तब भी इसमें यह बात स्वयमेव मिट्ट नहीं हो जाती कि समझौता सफल होगा और भारत व श्रीलंका के बीच विवाद आगामी से तत्काल समाप्त हो जायेगा। इस समझौते का क्रियान्वयन काफी विघट्ट हुआ था। हुआ निर्विक्रम इनका कि जयवर्द्धने ने बहुत बतुराई

असमयता से जहाँ एक ओर श्रीलंका सरकार की उच्छ्वसल तानाशाही बढ़ी, वही हाथ आयी जीत' को भारतीय हस्तक्षेप के कारण खोने से मुक्तिभीते बोलता गये। अर्थात् जहाँ एक ओर श्रीलंका सरकार के सामने भारतीय सैनिक क्षमता का मियक टूटा तो दूसरी ओर लिट्टेवादियों को यह लगा कि 'ईलम राज्य' और उनके बीच में बाधा सिर्फ भारत है। उन्होंने तमिलनाडु में अपनी पड़्यत्रकारी गतिविधियों का जाल फैलाया, जिसकी भयावह परिणति भारतीय चुनाव अभियान के दौरान मई, 1991 में पेराम्बूर में राजीव गांधी की बबर हत्या में हुई। इसके पहले लिट्टे के आतंकवादियों ने श्रीलंका के तत्कालीन रक्षा राज्य मंत्री विजयरत्ने की नृशंस हत्या कर दी थी और इसके बाद कोलंबो में सेना मुख्यालय को बम से उड़ाकर अपनी महार क्षमता का प्रदर्शन किया। लंका की स्थिति से स्पष्ट है कि वहाँ के घटनाक्रम को प्रभावित करने में भारत असमर्थ है। ऐसे में दोनों देशों के बीच तनाव बरकरार रहना ही संभव है।

भारत-बंगला देश सम्बन्ध (Indo-Bangla Desh Relations)

जब 1971 में स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में बंगला देश का उदय हुआ, तब भारतीय विदेश नीति नियोजकों के मन में आघात की एक किरण जगमगामी कि 1947 में देश का बँटवारा अब मटियामट किया जा सकेगा। भारत के शत्रु पाकिस्तान से बंगला देश न केवल अलग हो गया, बल्कि उसके नए नेताओं ने इस राष्ट्र को धर्म-निरपेक्ष और समाजवादी जनतन्त्र के रूप में स्थापित करने की अपनी महत्वाकांक्षा प्रकट की। भिन्निर गुप्त जैसे पाकिस्तानी मामलों के प्रतिष्ठित जानकार ने इस भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति में एक निर्णायक मोड़ समझा। यह दुर्भाग्य का विषय है कि इस आशावादिता को बनाये रखना बहुत समय तक सम्भव नहीं रहा। इसके कारणों को समझने और भारत बंगला देश सम्बन्धों के भविष्य के बारे में तर्कमग्न विस्लेषण करने के लिए सक्षिप्त ऐतिहासिक पुनरावलोकन जरूरी है।

ऐतिहासिक पुनरावलोकन (1947 से 1971 तक)—आधुनिक भारत के इतिहास के अधिकांश विद्यार्थी इस भ्रान्ति के शिकार हैं कि देश के विभाजन के समय साम्प्रदायिक हिंसा का विस्फोट और तद्जनित वैमनस्य पश्चिमी सीमात तक ही सिमट रहे थे। इस भ्रान्त पर निरन्तर जोर दिया जाता रहा है कि बंगाली बाह्य पूरब में हो या पश्चिम में, वे हमेशा सांस्कृतिक दृष्टि से एक-दूसरे से करीब रहे और उनमें विभाजन के बाद भी वैसी खाई कमी नहीं पड़ी जैसी हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले पंजाबियों के बीच गहरी हो गयी थी। यह बात एक सीमा तक ही ठीक है। इस भ्रान्त का अन्त नहीं किया जा सकता कि 1947 से 1971 तक पाकिस्तान के इस हिस्से (अर्थात् पूर्वी पाकिस्तान, लकिन अब बंगला देश) के साथ भी भारत सरकार के सम्बन्ध तनावग्रस्त रहे हैं और विवाद के कई मुद्दे बीच-बीच में उभर कर सामने आते हैं। साम्प्रदायिक हिंसा, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न, भूमि या जन विवाद, तस्करी और सीमा पार अपराधियों द्वारा धरम पाना निरन्तर चर्चित हो रहे हैं (हाँ, इतना अवश्य रहा कि तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के वासियों के मन में अपने पंजाबी उत्पीड़क शासकों के प्रति जितना द्वेष था, उसकी तुलना में वे स्वयं को अपने भारतीय बंगाली बन्धुओं से निश्चय महसूस करते थे)। यहाँ दोन सचके

के रूप में भारत की काफी निन्दा करवाई। तब भी, जब तक श्रीलंका में भारतीय सैनिकों की उपस्थिति थी, लिट्टे और श्रीलंकाई सरकार दोनों पर एक तरह का अग्रज था। अपराधी उच्छृङ्खलता और नस्लवादी नरसंहार दोनों को ही शांति रक्षक सैनिक दस्ते नियन्त्रित करते रहे। सवाद द्वारा समस्या के समाधान की सम्भावना अब नहीं बची।

आज राजनयिक पहल का कोई साधन भारत के पास नहीं। मान भी लें कि श्रीलंका के उत्तर पूर्वी प्रदेश में लिट्टे छापामार अपनी स्वाधीनता की घोषणा करते हैं या इस इलाके को 'आजाद' कर लेते हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय हित निरापद नहीं मझी जा सकते। लिट्टे के सैनिक व नेता इस बात को नहीं भूल सकते कि कैसे आरम्भ में प्रोत्साहित करने के बाद भारत सरकार ने उन्हें मझधार में छोड़ दिया था। वे ऐसी स्थिति में तमिलनाडु में असन्तोष और असन्तान को भड़काने की प्रयत्न कर सकते हैं। भारतीय शांति रक्षक सैनिक दस्तों की श्रीलंका में मौजूदगी के दौरान भारतीय इच्छानुसार ई० पी० आर० एल० एफ० की प्रान्तीय सरकार का गठन हुआ था। आज इसके प्रधान पेरुमल मारीयस में बन्दियों जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भारत की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को इससे नुकसान ही पहुँच सकता है कि वह अपने पर आश्रित विस्वामय्या व्यक्ति को रक्षा करने में असफल रहा।

इस बात का कोई नक्षत्र नहीं दीलता कि श्रीलंका में निकट भविष्य में घृह-युद्ध घण्टा। वहाँ जिन की भी स्थिति काफी समय तक बनी रहेगी। इसके चलते तकनीकी, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भारत और श्रीलंका के बीच सम्बन्धों में सुधार की बात सोची नहीं जा सकती। वैसे भी आरम्भ से ही तारिख, धातु आदि के निर्यात के मामले में भारत व श्रीलंका अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धी रहे हैं। बहुत लम्बे समय तक श्रीलंका की मुक्त व्यापारिक नीति और उसके खुले द्वार भारतीय विकास के लिए चुने गये मजदूरी नियोजन को अवसरवादी बतलाते रहे। स्वयं अराजकता और अव्यवस्था के कारण श्रीलंका मुक्त व्यापार का स्वर्ण नहीं रहा। वहाँ सरकार और जनता का एक हिस्सा अपनी तमाम मुसीबतों की जड़ भारत को ममझता है। श्रीलंकाई समाचार-पत्र भारत के बिहड़ निरन्तर विप बमन करते हैं। दूसरी ओर श्रीलंका सरकार द्वारा बार-बार सैनिक समाधान चुनता मानव अधिकारों की जानसूखकर हत्या करना है।

अन्य छोटे पड़ोसियों की तरह श्रीलंका की मजबूरी है कि वह अपनी स्वाधीनता प्रमाणित करने के लिए बार-बार भारत-विरोध का स्वर मृत्तर करे। उसने लिट्टे के साथ अग्ने सघर्ष के दौर में इजरायलियों, पाकिस्तानियों, दक्षिण अफ्रीका जैसे भारत विरोधियों की निमन्त्रण देना अपने कृत्य में समझा। यह भी गौर करने लायक बात है कि श्रीलंका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जयवर्द्धने और भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी जैसे नेताओं के बीच सम्बन्धों की आधारशिला पचासवाँ वर्ष पर टिकी थी। राजीव गांधी के कार्यकाल में इसका प्रभाव बचा रहा था, परन्तु बाद में ऐसा साम्य बचा नहीं रहा।

दुर्भाग्यवश वर्तमान स्थिति यह है कि श्रीलंका की जातीय समस्या के घातक विस्फोट में माघ भारत की नियति पाड़े-अवचाहे बुरी तरह गुथ गई है। कभी यह आशा की जाती थी कि श्रीलंका से शांति सेना की वापसी के बाद दोनों देशों के सम्बन्धों में सुधार होगा। परन्तु, हुआ इसके विपरीत ही। भारतीय सेना की

भले ही भारत में ही और इसका बड़ा हिस्सा भारत में ही बहता हो, मगर उमका सागर सगम उमकी भूमि पर होता है, इसलिए गंगा के पानी पर उसका भी हिस्सा है। परन्तु यह हिस्सा बराबर का नहीं हो सकता और जल वितरण का अनुपात प्राकृतिक व तकनीकी कारणों से किसी राजनयिक या राजनीतिक समझौते के द्वारा सन्तोषप्रद ढंग से तय नहीं किया जा सकता। जहाँ एक ओर भारत सरकार के लिए यह अनिवार्य बन गया कि वह फरक्का जल बांध के निर्माण से विनाशकारी बाढ़ पर नियन्त्रण प्राप्त करे, यहाँ के मोसम में सिंचाई की व्यवस्था करे और बलकत्ता बन्दरगाह को बचाने की चेष्टा करे, वहीं इस परियोजना ने बंगला देश की समस्याओं को और भी विकट बना दिया।

विदम्बना तो यह है कि बंगला देश स्वयं एक जल-बहुल दलदली भूमि वाला देश है और जिस समय भारत फरक्का जलबन्ध से जल की निकासी के लिए तत्पर होता है उस समय वह उसे ग्रहण करने की स्थिति में नहीं होता। इस झगड़े का निपटारा 'क्यूसेक' (क्यूबिक मीटर प्रति सैकण्ड) के जोड़-पटाने से नहीं हो सकता है और न ही यह कहकर छुटकारा पाया जा सकता है कि समस्या मूलतः तकनीकी है और विशेषज्ञों के 'महबारी परामर्श' द्वारा निपटायी जा सकती है। अब तक, दोनों देशों के विशेषज्ञों के संयुक्त आयोग की कई बैठकें हो चुकी हैं। उनसे भी यही बात सामने आयी कि बिना शीर्षस्थ राजनीतिज्ञों की सहमति के नौकरगाह विशेषज्ञ इस 'अन्तर्राष्ट्रीय गुत्थी' को नहीं सुलझा सकते। फरक्का जल बांध के निर्माण के बाद मुआवजे का प्रश्न भी उठाया गया और बंगला देश ने अपनी सुविधानुसार राजनयिक-मन्त्रादिक के दौरान भारत-पाक सिन्धु जल विवाद और भारत-नेपाल की भी गड़क जल वितरण प्रश्न को कुरेदने-जोड़ने का प्रयत्न किया। भारतीय पक्ष द्विपक्षीय समस्या के इस तरह के अन्तर्राष्ट्रीयकरण से विघ्न होता रहा है।

इस समस्या के दो और पहलू हैं, जो उनकी जटिलता बढ़ाते हैं। एक ओर बिद्वद वैक जैसी अन्तर्राष्ट्रीय मददगार संस्था ने इस मामले में अपनी शक्ति दर्शाकर बंगला देश की महत्वकाशियों को उकसाया है तो दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में विपक्षी दल (भाषासंवादी मास्यवादी पार्टों) का शासन होने के कारण केन्द्र सरकार इस विषय में एकपक्षीय निर्णय लेने में असमर्थ रहती है। जब कभी समस्या के समाधान की आशा जगती भी है तो चक्का प्रकरण या किसी अन्य मनामालिन्य के कारण यह पुराना प्रकरण पृष्ठभूमि में धकेल दिया जाता है।¹

शरणार्थियों की समस्या—नदी जल विवाद की तरह बंगला देश की सीमा पार कर भारत पहुँचने वाले अर्ध शरणार्थियों की समस्या काफी पुरानी व चट्टप्रद है। बल्कि यहाँ तक कहा जा सकता है कि बंगला देश का जन्म ही इन शरणार्थियों के अप्रत्यक्ष आक्रमण के कारण सम्भव हुआ था। इस समस्या के दो अलग-अलग पहलू हैं, जिन पर अलग से विचार किया जाना जरूरी है।

बंगला देश में भारत आने वालों में अभी हज़ारों तक काफी बड़ी तादाद उन लोगो की थी, जो बिहारी कहलाते हैं। इनमें से मज़ी 'बिहारी' नहीं, बल्कि यह एक ऐसा शब्द है, जो गैर-बंगाली मूल के सभी बंगलादेशियों को समेटता है। इन शरणार्थियों की शिकायत है कि बंगला देश में उनके साथ भेदभाव बरता जाता है।

¹ विस्तार के लिए देखें—Ministry of External Affairs, *The Farakka Barrage* (Delhi, 1976).

विस्तृत प्रमाण जुटाने की आवश्यकता नहीं। 1950 के दशक में पूर्वी बंगाल से भारत में पहुँचने वाले शरणार्थियों की बाढ़, फरक्का जलबंध से उपजा विवाद, जूट, चाय आदि की कीमतों को लेकर अन्तर्राष्ट्रीय मण्डियों में प्रतिद्वन्द्विता का उल्लेख भर किया जाता काफी है।

भारत-बंगला देश सम्बन्ध (1972 से आगे)—ऐसा नहीं था कि विद्वानों को ये सब बातें याद नहीं थी, किन्तु 1972 में इस सबकी याद दिलाना शिष्टाचार के विरुद्ध जान पड़ता था। तब भी कई लोगों ने इस बात को रेखांकित किया था कि जितने बड़े पैमाने पर भारतीय सहायता प्राप्त कर बंगला देश मुक्त हुआ था, उस क्षण व उपकार की स्मृति भर मनमुटाव के लिए काफी थी। कृतज्ञता-ज्ञापन को भारत का पिछलगुआ-विद्वत् बताकर-कहकर बदनाम किया जा सकता था। भारत से युद्धोत्तर पुनर्निर्माण विषयक बंगला देश की जो आशाएँ-अपेक्षाएँ थी, उन्हें भारत कतई पूरा नहीं कर सकता था। ऐसा मानना भी मोतापन था कि बंगला देश के मुक्त हो जाने के बाद विदेशी शक्तियाँ इस क्षेत्र में रुचि लेना बन्द कर देंगी या परोक्ष रूप से ही सही, हस्तक्षेप करने का लोभ सबरण करेंगी। शिमला समझौते के बाद पाले कुछ महीनों में यह बात साफ हो गयी कि भारत बंगला देश से जो चाहे, वह नहीं करवा सकता है और शेख मुजीब की पार्टी आवासी लीग बंगला देश में निर्बन्ध शासन नहीं कर सकती। 1973 से 1975 के बीच श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार आन्तरिक चुनौतियों से झुझने में व्यस्त रही और जून, 1975 में आपातकाल की घोषणा के बाद विदेश नीति विषयक प्रश्न और भी गौण बन गये। अगस्त 1975 में शेख मुजीब की हत्या हो गयी। तत्पश्चात् बंगला देश संघिक ताना-शाही के अधीन रहा। इस हासत में भारत-बंगला देश के सम्बन्धों के बारे में धनिष्ठ मंत्री का कोई भ्रम बनाये रखना सम्भव नहीं रहा और पुराने तनाव नए रूप में सकट पैदा करते रहे।

भारत-बंगला देश के बीच विवाद के प्रमुख मुद्दे—भारत में आपात काल की समाप्ति और चुनाव के बाद इन्दिरा गांधी अपवस्था हुई और लड़ोसियों के साथ सम्बन्ध सुधारने की व्यापक उदारता वाले अनियाम के अन्तर्गत जनता सरकार ने बंगला देश के साथ फरक्का जल वितरण समझौता कर लिया। तब भले ही बहुत जोर शोर के साथ इस सफलता का प्रचार किया गया, परन्तु अब तक यह आम बात निर्विवाद रूप से सिद्ध हो चुकी है कि इस समझौते से किसी भी पक्ष को कुछ हासिल नहीं हुआ। भारत-बंगला देश के बीच तनाव पैदा करने वाले विवाद के मुद्दे उस के तम हैं। इनके निकट भविष्य में गुलझने की कोई सम्भावना नहीं। इनके समुचित विवरण और इनके अन्तर-सम्बन्धों को समझने के लिए इन पर संक्षिप्त दृष्टिपात आवश्यक है।

नदी जल विवाद—भारत और बंगला देश के बीच सबसे अधिक चर्चित विषय गंगा जल वितरण का रहा है। गंगा अपनी सहभागी नदियों के साथ जहाँ सागर में मिलती है, वह हिस्सा बंगला देश में पड़ता है। गर्मियों के मौसम में गंगा नदी की यह मुख्य धारा बहुत खींच हो जाती है और स्वयं भारत को ही अपनी जल-सम्बन्धों जरूरतें पूरी करने में कठिनाई होती है। कलकत्ता बन्दरगाह में जल के अभाव के कारण बाणू की निकासी कठिन हो जाती है और इस बन्दरगाह को सतारा पैदा होने लगता है। दूसरी ओर बंगला देश को यह लगता है कि गंगा का उद्गम

और भारत सरकार का बंगला देश के प्रति असन्तोष एक सीमा तक निराधार नहीं। बंगला देश में सैनिक तानाशाही की जड़ें भजवृत होने का संशय धर्म-निरपेक्षता के अवमूल्यन के साथ हुआ। पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों में सुधार और चीन व अमरीका के साथ बढ़ती साठमाँठ, वहाँ के प्रशासन की विशिष्ट पहचान बन गये।

भारत-बंगला देश सम्बन्धों का भविष्य—इन सबको देखते हुए ऐसा नहीं जान पड़ता की भारत-बंगला देश के सम्बन्धों में निकट भविष्य में कोई अप्रत्याशित सुधार होगा। हाँ, नए-नए विवाद पैदा होने की सम्भावना अवश्य बनी रहती है। नवमूर द्वीप समस्या इसका एक अच्छा उदाहरण है। जुड़वाँ शरीर वाले दो सहोदर देशों के लिए सागर के 'एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन', नव प्रकट नवमूर जैसे द्वीप, 'कोटिनेटल शेल्फ' स्थित तेल आदि के बंटवारे की समस्याएँ हमेशा पेचीदा रहनी हैं। यह स्थिति तब कष्टकर होती है, जब दोनों पड़ोसी देशों के अन्दरूनी हालातों और सामरिक परिप्रेक्ष्य में इतना अन्तर हो, जितना भारत और बंगला देश के बीच है। बंगला देश के उदय के पहले बेरूबाड़ी पूर्वी बंगाल को मीपने की बात बिबादप्रस्त हुई थी, तो आज तीन बीघा गलियारा निर्विवाद नहीं है। नवमूर द्वीप समूह बढ़ती हुई राजनीतिक परिस्थिति में कभी भी फिर एक दुःख प्रसंग बन सकता है।

मुक्ति सघर्ष की सफलता से आज तक बंगला देश के राजनीतिक जीवन और वैदेशिक सम्बन्धों में एक बुनियादी द्वन्द्व का जो प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है, वह है—राजनीतिक दलों, जनतांत्रिक तत्वों और सेना के बीच सत्ता का सघर्ष। जब-जब सेना का प्रभाव बढ़ा है, भारत-बंगला देश सम्बन्धों में बिगाड़ आया है। बंगला देशी सिपाहियों के उत्पीड़न-क्षोषण से देश छोड़ने के लिए भजवूर जनजातियों या बिहारी मरणायियों को लेकर भारत और बंगला देश के बीच खिचाव रहा है। दोनों देशों के सीमा सुरक्षा बलों के बीच झुठभेड़ें भी आम बात हैं। आर्थिक जीवन की दुर्दशा हो या प्राकृतिक विपदा, बंगलादेशी सरकार की प्रवृत्ति भारत पर दोषारोपण की रहती है। इरशाद-प्रशासन के अंतिम वर्षों में तो हद हो गई थी। नए सैनिक डिवीजनों के गठन को जरूरी बतलाते हुए तत्कालीन बंगलादेशी राष्ट्रपति इरशाद ने भारत को शत्रु के रूप में परिभाषित करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई थी। इरशाद के पतन के बाद यह सम्भावना एक बार फिर प्रबल हुई है कि बंगला देश में मंच अर्थात् जनतन्त्र की वापसी हो सकती है। परन्तु, इस मामले में जरूरत में ज्यादा आशाविस्त होने की आवश्यकता नहीं। आज का बंगला देश भी 1971 का बंगला देश नहीं, जो अपनी पहचान एक धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी गणराज्य के रूप में बनाना चाहता हो। आज बंगला देश में इस्लामी तत्व वापसी सक्रिय हैं। भारत के साथ नदी व जल विवाद का समाधान भी दृढ़ता नहीं जा सका है। नेपाल की ही तरह बंगला देश में लोकप्रिय जनतन्त्रिक नेता के लिए भी सिरदर्द यह है कि भारत-प्रेम को वहाँ देशद्रोह का पर्याय समझा जा सकता है। अतः भारत-बंगला देश सम्बन्धों में एकाग्रक सौहार्द व सद्भाव बढ़ने की बात सोचना महज भोलापन होगा। वस्तुतः भारत-बंगला देश सम्बन्ध राष्ट्रीय हितों के संयोग या टकराव से बड़ी अधिक बंगला देश के अस्थिर आंतरिक घटनाक्रम पर निर्भर रहेंगे।

सीमावर्ती भारतीय राज्यों की सरकारों को यह सन्देश है कि बंगला देश की आर्थिक व राजनीतिक स्थिति डाँबाँडोल होने के कारण ये लोग भारत में उपलब्ध रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। सिर्फ इतना नहीं कि उनके आने से भारत की नागरिक सुविधाओं पर दबाव पड़ता है, बल्कि सत्तारूढ़ दल इन शरणार्थियों को समर्थन-सहायता देकर अपने पक्षधर को मतदाता के रूप में पंजीकृत करा लेते हैं। इससे वास्तव में भारत के नागरिक अर्थात् स्थानीय जनता का पलड़ा हल्का हो जाता है। असम समस्या का एक पंचोदा बहुत यही था।

कांटेदार बाड़ पर विवाद—बंगला देश के इन अयाचित आगतुकों को भारत में आने से रोकने के लिए कांटेदार बाड़ की व्यवस्था सुझायी गयी है, परन्तु इसे ज़िद्दान्वित करना असम्भव है। एक तो हजारों मील लम्बी सरहद्द की घेराबन्दी बेहद खर्चीला प्रस्ताव है। इसे घुसपैठियों किसी भी बल कहीं भी तोड़ सकते हैं। इससे बंगला देश की मानहानि तो होती ही है, किन्तु भारत की विशेष छान भी नहीं हो सकती। बंगला देशी सरकार यह घोषणा कर चुकी है कि इस तरह की घेराबन्दी को वह अपने विरुद्ध अभिमतपूर्ण कार्रवाई समझेंगी। इस कांटेदार तार की बाड़ की देखभाल के लिए सीमा सुरक्षा बल के दस्तों को तैनात करना पड़ेगा और उन पर घुसपैठियों या बंगला देशी सन्तानियों के हमलों से संकट का समाधान होने की अपेक्षा संकट और अधिक जटिल होगा।

अनेक विद्वानों का यह भी मानना है कि अधिकतर तयाकथित शरणार्थी पेशेवर तस्कर और सामाजिक अपराधी हैं, जिनकी सीमा पार दोनों तरफ से भ्रष्ट स्वार्थी तत्वों से मिश्रीभगत है और जिनके अपने व्यवसायिक हित, किसी भी देश के राष्ट्रीय हित की परवाह नहीं करते। इन तत्वों पर नियन्त्रण तभी किया जा सकता है, जब भारत व बंगला देश दोनों के बीच सहकार हो। विदग्धना यह है कि इन शरणार्थियों की गतिविधियों के कारण दोनों देशों में मनोमालिन्य निरन्तर बढ़ता रहा है और सहकार की सम्भावना घटी है।

चकमा शरणार्थियों की वापसी की समस्या—चकमा आदिवासियों की समस्या जरा भिन्न है। अधिकांश अन्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक इस मामले में एकमत हैं कि देश के विभाजन के समय चटगाँव जिले (वर्तमान में बंगला देश में) के आदिवासी-बहुल पहाड़ी क्षेत्र या सीमाकन सहो दंग से नहीं हो पाया था। जब तक मैदानी बंगला-देशियों ने पहाड़ी जंगल का अतिक्रमण नहीं किया था, तब तक चकमा आदिवासी क्षेत्र को अछूता रखना सम्भव नहीं रहा है। सरकार और नौकरशाही में व्याप्त भ्रष्टाचार में चकमा आदिवासियों के उत्पीड़न को निर्मम बना दिया है। अनेक चकमा समस्त वगवत के लिए विवश हुए हैं। बंगला देशी सैनिकों द्वारा पीछा किये जाने पर वे सरहद्द पार भारत में छरण लेते रहे हैं। एक ओर चकमाओं की समस्या माननीय है। इन्हें सर्वोच्च की नोक पर बापस बंगला देश में नहीं धकेला जा सकता। दूसरी ओर यदि चकमा आदिवासी भारत में बने रहकर राजनीति में सक्रिय रहते हैं तो बंगला देश भारत द्वारा इनकी महामानवाजी को धुत्तापूर्ण कार्रवाई मान सकता है। मणिपुर और त्रिपुरा में चकमाओं की सस्या पचास हजार से ऊपर पहुँच चुकी है। इस समस्या को ज्यादा दिनों तक टाला नहीं जा सकता। इस बारे में भी समस्या का समाधान दोनों पक्षों के बीच सद्भावना पर निर्भर है।

धर्म-निरपेक्षता का अवमूल्यन और चीन व अमरीका की साठगाँठ—दूसरी

में रहते रह और उनके वक्ताओं ने भारत की आजादी की लड़ाई में सहर्ष हिस्सा लिया। 1942 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण आदि ने नेपाल में शरण ली और बाद के वर्षों में कोइराला बन्धुओं ने नेपाली कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रेरणा और समयन से ही की। इन जनतांत्रिक व समाजवादी तत्वों को नेहरू जी ने निरन्तर प्रोत्साहित किया। यह इस प्रेरणा और प्रोत्साहन का ही प्रभाव था कि राजनीतिक चेतना वाले नेपालियों ने अपने देश के सामाजिक व राजनीतिक जीवन में राणा वंश की सामन्तशाही की जकड़ को दूर करने की रणनीति बनायी। 1950 में नेपाल सरकार और भारत सरकार के बीच जो व्यापार व पारगमन सन्धि हुई, उसमें उभयपक्षीय सम्बन्धों की गैर-बराबरी स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। 1950 से लेकर 1977 तक आवागमन व्यापार आदि इसी सन्धि के अनुसार अनुशासित होते रहे हैं।¹

सम्बन्धों का भू-राजनीतिक पक्ष—भारत-नेपाल सम्बन्धों का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष भू-राजनीतिक है। पिछले चार दशकों में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के व्याप्त शक्ति समीकरणों ने इसको निर्णायक ढंग से प्रभावित किया है। 1953 में जब नेपाली शासन को छापामारी ने राणा के उत्पीड़क कुषामन की रोड तोड़ डाली थी और असंतुष्ट नेता नेपाली राजा, राणाओं द्वारा बंदी बना लिये गए थे, उन्हें अन्ततः भारतीय दूतावास में ही शरण मिली। अर्थात् भारतीय समयन के बिना नेपाल में जनतन्त्र की स्थापना सम्भव नहीं थी। तब नेपाली मन्त्रिमण्डल की बैठकें भारतीय दूतावास में ही होती थीं। परन्तु इसके तत्काल बाद नेपाल में भारत-द्वेष का ज्वार बढ़ने लगा। सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस पार्टी के विपक्षियों के लिए यह आक्षेप लगाना सहज था कि नेपाली कांग्रेस के नेता भारत के 'पिछले' व 'बंछित' हैं। जनतन्त्र में विरोध और आक्रोश के स्वर की दवावा बैसे भी कठिन है। फिर, नेहरू जी की कोई क्षेत्रीय उप मात्त्राज्यवादी महत्वाकांक्षा नहीं थी।

परन्तु इस बात से कहीं अधिक महत्वपूर्ण घटना चीन में साम्यवादियों द्वारा सत्ता ग्रहण करना था। विरोधक, तिवत को मुक्त कराने का चीनी अभियान के बाद नेपाली राजनीति में मन्त्रिमण्डल को यह लगने लगा कि नेपाल के लिए अपने दो देशवादी पड़ोसी देशों भारत व चीन को मन्तुरित करने का जोखिम भरा खेल खिलना बेहद लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। भूमिबद्ध राज्य हाना अब नेपाल के लिए कमजारी नहीं बल्कि ताकत बन गया। अमरीका और ब्रिटन जैसी बाहरी शक्तियों के साथ-साथ चीन ने भी नेपाल की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वतन्त्र होने की सलक को भटकाया। 1962 में भारत चीन संधि के विस्फोट के पक्ष ही महाराजा त्रिभुवन का निघन हो गया और उनके उत्तराधिकारी महाराजा महेन्द्र ने अपनी हस्ती स्थापित करने के लिए भारत विरोधी रवैया अपनाया। 1962 के बाद यह स्थिति और भी बिगड़ गयी। भारत-चीन सीमा विवाद में नेपाल की तटस्थता अनपेक्षित थी। नेपाल ने भारतीय व्यापारियों व सलाहकारों के प्रभुत्व को सन्तुलित करने के बहाने बड़े पैमाने पर चीनी सहायता व अनुदान ग्रहण किए और सामरिक महत्व की अनेक परियोजनाओं में चीनी भागीदारी को बढ़ावा दिया। चीन ने नेपाल को दी गयी अपनी आर्थिक सहायता का भरपूर प्रचारार्थक लाभ उठाया। इस प्रकार चीनी

¹ विस्तार के लिए देख—Suman Narayan, *India and Nepal An Exercise in Open Diplomacy* (Bombay 1970).

भारत-नेपाल सम्बन्ध (Indo-Nepal Relations)

भारत और नेपाल इतने निकट और घनिष्ठ पड़ोसी देश हैं कि कई बार लोग नेपाल को विदेश मानने को तैयार ही नहीं होते। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन की खूनभरी सार्ई है तो लका को कष्ट-साध्य जब राशि हमसे अलग करती है। बर्मा और भारत के बीच दुर्गम दलदली जंगल है और बंगला देश के साथ समय-समय पर उगजने वाले तनाव कटीली बाड़ खड़ी कर देते हैं। भारत अपने पड़ोसी देश चीन के साथ सीमा युद्ध लड़ चुका है। इन सबकी तुलना में नेपाल भारत के बहुत करीब है। नेपाल अकेला ऐसा निदशी राष्ट्र है, जिनके नागरिक भारतीय सेना में मर्ती दिये जा सकते हैं। हिमालय पर्वत मासा और अनेक महत्वपूर्ण नदियाँ भारत व नेपाल के बीच साझे की सम्पत्ति है। नेपाल विश्व का एकमात्र 'हिन्दू राष्ट्र' है और महात्मा बुद्ध की जन्म-भूमि थी। इन पारम्परिक व सांस्कृतिक सम्बन्धों की खून और अम्य वैवाहिक सम्बन्ध सदियों से पुष्ट करते रहे हैं। आजादी के बाद भारत-नेपाल सम्बन्धों में भाभेव के कई मुद्दे उठ खड़े हुए।

1947 तक भारत-नेपाल सम्बन्ध—इस खताब्दी के दूसरे दशक में जब तत्कालीन बायमराय नाईके कर्जन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया, तब नेपालियों ने भारतीय साम्राज्य का हिस्सा बनने की इच्छा जाहिर की थी लेकिन आज यह ऐतिहासिक कुतूहल का विषय भर रह गया है। इस विषय पर अटकलें लगाता व्यर्थ है कि यदि ऐसा हुआ होता तो आज क्या होता। यहाँ सिर्फ इतना जोड़ने की जरूरत है कि नेपाल एक राजनन्वीय देश है और उसका बुनियादी संस्कार 1947 के पहले की किसी अन्य दूरस्थ-दुर्गम रियासत जैसा ही बना रहा, जबकि भारत में राजबाड़ी के विलय व राज्यों के गुर्नगठन के बाद राजनीतिक व आर्थिक एकरसता लायी जा सकी। भारत-नेपाल सम्बन्धों की कई अड़चनें इसी विषमता-विसंगति से उत्पन्न हुईं।

जब तक भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्ति विराजमान थी, तब तक नेपाल सम्यन्तु समानता (Sovereign Equality) और स्वाधीनता का कोई विशेष अर्थ नहीं था। नेपाल अने ही भारत की तरह पराधीन न रहा हो, किन्तु अपना स्वतन्त्र अस्तित्व बनाये रखने के लिए यह ब्रिटिश भारत की सरकार की छपा पर निर्भर था। 1816 के गोरखा युद्ध ने यह बात यत्नी-भाति प्रमाणित कर दी थी कि नेपाली मन्नाट की सेना भारत की केन्द्रीय सरकार से कोई 'मुकाबला' नहीं कर सकती थी। कनिष्ठ पद स्वीकार कर लेने के बाद नेपाली शासकों का आचरण ब्रिटिश मलिका चिबटोरिया की सरकार के प्रति निरन्तर अनुचर, स्वाधीनत व सेवक का सा ही था। नेपाल ने औपचारिक रूप से अने ही भारत का संरक्षण स्वीकार नहीं किया हो, किन्तु वास्तविक स्थिति यही थी। चीनी व तिब्बती हमलावरों से बचने, शासक वर्ग की विलास उपभोग सामग्री की आपूर्ति और नाम मात्र के आर्थिक विकास के लिए भी नेपाली भारत व ब्रिटेन के साथ सम्बन्धों में बिगाड़ नहीं कर सकते थे। दूसरी ओर नेपाली शासक जब तक स्वाधीनत बन रहे तब तक इस बकर देश के आन्तरिक घटनाक्रम से भारत व ब्रिटेन को कुछ लेना-देना नहीं हो पटना था। अनेक माघन-मन्त्र व प्रतिदिन नेपाली स्थायी प्रवासी के रूप में भारत

भारत ने उसकी आर्थिक नाकेबन्दी धुरु कर दी है, जो बाँह मरोड़ने के समान है, अन्यायपूर्ण है आदि। नेपाल ने जोर-शोर से यह घोषणा की कि नेपाल सम्प्रभु राष्ट्र है और भारत को इस बात का कोई अधिकार नहीं कि वह चीन के साथ नेपाल के सम्बन्धों को लेकर नाक-भौं सिकोड़े। नेपाल ने यह घोषणा करने में देर नहीं लगाई कि इसे अब भारत के साथ विशेष सम्बन्धों की कोई जरूरत नहीं। ये सम्बन्ध गैर-बराबरी वाले हैं और औपनिवेशिक काल की विरासत हैं।

भारत-नेपाल सम्बन्धों में नया मोड़ (New Turn in India-Nepal Relations)

नेपाल में बहुदलीय लोकतन्त्र के समर्थन और भारतीय मान सिंह की सरकार के खिलाफ चने-आन्दोलन की सफलता के बाद भारत-नेपाल सम्बन्धों में नई करबट ली। 1990 में नेपाल नरेश बीरेन्द्र ने बहुदलीय शासन व्यवस्था की माँग मजूर कर ली और श्रीकृष्ण प्रसाद मट्टराई नई अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने पद ग्रहण करते ही न केवल भारत से सम्बन्ध सुधार की घोषणा की, बल्कि जून 1990 में वह भारत-यात्रा पर भी आये, जिससे दोनों देशों के बीच कटुता व तनाव के बजाय सहयोग और मैत्री का नया वातावरण बना।

मट्टराई की भारत-यात्रा के दौरान दोनों देश अनेक प्रमुख मुद्दों पर महमत हुए और कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गये। उनके प्रमुख सहमति व फैसले इस प्रकार हैं—

(1) भारत और नेपाल 1 जुलाई 1990 तक व्यापार तथा पारगमन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सम्बन्धों पर व्यापक समझौता होने तक 1 अप्रैल 1987 की स्थिति बहाल करने पर सहमत हो गये। उल्लेखनीय है कि 23 मार्च 1989 को दोनों देशों के बीच व्यापार एवं पारगमन सन्धि समाप्त होने के बाद विवाद पैदा हो गया था, जिसके कारण भारत-नेपाल सीमा से होने वाले व्यापार को बहुत कुछ नियन्त्रित कर दिया गया तथा पारगमन स्थला को बन्द कर दिया गया। दोनों देशों के बीच पहले की तरह व्यापार व पारगमन धुरु करने पर सहमति हुई।

(2) भारत ने व्यापार व पारगमन समझौते की अवधि समाप्त हो जाने में बन्द हुए सभी 15 पारगमन केन्द्रों व 22 सीमा चौकियों को खोलने का निर्णय किया। भारत ने कोटा या नियन्त्रण वाले निर्माण को भी खोल दिया। इण्डियन ऑयल कारपोरेशन द्वारा नेपाल अब पेट्रोल, लुम्रीकेंट्स आदि नेट्रो उत्पादन से सवंगा। ऋण सीमा जो समझौते के लागू होने के काल में 25 करोड़ रुपये थी, उसे बढ़ाकर 35 करोड़ रुपये कर दिया गया। भारत ने तटकर में भी छूट दी। कोटा के सहित कोयल की आपूर्ति की चालू करने की बात कही गई।

(3) बातचीत में इस बात का संकल्प किया गया कि दोनों देश एक-दूसरे की सुरक्षा चिन्ताओं का पूरा-पूरा स्थान रखेंगे। मसुक्त विज्ञप्ति में कहा गया कि दोनों में से कोई भी देश अपने देश में दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ पढ़ने वाली गतिविधियों को नहीं हाने देवे। दोनों ने एक-दूसरे पर सतरे की आसका का स्थान रखकर प्रतिरक्षा से ताल्लुक रखने वाले सवाल पर सहमति बनाने के स्थान से परस्पर मसविदा करने का निर्णय किया।

(4) पहले नेपाल द्वारा चीन से हथियारों के आयात से भारत व नेपाल में तनाव पैदा हो गया था। लेकिन मट्टराई ने चीन से हथियारों में आयात की तीमरी

सहयोग से बने सिर्फ एक काठमाडू-कोदारी राजमार्ग ने भारत की दर्जनों परियोजनाओं को पीछे धकेल दिया। काठमाडू को चीनी सीमाव से जोड़ने वाले इस राजमार्ग का सैनिक महत्व भी कम नहीं। यहाँ यह टिप्पणी करना अनुचित नहीं होगा कि भारत-नेपाल सम्बन्धों में क्रमशः ह्रास के लिए चीनी पड़्यग्न और नेपाली असंतोष के साथ-साथ भारत की राजनीतिक अकर्मण्यता भी जिम्मेदार रही है।

भारत-नेपाल सम्बन्धों में विवाद के प्रमुख मुद्दे—भारत-नेपाल सम्बन्धों में विवाद के प्रमुख मुद्दों को मोटे तौर पर तीन बिन्दुओं के तहत बाँटा जा सकता है। भारतीयों का बहिष्कार, भारत की नेपालियों पर प्रभुत्व स्थापित करने की आकांक्षा और भारतीय मूल के विद्योतियों व व्यापारियों द्वारा दरिद्र नेपालियों का शोषण। ये त्रिकालवर्ष नेपाल की आम जनता व सरकार दोनों की हैं। नेपाली राज परिवार की एक और परेशानी यह है कि भारत सरकार नेपाल के विपक्षी व जनताप्रिय तत्वों को समर्थन देती है और अपना राष्ट्रीय हित इसी में समझती है कि राजशाही उसके समर्थन को कानर रहे। दूसरी ओर भारत सरकार को इस बात से गहरा अमनोप है कि नेपाल अपनी भू-राजनीतिक स्थिति का फायदा उठाते हुए भारत का नयाडोहन (Blackmail) करने का प्रयत्न करता है और सीमाव पर तत्कारी को बड़ावा देकर भारत को आन्तरिक नुकसान पहुँचाता है।

1977 में भारत की जनता सरकार ने नेपाल के साथ मुलह और रियायत का मार्ग अपनाया। उसने नेपाल की इच्छानुसार उसके साथ व्यापार और पारगमन की अवग-अलग मन्त्रियाँ की। यह एक तरह से 1950 की सन्धि को समाप्त करने की हद तक सशोधित करना था। भारत के इस समर्थन भाव के बावजूद भारत-नेपाल सम्बन्धों में प्राथमिक सुधार नहीं हो सके। पिछले वर्षों में पश्चिमी बंगाल में गोरालाई वाला जो आन्दोलन भड़का, उसके मूल काठमाडू तक ढूँढे गये। इसी तरह कुछ वर्ष पहले जब नेपाल में जन आन्दोलन फैला तो जनता का ध्यान दूसरी तरफ मोड़ने के लिए सोभाव्यपूर्ण सयोगवश नेपाल में आतङ्कवाद की छिटपुट घटनाएँ घटी। इन तिलमिल में नेपाल ने तात्कालिक रूप से भारत में रहने वाले शरणार्थी तत्वों पर गक किया। इन तरह मनोवैज्ञानिक दबावों के रहते जायकाएँ निर्मूल नहीं हो सकती और न ही भारत-नेपाल सम्बन्धों में सुधार की आशा की जा सकती थी।

विदेश नीति के मामले में भारत और नेपाल के बीच भन्स सबसे बड़ा मत-भेद नेपाल की शान्ति क्षेत्र (अर्थात् भारतीय प्रभाव क्षेत्र से बाहर) घोषित करने वाला प्रस्ताव है। गुट निरपेक्ष अफ्रो-एशियाई देशों में सिर्फ भारत ही इस प्रस्ताव का विरोधी है। बीना ही पक्ष इन विषय में पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। जब नी बंगला देग, भूटान, और धोलका किसी भारतीय राजनयिक कदम का प्रतिरोध करते हैं तो उन्हें नेपाली समर्थन का भरोसा रहता है।¹

भारत-नेपाल सम्बन्धों में नया विवाद—भावे, 1989 में व्यापार व पारगमन संधि की अवधि समाप्त होने पर भारत ने इसके नवीनीकरण से इकार कर दिया। राहन की अवधि समाप्त होने पर भारत ने सीमा जाँच, मुल्क आदि के बारे के सक्ती बरतना शुरू कर दिया। नेपाल ने तत्काल यह जाँच लगाता आरम्भ कर दिया कि

¹ देखें—S.D. Mook, *India and Regionalism in South Asia: A Political Perspective*; और L.S. Barak, *India and Nepal*, in Bimal Prasad (ed.), *India's Foreign Policy: Studies in Continuity and Change* (Delhi, 1979).

विरोध स ही होता रहेगा। भारत-नेपाल सम्बन्धों में 'नया मोड़' सिर्फ इतना हो सकता है कि जनहमति और असन्तोष प्रतीकाल्मक ढंग से अभिव्यक्त होंगे और आपोश की सीमा दोनों ही पक्ष भली-भाँति पहचानेंगे।

नेपाल में जनतन्त्र की पुनर्स्थापना के लिए मई, 1990 में चुनाव हुए। इनमें नेपाली कांग्रेस को बहुमत तो मिला, परन्तु चुनाव के कई परिणाम नाटकीय रहे। मृदु मायी एवं लोकप्रिय तत्कालीन प्रधान मंत्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई स्वयं चुनाव हार गए। इतना ही नहीं, नेपाली कांग्रेस के सर्वोच्च नेता गणेश मान सिंह ने परिवार के दो सदस्य, पत्नी एवं पुत्र भी चुनाव हार गए। काठमांडू घाटी भी, जहाँ की जनता सबसे अधिक साक्षर और राजनीतिक दृष्टि में प्रबुद्ध समझी जाती है, नेपाली कांग्रेस के साथ नहीं रही। पार्टी में सभी जगह साम्यवादियों का बोलबाला रहा। पूर्वी नेपाल में तो लाल लहर का उफान और भी जबरदस्त रहा। जिस समय चुनाव परिणाम सामने आ रहे थे पल भर को यह लगने लगा था कि नेपाली कांग्रेस को शायद स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाये। पुरे चुनाव अभियान के दौरान साम्यवादियों का प्रमुख मुद्दा यह था कि नेपाली कांग्रेस के नेता मजबूत राष्ट्रवादी नहीं समझे जा सकते। वे वहाँ में भारत सरकार से उपकृत-अनुग्रहित होने रहे हैं। नदी जल समझौते को देश के माथ गहारी के रूप में पेश किया गया। चुनाव के दौरान भी थोड़ी-बहुत हिंसा हुई। अतत नेपाली समद में साम्यवादी सदस्या की संख्या 210 में से 70 से भी कम रही। परन्तु इस मुद्दे पर विपक्षी दल को अनदेखा नहीं किया जा सकता।

ये दरिष्ठ साम्यवादी नेता मनमोहन अधिकारी ने एक साक्षात्कार में यह बात स्वीकार की कि चुनावी भारों और उत्तेजना का बर्ष यह नहीं कि भारत के साथ नेपाली साम्यवादियों का कोई बैमनस्य है, नयापि इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि दो-तिहाई बहुमत के अभाव में गिरजा प्रसाद कोइराटा की सरकार किसी अन्तर्राष्ट्रीय संधि को लागू नहीं कर सकती। जाहिर है कि ऐसी स्थिति में नदी जल विवाद का मामला खटाई में पड़ जाता है। नेपाल में बहुत नारे लोग यह मानने लगे हैं कि भले ही पश्चिमी नदियों का जल-विभाजन उभयपक्षीय परामर्श से हुआ जा सकता है, और पूर्वी नदियों का मामला बहुपक्षीय परामर्श में ही सुलझन वाला है। भविष्य में तनाव के और छोटे-मोटे मुद्दे उभर भी सकते हैं।

भारत-भूटान सम्बन्ध (Indo-Bhutan Relations)

कई भाषनों में भारत-भूटान सम्बन्धों की तुलना भारत-नेपाल सम्बन्धों से की जाती है। भूटान भी भूमिबद्ध व राजशाही वाला देश है। मध्ययुगीन मामलों में स्कारवांगे और आर्थिक दृष्टि से अल्प-विकसित भूटान की भारत पर निर्भरता नेपाल से वहीं ज्यादा है। भूटान वैदेशिक तथा प्रभिरक्षा के मामलों में भारत की सलाह मानने के लिए सहिष्णु है। मित्रिपत्र जैसे 'मरालिन टाइम्स' से उसकी स्थिति थोड़ी स्पष्ट रहती है। 1950 में भूटान के शासकों ने स्वाधीन भारत के साथ एक विदोष संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें भूटान ने नेपाल की ही तरह उभयपक्षीय सम्बन्धों की गैर-बराबरी स्वीकार की थी। नेपाल की ही तरह साम्यवादी चीन के उदय और भारत-चीन विषय के उभरण के बाद भूटान का अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व बढ़ा। उसने

और अन्तिम सेव रोक दी। उत्तेजनीय है कि 1947 से 1987 तक नेपाल भारत से लगभग अपनी पूरी आवश्यकता के हथियार खरीदता रहा, किन्तु 1988 में उसने ए० के० गन सहित बहुत बड़ी मात्रा में चीनी हथियार खरीदे। मट्टरार्ड ने कहा कि चीनी हथियारों के आयात का फैसला पिछली सरकार का था, किन्तु चीन ने जिस कीमत पर हथियार दिये, इसकी तुलना में भारतीय हथियारों की कीमत पाँच गुना अधिक थी। अगर भारत हमें उचित कीमत पर हथियार देगा तो हम उससे खरीदना ही पसन्द करेंगे।

(5) एक प्रश्न के उत्तर में मट्टरार्ड ने कहा कि कश्मीर का सवाल भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मामला है। उन्होंने उसे द्विपक्षीय समझौते के तहत निपटाने की भारतीय नीति का समर्थन किया।

(6) संयुक्त विज्ञप्ति में नेपाल में भारतीय नागरिकों के साथ हो रहा भेदभाव समाप्त करने की बात कही गई। कहा गया कि भारतीयों को वहाँ अब 'वर्क परमिट' लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भारतीय नागरिक स्कूलों में काम कर रहे हैं, उन्हें नेपाली नागरिकों की तरह ही सुविधाएँ दी जाएँगी।

(7) नेपाल इस बात के लिए भी सज्जी हो गया कि नेपाल में भारतीय मुद्रा पर जो प्रतिबंध लगाये गये, उन्हें समाप्त कर दिया जायेगा। इसके साथ नेपाल में भारतीय माल पर जो अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी लगाई जाती थी, उसे समाप्त कर दिया जायेगा। भारतीय माल के मुकाबले किसी अन्य तीसरे देश के माल पर 'करो' में अतिरिक्त सुविधा नहीं दी जायेगी। भारतीय मार्ग पर कस्टम ड्यूटी लगाने के लिए कारखाने के मूल्य को आधार माना जायेगा।

उपरोक्त बिस्लेषण से स्पष्ट है कि मट्टरार्ड की भारत यात्रा के दौरान हुए समझौते से भारत-नेपाल सम्बन्धों में नया अध्याय शुरू हुआ। हालांकि नेपाल में ऐसे नेताओं की कमी नहीं जो सोचते हैं कि सतत टकराव की मुद्रा अपनाकर भीर 'चीनी-काई' चलकर ही भारत से अधिकतम फायदा उठाया जा सकता है। भारतीय मानसिद्ध सरकार ने यही राजनयिक तैवर अख्तियार किया था। किन्तु आम नेपाल-वासी भारत से दोस्ताना और सहयोगपूर्ण सम्बन्धों का पक्षधर है। पिछली सरकार की अदूरदर्शी नीति के कारण ही अधिसंख्य नेपाली जनता लगभग 15 माह तक आवश्यक वस्तुओं में वंचित रही थी। किन्तु व्यापार और पारगमन के क्षेत्र में 1 अप्रैल 1987 की स्थिति बहाल होने से नेपाली जनता व उनके कई नेताओं ने राहत की सांस ली और विभिन्न मसलों पर सहमति का स्वागत किया। इस सबके बावजूद यह मानना जल्दबाजी होगी कि भारत व नेपाल ने सभी मतभेद दूर कर लिए हैं और मैत्री व सहयोग के सम्बन्ध स्थायी बने रहेंगे। नेपाल को प्रान्ति क्षेत्र घोषित करने, तम्कुरी की समस्या, जल समाधानों का बँटवारा, नेपाली परियोजनाओं में भारत की हिस्सेदारी जैसे कई और मामले हैं, जिन पर दोनों देशों की सरकारों के बीच मतभेद दूर किये जाने योग्य हैं।

यह बात याद रखने लायक है कि कोई भी नेपाली सरकार स्वदेश में भारत के मित्र के रूप में अपने को पेश नहीं कर सकती। किसी भी ऐसे नेपाली नेता की भारतीय दलात या एजेंट बहकर बदनाम किया जा सकता है। इतिहास इसका माधुरी है। भारत-नेपाल सम्बन्धों की वस्तुता-स्थिरता प्राप्त करने में अभी समय लगेगा। नेपाल द्वारा अपनी सम्प्रभुता स्वतन्त्रता का प्रदर्शन भारत की आलोचना/

जनमर्या ने 'लेपचा भूतियो' को जल सञ्चयक बना दिया है और वे दाजिलिंग के गोरखालैंड आन्दोलन में भी नेपाली विस्तारवाद की आक्रमक झलक देखते हैं। भूटान इस बात के लिए विवश हुआ कि अपने नागरिकों को भूटानी राष्ट्रीय सम्मान बरकरार रखने और अपनी सांस्कृतिक विरासत बचाये रखने के लिए सख्त निर्देश दे। भूटानी नागरिकों के लिए राष्ट्रीय पोशाक पहनना अनिवार्य बना दिया गया है और वे टेलीविजन पर विदेशी कार्यक्रम नहीं देख सकते। 'विदेशियों' के आवागमन पर और भी अधिक प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं। भूटानी और नेपालियों के बीच छिटपुट नस्ली झड़पें भी हुईं, जिनमें कुछ जानें गईं। दुर्भाग्यवश ये अग्रिम घटनाएँ भारत-भूटान सीमा पर हुई हैं—जहाँ सिक्किम के भारतीय प्रदेश और भूटान की सीमा मिलती है। इस तरह पर आवागमन पारम्परिक रूप से अबाध रहा है और बड़ाई से इसकी निगरानी भारत के लिए नष्टप्रद हो गई है। नेपाल में भूटान में रहने वाले नेपालियों के साथ भेदभाव का मामला तूल पकड़ रहा है और इसे मानवाधिकारों के हनन के रूप में देखा जाने लगा है। यह भी जाहिर है कि शिक्षा के प्रसार के साथ क्रमशः अधिकतर भूटानी अपने देश में व्याप्त मध्ययुगीन, सामंती धार्मिक व्यवस्था के बारे में सोचने-विचारने लगेंगे और सत्तारूढ़ थ्रैण्टि वर्ग ने दूरदर्शिता नहीं दिखाई तो इससे राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी।

भारतीय राजनय के लिए वर्तमान स्थिति एक नाजुक और जोखिमभरी चुनौती है। एक ओर तो उसे इस स्थिति से बचना होगा कि उस पर हस्तक्षेपकारी होने का आरोप लग सके तो दूसरी ओर इस बात के प्रति भी सतर्क रहना पड़ेगा कि अनावश्यक सकोच या शिष्टाचार में भारतीय राष्ट्रीय हितों को नुकसान नहीं पहुँचे। कुछ लोग यह कह सकते हैं कि विश्वव्यापी तनाव संघर्ष के इस दौर में जब भारत-चीन सम्बन्धों में सामान्यीकरण चल रहा है, तब भारत के लिए भूटान का सामरिक महत्व पहले जैसा नहीं रह गया है। हमारा मानना है कि यह बात सच नहीं। भारत के पूर्वोत्तरी सीमा के सदृश में विभेदकर मिश्रित के परिप्रेक्ष्य में भूटान सामरिक दृष्टि में महत्वपूर्ण बना रहता।

भारत के विरुद्ध चीन-पाक-अमरीकी धुरी (Sino-Pak-U. S Axis against India)

स्वतन्त्रता प्राप्ति के साथ ही देश के विभाजन के कारण भारत को दोनों पाक्षों पर 'शत्रु' का सामना करना पड़ा। भारत द्वारा अमरीकी सैनिक गठबन्धन की सदस्यता अस्वीकार करने पर पाकिस्तान की अमरीका का मोहरा बनना महत्त्व लगा और इसी कारण दक्षिण एशियाई भू-भाग में अमरीका-पाक मिश्रण आरम्भ हुई। कालान्तर में भारत-चीन सम्बन्धों में विवाद का नाम पाकिस्तान न उठाया। भूटो के दूरदर्शी-नचीन राजनय ने इसमें महायत्ना पहुँचायी। बंगला देश के उदय के बाद वियतनाम युद्ध के समाप्त होने-होने चीन और अमरीका के बीच भी मवाद आरम्भ हो चुका था। इस घटनाक्रम को मोवियन-चीन बंमनस्य ने प्रोत्साहित और गतिशील किया। 1972-73 तक भारत के विरुद्ध चीन-पाक-अमरीकी धुरी का निर्माण पूरा हो चुका था। इस मिश्रण में नहीं समझा जा सकता।

चीन आरम्भ से ही अपने को एशियाई भू-भाग में प्रमुख अद्वितीय शक्ति के

भी भारत सरकार का भयादोहन आरम्भ कर दिया। किन्तु भूटान नेपाल की तुलना में भारत का भयादोहन अधिक संयमित-संकीची तरीके से करता रहा। नेपाल की तरह भूटान के भारत के साथ तदी जल वितरण या तस्करी आदि को लेकर कोई मनमुटाव नहीं है। परन्तु भारतीय प्रभुत्व को लेकर भूटान व नेपाल की परेशानी एक जैसी है। हास के वर्षों में नेपाल की तरह अपनी स्वाधीनता प्रमाणित करने के लिए भूटान के लिए भारत के विरोध का स्वर मुखर करना अनिवार्य सा बन गया है। भले ही भूटान के दूतावास नई दिल्ली के अलावा सिर्फ सयुक्त राष्ट्र संघ और बंगला देश में ही है, किन्तु भूटानी राजनयिकों का खैया और रज-रज्जान अपने को भारत से अलग दर्शाने वाला रहा है।

भारत, नेपाल और भूटान के आपसी सम्बन्धों में दक्षिण एशियाई सहकार संगठन 'मार्क' की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होनी जा रही है। नेपाल का महत्व इसलिए भी बढ़ा है कि मार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थापित किया गया है तथा पाकिस्तानी परमाणु कार्यक्रम एवं लका में बिहली-तमिल साम्प्रदायिक हिंसा के कारण क्षेत्रीय सहयोग की पारम्परिक रूपरेखा धूमिल हो गयी है। वैसे भी मार्क की प्रस्तावना में पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा आदि के जिन क्षेत्रों को रेखांकित किया गया है, उनके समर्थन में नेपाल और भूटान के बीच आपसी सहयोग अधिक स्वाभाविक व सहज है क्योंकि उनकी बहुसंख्यक जनसंख्या मगोल-वंशज और एक जैसे प्राकृतिक-परिदृश की निवासी है। भारत को मरिच्य में इन दोनों देशों के साथ अपने सम्बन्धों का निर्वाह करते समय इस तथ्य को समुचित महत्व देना होगा।

पिछले दिनों भूटान में ऐसी घटनाएँ पटी हैं, जिनको लेकर भारतीय विदेश नीति निर्धारक चिन्ताग्रस्त हुए हैं। भूटान सदियों से अपने आप में सिमटा एक ऐसा भूमिबद्ध राज्य है, जिसके बारे में यह सोचा जाता था कि वहाँ कोई कष्ट या असंतोष नहीं है। आकस्मिक युवक जिम्मे सिंधेवागचुक वहाँ के शासक ही नहीं, परंपरा भी थे। भूटान की सांस्कृतिक पहचान इतनी स्पष्ट और पक्कीमियों से भरी थी कि यह सोचने का मवाल ही नहीं उठता था कि मुस-शांति वाली घाटियों में किसी तरह की हिंसक उपल-पुषल मच सकती है। मगर यह भ्रम आज टूट चुका है। जिम्मे सिंधे वागचुक के एकछत्र देवीय धामनाधिकार को चुनौती देने वाले लोकतांत्रिक असंतोष का विस्फोट एकाधिक बार हो चुका है। इसकी तुलना नेपाल में राजमाही के विरुद्ध जनमर्ष से नहीं की जा सकती। भूटान में जिम्मे सिंधे वागचुक और उनके समर्थकों का कहना है कि यह सारी गडबडी राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने वाले विदेशी पड़वप्रकारी कर रहे हैं। यह बात सच है कि पिछले 30-40 वर्षों में भूटानी जनसंख्या का स्वरूप तेजी से बदला है। रोजी-रोटी की तलाश में जाने वाले मजदूर, कारीगर और व्यापारी वहाँ बड़ी संख्या में बस गये हैं। इनमें से अधिकांश नेपाली मूल के हैं। भाषा, रहन-सहन, धर्म, किसी भी मापने में इनका कोई साम्य भूटान के मूल निवासियों से नहीं है। जहाँ यह बात तर्कवगव है कि पीढ़ी दर पीढ़ी भूटान में रहते आये वे लोग अपने को दूसरे दर्जे का नागरिक मानने के लिए तैयार नहीं, वही इनको लेकर भूटानियों की चिन्ता भी समय में जाती है। आज भूटान के सामने यह पतख उपस्थित है कि भूटानी अपने ही देश में वही अल्प संख्यक न बन जायें और भूटान अपनी सांस्कृतिक पहचान न गवा दे। भूटान के सामने निविक्रम का उदाहरण है, जहाँ आज नेपालियों की बढ़ती

माघ मंत्री सम्बन्ध पुष्ट विय । चीन इस वक्त दान और दह दोनों उपकरणों का कुशल प्रयोग करने की स्थिति में था । 1962 के भारत की छवि शिथिल-यतनोन्मुख देश की थी तो चीन की एक उदीयमान शक्ति के रूप की ।

नेपाल की तरह थोल्का का झुकाव भारत-चीन संघर्ष के बाद से चीन की ओर बढ़ा । चीन-समर्थित छापामार जनजातियों के विप्लव को देखते हुए बर्मा की सरकार भी चीनी आशा-अपेक्षा के अनुरूप भारत से विलग हो गयी । पाकिस्तान में इस समय फील्ड मार्शल अयूब खा का शासन था और उनके युवा विदेश मंत्री जुलिकार अली भुट्टो भारत की अधमता का भरपूर लाभ उठाने का कोई अवसर नहीं ढूँढना चाहते थे । भुट्टो की स्थिति और उनका अति-समर्थवादी विश्व दर्शन चीनी समूहों की पूर्ण में महायुक्त बना । चीनियों ने पाकिस्तान के माघ उमके द्वारा अविच्छिन्न कश्मीर के बारे में एक सीमा समझौता कर लिया । इसके बाद भविष्य में किमी विवाद की समाधान का उन्मुख करने के माघ-साथ भारत को और अधिक असमंजस में डालने वाली स्थिति पैदा हुई ।

इन्हीं दिनों वेल्सप्रेड गिल्लर सम्मेलन (1961) में मुकाबलों और नेहरू जी की मुठभेड़ हुई । यों यह टकराव दो भिन्न व्यक्तित्वों तथा परस्पर-विरोधी चिन्तन प्रणालियों से उपजा था, परन्तु इसका प्रभाव भारत-चीन सम्बन्धों पर पड़े बिना नहीं रह सकता । एक ओर मुकाबलों का मानना था कि नवउपनिवेशवाद अन्तर्राष्ट्रीय मान्दिक नियमों से बड़ा सबूत है तो दूसरी ओर नेहरू जी का मानना था कि नव-उपनिवेशवाद सही अधिक अहिंसक परमाणु युद्ध को टालने को दी जानी चाहिये । नेहरू जी शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के हिमायती थे तो इण्डोनेशिया मुठभेड़ का । गुट निर्पक्ष नेम में इस अन्तर-दृष्टि का तान उठाते हुए चीन ने नेहरू जी को समय से पीछे छोड़ दिया अर्थात् असमंजस में मिट्टी करने का प्रयत्न किया । इण्डोनेशिया और भारत के बीच वैमनस्य बढ़ाने में चीन की महायुक्त इण्डोनेशियाई साम्यवादी पार्टी ने भी की, जो मुकाबलों सरकार की एक आधार स्तम्भ थी । 1965 तक पीकिंग-जकार्ता-विही घुरी चारणर हो चुकी थी और यह साक्षात् ज्ञात है कि इनके अभाव में 1965 में भारत-पाक मुठभेड़ गायब नहीं होती ।²

1969 में चीन में महान साम्यवर्तिक क्रान्ति के मूत्रपात में बाद व्यापक उषा-मुषा हुई और राजनयिक मामलों कुछ समय के लिए वृष्टभूमि में घबल दिया गया । उधर इण्डोनेशिया में मुकाबलों का तत्का पनट दिया गया और पाकिस्तान में अयूब खा के बिहद असहाय-आश्रय के विस्फोट ने उन्हें विस्थापित कर दिया ।

परन्तु इसमें तत्का असमंजस बलन होगा कि भारत ने इस घटनाक्रम का लाभ उठाया । पाकिस्तान में भारत के 'बेरी' भुट्टो प्रभावशाली बन रहे और अमरीका तथा चीन का एक-दूसरे के बरोबर तान में अध्यस्थ की भूमिका निभाने के बाद भारत को उन्होंने और भी अकला-असहाय (मामरिक दृष्टि में) बना दिया । बगला देश मुक्ति अभियान के दौरान चीन का आचरण अनुसरणीय व घौम-घमकी वाला इसलिए बन गया कि वह इस बार में आश्वस्त था कि इस बार अमरीका का समर्थन भारत का नहीं मिलेगा । बगला देश युद्ध के दौरान अमरीका ने युद्धपोत पननय अपनाकर भारत को आनक्ति करने का प्रयत्न किया और इसके बाद से चीन-पाक-अमरीकी

² बिहार के निरु दह—Air Marshal (Retired) M. Asghar Khan, *The First Round: Indo-Pakistan War, 1965*.

रूप में देलना और पेश करता रहा। औपनिवेशिक काल में जैसे ही भारत के राष्ट्रवादी नेताओं के साथ चीनी नेताओं ने भाईचारा जतलाया हो, लेकिन साम्यवादियों द्वारा नत्ता ग्रहण करने के बाद बराबरी का नाव कभी उनके मन में नहीं रहा। माओ और चाऊ एन साई जैसे नेताओं को यह बात सिन्न करती रही कि आकार में छोटा, अपेक्षाकृत कम जनसंख्या वाला भारत अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन की तुलना में अधिक प्रतिष्ठित है। इसके कई कारण थे। ब्रिटिश औपनिवेशिक रितों के कारण भारतीय नेता अंग्रेजी भाषी थे और ब्रिटिश तथा अमरीकी समा-समितियों के नीचे तरीकों से भत्ती-भाँति परिचित भी। भारत ने अपनी आजादी शान्तिपूर्ण तरीके में प्राप्त की थी और गांधी-नेहरू जैसे सुधारवादी नेता अन्य देशों के जन-मुक्ति मैनिफेस्टो की अपेक्षा कम खतरनाक मझे जाते थे। इलेम जैसे ही गुट निरपेक्षता को 'अविश्वसनीय अवसरवादिता' समझते रहे हों, किन्तु शीत युद्ध के काल में तटस्थता शत्रु की पक्षधरता में बड़ी अधिक सहनीय थी। भारत विदेशी सहायता लेने को तैयार था, जिससे एक ग्लोबल तन्त्र का खुलापन भारतीय मताज में था।

भारत, अफ्रीका और एशिया के अन्य देशों के पहले स्वतन्त्र हुआ और उसने अनेक अन्य मुक्ति संग्रामों को अपना समर्थन दिया। बाङ्गु मम्बेलन (1955) तक बर्मा, इण्डोनेशिया, मिस्र आदि नेहरू जी को अपना अगुवा मानने लगे थे। चीन के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री चाऊ एन साई ने अपने सम्मरणों में यह बात स्वीकार की है कि बाङ्गु के अवसर पर उनके प्रति नेहरू जी और कृष्णा मेनन का आचरण कृपालु-सरलक जैसा ही था। उस वक्त चीन को जैसे ही घुन का घूँट पीना पड़ रहा हो, किन्तु भागे चलकर उसने इस मान हानि का बदला लेने का निश्चय कर लिया था। जब तक चीनियों को कोरियाई घटनाक्रम के बाद या हिन्द चीन प्रसंग में अमरीकियों का मुकाबला करने के लिए भारतीय समर्थन की आवश्यकता थी या जब तक वे आर्थिक व तकनीकी विकास के लिए नोचियत सघ पर निर्भर थे, उनका आचरण सघत रहा। परन्तु एक बार भारत के साथ भीमा विवाद को लेकर मम्बन्धों में कड़ुता प्रकट होने के बाद बेहिक भारत के खिलाफ राजनयिक मोर्चाबंदी आरम्भ कर दी। 1960 में लेकर 1979 तक वे इस काम में लगे रहे और भारतीय विदेश नीति के क्रियान्वयन को निधिल करने में एक बड़ी नीमा तक मफल भी रहे।

चीन के इस राजनयिक अभियान को 'चीन-शत्रु-अमरीका मठजीड़' के रूप में पहचाना जाना है। कुछ वर्षों पहले तक इसका एक दूसरा रूप 'विश्वी-जकार्ता-पौकिंग घुरी' के रूप में दीखता था। समय-समय पर इस विपक्षीय मोर्चे में नेपाल, भूतान, बंगला देश जैसे सहयोगी-अनुसर जुटते-जुड़ते रहे हैं। भारत को अकेला करने की दिशा में चीन द्वारा उठाया पहना कदम नेपाल को अपनी ओर आकर्षित करना था। भारत-चीन भीमा विवाद के दौरान नेपाल की पूर्ण तटस्थ भूमिका ने भारतीयों को सिन्न किया। महाराजा महेन्द्र इन बात के लिए सटिबद्ध थे कि उनके निरन्तर शासन को किसी भी तरह की कोई चुनौती न दे सकें। वह यह बात भत्ती-भाँति पहचानते थे कि नेपाल में जनताम्यिक परिवर्तनों को भारत सरकार का समर्थन-महानुभूति प्राप्त है। जैसे ही भारत में इस मामले में पूरी सतर्कता बरती कि नेपाल उस पर अपनी आन्तरिक राजनीति में हस्तक्षेप का आरोप न लगा सके, तब भी इस परिवर्तन में भारत-नेपाल सम्बन्धों का पारम्परिक मोहार्द कम हुआ। चीन ने इसका ग्लोबल उद्घाटन और बड़े पैमाने पर आर्थिक अनुदान की घोषणा कर नेपाल के

किं भय हा ऊपर से अमरीका कुछ भी नहीं, अमरीकी-याक गठबन्धन और इन दाना दाना के हिता का सामरिक मजबूत अभी बरकरार है। इस्लामी कट्टरपंथी विचार-धारा के उफान और मादक द्रव्यों की तस्करी को लेकर अमरीका व पाकिस्तान के बीच नले ही बीच-बीच में मनमुटाव पैदा होना है, किन्तु इससे वस्तुस्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता। अमरीकी सीनेट समय-समय पर पाकिस्तानी परमाणु कार्यक्रम पर चिन्ता प्रकट करती है परन्तु इन कार्यक्रम की प्रगति अब तक अबाध रही है। अमरीकी विशेषज्ञ इस बात का प्रमाण जुटाते नहीं सकते कि पाकिस्तान ने अभी बम हासिल नहीं किया है। वे कहते हैं कि यदि वह ऐसा करेगा तो उस अमरीकी सहायता से हाथ धोना पड़ेगा आदि। यह प्रश्न पूछने की फुसत किसी को नहीं कि यदि पाकिस्तान परमाणु बना लेता है तो उस अमरीकी सहायता की विषय अरुण नहीं रहेगा और इस इस्लामी बम को काबू में रखने के लिए अमरीका उसका साथ और भी अधिक लचीला रख अपना मकाना है। एफ-16 विमान हो या अवाकस, परमाणु कार्यक्रम हा या अफगान मुजाहिदीन के नाम पर दी गयी आर्थिक सहायता, इनका निदाना अलग भारत ही रहे। अमरीकी नतागण पूरे निष्ठाधार के साथ ही महा, भारत को यह धमकी देने का कोई अवसर नहीं देखते कि वे पाकिस्तान के ओर विघटन के झुक माथी नहीं रहेंगे।

आज इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान अमरीकी सैन्यीय समर्थन का एक प्रमुख अंग है और एशिया में चीन-अमरीका-याक घुर्नी में विशेष महत्वपूर्ण राष्ट्र। मुझे वे जीवन काल के बल ही पाकिस्तानी राजनयिका ने चीन और अमरीका का उपयोग किया हो, परन्तु आज अमरीका और चीन मिला-जुलकर उसे अपने इशारा पर नवान की स्थिति में है। जहाँ तक पाकिस्तानी परमाणु कार्यक्रम का प्रश्न है, अन्तर्राष्ट्रीय सामरिक परिदृश्य में चीन और अमरीका के हित इसमें निविध होन में ही समित हैं। जब तक इस विषय में स्थिति अस्पष्ट रहती है, तब तक भारत चीन टकराव में चान का पक्ष प्रबल रहेगा। समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचनाओं के अनुसार चीनी प्रणेतास्वा का लक्ष्य हिमाली और अमृतसर जैस नगरों को बनाया गया है। अमरीकी विशेषज्ञ ने भारत के मयादाहन के लिए इस बात की विस्तृत पड़नाम शुरू कर दी है कि भारत-याक परमाणु युद्ध के किनसे मवनायक परिणाम होंगे।

अमरीका-चीन गठबन्ध—भारत के विरुद्ध अमरीकी चीन काठगाठ उतनी प्रबल नहीं जितनी पाकिस्तान के मन्दन में। किं भी अमरीकी और चीनी राष्ट्रीय हिता का मद्रिपान दूरगामी महत्व का है। 1950 और 1960 के दशक का पयाव कुछ भी नहीं है, 1971-72 में आरंभक मारा घटनाक्रम इसी तथ्य को उदघाटित करता है। जब बगता दम मुक्ति अभियान के दौरान हनरी किंसिंगर ने भारत के विरुद्ध पाकिस्तान के प्रति मुकाब (Tilt) का नानि अपनायी तो इसमें प्रोत्साहित होकर चीन ने उत्तर-पूर्वी सीमान्त में धमकी देने के अन्दाज में मैच मचायन किया। मित्रिम के दिनय की कानी भरमार ने कड़ी आलाचना की और मयमय न्ना तरल के तर्कों के आधार पर अमरीका समाचार-पत्रों में भारत की निन्दा की गयी। अब तक यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि मित्रिम के चांगवात की अमरीकी प्रेयमी-यत्नी हाथ कुछ कुछ समय के लिए ही मित्रिम प्रेमी बनी थी। उसके अमरीकी गुप्तचर मस्या में सम्बन्ध हान वाली धकाओं का निवारण अभी

धुरी जगजाहिर हो गयी।

1971-72 से आज तक इस राजनयिक स्थिति में कोई विशेष महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। विद्वानों तो यह है कि आज बगला देव भारत की अपेक्षा चीन और पाकिस्तान के अधिक निकट है और उस पर अमरीकी प्रभाव साफ देखा जा सकता है। पाकिस्तानी परमाणु कार्यक्रम को वांछित चीनी सहायता मिलती रही और विद्वानों का मानना है कि 'ट्रिगर' का परीक्षण चीनी भूमि में ही किया गया है। काराकोरम राजमार्गों का निर्माण चीनी सहायता से हो रहा है और पाकिस्तान को परिष्कृत चीनी यन्त्रों की विश्व निरन्तर बढी है। ऐसा नहीं लगता कि निकट भविष्य में स्थिति में कोई परिवर्तन होगा और भारतीय राजनय की चीन-पाक-अमरीकी धुरी को निष्फल बनाने के लिए प्रयत्नशील रहना पड़ेगा।

अमरीका-पाक गठजोड़—एक प्रकार से 1947 से ही विभिन्न अमरीकी सरकारों ने भारत के विनाश पाकिस्तान का पक्ष लिया है। जब नेहरू जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि मुटु निरपेक्ष भारत किसी भी अमरीकी संगठन में शामिल नहीं हो सकता तो उसे मन्तुलित करने के लिए अपनी सामरिक जरूरतों के अनुसार अमरीका ने पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर सैनिक माद साप्लाव देना आरम्भ किया। इन सैनिक सहायता की परिणति अन्ततः पाकिस्तान में सैनिक तानाशाही की स्थापना में हुई। यह अमरीकी राष्ट्रीय हित के अनुकूल था, क्योंकि जनता द्वारा चुने गए किसी जनतान्त्रिक नेता की अपेक्षा तानाशाह की नियमित-अनुशासित रचना सामान है। सैनिक संगठन 'मिएटो' तथा 'सेन्टो' की सक्षमता ग्रहण करने के बाद पाकिस्तान और भी खुले रूप से अमरीकी प्रभाव क्षेत्र में आ गया। भले ही फोर्ड मार्शल अग्रव व्हा ने अपनी जीवनी का शीर्षक 'फ्रेंड्स, नोट मास्टर्स' रखा, तब भी हर निष्पक्ष विवेचक का यही मानना रहा है कि पाकिस्तान की स्थिति अमरीका के उपग्रह-निबिडानुचर में अधिक नहीं।

पाकिस्तान और अमरीका में घनिष्ठ सम्बन्ध सिर्फ सैनिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहे। भारत की तरह आत्म-निर्भर आर्थिक विकास का कोई हठ पाकिस्तान का नहीं रहा और अमरीकी कम्पनियाँ-बैंकों के लिए पाकिस्तानी बाजार खुला रहा है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि इन बाजार का आकार कितना बड़ा है और अमरीका इसमें कितना मुनाफा कमाना है। अमली बात तो यह है कि इन सम्बन्धों में जो आत्मीयता पनपी, उनका राजनयिक लाभ उठाया जाता रहा है। गीत बुद्ध के कर्णों में पाकिस्तान ने इस क्षेत्र में संतरी बुज (स्पॉट) की भूमिका निभायी। मौखिक संधि के ऊपर उड़ान भरने वाले अमरीकी यू-2 विमान पेगावर अड्डे पर ही तैनात थे और अरोसेमद सेवा का नरपूर पुरस्कार पाकिस्तान को मिला। चीन और अमरीका को घाम जलने में पाकिस्तान ने महत्वपूर्ण योगदान दिया।

1973 में तेन मकट के जाविभाव के बाद अमरीकी नीति-निर्धारकों ने पश्चिम एशिया में तुरत तैनाती दस्ते (Rapid Deployment Force) की बात सोची और केन्द्रीय कमान का गठन किया। अफगानिस्तान में सोवियत सैनिक हस्तक्षेप और ईरान में माह के पतन के बाद इक्षिण एशियाई ही नहीं, पश्चिम एशियाई मन्दर्म में भी पाकिस्तान अपनी यू-राजनीतिक स्थिति के कारण कई गुना अधिक महत्वपूर्ण बन गया। पाकिस्तान को दिये गये जवाकम विमान, एफ-16 नरान्क विमान और 3-2 अरब डॉलर की सैनिक सहायता इस बात के प्रमाण हैं

भारत आकार, आबादी, शक्ति-सामर्थ्य, सम्भावना और धमती की दृष्टि से अपने पड़ोसी देशों की तुलना में दैत्याकार है। पाकिस्तान, बंगला देश, नेपाल और लका सांस्कृतिक दृष्टि से जुड़वाँ महोदर से हैं। प्रखर राजनयिक टिप्पणीकार शिशिर गुप्ता यह कहा करते थे कि इन छोटे पड़ोसी देशों के लिए यह एक मनो-वैज्ञानिक विवशता है कि वे अपनी स्वतन्त्र राष्ट्रीय पहचान प्रमाणित करने के लिए भारत-विरोध का स्वर निरन्तर मुखर करते रहे हैं। इनमें से अनेक पड़ोसी देशों ने समय-समय पर बाहरी शक्तियों की हस्तक्षेप का आमन्त्रण देकर भारत को कृत्रिम रूप से सन्तुलित करने का प्रयत्न किया है। इसमें पाकिस्तान का अमरीका के साथ सैनिक गठबन्धन, नेपाल का चीन के प्रति झुकाव और लका की हिन्द महा-सागरीय नीति उल्लेखनीय है। यदि भारत अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन भर करता है तो उस पर भयादोहन (Blackmail) का आक्षेप लगाया जा सकता है। यदि भारत अपनी सहायता-मदभावना प्रमाणित करने के लिए रियायतें देता है तो पड़ोसी देश उसकी दुर्बलता का लाभ उठाने का प्रयत्न करते हैं और अपनी विवशमनीयता गँवाते रहे हैं। जनता सरकार के कार्यकाल में नेपाल के साथ सन्धि का पुनरीक्षण, पुनर्नवीनीकरण, संशोधन तथा बंगला देश के साथ फरक्का जलबन्ध समझौता इस अग्रिम तथ्य को उद्घाटित करते हैं। पाकिस्तान के विषय में ताश्कन्द और क्षिमला समझौते तथा लका के सन्ध में शास्त्री-सिरिमाओ समझौता तथा राजीव-जयवर्द्धने समझौता इसी कारण निष्फल रहे हैं।

विद्वानों का मानना है कि दक्षिण एशियाई सहकार परियोजना : 'सार्क' से भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच सम्बन्धों में सामाज्यीकरण की दिशा में प्रगति हो सकेगी, परन्तु हमारी समझ में इस मामले में बहुत आघातवादिता की गुंजाइश नहीं। भारत के सभी पड़ोसी देशों के सामूहिक हित इसी में हैं कि वे एक साथ एकजुट होकर भारत पर दबाव डाल सकें। दुर्भाग्यवश हाल में दिना के घटनाक्रम ने दक्षिण एशियाई भू-राजनीतिक स्थिति को और भी जोखिम में डाला है। पाकिस्तान में बढ़ती अमरीकी उपस्थिति, लका में विदेशी प्रवेश तथा सर्वत्र आतंकवाद एक साम्प्रदायिक विद्वेष में वृद्धि ने महार की अपेक्षा टकराव की सम्भावना ही बढ़ायी है। चीन और पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों में सामाज्यीकरण की दिशा में ठीस प्रगति के अभाव में अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी सम्बन्ध अमहज ही बने रह सकते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यही निष्कर्ष तर्कसंगत लगता है कि भारत पड़ोसी देशों के साथ अपने सम्बन्धों के निर्वाह में पूर्णतः असफल नहीं समझा जा सकता। हालांकि यह जोड़ने की जरूरत है कि निरन्तर भविष्य में उस कुशल एवं मर्क राजनय की आवश्यकता पड़ती रहनी।

भारत व दक्षिण-पूर्व एशिया (India and South-East Asia)

आज जिस भू-भाग को दक्षिण-पूर्व एशिया कहा जाता है, उसमें बर्मा (म्यान-मार), थाईलैण्ड, मलयेशिया, सिंगापुर, इण्डोनेशिया, कम्बोदिया, लाओस, वियतनाम और फिलीपींस नामक देश शामिल हैं। इस क्षेत्र में सबसे नवादिन राष्ट्र वुनई है, परन्तु इसे एक तरह से मलय राष्ट्र का पर्याय-परिधिष्ट (Synonym and Appendix) ही समझा जाता है। वुनई अपने छोटे आकार और अपार तेल सम्पदा के कारण

नहीं हो पाया। इसी तरह जिस समय चीन भारत के उत्तर-पूर्वी सीमान्त पर नागा-मिजो विद्रोहियों को सैनिक साज-सामान, सहायता और धरण दे रहा था, उस वक्त अमरीकी मिशनरी इस क्षेत्र में सक्रिय थे और राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा से कटे इन अल्पसंख्यकों में राजनीतिक चेतना के नाम पर अलगवा फैला रहे थे।

अमरीका ने चीन के पक्ष में अपना राजनय बेहद कुटिल ढंग से सम्पादित किया। सतही दृष्टि डालने से यह लग सकता है कि जो अमरीकी तिब्बत की स्वाधीनता के पक्षधर रहे हैं और दलाई लामा को हर सम्भव सहायता देते रहे हैं, वह क्यों चीन के पक्षधर हो सकते हैं? दलाई लामा भारत में शरण लिये हुए हैं। अब तक तिब्बत का प्रश्न हल नहीं होता, भारत-चीन सम्बन्धों के मामानीकरण में एक बड़ी अड़चन बनी रहेगी।

अब तक कई घटनाओं में अमरीका यह दर्शा चुका है कि भारत के भूमिबद्ध पड़ोसियों नेपाल व भूटान के राजनयिक परीक्ष रूप से भारत के विरुद्ध सूक्ष्म प्रचार द्वारा चीन की स्थिति मजबूत करते हैं। बाद में अमरीकियों ने भाबरण के पीछे काम करना बन्द कर दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से भारत को यह मैत्रीपूर्ण सलाह दी कि उसे सीमान्त पर चीन की बढ़काने-उकसाने वाली कोई हरकत नहीं करनी चाहिए, अन्यथा इसके खतरनाक परिणाम सामने आ सकते हैं। इसके ठीक पहले चीन ने भारत पर यह आरोप लगाया था कि भारत विवादास्पद सीमा के आस-पास उसकी जमीन कुतर रहा है। अमरीकी विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी की चीन गया के बाद बिया गया यह वक्तव्य अमरीकी पक्षपात का उदाहरण है।

अवगाहल को राज्य का दर्जा दिये जाने का चीन ने जोरदार विरोध किया। उस वक्त भी अमरीकी प्रशासन ने भारत की भौगोलिक अलगपड़ा या अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सीमा के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की। यदि वस्तुनिष्ठ ढंग से देखें तो इनो निष्कर्ष तक पहुँचा जा सकता है कि जाने वाले कई वर्षों तक चीन-अमरीकी-नाक धुरी भारत के लिए मिरदर्द बनी रहेगी। जहाँ पाकिस्तान और अमरीका ने भारत के साथ 'वैर' अवसरकारी ढंग से निभाया है, वहीं चीन ने एक मुनिचित-मुनिपोजित कार्यक्रम के अनुसार भाबरण किया है। आज शक्ति-सामर्थ्य और प्रतिष्ठा की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर चीन और भारत की कोई समता नहीं रही। इस उपलब्धि के लिए पहले करण ने पोलिंग-पिण्डो-जकार्ता धुरी तथा बाद के वर्षों में चीन-अमरीका-नाक त्रिकोण बेहद उपयोगी सिद्ध हुए।

पड़ोसी देशों के प्रति भारतीय विदेश नीति का मूल्यांकन

(Assessment of Indian Foreign Policy Towards
Its Neighbouring Countries)

उपर्युक्त मर्षण से ऐसा लग सकता है कि पड़ोसी देशों के साथ भारतीय विदेश नीति बुरी तरह अक्षत रही है। चीन हो या पाकिस्तान, नेपाल हो या श्रीलंका, बंगला देश हो या भूटान, सभी पड़ोसी देशों के साथ भारत के कटु विवाद उभरते रहे हैं। चीन, पाकिस्तान और श्रीलंका के सन्दर्भ में बस प्रयोग तक की आवश्यकता पड़ चुकी है। परन्तु यदि वस्तुनिष्ठ ढंग से देखें तो यथार्थ इसमें भिन्न है।

राजनयिक सम्पर्कों का प्रश्न ही नहीं उठता था। बाद के वर्षों में राष्ट्रमण्डल की मदस्यता तथा बड़ पैमाने पर भारतीय मूल के नागरिकों के रहने के कारण मलयेगिया और सिंगापुर के साथ भारत की घनिष्टता रही है।

सम्बन्धों में नाटकीय परिवर्तन—1960 वाले दशक में दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत के सम्बन्धों में नाटकीय परिवर्तन हुआ। इसका एक प्रमुख कारण वियतनामी गृह युद्ध में अमरीका का बढ़ता हस्तक्षेप था। दूसरा कारण दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की आन्तरिक राजनयिक स्थिति में परिवर्तन था। एक ओर इण्डोनेशिया में सुकार्णो की सरकार व्यक्तिगत तानाशाही में बदल गयी तो दूसरी ओर मलयेगिया और सिंगापुर एक महासंघ की स्थापना पर विचार करने लगे। इन प्रस्ताव को उकर पश्चिमी क्षेत्र के पक्षधर देशों में भी फूट पड़ गयी। इन्हीं वर्षों में चीन के साथ भारत के सम्बन्धों में तेजी से बिगाड़ हुआ और नू राजनीतिक कारणों से इसका प्रभाव दक्षिण एशियाई देशों के साथ भारत के सम्बन्धों पर पड़ा। नेहरू जी के जीवन काल में भारत की विदेश नीति या तो महाशक्तियों पर केन्द्रित (विश्व शान्ति गुट निरपेक्षता आदि को उकर) रही या उसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की चुनौती का सामना करने में बीता। 1947 से 1964 तक भारतीय विदेश नीति निम्नलिखित के पास दक्षिण पूर्व एशिया के छुटभय्या में लिए फुसत न थी।¹

तीन प्रमुख कसौटियाँ—वस्तुतः दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के सम्बन्धों का समुचित विवरण इन्दिरा गांधी के कार्यकाल में ही किया जा सकता है। तब से अब तक भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच सम्बन्धों को तीन प्रमुख सीढ़ियों में बाँटा जा सकता है—सामरिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। इन्हीं कसौटियों को उपलब्धियों पर कमा जाना चाहिये। अफ़ग़ानिस्तान देशों तथा वियतनामी वचस्व वाले हिन्द चीन के बीच दृढ़ में भारत की भूमिका को समुचित ढंग में समझने के लिए भी अपने राष्ट्रीय हित को इन तीन श्रेणियों में विभाजित कर विस्तारित करना उपयोगी होगा।

1965 का युद्ध और भारत इण्डोनेशिया सम्बन्ध—1965 की भारत-पाक सैनिक मुठभेड़ ने भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच सम्बन्धों पर बुरा असर डाला। इण्डोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकार्णो भारतीय नौसेना में बुरी तरह विमुख हो चुके थे। उन्होंने इस युद्ध के दौरान पाकिस्तानी गामकों को यह सन्देश भेजा कि यदि वे चाहें तो वह भारत को मुसीबत में डालने के लिए अश्वमेध निकादार द्वीप समूह पर कब्जा कर सकते हैं। यह याद रखना आवश्यक बात है कि इण्डोनेशिया के द्वीप समूहों से यह आग्राय प्रदत्त कुछ ही किलोमीटर दूर है और नौमनिक दृष्टि से हिन्द महासागर के एक बहुत बड़े इलाके पर नियन्त्रण बनाए रखने के लिए इसका अपना सामरिक महत्व है। पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव में रुचि नहीं दिखायी। इसके तत्पश्चात् बाद इण्डोनेशिया में सुकार्णो का गिरा पड़ा और बहुत बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक रक्तपात हुआ। तत्पश्चात् मुहार्तों ने गामकों की बाधशर में मानी और इण्डोनेशियाई राजनीति में साम्प्रदायिकों का मयाया धुस हुआ

¹ इस बारे में विद्वत्तापूर्ण विश्लेषण के लिए देख—D. R. Sardesai *India's Foreign Policy in Communist Laos and Vietnam 1947-1964* (Buckley 1963) और Too That Th en *India and South East Asia 1947-1960* (Geneva 1963)।

भले ही अक्सर चर्चित रहा है, परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय राजनयिक शक्ति समीकरणों में इसका महत्व नगण्य है। दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में बर्मा पूर्णतः तटस्थ व एकान्त-वासी देश है और कम्बोडिया, लाओस एवं वियतनाम को छोड़कर अन्य सभी छह देश क्षेत्रीय संगठन 'वासियान' के सदस्य हैं। वासियान देश का ख़ात पश्चिमी-पूँजीवादी है और अमरीकी सामरिक परिप्रेक्ष्य में उनकी साझेदारी है। हिन्द चीन के राष्ट्र लाओस, कम्बुचिया व वियतनाम समाजवादी-साम्यवादी राष्ट्र हैं और सोवियत संघ के पक्षधर। इनके बावजूद वियतनाम चीन के साथ युद्ध ख़ाद चुका है। इन सब बातों का आरम्भ में उल्लेख जरूरी है क्योंकि दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत के सम्बन्ध एक बड़ी सीमा तक इन अन्तर-सम्बन्धों के आधार पर संचालित होते हैं।

सदियों पुराने सम्बन्ध—'दक्षिण पूर्व एशिया' शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान साठें माउन्टबेटन ने किया था जो तबका स्थित दक्षिण-पूर्व एशियाई कमान के सेनानायक थे। परन्तु इन देशों के साथ भारत के सम्बन्ध सदियों पुराने हैं। हिन्द चीन में कुनान और चम्पा के राज्य तथा इण्डोनेशिया में श्रीविजय, मजपहित, जैनेन्द्र आदि साम्राज्य आज भी इतिहास की पुस्तकों में 'बृहत्तर भारत' के दीर्घक से प्रतिष्ठ हैं। फिलीपींस को छोड़कर इन सभी दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की भाषा, संस्कृति, कला व समाज पर भारत की छाप स्पष्ट देखी जा सकती है।¹ जिस वक्त भारत आजाद हुआ, उस वक्त नई दिल्ली ने एशियाई सम्बन्ध सम्मेलन (1947) के आयोजन में दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत के सम्बन्धों को सौहार्दपूर्ण एवं स्थिर बनाने में सहायता प्रदान की। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान नेहरू जी के व्यक्तिगत सम्पर्क वियतनाम के हो की मिन्ह तथा इण्डोनेशिया के हट्टा एवं मुकार्णों जैसे लोगों से हुए थे। बाद में जोंगसांग उनके करीब आये और कम्बुचिया के सिंहनुक उनसे प्रभावित हुए। फिर भी यह सोचना गलत होगा कि भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के सम्बन्धों में कोई उतार-चढ़ाव नहीं आया।

शीत युद्ध का आविर्भाव व भारत-दक्षिण पूर्व एशिया सम्बन्ध—शीत युद्ध के आविर्भाव के साथ दक्षिण-पूर्व एशिया साफ-साफ तीन हिस्सों में बँट गया। एक ओर सैनिक संगठन 'सिएटो' के सदस्य देश (थाईलैण्ड, दक्षिण वियतनाम व फिलीपींस) ये तीनों ठोमरों और गुट-निरपेक्ष देश (इण्डोनेशिया, बर्मा व कम्बुचिया) ये। इनके अलावा सोवियत संघ व चीन के पक्षधर देश (उत्तरी वियतनाम व लाओस) ये। गुट-निरपेक्षता व नेहरू के व्यक्तिगत रुझान और संस्कार के कारण 1947 से लेकर 1960-61 के दौर तक भारत के सबसे करीबी एवं मधुर सम्बन्ध इण्डोनेशिया व कम्बुचिया के साथ रहे। हालाँकि उन्होंने सिएटो के सदस्य देशों की निरन्तर भत्सना की तथापि मासृतिक कारणों से थाईलैण्ड के साथ भारत के सम्बन्ध मधुर रहे। यह उल्लेखनीय है कि 1950 बाने दफक में मलयेशिया व सिंगापुर पराधीन थे और 1954 के जेनेवा सम्मेलन तक हिन्द चीन के देशों के साथ भी स्वतन्त्र

¹ इन्हें—John F. Cady, *South East Asia: Its Historical Development* (New York, 1964); G. Coedès, *Indianized States of South East Asia* (Honolulu, 1963); और B. R. Chatterji, *Southeast Asia in Transition* (Meerut, 1963).

जैसे पारम्परिक मित्रों का प्रभाव इस क्षेत्र में और भी कम हुआ।

निराशाजनक अवमूल्यन से बचाव—इसके साथ ही कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ-पटनाएँ सामने आयी, जिन्होंने भारत को 'निराशाजनक अवमूल्यन' से बचाया। 1971 में बंगला देश मुक्ति अभियान के दौरान भारत ने अपने सैनिक बल का प्रदर्शन किया। इन्दिरा गांधी के कार्यकाल में हरित शान्ति की सफलता ने भारत को खाद्यालो के मामले में आत्मनिर्भर बनाया और उसके आत्म-सम्मान को लौटाया। भारत ने 1976 में चीन के साथ सम्बन्धों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया भी आरम्भ की। इन सब बातों का मिलता-जुलता प्रभाव यह हुआ कि दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए यह असम्भव हो गया कि वह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक सन्दर्भ में भारत को अवहेलना कर सके।

आसियान में भारतीय सहस्यता का मतलब—1967 में आसियान नामक क्षेत्रीय संगठन की स्थापना हुई, परन्तु इसका पहला गिखर सम्मेलन 1976 में आयोजित किया जा सका। इस सम्मेलन के बाद भी दक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीय भूमिका के बारे में अटकलें लगाया जाना तेज हुआ। इस समय तक वियतनाम में युद्ध विराम हो चुका था और वियतनाम का पुनरेकीकरण भी सम्पन्न हो चुका था। जहाँ एक ओर यह प्रभाव रखा गया कि भारत को आसियान के औपचारिक सदस्य के रूप में नहीं, मानद पर्यवेक्षक के रूप में ही आमन्त्रित कर लिया जाय, वहीं दूसरी ओर हिन्द चीन के समाजवादी दशा के साथ भारत की घनिष्ठता को दर्शन हुए पश्चिमोन्मुखी आसियान देशों की सरकारों की घबराहट थी। भारत के साथ सहकार और भी सीमित हुआ। इसमें सिंगापुर और इण्डोनेशिया ज्यादा मुखर रहे। भारत को आसियान में मानद पर्यवेक्षक या सदस्य बनाने पर भल ही मत्पक्षिया और साइडिंग स्वयं आपत्ति करने वाला नहीं थे परन्तु बाद में उनका आचरण भी पहले जैसा आत्मीय नहीं रहा।

भारत वियतनाम निबटता पर शकपूर्ण—यह सच है कि भारत ने वियतनाम को युद्धांतर पुनर्निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर सहायता दी और पोलपोट में विस्थापन के बाद कम्युनिस्टों के साथ भी तकनीकी और आर्थिक सहायता की प्रक्रिया तेज हुई। फिर भी, आसियान देशों का यह सोचना ठीक नहीं कि भारत की नीतियाँ एवं नीतिविधियाँ सामरिक दृष्टि से प्रेरित थीं और उनका राष्ट्रीय हितों के प्रतिबल था। शान्ति समझौते पर हस्ताक्षर करके बल स्वयं अमरीका ने वियतनाम को बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता देने का वचन दिया था। अमरीका के मुँह पर जान के बाद ही वियतनाम को अन्यत्र मदद ढूँढनी पड़ी थी। सामाजिक व राजनीतिक कारणों से वियतनामी सरकार ने अपने विराम के लिए जो दिया और मति तय की थी, उमर अनुसार भारत ही उनका 'अरोसमन्द सहायरी दन' मानित हो सकता था। यह सच है कि सोवियत संघ के साथ भी वियतनाम के सम्बन्ध बहुत मधुर रहे तथापि गमा नहीं साँचा जा सकता कि भारत ने सोवियत प्रभाव में आसियान राष्ट्रा के महत्व को कम करने के लिए किसी मुनियोजित पद्धति के अन्तर्गत कोई कदम उठाया। अनेक अमरीकी एवं अमरीका के पक्षधर विद्वान 1967 से 1986-87 तक यह विवरण प्रकाशित करते रहे कि दक्षिण-पूर्व एशिया में आसियान देशों और हिन्द चीन के दशा के बीच राजनीतिक व मासृतिक धुँवकरण हो चुका है और इसका दूरगामी सामरिक परिणाम होगा। यह निष्कर्ष बहुत तर्कमग्न नहीं था।

इस्लामी तत्व पृष्ठभूमि में चले गये और मुकाफों के करिश्माती नेतृत्व का स्थान मुहात्तों ने लिया। यह सब परिवर्तन इतने महत्वपूर्ण थे कि आज भी इण्डोनेशिया के इतिहास में इन दो कालखण्डों का अध्ययन पुरानों और नई व्यवस्था के रूप में किया जाता है।

मुकाफों के उपद्रव होने बाद भी भारत और इण्डोनेशिया के बीच सम्बन्धों में विशेष सुधार नहीं हो सका। इसके कई कारण हैं। मुकाफों का स्थान आन्तरिक कारणों से साम्यवादी चीन के प्रति या तो मुहात्तों अमरीका की तरफ झुके हुए रहे। दोनों ही हातों में इण्डोनेशिया के साथ गुट निरपेक्ष भारत की घनिष्ठता घट ही सकती थी। इसके अतिरिक्त मुकाफों के बाद इण्डोनेशिया में तैम की खोज, उसके शोध एवं निर्यात से इतने बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी कि उसके आर्थिक विकास कार्यक्रमों का स्वरूप ही आमूल-चूल बदल गया। आर्थिक दृष्टि से समर्थ होने के बाद इण्डोनेशिया के लिए भारत से प्राप्त हो सकने वाली मदद का कोई विशेष आकर्षण नहीं रहा। इस प्रकार इण्डोनेशिया क्रमशः अमरीका के निकट जाता रहा और उसकी गुट निरपेक्षता के ह्रास के साथ-साथ वियतनामी युद्ध में उसकी पक्षधरता ने उसे भारत से दूर किया।¹ इसके अलावा 1967 में 'आसियान' नामक क्षेत्रीय संगठन में गठन के साथ दक्षिण-पूर्व एशिया में क्षेत्रीय एकीकरण की भावना प्रबल हुई और भारत की पहचान एक बाहरी देश के रूप में सामने आयी। 1965 से 1969 तक इन्दिय गण्यी देश में दुर्घिस, विदेशी मुद्रा संकट और कांग्रेस पार्टी की अन्दरूनी फूट से जूझती रही थी। हिन्द चीन में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक आयोग में भारत की भूमिका अमरीकी आक्रामकता के उफान के सामने बिल्कुल निरर्थक मिट्ट हो रही थी। इन अधमता के प्रदर्शन के बाद दक्षिण-पूर्व एशिया के पड़ोसी क्षेत्र में भारत की आर्थिक क्षमता या सांस्कृतिक प्रतिष्ठा की बात करना बिल्कुल बेकार था। मिक इतना ही अच्छा रहा कि 1968-69 में चीन-सोवियत विग्रह के विस्फोट और चीन में महान सांस्कृतिक शान्ति के सूत्रपात के बाद चीन भी दक्षिण-पूर्व एशिया में निष्क्रिय हो गया। यदि ऐसा न होता तो भारत को और भी बड़ा राजनीतिक और सामरिक नुकसान उठाना पड़ता।

भारत के साथ सम्बन्धों की प्राथमिकता नहीं—स्वयं दक्षिण-पूर्व एशिया के देश आन्तरिक राजनीतिक दबावों के कारण अल्पज व्यस्त रहे। इनमें से किसी के लिए भी उभयपक्षीय कमीटी पर भारत के साथ सम्बन्ध प्राथमिकता प्राने नहीं थे। मलयेशिया और सिंगापुर आपसी सम्बन्धों के सामान्यीकरण में व्यस्त रहे तो कम्बुचिया ने 1970 में सिहानुक की तत्तापतट के बाद वननामक आत्मघाती गृह युद्ध के आरम्भ में हिन्द चीन के भविष्य पर कई प्रश्न चिन्ह लगा दिये। वियतनाम में यह युद्ध की समाप्ति और पुनर्र्दोकरण से भी स्थिति सहज रूप स्थिर नहीं हुई, क्योंकि वियतनाम-चीन सम्बन्धों में तनाव बढ़ने के साथ 'एक सीमित सीत युद्ध' इस क्षेत्र में गतह पर उभर आया। वहाँ ने तो 1962 में ही अपनी जलग एकान्तवासी राह पुन ली थी। अब उमने अपने को गुट निरपेक्ष आन्दोलन में भी बाहर कर लिया। इस दौर में ही बासान और आस्ट्रेलिनया दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र में अपना आर्थिक प्रभाव बढ़ाया और उनकी इन घुमपैठ के साथ दक्षिण-पूर्व एशिया के भारत

¹ भारत-एण्डोनेशिया सम्बन्धों पर बिलुप्त विवेचन के लिए देखें—B. D. Arora, *Indian-Indonesian Relations, 1961-80* (Delhi, 1981).

मार्कोम का पतन और कोरी एक्विनो द्वारा शासन की बागडोर सभालने (1986) के बाद भारत को इस दूरस्थ देश के साथ घनिष्ठता बढ़ाने का मौका मिला। मार्कोस के 18 वर्षीय शासन काल में लगभग एक दर्जन वर्ष सैनिक तानाशाही को समर्पित थे। इसके चलते भारत किसी ठोस प्रगति की अपेक्षा नहीं कर सकता था। सिर्फ इतना अवश्य था कि जिस तरह अपने दक्षिणी प्रान्तों में लीबिया समर्पित वट्टरपयी मुसलमानों की बगावत से मनीला सरकार उद्विग्न थी, उसी तरह भारत भी इस्लामी उग्रपयी ज्वार के स्वदेश में पड़ सकने वाले प्रभाव से चिन्तित था। श्रीमती एक्विनो के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत को ऐसा लगता रहा कि फिलीपींस के साथ अब कई लाभप्रद उभयपक्षीय सम्बन्ध स्थापित किये जा सकते हैं। फिलीपींस में स्थित अनेक अन्तर्राष्ट्रीय मस्वानों की अध्यक्षता भारतीय प्रशासक एवं वैज्ञानिक कर रहे हैं और इनके माध्यम से भी इन दो राष्ट्रा के बीच सवाद पुष्ट होता है। यहाँ वह टिप्पणी भी आवश्यक है कि फिलीपींस के सन्दर्भ में ही नहीं बल्कि मलयेसिया तथा इण्डोनेशिया के मामले में भी वैश्विक सम्बन्धों में इस्लामी सक्रियता का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है।

सम्बन्धों का आर्थिक आयाम—दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत के सम्बन्धों का एक और आयाम है—आर्थिक क्षेत्र में संयुक्त उद्यम (Joint Ventures)। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अनेक भारतीय उद्यमी इण्डोनेशिया, मलयेसिया और थाईलैण्ड में पूँजी निवेश या संयन्त्रों की स्थापना कर चुके हैं। इनके वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन से अब तक मिले जुले निष्कर्ष ही सामने आये हैं। अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर भले ही इस पूँजी का परिमाण ज्यादा न हो परन्तु इनके माध्यम से भारत की तकनीकी क्षमता तो प्रदर्शित होती ही है और विशेष मंत्री के प्रतीक के रूप में इनकी अपनी उपयोगिता भी है। किन्तु साथ-साथ इनकी असफलता और अकुशलता के कारण भारत की छवि घूमिल भी होती रही है। बिहम्बना यह है कि अधिकतर ऐसे उद्यम आसियान देशों में हैं, जो इनके बावजूद भारत की सन्देश की दृष्टि से देखते हैं।

सास परिवर्तन की सम्भावना नहीं—कुल मिलाकर, आज दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत के सम्बन्ध 'पिछड़ी स्थिति' में हैं। इनका स्वरूप न तो ऐतिहासिक-पारम्परिक रूढ़ गया है और न ही यह किसी नये मोर्चे में डाला जा सका है। भारत सामरिक व सैद्धान्तिक रूप में विपतनाम के करीब है जबकि आर्थिक आदान-प्रदान आसियान के साथ ज्यादा बड़े पैमाने पर संचालित होता है। दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र भारत का पड़ोस अवश्य है परन्तु महाशक्तियों के प्रवेश के कारण भारत तुलनात्मक दृष्टि से एक नगण्य शक्ति के रूप में देखा जाना है। जापान की आर्थिक क्षमता के आगे भारत की आर्थिक पहल बौनी मारित होती रही है। ऐसा नहीं जान पड़ता कि निश्चिन्त भविष्य में इस स्थिति में कोई साम परिवर्तन होगा। फिर भी, भारत इन देशों की 'उपधा-अवहलना नहीं कर सकता, क्योंकि दक्षिण-पूर्व एशिया सामरिक महत्व का पार्श्व (flank) है।

भारत, ब्रिटेन और राष्ट्रमण्डल (India, Britain and Commonwealth)

ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य के विघटन के साथ ही राष्ट्रमण्डल का अन्तर्राष्ट्रीय महत्व सामन आने लगा। या औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश राष्ट्रकुल

वियतनाम से प्रतिद्वन्द्विता या स्पर्धा निरुद्ध इण्डोनेशिया की हो सकती थी या वियतनाम की सैनिक शक्ति की दृष्टि से तात्कालिक रूप से सिर्फ थाईलैण्ड महसूस कर सकता था। निश्चय ही वियतनाम को दी गयी भारतीय सहायता व सहयोग का परिमाण और प्रकार ऐसा नहीं था कि वह शक्ति-सन्तुलन को प्रभावित कर सके।

भारत और वियतनाम जिस कारण अत्यन्त निकट था सके, वह चीन द्वारा वियतनाम पर हमला (1979) करना था। सीमा सभ्य और सैद्धान्तिक विवाद ने चीन व वियतनाम के बीच सैनिक मुठभेड़ का रूप लिया और चीन ने अपने आक्रमण के लिए वही क्षण चुना, जब तत्कालीन भारतीय विदेश मन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी चीन का दौरा कर रहे थे। इस अभियान के दौरान वियतनाम को सबक सिखाने के सिलसिले में जपान-जनक दश से '1962' (भारत-चीन मुठभेड़) की याद ताजा की गयी। इस प्रकार अनायास ही वियतनाम तथा भारत को बृहत्तर अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अपने सामरिक हितों का सजोम नजर आने लगा।

कम्बोडिया में हेंग सामरिन सरकार को मान्यता देने का प्रश्न—इसी तरह कम्बोडिया में वियतनामी हस्तक्षेप और नई हेंग सामरिन सरकार को भारत द्वारा मान्यता दिये जाने में दक्षिण-पूर्व एशिया के संदर्भ में भारतीय राजनय को जटिल बनाया है। इस बात से कोई भी इन्कार नहीं करता कि कम्बोडिया की पोल पोड सरकार उल्कीड़क, अत्याचारी और वंशनाशक थी। इसी कारण सदियों पुराना अदना बैर भूतकर अधिकतर कम्बोडियावासी वियतनामी सहायता स्वीकार करने को तैयार हुए। परन्तु नई हेंग सामरिन सरकार के गठन के साथ ही कम्बोडिया के सभी 'मिश्र देश' उनके शत्रु बन गये। अपने भू-राजनीतिक पूर्वाग्रहों के कारण या वियतनामियों को नीचा दिखाने के साधन में कम्बोडिया को मान्यता दिये जाने का प्रश्न जान-बूझकर और भी उलझा दिया गया। यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि इस सिलसिले में न तो भारत अपनी नीतियों को स्वतन्त्र प्रमाणित करने में असमर्थ रहा। कम्बोडिया को मान्यता देने वालों में सोवियत संघ और उसके पक्षधर समाजवादी देशों के साथ भारत अकेला गुट निरपेक्ष राष्ट्र है। भारत के तमाम प्रयत्नों के बावजूद गुट निरपेक्ष आन्दोलन और संयुक्त राष्ट्र संघ में कम्बोडिया की सीट खाली रखी गयी है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के शोर-शराबे में इस समस्या का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना दुर्लभ हो गया है। फिर भी इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि भारत के राष्ट्रीय हित में हेंग सामरिन सरकार को मान्यता देने के अलावा और कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता था। 1980 में जब इन्दिरा गांधी ने पुनः सत्ता प्राप्त करने के लिए चुनाव लड़ा तो उन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कम्बोडिया को मान्यता देना एक प्रमुख मुद्दा माना था। इस बात को भी अनदेखा करना कठिन है कि सहयोग वषों से कम्बोडिया भारत के सांस्कृतिक प्रभाव क्षेत्र में शामिल किया जाता रहा है। सिद्धान्त के शासन काल से ही कम्बोडिया के साथ भारत के सम्बन्ध विशेष रूप से आत्मीयता के रहे हैं। भारत के सामने ऐसी कोई विपत्ति नहीं कि वह दूसरों की नजर से कम्बोडिया को देखे या परहे। कुछ वर्षों बाद स्वयं जातिमान के राष्ट्र और प्रमुख नेतृत्व कम्बोडिया समस्या के हल के लिए वियतनाम के साथ सीधे सवाद के लिए तैयार हो गये थे। भारतीय विदेश नीति की दूरदर्शिता कम से कम इस मामले में अतीर्ण प्रमाणित हो चुकी है।

फिलीपींस से घनिष्ठता बढ़ाने का मोझा—फिलीपींस द्वीप समूह में तानासाह

की मुनियोजित जुबलबंदी के जाने उन्हें सफलता नहीं मिली। सिर्फ भारतीयों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाने के कारण 'ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल' का नाम बदल कर 'राष्ट्रमण्डल' किया गया। इसके साथ ही राष्ट्रमण्डल सचिवालय को एक कार्यकुशल विभाग के रूप में पठित करने का प्रयत्न आरम्भ हुआ और इसके सदस्य देशों को 'कनिष्ठ ही नहीं', सहयोगी, सहकारी व सहभागी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। उन्हें यह महसूस कराने के लिए कि राष्ट्रमण्डल की सदस्यता उनके लिये लाभप्रद है, ब्रिटेन ने विद्वानों-मुस्ली तकनीकी व आर्थिक सहकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की तत्काल घोषणा कर दी।

ऐसा सोचना ठीक नहीं कि नेहरू जी और कृष्णा मेनन मिर्फ अपने अंग्रेजी-प्रेम और अंग्रेजियत के कारण राष्ट्रमण्डल के प्रति आकर्षित होते थे। इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि भारत, पाकिस्तान और इसके जैसे किसी अन्य भूतपूर्व उपनिवेश की सबसे पहली ज़रूरत आर्थिक विकास की गति को तेज करना था। इसके लिए यह आवश्यक था कि इन देशों के आर्थिक क्रियाकलाप एवं विकास में व्यवधान न पड़े, विदेशों से पूँजी निवेश होता रहे, बाधित तकनीक का आयात हो सके और आवश्यकतानुसार विदेशों व प्रशासकों का किरायेती प्रशिक्षण चलता रहे। स्पष्ट है कि राष्ट्रमण्डल का मद्दस्य बनने का निर्णय ले लिये जाने पर वह देश 'स्ट्रैटिज क्षेत्र' में बना रहेगा। इस प्रकार राष्ट्रमण्डल के माध्यम से वह सब काम आसान बन जाता।¹

इसके साथ ही राष्ट्रमण्डल को एक परिवार के रूप में देखने का साम यह था कि इसके सदस्य राष्ट्रों के उभयपक्षीय विवादों को सुझा-झिपाकर रखने और उनके शान्तिपूर्ण समाधान की सम्भावना बढ जाती थी। मसलन, भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद को लेकर हुआ सीमा-समर्पण दोनों देशों को राष्ट्रमण्डल की सदस्यता के कारण कुछ समय बाद उतना विस्फोटक नहीं रहा, जितना आरम्भ में दृष्टिगोचर होता था। बँटवारे के बाद बड़े पैमाने पर रक्तपात को एक सीमा तक निमग्नित करने में भी यह बात भी निर्णायक रही कि भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च सेनाध्यक्ष ब्रिटिश थे। आज तक यह मिथक बना हुआ है कि राष्ट्रमण्डलीय मित्र सम्मेलनों में राष्ट्रध्यक्ष ऐसे मिलते-बतियाते हैं, जैसे किसी ब्रिटिश कबब में सरकारी तामसाम छोड़कर सहपाठी घनिष्ठ मित्र की तरह मिल रहे हों। इस तरह के व्यक्तिगत सम्पर्कों में बिगड़ अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का शान्तिपूर्ण समाधान सहज बनता है।

राष्ट्रमण्डल श्वेतों व अश्वेतों की मिली जुली सस्था—राष्ट्रमण्डल के मूल्यांकन के लिए इन बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है कि 1947 से अब तक के साढ़े चार दशकों में इसका निरन्तर रूपान्तरण (Transformation) हुआ है। मिर्फ भारत की मददगार भाव से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यह योरो की नहीं, बल्कि श्वेतों व अश्वेतों की मिली-जुली सस्था है। राष्ट्रमण्डल में इस समय 50 सदस्य राष्ट्र हैं।

राष्ट्रमण्डल की प्रारम्भिक सफलता के कारण—राष्ट्रमण्डल की प्रारम्भिक सफलता के लिए यह बात जिम्मेदार रही कि मलयेसिया, सिंगापुर व तत्कालीन

¹ इस सिर्जना में विस्तृत अध्ययन विवेचन के लिए देखें—S. C. Gangal, *India and the Commonwealth* (Agra, 1970), और M. S. Rajan, *The Post War Transformation of the Commonwealth* (Bombay, 1963).

या राष्ट्रमण्डल नामक संस्था का औपचारिक गठन हो चुका था, परन्तु इसका सामरिक, राजनीतिक और राजनयिक महत्व अधिक नहीं था। इसकी उपयोगिता सिर्फ़ इसी थी कि इसके जन्मबल से औपनिवेशिक तन्त्र और मोपन को मानवीय मुल्योटा पहनाया जा सके। ब्रिटेनबानी गोराम महाप्रभुओं द्वारा बारम्बार यह प्रचार किया जाता था कि राष्ट्रमण्डल एक समुक्त परिवार की तरह है, जिसका मुखिया या नेता ब्रिटिश सम्राट है।

इसका एक पक्ष और भी था। 19वीं सताब्दी से द्वितीय विश्व युद्ध की परिपक्वि तक ब्रिटिश साम्राज्य का अधिकांश हिस्सा अखंड देशों का था। 19वीं सताब्दी में ब्रिटेन को इन अखंड देशों में स्वाधीनता आन्दोलनों के बारे में इसकी चिन्ता नहीं थी, ब्रितानी उन ग़ोरे देशों के बारे में, जिन पर उसका प्रभुत्व-आधिपत्य था। आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा आदि ऐसे क्षेत्र थे, जिनके अन्तर्गत को नियन्त्रण में रखने के लिए यह आवश्यक था कि उनका यह अनुमति करावी जाये कि वे मुक्त नहों हैं और बाकी अशोक की व एमियाई लोगों से निम्न हैं। इसी तरह औप-निवेशिक सामकों का साथ देने वाले बिस्वानपान अखंडों का भी राष्ट्रमण्डल की गठिबिधियों में भाग लेने का अवसर देकर कृपापूर्वक सभानता का अहनाम कराया जाता रहा।

राष्ट्रमण्डल का एक महत्वपूर्ण पक्ष आर्थिक आदान-प्रदान वाला रहा। इस संस्था के माध्यम से भारत, श्रीलंका, बर्मा आदि जैसे उपनिवेशों में इच्छानुसार संप्रदायों का बौद्धन किया जा सकता था, परन्तु कनाडा, न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया जैसे देश, जो अपनी डोमिनियन स्थिति (Dominion Status) के कारण नाममान के लिए ही ब्रिटिश सम्राट की प्रभुता नाते थे, इनकी आमाती से नहीं छूटे-बनाते जा सकते थे। ब्रिटेन के पूर्ण और दूरदर्शों औपनिवेशिक सामकों ने अपना स्वार्थ साधने के लिए एक बिपट संरचना तैयार की, जो ब्रिटेन के अन्तर्पण्टीन व्यापार की लाभप्रद बनाये रखने के राष्ट्रमण्डलीय व्यापार प्राथमिकताओं (Commonwealth Trade Preferences) की व्यवस्था थी।

इस सबसे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिये कि राष्ट्रमण्डल सिर्फ़ प्रतीकात्मक महत्व की संस्था थी या है और इसका कोई महत्व नहीं। पहलें और दूसरे विश्व युद्ध के बीच के काल में ब्रिटिश औपनिवेशिक क्रियाकलाप का विदग्धन करने में यह बात किन्तुन स्पष्ट प्रमाणित होती है कि कामरूम में जिन ब्रिटिश प्रशासकों को राष्ट्रमण्डल का उत्तरदायित्व होता गया, वे अपने को ब्रिटिश विदेश मन्त्रालय और उपनिवेश विभाग के प्रतिद्वन्द्वी-प्रतिस्पर्धी के रूप में स्थापित करने का प्रयत्न करते नये थे। इसके अनिश्चित, जब नाया व कुछ अन्य देशों में स्वाधीनता संप्राप्त ने तेजी पकड़ी तो ब्रिटेन को यह महसूस होने लगा कि उसे अपने उपनिवेशों में अपना पूर्ववत् प्रभाव बनाये रखने के लिए अंग्रेजी प्रेमी इपनैंड के पक्षधर हज्जा मनन, जवाहर लाल नेहरू जैसे नेताओं की प्रसन्न रखने के लिए कुछ उसन करना पड़ेगा। राष्ट्रमण्डल नामक संस्था इन दृष्टि से विरोध उपयोगी निष्ठ हो सकती थी।

राष्ट्रमण्डल में भारत के शामिल होने के कारण—ऐतिहासिक अनुभव ब्रिटेन के इस मोच की तर्क सगति स्पष्ट करता रहा है। भारत ने देशी मुस्कार वाले डा० एम मनोहर मोहिया जैसे नेता आजादी के बाद भारत के राष्ट्रमण्डल में बने रहने के प्रति निरन्तर मुखर विरोध उठाने में करते रहे। परन्तु नेहरू जो और हज्जा मनन

सीमित रह गया है। 1987 में वेंकूवर (कनाडा) में आयोजित गिस्टर सम्मेलन में भी भविष्य के सम्बंध में इस संगठन की सम्भावनाओं को नहीं बल्कि सीमाओं और समस्याओं को रेखांकित किया।¹

भारत ब्रिटेन सम्बंध—भारत ब्रिटेन सम्बंधों के बारे में एक रोचक बात यह है कि प्रभु दास के सम्बंध होने के बावजूद भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन दो राष्ट्रों के बीच कोई मनोमालिन्य नहीं रहा। जैसाकि ऊपर इंगित किया जा चुका है कि इसका एक प्रमुख कारण यह रहा कि दीर्घसमय भारतीय नेता नेहरूजी कृष्णा मेनन आदि आत्मा प्रेमी थे। भारत के सुनियोजित आर्थिक विकास की प्राथमिकताओं को देखते हुए भी नीति निर्धारकों का यही मत था कि ब्रिटेन के साथ सामरिक व आर्थिक सम्बन्ध अक्षत रहे जायें। यह नेहरू जी की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने मुठभेड़ वाला रुख नहीं अपनाया परन्तु इसमें उस ब्रिटिश वास्तव का योगदान भी रहा जिसने भारत को आत्म सम्मान को आहत नहीं होने दिया। सिर्फ दो बार ऐसा हुआ है जब भारत ब्रिटेन सम्बंध तनावग्रस्त हुए हैं।

बहुतम मतभेद चरम सीमा पर—भारत और ब्रिटेन के बीच मतभेद अपनी बहुतम चरम सीमा पर गायब 1956 में पहुँचे जब स्वयं सकट व अवसर पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री एथनी ईडन और भारतीय रक्षामंत्री कृष्णा मेनन दो परस्पर विरोधी ध्रुवों पर खड़े रहे। इस अतिरिक्त कश्मीर प्रश्न में पाकिस्तान के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया ब्रिटिश नीति की प्रमुख पहचान रही है। विनायकर 1965 में भारत-पाक सैनिक संघर्ष के बाद पाकिस्तान को दी गई ब्रिटिश सैनिक सहायता में भारत को बेहद खिन्न किया। 1960 वाल दंगल के उत्तरादक में नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के साथ ब्रिटेन के सम्बंधों में निरंतर ह्रास हुआ। इसके अनेक कारण थे।

मतभेद के कारण—द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति या हस्ती नहीं रह गया था। यह कमजोर अपनी सुरक्षा और आर्थिक पुनर्हाली के लिए अमेरिका पर आश्रित होना गया। अटलांटिक भाइचारा एग्रीमेंट्स औपनिवेशिक रिसर्च का बहुत पहलु विस्थापित कर चुका था। यूरोपीय साम्राज्यवाद के गठन के बाद ब्रिटेन की दृष्टि उसके अपने तात्कालिक हितों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप से हटकर अन्यत्र केंद्रित हो गयी थी।

इस अतिरिक्त भारतीय उपमहाद्वीप में बड़े पैमाने पर ब्रिटेन पहुँचने वाले आक्रांता न ब्रिटेन में जातीय समस्या की जड़ दिया जिनमें पूर्वी अफ्रीका से पहुँचने वाले असंतुष्ट कुटुम्ब भारतीयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। इन लोगों का मानना था कि वे ब्रिटिश नागरिक थे और ब्रिटिश सरकार न अफ्रीकी उपलब्ध-पुष्टि में उनका हिता की रक्षा नहीं की थी। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार का मानना था कि यदि एम एग्रीमेंट्स आक्रांता का बिना रोक-टोक ब्रिटेन में जान दिया गया तो ब्रिटेन की पारम्परिक जीवन-यापन शैली और उसका जातीय संस्कार ही नष्ट हो जायगा। चूँकि ये सारे तथ्यार्थों भारतीय वास्तव थे अतः इनकी उपस्थिति का समीक्षात्मक भारत को भुगतना पड़ा। जब भारत विदेशी मुद्रा के सकट से जूझ रहा था तो बड़ी संख्या में ब्रिटेन में पढ़ाई के लिए भेजे जाने वाले छात्रों की आवाजाही

¹ रच—S C Parashar (ed) *Commonwealth Today* (Delhi 1983)

रोडेनिया (अब जिम्बाब्वे) जैसे अनेक ऐसे देश थे, जिन्होंने औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध बिना कोई उग्र संघर्ष किये स्वाधीनता हासिल की थी। ऐसी स्थिति में अपने मुलिया या अधुआ ब्रिटेन के प्रति सद्भाव बनाये रखना सहज था। स्वयं भारत जैसे देशों ने अपनी उपस्थिति से निरन्तर कमजोर हो रहे ब्रिटेन के प्रभाव को समुचित किया और हमारे देशों को राष्ट्रमण्डल में बने रहने के लिए प्रेरित किया।

राष्ट्रमण्डल ब्रिटिश हितों का साधक—यह सच है कि भाषा, शिक्षा और प्रशासनिक ढाँचे की समानता के कारण राष्ट्रमण्डल के सदस्य राष्ट्रों में सहकार और सवाद की सम्भावना अपेक्षाकृत बेहतर थी। परन्तु केवल इसी आधार पर राष्ट्रमण्डल के बारे में किये जाने वाले तमाम दावों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। यहाँ सिर्फ कुछ चुनिन्दा उदाहरणों के जिक्र से यह बात मसीमाँति उभर आयेगी कि इस मस्या ने मूलतः ब्रिटेन का ही हित साधन किया है।

कुछ देशों के प्रति ब्रिटेन का पक्षपातपूर्ण रवैया—ब्रिटेन का कुछ सदस्य देशों के प्रति रवैया पक्षपातपूर्ण रहा है। सबसे बुरा उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का है, जिनकी घिनौनी रणभेदी नीतियाँ और पाषाणिक दमन ब्रिटेन के समर्थन व सहकार के कारण निरन्तर जारी रह सके। यह सच है कि दक्षिण अफ्रीका को राष्ट्रमण्डल से निकाला गया, परन्तु उसके विरुद्ध आधिक प्रतिबन्ध सिर्फ ब्रिटेन के हठ के कारण लागू नहीं किये जा सके। इसी तरह रोडेनिया के मामले में भी ब्रिटेन की दुसमुल नीति के कारण अखिरके को इवान स्मिथ सरकार की गारान्टी का घातक मुकामान उठाना पड़ा था। 1987 में फिजी में दृढ़ नैतिक अन्ति व कर्नल राबुका सरकार को मान्यता देने के मामले में ब्रिटेन के दोहरे मानदण्ड एक बार फिर वीमस्म रूप में सामने आये। इसी प्रकार जब अमरीका की सैनिक बर्बरता ने ग्रेनाडा के साथ बनावटकार किया तो ब्रिटेन चुपचाप देखता रहा क्योंकि उसके लिए राष्ट्रमण्डल के पारिवारिक रिश्ते की अपेक्षा अमरीका से सैनिक गठबन्धन कहीं अधिक महत्वपूर्ण था।

यूरोपीय साम्राज्य बाजार की सदस्यता के लिए प्रयत्न—कुछ वर्ष पहले जब ब्रिटेन यूरोपीय साम्राज्य बाजार की सदस्यता के लिए प्रयत्नशील था तब उसने राष्ट्रमण्डलीय व्यापार प्राथमिकताओं (Commonwealth Trade Preferences) को ताक पर रखकर अपने लिए लाभप्रद इतने बेहिवक स्वीकार कर ली थी। पिछले वर्षों में ब्रिटेन का राजनीतिक सत्कार क्रमशः रणभेदी, दक्षिणपंथी और अनुदार होता गया है। एशियाई मूल के आग्रजकों के साथ नितान्त अपमानजनक व जुगुप्साप्रद व्यवहार किया जाता रहा है। कौमार्य परीक्षण की घर्त और हिन्दुस्तानियों व पाकिस्तानियों को गिटार्ड इसके उदाहरण हैं। मास्कुलिक एकता भी बुरी तरह खण्डित हो चुकी है। ब्रिटेन के प्रति बेस्ट इण्डियन के वासियों को भी तरह-तरह की आपत्तियाँ हैं।

विवादों के दान्तिपूर्ण निपटारे में राष्ट्रमण्डल की सीमाएँ—राष्ट्रमण्डल में या अन्य विवादों के दान्तिपूर्ण समाधान के सन्दर्भ में राष्ट्रमण्डलीय राजनय की सीमाएँ स्पष्ट हों चुकी हैं। अधिक से अधिक इनसे राष्ट्रमण्डल के महामन्त्रियों को अपने व्यक्तित्व के प्रदर्शन और प्रतिष्ठावर्धन के अवसर ही मिले हैं। राष्ट्रमण्डल के विभिन्न सदस्य देशों के आपसी सम्बन्ध बहुपक्षीय न होकर उभयपक्षीय रह गये हैं। वस्तुतः राष्ट्रमण्डल एक बार फिर ब्रिटेन के हित साधक खगडन के रूप में ही

आदि, जिनकी रुचि ब्रिटेन की परम्पराओं में, 'राज' के रिस्ते में रह गयी है। नीरज चौधरी और वी० एम० नैपोल जैसे लोग एक-दूसरे के ज्यादा करीब हैं, बनिस्वत युवा भारतीयों के। पत्र-पत्रिकाएँ सतमान रसादी, फारुक़ दोड़ी, हनीफ़ कुरेशी जैसी प्रवासी प्रतिमाओं का नाम उधालती रहती हैं, परन्तु यह उल्लेखनीय है कि मफल प्रवासी भारतीयों, वैज्ञानिकों, लेखकों, उद्यमियों का उत्तम भारतीय राष्ट्रीय हित साधन का पर्याप्त नहीं बन सकता। नस्लवाद और रंगभेद की जकड़ दक्षिण अफ्रीका में हल्की पड़ने के बाद इसके विरुद्ध संघर्ष के नाम पर राष्ट्रमण्डलीय बिरादरी में एका बनाये रखना भी कठिन होगा।

भारत और पश्चिम एशिया (India and West Asia)

भारत और पश्चिम एशियाई भू-भाग के बीच सम्बन्ध हजारों वर्ष पुराने हैं। मोहन जोदड़ो की खुदाई में प्राप्त सामग्रियों के आधार पर अनेक विद्वान् इस निष्कर्ष तक पहुँचे हैं कि आज के इराक़ से घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध इस सभ्यता के नागरिकों के थे। इसी तरह आज जो प्रदेश संयुक्त अरब अमीरात के नाम से जाना जाता है, वह भारत के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा रहा है। इस्लाम के आविर्भाव के साथ अरब लोगों में दारौदिक उद्यम तथा वैज्ञानिक आविष्कारों की सालसा तेजी ली बढ़ी। इन दौर में बरत, गुजरात व सिन्ध में आकर बसने वाले अरब उद्यमियों से भारत और पश्चिमी एशिया के बीच सांस्कृतिक तथा आर्थिक आदान-प्रदान की प्रक्रिया को बल मिला। दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में इस्लाम के प्रसार के लिए बरास्ता भारत वहाँ पहुँचने वाले अरबों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। ज्योतिष, अकगणित, जहाजरानी तथा चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में आदान प्रदान से दोनों पक्षों को लाभ हुआ। बाद के वर्षों में भारत में सल्तनत युग के दौरान मुसलमान शासकों के ऊपर अरब धार्मिक तथा सांस्कृतिक प्रभाव स्पष्ट था। इनकी भाषा व शासन प्रणाली पर इस्लामी पश्चिम एशियाई छाप गहरी देखी जा सकती है। इस्लाम का जन्म न ही पश्चिम एशिया में हुआ हो, परन्तु आज यह भारतीय धर्म बन चुका है। अभी कुछ वर्ष पहले तक पठे-सिखे भारतीयों के लिए अरबी व फारसी भाषाएँ जानना-समझना उतना ही आवश्यक था, जितना किनी पश्चिम एशियाई शिक्षित नागरिक के लिए। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का सर्वेक्षण करन का प्रमुख उद्देश्य यह है कि यह बात निर्विवाद रूप से उजागर की जा सके कि भारत और पश्चिम एशिया के सम्बन्ध पारम्परिक रूप से घनिष्ठ, बहु-आयामी और समोच्च मोहार्दपूर्ण रहे हैं। यह स्वाभाविक था कि इसका सम-सामयिक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर निर्णायक प्रभाव पड़ा।

भारत को पश्चिम एशियाई नीति के निर्धारक तत्व—ओपनिवाशिक काल में भारत-पश्चिम एशिया सम्बन्ध में थोड़ा व्यवधान जरूर पड़ा, परन्तु जहाँ मजबूत होन के कारण अवसर मिलत ही मावावश उत्पन्न होता था। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के व्यापक जन-आन्दोलनकारी रूपान्तरण के साथ ही महात्मा गांधी के नेतृत्व वाला खिलफत आन्दोलन जुड़ा है। अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में ओमन भारतीय की रुचि इस प्रमग से ही आरम्भ हुई। विभाजन के पहले समार भर में इस्लाम धर्मावलम्बियों का महम बड़ा जमाव भारतीय उपमहाद्वीप में था। चूँकि इस्लाम धार्मिक एवं राजनीतिक

भी कम हो गयी। अन्ततः इसने भी दोनों देशों के बीच आत्मीयता को क्षीण किया।

1969 में ब्रिटेन ने यह घोषणा की कि वह स्वेज नहर के पूर्व से वापस लौटना चाहता है। यह सिर्फ मनोबल का क्षय नहीं, बल्कि उसकी आर्थिक विवशता भी थी। इस आन्तरिकी सामरिक निर्णय ने भारत-ब्रिटेन सम्बन्धों को प्रभावित किया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के तत्काल बाद के वर्षों में सैनिक साज-सामान की खरीद का प्रमुख स्रोत ब्रिटेन था। यह स्वाभाविक भी था। बाद के वर्षों में इस विषय में मान्यता की निर्मरता क्रमशः मोबियत तथ्य पर बढ़ती गई और नये सम्बन्ध स्थापित होने के बाद यह बात स्पष्ट होने लगी कि ब्रिटेन जस्टिसों की विक्री में अनुचित मुनाफ़ाखोरी कर रहा है। यह आलोचन निराधार नहीं कि ब्रिटेन पुराने पड़ गये जीर्णोद्धार विमानवाहक पोत या लड़ाकू विमान भारत के सर भ्रष्टा रहा है। भारत को बेचे गये 'कैबरा' से लेकर 'जगुआर' विमान तक के बारे में यह आलोचना मटीक है। कुछ ही वर्षों पूर्व भारत द्वारा ब्रिटेन से हेलीकोप्टरों की खरीद इसी कारण विवादास्पद रही है।

1947 से आज तक ब्रिटेन का सांस्कृतिक अवमूल्यन भी हुआ है। तकनीकी प्रगति हो या सांस्कृतिक क्रियाकलाप को प्रथम, अमरीका की अमता और सामर्थ्य ब्रिटेन से कहीं अधिक है। न केवल युवक-युवतियाँ अपने मविष्य-निर्माण के लिए ब्रिटेन के बजाय अमरीका पढ़ने जाना पसन्द करते हैं, बल्कि सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भी अमरीका अधिक उपयुक्त सिद्ध हुआ है। आज बी० बी० सी० या ब्रिटिश कोसिल के कार्यक्रमों की पेंसी प्रतिष्ठा नहीं रह गयी है, जैसी कुछ वर्षों पहले थी। बी० बी० सी० के 'मस्तुनिष्ठ तरीके' को भारत-द्वेषी ही समझा जाता है। बी० बी० सी की अश्रेयित और अंग्रेजपरस्ती में ओपनिवेशिक अहंकार की भी बू आती है।

भारत-ब्रिटेन सम्बन्धों का भविष्य—हाल के वर्षों में भारत और ब्रिटेन के बीच अधिक गतिशीलता भी घटी है। मले ही भारतीय मुद्रा विनिमय पाँच स्टैलिंग की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत के उतार-चढ़ाव के साथ जुड़ा हुआ है, किन्तु ब्रिटेन की अधिक तेजी या मन्दी भारत के भविष्य के लिए निर्णायक महत्व की नहीं रह गयी है। यह सोचना तर्कसंगत होगा कि भारत और ब्रिटेन के सम्बन्ध दोनों देशों के लिए अतीत की तुलना में कमशः कम महत्वपूर्ण बनते जायेंगे। हाँ, इतना अवश्य है कि भारत में दो-तीन वर्ष लम्बे ब्रिटिश राज्य का इतिहास इसके कट्टर सचार्थ को आकर्षक ढंग में छिपाये रखेगा।

हाथ की कुछ घटनाओं ने बिनामें से कुछ अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की है और कुछ भारत और ब्रिटेन की आन्तरिक राजनीति से जुड़ी हुई है, राष्ट्रमण्डल का और भी अवमूल्यन किया है। सबसे पहली बात जर्मनी के पुनः एकीकरण और नये यूरोप के उदय की है। देगोल ने मने ही कभी ब्रिटेन को यूरोपीय समुदाय में घुसने से रोक़ा था, किन्तु आज का जायिक सचार्थ यह है कि ब्रिटेन और यूरोप दोनों ही पक्षों के मन में एक-दूसरे को मने लवाने में कोई हिचक नहीं है। दूसरी ओर राष्ट्रमण्डल के विभिन्न सदस्य अपनी-अपनी चिन्ताओं में फँसे हैं और जन्होंने काल प्रवाह के साथ अपनी राहें अलग-अलग पुनः ली है। भारत में मई, 1991 में राजीव गांधी की हत्या के माय नेहरू वंश की जामल प्रेमी विपणन भी समाप्त हो रही है। आज गिने-चुने बूढ़े ही बचे हैं, पुराने आर्ट्स सी० एम० नोकरशाह, अवकाज प्राप्त पत्रकार

और टोटो की 'तिकड़ी' लगभग सभी अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं में समान परिप्रेक्ष्य दर्शाती थी। गुट निरपेक्षता के अतिरिक्त साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरोध में भी भारत और अरब देशों के बीच महत्त्वपूर्ण अधिक महज था। अल्जीरिया में जन-मुक्ति संग्राम को भारतीय समर्थन प्राप्त था। भारतीय अनुभव ने मिस्र में आत्म-निर्भर आर्थिक विकास और समतापूर्ण समाजिक संरचना के निर्माण को प्रेरित-प्रोत्साहित किया। स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के समय भारतीय राजनयिक समर्थन के लिए मिस्र ने आभार माना।¹

इस तरह स्पष्ट है कि पश्चिम एशिया में न केवल धार्मिक व सांस्कृतिक आधार पर बल्कि प्रगतिशीलता, आधुनिकीकरण एवं अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में 'जनतांत्रिक दबाव' के कारण भी भारत और पश्चिम एशिया के अरब राष्ट्र एक-दूसरे के निकट आये। हाँ, इतना अवश्य है कि मध्ययुगीन राजशाही व सामन्ती मस्कार वाले पृथक्स्थिति पोषक जैसे मऊदी अरब, जोर्डन व मोरक्को जैसे राष्ट्रों के साथ भारत की अनिच्छता नहीं रही है। फिर भी भारत ने इनके साथ किसी प्रकार का कोई वैर या टकराव विवादस्पद नहीं बनने दिया। इस प्रकार अफ़ो-एशियाई बन्धुत्व के नाम पर भारत व अरब देशों के बीच सार्थक सवाद जारी रखा जा सका है। इसी स्थिति के कारण पश्चिम एशियाई मसूदा के हल में भारत की सार्थक भूमिका सम्भव हुई है।

इजराईल से सम्बन्ध सुधार की वकालत—परन्तु कई बार बाहरी शक्तियों के दखलाने के कारण भारत के प्रति सवा फैलता सहज हुआ है। इसका एक अच्छा उदाहरण रबॉत इस्लामी सम्मेलन (1969) है। इस सम्मेलन में भारत के भाग लेने का विरोध पाकिस्तानी जोड़-तोड़ के कारण अरब राष्ट्रों ने किया। इस प्रसंग के बाद बीच-बीच में भारत में यह भाँग उठायी जाती रही है कि क्यों नहीं हम इजराईल के प्रति अधिक मन्तुलित नीति अपनाकर अरब देशों को 'सबक' सिखा दें। विशेषकर जनता सरकार के क्षामन-काल में यह भाँग प्रबल हुई। जब से पाकिस्तान ने परमाणु कार्यक्रम आरम्भ किया है और इसके लिए अरबों ने आवश्यक सहायन जुटाये हैं, तब भी अरब देशों के प्रति भारत की निराशा बारम्बार मुखर हुई है। नेहरू जी और नानिब क निधन में व्यक्तिगत मंत्री का दौर भी पीका पड़ा और इन्दिरा गांधी के 1977 में अपदस्थ होने के बाद भारतीय विदेश-नीति पहले की तरह अरबोन्मुख नहीं रही।

उपयुक्त परिवर्तनों के लिए कई बालें उत्तरदायी हैं। 1967 और 1973 की अरब इजराईल मुठभेड़ों के बाद अरब राष्ट्रों की आन्तरिक स्थिति डाँवाँडोल रही है। पिलस्तीनी शरणार्थियों की समस्या और लेबनान के गृह-युद्ध ने उन्हें अपने क्षेत्र की परिधि के बाहर की घटनाओं से विलग किया है। ईरान-इराक, युद्ध के विस्फोट (1980) के बाद स्थिति और भी दारुण हुई।

भारत-अरब सम्बन्धों में तनाव—जहाँ तक भारत का प्रश्न है, अरबों के प्रति उनकी उदासीनता के कुछ और कारण भी हैं। 1973 के तेल संकट के बाद भारत की यह आशा-अपेक्षा थी कि तेर-उत्पादक अरब राष्ट्र भारत जैसे मित्र राष्ट्र को रियायती मूल्य पर तेल मुनब करायेंगे। यह आशा पूरी नहीं हुई और तेल से बचाये अध्याधुनिक पैसों ने तीसरी दुनिया के साथ उनके आचरण में अहंकार का पुट भी डाल

¹ देखें—ए० अण्णादुराई व एच० एम० रावन की पुस्तक 'मिस्र' पृ० 373 से 386 तक।

पक्षों को समन्वित करता है, इसलिए पश्चिम एशिया और भारत एक सशक्त व अदृश्य मूख से जुड़े हुए थे। देश के बंटवारे के बाद पाकिस्तान की स्थापना इस्लामी राज्य के रूप में हुई और भारत के लिए यह अनिवार्यता पैदा हुई कि अपने को धर्मनिरपेक्ष घोषित करने के बाद भी वह इस्लामी अरब राष्ट्रों को पाकिस्तान-समर्थक बनने से रोके। बंटवारे के बाद भी भारत की आबादी का एक हिस्सा मुसलमानों का है। इसलिए भारतीय राजनीतिक घटनाक्रम में पश्चिम एशियाई देशों की छवि और पश्चिम एशियाई घटनाक्रम के साथ भारतीय नागरिकों का लगाव पाया जाता है।

द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद यूहूदी राज्य इजराइल की स्थापना हुई, जिसे लगभग सभी अन्य राज्यों की भांति भारत ने भी तत्काल मान्यता दे दी। अरबों की तरह यहूदियों के साथ भी भारत के सदियों पुराने घनिष्ठ सम्बन्ध रहे हैं। संस्कृत और हिब्रू भाषा का रिश्ता, यहूदी और वैदिक अनुष्ठानों का साम्य और परस्पर-प्रेम ऐसी बातें थीं, जिनके आधार पर यह मोचा जा सकता था कि इजराइल के साथ वर्तमान में भी लाभप्रद नाता जोड़ा जा सकता है। नाजियों द्वारा उत्पीड़ित यहूदियों के प्रति भारतीयों के मन में सहानुभूति तो थी ही, टेक्नोलॉजी और विज्ञान के क्षेत्र में इजराइलवासियों की उपलब्धियाँ भी उनके साथ रचनात्मक सहकार की सम्भावना आकर्षक बनाती थी। फिर भी इजराइल के साथ दौत्य-सम्बन्ध स्थापित करने के बाद यदि भारत ने अरबों की ओर ध्यान केन्द्रित रखा तो उसका कारण यह था कि विदेश नीति की कसौटी पर भारतीय धर्मनिरपेक्षता खरी प्रमाणित की जा सकती थी।

अरब देशों के साथ राष्ट्रीय हितों का संयोग—परन्तु इससे यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि भारतीय मुसलमानों की भावनाओं के दबाव में भारत ने पश्चिम एशियाई राजनीति में अरब देशों की पक्षधरता का बीड़ा उठाया। वस्तुनिष्ठ दृष्टि से परीक्षण करने पर यह बात सहज ही स्पष्ट हो जायेगी कि भारतीय राष्ट्रीय हितों का संयोग अरब राष्ट्रीय हितों के साथ रहा है। जनसंख्या, क्षेत्रफल और नू-राजनीतिक दृष्टि से पश्चिम एशिया के अरब देश इजराइल की अपेक्षा भारत के लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। इनमें अनेक तेल-उत्पादक देश हैं। इसके अतिरिक्त यह बात भी नहीं भुलायी जा सकती कि इन अरब राष्ट्रों ने स्वयं 'मुस्लिम राष्ट्र' होने के बावजूद सिर्फ धार्मिक व साम्प्रदायिक भाईचारे के आधार पर अखंड मूँदकर पाकिस्तान का समर्थन किया। कश्मीर प्रकरण इस बात का अच्छा उदाहरण है।

अरब देशों के प्रति झुकाव के कारण—इसके प्रभाव गृह निरपेक्षता के आविर्भाव और गृह निरपेक्ष आन्दोलन के प्रभाव ने अरब देशों की ओर भारत के झुकाव को बढ़ाया। इजराइल अपनी स्थापना के साथ ही 'अमरीका का जिविरामुन्धर' और 'पश्चिम एशिया में महाशक्तियों के मत्ता सघर्ष में एक स्तरनाक मोहरा' बन गया था। इसके विपरीत मिस्र, इराक और सीरिया जैसे प्रमुख अरब राष्ट्र गृह निरपेक्ष थे और इनकी नीतियों के साथ भारतीय विदेश-नीति का तालमेल सहज सम्भव था। बार्डन सम्मेलन (1955) के वर्ष से ही नागिर और नेहरू की मैत्री अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण बन चुकी थी और बेनबैद सम्मेलन (1961) तक नेहरू, नासिर

¹ विस्तृत विश्लेषण के लिए देखें—M. S. Agwani, *India and the Arab World*, in B. R. Nanda (ed.), *Indian Foreign Policy: The Nehru Years* (Delhi, 1974).

मह नहीं कि नेहरू जी के शासन काल के 18 वर्षों में भारत द्वारा अणुबम बनाये जाने की माँग नहीं की गयी। एक नगण्य अल्पसंख्यक राजनीतिक तत्वका इस माँग को मुखर करता रहा। इस बात को भी याद रखना जरूरी है कि भारत द्वारा शान्तिपूर्ण अणु नीति सिर्फ नेहरू जी के 'आदर्शवाद' पर ही नहीं टिकी थी। नेहरू जी के जीवन काल में मले ही भारत-चीन सम्बन्धों में तनाव उभरने लगे थे परन्तु चीन अणु शक्ति सम्पन्न नहीं था। पाकिस्तान के बारे के तो यह बात दूर तक भी सोची नहीं जा सकती थी। नेहरूकालीन भारत बड़े पैमाने पर अपने आर्थिक विकास के लिए विदेशी सहायता पर निर्भर था। नेहरू जी अपने दाताओं द्वारा परमाणु दुस्साहसिकता-महत्वाकांक्षा के लिए दबित होने का सतरा नहीं उठा सकते थे (गोखरन प्रसंग ने यह बात भली-भाँति दर्शा दी कि शान्तिपूर्ण परमाणु क्षमता को भी बड़ी कीमत स्वाधीन देश को चुकानी पड़ सकती है)।

किन्तु नेहरू जी की मृत्यु तक यह बात झलकने लगी थी कि भारतीय परमाणु नीति में परिवर्तन आवश्यक है। 1962 की अपमानजनक हार के बाद कई विद्वान यह सुझाने लगे थे कि यदि भारत के पास परमाणु बम होता तो चीन भारत पर हमला करने का दुस्साहस नहीं करना। कुछ और विद्वान यह सुझाने लगे कि कुगल व कारगर परमाणु शास्त्रों की तुलना में दैत्याकार पारम्परिक सेना का रख-रखाव कहीं अधिक खर्चीला और अबुधल सिद्ध होता है। इस समय तक दश के तेवर भी अहिंसक व शान्तिप्रेमी नहीं रह गये थे। नेहरू जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री द्वारा सत्ता ग्रहण करने तक भारत के सार्वजनिक जीवन में परमाणु नीति सम्बन्धी बहस काफी गरम हो चुकी थी।

शास्त्रीकालीन परमाणु नीति: महत्वपूर्ण परिवर्तन—शास्त्री जी नेहरू जी की तरह के बौद्धिक-दार्शनिक दृष्टान्त वाले व्यक्ति नहीं थे और न ही उनका विश्व-दर्शन सामान्य निरासनीकरण के लिए प्रतिबद्ध था। कई आलोचक शास्त्री जी पर यह आरोप लगाते थे कि उनके मानविक क्षितिज संकुचित थे। वास्तविकता यह है कि शास्त्री जी राष्ट्र-हित की मोटी व सामान्य ज्ञान-मुक्त परिभाषा और उस पर आधारित नीति निर्धारण को मध्यम समझते थे। भारत की परमाणु नीति के मन्दमं में तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए यह कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत थी। इसी तरह शास्त्री जी अपने संक्षिप्त प्रशासनिक अन्तराल में ही नेहरू जी की स्थापनाओं पर आधारित देश की परमाणु नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने में सफल हुए।

जहाँ एक ओर 1965 में पाकिस्तान के माघ मैनिफेस्ट मुठभेड़ ने यह बात सामने ला दी थी कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा निरापद नहीं समझी जा सकती, वहीं दूसरी ओर 1964 में चीन द्वारा अणु अस्त्र हामिल कर लेने के बाद उत्तरी सीमाना का संकट भी 1962 की तुलना में कई गुना बड़ा हो गया था। कुछ वुटिल विश्लेषकों ने यह टिप्पणी की कि इस संकट का सामना करने के लिए शास्त्री जी ने पश्चिमी राष्ट्रों विशेषकर अमरीका से 'सुरक्षा छतरी' पाने के लिए अनुरोध किया था। परन्तु यह आरोप बिल्कुल गलत था। भारत की प्रतिरक्षा के बारे में शास्त्री जी नेहरू जी की तुलना में बहीं अधिक यथार्थवादी तरीक़े में सोचते थे। उन्हें भारत की स्वाधीनता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं था। इस विषय में सबसे अच्छी जानकारी विद्वान लेखक अशोक कपूर ने जुटायी है। उन्होंने

दिना। खाड़ी देगो से भारतीय प्रवानियों ने बड़े पैमाने पर विदेशी नुदा जमित कर भेजी, परन्तु कालान्तर में यह बात धुसाई नहीं रही जा सकी कि इन धमिकों की स्थिति दावों जैनी थी। इनकी दुर्दशा को लेकर भारत-अरब सम्बन्धों में तनाव पैदा हुए।

मट्टरपयी इस्लाम के ज्वार के साथ लीबिया की नइकने वाली गतिविधियों आरम्भ हो गयीं और कनक: अधिकतर अरब राष्ट्रों ने पाकिस्तान के प्रति अमलस समर्थन का रख अपनाया। इस्लामी सचिवालय, इस्लामी अदालत और इस्लामी विकास बैंक की स्थापना के बाद इन सत्पाओ के नाम्न से पाकिस्तान के लिए यह सहज हो गया कि वह अपनी परिचन एजिपाई पड़ोसी स्थिति का लाभ उठा सके। अनरीका द्वारा इन क्षेत्र में 'चुरन रैनाजी दस्ते' (Rapid Deployment Force) की योजना बनाने के बाद इस क्षेत्र के अधिकतर देश अनरीका की ओर अपनी राजनीतिक स्थिति को विरपद रखने के लिए आलापित रहे हैं। कुल मिलाकर इन सब बातों ने भारत और परिचन एजिपाई देशों के बीच अतमाय का भाव पैदा किया है। बंसे भी भारत अपने पड़ोस के साथ सरदई पैश करने वाले विवादों में उलझा रहा है।

बुनियासी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं—उपरोक्त विवेचन के बाद इसी निष्कर्ष पर पहुँचना ठकंसन है कि तनाम उतार-नड़ाव के बावजूद भारत की परिचन एजिपा नीति ने किनो बुनियासी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं। भारतीय और अरब हित परस्पर विपरीत नहीं तथा दूरदर्शी परिष्पेय में इन्ही सम्बन्धों को सुदृढ करना भारत के लिए लाभद है। हाल के वयों में भीतका ने इजराइली सुतचर सत्पा 'मोनाब' की पुतपंत के बाद यह बात निर्भूल सिद्ध हुई है कि इजराइल भारत के साथ सम्बन्ध सुधारने के लिए उत्तुक है। अतः इजराइल की सहानता से अरब देशों को संतुमित करने वाला प्रदल नादानी ही होगा।

बहुरात, पिछले दिनों एक रोचक बात देखने में आयी कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े विद्वेयकों ने यह मुझाना शुरू कर दिया कि भारत को इजराइल के साथ अपने सम्बन्धों को सुधारने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये। जुलाई 1991 में करनौर में इजराइली परंतको ने बग्यक बनाने जाने के बाद उजराइलो से स्टकर लोहा लिया, जिनके बाद यह भटकते लपायी जाने लगीं कि क्या इन आतंकवादियों का मुझाबता करने के लिए भारत सरकार ने इजराइल से गुपगुप सुतह कर ली है। इन इजराइली बग्यको को धुझने के लिए एक बरिष्ठ इजराइली राजनयिक ने भारत पहुँचा और उसके स्थापन-उत्कार पर बंनो मौहू नहीं बजाई गई, जैसी अब तक बजाई जाती रही थी। इस बात की समाचना प्रबल हुई कि पाकिस्तानी परमानु आवंक्रम को देखते हुए उस पर राजनयिक दबाव बातने के लिए भारत इजराइल के निकट पहुँचने की कोशिस करेगा। गुट निरपेक्षता के 'अन्त' और दुर्वर्ती मसले को लेकर सिद्धे लाड़ी नुद के बाद परिचन एजिपा ने राजनीतिक तनीकरण इतनी तेजी से बढ़ने है कि इजराइल और अरबों के बारे में पुराने उमान विरुपन बेनानी हो रने है।

भारतीय परमाणु नीति (India's Nuclear Policy)

भारत सनार के उन बटन कम देनों में है जिन्हें परमानु धनता-मन्त्र

परमाणु प्रतिष्ठान को मिल जाता है। नीति के अभाव एवं इसकी दुर्बलता को राष्ट्र-हित में गोपनीय रखा जाता है। विषय की दुरुहता एवं विरोधीकरण के कारण भी ससद और संचार माध्यमों में इस सन्दर्भ में खुली बहस चलाना सहज नहीं। दसवों से यह सवाद या विवाद एक सीमित वर्ग तक ही चालू रहा। अभी हाल में जाकर इसका रूपांतरण सार्वजनिक हुआ है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफसर धीरेन्द्र शर्मा ने अपनी पुस्तक 'इंडियन न्यूक्लियर इस्टेट' में इस बात पर अच्छा प्रकाश डाला है कि भारतीय परमाणु वैज्ञानिकों का ठग गिरोंह (माफिया) अपने वैज्ञानिक साम्राज्य के विस्तार के लिए क्रिम प्रकार मामूली, चाटुकार व दादगिरी वाला आचरण करना है और अपने राजनीतिक स्वामियों तथा भारतीय जनता को एक साथ अंधकार में रखता है।¹ श्रीमती गांधी इस बात को एक सीमा तक समझती थी। इसी कारण उन्होंने एक बार सैनिक विद्रोह का वर्णन करने के बाद भी पुनः परमाणु निदास्त्रीकरण की जोरदार वकालत आरम्भ की।

इन्दिरा गांधी के काल में परमाणु नीति (1965 में 1977 तक)—श्रीमती गांधी की एक विवशता यह थी कि वह अपनी नीतियों में शास्त्री जी से भिन्न दिखना चाहती थी। वह अपनी आन्तरिक स्थिति मूढ़ बनने के लिए अपने को नेहरू जी के वास्तविक उत्तगधिकारी के रूप में पेश करना चाहती थीं। इसके लिए भारत द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय भय पर निदास्त्रीकरण का झंडा उठाता उपयोगी सिद्ध हो सकता था। परन्तु सिर्फ इसी कारण श्रीमती गांधी ने भारत द्वारा परमाणु बम बनाने का निर्णय स्थगित नहीं किया। जैसाकि ऊपर इशारा किया जा चुका है कि श्रीमती गांधी अपने मन में यह जानती थी कि भारत निकट भविष्य में परमाणु सैनिक सामर्थ्य हासिल नहीं कर सकता। उन्होंने इस बात के अथक प्रयत्न किये कि भारत को मुकमान पहुँचाने वाली कोई अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु व्यवस्था (International Nuclear Regime) उस पर थोपी न जा सके। परमाणु प्रसार रोक संधि (Non-Proliferation Treaty) पर हस्ताक्षर नहीं करने की भारतीय नीति इस बात का प्रमाण है। ऐसा नहीं था कि भारत अपने और दूसरे सन्दर्भ में दो अलग-अलग मानदण्डों का प्रयोग करता था या कि उसने इस मामले में अपने मिद्धान्तों व माप मसौदा करना मजूर कर लिया। वस्तुतः यह प्रश्न देश की सम्प्रभुता और स्वाधीनता का शत प्रतिशत बनाय रखने के लिए निर्धारित नीति न जुड़ा हुआ है। भारत इस निष्कर्ष तक पहुँचने वाला अकेला देश नहीं। उस इस विषय में ब्राजील जैसे अन्य राष्ट्रा का समर्थन-सहयोग भी मिला।

जहाँ भारत का राजनीतिक नेतृत्व इस क्षेत्र में अपनी स्वाधीनता बनाय रखने के लिए दृढ़ मन्त्र था, वहीं उसके वैज्ञानिकों का वाछित योगदान उस नहीं मिल सका। उदाहरणार्थ, भारतीय वैज्ञानिकों ने न तो किसी परमाणु मट्टी का स्वदेशी डिजाइन तैयार किया और न ही 'भारी पानी' का उत्पादन या यूरैनियम सवधन (Enrichment of Uranium) की आत्म-निर्भर प्रक्रिया का विकास हो सका। परमाणु ऊर्जा के सामरिक उपयोग की वन छोटिय, परमाणु शक्ति से विजली ऊर्जा उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य भी पूरे नहीं किये जा सके। इस सबका दखत हुए भारत परमाणु विद्रोह को बचाये रखने के अलावा और करता भी क्या ?

¹ Dhirendra Sharma, *India's Nuclear Estate* (Delhi, 1983)

सप्रमाण यह कहा है कि दिसम्बर, 1965 में शास्त्री जी ने परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष को यह निर्देश दिया था कि अणु शक्ति के सैनिक उपयोग के लिए तत्काल आवश्यक परियोजनाएँ बनायी जायें।¹ दुर्भाग्यवश इसके एक माह बीतने से पहले ही शास्त्री जी की मृत्यु हो गयी। अतः एक बार फिर प्रधानमन्त्री स्तर पर सत्ता के हस्तान्तरण का प्रश्न महत्वपूर्ण बन गया और यह बात अमूरी छूट गयी। तब भी के० सुब्रह्मण्यम जैसे विद्वानों का मानना है कि पोखरण का प्रयोग दत्त निर्णय से प्रभावित हुआ था।

इसके अतिरिक्त एक विमान दुर्घटना में होमी जहाँगीर भाभा की मृत्यु (1966) से भारत के परमाणु कार्यक्रम की गति घोमी पड़ी। भाभा के बाद विक्रम साराभाई परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने परन्तु उनकी व्यक्तिगत विशेषज्ञता और रुचि अणु ऊर्जा में उतनी नहीं थी, जिसनी अतिरिक्त शोध में। दुर्भाग्यवश, विक्रम साराभाई भी अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहे। उनके बाद परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद का कार्यभार होमी सेठना ने सम्भाला। सेठना, डा० राजा रामन्ना, डा० पी० के० श्रीनिवासन जैसे वैज्ञानिकों के प्रति पूरे सम्मान का नाव रखते हुए भी इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि ये उन अन्तर्राष्ट्रीय-स्तर के स्वप्न-दृष्टा वैज्ञानिक नहीं थे, जिनमें भाभा और साराभाई विराजमान थे, न ही इन वैज्ञानिकों का व्यक्तिगत आत्मीय समीकरण-मन्वन्ध शीर्षस्थ राजनेताओं से था। अधिक से अधिक इन्हें कुशल वैज्ञानिक-प्रशासक ही समझा जा सकता है। ये मलाहकार भर हो सकते थे, स्वप्न-दृष्टा (visionary), सहयोगी और पथ प्रदर्शक नहीं। अनेक टिप्पणीकारों का यह भी मानना है कि भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का नौकरगारी के चंगुल में फँसना, उसका धुंध राजनीतिकीकरण, वैज्ञानिकों का पारसी और मद्रासी घटों में बँटना, इन्जीनियरों तथा भौतिक-शास्त्रियों की गुटबंदी इसके माथ ही धुक हूँ। यहाँ इन सब बातों को कुरेदने का प्रमुख उद्देश्य यह है कि 1965 से 1974 के बीच भारतीय परमाणु कार्यक्रम की दिशा एवं गति गड़बड़ाने का विक्षेपण किया जा सके। यदि विकास के इसी चरण में चीन और पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रमों से तत्कालीन भारतीय अनुभव की तुलना करें तो यह बात बहुत अच्छी तरह स्पष्ट हो जायेगी कि जहाँ चीनी वैज्ञानिकों ने प्रशमनीय त्याग और देश प्रेम का परिचय दिया और पाकिस्तानी वैज्ञानिक आणविक भस्म प्राप्त करने के लिए थोरी, नमकी और गुप्ताचरी कर अपनी जान सतरे में डालते रहे, वहीं उनके भारतीय वैज्ञानिक बंधु अपने राजनीतिक महाप्रभुओं से प्रेरणा की प्रतीक्षा करते रहे। इन भारतीय वैज्ञानिकों ने कोई विशेष जीवट या उद्यम नहीं दिखाया।

जहाँ एक ओर अणु शक्ति को सामरिक महत्व का माना जाता है और वह बात स्वयंनिष्ठ मनझी जाती है, कि इसके लिए खर्च की जाने वाली धन राशि के बजट में कटौती नहीं की जा सकती या इसके लेखा परीक्षण की कोई जरूरत नहीं, वहीं ऊर्जा-उत्पादन जैसे धानिपुर्न प्रयोगो-परियोजनाओं की सामियों की ओर ध्यान दिलाने वाला शक्ति देशद्रोही-विदेशी एजेंट करार दिया जाना है। इन सामरिक परदे के पीछे अपनी अक्षमताओं-अनफलताओं को छुपाने का पूरा अवसर भारतीय

¹ देखें—Ashok Kapur, *India's Nuclear Options: Atomic Diplomacy and Decision-Making* (New York, 1976); and *Pakistan's Nuclear Development* (London, 1987)

दिलाई यही प्रमाणित करती है। पहले मास ने यह आश्वासन दिया कि वह तारापुर सयन्त्र के लिए ईंधन देने में अमरीका या कनाडा का स्थान ले सकता है, परन्तु अन्ततः अपने मित्र राष्ट्रों के दबाव में उसने भी हाथ खींच लिये। पोखरण के परीक्षण का एक और बुरा प्रभाव पड़ा। इसके बाद पाकिस्तानी शासकों के लिए उनके परमाणु मामरिक कार्यक्रम को प्रतिरक्षात्मक कहना आसान हुआ और खासकर इस्लामी विरादरी में इसका पक्ष में आर्थिक व राजनयिक समर्थन जुटाना सहज हुआ।

पोखरण परीक्षण के बाद से अब तक भारत के लिए दक्षिण एशियाई परिस्थितियों में अपने पड़ोसी देशों के साथ परमाणु-मुक्त क्षेत्र (Nuclear Free Zone) के विषय में अपनी नीतियों का तालमेल बिठाना दुरूह रहा है। इसीलिए यह प्रश्न पूछा जाना आवश्यक है कि भारत के लिए आखिर पोखरण विस्फोट की क्या सगति थी? वस्तुतः पोखरण परीक्षण का निर्णय और इसका एक निश्चित समयबद्ध कार्यक्रम बुनियादी तौर पर भारत की आन्तरिक राजनीति के दबावों से प्रेरित थे। 1974 में केन्द्र में सरकार को रेल कर्मचारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का सामना करना पड़ रहा था। गुजरात और बिहार में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में व्यापक जन-आन्दोलन गति पकड़ रहा था। युवा छात्र समर्थ के तेवर हिंसक-विस्फोटक थे। ऐसे में श्रीमती गांधी के लिए यह आवश्यक था कि वह अपनी अजेय रणचण्डी दुर्गा वाली छवि को धूमिल न पड़ने दें। अन्तर्राष्ट्रीय राजनयिक दबाव भी उनके इस निर्णय को पुष्ट करने में सहायक सिद्ध हुए। 1971 में भले ही भारत ने अमरीका की इच्छा के खिलाफ बंगला देश को मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की थी और अमरीका ने उसे आधे-अधूरे मन से ही दक्षिण एशिया की प्रमुख शक्ति के रूप में स्वीकार कर लिया था। किन्तु 1972 में अमरीकी राष्ट्रपति निकसन की चीन यात्रा के बाद अमरीका-चीन सम्बन्धों में बहुत तेजी से सुधार हुआ और भारत की स्थिति एक बार फिर संकटग्रस्त न रही, निरापद नहीं रही। पोखरण विस्फोट का एक लक्ष्य यह भी था कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ-साथ विभिन्न-निकमन की अमरीकी सरकार तक को यह संदेश पहुँचाया जा सके कि भारत को अनदेखा नहीं किया जा सकता। परन्तु पोखरण परीक्षण के 18-19 वर्षों के बाद अब इस तर्क-पद्धति की सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह लगाये जा सकते हैं। पोखरण परीक्षण के बाद परमाणु बम के निर्माण ने निश्चय ही भारत के मामरिक महत्त्व को निर्विवाद रूप से प्रमाणित कर दिया होता और किसी के लिए भी भारत की सैनिक व सामरिक उपेक्षा सहज नहीं होती। परन्तु ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पोखरण परीक्षण के बाद अन्तर्राष्ट्रीय (अमरीकी व पश्चिमी) दबावों का सामना करने में भारत सफल रहा। भारत की अममर्थता के कारणों पर दृष्टिपात करने से पहले पोखरण परीक्षण के एक और मुख्य स्रोत का उल्लेख आवश्यक है।

पहले यह कहा जा चुका है कि होमी बाभा और विक्रम साराभाई की मृत्यु के बाद भारत के परमाणु कार्यक्रम में पहुँचे जैसी तेजी नहीं रह गयी थी। खर्चीली वैज्ञानिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के साधन मुलम नहीं रहे। भारतीय परमाणु वैज्ञानिकों की जमात यह बात नवीनीति समझती थी कि सिर्फं मामरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा की दलील देकर ही कुछ हासिल किया जा सकता है। परमाणु ऊर्जा के शान्तिपूर्ण प्रयोग से सारे भारतीय कार्यक्रमों की प्रगति बेहद निराशाजनक थी। इन विरोधाधिकार सम्पन्न और भुविधाभोगी वैज्ञानिकों के लिए अपनी योग्यता

पोखरन विस्फोट—24 मई, 1974 को भारतीय परमाणु नीति के विश्लेषकों को एक नाटकीय घमाका सुनने को मिला। राजस्थान में पोखरन नामक रेगिस्तानी इलाके में नाकेतिक भाषा में एक टेलिकम सन्देश दिल्ली भेजा गया—'Buddha is smiling' (अर्थात् बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं)। शांति के अग्रदूत बुद्ध की यह मुस्कान रहस्यमय होने के साथ-साथ व्यंग्यपूर्ण भी थी। इसके द्वारा यह सूचना भेजी गयी थी कि भारत ने परमाणु 'विस्फोट' कर लिया है। इस शब्द को लेकर आज तक बाल की दात निकाली जाती रही है। अंग्रेजी भाषा में इसका नामकरण था—शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट (Peaceful Nuclear Explosion)। जब आलोचकों ने यह कहना शुरू किया कि परमाणु विस्फोट आखिर शांतिपूर्ण कैसे हो सकता है तो भारतीय वैज्ञानिकों ने वह कहना आरम्भ किया कि पोखरन में विस्फोट नहीं, अतस्फोट (Implosion) किया गया। परन्तु इस शब्दजाल से कोई भी नोचिगत लाभ नहीं उठाया जा सका। पोखरन के बाद इस मन्देह की कोई गुज़ाईश नहीं थी कि भारत परमाणु बम का निर्माण कर सकता है। हज़ारों और इक्षिण अफ्रीका जैसे देश अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में इस बात का लाभ उठाते रहे हैं कि धमता और सामर्थ्य प्रदर्शित करने के बाद परमाणु बम के सन्दर्भ में परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं रहती।

भारत सरकार ने यह दावे का मरसक प्रचलन किया पोखरन के बाद विदेशी, भारत की कबली और करनी में कोई डण्ड या अन्तर्डण्ड न दिखला सकें। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में रेखांकित किया कि भारत की विकास परियोजनाओं को सम्पन्न करने के लिए हम तरह की तकनीकी सामर्थ्य प्राप्त करना एक अनिवार्यता थी। बड़े पैमाने पर पहाड़ तोड़ने, जमीन खोदने और भूवर्ष शास्त्रीय गवेषणाओं के लिए शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट की विशेष उपयोगिता बतलायी गयी। इस सन्दर्भ में यह बात आसानी से अगदली की जाती रही कि सोवियत संघ के बाहर किसी अन्य परमाणु सम्पन्न देश में परमाणु ऊर्जा का ऐसा उपयोग नहीं किया गया।

भारत के परमाणु विकास कार्यक्रम में महत्त्वपूर्ण सहयोगी देश कनाडा ने दो टुक गर्मी में यह बात कह दी कि पोखरन के विस्फोट के बाद वह भारत के परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण गानने को तैयार नहीं। इसके साथ ही उसने यह घोषणा भी कर दी कि भविष्य में वह भारत को परमाणु प्रौद्योगिकी के मिलमिले में तब सहायता देगा, जब वह अपने परमाणु समन्त्री की अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण निश्चयन प्रणाली के लिए सहमति दे देगा। भारत का मानना था कि वह ऐसी किसी भी बात को अपनी सम्मनुता व स्वाधीनता का अवमूल्यन मानेगा और इसकी स्वीकृति नहीं दे सकता। पोखरन के घमाके का सबसे बड़ा दुष्परिणाम यही हुआ। तब तक भारत-कनाडा सम्बन्ध उनावरहित रहे थे। लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में उनमें गौहार्द बड़ा था। जब कनाडा ही भारत के नीति परिवर्तन से विप्र-अप्रसन्न हुआ तो अमरीका की हवाई और बंदरगाहों में समझ में आ सकते हैं। अने बातें वर्षों में जयरीख द्वारा पहले चिन्ने गये समझौतों को तोड़कर तारापुर संयंत्र को दिए जाने वाले ईंधन में कटौती नहीं न कही पोखरन प्रसंग से जुड़ी हुई है। यह बात भी स्वीकार करनी ही पड़ेगी कि विशेष मेंत्री के तमाम दावों के बावजूद सोवियत संघ भी इस घटनाक्रम से प्रसन्न नहीं दिखाई दिया। भारत की राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए 'आरी पानी' देने के बारे में सोवियत संघ का

पञ्जाब समस्या के कारण आतंकवाद के देशव्यापी हिंसक विस्फोट ने शान्ति और मुख्यवस्था को ही सबसे महत्वपूर्ण सामरिक प्रश्न बना दिया था। साम्प्रदायिक दंगे, केन्द्र सरकार को क्षेत्रीय चुनौतियाँ आदि ऐसी अन्य प्रवृत्तियाँ थी जिन्होंने सरकार का ध्यान इस मुद्दे से हटाया।

इन्दिरा गांधी की हत्या (1984) के बाद जब राजीव गांधी ने सत्ता संभाली तो जरूर यह आशा जगी कि तकनीकी दृष्टान्त वाला यह विमान-चालक प्रधानमन्त्री परमाणु नीति के विषय में अधिक रुचि लेगा। परन्तु ऐसा कुछ नहीं हुआ। राजीव गांधी की अनुभवहीनता और अपरिपक्वता के कारण अतंत रेलवे टिकटों का कम्प्यूटरी आरक्षण और परमाणु सामरिक विफल एक ही बठखरे से तोल जाने लग। राजीव गांधी ने अपने को अकस्मात् मयागवण ही गुट निरपेक्ष आन्दोलन का अभ्यक्ष पाया और अन्य प्रगतिशील तथा शान्ति प्रेमी तीसरी दुनिया के नेताओं की संपत्ति में वह भी निरासन्नकरण के हिमायती बनने को विवश हुए। इस दौर की परिणति हुई—1986 में, जब पाँच अन्य देशों के नेताओं के साथ उन्हें 'बियोड बार' नामक अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति पुरस्कार दिया गया। वस्तुतः भारत के परमाणविक सामरिक स्वरूप को कमजोर करने का यह कुटिल प्रयत्न था। जिस सत्ता के तत्वावधान में 'बियोड बार' पुरस्कार की घोषणा की गयी, उसका नाम पहले कभी किसी न नहीं सुना था और तत्स्थानीय प्रचार भी अभूतपूर्व था।

राजीव गांधी एक और कारण से भारत के परमाणु विफल को शब्दाडम्बर तक सीमित रखने को बाध्य थे। भारत की सफेद प्रयोगात्मक परियोजनाएँ दीर्घमूर्ती हैं और अगल ही सकल रही। मनुष्यन द्वितीय प्रणाली के अभाव में भारत इस विफल को विश्वस्तनीय नहीं बना सकता। भारत में भी वि० प्र० मिह व धी चन्द्रोत्तर के प्रधान मन्त्री काल में भारतीय परमाणु नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कट्टर यथार्थ तो यह है कि आज भारत की परमाणु नीति का विक्षेपण भारतीय राष्ट्रीय हित के मन्दर्भ में दूरदर्शी दृष्टि में नहीं किया जा रहा, बल्कि सारी मायापञ्ची पाकिस्तान के त्रिशकलाप के प्रतिक्रिया स्वरूप ही की जा रही है। बहुम को मते ही कितना ही नया बनाकर पेश क्यों न किया जा रहा हो किन्तु मृदे और तर्क वही पुरान है।

आजादी के दिनों से ही भारत में दो पक्ष रह रहे हैं—बम बनाना आवश्यक समझने वाले और बम विरोधी। आरम्भ में 1947 में 1957-58 तक लगभग सभी भारतीय नेता (मावंचनिक रूप में सक्रिय) निरासन्नकरण व प्रति प्रतिबद्ध थे। 1957-58 में चीन के साथ सम्बन्धों में उड़बाहट आने के बाद महावीर त्यागी जैसे विद्वानपात्र समझे जाने वाले कापेंसी सामदो ने बम की माग करना शुरू कर दिया। आगे चलकर 1960 वाले दंग के पूर्वार्ध में अनेक बुद्धिजीवियों प्राध्यापकों, पत्रकारों आदि ने शोध और विक्षेपण द्वारा परमाणु बम की प्राण-महत्वकाथा को तर्कनगन मिट्ट किया। इनमें राजकृष्ण, निशिर गुप्ता, जयदेव सेठी और मुद्रहमण्यम स्वामी आदि खास तौर पर उल्लेखनीय हैं। मोटे तौर पर इनमें राजकृष्ण दक्षिणपथी, निशिर गुप्ता वामपथी, जयदेव सेठी देशज दक्षिणपथी (Native Centrist) और मुद्रहमण्यम स्वामी हिन्दू राष्ट्रवादी कह जा सकते हैं। महावीर त्यागी के अनुसार भारत के लिए अपने अन्तर्राष्ट्रीय महत्व को बनाये रखने और अहंकार की रक्षा के लिए परमाणु बम बनाना आवश्यक था। इस दौर में चीन

और महत्व को प्रमाणित करना जरूरी हो गया था। इसके बिना उनका अस्तित्व संकट में पड़ सकता था। किसी ऐसे चमत्कार की जरूरत थी, जो प्रतीकात्मक और भ्रान्तिपूर्ण ढंग से ही सही, उपयोगिता और लाभ-लागत की दृष्टि से इस कार्यक्रम की नार्चरता दर्शा सके। अतः यह गुमाना संकेंसगत होगा कि पोखरन परीक्षण सम्बन्धी नीति निर्णय इन भूध्वंश वैज्ञानिकों द्वारा श्रीमती गांधी को बहुलाने-फुललाने से आसान हुआ।

पोखरन परीक्षण के बाद भारत की आन्तरिक राजनीति में इसनी तेजी से अति-माटकीय परिवर्तन हुए कि परमाणु नीति निर्धारण का काम एक बार फिर टटाई में पड़ गया। जून, 1975 में आपातकाल की घोषणा और 'अनुशासन पर्व' में 'नीति की बात करना' लगभग अप्राप्तिक संभव था। आज यह कहना कठिन है कि 1975 से 1980 के बीच वर्षों में किस सीमा तक भारतीय परमाणु कार्यक्रम की शिथिलता राजनीतिक नेतृत्व की संकल्पहीनता व इच्छा शक्ति के अभाव से उपजी थी या इसका असली कारण भारतीय परमाणु वैज्ञानिकों की अयोग्यता-अक्षमता था।

जनता सरकार के काल में परमाणु नीति (1977 से 1980 तक)—जनता सरकार के काल (1977 से 1980 तक) में भारत की परमाणु नीति के सम्बन्ध में नीति निर्देश तो नहीं, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने एकपक्षीय घोषणा की कि भारत कभी भी किसी भी हतव्य में परमाणु ब्रह्म नहीं धत्तायेगा। जनवरी, 1980 में श्रीमती गांधी द्वारा पुनः सत्ता ग्रहण करने के बाद ही परमाणु नीति निर्धारण का काम पुनः आरम्भ हो सका।

जनता सरकार के अन्तराल में सिर्फ एक बात उल्लेखनीय है, जिसे यहाँ जोड़ा जा सकता है। श्रीमती गांधी द्वारा जनवरी, 1980 में पुनः सत्ता ग्रहण करने तक अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल चुका था। अफगानिस्तान में सोवियत सैनिक हस्तशेष और पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर वी सयी अमरीकी सैनिक सहायता के बाद भारत की अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा का परिप्रेक्ष्य और परिवेश आन्तक-भूल ढंग से बदल गये थे। 1980-82 के बीच यह बात भी बिल्कुल साफ हो गयी कि पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम विधुद रूप से सैनिक अभियान ही है। इन सबको ध्यान में रखते हुए यह बात एक बार फिर प्रासंगिक बन गयी कि भारत की परमाणु नीति पर पुनर्विचार एक तात्कालिक आवश्यकता है। अतः यह प्रश्न फिर सिर उठाने लगा कि भारत परमाणु कम बनाने या नहीं?

सम-सामयिक भारतीय परमाणु नीति (1980 से अब तक)—इन्दिरा गांधी द्वारा पुनः सत्ता ग्रहण करने के बाद भारतीय परमाणु नीति में कोई बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ। एक बार फिर अति माटकीय ढंग से आन्तरिक राजनीति में रजगत राजनीति में उठा-पटक ने नीति-निर्धारण को गोल बना दिया। 1980 से 1984 तक कई बार 'पाकिस्तानी बम' की चर्चा हुई। परन्तु इसके उत्तर में भारतीय प्रधानमंत्री ने कोई सार्वक पहल नहीं की। यहाँ पापद यह जोड़ने की जरूरत है कि भारतीय राजनीति के आवाज में अपने दूसरे अवतरण में इन्दिरा गांधी को विद्व इतिहास में अपने स्थान का ज्यादा गहरा जहलास था। संयोगवत् ही सही, गुद निरपेक्ष आन्दोलन का नेतृत्व हासिल करने के बाद तीसरी दुनिया के प्रवक्ता के रूप में निजम्तीकरण के प्रति उनकी अट्टा का भाव ज्यादा सुभर होने लगा था।

सम्पन्न राष्ट्रो की सख्या बढ़ने से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में गैर जिम्मेदारी और अनिश्चय की स्थिति बढ़ेगी जो सर्वनाश तक ले जा सकती है। इसके जवाब में हम समर्थक यह सुझाते रहे कि आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि 'सीमित परमाणु युद्ध' की परिकल्पना एक सार्वक अवधारणा है और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में आतंक का मन्तुलून साधने की सबसे बड़ी गारंटी। इसका अतिरिक्त बम-विरोधियों का कहना है कि परमाणु युद्ध के मन्दर्भ में किसी भी तक-सगत अवधारणा की बात करना पागलपन है। मानव जाति किसी अमूर्त सिद्धान्त की सार्वकता में परीक्षण के लिए सर्वनाश की जोखिम नहीं उठा सकती।

यह प्रश्न इसलिए और भी जटिल हो गया है कि आन्तरिक राजनीतिक दबावों के कारण और अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के अनुसार बहम में भाग लेने वाले लोग एक से अधिक बार अपना रुख बदल चुके हैं। कृष्ण चन्द्र पन्त, भुवानी सेन गुप्ता और जयदेव सेठी इसी बदलते रुख की मिशाल हैं। बम-विरोधियों में चीन-अमरीकी सम्बन्धों में सुधार के बाद माओवादियों और अमरीका में अद्भुत मनैक्य देखने को मिलता है तो भारतीय परमाणु अस्त्रों के पक्षधर अपनी सोवियत पक्षधरता के साथ-साथ साम्प्रदायिक हिन्दू उग्र राष्ट्रवादियों की गठरी लादने को विवश हुए हैं। डा० सी० राजमोहन जैसे लोगों के लिए अपनी राजनीतिक ईमानदारी का तालमेल के० सुब्रह्मण्यम की गुरु-मक्ति के साथ बिठाना जरूरी हो गया है। राज-मोहन के अनेक लेखों में बम के पक्ष और विपक्ष में तर्क एक साथ असमझम वाले ढंग से देने जा सकते हैं। वास्तव में वह आज सुब्रह्मण्यम के भारतीय रक्षा अध्ययन संस्थान और रजनी कोठारी के 'सेक्टर फार डेवस्तपिंग सोसाइटीज' के बीच बौद्धिकता प्रचारात्मक रस्साफाँसी में बदल चुकी है। इस बाद-विवाद प्रतियोगिता में किसी निश्चित फ़ैसले तक पहुँचना आसान नहीं है, क्योंकि इस सिलसिले में अन्तिम निर्णय किसी तर्क (Logic) में आधार पर नहीं, बल्कि व्यक्तिगत मूल्यों और विवेक (Conscience) के आधार पर ही लिया जाना है।

हमारी समझ में वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए निष्पक्षीकरण के प्रति निष्ठा और परमाणु अस्त्रों के उत्पादन के बिकल्प को बचाये रखने की एक साथ बात करना घोर पाछण्ड है। भारत के राष्ट्र हित में परमाणु अस्त्र हानिल करना एक अनिवार्यता है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो परमाणु बिकल्प अनिश्चित काल तक बचा नहीं रहे सकता। परन्तु इस बात को भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि कोई दूसरा व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार इससे बिल्कुल विपरीत निष्कर्ष तक भी पहुँच सकता है। अर्थात् वह परमाणु अस्त्र न बनाने का निष्कर्ष पर भी पहुँच सकता है।

सास परिवर्तन की सम्भावना नहीं—भारतीय परमाणु नीति विषयक बहस कभी समाप्त होने वाली नहीं है, क्योंकि हमारी समझ में इसमें हिस्सा लेने वाले लोग वहाँ से नहीं कुतर्क या भाव-विह्वलता से मचावित होत हैं। एक ओर नगवान बुद्ध, असोक और महात्मा गांधी की दुहाई दी जाती है कि कम भारत जैसा अहिंसक देश परमाणु बम जैसे सर्वनाशक अस्त्र बना सकता है। दूसरी ओर 'शाक्त परम्परा' की छाँट भी भारतीय इतिहास पर बम गहरी नहीं है। दलील यह है कि यदि भारत को स्वतन्त्र और स्वाधीन रहना है तो बिना परमाणु अस्त्रों के कान नहीं

विज्ञा-विशारद और अर्थशास्त्री के रूप में सुब्रह्मन्यम स्वामी शुद्ध साम-लागत की दृष्टि से यह मार्ग मुझा रहे थे। राजकृष्ण और जयदेव सेठी चीनी खतरे से आशंकित थे तथा विश्विय गुप्ता विद्युद शक्ति-सन्तुलन के अनुसार भारत की स्वायत्तता व स्वाधीनता बचाये रखने के लिए परमाणु बम का निर्माण जरूरी व महत्वपूर्ण समझते थे।

1965 के आम-पास जद्भुत प्रतिभागाती नौकरसाह के० सुब्रह्मन्यम का व्यावर्भाव रणनीति विश्लेषक (Strategy Analyst) के रूप में हुआ। भारतीय रक्षा अध्ययन संस्थान के निदेशक के रूप में उनकी बढ़ी उपलब्धि यही रही कि वह निम्न राजनीतिक कृद्धानों वाले विषय अवविरोधी से ग्रस्त तबको को भारतीय बम समर्थक लादी में एक साथ सा सके।¹ कापेसी शुभा तुर्क कृष्ण कान्त, भारतीय जनता पार्टी के जसवन्त सिंह और वायुसेना के अधिकारी एयर कमांडोर जसजीत सिंह जैसे बम समर्थक लोग के० सुब्रह्मन्यम की विषय परम्परा में आते हैं। विज्ञान के विद्यार्थी के० सुब्रह्मन्यम विषय की बुद्धता से आक्रान्त नहीं थे। समुक्त राष्ट्र सभ की निपासीकरण समितियों की सदस्यता ने उन्हें अनुद्धी विशेषज्ञता प्राप्त करने का अवसर दिया। रक्षा मन्त्रालय के अपने अनुभव से के० सुब्रह्मन्यम बहस में हस्तक्षेप न करने की परम्परा में पले। चूंकि भारतीय सेनाध्यक्ष परमाणु बम उत्पादन का समर्थन नहीं कर सकते, अतः उन्होंने स्वयं यह जिम्मेदारी ओढ़ ली कि वह अकेले ही प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ससद, समाचार-पत्रों और विश्वविद्यालयों में इस बहस को चरम रखेंगे।

नेहरू जी की मृत्यु के बाद परमाणु बम के विरोधियों में जयप्रकाश नारायण जैसे गांधीवादी मर्बोदमी और रजनी कोठरी जैसे गांधीवादी विचारक, वामपंथी-समाजवादी छद्धान में वैज्ञानिक पत्रकार सलोद अस्वारेस और प्रफुल्ल विदवर्दी, यूरोपीय परिवेश में प्रभावित बुद्धिजीवी भरत बाडियावाला तथा चीन विशेषज्ञ गिरिदेसकर उल्लेखनीय हैं। इन लोगों का तर्क द्विपक्षीय है, जिसकी सबसे स्पष्ट ढंग से प्रफुल्ल विदवर्दी ने परिमाणित किया है। इनके अनुसार परमाणु अस्त्र प्रति-रक्षा का कवच नहीं, बल्कि व्यापक संहार का उपकरण है। अतः भारत की हत्या या आत्महत्या के इस चर्चित साधन की जरूरत नहीं है। इसी का दूरमंच पहलू रजनी कोठारी, गिरिदेसकर आदि का सैद्धान्तिक शक्ति प्रेम है। गिरिदेसकर का मानना है कि परमाणु बम की ललक भारतीय उपमहाद्वीपीय साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का हिस्सा है। धीरेन्द्र शर्मा और वसोद अस्वारेस परमाणु बम को व्यापक सन्दर्भ में और भी खतरनाक और बेमानी समझते हैं। इनके अनुसार न केवल आणविक अस्त्रों का उत्पादन, बल्कि तमाम परमाणु ऊर्जा का उत्पादन बेहद खर्चे वाला है और दुर्घटना-जनित प्रदूषण या परमाणु राख (Nuclear Waste) के खतरे युद्ध के संयन्त्रास से कम भयावह नहीं।

परमाणु बम बनाने की माँग के समर्थक लोग यह मुझाते हैं कि बात सिर्फ साम-लागत की नहीं, बल्कि अवसर-लागत (Opportunity Cost) की भी है। पाकिस्तान या चीन द्वारा बगदोहन (blackmail) के अवसर पर भारत नरुमक नहीं रह सकता। जबकि परमाणु बम-विरोधी यह बात उल्लेखते हैं कि परमाणु शक्ति

¹ K. Subrahmanyam (ed.), *Nuclear Myths and Realities : India's Dilemma* (Delhi, 1981), 52-70.

द्वारा निर्मित भारतीय विदेश नीति रूपी भव्य प्रासाद की नींव बहुत कमजोर थी। इसीलिए उनकी जीवन सध्या में इस भवन के छतहूर ही रोप रहे गये थे। वस्तुतः किसी भी दश की विदेश नीति की सफलता एवं असफलता की एक वस्तुनिष्ठ कमीटी हो सकती है, वह है—देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा। इस तरह देखें तो नेहरू ने 'आदर्श की मृग-मरीचिका के तहत 'मथार्य' की बलि दे दी थी। परन्तु इसके उत्तर में ए० अण्णादुराई और एम० एस० राजन जैसे विद्वान नेहरू के पक्ष में स्वयं नेहरू को उद्धृत करते रहे हैं—'आखिरकार आदर्शवाद क्या है? आने वाले कल का मथार्यवाद ही तो है।' आज भी भारतीय विदेश-नीति के विद्याधियों के लिए यह बुनोती बची रहती है कि वे किस निष्कर्ष पर पहुँचे? 1947 से आज तक भारत का अन्तर्राष्ट्रीय आचरण 'आदर्शवादी' माना जाये या 'मथार्यवादी'? इस महत्वाकांक्षी परियोजना का क्रियान्वयन सफल समझा जाये या असफल?

1964 से आज तक केन्द्र सरकार में कई महत्वपूर्ण दुनियादी परिवर्तन हुए हैं और भारतीय विदेश-नीति निर्णायक ढंग से संशोधित परिवर्तित की गयी। अनेक अन्य प्रश्न इस सन्दर्भ में महत्वपूर्ण जान पड़ते हैं? भारतीय विदेश-नीति में सिद्धान्त अधिक महत्वपूर्ण हैं या व्यक्तित्व? इसमें परम्परा का प्रभाव अधिक स्पष्ट है या परिवर्तनकारी क्षतियाँ भारत के आचरण को अनुकूलित करती हैं? इसमें दीर्घस्थ राजनेताओं एवं विचारकों का प्रभाव अधिक प्रभावशाली है या लोकशाही प्रशासकों का? यह भी सोचने लायक बात है कि क्या कालान्तर में भारतीय विदेश-नीति की प्राथमिकताएँ या क्षितिज सिमटे हैं?

सिद्धान्त अधिक महत्वपूर्ण हैं या व्यक्तित्व—यह खेद का विषय है कि अब तक भारतीय विदेश नीति का अध्ययन व विद्वेपण मुख्यतः नेहरूपुरीन अनुभव पर केन्द्रित रहा है। श्रीमती इन्दिरा गांधी की विदेश-नीति के बारे में भी टिप्पणियाँ हमी शैली के अनुरूप हैं कि जैसे वह नेहरू की परिशिष्ट मात्र है। वैसे कुछ ऐम आलोचक भी हैं जो श्रीमती गांधी को दूसरा छोर या ध्रुव मानते हैं, जिनका नेहरू का चिन्तन और आचरण से जन्मजात वैर था। जनता सरकार के अन्तराल को एक व्यवधान या उप-विराम बिन्दु भर समझा जाता है। एक पक्षीदगी यह भी है कि स्वयं श्रीमती गांधी के कार्यकाल का एक अन्तराल दो हिस्सों में बँटा है और इन दो अवधियों में निरन्तरता स्पष्ट परिलक्षित नहीं होती है और न ही यह आसानी से आरोपित की जा सकती है।

परम्परा बनाम परिवर्तन—इन सब बातों को ध्यान में रखकर जब हम पिछले चार दशकों की भारतीय विदेश-नीति पर आलोचनात्मक दृष्टिपात करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य स्वयंमव सामने आते हैं। नेहरू जी का विश्व दृष्टान आज तक भारतीय विदेश-नीति का निर्धारण व क्रियान्वयन के लिए सार्वक पृष्ठभूमि का नाम करता रहा है। इसमें यह जोड़ने की आवश्यकता है कि यह विश्व दृष्टान 1947 से लेकर आज तक बराबर उपयोगी नहीं रहा है। शीत युद्ध के शारम्भिक दौर में सान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व वाला राजनय का जो सामरिक महत्व था, वह तनाम शैलियों के दौर में नहीं रह सकता था। इसी तरह अफो-एशियाई जगत में हर राष्ट्र का औपनिवेशिक दासता में मुक्ति पाने का रास्ता फँक रहा। अफो-एशियाई जगत या तीसरी दुनिया की एकता भी आकाश बुलुम ही रही। भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज व महत्वपूर्ण उद्योग-व्यवसायों ने साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के समावातों ने भी

नल सकता। इनके अभाव में चीन हो या पाकिस्तान, हमारा मनमाना भयादोहन (जुनकमेल) कर सकते हैं। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि यदि आज भारत सरकार सख्त पार बरमोरी उन्नवादियों के अड्डे मटियाभेट करने का साहस नही जुटा पा रही है तो सिर्फ इसीलिए कि पाकिस्तान के पास 'बम' है। विश्व बैंक से ऋण की जरूरत ने एक नया आराम जोड़ा। जाने वाले महीनों में परमाणु प्रसार रोक सन्धि पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत पर दबाव निरन्तर बढ़ेगा। एक ओर के० मुखहममद जस विद्वान है, जो मानते हैं कि परमाणु बम बनाने के बाद भारत के रक्षा खर्च में कटौती की जा सकेगी और आतंक का सन्तुलन बरकरार रखकर पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों का सामान्यीकरण सहज होवा। दूसरी ओर दिलीप मुखर्जी जेमे वरिष्ठ विश्लेषक हैं, जिनका मानना है कि रक्षा खर्च में कटौती नहीं होगी, बल्कि परमाणु क्षेत्र में एक अन्वो दौड़ तथा आत्मघातक होड़ और गुरू हो जायेगी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर धीरेन्द्र शर्मा की स्थिति अनुडी है। वह परमाणु शक्ति के दान्तिपूर्ण उपयोग के भी बिरुद्ध है। उनका मानना है कि परमाणु वैज्ञानिकों का अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय माफिया अपनी सफलताओं का झूठा प्रचार कर साम्राज्य का विस्तार करता है और इस दुस्साहसिक अधिपान के दुषदायी सामाजिक व आर्थिक परिणामों के प्रति आँख-कान मूदे रखता है। एक ओर यह सवाल भारत के राष्ट्रीय सम्मान से जुड़ा है तो दूसरी ओर आर्थिक तकनीकी समदा और आरम निरन्तरा है। आज भारत के सामने सामरिक चुनौती मुंह धाएँ लड़ी है और अन्तर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप-दबाव निरन्तर बढ रहा है। आम भावनी हो या विरोध, तमाम प्रतिक्रियाएँ परस्पर विरोधी जीवन मूल्यों और दनगत राजनीतिक पलधरता से जुड़ी है। इस स्थिति में भारतीय परमाणु नीति में खाग परिवर्तन की भाषा निकट भविष्य में नही की जा सकती।

भारतीय विदेश नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन (Critical Assessment of Indian Foreign Policy)

भारतीय विदेश नीति के बारे में आरम्भ से ही विद्वानों का यह मत रहा है कि यह एक अनुद्य अमिपान है। माइकिल बेघर के अनुसार इसके निर्मोजक व निदामक जवाहर लाल नेहरू की भूमिका अनुभुत थी। उन्होंने ही विदेश नीति रूपी इन भवन की कल्पना व स्वरंखा तैयार की थी और इसके निर्माण में हाथ बँटाया था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद के इस वर्षों में इस भवन का बाह्य रूप नब्ध था और यह वर्तकों की प्रभावित करता था। जयन्तनुज बंयोपाध्याय जैसे विद्वानों का मानना है कि नेहरूकालीन भारतीय विदेश नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसकी सुनियारी अयमारणाओं ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में प्रतिष्ठित एवं पारम्परिक विद्वानों को चुनौती दी गयी थी। बंयोपाध्याय ने इन बात पर जोर दिया है कि भारतीय विदेश नीति मत्ता-समय और शक्ति-समय को नकार कर सामूहिक हित और दान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व का विकल्प प्रस्तुत करने की चेष्टा कर रही थी।

किन्तु इनके बाद के दो दशकों में जो षट्पाश्रम नामने आया, उनमें भारतीय विदेश नीति के इस प्रारम्भिक मूल्यांकन पर कई प्रश्न बिहू लगा दिये। 'इण्डियाज पायना वार' के लेखक नेविल मेकमेले ने नेहरू जी के निधन के दन वर्ष बाद भारतीय विदेश नीति का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रकाशित किया कि नेहरू

विशेष व घनिष्ठ सम्बन्ध, जो पराधीनता के सूचक बतई नहीं हैं, नेहरू के काल से आज तक एक से रहे हैं। जनता सरकार के काल में इनको परिवर्तित करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया।

रगभेद विरोध हो या उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद के विरुद्ध सघर्ष, भारत की नीति सायंक, तर्कसंगत, निरन्तर एक जैसी और प्रगतिशील रही है। संयुक्त राष्ट्र सभ के तत्वावधान में, विशेषकर इसके विशेषीकृत अभिकरणों के अन्तर्गत क्रियान्वित हो रही परियोजनाओं में भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी तरह गुट निरपेक्ष आन्दोलन हो या राष्ट्रमण्डल की गतिविधियाँ, इसका अध्ययन-विश्लेषण आरम्भ करते ही भारत का महत्व सामने आ जाता है।

अक्सर भी हैं और चुनौतियाँ भी—भारतीय विदेश-नीति के निर्धारण व क्रियान्वयन के सन्दर्भ में यह बात हमेशा ध्यान में रखने लायक है कि निम्नलिखित 50-60 वर्षों में तत्सम्बन्धी राजनय तभी गतिशील रहा है, जब दीर्घस्थ नेता आंतरिक और बाह्य नीतियों के अन्तर-सम्बन्ध को ध्यान में रखकर इनको अन्तर-सन्तुलित करते हुए 'नेतृत्व' का जोखिम उठाने को तैयार रहे हैं। श्रीमती गांधी के निधन के बाद यह बात अवश्य खटकने वाली है कि प्रधानमंत्री और उनके सलाहकारों की सक्रियता किमी निश्चित सक्षम तक पहुँचने की अभिलाषा से प्रेरित नहीं जान पड़ती। उनमें परिवर्तन और पहल का उत्साह तो है, परन्तु उनका परीक्षण देश की रक्षा और गन्तव्य दिशा को अच्छी तरह समझे-पहचाने बिना नहीं किया जा सकता। अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में श्रीमती गांधी अक्सर इस बात पर ध्यान देती थी कि देश के सामने चुनौतियाँ भी हैं और अक्सर भी। यदि हम अक्सर का लाभ उठाने को तैयार नहीं होते हैं तो चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते।

नेहरू की विरासत को एकमात्र मूलमंत्र मानना शोचनीय—अन्त में, इस तरफ ध्यान दिलाया जाना परमावश्यक है कि नेहरू जी की विरासत को भारतीय विदेश नीति के निर्धारण व नियोजन का एकमात्र मूल मंत्र नहीं बनाया जा सकता। भारतीय नेताओं व प्रशासकों का ह्रास अब तक ऐसा रहा है, जैसा मध्य युग में प्राचीन सभ्यता के दीर्घाकारों का हुआ करता था। मौलिक चिन्तन से नाता तोड़कर अन्वय-विश्लेषणों और मशौल्कार मात्र से ही काम चल जाता था। यह स्थिति शोचनीय है। नेहरू जी जिस दुनिया से परिचित थे और जिसमें रहने और सघर्ष करने का उन्होंने भारत को रास्ता बतलाया, वह आज दुनिया की तरफ पर बदल चुका है। यदि हम आज भारत को 21वीं सदी में पहुँचाने की बात करते हैं तो 1927 के बुसेल्स सम्मेलन या हिस्पानी (स्पेन में) ग्रह युद्ध और यूरोप में नाज़ियों के उत्थान की यादें ताज़ा करने में काम नहीं चल सकता। बड़े विराट पैमाने पर आयोजित सांस्कृतिक राजनय, पर्यटन विभाग की जरूरतें भले ही पूरी कर सक्ता हो, किन्तु हम माध्यम से राष्ट्रीय हित के मापन की बात नहीं मोची जा सकती।

विदेश-नीति के पूर्वाग्रहों और पूर्वानुमानों को मद्धमदृष्ट कर दिया। भारत-चीन सीमा संघर्ष, सोवियत-चीन विग्रह, यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय एकीकरण, हिन्द चीन व पश्चिम एशिया में निरन्तर चल रहे संकट, इस्लामी पुनरुत्थानवादी उग्रवाद का ज्वार तथा अस्तिकवाद का आविर्भाव ऐसे परिवर्तन हैं, जिनका मुकाबला करने में असमर्थता का दोष भारतीय विदेश-नीति के निर्धारकों को देना न्यायोचित नहीं।

इस बात को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति महाभक्ति-केन्द्रित रही है। भारत स्वयं एक बड़ी शक्ति नहीं। भू-राजनीतिक कारणों से भारत के पड़ोस (अफगानिस्तान व पाकिस्तान) या हिन्द महासागर में महाभक्तियों की उपस्थिति व प्रतिस्पर्धा को रोकने में या अन्तर्राष्ट्रीय संकट समाधान में मध्यस्थता के सन्दर्भ में आज भारत की क्षमता सीमित ही है। किसी अन्तर्राष्ट्रीय खेल का नेतृत्व करने की अपेक्षा आर्थिक विकास और समतापूर्ण समाज की उपलब्धि भारतीय राजनीति की प्राथमिकताएँ हैं। जो आलोचक यह सोचते हैं कि विदेश नीति में व्यस्तता पहले नेहरू की और आज नरसिंह राव की सर्पिली विलासिता है, उन्हें जानना चाहिए कि अब आन्तरिक लक्ष्य बाहरी दुनिया के दबावों से निर्णायक रूप से प्रभावित होते हैं।

आदर्शवाद व यथार्थवाद का द्वन्द्व—जैसा कि आरम्भ में कहा गया है कि किसी भी देश की विदेश-नीति उसकी आन्तरिक नीतियों का विस्तार-प्रक्षेप ही होती है। राष्ट्रीय हितों के सर्वधन-संरक्षण का अर्थ दिग्विजय की गवाकाएँ फहराना नहीं, बल्कि अपनी भौगोलिक अखण्डता को जलत रखना और आर्थिक विकास को स्वाधीन बनाना होता है। इस दृष्टि से देखें तो भारतीय विदेश-नीति आशिक रूप से ही सफल मानी जा सकती है। यह बात रेखांकित किया जाना जरूरी है कि अमरीका हो या रूस, चीन हो या अन्य कोई देश, सभी की विदेश-नीति कुल मिलाकर आशिक रूप से ही सफल मानी जा सकती है। इसी तरह परम्परा और परिवर्तन का पक्ष भी है। हर महत्वपूर्ण राष्ट्र की विदेश-नीति ऐतिहासिक उत्तराधिकार के बोझ के साथ-साथ नवविषय के दबावों का सन्तुलन करने का प्रयत्न करती है।

इस प्रकार, आदर्शवाद व यथार्थवाद के द्वन्द्व की बहुत भी कुल मिलाकर बेवुनियाद है। नेहरू जी अपनी हर नीति का आदर्शमूलक परिचय दे सकते थे। परन्तु भारत के हिन्दू की रक्षा के मामले में नेहरू को बल-प्रयोग में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं हुई। 1947-48 में कश्मीर, 1961 में गोवा, 1962 में चीन के साथ मुठभेड़ आदि सभी इस बात की भलीभाँति दगति हैं। बल्कि कहने वाले तो यहाँ तक पहुँचते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में बल प्रयोग से समस्या-समाधान ढूँढ़ने वालों में भारत अग्रणी रहा है। नेहरू के बाद गांधी ने 1965 में पाकिस्तान के साथ और श्रीमती गांधी ने 1971 में बंगला देश को मुक्त कराने के लिए सैनिक बल के प्रयोग का मार्ग चुना।

स्वाधीनता गिरवी नहीं—इसी तरह आर्थिक आदान-प्रदान के क्षेत्र में भारत की अतृप्ति उपलब्धि यह रही है कि उगने पूँजीवादी और समाजवादी दोनों खेलों से बड़े पैमाने पर आर्थिक व तकनीकी सहायता ग्रहण की, परन्तु उसने कभी अपनी स्वाधीनता गिरवी नहीं रखी। भारत-सोवियत मैत्री व सहयोग सन्धि उसके सोवियत संघ के साथ सम्बन्धों में विशेषता को उजागर करती थी। परन्तु इससे भारत की मुक्त निर्णयता का छाय प्रमाणित नहीं होता। भारत व सोवियत संघ के बीच में

के अन्य बहुसंख्यक सदस्यों के लिए भी यह शक्ति समीकरण निर्णायक महत्व का सिद्ध हुआ। इससे पहले कि हम इस विषय का विस्तृत विवेचन करें, सोवियत-चीन सम्बन्धों के प्रारम्भिक मैत्रीपूर्ण आत्मोद्योग और वास्तुनिष्ठ मूल्यारण उपयोगी होगा। इस दौर में साम्यवादी चीन और सोवियत मध्य के बीच सम्बन्ध पारम्परिक साम्यवादी फार्मूले के अनुसार ही निर्धारित-मंचालित होते रहे, जिसमें मारे ममाजवादी राष्ट्र एक-दूसरे में खे जाते हैं और बुर्जुआ देश दूसरे से में। इस पूरे दौर में चीन की भूमिका ममाजवादी से के सदस्य के रूप में ही परिभाषित की गयी।¹²

मैत्रीपूर्ण आत्मोद्योग सम्बन्धों का दौर (1949-1960)—सोवियत मध्य और चीन दोनों ऐसे पड़ोसी देश हैं, जिनकी 'विशेषता' और 'महानता' का दावा अपनी-अपनी तरह से अनूठा था। सोवियत मध्य पृथ्वी का सबसे बड़ा भू-भाग (1/6) घेर हुए था तो चीन सबसे ज्यादा आबादी (एक अरब से भी ज्यादा) वाला देश है। चीन सबसे पुरानी जीवित सांस्कृतिक परम्परा का धारण है तो कम मध्य काल से ही यूरोप की बड़ी ताकतों में गिना जाना रहा था। साम्राज्यवाद के विस्तारवादी दौर (1905 तक) में मने ही इन दोनों देशों के बीच सीमान्त पर टकराव होता रहा, परन्तु सन् के रूप में एक-दूसरे को देखने की कोई भी जरूरत किसी ने महसूस नहीं की, क्योंकि राष्ट्रीय नीति और पहचान मुख्यतः राजधानियों पर सीमित रही और मास्को तथा नानकिंग (चीन की तरापीलीन राजधानी) के बीच की दूरी अलघ्य थी। साइबेरिया के जिस सख्त पर इन दो देशों की सीमाएँ मिलती थी, वहाँ आधुनिक वैज्ञानिक माधनों के अभाव में मानव जीवन दुष्कर था। वैसे भी, कम और चीन बीमारी सदी के उत्तरार्द्ध तक आन्तरिक राजनीतिक उल्ल-गुल्ल के कारण अपने देश की गरुद से बाहर जीवने लायक हालत में नहीं थे। ऐसी हालत में मने ही उनमें घनिष्ठता नहीं रही हो, परन्तु एक तटस्थ उपाय का भाव रखना सहज था।

मावियत मध्य और चीन दोनों जगह साम्यवाद के आविर्भाव के पहले नीतियों के समायाजन या मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों की स्थापना के लिए पहल करने की जरूरत किसी भी पक्ष ने महसूस नहीं की। साम्यवाद के आविर्भाव के बाद दोनों देशों के सम्बन्ध हमसा मैत्रीपूर्ण या तनाव में मुक्त रहे हो, ऐसा भी नहीं हुआ। कम में बोल्शेविक शान्ति के बाद कमिन्टर्न (Comintern) की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य अन्य देश में साम्यवादी शान्ति का निर्यात करना था। इस दौरान मावियत शासक स्टालिन ने बुगारिन और बोरादीन जैसे अपने एजेंटों की सहायता से अन्य ओशनियनिक व दशरक्षक देश में साम्यवादी पार्टियों का अपने नियन्त्रण में रखने का भरमक प्रयत्न किया। चीन के साम्यवादी अपनी असमर्थता-सुरक्षा के कारण मने ही अपने देश में गृह युद्ध के दौर में कम पर निर्भर रहने को विषय हुए, किन्तु बाद में उनका लिए इस सम्बन्ध का बनाय रखना किसी भी तरह सहज या आत्म-सम्मानपूर्ण नहीं था। गान्धर उग स्थिति में जब माओरमे मुँग और स्टालिन दोनों ही उभ एक अहकारी व्यक्तित्व बाने नेता थे।

इन सब कारणों के बावजूद यदि 1945 के बाद सोवियत मध्य और चीन के आपसी सम्बन्ध महापानियों की तरह रह गये तो उसका लिए द्वितीय विश्व-युद्धोत्तर काल के अन्तराष्ट्रीय दवाय क्रिमेदार थे। जहाँ एक ओर युद्धोत्तर पुनर्निर्माण में

¹² Michael Yabuda, *China's Foreign Policy After Mao* (London, 1981), 20.

सोलहवां अध्याय

विश्व राजनीति के अन्य प्रमुख मामले

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसे कई अन्य प्रमुख मामले न सकट उठे, जिन्होंने विश्व शान्ति और सुरक्षा को संकटग्रस्त कर दिया। ये मामले न केवल गम्भीर चर्चा के केन्द्र-बिन्दु रहे, बल्कि उन्होंने सम्पूर्ण मानव समाज के समक्ष नई चुनौतियाँ खड़ी कर दी। सामयिक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसे अनेक मामले-सकट भाग भी मूँह बाएँ छड़े हैं, जिनका अपेक्षित विस्तरेष्य इस पुस्तक के पिछले अध्यायों में नहीं हो पाया है। यहाँ ऐसे ही अन्य अत्यन्त महत्वपूर्ण मामलों का चिबचन किया जा रहा है। ये मामले हैं—

- (1) सोवियत-चीन सम्बन्ध।
- (2) कबोडिया विवाद और हिन्द-चीन संकट।
- (3) विश्व तेल संकट व भारत।
- (4) आतंकवाद की समस्या।
- (5) हिन्द महासागर में महाशक्तियों की पैतरेबानी।
- (6) पाकिस्तान की परमाणु तैयारियाँ।
- (7) रंगभेद की समस्या: दक्षिण अफ्रीका व नामीबिया।
- (8) नामीबिया की आजादी एवं नई चुनौतियाँ।
- (9) नई विश्व अणुअवस्था की तलाश।
- (10) तीसरी दुनिया की एकता का सवाल।
- (11) अफगान संकट एवं जेनेवा समझौता।
- (12) पूर्वी यूरोप में परिवर्तन व उनके विश्व राजनीति पर प्रभाव।
- (13) जर्मनी के एकीकरण का मसला।
- (14) मुफर-301 पर भारत व अमरीका में मतभेद।

सोवियत-चीन सम्बन्ध (Sino-Soviet Relations)

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बेहद महत्वपूर्ण व नाटकीय घटनाक्रम सोवियत संघ और जनवादी चीन के बीच गहरी और खतरनाक दरार का पैदा होना था। इसे रूस-चीन विग्रह, वैमनस्य या टकराव (Sino-Soviet Dispute) के नाम से भी जाना जाता है। यह वास्तव में बड़ी अटपटी बात थी कि एक ही विचारधारा को मानने वाले और एक ही सामरिक परिप्रेक्ष्य के साक्षीवार दो राष्ट्र आपस में सैनिक मुठभेड़ तक पहुँच जायें। इस परिवर्तन से दोनों महाशक्तियों के आपसी सम्बन्धों पर जो प्रभाव पड़े, उनकी किसी भी चर्चा में उपेक्षा नहीं की जा सकती। साथ ही, अन्य बड़ी शक्तियों और अफ्रो-एशियाई जगत

खतरनाक रूप से ठहर कर सामने आये। सोवियत संघ ने स्ट्रुइव के सत्ता ग्रहण करने के साथ यह स्पष्ट कर दिया कि नवियुग में उनकी नीतियाँ शान्तिपूर्ण मह-अस्तित्व के मिद्धान्त पर आधारित होंगी। सोवियत संघ द्वारा अमरीका को 'सहयोगी प्रतिस्पर्धी' (Adversary Partner) के रूप में देखे जाने की यह गुरुवात थी। यह वह दौर था, जब माओवादी चीन 'जीवित गुलाबी' से 'अन्तिमारी शहादत' को श्रेष्ठ (Better red than dead) बतलाने में लगा हुआ था और अमरीका को 'कागजी घेर' कह रहा था। सोवियत संघ में बीमवी पार्टी कांग्रेस के साथ 'विस्तारितनीकरण' (Destalinization) की जो प्रक्रिया आरम्भ हुई, उसके बारे में माओ जैसे वरिष्ठ नेता से सलाह मागविरा नहीं किये जाने पर अनेक चीनी नेता बेहद खिन्न थे। इस प्रकार 'विस्तारितनीकरण' सोवियत संघ और चीन के बीच कटु मतभेद का कारण बना।

2. क्यूबा संकट व भारत-चीन सीमा विवाद—इन बीच अन्तर्राष्ट्रीय रणमंच पर अनेक ऐसी घटनाएँ घटीं, जिन्होंने सोवियत संघ व चीन के बीच क्लेश को बढ़ाया। क्यूबाई प्रक्षेपास्त्र संकट (1962) के बाद अमरीका व रुस के आपसी सम्बन्धों और सवाद की विशेषता उजागर हुई तो भारत-चीन सीमा विवाद के वक्त सोवियत संघ द्वारा माह्वा और मित्रों में फर्क न किये जाने से चीनी नेता सोवियत संघ के प्रति बेहद खिन्न हुए।

3. जातीय-नस्लवादी तत्व—इस मरनीकृत निष्कर्ष तक पहुँचना आसान है कि सोवियत संघ और चीन ने जरूरत न रह जाने पर अपने अपने अलग-अलग धुन लिये। परन्तु ऐसा समझना तर्कसंगत नहीं होगा। यह भी नहीं कहा जा सकता कि सोवियत संघ और चीन के बीच की साईं मित्र पारम्परिक हित मर्ष का उभरना थी। वस्तुतः मरिया पुराने पारम्परिक और सम-नामयिक मधुपर्जनक तत्वों के सन्निपात से दोनों देशों के बीच यह ठनावपूर्ण स्थिति पैदा हुई थी। इस विवाद का एक पक्ष जातीय-नस्लवादी था। स्लाव लोग अर्थात् बहुमुखक रुसी मूलक युरोपीय सत्कार वाले गौर लोग हैं और चीनी अस्वतंत्र पीले एशियाई। दोनों जातियों में नस्लवादी अहकार बड़-पड़कर है। साम्राज्यवादी मध्ययुगीन दौर में इस जातीय टकराव से मर्यादित के स्वाभित्व का मनला भी जुड़ गया। रुसियों का मानना था कि माओ राजाओं ने उनकी जमीन पर कब्जा कर रखा है तो चीनियों का मानना था कि वे स्वयं आरम्भाही के शिकार होत रह हैं।

4. मार्क्सवाद-लेनिनवाद की व्याख्या के बारे में मतभेद—दोनों दलों द्वारा मार्क्सवाद का रास्ता अपनाने के बाद फर्क और विवाद का एक और आधार उद्घाटित हुआ। सोवियत व चीनी नेताओं के बीच मार्क्स और लेनिन की व्यापनाओं की व्याख्या के विषय में एक बुनियादी फर्क रहा। हाँ, दोनों दलों के नेताओं के तर्क अपनी-अपनी जगह पर जरूर 'मर्ग' थे और उनसे अपने राष्ट्रीय अनुभव से अनुशासित-प्रभावित। सोवियत संघ में बोलशेविक अग्नि की मरसना गुप्त रूप से सगठित और लगभग पेंगेबर पार्टी पर निर्भर थी तथा सर्वहारा के पक्ष में पार्टी के अधिनायकत्व की पक्षधर, जबकि चीन का जन मुक्ति युद्धात्म माओवादी ध्यापामारी पर आधारित था और इनके दौरान अनेक मार्क्सवादी व्यापनाओं-परिवर्तनाओं में महत्वपूर्ण ढंग से संशोधन-परिवर्तन किया गया। मरसन, चीनी साम्यवादी पार्टी 'धर्मिक' नहीं, बल्कि 'रूपक' को 'अग्नि की नींव का पत्थर' मानती थी और पार्टी को अधिनायक नहीं,

लगा सोवियत संघ अमरीका द्वारा प्रस्तुत बहुमुखी चुनौतियों (सामरिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक) का सामना करने के लिए कमर कस रहा था, वहीं चीनी साम्यवादी अपने प्रतिद्वन्द्वी 'राष्ट्रवादी' कुमिनतांग पर विजयी होने के निर्णायक क्षण तक पहुँचने के बाद भी निरापद नहीं थे। जहाँ एक ओर चीन के साम्यवादियों के सामने यह सतरा था कि कोई बाहरी शक्ति हस्तक्षेप कर उनके तमाम किये परे पर पानी फेर सकती है वहीं दूसरी ओर आन्तरिक विध्वंसकारियों के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता भी महसूस की जा रही थी। चीनी नेताओं का एक प्रमुख उद्देश्य 'अपनी भूमि' के बचे हिस्से—ताइवान, किम्मोय, माजत्सु आदि को स्वाधीन कराना था। इसके लिए यह जरूरी था कि शत्रु पक्ष को प्राप्त महाशक्ति अमरीका के समर्थन को सन्तुलित करने के लिए दूसरी तत्कालीन महाशक्ति (अर्थात् सोवियत संघ) के साथ सम्बन्ध मधुर किये जायें।

इसके अलावा रूस व चीन के बीच हिंस्र के संयोग का आर्थिक पक्ष भी महत्वपूर्ण साबित हुआ। कुमिनतांग के दौर में अमरीकी पूँजीपति-उद्योगपति बड़े पैमाने पर चीन में सैन्य रहे। रूसी इस एकट को अनदेखा नहीं कर सकते थे कि वह अस्थिर स्थिति का साम उठाये। सोवियत संघ स्वयं भले ही अपने आर्थिक विकास के लिए साधनों के अभाव से पीड़ित था, लेकिन चीन के पिछड़ेपन को देखते हुए उनकी तकनीकी एवं आर्थिक सहायता करने नायक सामर्थ्य उसकी थी ही। इसके अलावा दो अन्य कारण थे। पहला तो यह कि चीनी नेताओं ने सोचा कि यदि सोवियत संघ के साथ सन्निवृद्ध मित्र राष्ट्र जैसे सम्बन्ध स्थापित किये जायें तो शायद मन्चूरिया और सिक्किम में स्टालिन की विस्तारवादी घुसपैठ को रोक जा सकता है। दूसरा कारण, दोनों देश मानसुंवादी विचारधारा के प्रति कटिबद्ध होने के कारण उनके बीच व्यापक, सार्वक और ठोस सहकार की जमीन तैयार थी। निरास्त्रीकरण, रणभेद, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, पूँजीवाद आदि के विषय में दोनों देशों में मतभेद था। 1949-50 से लेकर 1960-62 के दौरान इन सब कारणों से चीन और सोवियत संघ की एकता अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करती रही।

मैत्रीपूर्ण आत्मीयता के दौर में असन्तोष का बीजारोपण

बैसे दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण आत्मीयता के इस दौर में असन्तोष का बीजारोपण भी हो रहा था जो निरन्तर बढ़ता रहा। इसकी परिणति अन्ततः हिंस्रक अंतगाय में हुई। चीन को यह समझता रहा कि सोवियत संघ उसकी भौगोलिक अखण्डता और सम्प्रभुता की रक्षा के लिए परमाणु अस्त्रों का उपयोग करने में या कम से कम इसकी शक्ति देने में हिचकिचाता है। चीन को दो जाने वाली आर्थिक व तकनीकी सहायता उसकी जरूरत के मुताबिक नहीं, बल्कि इसी कृपा और उसकी अपनी सामरिक व राजनयिक तर्क प्रणाली पर निर्भर थी। दूसरी ओर रूसियों को इस बात से पड़ी आपत्ति थी कि चीनी नेता सोवियत संघ को साम्यवादी छेदे का गढ़ या राजधानी मानने के लिए तैयार नहीं थे। चीनी नेता जको-एशियाई देशों में अपनी अलग हस्ती बनाने के लिए मश्रिय रहते थे—खासकर दक्षिण पूर्व एशिया में।

सोवियत चीन मतभेद के कारण—सोवियत संघ और जनवादी चीन के बीच मतभेद के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे—

1. विस्तारितनीकरण—स्टालिन की मृत्यु के बाद दोनों देशों में मतभेद



सोवियत-चीन सीमा विवाद के प्रमुख बिंदु

व नैतिक काफी मझा म तैनात रह और दाना क परमाणु प्रक्षेपणों का मन एव दूबर का तरफ था। जब तक साम्यवादी-समाजवादी खमा एकजुट हानर पूजावादी साम्राज्यवादी खन व तिलाफ मझा था, तब नैतिक व सामरिक मामला म उपरम्य संसाधना व समुचित उपयोग और महार की बात सोची जा सकती थी। दाना पक्ष क लिए दाना पाद्यों म गन्धु की स्थिति न सैनिक तैयारी व मरु को बढ़ाया और अब तक सबसे बड़ गन्धु मझने जान वान अमेरिका व माप मुन्ह का माप प्रगस्त किया। साविकत चीन भीमा मझ का प्रभाव पूर बिस्व म शक्ति सनोकरणा और इस विवाद क सैदानिक पक्ष पर भी पड़ा।

7 एक-दूसरे क तिलाफ प्रचार अभियान—बानी नताजा व लिए इस बात का प्रचार आसान हुआ कि साविकत मझ एक समाजवादी शक्ति नहा, बल्कि एक 'सामाजिक साम्राज्यवादी' शक्ति है। उमूरी कतए पर टकराव का एक नम्यी श्रृंखला की आगिरी बड़ी बननाया जा सकता था, जिसकी गुरुजात खपी पढ़न हगरी व पानेय म हुई थी और इस तरह की हलक का चकोस्ताशकिया (1968) म

वल्कि 'मर्वेहारा का मेचक' समझती थी। इसके अलावा भ्रान्ति की रणनीति हड़ताल और गृह युद्ध के जरिये नहीं, वल्कि छापामार जन मुक्ति सशस्त्र के जरिये लाना चाहती थी। चीनी नेताओं की दृष्टि में भ्रान्ति कोई घटना नहीं, वल्कि निरन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। इसके अलावा में उत्पीड़क नौकरशाही या संशोधनवादी ही अपनी जड़ें जमा सकते हैं। इस तरह माओ का दर्शन रोटस्की की विचारधारा से अधिक नजदीक था। चीनी आचरण के बाद अपेक्षाकृत छोटे यूरोपीय राष्ट्रों के लिए अपनी तरह से साम्यवाद का राष्ट्रीय संस्करण तलाशना और तराशना सम्भव हुआ। उपर मोक्षियत संघ माओवाद को मार्क्सवाद-लेनिनवाद मानने को तैयार नहीं था। मोक्षियत दृष्टि में माओ दार्शनिक वित्तावाद और धब्दाद्वार की जड़ें एक ओर कम्यूनियस जैसे धर्म-संस्थापकों के कुतिलत्व तक पहुँचती थी और दूसरी ओर स्टालिनशाही व्यक्ति पूजा तथा चाटुकारिता की बाढ़ दिलाती थी। इस प्रकार, मार्जावाद और छापामार भ्रान्ति के निर्भाव की चीनी अवधारणाओं का कोई तालमेल सोवियत संघ की तान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की योजना के साथ नहीं बिठाया जा सकता था।

5. महाशक्तियों के बीच निराश्रीकरण घातों में प्रगति—सोवियत-चीन संमनस्य विस्फोटक नहीं होता, यदि स्थिति में 'कुछ विरोध बिगाड़' व्यक्तिगत और नीति सम्बन्धी घटनाओं में नहीं होता। तनाव-संधिस्थ की प्रक्रिया की प्रगति के साथ भमरोका और रुम के बीच व्यापक सहकार की जमीन तैयार हुई, जिसका स्पष्ट प्रभाव सधर्म पहले निराश्रीकरण के क्षेत्र में देखने को मिला। 1963-64 के दौरान अधिक परमाणु परीक्षण रोक मण्डि ने चीनी नेताओं के मन में सोवियत संघ के प्रति सन्नेह को पुष्ट किया। उनका ऐसा सोचना अस्वाभाविक नहीं था, क्योंकि जहाँ तक परमाणु अस्त्रों का प्रसार रोकने का प्रश्न है, दोनों महाशक्तियाँ एक हो जाती थी और अन्य देशों पर अपना 'जातताती एकाधिपत्य' बरकरार रखना चाहती थी। चीन की इस अवधारणा को तीसरी दुनिया के अनेक राष्ट्रों का समर्थन प्राप्त था। बहरहाल, 1960 में सोवियत वैज्ञानिक चीन से वापिस बुला लिये गये और चीन ने इन वैज्ञानिकों के मार्ग दर्शन के बिना परमाणु अस्त्र हासिल कर लिए। इसी दौरान माओसे तुंग ने चार दुनिया बानी अपनी प्रस्तावना प्रकाशित की, जिसमें दोनों महाशक्तियों को एक ही सोपन-उत्पीड़क श्रेणी में रखा गया था।

6. सीमा-संघर्ष—निराश्रीकरण के अलावा सोवियत-चीन सीमा-संघर्ष में संयोगवश इसी दौर में गूनी रूप लिया। सोवियत-चीन सीमा लगभग सात हजार किलोमीटर लम्बी है और इसका विभाजन दुर्गम माइवेरिया में आमूर तथा उत्तरी महायक उगुरी नदियाँ करती है। मार्च, 1969 में मैदान्तिक बहल की गर्मी का साथ उठाते हुए चीनी सैनिक टुकड़ों ने रूसियों को लिमन्स्की टापू से उधेड़ने की कोशिश की। इस मुठभेड़ में दोनों पक्षों के सैनिक हताहत हुए। इस घटना के बाद यह धम हमेला के लिए टूट गया कि चीन-रूस सीमा विचार द्विपक्ष मुठभेड़ और सर्वनाशक युद्ध का रूप नहीं ले सकता। इस बार विश्व भ्रान्ति के लिए संकट भारत-चीन सीमा विवाद में बढ़ी जघिक था, क्योंकि दोनों पक्षों के पास परमाणु अस्त्र थे। इन मुठभेड़ के बाद रूस और चीन दोनों को अपना 'सबसे बड़ा शत्रु' नए दण से परिभाषित करना पड़ा और उनके निदान के लिए अपनी सैनिक तैयारी व तैनाती नाटकीय दण से बढ़तनी पड़ी। अभी हाल तक चीन-रूस सीमा पर दोनों पक्षों

जब चीनी दूतावास पर कब्जा कर लिया और कुत्हाड़े भाँज कर अपने विशेषाधिकार का प्रदर्शन किया तो यह बात स्पष्ट हो गयी कि इन चीनियों के साथ सवाद नहीं साधा जा सकता ।

चीन, पश्चिमी देश व रूस (1971 के बाद)

यह समझना गलत होगा कि सांस्कृतिक क्रान्ति के दौर में वास्तव में चीनी राजनय क्रान्तिकारी, मार्क्सवादी और समता प्रोपक था । ईरान के शहसाह के साथ मैत्री बनाये रखने का प्रयत्न हो या वगला देश में मानवाधिकारों के हनन के वक्त पाकिस्तानी सैनिक तानाशाही को सह्यता देने का मामला, माओवादी चीन अन्तर्विरोधों से मुक्त नहीं था । इन अन्तर्विरोधों का प्रत्यक्ष प्रभाव सोवियत-चीन सम्बन्धों पर पड़ा । कई पश्चिमी पूँजीवादी राष्ट्रों ने इस विवाद का लाभ उठाते हुए चीन के साथ मुलह और दोस्ती का हाथ सिर्फ़ इसलिए बढ़ाया, ताकि पड़ोस में सामने खड़े अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली और खतरनाक शत्रु सोवियत संघ को कमजोर किया जा सके ।

चीन के साथ 'दोस्ती की पहल' करने वालों में फ़्रान्स सबसे पहला देश था । निकमन के अमरीका ने भी जल्दी ही अन्तर्राष्ट्रीय जुए में चीनी तुष्ट का महत्व समझ लिया । वगला देश मुक्ति अभियान के समय भारत सोवियत संघ के साथ संधिबद्ध होने को विवक्षित हुआ । इस असन्तुलन को दूर करने, पाकिस्तान का विखंडन नकारने और पाकिस्तान के माध्यम से चीन के साथ अपने सम्बन्ध सुधारने के लिए किमिज़र का 'शटन राजनय' सत्रिय हुआ ।

1972-75 के दौरान वियतनाम में युद्ध विराम हुआ और चीन में माओ युग का समापन देखने को मिला । भले ही माओ जीवित रहे, मगर चीनी राजनीति और विदेश नीति पर उनका प्रभाव नाममात्र को ही शेष रहा । चीन में माओ के बाद दंग मियाओ पिंग का वर्चस्व निरन्तर बढ़ा और इस सिद्धान्त को तिलाजलि दे दी गयी कि 'राजनीतिक शक्ति बन्दूक की नाल से उपजती है ।

1975 में हेलमिची समझौते ने तनाव-शैथिल्य के चरमोत्कर्ष को दर्शाया । इनके बाद शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की सीमाएँ देखने को मिलीं । साल्ट-डो समझौते के अनुमोदन की असफलता, मानवाधिकारों को लेकर महाशक्तियों के बीच मनमुटाव, अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप तथा अमरीका द्वारा स्टार वार्म की घोषणा ने चीन युद्ध की कट्टरता और मानसिकता को सोवियत संघ और अमरीका के बीच फिर से लौटा दिया । इन परिस्थितियों में सोवियत-चीन मध्य अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण पथर्षों के रूप में प्रकट हुआ ।

दंग सियाओ पिंग और रूस-चीन सम्बन्ध (1976 से आगे)

यह स्थिति लगभग एक दशक तक बनी रही । सोवियत संघ में सत्ता परिवर्तन और चीन में दंग मियाओ पिंग की पकड़ मजबूत होने के साथ इसमें बदलाव नज़र आने लगे । दंग मियाओ पिंग ने 21वीं मदी शुरू होने तक चीन को एक शक्तिशाली हस्ती बना लेने के राष्ट्रीय स्वल्प की घोषणा की और इसके लिए चार आधुनिकीकरण अनिवार्य बतलाये । इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पूँजी और परिष्कृत टेक्नोलॉजी का आयात जरूरी था । चीन के नये नेतृत्व ने आर्थिक

दोहराया गया था। दुर्भाग्यवश, चेकोस्लोवाकिया प्रकरण के समय सोवियत नेता ब्रेज्नेव ने समाजवादी राष्ट्रों की सीमित सम्प्रभुता के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जिससे चीनी आक्षेपों की पुष्टि होती जान पड़ती थी।

हमारी ओर माओ के सहयोगी उग्रवादी ल्यू साओ ची और जिन पियाओ ने कभी इन बातों को छिपाने का कोई प्रयत्न नहीं किया कि उनके सामने निकट भविष्य में त्रिपक्षित की जाने वाली क्रान्ति के निर्धारित की सुस्पष्ट रूपरेखा थी। दुनिया भर के विपन्न देशों की उत्पत्ति 'पाँच' के रूप में की गयी थी, जो व्यापार हमलों के बाद जानलेवा ढंग से घेरने के लिए उकसाये जा रहे थे। इसको ध्यान में रखते हुए हमें यह प्रमाणित कर सकते थे कि चीनी आचरण खतरनाक और गैर-जिम्मेदार था।

इसी तरह बर्मा, इण्डोनेशिया आदि में माओवादी साम्यवादियों की बढ़ती गतिविधियों ने सोवियत तर्फ को पुष्ट किया। चाऊ एन साई की 'अफ्रीका सफारी' के बाद संजानिया आदि देशों में चीनी राजनयिक त्रिपक्षिता को घुसपैठिया व पड़पनकारी समझा जाने लगा। अफ्रो-एशियाई बिरादरी में गुट निरोधक आन्दोलन के मुकाबले अपना जमपट खड़ा करने का चीनी प्रयत्न भी उनके पक्षीसियों को निश्चित नहीं बैठे रहने दे सकता था।

1969 में उमुरी नदी पर टकराव के बाद अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम काफी तेजी व नाटकीय ढंग से बदला। अमरीका सबसे पहले वियतनाम की दलदल में फँसने के कारण इन बातों के प्रति बहुत सतर्क था कि उत्तरी वियतनाम की बमबारी भूलें से भी चीनी भूमि या सम्पत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाये। साथ ही मौसोलिक दूरी के कारण सोवियत संप वियतनाम की चीन की सहायता के बिना यथेष्ट सहायता पहुँचाने में असमर्थ था।

8. सांस्कृतिक क्रान्ति—इसी दौरान चीन की अन्तरिक राजनीति में नाटकीय उपलब्धियाँ घुस गईं। यह घटनाक्रम 'महान सर्वेहारा सांस्कृतिक क्रान्ति' के नाम से मशहूर हुआ। इसमें नाओं के व्यक्तित्व के प्रति बलिहारी ढंग से समर्पित किशोर लाल रक्षकों ने निर्णायक भूमिका निभायी। लाल रक्षकों की मुख्य भाँग थी कि चीनी क्रान्ति को गुट और निरन्तर उकास पर रखा जाये। इसके लिए राजनीतिक हलचल जरूरी है, जिसके अन्तर्गत वे पार्टी बहुत आसानी से जड़ तथा नीकरखाही और उत्पीड़क-न्यून स्तरों में बदल जाती है। इन लाल रक्षकों की पट्टरस्ता, धर्मापता की सीमा खूबी थी, पर अनुसूच लगाने का साहस किसी और चीनी नेता में नहीं था। अनेक चीन विरोधों ने आरम्भ में यह बात सुनायी कि माओ का प्रयोग सिर्फ दिवाने के लिए अनुमोदन की मोहर लगाने भर के लिए किया गया, जबकि सत्ता के सूत्रों पर अमली पकड़ माओ की चौथी महत्वनाथी पत्नी जियांग जिंग और शहाई के भेपर सहित उनके दो और अनुचरों की थी, जो संयुक्त रूप से 'पञ्जाल चोफड़ी' के नाम से प्रख्यात थे। बहरहाल, सच तो जो भी रहा हो, लेकिन इसमें चाऊ एन साई जैसे 'व्यावहारिक व मध्यममार्गी नेता का चीनी राजनीति पर प्रभाव कम हुआ। 1969 से 1972 तक के दौरान किसी के लिए चीन में यह गुप्ताना आत्मघातक था कि सोवियत संघ के साथ सम्बन्धों का सामान्यीकरण किया जाये। हाँ, इस परिवर्तन का यह प्रभाव जरूर हुआ कि इस विवाद में विश्व के दूसरे देशों की सहानुभूति क्रमशः सोवियत संघ की ओर मुकने लगी। उदाहरणार्थ, लन्दन में लाल रक्षकों ने

अमरीका ने उनकी आशा के अनुसार 'पूँजी' और 'तकनीक' का हस्तान्तरण नहीं किया, वही अमरीकियों के सामने 'विराट चीनी बाजार की असलियत' अब तक खुल चुकी थी। जिस तरह 1980 के दशक के आरम्भ में सोवियत-अमरीका सम्बन्धों में सामान्यीकरण की सीमा स्पष्ट होने लगी थी, उन्ही तरह 1985-86 तक चीन-अमरीका शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व का दायरा जितना फैलना था, उतना फैल चुका था।

जहाँ तक सोवियत संघ का सवाल है, वह अब इस बात को स्वीकार करने को विवश हुआ कि पूँजीवादी अमरीकी संघे में फूट डालने या धुतपैठ करने में वह असफल रहा है। इसी तरह जापान के साथ रुस के आर्थिक व राजनयिक सहकार की आशा घूमिल हुई। इसी बीच राष्ट्रपति रीगन द्वारा प्रस्तावित अन्तरिक्ष युद्ध परियोजना ने सोवियत संघ को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि वह कम से कम एक पारस पर अपने को निरापद न रखे।

सोवियत-चीन शिखर सम्मेलन (मई, 1989)—सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाच्योव की मई, 1989 में चीन-यात्रा से इन दो साम्यवादी शक्तियों के सम्बन्धों में निश्चय ही एक नया दौर आरम्भ हुआ। गोर्बाच्योव ने अपनी यात्रा के दौरान एक्सटरना घोषणा के तहत सोवियत संघ के एसियाई भाग से 1990 में दो लाख सैनिक हटा लेने की घोषणा की। इसमें सुदूरपूर्व में चीन के साथ लगने वाली सीमा से एक लाख बीस हजार सैनिक हटाना शामिल था। उन्होंने भंगोलिया में भी भारी सैन्य कटौती की घोषणा की। इन सम्मेलन में चीन और सोवियत संघ वियतनामी सेना की वापसी (सितम्बर, 1989) के बाद प्रतिरोधी कंबोडियायी गुटों को सैनिक सहायता में कटौती करने और धीरे-धीरे सहायता बन्द करने पर सहमत हो गये। दोनों देशों के बीच विवादग्रस्त सीमा दो दशक के अन्तराल में स्वयमेव सामान्य हो चुकी है।

कम्बोडिया का मसला व हिन्द चीन में संकट (Cambodia Issue and the Crisis in Indo-China)

जिन तरह अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप ने शीत युद्ध के नए दौर की कटुता और संकट को बढ़ाया, उन्ही तरह दक्षिण-पूर्व एसिया में कम्बोडिया¹ में वियतनामी हस्तक्षेप (जनवरी, 1970) ने तनाव-सैन्यता की प्रक्रिया पर प्रतिबल डाला। इन समस्याओं को समुचित ढंग से समझने के लिए इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का मक्षिप्त सर्वेक्षण जरूरी है।

हिन्द चीन संकट की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

द्वितीय विश्व युद्ध के पहले पूरा हिन्द चीन क्षेत्र (कम्बोडिया, लाओस व वियतनाम) फ्रांसीसी उपनिवेश था। फ्रांस ने इन देशों में सर्वेधानिक विद्रोह और प्रजासत्त में स्थानीय वर्गों के योगदान को प्रोत्साहित नहीं किया। इन सभी देशों में साम्राज्यवाद-विरोधियों का मूल स्वर सशस्त्र छापागार संघर्ष वाला रहा। वियत मिन्ह नामक मुख्य स्वाधीनता सैनिक साम्यवादी लो थे, परन्तु राष्ट्रवादी नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस भू-भाग पर जापान का आधिपत्य स्थापित हो गया।

¹ मई 1989 में कम्बोडिया का नाम बदलकर कम्बोडिया कर दिया गया है।

और वैज्ञानिक क्षेत्र में आत्म-निर्भरता का हठ छोड़ दिया। चीन द्वारा अमरीका के साथ सम्बन्धों का सामाज्यीकरण अब सिर्फ राजनयिक जोड़-झोड़ नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय जरूरतों में बढ़ा गया। चीन-रूस विग्रह इस तर्क को अमरीकियों के लिए सहज रूप से पार्श्व बना चुका था। इस प्रकार दो चीजों का संयोग हुआ। जहाँ एक ओर रूस-अमरीका सम्बन्धों में तनाव-सौधिल्य की बति घोभी पड़ी, वहीं अमरीका-चीन सम्बन्धों में नई सम्भावनाएँ उजागर हुईं।

इस घटनाक्रम के बाद चीन की चार विश्व वाली परिकल्पना, निरन्तर शान्ति की माँगना, निज पिछाड़ी वाली छपायार रचना की निरपेक्षता आदि पर फिर से पुनर्विचार जरूरी हुआ। चीन-रूस दरार को सहो परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए यह आवश्यक था कि सुदूर पूर्व में कुछ और महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों पर दृष्टिपात किया जाये। जहाँ तक अमरीका के मन में चीन के प्रति आकर्षण का प्रश्न है, जापान की बढ़ती आक्रमक आर्थिक क्षमता और जानसेवा प्रतिपोगिता ने इसे महत्वपूर्ण दंग से प्रभावित किया। अमरीका जापान को बहुप्रदर्शित करना चाहता था कि उसके लिए वह अपरिहार्य नहीं है। सोवियत संघ ने अपनी राह से बढ़ती परिस्थितियों का ध्यान बढ़ाने की कोशिश की। इसी दौर में सोवियत संघ ने उन परियोजनाओं को सुझाया, जिनमें जापानी पूँजी और तकनीक की सहानता से साइबेरिया के प्राकृतिक समाधनों के दोहन की योजना की थी। यदि अमरीका सोवियत-चीन विग्रह का लाभ उठाकर सुदूर पूर्व में नया सहयोगी चुनना चाहता था तो सोवियत संघ भी जापानी वरुष खेलने का प्रयत्न कर सकता था। सोवियत संघ ने अमरीका के पश्चिमी यूरोपीय सन्धि मित्र देशों को गैर पाइप लाइन निर्माण के मुताबिक के जरिये अपनी और आकर्षित करने का प्रयत्न किया था। सरसरी निगाह से देखने पर इन सब बातों का रूस-चीन विग्रह से सीधा सम्बन्ध नहीं दीखता, परन्तु यदि दूरदर्शी विलेखन किया जाये तो यह बात सिद्धी नहीं रह सकती कि इन सब क्रियाकलापों से रूस-चीन तनाव-बढ़ाव को मनुष्यित करने का प्रयत्न हो रहा था।

चीनी और रूसी सैनिक शक्ति का दो बार अक्षरपातित प्रयोग 1978-79 में हुआ, जिनमें इस विषय को प्रभावित किया। इनमें पहली घटना अफगानिस्तान में रूसी सैनिक हस्तक्षेप की थी। सोवियत संघ की दृष्टि से उसे ऐसा करने के लिए विवश करने वाले कारणों में एक यह भी था कि सोवियत संघ के दक्षिणवर्ती मुस्लिम-बहुल प्रांतों में चीनी सह पर अनेक सशस्त्री (जैसे शोव-ए-आवेद) भड़काने-उकमाने वाली गतिविधियों में संवे थे। इस घटना के बाद दक्षिणपंथी अमरीका के अनेक समूह पुष्ट हुए। यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो गयी कि सोवियत संघ अपनी सीमा के बाहर बल प्रयोग के लिए सक्षम है और तत्पर भी। इस तरह चीन ने विद्यमान की 'सबक' मित्राने के लिए दक्षिण-पूर्व एशिया में जो अभिव्यक्त साधा, उसने सोवियत संघ की संज्ञाओं को बढ़ाया ही।

गुप्त मितानकर, इन सब बातों से न तो सोवियत-चीन सम्बन्धों की कटुता अनावश्यक रूप से बढ़ी और न ही वैयक्तिक शक्ति गमीकरण जमर लगे। विडम्बना तो यह है कि 1986 में सोवियत विदेश मंत्री के मंगोलिया के दौर के समय इस बात के स्पष्ट भ्रूकेन मिले कि सोवियत संघ चीन के साथ सम्बन्ध सुधारने के लिए उत्सुक है (उनके बीच गुप्त परामर्शों तो लम्बे अर्से से चल रहा था)।

एक ओर चीनी नेताओं के मन में इस बात को लेकर अमनोप या कि

उसके प्रभाव में पड़कर हाथ से निकल जायेंगे। इसलिए 1954 के जेनेवा सम्मेलन में जब हिन्द चीन के देशों की स्वाधीनता स्वीकार की गयी तो शीत युद्ध के सामरिक परिप्रेक्ष्य में इसका विभाजन अनिवार्य समझा गया। उत्तरी वियतनाम में साम्यवादी सरकार बनी जबकि दक्षिणी वियतनाम में अमरीका की वठ्ठुनली सरकार ने सत्ता संभाली। कम्बोडिया गुट निरपेक्ष था तो लाओस में दक्षिणपंथी, वामपंथी और गुट निरपेक्ष तत्व गृह युद्ध में संघर्षरत थे।¹

यह तो इस विवाद का सिर्फ वैचारिक व सैद्धान्तिक पहलू है। प्रारम्भ से ही हिन्द-चीन के देशों विशेषकर कम्बोडिया व वियतनाम का महत्व शीत युद्ध की भू-राजनीतिक अनिवार्यताओं के कारण महाशक्तियों के लिए ऊँची प्राथमिकता वाला रहा।

हिन्द चीन संकट और महाशक्तियाँ

1954 से 1973 तक का लम्बा अन्तराल बहू रहा, जब जेनेवा सम्मेलन को लागू न किये जाने के बाद दक्षिणी वियतनाम में हिंसक सल्तापलट, सर्वनाशक गृह युद्ध और बड़े पैमाने पर नृपम अमरीकी हस्तक्षेप एक साथ चलते रहे। 1965 के बाद इस हस्तक्षेप में तेजी आयी और वियतनामी छापामारी का मुकाबला करने के लिए अमरीका ने पड़ोसी कम्बोडिया में पुसपंठ आरम्भ की। उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम तक कुमुक पहुँचने वाली हो ची मिन्ह ट्रेल (Trail) कम्बोडिया हो कर जाती रही। इसी कारण इसे अनदेखा करने वाली सिन्हु सरकार को गिराने के बाद लोन नोल को अपने मोहरे के रूप में नोम पेन्ह (कम्बोडिया) में गद्दी पर बैठाया। परन्तु इस समय तक बात अच्छी तरह प्रकट हो चुकी थी कि अमरीका अपने सैनिक बल और आर्थिक सामर्थ्य के बाद भी वियतनामी मुक्ति सैनिक बल का मुकाबला करने में असमर्थ था। दक्षिणी वियतनामी सरकार की तरह ही कम्बोडिया में लोन नोल की सरकार भ्रष्ट, अवर्मण्य और परोपजीवी माहित हुई। वियतनाम से अमरीका की वापसी व पलायन के बाद कम्बोडिया के शान्तिवारियों ने अनुकूल परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए नोम पेन्ह पर बम्बा कर लिया। शान्तिवारियों के इस गुट का नेतृत्व खमेर रूज तबके के हाथ में था, जो माओपथी साम्यवादी थे और निकट भविष्य में ही निर्मम वठ्ठुल्ले माहित हुए।

कम्बोडिया में बवंर नरसंहार

पोल पोर्ट ने अपने छोटे से शासन काल (1975-79) में बवंर नरसंहार द्वारा नातक के माध्यम से शान्तिकारी परिवर्तनों का सूत्रपात किया और वसनाशक नाजियों की याद ताजा की। पोल पोर्ट की गतिविधियाँ चीनी सवंहारा लाल शान्ति की याद दिलाती थीं परन्तु इसका क्रियान्वयन नहीं अधिन अदूरदर्शी और हिंसक ढंग से किया गया। पोल पोर्ट द्वारा कम्बोडिया की सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था को पहुँचाये गये नुकसान का अनुमान सिर्फ इन आँकड़ों से लगाया जा सकता है कि

¹ हिन्द चीन, विशेषकर कम्बोडिया के संदर्भ में भारतीय गुट निरपेक्ष दृष्टिकोण वाले उपयोगी विश्लेषण के लिए देखें—L. M. Singh, *Power Politics in South East Asia* (Delhi, 1979), 3-38

1945 के बाद जब फ्रांस ने बताया अपने उपनिवेश (वियतनाम) पर फिर से कब्जा करना चाहा तो छापामारों ने उसका विरोध किया। राष्ट्रवादी सामन्तवादियों को यह सड़ाई मूलतः उपनिवेश व साम्राज्यवाद विरोधी थी। जंगल हो बी मिन्ह व जनरल शियाव के नेतृत्व में अपनायो गयी छापामार रणनीति वैद्व सफल रही। 1954 तक वियेतकर दियेन वियेन फू के युद्ध तक यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि फ्रांस इस भू-भाग पर पुनः अपना अधिकार नहीं जमा सकेगा। इस समय तक शीत युद्ध का ज्वार उफान पर था और तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री डेनेस जैसे लोग डोमिनो सिद्धान्त का प्रतिपादन कर चुके थे। इस सिद्धान्त के अनुसार यदि कोई भी एक तबोदित राष्ट्र साम्यवादियों के प्रभाव में आता है तो छेय के अन्य देश भी साथ-साथ



हिन्द-चीन के सन्दर्भ में कम्बोदिया संकट

की प्रतिविबिधी विदेशी अमरीका महापता क बिना संचालित नहीं की जा सकती। साइरैण्ड में उपस्थानिया क लिए जा शिविर स्थापित किए गए हैं, इनकी सामरिक उपस्थानिया विपन्नता विरोधी हस्तक्षेपकारी बाह्य प्रतिष्ठों क लिए बनी हुई है।

कम्बोडिया समस्या क हल के कितने आधार—मई, 1989 में कम्बोडिया क पटनाक्रम न नया मोड़ दिया। कम्बोडिया का कम्युनिस्ट सरकार क प्रधानमंत्री हुनसेन और भुवनेश्वर राष्ट्राध्यक्ष राजकुमार नरसिम मिहानुक इण्डोनेशिया की राजधानी जकार्ता में मिले। दोनों नेताओं के बीच कई बातों पर महमति हुई, जिन्हें दसहरे निकट अविष्य में कम्बोडिया से विपन्नता की समाप्ति क हटान और जनताधिकारी तरीके से चुनी गयी सरकार द्वारा सत्ता सौंपने की योजना बनवती हुई। जकार्ता बैठक में तय किया गया कि मिहानुक राष्ट्राध्यक्ष बनाय जायेंगे और हुनसेन प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे। गासन क नये दावे में प्रतिरोधी सांस्कृतिक कम्बोडिया सरकार क लक्ष्य गुट क प्रतिनिधि मान मान और लक्ष्य क्षेत्र क सीधे साम साम समुक्त रूप से उपस्थिति है।

विपन्नता पहलू हा पायला कर चुका था कि वह मितम्बर, 1989 तक कम्बोडिया से अपनी समाप्ति होगा तथा। उधर मई, 1989 में सावित्र नया साक्षात्कार की चीन-यात्रा के दौरान कम्युनिस्ट चीन विपन्नता की समाप्ति के बाद कम्बोडियाई गुणों का सैनिक दृष्टिकोण में कटोरी करने और चीन और महापता बन्द करने पर महमति हुई। इस बीच विपन्नता में अपनी पायला क अनुसार निधारित विधि से पूर्व कम्बोडिया से अपनी समाप्ति सैनिक दृष्टिकोण साधन बुला गी। इन सभी आशा-प्रसन्न पायलाओं के बावजूद यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगा कि कम्बोडिया समस्या का हल अल्पकालिक है। कम्बोडिया के प्रतिरोधी गुण और कम्युनिस्ट सरकार के बीच अल्पकालिक मुनह और शांति-स्थापना के माध्यम से कई व्यावहारिक अडचन नष्ट होंगे, जिन्हें दूर करना आसान काम नहीं होगा। इसके अलावा अमरीका और चीन मुनह-शांति प्रक्रिया में अपने अपने हित साधन के लिए अडचनों से बाध माने जाने लगे।

हाल में कुछ आकाशिक सकेत दमन का मित है। कम्बोडिया के प्रधानमंत्री हुनसेन की चीन-यात्रा से मुकट-समाधान के आसार मजबूत माने जाते हैं। उधर अन्तराष्ट्रीय मंच पर सावित्र मंच के पल्लू हा जाने के कारण अमरीका राजनय पहल से कहा जायिक प्रभावगता हुआ है। इन बीच निरन्तर तकरार रहने के बावजूद राष्ट्रीय मंच विश्व का स्थिति बनी हुई है। आनिधान-दलों ने कम्बोडिया और विपन्नता के साथ सम्बन्ध में मुधार की प्राथमिकता बढ़ायी है और नुनक मिहानुक राजकुमार मिहानुक व्यावहारिक समझौते के लिए राजी हुए हैं। मनवत अब यह निर्णय दूर हो सका।

कम्बोडिया विवाद व भाग्य

भारत के लिए कम्बोडिया विवाद और हिन्दू धर्म में मुकट राजनयिक व सामरिक महत्व के विषय बने हुए हैं। गुट निरपेक्ष दलों के हवाला दिखाने सम्मेलन में तकरार अब तक कम्बोडिया का मोट माना गया है। यही स्थिति समुक्त राष्ट्र मंच में है, जहाँ मिष्ट सावित्र बाटा पान-यात्रा का महत्व दिखाने में सक्षम रहा। विपन्नता हस्तक्षेप का विरोध न करने वाला म भारत अथवा अन्य निरपेक्ष व

चार-पाँच वर्षों में कम्बोडिया की कुल आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा मार डाला गया, नागरिक जीवन ध्वस्त हो गया और बाहरी दुनिया के साथ (चीन को छोड़कर) सम्बन्ध टूट गये।

वियतनाम-कम्बोडिया तनाव के कारण

कम्बोडिया और वियतनाम के बीच कटुता के लिए सिर्फ राजनीतिक व सैद्धान्तिक ही नहीं, बल्कि जातीय पक्ष भी महत्वपूर्ण है। हिन्द-चीन के हजारों वर्ष पुराने इतिहास में वियतनामी और खमेर (कम्बोडियाई) एक-दूसरे के जानलेवा दुश्मन रहे हैं। एक के साम्राज्य का विस्तार दूसरे की कीमत पर हुआ है। खमेर विस्तारवाद का मुकद्दाम थाईलैण्ड भी उठाता रहा है। अर्थात् वियतनामी, कम्बोडियाई, लाओस और थाई सरकारों का प्रयत्न औपनिवेशिक और युद्धोत्तर काल में यही रहा है कि वे बाहरी अन्तर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप के द्वारा आपसी असन्तुलन को दूर कर सकें। जनवरी, 1979 में वियतनाम की सैनिक मदद से कम्बोडिया की राजधानी नाम पेंह में हंग सामरिन सरकार का कब्जा हो गया।

वियतनाम कम्बोडिया में पोल पोट की सरकार को स्वच्छन्द आचरण के लिए नहीं छोड़ सकता था। ज़ेनिन यह तर्क दिया जा सकता है पोल पोट सरकार का बनना या गिरना कम्बोडिया का आन्तरिक राजनीतिक मामला था, जिसमें वियतनामी हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश न थी। परन्तु इस ओर भी आँख नहीं मूँदी जा सकती कि पोल पोट द्वारा भत्ता ग्रहण करने के बाद कम्बोडियाई भूमि में वियतनाम को उकसाने-मड़काने वाली सैनिक गतिविधियाँ जोर पकड़ने लगी थी। इस बीच वियतनाम व चीन के बीच टकराव सतह पर आ चुका था। वियतनामी सरकार का यह मोहना गलत नहीं था कि घुमपैठ और तोड़फोड़ द्वारा उसकी राष्ट्रीय एकात्मता को कमजोर करने वाला यह पड़्यन्त्र एक घातक मकद था। चीन और वियतनाम के बीच भीमा विवाद विस्फोटक रूप ले चुका था, जिसकी परिणति फरवरी, 1979 में सैनिक मुठभेड़ में हुई। चीन का प्रमुख सामरिक उद्देश्य वियतनाम को परीत रूप में नियन्त्रण में रखने का था। पोल पोट की क्रूर नीतियों ने बहुसंख्यक कम्बोडियाई जनता को विद्रोह के मयार पर ला खड़ा किया था। इस प्रकार वियतनाम-कम्बोडिया संघर्ष अब अफगान समस्या में एक बड़ा मामू और एक बड़ा फर्क देने को मिलता है। दोनों बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप अकारण नहीं था। परन्तु कम्बोडियाई जनता का राजनीतिक चैतन्य, सैनिक प्रतिरोध का उभरा सत्कार, हस्तक्षेपकारियों के सैद्धान्तिक मामू और इसके साथ ही जातीय वैमनस्य सुलनीय नहीं है।

कम्बोडिया में वियतनामी हस्तक्षेप को लेकर जो अटकलें लगायी जाती रही हैं, वे ग़रनीकरणों से ग्रस्त हैं। कई लोगों का मानना है कि जिस तरह अफगानिस्तान मोर्चित मूष का वियतनाम बन सकता है, उसी तरह कम्बोडिया 'वियतनाम का वियतनाम' बन सकता है। हालाँकि वियतनाम को बड़े पैमाने पर कम्बोडिया में अपने सैनिक सैन्य स्तरीय करने की कमरतोड़ कीमत चुकानी पड़ी और उगका अपना आर्थिक विनाश गढ़वड़ा गया। फिर भी कम्बोडिया सरकार के सामने निहानुक, मोनमान या पोल पोट के पक्षधर मुक्ति सैनिकों या उनके मयुक्त मोर्चे का कोई सतरा (सैनिक या राजनीतिक) नहीं है। अफगान मुजाहिदीनों की तरह इन अमनुष्ट तत्वों

दी है कि कैसे कभी-कभी बिल्कुल अप्रत्याशित ढंग से अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम नया तेल सफट पैदा कर सकता है। इराक द्वारा कुवैत पर हमले और अमरीका व मित्र राष्ट्रों द्वारा इराक में सैनिक हस्तक्षेप के बाद सभी तेल आयातक देश नये सिले स सकटग्रस्त हो गये। पश्चिम एशिया की विस्फोटक स्थिति को देखते हुए तेल की तयों और महँगाई फिर कभी भी सिरदर्द बन सकती है।

तेल सफट की शुरुआत—अन्तर्राष्ट्रीय तेल सफट 1973 के अरब-इजराईल युद्ध से शुरू हुआ। अमरीका, पश्चिम यूरोपीय देश और जापान इस युद्ध में इजराईल का साथ दे रहे थे। ऐसे में सऊदी अरब के तत्कालीन तेल मन्त्री शेख यामनी ने पश्चिमी देशों का जापान पर दबाव डालने की एक योजना पेश की। इसी योजना के तहत ओपेक (Organization of Petroleum Exporting Countries or OPEC) नामक संगठन बनाया गया। इस संगठन में 13 देश हैं—सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, अलजीरिया, लीबिया, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया, वेनेजुएला, इण्डोनेशिया, गेबन और इक्वाडोर।

1973 में ओपेक ने सर्वप्रथम इजराईल के हिमायती देशों (अमरीका, पश्चिम यूरोप व जापान) को होने वाले तेल निर्यात पर पाबन्दी लगा दी। फिर उन पर इजराईल पर लगान रखने के लिए दबाव डाला। हालांकि उन्होंने 1973 में ही तेल आपूर्ति पर उक्त रोक हटा दी, किन्तु तेल का भाव दो डालर से बढ़ाकर आठ डालर प्रति बैरल कर दिया। दिसम्बर, 1981 में तेल की अधिकृत कीमत 34 डालर प्रति बैरल की ऊँचाई पर पहुँच गयी (परन्तु मुक्त अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में यह कहीं-कहीं 40 डालर प्रति बैरल तक के आसपास भी बिक रहा था)। इसका पीछे कोई सयोग नहीं, बरन् ओपेक की मुनिपोजित कार्याप्रणाली और सदस्य देशों में एकरा थी। लेकिन 1982 से तेल के दाम लगातार घटने शुरू हो गये।

तेल के दाम गिरने के कारण—तेल के दामों में भारी कमी के लिए अनेक कारण जिम्मेदार रहे थे। ओपेक ने जब 1973-79 के दौरान भाव में घडाघडा वृद्धि की तो कई तेल आयातक पश्चिमी और बिकासशील राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था चरमरान लगी थी। परिणामस्वरूप तेल आयातक देशों ने 'ऊर्जा बचाओ अभियान' शुरू किया, जिसमें वे एक हद तक सफल रहे। फ्रांस, जापान, पश्चिम जर्मनी आदि ने तो अपनी खपत में भारी कमी की। मगर ओपेक की सबसे बड़ा झटका पैर-ओपेक देशों के तेल-उत्पादन में वृद्धि से लगा है। ब्रिटेन, नार्वे, मैक्सिको में तेल के नवीन स्रोतों की खोज हुई और उन्होंने भारी मात्रा में तेल निकालकर विदेश बाजार में पहुँचा दिया। इससे जहाँ आपस देशों का तेल के बारे में एकाधिकार टूटा, वहीं बाग की तुलना में मज्झाई ज्यादा होने से इनके दाम गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। 1979 में ओपेक देश विश्व का 60 प्रतिशत तेल (310 करोड़ बैरल प्रतिदिन) का उत्पादन करते थे, जो अब गिरकर 39 प्रतिशत (170 करोड़ बैरल प्रतिदिन) रह गया है। जबकि 1979 में गैर ओपेक देश 210 करोड़ बैरल तेल प्रतिदिन उत्पादन करते थे, जो अब बढ़कर 264 करोड़ बैरल प्रतिदिन हो गया है। जो तेल के दाम कम करने में योग्यत सघ की जो भूमिका कम नहीं रही। वह पिछले कुछ वर्षों से 'हाई' विदेशी मुद्रा अर्जन करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेल बेचता रहा था। इसी प्रकार रोनल्ड रीगन व सत्ता में आने के बाद अमरीका ने भी भारी मात्रा में युव विश्व बाजार में तेल बेचा, जबकि इसने पूर्व वह अपने तेल-मण्डार खाली न करने की

गैर-समाजवादी देश है। भारत को अफगान संकट की तरह इस सन्दर्भ में भी सोवियत संघ के साथ 'विशेष सम्बन्धों' की एक गैर जरूरी कीमत चुकानी पड़ी है। इस सिलसिले में यह याद रखने की जरूरत है कि भारत और वर्तमान वियतनाम के विश्व-दर्शन में व्यापक सहयोग है, चाहे वह चीन के साथ विश्व हो या हिन्द महासागर में महाशक्तियों की उपस्थिति-जनित संकट। वियतनाम ने आर्थिक विकास का जो रास्ता चुना है, वह भी भारत के नियोजित विकास व बहुमुखी ग्रामीण विकास वाली रणनीति से मेल खाता है। सिंगापुर, इण्डोनेशिया, मलयेशिया और थाईलैण्ड जैसे देशों के आर्थिक व सामरिक नजरिये में भारत के साथ 'सहकार' की भूमिका कभी भी महत्वपूर्ण नहीं रही। इन देशों ने पिछले 20-25 वर्षों में अमेरिका, यूरोप और जापान के साथ जो रिश्ते जोड़े हैं, उनमें किसी दुनिपादो परिवर्तन की आशा नहीं की जा सकती। इसलिए यह सुझाना उचित होगा कि राष्ट्रीय हितों के व्यापक सहयोग के कारण भारत और वियतनाम के बीच राजनयिक समायोजन सहज हुआ है।

विश्व तेल संकट व भारत (World Oil Crisis and India)

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में खनिज तेल के दाम पिछले कुछ वर्षों के दौरान अप्रत्याशित रूप में बढ़े हैं। जो कच्चा तेल 1973 में लगभग दो डॉलर प्रति बैरल से घिबता था, वह 1981 में न्यूवी छला में मारता हुआ 34 डॉलर प्रति बैरल (17 गुना बढ़ि) तक जा पहुँचा। तत्पश्चात् इसके भाव में गिरावट का दौर आरम्भ हुआ। तेल निर्यातक पश्चिम एशियाई देशों द्वारा तेल उत्पादन के कोटे में कमी और अधिकृत दाम निर्धारित करने के वावजूद मंदी का खिलखिला नहीं घमा। 1986 में तो तेल के दाम अप्रत्याशित रूप से गिरे। जनवरी, 1986 में इसकी कीमत 25 डॉलर प्रति बैरल थी, जो अप्रैल में 14 डॉलर तक गिर बयी। हालाँकि अब इसका मान 18 से 21 डॉलर प्रति बैरल के आसपास है, फिर भी इसे 'मारी मंदी' की संज्ञा दी जा सकती है।

भाव में इस भारी गिरावट से जहाँ एक ओर तेल-निर्यातक देशों की आय काफी घटी है और उनके वहाँ अनेक निर्माण व विकास कार्य ठप्प हो गये हैं, वही दूसरी तरफ तेल-आपातक राष्ट्रों को इससे फायदा पहुँच रहा है। तेल निर्यातक राष्ट्र तो इस मंदी से दुःखी ही है, लेकिन भारत जैसे तेल आयातक विकासशील राष्ट्रों को लाभ पहुँचाने के साथ-साथ उनके सामने नये जटिल ढंग की स्थिति भी पैदा हुई है। आयातक राष्ट्रों के समक्ष यह तबाल उठ खड़ा हुआ है कि मंदी के मौजूदा दौर में क्या वे भारी मात्रा में हाजिर भाव पर तेल खरीद लें या भाव और घटने का इन्तजार करें? यह प्रश्न भी कम महत्वपूर्ण नहीं कि तेल क्षेत्रों की खोज, वियतनाम और उत्पादन पर किये जा रहे प्रयासों को क्या वे कम कर दें या छोड़ दें, क्योंकि सस्ते दाम पर अन्यत्र तेल उपलब्ध है (अतएव ऊँची लागत पर घरेलू उत्पादन करने से क्या फायदा?)। मगर इस बात की क्या गारन्टी है कि इसके दाम भविष्य में फिर जोरदार तेजी नहीं पकड़ेंगे? तब क्या तेल संकट उनके लिए पुनः विस्फोटक स्थिति पैदा नहीं कर देगा?

कबले मामले पर छिड़े खाड़ी युद्ध 1991 ने एक बार फिर यह बान धनका

गेर ओपक देगा म तल उत्पादन पर लागत अपभावित ज्यादा जाता है, जिसमें उन्हें मुनाफा कैसे मिलेगा ? अतएव ब्रिटेन, नार्वे आदि दाम को 18-20 डॉलर प्रति बैरल तक रखने का पूरा प्रयास करेंगे । दाम काफी नीचे गिरने पर उन अमरीकी कम्पनियों और बैंकों का क्या होगा, जिन्होंने ओपक राष्ट्रीय म विमान पूंजी लगा रखी है ? एस में क्या अमरीका दाम एक हद से ज्यादा नीचे गिरने देगा ?

भारत व तेल संकट—बव मवाल उठना है कि भारत जैसा तेल-आयातक विकसमानेला राष्ट्र क्या करे जा पिछली तेली के दौरान अपना 75 प्रतिशत विदेशी मुद्रा तेल आयात पर खर्च करता रहा था और इस विकट मुद्दे को देखते हुए जिसमें नये तेल क्षेत्रों की खोज, विकास और उत्पादन पर भारी मात्रा में समावेश लगाना शुरू कर दिया था । इसमें कोई सन्देह नहीं कि कम दाम में आयातक राष्ट्रीय की काफी विदेशी मुद्रा बचती, औद्योगिक विकास का बड़ा मित्रगा और भुगतान संतुलन की स्थिति सुधरती । मगर इस तथ्य का नजरअन्दाज नहीं किया जाना चाहिए कि कम दाम से जहाँ एक ओर तेल की खपत बढ़ती वहीं दूसरी तरफ तेल बचन अभियान और ऊर्जा व अन्य वैकल्पिक स्रोतों का विकास की योजनाओं को धक्का लगाता । आज तेल कर्षों में खासकर ब्रिटेन, नार्वे आदि देशों में तेल भण्डार कम हान गये और उत्पादन घट जायगा । सम्भव है कि यह स्थिति 1990 या 1995 तक पैदा हो जाय और तेल का मूल्य फिर जोरदार तेजी पकड़ लें । एस में भारत जैसा तेल आयातक राष्ट्रीय का कौन-सा मांग अपनाता चाहिए ? इस मवाल का जवाब का लिए कतिपय बुनियादी बातों का मूनामा करना जरूरी है ।

तेल संकट का भारतीय व्यवस्था पर कुप्रभाव—अरब इजराइल युद्ध (1973) का पूरा अन्तराष्ट्रीय बाजार में तेल मस्ता था । पर्याप्त धरनु उत्पादन का अभाव में भारत इसका आयात करना था । तबसे इस युद्ध का बाद तेल का दाम ज्यादा ज्यादा बढ़ने लगे । तबसे-तबसे भारत का आर्थिक मजबूती भी बढ़ना गया । अरब देशों का पारम्परिक एवं घनिष्ठ दाल होने का नाते भारत उनकी कटु आलोचना का नही कर सकता था । क्योंकि दाम में इस वृद्धि का निगाना इजराइल समर्थक सामर्य पश्चिमी विकसित देश थे । मगर इस वृद्धि का भारत पर इतना प्रतिकूल असर पड़ रहा था कि उसकी 75 प्रतिशत ब्रिटेन बड़ी मूल्यवान विदेशी मुद्रा मिक तेल का आयात पर स्वाहा हान गया । उसकी भुगतान संतुलन की स्थिति बदतर होती गयी और उच्च औद्योगिकी मशीनें, उपकरण आदि का आयात में समक सामने अनक दिक्कत पैदा हो गई । कई परियोजनाओं को मँहूँगे तेल का कारण बंद होना पड़ा ।

भारत में धरनु तेल-उत्पादन व विदेश से आयात—एस में भारत का मसला एक ही विकल था कि वह अपने यहाँ नए तेल क्षेत्रों की खोज कर और धरनु उत्पादन बढ़ाकर पुनर्जीवी का नामना कर । इस रास्ते पर चलते हुए नए तेल क्षेत्रों की महान मात्रा मुक्त हुई और 1974 में बम्बई हाई में बटन बहा तेल भण्डार हाथ लगा । या इसमें पहले और बाद में भी विभिन्न स्थानों पर छान-छान तेल भण्डार । 1950-51 में भारत का धरनु तेल उत्पादन मात्र 2.5 लाख टन था, जो ठाम प्रयोगों का कारण 1981-82 में बढ़कर 1.62 करोड़ टन तक आ पहुँचा । फिर भी 1981-82 में 5000 करोड़ रु० मूल्य का 2.01 करोड़ टन तेल का आयात करना पड़ा । इस प्रकार जहाँ एक ओर धरनु तेल उत्पादन बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ जनवरी 1982 में तेल का दाम घटने शुरू हो गया । भाव में यह कभी आपक

नीति अपनाकर दूसरे देशों से तेल खरीदता रहा था।

इसके अतिरिक्त 1973 से ही पश्चिमी देशों ने तेल के अलावा अन्य ऊर्जा स्रोतों की खोज के ठोस प्रयास शुरू कर दिये। उन्होंने कुछ क्षेत्रों में परमाणु ऊर्जा को अंगीकार किया। कुछ मामलों में उन्होंने तेल की जगह कोयले से काम चलाया। इस प्रकार, इन सब कारणों ने तेल के आसमान छूते भावों को थामा ही नहीं, बल्कि उन्हें उतार की ओर मोड़ दिया।

कीमत में स्थायित्व का प्रयास—1982 से जब तेल के भाव घटने लगे तो ओपेक ने उत्पादन घटाकर कीमतों में स्थायित्व लाने की कोशिश की। उसने समय-समय पर सदस्य-देशों को उत्पादन घटाने को कहा और उत्पादन कोटा तथा अधिकृत दाम तय किये। इसका कुछ समय तक तो पालन हुआ, परन्तु बाद में कई राष्ट्र चोरी छिपे निश्चित कोटे से ज्यादा तेल का उत्पादन करने और अधिकृत से भी कम कीमत तथा रियायतों के साथ तेल बेचने लगे। इसी फूट को देखते हुए ओपेक की जेनेवा-वैंठको में सदस्य देशों ने कहा कि उत्पादन-कोटा बाँधकर कीमतों में स्थायित्व नहीं लाया जा सकता। यह मान लिया गया है कि विद्यमान ओपेक का तेल निर्यात हिस्सा बढ़ाया जाये, भले ही दामों में भारी कमी और उत्पादन में घृष्टि करनी पड़े।

तेल के कम दाम से किसको लाभ, किसको नुकसान—दाम कम होने से कई तेल आयातक औद्योगिक और विकासशील राष्ट्रों को लाभ पहुँच रहा है, क्योंकि इससे उनके उत्पादन की बल मिलेगा, लागत कम जायेगी और वे व्यापार बढ़ा सकेंगे। परन्तु कीमतों में कमी से ओपेक को भारी हानि उठानी पड़ रही है क्योंकि उनकी आय का प्रमुख स्रोत तेल है। दाम में थोड़ा-कमी भी उनकी आय वैसे भी सिक्कड़ गयी है। कई देशों में घाटे का बजट चल रहा है और अनेक विकास कार्य धन के अभाव में ठप्प पड़े हैं। उनमें कुछ वर्षों पूर्व करोड़ों-अरबों डॉलर की लागत वाली शुरू की गयी विकास योजनाओं के लिए भी भारी खतरा पैदा हो गया है। एक अनुमान के अनुसार यदि तेल का भाव एक डॉलर प्रति बैरल घटा तो ओपेक को सालाना छह अरब डॉलर की हानि होगी। नाइजीरिया पर 22 अरब डॉलर का विदेशी ऋण है, उसे वह कैसे चुकायेगा?

यहाँ यह सवाल उठता स्वभाविक है कि भाव में कमी से क्या गैर-ओपेक तेल उत्पादक देश नुकसान नहीं उठावेंगे? विदेश दाम में कमी को बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था तेल के निर्यात से होने वाली आय पर निर्भर नहीं है। तेल से उसे निर्यात आय का मात्र आठ प्रतिशत राजस्व मिलता है। नाबो और सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था भी तेल की आय पर निर्भर नहीं रही। मगर मैक्सिको तेल की आय पर अत्यधिक निर्भर है और उस पर 96 अरब डॉलर जितना बड़ा विदेशी कर्ज है, जो उसे अभी चुका रहा है। दाम एक डॉलर प्रति बैरल कम होने पर मैक्सिको को 55 करोड़ डॉलर का सालाना घाटा होगा। अर्थात् भाव में कमी मैक्सिको की अर्थव्यवस्था को चौपट कर देगी।

कुछ विद्वानों का यह मानना एक हद तक सही है कि कीमत में कमी को मार न सिर्फ ओपेक देशों पर पड़ेगी, बल्कि गैर-ओपेक तेल उत्पादक देश भी इसके कुप्रभाव से बच नहीं सकते। यदि दाम 15 डॉलर प्रति बैरल से भी नीचे रहते हैं तो ओपेक देश फिर भी लागत से काफी ज्यादा कीमत पर तेल बेचेंगे, परन्तु

भारत की भावी तेल नीति उत्पादन व आयात में समुत्पन्न अरुणो—वर्तमान, व दूरगामी परिणाम भारत को भुगतने ही पड़ेंगे। तबले यहाँ यह मुख्य प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इन पचीस परिस्थितियों में देश की भावी तेल नीति क्या हो ? इसके लिए दो रास्ते हैं। एक तो यह कि घरेलू तेल उत्पादन काफी कम कर दिया जाये और ग्लोबल विश्व बाजार में नए तेल के स्रोतों का बड़ी मात्रा में खरीद लिया जाय। इससे हम अपने भण्डार सुरक्षित रख सकेंगे और ऊँचे भाव वाले तेल का उपयोग कर सकेंगे। दूसरा रास्ता यह है कि घरेलू तेल उत्पादन और आयात के बीच समुत्पन्न कायम रखा जाय। अर्थात् घरेलू उत्पादन पर जोर दिया जाय और अरुणो के मात्राविक आयात को हटा दिया जाय।

पहला रास्ता अपनायें के कुछ फायदे अरुण हैं मगर उसका दीर्घकालिक तोर पर बुरा असर पड़ेगा। भारत तेल के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है जिस कारण तेल सत्रा की खोज, खुदाई तेल-उत्पादन के बारे में अन्वेषण (Research) आदि चल रहे हैं उनका गति धीमी पड़ जायेगी। इस क्षेत्र में कार्यरत तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और आपल इण्डिया लिमिटेड नामक प्रतिष्ठान का भी विस्तार रुक जायेगा। यही नहीं, तेल के विनियमन के रूप में मीट व परमाणु ऊर्जा के विकास और परमाणु ऊर्जा बचत विनियमन जैसे कार्यक्रमों का गहरा प्रभाव लगने के तथ्य को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता। फिर यह बात अरुणो नहीं कि तेल में मौजूदा भंडारों की स्थिति तोर पर खराब है। यदि कुछ वर्षों बाद इसके भंडारों में फिर तबली पड़ेगी तो 1973 जैसा ही विप्लव हमारे सामने पैदा हो सकता है। वर्तमान में समझें तेल की खोज पर यह खर्च हमें नहीं हानी चाहिए कि हम तेल सत्रा में उबर चुके हैं। हम पहले जितने सत्राप्त नहीं रहे, तबले सत्रा के काँची छाना अभी पूरी तरह मिटी नहीं है। अतएव घरेलू तेल उत्पादन व आयात में समुत्पन्न कायम रखा जाय अपनायें हो अत्यन्त ही आवश्यक होगा।

इस सदन में यह बात गठ बाधन साधक है कि तबली में तेल के मुद्रा के बाद तेल की अन्तराष्ट्रीय कीमतेँ तब करना आसकर विवादों का विषयाधिकार नहीं रहे गया है। अरुणो महाशक्ति अमराका आर्थिक विकास में देशों तक पहुँचने के तब का मात्रा और उनकी कायम वस्तु में तब करने की स्थिति में है। पिछले वर्षों में यह हाँवा रहा है कि अपने कायम सत्रा से मुक्त करने के लिए भारत के तब का आयात मोविमन मध्य या इराक जैसा देश से करना रहा था। आज इस बात की काई सम्भावना गैर नहीं कि इस मामले में ये देशों भारत की कुछ महाशक्ति कर सकें। इसके अतिरिक्त स्वयं भारत में तेल के अन्वेषण का काम धीमा पड़ा है। कभी तब और प्राकृतिक गैस आयोग के दीर्घस्थायी अधिकाधिकारी की नियुक्तियों के राजनयिकरण में इन कामों का प्रभावित किया है ता कभी अन्त में कदमों में जातकवाद गतिविधियों में इन कामों में बाधा डाली है। साथ ही भारत का विदेशी मुद्रा भंडार खराब होने से अपना अरुणो भर का तब का आयात मुश्किल हो गया है। पिछले दस-दो वर्षों में भारतीय राजनयिक और आर्थिक जीवन में बिना तब का अनुमान नहीं रहे गया है। इस कारण तब के तब अरुणो तब में कोई कमी नहीं की जा सकती। आज बात दिना में भारत के लिए तब सत्रा एक कठिन चुनौती बन सकता है।

देशों में आपसी घूट, गैर-ओपेक देशों (ब्रिटेन, नार्वे, मैक्सिको, सोवियत संघ) द्वारा तेल उत्पादन में वृद्धि, तेल के अन्य स्रोतों की खोज, पश्चिमी देशों में ऊर्जा बचत अभियान, ईरान-इराक युद्ध आदि कारणों से हो रही थी। 1986 में तो भाव तेजी से घिरे।

मोजूदा तेल खपत व जरूरत—अब जरा भारत की मौजूदा तेल आवश्यकता, घरेलू उत्पादन, आयात पर विदेशी मुद्रा का खर्च और घटते दामों के कारण होने वाली बचत का जायजा लिया जाये। 1985-86 में देश में 4.80 करोड़ टन कच्चे तेल एवं पेट्रोलियम उत्पादों की खपत हुई। घरेलू उत्पादन इसका लगभग 70 प्रतिशत अर्थात् तीन करोड़ टन रहा। अतः देश 1.80 करोड़ टन तेल आयात किया गया। भारत ने 1984-85 में 1.70 करोड़ टन तेल का आयात किया था। 1984-85 में तेल का औसत आयात भाव 28 डॉलर प्रति बैरल पड़ा। 1984-85 में भारत के 4500 करोड़ रु० ही खर्च हुए, अर्थात् तेल आयात में 1500 करोड़ रु० जितनी विदेशी मुद्रा की बचत हुई। सरकार ने मंदी के कारण पारम्परिक सप्ताहवारी से तेल-आयात के बारे में कोई मियादी सौदे (term contracts) नहीं किये। इस बीच सरकार ने फरवरी, 1987 में देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में जो वृद्धि की थी, उससे उनकी खपत में कोई कमी नहीं आयी। कुर्बत के मसले पर छिड़े राबी युद्ध (1991) के बाद भी भारत में पेट्रोल के दाम में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गयी। एक अनुमान के अनुसार तेल की 8 प्रतिशत सालाना खपत बढ़ रही है।

दाम घिरने से भारत को लाभ—बहरहाल, तेल के दाम में गिरावट से भारत को अनेक सीधे आर्थिक फायदे हैं। इससे न केवल विदेशी मुद्रा की बचत होगी और भुगतान-संतुलन की स्थिति में तेजी से सुधार होगा, बल्कि उर्ध्वरक और पेट्रो-कैमिकल्स के आयात पर भी कम खर्च होगा, पेट्रोलियम उत्पादों के जरिये निमित्त होने वाली अनेक वस्तुओं पर लागत कम आयेगी और कृषि उत्पादन बढ़ेगा। विदेशी मुद्रा में बचत की राशि से विदेशी उच्च प्रौद्योगिकी का आयात किया जा सकेगा और औद्योगिक विकास की ओर घरेलू संसाधनों को सगाया जा सकेगा।

दाम घिरने से भारत पर बुरा असर भी—मगर, तेल के भाव में कमी से होने वाले फायदे एक सीमा तक ही लाभकारी होंगे। सबसे भारतीय ओपेक देशों में गोरूरी कर रहे हैं, लेकिन अब तेल से जाने वाली अपार राशि कम हो रही है, जिसका प्रतिकूल असर इन भारतीयों की आमदनी पर पड़ेगा। ये भारतीय बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा स्वदेश भेजते रहे हैं। तेल में मंदी के कारण कई भारतीय रोजगार से हाथ धोकर स्वदेश लौट रहे हैं। दूसरी बात, भारत को अनेक ओपेक-देशों में पॉल सितारा होटल, पुल, रेलवे-साइन, हवाई अड्डे, जैसी इमारतें बनाने का ठेका मिला हुआ था, लेकिन अब धन के अभाव में ऐसी जगह परियोजनाएँ ठप्प पड़ने की संभावना है। भारत के लिए यह बहुत बड़ी हानि भिड़ होगी। खाड़ी युद्ध के बाद इराक में तो भारत के बहुत सारे ठेके एकदम ठप्प पड़े हुए हैं। तीसरी बात, ओपेक देश अपार दौलत के नूतों पर भारत में आत्मांनी से जो पूँजी निवेश करते थे और दोनों मिलकर अन्य देशों में संयुक्त उद्यम खोलते थे, उस सिलसिले को भी गहरा धक्का लगेगा। यह भी किमी से छिपा हुआ नहीं है कि ओपेक देश भारत को मदद व ऋण देते हैं, जिनमें कभी आये तो कोई आश्चर्य नहीं होगा।

गतिविधियाँ उच्छृंखल, अन्यायपूर्ण तथा सामरिक ही नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए भी मंचालित हो सकती हैं। तथ्यभग इसी समय अमरीका द्वारा उत्तर वियतनाम में की जा रही बमबारी ने भी लोगों का ध्यान इस समस्या की ओर खींचा।

आतंकवाद की समस्या का एक और पक्ष है। यह जरूरी नहीं कि इसका लक्ष्य हमेशा शत्रु ही हो। अक्सर मित्रों को भी इसकी चपेट में आना पड़ता है। जब अनेक फ़िलिस्तीनियों को यह लगने लगा कि 1973 के बाद बढ़ती परिस्थिति में अनेक अरब विरादर उनकी वांछित महारक़्त नहीं कर रहे हैं तो उन्होंने यथास्थिति के पोषक अरब शासकों को अपने आतंक व घेरे में लाने का प्रयत्न किया। जब पेरिस में ओपेक के तेल मन्त्रियों का सम्मेलन चल रहा था तब मऊदी प्रतिनिधि शेख अल यमनी समेत उन सभी को बंधक बनाया गया। यह स्वाभाविक था कि अनेक अरब राज्य फ़िलिस्तीनियों को शरण देने के फलस्वरूप इजराईल का बोप भोजन नहीं बनना चाहते थे और बिना उन्हीं आतंकिन किये उनसे शरण या सहायता पाना सहज नहीं था। परन्तु इस तरह का मयादोहन हमना ही सफल हो, यह आवश्यक नहीं। ज़ोहैन के शासक हुसैन ने व्यापक नरसंहार का जवाबी हमले वाला रास्ता अपनाया और लेबनान में फ़िलिस्तीनियों की बढ़ती अलौकप्रियता इसी से जन्मी।

अमरीका व पश्चिमी यूरोप में आतंकवाद—जिस समय पश्चिम एशिया में मानकवादी मर उठा रहे थे, उस समय समार के अन्य भागों में भी वह प्रवृत्ति तीव्रतर हो रही थी। उदाहरणार्थ, अमरीकी महाद्वीप में दक्षिणी अमरीका के उरग्वे देश में टोपामरो नामक नागरिक छापामार प्रभावशाली बल से सक्रिय थे। अमरीका में भी विलामितापूर्ण उपभोग से ऊबे, कुठिन, अपन्तुष्ट युवा वर्ग में हिंसक अराजकता लोकप्रिय हो रही थी और एक क्षम तन्हू की आतंकवादी गतिविधियों को मड़का रही थी, जिस कुल मिलाकर अराजकता ही कहा जा सकता है। करोड़पति हर्स्ट की पानी का अपहरण करने वाले सिम्बियोनिज मुक्ति सैनिक और पेंटरमेन नामक समूह ऐसे ही असांमाजिक तत्वों का जमघट थे।

इस दौर में दक्षिण अमरीका के अनेक देशों में राजनयिकों के अपहरण की बाढ़ भी आ गयी। इससे पहली बार यह बात ग्वाकित हुई कि आतंकवाद की चुनौती न केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं है। इसका एक अन्तर्राष्ट्रीय कानूनी पक्ष भी है, जिस अनदेखा नहीं किया जा सकता।

इसी समय यूरोप में भी बादर मिन्नहोफ़ नामक गिरोह आक्रामक तेवर अपनाये हुए था। वह अति-सिंहक वामपंथी अग्रगमिता को अपनी विचारधारा घोषित कर चुका था। इटली, फ्रान्स जर्मनी में उद्योगपतियों, उच्च-मदस्य सरकारी अधिकारियों, राजनीतिक नेताओं आदि के अपहरण और उनकी हत्या आम होत जा रहे थे। मध्य नाटकीय प्रमन इटली के भूतपूर्व प्रधान मंत्री अल्डोमारा के अपहरण और हत्या का था। जापानी सैनिकों की हिंसक गतिविधियों का विस्फोट भी कई जगह हुआ। अफ़िकाज लोगों के लिए यह तय करना कठिन हो गया कि कौन-से आतंकवादी राजनीतिक उद्देश्य न धरेलिये और कौन-से सिर्फ़ पैसेवर, दुस्साहसिक व भाड़े के हत्यारे सैनिक। राजनीतिक दृष्टि से इस समूह के माय परामर्श की सम्भावना भी कम होती जा रही थी।

सोबियाई आतंकवाद—मगर आपसी मतभेद, हत्याकाण्ड आदि के कारण

आतंकवाद की समस्या (Problem of Terrorism)

आतंकवाद का इतिहास सदियों पुराना है। जब भी कोई व्यक्ति या समूह आतंतायी के उत्पीड़न का सामना करने में असमर्थ सिद्ध हुआ, उसने शक्ति अंतुलन को समाप्त करने के लिए आतंकवाद को अपनाया। फ्रांस की पहली क्रान्ति (1789) के दौरान तथा दूसरी क्रान्ति (1848) की पूर्व संध्या में क्रान्तिकारी आतंकवाद तेजी से बढ़ा। स्वयं मारनीय स्वाधीनता संग्राम में कई ऐसे संगठन थे, जिन्होंने हिंसक क्रान्ति का मार्ग चुना। वे अपने को बवं से आतंकवादी कहते थे। पिछले दशक से अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद की समस्या इतनी तेजी से उभर हुई है कि ऐसा लगने लगा कि 'पारम्परिक आतंकवाद' से इस 'आधुनिक आतंकवाद' का कोई सीधा या स्पष्ट सम्बन्ध नहीं रह गया है।

आतंकवाद की परिभाषा—आतंकवाद की समस्या का विश्लेषण करने से पहले आतंकवाद की परिभाषा स्पष्ट करना उपयोगी होगा। आतंकवाद का अर्थ है—हिंसा का ऐसा प्रयोग, जो सैनिक दृष्टि से नहीं, बल्कि लक्ष्य (शिक्कार) को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करे।¹ दूसरे शब्दों में आतंकवाद एक तरह का भयावोहन (blackmail) है। इसकी प्रमुख उपयोगिता राजनीतिक व राजनयिक है। यही बुनियादी फार्म क्रान्तिकारियों और आतंकवादियों में है। अल्जीरिया और बियतनाम के उदाहरण इसकी पुष्टि करते हैं।

फिलिस्तीनी व इजराइली आतंकवाद—वर्तमान दौर में आतंकवाद के प्रति लोगों का ध्यान पश्चिम एशिया में फिलिस्तीनियों की गतिविधियों से मुड़ा। फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के एक उग्रपंथी पड़े 'अस फतह' के सदस्यों ने इजराइली विमानों का अपहरण आरम्भ कर दिया तथा बम विस्फोट आदि द्वारा इजराइल के 'निर्दोष पक्षियों' को आतंकित करना शुरू कर दिया। चूँकि फिलिस्तीनी स्वयं नागरिकता-विहीन शरणार्थी थे, इसलिए उनके आचरण के लिए किसी देश को कलंकित करना कठिन था। अमरीका और अन्य पश्चिमी राष्ट्रों ने इन्हें असामाजिक अपराधी माना। पश्चिमी राजनय की पूरी चेष्टा यह रही कि फिलिस्तीनी आतंकवादी कार्रवाई को पूरी मानव जाति के विरुद्ध अपराध के रूप में प्रचारित किया जाये। इन बीच 1973 में अरब-इजराइल सैनिक मरण के कारण फिलिस्तीनी लोग और ज्यादा मूढ़ता में डूब गए और आतंकवाद में वृद्धि हुई। इस सैनिक मुठभेड़ के बाद इजराइल ने अरबों का और तेजी से दमन किया तथा आतंकवादी गतिविधियों की क्रिया-प्रतिक्रिया 'प्रतिघोषात्मक' बन गयी। यदि फिलिस्तीनी किसी विमान का अपहरण करते तो इजराइल बदले में फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविरों पर बमों की बरबादारी कर बदला लेता। इसके जवाब में फिलिस्तीनी आतंकवादियों के हिराबल दस्ते इजराइली स्कूलों के निर्दोष बच्चों का अपहरण कर लेते। इस प्रकार यह दुष्पक तोड़ना कठिन होता गया।

इस अनुभव से एक और बात स्पष्ट हुई। इजराइली आचरण ने यह दर्शाया कि व्यक्ति ही नहीं, बल्कि राज्य भी आतंकवाद फैला सकता है। राज्य की सैनिक

¹ आतंकवाद की तर्क-संगत परिभाषा और समुचित परिचय के लिए देखें—Walter Laquer, *The Age of Terrorism* (London, 1987)

के लिए सैनिक या परामर्श वाले समाधान के तालमेल बिठाने की बढ़चन भी बची रहनी है। बंगलोर में आयोजित साकं शिखर सम्मेलन (नवम्बर, 1986) में आतंकवाद की सर्वसम्मन परिभाषा तक नहीं हो सकी। इससे पट्टी प्रमाणित होता है कि आतंकवाद की गुत्थी जटिल है और आज यह समस्या विदेशी ही नहीं, बल्कि हमारी अपनी भी है।

उत्तर हो या दक्षिण, पूर्व हो या पश्चिम, भारत के हर भीमान पर असतुष्ट तत्वों ने अपनी मांगों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए आतंकवादी हिंसा का अवलम्बन किया है। इस बात के अनेक प्रमाण मिल चुके हैं कि भारत की एकता को नुकसान पहुँचाने और उनकी भौगोलिक एकता के अतिक्रमण के लिए विदेशी शक्तियाँ आतंकवादियों को समर्थन दे रही हैं। एक छोटे से उदाहरण से इस समस्या के व्यापक बापान और इससे पैदा हुई राजनयिक समस्या स्पष्ट हो जायेंगी। खालिस्तानी आतंकवादियों ने ब्रिटेन में एक कार्यकारी सरकार की घोषणा की और भारत-विरोधी विपरीत प्रचार अभियान को निरन्तर जारी रखा। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने इस कार्यकारी खालिस्तानी सरकार को विधिवत मान्यता नहीं दी है, परन्तु उसने इन अनुरोधपूर्ण तत्वों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगायी है। इसी तरह जर्मनी, कनाडा आदि देशों ने राजनीतिक विचारधारा के कारण 'उत्पीडित सिख मर्यापिया' को धरण देने की जो नीति अपनायी, वह भी खालिस्तानी आतंकवाद को प्रोत्साहित करने वाली मिड हुई है। इस मामले में पश्चिमी 'जनतागिक' देशों की तापरवाही का दुष्परिणाम कनिष्क विमान के विस्फोट के रूप में सामने आया। अमरीका में केम्पर के छापामार सैनिक प्रशिक्षण सम्मान की गतिविधियाँ भी सदिग्ध रही हैं। अतः यह मोचना अकारण नहीं है कि अमरीकी सरकार अपने राजनयिक हिंसा के अनुरूप ऐसी गतिविधियों पर कोई रोक-टोक नहीं लगाना चाहती। इम्लैण्ड और कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी अनेक बार सरकारी छुट का फायदा उठाते हुए भारतीय राजनयिकों व अधिकारियों के साथ पाली-गलौड़ और मारपीट करते रहे हैं। जम्मू-कश्मीर मुक्ति मोर्चे के नाम पर सज्जन आतंकवादियों ने ब्रिटेन में कार्यरत भारतीय राजनयिक महाने का अपहृत कर उनकी हत्या कर दी थी। इसी तरह मित्रो राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे के अध्यक्ष सालहेंपा ब्रिटिश सरकार की कृपा से वहाँ काफी लंबे समय तक रहे और भारत के खिलाफ विप बमन करते रहे। आज नल ही भारत को जम्मू-कश्मीर मुक्ति मोर्चे और मित्रो राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे के उषावादियों की चिन्ता न हो, परन्तु इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि भारत की स्वाधीनता, गुट निरपेक्षता, आत्म-निर्भर आर्थिक विकास को न देख सकने वालों विदेशी शक्तियाँ उसको अपने पप से विचलित करने व कमजोर बनाने के लिए किसी भी समय इन 'पासतू आतंकवादियों' का भयानक राजनयिक अस्त्र के रूप में उपयोग कर सकती हैं। इसकेअतिरिक्त और कुनैई जैन दस वरिष्ठ 'खालिस्तानी सरकार' की मान्यता देने को तत्पर हैं। इन दोनों दलों की अन्तराष्ट्रीय राजनीति में कोई हस्ती नहीं और न ही भारत के साथ इनके राजनीतिक और आर्थिक सम्बन्ध महत्वपूर्ण हैं। परन्तु इस बात को याद रखना उपयोगी होगा कि वे महत्वपूर्ण देश ऐसे 'कठपुतलों' का प्रयोग अपने मोहुरों के रूप में करते रहे हैं, जिनके साथ भारत के सम्बन्ध आर्थिक व सामरिक महत्व के हैं। खालिस्तानी आतंकवादियों की समस्या सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच का

चुम्पुट आतंकवादी गिरोहों का सफाया नहीं होने लगा था। अंततः 1979-80 तक राजनीतिक आतंकवादी ही बचे रहे।¹ लेकिन इनके द्वारा प्रस्तुत चुनौती भी कम खटिल और हिमक नहीं रही है। हाल के दिनों में लीबिया इस सन्दर्भ में बहुत बदनाम रहा है। कर्नल गद्दाफी जिन विचारवादा के पक्षधर हैं और जिसका विश्व-व्यापी प्रचार कर रहे हैं, उनमें इस्लामी कट्टरता और 'समाजवादी' क्रांतिकारिता का संयोग है। अर्थात् लीबिया द्वारा प्रोत्साहित व समर्थित आतंकवाद इस्लामी सत्ता के साथ-साथ बाकी तीसरी दुनिया के लिए भी कम आकर्षक नहीं। अपनी तेज सम्पदा और कम जनसंख्या के कारण गद्दाफी अपने देश के विकास और समृद्धि के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं। लीबिया के आतंकवादियों का येरा फिनीषीस से लेकर बिंदेन तक फैला हुआ है। क्या-स्थिति चाहने वाले पश्चिमी देशों की असली चिंता यह है कि गद्दाफी खतम, उधड़खल व उड़ड़ है और उस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। लीबिया के आतंकवादी अन्य देशों, विशेषकर, अमरीका के परमाणु संयंत्रों को अपने आतंकवाद का निशाना बना सकते हैं, जिससे कभी भी मजंनाराश दुर्घटना घट सकती है। अमरीका ने लीबिया को अनुशासित करने और उसके आतंकवादियों का सफाया करने के लिए जिन तरह उनके पर में घुसकर कदम उठाये, वे भी सरकारी आतंकवाद ही कहे जा सकते हैं।

कमोबेरा इन्हीं तरह के भांशों मीरिया और ईरान पर लगाये जाते हैं। राष्ट्रपति रीगन ने अनेक बार यह कहा था कि आतंकवाद को समर्थन देने वाले देशों का बहिष्कार किया जाना चाहिये। इसके अभाव में दबु और मित्र के बीच अन्तर किया जाना कठिन है और इन तरह के फ़िरावलाप से फैलने वाली भातियों से मिक्रॉ भीत युद्ध के दबाव ही बढ़ सकते हैं। यह सब भी है कि नीरियाई राष्ट्रपति अमद और ईरानी सामक जमानुस्सा खुर्मी ने कई बार आतंकवादियों को प्रोत्साहित किया है। परन्तु परों के पीछे अमरीकी गतिविधियाँ इन देशों के आचरण से बहुत भिन्न नहीं रही हैं। निष्कारणता में 'कोना' सैनिकों को बड़े पैमाने पर सैनिक श्रृंखला देना इस मामले में अमरीका के गैर-जिम्मेदाराना रुत को उजागर करता है। जिन ईरानियों ने अमरीकियों को साल भर से ज़ारा बन्दक बनाकर रखा, अमरीका ने बाइ में उन्हीं को सैनिक साथ सामान बेचना अपने राष्ट्रीय हित में समझा। जब मीरिया को और जगुली उठावी मनी तो अजद ने यह कहा कि इजरायल ने उन्हें उदनाम करने के लिए जान-बूझकर अपने ही भादमियों को मीरियाई आतंकवादी के रूप में पड़वाया।

भारत के समक्ष आतंकवाद की चुनौती—भारतीय उप-महाद्वीप में भी आतंकवाद महत्वपूर्ण राजनयिक चुनौती बन चुका है। सातिस्तानी आतंकवादी हो या श्रीलंका में असन्तुष्ट तमिल, बयला देश व भारत को सीमा पर चकमा आदिनासी हो या नेपाल में बन विस्फोट करने वाले लोग, भारतीय विदेश नीति के नियोजन और संचालन के लिए सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद से भुगतवता हो है। यह प्रत्यक्ष आतंकवादियों के उन्मूलन का ही नहीं, बल्कि पड़ोसी देशों के साथ भारत के सम्बन्धों और बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप का भी है। हिन्दी के टकराव को दूर करने

¹ आतंकवाद के तुनारणक बन्धन और प्रमुख उदाहरणों के सबसे अच्छे सविस्तर सर्वेक्षण के लिए देखें—Alexander Yoniss, *International Terrorism : National, Regional and Global Perspectives* (New York, 1976).

बर्चस्व स्थापित करेगा। यह महासागर सात समुद्रों की कुञ्जी है। 21वीं शताब्दी में विश्व का भाग्य-निर्धारण इसकी समुद्री मनहो पर होगा।¹ माहून का यह कथन सिर्फ अमरीका के लिए ही नहीं, बल्कि सभी विश्व शक्तियों के लिए नौसैनिक नीति-निर्धारण करना जरूरी है। अमरीका और सोवियत संघ दोनों हिन्द महासागर में अपना नौसैनिक बर्चस्व कायम करने के लिए आज कटिबद्ध प्रतीत होते हैं।

यों तो हिन्द महासागर 18वीं शताब्दी में भी यूरोप के उपनिवेशवादी देशों की प्रतिस्पर्धा का केन्द्र रहा था, किन्तु 18वीं से 20वीं शताब्दी के अधिकांश काल में यह वस्तुतः 'ब्रिटिश झील' बना रहा।² हिन्द महासागर में 'शक्ति-शून्यता' की स्थिति तब पैदा हुई, जब ग्रेट-ब्रिटेन ने स्वेज पूर्व के सैनिक ठिकानों से हट जाने की



हिन्द महासागर में महाशक्तियों की पंजरबाजी और
दिएगो गार्सिया की भौगोलिक-सामरिक स्थिति

¹ ऐतिहासिक परिच्छेद में हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा के विचारोत्तेजक विश्लेषण के लिए रचें—K. M. Panikkar, *India and the Indian Ocean* (Delhi, 1971)

सिरद्वंद्व ही नहीं, बल्कि इसके साथ अमरीका जैसी महाशक्ति और ब्रिटेन भी जुड़े हुए हैं।

भारत के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह ब्रिटेन जैसी सरकार के सामने स्पष्ट कर दे कि यदि वह ब्रिटेन में रह रहे भारत-विरोधी आतंकवादियों को दण्डित व अनुशासित करने के लिए तत्पर नहीं है तो भारत भी उसके साथ सैनिक साज सामान की खरीद-फरोख्त और किसी भी व्यापक आर्थिक सहकार के लिए तैयार नहीं है। इस नये दौर में आतंकवाद की समस्या का एक और जटिल पक्ष है। स० १० सष और गुट निरपेक्ष आन्दोलन के शिखर सम्मेलनों में आतंकवाद की भरसंगा (चाहे वह दक्षिणपंथी हो या वामपंथी) सर्व सम्मति से स्पष्ट थावो में की गयी है, परन्तु दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और फिलस्तीन में साम्राज्यवादी व नस्लवादो अत्याचार के खिलाफ शास्त्र उठाने वाले भुक्ति सैनिकों को आतंकवादी अथवाही नहीं समझा जा सकता। भारत के सामने सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि खालिस्तानी आतंकवादियों का उन्मूलन करने के साथ-साथ श्रीलंका में तमिलो को सरकारी आतंकवाद से कैसे दबाया जाये।

इस प्रकार आतंकवाद की समस्या सिर्फ धार्मिक और मुख्यवस्था का प्रश्न ही नहीं है, बल्कि बुनियादी मतभेदों का परामर्श द्वारा राजनयिक हल ढूँढना भी है। आतंकवाद की समस्या का हल किसी भी स्थिति में उभयपक्षीय नहीं, बल्कि बहु-पक्षीय अन्तर्राष्ट्रीय परामर्श द्वारा ही ढूँढा जा सकता है।

विडम्बना यह है कि अपने तात्कालिक 'सकीर्थ' सामरिक हितों के पोषण के लिए विभिन्न राष्ट्र तरह-तरह के आतंकवादियों को बढ़ावा देते हैं। कालान्तर में रक्त बीज राक्षस बन जाते हैं और जातीय असन्तोष, सीमा विवाद और मादक द्रव्यों एवं हथियारों की तस्करी के घनिपात से नये और बेहद खतरनाक न्यस्त स्वायं बनपने लगते हैं। भस्मानुसार की तरह इन पर काबू पाना इनके जन्म के लिए भी सम्भव नहीं रह गया है। दक्षिण अमरीका के कोलरा हों, अफ्रीका में तैनात तयाकथित भाडे के सैनिक, अफगाण मुजाहिदीन, खालिस्तानी कमराडो या लिट्टेवादी मुक्ति चीत, सभी जगह यह बात देती जा सकती है कि ऐसी हालत में दो देशों के बीच राजनीतिक गमत्साबी के समाधान के बाद भी इन पर काबू पाना कठिन हो जाता है। भारत और श्रीलंका का अनुभव तथा अफगानिस्तान के बारे में पाकिस्तानी अनुभव यही संकेताता है। पश्चिम एशिया में फिलस्तीनी आतंकवादियों की गति-विधि या कम्बोडिया में समेर रुज के क्रियाकलाप, यह बात प्रमाणित करते हैं कि आतंकवादियों के आश्रयदाता, समर्थक और सहायक हमेशा उन्हें अपनी इच्छा-नुसार अपने-अपने राष्ट्रीय हितों के अनुकूल अनुशासित और नियोजित नहीं कर सकते। यही मित्र एक बान और जोड़ने की जरूरत है। अने नाले दिनों में आतंकवाद का सिरद्वंद्व अमरीका या यूरोप को नहीं, बल्कि भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों को ही होना पड़ेगा।

हिन्द महासागर में महाशक्तियों की मंतेरेवाजी (Super Power Rivalry in Indian Ocean)

उप्रीनवी मनाब्दी के आरम्भ में अमरीकी नौसेना विशेषज्ञ अल्फ्रेड माहन ने कहा था—'जो भी देश हिन्द महासागर को नियन्त्रित करता है वह एशिया पर

किया गया कि हिन्द महासागर में सोवियत संघ की गतिविधियाँ आवश्यकता से अधिक बढ़ती जा रही हैं।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि 1972 के बाद से ही साम्यवादी चीन अमरीकी सेमे की ओर झुकता जा रहा था। वियतनाम युद्ध के बाद की घटनाओं ने चीन और अमरीका को एक-दूसरे के और अधिक निकट ला दिया तथा इस निकटता ने प्रशान्त महासागर के अमरीकी सैनिक अड्डों का महत्व काफी हद तक कम कर दिया। दूसरी ओर चीन अमरीका पर यह दबाव भी डालने लगा कि वह अन्य देशों की नौसैनिक शक्ति का प्रशान्त महासागर के बजाय हिन्द महासागर में सन्तुलन करे।

अमरीका ने 1970 के दशक में अपने नौसैनिक बेड़े में 'पोतरिस्' एवं 'पोमीडन' पनडुब्बियों पर विशेष जोर दिया था जिनमें छ हजार मील तक मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र (Missiles) लगे होते हैं। इस प्रकार वह न केवल पश्चिम एशिया के तेल-मृदा देशों वरन् सोवियत संघ के अधिकांश हिस्सों को अपनी मार में ले सकता है। अगोवा में 1973 के बाद होने वाली घटनाओं ने भी अमरीकी नीति-निर्धारकों के सम्मुख हिन्द महासागर में नौसैनिक उपस्थिति को आवश्यक बना दिया था। इस सन्दर्भ में अमरीका के भूतपूर्व नौसेनाध्यक्ष एडमिरल जूमवाल्ड ने कहा था कि किसी देश की राजनीति को प्रभावित करने के लिए उसके नजदीकी समुद्र में एक विमान वाहक युद्धपोत भेज देना पर्याप्त होता है। इस दृष्टि से अमरीका ने विमान-वाहकों के निर्माण पर अधिक बल दिया। उसका नवीनतम विमान वाहक 'नीमिड्स' अपने आप में सम्पूर्ण युद्ध मशीनरी है। इन विमान वाहकों तथा अन्य युद्धपोतों के स्थायी रूप में हिन्द महासागर में रहने का तात्पर्य वहाँ 'स्पृष्टिक बे' या 'ओकिनावा' जैसी मरम्मत-मुविधार्थ जुटाना आवश्यक था।

सऊदी अरब, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान हिन्द महासागर को फारस की खाड़ी से जोड़ने की भौगोलिक-प्रक्रिया अदा करते हैं। फारस की खाड़ी पिछली सताब्दी से ही रुमिया के आनयण का प्रमुख केन्द्र रही है। यद्यपि फारस की खाड़ी स्थित देश परम्परागत रूप से कमोबेश अमरीका परस्त रहें हैं, किन्तु ईरान में शाह राजा पهلवी के अपदस्थ होने (1979) तथा ईरान से उठी इस्लामी पुनर्जागरण की लहर के अन्य देशों के फँस जाने के मिलमिले ने अमरीका के लिए इस क्षेत्र में कई चुनौतियाँ खड़ी कर दी। इधर अफगानिस्तान पर 'सोवियत कब्जे' में भारतीय उपमहाद्वीप के साथ ही समस्त हिन्द महासागर की भू-राजनीतिक स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन ला दिये थे। जहाँ एक ओर तेल की आपूर्ति पर तात्का लगे जान का खतरा पैदा हो गया, वहीं हिन्द महासागर में सोवियत प्रभुत्व स्थापित हो जाने का रास्ते भी प्रशस्त दिखाई देने लगे। इस स्थिति में अमरीका जहाँ जल्फेज-माहन की नविष्यवाणी की याद करके भयावह परिरक्षण से प्रसन्न है, वहीं वह अपने हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध भी प्रतीत होता है।

अफगानिस्तान, ईरान या पाकिस्तान में अमरीका सीधे सैनिक हस्तक्षेप की कार्रवाई अन्तिम किन्तु के रूप में ही स्वीकार करेगा, बल्कि उसका मूल उद्देश्य फारस की खाड़ी से तांबिक-सम्पर्क बनाये रखना एवं वहाँ के देशों को अमरीका की तरफ झुकाव के लिए बाध्य करना भर माना जा सकता है। दोनों ही योजनाएँ दिये गये मामलों को पूर्ण सैनिक अड्डा बनाकर तथा वहाँ एक नौसैनिक कमान का

योजनाओं को क्रियान्वित करने का निश्चय कर लिया। 1967 में जब उसने इसकी घोषणा की तो सामरिक विशेषज्ञों ने यह सहज ही अनुमान लगा लिया कि ब्रिटेन स्वयं हिन्द महासागर से हटकर वहाँ अमरीका का नौसैनिक वर्चस्व स्थापित कराने के लिए प्रयत्नशील है। आसन्न इसीलिए एक वर्ष पूर्व ही उसने डिएगो गार्सिया वासिमटन को सौंप दिया।

लन्दन और वासिमटन की इन चालों से सोवियत संघ चौखटा उठा। उन दिनों मास्को के नौसैनिक हलकों में सर्वाधिक चर्चित व्यक्ति एडमिरल मारशकोव हुआ करता था जो यह मानता था कि कोई भी राष्ट्र समुचित नौसैनिक शक्ति के बिना विश्व शक्ति नहीं बन सकता। उसने सोवियत नौसेना से लिए एक बड़ी योजना तैयार की जिसके अन्तर्गत दस वर्ष में ही सोवियत संघ को नौसैनिक शक्ति के क्षेत्र में अमरीका के समकक्ष हो जाना था। इसके साथ ही सोवियत पनडुब्बियाँ और लड़ाकू जहाज हिन्द महासागर के तल में और सतह पर घुसने लगे। इन गति-विधियों ने अमरीका के लिए हिन्द महासागर की 'रक्तता' को शीघ्रातिशीघ्र भरना आवश्यक बना दिया और इस प्रकार डिएगो गार्सिया हिन्द महासागर में अमरीकी नौसैनिक शक्ति का एकमात्र 'लगरगाह' बन गया।

हिन्द महासागर के तटीय देशों का अमरीका के लिए महत्त्व इन परि-स्थितियों में बढ़ता ही गया। आर्थिक दृष्टि से पश्चिमी राष्ट्र आयात और निर्यात दोनों के लिए इन देशों पर निर्भर रहे। अमरीका चूँकि पश्चिमी छेमे की सैनिक शक्ति में रीड की हड्डी की तरह है, अतएव सोवियत संघ की शक्ति को समुचित करने के लिए योजना बनाना और उसे क्रियान्वित करना उसी के कर्तव्य पर टिका हुआ है। जापान और पश्चिमी यूरोपीय देश जहाँ अपनी खुशहाली के लिए पश्चिम-यूरेशिया के तेल-निर्यातक देशों पर निर्भर है, वही सुरक्षा के लिए वे अमरीका पर निर्भर हैं। हिन्द महासागरीय क्षेत्र से अमरीका 8% काष्ठ 51%, पश्चिमी जर्मनी 62%, ब्रिटेन 66%, आस्ट्रेलिया 69%, इटली 85.5% तथा जापान 90% तेल अपने देश की आवश्यक करते हैं। अमरीका और पश्चिमी राष्ट्रों के लिए 'डिएगो गार्सिया' का महत्त्व नई इस तेल की राजनीति में जुड़ा हुआ है।

विगतनाम में 1975 में अमरीका की पराजय एवं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में अमरीकी प्रभाव की डगमगाती स्थिति ने यह आवश्यक बना दिया कि अमरीका प्रशान्त महासागर से आगे बढ़कर हिन्द महासागर में अपना सैनिक जमाव केन्द्रित करे। इसका एक कारण 1973 का अरब-इजरायल सघर्ष और तदनन्तर अरब देशों द्वारा पश्चिमी राष्ट्रों के विरुद्ध तेल-आपूर्ति की पाबन्दियाँ भी रही थी। तत्कालीन अमरीकी विशेष मन्त्री हेनरी किस्सिजर ने इन पाबन्दियों की छद्मपटाहट में यहाँ तक कह दिया था कि अरबों को सबक सिखाने के लिए अमरीका को बल-प्रयोग भी करना पड़ सकता है। इस सबक सिखाने की वृष्ठभूमि और बल-प्रयोग की आवश्यकता ने डिएगो गार्सिया के महत्त्व को और नई बढ़ा दिया।

विगतनाम युद्ध की समाप्ति ने दक्षिण पूर्व एशिया के आसिपास देशों (इण्डोनेशिया, फाईलैंड, मलेनिया, सिंगापुर एवं फिलीपींस और ब्रुनई) एवं आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में सुरक्षा की तंकर अनेक जगहों पर कर दिये थे। आस्ट्रेलिया की मास्कोम क्षेत्र की सरकार देश की सुरक्षा के लिए डिएगो गार्सिया में अमरीकी सैनिक शक्ति का जमाव आवश्यक मानती थी। अमरीका द्वारा यह नई प्रचारित

घोषणा 1967 में की। इसके साथ ही हिन्द महासागर में सोवियत, नौसैनिक गति-विधियों में वृद्धि होने लगी। अमरीका के नौसेना विभाग ने 'शक्ति-शून्यता' की दुहाई देकर अमरीकी संसद से हिन्द महासागर में सैनिक बढ़ा देने की इजाजत चाही, किन्तु 1970 में अमरीकी संसद ने इसके लिए इन्कार कर दिया। फिर भी 15 दिसम्बर, 1970 को ब्रिटेन और अमरीका ने डिएगो गार्मिया 'के सम्बन्ध में एक रहस्यपूर्ण समझौता किया। मार्च, 1971 में वहाँ निर्माण कार्य शुरू हुआ और मार्च, 1973 में डिएगो गार्मिया ने एक संचार केन्द्र के रूप में काम करना शुरू कर दिया। मई, 1973 में 'न्यूयार्क टाइम्स' ने टीक ही लिखा था कि हिन्द महासागर में विदेशी भूमि पर सैनिक बढ़ा बनाने वाला प्रथम देश अमरीका बन गया है।

वस्तुस्थिति यह थी कि अमरीका डिएगो गार्मिया पर एक सैनिक अड्डा बना चुका था और केवल उसे विकसित करने का काम रह गया था। शायद यही कारण था कि 1970 और 1973 के बीच वहाँ निर्माण कार्य में खर्च की गई राशि को गुप्त रखा गया, यद्यपि अधिकारिक तौर पर अमरीका ने स्वीकार कर लिया था कि वहाँ 800 फुट लम्बी हवाई पट्टी और एक रेडियो स्टेशन का निर्माण पूरा कर लिया गया है। इसके लिए 174 नौसैनिक तकनीशियन नियुक्त किये गये।

प्रश्न यह उठता है कि अमरीका ने डिएगो गार्मिया को ही क्यों चुना? उत्तर साफ है—इसकी सामरिक स्थिति को देखते हुए हिन्द महासागर का 'घोषरी' बनने के लिए। यह भारत से केवल 1130 मील की दूरी पर है और सिंगापुर, अदन, आस्ट्रेलिया, इराक, कुवैत तथा कतार से क्रमशः 2560, 2670, 3400, 3800, 3500 तथा 3000 मील की दूरी पर है। इसकी एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसके आम-आम चागाम द्वीप समूह के अनिरुक्त और कोई ऐसा बड़ा द्वीप नहीं है, जहाँ अमरीका के विरोधी अपने अड्डे बना सकें। दूसरी बात इस द्वीप पर रह रहे 1200 लोगों को सैनिक अड्डा बनाने से पहले ही द्वीप छोड़ देने की बाध्यता कर दिया गया था और इसलिए वहाँ अमरीकी गतिविधियों के विरुद्ध जामूनी या तोड़फोड़ की आशंका नहीं रह गयी। तीसरी बात, ब्रिटेन को अपना सहयोगी रखकर अमरीका अपने-बदनाम होने में बच गया।

दूसरा शेर—1974 में अमरीका ने डिएगो गार्मिया के विस्तार का दूसरा दौर आरम्भ किया। वहाँ नौसैनिक अड्डा बनाने के लिए पहले उसने 290 करोड़ डॉलर की राशि खर्च करने की घोषणा की। 1975 में हिन्द-चीन में अमरीका की पराजय और पश्चिम एशिया की बिगड़ती हुई राजनीतिक स्थिति ने अमरीकी प्रशासकों के सम्मुख डिएगो गार्मिया पर एक विशाल सैनिक अड्डे के औचित्य का साबित कर दिया। इसके बाद वहाँ निरन्तर नवीन निर्माण कार्य जारी रहे। ईरान में शाह रजा पهلवी के 1979 में पतन के बाद अमरीका हिन्द महासागर में अपनी सैनिक उपस्थिति को लगातार बढ़ाता रहा। किन्तु उसकी नीयत के छूटे और सातवें बेड़े (जो क्रमशः भूमध्य सागर और प्रशांत महासागर में है) के जहाज ही हिन्द महासागर की गहराई पर भेजे जाते रहे। फरस की खाड़ी में गहराते हुए सक्क और ईरान में अमरीकी जहाजों के प्रश्न ने अमरीका और उसने तेल आयातक मित्र देशों का विचित्र कर दिया। अमरीकी मदद हिन्द महासागर में अमरीकी हितों को उसके विश्वव्यापी हितों का यथासंभव मानते हुए अन्तराष्ट्रीय वादों के प्रशासन द्वारा प्रस्तुत

मुख्यालय स्थापित कर पूरी की जा सकती है। डिएगो गार्सिया से अमरीका सोवियत संघ के नौसैनिक रास्ते पर नजर रख सका और प्रधानत्व महासागर में सोवियत सैनिक अड्डे स्लादीवोस्तक और उसके काले सागर स्थित नौसैनिक अड्डों के बीच निरन्तर आवागमन पर भी अक्रुश रह सका। साथ ही हिन्द महासागर ने स्थायी अड्डा बनाकर वह प्रधानत्व महासागर की अपनी भूमिका को शायद वहाँ भी दोहराना चाहता रहा।

डिएगो गार्सिया विषयक अमरीकी रणनीति

हिन्द महासागर क्षेत्र में अमरीकी महत्वानुवादाओं और मंसूबों को समझने के लिए डिएगो गार्सिया विषयक रणनीति का विश्लेषण बहुत उपयोगी है। डिएगो गार्सिया पिछले 15-20 वर्षों से अमरीका की सामरिक योजनाओं में महत्वपूर्ण बना हुआ है। अमरीका के सैनिक विशेषज्ञों ने बहुत पहले यह अनुमान लगा लिया था कि 1980 के दशक के शुरू में महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा हिन्द महासागर पर केन्द्रित हो जाएगी, क्योंकि अटलांटिक और प्रधानत्व महासागरों में प्रतिस्पर्धा के दावरे बहुत सीमित हो गये हैं। हिन्द महासागर एशिया और अफ्रीका के विकासशील देशों पर बचस्व स्थापित करने या उन पर आर्थिक व राजनीतिक दबाव डालने के लिए कुंजी का काम करेगा। यही कारण था कि ब्रिटेन के पलायनवादी इरादों को भाँपकर अमरीका ने 30 दिसम्बर, 1966 को ब्रिटेन से डिएगो गार्सिया और चागोस द्वीप समूह को सी बर्षों के लिए प्राप्त कर लिया।

डिएगो गार्सिया को लेकर पिछले डेढ़ दशक से जितने समाचार प्रकाशित हुए हैं, उनसे विश्व के भावी घटनाक्रम में इसके सामरिक महत्व को समझा जा सकता है। यह द्वीप चागोस द्वीप समूह का अंग्रेजी 'बी' भाँवर का द्वीप है और 15 मील लम्बा तथा चार मील चौड़ा है। इस द्वीप का नामकरण 1532 में इसे खोजने वाले पुर्तगाली नाविक के नाम पर किया गया है। यह द्वीप 1815 तक फ्रांस के अधीन रहा, किन्तु बाद में ब्रिटेन ने हिन्द महासागर स्थित अन्य फ्रान्सीसी द्वीपों के साथ-साथ इसे भी अपने अधिकार में ले लिया।

डिएगो गार्सिया बर्षों मारीशस से 1987 किशोरीद्वर उत्तर-पूर्व में स्थित है, तथापि 1965 से पहले तक इसका प्रशासन इसे मारीशस का हिस्सा मानकर ही चलाया जाता रहा। 1965 में ब्रिटेन ने मारीशस के अर्ध-स्वतन्त्र शासकों से एक समझौता करके डिएगो गार्सिया समेत सम्पूर्ण चागोस द्वीप समूह पर अधिकार कर लिया। इधर 1968 में मारीशस को पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त हुई, किन्तु इसके एक वर्ष पूर्व ही ब्रिटेन ने डिएगो गार्सिया और अन्य द्वीप मारी मुताफे पर अमरीका को सौंप दिये। उदने में अमरीका ने 115 लाख डॉलर के अस्वास्थ्य ब्रिटेन को मुफ्त में सौंपे। अमरीका और ब्रिटेन के बीच हुए समझौते के अनुसार उपरोक्त द्वीपों का स्वामित्व ब्रिटेन के पास रहेगा, किन्तु दोनों देशों की सुरक्षा की दृष्टि से अमरीका वहाँ सैनिक अड्डे बनाने और सैनिक साज-सामान तथा सैनिकों का जमाव करने के लिए स्वतन्त्र होगा।¹

सैनिक होड़ क्यों—ब्रिटेन ने 'स्वेज-यूरे' के अपने सैनिक अड्डों को हटाने की

¹ डिएगो गार्सिया विषयक जानकारी के लिए देखें—K. P. Masta, *Quest for an International Order in the Indian Ocean* (Delhi, 1977), 37-46.

टकराव की सम्भावनाओं को बढ़ा दिया है। ब्रिटेन ने मारीशस की मांग ठुकरा दी और हिन्द महासागर में अमरीकी योत्रनाओं का पूर्ण समर्थन किया।

वास्तविकता यह है कि डिएगो गार्सिया पर अमरीकी बड़े का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से और पश्चिमी देशों की विश्व शक्ति-सन्तुलन में भावी रणनीति को दृष्टिगत रखते हुए किया गया। ऐसे में उसे मारीशस को लौटाए जाने या सैनिक बड़े का विस्तार रोक देने की कोई सम्भावना नजर नहीं आती। किसी भी सम्भावित महायुद्ध में यह छोटा-सा द्वीप एशिया के लिए कितना खतरनाक साबित होगा, इसका अनुमान बहुत भयावह है।

भारतीय नीति—यहाँ सवाल उठता है कि हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा को देखते हुए भारत क्या नीति अपनाने? इस सन्दर्भ में के० एम० पाणिकर की टिप्पणी उसके निम्ने जाने के 3 दशक बाद भी सार्थक है। उनका कहना था— हिन्दमहासागर के विषय में भारत की दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों तरह की नीति जरूरी है। इस समुद्री क्षेत्र में अपन हितों की रक्षा के लिए भारत का एक समर्थ नाविक शक्ति के रूप में विकास अनिवार्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति तभी हो सकती है, जब भारत एक प्रमुख औद्योगिक शक्ति के रूप में उमरे और उसकी वैज्ञानिक व तकनीकी उपनब्धियाँ अन्य विकसित देशों की बराबरी करने वाली हों।

कुछ विद्वानों का मानना है कि आज अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में हिन्द महासागर की समस्या उतनी ज्वलंत नहीं रह गयी है, जितनी एक दशक पहले थी। आज न तो हिन्द चीन में कोई खट है और न ही अमरीकी बड़े की उपस्थिति को लेकर तटवर्ती राज्य नकाबुल हैं। कुछ सामरिक विशेषज्ञ तो यह भी मुझाते हैं कि शक्ति संपर्प का फलभ्रम हिन्द महासागर से हटकर प्रशांत क्षेत्र की परिधि तक पहुंच गया है। मारू, मोलोमन द्वीप, फिजी, जैसे 'मूढम राज्य' सामारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। कुछ और विश्लेषक यह भी मुझाते हैं कि भारतीय नौसेना आजादी के लगभग साठे चार दशक बाद भी हिन्द महासागर में अपने शक्ति के प्रक्षेपण में धमधम है। फिजी तो बहुत दूर की बात है, मारीशस में भी राजनीतिक घटनाक्रम को प्रभावित करने में वह अमफल ही है। यहाँ इस बात पर जोर दिया जाना आवश्यक है कि हिन्द महासागर में भारत की तत्संगत भूमिका ब्रिटेन, अमरीका या रूस जैसी नहीं हो सकती। हमारा लक्ष्य किसी भी शक्ति गून्ध का करने का कभी नहीं रहा। परन्तु हम हम बात की वतइ अमदमी नहीं कर सकत कि सागर तन की संपदा का दाहन हो या मछली पकड़ना या तस्करी की चुनौती, भारतीय राष्ट्रीय हिन्द महासागर व सदर्भ में एक खास अलग ढंग से पारिभाषित हात है। यहाँ दो-चार चुनिन्दा उदाहरण ही देना मयष्ट हागा।

कुछ वष पहले जब मालदीव में गम्भूम सरकार व मिनाफ तह्नापलट की माजिग की गयी थी, तब उसे भारत न ही नाजाम किया था। आज भी भारतीय नौसैनिक यदि मन्नार की खाड़ी में तैनात नहीं रहत तो लिट्टे उग्रवादिया की गतिविधिया व और भी घातक परिणाम तमिलनाडु और भारत पर पड सकत है। अरब सागर में भी दुबई और अन्य साड़ी राज्या से बडे पैमाने पर तस्करी होती है, जो अम्रत्यक्ष परन्तु घातक रूप से दस की आर्थिक क्षमता का क्षय करती है। भारत के माव अश्रुता का माव रलन वाता कोई दश हजारों चीन फंड भारतीय सागर तट

प्रत्येक सैनिक व्यय को पारित करती रही। दिसम्बर, 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप ने कार्टर प्रशासन को हिन्द महासागर में अमरीकी सैनिक जमाव करने का अच्छा बहाना दे दिया था।

अमरीकी व्ययको को ईरान से छुड़ाने और तेल-आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अमरीका ने जो ब्यूह रचना तैयार की, उसका एक आवश्यक अंग डिएगो गार्सिया में मात विद्यालय तैरते हुए दस्त्रागार बनाना था। जून, 1980 के आरम्भ में अमरीका के तत्कालीन रक्षा सचिव हेराल्ड ब्राउन ने डिएगो गार्सिया के सम्बन्ध में कार्टर प्रशासन की योजना ब्रिटिश प्रधानमन्त्री श्रीमती मारशेट पेंचर के सम्मुख रखी थी। दोनों देशों में यह तय हुआ कि उक्त सैनिक अड्डे को स्वेज के पूर्व में एक प्रमुख 'सिग्न बोर्ड' के रूप में विकसित किया जाये।

इन समाचारों के बाद तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के सामने बड़ा विरोध प्रकट किया तथा लका, सिगापुर, मलेशिया और इन्डोनेसिया को ब्रिटिश-अमरीकी योजनाओं के विरोध के लिए तैयार करने की कॉमिगस युद्ध की। द्वाय मारोसस डिऐगो गार्सिया अड्डे की विस्तार योजनाओं से आशंकित हो गया और जून, 1980 के मध्य में मारोसस ने उसे वापस प्राप्त करने के लिए प्रयास आरम्भ कर दिए।

विरोध विफल—मारोसस और तटवर्ती युद्ध निरपेक्ष देशों का विरोध आग्ल-अमरीकी योजनाओं को परिपूर्ण होने से रोकने में असफल रहा। 16 जून, 1980 को कोलम्बो के समाचार पत्र 'वन' ने विश्वस्त राजनयिक सूत्रों के आधार पर यह समाचार प्रकाशित किया कि अमरीका डिऐगो गार्सिया पर एक विद्यालय दस्त्रागार का निर्माण और सैनिकों का जमाव कर चुका है। यह भी कहा गया कि 1973 में निर्मित 800 फुट की सामान्य सी हवाई पट्टी को 12 हजार फुट लम्बी अधुनातम हवाई पट्टी के रूप में विकसित कर लिया गया है जिस पर परमाणु शक्ति चालित बमबर्क वी-52 तथा भारी मालवाहक एवं ईंधनवाहक विमान जैसे वी-5 ए तथा वी-141 आसानी से उतर सकते हैं। डिऐगो गार्सिया अड्डे पर 45 फुट घेरे नौसैनिक बन्दरगाह का निर्माण भी पूरा कर लिया गया, जहाँ अमरीका के विद्यालय विमान-वाहक जहाजों को 'होम पोर्टिंग' की सुविधाएँ उपलब्ध की जा सकती हैं।

जून, 1980 में वहाँ 1750 अमरीकी व्यक्ति निर्माण-कार्यों में लगे हुए थे। जुलाई, 1980 के आरम्भ में टैको, बल्सरबन्द गाड़ियों, गोला-बारूद, भोजन-सामग्री आदि में तंदे हुए मात विमान अमरीकी मालवाहक जहाज वहाँ लाती किये गये। अनुमान है कि यह मात्र-मानान 12 हजार अमरीकी सैनिकों के लिए महीने भर तक के लिए काफी होगा।

इन चौंका देने वाले तथ्यों की जानकारी मिलने पर मारोसस के तत्कालीन प्रधानमन्त्री सर शिवनाथ रामगुलाम ने 7 जुलाई, 1980 को लन्दन में ब्रिटिश प्रधानमन्त्री श्रीमती मारशेट पेंचर से मेट कर डिऐगो गार्सिया पुनः मारोसस को लौटाने की विधिबत माँग की। उन्होंने तर्क दिया कि आग्ल-मारोसस ममसीते के अनुसार डिऐगो गार्सिया को महज नौसैनिक और मालवाही जहाजों के लिए ईंधन प्राप्त करने का स्टेगन बनाने की बात तय हुई थी। किन्तु इनके विपरीत अमरीका ने उसे एक विद्यालय सैनिक अड्डे में बदल कर हिन्द महासागर में महाशक्तियों के

किया गया दस्तावेज ।

अप्रैल, 1984 में अमरीकी राष्ट्रपति रीनाल्ड रीगन ने चीन से किये गये परमाणु सहयोग समझौते की संसद से पुष्टि कराने का फैसला किया था, ताकि वह इस समझौते को 'सबसे बड़ी कूटनीतिक सफलता, बताकर नवम्बर, 1934 में होन वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव को दुबारा जीत सकें । बाद में रीगन ने यह पुष्टि करान का विचार छोड़ दिया क्योंकि उन्हें डर था कि यदि अमरीका ने इस समझौते के तहत चीन को परमाणु टेक्नोलॉजी दी तो चीन उसे परमाणु बम बनाने के लिए पाकिस्तान को दे देगा । अमरीका को कई खाना से जानकारी मिली कि चीन पिछले कुछ वर्षों से पाकिस्तान को बम बनाने में चोरी-छिप मदद करता रहा है ।

दूसरी तरफ सीनटर एलन क्रैन्स्टन ने 21 जून, 1984 की अमरीकी सीनेट में प्रस्तुत किये गये अपने दस्तावेज में पाकिस्तान द्वारा परमाणु बम बनाने सम्बन्धी जोरदार तैयारियों और उसमें चीनी मदद का जिक्र किया । उनके अनुसार इससे पाकिस्तान का पड़ोसी भारत भी बम बनाने की ओर उन्मुख होगा, जो अन्तः दोनों देशों में युद्ध का माग प्रदास्त करेगा । इसमें न केवल भारतीय उपमहाद्वीप में अस्थान्ति फैलेगी, बल्कि विश्व शान्ति भी भंग होगी और अमरीकी हितों को चोट पहुँचेगी । एलन क्रैन्स्टन की माँग थी कि पाकिस्तान को अमरीका द्वारा दी जाने वाली आर्थिक व सस्त्रास्त्र सहायता तत्काल रोक दी जाये और उस पर इस पातक हथियार को न बनाने के लिए दबाव डाला जाय ।

वैसे पाकिस्तान द्वारा परमाणु बम बनाने की कहानी 1971 में बंगला देश के स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में उद्भित होने और भारत से युद्ध में हारने से जुड़ी हुई है । जुल्फिकार अली भुट्टो ने सत्तानशील होने के बाद कहा था कि भारत जैन पड़ोसी देश के साथ रहने के लिए पाकिस्तान की सैनिक ताकत लगातार बढ़ती रहनी चाहिए । परमाणु बम का निर्माण इसी सैनिक ताकत का प्रमुख अंग था । स्वयं भुट्टो ने 1978 में पोलो की मजा सुनाने पर जेल-कोठरी में लिख अपने अन्तिम टेस्टामेंट (वसीयत) 'अगर मैं मर जाऊँ' (If I am Assassinated) में जनरल जिया उल हक की सैनिक सरकार पर आरोप लगात हुए कहा था कि उन्होंने देश को शक्तिशाली बनाने के लिए जो परमाणु कार्यक्रम शुरू किया था, जिया सरकार उसकी उपेक्षा कर देश को कमजोर कर रही है । परमाणु बम के पक्ष में उनका ठकं था—'ईसाई, यहूदी तथा हिन्दू सम्प्रदायों के पास परमाणु बम की क्षमता है । साम्यवादी देशों के पास भी यह क्षमता है । सिर्फ इस्लामी सम्प्रदाय ही ऐसी है, जिनके पास परमाणु बम नहीं है ।' भुट्टो परमाणु बम बनाने के प्रति कितन दृढ-संकल्प थे, यह उनके इस बयान में स्पष्ट है । उन्हीं के शब्दों में—'हमें घास-पाव ही क्यों न खानी पड़े, लेकिन हम परमाणु बम अवश्य बनायेंगे ।'²

इस परमाणु बम बनाने की योजना का 'कोड' नाम 'प्रोजेक्ट 706' रखा गया । भुट्टो न इसके लिए पश्चिम एशिया के मुस्लिम देशों का तूफानी दौरा किया और खामकूद नीतियाँ तथा मक्कदी अरब में 'इस्लामी बम' के नाम पर विज्ञापन

² 'We know that Israel and South Africa have full nuclear capability. The Christian, Jewish and Hindu Civilizations have this capability. The Communist powers also possess it. Only the Islamic civilization was without it, but that position was about to change.'—Zulfikar Ali Bhutto, *If I am Assassinated* (Delhi 1979)

का दुरुपयोग, बिघटनकारी घुसपैठ या अतगाववादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने के लिए कर सकता है।

यह बात भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि भारतीय भू-भाग के सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ हिस्से हिन्द महासागर स्थित द्वीप समूह हैं। इनमें अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप भारतीय भू-भाग से काफी अलग-थलग है। हम उनकी ओर से अपनी आँखें नहीं मूंद सकते।

यह ठीक है कि हवाई मार्ग से यात्रा सहज, सुगम और तेज होने के कारण हम अवसर जलमार्गों की उपेक्षा करते हैं। परन्तु पर्यटक व पत्रकार चाहे कुछ भी करें, पड़ोसी व्यापारी ऐसा नहीं कर सकते। पूर्वी अफ्रीका के देशों की स्थिति में (आर्थिक व राजनीतिक) गुंथार होने के बाद एक बार फिर हिन्द महासागर के इस जलमार्ग का महत्व भारत के लिए बढ़ेगा। औरों के लिए हिन्द महासागर का महत्व घटता-बढ़ता रह सकता है, किन्तु भारत के लिए इसका महत्व हिमालय पर्वत श्रृंखला की तरह हमेशा बना रहेगा, क्योंकि वह हमारी भू-राजनीतिक नियति का अभिन्न हिस्सा है। सदियों से भारतीय भूगोल की सीमा-रेखा उसके सदर्म में निर्धारित होती रही है। ठीक ही कहा गया है—‘उत्तरम पद समुद्रस्य हिमाद्रिश्चय दक्षिणम—वर्षम तद् भारत नाम, भारतीय तत्र सति।’

पाकिस्तान की परमाणु तैयारियाँ (Pakistan's Efforts for Nuclear Bomb)

पाकिस्तान अपनी स्थापना के साथ ही अपने को भारत के प्रतिद्वन्दी व प्रतिस्पर्धी के रूप में देखता रहा है। आकार, आबादी और क्षमता के मामले में पाकिस्तान भारत की तुलना में उन्नीस वें भी कम ठहरता है। फिर भी, पाकिस्तानी नेता भारत के साथ सैनिक संघर्ष में तान उठाने के उद्देश्य से ‘एक कृत्रिम शक्ति-सन्तुलन’ स्थापित करने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहे हैं। शीत युद्ध के वर्षों में पाकिस्तान द्वारा अमरीकी सैनिक संगठनों की सदस्यता स्वीकार करना, इसी रणनीति का हिस्सा था। लेकिन भारत के साथ 1947-48, 1965 तथा 1971 की सैनिक मुठभेड़ों में पाकिस्तान के इन प्रयत्नों की निरर्थकता उजागर हुई। परिणाम-स्वरूप पाकिस्तान अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए कोई और विकल्प ढूँढ़ने को प्रेरित हुआ। जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस संदर्भ में पाकिस्तान द्वारा परमाणु हथियार बनाने की बात सुझाई। उस वक्त (1972-73 में) अधिकांश भारतीय विद्वानों की सलाह थी कि यह पाकिस्तान के लिए भ्रम मरीचिका है। परन्तु आज यह बात सामने आने लगी है कि यह मरीचिका नहीं, बल्कि एक न्यायावह दुःस्वप्न है, जो किसी भी क्षण पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए सर्वनाशक यथार्थ में बदल सकता है।

पाकिस्तान के भूतपूर्व राष्ट्रपति जनरल जिवा उल हक समय-समय पर दोहराते थे कि ‘उनके देश की न तो परमाणु बम बनाने की मशा है और न ही उसके पास इसके निर्माण के लिए पर्याप्त साधन हैं। उनका देश परमाणु ऊर्जा का उपयोग शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए करना चाहता है।’ मगर उनका यह दावा खोखला साबित हो चुका। इसकी ‘मिसालें’ हैं—अमरीका द्वारा चीन के साथ किये गये परमाणु सहयोग समझौते को समद की पुष्टि के लिए पेश न करना और सीनेटर एलन क्रैन्स्टन द्वारा अमरीकी संसद में पाकिस्तान के परमाणु मन्त्र के बारे में पेश

हाइड्रोजन बम भी बना सकते हैं।'' यदि पाकिस्तानी सरकार ने कहा तो हम उसे परमाणु बम बनाकर दे देंगे।' इस साक्षात्कार पर अमरीका में काफी हो हल्ला मचा और सीनेट की वैदेशिक सम्बन्ध समिति ने पाकिस्तान को 3.2 अरब डॉलर की सहायता की एक किस्त देने में अड़गा लगा दिया और माग की कि राष्ट्रपति रीगन इस आग्रह का लिखित प्रमाण पत्र दें कि पाकिस्तान ने न तो परमाणु बम बनाने की क्षमता हासिल की है और न ही वह इसे पाने की कोशिश कर रहा है। रीगन ने ऐसे प्रमाण पत्र देने में असमर्थता व्यक्त की, लेकिन वह अपनी रिपब्लिकन पार्टी के मददगारों के जरिये पाकिस्तान के लिए सहायता की उक्त किस्त मंजूर कराने में कामयाब रहे।

अप्रैल, 1984 में अमरीका जिन तीन प्रमुख कारणों से चीन के साथ परमाणु सहयोग समझौता करने को प्रेरित हुआ, वे थे—चीन द्वारा किसी अन्य देश को परमाणु बम बनाने में मदद न देने का आश्वासन, पाकिस्तान के परमाणु प्रयासों को व्यर्थ का दुस्साहस और अडबोलापन मानना और रीगन द्वारा इस समझौते को राष्ट्रपति चुनाव (नवम्बर, 1984) में एक सशस्त्र बैसाखी के रूप में इस्तेमाल करने की मन्ना। परन्तु बाद में रीगन ने राष्ट्रपति चुनाव में इस बैसाखी को इस्तेमाल करने का विचार त्याग दिया, जिसका यही मतलब लगाया गया कि अमरीका को ऐसे ठोस सबूत मिले हैं, जिनसे साबित होता है कि पाकिस्तान परमाणु बम बनाने में मुस्लिमी से कार्य कर रहा है और चीन इसमें बड़े पैमाने पर मदद कर रहा है। अमरीका को यही डर है कि इस समझौते के तहत वह जो परमाणु टेक्नोलॉजी चीन को देगा, वह उसे पाकिस्तान को भी दे देगा, जिससे वह भी परमाणु बम बनाने में समर्थ हो जायेगा।

इस बीच सीनेटर एलन क्रैन्स्टन ने इस बारे में सनसनीखेज जानकारी दी। उन्होंने अपने दस्तावेज में कहा है कि पाकिस्तान ने बाहुता के यूरेनियम संवर्धन मयन्न का विस्तार किया है। इन संवर्धन के लिए अती भी टर्बो के जरिये वासकर पश्चिम जर्मनी व फ्रांस की कंपनियों से परमाणु उपकरण पहुँच रहे हैं। पाकिस्तान प्लुटोनियम को पुनः संशोधित करने का कार्य गोपनीय रूप से कर रहा है, जिससे वह हर वर्ष एक परमाणु हथियार बना सकता है। उसने परमाणु हथियार डिजाइन दल 'बाहू ग्रुप' का विस्तार किया है। पाकिस्तान के माध्य परमाणु हथियार छोड़ने की क्षमता भी है।

एलन क्रैन्स्टन ने अपने दस्तावेज में चीन-पाक परमाणु साठ-गाँठ का जिक्र विस्तार से किया। उन्होंने कहा कि ये दोनों देश एक-दूसरे के फायदे के लिए परमाणु सहयोग कर रहे हैं। चीन पाकिस्तान को 'सैन्ट्रोफ्यूज' बनाने में उठ खड़ी हुई इंजीनियरिंग समस्याओं को हल करने में मदद दे रहा है तो इसके बदले में पाकिस्तान ने चीन को यूरेनियम-संवर्धन की वे विधियाँ और बम डिजाइनों उपलब्ध करा दी हैं, जो डा० वादिर साँ ने हालैण्ड की एक परमाणु भट्टी से पुराई कीं। चीन पाकिस्तान को परमाणु परीक्षण मज्दगी भी बड़े उपलब्ध करा रहा है। चीन पाकिस्तान को परमाणु बम की 'ट्रिगर टेक्नीक' भी मिला सकता है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर एलन क्रैन्स्टन ने अन्त में कहा कि चीन की इस मदद से पाकिस्तान बिना परीक्षण किये परमाणु बम बनाने में समर्थ हो जायेगा।

तब से अब तक यह बात निर्विवाद रूप से प्रमाणित हो चुकी है कि पाकिस्तान

मात्रा में घन जुटाने में सफल रहे। पाकिस्तान जहाँ एक तरफ फ्रांस व अन्य पश्चिमी देशों से परमाणु उपकरण एकत्र करने लगा, वहीं दूसरी ओर परमाणु विशेषज्ञ तैयार करने का कार्यक्रम चल रहा था। उसने उत्कृष्टी व फर्जी कम्पनियों के नाम से बड़े पैमाने पर परमाणु साज-समान हासिल करना भी आरम्भ कर दिया।

इस बीच यह रहस्योद्घाटन हुआ कि पाक वैज्ञानिक डा० अब्दुर कादिर ख़ाँ हार्लैण्ड की एक परमाणु भट्टी से यूरेनियम संवर्धन (Enrichment) की 'सेन्ट्रीफ्यूज विधि' के बारे में चोरी-छिपे जानकारी कर रहे थे। कहते हैं कि उन्होंने अपनी एक डच प्रेमिका की मदद से 'सेन्ट्रीफ्यूज प्रोसेस' की गुप्त कुजियाँ सीख ली और उन्हें यूरेनियम संवर्धन के अत्यन्त परिष्कृत फार्मूले और बम डिजाइनों बुराने में कामयाबी मिल गयी। दिसम्बर, 1975 में वह पाकिस्तान भाग गये, जहाँ उन्हें काहुता के यूरेनियम-संवर्धन संयंत्र का कार्यभार सौंपा गया।

इसके बादबूद अमरीका ने पाकिस्तान की परमाणु तैयारियों को गम्भीरता से नहीं लिया। सम्भवतः उसका ख्याल था कि पाकिस्तान अकेले परमाणु बम बनाने में सफल नहीं होगा। जब दिसम्बर, 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत सशस्त्र सैनिक हस्तक्षेप किया तो अमरीका ने पाकिस्तान को 'सुरक्षा आवश्यकता' के नाम पर 3.2 अरब डॉलर मूल्य की आर्थिक व सशस्त्र की बड़ी सहायता देने की घोषणा कर डाली। मगर अमरीका इस सत्य को नजरअन्दाज कर गया कि पाकिस्तान ने गोपनीय तरीके से परमाणु बम बनाने सम्बन्धी काफी उपकरण व सामग्री एकत्र कर ली है और चीन भी उसके इस प्रयास में बड़े पैमाने पर मदद दे रहा है।

हालांकि फरवरी, 1983 में तत्कालीन अमरीकी उप विदेश मंत्री हारवर्ड स्टेकर ने एक ममदीय समिति के समक्ष दिये गये अपने साक्ष्य के दौरान स्वीकार किया था कि पाकिस्तान परमाणु बम बनाने में सक्रिय है। मगर एक तरफ पाकिस्तान सरकार बार-बार परमाणु बम न बनाने की कसमें खाती रही तो दूसरी ओर अमरीकी प्रशासन यह मानता रहा कि पर्याप्त साधनों के अभाव में पाकिस्तान अतः परमाणु बम बनाने का इरादा छोड़ देगा। उसका यह भी ख्याल था कि पाकिस्तान को दी जा रही 3.2 अरब डॉलर की आर्थिक व सशस्त्र मदद उसे परमाणु बम बनाने के मसूवे से विमुख करेगी।

इस बीच जनवरी, 1984 में चीन अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का सदस्य बन गया, जिससे अमरीका की चीन द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली परमाणु मदद के बारे में आश्चर्य खत्म हो गयी। साथ ही यह आभा की गयी कि चीन अब परमाणु मसले पर सख्त और जिम्मेदारीपूर्ण ढंग से आचरण करेगा। जनवरी, 1984 में ही चीनी प्रधानमंत्री शाओ जियांग ने अपनी वाशिंगटन यात्रा के दौरान भावजनिक रूप से आश्वासन दिया कि उनका देश किसी अन्य राष्ट्र को परमाणु हथियार बनाने में मदद नहीं करेगा।

मगर फरवरी, 1984 में डा० अब्दुर कादिर ख़ाँ ने साहौर के 'भवावे बक्त' नामक अखबार को ब्रीका देने वाला साक्षात्कार दिया। उन्होंने कहा कि 'पाकिस्तान ने कुछ ही वर्षों में 'सेन्ट्रीफ्यूज विधि' के जरिये यूरेनियम सर्वाधिक करने की टेक्नोलॉजी पा ली है, जबकि पश्चिम के देशों को इसे पाने में दो दशक जितना लम्बा समय लगा था।' "इस क्षेत्र में हमने भारत को भी पोछे छोड़ दिया है" हम

दुगुना हो जायेगा। ऐसी परिस्थिति में जरूरत इस बात की है कि भारत जहाँ एक ओर चीन-पाक परमाणु मिलीभगत पर कड़ी नजर रखे, वहीं दूसरी ओर वह अपने समक्ष भोजपद परमाणु विस्फोटों पर पुनर्विचार करे।

रंगभेद की समस्या - दक्षिण अफ्रीका व नामीबिया (Problem of Apartheid South Africa & Namibia)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ समस्याएँ ऐसी होती हैं, जो दशकों तक उलझी रहनी हैं। उनके स्पष्ट मर से अन्य समस्याएँ भी जटिलतर हो जाती हैं। कई वर्ष बीत जाने के बावजूद भी ये समस्याएँ विस्फोटक बनी रहती हैं और ऐसा जान पड़ता है कि राजनय या छापाकार अथवा पारम्परिक युद्ध के माध्यम से भी इनका समाधान नहीं ढूँढ़ा जा सकता। दक्षिण अफ्रीका की सरकार की रंगभेद नीति लगभग आठ दशकों में विश्व के सामने ऐसी ही चुनौती पेश करती रही है।

रंगभेद नीति के तीन बुनियादी पहलू—दक्षिण अफ्रीका के प्रदन के नाथ आरम्भ से ही तीन बुनियादी पहलू आपस में जुड़े रहे हैं। ये हैं—(1) औपनिवेशिक उत्पीड़न और शोषण, (2) रंगभेद की अमानवीय बर्बर 'नीति', तथा (3) साम्राज्यवादी सामरिक पड़ोश। बहुत सक्रिय ढंग से इष्टिपात करने पर यह बात स्पष्ट हो जायेगी कि इन तीनों पहलूओं में आपस में सिर्फ अन्तर-द्वन्द्व ही नहीं है बल्कि ये एक दूसरे को खतरनाक ढंग से पुष्ट करते हैं।¹

रंगभेद समस्या की जड़ें—रंगभेद की समस्या की जड़ें 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में यूरोप से जर्मन और डच औपनिवेशिकों के उम निष्क्रमण (Exodus) तक ढूँढ़ी जा सकती हैं, जिनमें अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से को आबाद किया। आरम्भ से ही इस औपनिवेशिकीकरण और अन्यत्र औपनिवेशिकीकरण में अन्तर था। पूर्वी अफ्रीका हो या रोडेशिया या फिर ब्रिजियायी कायो या फ्रांसीसी मोनालिया, इन उपनिवेशों का अपने स्वामी देश, 'मातृ-पितृ देश' से नाता टूटा नहीं था। मध्यम देश का नियन्त्रण औपनिवेशिक शासकों पर बना रहा और उनका शैक्षणिक, आर्थिक व सांस्कृतिक जीवन पर निर्द्वन्द्व वर्चस्व रहा।

दक्षिण अफ्रीका में स्थिति अपवाद स्वरूप रही। प्रवासी डच और जर्मन, जो आगे चलकर 'बोयर्स' नाम से प्रसिद्ध हुए, दूरी तथा अन्य ऐतिहासिक कारणों से अपने जन्म स्थान से कट से गये। उन्होंने एक नई भाषा और एक विशेष 'अप-यूरोपीय जीवन शैली' विकसित की, जो आज 'अफ्रीकन संस्कृति' के नाम से जानी जाती है। मरिच से जिस भूमि को उन्होंने अपनाया, वह न केवल शस्य श्यामल थी, बल्कि स्वर्ण, हीरो, कोमियम और आगे चलकर यूरेनियम जैसे दुर्लभ खनिजों से समृद्ध थी। दक्षिण अफ्रीका की भू-राजनीतिक स्थिति भी ऐसी थी कि उस अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार या अपनी सुरक्षा के लिए किसी अन्य देश पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी। जब तक अफ्रीकी महाद्वीप में उपनिवेशवादी उथल-पुथल का ज्वार नहीं उठा था, तब तक अल्प-भार्यक यूरोपीय आचरक विशेषाधिकार सम्पन्न व सुविधाभावी शासकों के रूप में निरपवाद रह सकते थे। बोयर्स मूल के अफ्रीकन शासक वर्ग ने अपने स्वार्थ साधने के लिए यह दूरदर्शिता बरती कि उसने मरिच में गरी के लिए खतरा बन सकने वाले सभी तत्वों का नितात बर्बरता से दमन किया।

¹ दवे—Wilfred Butchett, *Southern Africa Stands Up* (Calcutta, 1980)

ने परमाणु बम बना लिया है। भारतीय रक्षा अध्ययन संस्थान के भूतपूर्व निदेशक के० मुब्रहमण्यम हमेशा से यह कहते रहे हैं कि पाकिस्तान को अपने बम के परीक्षण की सामरिक दृष्टि से कोई भी आवश्यकता नहीं है। मुब्रहमण्यम यह बात भी रेखांकित करते रहे हैं कि भारत इस विषय में आश्वस्त नहीं बैठ सकता, क्योंकि रेडियो-धर्मिता आदि के डर से पाकिस्तान परमाणु अस्त्र के प्रयोग से हिचकिचाने वाला नहीं। यह आवश्यक नहीं कि पाकिस्तान भारत के नागरिक ठिकानों पर ही परमाणु हमला करेगा। इसका सबसे बड़ा लाभ तो मनोवैज्ञानिक दबाव डालने वाला होगा। चूँकि के० मुब्रहमण्यम उच्च राष्ट्रवादी भूमिसे जाते हैं, अतः पाकिस्तानी बम-विषयक उनका विश्लेषण अनेक लोगों को अतिरजनापूर्ण लगता रहा है।¹ फिर भी, हात में ऐसे रहस्योद्घाटन हुए हैं, जिनके बाद किसी असमंजस की कोई गुंजाइश नहीं रह गयी है।

प्रसिद्ध भारतीय पत्रकार कुलदीप नैय्यर की पाकिस्तान यात्रा के दौरान पाकिस्तान बम के जनक डा० अब्दुल कादिर खाँ ने उनके साथ एक सनसनीखेज साक्षात्कार के दौरान यह बात 'स्वीकार' की कि पाकिस्तान ने परमाणु बम बना लिया है। बाद में पाकिस्तानी राजनयिकों ने इस बात को लेकर बड़ा धोर भचाया कि कुलदीप नैय्यर ने डा० कादिर खाँ के साथ सिर्फ अनौपचारिक बातचीत की थी और उन्होंने अपने मेजबान के साथ वेषफाई की आदि। पाकिस्तान के कुछ भारतीय मित्रों ने इस बात को तूल दिये जाने पर भारजगी जाहिर की और यह मत सामने रखा कि यह रहस्योद्घाटन सिर्फ राजनयिक रसाकशी का एक हिस्सा था। परन्तु इस बात को मनदेखा नहीं किया जा सकता कि कुलदीप नैय्यर के दृष्टान्त और विश्लेषण में किसी भी बात का 'प्रामाणिक प्रतिवाद' अब तक प्रकाशित नहीं किया गया है। इन्हीं दिनों अमरीकी सीनेट की विशेष समिति की सुनवाईयों में विभिन्न अमरीकी विशेषज्ञों ने यही राय सप्रमाण प्रस्तुत की कि पाकिस्तान बम बना चुका है।

तदुपरान्त डा० परवेज नामक एक और पाकिस्तानी वैज्ञानिक यूरोप में परमाणु गुप्तचरी करते हुए पकड़ा गया। इस प्रकार पाकिस्तानी परमाणु परियोजना मूलला की कोई भी कड़ी अब अख्य नहीं रह गयी है। इन्हीं दिनों यह मुद्दा भी चर्चित रहा कि यदि पाकिस्तान अपने परमाणु संयन्त्रों के अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण-नियन्त्रण के लिए तैयार नहीं होता तो उसे अमरीकी सहायता का हकदार नहीं समझा जा सकता। परन्तु अफगान संकट के रहते और खाड़ी के क्षेत्र में बढ़ते तनाव के कारण अमरीकी सरकार अपने सामरिक दावों के अनुसार पाकिस्तानी परमाणु कार्यक्रम के बारे में जंघी, गुंथी और घुंथी बनी रहने को मजबूर रही।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि पाकिस्तान द्वारा परमाणु बम बनाने की कोशिशों और उसमें चीन द्वारा मदद देने से भारत अप्रभावित नहीं रह सकता, क्योंकि ये दोनों देश भारत के पड़ोसी हैं और इनके साथ भारत के सम्बन्ध गैरौपचारिक नहीं। चीन 1964 से ही परमाणु हथियार सम्पन्न है और यदि पाकिस्तान भी इस सतर्लक परमाणु खिनीले को बना वेला है तो भारत के समक्ष सुरक्षा का खतरा

¹ पाकिस्तानी बम से उत्पन्न सामरिक चुनौती के विस्तृत अध्ययन के लिए देखें—Major General D. K. Palit and P. K. S. Namboodari, *Pakistan's Islamic Bomb*, (Delhi, 1979) 138-150.

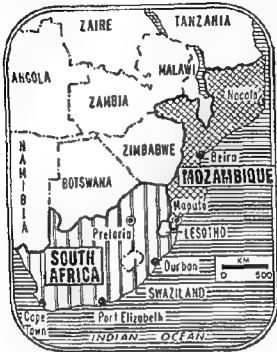
नेल्सन मंडेला इसके एक प्रमुख उदाहरण हैं। जिन लोगों ने मिथिल नाफरमानी का नहीं, बल्कि हिंसक बगावत का मार्ग चुना है, उन्हें अधिक सफलता नहीं मिली। ऐसे लोग कटखत कुत्ते, अथुबैम, घुड़सवार सैनिकों और गोलियों का सामना करते हुए दर्जनों की तादाद में बलि होने रहे हैं। दक्षिण अफ्रीकी सरकार निहत्थे अश्वेतों की निर्भय हत्या से असन्तुष्टों को सबक सिखाने में कभी नहीं हिचकिचायी। छापबिल और मुबतों के हत्याकाण्ड ऐसे ही उदाहरण हैं। समुक्त राष्ट्र सच, राष्ट्रमंडल और गुट निरपेक्ष आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रीय जनमत तैयार कर दक्षिण अफ्रीका की दुष्ट सरकार को दण्डित या अनुसामित करने में पूरी तरह से असमर्थ रहे हैं। राष्ट्रमंडल से निष्क्रामन या अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताओं से बहिष्कार का कोई प्रभाव दक्षिण अफ्रीका पर नहीं पड़ा। इसी तरह समुक्त राष्ट्र सच की आम सभाओं में उसकी निरन्तर भर्त्सना और बर्जना करने वाले प्रस्तावों का अनुमोदन एक वापिक अनुष्ठान भर बनकर रह गये हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आर्थिक प्रतिबन्धों की चर्चा वर्षों में होती रही है, पर अमरीका व ब्रिटेन का सहयोग न मिलने के कारण इनका अस्तित्व नामोल्लेख भर के काम का रह गया है।

जब समुक्त राष्ट्र सच का पूर्ववर्ती मगडन राष्ट्र सच सक्रिय था, तब नामीबिया का विलुप्त प्रदेश 'मेडेट' व्यवस्था के तहत नियरानी और हिफाजत के लिए दक्षिण अफ्रीका को सौंपा गया था। मेडेट व्यवस्था की दुर्बलताओं और कमियों के विश्लेषण का यहाँ अवकाश नहीं, फिर भी इस उत्तरदायित्व के निर्वाह में दक्षिण अफ्रीका ने जितनी बेईमानी की है, वह उल्लेखनीय है। मेडेट व्यवस्था का अर्थ था अधिकृत प्रदेश को आत्म निर्भरता, आर्थिक विकास और स्वायत्तता के लिए तैयार करना। दक्षिण अफ्रीका ने निहायत घूर्तता के साथ चुनावों का दिक्तावा पूरा करते हुए इस भू भाग को एक ऐसे उपनिवेश में बदल दिया, जिसकी दशा किसी भी पारम्परिक उपनिवेश से बदतर बनी। इसी तरह बाटूस्तान तथा स्वाजीलैंड के उदाहरण हैं, जिनकी स्वायत्तता घोषणा पत्रों तक सीमित है। इनका निरूपण ऐसे किया गया है जैसे अजूबे आदिवासियों को नवाइली संग्रहालयों में रखा गया हो और इन पर आसानी से नियन्त्रण रखा जा सक।

दक्षिण अफ्रीका की ताकत

एक सम्बन्ध समय से यह अटकल लगायी जानी रही है कि अग्रिम शक्ति के राष्ट्रों की आजादी के बाद दक्षिण अफ्रीका में मुक्ति संग्राम तेज होगा और इसके दबाव से दक्षिण अफ्रीका में आन्तरिक राजनीतिक दबाव बढ़ेगा। परन्तु कई कारणों से ऐसा नहीं हुआ। अग्रिम शक्ति के अफ्रीकी राष्ट्र सैनिक सामर्थ्य के मामले में दक्षिण अफ्रीका की तुलना में बेहद कमजोर है और अनेक देश भूमिबद्ध हैं। मात्र ऐसे भूमिबद्ध देशों का कुल व्यापारिक सामान का 50 प्रतिशत हिस्सा दक्षिण अफ्रीका के माध्यम से गुजरता है। अफ्रीका में बिछी रेल पटरियाँ का एक-चोपाई हिस्सा दक्षिण अफ्रीका में है और एस रगभेदी देश का छह हजार रेल-डिब्बे अश्वेत देशों का भाग होते हैं। यदि दक्षिण अफ्रीका जवाबी हमले में अश्वेत मजदूरों को काम पर लेना बन्द कर दे तो लेमोयो जैसे देश का 40 प्रतिशत राष्ट्रीय उत्पाद नष्ट हो जायेगा। दक्षिण अफ्रीका की प्रतिश्रियावादी सरकार के पक्षधर गोर अमरीकी एव अफ्रेजों का कहना है कि रगभेद के विरुद्ध मध्यम उत्र करने का बुरा परिणाम होगा,

साथ ही ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय सैनिक गठबन्धन किये जिससे पश्चिमी साम्राज्यवादी देशों का उसे समर्थन मिलता रहे। दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद की यह नीति, जो 'अपारथाइड' (Apartheid) के नाम से कुख्यात है, अश्वजों से लोहा लेने के लिए गांधी जी की प्रेरणा बनी।



दक्षिणी अफ्रीका : समस्या-स्थल

रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष—बीसवीं शताब्दी के आरम्भ के साथ एशिया और अफ्रीका में सर्वप्रथम स्वाधीनता संग्राम तेज हुआ और अन्ततः यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियाँ पापम सौटने को विवश हुईं। किन्तु यह बात दक्षिण अफ्रीका पर लागू नहीं की जा सकी क्योंकि अफ्रीकान लोगों का तर्क था कि उनके लिए 'मातृ-पितृ देश' तोड़कर जाने कि कोई जगह नहीं बची रही है। इसे कुतर्क ही कहा जा सकता है, क्योंकि यदि इन आप्रवासियों की मूल स्थानीय अफ्रीकियों के समतुल्य मान भी लिया जाये तो उनकी भेदभाव वाली नीतियों का औचित्य मिट नहीं किया जा सकता। आज दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले गौरे लोग कुल जावादी के तिरफे दल प्रतिष्ठित हैं, किन्तु ज्ञान, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, भूमि पर स्वामित्व व मतदान सभी क्षेत्रों में उनका दमघोंटू आधिपत्य है। अश्वेत लोग पशुवत जीवन यापन करने को विवश हैं और असहमति का स्वर मुखर करने वाले अफ्रीकी राष्ट्रवादी राष्ट्रीय के सदस्य दशकों तक जेल में बन्द रहे जाते हैं। 28 साल का कारावास मोय भुके

अधिक सतोष का विषय तो यह है कि दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रपति डि क्लार्क ने काफी जोखिम उठाते हुए रंगभेद को क्रमशः समाप्त करने की दिशा में सार्थक कदम उठाया है। खेल के मैदान में नस्लीय भेदभाव का अंतर दृष्टिगोचर हो रहा है। अफ्रीकी मूल के विश्व विख्यात क्रिकेट खिलाड़ी गैरी सोबर्स का दक्षिण अफ्रीकी-दौरा बहुत सफल रहा। उनके बाद सुनील गावस्कर की दक्षिण अफ्रीका यात्रा पर भी भारत सरकार ने कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया। भारतीय फिल्म अभिनेताओं, पार्श्व गायक-गायिकाओं को भी अपेक्षाकृत आसानी से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की अनुमति दे दी गई। इसीलिए कि दक्षिण अफ्रीकी सरकार को यह संकेत मिले कि वह रंगभेद की नीति को समाप्त करे तो उसे पुरस्कृत किया जायेगा। अन्तर्राष्ट्रीय विरादरी उनका बहिष्कार समाप्त करेगी और वह उसे अप्रसन्न नहीं समझेगी। यह स्पष्ट है कि आर्थिक प्रतिबन्ध निषेध और सोच-समझ कर विये गये सयन सम्पत्तियों के सतुलन वाला राजनय ही दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की समाप्ति के लिए कारगर सिद्ध हो सकता है।

नामीबिया की आजादी एवं नई चुनौतियाँ (Independence to Namibia and New Challenges)

अफ्रीकी महाद्वीप में नामीबिया द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति एक ऐसी घटना है जिसका सही ढंग से अन्तर्राष्ट्रीय भूस्थानन किया जाना अभी बाकी है। दशकों तक यह सोचा जाता था कि इस भू-भाग पर दक्षिण अफ्रीका द्वारा इतने जबरदस्त ढंग से जबरन कब्जा किया गया है कि उसका शिकजे से यह छूट नहीं सकता। यह अटकल भी लगायी जाती थी कि भूगर्भीय सम्पदा के दोहन के लिए उत्सुक पश्चिमी राष्ट्र इस मामले में दक्षिण अफ्रीका के साथ अपनी मुनाफाखोर साझेदारी जारी रखेंगे। जंगला या मोजाम्बिक जैसा कोई जुझारू सघर्ष भी नामीबिया में नहीं चल रहा था। बहुदलान, इस सारे घटनाक्रम से यही उजागर होता है कि कभी-कभार ऐतिहासिक प्रवृत्तियों की क्रमशः प्रगति भी निर्णायक बन जाती है। नामीबिया को काफी लंबे सघर्ष के बाद अन्ततः 21 मार्च, 1990 को आजादी मिली।

नामीबिया का महत्व—हीरो, गूरनियम, सोना तथा अन्य कीमती धातुओं जैसी प्राकृतिक सम्पदा से ओत-प्रोत इस देश में मात्र 80 हजार स्वेत नागरिक थे, जबकि जश्नेती की संख्या 13 लाख थी। हालाँकि नामीबिया का पुराना नाम दक्षिण पश्चिम अफ्रीका है लेकिन 1968 में संयुक्त राष्ट्र मध्य में इसका नाम बदल कर नामीबिया रख लिया। प्राकृतिक सम्पदा के अपार भंडार के कारण 17वीं शताब्दी में यूरोपीय देश नामीबिया की ओर आकर्षित हुए, जो विश्व में जगह-जगह उपनिवेश स्थापित करते जा रहे थे। फिर भी, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका को शीघ्र ही उपनिवेश नहीं बनाया जा सका। 1884 में जर्मनी ने नामीबिया को अपना संरक्षित राज्य (Protectorate State) घोषित कर दिया। मगर, पहले विश्व-युद्ध के दौरान 1915 में दक्षिण अफ्रीकी सेनाओं ने जर्मनी को परास्त कर नामीबियाई भू-भाग पर कब्जा जमा लिया।

मेडेट व्यवस्था—1920 में राष्ट्र मध्य ने मेडेट व्यवस्था के तहत प्रशासन चलाने के लिए दक्षिण अफ्रीका को नामीबिया सौंपा। राष्ट्र मध्य के विघटन के बाद भी दक्षिण अफ्रीका ने इसे अपने कब्जे में मुक्त नहीं किया। 1946 में म० रा०

जिसका समियाजा अर्थात् लोगों को भुगतना पड़ सकता है। ऐसे लोगों का मानना है कि क्रमशः मुद्रास्व व दबाव से मुधार के लिए ही प्रयत्न करना होगा।

दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका सरकार स्वदेश में अन्तन्तीय और अन्तर्जनिक का स्वर दबाने में सफल रही है। अनेक संवेदनशील व समतुल्य दक्षिण अफ्रीकी गोरे लोग अन्तर्ज जा चुके हैं। नेल्सन मंडेला जैसे अर्थात् नेताओं को दसको तक जेल में बन्द रहने के कारण अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस की लोकप्रियता को भारी मुक्तान पहुँचा। हम भारतवासी मने ही कुछ भी सोचें किन्तु दक्षिण अफ्रीका में गांधीवादी शान्तिप्रिय व असहयोग आन्दोलन चलाने की कड़ी कठ की वीथ चुनी है।

दक्षिण अफ्रीकी नगरो व कस्बो में हुए हिंसक दंगे एवं भागजनी की बारदावो से यह प्रगट होता है कि युवा अर्थात् लोगों का धर्म चुक गया है। परन्तु दुर्भाग्य का विषय यह है कि उनके मुस्से के जिकार उत्पीड़क गोरे लोग नहीं, बल्कि अपना पैट पातने के लिए गोरो के साथ सहकार करने की नज्बूर इनके ही अर्थात् भाई जन्पु हैं। यह उम्मीद करना व्यर्थ है कि यदि अमरीका, जर्मनी, ब्रिटेन आदि जैसे बड़े देश दक्षिण अफ्रीका से अपनी पूँजी वापस लाना आरम्भ करें तो तेज होते आर्थिक संकट के साथ क्लार्क सरकार घुटने टेकने को विवश होगी। कुछ साल पूर्व कुछ बड़े बहुराष्ट्रीय निगमों और बैंको ने अन्तर्राष्ट्रीय जनमत के प्रभाव में दक्षिण अफ्रीका से अपना कारोबार समेटना आरम्भ किया था, परन्तु धार्मिक उत्तेजना साज होने के साथ ही इनकी सभासना भी बूक बयी। बोपा की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यह था कि वह सकीर्ण राष्ट्रीय-हित के गान पर और भीत पुढ के तर्क दोहरा कर अपने हिमायतियो का भयावोहन करते रहे। मसलन, मारसेट रॉयलर की सरकार, जो मरीची और बेरोजगारी से जूझती रही, यह कठई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि दक्षिण अफ्रीका में तबी समझ सात अरब पीड की उमरी पूँजी मानवतावादी नीतियो के कारण खटाई में पड़ जाये। इसी तरह बोपा सरकार अमरीकी राष्ट्रपति रीगन को अंजीबा में सोवियत सैनिक मलाहकारो की याद दिलाते रहकर अपने अनुकूल करती रही।¹

भारतीय भूमिदा—दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने गुट निरपेक्ष आन्दोलन की एतता में फूट डालने की कोशिश की। उसने मंका में आतीत-सन्स्था जनित यह गुड में भाड़े के सिपाही व सनाहकार अर्थात् रंभेद के कट्टर विरोधी भारत को नम्मे मन्म तक अन्तर्ज उत्तलाये रखने का प्रयत्न किया था। अरनी गद्दी नुरजित रखने की बोपा की रणनीति का एक और पक्ष था। यदि उनकी मन्विपरिपद् का एक सदस्य कट्टरपंथी रस अपनाता था तो दूसरा सदस्य अन्य देशो को भ्रम में डालने के लिए मुधारवादी पंहरा प्रस्तुत करना था। बोपा सरकार दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयो का कुटिलतापूर्ण उपयोग काफी सम्मे समय से करती रही।

भारत रंभेद के विरोध की नीति पर पूँजवत अटल है और यह संवोध का विषय है कि इसके अन्ते परिणाम धीरे-धीरे सामने आने लगे हैं। नानीबिया बाजाद हो चुका है और नेल्सन मंडेला 25 वर्ष जेल में रहने के बाद रिहा हो गए। सबसे

¹ रंभेद की बर्दाश के अन्तर्राष्ट्रीय आगम के बारे में जिल्स रिम्नेन के निरु देवे—
 Mai Palmberg (ed.), *The Struggle for Africa* (London, 1983) and E. S. Reddy, *Struggle for Freedom in Southern Africa: Its International Significance* (Delhi, 1987).

अनुमान के अनुसार इसके लिए उसे 35 करोड़ अमरीकी डालर की सहायता की जरूरत होगी, जिसे जुटाना आसान काम नहीं है। नामीबिया विभिन्न स्रोतों से यह मदद पाने की जी-तोड़ कोशिश कर रहा है। भारत ने उसे 120 करोड़ डालर की द्विपक्षीय मदद देने की घोषणा की।

दुमरी समस्या वहाँ रंगभेदी शासन से पैदा हुए सामाजिक और आर्थिक असंतुलन को दूर करने सम्बन्धी है। जहाँ दक्षिण अफ्रीका ने अपने शासन काल के दौरान नामीबिया में अखेटा के कई गुटों को प्रोत्साहित कर उन्हें आपस में लड़ाया वहीं जनता की आर्थिक हालत सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। वहाँ आज भी तीस प्रतिशत श्रमिक बेरोजगार हैं। अधिकांश अखेट अशिक्षित हैं। वहाँ आजादी के बावजूद नामीबिया की स्वयं अपनी मुद्रा द्वा प्रचलन शुरू नहीं हुआ है। अभी भी वहाँ दक्षिण अफ्रीकी मुद्रा 'रेंड' का प्रचलन है। अतः देश में सामाजिक व आर्थिक असंतुलन का उन्मूलन कोई आसान कार्य नहीं होगा।

तीसरी समस्या नये नामीबियाई संविधान के निर्माण की है। चुनाव में सत्ताधारी स्वापो कृो दो तिहाई बहुमत नहीं मिला, जो प्रस्तावित संविधान को लागू करने के लिए अनिवार्य है। अतः राष्ट्रपति नुयोमा को इसके लिए विपक्षी दलों पर निर्भर रहना पड़ेगा।

नई विश्व अर्थव्यवस्था की तलाश (Search for New World Economic Order)

भारत के प्रधानमन्त्री नेहरू जी ने एक बार कहा था कि 'आर्थिक स्वाधीनता के बिना राजनीतिक आजादी कोई अर्थ नहीं रखती।' वस्तुतः अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल विषय राष्ट्र के आर्थिक हितों का सम्पादन ही है। सांस्कृतिक और सामरिक राजनय की शतरंजी चालें इस राष्ट्रीय हित व सन्दर्भ में ही समझी जा सकती हैं। हाल के वर्षों में आर्थिक राजनय का क्रमग बढ़ता महत्त्व अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वीकार किया जाता रहा है।

नई विश्व अर्थव्यवस्था की पृष्ठभूमि—ऐतिहासिक दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का आर्थिक आयाम द्वितीय युद्ध के बाद तब उद्घाटित हुआ, जब अमरीका ने मार्शल योजना के तहत युद्ध से घबस्त यूरोपीय देशों के पुनर्निर्माण के लिए सहायता कार्यक्रम आरम्भ किया। इसके साथ ही जब अमरीका ने बड़े पैमाने पर विदेशी सहायता की अपनी विदेश नीति के एक बारगार अस्त्र के रूप में प्रयोग किया तो इस त्रियाकलाप के साथ शीत युद्ध के तमाम युक्त जुड़ गये। द्वितीय विश्व युद्ध की परिणति के साथ पारम्परिक उपनिवेशवाद की समाप्ति भी स्पष्ट हुई। दक्षिण नवोदित राष्ट्र उपनिवेश से सम्प्रभु देश में बदल गये। परन्तु इनमें से अधिकांश देश अपने पैरों पर खड़े होने में असमर्थ थे और आत्म निर्भर विकास द्वारा मुद्गर भविष्य में भी स्वावलम्बी बनने के लिए इन्हें बड़े पैमाने पर विदेशी पूँजी और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता थी। 1945 के बाद के 10-15 वर्षों में इन नवोदित देशों का पश्चिमी पूँजीवादी समर्थ-युद्धाचरण राष्ट्रों के साथ एक ऐसा रिश्ता विकसित हुआ, जिसे नवउपनिवेशवादी ही कहा जा सकता है। मुकाबलों और एन्कूमा जैसे अनेक एशियाई नेता, समीर अमीन जैव अर्थशास्त्री और फ्रांज फेनोन जैव समाजशास्त्री

संघ ने बाकायदा मेटेड समाप्ति की घोषणा कर दक्षिण अफ्रीका से नामीबिया को स्वतंत्र करने को कहा, किन्तु दक्षिण अफ्रीका ने उसे नामजूर कर दिया।

संश्लेष संघर्ष—1960 में सैम नुपोमा के नेतृत्व में 'स्वापो' (South-West Africa Peoples Organization : Swapo) नामक संघटन का गठन हुआ, जिसने देश में तेजी से राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन चलाया। समाजवादी और तीसरी दुनिया के देशों ने इस आन्दोलन को नैतिक और भौतिक समर्थन दिया। इस बीच जहाँ एक ओर वहाँ संश्लेष संघर्ष और तेज हुआ, वहीं दूसरी ओर स्वतंत्रता सेनानियों पर दक्षिण अफ्रीकी दमन बढ़ता गया। आजादी की भाग करने वाले इन अल्पसंख्यकों की विरपत्तारियों, हत्याओं और उत्पीड़न का सिलसिला दिन-ब-दिन और तेज होता गया। 1971 में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने नामीबिया में दक्षिण अफ्रीकी कब्जे को अर्द्ध शरारत दिया। साथ ही नामीबियाई आजादी के पक्ष में विश्व जनमत तेजी से तैयार होने लगा। इन दवावों के सहित अन्तः 1972 में दक्षिण अफ्रीका नामीबिया की स्वतंत्रता के भसले को सुलझाने के लिए सं० रा० संघ को मदद देने को सहमत हुआ। इसके बावजूद अपनी बहुराष्ट्रीय निगमों के हितों की रक्षा के लिए अमरीका, ब्रिटेन और कई अन्य पश्चिमी देश नामीबिया पर दक्षिण अफ्रीकी कब्जे और वहाँ की बहुमुखी प्राकृतिक सम्पदा के अर्द्ध दोहन को परोक्ष तथा अपरोक्ष समर्थन देते रहे।

1978 में सं० रा० संघ ने 'स्वापो' को नामीबियाई जनता के एकमात्र प्रतिनिधि संगठन के रूप में मान्यता दी। सुरक्षा परिषद ने अपनी प्रस्ताव संख्या 435 के तहत नामीबिया में युद्ध-विराम की घोषणा की और अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण में चुनाव कराने की बात कही किन्तु दक्षिण अफ्रीका ने चालाकी खेलते हुए स्वयं अपने निरीक्षण में चुनाव कराये और उसमें 'स्वापो' को भाग नहीं देने दिया। हालांकि अन्य अल्पसंख्यकों ने चुनाव में भाग लिया, किन्तु उसके नतीजों को अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली।

जहाँ एक ओर नामीबिया में दक्षिण अफ्रीकी दमन बढ़ रहा था, वहीं दूसरी ओर स्वापो का मुक्ति संघर्ष भी पूरे जोर पर चल रहा था। इस बीच 1988 के आते-आते अंगोला की सीमा पर एम० वी० एन० ए० और न्यूबर्ग सैनिकों से लड़ रहे दक्षिण अफ्रीका की सारी हानि उठानी पड़ रही थी। अमरीकी और सोवियत संघों के कारण भी दक्षिण अफ्रीका रक्षात्मक मुद्रा में आया और अंगोला से न्यूबर्ग सैनिकों की वापसी के एजेंडे में दक्षिण अफ्रीका भी अंगोला और नामीबिया से शरणार्थी ढंग से हटने पर सहमत हुआ। नवंबर, 1989 में सं० रा० संघ के तत्वावधान में नामीबिया में चुनाव हुए, जिसमें स्वापो की बहुमत मिली। मगर यह दो-तिहाई बहुमत नहीं प्राप्त कर पाया।

नई चुनौतियाँ—हालांकि शरणार्थी ढंग से आजादी की घोषणा के तहत राष्ट्रपति सैम नुपोमा के नेतृत्व में सरकार गठित हो गयी और 21 मार्च, 1990 को नामीबिया का स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय हो गया। वह सं० रा० संघ का 160वाँ और अफ्रीकी एकाता संघटन का 51वाँ सदस्य भी बन गया। किन्तु मात्र आजादी में नामीबिया और उसकी जनता को समझाई सत्य नहीं हो गयी। नामीबिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यह सच्चे समय तक चले संश्लेष संघर्ष के कारण क्षत-विक्षत हुई अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करे। एक विद्वत्सन्धीय

अनौपचारिक सगठन उभरे, जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय राजनयिक परामर्श में आर्थिक पक्ष को निरन्तर सामने रखा। अकटाड की बैठकों के अतिरिक्त स० रा० सघ की महासभा के विशेष अधिवेशन नई अन्तर्राष्ट्रीय अव्यवस्था के सन्धान पर केन्द्रित रहे हैं।

(2) गैट का सूत्रपात—सगमय इसी समय गैट (General Agreement on Trade and Tariffs GATT) का सूत्रपात हुआ। मले ही आज तक इस दिशा में सीमित प्रगति हो सकी है, किन्तु इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि इस मंच के माध्यम से नई विश्व अव्यवस्था की तलाश सार्थक ढंग से जारी रखी जा सकी है। व्यापार की शर्तों एवं प्रशुल्को (Tariffs) के बारे में कुछ ठोस प्रगति अवश्य हुई है।

(3) विकासशील देशों की प्रमुख मांगें—संक्षेप में विकासशील देशों की प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं—अपने भू-भाग और नियन्त्रणाधीन समुद्र एवं समुद्री तल में उपलब्ध सभी प्राकृतिक ससाधनों पर अपनी सम्प्रभुता की स्थापना, कच्चे माल की न्यायप्रद व लाभप्रद कीमतें तय करवाना, विकसित देशों से आयात-उपभोक्ता सामान, समान आदि में अनावश्यक मुनाफाखोरी को रोकना, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यवस्था का सामान्यीकरण, विकासशील देशों पर विदेशी सहायता और अन्तर्राष्ट्रीय श्रृण के जानलेवा बोझ को कम करना, समृद्ध-समर्थ देशों के भक्ष्य उत्पीड़क एजेंटों के रूप में बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियों पर अकुल लगाना, और व्यापार की शर्तों में सुधार।

(4) घोषणा पत्र—स० रा० सघ की महासभा ने 1974 में अपने एक विदेश अधिवेशन में नई अन्तर्राष्ट्रीय अव्यवस्था हेतु एक घोषणा पत्र जारी किया और एक कार्यक्रम अंगीकार किया। समाजवादी देशों ने भी इसका समर्थन किया। इसमें उपर्युक्त सभी मुद्दों-मांगों का समावेश किया गया था। स्पष्ट है कि कुल मिलाकर नई विश्व अव्यवस्था की खोज दो-तीन प्रमुख मुद्दों तक सिमटी है जबकि अन्य मांगें उन्हीं का विस्तार या परिष्कार हैं—गरीब राष्ट्रों को उनके ससाधनों की वाजिब कीमत मिले उनके द्वारा खरीदी जाने वाली सामग्री मयत्र आदि में अन्धाधुन्ध मुनाफाखोरी न हो तथा प्रौद्योगिकी का हस्तान्तरण (Transfer of Technology) इस तरह किया जाये कि अन्ततः अफ्रो-एशियाई देशों के स्वावलम्बी बनने की सम्भावना पुष्ट हो। इनके माध्यम से दमघोटू नव-उपनिवेशवादी शिकम्जा न जकड़ा जाये। जाहिर है कि यह सभी सामंजस्य तक प्राप्त नहीं हो सकते, जब तक कि विदेशी सहायता के स्वरूप और अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के प्रियावर्तन बुनियादी तौर पर परिवर्तित नहीं होते। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सुधार भी इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है।

साप्ताहिक परामर्श पर बल—इन सब बातों को मद्दे नजर रखते हुए अफ्रो-एशियाई राष्ट्रों ने अनौपचारिक ढंग से ही महो, यह तय किया है कि विकसित देशों को कृपा पर निरन्तर रहने या उनके सामने याचक की मुद्रा में खड़े रहने की अपेक्षा एकरता में बन है' की उक्ति के अनुसार स्वयं विकासशील देशों में साप्ताहिक परामर्श पर बल दिया जाये, क्योंकि वह उनके लिए लाभप्रद हो सकता है। इसीलिए उत्तर-दक्षिण संवाद (अमीर व गरीब देशों के बीच) की जगह हान के दिनों में दक्षिण-दक्षिण संवाद (विकासशील देशों के बीच) ने ले ली है। 'आमियान', खासी महयोग परिषद और दक्षिण (SAARC) जैसे क्षेत्रीय सहकारक प्रयत्न भी नहीं न नहीं और अन्तर्गत

नव-उपनिवेशवाद के इसी घातक संकट के प्रति तीसरी दुनिया को सचेत करते रहे हैं।

समस्याओं के स्रोत—1960 के दशक के आरम्भ में यह बात मलीनांति स्पष्ट हो चुकी थी कि जहाँ एक ओर मुक्त निरपेक्ष रणनीति और पंचशील वाले समाधान में शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व को प्रोत्साहित किया, वहीं अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में विषमता निरन्तर बढ़ती जा रही थी। अधिकतर विकासशील देश जिस प्रमुख समस्या से पीड़ित हैं, वह है—निर्यात संवर्धन की समस्या—कैसे निर्यात बढ़ाकर आवश्यक उपभोक्ता सामग्री, खयत्रो, सैनिक साज सामान की खरीद के लिए दुर्लभ विदेशी मुद्रा अर्जित की जाये? अधिकांश नवोदित राष्ट्रों के लिए यही विकट चुनौती है। यदि निर्यात में वृद्धि के प्रयत्न किये जाते हैं तो इसका प्रभाव स्वदेश में उपभोग पर पड़ता है और निर्यात को प्रोत्साहित करने को प्राथमिकता के कारण आर्थिक विकास गड़बड़ा कर असन्तुलित हो सकता है।

अन्य समस्याएँ भी कहीं न कहीं इसी से जुड़ी हुई हैं। अधिकतर विकासशील दक्षिण देश विकसित देशों को कच्चे माल का ही निर्यात करते हैं जिसकी बाज़िब कीमत उन्हें नहीं मिलती। गरीब राष्ट्र विकसित देश से जिस सामग्री या आयात करते हैं, वह परिष्कृत औद्योगिक उत्पादन होता है। अतएव समानता व व्यापार पर आधारित नहीं बिद्व अर्थव्यवस्था की माँग अनिवार्यतः इस बात से भी जुड़ी है कि गरीब देशों को अपने उत्पाद या कच्चे माल का बाज़िब दाम मिले और उनको बेचे जाने वाली सामग्री के अन्धाधुन्ध काम मिर्ग मुनाफ़ाखोरी के लिए बनूल न किये जायें।

औपनिवेशिक काल में अधिकतर यूरोपीय देशों ने बहुत बड़े पैमाने पर क्षेत्र विरम के विस्तृत भू-भाग की प्राकृतिक संपदा का निर्बंध दोहन किया गया था। इससे उनको ऐसे उपभोग की आदत पड़ गयी कि आज तक कच्चे माल के आयात से ही उनका व्यापार तीसरी दुनिया के साथ असन्तुलित रहा है। इस असन्तुलन पर काबू पाने के लिए उन्होंने व्यापार की ऐसी शर्तें रखी कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कमजोर देशों पर प्रभुत्व स्थापित करने का एक जरिया भर बनकर रह गया है।

इस तिलतिल में एक और प्रमुख बात उल्लेखनीय है। अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था जिस प्रकार विकसित हुई है, उसमें 'चक्रिय परिवर्तनों' (cyclical changes) पर बहुत कुछ निर्भर करता है। यूरोपीय साक्षा बाज़ार ही या मन्दी-तैजी का दौर, मुद्रा-स्फीति ही या इन सबका समिपाव, इन चक्रीय परिवर्तनों का प्रभाव विकासशील देशों पर भी अधिक पड़ता है। साथ ही विकासमान राष्ट्रों की आपसी प्रतिस्पर्धा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक क्रियाकलाप के क्षेत्र में उन्हें मुकताम पहुँचाती रही है। राष्ट्रमंडल के सम्मेलन ही या मुक्त निरपेक्ष आन्दोलन की बैठकें, सामूहिक आर्थिक हितों की एकता विस्तारशील देशों के सामने उजागर होती रही है और अब तक कुछ मर्ग स्पष्ट रूप से पुत्ती हैं।

समुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में नई बिद्व अर्थव्यवस्था की तलाश

(1) अंकटाड सम्मेलन—1964 में पहला अवटाड सम्मेलन (United Nations Conference on Trade and Development : UNCTAD) आयोजित किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य स० रा० मण के तत्वावधान में समस्या का समाधान ँढना था। इसके माध्य जुडे प्रयासों में हो 'ग्रुप आफ 77' जैसे

को मिलता है वही अन्तराष्ट्रीय यथार्थ में भी प्रतिबिम्बित होता है। वैनपुण शाव हो या परानय का कौशल, बिना सहानुभूति और सहकार के कुछ हासिल नहीं हो सकता। इन स्थिति में नारन का यह कर्तव्य हो जाना है कि वह अपने अन्य विकासशील भाई-बन्धों को इस अभियान में दिखा दे।¹ यह ठीक है कि नई विश्व अर्थव्यवस्था की तलाश का एक पहलू विकसित देशों के साथ जुनारु सवाद वाला है परन्तु यह अनदेखा नहीं किया जा सकता कि इस बारे में तब तक प्रगति अल्पमेव है जब तक कि विकासशील दश स्वयं पारस्परिक सम्बन्धों में वांछित परिवर्तन (वित्त वितरण व्यापार सन्तुलन, प्रौद्योगिकी क हस्तान्तरण आदि के विषय में) नहीं लाते हैं।

तीसरी दुनिया की एकता का सवाल (Question of Third World Unity)

अफ्रीका एशिया, सातीनी अमरीका एव करेबिया क विकासशील देशों को तीसरी दुनिया कहा जाता है जिनमें से अधिकांश देश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशवादी शक्तियों के अंगुल से मुक्त हुए। तीसरी दुनिया के करीब 130 देशों में से 103 राष्ट्र गुट निरपेक्ष हैं एव उत्तरोत्तर कुछ अन्य राष्ट्रों द्वारा भी गुट निरपेक्ष आन्दोलन में सम्मिलित होने को सम्भावना बनी रही है।

तीसरी दुनिया में मतभेद—विगत कुछ ही वर्षों पूर्व तीसरी दुनिया के देशों में आपसी मतभेद एव राष्ट्रों हिता का टकराव गहरे रूप में पाये जाते थे। शीत युद्ध के काल में महाशक्तियों ने इन राष्ट्रों क बन्धों पर बहुत क रखकर उनके आपसी विवादों को उग्र किया जिससे अफ्रीका एव पश्चिमी एशिया क कुछ राष्ट्रों ने हतोत्साहित होकर अपनी सुरक्षा हेतु बड़ी शक्तियों के साथ गुप्त रूप से कई नैतिक व अमैतिक समझौते किए जो कबल बड़ी शक्तियों क राजनीतिक एव आर्थिक व्यापारों क माधन मात्र थे। शीत युद्ध के उक्त वर्षों में तीसरी दुनिया के देशों में विदेशी गुप्तचर संगठनों की गैर-कानूनी हस्तगतों में वृद्धि हुई दो देशों को युद्ध में जोड़कर राक्षसों की नैतिकता की गयी चिली में अत्याद एव अन्य कमजोर देशों को मरकार का अनुचित ढंग में उत्थापन किया गया एव क्यूबा तथा अंगोला में भी महानाशक्तियों ने नहीं प्रयत्न करना चाहा। यदि तीसरी दुनिया में ऐसी विध्वंसकारी प्रतिस्पर्धा को रखा नहीं गया तो समस्त सत्ता उनके ध्वंशपूर्ण आधिपत्य एव गुटबाजी की नीति में ही समाहित होना रहेगा तथा विश्व शान्ति एव सुरक्षा के स्वप्न को कभी साकार नहीं किया जा सका।

अमरीक देशों का शोषक रवैया—अमरीक देशों द्वारा विद्युत देशों का शोषण के पूर्वानुमान बनाने का ग्यान यह इंगित करता है कि उन्होंने राष्ट्रों को अपनी मजदूरी में और वृद्धि करने का उद्देश्य में उनकी आन्तरिक समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए कभी प्रयत्न किया ही नहीं। इसलिए तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को विकसित राष्ट्रों की शोषणकारी प्रवृत्तियों से मुक्ति प्राप्त क लिए अपने आपसे पूरा मजदूरी में गठित होना पडगा। वस्तुतः इन विकासशील देशों को एकता के सूत्र में पिरोन बानी कई कदमों हैं।

¹ नई विश्व अर्थव्यवस्था की तलाश में आरतीय योगदान क लिए देख—J. B. Lal
Struggle for Change International Economic Order (Delhi 1983) 706-25.

नई विश्व अर्थव्यवस्था की तलाश को पुष्ट करने हैं।

नई विश्व अर्थव्यवस्था के मार्ग में अड़चने—उपरोक्त सर्वेक्षण से इस निष्कर्ष पर पहुँचना नादानों होमा कि नई विश्व अर्थव्यवस्था की स्थापना के मार्ग में कोई बाधा या अड़चन नहीं है। जहाँ एक ओर विकासशील देशों के आपसी सकीर्ण हितों का टकराव-महकार और सामूहिक परामर्शों को जटिल बनाता है वहीं दूसरी ओर अनेक विकासशील राष्ट्र विकसित देशों की पूँजीवादो-साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था का अमित्र अनुचर अंग बन चुके हैं। इन्हे आपस समतापूर्ण नई विश्व अर्थव्यवस्था के सधर्प की मुख्य धारा में लाना काफी कठिन काम है। अनेक ऐसे राष्ट्र भी हैं (जैसे ताइवान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया आदि) जिनके लिए आर्थिक स्वावलम्बन या राजनीतिक स्वायत्तता उतनी महत्वपूर्ण नहीं, जितनी कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक वृद्धिवादी। इसकी कीमत ये राष्ट्र पर-निर्भरता के रूप में चुकाने को तैयार हैं। इस तरह के देशों के राजनय से नई विश्व अर्थव्यवस्था की तलाश दिगभ्रष्ट होती रही है।

तेल-उत्पादक देशों का उपेक्षापूर्ण रवैया—इसके अतिरिक्त कुछ और अपवाद हैं, जैसे तेल-उत्पादक अरब राष्ट्र। यह कहना कठिन है कि इनके हित नई विश्व अर्थव्यवस्था के मामले में बाकी तीसरी दुनिया के लोगों से मिलते हैं। बल्कि यहाँ तक कहा जा सकता है कि 'ओपेक' की अदूरदर्शी कारस्तानियों से 1973 से जिन ऊर्जा संकट का विस्फोट हुआ, उसका दण्ड साम्राज्यवादी देशों की अपेक्षा अफो-एशियाई देशों को अधिक भुगतना पड़ा।

अनेक राष्ट्र इन ममूढ़ तेल उत्पादक देशों को रिक्त कर अपना उल्लू सीधा करने के प्रयत्न में लगे हुए हैं। इस्तामो कट्टरपंथिता का उफान हो या राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अराजकतावादी आतंकवाद का समर्थन, विदेशी महायत्ता (वित्तीय या तकनीकी) इसके साथ जुड़ जाती है। अर्थात् एक स्तर पर नई विश्व अर्थव्यवस्था का भन्वान आन्तरिक राजनीतिक दबावों में जुड़ता है तो दूसरी ओर उसे अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं का दबाव सेलना पड़ता है।

इन सभी बाधाओं को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसी तरह विकासशील देशों में धोखीय आर्थिक महकार के प्रचल राजनीतिक टकराव के सामने परास्त होते रहे हैं। ऐसा नहीं जान पड़ता कि निरुद्ध अभिप्राय में नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की तलाश तेज होगी या इन दिना में अप्रत्याशित नाटकीय प्रगति देखने को मिलेगी।

भारत की महत्वपूर्ण भूमिका—नई विश्व अर्थव्यवस्था की तलाश में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के जनतान्त्रिकीकरण में भारत का मार्गक योगदान रहा है। इसके अतिरिक्त स्वदेश में मुनियोजित विज्ञान एवं बहुमुनी-बहुआयामी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों के भारतीय अनुभव से अनेक उपयोगी सबक सीखे जा सकते हैं। संस्थाओं का समूहन हो या प्रांशवाजों का परिष्कार, भारत इस बारे में मतकें रहा है कि उन जैसे नवोदित राष्ट्र को आर्थिक दृष्टि से आत्म-निर्भर एवं स्वायत्तम्भी हो बने रहना चाहिए। इसके अभाव में राजनीतिक स्वतन्त्रता निरर्थक है। इसी कारण नई विश्व अर्थव्यवस्था की प्रमुख माँगों को भारतीय प्रवक्ताओं ने सबसे अधिक कारणर डग से सुवर किया है।

भारत की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक परामर्श में लम्बे अर्थ ने जग लेने वाले राजनयिक के० बी० सल ने यह टिप्पणी गलत नहीं की कि भारतीय उपमहाद्वीप में बेमुमार अमीरी और लज्जास्पद दरिद्रता का जो मह-प्रतिस्व देखने

कर सकते हैं एवं यह पश्चिमी देशों की टेक्नोलोजी के आयात की अपेक्षा अधिक सस्ती एवं दबावमुक्त होगी। असल में, इन देशों में ज्यादा से ज्यादा आपसी लेन-देन, सम्पर्क व सहयोग एकता को बढ़ायेगा एवं यह सामूहिक अन्तर-निर्भरता तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक रंगमंच पर प्रभावशाली भूमिका निभाने का मार्ग प्रशस्त करेगी।

संयुक्त राष्ट्र सघ में तीसरी दुनिया की सख्यात्मक शक्ति—सं० रा० सघ में तीसरी दुनिया के राष्ट्र अपनी विद्याल सख्यात्मक शक्ति से विश्व की बड़ी शक्तियों की गलत नीतियों एवं अहितकारी हथकण्डों से झरी चालों को नाकाम कर सकते हैं। यह अलग खान है कि बड़ी शक्तियों के पास निषेधाधिकार होने से तीसरी दुनिया के देशों को आशातीत सफलता नहीं मिलेगी। फिर भी, उनकी नैतिक विजय अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उनके लिए कुछ लाभकारी रंग ही लायेगी। वस्तुतः उपर्युक्त प्रयत्नों की सफलता को अवश्यम्भावी बनाने लिए संगठित नीति के साथ ही नैतिक माहुर की भी आवश्यकता है। तीसरी दुनिया के देशों को उनमें ही ज्यादा से ज्यादा आपसी व्यापारिक सम्बन्ध कायम करने चाहिए क्योंकि वहाँ अविश्वास एवं अनर्गल दबाव की सम्भावना काफी कम रहेगी। उन्हें सामूहिक आत्म-निर्भरता पर जोर देना चाहिए। तभी तीसरी दुनिया की एकता सम्भव है।

अफगान संकट एवं जेनेवा समझौता (Afghan Crisis and Geneva Agreement)

नए शीत युद्ध के तनाव को सतह पर लाकर विश्व शान्ति के संकट को उजागर करने वाली सबसे प्रमुख घटना अफगानिस्तान में सोवियत सैनिक हस्तक्षेप थी। यह संकट इतना विकट था कि इसने न केवल महाशक्तियों, बल्कि अन्य देशों के बीच भी आपसी कटुता पैदा हुई। दिसम्बर, 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत सैनिक हस्तक्षेप को लेकर दुनिया के कई देश इस हस्तक्षेप का विरोध करने लगे तो अन्य अनेक देश इसका समर्थन। भारत जैसे कुछेक देश एस भी थे, जो इस विरोध व समर्थन के पक्ष में न पड़कर समस्या के दीर्घ राजनीतिक हल पर जोर देते रहे। अफगान संकट को लेकर कटु विवाद लम्बे समय तक चलता रहा और इसके न केवल भारतीय उपमहाद्वीप, बल्कि विश्व राजनीति पर भी दूरगामी असर पड़े। दो आठ वर्ष तक चलने वाला यह संकट 14 अप्रैल, 1988 को जेनेवा समझौते पर हस्ताक्षर से 'समाप्त' हुआ, किन्तु यह सोचना तर्कमग्न है कि समस्या का वास्तविक समाधान अभी बाकी है, क्योंकि विभिन्न मसलों पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है। जेनेवा समझौते के बाद आशा की गयी कि अफगानिस्तान में शान्ति कामम हो जायेगी, मगर वहाँ सरकार और विद्रोहियों के बीच भीषण संघर्ष जारी रहा। इस एह युद्ध की मज्जा दना अतिशयातिपूर्ण नहीं होगा। अतएव, अफगान संकट अविष्य में एक महत्वपूर्ण राजनयिक चुनौती बना रहूँगा। इस संकट को समाप्त करने के लिए सर्वप्रथम अफगानिस्तान का नू-राजनीतिक महत्व स्पष्ट करना जरूरी है।

अफगानिस्तान का नू-राजनीतिक महत्व—19वीं सताब्दी के उत्तरार्द्ध में भूमिबद्ध (land locked) अफगानिस्तान की स्थिति दो विस्तारवादी साम्राज्यों के बीच एक 'बंदर राज्य' की रही। इसी कारण अफगान शासक अपनी स्वतन्त्रता बचाव रणने में सफल रहे। अफगान सम्राट कट्टर व कबाइली है। इसकी भौगोलिक

तीसरी दुनिया की सौदेबाजी की स्थिति—तीसरी दुनिया के देशों के पास अथाह प्राकृतिक सम्पदा होने से विकसित देशों को कच्चे माल की आपूर्ति के सम्बन्ध में उनकी कई प्रकार की इजारेदारी है जिसके औद्योगिक राष्ट्र जरूरतमन्द हैं। यदि कच्चे माल की आपूर्ति, मूल्य निर्धारण एवं वितरण के बारे में तीसरी दुनिया के देश प्रभावशाली नियन्त्रण की नीति अपनाते हैं तो स्वाभाविक रूप से अमीर देश स्वयमेव उनकी आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को समझने के लिए विवश होंगे जिससे उनकी औद्योगिक राष्ट्रों के साथ सौदा करने की स्थिति भी बढेगी। प्राकृतिक सम्पदा का स्वयं द्वारा उपयोग करने के लिए उन्हें स्वयं अपनी स्वतन्त्र तकनीकी का निर्माण एवं सम्पदा-राष्ट्रवाद (Resource Nationalism) की भावना को बल प्रदान करना होगा। तेल-उत्पादक अरब राष्ट्रों ने इन समकालीन वर्षों में विश्व की बड़ी शक्तियों के सम्मुख अपनी एकता प्रदर्शित कर यह स्पष्ट कर दिया है कि कुशल संगठन एवं एकता से क्या-क्या पाया जा सकता है? इनसे तीसरी दुनिया के देशों की प्राकृतिक सम्पदा के भावी सकल के सम्बन्ध में वैकल्पिक विकास के तरीकों की दृढ़ निकासने की दिशा में अभी से प्रयत्न आरम्भ कर देना चाहिए, जैसा कि पश्चिमी देशों ने ऊर्जा खपत को सीमित करने के सम्बन्ध में कुछ नये विकल्प तलाशने शुरू किये। असल में तीसरी दुनिया के राष्ट्र पश्चिमी दुनिया के देशों की अपेक्षा इस सम्बन्ध में अभी बेहतर स्थिति में हैं क्योंकि इन देशों में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत दर कम है।

टैक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत से समर्थन—पिछले कुछ सालों से भारत एवं तीसरी दुनिया के कतिपय अन्य देशों ने कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धतियों अपनाकर अपने खाद्य उत्पादन में अमरवस्तु वृद्धि की है जिससे उनकी पश्चिमी देशों पर खाद्य सहायता की निर्भरता में महत्वपूर्ण कमी हुई है। इसी प्रकार टैक्नोलॉजी के मामले में भारत सहित कुछ अन्य तीसरी दुनिया के राष्ट्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। जिससे ये राष्ट्र अपने साथी पिछड़े राष्ट्रों को तकनीकी मदद देने की स्थिति में हैं। कुछ समय पूर्व जाम्बिया के राष्ट्रपति कॅनेथ कौंडा ने अफ्रीकी देशों को सलाह दी थी कि उन्हें तब-उपनिवेशवादी शक्तियों के बजाय भारत से टैक्नोलॉजी के मामले में मदद लेनी चाहिए। भारतीय सहयोग द्वारा कई देशों में इस्पात, सीमेंट व गन्ना उद्योग के कारखाने लगाने का कदम विकासशील देशों के प्रति उसके सौहार्दपूर्ण एवं सहयोगपूर्ण रुख को उजागर करता है। भारत अपने स्वतन्त्र तकनीकी ज्ञान में लीबिया में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा निर्माण कर चुका है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में भारत ने करोड़ों रुपये की लागत का 'मुपर बर्मल पावर स्टेशन' खड़ा करने का ठेका प्राप्त कर लिया जबकि वहाँ ठेका प्राप्त करने में कई अन्तर्राष्ट्रीय निगमों से तगड़ी प्रतिस्पर्धा थी। इसी प्रकार ईरान में भारतीय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोजन एक पाँच हजार मीटर गहरे तेल के कुएँ की खुदाई एवं इराक में भारतीय तकनीशियन तेल के क्षेत्र खूँडने में कार्यरत हैं।

यह सही है कि विकसित राष्ट्रों के पास तीसरी दुनिया के प्रमुख राष्ट्रों की तुलना में कई गुनी अधिक परिष्कृत एवं उच्च टैक्नोलॉजी है, किन्तु क्या वर्तमान में इन दूरिद राष्ट्रों को ऐसी उच्च परिष्कृत टैक्नोलॉजी की आवश्यकता है जो अपने साथ प्रदूषण एवं अन्य कई प्रकार की गम्भीर समस्याओं को भी उत्पन्न करती है। इन अविकसित देशों की किस प्रकार की टैक्नोलॉजी एवं तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है वह तीसरी दुनिया के प्रमुख देश, जो इस दिशा में विकसित हैं, वास्तव में प्रदान

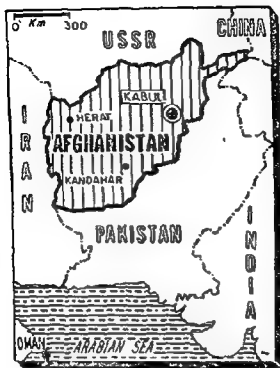
कबाइली सरदारों को उनके क्षेत्रों में समय-समय पर स्वाधीनता दे चुकी थी। ग्रामीण अंचल में जनहितकारी कार्यक्रम कामजो तक सीमित थे। निश्चय ही, यह स्थिति अनिश्चित काल तक नहीं चल सकती थी। बहुत छोटी सख्या में ही सही, वहाँ एक मध्यम वर्ग का आविर्भाव हो रहा था, जिसमें राजनीतिक चेतना के साथ-साथ असन्तोष भी मुखर होने लगा था।¹ इनमें अधिकांश का रुझान समाजवादी-साम्यवादी था। इनमें से अनेक ने सोवियत संघ में शरण ली थी। इन असन्तुष्ट प्रवासी अफगानों ने ही अफगान साम्यवादी पार्टी का गठन किया।

बीस माह में तीन सैनिक क्रान्तियाँ—अफगानिस्तान में राजतन्त्र का अन्त हुआ—27 अप्रैल, 1978 को, जब नूर मोहम्मद तरेकी के नेतृत्व में सैनिक क्रान्ति हुई। तरेकी तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद दाऊद को मत्ताच्युत कर राष्ट्रपति बने। मगर 11 सितम्बर, 1978 को एक और सैनिक क्रान्ति हो गयी, जिसमें हुफीज उल्लाह अमीन ने तरेकी की हत्या कर शासन की बागडोर संभाली। 27 दिसम्बर, 1979 को तीसरी सैनिक क्रान्ति हुई, जिसमें अमीन की हत्या कर दी गयी और बबरक करमाल राष्ट्रपति बने। इस तीसरी सैनिक क्रान्ति के दौरान सोवियत सेनाओं ने अफगानिस्तान में प्रवेश किया और करमाल को गद्दीनशीन करने में मदद की। बीस माह के भीतर अफगानिस्तान में तीन सैनिक क्रान्तियाँ होना अप्रत्याशित घटना थी, किन्तु सबसे ज्यादा विवादास्पद मुद्दा तीसरी क्रान्ति के वक्त सोवियत संघ का सैनिक हस्तक्षेप बना। विश्व जनमत द्वारा सोवियत सैनिक हस्तक्षेप की जमकर आलोचना हुई। सोवियत संघ ने यह तर्क दिया कि तत्कालीन राष्ट्रपति अमीन के निमन्त्रण पर उसकी सेनाएँ अफगानिस्तान गयीं। अमीन ने उससे इस मदद की मांग की थी।

अप्रैल, 1978 में तरेकी के नेतृत्व में हुई तत्तापसद को 'सौर क्रान्ति' की सजा दी गयी। निश्चय ही यह परिवर्तन नाटकीय था और अप्रत्याशित भी। परन्तु बाद की घटनाओं की तुलना में इसे अपेक्षाकृत सहज रूप में ही विश्लेषित किया जाता है। इस 'सौर क्रान्ति' के बाद नए शासक तरेकी ने ध्यापक सामाजिक व आर्थिक सुधारों की घोषणा की और अन्य बाहरी शक्तियों को यह आश्वासन दिया कि अफगान विदेश नीति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह पूर्ववत् गुट निरपेक्ष और महाशक्तियों के बीच सम-सामीप्य रखने वाली बनी रहेगी। स्पष्ट है कि सिर्फ ऐसे आश्वासनों से अमरीका निरापद नहीं रह सकता था। तत्कालीन अमरीकी रक्षा सचिव ब्राउन एंव राष्ट्रीय सुरक्षा मलाहकार ब्रेसेजिन्स्की ने इस सन्दर्भ में सघोलें छानने वाली मुद्रा में बड़े बयान जारी किये और खूब-खूब दरें पर खड़े होकर चुनौती देने वाले अन्दाज में हम ठीकने शुरू किये।

इस बीच एक और अति-नाटकीय परिवर्तन हुआ। सितम्बर, 1979 में तरेकी की हत्या कर उनके एक महयोगी हुफीज उल्लाह अमीन ने सत्ता की बागडोर सम्भाल ली। नए राष्ट्रपति अमीन ने बारीक लगाया कि तरेकी अमरीकी गुप्तचर मस्या मी० आई० ए० के एजेंट थे। अमीन द्वारा मस्ती से समाजवादी क्रान्तिकारी कार्यक्रम लागू किया गया, जिसने अफगानिस्तान की घर्मप्रिय व कबाइली जनता को काफी प्रसन्न किया तथा केन्द्र सरकार के प्रति उनका अनुरोध बढ़ाया। ऐसा मुझाना

¹ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से उपयोगी ऐतिहासिक सर्वेक्षण के लिए देखें—Victoria Schofield, *North-West Frontier and Afghanistan*, (Delhi, 1984),



अफगानिस्तान और उसके पड़ोसी देश

स्थिति भू-राजनीतिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ईरान के बढ़ते महत्व तथा सोवियत संघ के दक्षिणी मुस्लिम-बहुल जनसंख्या वाले प्रदेशों के सामरिक पक्ष को देखते हुए अफगानिस्तान का महत्व बढ़ गया। सिर्फ महानक्तियों के लिए ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय भक्ति-सन्तुलन में भी अफगानिस्तान महत्वपूर्ण पटक बना रहा। पस्तून व बलूच समस्या को लेकर पाकिस्तान के साथ अफगानों का मन-मुटाव रहा। भारत के साथ अफगानिस्तान के सम्बन्ध सोहार्दपूर्ण रहे। अफगान सीमा का एक हिस्सा साम्यवादी चीन द्वारा अधिकृत तिब्बत से जुड़ा है। इस प्रकार 1950 के बाद अफगानिस्तान कालक्रम में अनचाहे ही रूस-चीन विवाद में भी लिख गया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति-सम्पर्क और आन्तरिक दबाव के कारण अफगानिस्तान गुट निरपेक्ष देश रहा है, परन्तु राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक जीवन में उड़ता की स्थिति पिछले दशक तक बनी रही। अफगान सामक वर्ग राजवंश और कुलीनो तक सीमित था। शिक्षा एवं आधुनिकता का प्रसार इसी अल्प-संख्यक वर्ग तक सीमित था। जब तक बाहरी शक्तियों के राष्ट्रीय हित असत रहे, तब तक उन्होंने इस स्थिति में परिवर्तन जरूरी नहीं समझा। अफगानिस्तान में काबुल को छोड़कर नाम लेने लायक कोई नगर नहीं था। केन्द्रीय अफगान सरकार

उसने बबरक करमाल को लाकर अमीन को बिस्थापित किया। यह काम भी बिना सैनिक हस्तक्षेप के हो सकता था, परन्तु बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप के बिना मुजाहिद्दीनों की छापाकारी को नहीं रोका जा सकता था।

लेकिन ऐसा सोचना गलत होगा कि अफगानिस्तान में सोवियत सैनिक हस्तक्षेप सिर्फ 'बचाव की मुद्रा' में किया गया। इसका एक प्रमुख उद्देश्य विश्व को विशेषकर अमरीका को यह जतला देना था कि सोवियत संघ किसी भी तरह दूसरी महाशक्ति से कम नहीं और वह भी अपनी सैनिक-सामरिक शक्ति का प्रक्षेप तत्काल अन्यत्र कर सकता है। यह जतलाना इसलिए भी जरूरी था कि अन्तर्राष्ट्रीय संकट निवारण में अमरीका उसके सहयोग का अवमूल्यन न करे।

विपतनाम जैसा दलदल नहीं—अनेक दक्षिणपंथी अमरीकियों को यह भ्रम था कि अफगानिस्तान में रूसी हस्तक्षेप कालक्रम में 'विपतनाम' बन जायेगा। एक ऐसा दलदल जिससे रूसी बाहर नहीं निकल पायेंगे—एक ऐसा रिसता हुआ नासूर जो तमाम खर्चीली बिबिसा के बावजूद ठीक नहीं हो सकता और जान लेकर ही जाता है। शुरू की घटनाओं ने इस धारणा को पुष्ट किया। घात लगाने वाले अफगान 'मुक्ति सैनिकों' ने बड़े पैमाने पर सोवियत सैनिकों को मारा। राजधानी काबुल को निरन्तर कर्फ्यू में रहना पड़ा और प्रगतिशील विवादात्मक कार्यक्रमों को अन्यत्र लागू करना असम्भव हो बन गया। इन छापाचारों का पीछा करने वाली सोवियत सैनिक टुकड़ियाँ कमी-कमीर पाकिस्तानी सीमा का अतिप्रवेश कर जाती और इससे भी अन्तर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ा। एकाध बार सोवियत सैनिक अफसरों को अफगान मुजाहिद्दीनों ने बन्दी भी बना लिया और उनकी स्वीकारोक्तियों को बहुत प्रचारित किया गया। इस सबका प्रयोजन यही सिद्ध करना था कि अफगानिस्तान में सोवियत सैनिक बड़े पैमाने पर उनकी अपनी इच्छा के विरुद्ध तैनात किये गये हैं और यदि अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप ज्यादा दिन तक चला तो वह बग़ावत की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे सकता है, अर्थात् सोवियत संघ की आन्तरिक राजनीति में इसके दूरगामी घातक परिणाम सामने आ सकते हैं। यह सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी और सेना के सर्वोच्च अधिकारियों के बीच रस्माद्वी को जन्म देकर जारी असंतोष पैदा कर सकता है। इस विषय में एक संक्षिप्त टिप्पणी आवश्यक है। यदि अफगान समस्या के सैनिक समाधान में सोवियत जनरल असफल रहते तो वे पार्टी नेतृत्व की सम्प्रभुता को चुनौती देने की स्थिति में नहीं रह सकते थे। दूसरी ओर वे यह भी कह सकते थे कि अफगान कौबड में उनकी फँसाने वाली पार्टी के नेताओं की मूर्खता का प्रमाण है और जन-धन का ऐसा अपव्यय, जो अमरीका का मुकाबला करने की रूसी सामर्थ्य को घटाता था। दोनों ही तरह से अफगान घटनाक्रम अस्थिरता को बढ़ाने वाला सिद्ध हुआ। भले ही अफगानिस्तान में रूसी हस्तक्षेप नए शीत युद्ध का प्रमुख कारण न रहा हो। परन्तु इसके नष्टाने में उसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही।

अफगान संकट और पश्चिमी देशों की नीति—पश्चिमी अटकलें पूर्णतः सही मानित नहीं हुईं, पर पश्चिमी आचरण ने निश्चय ही यह स्पष्ट कर दिया कि उम्मा अपना राजनय शीत युद्ध की मानसिकता बढ़ाने वाला रहा। उदाहरणार्थ, अमरीका और पश्चिमी यूरोप के देशों में जितनी आसानी और बड़े पैमाने पर बिना किसी जाँच-परख के असन्तुष्ट अफगान तत्वों को धारण दी गयी, वह निश्चय ही इस मद्देह को पुष्ट करती है कि अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप के विरुद्ध प्रतिरोध

अनुचित न होगा कि अमीन द्वारा वल प्रयोग के साथ जिस परिवर्तन की रूपरेखा क्रियान्वित की जा रही थी वह कम्युनिज्म में पोल पोट के नरसंहार का स्मरण दिलाने लगी थी। बिना इस बात की तफ़्तील में जाये कि तरक्की थी० आई० ए० के एजेंट थे या नहीं, इस बात के प्रमाण जुटाये जा सकते हैं कि इसी दौर में बाहरी (पश्चिमी) शक्तियों ने अमीन सरकार के खिलाफ असन्तुष्ट तत्वों को प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया। काबुल से दूरस्थ चीन-अफगान सीमान्त पर 'शोल-ए-बावेद' नामक एक ऐसा मुजाहिद संगठन सक्रिय था, जो अफगानी शरण (Sanctuary) से दक्षिणी सोवियत संघ में मुस्लिम जनता में असन्तोष फैलाने की कोशिश कर रहा था। इसी तरह की घटनाएँ पश्चिमी सीमा पर ईरानी सीमान्त पर प्रारम्भ हो चुकी थी। शहंशाह मोहम्मद रजा पहलवी के पतन के बाद ईरान पश्चिमी सामरिक व्यवस्था के एक मुख्य स्तम्भ के रूप में नहीं बचा रह गया था। इस प्रकार अफगानिस्तान में राजवश के उन्मूलन के बाद ये तमाम परिवर्तन समाजवादी सोवियत हिनों के पक्ष में थे। ऐसी स्थिति में सोवियत संघ के लिए नैजिक हस्तक्षेप का जोखिम उठाना 'अनिवार्यता' नहीं थी। दूसरी ओर इन सब बातों से गुट निरपेक्ष व अफर राज्य के रूप में अफगान भूमि का निश्चित रूप से अवमूल्यन हुआ। तब यह पूछा जाना उचित है कि सोवियत संघ ने दिसम्बर, 1979 में अफगानिस्तान में सेनाएँ भेजना क्यों आवश्यक समझा ?¹

सोवियत सैनिक हस्तक्षेप क्यों ?—कुछ विद्वानों ने यह सुझाया कि तरक्की को अपदस्थ करने वाले अमीन समय बीतने के साथ सोवियत संघ की कठपुतली बनने को तैयार नहीं थे और 'स्वतन्त्र आचरण' करने लगे थे। परन्तु यह बात तर्क-संगत नहीं लगती। यदि ऐसा था भी तो अमीन को तत्कालीन द्वारा अपदस्थ करना कहीं अधिक सहज था। इसके अलावा अमीन अपने कार्यक्रमों के क्रियामयन के लिए सोवियत सहायता पर पूरी तरह निर्भर थे और वह सोवियत समर्थन के अभाव में बचे रहने की बात सोच भी नहीं सकते थे। इन विश्लेषकों का यह भी मानना है कि अमीन ने वस्तुतः सोवियत सेनाओं को आमन्त्रित किया ही नहीं। अमीन के सपाथे के बाद सिर्फ बहाने के रूप में इस निमन्त्रण की बात कही गयी। इस सिलसिले में यह दोहराना जरूरी है कि सोवियत संघ अपने राष्ट्रीय सामरिक हितों की हिकाजत के लिए पड़ोसी स्वाधीन राष्ट्रों में सैनिक दुकड़ियाँ भेजने में कभी हिचकिचाया नहीं है। ऐसी स्थिति में सोवियत सरकार ने अपनी सफाई देने की कमी कोई जबरत नहीं समझी है। हंगरी, चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड इसके अच्छे उदाहरण पेश करते थे। यहाँ यह कहा जा सकता है कि ये तीनों देश रूसी क्षेत्र के 'उपग्रह राज्य' थे, जिनकी सम्प्रभुता सीमित समझी जाती थी। परन्तु ऐसा करना बात की छल निकासना ही होगा क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतन्त्र अफगानिस्तान को भी अन्य शक्तियों ने रूसी प्रभाव क्षेत्र में ही रखा है। ऐसा सोचना अधिक ठीक होगा कि अफगानिस्तान में असन्तुष्ट छापामारों की गतिविधियाँ, जिन्हें बड़े पैमाने पर विदेशी प्रोत्साहन प्राप्त था, न केवल काबुल, बल्कि मास्को के विरुद्ध भी केन्द्रित थी। साथ ही सोवियत संघ यह नहीं चाहता था कि अमीन की कट्टरता का मुक़्तान समाजवादी-समर्थक व सहायक के रूप में उसे उठाना पड़े। सोवियत संघ को अपमान मानसिकता समझने, धीरज रखने वाले और अपेक्षाकृत उदार मध्यममार्गी सहयोग-नेतृत्व की जरूरत थी। इसीलिए

¹ सोवियत हस्तक्षेप के अनुचित निरूपण के लिए देखें—John Fullerton, *Soviet Occupation of Afghanistan*, (Hong Kong, 1983).

प्रवक्ताओं का यह भी कहना था कि लगभग 20 लाख अफगान शरणार्थी उनके देश में रह रहे हैं और इससे उनकी सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था पर अमहनीय दबाव पड़ रहा है। अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप और इसके बाद बढ़ती परिस्थिति को कम से कम पाकिस्तान किसी भी तरह अफगानिस्तान का आन्तरिक मामला नहीं मानता था।

संयुक्त राष्ट्र सच की भूमिका—अफगान संकट के हल में सं० रा० सच ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। उसके छह वर्षों के अथक प्रयासों के फलस्वरूप 14 अप्रैल, 1988, को जेनेवा (स्विट्जरलैंड) में एक समझौता हुआ, जिसे 'अफगान संकट पर जेनेवा समझौते' की संज्ञा दी गयी। अफगान समस्या पर सं० रा० सच की प्रयत्नश्रुति भूमिका की शुरुआत महासभा के 20 नवम्बर, 1980 के प्रस्ताव से हुई। बाद में पाकिस्तान के आग्रह पर सं० रा० सच के महामन्त्रि ने इस प्रस्ताव पर सम्बन्धित पक्षों से बातचीत का सिलसिला शुरू किया। फरवरी, 1981 में तत्कालीन महासचिव कुर्न बाल्दाहीम ने काबुल की यात्रा कर बातचीत के लिए चार सूत्री मसौदा तैयार किया। ये चार सूत्र थे—(i) सोवियत फौज की अफगानिस्तान से वापसी, (ii) पाकिस्तान और अफगानिस्तान द्वारा एक-दूसरे के अदखली मामलों में हस्तक्षेप न देने का आश्वासन, (iii) हस्तक्षेप न देने के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय गारन्टी, और (iv) शरणार्थियों की वापसी। परोक्ष वार्ता का पहला दौर न्यूयार्क में सितम्बर, 1981 में हुआ। उसका नतीजा नहीं निकला।

1982 में पेरेज दि कुयार के महामन्त्रि बनने पर उन्होंने अफगान वार्ता में मध्यस्थता की जिम्मेदारी कार्दोवीज को सौंपी। उनकी मध्यस्थता में जेनेवा में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अगस्त, 1985 तक परोक्ष वार्ता के पाँच दौर हुए। इन वार्ताओं में उतार-चढ़ाव आत रहे।

उधर इसी बीच मोर्जाब्योव सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के महामन्त्रि बने। इसके बाद सोवियत संघ ने अफगानिस्तान से फौज वापसी के बारे में स्पष्ट संकेत देने शुरू कर दिए। मोर्जाब्योव ने अपनी ऐतिहासिक ब्लादीवोस्तक घोषणा में अफगानिस्तान को सोवियत संघ का 'रिमना घाब' बताया। 6 फरवरी, 1988 को मोर्जाब्योव ने स्पष्ट तौर पर कहा कि सोवियत फौज 15 मई, 1988 से वापस होना शुरू हो जाएगी और हम महीने के भीतर यह काम पूरा हो जाएगा। यह काम पूरा हो भी गया।

सं० रा० सच के मध्यस्थ कार्दोवीज ने भी इसी बीच समस्या मुलज्ञान के लिए अथक परिश्रम किया। जनवरी-फरवरी, 1988 में 20 दिन काबुल और इस्लामाबाद के बीच उनकी राजनयिक भागदौड़ इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण रही। इसी के चलते जेनेवा समझौते पर दस्तखत हुए।

जेनेवा समझौता—सं० रा० सच के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप 14 अप्रैल, 1988 को जेनेवा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अन्ततः एक शांति समझौता सम्पन्न हुआ। समझौते पर विद्वत् की दो महासक्तियों अमेरिका व सोवियत संघ ने भी गारंटीदाता के रूप में हस्ताक्षर किए। सं० रा० सच के महासचिव कुयार की उपस्थिति में उक्त चारों देशों के विदेश मंत्रियों ने हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत अफगानिस्तान से सोवियत सेनाएँ 15 मई, 1988 से नौ माह के भीतर हटाने की व्यवस्था की गयी। सोवियत संघ अपने करीब 1.15 लाख

की प्रेरणा 'मौलिक' नहीं। इसी तरह अमरीका ने अब तक पाकिस्तान को अरबों डॉलर मूल्य की जो सैनिक सहायता दी, उससे पैदा होने वाला सकट सोवियत सैनिक हस्तक्षेप से कम जोखिम मंच नहीं था। इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान को सैनिक सहायता और सोवियत हस्तक्षेप में कोई सीधा कार्य-कारण सम्बन्ध नहीं है। भले ही यह बात जोर-शोर के साथ प्रचारित की जाती रही कि अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप दक्षिण एशिया में रूसी साम्यवादी व साम्राज्यवाद के प्रसार की पूर्ण भूमिका है, मगर इस तर्क में ज्यादा दम नहीं। 19वीं सदी के अन्त में 20वीं सदी के पूर्वार्द्ध तक सामरिक विशेषज्ञ यह अटकल लगाया करते थे कि सोवियत विदेश नीति का एक प्रमुख उद्देश्य गरम दक्षिणी जल रानि (Warm Waters in the South) तक पहुँचना है। परन्तु अणु नाभिकीय अस्त्रों से सज्जित पनडुब्बियों से लैस सोवियत मौलिक बंदे के बारे में इस तरह की बातों में कोई सार नहीं रह गया था। साथ ही यह बात नहीं भुलाई जा सकती कि लाठी छेप के बारे में सोवियत रुचि अपने आप ही उपजी, जब तेल-सकट के बाद अमरीका ने खाड़ी के तेल कुपो पर अपना 'आधिपत्य' बनाये रखने के लिए तुरत तैनाती दस्ता (Rapid Deployment Force) प्रस्तावित किया। तभी सोवियत सप नी यह प्रतिक्रिया आरम्भ हुई। यहाँ यह बात उठायी जा सकती है कि किसी भी सम्भावित भटनाक्रम में पाकिस्तान अमरीका से प्राप्त तमाम सैनिक साज सामान के बावजूद किसी भी तरह सोवियत सप से टक्कर नहीं ले सकता था। वस्तुतः अमरीका के लिए पाकिस्तान की उपयोगिता इमेनडोसिक दुर्किमानिरी और भारत की अस्थिर कहने के सम्बन्ध में है। अमरीकी राजनयिक रणनीति इसी के अनुसार गठान्वित होती रही है। कुल मिलाकर, पाकिस्तान की अमरीकी सैनिक सहायता जनरल बिना की तलाशाही मजबूत करने वाली और भारत के विरुद्ध थी। पाकिस्तान को अमरीकी सैनिक सहायता से अफगान समस्या का समाधान नहीं हो सकता था। पहले मजीली दवाओं की तस्करी को लेकर अमरीका और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा था, जिसके परिणामस्वरूप एक बार पाकिस्तान में अमरीकी हवाईबास में आग ली गयी थी। अफगान सकट ने इस विवाद से ध्यान हटाने का काम भर दिया।

अफगान संकट के हल के प्रयास विफल—चीत युद्ध के पहले चरण में ऐसे अनेक सम्भाव्यों के राजनयिक समाधान बूँटे जा सके, परन्तु अफगान सकट के सम्बन्ध में न० रा० संध, गुट निरपेक्ष आन्दोलन और 'टकराने वाली शक्तियों' को प्रत्यक्ष बाटर्पै जड़ता लौटने में असफल रही। जेनेवा साम्ति बातचीतों में राजनयिक दिला का एक नया रूप देवर्न को मिला, जिसे 'सामीप्य का परामर्श' (Proximity Talks) नाम दिया गया। इसमें अफगान और पाक सरकारों के प्रतिनिधि एक जगह तो बैठे, पर आमने-सामने नहीं। इनके बीच 'सवाद' किसी सीधे राजनयिक के माध्यम से जारी रखा गया। परन्तु दस तीसरे व्यक्ति ने मिफे संदेशवाहक की भूमिका निभानी, सहाय्यी मध्यस्थ की नहीं। इस तरह का प्रयत्न इसलिए आधारभूत हुआ कि न तो अफगान सरकार यह मानने को तैयार थी कि उसके आन्तरिक मामलों में पाकिस्तान की कोई भूमिका है एवं उसके साथ सलाह-मशविरे की कोई जरूरत है, न ही पाकिस्तान यह स्वीकार करने को तैयार था कि अफगानिस्तान में राजतन्त्र का उन्मूलन करने वाली किसी सरकार को उगने मान्यता दी। पाकिस्तानी

नामजूर कर दिया था। इस अफगानिस्तान में खून सराब की सभावना बढ गई। इरान में भी करीब 20 लाख अफगान शरणार्थी रह रहे हैं। ईरान पहुँच ही कह चुका है कि जिस समझौते में विद्रोही शामिल नहीं होंगे, वह उसका समर्थन नहीं करेगा।

जनता समझौते में अफगान 'गरणायिया' की स्वीच्छिक स्वयं वापसी की व्यवस्था है। लेकिन मौजूदा परिस्थितियाँ में नहीं लगता कि अफगानिस्तान में उनकी वापसी के लिए स्थिति निकट भविष्य में अनुकूल हो जाएगी।

समझौते में तहत अमरीका और मोवियत सफ़रमस अफगानिस्तान छापामारा और अफगान सरकार का हथियार सप्लाई पर रोक लगाने पर भी सहमत नहीं हुए। जिससे आगे चलकर कभी भी तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो सकती है।

अफगानिस्तान से सावियत सैनिकों की वापसी के बाद यह आगा जंगी की कि अफगान समझौते का समाधान हम सान की राखदा के बाद हो सकेगा। परन्तु मुजाहिदीना न अमर का 'सम ए' निर्णायक हमर (1989) द्वारा जलालाबाद का हथियार के लिए उठाना चाहता। अफगानिस्तान में नजीबुल्ला सरकार के सैनिकों ने यह प्रमाणित कर दिया कि सभी सैनिकों की वापसी के बाद भी वे अपनी रक्षा करने में समर्थ हैं। जलालाबाद की गद्दाई में मुजाहिदीना का जन घन की भारी हानि उठानी पड़ी। बहरहाल अफगानिस्तान में मौजूदा राजनीतिक स्थिति जिस बानी है और निरन्तर भविष्य में शांति स्थापना की सम्भावना क्षीण नजर आता है।

सावियत सभ की साखी मुठ के बाद अन्तर्राष्ट्रीय मान-हानि हुई यह निर्विवाद है। दर-सवर इसका अमर बाबुन सरकार पर पड़ गया नहीं रहे सकता। इस कारण अफगान समस्या का अन्तर्राष्ट्रीय अवमूल्यन हुआ है। रूस हा या अमरीका या भारत, इन सभी के राष्ट्रीय हितों के परिपन्थ में अफगानिस्तान की स्थिति पहुँच जैसी नहीं रही। हाँ, यह जरूर है कि पाकिस्तान का काफी समय तक अपने मीमावर्ती क्षेत्र में अफगान 'गरणायिया' या अमाभाविक और आरंभिक गतिविधियों के प्रति सतक रहना पड़ेगा। अफगानिस्तान की तुलना कुछ कुछ रम्बाडिया के साथ की जा सकती है। दोनों सभट 'गमभग' एक साथ उपद्रव और कुन मिनाकर अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का इहान एन ही तरह में प्रभावित किया है। इन दोनों छोटे-छोटे राष्ट्यों की दुर्भाग्यपूर्ण निमिति यहाँ जान पड़ता है कि धार पीर दुनिया इन्हें मृता दगी। न तो ये मकट रहे और न ही किसी का इस बात की चिन्ता रहेगी कि स्थानाय सदन में शांति का पुनर्स्थापना हुई या नहीं? अब अस्थिरता और उपद्रव का ही स्वभाविक माला जान लगता है।

अफगान संकट के भारतीय विद्वान् नोति—अफगान संकट के पहुँच परण में जब भारत में जनता सरकार का तब से २० स. २० मघ में भारतीय प्रतिनिधि वृत्त मिथ न स्वयं पहुँच कर एन वलव्य के डाता जो बाद में विवादास्पद बना। पर इस 'भूत' का अनावश्यक नून दन की जरूरत नहीं। तत्कालीन अस्पष्ट राजनयिक तथा भारत की आन्तरिक राजनीतिक स्थिति के वलव्य दृष्ट, यह प्रतिनिध्या समझी जा सकती है। तब से अब तक भारत का अफगान नीति की आनाचना इस आधार पर की जाती रहा है कि भारत न सावियत राष्ट्रीय हितों के पराधरता में अपने हितों की निरन्तर रति दी है। गुट निरपेक्ष गिम्बर सम्मेलन के दौरान भारत ने अफगानिस्तान के मामलों पर सावियत सभ का जा समर्थन दिया उसकी भी कटु आलोचना की

सैनिकों में से अधिकतर को 15 अगस्त, 1988 तक अफगानिस्तान से हटाने पर सहमत हो गया। समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले चारों पक्ष इस बात पर सहमत हो गये कि राजनीतिक समाधान के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 15 मई से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा।

अमरीकी विदेश मन्त्री शुल्ज और सोवियत विदेश मन्त्री शेवर्दनात्जे ने समझौते के एक अलग दस्तावेज पर भी हस्ताक्षर किए। इसमें कहा गया कि अमरीका और सोवियत संघ अफगान और पाकिस्तानी मामलों में किसी तरह के हस्तक्षेप से दूर रहेंगे। महाशक्तियों ने सभी देशों से भी ऐसा ही करने का अनुरोध किया। महाशक्तियों ने दोनों देशों के बीच सम्बन्धों को सामान्य बनाने और अच्छे पड़ोसी बनने के उद्देश्य से राजनीतिक समाधान ढूँढने के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के निर्णय का समर्थन किया।

पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने जिस समझौते पर हस्ताक्षर किए, उसके तहत दोनों देश एक-दूसरे की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखण्डता, राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और मुटु गिरपेक्षता का सम्मान करेंगे।

दोनों देशों ने धमकी अथवा दल प्रयोग से दूर रहने का वचन दिया, ताकि एक दूसरे की सीमा का उत्सर्जन नहीं हो, दूसरे की राजनीतिक, सामाजिक अथवा आर्थिक व्यवस्था में बाधा नहीं पड़े अथवा राजनीतिक व्यवस्था को उखाड़ नहीं फेंका जाए।

पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने सकल्प किया कि वे अपने क्षेत्र का उपभोग भाड़े के सैनिकों को भर्ती करने, प्रशिक्षण, उपकरणों के मुसज्जित करने और उन्हें वित्तीय मदद देने के लिए नहीं करेंगे। उन्होंने 'भाड़े के सैनिकों' का अपनी सीमा में आवागमन नहीं होने देने का सकल्प किया।

केवल अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने एक अन्य प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत पाकिस्तान में रह रहे करीब तीस लाख अफगान शरणार्थियों की व्यवस्थित तरीके से स्वदेश वापसी की व्यवस्था की गयी। अफगान सरकार ने शरणार्थियों को स्वतंत्र वातावरण में स्वदेश लौटने की दिया में कदम उठाने का वचन दिया। उधर पाकिस्तान ने शरणार्थियों की स्वदेश वापसी में 'हर सम्भव सहयोग' देना स्वीकार किया।

शान्ति की सम्भावना क्षीण—इस समझौते के बावजूद अफगानिस्तान में शान्ति की सम्भावना क्षीण हो रही है। सम्बद्ध पक्षों के बीच अविश्वास और संदेह बने रहे। जेनेवा समझौता राजनयिक दृष्टि से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण घटना है, परन्तु इसे निश्चित तौर पर अफगानिस्तान में शान्ति की गारंटी नहीं कहा जा सकता। गत लगभग नौ-दस वर्षों से लगातार मर्या और तनाव के बीच जो रही अफगान जनता को सोवियत फौज से 'मुक्ति' तो मिल गयी, लेकिन इससे उसकी समस्याएँ खत्म नहीं हो गयी। समझौते में कई पेंच हैं, जिससे इस पर हस्ताक्षर करने वाले पक्षों की नीयत के बारे में तरह-तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं।

समझौते की सबसे बड़ी कमी तो यह है कि तीन महत्वपूर्ण पक्ष मुजाहिदीन, अफगान शरणार्थी और ईरान इसमें शामिल नहीं थे। मुजाहिदीन ने समझौते को

संस्कृत नाम्मवद के अनन्तर मरु नाम्मवदी अब न पाई और तब के सम्भव न पुनर्वाच्य अवस्थक है। यदि सम्भव की रत्न स्वयं न धनकोनकनों का समुपन यथा दत्त है और उनका काव्यजन बना है तो फिर उनका एकत्र अवसर स्तन बना ही हो नक्य है। यन्तु एक बार यह बात बाहर हो जाने पर पाई कना समक अनन्तरों सम्भव की वद तक बचा पड़े ?

होने पुराव के यथा के बार न तो यह बात बाहर रहा है कि व सम्भव उध न कन पुन स कना उध रहा है—भीनेतक एह उध अवक और मस्त्विक दष्ट से। पालक हनी रत्नवरा वस्तवका पूर्वो यमनी मभी पर यह बात बाहर लाना उठी है। 1970 दल दलक न अब हूकेन्मूनम का बावना या उध नाम्मवद के पष्टीन सम्भवों का यदनपन भी दली सलन म किया जाता रहा है। पन्त नाम्मवद की अवस्था और उत्तम तक चिक पर्व दान तक नानत नता रहा।

चन न कन अन नन चैक की ददन (उन 1989) दल बात की पुष्ट कना है। कि चैन न भी नाम्मव नरर अनजानाव अवन धनकावृषकी के समुपन पर नता बाक समक दलिक बावर पर िकी है। वही भी पाई और तना के रिपु अभी अस्पष्ट है और सम्भव के प्रति अनन्त सेना की प्रवृत्ति निवद नही सनी जा सकता है।

नो तरह एक और मरुव पतु है या पूर्वो दूयन से वृत्तर मदन म लाना होता है। यह भी सम्भव की उध अना रत्नका के अनन्तर पष्टीना के दल (उत्पद्यता के दल) की दलन म उध न हो सका है। 19 0 दल दलक न सलन नोवत उध न उधनी की नुवनन की काव्य कर रह से और दद म दोवन्व न नो विपुलनिना एन्नेना और लानिना बाद दारा स्वाधनता की दाना की कवनत उध के विधान का सवत नना। एन दनपन पर ता बावर नोवत उध न अना कना 1941 के दाननन बनना था। मध्य एरना न कनाकलान वनेतिना अबबाइवन कुनविस्तन उधन बाद की स्थिति भी अन्तर और धरक प्रजानुनी की था। चन विवत पर कबु पन न वजन रहा। और तो और दनवाचना भी मदनना उध की लकर पान रहा है। अनक एव रष्टी की नदता है। कि उनका पाननयम जनताक कानिअ और वानन निनेवन के नन पर किया जाता रहा है। उध अपनी स्थित बाजारक उधनवसा यमी ननी है। 'नननल' और 'पलनका' न नामनत उध न और वन्त दष्टुवद और उत्पद्यवद की प्राप्ताव किया। एन सदन न नो सना और पाई के सम्भव अवत नहवून बन उत है। 'ननन' के और पर अब वननिम्नन न नविनत सना ननी उठी है तो किन दमराय के समक अना पुन दत्त है ? फिर अब इत दमराय न दति और अवस्था नष्ट हाती है ता किन दूर दमराय के समक निपझना के सध सम्भवक हिला पर नबू पात है ? यह सवन भी उधना दना है कि यदि नाम्मवदी दान न तना निरतर इत प्रकार एनिन की विन्यासिनी का निवह कता रही तो प्रविनन न वह का पुस्तकार या विद्वानवर बहरी ?

उन्नी बात अवक नीतना के पुनर्वाच्य और इनन सधन की है।

जाती रही है। मगर स्वयं भारत के 'राष्ट्रीय हितों का संयोग' (Coincidence and Community of Interests) सोवियत हितों के साथ थी। पाक-चीनी-अमरीकी गठजोड़ दक्षिण एशिया में हमेशा ही भारत को नुकसान पहुँचाता रहा है। भारत को इस विषय में अनावश्यक रूप से विनम्र होने या 'रक्षात्मक मुद्रा' ग्रहण करने की कोई जरूरत नहीं। भारत यह स्पष्ट कर चुका है कि वह किसी भी देश के आन्तरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप के विरुद्ध है—विशेषकर सैनिक। परन्तु साथ ही यह जोड़ना जरूरी समझा गया है कि अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप की पूर्व पीठिका और बाद की अस्थिरता-वर्द्धक गतिविधियों को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए।

पूर्वी यूरोप में परिवर्तन व उनके विश्व राजनीति पर प्रभाव (Changes in East Europe and their Impact on World Politics)

बीसवीं सताब्दी के अन्तिम दशक का उद्घाटन अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद के लिए बहुत नासद ढंग से हुआ है। इसके दो-चार वर्ष पहले से ही ऐसे आसार लगने लगे थे कि मार्क्सवाद-साम्यवाद अपनी जुआल ओजस्थिता गँवा चुका है और अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर पूँजीवादी खेल के सामने समाजवादी खेल कमजोर पड़ने लगा है। यों तो ए.एस.एच. कास में सोवियत संघ में घोसवी पार्टी कांग्रेस (1956) से ही संशोधनवादी तैयार हो रहे थे, परन्तु माओवादी चीन ने उग्र प्रातिकारिता के दौर को कुछ समय तक गम रखा।

सोवियत खेल में सबसे पहले और सबसे बड़ी बरार पोलैण्ड ने डाली। यों 1968 में दुवचेक का बेनोस्तीबानिया वह दर्शा चुका था कि पूर्वी यूरोप के देश 20-25 वर्ष बाद भी सोवियत ढाँचे में नहीं ढल सके हैं और इस महाशक्ति का 'उपग्रह' भर बने रहने को तैयार नहीं हैं। इतिहास के पन्ने और पलटने पर 1956 में हुगरी और कमी-कमी पोलैण्ड की बचावत की याव भी ताज़ा की जा सकती है। तीन दशकों तक सोवियत सैन्य शक्ति का आतंक इन सभी 'पूर्वी यूरोपीय उपग्रहों' को अनुनासित रखने के लिए काफी था।

पोलैण्ड में स्थिति जिस तरह विकसित हुई, वह बड़ी विचित्र थी। सत्ताह्व साम्यवादी दल का विरोध असंगुट दक्षिणपथी ख़ान बलि बौद्धिक या जनजातीय भ्रमररूपक नहीं कर रहे थे, बल्कि पार्टी को सबसे कठिन चुनौती सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली ट्रेड यूनियन दे रही थी। 'सोलिडेरिटी' नामक इस ट्रेड यूनियन का नेतृत्व गोडी मजदूर सेव बालेसा कर रहे थे। बालेसा तथा उनके समर्थकों पर यह आरोप लगाना बेहूद कठिन था कि वे अमरीकी एजेंट या वगैरे हैं। ट्रेड यूनियन कर्मचारियों को मागे मुख्यतया आर्थिक ची—रोजमर्रा की जरूरत की चीजें मुहैया कराने और महँवाई घटाने जानी इन मागों के मुखर होने का अर्थ नर था—पोलैण्ड में केन्द्रीय आर्थिक नियोजन का दिवालियापन। बालेसा की चुनौती का सामना करने में पोलैण्ड की साम्यवादी पार्टी बुरी तरह असफल रही और उमने डटे का सहारा लिया। इस बीच संसत्तानायक जनरल जेकबलस्की ने सत्ता की बागडोर संभाली। इससे स्थिति नियंत्रण में भले ही आयी हो, किन्तु पार्टी की जयफलता फिर सती-मोर्ति प्रमाणित हो गयी।

पोलैण्ड की घटनाओं ने विशेषज्ञों को यह सोचने को विवश किया कि

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि अफ्रीका, एशिया और लातीनी अमरीका के देशों को समाजवादी साम्यवादी खेल से महत्वपूर्ण समर्थन और सहायता प्राप्त होती रही। बदल माहौल में इसकी उम्मीद कतई नहीं की जा सकती। बैसे वह तक दिया जा सकता है कि आज इसकी जरूरत भी नहीं रही, क्योंकि दुनिया के सभी देश स्वतंत्र हो चुके हैं। नस्लवादी दक्षिण अफ्रीका तक में गोरे लोगों का रबैया समझाते वाला नजर आने लगा है। परन्तु नव उपनिवेशवादी चुनौती कम खतरनाक नहीं है। सभी अफ्रीकी एशियाई देशों और गुट निरपेक्ष आंदोलन के कर्णधारों को बदले अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अपनी स्थिति के बारे में पुनर्विचार करना होगा।

एक और बात कम महत्वपूर्ण नहीं है। तीसरी दुनिया के अनेक राष्ट्रों की आन्तरिक राजनीति में साम्यवादिया-समाजवादियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वैदेशिक नीति के क्षेत्र में ये मुक्त और प्रभावशाली रहे हैं। मसलन, भारत में साम्यवादियों की धर्म निरपेक्षता भारत-पाक सम्बन्धों को अनुकूलित करती थी और राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को समर्थन देने वाली भारतीय जनता पार्टी का समुल्लेख करती थी।

दो उल्लेखनीय क्षेत्र—सैनिक हस्तक्षेप व शस्त्रास्त्रों की बिक्री और आर्थिक विकास इस सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। अफगानिस्तान में सावियत सघ हो, कम्बुजिया में वियतनाम, वियतनाम में चीन हो या अफ्रीका में ब्यूवा, स्थिति पहले जैसी नहीं रह सकी। इसी तरह, तीसरी दुनिया के राष्ट्र घरों की खरीद के मामलों में समाजवादी विचलन के कारण अपने हितों का साधन बेहतर और किफायती ढंग से कर लेते थे। समाजवादी देशों के साथ शस्त्र व्यापार, अन्तर्राष्ट्रीय सामरिक स्थिति के कारण सहज होता था। फिर ऐसे अनेक ऐसे देश हैं जिन्होंने समाजवादी विचलन राजनीतिक व आर्थिक पुनरचना के लिए चुना था। पर अब समाजवादी विचलन बचा ही कहाँ रहा है?

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक विम्लेषण के मद्देन में साम्यवाद का अन्त हो गया है। मध्यमार्गी समाजवादी युगान्माविद्या में स्लोवानिया और क्रोशिया गणराज्य जिन तरह बगावत व रास्त पर चल पड़े, उससे यही पता चलता है कि यूरोप व एशिया के कारण बृहत्तर पूर्वी यूरोपीय भाग में राजनीतिक उपल-पुचन और विघटनकारी आर्थिक संकट जारी रहेंगे। आज भय ही पोर्नो, हंगरी, चेकोस्लाविया और रूमानिया समाचार पत्रों की मुखियों में नहीं छाय हुए हैं, परन्तु इससे यह नहीं समझा जा सकता कि इन देशों में स्थिति निरापेक्ष है।

भारतीय दृष्टिकोण—वर्ष 1990 और 1991 का यूरोपीय घटनाक्रम भारतीय विदेश नीति निर्धारकों के लिए काफी देर तक एक जटिल गुत्थी बना रहा। जिन पश्चिम यूरोपीय राष्ट्रों के साथ भारत की अच्छी पहचान थी या उनके साथ घनिष्ठ संबंध थे, व यूरोपीय एकीकरण और नवोदय के बाद इस तरह आत्मनिष्ठ और व्यस्त हो जायेंगे कि उनका साथ भारत के लिए बहुत समय या साधन नहीं बचेगा। दूसरी ओर पूर्वी यूरोप के राष्ट्र साम्यवाद के सोवियत दुर्ग' के ढहने के बाद तरह-तरह की विपदाओं और घटनाओं से घिर गए हैं। उनकी राजनीतिक और आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि भारत उनकी ओर एक विचलन के रूप में दृष्टि न करे। युगान्माविद्या हो या रूमानिया हंगरी चेकोस्लाविकिया पोर्नो

चाहे देंग सियाओ पिंग यथार्थवाद के नाम पर चार महान् आधुनिकीकरणों की बात करें, हुकीकत यह है कि समाजवादी अर्थ-व्यवस्था बुरी तरह असफल रही है। इन देशों की उत्पादकता की कोई बराबरी पूँजीवादी व्यवस्था से नहीं हो सकती। पोलैण्ड और हंगरी में ही नहीं, सोवियत संघ में भी खाले-कपड़ों की दुकानों पर लम्बी कतारें लगती थी और उपभोग की वस्तुओं का अभाव लगातार था। रिहायशी मकानों, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव बेहद दुखद था। ऐसी स्थिति में कालाबाजारी व मुनाफाखोरी की घटनाएँ बढ़ी और साम्यवादी दल के प्रति जनसाधारण की आस्था संशय पड़ी। न्यूवा हो या वियननाम, कही भी स्थिति में कोई अंतर नहीं था। बहुसंख्यक युवा पीढ़ी का साम्यवाद से मोह भंग हो चुका था और अश्लीलता, अपराध, उच्छृङ्खलता, भ्रष्टाचार और मूल्यों के क्षय ने समाजवाद के गढ़ की नींव खोसनी कर दी थी। इसी का परिणाम हुआ कि पूर्वी और पश्चिमी यूरोप को विभाजित करने वाली बर्लिन की दीवार उड़ानी पड़ी, और निष्पक्ष चुनाव में हर जगह साम्यवादी दल को मुँह की खानी पड़ी।

एक बात और और करने लायक है। साम्यवादियों का दावा भले ही हमेशा यह रहा था कि व्यक्ति नहीं, विचारधारा महत्वपूर्ण है। व्यवहार में व्यवस्था बेहद व्यक्ति-केन्द्रित रहती रही। लेनिन हो या स्टालिन, झुझेव हो या ब्रेझनेव, माओ हो या देंग सियाओ पिंग, हो ची मिन्ह हो या फिदेल कास्त्रो या फिर अलबानिया में अवर होस्सा, व्यक्ति और परिवार की तानाशाही साम्यवाद का यथार्थ बनते रहे। रोमानिया में चाउसेस्कु का जिन तरह रक्तरेजित बत हुआ, उससे यह पता चलता है कि साम्यवादी तानाशाहों की कुत्सित विलास-शीला किमी मार्कोस को भी लगाने वाली थी।

मरीप में, साम्यवाद जिन पातक कमबोखियों से छुटकारा नहीं पा सका, वह अत्यधिक अमफलता, रोना तथा ट्रेड यूनियन के साथ पार्टी के स्वार्थों के समीकरण बिठाने में असमर्थता और राष्ट्रवाद की समस्या का हल ढूँढ़ने में अक्षमता थे। इन सभी को व्यक्ति-पूजा की प्रवृत्ति, सैद्धान्तिक दकियानुशी तथा बाण्डपूर्ण भ्रष्टाचार ने और भी गंभीर बनाया।

कुछ लोगों ने बचाव पथ के धकील की मुद्रा में यह दलील भी दी कि समाजवाद की इस धोर अमफलता में दोष दुर्वल, भ्रष्ट, दुष्ट अनुभरणकर्ताओं का है, मूल चिन्तक का नहीं। सोवियत संघ में तो यह बात जड़ापी जा चुकी है कि स्टालिन के उत्थान के लिए लेनिन कहीं न कहीं जिम्मेदार है। इस प्रश्न को ठगने में देर नहीं लगी कि वही मार्क्सवाद में बुनियादी खोट है, तभी यह हर जगह हर नये दौर में पयज्रष्ट हुआ है।

दूरगामी अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव—साम्यवाद के ज्हास के अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव दूरगामी थे। भले ही सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका का समरथ कभी न रहा हो, किन्तु सैनिक मामलों में ही जोड़ के कारण आतंक का सन्तुलन विश्व शांति के लिए तानप्रद रहा था। यह एक गंभीर प्रश्न है कि अब बदली परिस्थितियों में मानव का सन्तुलन या तनाव-सौख्य की प्रक्रिया फिर तौमा तक पूर्ववत् गतिशील रहेंगे ?

पूर्वी यूरोपीय देशों की नोबियत साम्राज्यवाद से कितना भी कष्ट पहुँचा हो, या चीन में वियतनाम, कम्बुजिया जैसे को कितना ही खतरा लगता दीखता हो,

परमाणु अस्त्रों के निर्माण व विकसन के क्षेत्र में जारी रही और एक बार आतंक का सन्तुलन स्थापित होने के बाद पूर्वी जर्मनी में लाल रंग का दैत्याकार जनघट उठना महत्वपूर्ण नहीं रहा। परन्तु तब भी यह समझना मतलब होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में विभाजित जर्मनी की समस्या का समाधान हो गया।

अमरीकी और शेष पश्चिमी राष्ट्र इस बात की भत्ती-भौति समझते थे कि साम्यवाद अपनी जड़े आर्थिक अभाव और राजनीतिक अस्थिरता के माहौल में ही जमा सकता है और इन्हीं परिस्थितियों का लाभ उठाकर असतोष-प्रतिशोध की भावना अराजकता पैदा सकते हैं और नव नाज़ीवाद के पैदा होने के लिए जमीन तैयार कर सकते हैं। माघन योजना की रूपरेखा इसीलिए तैयार की गयी थी कि जर्मनी का पुनोत्तर पुनर्निर्माण हो सके। हालांकि यह प्रयोजन सफल रहा, परन्तु इसने जर्मनी को विभाजित करने वाली खाई को और भी खतरनाक ढंग से गहरा किया। पश्चिमी जर्मनी ने आर्थिक रूप से स्वास्थ्य लाभ किया और घामलर आडिनआबर के दूरदर्शी समझदार नृत्व में शोध, क्लेश, अपराध-शोध से नुक्ति पाकर राजनीतिक स्थिरता हासिल की। इसके विपरीत पूर्वी जर्मनी को इस तरह का कोई अनुदान-महायत्ता नहीं मिल सकी। सोवियत संघ ने स्वयं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान उठाया था और वह युद्ध अमरीका से पुनोत्तर पुनर्निर्माण के लिए सहायता की अपेक्षा करता था। विचारधाराओं के टकराव के कारण ऐसा सम्भव नहीं हुआ और स्टालिन युग में पूर्वी यूरोप के अन्य राज्यों की भाँति पूर्वी जर्मनी भी सोवियत समाजवादी साम्राज्य का सीमान्त भर बना रहा।

जर्मनी का विभाजन जर्मनवासियों की इच्छा के प्रतिकूल बलपूर्वक तथा कृत्रिम माघनों से किया गया था। इसे अपनी नियति मानने की जमनवासी तैयार नहीं थे। भिन्न अभाव से बचने के लिए ही नहीं, अपने पारिवारिक जनों से मिलने और नाबात्मक कारणों से भी ज्यादा घुल माहौल में जीने के लिए जर्मन शरणार्थी-धुपपैठिये पूर्व से पश्चिम जर्मनी आते रहे। जहाँ यह प्रकृति सोवियत साम्यवादी व्यवस्था की असफलता को झलकानी थी, वही ५० जर्मनी में बिराजमान अमरीकी सैनिक अधिकारी भी मामरिक दृष्टि से इसे खतरनाक समझते थे। 1961 में ब्यूबा में 'व आफ पिग्न' प्रकरण और चीन-रूस विवाद उभरने के माघ शीत युद्ध-जनित मकट और गम्भीर हो गया। यु-2 विमान बाड (मई, 1960) के कारण बर्लिन में बरुइच और कैनडी का शिखर सम्मेलन स्थगित हुआ और कैनडी ने "मैं भी बर्लिनवासी हूँ" की घोषणा कर आक्रामक तैयार अपनाये। इसके बाद जर्मनी के विभाजन को और भी दुःखादायक और अपमानजनक ढंग से स्थायी बनाने का प्रयत्न किया गया। बर्लिन शहर के बीचो-बीच एक दीवार का निर्माण किया गया, और इस कुरूप बाधा की अनधिकृत रूप से पार करने वालों को बहिष्कृत मोत के घाट उतारा जान गया। चक प्वाइड चार्ली शीत युद्ध के इतिहास में माई माई के जैसा हो बदनाम स्थान है और 'फूगुरल इन बर्लिन', 'दि स्पाई हु बेम इन काल्ड' जैसी माहुरितिक फिल्मों की कृतियों इस वरण गाथा का ऐतिहासिक दस्तावेज बन चुकी हैं। परन्तु ये सार प्रयत्न जर्मनी के एकीकरण के लिए मन्त्रिय राष्ट्रवाद की भावना पर विजय नहीं पा सके। दीवार के नीचे मुरख खोदकर या इसके ऊपर गुब्बारे में उड़कर पश्चिम जर्मनी तक पहुँचने वाला की मम्पा नने ही बहुत कम हो, किन्तु प्रतीक के रूप में इसका महत्व बड़ा था।

या फिर पारम्परिक रूप से तटस्थ समझे जाने वाले नाबो, फिनलैंड, स्वीडन आदि किसी के साथ नई पहल या पुराने सम्पर्कों को ही पुष्ट करने की संभावना दृष्टिगोचर नहीं होती। इस समस्या का सबसे क्लेशदायक पक्ष यह है कि आज जब भारत विश्व बैंक के दबाव में अपनी अर्थव्यवस्था को तभीला और उबार बना रहा है और उसे बड़े पैमाने पर विदेशी पूँजी और टेक्नोलॉजी की जरूरत है, किन्तु यूरोपीय स्रोत पहले जितना सुलभ नहीं रह गया है।

जर्मनी के एकीकरण का मसला (Issue of German Unification)

सदियों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जर्मनी एक महत्वपूर्ण घटक रहा है। यूरोपीय इतिहास में पाँच बड़ी शक्तियों में उसकी गिनती निरन्तर की जाती रही है। 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मनी ने यूरोप में व्याप्त शक्ति-सन्तुलन के पारम्परिक सिद्धान्त को ठुरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया और प्रथम विश्व युद्ध के विस्फोट तक कैसर विलियम की सैनिक महत्वाकांक्षा और साम्राज्यवादी विस्तारवाद बेमिसाल हो चुके थे। प्रथम विश्व युद्ध में पराजित होने के बाद जर्मनी का अंतर्राष्ट्रीय अवगूह्यन हुआ, परन्तु यह स्थिति सिर्फ एक दशक तक ही बनी। राष्ट्र संधि वाला प्रयोग असफल रहा और हिटलर के नेतृत्व में जर्मनीवासी युद्ध-मुआवजे और जर्मनी के बर्सात निःशस्त्रीकरण की अत्यायपूर्ण शर्तों का विरोध करने के लिए एकजुट हो गये। नाजीवाद के उदय के माध्यम जर्मनी ने पुनः एक बड़ी शक्ति के रूप में अपना एक अलग स्थान बनाया और उसका विस्लेषण विश्व शान्ति के लिए बड़े खतरे के रूप में किया जाने लगा।

द्वितीय विश्व युद्ध का घटनाक्रम सर्वविदित है और उसे यहाँ दोहराने की जरूरत नहीं। इतिहास का पहला पूरा घूमा और 1945 में जर्मनी को फिर एक बार सर्वनाशक पराजय का भूँह देखना पड़ा। इस बार मित्र राष्ट्र यह खतरा उठाने को तैयार नहीं थे कि जर्मनी फिर अपना तिर उठा सके। इसलिए परास्त-व्यस्त जर्मनी का विभाजन कर दिया गया। जर्मनी के लिए पूर्वी हिस्से (पूर्वी जर्मनी) पर सोवियत सार सेनाएँ काबिज थीं। वह उन्हीं के प्रभाव क्षेत्र में रहा और समाजवादी धर्म का 'उपग्रह' बन गया। जर्मनी का पश्चिमी भू-भाग (पश्चिमी जर्मनी) तिस्रें जनरल आइजनहावर की सेनाओं ने 'आजाद' कराया था, पराजित शत्रु होने के बाद भी पश्चिमी पूँजीदार खेमे में अपेक्षाकृत आसानी से दाखिल हो सका। राजधानी बर्लिन को चार टुकड़ों में विभाजित किया गया, जिन्हें चार विजयी राष्ट्रों—अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संध ने—अपने-अपने कब्जे में कर लिया। शीत युद्ध की कड़वाहट ने जर्मन राजनीतिक जीवन को विपात कर दिया। आरम्भ में सोवियत संध ने एकाध बार यह प्रयत्न किया कि बर्लिन में शक्ति-सामर्थ्य के प्रदर्शन के द्वारा पश्चिमी खेमे पर यह दबाव डाले। 1948 में बर्लिन की नाकेबन्दी इगो उद्देश्य से की गयी परन्तु जब अमरीका ने अपनी वायुसेना की शक्ति के प्रयोग से इन पराबन्दी को नाकाम कर दिया तो सोवियत संध को यथा-स्थिति स्वीकार करने की विवश होना पड़ा। इस बर्लिन मरुट के बाद महाशक्तियों की होठ

सुपर-301 पर भारत व अमरीका में मतभेद (Indo-U.S. Relations : Super 301)

यह एक विधिवत विडंबना है कि भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के आपसी सम्बन्ध जब कभी सामान्य होने लगते हैं तो कोई न कोई नया अड़ंगा या तनाव इन्हें असन्तुलित कर देता है। इसका सबसे ताजा उदाहरण सुपर-301 विवाद है।

सुपर-301 है क्या ?—विज्ञान-फ़तासी कथाओं की सन्दावली याद दिताने वाला सुपर-301 ओम्नीबस ट्रेड एक्ट, 1988 का एक प्रावधान है, जिसके अनुसार अमरीका किसी भी देश को विदेश व्यापार के क्षेत्र में 'अवरोध' लगाने के कारण दोषी ठहरा सकता है। इसके बावजूद यदि 8 महीने के अन्दर ये अवरोध हटाये नहीं जाते तो उसे दंडित करने के लिए उसके विरुद्ध अमरीका उस देश से आयातों पर शत-प्रतिशत निषेध लगा सकता है तथा अन्य प्रतिबंध भी। सुपर-301 का हौष्वा पैदा करने के लिए अमरीकी नीति निर्धारक समय-समय पर अपने दुरमनो की एक निम्नाना सूची (Hit List) तैयार करते रहते हैं और पुनः ही इन नामों को अलबारी में 'लीक' करते रहते हैं ताकि उन देशों पर राजनयिक दबाव डाला जा सके।

सूची में नाम—अमरीका ने मई, 1989 में उक्त निम्नाना सूची में जापान, ब्राजील और भारत का नाम रखा और चेतावनी दी कि यदि इन देशों ने 'अवरोध' नहीं हटाये तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। किन्तु मजबूत बात यह है कि जब अमरीका ने अप्रैल, 1990 में दूसरी सूची प्रकाशित की तो उसमें 'दो प्रमुख दोषियों'—जापान और ब्राजील का नाम काट देने के बाद भी भारत का नाम बचा रहा। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अहंकारी अमरीकी नीति निर्धारक भारत को अनुशासित करने के लिए वैर-आधिकारणों से सुपर-301 की दुहाई देते रहे हैं। विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा निर्यात के मामले में 0.50% और आयात के मामले में 0.75% है, जबकि हमारी आवादी को देखते हुए भारत का आयात-निर्यात 17% होना चाहिए। अमरीकी प्रतिनिधि कार्लो हिस्स ने बारम्बार इस बात पर जोर दिया कि अमरीकी व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए सुपर-301 पर सख्ती से अमल करना जरूरी है। परन्तु इन तर्कों ने कोई दम नहीं। आखिर हर सम्प्रभु राष्ट्र को अपनी आर्थिक नीतियों का नियोजन अपने राष्ट्रीय हितों के सन्दर्भ में करने का अधिकार है।

पूँजी निवेश व औद्योगिक सम्पत्ति से सम्बन्ध—सुपर-301 के तिलतिले में दो और बातों की तरफ ध्यान देना परमावश्यक है। इसके प्रावधानों का सीधा सम्बन्ध पूँजी निवेश और औद्योगिक सम्पत्ति से जुड़ा है। भारत में विदेशी पूँजी निवेश की सरकार नियंत्रित करती है। कोई भी विदेशी कम्पनी, जब तक वह टेक्नोलॉजी के सीमान्त पर काम न कर रही हो, 51 प्रतिशत से अधिक निवेश नहीं कर सकती। इसके अलावा भारत में विदेशी कम्पनियों का प्रवेश उन क्षेत्रों में बहिष्कृत है, जिनमें लघु उद्योगों के लिए आरक्षित रखा गया है या जो सेवा-क्षेत्र (Service Sectors) वाला है। कोला कोल, पंपी कोला आदि कम्पनियाँ इसी भारतीय नीति के तहत भारत में स्वैच्छानुसार अपना आरोबर नहीं फैला सकीं। अपनी 'इक्विटी' को भारतीय निवेशकर्ताओं के साथ बांटने (Dilute) में इन्कार करने के कारण आई० बी० एम० की भी भारत से पला जाना पड़ा। सिर्फ हिन्दुस्तान सीवर ने अद्भुत

विली ब्रांट के चासत्तर होवे-होते पश्चिम जर्मनी एक बार फिर पश्चिमी राष्ट्रीय विरादरी का सम्मानित सदस्य बन चुका था—सम्बन्ध और विश्वासपात्र। विली ब्रांट ने अपनी 'ओस्त पोलिटिक' की नीति अपनायी। उन्होंने साम्यवादी सेन के साथ सदाद आरम्भ किया तथा जर्मनी के एकीकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम लिया। इसके बाद से यूरोपीय समुदाय की एकता और बढ़ी और 1990-91 में पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के पतन ने जर्मनी के एकीकरण के सपने को यथार्थ में बदल दिया। परन्तु तब भी यह सोचना गलत होगा कि जर्मन-एकीकरण से अमरीका व अन्य पश्चिमी राष्ट्र आश्वस्त हैं।

पिछले कई वर्षों से जर्मनी में जब नाज़ीवाद का कुल्लु भेहरा दीखता रहा है। इसका नस्तवादी स्वरूप काफी भयावह है। हिटलर के अधीन जर्मन विस्तार की कीमत पोलो, चेकोस्लोवाकियों को चुकानी पड़ी थी। जापानी प्रधानमन्त्री ने 1990 में दक्षिण कोरिया को याना के शोरान युद्ध-अपराधों के बारे में जैसी क्षमा पाचना की थी, वैसी कोई मुलह की मुद्रा जर्मनी ने नहीं अपनायी है।

अमरीका को चिन्ता इस बात को लेकर है कि एकीकृत जर्मनी उसके लिए और बड़ा आर्थिक निरदद बन जायेगा। उधर यूरोपीय समुदाय के और सदस्यों को अपने संगठन के असन्तुलित होने का खतरा है।

स्वयं जर्मनी वासी के लिए एकीकरण नई परेशानियों को साथ लाया है। आर्थिक स्तर, राजनीतिक प्रणाली और सामाजिक संस्कार के सन्दर्भ में कोई साम्य पिछले लगभग साढ़े चार दशकों से पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के निवासियों के बीच नहीं रहा। ऐसे में राजनीतिक एकीकरण के बाद भी नए राष्ट्र का सुचारु रूप से कार्य करना कठिन है। क्या एकीकृत जर्मनी अपने भू-भाग पर विदेशी (अमरीकी) सैनिकों की मौजूदगी बर्दाश्त करेगा? इनकी उपस्थिति और मँसले भार वाले प्रशेनास्यों की सँनाती जर्मनी की स्वायत्तता-स्वाधीनता के साथ प्रतीकारमक रूप से जुड़े हैं। अब तक यूरोपीय समुदाय का नेतृत्व फ्रांस के हाथों में था, परन्तु अब एकीकृत जर्मनी के बाद इसे निर्विवाद नहीं माना जा सकता। और जर्मनी के एकीकरण के बाद अमरीका के सम्बन्ध यूरोप और जापान के साथ कैसे रहेंगे? जर्मनी और फ्रांस के परस्पर सम्बन्ध क्या होंगे? क्या पूर्वी जर्मनी के विलय के बाद पश्चिमी जर्मनी मनुष्य और स्थिरता बनाये रखेगा? जर्मनी का रुझान और जॉर हमेशा से औद्योगीकरण पर रहा है। इसके विपरीत धरा में महत्वपूर्ण राजनीतिक सबके कृषि क्षेत्र पर जोर दे रहे हैं। कृषि और प्रौद्योगिकी का सन्तुलन और अन्तराष्ट्रीय समीकरण जर्मन-एकीकरण से घनिष्ठ रूप से प्रभावित होंगे। किन्तु अभी नहीं कहा जा सकता है कि कैसे?

अब तक भारत के सम्बन्ध दोनों ही जर्मनियों के साथ मधुर रहे, किन्तु हमें यह जय नहीं कि भविष्य में भी ये अनामान पूर्णवत् रहेंगे। अन्य राष्ट्रों की तरह हमारे लिये भी एकीकृत जर्मनी के बारे में अपने राष्ट्रीय हित के सम्बन्ध में पुनर्विचार करना परमावश्यक है।

चलते ही रहेंगे। भारत में विदेश व्यापार तथा औद्योगिक नीति को उदार बनाने के फैसलों की घोषणा के बाद यह सोचा जा सकता है कि अमेरिका को भारत के प्रति ज्यादा शर्क-संकोच नहीं रहूँगा। हाँ, यह बात बिल्कुल फर्क है कि इस तनाव-शैथिल्य से भारतीय विदेश नीति की स्वाधीनता पर कौन से दूरगामी परिणाम-प्रभाव पड़ेंगे।

सोवियत संघ का विघटन और संभावित इस्लामी महासंघ का प्रस्ताव (Dissolution of USSR and the Proposal of Islamic Federation)

7 नवम्बर, 1917 में सोवियत संघ की स्थापना की गई थी। मन् 1921 में लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की और 1922 में स्टालिन को कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बना दिया गया। 1924 में लेनिन का स्वर्गवास हो गया। उसके बाद स्टालिन को उसके पद में हटाने की हर कार्यवाही बेकार गई। 1926 में स्टालिन ने 'एक देश में समाजवाद' (Socialism in one country) का सिद्धान्त प्रतिपादित किया। 1953 में स्टालिन की मृत्यु हो गई और छुश्चेव को पार्टी का महासचिव चुनवाया गया। 1956 से छुश्चेव ने स्टालिनवाद को अपमानित करना



बेलारूस, मोल्दोविया, यूक्रेन, आर्मीनिया, अज़रबाइजान, तुर्कमेनिस्तान, अज़र्बैजस्तान,
उझबेकिस्तान, किरगीजिया, कजाखस्तान और रूस

रूस का नया राष्ट्रकुल (C.I.S.)

दुरदस्तिता का परिचय देते हुए पूँजी निवेश और प्रबन्ध-नियंत्रण के मामले में रियायतें हासिल की, मगर इस कम्पनी को भी सखुन, तेल, वनस्पति वाले अपने कारोबार को उच्च टैक्नीलॉजी, शोध आदि से अलग करना पड़ा।

विदेश बैंक का भी दबाव—अमरीका का ही नहीं, विश्व बैंक का भी भारत पर इस बात के लिए निरंतर दबाव रहा है कि वह विदेशी कम्पनियों को शत-प्रतिशत तक पूँजी निवेश करने दे और उन पर लगे नियंत्रणों को समाप्त करे।

अमरीकी शिकायतें गैर-वाजिब—भारत के बारे में अमरीका की सारी शिकायतें गैर-वाजिब हैं। इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि पिछले दशक में भारत की आर्थिक नीतियाँ क्रमशः लचीली हुई हैं और विदेश व्यापार के क्षेत्र से तरह-तरह के अवरोध हटाये गये। बल्कि उदारवादी नई उद्योग नीति की कड़ी आलोचना स्वदेश में इस आधार पर हुई कि भारत शायी-नेहरू के बताये रास्ते से विचलित हुआ है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि अमरीकी हित साधन के लिए भारत बिल्कुल ही घुटने टेक दे। एक बार आर्थिक स्वावलम्बन छोड़ देने के बाद वैदेशिक मामलों में राजनीतिक स्वायत्तता-स्वतंत्रता बेमानी हो जाती है।

इसी तरह बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार वाला प्रकरण है। इस मामले में सबसे ज्यादा गैर-जिम्मेदार और अपराधपूर्ण आचरण सिंगापुर का रहा है। उससे शिकायत करने के बदले भारत के साथ अमरीका द्वारा इस तरह का आचरण करना समझ में नहीं आता।

यह बात भी सर्वविदित है कि भारत में बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण वर्षों पहले कर दिया गया था। विदेशियों को आज इसमें प्रवेश का मौका देने का प्रश्न ही नहीं उठता, जबकि अमरीका अपनी कम्पनियों को भारतीय बीमा उद्योग में कारोबार करने की छूट चाहता है।

एकता नष्ट करने का प्रयास—यदि तर्कसंगत विस्तेषण का प्रयत्न किया जाए तो अमरीकी आचरण का सिर्फ एक ही कारण दृष्टिगोचर होता है। भारत विकासशील राष्ट्रों का मुखर प्रवक्ता है। उसके नेतृत्व में, जैसा कि उद्घवे-वार्ता के दौरान जाहिर हुआ, अन्य विकासशील राष्ट्र भी सामूहिक रूप से हित साधन की बात उठा सकते हैं। भारत को दंडित किये जाने पर इन सभी देशों का मनोबल कमजोर होगा और उदीयमान एकता को नष्ट किया जा सकता है।

यदि जापान को सुपर-301 के दहत दोषी कथार कर दंडित करने का प्रयत्न किया जाता तो जापान ऐसी जवाबी कार्रवाई करने की स्थिति में है, जो अमरीका को नुकसान पहुँचा सके। मगर अमरीका को भारत से ऐसा कोई खतरा नहीं।

सिरदर्द दूर नहीं—भारत और अमरीका के बीच सुपर-301 पर सकट फिट-हाल टल गया है। किन्तु यह सोचना बसत है कि भारत का सिरदर्द सदैव के लिए दूर हो गया है। भविष्य में सुपर-301की प्रेत बाधा भारत-अमरीका सम्बन्धों को कभी भी नुकसान पहुँचा सकती है। इनके अतिरिक्त हाल के दिनों में प्रेसखर सशोधन का होना भी भारत के ऊपर छाया हुआ है। इस सर्वधार्मिक उपाय का प्रावधान यह है कि परमाणु अस्त्रों के निर्माण में रत किसी भी देश को अमरीकी सहायता नहीं दी जा सकती। इस निषेध से निजात पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि स्वयं अमरीकी राष्ट्रपति इस मामले में निर्दोष होने का पारिवर्तक प्रमाण पत्र उस राष्ट्र को दे दें। ऐसी कृपा अपवाद के रूप में ही की जाती है। बहरहाल, ये सब सिरदर्द तो

हैं। वे अपनी परिस्थितियों और अपने यहाँ की सामाजिक-राजनीतिक शक्तियों के समीकरणों के अनुरूप नीतियाँ निर्धारित कर रहे हैं। आवश्यक नहीं कि उनके तिर्ण्य सदैव सही ही रहे, किन्तु गलतियाँ भी अब उनकी अपनी होगी। उनके लिए वहाँ के शासक अपने देशवासियों के प्रति उत्तरदायी होंगे। गीर्वाण्योव की एक ओर बड़ी उपलब्धि रही कमोबेश शान्तिपूर्ण ढंग से पुरानी सोवियत राजनीतिक प्रणाली का अवसान और उसकी जगह नयी राजनीतिक प्रणाली का उदय।

नए राष्ट्रकुल (CIS) में सभी 11 सदस्य बराबरी के दावों से रहेंगे। लेकिन वास्तविक स्थिति जानने वाले समझ सकते हैं कि रूस का वर्चस्व बराबर बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस ही सोवियत संघ का स्थान लेगा। रूस के राष्ट्रपति को ही सभी परमाणु अस्त्रों की कुंजी सौंपी गई है और यह तय हुआ है कि सभी गणराज्यों के परमाणु अस्त्र एक ही कमान के तहत रहे जायेंगे। इसका संचालन रूस को सौंपा गया है। शर्तें यह हैं कि रूसी राष्ट्रपति इनका प्रयोग और तीन गणराज्यों—बेलारूस, यूक्रेन और कजाकिस्तान के राष्ट्रपतियों की सहमति से ही कर सकेंगे। इसके लिए चारों गणराज्यों को जोड़ने के लिए एक 'हाट लाइन' बनाई गई है। परमाणु हथियारों को केन्द्रीय नियन्त्रण में रखने की इस सहमति के पीछे अमरीका और यूरोपीय देशों का दबाव है। अमरीका ने स्पष्ट कर दिया था कि परमाणु हथियारों के सुरक्षित प्रबन्ध के बिना अमरीका के लिए राष्ट्रकुल के गणराज्यों की मदद नहीं की जायेगी। लेकिन पारम्परिक सेनाओं और नए परमाणु हथियारों के नियन्त्रण पर कोई समझौता नहीं हुआ। हर गणराज्य में राष्ट्रवादी भावनाएँ इतनी तेज हैं कि वे अपनी सेनाओं पर रूस के नियन्त्रण को अपनी प्रभुसत्ता में हस्तक्षेप मानते हैं। इसलिए बेलारूस, यूक्रेन और कजाकिस्तान ने कह दिया है कि वे अपनी सेनाओं का निर्माण करेंगे।

रूस तथा उसके सहयोगी राष्ट्र कुल के अन्य राष्ट्रों की 1990 में परमाणु अस्त्रों में निम्न स्थिति थी—

राष्ट्र	परमाणु अस्त्रों की संख्या
रूस	19,000
यूक्रेन	4,000
कजाकिस्तान	1,800
बेलारूस	1,250
अज़रबाईजान	300
आर्मीनिया	200
तुर्कमेनिस्तान	125
उजबेकिस्तान	105
मानदीविया	90
तदजाकिस्तान	75
किर्गिजिया	75
लिथुआनिया	325
ज़ाज़िया	320
एस्टोनिया	270
लैटविया	185

शुरू किया। 1964 में छुस्चेव को हटाकर ब्रेझनेव पार्टी के महामन्त्री बन बैठे और 1982 तक अपने पद पर बने रहे। उनकी मृत्यु के 3 साल बाद 1985 में गोर्बाच्योव कम्युनिस्ट पार्टी के महामन्त्री बने। उन्होंने ग्लास्नोस्ट (खुलापन) और परेस्त्रोयका (पुनर्निर्माण) के सिद्धान्त लागू किए। प्रतीफल यह हुआ कि दिसम्बर, 1991 में सोवियत संघ का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। लिबुआनिया, लटविया और एस्टोनिया के तीन राज्य सोवियत संघ से अलग हो गए और शेष 11 राज्यों—बेलारूस, मोलदोविया, यूक्रेन, आर्मीनिया, अज़रबाइजान, तुर्कमेनिस्तान, उज़बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किरगीजिया, कजाखस्तान और रूस ने एक राष्ट्रकुल (Commonwealth of Independent States - CIS) स्थापित किया। इस राष्ट्रकुल की शुरुआत रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने मिल कर की थी।

इतने पुमान्तकारी परिवर्तन के आसान कारण खोजने के भाड़ी लोग सारा दोष गोर्बाच्योव के मल्ले मढ़ रहे हैं। इनमें वे लोग भी शामिल हैं, जो इतिहास के नियमन में व्यक्ति की भूमिका को मिद्वान्त रूप से नकारते रहे हैं और कहते रहे हैं कि मनुष्य का प्रारब्ध तो कार्ल मार्क्स के फौलादी नियमों का अनुषर मात्र है। हम नहीं जानते कि अविष्य गोर्बाच्योव पर क्या निर्णय देगा, किन्तु स्वातंत्र्य और समता मानव समाज के उच्चतम आदर्श हैं, तो मानना होगा कि गोर्बाच्योव ने अपदस्य हो कर भी ऐतिहासिक भूमिका निभायी है। उन्होंने सर्वसत्तावादी व्यवस्था के शिखर पर पहुँच कर अपनी सत्ता बनाये रखने के लिए उन साधनों का उपयोग नहीं किया, जिनके बल पर अधिनायकवादी धामन चलता है। उन्होंने सोवियत संघ की व्यवस्था के तीन अत्यन्त महत्वपूर्ण पाथों—सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी, सर्वव्यापी गुप्तचर सस्य के० जी० वी० और ईश्वरीय विधान जैसे महिमा से मडित साम्यवादी विचारधारा को हिला कर अद्भुत साहस का परिचय दिया।

इस काम में गोर्बाच्योव से कुछ गलतियाँ जरूर हुईं। वे ग्लास्नोस्ट (खुलापन) और परेस्त्रोयका (पुनर्निर्माण) के राजनीतिक परिणामों का सही-सही अंदाज नहीं लगा सके। वे विशालकाय सोवियत संघ में सम्मिलित गणतन्त्रों की दबी हुई राष्ट्रीय आकांक्षाओं की उत्कटता को भी नहीं समझ पाये। वे और उनके सहयोगी तीन चौथाई सदी से चल रही अतिशय केन्द्रित अर्थव्यवस्था तथा उससे लाभान्वित साम्यवादी नौकरशाही को आमूल रूप से बदलने में अन्तर्जिहित जोशियों का भी वस्तुपरक आकलन नहीं कर सके। यह भी गिलान्त स्वामाविक था कि उनसे परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी दोनों ही विभूषण होते। इस विक्षोभ का एक रूप अगस्त 1991 में कट्टरपथियों की प्रतिग्रान्ति के रूप में सामने आया था तो दूसरा रूप रूसी कंठरेगन के अध्यक्ष बोरीस येल्तसिन की महत्वकांक्षा के रूप में उभरा। गोर्बाच्योव दो पाटों के बीच में फिसे।

किन्तु अपदस्य गोर्बाच्योव की भी अपनी उपलब्धियाँ हैं। अपने सात साल के धामन काल में उन्होंने विद्वधान्ति की दिशा में असाधारण प्रयाम किये। वे सत्तासीन हुए थे तब पृथ्वी तो क्या अन्तरिक्ष तक में परमाणु-युद्ध का सतरा मडरा रहा था। यह गोर्बाच्योव-युग की ही सकारात्मक परिणति है कि आज मनुष्यता अपने को तब से गही अधिक सुरक्षित महशूस करती है। इसी तरह से एक समय में रूस के जारशाही भाषामय के जुए की और बाद में वारसा सधि के नियन्त्रण की स्वीकार करने की विषय पूर्वी यूरोप के देस आज स्वतन्त्र और सधप्रभुता सम्पन्न

घन भी प्राप्त हो सकें। इस्लामी महासच द्वारा ये सब चीजें उपलब्ध हो सकेंगी और वह भी निःशुल्क। इसलिए ऐन महासच से भारत का वास्तव में गम्भीर खतरा है।

सीनेटर प्रेसलेर का यह कहना सही है कि इस्लामी महासच की स्थापना रोकी नहीं जा सकती। पर यह भी उतना ही सही है कि यदि भारत चाहे और कोशिश कर तो इस्लामी महासच की स्थापना द्वारा उत्पन्न हुए आतंकवाद और नैतिक क्षरण का मूछावना करने में निश्चय मिल कर संयुक्त राष्ट्र के कारणर उपाय लाये जा सकते हैं। राजनीति की भाँति है और कूटनीति का भी उद्देश्य है कि भारत को अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए कारणर उपाय करने पड़ेंगे न ही उन उपायों को कार्य में लाने के लिए भारत को किसी की भी सहायता की न लेनी पड़े। अब प्रश्न वैचारिक प्रतिबद्धता का नहीं है, अब तो प्रश्न है स्वयं राष्ट्र की रक्षा का।

आर्थिक मामलों में बाजार व्यवस्था और निजीकरण पर तो व्यापक सहमति हो गई है लेकिन राष्ट्रीय मान्यताएँ और सामाजिक जरूरतें आड़े आ रही हैं। मसलन कजाकिस्तान के राष्ट्रपति का मानना है कि आर्थिक सुधारों के स्वरूप और गति में सभी गणराज्यों में एकदम समानता नहीं हो सकती। अपनी आवश्यकता के अनुसार निजीकरण की गति कम या ज्यादा रखी जा सकती है। नजरवायेव का यह तर्क काफी कुछ सही है। कई गणराज्यों की आर्थिक स्थिति रूस की तुलना में काफी खराब है। सांस्कृतिक और जातीय विभिन्नताओं के कारण भी आर्थिक स्तर में फर्क आया है। इसलिए ऐसे गणराज्यों के लिए कमजोर वर्गों के लिए किसी न किसी प्रकार के संरक्षण की आवश्यकता होगी। दरअसल यही स्थिति सभी एशियाई गणराज्यों की है। लेकिन सब से गंभीर विवाद सोवियत संघ की सम्पत्ति का है। हालांकि येल्तसिन ने सारी संप्रदाय सम्पत्ति को कब्जे में ले लिया था लेकिन अब सभी गणराज्य अपना हिस्सा मांग रहे हैं। मुश्किल यह है कि ज्यादातर सम्पत्ति रूस की राजधानी या दूसरे शहरों में ही है। इस विवाद में कटुता काले सागर में सोवियत नीतिना की बजह से पैदा हो गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का दावा है कि यह तीसेना यूक्रेन को ही मिलनी चाहिए। लेकिन रूस इससे सहमत नहीं है, क्योंकि येल्तसिन के अनुसार हम ही सोवियत संघ का सही उत्तराधिकारी हैं।

राष्ट्रकुल के सभी सदस्यों के प्राकृतिक साधन समान नहीं हैं। एशिया की ओर के राष्ट्रों (Asiatic Republics) को इस राष्ट्रकुल में ज्यादा कुछ मिलने की सम्भावना नहीं है। उदाहरण के लिए तदजाकिस्तान को तै। इसके 93% भूभाग पहाड़ी हैं। उयर किरगीजिया के 75% भू-भाग बारह मास वर्ष से ढके रहते हैं। कजाकिस्तान और तुर्कमेनिया विद्युत उत्पादन करने वाले क्षेत्र हैं और वह विद्युत रूस को बेनी जाती है। कजाकिस्तान की खनिज सम्पदा भी बहुत बड़ी है। उमर रूस के पास बहुत बड़ा भू-भाग है। 90% तेल खनिज रूस में उत्पादित होता है, 70% प्राकृतिक गैस और 75% खनिज सम्पदा भी रूस के पास है। इस बात से भी रूस राष्ट्रकुल में अन्य राष्ट्रों के बराबर होता हुआ भी उन सभी से ऊपर रहेगा।

इस नए राष्ट्रकुल में अल्पसंख्यकों का प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरणार्थ, कजाकिस्तान की बात लें। वहाँ की कुल आबादी 1 करोड़ 65 लाख है जिसमें 31% कजाक है, 41% रूसी है, 6% यूक्रेनी है। यूक्रेन में 21% रूसी और बेलारूस में 12% रूसी हैं, उजबेकिस्तान में 11% रूसी, किरगीजिया में 26% रूसी हैं। तदजाकिस्तान में 23% उजबेक और 10% रूसी हैं। तुर्कमेनिया में 13% रूसी हैं। इस प्रकार जब तक मुजह मफाई से अल्पसंख्यकों का प्रश्न नहीं मूलजाया जाता, तब तक शास्त्रात्मक सम्बन्धों में चिरस्थायित्व पैदा नहीं हो सकता।

सम्भावित इस्लामी महासंघ और भारत (Islamic Federation and India)

अमरीकी सीनेटर लैरी प्रेसलर जनवरी 1992 में अपनी यात्रा यात्रा पर थे। इसी दौरान उन्होंने नई दिल्ली में भारत सरकार से बातचीत की तथा बताया कि उसे इस्लामी संघ के तत्वे से आखिरी बड़ी भ्रष्टाचार चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि भारत के लिए नये के दशक में कोई सबसे बड़ा खतरा है तो यह है इस समय

NOTES
